

April to June 2020  
E-Journal  
Volume I, Issue XXX

RNI No. – MPHIN/2013/60638  
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793  
Impact Factor - 5.610 (2018)

# Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)



# नवीन शोध संसार

**Editor - Ashish Narayan Sharma**

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)  
Mob. 09617239102, Email : nssresearchjournal@gmail.com, Website [www.nssresearchjournal.com](http://www.nssresearchjournal.com)

## Index/अनुक्रमणिका

01.	Index/ अनुक्रमणिका .....	02
02.	Regional Editor Board / Editorial Advisory Board .....	07 / 08
03.	Referee Board .....	09
04.	Spokesperson .....	11
05.	Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic: A Review of Infection, Virus–Host Interactions ..... and Impacts of Human Corona Viruses on Global Economy and International Trade (Santosh Ambhore, Ashok Sharma)	13
06.	Assessment of ground water quality of Taloja Industrial Area of Raigad District (Maharashtra) .. (Dr. A.N. Thakkar)	21
07.	Covid-19: A Challenge For Education System Or A Boon For E-Learning? (Dr. Vandana Sharma) ...	24
08.	K.A. Abbas's Cosmic Approach : Transcending Parochialism (Dr. Shefali Jain) .....	27
09.	An evaluation of Basel norms and their impact (Rahul Joshi) .....	31
10.	Human rights and custodial violence: An overview (Shikha Sodhiya) .....	35
11.	Yoga for Stress Management and Well Being (Manju Rani, Surendra Kumar Yadav) .....	39
12.	Violence Against Women And Their Remedies In Present Laws (Richa Agrawal) .....	42
13.	वैश्विक महामारी संकट और मानवाधिकारों का बदलता परिदृश्य (डॉ. भारती लुणावत) .....	48
14.	वर्तमान परिदृश्य और पत्रकारिता (डॉ. अनुसुइया अग्रवाल, डी.लिट्.) .....	51
15.	भारिया जनजाति की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पद्धति पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन (सृष्टि जोन) .....	53
16.	कश्मीर में आतंकवाद की समाप्ति हेतु कुटनीतिक, राजनीतिक एवं सैन्य स्तर पर किये गये प्रयास एवं सुझाव .....	55
	(डॉ. रजनी दुबे)	
17.	अज्ञेय के काव्य में अभिजात्य-वर्ग के प्रति विद्रोह (डॉ. अनुकूल सोलंकी) .....	58
18.	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में महत्व (डॉ. शक्ति जैन) .....	61
19.	हैदराबाद के निजाम संग्रहालय में संग्रहित 18वीं- 19वीं शताब्दी में निजाम परिधान के सन्दर्भ में .....	64
	(डॉ. आशीष गर्ग, साक्षी सिंहवाल)	
20.	भारत की अर्थव्यवस्था पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) का प्रभाव (डॉ. राजीव कुमार झालानी, माधुरी रोजड़े) .....	68
21.	Effects of mental health during Covid-19 (Dr. Sonali Singh) .....	70
22.	Management of Agricultural Waste (Dr. Sadhna Goyal) .....	72
23.	Overview Of Detection And Control Of Environmentally Toxic Gases From Human Health .....	74
	Perspective (Dr. Rashmi Ahuja)	
24.	Remapping Social Narratives in Seven Steps Around The Fire (Dr. P.K.Jain) .....	77
25.	Intellectual property right in digital era special reference of copyright (Niti Nipuna Saxena) .....	81
26.	An extensive analysis on quality of Indexed Journal (Neha Agrawal, Dr.Sagaya Aurelia) .....	83
27.	Social Security benefits and measures for the Women Labour – A Legal Analysis .....	88
	(Dr. Sairam Patro)	

28.	Online Insurance Market in India: Opportunities and Challenges ..... 95 (Dr. Santosh Kumar Panigrahy)	95
29.	Exploration of Pattachitra Paintings – A Reflection of Indian Culture and Traditions ..... 100 (Dr. Smita Jain)	100
30.	CiteScore Analysis of IEEE Journals Indexed by Scopus (Moumita Roy)..... 102	102
31.	खदान एवं पावर प्लांट के अवशिष्टों द्वारा संसाधन प्रबंधन (डॉ. कामता प्रसाद जायसवाल) ..... 106	106
32.	पराम्पराएँ संगीत के धनी हो समुदाय के नारियाँ (ज्योति रानी सिंघु) ..... 111	111
33.	शारीरिक रूप से सामान्य एवं दिव्यांग (मूक-बधिर) विद्यार्थियों की सृजनात्मकता : एक तुलनात्मक अध्ययन ..... 113 (विनिता पालीवाल)	113
34.	Jawaharlal Nehru's Identity and His Encounter with Socialism: A Historical Outlook ..... 118 (Rajeesh F)	118
35.	Bamboo and the environment- The grass grows in Balaghat ..... 121 (Dr. Aalok Kumar Yadav, Poonam Mishra)	121
36.	Soil Contamination And Need Of Public Awareness (Dr. Arun Sikarwar, Dr. Vaishali Lal) ..... 124	124
37.	Correlation Of Group Solar Flare With Sunspot Numbers ..... 127 (Dr. Lokendra Kumar Borker, Dr.S.K. Khandayat)	127
38.	A Comparative Study Of Health Related Fitness Between International And Convent School ..... 130 Of Ujjain Division Madhya Pradesh (Punit Gupta)	130
39.	Preventive Steps To Minimize, Soil Degradation By Fertilizers And Pesticides ..... 133 (Dr. Vaishali Lal, Dr. Arun Sikarwar)	133
40.	किशोरावस्था में समायोजन (श्रीमती कृष्णा शर्मा) ..... 137	137
41.	बालश्रम एवं नियमन एक अलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. विश्वास चौहान, गीता परतेती) ..... 140	140
42.	मध्यप्रदेश के धार जिले में साक्षरता का एक भौगोलिक अध्ययन (प्रो. किरण मण्डलोई, डॉ. एम.एल. नाथ) ..... 142	142
43.	पत्रकारिता : अर्थ और स्वरूप (डॉ. दाशरथी बेहेरा) ..... 144	144
44.	Institutionalization of Social Audit and its impact on MNREGA in Himachal Pradesh - ..... 149 A case study of Kangra and Hamirpur district (Dr. Shivani Sabharwal, Naresh Kumar)	149
45.	भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में लोक कला की भूमिका (डॉ. निशा गुप्ता) ..... 155	155
46.	जीवन बीमा नियमन, नियंत्रण कानून एवं शिकायत निवारण (डॉ. महेश शर्मा, मोनिका सिंघल, डॉ. डी.के. सिंघल) ..... 157	157
47.	राष्ट्रवाद के विकास में आदिवासियों की भूमिका (प्रेमिका पंत) ..... 161	161
48.	कृषि विकास की दिशा में ई-तकनीकी का योगदान (डॉ. प्रभु प्रकाश पाण्डेय, बिन्दु बहादुर कुशवाहा) ..... 163	163
49.	नवीन कर प्रणाली जी.एस.टी. के स्वरूप का भारत के परिपेक्ष में अध्ययन (डॉ. देवेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, आशीष सिंह) ..... 166	166
50.	Human Rights And Terrorism (Mohammad Yusuf, Dr. Shyam Sunder Choudhary) ..... 171	171
51.	महिलाओं में मद्यपान की प्रवृत्ति (उदयपुर जिले के संदर्भ में) (डॉ. सुनीता खण्डेलवाल) ..... 176	176
52.	बाग गुफाओं और भित्ति चित्र का पुरातात्विक महत्व- पर्यटन के संदर्भ में (प्रेमविजय पाटिल) ..... 180	180
53.	महामारी प्लेग का भारतीय जन-मानस पर प्रभाव (डॉ. वन्दना अग्निहोत्री) ..... 185	185
54.	किशोर/किशोरियों के व्यवहार तथा समायोजन पर किये गये विभिन्न शोध - एक अध्ययन ..... 188 (नीतू छिनीवाल, डॉ. दिव्या दुबे)	188

55.	गिरवा तहसील के व्यवसायिक संरचना में ग्रामीण महिलाओं का योगदान ..... 191 (डॉ. युवराज सिंह राठौड़ , धीरज पालीवाल)	191
56.	Sexual Violence Against Women in India (Dr. Nilesh Sharma, Asish Kumar) ..... 193	193
57.	कोरोना, भूगोल एवं समाज (डॉ. सौरभ त्यागी) ..... 201	201
58.	माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य, स्वच्छता सम्बन्धित आदतों एवं योगा के प्रति ..... 204 अभिवृत्ति का विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. प्रीति ग़ोवर, आरती)	204
59.	Position and Structure of Human Management (Dr. Saurabh Dubey) ..... 206	206
60.	समतामूलक समाज और बालिका शोधार्थियों में तनाव स्तर संबंधी अध्ययन (विनीता मुजाल्दे , डॉ. मंजू शर्मा) 209	209
61.	HR Practioners Role : HR Specialists Deals with Job Satisfaction, Loyalty and Commitment ..... 212 (Dr. Saurabh Dubey)	212
62.	प्रवासी साहित्य की भाषा-शैली (मॉरीशस की विशेष संदर्भ में) (डॉ. ज्योति मिश्रा) ..... 214	214
63.	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का सामाजिक जागरूकता के साथ उसके बाधक तत्वों का ..... 217 विश्लेषणात्मक अध्ययन उज्जैन नगर के संदर्भ में (श्रीमती करुणा तिवारी)	217
64.	अभ्यास शिक्षण के दौरान शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व (डॉ. नीलम निगम, श्रीमती सुषमा शर्मा) ..... 221	221
65.	भारत में महिला शिक्षा एवं रोजगार (डॉ. ए.के. पाण्डेय) ..... 223	223
66.	बी एड. प्रशिक्षणार्थियों द्वारा नवाचार एवं अच्छी आदतों के उपयोग का अध्ययन (डॉ. नीलम निगम) ..... 225	225
67.	Skills Related Physical Fitness Variables of Tribal School Children ..... 227 (Ramadhar Pipladiya)	227
68.	The Significance of Teaching English Language to the Students of Hospitality and ..... 232 Tourism Industry (Ms. Monika Choudhary)	232
69.	अवनद्ध वाद्य तबले का विकास (डॉ. प्रवीण कुमार शर्मा) ..... 234	234
70.	जल का उपयोग एवं माँग: रीवा जिले के संदर्भ में एक भौगोलिक अध्ययन (डॉ. भास्कर प्रसाद तिवारी) ..... 236	236
71.	ग्रामीण जीवन के विविध आयाम (डॉ. आर. एस.वाटे) ..... 238	238
72.	हिन्दी कविता में आदिवासी स्त्रियों के सवाल और संघर्ष चेतना (डॉ. त्रिभुवन कुमार साही) ..... 241	241
73.	कलचुरियों का विंध्य भूमि से सम्बन्ध (डॉ. सरोज सिंह) ..... 245	245
74.	हिंदी कविता के विकास में दलितों और गैर- दलितों की भूमिका (कल्पना शेवाळे) ..... 247	247
75.	Violation of Right of Privacy in COVID 19 Pandemic Scenario ..... 250 (Mr. Bijay Kumar Yadav, Dr. Gurpreet Singh)	250
76.	Media Vehicle Preference, Likings and Influence on Purchase and Loyalty of Customers : ..... 252 A Study of the Urban Gujarat's Customers of E-Retail Market (Dr. Himanshu Vaidya, Ayushi V Sutaria)	252
77.	Status of Traditional Collections in State University Libraries : Special References of ..... 261 Gujarat State (Dr. Saiyed Faheem Ali, Alka Jaidatt Gajre)	261
78.	मध्यप्रदेश में कृषको के आर्थिक विकास में लघु सिंचाई परियोजनाओं का योगदान एक विश्लेषणात्मक अध्ययन ..... 269 (सतना जिले के विशेष संदर्भ) (खुशबू त्रिपाठी, डॉ. ए. के. पाण्डेय)	269
79.	मध्यप्रदेश के कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण का योगदान सतना के सन्दर्भ में (प्रभा सिंह, डॉ. ए. के. पाण्डेय) ..... 271	271
80.	बृहस्पति की दृष्टि के आधार पर उसके केन्द्राधिपति दोष का विश्लेषण (अभिषेक आर्य) ..... 273	273



81.	मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन पर कोरोना वायरस ..... 275	275
	महामारी के प्रभाव एवं परिवर्तन की संभावनाएं (डॉ. आशीष नीलकंठ)	
82.	दबाव समूहों का बदलता स्वरूप (देवेश कुमार) ..... 277	277
83.	आत्मा की अमरता के विविध आयाम (के. के. सिंह) ..... 280	280
84.	Mauryan Administration and It's Influence On Present Administrative System ..... 283	283
	(Dr. Madhusudan Choubey)	
85.	आर्थिक विकास को अवस्थाएं तथा प्रक्रिया (डॉ. पी. डी. ज्ञानानी) ..... 286	286
86.	दक्षिणी राजस्थान वर्षा की प्रवृत्ति, कृषि भूमि का उपयोग का वर्गीकरण एक भौगोलिक विश्लेषण ..... 288	288
	2010-11 (रोहित लौहार)	
87.	Role of Information Technology in Insurance Industry (Dr. Nilesh Gangwal) ..... 291	291
88.	Custodial Deaths: Concept and Prospective (Ratna Bhattacharjee, Dr. B.K. Yadav) ..... 294	294
89.	Printed Hindi Characters: Pattern Recognition and Classification ..... 298	298
	(Prof. Rafi Mohammed Shaikh)	
90.	Development of Teaching-Learning Materials (Dr. Pritam Kaur) ..... 300	300
91.	The Impact of Technology on the Environment and How Environmental Technology Could ..... 304	304
	Save Our Planet (Nitesh Sharma)	
92.	Mass Media Exposure of Dairy Farmers in North Gujarat (Dr. Yogesh Chandra Joshi) ..... 307	307
93.	मध्यकाल में मध्यवर्ती भारत में तालाबों व बावड़ियों द्वारा जल संग्रहण (डॉ. अलीमा शहनाज सिद्दीकी) ..... 309	309
94.	मर्यादित राम (डॉ. तृष्णा शुक्ला) ..... 311	311
95.	Cephalosporin $\beta$ -Lactam Antibiotics - A Review (R. K.Prajapati) ..... 313	313
96.	योगदर्शने वृत्तयः (डॉ. नरेन्द्रकुमारः) ..... 321	321
97.	मुस्लिम परिवारों में शिक्षा की प्रगति में महिलाओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन ..... 322	322
	(रीवा शहर के विशेष संदर्भ में) (निगार फातिमा)	
98.	प्रसादोत्तर हिन्दी नाटक और समसामयिक जीवन का स्वर (चरित्र स्थापन के संदर्भ में) (डॉ. ओमवती देवी) .... 324	324
99.	रणकपुर-पर्यटन स्थल : एक भौगोलिक अध्ययन (डॉ. उम्मेद कुमार चौधरी) ..... 327	327
100.	Physical Education Facility in Secondary Schools of Rajasthan ..... 330	330
	(Pawan Kumar Regar, Dr. B. S. Chauhan)	
101.	वैश्वीकरण का भारतीय सभ्यता व संस्कृति पर प्रभाव (डॉ. विनीता मिश्रा) ..... 332	332
102.	Non Performing Assets in Indian Banking Sector (Dr. Rajesh Shroff) ..... 335	335
103.	Effect of Foliar application of Boron and Zinc on Growth, Yield and Quality of Tomato cv. .... 338	338
	Arka Rakshak (Sanjay Kumar, Arvind Kumar, R.N. Singh, Subhash Chandra, P.K. Rathi)	
104.	स्त्री विमर्श और आज की हिंदी कविता (उमेश कुमार विश्वकर्मा) ..... 343	343
105.	E-Waste, Problems, Consequences and Disposal Practices in India : A Review ..... 346	346
	(Dr. Amar Kumar)	
106.	विभाजन पर आधारित हिन्दी उपन्यासों का परिचयात्मक विवरण (डॉ. जयराम त्रिपाठी) ..... 350	350
107.	Mineral Consumption in Different Socio- Economic Status of Urban Population in ..... 354	354
	Moradabad City (Dr. Shobha Gupta)	
108.	कला एवं संगीत का अन्तरंग सम्बन्ध (डॉ. नीतू वशिष्ठ, नेहा गुप्ता) ..... 356	356

109. मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास 'चाक' में अभिव्यक्त नारी-चेतना (रंजीता राय, अमित कुमार) .....	359
110. Parents Intervention to Help Their Mentally Disabled Children (Dr. Mani Bansal) .....	361
111. Sarva Shiksha Abhiyan (Dr. Kiran Yadav) .....	363
112. Understanding Certiorari: With Highlighting Features in India (Dr. Saptmuni Dwivedi) .....	365
113. परम्परागत दृश्य कला रूप और संस्थापन कला (डॉ. अनुराधा आर्य) .....	367
114. On Some Properties of Metric F – Structure Satisfying $F^5 + F = 0$ (Lakhan Singh) .....	371
115. Environmental Sustainability and Public Policy in India (Dr. Archana Singh) .....	373
116. महिला सशक्तिकरण और भारत में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (डॉ. नीरजा शर्मा) .....	376
117. झाला वंश का मेवाड़ के लिए आत्मोत्सर्ग एवं बड़ी सादड़ी ठिकाना (डॉ. सुदर्शन सिंह राठौड़) .....	379
118. ब्रिक्स विकास बैंक और भारत के लिए इसका महत्व (डॉ. प्रवीण पंड्या) .....	381
119. वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव-एक आकलन (डॉ. पन्नालाल कटारा) .....	384
120. रामचरितमानस : नारी पात्रों का चरित्र (डॉ. पुष्पा देवी) .....	386
121. Merger of Canara Bank and Syndicate Bank: An Overview (Mahendra Krishna, Dr. Anil Saxena) .....	390
122. Research: Impact of Public Distribution System Reform on Food Security in Chhattisgarh (Dr. Syed Saleem Aquil, Rakesh Minj) .....	395
123. नयी कविता को मुक्तिबोध का प्रदेय (डॉ. डी.पी. चंद्रवंशी) .....	398
124. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यों एवं नीतियों का विश्लेषण (मोहित कुमार नायक) .....	400
125. चित्रकला व मूर्तिकला के संगीकार (डॉ. राजीव शर्मा) .....	403

## Regional Editor Board - International & National

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Dr. Manisha Thakur              | - Fulton College, Arizona State University, America.   |
| 2. Mr. Ashok Kumar                 | - Employability Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.                       |
| 3. Ass. Prof. Beciu Silviu         | - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.               |
| 4. Mr. Khgendra Prasad Subedi      | - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.     |
| 5. Prof. Dr. G.C. Khimesara        | - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India  |
| 6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav     | - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India                          |
| 7. Prof. Dr. Anoop Vyas            | - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India                              |
| 8. Prof. Dr. P.P. Pandey           | - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India                                |
| 9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani        | - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India                      |
| 10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam     | - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India                                      |
| 11. Prof. Dr. B.S. Jhare           | - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India                              |
| 12. Prof. Dr. Sanjay Khare         | - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India                    |
| 13. Prof. Dr. R.P. Upadhyay        | - Exam Controller, Govt. Kamalraj Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India                     |
| 14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma   | - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India                            |
| 15. Prof. Akhilesh Jadhav          | - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India                     |
| 16. Prof. Dr. Kamal Jain           | - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India   |
| 17. Prof. Dr. D.L. Khadse          | - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharashtra) India                           |
| 18. Prof. Dr. Vandna Jain          | - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India                                   |
| 19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar     | - Prof., Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India   |
| 20. Prof. Dr. Sharda Trivedi       | - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India   |
| 21. Prof. Dr. Usha Shrivastav      | - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India |
| 22. Prof. Dr. G. P. Dawre          | - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India  |
| 23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya      | - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India   |
| 24. Prof. Dr. Vivek Patel          | - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anoopur (M.P.) India                              |
| 25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary | - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India                   |
| 26. Prof. Dr. P.K. Mishra          | - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India  |
| 27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma   | - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India                          |
| 28. Prof. Dr. R. K. Gautam         | - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India                        |
| 29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai       | - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India                     |
| 30. Prof. Dr. Avinash Shendare     | - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India                              |
| 31. Prof. Dr. J.C. Mehta           | - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India                        |
| 32. Prof. Dr. B.S. Makkad          | - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India                            |
| 33. Prof. Dr. P.P. Mishra          | - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India                                      |
| 34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar | - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India                                      |
| 35. Prof. Dr. K.L. Sahu            | - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India                                   |
| 36. Prof. Dr. Malini Johnson       | - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India   |
| 37. Prof. Dr. Ravi Gaur            | - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India                      |
| 38. Prof. Dr. Vishal Purohit       | - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India                                  |

## Editorial Advisory Board, INDIA

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav | - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India  |
| 2. Prof. Dr. Aditya Lunawat      | - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India |
| 3. Prof. Dr. Sanjay Jain         | - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India  |
| 4. Prof. Dr S.K. Joshi           | - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India                                      |
| 5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey       | - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India                              |
| 6. Prof. Dr. Sumitra Waskel      | - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India                                    |
| 7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar     | - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India   |
| 8. Prof. Dr. Mangal Mishra       | - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India                                |
| 9. Prof. Dr. R.K. Bhatt          | - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India  |
| 10. Prof. Dr. Ashok Verma        | - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India                                  |
| 11. Prof. Dr. Rakesh Dhand       | - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India                                      |
| 12. Prof. Dr. Anil Shivani       | - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India          |
| 13. Prof. Dr. PadamSingh Patel   | - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India   |
| 14. Prof. Dr. Manju Dubey        | - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India                                  |
| 15. Prof. Dr. A.K. Choudhary     | - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India                                   |
| 16. Prof. Dr. T. M. Khan         | - Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India  |
| 17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao  | - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India  |
| 18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava   | - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India                              |
| 19. Prof. Dr. Kanta Alawa        | - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India                                     |
| 20. Prof. Dr. S.C. Jain          | - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India   |
| 21. Prof. Dr. Kishan Yadav       | - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India                                 |
| 22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya       | - Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India  |
| 23. Prof. Dr. Purshottam Gautam  | - Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India  |
| 24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta    | - HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India   |
| 25. Prof. Dr. S.C. Mehta         | - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India                               |
| 26. Prof. Dr. A. K. Pandey       | - HOD, Economics Deptt., Govt. Girls College, Satna (M.P.)   |

\*\*\*\*\*



## Referee Board

- Maths** - (1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
- Physics** - (1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
- Computer Science** - (1) Prof. Dr. Umesh Kumar Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
- Chemistry** - (1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
- Botany** - (1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)  
(2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
- Life Science** - (1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)  
(2) Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
- Statistics** - (1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
- Military Science** - (1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
- Biology** - (1) Dr. Kanchan Dhingra, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
- Geology** - (1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
- Medical Science** - (1) Dr. H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
- Microbiology Sci.** - (1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
- \*\*\*\*\* Commerce \*\*\*\*\*
- Commerce** - (1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)  
(3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)  
(4) Naresh Kumar, Assistant Professor, Sidharth Govt. College, Nadaun (H.P.)
- \*\*\*\*\* Management \*\*\*\*\*
- Management** - (1) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
- Human Resources** - (1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
- Business Administration** - (1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
- \*\*\*\*\* Law \*\*\*\*\*
- Law** - (1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
- \*\*\*\*\* Arts \*\*\*\*\*
- Economics** - (1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)  
(2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)  
(3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)  
(4) Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
- Political Science** - (1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)  
(3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
- Philosophy** - (1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
- Sociology** - (1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)  
(2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)  
(3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

- Hindi** - (1) Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)  
(3) Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)  
(4) Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)  
(5) Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
- English** - (1) Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
- Sanskrit** - (1) Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
- History** - (1) Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
- Geography** - (1) Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)  
(2) Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
- Psychology** - (1) Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
- Drawing** - (1) Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)  
(3) Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
- Music/Dance** - (1) Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak), Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)  
(2) Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
- \*\*\*\*\* Home Science \*\*\*\*\*
- Diet/Nutrition Science** - (1) Prof. Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)  
(2) Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)  
(3) Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
- Human Development** - (1) Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)  
(2) Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
- Family Resource Management** - (1) Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
- \*\*\*\*\* Education \*\*\*\*\*
- Education** - (1) Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)  
(2) Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific Education College, Udaipur (Raj.)  
(3) Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)  
(4) Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education, Tigaon, Faridabad (Haryana)  
(5) Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)
- \*\*\*\*\* Architecture \*\*\*\*\*
- Architecture** - (1) Prof. Kiran P. Shindey, Principal, School of Architecture, IPS Academy, Indore (M.P.)
- \*\*\*\*\* Physical Education \*\*\*\*\*
- Physical Education** - (1) Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)  
(2) Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)  
(3) Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)
- \*\*\*\*\* Library Science \*\*\*\*\*
- Library Science** - (1) Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

## Spokesperson's

1. Prof. Dr. Davendra Rathore - Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2. Prof. Smt. Vijaya Wadhwa - Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3. Dr. Surendra Shaktawat - Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4. Prof. Dr. Devilal Ahir - Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5. Shri Ashish Dwivedi - Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6. Prof. Manoj Mahajan - Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7. Shri Umesh Sharma - Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8. Prof. Dr. S.P. Panwar - Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9. Prof. Dr. Puralal Patidar - Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10. Prof. Dr. Kshitij Purohit - Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11. Prof. Dr. N.K. Patidar - Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12. Prof. Dr. Y.K. Mishra - Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13. Prof. Dr. Suresh Kataria - Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14. Prof. Dr. Abhay Pathak - Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15. Prof. Dr. Malsingh Chouhan - Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16. Prof. Dr. Gendalal Chouhan - Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17. Prof. Dr. Prabhakar Mishra - Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18. Prof. Dr. Prakash Kumar Jain - Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19. Prof. Dr. Kamla Chauhan - Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20. Prof. Abha Dixit - Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21. Prof. Dr. Pankaj Maheshwari - Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22. Prof. Dr. D.C. Rathi - Swami Vivekanand Career Gudiance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23. Prof. Dr. Anita Gagrade - Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24. Prof. Dr. Sanjay Pandit - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25. Prof. Dr. Rambabu Gupta - Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26. Prof. Dr. Anjana Saxena - Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27. Prof. Dr. Sonali Nargunde - Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28. Prof. Dr. Bharti Joshi - Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29. Prof. Dr. M.D. Somani - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30. Prof. Dr. Priti Bhatt - Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31. Prof. Dr. Sanjay Prasad - Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32. Prof. Dr. Meena Matkar - Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33. Prof. Dr. Mohan Waskel - Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34. Prof. Dr. Nitin Sahariya - Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35. Prof. Dr. Manju Rajoriya - Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36. Prof. Dr. Shahjad Qureshi - Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37. Prof. Dr. Shail Bala Sanghi - Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38. Prof. Dr. Praveen Ojha - Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39. Prof. Dr. Omprakash Sharma - Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40. Prof. Dr. S.K. Shrivastava - Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41. Prof. Dr. Anoop Moghe - Govt. Kamalaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42. Prof. Dr. Hemlata Chouhan - Govt. College, Badnagar (M.P.)
43. Prof. Dr. Maheshchandra Gupta - Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44. Prof. Dr. Mangla Thakur - Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45. Prof. Dr. K.R. Kumhekar - Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)

46. Prof. Dr. R.K. Yadav - Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta - Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi - Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey - Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar - Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel - Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta - Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash - Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava - Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai - Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya - Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
57. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain - Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
58. Prof. Dr. Niyaz Ansari - Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)
59. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel - Govt. College, Harda (M.P.)
60. Dr. Suresh Kumar Vimal - Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
61. Prof. Dr. Amar Chand Jain - Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
62. Prof. Dr. Rashmi Dubey - Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. A.K. Jain - Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. Sandhya Tikekar - Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Rajiv Sharma - Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
66. Prof. Dr. Rashmi Srivastava - Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Laxmikant Chandela - Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
68. Prof. Dr. Balram Singotiya - Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Vimmi Bahel - Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
70. Prof. Aprajita Bhargava - R.D.Public School, Betul (M.P.)
71. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan - Govt. College, Maksi, Distt. Shajapur (M.P.)
72. Prof. Dr. Pallavi Mishra - Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
73. Prof. Dr. N.P. Sharma - Govt. College, Datia (M.P.)
74. Prof. Dr. Jaya Sharma - Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
75. Prof. Dr. Sunil Somwanshi - Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
76. Prof. Dr. Ishrat Khan - Govt. College, Raisen (M.P.)
77. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi - Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
78. Prof. Dr. Bhawana Thakur - Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Keshavmani Sharma - Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
80. Prof. Dr. Renu Rajesh - Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
81. Prof. Dr. Avinash Dubey - Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
82. Prof. Dr. V.K. Dixit - Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
83. Prof. Dr. Ram Awdesch Sharma - M.J.S. Govt. P.G. College, Bhind (M.P.)
84. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri - Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
85. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla - Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
86. Prof. Dr. Anoop Parsai - Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh )
87. Prof. Dr. Anil Kumar Jain - Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
88. Prof. Dr. Kavita Bhadiiya - Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
89. Prof. Dr. Archana Vishith - Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
90. Prof. Dr. Kalpana Parikh - S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Gajendra Siroha - Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Krishna Pensia - Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Pradeep Singh - Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
94. Prof. Dr. Smriti Agarwal - Research Consultant, New Delhi



# Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic: A Review of Infection, VirusHost Interactions and Impacts of Human Corona Viruses on Global Economy and International Trade

Santosh Ambhore\* Ashok Sharma\*\*

**Abstract** - The 2019–20 coronavirus pandemic is an ongoing pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The outbreak was identified in Wuhan, China, in December 2019. The World Health Organization declared the outbreak to be a Public Health Emergency of International Concern on 30 January 2020, and recognized it as a pandemic on 11 March 2020. As of 19 April 2020, more than 2.33 million cases of COVID-19 have been reported in 185 countries and territories, resulting in more than 160,000 deaths. More than 598,000 people have recovered, although there may be a possibility of relapse or reinfection.

Coronaviruses are a group of related viruses that cause diseases in mammals and birds. In humans, coronaviruses cause respiratory tract infections that can be mild, such as some cases of the common cold (among other possible causes, predominantly rhinoviruses), and others that can be lethal, such as SARS, MERS, and COVID-19. The name “coronavirus” is derived from Latin *corona*, meaning “crown” or “wreath”, itself a borrowing from Greek *κορώνη* *korōnē*, “garland, wreath”. The name refers to the characteristic appearance of virions (the infective form of the virus).

Coronaviruses vary significantly in risk factor. Some can kill more than 30% of those infected (such as MERS-CoV), and some are relatively harmless, such as the common cold. Coronaviruses cause colds with major symptoms, such as fever, and sore throat from swollen adenoids, occurring primarily in the winter and early spring seasons. Coronaviruses can cause pneumonia (either direct viral pneumonia or a secondary bacterial pneumonia) and bronchitis (either direct viral bronchitis or a secondary bacterial bronchitis). The much publicized human coronavirus discovered in 2003, SARS-CoV, which causes severe acute respiratory syndrome (SARS), has a unique pathogenesis because it causes both upper and lower respiratory tract infections. Around 200 countries and territories have had at least one case. Due to the pandemic in Europe, many countries have restricted free movement and set up border controls. National reactions have included containment measures such as quarantines and curfews (known as stay-at-home orders, shelter-in-place orders, or lockdowns). As of 12 April, nearly 300 million people, or about 90 per cent of the population, are under some form of lockdown in the United States, more than 50 million people are in lockdown in the Philippines, about 59 million people are in lockdown in South Africa, and 1.3 billion people are in lockdown in India. On 26 March, 1.7 billion people worldwide were under some form of lockdown, which increased to 3.9 billion people one week later – more than half of the world’s population.

**Keywords**-pandemic, swollen adenoids, quarantines, lockdown, pathogenesis, epidemiology.

**Introduction** - The 2019–20 coronavirus pandemic is an ongoing pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The outbreak was identified in Wuhan, China, in December 2019. The World Health Organization declared the outbreak to be a Public Health Emergency of International Concern on 30 January 2020, and recognized it as a pandemic on 11 March 2020. As of 19 April 2020, more than 2.33 million cases of COVID-19 have been reported in 185 countries and territories, resulting in more than 160,000 deaths. More than 598,000 people have recovered, although there may be a possibility of

relapse or reinfection.

Coronaviruses are a group of related viruses that cause diseases in mammals and birds. In humans, coronaviruses cause respiratory tract infections that can be mild, such as some cases of the common cold (among other possible causes, predominantly rhinoviruses), and others that can be lethal, such as SARS, MERS, and COVID-19. Symptoms in other species vary: in chickens, they cause an upper respiratory tract disease, while in cows and pigs they cause diarrhoea. There are yet to be vaccines or antiviral drugs to prevent or treat human coronavirus infections.

\* Department of Chemistry, Government Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

\*\* Department of Military Science, Government Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

Coronaviruses constitute the subfamily *Orthocoronavirinae*, in the family *Coronaviridae*, order *Nidovirales*, and realm *Riboviria*. They are enveloped viruses with a positive-sense single-stranded RNA genome and a nucleocapsid of helical symmetry. The genome size of coronaviruses ranges from approximately 27 to 34 kilobases, the largest among known RNA viruses. The name *coronavirus* is derived from the Latin *corona*, meaning “crown” or “halo”, which refers to the characteristic appearance reminiscent of a crown or a solar corona around the virions (virus particles) when viewed under two-dimensional transmission electron microscopy, due to the surface being covered in club-shaped protein spikes.

**History** - There are various theories about where the very first case (the so-called patient zero) may have originated. The first known case may trace back to 1<sup>st</sup> December 2019 in Wuhan, Hubei, China. Within a month, the number of coronavirus cases in Hubei gradually increased. These were mostly linked to the Huanan Seafood Wholesale Market, which also sold live animals, and one theory is that the virus came from one of these animals; or, in other words, has a zoonotic origin.

A pneumonia cluster of unknown cause was observed on 26 December and treated by the doctor Zhang Jixian in Hubei Provincial Hospital, who informed the Wuhan Jiangnan CDC on 27<sup>th</sup> December. On 30<sup>th</sup> December, a group of doctors at Wuhan Central Hospital alerted their colleagues of a “SARS-like coronavirus”. The Wuhan Municipal Health Commission released a public notice on 31<sup>st</sup> December. Eight of these doctors, including Li Wenliang, were then admonished by the police for spreading supposedly false rumours, and another, Ai Fen, was reprimanded by her superiors for raising the alarm. Enough cases of unknown pneumonia had been reported to health authorities in Wuhan to trigger an investigation in early January.

**Discovery** - Human coronaviruses were first discovered in the late 1960s. The earliest ones discovered were an infectious bronchitis virus in chickens and two in human patients with the common cold (later named human coronavirus 229E and human coronavirus OC43). Other members of this family have since been identified, including SARS-CoV in 2003, HCoV NL63 in 2004, HKU1 in 2005, MERS-CoV in 2012, and SARS-CoV-2 (formerly known as 2019-nCoV) in 2019. Most of these have involved serious respiratory tract infections

**Taxonomy/Etymology** - The name “coronavirus” is derived from Latin *corona*, meaning “crown” or “wreath”, itself a borrowing from Greek *κορώνη* *korōnē*, garland, wreath”. The name refers to the characteristic appearance of virions (the infective form of the virus) by electron microscopy, which have a fringe of large, bulbous surface projections creating an image reminiscent of a crown or of a solar corona. This morphology is created by the viral spike peplomers, which are proteins on the surface of the virus.

The scientific name for coronavirus is *Orthocoronavirinae* or *Coronavirinae*. Coronavirus belongs to the family of *Coronaviridae*.

- Genus: **Alphacoronavirus**

Species: *Human coronavirus 229E*, *Human coronavirus NL63*, *Miniopterus bat coronavirus 1*, *Miniopterus bat coronavirus HKU8*, *Porcine epidemic diarrhea virus*, *Rhinolophus bat coronavirus HKU2*, *Scotophilus bat coronavirus 512*

- Genus **Betacoronavirus**; type species: *Murine coronavirus*

Species: *Betacoronavirus 1*, *Human coronavirus HKU1*, *Murine coronavirus*, *Pipistrellus bat coronavirus HKU5*, *Rousettus bat coronavirus HKU9*, *Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus*, *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2*, *Tylonycteris bat coronavirus HKU4*, *Middle East respiratory syndrome-related coronavirus*, *Human coronavirus OC43*, *Hedgehog coronavirus 1 (EriCoV)*

- Genus **Gammacoronavirus**; type species: *Infectious bronchitis virus*

Species: *Beluga whale coronavirus SW1*, *Infectious bronchitis virus*

- Genus **Deltacoronavirus**; type species: *Bulbul coronavirus HKU11*

Species: *Bulbul coronavirus HKU11*, *Porcine coronavirus HKU15*

**Human Corona Viruses** - Coronaviruses vary significantly in risk factor. Some can kill more than 30% of those infected (such as MERS-CoV), and some are relatively harmless, such as the common cold. Coronaviruses cause colds with major symptoms, such as fever, and sore throat from swollen adenoids, occurring primarily in the winter and early spring seasons. Coronaviruses can cause pneumonia (either direct viral pneumonia or a secondary bacterial pneumonia) and bronchitis (either direct viral bronchitis or a secondary bacterial bronchitis). The much publicized human coronavirus discovered in 2003, SARS-CoV, which causes severe acute respiratory syndrome (SARS), has a unique pathogenesis because it causes both upper and lower respiratory tract infections.

Seven strains of human coronaviruses are known, of which four produce the generally mild symptoms of the common cold:

1. Human coronavirus OC43 (HCoV-OC43)
  2. Human coronavirus HKU1
  3. Human coronavirus NL63 (HCoV-NL63, New Haven coronavirus)
  4. Human coronavirus 229E (HCoV-229E)
    - and three, symptoms that are potentially severe:
1. Middle East respiratory syndrome-related coronavirus (MERS-CoV), previously known as *novel coronavirus 2012* and *HCoV-EMC*
  2. Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV or “SARS-classic”)
  3. Severe acute respiratory syndrome coronavirus

2 (SARS-CoV-2), previously known as 2019-nCoV or "novel coronavirus 2019"

The coronaviruses HCoV-229E, -NL63, -OC43, and -HKU1 continually circulate in the human population and cause respiratory infections in adults and children worldwide.

**Epidemiology** - Health authorities in Wuhan, Hubei reported a cluster of viral pneumonia cases of unknown cause on 31 December 2019, and an investigation was launched in early January 2020. The cases mostly had links to the Huanan Seafood Wholesale Market and so the virus is thought to have a zoonotic origin. The virus that caused the outbreak is known as SARS-CoV-2, a newly discovered virus closely related to bat coronaviruses, pangolin coronaviruses and SARS-CoV. In March and April 2020, scientists reported that the virus originated naturally. The earliest known person with symptoms was later discovered to have fallen ill on 1 December 2019, and that person did not have visible connections with the later wet market cluster. Of the early cluster of cases reported in December 2019, two-thirds were found to have a link with the market. On 13 March 2020, an unverified report from the South China Morning Post suggested a case traced back to 17 November 2019, in a 55-year-old from Hubei, may have been the first.

**Morphology** - Coronaviruses are large pleomorphic spherical particles with bulbous surface projections. The diameter of the virus particles is around 120 nm. The envelope of the virus in electron micrographs appears as a distinct pair of electron dense shells. The viral envelope consists of a lipid bilayer where the membrane, envelope and spike structural proteins are anchored. A subset of coronaviruses also have a shorter spike-like surface protein called hemagglutinin esterase. Inside the envelope, there is the nucleocapsid, which is formed from multiple copies of the nucleocapsid protein, which are bound to the positive-sense single-stranded RNA genome in a continuous beads-on-a-string type conformation. The lipid bilayer envelope, membrane proteins, and nucleocapsid protect the virus when it is outside the host cell.

**Virology** - Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is a novel virus, first isolated from three people with pneumonia connected to the cluster of acute respiratory illness cases in Wuhan. All features of the novel SARS-CoV-2 virus occur in related coronaviruses in nature. SARS-CoV-2 is closely related to SARS-CoV, and is thought to have a zoonotic origin. SARS-CoV-2 genetically clusters with the genus *Betacoronavirus*, and is 96 per cent identical at the whole genome level to other bat coronavirus samples and 92 per cent identical to pangolin coronavirus.

**Genomic cis-acting elements and Genome packaging** - In common with the genomes of all other RNA viruses, coronavirus genomes contain cis-acting RNA elements that ensure the specific replication of viral RNA by a virally encoded RNA-dependent RNA polymerase. The embedded cis-acting elements devoted to coronavirus replication

constitute a small fraction of the total genome, but this is presumed to be a reflection of the fact that coronaviruses have the largest genomes of all RNA viruses. The boundaries of cis-acting elements essential to replication are fairly well-defined, and the RNA secondary structures of these regions are understood. However, how these cis-acting structures and sequences interact with the viral replicase and host cell components to allow RNA synthesis is not well understood.

The assembly of infectious coronavirus particles requires the selection of viral genomic RNA from a cellular pool that contains an abundant excess of non-viral and viral RNAs. Among the seven to ten specific viral mRNAs synthesized in virus-infected cells, only the full-length genomic RNA is packaged efficiently into coronavirus particles. Studies have revealed cis-acting elements and trans-acting viral factors involved in the coronavirus genome encapsidation and packaging. Understanding the molecular mechanisms of genome selection and packaging is critical for developing antiviral strategies and viral expression vectors based on the coronavirus genome.

**Replication** - A number of the nonstructural proteins coalesce to form a multi-protein replicase-transcriptase complex (RTC). The main replicase-transcriptase protein is the RNA-dependent RNA polymerase (RdRp). It is directly involved in the replication and transcription of RNA from an RNA strand. The other nonstructural proteins in the complex assist in the replication and transcription process. The exoribonuclease non-structural protein, for instance, provides extra fidelity to replication by providing a proofreading function which the RNA-dependent RNA polymerase lacks.

One of the main functions of the complex is to replicate the viral genome. RdRp directly mediates the synthesis of negative-sense genomic RNA from the positive-sense genomic RNA. This is followed by the replication of positive-sense genomic RNA from the negative-sense genomic RNA. The other important function of the complex is to transcribe the viral genome. RdRp directly mediates the synthesis of negative-sense subgenomic RNA molecules from the positive-sense genomic RNA. This is followed by the transcription of these negative-sense subgenomic RNA molecules to their corresponding positive-sense mRNAs.

**Transmission** - Some details about how the disease is spread are still being determined. The disease is believed to be primarily spread during close contact and by small droplets produced during coughing, sneezing, or talking with close contact being within 1 to 2 metres (3 to 6 feet). Both sputum and saliva can carry large viral loads. Studies have found that an uncovered cough can lead to droplets travelling up to 4.5 metres (15 feet) to 11.4 metres (37 feet). Some have proposed the virus may also be transmitted by small droplets that stay for more prolonged periods in the air, as may be generated during speech.

Respiratory droplets may also be produced during



breathing out, including when talking, though the virus is not generally airborne. The droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby or possibly be inhaled into the lungs. Some medical procedures such as intubation and cardiopulmonary resuscitation (CPR) may cause respiratory secretions to be aerosolized and thus result in airborne spread. It may also spread when one touches a contaminated surface, including skin, and then touches their eyes, nose, or mouth. While there are concerns it may spread by faeces, this risk is believed to be low. The Government of China denied the possibility of faecal–oral transmission of SARS-CoV-2. The virus is most contagious during the first three days after onset of symptoms, although spread may be possible before symptoms appear and in later stages of the disease. People have tested positive for the disease up to three days before onset of symptoms, suggesting transmission is possible before developing significant symptoms. Only a few reports of laboratory-confirmed asymptomatic cases exist, but asymptomatic transmission has been identified by some countries during contact tracing investigations. The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) says while it is not entirely clear how easily the disease spreads, one person generally infects two to three others.

The virus survives for hours to days on surfaces. Specifically, the virus was found to be detectable for up to three days on plastic (polypropylene) and for one day on cardboard, and for up to four hours on copper. This, however, varies based on the humidity and temperature. Pets and other animals have tested positive for COVID-19. There is no evidence animals can pass the virus on to humans, though British authorities advise washing one's hands after contact with animals, like after contact with other potentially contaminated surfaces.

**Diagnosis/ Viral testing** - Infection by the virus can be provisionally diagnosed on the basis of symptoms, though confirmation is ultimately by reverse transcription polymerase chain reaction (rRT-PCR) of infected secretions or CT imaging. A study comparing PCR to CT in Wuhan suggests CT is significantly more sensitive than PCR, though less specific, with many of its imaging features overlapping with other pneumonias and disease processes. As of March 2020, the American College of Radiology recommends that "CT should not be used to screen for or as a first-line test to diagnose COVID-19". The WHO has published several RNA testing protocols for SARS-CoV-2, with the first issued on 17 January. The test uses real-time reverse transcription polymerase chain reaction (rRT-PCR). The test can be done on respiratory or blood samples. Results are generally available within a few hours to days. Generally this test is carried out on a nasopharyngeal swab though a throat swab may also be used. A number of laboratories and companies are developing serological tests, which detect antibodies. As of 6 April 2020, none of these has been proved sufficiently accurate to be approved for widespread use.

**Cases** - Cases refers to the number of people who have been tested for COVID-19, and whose test has been confirmed positive according to official protocols. As of 18 April, the countries that made public their testing data have on average performed an amount of tests equal to only 1.1 per cent of their population, while no country has tested samples equal to more than 12 per cent of its population. Many countries (for example, Italy and Switzerland, as well as the Netherlands and Spain) have had official policies not to test those with only mild symptoms. An analysis of the early phase of the outbreak up to 23 January estimated 86 per cent of COVID-19 infections had not been detected, and that these undocumented infections were the source for 79 per cent of documented cases. Several other studies, using a variety of methods, have estimated that numbers of infections in many countries are likely to be considerably greater than the reported cases.

**Treatment** - There are no specific antiviral medications approved for COVID-19, but development efforts are underway, including testing of existing medications. Taking over-the-counter cold medications, drinking fluids, and resting may help alleviate symptoms. Depending on the severity, oxygen therapy, intravenous fluids, and breathing support may be required. The use of steroids may worsen outcomes. Several compounds which were previously approved for treatment of other viral diseases are being investigated for use in treating COVID-19.

**Deaths** - The first confirmed death was in Wuhan on 9<sup>th</sup> January 2020. The first death outside mainland China occurred on 1 February in the Philippines, and the first death outside Asia was in France on 14 February. By 28<sup>th</sup> February, outside mainland China, more than a dozen deaths each were recorded in Iran, South Korea, and Italy. By 13<sup>th</sup> March, more than forty countries and territories had reported deaths, on every continent except Antarctica. Official deaths from the COVID-19 generally refer to people who died after testing positive according to official protocols. This may ignore deaths of people who die without testing – e.g. at home or in nursing homes. Conversely, deaths of people who had underlying conditions may lead to overcounting. There are indications of undercounting of deaths in Brazil, China, Iran, North Korea, Russia, the UK, and the U.S., and overcounting in Belgium. Several measures are commonly used to quantify mortality. These numbers vary by region and over time, and are influenced by the volume of testing, healthcare system quality, treatment options, time since initial outbreak, and population characteristics such as age, sex, and overall health. The death-to-case ratio reflects the number of deaths attributed to COVID-19 divided by the number of diagnosed cases within a given time interval.

**Prevention** - Strategies for preventing transmission of the disease include maintaining overall good personal hygiene, washing hands, avoiding touching the eyes, nose, or mouth with unwashed hands, and coughing or sneezing into a



tissue and putting the tissue directly into a waste container. Those who may already have the infection have been advised to wear a surgical mask in public. Physical distancing measures are also recommended to prevent transmission. Health care providers taking care of someone who may be infected are recommended to use standard precautions, contact precautions, and eye protection. Many governments have restricted or advised against all non-essential travel to and from countries and areas affected by the outbreak. However, the virus is already spreading within communities in large parts of the world, with many not knowing where or how they were infected. Misconceptions are circulating about how to prevent infection; for example, rinsing the nose and gargling with mouthwash are not effective. There is no COVID-19 vaccine, though many organizations are working to develop one.

**1. Hand washing** - Hand washing is recommended to prevent the spread of the disease. The CDC recommends that people wash hands often with soap and water for at least twenty seconds, especially after going to the toilet or when hands are visibly dirty; before eating; and after blowing one's nose, coughing, or sneezing. This is because outside the human body, the virus is killed by household soap, which bursts its protective bubble. CDC further recommended using an alcohol-based hand sanitizer with at least 60 per cent alcohol by volume when soap and water are not readily available. The WHO advises people to avoid touching the eyes, nose, or mouth with unwashed hands.

**2. Surface cleaning** - Surfaces may be decontaminated with a number of solutions (within one minute of exposure to the disinfectant for a stainless steel surface), including 62–71 per cent ethanol, 50–100 per cent isopropanol, 0.1 per cent sodium hypochlorite, 0.5 per cent hydrogen peroxide, and 0.2–7.5 per cent povidone-iodine. Other solutions, such as benzalkonium chloride and chlorhexidine gluconate, are less effective. The CDC recommends that if a COVID case is suspected or confirmed at a facility such as an office or day care, all areas such as offices, bathrooms, common areas, shared electronic equipment like tablets, touch screens, keyboards, remote controls, and ATM machines used by the ill persons, should be disinfected.

**3. Face masks and respiratory hygiene** - Health organizations recommended that people cover their mouth and nose with a bent elbow or a tissue when coughing or sneezing, and disposing of any tissue immediately. Surgical masks are recommended for those who may be infected, as wearing a mask can limit the volume and travel distance of expiratory droplets dispersed when talking, sneezing, and coughing. The WHO has issued instructions on when and how to use masks. Masks have also been recommended for use by those taking care of someone who may have the disease. The WHO has recommended healthy people wear masks only if they are at high risk, such as those who are caring for a person with COVID-19. China and the United

States, among other countries, have encouraged the use of face masks or cloth face coverings more generally by members of the public to limit the spread of the virus by asymptomatic individuals. Several national and local governments have made wearing masks mandatory.

**4. Social distancing** - Social distancing (also known as physical distancing) includes infection control actions intended to slow the spread of disease by minimizing close contact between individuals. Methods include quarantines; travel restrictions; and the closing of schools, workplaces, stadiums, theatres, or shopping centres. Individuals may apply social distancing methods by staying at home, limiting travel, avoiding crowded areas, using no-contact greetings, and physically distancing themselves from others. Many governments are now mandating or recommending social distancing in regions affected by the outbreak. The maximum gathering size recommended by U.S. government bodies and health organizations was swiftly reduced from 250 people (if there was no known COVID-19 spread in a region) to 50 people, and later to 10 people.

**5. Self-isolation** - Self-isolation at home has been recommended for those diagnosed with COVID-19 and those who suspect they have been infected. Health agencies have issued detailed instructions for proper self-isolation. Many governments have mandated or recommended self-quarantine for entire populations living in affected areas. The strongest self-quarantine instructions have been issued to those in high risk groups. Those who may have been exposed to someone with COVID-19 and those who have recently travelled to a country or region with widespread transmission have been advised to self-quarantine for 14 days from the time of last possible exposure.

**Domestic Responses** - Around 200 countries and territories have had at least one case. Due to the pandemic in Europe, many countries have restricted free movement and set up border controls. National reactions have included containment measures such as quarantines and curfews (known as stay-at-home orders, shelter-in-place orders, or lockdowns). As of 12 April, nearly 300 million people, or about 90 per cent of the population, are under some form of lockdown in the United States, more than 50 million people are in lockdown in the Philippines, about 59 million people are in lockdown in South Africa, and 1.3 billion people are in lockdown in India. On 26 March, 1.7 billion people worldwide were under some form of lockdown, which increased to 3.9 billion people one week later – more than half of the world's population.

**1. Asia** - As of 16 April 2020, cases have been reported in all Asian countries except for Tajikistan and Turkmenistan, although some suspect such countries also have cases.

**2. Mainland China** - Wuhan Leishenshan Hospital, an emergency specialty field hospital built in response to the 2019–20 coronavirus pandemic. A temporary hospital for treating mild cases of COVID-19 in Wuhan, one of more

than 10 such hospitals in the city. The first confirmed case of COVID-19 has been traced back to 1 December 2019 in Wuhan one unconfirmed report suggests the earliest case was on 17 November. Doctor Zhang Jixian observed a cluster of pneumonia cases of unknown cause on 26 December, upon which her hospital informed Wuhan Jiangnan CDC on 27 December. Initial genetic testing of patient samples on 27 December 2019 indicated the presence of a SARS-like coronavirus. A public notice was released by Wuhan Municipal Health Commission on 31 December. The WHO was informed on the same day. As these notifications occurred, doctors in Wuhan were warned by police for "spreading rumours" about the outbreak. The Chinese National Health Commission initially claimed there was no "clear evidence" of human-to-human transmission.

**Effect of COVID-19 on Environment and climate** - The worldwide disruption caused by the coronavirus pandemic has resulted in numerous impacts on the environment and the climate. The severe decline in planned travel has caused many regions to experience a drop in air pollution. In China, lockdowns and other measures resulted in a 25 percent reduction in carbon emissions, which one Earth systems scientist estimated may have saved at least 77,000 lives over two months. However, the outbreak has also disrupted environmental diplomacy efforts, including causing the postponement of the 2020 United Nations Climate Change Conference, and the economic fallout from it is predicted to slow investment in green energy technologies.

#### **Effect of COVID-19 pandemic on Global Economy**

**UNITED NATIONS:** The global economy could shrink by up to 1% per cent in 2020 due to the coronavirus pandemic, a reversal from the previous forecast of 2.5 per cent growth, the UN has said, warning that it may contract even further if restrictions on the economic activities are extended without adequate fiscal responses. The analysis by the UN Department of Economic and Social Affairs (DESA) said the COVID-19 pandemic is disrupting global supply chains and international trade. With nearly 100 countries closing national borders during the past month, the movement of people and tourism flows have come to a screeching halt. "Millions of workers in these countries are facing the bleak prospect of losing their jobs. Governments are considering and rolling out large stimulus packages to avert a sharp downturn of their economies which could potentially plunge the global economy into a deep recession. In the worst-case scenario, the world economy could contract by 0.9 per cent in 2020," the DESA said, adding that the world economy had contracted by 1.7 per cent during the global financial crisis in 2009. It added that the contraction could be even higher if governments fail to provide income support and help boost consumer spending. The analysis noted that before the outbreak of the COVID-19, world output was expected to expand at a modest pace of 2.5 per cent in 2020, as reported in the World Economic Situation and Prospectus 2020. Taking into account rapidly changing

economic conditions, the UN DESA's World Economic Forecasting Model has estimated best and worst-case scenarios for global growth in 2020.

**INDIA**— The economic impact of the 2019–20 coronavirus pandemic in India has been hugely disruptive. World Bank and credit rating agencies have downgraded India's growth for fiscal year 2021 with the lowest figures India has seen in three decades since India's economic liberalization in the 1990s. However, the International Monetary Fund projection for India for the financial year 2021-22 of 1.9% GDP growth is the highest among G-20 nations. Within a month unemployment rose from 6.7% on 15 March to 26% on 19 April. During the lockdown, an estimated 14 crore (140 million) people lost employment. More than 45% of households across the nation have reported an income drop as compared to the previous year.

The Indian economy is expected to lose over 32,000 crore (US\$4.5 billion) every day during the first 21-days of complete lockdown which was declared following the coronavirus outbreak. Under complete lockdown less than a quarter of India's \$2.8 trillion economy is functional. Up to 53% of businesses in the country will be significantly affected. Supply chains have been put under stress with the lockdown restrictions in place; initially there was a lack of clarity in streamlining what is an "essential" and what isn't. Those in the informal sectors and daily wage groups are the most at risk. A large number of farmers around the country who grow perishables are also facing uncertainty. Various businesses such as hotels and airlines are cutting salaries and laying off employees. The live events industry has seen an estimated loss of 3,000 crore (US\$420 million).

Major companies in India such as Larsen and Toubro, Bharat Forge, UltraTech Cement, Grasim Industries, Aditya Birla Group, Tata Motors and Thermax have temporarily suspended or significantly reduced operations. iPhone producing companies in India have also suspended a majority of operations. Young startups have been impacted as funding has fallen. In the third week of March, Amazon and Walmart-owned Flipkart stopped sale of non-essential items in India so that it could focus on essential deliveries. Other fast-moving consumer goods companies in the country have significantly reduced operations and are focusing on essentials. Some defense deals have been affected/delayed due to the pandemic such as the delivery of Dassault Rafale fighter jets. Stock markets in India posted their worst losses in history on 23 March 2020. However, on 25 March, one day after a complete 21 day lockdown was announced by the Prime Minister, SENSEX and NIFTY posted their biggest gains in 11 years, adding a value of 4.7 lakh crore (US\$66 billion) crore to investor wealth.

The Government of India has announced a variety of measures to tackle the situation, from food security and extra funds for healthcare, to sector related incentives and tax deadline extensions. On 27 March the Reserve Bank of India also announced a number of measures which would

make available 374,000 crore (US\$52 billion) to the country's financial system. On 29 March the government allowed the movement of all essential as well as non-essential goods during the lockdown. On 1 April, World Bank approved \$1 bn in support to India to tackle the coronavirus pandemic. On 3 April the central government released more funds to the states for tackling the coronavirus totalling to 1 28,379 crore (US\$4.0 billion). On 6 April a 30% salary cut for one year was announced for the President, Prime Minister and Members of Parliament. On 14 April 2020, the Prime Minister of India extended the lockdown to 3 May. A new set of guidelines for the calibrated opening of the economy and relaxation of the lockdown were also set in place which will take effect from 20 April. On 17 April, the RBI Governor announced more measures to counter the economic impact of the pandemic including 50,000 crore (US\$7.0 billion) special finance to NABARD, SIDBI, and NHB. On 18 April, to protect Indian companies during the pandemic, the government changed India's foreign direct investment policy. The Department of Military Affairs has put on hold all capital acquisitions for the beginning of the financial year.

On 24 March the Press Information Bureau brought out a fact check that stories about a financial emergency being imposed in India are fake. A financial emergency has never been imposed in the history of India as yet. On 4 April, former RBI chief Raghuram Rajan said that the coronavirus pandemic in India may just be the "greatest emergency since Independence".

**Conclusions** - The relationship between a virus and its host is a complicated affair: a myriad of factors from the virus and the host are involved in viral infection and consequential pathogenesis. During viral infections, the host must respond to the virus by putting multiple lines of defence mechanisms in place. As intracellular obligate parasites, viruses have also evolved various strategies to hijack the host machineries. In this review, we first showed how viral factors could manipulate the host cell to expedite its own replication cycle and pathogenesis. We also highlighted how multiple cellular and viral factors come into play in their long-standing battle against one another. For years, HCoV have been identified as mild respiratory pathogens that affect the human population. However, it was the emergence of SARS-CoV that thrust these human viruses into the spotlight of the research field. Therefore, most of the HCoV research today is pertained towards SARS-CoV. While the recent MERS-CoV outbreak has been mostly limited to the Middle East region, it is likely that more emerging or re-emerging HCoVs might surface to threaten the global public health, as seen from the high mortality rates in the past two outbreaks: SARS-CoV (10%) and MERS-CoV (35%). Therefore, study of the pathogenesis of all HCoVs would gain more insights for the development of antiviral therapeutics and vaccines.

There are hundreds of coronaviruses, most of which circulate in animals. Only seven of these viruses infect

humans and four of them cause symptoms of the common cold. But, three times in the last 20 years, a coronavirus has jumped from animals to humans to cause severe disease. SARS, a beta coronavirus emerged in 2002 and was controlled mainly by aggressive public health measures. There have been no new cases since 2004. MERS emerged in 2012, still exists in camels, and can infect people who have close contact with them. COVID-19, a new and sometimes deadly respiratory illness that is believed to have originated in a live animal market in China, has spread rapidly throughout that country and the world. The new coronavirus was first detected in Wuhan, China in December 2019. Tens of thousands of people were infected in China, with the virus spreading easily from person-to-person in many parts of that country.

The novel coronavirus infections were at first associated with travel from Wuhan, but the virus has now established itself in over 177 countries and territories around the world in a rapidly expanding pandemic. Health officials in the United States and around the world are working to contain the spread of the virus through public health measures such as social distancing, contact tracing, testing, quarantines and travel restrictions. Scientists are working to find medications to treat the disease and to develop a vaccine. The World Health Organization declared the novel coronavirus outbreak "a public health emergency of international concern" on January 30. On March 11, 2020 after sustained spread of the disease outside of China, the World Health Organization declared the COVID-19 epidemic a pandemic. Public health measures like ones implemented in China and now around the world, will hopefully blunt the spread of the virus while treatments and a vaccine are developed to stop it.

#### References :-

1. Arbour, N.; Day, R.; Newcombe, J.; Talbot, P.J. Neuroinvasion by Human Respiratory Coronaviruses. *J. Virol.* 2000, *74*, 8913–8921. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
2. CDC (2019-08-02). "MERS Transmission". Centers for Disease Control and Prevention. Archived from the original on 2019-12-07. Retrieved 2019-12-10.
3. Fehr AR, Perlman S (2015), Maier HJ, Bickerton E, Britton P (eds.), "Coronaviruses: An Overview of Their Replication and Pathogenesis; Section 4.1 Attachment and Entry", *Coronaviruses: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology*, Springer, 1282, pp. 1–23, doi:10.1007/978-1-4939-2438-7\_1, ISBN 978-1-4939-2438-7
4. Gorse, G.J.; O'Connor, T.Z.; Hall, S.L.; Vitale, J.N.; Nichol, K.L. Human Coronavirus and Acute Respiratory Illness in Older Adults with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. *J. Infect. Dis.* 2009, *199*, 847–857. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
5. Jacomy, H.; Frago, G.; Almazan, G.; Mushynski, W.E.; Talbot, P.J. Human coronavirus OC43 infection induces chronic encephalitis leading to disabilities in



- BALB/C mice. *Virology* 2006, 349, 335–346. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
6. Jones, B.A.; Grace, D.; Kock, R.; Alonso, S.; Rushton, J.; Said, M.Y.; McKeever, D.; Mutua, F.; Young, J.; McDermott, J.; et al. Zoonosis emergence linked to agricultural intensification and environmental change. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 2013, 21, 8399–8340. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
7. Kahn, Jeffrey; McIntosh, Kenneth (November 2005), "History and recent advances in coronavirus discovery", *Pediatric Infectious Disease Journal*, 24 (11):223–227, doi:10.1097/01.inf.0000188166.17324.60, archived from the original on 2020-02-05.
8. Kelland K (2012-09-28). "New virus not spreading easily between people: WHO". Reuters. Archived from the original on 2012-11-24. Retrieved 2013-03-16.
9. "Laboratory testing of human suspected cases of novel coronavirus (nCoV) infection. Interim guidance, 10 January 2020" (PDF). Archived (PDF) from the original on 2020-01-20. Retrieved 2020-01-14.
10. "Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)". WHO. Archived from the original on 2019-10-18. Retrieved 2019-12-10.
11. Neuman BW, Kiss G, Kunding AH, Bhella D, Baksh MF, Connelly S, et al. (April 2011). "A structural analysis of M protein in coronavirus assembly and morphology". *Journal of Structural Biology*. 174 (1):11–22.
12. "New SARS-like virus found in Middle East". Al-Jazeera. 2012-09-24. Archived from the original on 2013-03-09. Retrieved 2013-03-16.
13. Nouveau coronavirus—Point de situation : Un nouveau cas d'infection confirmé Archived 8 June 2013 at the Wayback Machine (Novel coronavirus—Status report: A new case of confirmed infection 12 May 2013.
14. "Novel Coronavirus 2019, Wuhan, China | CDC". www.cdc.gov. 2020-01-23. Archived from the original on 2020-01-20. Retrieved 2020-01-23.
15. "Novel coronavirus infection—update". World Health Association. 2013-05-22. Archived from the original on 2013-06-07. Retrieved 2013-05-23.
16. Pene, F.; Merlat, A.; Vabret, A.; Rozenberg, F.; Buzyn, A.; Dreyfus, F.; Cariou, A.; Freymuth, F.; Lebon, P. Coronavirus 229E-Related Pneumonia in Immunocompromised Patients. *Clin. Infect. Dis.* 2003, 37, 929–932. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
17. Sang-Hun C (2015-06-08). "MERS Virus's Path: One Man, Many South Korean Hospitals". The New York Times. Archived from the original on 2017-07-15. Retrieved 2017-03-01.
18. Simmons G, Zmora P, Gierer S, Heurich A, Pöhlmann S (December 2013). "Proteolytic activation of the SARS-coronavirus spike protein: cutting enzymes at the cutting edge of antiviral research". *Antiviral Research*. 100 (3): 605–14.
19. Snijder EJ, Bredenbeek PJ, Dobbe JC, Thiel V, Ziebuhr J, Poon LL, et al. (August 2003). "Unique and conserved features of genome and proteome of SARS-coronavirus, an early split-off from the coronavirus group 2 lineage". *Journal of Molecular Biology*. 331 (5): 991–1004. doi:10.1016/S0022-2836(03)00865-9. PMID 12927536.
20. Vabret, A.; Mourez, T.; Gouarin, S.; Petitjean, J.; Freymuth, F. An Outbreak of Coronavirus OC43 Respiratory Infection in Normandy, France. *Clin. Infect. Dis.* 2003, 36, 985–989. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
21. Van der Hoek, L. Human coronaviruses: What do they cause? *Antivir. Ther.* 2007, 12, 651–658. [Google Scholar] [PubMed]
22. Vijgen, L.; Keyaerts, E.; Moës, E.; Maes, P.; Duse, G.; van Ranst, M. Development of One-Step, Real-Time, Quantitative Reverse Transcriptase PCR Assays for Absolute Quantitation of Human Coronaviruses OC43 and 229E. *J. Clin. Microbiol.* 2005, 43, 5452–5456. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
23. "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). March 2019. Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2020-01-24.
24. Walsh 2007, E.E.; Shin, J.H.; Falsey, A.R. Clinical Impact of Human Coronaviruses 229E and OC43 Infection in Diverse Adult Populations. *J. Infect. Dis.* 2013, 208, 1634–1642. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
25. "WHO Statement Regarding Cluster of Pneumonia Cases in Wuhan, China". www.who.int. 2020-01-09. Archived from the original on 2020-01-14. Retrieved 2020-01-10.

\*\*\*\*\*



# Assessment of ground water quality of Taloja Industrial Area of Raigad District (Maharashtra)

Dr. A.N. Thakkar\*

**Abstract** - The present research study was focused to evaluate the physico-chemical characteristics of ground water at Taloja industrial area of Raigad District (Maharashtra). The ground water samples were collected from ten sampling sites, of which three from residential area, three from market area, two from agricultural area and two from solid waste dumping sites. The analysis of ground water samples was done by using the procedure of standard methods (APHA, 1995). The findings of present investigations were compared with standards for drinking water (BIS, 1998). Present research findings revealed that values of several parameters cross their permissible as well as excessive limits and pointing out to the necessity of proper treatment before disposal of municipal waste, industrial waste and domestic waste in the study area.

**Keywords** - Ground water quality assessment, Taloja.

**Introduction** - Water is a greatest natural resource, which is essential to all forms of life. Nothing could survive on earth without water conservation and keeping up of the good quality of water area prime importance, since water is a natural resource "limited" in a sense. Man has polluted much of this limited quantity of water by sewage, industrial wastes and wide array of synthetic chemicals. Pollution of fresh water is one of the most serious environmental problem in India. In India about 12% of people get clean drinking water, the rest 88% quench their thirst from polluted water. The piped water which is available in cities, is mixed with number of impurities causing jaundice, cholera, typhoid and gastroenteritis<sup>[1]</sup>. Sometimes in cities the less dose of bleaching powder invites some diseases due to non-oxidation of the essential constituents of the bacterial cell while excess bleaching powder may cause lung diseases and dysentery. Improper dumping of sewage effluents and industrial effluents are very serious problem, causing pollution in ground water. Besides industrial wastes, the use of pesticides like D.D.T. has posed a serious water pollution problem and a potential hazard to human beings and other animals.

## Material and Methods

**Collection of Samples** - Sampling of ground water was done during December 2019. High grade plastic bottles of one litre capacity were used, which were thoroughly cleaned prior to filling, were rinsed with the water being sampled. Ten samples were collected from public hand pumps after running from 15 to 20 minutes, so as to avoid errors due to water contained within the pipes.

**Analysis of Samples** - For the analysis of water sample using procedure of standard methods<sup>[2]</sup> and to analyze the

water samples, which are very essential to know the water quality for drinking purpose. The findings of the present investigations are summarized in Table-1 and it has been made with<sup>[3]</sup> drinking water standards in Table-2, which provides comprehensive picture of physicochemical characteristics of ground water in the study area.

The parameters like pH, Electrical conductivity and Total Dissolved Solids were measured in the field at the time of sample collection, using water analysis kit (ELICO). Turbidity of water samples were measured using Nephelometer. Total hardness, Calcium, Magnesium and Alkalinity by the titrimetric method, Thus, Sulphate and Phosphate by Spectrophotometric method.

**Observation and Discussion** - The total of Eight numbers of water samples were taken from different locations of Taloja industrial area. Two samples were taken from residential area (S1, S2); Two samples were taken from market area (S3, S4), Two each from agricultural fields (S5 and S6) and Two solid waste dumping sites (S7 and S8).

## Table 1 & 2 (see in last page)

The pH values of ground water of the study area are in between 6.9 to 7.4 and are well within the permissible limits prescribed for drinking water standards. However, higher values of pH hasten the scale formation in water heating apparatus and reduce the germicidal potential of chlorine<sup>[4]</sup>.

The values of **Electrical Conductivity** of the samples were observed and recorded as 840 to 1720  $\mu\text{mhos/cm}$ . It also shows that all the water samples collected for present observation fall well within the excessive limit (750-2000  $\mu\text{mhos/cm}$ ). It is indicating high mineralization in that area and also the presence of higher concentration of acid, base

\*Department of Zoology, Veer Wajekar A.S.C.College, Phunde (Maharashtra) INDIA

and salts in water, higher will be the electrical conductivity<sup>[5]</sup>. The values of **Total Dissolved Solids** of the ground water samples of the study area are in between the 510 to 1310 mg/l. These two sampling stations are at the solid municipal dumping area. Here the local municipal authority adopted a common method for the disposal of solid municipal wastes by deposition on land. During percolation process, leachates from solid waste dumping sites may reach the ground water table and alters the quality of the water. The amount of dissolved solids increase with the depth and with time and distance, the water has traveled in the ground<sup>[6]</sup>. Landfills can be any area of land used for the deposition of mainly solid wastes and they constitute important potential sources of ground water pollution. It is also reported that the ground water pollution from refuse leaches in the vicinity of dumping sites detectable through increased TDS of water<sup>[7]</sup>.

In the present study the values of **Turbidity** varies from 2.8 to 19.2 NTU. Here all water samples are well within the desirable limit. Generally ground water is less turbid since sand is a good filtering media. If an aquifer receives a leachate from the domestic solid waste and industrial waste water points which may result in increasing turbidity in ground water<sup>[8]</sup>.

The values of **Total Hardness** varies from 490 to 890 mg/l,.

The values of **Calcium** varies from 78.4 to 154.2 mg/l and it shows the all samples are well within the desirable limit prescribed for drinking water quality standards.

The values of **Magnesium** ranges between 80.2 to 171.6 mg/l, and are well within the desirable limit of ground water standards (150 mg/l).

The more amount of total hardness, and magnesium contents are may be due to the ground water of the region presenting the low natural quality, in other words depth of the well and the nature of the geological materials with which the ground water comes in contact may influences the quality of water.

The ground water chemistry is controlled by the composition of its recharge components as well as by geological and hydrological variations. The hard water causes a toughening of some vegetables, notably beans and peas and in textile finishing. However, excess amount of total hardness, calcium, magnesium accounts on scale formation in boilers, pipelines, utensils and consume more detergents in washing process.

The values of **Alkalinity** ranges between 226 to 560 mg/l. All samples were found to be well within the desirable limit. When alkalinity of water exceeds the excessive limit, it is likely to produce incrustation sediment deposits, difficulties in chlorination, certain physiological effects on human systems etc.

The **Chloride** levels are found to be 112 to 680 mg/l. Here all samples were well within the desirable limit except the 2 samples S9 and S10. These sampling stations are to be located on the solid waste dumping sites. The contamination of chloride in ground water is usually

attributed to improper dumping of municipal excreta particularly urine contain chloride in an amount about equal to the chloride consumed with food and water. Chloride in excess imparts the salty taste to water and people are not accustomed to high chloride are subjected to laxative effect<sup>[9]</sup>.

The present investigation data reveals for **Sulphate** values ranging between 66 to 186 mg/l, which were well within the permissible limit for drinking water standards. Sulphate in ground water takes place the breakdown of organic substances in the soil. However, geological, hydrological and geomorphologic characteristics show remarkable variations and also the human influences<sup>[10]</sup>.

The **Phosphorus** is also an essential elements for sustained primary productivity in the ecosystem. The form of phosphorus discussed is ortho-phosphate. The amount of phosphorus in natural water is very low. Domestic wastes, industrial effluent and agricultural runoff is major sources of phosphorus in water. Hence its high concentration is indicative of pollution. In the present study the value of phosphate varies from 0.14 to 0.24 mg/l, which were well within the permissible limit for drinking water standards.

**Conclusion** - Present investigation is a step in the direction to observe the size and extent of the problem of ground water quality in Taloja Industrial Area of Raigad District (Maharashtra). The reason for higher values of physico-chemical parameters at certain sampling locations is due to unscientific disposal of urban solid wastes and landfill. Here the leachate percolates through solid wastes and contaminates the ground water. The depth of well and nature of the geological materials which comes in contact may also influence the quality of the water. Concerned with the study area, there is no proper drainage system and due to a regular addition of large amount of sewage and detergents from the residential localities and market area, the water quality is getting from bad to worse.

These contain both sanitary and non-sanitary components. It can be concluded that the ground water of study area in some localities like agricultural area and solid waste dumping sites are not suitable for drinking purpose. The need of a suitable dumping site and the proper management of solid waste in this area is suggested on the basis of present study and pointing out the necessity of proper treatment of ground water before use as drinking water.

#### References :-

1. Alexander M. Introduction to soil microbiology, Wiley, New York-London, 1961, 472.
2. APHA. Standard methods for the examination of water and waste water, 18th Edn. AWWA, WPCF, New York, 1995.
3. BIS. Specifications for drinking water, New Delhi, 1998, 171-178.
4. Knight AB. The photometric estimation of colour in turbid waters, Journal Institution of Water Engineering

- 1951; 5: 623.
5. Everett LG. Groundwater monitoring general electric company Schenectady, New York, 1980, 440.
6. Mohapatra TK, Purohit KM. Qualitative aspects of surface and groundwater for drinking purpose. Ecology of Polluted Water 2000; 1:144.
7. Naqvi SM. Geochemistry of gneisses from Hassan district and adjoining areas, Karnataka, India. In: Naqvi, S.M. and J.J.W. Rogers (eds), Precambrian of South India. Geological Society of India, Memo 1983; 4:401-416.
8. Narayana AC, Suresh GC. Chemical quality of Ground water of Manglore city, Karnataka, Indian Journal Environmental Health 1989; 31:228-236.
9. Ramaswamy V, Rajaguru P. Groundwater quality of Tiruppur, Indian Journal Environmental Health 1991; 33(2):187-1991.
10. Swaminath J, Ramakrishnan. In: Swaminath, J. and M. Ramakrishnan (ed.) Early precambrian supracrustals of South India, Geol. Surv, Ind Mem 1981; 3:23-38

**Table 1:** Physico-chemical characteristic data of Ground water of Taloja industrial area of Raigad District (Maharashtra)

Sr.	Physico-chemical Parameters	Sample Numbers							
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
1	pH	6.9	6.9	7.0	7.0	7.2	7.3	7.4	7.4
2	EC	920	840	1270	1210	1630	1720	1330	1420
3	TDS	730	510	780	760	810	790	1230	1310
4	Turbidity	2.8	2.6	3.7	5.8	6.0	9.6	16.6	19.2
5	TH	510	490	760	780	650	880	790	890
6	Ca <sup>2+</sup>	80.2	68.4	88.4	154.2	111.4	86.3	116.4	130.2
7	Mg <sup>2+</sup>	92.6	80.2	128.2	171.6	89.4	122.4	118.6	133.2
8	Alkalinity	330	370	226	236	326	460	490	560
9	Cl <sup>-</sup>	120	112	132	170	570	568	674	680
10	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	36	47	92	87	80	134	162	186
11	PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	0.14	0.15	0.16	0.18	0.17	0.19	0.22	0.24

**Note:** All the parameters are expressed in mg/l, except pH, Electrical conductivity (µmhos/cm.) and Turbidity (NTU).

**Table 2:** Comparison of Ground water quality data with drinking water standards (BIS, 1998)

Sr.	Physico-chemical Parameters	BIS, 1998		Observed Values	
		Permissible limit	Excessive limit	Range	Mean ± SD
1	pH	6.5 – 8.5	<6.5 - >8.5	6.9 – 7.4	7.1 ± 0.20
2	Electrical Conductivity	750	2000	840 - 1720	1293 ± 288
3	TDS	500	1000	510 - 1310	865 ± 251
4	Turbidity	5	25	2.8 – 19.2	8.28 ± 5.96
5	Total Hardness	100	600	490 – 890	719 ± 144
6	Calcium	75	200	78.4 – 154.2	104 ± 27
7	Magnesium	500	100	80.2 – 171.6	117 ± 28
8	Alkalinity	200	600	226 – 560	374 ± 112
9	Chloride	200	600	112 – 680	378 ± 248
10	Sulphate	200	400	66 - 186	103 ± 50
11	Phosphate	0.25	0.40	0.14 – 0.24	0.18 ± .032

\*\*\*\*\*

# Covid-19: A Challenge For Education System Or A Boon For E-Learning?

Dr. Vandana Sharma\*

**Abstract** - As the planet suffers with the Covid-19 pandemic, the industries start searching for alternatives to get life back on the track. This search for an alternative in the education system has ended with the contemplation of online teaching. E-learning has come up as a godsend in this pandemic, but it has also attracted a number of criticisms ranging from the lack of trained teachers to ineffectiveness, from infrastructural issues to harmful effects on health, from disinterest among students to what not. But criticizing hundred things is much easier than appreciating a single one, isn't it?

Our education system though very fundamental in its nature and seemingly flawless in its approach shall also adapt according to the need of the hour. This search for disseminating knowledge had ended with the contemplation of online learning. E-learning though has emerged as a perquisite in the reign of this rampant virus, it has also attracted a number of criticisms. Some people even labelled it as a "health hazard". Though some of these critiques account for equivalent relevance, but even the fact that the globe is not under a normal circumstance is also pertinent. And E-learning is the need of the hour. Covid-19 can force schools, colleges and universities to close their gates, but the process of learning shall not stop. E-learning may be called as an entirely flawed concept, but we don't have any alternative. we may call upon the betterment of this teaching concept. Practically no concept in our generation is flawless. Having corrupt politicians and sinful policy makers doesn't mean that we stop believing in our democracy. Similarly E-learning is a new concept, but that doesn't mean we shall give up entirely. Online teaching is the future and it is the time to adapt it, practice it and groom it not only as an alternative but as a substitute for the conventional learning process. For we stand in the Era of change, we are here to witness a transition, a technical revolution and we must welcome it with open arms.

Even before this crisis online learning was popular due to its flexibility and cost efficiency. A study reveals that online graduates on an average earn up to 84,000 \$ in the U.S. alone annually and 29 percent can earn between 85,000 – 1,50,000\$ providing proves for the credibility of E-learning.

My aim and objective in the proposed paper is to present the pros and cons of E-learning. I will try to show the future prospects of E-learning and find out the new possibilities in the field. I am going to discuss the obstacles in the way of E-learning, especially in a developing country like ours and how to overcome its flaws.

**Keywords** - Covid-19, pandemic, E-learning, education system, technical revolution, cost – efficiency, flexibility, infrastructure, comprehension, convenience.

**Introduction** - As corona virus continues its march around the world, our future is still into the grips of a substantial uncertainty. The Covid-19 pandemic is a health crisis of colossal proportion. Our fast paced lives have come to a standstill. As the government force social distancing and nation wide lockdown, apparently everything marks the beginning of a new era.

**In December 2002, the government of India through its 86<sup>th</sup> amendment of the constitution declared for free and compulsory education as a fundamental right to all children in the age group of 6-14 years.**

Thus, our constitution recognizes education as a fundamental right and guarantees it to every citizen of our nation. The Covid-19 pandemic posed as a major challenge

for our education system. Though everyone is looking forward with keen eyes towards the government for relief and lifting of this lockdown. But even after lockdown is over and we are free to move out of our homes, the policy makers may not entertain mass gatherings or communal meetings in the forthcoming years. Thus, it's almost certain that educational campuses will not be fully populated any time soon.

E-learning has appeared to us as a boon in this time of crisis. Online education allows us to access various courses and educational programs from the safety of our homes. Online education allows students, from working professionals to recent graduates to learn with a more flexible and time efficient approach. It has numerous

\* Assistant Professor (Deptt. Of Eng.) J.K.P.(P.G.) College, Muzaffernagar (U.P.) INDIA



benefits from convenience of students to lower costs. Our conventional teaching system forces the students to show up in class at a particular time, sit through a lengthy lecture and following the same routine for the next class. This can be a grind for some students. In addition to this college education is very high priced. Not every student can afford the college fees, hostel fees and meal charges. Online education provides an easy gateway for all these expenses. Students can even juggle between their respective jobs and further studies. Because they are not tied down to a fixed schedule, like the conventional methods of teaching.

**“Online learning is rapidly becoming one of the most costeffective way to educate world’s rapidly expanding workforce”.**(Jack Messman, Cambridge technology partners)

Various E-learning platforms allows students to choose from a wide array of courses, let it be algebra, language composition or fine arts. Students can even study new subjects like entrepreneurship and human sociology.

Upskilling is the latest trend among MNCs. It refers to the need for the people to take their existing skills and upgrade them in order to perform better in current roles or to gain more potential for promotions. Upskilling is not possible in the traditional world of education involving campuses and universities. E-learning not only welcomes fresh students but also trained professionals who are looking to upskill themselves.

Our education system, involving physical interactions between the students and their teachers, though very fundamental in its behavior, is very rudimentary in its nature. Education in our country not only involves pre-defined courses and some selected text-books, it covers a wide range of personality development and human interactions. Learning involves acquisition of given knowledge didactically by a teacher or a professor. Courses particularly at under-graduate levels are largely course defined and textbook oriented i.e. they are relatively stable bodies, and it is somewhat possible based on the texts and predefined syllabus but this cannot be achieved for further courses. Higher education involves development as an individual rather than development as a student. It involves development of analytical and social skills. Our education system as at imparting knowledge at under-graduate levels whereas the aim at higher levels of education is to critically deconstruct and comprehend the imparted knowledge. The process of learning is not confined to a textbook or a syllabus, but it is the amalgamation of practical skills, comprehension and critiquing the knowledge. Learning even happens through osmosis in the atmosphere.

In a country like India where teachers are referred as “Gurus” and viewed as role models, the word “education” has a wider perspective. It necessarily emphasizes on the process of learning through interactions between the students and their teachers. Critiquing the imparted knowledge in seclusion is never as dynamic as doing it in a group. Students not only learn from their teachers but also

from other fellow students. Building this on a digital platform is not an easy job and it cannot suffice in a country like ours where many struggle for livelihood against the backdrop of an underdeveloped nation. Online courses appear beneficial only for the connected. Only a privileged section of society can go for these online classes. As only those who have a smartphone or a computer with a strong internet connection can be actually benefitted with these online methods of teaching. Only some schools are well equipped with smart classrooms. It would be very depressing if some students are deprived of their fundamental right to education just because they don’t have access to a smartphone or a computer. Won’t that be called discrimination? How could a classroom be limited to only to a particular section of society? Given in our country every child and every student cannot afford a smartphone.

**“More than 90% of the ed-tech products in the market are build with the middle and higher income families in mind. So even if those products are being made available for free during lockdown, they are not contextualized for a poorer or a rural audience. For example if you explain fractions using the slices of a pizza, that is simply not accessible for those who have never eaten pizza.”**(GouriGupta,CSF Director)

Internet connection is still an issue in many parts of our country. Lagging infrastructure poses as a major problem in front of the E-learning methodology. Teachers still not familiar with the new apps and technologies find it difficult to give their best in these “virtual classes”. Only a section of educators who are comfortable with the upcoming technologies are able to conduct these classes efficiently. Teachers in the villages and outskirts areas find it hard to get stable internet access to carry out these lessons. While those in urban areas are battling with disinterest among students as students find E-classes less interactive and boring. Moreover teachers also face lack of support from parents and other challenges of a non-conductive learning environment. It also poses us the potential risk of isolation. Students are cut-off from their peers thus making them vulnerable to the risk of depression and seclusion. There is no direct sharing of knowledge in the methodology of online teaching. And while going for the flexibility and compressive nature of online teaching, we cannot deny it’s adverse effects on the health of the students. Conventional teaching system not only equipped us with a routine, but also incorporated physical activities in our way of life. There is no school or college without a sports ground. Now confined to the computer screen, the classroom is a threat to the health of its pupils. Obesity will be on a rise, and continuous glaring at the screen will lead to eye-sight issues among students. In spite of strenuous attempts of the teachers to engage their students in these virtual classrooms, lack of interest prevail as a major drawback.

**“Technology-driven education to be the focus PM eVIDYA program for multimode access to digital or online education to be launched immediately. Top 100**

**universities will be permitted to automatically start online courses by 30<sup>th</sup> May, 2020. “Manodarpan”, an initiative for psychological support of students, teachers and families for mental health and emotional well-being.”.** (Nirmala Sitharaman, Minister of Finance of India)

Online learning maybe the future of imparting education. But the shift from traditional to modern methods should have been a very gradual process, it cannot be effectively achieved by a sudden shift. Though the government is making attempts to conduct classes via television, this online teaching concept cannot fully replace the conventional methodology of teaching yet.

Online teaching maybe an entirely flawed concept. But do we have any alternative ways to keep up in this global pandemic? Thus, it's high time for us to adapt to this new era of teaching and to groom it as the future of learning. Covid-19 can force shut the gates of colleges and universities but the process of learning shall not stop.

**“The students of the future will demand the learning support that is appropriate for their situation or context. Nothing more, nothing less. Mobile devices will be a key technology to provide that learning support.”** (Dr. Marcus Specht, Professor of Advanced

Learning University of Netherlands)

Online learning will be the turning point in the field of education. There maybe many questions on these subject. Like when will be able to completely adapt it? Who will be the teachers in this paradigm? Where will the physical touch points be in this system? What would be the subjects that are going to be taught? This is an inflection point for higher education and we should collectively imagine it.

**“ Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.”** (Albert Einstein)

#### References :-

1. The Hindu (29 April, 2020)
2. The Hindu (23 April, 2020)
3. Times Of India (24 April, 2020)
4. The Financial Express ( 17 May, 2020)
5. Constitution of India
6. Specht, Professor Marcus, Open Universiteit, Netherlands, September 8 2009, Science news
7. Sitharaman, Nirmala, Finance Minister, News Express, May 17 2020.
8. Gupta, Gouri, Central Square Foundation, The Hindu, April 24 2020.
9. Messman, Jack, Cambridge Technology Partners, Higher Education Review, May 2020.

\*\*\*\*\*

## K.A. Abbas's Cosmic Approach : Transcending Parochialism

Dr. Shefali Jain\*

**Abstract** - Khawaja Ahmad Abbas, founder of IPTA, (Indian People's Theatre Association), leader of many delegations, director, film producer, writer, is an unexplored island in the world of Indian writing in English. He has written more than seventy books, twelve novels and six collections of short stories and thirteen outstanding films which were praised worldwide for their thematic and artistic sophistication. But his real talent manifested itself in his 'Last Page' in the Blitz as a journalist. While other writers were addressing their work to, education and sophisticated readers he spent his life trying to reach the mass, more or less uneducated, Dalits, downtrodden and untouchables. Abbas traveled round the world as a messenger of universal brotherhood, conveyed the message of love, peace and humanity, Pt. Jawaharlal Nehru once said about him that Khawaja Ahmad Abbas remained an omnibus personality of Indian journalism as well as literature and films.

His infinite sympathy, compassion for underdogs, the exploited and the unprivileged and his belief in sacularism, is producing a strong feeling to unravel this island, who himself named his autobiography 'I Am Not An Island' as he has become the need of the hour.

Man's success, his desire to touch the horizon, exploration of new skies, transcended him from spirituality to materialism, from cosmic to parochialism left no one untouched with this changing phenomena. Abbas who was not fed up on books for knowledge, had great vision of life and faith in humanity, he transcends Parochialism through his novels. So the purpose of this piece writing is to trace out Abbas as a man of religion and a philanthropist who discriminates cast and creed and takes man as the centre of all religion. He endeavoured to transcend from the trifle to cosmic, in an attempt to live a loftier life full of high values of philanthropist. He projects his vision through Rajoo and Mary (main figures in *Mera Naam Joker*, one of his novels) who had no prejudice against poverty and believes in the message of Jesus Christ. Rajoo is presented with a huge heart in which, he is ready to accommodate the whole world. Abbas wanted to convey to the people of the world to go beyond this narrow outlook.

**Keywords** - IPTA, underdogs, unprivileged transcended, cosmic, parochialism, philanthropist, communism.

**Introduction** - "For what shall profit a man if he shall gain the whole world and lose his soul."<sup>1</sup>

-Eugene O'Neil

"Most modern plays are concerned with the relation between man and man; but that does not interest at all. I am only interested in the relationship between man and God... The playwright must dig at the roots of the sickness of today as he feels it... The death of the old God and the failure of the science and materialism to give any satisfying new one for the surviving primitive religious instinct to find a meaning for life in, and comfort its fears of death."<sup>2</sup>

The novel is not the vehicle of presenting directly philosophy or moral preaching or the writer's doctrinaire opinions. In place of it the novel should be used, brooding on human destiny and exhorting men and women to seek personal salvation. In short, he opines that novel should not be an exposition of same system of philosophy; rather it should portray the wisdom of the heart, the heart which is

same in all over the world while writing about humanism a writer does not deal with the human being of his country but of the world. This is known '**cosmic approach**'.

So the purpose of this paper is to present K.A. Abbas's zeal for self sacrifice, his concern with humanity, his efforts to **transcend** the **parochialism**, his decision that humanity should come out of the narrow boundaries of castes, makes him a cosmopolitan personality. This cosmic approach has been clearly visible in his novels *Mera Naam Joker*, *Maria*, *Inquilab* and *The Walls of Glass*.

Abbas has a broader outlook and makes his characters able to rise from their personal and pretty interests to the humanity. He has endeavoured to transcend from the trifles to cosmic in an attempt to enable them to live a loftier life full of high values of philanthropist.

In *Mera Naam Joker*, Rajoo is an embodiment of Abbas's cosmic philosophy. He faces the harsh blows and buffets of life but puts on a smiling face of a Joker, though his heart bleeds inside, to make the world happy. Ahmad

Hasib writes :

**“He was a joker par excellence laughter was his hobby, his way of life, his profession. Even when he wept bitterly people roared with laughter, thinking this to be another of his prank.”<sup>3</sup>**

This novel is not primarily concerned with social and economic problems but Abbas shows his sympathy and kindness for the humanity and emphasises, in a pessimistic vein, the irony of circumstances which is same with all the human beings in the world. Here Abbas resembles with Hardy :

**And indeed it is significant that Hardy- as a rule- emphasises the fact that even those characters the world call wicked, are so much the creatures of circumstances that they are far more to be pitied than to be blamed.<sup>4</sup>**

The novel presents Abbas's broad vision that man should be considered in term of man. Abbas projects his vision through Mary, who had no prejudices against poverty and believed in the message of Jesus Christ. She gave full recognition to the common humanity. When Raju sings, '*Jeena Yahaan Marna Yahaan...*' She says :

“Rajoo this is a beautiful tune, but the song is too pessimistic for a young man like you who is standing on the threshold of his life.” With the help of her teaching, guidance and motivation Rajoo lifts himself and out of sorrow, creates happiness for the world. Standing in the arena of circus, he was laughing and the world laughed with him. It seemed as if he had discovered the great secret that **“Life was a huge joke, a game of alternating Light and Darkness, Day and Night, Happiness and Sorrow. Who was playing this game- and why ? Even the wise ones had not been able to find the answer.”<sup>5</sup>** In this novel, Abbas gives the message to the world, that one should live life in its entirety as there is no option too.

This is the reason that this novel gain popularity not only in India but the whole world appreciated it for its cosmic theme. Abbas wants to convey here that day by day as man is getting the resources to know the whole world but his heart is shrinking for humanity. When Rajoo was in need of operation, the surgeon was asked, “But will the operation save him ?” “Absolutely not”, replied the doctor. Abbas criticises “the doctor will get their fees, whether the patient lives or dies”. Then the doctors get ready to do it because : It's not merely the fees, but we will have a chance to see a big heart. Otherwise these days whenever you open a man's chest, you take out a sparrow's heart.

Here we find that Abbas not only wants the Indians but the whole world to come closer and in this way he made Rajoo the universal joker, an immortal figure who laughed and lived for others only. In his novel *Inqilab* Abbas presents Anwar as '*Human Sangam*', in whom diverse streams have met. He like Rajoo rises above the personal to the cosmic. *Inqilab* has been, perhaps, the best novel of Abbas, the autobiographical one as well, the novelist like, in his autobiography, involves Anwar in mankind neglecting all

prejudices as national , religious, and casteism. Abbas illustrates the ideal of universal brotherhood through Anwar Ali, Robert Mill and J. L. Nehru. Robert says :

**Leave the leaders alone. There are dozens of correspondence to report their speeches. Let's study the people.<sup>6</sup>**

Ahmad Hasib writes :

**The novel is lit up with a set of values : hope, noble aspirations, perseverance dramatizes the ups and downs in friendly and patriotic sentiments and suggests certain desirable values in the face of current parochial tendencies.<sup>7</sup>**

Anwar Ali to whom Abbas has presented in this novel as he himself does not believes and differentiate Hindu and Muslim. He says that they both share the same blood. The discovery of the secret of his birth aroused in him, with still greater strength, a longing for not reckoning with the religious differences, a longing for the friendship of people of all nationalities and religions. Here we find cosmic approach : **“Could it be that he (Anwar) who by birth was neither a Hindu nor wholly a Muslim or , rather, who was both, an oddly symbolic son of India, was in a particularly advantageous position both the communities.”<sup>8</sup>**

Abbas like Mahatma Gandhi favours and believes in the universal phenomena of humanity. In *The World Is My Village* Mahatma Gandhi says “I will go ahead not for India's sake alone but for the whole world.” It is India and these Indian writers and philosophers like K.A Abbas, J.L. Nehru, Mahatma Gandhi who taught the world the lesson of non-violence. Abbas was against the weapons which are harmful for both, the one who use it and other who is victim of it. In his book *I Write as I Feel* Abbas writes :

**“If some one kills two of your tribes, then you kill ten of his tribe, so he kills a hundred of your tribe, and you retaliate by killing a thousand of his tribe ... and so it goes on. If your enemy invents a rifle, you invent a bomb, then he invents a submarine, so you invent a bomber; he sends a robot bomb and you retaliate with an atomic bomb ... and so it goes on! And WILL go on unless something is done to break this vicious circle of violence begetting greater violence, which is steadily narrowing down to an inevitable doom.”<sup>9</sup>**

Having been inspired by a zeal to provide a better life to man Abbas stresses through *Blitz* and in his novels that the feeling of killing, revenge, narrow parochialism prevent man from thinking of high goals and grand values of life. Abbas was the man of religion. His works advocate the duty of a man for man irrespective of their caste or community. The reason of it is perhaps Abbas visited the whole world, listened to the music of Bade Ghulam Ali Khan, Onkarnath Thakur, heard Josh and Nirala and Evteshenko and Faiz reciting their poetry, beauty of man and beauty created by man, seen the Taj and Ajanta as also the Acropolis and the Parthenon, serene face of Buddha and sad smile of the Mona Lisa. He has suffered with Christ



and laughed at Charlie Chaplin's comic tramp, all these things broaden his point of view and made him able to think from personal to cosmic point of views :

**All this I have witnessed, observed, experienced, felt, all this is within me, a part of me and I am a part of all that I have observed, experienced, felt! The world has made me and I have made the world (at least two thousand million part of it), I am involved in humanity even as humanity is involved in me, as the seed is born of the tree, and tree is the offspring of the seed.**<sup>10</sup>

All art is propaganda. The art of Ajanta is propaganda for Buddhism. The art of Ellora is propaganda for Hinduism. The art of the western novel is propaganda for humanity against the bourgeoisie. Gorky as a humanist dared to speak of man, man's condition not to say how awful it is, but he also suggested what man could be. And thus he did propaganda for man.

But Abbas is genius while expressing his view in his novels. His characters are real and role model for humanity through which, he discriminate and transcends parochialism. For example J.L. Nehru in *The World Is My Village* and Mahatma Gandhi in *Inqilab*. The title of the novel "*The World Is My Village*" in itself suggests that the whole world has shrunk into a village or a family, and no one is permanent here. "I am not here permanently. This place, like this world itself, is temporary. We will pass on". Abbas wants to convey that for a short while the human being gather here so they should have no time to hate and discriminate humanity on the basis such trifle things like of Caste, creed and culture. J.L. Nehru was against it so when ever he was called '*Pandit*' he dislikes it. "Again you are addressing me as Panditji I told you a dozen times I don't like these caste prefixes."

Besides J.L. Nehru Abbas present another character, Mehmooda also to transcend parochialism. She, being a doctor treats the injured, the victims of the roits of the Hindus and Muslims. Without caring to what community they belong she first treats a Hindu then a woman according to the causalities. Anwar thought seeing her involved in humanity .

Thus for Abbas human life is above all, he is too concern with humanity to indulge in parochialism.

Like Mehmooda there is Maria in the novel *Maria* who treats Mahadevan as friend not a *Harijan*. When Mahadevan offers her food she simply denied, "I have no food to eat, Don't worry about me. I am not hungry". Mahadevan misunderstanding her hesitation asked "Is that because I am a Harijan". Maria accepts food from him, she says :

"I didn't know that you are a *Harijan* and , now that I know, I don't care, I only know you are a friend who has come to help our people in their fight for freedom. Give me the food."

But Ahmad Hasib writes :

' What Abbas has done is to render the very process through which the caste prejudice of a life time withers away under the stress of a crises.'What Abbas wants to underline is the fact that prejudice such as Sharma's is a big problem

before the nation; we have to rise above caste and untouchability to achieve something worthwhile. An another prejudice of Sharma as a Hindu is to entertain an unjustifiable doubt about the loyalty of Anwar, a Muslim, in regard to their action in Goa. While Anwar, with hurt sole was slowly walking and lags behind from the group. Sharma spoke out of the bitterness of his heart, that Anwar turned a traitor.

Dr. Ashraf in *The Naxalites* is presented by Abbas like **Maria, who is** beyond this parochialism and treats Raghuo, a dalit rickshaw **puller as** his brother.

Raghuo takes a fat man with his luggage from station to his **home in** his rickshaw and lifts and carries his heavy trunks to his second **floor** flat, hoping to get an extra tip, but receives a 50 paise coin. With this coin he purchased a cup of tea which "was poured in a very conspicuously insulting manner" "... in a metal glass tied **to a chair** that was lying outside". Raghuo as usual takes tea and went away for his earning but his rickshaw collapse and he vomited blood. Dr. Ashraf, being a doctor to whom Abbas presents as a true picture of humanity, ignoring his caste, colour and religion supply **him** his plasma. "The unconscious Raghuo felt new strength pouring in his body. He opened his eyes." Not only this even Dr. Ashraf invites him to have breakfast with him but Raghuo hesitatingly refuses, "Dr. Saheb I am an untouchable." "As Dr. Ashraf gave him his blood he says, "So what? Being your blood-brother, then I must be also an untouchable."

Thus Abbas discarded this parochialism of language, caste, creed, religion and social status in all of his novel. He wants to convey to the people of the world to go beyond this narrow outlook. He has given us very convincing picture of Muslim communalism, Hindu communalism, Scheduled caste communalism, Christian communalism, linguistic regionalism, religious fanaticism, separatism—all a matter of every day experience in this world. In his autobiography *I Am Not An Island* he makes clear the purpose of his writing which really transcends him from parochialism :

**"Here (in this world) I was involved in mankind. And mankind is involved in me. Ram and Mohamd, Gandhi and Goethe, Shakespear and Shelley, Lenin and Jawahar Lal Nehru, they were all part of me and I was a part of them."**<sup>11</sup>

These lines throw light on Abbas out look, which is universal and dipped in brotherhood. Not only this he even presents India in his autobiography in a very broader sense which think not only about its countrymen but for the welfare of the world transcending parochialism of territory, language and enemies :

The great writings are instead of being sugar coated pills or tranquillizers, they are capable of changing human personality and turning 'the world upside down'. No doubt, the novel work of an author expresses the author's fundamental experience, the inchoate urges of his 'body soul'; but at the same time, it presents like in its essential nature, with all its vagueness, conflicts and disorders. The

novel should interpret the truth of life from left experience, and not from books.

The purpose of this paper is to highlight how Abbas uses this form to express of expression. Then we find where he expresses his literary, social, political, cultural point of view he also expresses his religious beliefs which are not entangled in parochialism but have universality and cosmic approach. Abbas also believes in spirit and religion thoughnot in fanatic mannei4as he wrote in his autobiography *I Am Not An Island* :

**I got the talisman of *Imam Zamin* tied round my right arm-I was on the way, this time all alone, to Bombay. No sooner had the train steamed out of New Delhi station where my father had came to see me off, than I had taken off the *Imam Zamin* from my arm, and hidden it in my attache case. I was self-conscious about it. It was a compromise with religion, and I was a new convert to agnosticism, without realizing that itself was a compromise. I believed and I didn't believe. I was not sure of anything God and the Devil, Heaven and Hell-the prophets and the Apostles.<sup>12</sup>**

Though Abbas believes in if you want to know the God, the first step should be to know the soul and for it, we should win mastery over self.

Man, having advance knowledge of science and technology today, might be able to produce the plenty of food or clothing by means of sophisticated computer technology but all this do not satisfy the goal of human life.

Though about this omnibus personality I endeavor to unravel all the aspects of his life but as a universal

personality and versatile genius, we know not; "How shall we rank thee upon glory's page?"

#### References :-

1. Quoted in Barret Hclark, Eugene O' Neil, *The Man and His Plays* (New York : Dover Publications, 1947) 152.
2. Quoted in Joseph Wood Crutch, "*The American Drama since 1918*" (New York : Random, 1993) 92-93.
3. K.A. Abbas, *Mera Naam Joker* (New Delhi : Orient Paperbacks, 1970) 125.
4. Cecil David, Hardy : *The Novelist* (Ludhiana : Lyall Book Depot, 1967) 27.
5. K.A. Abbas, *Mera Naam Joker* (New Delhi : Orient Paperbacks, 1970) 155.
6. K.A. Abbas, *Inqilab* (New Delhi : Orient Paperbacks, 1977) 328-329.
7. Ahmad Hasib, *The Novels of Khwaja Ahmad Abbas* (New Delhi : Seems Publications, 1987) 52.
8. J. Kalinnikava Elient, *Indian English Literature* (Ghaziabad : 1983) 116.
9. K.A. Abbas, " I Write As I Feel", *Blitz* (Bombay: 19 August, 1947).
10. K.A. Abbas, *I Am Not An Island* (New Delhi : Vikas Publishing House Pvt Ltd., 1977)
11. Khwaja Ahmad Abbas, *I Am Not An Island*, An Experiment in Autobiography (New Delhi : Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1977) 117.
12. Khwaja Ahmad Abbas, *I Am Not An Island*, An Experiment in Autobiography (New Delhi : Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1977) 418.

\*\*\*\*\*

# An evaluation of Basel norms and their impact

Rahul Joshi\*

**Abstract** - This study aimed to examine & compare the performance of Basel norms on the profitability & Liquidity of the banks of India. The paper deals with the banking sector reforms in India and the ways designed to manage the risk associate with huge banking sector. An evaluation of Basel norms and their impact on economic growth of the country has been done pursuant to globalization of the industry. Reforms in the financial and the banking sectors have enabled better financial products. This have been allowed financial viability of the banks and help to boost the economic growth.

**Key Words** - Non-performing Assets, Fortify, Supervisory, Arbitrage, Portfolios, Spillover, Liquidity, Leverage, Debt Conversation, Liquidity Coverage Ratio (LCR), Capital to Risk – Weighted Asset Ratio(CRAR).

**Basel Norms** - Basel norm are banking supervision regulations which are issued by the Basel committee on banking supervision. It was established by the central banking governors of the group of ten country in 1974. Its objective is to enhance understanding of key supervisory issues and improve the quality of banking supervisory worldwide. Such norms are the backbone of all banking structures. The committee drafted a first document to set up an international minimum amount of capital that banks should hold. This minimum amount is a percentage of the total capital of bank, which is called minimum risk-based capital adequacy.

**Introduction** - Bank plays a very important part of our economy. In a narrow sense, a bank refers to an institution which operates the transaction of money. A bank accepts deposits from public and lends its funds to public as and when required by the public. In a wider sense, a bank represents an institution which deals with money and credit. The sphere of a bank's function has become too vast to express. They are the nerve centers of modern commerce and industry. Banks induce people to save and deposit their surplus money in the banks by paying interest and securing the fund. This promotes capital formation in the country. Banks also helps in improving the standard living of people.

**According to Kinley** "Bank is an establishment which makes to individuals such advances of money as may be required and safety made and to which individual entrust money when not required by them for use".

Banking sector of India has undergone various changes and reforms. Through it was a part of overall economic reforms, it has changed the function of Indian banks. In the reforms of 1991, The Indian banking sector make more efficient, stronger and more dynamic. Approx. 80% of business are still controlled by public sector banks (PSBs). PSBs will plays an important role in the industry

due to its number of branches. So, in order to achieve an efficient banking system, the onus is on government to encourage the PSB to be move on professional dash.

## Literature Review

\***Abdullah Barakat** (2009), "Bank Basel III Norms Requirement Regarding Internal Control" His study aiming to investigate the degree of application of Basel's committee requirement by Jordan banks. Internal Conflict arises between shareholders and management influence the asset types and threatens capital and ignores depositors' interests. This study recommends the necessity that banking loans portfolios should be tested by external credit agencies and not depend only on internal control operations.

\***Rajkumara** (2013), "Basel III Accord in Indian Perspective" In this research paper threw light upon the basic objectives and components of the Basel III accord in the light of existing RBI norms and proposed Basel III norms.

\***Chakrabarti & Rakshit** (2014) "Basel norms Implementation with Respect to Indian banks with Respect to Indian banks. With a Goal of findings and effect on Basel III in Indian Context." The major part of study was in reduces the profitability & stiffness of future trouble, it reduces the profitability & Indian banks and make loan more costly.

\***Shilam Sharma** (2020) "Basel norms in Indian Banking Industry And Its Current Status: A Review Based Study" Its main objective is to investigate the impact of Basel III on the Indian banking system & also explains why the changes from Basel III to Basel III norms has become necessary to take measures & safety standard which would equip the banks to become more resilient during financial crises.

\***Sarmah, A., and Bharadwaz D.** (2017) 'Basel III In India Banks: A Review of Literature' With a goal of analyzing banking regulation and capital adequacy of Indian banks. The main focus of the Indian banks should be on

strengthening their risk management system.

**\*Amitabh Bhowmick (2020)** "CRAR as the measure of financial health of banks; A study of its patterns, relationship & determinants in Punjab national banks and ICICI bank during BaselIII" This study focuses on pattern, determinants & relationship of CRAR in banks at the period of implementation of BaselIII. The CRAR of ICICI bank has been more than Punjab national bank during (2009-2014) entire period of BaselIII. According to results of this study, The Indian banking system has dominance of government ownership coupled with significant private shareholder in public sector bank which in turn continue to have a dominant share in total banking system.

**\*Michael S. Barr and P. Miller 2006** "Global administrative law: The view from Basel". This article examines the Basel committee on banking supervision, a club of central bankers who meets to develop international banking capital standards and develop supervisory guidance.

**Based I -** In 1988, the Basel I capital accord (agreement) was created. BaselI, refer to a set of international banking regulations created by the Basel committee on bank supervision (BCBS). The committee defines the minimum capital needed for financial institutions, with the primary goal of minimizing credit risk.

**Execution-BaselI** primarily focus on credit risk and risk-weighted assets. It classifies an asset according to level of risk associated with it. The framework requires the minimum capital ratio of capital to RWA for all banks to be 8%

**Bank Asset Classification System-**The bank asset classification system classifies a bank's assets into five risk categories on the basis of a risk percent – 0%, 10%, 20%, 50%, and 100%. The assets are classified into different categories based on the nature of the debtor, as shown below:

#### 0% Risk

# Government debt central bank debt and the debt of govt. departments or organizations.

#### 10% Risk

# Central bank debt of countries with high inflation in the recent past.

#### 20% Risk

# Development bank debt, OECD bank debt, non-OECD bank debt under one-year maturity and non-OECD public sector debt.

#### 50% Risk

# Residential mortgages, municipal revenue bonds.

#### 100% Risk

# Private sector debt, non-OECD bank debt with maturity over a year, real-estate, plant and equipment, and capital instruments issued at other banks.

In BaselI, capital define in two tiers.

Tier 1 = Capital refers to capital of more permanent in nature. It should make up at least 50% of the bank's total capital base. It focuses almost entirely on credit risk.

Tier 2 = Capital is temporary or fluctuating in nature India adopted BaselI guidelines in the year 1999.

In my observation, finds some benefits and disadvantages of BaselI

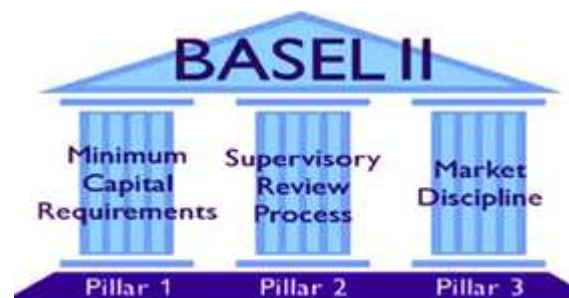
#### Benefits :-

1. Equality among global banks
2. A benchmark for financial evaluation for users.
3. Substantially increased the capital ratios of international of banks and enhanced competitive equity.
4. Relatively simple structure.

#### Disadvantages :

1. Limited differentiation of credit risk.
2. Static measure of default risk.
3. NO recognition of term structure of credit risk.
4. Lack of recognition of portfolio diversification effects not attached with actual risk faced by banking organization.
5. Broad -Brush risk weighting structure.
6. Emphasis is put on the book values of assets rather than the market value.
7. Potential future counterparty risk.

**BaselII -** BaselII is the second set of international banking regulations defined by BCBS. It is an extension of the regulations for minimum capital requirements as defined under Basel I. In June 1999, the committee issued a proposal for a new capital adequacy framework to replace the 1988 Accords. This led to the release of a revised capital framework in June 2004, known as BaselII. The revised framework comprised three pillars:



Source – QS Study

**Pillar 1-**It improves on the policies of BaselI by taking into consideration operational risks in addition to credit risks associated with risk – weighted assets (RWA). It requires to maintain a minimum capital adequacy requirement of 8% of its RWA BaselII also provides bank with more informed approaches to calculate capital requirement based on credit risk, while taking into account each type of asset's risk profile and specific characteristics. The two main approaches include the:

**1. Standardized approach-** This approach is suitable for banks with a smaller volume of operations and a simpler control structure. It involves the use of credit ratings from external credit assessment institutions for the evaluation of creditworthiness of a bank's debtor.

**2. Internal Ratings – based approach-**It is suitable for banks engaged in more complex operations, with more developed risk management systems. There are two IRB



approaches for calculation capital requirements for credit risk based on internal ratings.

- (a) Foundation internal rating based
- (b) Advanced internal rating based

**Pillar 2, Supervisory Review** -The necessity of efficient supervision and lack thereof in Basell, pertaining to the assessment of a bank's internal capital adequacy. Under pillar 2, banks are obligated to assess the internal capital adequacy for covering all risk they can potentially face in the course of their operation.

**Pillar 3, Market Discipline & Disclosure** -To ensure market discipline by making it mandatory to disclose relevant market information. This is done to make sure that the users of financial information receive the relevant information to make informed trading decisions and ensure market discipline.

**Implementation in India** - The process of implementing BaselIII accords in India was planned to be carried out in phases, Phase 1 was for foreign banks operating in India and Indian banks having operational presence outside India with effect from march 31, 2008. In phase 2, all other scheduled commercial banks except local area banks and RRBs were to adhere to BaselIII guidelines by march 31, 2009. The minimum capital to risk-weighted asset ratio (CRAR) in India placed at 9%, one percentage point above the Basel II requirement. As per Basel II norms, Indian banks should maintain tier 1 capital of at least 6%.The difficulties which were faced by India for implementation of BaselIII, were firstly need for improved risk management and measurement. It aims to give impetus to use of internal rating system by banks. Secondly requirement is to arrange risk capital requirement by the banks.

**In My Observation, finds some benefits and disadvantages of BaselIII**

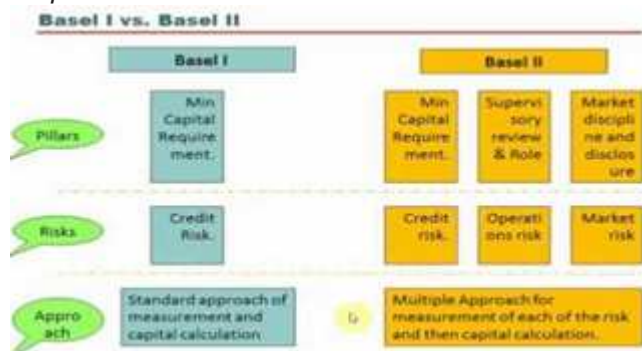
**Benefits :**

- (1) Wider recognition of credit risk mitigation.
- (2) More risk sensitive
- (3) The difference between economic capital & regulatory capital is reduced significantly, due to the regulatory requirement.

**Disadvantages :**

- (1) The accord is very difficult and complex, therefore demanding for supervisors and unworlly (naive) banks.
- (2) Too much regulatory compliance.

*Comparison between Basell and Basel II*



SourceYouTube

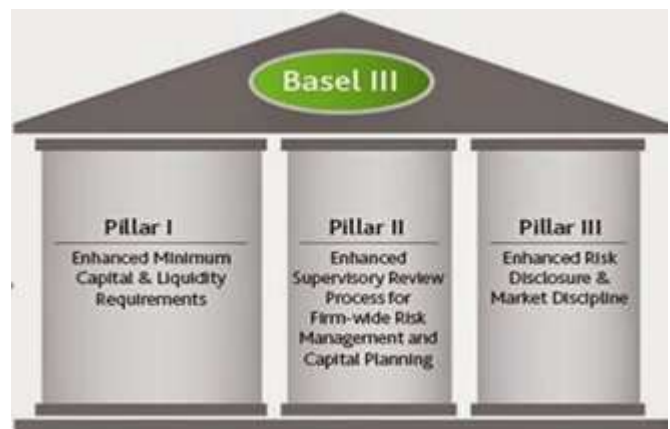
**BaselIII** - After the 2008 financial crisis, need arose to strengthen the banking system further so that they could meet further risks. To meet these dangers, banks were asked to maintain a certain minimum level of capital and not lend all the money they receive from deposits. This acts as a buffer during hard times. The BaselIII accords is a set of financial reforms that was developed by Basel committee on banking supervision (BCBS) with the aim of strengthening regulation, supervision and risk management within the banking industry. Its aim is to improve risk management and governance, strengthen banks, transparency and disclosures.

**The Pillars of Basel norms**

In BaselIII, three very important aspects which are called three pillars of BaselIII

- \* **Pillar 1** ->The first pillar 'minimum capital requirement is mainly for total risk including the credit risk, market risk, write-off or debt conversion, liquidity coverage ratio (LCR) as well as operational risk.
- \* **Pillar 2** ->The second pillar is supervisory review process is basically is to ensure that banks have adequate capital to support all the risks associated in their business.
- \* **Pillar 3** ->The third pillar is to complement the first & second pillar i.e. market discipline. This is basically a discipline followed by the book such as risk disclosing.

Pillars of Basel III Norms



Source Jagran Josh

**Comparison Table of Basel II and BaselIII**

Requirement	Baselll	BaselIII
*Minimum ratio of total capital to RWA	8%	10.50%
*minimum ratio of common equity to RWA	2%	4.5 TO 7.00 %
* Tier 1 capital of RWA	4%	6%
*Lore tier 1 capital to RWA	2%	5%
*Capital conservation buffers to RWA	None	2.50%
* Leverage ratio	None	3.00%
*Countercyclical buffer	None	0% to 2.50 %
*Minimum liquidity coverage ratio	None	2015

*Minimum net stable funding ratio	None	2018
*Systemically important financial institutions charge	None	2011

Source ->www.Quora.Com

#### *\*Significance of BaselIII for Indian banking.*

BaselIII guidelines attempt to enhance the ability of banks to withstand periods of economic and financial stress by prescribing more stringent capital and liquidity requirement for them. Implementing BaselIII will only be an evolutionary step, the impact of BaselIII on banking sector cannot be under estimated, as it will drive significant challenges that need to be understood and addressed. Working out the most cost-effective model for implementation of BaselIII will be a critical issue for Indian banking.

#### **# Impact on financial system**

Basel III frame work implementation would lead to reduced risk of systemic banking crises as the enhanced capital and liquidity buffers together lead to better management of probable risks emanating due to counterparty defaults and or liquidity circumstances. Undoubtedly BaselIII implementation would strengthen the Indian banking sector's ability to absorb shock arising from financial and economic stress, whatever the source be, and consequently reduce the risk of spillovers from the financial sector to the real economy.

#### **# Impact on weaker banks**

There would be a drastic impact on the weaker banks leading to their crowding out. As is well established, as conditions deteriorate and the regulatory position get even more intensive, the weaker banks would definitely find it very challenging to raise the required capital and funding. In turn, this would affect their business models apart from tilting the banking businesses in favor of large financial institutions and thereby tilting the competition.

#### **# Increased Supervisory**

Banking operation might experience a reduced pace as there would be an increased supervisory vigil on the activities of the banks in terms of ensuring the capital standards, liquidity ratio and others.

#### **# International Arbitrage**

Inconsistent implementation of BaselIII frame work among different countries would lead to international arbitrage thereby resulting in disruption of global financial stability.

#### **#Reorganization of institutions**

The increased focus of the regulatory authorities on the organizational structure and capital structure ability of the financial firms would lead the banks to reorganize their legal identity by resorting the mergers & acquisition and disposals of portfolios, entities, or parts of entities wherever possible.

#### **BaselIII guidelines V/s RBI Norms**

Basis	BaselIII	RBI norms
Limit on deduction	Deduction would	All deductibles

	be made if deductibles exceed the 15% of core capital at an aggregate level or 10% at the individual item level.	to be deducted.
Deductions from tier 1 or tier 2	All deduction from core capital.	50% of deduction from tier 1 and remaining 50% from tier 2 capital.

Source google

**Methodology** - This study uses the observation approach has been used to analyze & compare the main findings as well as applicability of the research papers. Hence by using an interpretive and critical approach through content analysis of studies reviewed.

**Conclusion** - The objective of the research has been to explore the Basel norms and examine how they have impacted risk management process in the Indian banks. The primary objective of based committee is to give the internationally active banks a level playing ground to ensure safety among these banks.

Basel norms has brought about important changes in the capital format of the banks. The based norms have brought up the idea of maintenance of capital adequacy ratio to balance the profitability of the bank. We have focused on these changes in the asset and investment composition of the banks in the different regulatory rules (BaselI, BaselII) of the Indian banking sector.

RBI has indicated more regard for this angle in sticking to BaselIII consistency, it has revered a lot of useful and through rules to banks that would fortify the capital base more adequately with less Non-performing assets. BaselIII standard is a foremost need for Indian banks from the blessed messenger of individual resident of this nation for their long. In this way some banks should rebuild and adjust to make due in new condition.

#### **References :-**

- 1 <https://www.bis.org/bcbs/index.htm?m=3%7C14%7C625>
- 2 <https://www.bis.org/bcbs/about/overview.htm?m=3%7C14%7C573>
- 3 [https://www.investopedia.com/terms/b/basel\\_i.asp](https://www.investopedia.com/terms/b/basel_i.asp)
- 4 <https://www.investopedia.com/terms/b/baselii.asp>
- 5 [https://www.investopedia.com/terms/b/basel\\_committee.asp](https://www.investopedia.com/terms/b/basel_committee.asp)
- 6 [https://en.wikipedia.org/wiki/Basel\\_Accords](https://en.wikipedia.org/wiki/Basel_Accords)
- 7 <https://www.slideshare.net/SyedAshrafAli3/basel-accords-basel-i-ii-and-iii-advantages-limitations-and-contrast>
8. <https://www.youtube.com/watch?v=6aEetRHolfM>

# Human rights and custodial violence: An overview

Shikha Sodhiya\*

**Abstract** - The word custody means guardianship and protective care. The violation of human rights under the support of uniform and four walls of police station, prison where the victim is helpless. Violence is an apparatus is used to impose the one will on another and to feels the power and superiority over other. Criminal Law promotes the desirable behaviour of human being in society and prevents the undesirable behaviour of human being in the society. Hence Penal Law governs the forces that we permit the official agencies to bear on the individual. Custodial violence is the darkest reality of democratic country governs by "rule of law".<sup>1</sup> In democratic country, the role of police is to safeguard the rights of human being and enshrined according to Constitution of India. The practice of custodial violence in the developing country like India, it is not due to individual, but due to a complex system of law, which governs the protection of human rights. This dehumanising torture, humiliation, physical violence and death in custody have alarming the serious question about the credibility of law implication and criminal justice administration.<sup>2</sup> National Human Rights Commission, Law Commission, Supreme Court recommended the government of country to make a special law on custodial violence. The researcher in this paper made a study on custodial violence and violation of human right with a strong and effective, preventive measures for the same.

**Keywords** - Custodial Violence, Torture, National Human Rights Commission.

**Introduction** - "Torture is the wound in the soul so painful that sometimes you can almost touch it, but it is also intangible that there is no way to heal it. Torture is despair and fear and rage and hate. It is a desire to kill and destroy including yourself".

- Adriana P. Bartow<sup>3</sup>

The term Custodial violence, "Custody" which is not define by procedural law but according to dictionary meaning is, the legal right and duty to care of someone. "Violence" means the behaviour of someone which harms or damage physically or used energy and in layman's language is 'cruelty', 'atrocities', 'hurt'. It is the State who protects the right of individual whether he/she is prisoner or not. Here the meaning of custody used in reference when a person is detained or arrested by official authority. Kinds of official authorities are police, judicial or any other institution obliged to take care of that particular like special homes, hospitals etc. According to Section - 167 of Code of Criminal Procedure, there is two type of custody. Section-167(1), "police custody can be granted for the maximum period of 15 days only". Therefore police officer can arrest the person in two occasions, first from the period of arrest till produce him before and second when the police gets the remand after producing him in the court and after this it is said accused sent in judicial custody till he gets the bail.<sup>4</sup>

## Aspect Of Custodial Violence

**Torture** - Torture ruins the life of individual, it put the long-lasting impression on mind of victim. It effects the physically as well as mentally. This act done by police for investigate

the offender or to confess the information by offender. This is only done by police because, the power to investigate has police by the law. To perform their duties they used wrong way, they commit heinous crime by using violence, torture. The crime committed, by the person who should be consider the guardian of the citizens, under the shield of uniform and inside the four walls of authority. Intentionally imposed the force or fear on the mind of accused to confess the matter.

**Some Facts And Figures** - The National Crime Records Bureau does not record the crime in the custodial violence, National Human Rights Commission records the cases related to torture in custody, but the does not mentioned the cases in their report. The following table collected from the answers of parliament on the cases record by NHRC<sup>5</sup>:

Year	2011 -2012	2012 -2013	2013 -2014	2014 -2015	2015 -2016	2016 -2017
Torture in police custody	678	366	303	431	493	293
Death in police custody	128	143	140	130	153	145

**1. Sexual Harassment** - Admonish the one's dignity and attack the self-respect of someone. Sexual Harassment/ Sexual Violence is the great, worst and extended form of torture. It might be verbal sexual abuse and humiliation for the dignity of one's. Custodial Rape is a term which means rape taken place when the victim is in custody or under their possession and the rapist are the agent of the power/

\*B.A. L.L.B.,L.L.M. (Criminology) Rani Durgawati Vishwavidhyalaya, Jabalpur (M.P.) INDIA



authority so that they keep the victim in custody. Protection and punishment against custodial rape is given under section-376(2) Of Indian Penal Code. But there are very few cases which are reported. According to National Crime Record Bureau in 2002, court tried 132 policemen, but only 4 was convicted. Between 2000 to 2016, there was 1,022 death in police custody, but FIR's filled of 428 cases only.<sup>6</sup>

**Violation Of Human Rights** - In the modern era most evil practice is inflicting torture upon the individual amounting inhumanity, ill-treatment. The investigating authorities to complete the investigation through shortcut and to obtain the confession often resort to inhuman treatment. Sometimes the whole situation become so worst, victims are forced to do such thing which are against their ideological, religious, self-respect or self-esteem. Hence victims are interrogated in terrifying ways and they used the in human treatment to get the false confession. These authorities by using mal-treatment in interrogation or against the accused who is in prison amounting the violation of Human Rights.

**Remedies Available Under Constitution Of India** - The Constitution of India had given recognition to prisoner's rights and dignity as citizen of India. Court is in position and have power to impose the human rights concept in favour of prisoners, so they treated as human being. It mentioned that punishment in civil society must not for degrade the human dignity. Acceptance of inherent dignity and equal rights is the foundation of peace, freedom and justice in society. Our Indian Constitution provides the certain rights to citizens of India. The court as well as police officer, the law enforcement officer of state should prevent anyone from breach their rights. These rights are guarantee under Article- 14, 19, 20, 21, 22 of constitution. But these rights are violated by police officers in custodial violence by using unlawful force on prisoners.

**Article – 14:** Equality before law – Under this article accused shall be treated as equal as other person before law. This is the duty of state i.e. guards of laws, shall not deny to any person equality before the law. But the officials for quick disposal of the case, they breach this article. They did not treat equally them, they consider convicted before court judgement.

**Article – 19:** Protection of right regarding to speech and expression etc. Here authorities, guards of laws are suspended their freedom of speech.

**Article – 20:** It provides protection in respect of conviction for offences.

**Article – 20(1),** It is protection available to accuse, it is concerned with substantive law of criminality and penalty. The retrospective effect of criminal legislation is prohibited and no liability is imposed. A person shall be convicted of offence which is violate the law in force at that time of commission of offence. It prohibits on ex post facto laws.

**Article – 20(2),** It provide, no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once. This prohibits against double jeopardy. Here must

shows that person prosecuted for the offence and convicted for the same once so prosecuted again for the same is prevented.

**Article - 20(3),** It provides no person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself.

**Article – 21:** Protection of Life and Personal Liberty – No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to law. This article does not expressly say against torture or custodial violence. But 'Life or Personal Liberty'. Therefore to include the constitutional protection against torture, assault or injury against a person.

In *Maneka Gandhi v. Union of India*<sup>7</sup>, the court expand the scope and ambit of A-21. Here right to live is not limited by physical existence but it also includes the ambit the right to live with human dignity.

In *Sunil Batra (II) v. Delhi Administration*<sup>8</sup>, the court restated that "handcuffs and irons be speaks a ruthlessness, aggressive to our goal of human dignity and social justice".

**Article – 22:** Protection against arrest and detention in certain cases –

**Article – 22(1)** No person is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult and to be defended by, a legal practitioner of his choice. If this is not followed by police authority then it shall be illegal arrest or detention of person.

In *A.K. Gopalan v. State of Madras*<sup>9</sup>, It was held that the right to counsel as a statutory provision is immune from legislative attack.

**Article – 22(2)** Right to speedy trial - Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of magistrate and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate. The above rights are available to the citizen and non-citizen, but not available to the person who arrested or detained according to preventive detention laws. These rights under Article 22(1) & 22(2) are as follow:

1. Right to informed the grounds of arrest to accused.
2. Right to consult a legal advisor and represent him before court, of his choice.
3. Within 24 hours of arrest, right to produce before magistrate
4. Right to freedom from arrest beyond 24 hours except order of magistrate.

In *Kadra Pahadia v. State of Bihar*<sup>10</sup>, the Supreme Court again stated that "speedy trial is the fundamental right of an accused under Article 21 of Constitution."

#### **National Framework On Custodial Violence**

**A) Protection of Human Rights Act, 1993** - This Act was passed by parliament to meet the demand of national and international to protect the human rights by a law. Changing in society needs and nature of crime, demands the effective and efficient method for dealing with this issue and



provides the justice through transparency and greater accountability.

**Guidelines of Supreme Court in case of D.K Basu v. State of West Bengal<sup>11</sup>** - In this case the court felt the urgency of situation and needs of machinery responsible for arresting a person. Court said that there should need more transparency and accountability in the system. Therefore certain guidelines given by Apex Court and it mandate to follow by the law enforcement agencies on the time of arrest a person:

1. The police officer should carry a accurate and clear identification of that person and also all particulars of that police person who handle the investigation of that accused person shall record.
2. There should be prepare a memo of arrest that arrest time by police officer and shall signed by one witness whether it can be a family member of arrestee or any locality person and also signed by arrested person with date and time on it.
3. The person who has been arrest, detained in custody of police or in lock up shall entitle to inform his family member, relatives, friends as soon as possible.
4. If member of family and friend of arrestee lives outside of town or district, they shall be informed through Legal Aid Organisation in district or police station within 8 to 12 hours after arrest.
5. The arrestee shall aware of his right and reason of his arrest.
6. A diary of entries should maintain in which mentioned the name of his next friend and also detail regarding the police officials in whose custody the arrestee is.
7. After every 48 hours during the arrest, must have the medical examination of arrestee by a certified doctor appointed by Director Health Services of State or Union.
8. The arrestee shall entitle to meet his lawyer but not throughout the interrogation.
9. Police central room should have at all District level and State headquarters. The information regarding arrest and place of custody should be given.

#### **REPORT OF ROYAL COMMISSION ON 'CRIMINAL PROCEDURE' In Case Of D. K. BASU V. STATE OF WEST BENGAL**

ROYAL COMMISSION recommended the basis necessary principle of arrest and restriction on arrest. This commission said detention should be and to be continuous for following criteria:

1. On summon served, person intentionally un-identify himself.
2. To prevent the continuation and repetition of offence.
3. Need to protect the other person or property or himself.
4. Protect the evidence relating offence and need to questioning to him for getting evidences.
5. When there are chances to escape of person and failing to appear in police station if any charge made against him.

**National Human Right Commission** - Guidelines of National Human Rights Commission, New Delhi ,2000 provides detailed guideline regarding to pre-arrest, arrest and post-arrest and also provides principle to enforcement of guidelines. These National Human Rights Commission's guidelines are requested to all State to adopt them.

#### **Remedies Available Under Other Laws**

##### **CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973**

Section – 46 & 49 of code protect the person who under the custody and not the accused of offence of punishable with life imprisonment and death, from torture.

Section - 54 of code, when an allegation is made by a person on police person or other official in whose custody, its magistrate duty to examine that person 's body and maintain the record of examination. When it comes to the court notice it shall be examined by medical practitioner by his request.

Section – 176 of code, where a mandatory inquiry take place by magistrate on the death of accused in police custody.

Section – 167 & 309 of code, object behind the taking the accused before magistrate, so safeguard the rights and interest of that person.

##### **INDIAN PENAL CODE, 1860**

An amendment added clause (b) in Section – 376(1), provides the punishment to police officers if custodial rape is committed in police custody.

Section – 330, 331, 342 & 348 these sections designed to deter the police officer, those who have power to arrest a person and investigate him and during investigation of offence prevents any kind of third degree method which causing torture.

*Sheela Barse v. State of Maharashtra<sup>12</sup>*, this case provides guidelines specially for arrested women and also regarding the rights of arrested person. The court state that it is duty of magistrate to inform their rights to all arrested person.

##### **INDIAN EVIDENCE ACT, 1872**

Section – 24, confession made by threat or inducement from a person in authority to avoid any kind of gain and evil of temporal nature to accused would be irrelevant in criminal proceeding.

Section – 25, provides that confession made by an accused person to police officer shall not take as evidence against that accused person.

Section – 26, provides that confession made by accused person in police custody, shall not to be proved against him, unless confession is made in presence of magistrate.

##### **INDIAN POLICE ACT, 1861**

Section -7 & 29 provide if any police officer who are negligent in performing his duty and unfit for perform, is liable to dismissal, penalty, suspension. This can be seen in light when police officer violating the constitutional and statutory provisions.

**International Framework On Custodial Violence** - There are many Declaration, Conventions and Policies at international level which dealt with rights of prisoners or arrested person. In 1945, India with other 50 nations of world signed United Nation Charter regarding to Human

Rights and create United Nation. Activities of United Nation has formed several devices and adding more detail to its prototypes. In present to analysing the custodial violence important international work are: Universal Declaration of Human Rights 1948, European Convention of Human Rights and Fundamental Freedom, Declaration on Protection from Torture. However together all these instruments make an international instrument of Human Rights which deal with issue of Custodial Violence.

Therefore,

**A) Universal Declaration of Human Rights 1948** - This provides the outline of human rights mentioned in draft and provide the framework for International Bill of Human Rights. Universal Declaration computes the fundamental rights which are soul object of charter of United Nation and these define under Articles – 1, 3, 5, 6, 7, 10 and 11.

Article – 1: All Human being are born free and equal in dignity or in rights.

Article – 3: It mentioned that everyone has right to liberty, life and security of person.

Article – 5: Everyone has right not to be subject of torture, cruelty, inhumanity, ill-treatment or punishment.

Article – 6: Everyone has right to be recognised as a person before law.

Article – 9: Everyone has right not to be subject of arbitrary arrest, detention or exile.

Article – 10: Everyone has right of full equality regarding trial such as fair trial, public hearing and impartial trial and guarantee for his defence.

Article – 11: Every person has right to be treated as innocent person before of law until guilt is proved of that person; and provide no punishment before law for such act, omission which is not offence at that time under any law and not imposed heavy penalty which should impose when offence is committed.

**B) European Convention of Human Rights and Fundamental Freedom, 1950** - This instrument not only provides the international protection but also provides establishment of machinery for supervision and enforcement of that protection.

**C) Declaration on Protection from Torture, 1975** - Article – 2: Any act related to torture, inhumanity, ill-treatment or punishment is an offence against human dignity and it shall be a conduct against the object of charter of United Nation and violation of Human Rights and Fundamental Freedom given by Universal Declaration on Human Rights. Article – 3: Not a single State allows the torture, cruelty, ill-treatment with human, inhumanity or punishment. But there are some exceptional cases where such act related to

torture, inhumanity, cruelty may be justified and these cases are state of war, threat of war, political instability and other public emergency.

**D) Standard Minimum Rules for the Treatment of prisoner, 1955** - In 1955, United Nation Congress on prevention of crime and treatment of offender for first time adopted the Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners. It provides no discrimination on the basis of sex, colour, gender, religion, political, opinion, national or social origin, property, birth or status among prisoners. Prisoner's authorities are made-up to respect the religions belief of prisoners.

**Conclusion** - Custodial Violence and Custodial Torment is nothing but another wonder, which is regulate normally. It is turned out basic now-days and the police, administration even normal person under estimate as it is normal routine of police agencies. When any news flashes regarding custodial torment whether it fades away with time or that person is free from the law or charges due to political freedom. Custodial crimes invade upon human rights and the confession so pull out often fails to stand the legal scrutiny. Custodial Violence management is very vital and serious to overall jail management program, so that the officials are able to complete the mission in spite of various challenges.

#### References :-

1. [slideplayer.com/slide/5872238/](http://slideplayer.com/slide/5872238/) (Presented By Dr K. Kottai Rajan, Asst Prf. Of Department of Political Science and Public Administrative).
2. Baljeet Kaur, "India's Silent Acceptance Of Torture Has Made It Public Secret", Quill Foundation, 6 September, 2018
3. Dr D. P. Verma , Dr Ramesh Chhajta , "Torture In Opposition Of Human Rights : A Discourse", 21 IOSR-JHSS 30-38 (2016).
4. Manmeet Singh, "Custodial Violence In India ", Legal Service India .com .
5. Baljeet Kaur, "India's Silent Acceptance Of Torture Has Made It Public Secret" ,Quill Foundation, 6 September,2018
6. Ankur Sharma, "Only 428 FIRs Filled in 1,022 custodial deaths between 2000to 2016 says NCRB", The New Indian Express,15 April,2018.
7. AIR 1978 SC 597
8. AIR 1980 SC 1579
9. AIR 1950 SC 27
10. AIR 1982 SC 1167
11. AIR 1997 SC 610
12. AIR 1983 SC 378

# Yoga for Stress Management and Well Being

Manju Rani\* Surendra Kumar Yadav\*\*

**Abstract** - Effective techniques for **stress management** are varied. They typically include behaviors that improve physical health, such as meditation and yoga exercise, but may also yogic strategies that improve cognitive, emotional functioning and well-being.

**Keyword** - Stress, Yoga, Meditation, Well-Being.

**Introduction - Stress** is the way that we react physically, mentally and emotionally to various conditions, changes and demands in our lives.

Many students and faculties experience varying levels of stress each semester.

**According to Walter Canon (1929)** we need stress to help us with an acute response such as in "fight or flight" response.

**Fight or flight response**, forgetfulness, loss of mental concentration, anxiety and fear, depression, extreme anger and frustration, family conflict, social withdrawal, and loss of interest in activities,

## Some Symptoms of Stress:-

1. headaches
2. nervous stomach
3. change in appetite
4. rapid breathing
5. rapid heart rate
6. sweaty palms
7. irritability
8. anxiety
9. fatigue
10. insomnia
11. dissatisfaction
12. anger
13. depression
14. inability to concentrate
15. emotional problems
16. tiredness all the time
17. neck pain, back pain migraine headache
18. suicide

## Causes Stress

### Changes in Life's Expectations or Demands

Ex. Marriage, divorce, pregnancy, illness, bills, increasing demands of university and classes.

Disorganization: Feeling unprepared and powerless  
Physical Constraints.

Ex. Physical exhaustion, lack of good exercise and diet strategies.

**Techniques of Stress Management** - There are several ways of coping with stress. Some techniques of time management may help a person to control stress. In the face of high demands, effective stress management involves learning to set limits and to say "No" to some demands that others make. The following techniques have been recently dubbed "Destressitizers" by The Journal of the Canadian Medical Association. A destressitizer is any process by which an individual can relieve stress. Techniques of stress management will vary according to the theoretical paradigm adhered to, but may include some of the following:

1. Autogenic training
2. Cognitive therapy
3. Conflict resolution
4. Exercise
5. Getting a hobby
6. Meditation
7. Deep breathing
8. Relaxation techniques
9. Artistic Expression
10. Fractional relaxation
11. Progressive relaxation
12. Spas
13. Spending time in nature
14. Stress balls
15. Natural medicine
16. Clinically validated alternative treatments
17. Time management
18. Listening to certain types of relaxing music, particularly:
19. New Age music
20. Classical music
21. Psychedelic music

**Measuring Stress** - Levels of stress can be measured. One way is through the use of the Holmes and Rahe Stress

\*Ex Yoga Student, V.M.O.U Kota University, Kota (Raj.) INDIA

\*\* Yoga Teacher, Army Public School, Suratgarh (Raj.) INDIA

Scale to rate stressful life events. Changes in blood pressure and galvanic skin response can also be measured to test stress levels, and changes in stress levels. A digital thermometer can be used to evaluate changes in skin temperature, which can indicate activation of the fight-or-flight response drawing blood away from the extremities.

Work on your attitude

Put things into perspective. Do not take yourself too seriously.

Think positive. "If you think you will fail, or think you will succeed, you are probably right." Henry Ford

**Stress Management through Yoga** - Various techniques in yoga have been documented to help in stress management. These techniques work at an individual level and also at a collective level to ensure that there is significant respite from the condition of extreme stress. They help in relieving the physical as well as the psychological negative effects of the problem by ensuring a healthy and productive response to the stress stimuli.

Yoga can have a positive effect on the parasympathetic nervous system and aid in lowering heartbeat and blood pressure. This reduces the demand of the body for oxygen. Yoga can also improve digestion, strengthen immunity, help in effective elimination of toxic wastes and also increase lung capacity. Effective use of this practice can also reduce the chances of stress culminating in anxiety and depression.

The practice of yoga involves forming various body postures, slow stretching movements, breathing exercises that can at times lead to progressive relaxation, imagery and meditation. All these specific techniques are meant for a specific purpose and they culminate into a higher awareness of what is happening to oneself during stress – emotionally, physically, mentally and energetically.

So back to stress management, yoga provides a unique way of managing stress through pranayama (A birthing technique), in this technique an individual do slow and steady breathing steady- like inhaling through his one nostril and exhaling through other. Besides there are fast breathing movements like intake of air through nostrils and exhaling through mouth at fast pace, this way air is passed properly through blood capillaries and the person feels himself / herself in light mode i.e. he / she feels that there is no burden over their mind and soul.

**Meditation Techniques** - Dhyana (Meditation) is also a good method of controlling stress, in this part of Yoga a person sit comfortably and think of a favorite place. Imagine yourself in a successful situation. Than after breathe deeply and slowly. Continue for five or six breaths. It is calming and the extra dose of oxygen increases the brain's thinking ability.

Finally Yoga has and is proving itself as "Stress Management Tool" and now a day it is being used in Western world too as a major alternative to the offensive allopathic drugs.

**Yoga Meditation a Way of Complete Well Being** - Researchers have postulated that yoga meditation

programs may affect a range of outcomes related to psychological stress and well-being. The research ranges from the rare examination of positive outcomes. Such as increased well-being, to the more common approach of examining reductions in negative outcomes, such as anxiety or sleep disturbance. Some studies address symptoms related to the primary condition ( pain in patients with low back pain or anxiety in patients with social phobia), whereas others similar emotional symptoms in clinical groups of people who may not have clinically significant symptoms ( anxiety of depression in individuals with cancer).

1. Yoga and meditation go hand in hand and neither could survive alone. When combined to together, Yoga meditation is a powerful tool that can greatly benefit those that practice this from of reflection.
2. Yoga meditation allows you to use deliberation to bring your body into a state of rumination. Using yoga meditation on a regular basis can bring about a variety of wonderful health benefits as well as giving you a wonderful sense of well being.
3. One of the biggest benefits of yoga meditation is the way it promotes peace of thought and health of body instead of stress. Yoga meditation teachers both body postures for relaxation and agility as well as mind cleansing exercise that work together to being your body to a peaceful state of contemplation, which helps to erase the stress of the outside world.
4. There are also a variety of physical benefits that come with the practice of yoga meditation as well. E. g: improved blood pressure and pulse rates, healthy immune system.
5. Yoga meditation has been found? to be a great help to people who deal with bouts of depression and has brought them to a state of rumination instead of unease and hopelessness.

### Benefits of Yoga

**Mental calmness** - Yoga asana practice is intensely physical. Concentrating so intently on what your body is doing has the effect of bringing calmness to the mind. Yoga also introduces you to meditation techniques, such as watching how you breathe and disengagement from your thoughts, which help calm the mind.

**Stress reduction** - Physical activity is good for relieving stress, and this is particularly true of yoga. Because of the concentration required, your daily troubles, both large and small, seem to melt away during the time you are doing yoga. This provides a much-needed break from your stressors, as well as helping put things into perspective. The emphasis yoga places onbeing in the moment can also help relieve stress, as you learn not to dwell on past events or anticipate the future. You will leave a yoga class feeling less stressed than when you started. Read more about yoga for stress management here.

**Body awareness** - Doing yoga will give you an increased awareness of your own body. You are often called upon to make small, subtle movements to improve your alignment.



Over time, this will increase your level of comfort in your own body. This can lead to improved posture and greater self- confidence.

**Conclusion** - Actually yoga combines several techniques to combat stress management. yoga provides a combination of benefits such as breathing exercises, stretching exercises, fitness program, and meditation practice and guided meditations all in one technique for well being. That is powerful, that is very powerful! Even for people who have physical limitations yoga can be very beneficial just by practicing the breathing techniques, the meditation and the guided meditation. Just by doing this you can have great benefits with the practice of yoga. So in conclusion yes yoga can be a great remedy for stress and can offer some stress relief. Yoga has combined set of principles and exercises that can greatly benefit you and help you to deal with stress management and well being.

#### References :-

1. Butlin, J. (2001), Links between the Physical and the Emotional. Wholistic Research
2. Company, 1-3. Retrieved April 29, 2003 from Annotation: Information about emotional influences on the physical body.
3. Cooper CL, Marshall J (1976) Occupational sources of stress: a review of the literature relating to coronary heart disease and mental ill-health, Journal of Occupational and Organizational physiology 49: 11-28.
4. Chugh, D. (1987). Effects of Sahaja Yoga practice on the patients of psychosomatic diseases. Delhi University, Annotation: Information about mechanism of Sahaja Yoga and research on psychosomatic diseases.
5. Dally, E., et al. (1993) Measuring the impact of menopausal symptoms on quality of life. Br. Medical Journal, 307, 836-840, Annotation: information about menopausal symptoms.
6. Malathi A, Damodaran A (1999) Stress due to exams in medical students—role of yoga. Indian J Physiol Pharmacol 43: 218-224.
7. Network, <http://www.cyc-net.org/reference/refs-psychosomatic-levenstein.htm>

\*\*\*\*\*

# Violence Against Women And Their Remedies In Present Laws

Richa Agrawal \*

**Introduction** - Women of all ages and social classes, of all races, religions and nationalities all over the world experience violence against women. This is committed primarily by men. It is the most widespread human rights abuse in the world today. The manifestations are both subtle and flagrant, and its developmental effect is profound. And it's rooted so profoundly in communities around the world that it's almost invisible.

The term aggression derives from the Latin word vis, which means force on the other person and refers to the conceptions of coercion and the use of physical dominance. Violence is unique as it is affected by times, situations, conditions and experiences that are very different. Violence is accepted and denounced, as violence has existed on Earth because mankind takes that, increasingly complex and at the same time more fractured and articulated forms. The UN Declaration on Violence against Women offers a framework on which to describe gender-based violence. According to Article 1 of the Declaration, violence against women is to be interpreted as: "Any act of gender-based violence that causes, or is likely to cause, physical, sexual or psychological harm or distress to women, including threats of such actions, intimidation or arbitrary deprivation of liberty, whether in public or private life"<sup>4</sup>.

The term is reiterated in Article 2 of the Declaration, which defines three places where violence commonly occurs:

1. Physical, sexual and psychological violence occurring within the family, including battering; domestic sexual abuse of female children; dowry-related violence; marital rape; female genital mutilation and other cultural practices detrimental to women; non-spousal violence; and exploitation-related violence;
2. In general, physical, sexual and psychological brutality, including rape; sexual abuse; sexual harassment and coercion at work, in educational institutions and elsewhere; trafficking in women; and forced prostitution;
3. The State committed or condoned physical, sexual, and psychological abuse, wherever it occurred.

**Stages Of Gender-Based Violence** - Gender-based violence is at three stages. These are household or

relatives, group level and state level-

1. Violence With Home-
2. Violence within community
3. Violence Within State

**Constitutional Provisions for women are as under:**

1. Article 14, confers on men and women equal rights and opportunities in political, economic and social sphere.
2. Article 15, prohibits, discrimination against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex etc.
3. Article 16, provides for equality of opportunities matters relating to employment or appointment to any office under the state.
4. Article 39(a) (d), mentions policy security of state equality for both men and women the right to a means of livelihood and equal pay for equal work for both men and women.
5. Article 42, Direct the State to make provision for ensuring just and humane
6. Conditions of work and maternity relief.

**Other Legal Provisions for women are as under:**

1. Factories Act 1948: Under this Act, a woman cannot be forced to work beyond 8 hours and prohibits employment of women except between 6 A.M. and 7 P.M.
2. Maternity Benefit Act 1961: A Woman is entitled 12 weeks' maternity leave with full wages.
3. The Dowry Prohibition Act, 1961: Under the provisions of this Act demand of dowry either before marriage, during marriage and or after the marriage is an offence.
4. The Protection of Human Rights Act, 1993
5. Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005:
6. Protection of Women against Sexual Harassment at Workplace Bill, 2010

**Review Of Literature** - Producing a literature review may also be part of graduate and post-graduate student work, including in the preparation of a thesis, dissertation, or a journal article. Literature reviews are also common in a research proposal or prospectus (the document that is approved before a student formally begins a dissertation or thesis).<sup>1</sup>

The given chapter is based on the review of literature.

During this work, many of the literature reviewed. Some of the prominent reviews have been presented in the given chapter.

**Ritu Dhanoo (2008)** - In her paper "Violation of Women's Human Rights in India" she pointed out that while the constitution of India guarantees equal rights for both men and women, there is a significant gap between the law and its practice. In India, women have always been considered inferior to men. And if none of the Population is often discriminated against by women and faces abuses in all aspects of life. They are the victims of numerous crimes, including abduction, dowry, bridal burning, sexual abuse, prostitution and trafficking.

**UNICEF (2015)** - Unicef (2015) in its working paper titled "DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN AND GIRLS" mentioned the global burden of domestic violence and its implication over the girls and highlight how the girls face various types of discrimination in her lifestyles. Violence in opposition to ladies is considered as a global epidemic by which the sufferer girls face bodily, psychological and sexual abuse and even torture and dying. Due to this violation girls are deprived from equality, safety, dignity, self-worth, and their proper to experience essential freedoms.

Every U.S.A few or the alternative shape of violence is prevailing across the globe. Violence prevails across the subculture, class, schooling, earnings, ethnicity and age. However, the vulnerability is varying organizations to corporations. Women belong to minority organizations, indigenous and migrant girls, refugee ladies and ladies in battle quarter are extra prone than the others. It is shocking that out of all shape of violence between 20 – 50 percentage of girls experiencing violence are from the close relationship, both from the partner or from the own family members.

However, the significance of the domestic violence isn't visible as most of the instances are unreported and unrecorded as most of the girls are reluctant to document the occurrence of violence. The first actual cause is insensitiveness of the healthcare professional and police professionals in responding such instances and the second purpose is the concern, and unawareness associated with the prison structures.

**Margins Yeomen(2018)** - In her article Acid Attack within the Back Drop of India and Criminal Amendment Act, 2013 mentioned the motives behind this heinous crime and its outcomes. She also attempted to examine the laws of acid attack in extraordinary international locations within the lower back drop of India.

Violence against girls is a manifestation of historically unequal energy family members among ladies and men that have caused domination over and discrimination in opposition to ladies through guys and to the prevention of the overall development of girls. Acid assault, more officially referred to as vitriol age, is an act of intimate terrorism that entails the premeditated throwing of sulfuric, nitric, or hydrochloric acid onto some other with the primary purpose of disfigurement.

In a case of **Devanand vs. The State**, a person threw acid on his estranged wife due to the fact she refused to cohabit with him. The wife now not best lost her eye sight, but also caused permanent disfigurement of her face. Although the accused became held guilty through the Court, the punishment provided became a minimal duration of seven years under Section 307 IPC. **Laxmi Agrawal**, the daughter of a home cook dinner, was most effective 16 while 32-year-vintage man commenced pursuing her. After she refused his marriage proposal some instances, he roared up someday on a motorcycle with a companion and threw acid on her face, chest and palms. She misplaced all her early life, misplaced all pals and has become a school dropout. People mocked her and stared at her, blaming her with the aid of announcing that she may have executed something to earn the man's wrath. She spent eight years hiding her face. But she won braveness while India exploded within the outrage over a gang rape on a bus closing year. She without delay filed a PIL and sought a ban on the sale of poisonous beverages. Under large pressure the Government handed a regulation that for the first time created criminal costs specially for stalking, voyeurism, acid assaults and forcible public disrobing of women, an act once in a while performed in rural regions to motive humiliation. Under the new regulation, someone convicted of an acid assault faces at least ten (10) years and a most life sentence.

**Sandra Neumann (2013)** - In her proposition titled The Issue of Sexual Violence against Women in Contemporary India. featured a portion of the fundamental components of expanded revealing of sexual brutality in India. Studies have been directed during the most recent decades in regards to basic variables for sexual brutality against ladies in India. A portion of these basic elements are; a culture that endorses viciousness, liquor, experience of maltreatment as a youngster, destitution, and fast financial changes.

**Population board (2016) in the paper Reducing Violence Against Women and Girls in India** talk about the **Do Kadam** task of populace committee for testing methodologies to decrease the pervasiveness and acknowledgment of private accomplice savagery against ladies and young ladies.

The Government of India has focused on killing savagery against ladies and young ladies through various arrangements, laws, and projects, yet one of every three ladies matured 15–49 encounters some type of physical or sexual brutality during her lifetime.

Through **Do Kadam: Barabari ki Ore** (In Step: Towards Equality), the Council and its accomplices are creating a more noteworthy comprehension of savagery against ladies and young ladies, creating and assessing projects to forestall it, and evaluating the viability of administrations gave by an administration run helpline, emergency focuses, and protects for ladies who have encountered brutality. Preceding propelling intercessions and surveying administrations for ladies in trouble, the

Council and its accomplices inspected the worldwide proof on best practices to forestall savagery.

### Research Methodology

**Presentation:** Procedure is the efficient, hypothetical investigation of the techniques applied to a field of study. It contains the hypothetical investigation of the assortment of techniques and standards related with a part of information. Regularly, it includes ideas; for example, worldview, hypothetical model, stages and quantitative or subjective techniques.<sup>2</sup> the current examination likewise were completed with the assistance of methodical examination and logical strategy has additionally been applied. Different strategies and methods have been utilized to finish introduced study. The current part manages the techniques and devices utilized in this exploration venture.

**Title of Study -** Handling Violence against Women: A Study of State Intervention Measures

**Point -** The examination planned for reporting the adjustments in enrolment of the instances of viciousness against ladies after the approach level changes particularly before after 2013 and to contrast the national situation related with the brutality against ladies from low and high predominance territories.

### Targets :

1. To embrace relative investigation of the approaches confined on State reserves/developers like Nirbhaya Fund for examination regarding their usage extension and constraints and so forth.
2. To investigation the realities in execution and usage of these arrangements in High and Low commonness locale from states chose.
3. To distinguish the Gaps and to Scale up of the best advancements in the arranging and execution of these approaches.
4. A near investigation of effect of new laws, crime percentage and announcing rate, change in mindfulness level.

### Center Areas of Study :

1. The examination on viciousness against ladies has expansive comprehension. As given in the greeting three regions will be engaged: - a) Sexual Violence, b) Communal Violence, c) Sectarian Violence
2. The nature of such occurrences is extremely questionable and dubious. The Study will discover number of individuals enrolled and FIRs stopped. For the most part, the realities are not uncovered from the outset hand however need to secure for the strategy. Accordingly, the partners assume significant job in such cases, for example, – Police Stations, Government Social Cells, Counseling Centers, Voluntary Organizations, Medical and Legal Practitioners. The current job of these organizations in such cases and operational rules will be proposed.
3. Study will think about assembly of administrations in the States for better administrations and effects on the ladies casualties.

4. The investigation will likewise kind of well known answers for the issue, different administrations in activity and restoration rates to catch the accepted procedures.

**Methods & Tolls of data Collection -** This study has been completed with the data from both primary and secondary source. The details of the methods and techniques of data collection for this study have been mentioned below.

**Primary Source of Data -** The data from primary source has been collected with the help of interview method. For conducting the interviews of various types of respondents, the six types of structured interview schedules were specially developed.

**Secondary Source of Data -** For collecting the data from the secondary sources a check list was prepared. And the data have been collected from the books, journals, magazines, newspapers, and internet.

**Data Processing and Analysis -** As the study was purely quantitative in nature hence the data has been processed using SPSS. The expert professional help has been taken for that. The Editing, Numbering, Classification, Coding, Data definition file preparation, Data Entry and Analysis steps has been followed. To understand the data more in depth the central tendency has also been calculated. As it was non-probability sample based study hence measures of associations and mean differences has not been calculated as it was not applicable.

### Limitations of the study :

1. The geographical area of the study is large and the number of sample contributed data is in small number in respect to size of universe hence there is limitations in generalizing the findings to the larger universe.
2. The study has been conducted in four states and only two districts have been covered from each state hence there is no representation from the entire district. The study also has covered only four states hence there is also not the representation from all the states hence here also the findings of the study becomes limited.
3. The study is based on non-probability sampling method hence there is no proportionate or equal representation from all the district and state covered by this study hence this study also gets limited here.
4. The study is conducted on the violence against women in India. It was aimed to study the situation, prevalence and lodging the complaints by victims in case of rape, acid attack, molestation etc. Following the incident in 2012, the Govt. set up the NIRBHAYA fund. The funds are mainly used for prevention strategies.
5. The time for conducting the study was short and the subject was very vast.
6. It was very difficult to make departments understand the importance of the study. They took very long time to provide data.
7. There are different patterns of funding in States; they have developed their own funds for the same.
8. RTI application has been filed for getting data. So, it is dependent on the systems for data collection. It was



difficult to get statistics from police station.

**Provisions Under The New Domestic Violence Law -** PWDVA is a comprehensive law and it addresses all issues related to women in the domestic sphere. It is for the first time that an act has been made to address women's issues in such detail.

The act has categorized 'domestic violence' into four categories, namely

- a) physical,
- b) sexual,
- c) verbal & emotional, and
- d) economic violence, and attempted to define such violence comprehensively.

The law also makes a provision for positive entitlements under sections 20 and 22 through an interim monetary relief order related to

- (a) Maintenance for the victim or her children,
- (b) Compensation for physical injury including medical expenses,
- (c) Compensation for mental torture and emotional distress,
- (d) Compensation for loss of earning,
- (e) Compensation for loss caused by destruction, damage, removal of any property from her possession or control.

**Study area and participants -** I choose 4 area including Chhatarpur namely Chhatarpur now gong mahusania and harpalpur. Of these four regions, three areas were selected to have a wider representation of the zone. The population of these states was 5 laky, 2.5 lakh , 2 lakh, 3 lakh in the year 2011 . This study was a cross-sectional study. The participants were both men and women. The study involved collecting quantitative data through structured questionnaires. The questionnaire for women included items on socio-economic details and domestic violence experience. To assess domestic violence exposure, women were asked several questions on various behaviors of violence.

The questionnaire for men included similar questions about his perpetration of violence against his wife. A multiphase process was used to develop these questionnaires to ensure that it was culturally and linguistically appropriate. These questionnaires were prepared initially in English and translated into the languages of the study areas. In addition, piloting provided practice to the research staff, which collected data using these questionnaires.

All the interviews were held in local language of the areas . Interviews took place in a private place in or outside the respondents' home, and care has been taken to avoid presence of other family/community members during interviews. Women and men were interviewed by women and men investigators, respectively. Individual verbal informed consent was obtained from all participants by explaining the purpose of the study. These field works were carried out during January -February 2020.

**Sampling -** The sample size was calculated based on the

available estimated prevalence of domestic violence for these states . Based on the prevalence of domestic violence, with a confidence level of 95% and absolute precision of 0.05, the samples required were: 450 women for Chhatarpur , 740 women for harpalpur and 480 women for mahusania. Same sample sizes were considered for men sample. Keeping in view of 70:30 ratio of rural and urban population, the samples were distributed accordingly. From each district allocated for urban sample, an urban area (a city or a town) was selected. In each urban area, sixteen pockets belonging to different socio-economic strata were identified. These strata were high-income group, middle-income group, low-income groups and slums and were identified based on the information obtained from the local key-informants and physical appearance of housing. Of these 16 pockets, eight (two each from each stratum) pockets each were allotted to sample male and female participants. Thus, from each area 4 villages and 2 urban pockets were chosen for sampling of female and male participants.

After selecting the village/urban pocket, the research team met village/community heads and elders before initiating the data collection, and the purpose of the survey was explained. Rapport is established with the community and especially the women were taken to the confidence. The sample to be collected from each village was determined by dividing total rural sample required for that state by total number of villages (eight). In each village, eight random points were identified from all corners and care has been taken to include all communities. From each point, required number of sample was collected from households spread in four directions of the point. Similarly, in each urban pocket, participants were selected from the households spread in all the four directions.

**Measurements & Outcome variables -** Three principle domestic violence outcome variables considered in our analysis are: physical violence, psychological violence and sexual violence. They were determined by response to a set of questions for each outcome variable. If a woman (as a victim)/man (as a perpetrator) gave a positive response to any of the questions in a set, it is considered as violence of that category. The questions used for women and men were listed in Annexure 1a and 1b, respectively in Additional file 1. In addition, the fourth variable, i.e. any form of domestic violence was derived. If at least one of the three forms of domestic violence (physical and/or psychological and/or sexual) was present, it was considered as the presence of any form of domestic violence. During logistic regression analyses, these outcome variables were dichotomized into presence and absence of violence, for each type of violence.

**Socio-economic variables -** Data were collected on a number of community-level and individual-level variables that have been linked to domestic violence. The community-level variables included are the residence, residence (living in rural or urban), religion (Hindu, Muslim, Christian

or any other religion) and caste. During the survey, individual caste of the respondent was collected and they were categorized subsequently during analysis. The Government of India had categorized some ethnic groups (castes and tribes) into scheduled castes, scheduled tribes and backward castes. The uncategorized castes, which form the majority of the population, are often referred to as forward castes. The individual-level variables were: age in years (which was categorized into individuals less than 20 years of age, those between 20 and 29 years, and those above the age of 30 years), education, which was categorized into illiterate, functional literate (those who can read or write, but did not have formal schooling), school education (1–10 years of schooling) and, college education and above (those having more than 10 years of education). The occupation of the participant was recorded and the responses were categorized into salaried jobs, farming and small business, laborer, housewives and other occupations. The monthly income of the family was calculated during data analysis based on the information collected on income of all members as well as from common sources of the family. The income details were collected in Indian Rupees (INR). The age was taken as continuous variable.

**Discussion** - In the present study, women reported as high as 56% of some form of violence against them in Eastern part of India. The levels of physical, psychological and sexual violence against women were also considerably high. These data along with the world-wide literature confirm that domestic violence is a universal phenomenon existing in all communities. Also, it is confirmed that women were at more risk of violence by their husband than any other perpetrator. However, these figures should be understood cautiously as some of the behaviors considered as violent behavior (such as coerced sex by husband-husband having sex with his wife when she is unwilling) may not be perceived by either partners or people as being inappropriate or wrongful. However, irrespective of the people's perceptions, these behaviors have influence on both physical and mental health of women.

This study, along with the domestic violence rates based on the reporting of women, presented the prevalence of domestic violence reported by men, as perpetrator. These rates are in corroboration with those reported by women. Almost all research on domestic violence has relied on women's rather than men's report of their experiences. In the present socio-cultural context, the initiator for sex is usually the husband. To larger extent, sex remained as a hidden subject of discussion even between wife and husband; and women are not expected to express their desire. Recently, India, through the Protection of Women from Domestic Violence Act of 2005, recognized different forms of physical, sexual, verbal, emotional or economic abuse as domestic violence. Under this act, rape within the marriage is considered as a crime.

**Conclusion from my observation** - The study confirms the high prevalence of all forms of violence against women

across all socio-economic settings in this selected as well as all other part. However, urban residence, older age, lower education and lower family income are associated with occurrence of domestic violence. Women are at risk of violence from the husband than any other type of perpetrator. This situation has public health implications as public health can have a role in preventing the violence and its health consequences. Also, the primary healthcare institutions in India should institutionalize the routine screening and treatment for violence related injuries and trauma. These results also provide vital information to assess the situation to develop interventions as well as policies and programmes towards preventing violence against women. As India has already passed a bill against domestic violence, the present results on robustness of the problem will be useful to sensitize the concerned agencies to strictly implement the law.

**Conclusion** - It is quite clear from the foregoing discussion that mere presence of acts in the law books is not enough to curb the crime, unless affirmative actions are seriously initiated. Enactment of a law for dowry prohibition or restricting cruelty at matrimonial home could not change the attitude of a large number of men and women, socialized in a patriarchal culture. Similarly, success of the new Domestic Violence Act is also dependent on the attitudinal change in society. In this context, civil society has a critical role to play. In a country where women are socialized to consider marriage as 'essential' and domestic violence as 'normal' for the sake of her own and children's interest, the recent act may not particularly help those majority who often fail to recognize even their basic human rights. Furthermore, the dwindling rate of conviction ranging between 15 and 32 per cent in the domestic violence and dowry related cases is discouraging to those who hope for justice.

It is a fact that even educated and resourceful women have to run from pillar to post to get justice. Hence there remains serious concern about how the new law may be made effective to provide much needed justice to women coming from weaker sections. The stakeholders should generate motivation in public mind to abide by the laws, seek legal redress whenever required and stand by the suffering of women, apart from improving the infrastructure for the justice-delivery system. It is high time for the lawmakers, seeking to protect the rights of women in the domestic sphere, to create appropriate institutions and mechanisms to realize the cherished goal. Since Independence, we have witnessed a lot of official commitment to the cause of women in the form of a law drafted with all good intentions. But our experience tells us that all these are mere palliatives rather than curing the malady. The problem of dowry and domestic violence cannot be tackled without addressing the basic question of power inequality under patriarchy.

#### References :-

1. Caplan, Lionel. 2000. 'Bridegroom Price in Urban In-

- dia: Class, Caste and 'Dowry Evil' Among Christians in Madras', in Patricia Uberoi (Ed.), *Family, Kinship and Marriage in India* (357-79). New Delhi: Oxford University Press.
2. Chowdhary, Manjaree. 1998. Miles to Go: An assessment of the enforcement hurdles in the implementation of the anti-dowry law in India', in Werner Menski (Ed.), *South Asians and the Dowry Problem* (151-162). Vistaar Publications: New Delhi
  3. 2011, Child Marriage, Society and the Law: A Study in a Rural Context in West Bengal, India', *International Journal of Law, Policy and the Family*, 25 (2): 199-219.
  4. Ray, Sawmya. 2006. Legal Constructions of Domestic Violence', *Sociological Bulletin*, 55 (3), September-December: 428-9.
  5. The Times of India. 2018. Bahu Can't claim in-laws' property: HC', August 11, Page 9, Kolkata edition.
  6. Saunders, Kriemild. 2004. *Feminist Post-Development Thought*. London: Zed Books
  7. Martin SL, Tsui AO, Maitra K, Marinshaw R: Domestic violence in northern India. *Am J Epidemiol*. 1999, 150: 417-426.
  8. Duvvury N, Nayak M, Allendorf K: Domestic Violence in India 4: Exploring Strategies, Promoting Dialogue. Men Masculinities and Domestic Violence in India: Summary Report of Four Studies. 2002, Wasington, D.C., International Centre for Research on Women
  9. Hassan F, Sadowski LS, Bangdiwala SI, Vizcarra B, Ramiro L, De Paula CS, et al: Physical intimate partner violence in Chile, Egypt, India and the Philippines. *Inj Control Saf Promot*. 2004, 11: 111-116. 10.1080/15660970412331292333.
  10. International Clinical Epidemiological Network: Domestic Violence in India: A Summary Report of a Mutlti-Site Household Survey. 2000, Washington, D.C., International Centre for Research on Women and the Centre for Development and Population Activities, Ref Type: Report
  11. Jeyaseelan L, Kumar S, Neelakantan N, Peedicayil A, Pillai R, Duvvury N: Physical spousal violence against women in India: some risk factors. *J Biosoc Sci*. 2007, 39: 657-670. 10.1017/S0021932007001836.

\*\*\*\*\*

## वैश्विक महामारी संकट और मानवाधिकारों का बदलता परिदृश्य

**डॉ. भारती लुणावत \***

**प्रस्तावना** – आज एक अदृश्य वायरस कोविड 19 से संक्रमण के बचाव हेतु वैश्विक प्रयास निष्फल साबित हो रहे हैं। कोई नहीं जानता यह महामारी कितने और समय तक रहने वाली है तथा विश्व के कितने मनुष्यों और मानवता को प्रभावित करने वाली है। पूरी वैश्विक आधुनिक सभ्यता इसके निदान और निराकरण हेतु आज सामूहिक प्रयासों हेतु प्रतिबद्ध दिखाई पड़ती है, किंतु इसी बीच राजनीति विज्ञान की एक प्रमुख अवधारणा 'मानवाधिकार' आज आधुनिक विश्व सभ्यताओं के इन सामूहिक प्रयासों के तले दम घुटने को मजबूर हो चुकी है।

जहां कुछ समय पहले तक एक मनुष्य के मनुष्य होने के नाते, उसे गरिमामय जीवन प्रदान करने के नाते जो अधिकार दिए जाते हैं, उन मानवाधिकारों का संरक्षक पूरा विश्व था, किंतु विडंबना देखिए आज विश्व मानवता इन मानवाधिकारों को रौंदकर ही सभ्यता को विनाश से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मनुष्य की निजता और उसके विचारों को केद रखना, उसे निश्चित आजीविका प्रदान करना, भरण-पोषण की व्यवस्था करना, उसकी शिक्षा, कृषि, व्यवसाय, उद्यमों का संरक्षण करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य था, और आज सारी आधुनिक सभ्यता ही मिलकर मनुष्य के इन सभी मानवाधिकारों को मनुष्य के ही जीवन की रक्षा के लिए कुचलने को बेबस है।

इसी को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में किस प्रकार से मानवाधिकारों के विभिन्न मुद्दों का किस किस रूप में उल्लंघन हुआ है जिन से बच पाने के लिए स्वयं मानवता भी अक्षम सिद्ध हो रही है, उनका संक्षिप्त विवेचन इस शोध पत्र में किया गया है। शोध पत्र का उद्देश्य यह है कि महामारी के इस काल में भी किस प्रकार से सरकार और प्रशासन मानवाधिकारों के प्रति सचेत रहें किस प्रकार से मनुष्य के जीवन को बचाते हुए उनकी जीवन उपयोगी आवश्यकता को पूर्ण कर सकें। उक्त शोध पत्र में विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार एवं आलेखों का विस्तृत अध्ययन कर चिंतन किया गया है।

महामारी के संक्रमण के दौर में मानवाधिकारों की स्थिति क्या है इसे समझने के लिए निम्न विचार प्रकट होते हैं

1. विश्व के अरबों लोग अब स्वतंत्रता ही चाहते ,उन्हें घर में कैद कर दिया जाना आवश्यक है ताकि वे इस अदृश्य वायरस की चपेट में आने से बच सकें ।
2. विश्व के करोड़ों लोग अब घूमने फिरने की आजादी से विमुख हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर प्रमुख उड़ानसेवाएं अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय और घरेलू प्रमुख बस मार्ग यहां तक कि भारत जैसे विशाल देश की हजारों ट्रेनों का परिचालन बंद हो चुका है ।
3. आप यदि घर से बाहर निकलने का छोटा सा भी प्रयास करते हैं तो

प्रशासन अपने डंडे के जोर पर आपको घर के अंदर बैठने को मजबूर कर देने के लिए लालायित है।

4. मानवाधिकारों की विडंबना देखिए कि आज विश्व के मानवों की अपेक्षा प्रकृति के पशु और पक्षियों, जीव और जंतुओं को अधिक स्वतंत्रता और स्वच्छंदता प्राप्त हो गई है। विश्व के करोड़ों मनुष्य चिड़ियाघर में बंद उन निरीह पशु पक्षियों की भांति हो गए हैं जो अपने घर की वैभव पूर्ण अट्टालिका या छोटी -छोटी गैलरियों से घर के अंदर से झांक झांक कर बाहर के परिदृश्य का नजारा देखने के लिए केवल उत्सुक हैं ।
5. प्रकृति ने मनुष्य सभ्यता को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है, कि मानवाधिकारों से संबंधित सारे प्रश्न गौड़ हो चुके हैं ,वास्तव में आज मनुष्य की जान बचाना ही प्रमुख उद्देश्य है और मनुष्य के सारे मानवाधिकार दोराहे पर खड़े नजर आ रहे हैं।
6. कहां है वे मानवाधिकार जो मनुष्य की गरिमा और उसे स्वतंत्र और स्वच्छंद विचरण करने का अधिकार देते हैं।
7. कहां है वे मानवाधिकार जो मजदूरों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर कर देते हैं जबकि आज विश्व सभ्यता में एक से एक आधुनिक वाहनों का बोलबाला है।
8. कहां है वे मानवाधिकार जो भारत जैसे खाद्यान्न में आत्मनिर्भर देश के नागरिकों को भी दो वक्त की रोट प्रदान नहीं कर सकते।
9. कहां है मानवाधिकार जो एक कार्य करने वाले मजदूर, एक फसल उगाने वाले किसान, एक नवोन्मेषी उद्यमी को एक साहसी को उसके उद्योग, उसके कार्यस्थल पर जाने से रोक रहे हैं। कहां है वे मानवाधिकारों जो स्वतंत्र विश्व व्यापार की बात करते हैं।

यही सब बातें एक अदृश्य वायरस के कारण उस वायरस से भी अधिक सूक्ष्म हो चुकी हैं, किंतु फिर भी मानवाधिकार तो मानवाधिकार है। युद्ध काल में भी मानवाधिकारों का ध्यान रखा जाता है। चाहे यह युद्ध विश्व मानवता का इस अदृश्य वायरस के विरुद्ध है, किंतु इस युद्ध में भी मानवों की गरिमा, मनुष्यों की भूख, मनुष्यों के छोटे-छोटे बच्चे, स्त्रियों के मानवाधिकारों, आदि की हर संभव रक्षा का प्रण भी सरकार को करना चाहिए। जीवन के संकट के इस दौर में मानवाधिकारों को बचाने की जद्दोजहद किस हद तक कमजोर पड़ चुकी है यह प्रवासी मजदूरों, गरीब एवं निम्न वर्ग की वर्तमान स्थिति को देखकर पता चलता है। लॉक डाउन के प्रथम चरण में ही हजारों प्रवासी मजदूर विशेष रूप से बिहार एवं उत्तर प्रदेश से आने वाला गरीब तबका जो कि मुंबई, दिल्ली एवं अन्य महानगरों में अपने दैनिक मजदूरी के कार्यों से संबंधित रहता है और जो छोटी -छोटी दुकानों, रेहड़ियों, ढाबों एवं होटलों में कार्य करता है, उन सभी के लिए जीवन और आजीविका का



संकट उपस्थित हो गया है, और इस संकट से निपटने में सभी राज्यों की सरकारें असफल दिखाई दे रही हैं। लॉक डाउन के द्वितीय चरण में भी मुंबई, दिल्ली से कई मजदूर पैदल सुदूर गांव की ओर पलायन करते दिखाई दिये। इन गरीब और निम्न वर्गों के जीवन और आजीविका के मानवाधिकारों का क्या होगा या भविष्य के गर्त में छुपा है।

मानवाधिकारों का संकट उन लोगों के लिए भी उपस्थित हो गया जो लोग जीवन के इस संकट से लोगों को बचाने के लिए सबसे आगे की पंक्ति में साहस के साथ खड़े हुए हैं। इनमें प्रमुख रूप से देश के डॉक्टर एवं अन्य चिकित्सा स्टाफ शामिल हैं। कोरोना वायरस संक्रमण का सबसे पहले सामना इन्हीं लोगों का हुआ किंतु यह स्वयं को संक्रमित होने से नहीं बचा सके क्योंकि देश में चिकित्सा से संबंधित सुविधाओं का अभाव है। आज भी चिकित्सा स्टाफ को हम पर्याप्त PPE Kit एवं अन्य सुरक्षा उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे हैं। इसी का परिणाम है कि कोरोना संक्रमण में वृद्धि के आंकड़ों में कई डॉक्टरों के नाम भी शामिल रहे।

इसी क्रम में लॉक डाउन का पालन करने के लिए दिन रात सड़कों पर जुटे पुलिसकर्मियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के भी जीवन का अधिकार असुरक्षित हो गया, जब वे स्वयं संक्रमित इलाकों में जाने के कारण इस वायरस से संक्रमित हो गए। मध्य प्रदेश में ही कई पुलिस अधिकारी अपनी जान गवा चुके हैं एवं कई प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य सहायक स्टाफ वायरस से संक्रमित पाए गये हैं।

महामारी संक्रमण के कारण हम अपने सफाई कर्मचारियों को भी सुरक्षित नहीं रख पाए हैं क्योंकि इस समय सफाई एवं सैनिटाइजिंग का कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है, किंतु इस हेतु तकनीकी एवं पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों की अपर्याप्तता के कारण कई सफाई कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को भी संक्रमण का सामना करना पड़ा है।

कोरोना संक्रमण के प्रसार के प्रारंभ से ही शिक्षण संस्थानों को पूरी तरीके से बंद करने का फैसला लिया गया। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा एवं विद्यालय एवं विश्वविद्यालयीन परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। ऐसे में विद्यार्थियों का एक बड़ा वर्ग चिंतित है कि किस प्रकार से अपने पाठ्यक्रम पूर्ण कर पाएंगे विशेष रूप से तकनीकी पाठ्यक्रम जो पूर्ण रूप से अधूरे हैं। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर पुनः प्रारंभ होने में अभी अत्यधिक समय लगने की आशंका है। ऐसे में युवा वर्ग का भविष्य असुरक्षित है। कोटा, दिल्ली एवं जयपुर जैसे क्षेत्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग संस्थानों एवं उनसे संबंधित तैयारी करने वाले छात्रों से भरे होते थे, वहां से राज्यों की सरकारों ने अपने छात्रों को निकाल कर सुरक्षित घर पहुंचा दिया है। अब आगे की भविष्य की रणनीति में किस प्रकार से पूरी कर पाएंगे यह निश्चित नहीं है।

मनुष्य का एक महत्वपूर्ण अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित होता है किंतु संकट के इस दौर में अंतःकरण धर्म पूजा एवं उपासना आदि के अधिकार गण हो चुके हैं। जहां नवरात्रि के दौरान अधिकांश मंदिरों के दरवाजे अपने भक्तों के लिए बंद हैं, वहीं रमजान जैसे महीने में भी मस्जिदों में नमाज प्रतिबंधित है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर सहित भारत के समस्त गुरुद्वारे, इसाई गिरजाघर एवं अन्य धार्मिक स्थल आज सूने हैं। प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा को भी स्थगित करने का निर्णय लिया गया है, बद्दीनाथ अमरनाथ जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिर अपने कपाट खुलने का इंतजार कर रहे हैं।

सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जीवन एवं गरिमा का अधिकार है। किंतु वर्तमान दौर में महामारी के संक्रमण के कारण मृत शरीर भी अंतिम संस्कारों

एवं गरिमामय तरीके से अंतिम यात्रा का अधिकार नहीं रह गया है।

विदेशों में ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से शव परिजनों को नहीं दिया जाकर अपने स्तर पर उनका अंतिम क्रिया सम्पन्न कराई जा रही है। स्पेन और इटली में तो ऐसी भयावह तस्वीर सामने आ रही है जिसमें शवों को सड़कों के किनारे एवं पार को परिजनों द्वारा छोड़ा जा रहा है।

विश्व में गरीबी के आंकड़े भयावह रूप से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व के कई देशों में महामारी के संक्रमण के पश्चात अकाल एवं भुखमरी की संभावना है। एशिया और अफ्रीका के कई गरीब राष्ट्रों में लगभग 26.5 करोड़ भुखमरी से प्रभावित होंगे। ऐसे में इन देशों में मानवाधिकारों से संबंधित संकट भी उपस्थित होगा।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवाधिकार व्यक्ति के जीवन की रक्षा है। जिसमें संपूर्ण मानवता, विश्व के सभी देश अपने समस्त हर संभव प्रयास कर सारे संसाधनों को झोंक रहे हैं, किंतु यह भी देखा जाना चाहिए कि एक युवा के जीवन का भी उतना ही अधिकार है जितना एक वृद्ध का संसाधनों की कमी के कारण उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। अमीर एवं संभ्रांत लोगों के भी मानवाधिकार उतने ही आवश्यक हैं जितने की एक गरीब, मजदूर वर्ग और दिहाड़ी का कार्य करने वाले व्यक्ति के, इसलिए उसे सड़कों पर भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। यह याद रखना चाहिए कि किसानों के भी मानवाधिकार हैं, उनकी पकी हुई फसलों को सड़ने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता।

मानवाधिकार रेंदे जाने के इस समय काल में एक और अदभुत विडंबना सामने आई है। कुछ समय पूर्व तक यह देखा जा रहा था की स्त्रियों के मानवाधिकारों और बच्चों के मानवाधिकारों निरंतर संकट में थे। महिलाओं और बच्चों पर अपराधों का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा था। चोर, हत्या, बलात्कार अन्य अपराधों से पूरा वैश्विक समाज चिंतित था। पर्यावरण प्रदूषण के कारण मानव सभ्यता अपने मूल अधिकार स्वच्छ प्रकाश, स्वच्छ हवा, स्वच्छ जलवायु, स्वच्छ नदियों, स्वच्छ सागर के जल से वंचित थी, किंतु विडंबना देखिए, यदि इस महामारी संक्रमण के पिछले कुछ महीनों का आंकलन करेंगे तो मनुष्य के मानवाधिकारों पर चोट करने वाले इन सभी लक्षणों का आंकड़ा शून्य से 5 % तक ही रह गया है। महामारी से बचाव के दौरान दुनिया तेजी से परिवर्तित हो रही है। पृथ्वी की जलवायु ने अपनी रिपेयरिंग स्वतः कर ली है। नदियों का जल स्वच्छ हो गया है, जो इटल की नहरे गंदे नाले में परिवर्तित हो गई थी उनमें तल तक स्वच्छ जल देखा जा सकता है। यमुना और गंगा जैसी नदियों में करोड़ों रुपए खर्च करने के उपरांत भी जो सफाई नहीं हो सकी वह मनुष्यों के आगमन को प्रतिबंधित कर देने के कारण कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वच्छ हो गई है। वायु इतनी साफ है, प्रकाश इतना स्पष्ट है कि जालंधार जैसे शहर से 200 किलोमीटर दूर हिमालय की धोलावाड़ चोटियां स्पष्ट नजर आने लगी हैं तो इस विडंबना को क्या कहा जाए।

निष्कर्षतः कोरोना वायरस की महामारी से उपजे संकट के दौरान यद्यपि संपूर्ण राज्यों की सरकारों का एक ही लक्ष्य है, व्यक्तियों का जीवन बचाना किंतु यह भी महत्वपूर्ण है इस उद्देश्य को पूरा करने में कही मानवाधिकारों का दायरा बहुत अधिक पीछे न हट जाय। मनुष्य के जीवन के साथ ही जीवन की गरिमा भी आवश्यक रूप से बनाए रखी जानी चाहिए। ना केवल उसे जीवन के संकट से निकाला जाना चाहिए बल्कि आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक दबावों से मुक्त किया जाना भी आवश्यक है।

एक बात स्पष्ट है कि इस महामारी से युद्ध के दौरान भी मानवाधिकारों का उल्लंघन किंचित भी नहीं होना चाहिए। मनुष्य की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है, उसके जीवन की रक्षा के लिए उसे घर में बंद किया जा सकता है, इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों को अलग-थलग किया जा सकता है, कुछ लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से अलग रहने के लिए मजबूर किया जा सकता है। मनुष्यों को बाहर घूमने फिरने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पूर्ण पाबंद लगाई जा सकती है, किंतु ऐसे में उसकी गरिमा, उसके जीवन का सम्मान करना मानवाधिकारों की दृष्टि से आवश्यक है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण इस महामारी में गरीबों एवं दिहाड़ी मजदूरों को सड़क पर नहीं छोड़ा जा सकता यदि एक भी व्यक्ति आज उसकी दो जून की रोटी कमाने में असमर्थ रहता है तो ऐसे में संपूर्ण मानवता, संपूर्ण प्रशासन का लक्ष्य होना चाहिए कि भारत और विश्व की लगभग आधी आबादी जो इस महामारी से संक्रमण काल में अपने जीवन को बचाने के साथ ही भविष्य की पूर्तियां करने में अक्षम होने

की संभावना से चिंतित है जिनके पास आज अपने और अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए आवश्यक संसाधन नहीं हैं, उनकी उचित पूर्ति करना ही आज मानवाधिकारों का सर्वोच्च और अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। साथ ही कुछ महीनों के उपरांत जब इस महामारी से निपटने में वैश्विक समुदाय को सफलता प्राप्त होगी उसके पश्चात मानवाधिकारों से निपटने का असल चेहरा सामने आएगा। देखना होगा कि किस प्रकार से सरकार तब मनुष्य के मानवाधिकारों का, उसके जीवन की गरिमा का, उसकी आर्थिक स्थिति का, उसके भविष्य की चिंताओं का कितना समाधान कर पाती है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ई जनसत्ता 5 अप्रैल 2020
2. ई दैनिक जागरण 6 अप्रैल 2020
3. ई पान्चजन्य 19 अप्रैल 2020
4. ई इंडिया टुडे अप्रैल 2020
5. दैनिक भास्कर अप्रैल 2020

\*\*\*\*\*

## वर्तमान परिदृश्य और पत्रकारिता

**डॉ. अनुसुइया अग्रवाल, डी.लिट्.\***

**प्रस्तावना** – पत्रकारिता संप्रेषण की एक कला है। अपने विविध आयामों के माध्यम से विचारों एवं अभिव्यक्तियों को सरलता से संचार करने का श्रेय पत्रकारिता को है। यह मानव को निरन्तर संदेश देने वाली एक विलक्षण विधि है। रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर के अनुसार- 'ज्ञान और विचार, शब्दों तथा चित्रों के रूप में दूसरे तक पहुँचाना ही पत्रकला है।' इसे एक वैज्ञानिक पद्धति भी कहा जा सकता है जो सुदूर विश्व की समस्त गतिविधियों और क्रियाकलापों से जनसाधारण को अवगत कराती है। एक देश की सभ्यता और संस्कृति को दूसरे देश में ले जाने का कार्य पत्रकारिता को ही जाता है। यह अपने भीतर शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति, विज्ञान आदि सबको समेटे हुए है इसलिए यदि कहें कि पत्रकारिता विविध शक्तियों का समूह है तो गलत नहीं होगा। इन्द्र विद्यावाचस्पति लिखते हैं- 'पत्रकारिता पाँचवा वेद है जिसके द्वारा ज्ञान- विज्ञान संबंधी बातों को जानकर हम अपने बंद मस्तिष्क को खोलते हैं।' पत्रकारिता पूरी निर्भीकता, ईमानदारी और स्वतन्त्रता से कार्य करने वाली सत्य का अन्वेषक है। इसके माध्यम से समाज में निर्भीकता, स्पष्टवादिता है।

पत्रकारिता राष्ट्रीय चेतना की वाहक है। आज यह समूचे राष्ट्र के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य कर रही है। वर्तमान में पत्रकारिता सूचनाओं और समाचारों का संकलन मात्र न होकर मानव जीवन के व्यापक परिदृश्य को अपने भीतर समेटे हुए है। जीवन के आस- पास की वास्तविकता अथवा सूचना; जिसका संबंध मानव- जीवन से है; को ही समाचार का रूप देकर पाठकों तक पहुँचाने का कार्य पत्रकारिता करती है। हमारे जीवन में प्रतिदिन कुछ न कुछ सामान्य अथवा असामान्य रूप से घटता रहता है; इन्हीं घटनाओं में से मनुष्य की जानकारी अथवा दिलचस्पी के लिए कुछ का विवरण या वर्णन समाचार पत्र में दिया जाता है। ताकि जनसमुदाय को घटनाओं से अवगत कराया जा सके। उन घटनाओं के संबंध में उसकी राय जानी जा सके। उनके उचित- अनुचित के विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाते हुए उन्हें उचित का समर्थन तथा अनुचित के विरोध के लिए प्रेरित किया जा सके। इस आधार पर इसे दैनिक घटनाओं का छायाचित्र भी कहा जा सकता है जो संक्षेप में विविध विषयों की जानकारी प्रस्तुत करता है किंतु सामान्य घटनाएँ, सूचनाएँ या क्रियाएँ समाचार नहीं बनती; उसका विशेष प्रयोजन या संदर्भ होना आवश्यक है। अमेरिकी पत्रकार वाल्टर लिपमैन के अनुसार- समाचार का मुख्य कार्य किसी घटना को चित्रित करना है किसी सत्य को चित्रित करना नहीं। पत्र का कार्य किसी घटना के रहस्य को उजागर करना है। प्रेस का मुख्य कार्य घटनाक्रम को यथातथ्य रखना है। यह सर्चलाइट के समान विभिन्न घटनाओं पर रोशनी डालता है तथा उन्हें उजागर करता है। आज यह कार्य जटिल, चुनौतीपूर्ण तथा व्यवसायिक हो चला है। क्योंकि समाचार

लेखन और सत्य का उद्घाटन एक ही बात नहीं है। कभी- कभी समाचार सच्चाई को उजागर करता है तो कभी- कभी उस पर पर्दा भी डाल देता है। पत्रकार अरुण शैरी के शब्दों में- 'पत्रकारिता का मूल सरकार है। उसकी सामग्री का स्रोत सरकार है। तथा उसका पाठक भी सरकार है। सफल पत्रकार वह है जिसके अच्छे जनसंपर्क हैं तथा जो सरकार द्वारा दिये गये प्रेस नोट को शीघ्रता से बिना विचार किये प्रकाशित कर देता है।'

इस तरह पत्रकारिता संप्रेषण की एक कला है तो प्रेस वाक् एवं अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है जो आज राष्ट्र के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य कर रही है। विचारों एवं जनहित से जुड़े संदेशों को सरलता से संचार करने यानि जन- जन तक पहुँचाने का श्रेय प्रेस को ही जाता है।

आज जब देश भर में कोरोना वायरस ने तेजी से फैलकर भयानक संकट उत्पन्न कर दिया है। कोरोना, लॉकडाउन और भविष्य को लेकर अनिश्चितताएं हम सभी के लिए तूफान बनकर आई हैं। इस आपातकाल में जब बाहर- भीतर सन्नाटा सा पसरा हुआ है; तो अखबार ही है जो हर सुबह.....सूरज की पहली किरण के साथ.....मन के भीतर पसरे भयानक संशय रूपी अंधकार और सन्नाटे को तोड़ता हुआ स्पन्दन और जीवन का संदेश देता हृदय को आशान्वित करता रहा। अभी तक सभ्यता और संस्कृति के संवाहक के रूप में इसे जाना जाता था जो शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान आदि को अपने भीतर समेटे था किंतु अब सर्तकता, सावधानी, समझदारी से किस तरह अपने; फिर घर- परिवार, समाज, प्रांत और देश को सुरक्षित रखा जा सकता है....यह दायित्व बोध कराता गतिमान रहा पत्रकारिता का दिव्य अश्व। मानों घर का कोई बड़ा- बुजुर्ग, सियान बड़ी सुबह हमारे पास आकर हमें पुचकार जाता हो, भय मुक्त कर जाता हो, जीने की आस दे जाता हो, हमारे सिर पर अपना आशीर्वाद रख जाता हो। हमारे डरे, सहमें, घबराये मन को हौसला दे जाता हो। हमारी नासमझी के समय में हमें समझा जाता हो; किसी उदाहरण और सप्रमाणित आंकड़ों के साथ वर्तमान स्थिति की सत्यता को पूरी ईमानदारी के साथ हमारे सामने प्रस्तुत कर जाता हो।

सच कहूँ, मैं ही क्यों हर कोई दुबका, सहमा, डरा हुआ जी रहा है आज। संकट की इस घड़ी में अपने साये से भी भय लग रहा है। संक्रमण का भय इतना प्रबल था कि मैंने तो अपने घर पर अखबार डालने से मना कर दिया था कि उधर से धीरे- गंभीर दिव्य वाणी कानों में गूँजी..... अखबार कोरोना नहीं लाता मैं जी; सही खबरें लाता है। लगा.....सच ही तो कहा। यह कमजोर मन तो कुछ भी सोंच बैठता है। और फिर किसी सजग पहरेदार की भांति बिना नागा के हर दिन घर पर अखबार आता रहा। सही खबरों के साथ। आत्मोन्नति की शिक्षा के साथ। निर्णय लेने की क्षमता की सुदृढ़ता के साथ। घर पर रहने का सदाचार और शिष्टाचार का पाठ पढ़ाता। यह वह समय था

जब सोशल मीडिया पर भी कोरोना से जुड़े अनाधिकृत चर्चा पर प्रतिबंध था क्योंकि वहां समाचारों को सनसनीखेज या चटपटा बनाने की कोशिश में गलत बयानबाजी और टिप्पणी की संभावना थी; जो किसी व्यक्ति विशेष को ही नहीं अपितु किसी राष्ट्र की भावना को भी ठेस पहुंचा सकता था और हम आकुल थे पल- पल की खबर जानने को। तब यह अखबार ही था जो पूरे सद्भाव और लोकहित का ध्यान रख हमारी ऐसी हर भूख को शांत कर रहा था। हमें सजग और सतर्क कर रहा था।

कानून और पुलिस से वांछित निकटता के लिए टोल फ्री नंबर से लेकर उनके कामों और उनके द्वारा दिए जा रहे हर सुविधा से हमें अवगत कराता रहा तो हमें कानून के उल्लंघन किए जाने पर मिलने वाले दंड से बचने के लिए सावधान भी करता चला। सरकारी नीतियों और निर्णयों को जनसाधारण तक पहुंचाने का कार्य भी करता चला। संवेदनशील बनकर मानवीय पीड़ा और परेशानियों को रेखांकित करता तथा नैतिक मूल्यों की रक्षा की अपील करता चला। परिणामतः अनेक सेवाभावी संस्थाएँ, व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी, चिकित्सक, कार्यकर्ता, राजनेता और तो और विद्यार्थी भी अपने-

अपने स्तर पर आर्थिक मदद के लिए आगे आए। अखबार ने जान पर बन आए संकट की इस घड़ी में जगत् को तपोवन सा बना दिया जहां एक ही घाट पर सर्प, मयूर, हिरण और बाघ जैसे अलग- अलग प्रकृति के प्राणी अपना बैर- भाव और निजी स्वार्थ- लाभ को भूलकर एक साथ सेवा के लिए हाथ बढ़ाते चले और प्राणीमात्र की सेवा, रक्षा और सद्भाव प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हो चले।

पत्रकारिता से जुड़े हर व्यक्ति ने अपने लिए स्वयं एक आदर्श आचार संहिता बना ली। जहां लोकहित के साथ लोक अभिरूचि को भी पूरा महत्व दिया जा रहा था। घड़ी परीक्षा की थी.....अखबार को एक कुशल नट की भांति सत्य का अनुसंधान करते हुए धैर्य की पतली रस्सी पर चलना था...वह चला और वीर योद्धा की भांति अंतिम समय तक डटा रहा। हे कर्मवीर! नमन् तुम्हें!!

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

\*\*\*\*\*



## भारिया जनजाति की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पद्धति पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन

सृष्टि जोन\*

**प्रस्तावना** - जनजातीय समुदाय प्राचीनकाल से वनों के मध्य निवासरत् रहे हैं। ये समुदाय आत्मनिर्भर रहा है जो कि अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर रहे हैं। हमारे देश पर कई प्रकार के आक्रमण हुए इन आक्रमणों के कारण जनजातीय लोग अपने निवास से दूर जंगलों की ओर चले गये और वहीं कृषि कार्य एवं पशुपालन करने लगे जिससे नगरों से इनका संपर्क कम होने लगा। उन्होंने अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कुछ विशेष देशज चिकित्सा पद्धति का विकास किया। जनजाति चिकित्सा पद्धति के मुख्य रूप से दो रूपों का विकास हुआ, पहला जिसमें जनजाति समाज के धर्म, जादू एवं विश्वास के आधार पर तंत्र-मंत्र चिकित्सा पद्धति जिसमें एक गुनिया या ओझा झाड़ू-फूंक के माध्यम से बीमारी का उपचार करता है। दूसरा रूप वन औषधियों पर आधारित है जिसमें एक वैद्य बीमारी के लक्षणों के आधार पर किसी विशेष प्रकार की वन औषधी बीमार व्यक्ति को देता है। ये दोनों पद्धतियां ही लंबे समय से इस समाज में प्रचलित हैं। पहली पद्धति का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और इससे जनजातियों में स्वास्थ्य के प्रति गंभीर समस्याएँ उत्पन्न की है। दूसरी पद्धति बहुत कुछ आयुर्वेद पर आधारित है जिसे वैज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता है।

आजादी के बाद से सरकार ने सभी स्तरों पर विकास के लिए प्रयास किये हैं ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में इसके दूरगामी प्रभाव दिखाई देते हैं सड़क एवं संचार साधनों ने जहां इन ग्रामीण एवं वनों से नगरों का संपर्क बढ़ाया है, ऐसे में स्वाभाविक रूप से वैश्विक महामारी एवं बीमारियां इन जनजाति क्षेत्रों में पहुंची है।

पहले से ही इन क्षेत्रों में कुपोषण, मातृ मृत्यु दर एवं बाल मृत्यु दर बहुत अधिक है। ऐसे में इन समुदायों में आधुनिक चिकित्सा पद्धति के प्रसार की महती आवश्यकता है।

भारिया जनजाति में शिक्षा के प्रसार के प्रभाव से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पद्धति पर क्या प्रभाव हुए हैं यही जानने के उद्देश्य से यह शोध कार्य किया गया है।

**शोध के उद्देश्य** - प्रस्तुत शोध अध्ययनके निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये थे -

1. भारिया जनजाति में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की स्थिति पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. भारिया जनजाति की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की स्थिति से सुधार हेतु उपयुक्त सुझावों को प्रस्तुत करना।

**शोध विधि :**

1. **शोध संरचना** - प्रस्तुत शोध अध्ययनमें वर्णनात्मक शोध प्ररचना का प्रयोग किया गया है।

2. **अध्ययन का समग्र** - प्रस्तुत अध्ययन से समग्र छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में निवासरत् भारिया जनजाति है।

3. **अध्ययन की इकाई** - प्रस्तुत अध्ययन की इकाई भारिया जनजाति का परिवार है।

4. **निर्दर्शन विधि** - प्रस्तुत शोध में उद्देश्यपूर्ण निर्दर्शन विधि से छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र से 50 भारिया जनजाति परिवारों को अध्ययन के लिए चयन किया गया है।

5. **तथ्यों का संकलन** -

**प्राथमिक तथ्य** - प्राथमिक तथ्यों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची एवं अवलोकन के माध्यम से किया गया है।

**द्वितीयक तथ्य** - द्वितीयक तथ्यों का संकलन पुस्तकों एवं शोधपत्रों के आधार पर किया गया है।

6. **तथ्यों का विश्लेषण** - प्राथमिक तथ्यों का सारणीयन एवं सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया है।

7. **अध्ययन क्षेत्र** - प्रस्तुत अध्ययनका क्षेत्र मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का पातालकोट क्षेत्र है।

**तथ्यों का विश्लेषण** - प्रस्तुत शोध अध्ययनके दौरान संकलित किये गये तथ्यों का विश्लेषण इस प्रकार है -

**तालिका क्रमांक 01 - भारिया परिवार की दो पीढ़ियों में शिक्षा स्तर की तुलनात्मक स्थिति**

क्र.	शिक्षा का स्तर	उत्तरदाता		उत्तरदाता के पिता	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अशिक्षित	22	44	39	78
2	अक्षर ज्ञान (प्रौढ़ शिक्षा)	14	28	04	08
3	प्राथमिक शिक्षा	05	10	03	06
4	माध्यमिक शिक्षा	03	06	02	04
5	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा	04	08	02	04
6	स्नातक	01	02	00	00
7	स्नातकोत्तर	00	00	00	00
8	तकनीकी शिक्षा	01	02	00	00
	<b>योग</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्तमान में 44 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित है जबकि उत्तरदाता के पूर्व पीढ़ी में 78 प्रतिशत लोग अशिक्षित थे। वर्तमान में 28 प्रतिशत उत्तरदाता अक्षर ज्ञान रखते हैं लेकिन पूर्व की पीढ़ी में मात्र 08 प्रतिशत लोग ही अक्षर ज्ञान रखते थे। वर्तमान में 10 प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हैं जबकि पूर्व की पीढ़ी में 06 प्रतिशत लोग

ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त थे।

वर्तमान में 06 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माध्यमिक शिक्षा पूर्ण की है जबकि पूर्व की पीढ़ी के मात्र 04 प्रतिशत लोगों ने माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की थी।

वर्तमान में 08 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की थी जबकि पूर्व की पीढ़ी में 04 प्रतिशत लोग ही उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त थे।

वर्तमान 02 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्नातक तक शिक्षा ग्रहण की है जबकि पूर्व में कोई भी उत्तरदाता स्नातक तक शिक्षा प्राप्त नहीं थी। स्नातकोत्तर की शिक्षा न वर्तमान पीढ़ी के उत्तरदाता ने प्राप्त की है न ही पूर्व की पीढ़ी ने प्राप्त की थी।

वर्तमान में 02 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है जबकि पूर्व की पीढ़ी में किसी ने भी तकनीकी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पूर्व की पीढ़ी की तुलना में भारिया जनजाति की वर्तमान युवा एवं प्रौढ़ पीढ़ी में शिक्षा की स्थिति बेहतर है।

#### तालिका क्रमांक 02 – भारिया परिवारों में चिकित्सा पद्धति की स्थिति

क्र.		पूर्व में		वर्तमान में	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	गुनिया/वैद्य	40	80	25	50
2	चिकित्सालय	10	20	25	50
	<b>योग</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पूर्व में 80 प्रतिशत भारिया परिवारों में गुनिया एवं वैद्य से बीमारी का उपचार कराया जाता था तथा 20 प्रतिशत परिवार ही गंभीर अवस्था में उपचार के लिए चिकित्सालय जाते थे। वर्तमान में 50 प्रतिशत परिवारों में अभी भी गुनिया एवं वैद्य से उपचार कराया जाता है तथा 50 प्रतिशत परिवारों में चिकित्सालयों से बीमारी का उपचार कराया जाता है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शिक्षा के प्रसार से भारिया जनजाति में चिकित्सालय में बीमारी का उपचार कराने का प्रतिशत काफी बढ़ गया है।

#### तालिका क्रमांक 03 : परिवार नियोजन की स्थिति

क्र.	परिवार नियोजन	पूर्व में		वर्तमान में	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	00	00	10	20
2	नहीं	50	100	40	80
	<b>योग</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पूर्व में किसी भी भारिया परिवार में परिवार नियोजन नहीं अपनाया गया था लेकिन वर्तमान में शिक्षा के प्रभाव से 20 प्रतिशत भारिया परिवारों में परिवार नियोजन अपनाया जा रहा है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शिक्षा के प्रभाव से भारिया जनजाति परिवारों में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ी है।

#### तालिका क्रमांक 04 : गर्भवती महिलाओं के प्रसव स्थल की स्थिति

क्र.	प्रसव स्थल	पूर्व में		वर्तमान में	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	घर में	46	92	05	10
2	अस्पताल में	04	08	45	90
	<b>योग</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पूर्व में 92 प्रतिशत भारिया परिवारों में घर में ही प्रसव कराया जाता था मात्र 08 प्रतिशत परिवारों में ही गंभीर अवस्था में अस्पताल में प्रसव कराया जाता था।

वर्तमान में 90 प्रतिशत भारिया परिवारों में अस्पताल में प्रसव कराया जा रहा है एवं 10 प्रतिशत परिवारों में अभी भी घरों में प्रसव हो रहे हैं।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शासन के प्रयास एवं शिक्षा के प्रभाव से भारिया परिवारों में संस्थागत प्रसव के प्रति जागरूकता बढ़ी है।

**निष्कर्ष** – प्रस्तुत अध्ययन में तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात् निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं –

भारिया परिवारों की वर्तमान युवा पीढ़ी में पूर्व की पीढ़ी की तुलना में शिक्षा स्तर में सुधार हुआ है।

1. शिक्षा के प्रसार से भारिया जनजाति में चिकित्सालय में बीमारी का उपचार कराने के प्रतिशत में वृद्धि हुई है।
2. शिक्षा के प्रभाव से भारिया जनजाति परिवारों में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
3. शिक्षा के प्रसार से भारिया परिवारों में संस्थागत प्रसव के प्रति जागरूकता बढ़ी है।

#### सुझावः

1. भारिया जनजाति के विकास की संभावनाओं को एक नियोजित कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
2. भारिया बाहुल्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु भारिया विकास अभिकरण एवं अन्य विभागों को सामंजस्य पूर्वक कार्यक्रमों को सुचारु रूप से संचालित करना चाहिए।
3. भारिया गांवों तक चिकित्सा की सुविधाएँ पहुंचायी जानी चाहिए।
4. भारिया परिवारों में मातृ एवं बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए विशेष व्यवस्था बनायी जानी चाहिए।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अटल, योगेश (1965) 'आदिवासी भारत' राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
2. विद्यार्थी, ललित प्रसाद (1975) 'भारतीय आदिवासी' हिन्दी समिति, लखनऊ
3. आहूजा, राम (1994) 'सामाजिक समस्याएँ' रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर
4. दुबे, श्यामाचरण (1995) 'संक्रमण की पीड़ा' वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
5. शुक्ला, हीरालाल (1997) 'आदिवासी अस्मिता और विकास', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल

## कश्मीर में आतंकवाद की समाप्ति हेतु कूटनीतिक, राजनीतिक एवं सैन्य स्तर पर किये गये प्रयास एवं सुझाव

**डॉ. रजनी दुबे\***

**प्रस्तावना** – कश्मीर के आतंकवाद को समाप्त करने हेतु द्विस्तरीय प्रयासों की आवश्यकता है। प्रथम आंतरिक। घरेलू एवं द्वितीय वाहना। कूटनीतिक।

कश्मीर का आतंकवाद अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी पिछड़ने के कारण असंतुष्ट और नाराज कश्मीरियों का महज उग्र और हिंसक आंदोलन नहीं है, अपितु पाकिस्तान द्वारा कुनिसत मानसिकता के अंतर्गत भारत को कश्मीर से अलग करने का कुकृत्य है। इसलिये कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। आतंकवाद से धरती की रक्षा करने की आवश्यकता है।

आतंकवाद को समाप्त करने के लिये सरकार को एक साथ कई कदम उठाने पड़ेंगे, अन्यथा ये दीमक की भांति राष्ट्र की जड़ों को खा-खाकर खोखला कर देंगे। सरकार को आतंकवाद समाप्त करने के लिये एक व्यापक नीति अपनानी चाहिये जिसमें प्रत्येक पहलू पर विचार हो तभी देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रह सकती है।

**सीमा पर चौकियां स्थापित करना** – पाकिस्तान से आतंकवाद का प्रशिक्षण लेकर घुसपैठ करने वाले आतंकवादी पहाड़ों और जंगलों से होकर भारत में प्रवेश करते हैं डोड़ा जिले की सीमा कश्मीर के अनंतनाग जिले के साथ लगती है पाकिस्तान में प्रशिक्षण देने के बाद आतंकवादी अत्याधुनिक हथियार लेकर इन्हीं रास्तों से प्रवेश कर जाते हैं। पर्याप्त संख्या में सीमा पर चौकियां स्थापित होने से घुसपैठ रूक जायेगी।

**सीमा पर पुलिस बल बढ़ाने की व्यवस्था करना** – आतंकवादी बारदातें करने के बाद सीमावर्ती हिमाचल प्रदेश, चंबा पांशी घाटी और जंगलों में छिप जाते हैं। सेना द्वारा अधिक खोजबीन करने पर अनेक आतंकवादी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आदि राज्यों में जाकर शरण लेते हैं, और वहां बम विस्फोट करते हैं। जम्मू-कश्मीर से लगे अन्य प्रदेशों की सीमा पर पुलिस गस्त तेज करने और चौकियां स्थापित करने से आतंकवादी अन्य प्रदेशों में जाकर वारदातें नहीं कर पाएंगे।

**सेना को अधिक अधिकार प्रदान करना** – आतंकवाद पर अंकुश लगाने में स्थानीय पुलिस समर्थ नहीं हैं। इसके मुख्यतः दो कारण हैं पहला तो यह कि अधिकांश स्थानीय पुलिसकर्मी आतंकवाद के समर्थक हैं और दूसरा यह कि इनके पास अत्याधुनिक हथियार नहीं हैं। वास्तव में सैनिक एवं अर्ध सैनिक बल ही इस आतंकवाद को समाप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के 'कतिपय क्षेत्रों को सेना को सुपुर्द कर देना चाहिये एवं वहां का नागरिक प्रशासन सेना के निर्देशन में कार्य करेगा। सीमावर्ती क्षेत्र जहां नियंत्रण रेखा के पास सेना की तैनाती है तथा वह क्षेत्र जहां का नागरिक प्रशासन ठप हो गया है इस व्यवस्था हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जगह है।'

**प्रशासन और सुरक्षा बलों का आपसी समन्वय** – स्थानीय प्रशासन

पुलिस प्रशासन सेना एवं अर्धसैनिक बलों का आपस में समन्वय स्थापित होना चाहिए, ताकि वे सब मिलकर पूरी शक्ति के साथ कार्य कर सकें जिससे परिणाम भी अच्छे आयेगें। समन्वय के अभाव में जब सेना किसी आतंकवादी को पकड़ती है तो स्थानीय प्रशासन उसे छोड़ देता है। दूसरी बात है कि सेना को क्षेत्र की सही जानकारी नहीं रहने के कारण काम करने में कठिनाई होती है। आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाने के लिये समन्वय समिति बनाई जाये। जिसमें स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाई जाये जो कि निश्चित समय अवधि में सामूहिक रूप से बैठक कर योजनाएं बनाये।

**प्रशासन को विशेष प्रशिक्षण देना** – आतंकवाद की गतिविधियां तेज होने के कारण कई बार तो प्रशासन को यह समझ में नहीं आता कि वह क्या करें क्योंकि उन्हें तो सामान्य स्थिति में हो कार्य करने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है, जिसके कारण आतंकवादी अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। प्रशासन को विशेष प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाने की आवश्यकता है। आतंकवाद का मुकाबला किस प्रकार किया जाये आतंकवादी घटना होने पर कैसे कार्य करने चाहिए समाज को विस्थापित होने से किस प्रकार रोका जाये ऐसे अनेक विषयों का प्रशिक्षण प्रशासन के अधिकारियों को देना आवश्यक है। जिससे प्रशासन पंगु न बनकर गतिशील होकर कार्य करेगा।

**नागरिक प्रशासन** – शासन को परिवर्तनशील होना चाहिये ताकि नागरों और गांव में अधिक से अधिक लोगों की समस्या सुलझाने के लिये उन तक पहुंच सके उसे चाहिये कि-

1. वह सरकारी कर्मचारियों को पर्याप्त अधिकारों के साथ सुदूर गांव में भी लोगों की शिकायतें दूर करने के लिये भेजे।
2. जो समस्यायें न सुलझाई जा सकती हो उन पर एक पखवाड़े के भीतर ही पुनर्विचार करके उचित कदम उठाये जाने चाहिये।
3. सरकारी अधिकारियों को यह चाहिये शिक्षा तथा रोजगार की नवीन योजनाओं के विषय में लोगों को पूरी जानकारी दें और जो लोग उनका लाभ उठाना चाहे, उसकी सहायता भी करें। इस प्रकार प्रशासनिक सेवाओं को दूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने से इस लोकप्रिय प्रशासन को बहुत लाभ होगा। वह उग्रवादियों के प्रभाव को बेकार कर अपनी सत्ता भलीभांति स्थापित कर पायेगा। तत्कालीन परिणामों से नागरिक संतुष्ट भी हो जाएंगे और आतंकवादियों के गैर कानूनी संगठनों की वजह सरकारी विभागों से संपर्क रखेंगे।

**सैनिक छावनी की स्थापना** – जम्मू कश्मीर की सामरिक, भौगोलिक और सामाजिक स्थिति इस प्रकार की है कि यह हमेशा से संवेदनशील है।

इसलिये केंद्र सरकार ने एक सैनिक छावनी स्थापित करने का निर्णय किया। क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुये हर जिले में छोटी छोटी छावनी बनाने की आवश्यकता है।

**राष्ट्रीय चेतना का जागरण और संस्कारों का भारतीय करण** – प्रारंभ से ही किसी भी सरकार ने कश्मीर में भारतीय मूल्यों को महत्व नहीं दिया। घाटी में इस्लाम मजहब की जनसंख्या निवास करती हैं, उनका शिक्षा एवं संस्कारों के माध्यम से भारतीयकरण करना जरूरी है। उनके दिलों में हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी और हिंदू के प्रति प्यार एवं भक्ति का भाव पैदा करने की आवश्यकता है। जय भारत, भारत माता की जय, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और भारतीय होने का गर्व हो इसके लिये अपेक्षित कदम उठाये जाने चाहिये। यह भाव जानना आवश्यक है कि राष्ट्र सर्वप्रथम है देशभक्ति मजहब से बड़ी है। पूरा भारत एक है और अपना देश है। राज्य की विधानसभा में भी राष्ट्रीय गान विद्यालयों में देशभक्ति के गीत, सरकारी भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों पर महापुरुषों के प्रेरणादायक वाक्य लिखे जाने चाहिये।

**वार्ता की सार्थकता एवं पंजाब पुलिस के तरीकों का प्रयोग** – किसी भी जटिल समस्या को सुलझाने के लिए वार्ता अर्थात् आपसी बातचीत की आवश्यकता पड़ती है। राज्य की समस्या के समाधान हेतु वार्ता के अनेक दौर चले हैं। लेकिन बातचीत केवल आतंकवादी नेताओं के साथ ही नहीं बल्कि आतंकवाद से संघर्षरत समाज के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक नेताओं के साथ भी होनी चाहिये। पंजाब राज्य का उदाहरण देश के सामने है। जब राज्य में आतंकवाद समाप्त करने का दृढ़ संकल्प सरकार ने किया तो उसने आतंकवादियों से लंबी वार्तयें या एक तरफा संघर्ष विराम जैसे तरीके नहीं अपनाये। बल्कि वहां से संघर्षशील समाज को आतंकवाद के विरुद्ध तैयार करके आतंकवादियों को ढूँढ-ढूँढकर मारा और उनके नेताओं को शक्तिहीन बना दिया। परिणाम स्वरूप वहां फिर से अमन-चैन बहाल हुआ। पंजाब का आतंकवाद भी कश्मीर की भांति पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था। इसलिये वार्ता की सार्थकता पर विचार की योजना बनानी चाहिये।

अंतर्राष्ट्रीय एवं कूटनीतिक स्तर पर भी गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। भारतीय कूटनीतिज्ञों को पाकिस्तानी साजिशों का पर्दाफास करते हुये विश्व जनमत अपने पक्ष में करना होगा तथा ज्यादा मित्रभाव न रखने वाले चीन जैसे पड़ोसी देशों से संबंधों को सुधारना होगा। इसके साथ ही साथ निम्न सुझावों पर भी विचार किया जा सकता है।

**मानवाधिकार** – कश्मीर में मानवाधिकार एक महत्वपूर्ण विषय है और भारत गंभीरतापूर्वक इसकी ओर पूरा ध्यान देता रहा है। भारतीय सुरक्षा सेनाओं ने उग्रवादियों के विरुद्ध कम से कम बल प्रयोग किया है, केवल उतना ही जितना की सुरक्षा के लिये आवश्यक था। भारत को अपनी रक्षात्मक युद्ध त्यागकर कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में मानवाधिकारों के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के विषय में जोर से आवाज उठानी होगी। उसे राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति की स्थापना के विषय में सबको बताना होगा, जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व और जिसके अधिकार क्षेत्र में जांच करने की स्वायत्तता है। भारत को चाहिये कि वह मानवाधिकारों के क्षेत्र में अपने प्रयासों को जारी रखे, ताकि पाकिस्तान को उसे बदनाम करने का अवसर ही ना मिले।

**मनोवैज्ञानिक युद्ध** – घाटी में कई मुसलमान उग्रवादियों की विचारों से सहमत नहीं परंतु उन्हें डराया धमकाया जाता है संप्रदाय से उनका वहिष्कार कर दिया जाता है और कभी-कभी उनकी हत्या भी कर दी जाती है।

असहिष्णुता इतनी तीव्र हो गई है कि नरमपंथी स्वयं को एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष में घिरा पाते हैं। जब उनके साथ दुर्घटनवार किया जाता है, उनकी संपत्ति का अनुचित लाभ उठाया जाता है या उनकी महिलाओं का अपमान किया जाता है तब भी किसी का कुछ कहने या करने का साहस नहीं होता।

आतंकवादियों को अपने विरोधियों को चुप कराने के लिये डराने धमकाने की युक्तियां बेकार कर दी जानी चाहिये। इलेक्ट्रॉनिक या अन्य संचार माध्यमों तथा कश्मीरी, उर्दू और अंग्रेजी में छपे इशतहारों का भी पूरा उपयोग किया जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त दूरदर्शन, रेडियों तथा समाचार पत्रों द्वारा की घाटी की सारी जनता को उग्रवादियों द्वारा कश्मीरी मुसलमानों पर किये जाने वाले अत्याचारों की सूचना भी दी जानी चाहिये। यह बताना चाहिये कि किस प्रकार युवकों को झूठे वादे करके पहले उग्रवाद अपनाते के लिये बाध्य किया जाता है और फिर मरने के लिये छोड़ दिया जाता है। यह तथ्य प्रकाश में लाया जाना चाहिये कि किस प्रकार उग्रवादियों के नेता जनता के पैसों पर वैभव से रहते हैं, और किस प्रकार वे इतने अमीर हो गये हैं, जबकि साधारण जनता आतंकवाद के कारण आजीविका भी नहीं कमा पाती। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि कश्मीर में आतंक से निपटाने के लिये 4 डी फार्मूले की आवश्यकता है। 4 डी यानि डॉयलॉग डेवलपमेंट, डिप्लोमेसी और डिफेंस के नाम से ही संभव कश्मीर घाटी में शांति बहाल संभव है।

**डॉयलॉग** – कश्मीर समस्या हल करने में अटल बिहारी वाजपेई की कूटनीति अब भी मौजूद है। उन्होंने पहली सैन्य ताकतों की बजाय 80 प्रतिशत तक फोकस कूटनीतिक और राजनीतिक तरीकों पर किया। टॉक बिटवीन टेलर फॉर्मूला यानी युद्ध और बातचीत दोनों साथ-साथ जारी रखी। बातचीत का यह प्रयास हर मोर्चे पर होना चाहिये। मसलन नई दिल्ली इलाहाबाद, नई दिल्ली कश्मीर के बीच निरंतर प्रभावी डॉयलॉग बना रहना चाहिये। संवाद में कभी की वजह से ही आतंक को जगह मिलती है। इसलिये 2000 के दशक में कारगिल, सांसद और अक्षरधाम पर हमलों के बीच 350 बार दोनों देशों के अधिकारी टेबल पर बैठे।

**डिफेंस** – कश्मीर में सेना का अहम रोल है। सेना ने 1971 की जंग में इस समस्या के हल का सबसे मजबूत मौका दिया। सेना को और ताकत देने के लिये अब हमें जरूरत है इजरायल मॉडल की तरह सैन्य टेक्नोलॉजी पर ध्यान देने की। इस मॉडल में इजरायल जैसा छोटा सा देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी को हथियार बनाये हुये है। इस सैन्य टेक्नोलॉजी के डर से आतंकी यहां कुछ भी गलत करने से पहले हजार बार सोचते हैं। यह फायदा हमें भी मिल सकता है। इन सबके बीच में फोकस कश्मीर के लोगों और सेना के बीच के संबंधों के बेहतरी पर भी हो।

**डेवलपमेंट** – घाटी में आर्थिक-सामाजिक पहलुओं पर ज्यादातर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि राज्य में बेरोजगारी दर 21 प्रतिशत से ज्यादा है, जो देश में त्रिपुरा के बाद सबसे अधिक है। यहां 3866 लोगों पर महज एक डॉक्टर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक प्रति हजार लोगो पर एक डॉक्टर होना चाहिये। राज्य में 23771 में से 76 प्रतिशत स्कूलों में बिजली नहीं है। बिना बिजली वाले स्कूलों के मामले में जम्मू कश्मीर में देश के 36 राज्यों में से 31 वें नंबर पर है। इन्हीं पिछड़ेपन की वजह से अलगाववादी युवाओं को आतंक से जोड़ने में सफल होते हैं।

**डिप्लोमेसी** – 72 सालों में इसी के जरिये सबसे ज्यादा बात बनती दिखी है। डिप्लोमेसी के दम पर ही पिछले दशक में दो बार हम कश्मीर समस्या



सुलझाने के करीब पहुंच गए थे। लेकिन मौजूदा सरकार में दोनों देशों के बीच एक भी स्ट्रक्चर्ड कम्पोजिट डायलॉग नहीं हुआ। जबकि अटल जी शांति वार्ता न रोकने के पक्षधर थे। उनका एक ही मकसद रहा कि आतंकी हमलों के बीच भी शांति वार्ता और डिप्लोमेसी न रुकने पाये।

हमें दोनों देशों के बीच भी निरंतर डिप्लोमेसी जारी रखनी होगी।

**शांति का अटल फार्मूला** – 2001 में अटल जी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति मुशर्रफ ने 4 सूत्रीय कश्मीर फार्मूला दिया था। एक्सपर्ट तक इसे अब तक का सबसे कारगर तरीका मानते हैं। भारत-पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरों के बीच करीब हर साल होने वाली टेक 2 वार्ता में इसे अपनाने की मांग उटती है। ये वार्ता किसी तीसरे देश में होती है। यह फार्मूला है –

1. चरणबद्ध तरीके से दोनों देया एल ओ सी से सेना कम करें।
2. जम्मू कश्मीर की सेना में बदलाव नहीं हो। यहां के लोगों को नियंत्रण रेखा के आर-पार जाने का हक हो।
3. जम्मू कश्मीर को स्वशासन की स्वायतता मिले।
4. जम्मू कश्मीर की देखरेख भारत, पाकिस्तान और कश्मीर को मिलकर

बना एक संयुक्त तंत्र करे। अटल बिहारी वाजपेई ने कहा था –

‘अभी तक जो खेल होता रहा। मौन का .....खून का ..... वो बंद होना चाहिये। बंदूक से मसले हल नहीं होंगे, बंदूक से आदमी को मारा जा सकता है लेकिन बंदूक से उसकी भूख नहीं मिट सकती।’

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. जॉन ब्रे ‘एशिया’ रिसर्च .....द्वारा सम्पादित पुस्तक द फ्यूचर आफ पालिटिकल वायलेक्स लुदन मेकलिन न प्रेस लि. 1986
2. अरुण त्रिपाठी एवं अरुण पांडये मुस्लिम आतंकवाद बनाम अमेरिका नई दिल्ली वाणी प्रका.2002
3. आई.एल. व्दारोविट्ज ‘द रूटिनाइजेशन आफ टेरेरिज्म’ मार्या क्रेशन की पुस्तक टेरेरिज्म लेजिटीनेसी एंड पांवर (केन्कटीकर वेसलीमेन यूनी. प्रेस 1983)
4. आक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी वाल्यूम XI लंदन मार्यल डेकर 1998
5. भास्कर न्यूज/नई दिल्ली/जम्मू कश्मीर दिनांक 23 फरवरी 2019
6. अन्य समाचार एवं पत्रिकायें

\*\*\*\*\*

## अज्ञेय के काव्य में अभिजात्य-वर्ग के प्रति विद्रोह

डॉ. अनुकूल सोलंकी \*

**प्रस्तावना** – सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय बौद्धिक चिंतनशील व्यक्तित्व के धनी हैं। अज्ञेय काव्य में सभी वर्गों के प्रति समान दृष्टिकोण की छाप मिलती है। लेकिन प्रगतिवाद की तरह प्रयोगवादी कवि अज्ञेय में भी अभिजात्य वर्ग के प्रति तीव्र विरोध की चेतना प्रखर हो उठी है अज्ञेय मानते हैं कि अभिजात्य वर्ग ने अपनी

सुख-सुविधा के लिये अनेक दोशों को जन्म दिया।

इसलिए उनके काव्य में शोषित-जन के प्रति सच्ची सहानुभूति के दर्शन प्राप्त होते हैं। शैल सिन्हा के शब्दों में – ‘अज्ञेय के काव्य में अभिजात्य वर्ग के प्रति तीव्र विद्रोह और पद-दलितों के प्रति सच्ची सहानुभूति के दर्शन होते हैं।’<sup>1</sup>

अज्ञेय अपने बौद्धिक मानस में मानते हैं कि ‘दुःखी और सुखी की कोई आत्यंतिक श्रेणियाँ तो जीवन में हैं नहीं। दुःख अपूर्णता, पीडा ये सर्वव्यापी हैं। गरीबों ने इनका ठेका नहीं लिया है।’<sup>2</sup>

अभिजात्य वर्ग के दर्प को उसके सुखों को अज्ञेय ने बखूबी जाना और पहचाना है। इसलिए शोषित-जन के विरुद्ध आवाज भी खूब उठायी। अभिजात्य वर्ग के आततायी परिवेश को उसकी परिवृत्ति को अज्ञेय ने पूरे दम-खम के साथ ललकारा है :-

‘ठहर, ठहर आततायी! जरा सुन ले  
मेरे कुधद वीर्य की पुकार आज सुन जा  
रागा तीत, दर्पस्फीत, अतल, अतुलनीय  
मेरी अवेहलना की टक्कर सहार ले-  
क्षण भर स्थिर खड़ा रह ले-  
मेरे हृद पौरुष की एक चोट सह ले।’<sup>3</sup>

मध्य वर्ग के सुदृढ़ आर्थिक सम्बन्धों पर अज्ञेय बखूबी कलम चलाते हैं। अज्ञेय का चिंतनशील मन उन्हें मध्यवर्ग में कवि रूप में त्रिशंकु सा बना देता है। निर्धन कवि असम्मान का पात्र बनता है और आत्म हनन का शिकार होने लगता है। अज्ञेय न तो धनी वर्ग के कवि हैं और न ही निर्धन वर्ग के। किन्तु अज्ञेय का मध्यवर्गीय बौद्धिक मन शोषित और शोषक के सम्बन्धों को अच्छी तरह पहचानता है। डॉ. नामवर सिंह के इस कथन को उचित नहीं समझा जा सकता है कि – ‘इस तरह इस विद्रोही कवि का उच्च मध्यवर्ग तथा उसकी समाज व्यवस्था के प्रति सारा असंतोष और युयुत्सु-भाव अन्त में इस प्रस्ताव पर खत्म हुआ कि उसे संरक्षण प्राप्त हो। केवल इस टुकड़े पर उच्च मध्यवर्ग का सारा अत्याचार और अपनी सारी पीडा भुलाई जा सकती है।’<sup>4</sup>

अज्ञेय इन सब से अलग होते हुए भी निजता का भाव कवि मन में, कवि जीवन में रखना चाहते हैं। अज्ञेय ने अनेक कविताओं में अभिजात्य वर्ग

के प्रति तथा शोषित वर्ग के प्रति विद्रोहात्मक सूर कहा है ‘बंदी-स्वप्न’ की अधिकांश कविताएँ इसी विद्रोह को व्यावहारिक रूप प्रदान करती हैं

‘सुनो तुम्हें ललकार रहा हूँ, सुनो घृणा का गान!  
तुम जो भाई को अछूत कह वस्त्र बचा कर भागे,  
तुम जो बहिने छोड़ बिलखती बड़े जा रहे आगे!  
रुक कर उत्तर दो, मेरा है अप्रतिहत आहावन  
सुनो तुम्हें ललकार रहा हूँ सुनो घृणा का गान!

तुम, जो बड़े-बड़े गद्दों पर ऊँची दूकानों में,  
उन्हें कोसते हो जो भूखे मरते हैं खाने में,  
तुम, जो रक्त चूस ठठरी को देते हो जल दान  
सुनो, तुम्हें ललकार रहा हूँ सुनो घृणा का गान !

तुम जो महले में बैठे दे सकते हो आदेश  
मरने दो बच्चे, ले आओ खींच पकड़कर केश!  
नहीं देख सकते निर्धन के घर दो मुठ्ठी धान  
सुनो तुम्हें ललकार रहा हूँ सुनो घृणा का गान!

तुम जो पा कर शक्ति कलम में हर लेने की प्राण  
निशक्तों की हत्या में कर सकते हो अभिमान!  
जिनका मत है नीच मेरे हृद रहे हमारा स्थान,  
सुनो तुम्हें ललकार रहा हूँ सुनो घृणा का गान!

तुम जो मंदिर में वेदी पर डाल रहे हो फूल,  
और इधर कहते जाते हो जीवन क्या है! धूल  
तुम जिसकी लोलुपता ने ही धूल किया उद्यान  
सुनो तुम्हें ललकार रहा हूँ सुनो घृणा का गान!

सुनो तुम्हें ललकार रहा हूँ, सुनो घृणा का गान  
तुम जो भाई को अछूत कह वस्त्र बचा कर भागे  
तुम जो बहिने छोड़ बिलखती बड़े जा रहे आगे  
रुक कर उत्तर दो मेरा है अप्रतिहत आह्वान  
सुनो तुम्हें ललकार रहा हूँ सुनो घृणा का गान  
तुम, सत्ताधारी, मानवता के शव पर आसीन,  
जीवन के चिर रिपु, विकास के प्रतिद्वन्दी प्राचीन,  
तुम, शमशान के देव सुनो यह रणभेरी की तान

आज तुम्हें ललकार रहा हूँ, सुनो घृणा का गान<sup>15</sup>  
कवि अज्ञेय का विद्रोहात्मक स्वर या विद्रोह की अधिकता कवि की अगणित  
जिन्हाओ की ज्वाल बन जाती है -

‘मैं कृतान्त हूँ मेरी अगणित जिन्हाओ की ज्वाल,  
जग की झूठी मृदुताओं की भ्रमकरी विकराल!  
आशा की इस मधु विडम्बना से ओ पागल जाग!  
मेरा वरद हस्त देता है- आग आग बस आग!  
मुझसे स्निग्ध ताप मत मांग’<sup>16</sup>

अज्ञेय कवि के रूप में अपनी ज्योति को अखंड रखना चाहते हैं, अज्ञेय  
चाहते हैं की उनके विद्रोह की यह शिक्षा सम्पूर्ण विश्व को आलोकित कर दे  
जो उचित भी कई जा सकती है -

‘कर से कर तक, उर से उर तक, बढ़ती जाओ ज्योति हमारी,  
छप्पर- तल से महल-शिखर तक चढ़ती जाओ ज्योति हमारी’

++ ++ ++ ++

कहीं बच गया हो कोई तो तू उसमें भी स्फूर्ति जगा दे -  
विश्व कँपा दे ज्योति ! जगत में आग लगा दे ! आग लगा दे !<sup>17</sup>

डॉ. चन्द्रबलि सिंह उपर्युक्त इत्यलम की लिखी कवि अज्ञेय की कविताओं  
को केवल एक व्यक्ति का विद्रोह ही दिखता है, मानते हैं और कहते हैं -

यह विद्रोह एक व्यक्ति के अहं मात्र का विद्रोह है और उसका कोई  
विशेष सामाजिक महत्व नहीं समाजनिष्ठ होकर वह समाज की उपेक्षा करता  
है

इस व्यक्तिगत अहं की सीमा के ऊपर विद्रोह भावना कुछ ही कविताओं  
में उठ पायी है।<sup>18</sup>

डॉ. चन्द्रबली सिंह का यह कथन सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं यह तर्क  
अनुचित है। क्योंकि विद्रोह किसी का भी हो सामाजिक महत्व रखता है।

आग एक तिली से ही लगती है एक चिंगारी सम्पूर्ण को जलाकर भस्म  
कर देती है इसलिए उपर्युक्त कथन अत्युक्ति लगता है।

अज्ञेय की अनेक कविताओं में आभिजात्य - वादी विद्रोह स्पष्ट दिखाई  
देता है। अज्ञेय उच्च वर्ग में गहरे सूक्ष्म बाणों की, व्यंग्यों की वर्षा करते  
दिखाई देते हैं। उन्हें साम्यवादी विरोधी कहना अनुचित लगता है-

‘डरो मत, शोशक भैया,  
पी लो।

मेरा रक्त ताजा है  
मीठा है  
हुँग है।

पी लो, शोशक भैया,  
डरो मत।

शायद तुम्हें पचें नहीं-

अपना मेदा तुम देखो, मेरा क्या दोष है।

मेरा रक्त मीठा तो है, पर पतला या हल्का भी हो

इसका जिम्मा मैं तो नहीं ले सकता,

शोशक भैया !

जैसे सागर की लहर

सुन्दर हो यह तो ठीक ,

पर यह आश्वासन तो नहीं दे सकती कि

किनारे को लील नहीं

लेगी !

++ ++ ++  
++ ++ ++

वह मैं नहीं, वह तो तुम्हारा मेरा सम्बन्ध है !

जो तुम्हारा काल है।<sup>19</sup>

अज्ञेय में कवि रूप में अभिजात्य - वर्ग के प्रति तीव्र विराध हैं और अभिजात्य  
- वर्ग की छलना के प्रति तीव्र रोष भरा है उन्होंने स्पष्ट रूप से शोषक की  
भर्त्सना की है।

‘जो राज करें

उन्हें गुमान भी न हो

कि उनके अधिकार पर

किसी को शक है

और जिन्हे मुक्त जीना चाहिये

और उन्हें अपनी कारा में

इसकी खबर ही न हो

कि उनका यह हक है।<sup>10</sup>

अभिजात्यवादी शोषक अर्थव्यवस्था की ओर संकेत करते हुए एक कविता  
में कहा गया है कि समाज का सामान्य वर्ग भले ही अपनी इच्छा से अपनी  
धरती देने को तैयार हो या न हो परन्तु बर्बर लुटेरे उसे जबर्दस्ती खींच ही ले  
जायेंगे परन्तु इस निश्चित स्थिति के बाद भी अपनी इच्छा से अपने साधनों  
को दूसरों को न देना इसलिए भी जरूरी कि इस संघर्ष में होने वाली पीड़ा  
हमारे सांस्कृतिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगी।

‘पर दोगे तो

कैसे जानोगे दर्द के अभी तक

अनन्वेषित आयाम ?

क्योंकि दर्द के

अभी और बहुत आयाम हैं

बहुत आयाम है

जिन्हें संस्कृति उद्घाटित करती हैं।<sup>11</sup>

**निष्कर्ष** - निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि अज्ञेय अभिजात्य - वर्ग के प्रति  
अपनी कविताएँ ऐसे ढंग से लिख पायें जितना कोई प्रगतिवादी कवि भी  
नहीं लिख पाया।

विभिन्न कविताओं के माध्यम से स्पष्ट होता है कि अज्ञेय किसी  
विचारधारा से बंधे नहीं वे सदैव विचारधारा का अतिक्रमण करते हैं। अज्ञेय  
साम्यवादी विचारधारा के हिमायती नहीं ऐसा आरोप अनुचित है वे सम्पूर्ण  
ढंग से देखने के अनुवर्ती हैं किसी एक पक्ष को लेकर चलना उनका कविकर्म  
नहीं है। डॉ. शैल सिन्हा के शब्दों में कह सकते हैं कि इस प्रकार देखा जा  
सकता आर्थिक व्यवस्था को सुधार की भावना तथा सामाजिक वैषम्य के  
अन्त की कामना अज्ञेय में सदैव प्रबल रही।<sup>12</sup>

**संदर्भ ग्रन्थ सूची:-**

1. शैल सिन्हा - प्रयोगवाद और अज्ञेय पृ. 61
2. अज्ञेय डॉ. नामवर सिंह की पुस्तक आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियों से  
उद्धृत पृ. 139
3. अज्ञेय, इत्यलम पृ. 156
4. डॉ. नामवर सिंह आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ पृ. 140

- |  |   |
|--|---|
| 5. अज्ञेय- सदानीरा प्रथम भाग पृ. 149-150           | 9. अज्ञेय -बावरा अहेरी - पृए क्र.42-43        |
| 6. अज्ञेय - इत्यलम पृ. 70 )                        | 10. अज्ञेय - इन्द्रधनु रौंदे हुए ये - पृ. 30  |
| 7. अज्ञेय - इत्यलम पृ. 60                          | 11. अज्ञेय - अन्तरा पृ.85                     |
| 8. चन्द्रबली सिंह लोकदृष्टि और हिंदी साहित्य पृ 88 | 12. डॉ. शैल सिन्हा-प्रयोगवाद और अज्ञेय पृ. 63 |

\*\*\*\*\*



## उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में महत्व

**डॉ. शक्ति जैन\***

**प्रस्तावना** - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जिसे बने हुए 33 वर्ष पूरे हो चुके, 1986 में जब यह अधिनियम सामने आया तो यह भी उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा व उपभोक्ता जागरूकता के लिए ही बनाया गया था। परन्तु धीरे-धीरे इसमें कई कमियां व समस्याएँ आने लगी जिनमें प्रमुख रूप से कई वर्षों तक उपभोक्ता अदालतों में मामले लंबित रहना, उपभोक्ता आयोगों पर काम का बोझ, क्रेता-विक्रेता अनुबंध विक्रेता के पक्ष में झुका होना, प्रक्रिया लम्बी और महंगी तथा जटिल होना, अनुचित नियम एवं शर्तें, उपभोक्ता अदालतों में पदों का खाली रहना, जिन कर्मचारियों की नियुक्ति हो उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का ज्ञान न होना, तथा सबसे बड़ी समस्या वर्तमान समय में बढ़ता ई-मार्केट, ई-कंपनियों का बाजार में आना आदि।

इन सभी कमियों के कारण वर्तमान में बदलते उपभोक्ता बाजार में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रासंगिकता कम हो रही थी अतः उपभोक्ता के अधिकारों की हितों की सुरक्षा के लिए एवं उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों तथा जिम्मेदारी के सम्बन्ध में अधिक जागरूक बनाने की आवश्यकता को देखते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लाया गया तथा 09 अगस्त 2019 को यह देश में लागू किया गया।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम - 2019 का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुरक्षा और त्वरित न्याय का मिलना है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा समय पर प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा उपभोक्ताओं के विवाद निपटाने के लिए प्राधिकरणों की स्थापना करना है।

**उपभोक्ता की अधिनियम 2019 की प्रमुख बातें -**

**उपभोक्ता की परिभाषा**- उपभोक्ता वह व्यक्ति जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो दो बार बेचने के लिए किसी वस्तु को हासिल करता है या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेलीशापिंग, मल्टीलेबल मार्केटिंग या सीधे खरीद के जरिये किया जाने वाला सभी तरह का ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन देन शामिल है। इस तरह इसमें ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों उपभोक्ता आयोगों तथा अब उपभोक्ता कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है उपभोक्ता के हिसाब से यह बड़ी राहत है पहले उपभोक्ता वही शिकायत दर्ज कर सकता था जहाँ विक्रेता अपनी सेवाएँ देता है। ई-कामर्स से बढ़ती खरीद को देखते हुए यह अच्छा कदम है क्योंकि इस मामले में विक्रेता किसी भी लोकेशन में अपनी सेवाएँ देते हैं इसके अलावा इस अधिनियम में उपभोक्ता वीडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा भी सुनवाई करने की इजाजत है इसमें उपभोक्ता का पैसा व समय दोनों बचाता है।

**उपभोक्ता के अधिकार** - इस अधिनियम में उपभोक्ता के अधिकारों को

स्पष्ट किया गया है :-

1. ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना जो जीवन व संपत्ति के लिए जोखिमपूर्ण है।
2. वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्य की जानकारी प्राप्त होना।
3. प्रतिस्पर्धा मूल्य पर वस्तु और सेवा उपलब्ध कराने का आश्वासन प्राप्त होना।
4. अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार की स्थिति में मुआवजे की मांग करना।

**केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority) (CCPA)**- उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी सुरक्षा करने, लागू करने, उपभोक्ता को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए जाँच करने तथा जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करने और उत्पाद वापिस लेने और पीड़ित उपभोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से मुकदमा दायर करने की कार्यवाही शुरू करने के लिए केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई यह प्राधिकरण इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बिन्दु है। यह प्राधिकरण निम्न कार्य करता है -

1. व्यापार के अनुचित तरीकों की शिकायतों पर कार्यवाही।
2. उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच, इन्वेस्टिगेशन और उपयुक्त मंच पर कानूनी कार्यवाही शुरू करना।
3. जोखिमपूर्ण वस्तुओं को रीकॉल करने या सेवाओं को विद्वृत्त करने के आदेश जारी करना, चुकाई गई कीमत की भरपाई करना और अनुचित व्यापार को बंद करना।
4. खतरनाक और असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं के प्रति उपभोक्ताओं की सेप्टी नाटिस जारी करना।
5. झूठे या भ्रामक विज्ञापन को बंद करने या उसे सुधारने का आदेश जारी करना तथा जुर्माना लगाना। CCPA झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए मैनुफैक्चरर या एन्डोर्सर पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है दो बारा अपराध की स्थिति में यह जुर्माना 50 लाख रुपये तक बढ़ सकता है। मैनुफैक्चरिंग को दो साल तक की कैद की सजा भी हो सकती है जो हर बार अपराध करने पर पांच वर्ष तक बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त CCPA भ्रामक विज्ञापनों में एन्डोर्सर को उस विशेष उत्पाद या सेवा को एक वर्ष तक एन्डोर्स करने में प्रतिबंधित भी कर सकता है। एक बार में ज्यादा बार अपराध करने पर प्रतिबंध की अवधि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। तथा केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास भ्रामक विज्ञापन को हटाने का निर्देश देने का अधिकार है।

### अधिनियम की अन्य बातें :-

1. अधिनियम में उन लोगों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाहियों को भी सूचीबद्ध करने का प्रावधान है जो नकली या मिलावटी वस्तुओं के उत्पाद का विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री या आयात करते हैं।
2. किसी भी उत्पाद के कारण होने वाले नुकसान के लिए दावेदार के प्रति निर्माता की देयता निर्धारित कर 'उत्पाद देयता' कार्यवाही का प्रावधान किया गया है।
3. उपभोक्ता अदालतों में न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोगों में मध्यस्थता केन्द्रों की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुच्छेद 74-80 में वैकल्पिक विवाद पिटाना तंत्र के रूप में मध्यस्थता का प्रावधान है। जिसका उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए विधायी आधार प्रदान करता है इस प्रकार यह प्रक्रिया कम बोझिल सरल व तेज होती है यह प्रक्रिया उपभोक्ता अदालतों के तत्वाधान में क्रियान्वित की जायेगी और राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार मध्यस्थता प्रकोष्ठ के गठन का फैसला करेगी। अधिनियम की धारा 74 में उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार एक उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ की स्थापना करेगी जो उपभोक्ता अदालतों और प्रत्येक क्षेत्रीयपीठ से होगा प्रत्येक उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार कर सम्बद्ध जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग को प्रस्तुत करेगा। मध्यस्थता प्रकोष्ठ पैनल का कार्यकाल में तेजी से न्याय हो इसके लिए मध्यस्थता प्रकोष्ठ का गठन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

### ई-कामर्स के सम्बन्ध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की निम्न बातें रखी गयी हैं -

1. उपभोक्ता संरक्षण कानून में ई-कामर्स दिशा निर्देश अनिवार्य होगे जिसमें धनवापसी अनुरोध को सम्पन्न करने के लिए 14 दिन की समय सीमा शामिल होगी।
2. ई-कॉमर्स को अपनी बेवसाइट पर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने वाले विक्रेताओं का विवरण प्रदर्शित करने और उपभोक्ता शिकायतों को हल करने की प्रक्रियाकी बाध्यता होगी।
3. ई-कामर्स कंपनियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान सम्बंधी जानकारी सुरक्षित रहे।
4. वस्तु वापसी, धन वापसी, वस्तु बदलने वारंटी/गारंटी, वितरण/शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र आदि के बारे में विक्रेता और ई-कामर्स इकाई के बीच अनुबंध की शर्तें उपभोक्ताओं को सूचित व प्रकाशित की जानी चाहिए।
5. मैनुफैक्चरिंग में खामी या खराब सेवाओं में अगर उपभोक्ता को नुकसान होता है तो इसे बनाने वाली कंपनी को हर्जाना देना होगा इसके साथ उपभोक्ता को होने वाले नुकसान / हादसे का भी जुर्माना देना होगा जैसे मैनुफैक्चरिंग में खराबी के कारण प्रेशर कुकर में कटने पर उपभोक्ता को चोट पहुंचती है तो उस हादसे के लिए कंपनी को प्रेशर कुकर की लागत के साथ नुकसान का हर्जाना भी देना होगा।
6. ई-कामर्स प्लेटफार्म में सेवा प्रदाता भी शामिल होंगे। प्रोडक्ट की जवाबदेही अब मैनुफैक्चर के साथ सर्विस प्रावाइडर और विक्रेताओं पर भी होगी।
7. ई-कामर्स कंपनियों पर डायरेक्ट सेलिंग पर लागू सभी कानून प्रभावी

होंगे। जैसे अमेजन, फिलिपकार्ट, स्नेपडील जैसे प्लेटफार्म को विक्रेताओं के व्योरे का खुलासा करना होगा इसमें उनका पता, बेवसाइट, ई-मेल आदि शामिल हैं।

8. ई-कामर्स कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि वे सुनिश्चित करे कि उनके प्लेटफार्म पर किसी तरह के नकली उत्पाद बिक्री न हो अगर ऐसा होता है तो कंपनी पर पैनल्टी लगेगी। यह कदम उठाना बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि ई-कामर्स प्लेटफार्म पर नकली उत्पादों की बिक्री के मामले बढे हैं।

**उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन (CDRCS) (Consumer Disputes Redressal Commission)** - जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन का गठन किया गया है एक उपभोक्ता निम्न के सम्बन्ध में आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है :-

1. अनुचित और प्रतिबंधित तरीके का व्यापार
2. दोषपूर्ण वस्तु या सेवायें
3. अधिक कीमत वसूलना या गलत तरीके से कीमत वसूलना
4. ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री के लिए पेश करना जो जीवन और सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण हो सकती हैं।

जिला CDRC के आदेश के खिलाफ राज्य CDRC में सुनवाई की जायेगी तथा राज्य CDRC के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय CDRC में सुनवाई की जायेगी। अंतिम अपील का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा।

### CDRC का क्षेत्राधिकार

1. जिला CDRC उन शिकायतों के मामलों की सुनवाई करेगा जिनके वस्तुओं और सेवाओं की कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक न हो।
2. राज्य CDRC उन शिकायतों के मामलों की सुनवाई करेगा जिनके वस्तुओं और सेवाओं की कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक हो लेकिन 10 करोड़ से अधिक न हो।

CONSUMER PROTECTION ACT 1986	PROVISIONS	CONSUMER PROTECTION ACT 2019
No separate regulator	Regulator	Central Consumer Protection Authority (CCPA) to be formed
Complaint could be filed in a consumer court where the seller's (defendant) office is located	Consumer court	Complaint can be filed in a consumer court where the complainant resides or works
No provision. Consumer could approach a civil court but not consumer court	Product liability	Consumer can seek compensation for harm caused by a product or service
District: up to ₹20 lakh State: ₹20 lakh to ₹1 cr National: above ₹1 cr	Pecuniary jurisdiction	District: up to ₹1 cr State: ₹1 cr to ₹10 cr National: Above ₹10 cr
No provision	E-commerce	All rules of direct selling extended to e-commerce
No legal provision	Mediation cells	Court can refer settlement through mediation

3. 10 करोड़ रुपये से अधिक की कीमत की वस्तुओं और सेवाओं से सम्बन्धित शिकायत राष्ट्रीय CDRC द्वारा सुनी जायेगी।
4. उपभोक्ता अदालतों में उपभोक्ता विवादों के मामलों में निर्णय देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से कई प्रावधान किये गये हैं जैसे -

उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के वित्तीय अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना, शिकायतों के त्वरित निपटाने की सुविधा के लिए उपभोक्ता अदालतों में न्यूनतम सदस्य संख्या बढ़ाना, राज्य तथा जिला आयोग द्वारा अपने स्वयं के अदेशों की समीक्षा करने का अधिकार।

5. शिकायतों के त्वरित निपटाने की सुविधा के लिए सर्किट पीठ का गठन।
6. जिला अदालत के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया में सुधार
7. आन लाइन शिकायतें दर्ज करना तथा उसे उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराना जिसके अधिकार क्षेत्र में शिकायतकर्ता का निवास आता हो।

#### अधिनियम की उपयोगिता -

1. केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के माध्यम से विधेयक में त्वरित न्याय की व्यवस्था की गयी है।
2. भ्रामक विज्ञापनों व मिलावट के लिए कठोर सजा का प्रावधान है ताकि इस तरह के मामलों में कमी आये।
3. दोषपूर्ण उत्पादों या सेवाओं को रोकने के लिए निर्माताओं और सेवादाताओं की जिम्मेदारी का प्रावधान होने से उपभोक्ताओं को छानबीन करने में अधिक समय खर्च करने की जरूरत नहीं होगी।

4. उपभोक्ता आयोग से सम्पर्क करने में आसानी और प्रक्रिया का सरलीकरण होना।

इस तरह यह अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पर सुधार के रूप में आया है। इसकी बहुत ही अधिक आवश्यकता थी इस अधिनियम में त्वरित न्याय व उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा का ध्यान दिया गया है। इस नये कानून में उझअअ का गठन, भ्रामक व झूठे विज्ञापन पर नियम, मध्यस्थता प्रकोष्ठ का गठन, ई-कामर्स फर्मों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेचने वाली कंपनियों के लिए दिये गये सख्त दिशा निर्देश इस अधिनियम की उपयोगिता को बताते हैं। अब आवश्यकता है कि उपभोक्ता जागरूक रहे और आवश्यकता पड़ने पर इस अधिनियम का लाभ उठाये। निश्चित है यह अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने व जागरूक करने तथा समय पर न्याय दिलाने में प्रभावी और मददशील होगा।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पत्रिका योजना दिसम्बर 2019
2. उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986, 2019 (भारत का राजपत्र)
3. PRS Legislative Research
4. www.drishtias.com
5. Economic Times App.

\*\*\*\*\*

## हैदराबाद के निजाम संग्रहालय में संग्रहित 18वीं-19वीं शताब्दी में निजाम परिधान के सन्दर्भ में

डॉ. आशीष गर्ग\* साक्षी सिंहवाल\*\*

**प्रस्तावना** - तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित निजाम संग्रहालय पुरानी हवेली में स्थित है। यह संग्रहालय निजाम शासकों की बेशकीमती चीजों के लिये विश्व प्रसिद्ध है। इस हवेली के पूर्वी हलके में सीढ़ियों से चढ़ते ही आपको निजाम शासकों की शानो-शौकत दिखाई देने आरम्भ हो जाती है। यह हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान के **240 फुट** लम्बे इमारती लकड़ी के **वाईरोब** के बीच का हिस्सा है। इस दो मंजिला वाईरोब को दुनिया का सबसे बड़ा वाईरोब माना जाता है, जिसमें इनकी शाही पोशाकें, जूते, पगड़ियां ही नहीं वरन् आसिफ जाह खानदान के शानदार जेवरात और दुनिया भर से एकत्र की गयी अनोखी कलाकृतियों का आकर्षक संग्रह है।



अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में मुगल सम्राट औरंगजेब ने मीर कमरुद्दीन को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया। योग्य एवं कर्मठ कमरुद्दीन को सन् 1713 में फर्रुखसियर ने 'निजात-उल-मुल्क-फतेह जंग' की उपाधि प्रदान की। उसके बाद से ही वे और उनके वंशज '**निजाम**' के नाम से अधिक लोकप्रिय हुए, जिससे तत्कालीन मुगल शासकों का प्रभाव धीरे-धीरे कम होने लगा और वे एक स्वतन्त्र शासक के रूप में राज करने लगे।

निजाम शासकों की जीवन-शैली एवं दरबार-पद्धति मुगलों से प्रभावित रहीं, ऐसा उनके लघु-चित्रों एवं छाया-चित्रों को देखकर लगता है, जो आज हैदराबाद के चौमोहल्ला महल, पुरानी हवेली, सालारजंग संग्रहालय, राजा दीन दयाल संग्रह एवं अनेक निजी संग्रहों में संग्रहित हैं। इन चित्रों में निजाम शासक मुगलों की ही भाँति जामा-पजामा-पटका-पगड़ी पहने दिखायी देते हैं। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले परिधान '**जामा**' वस्तुतः मध्य एशिया में पहने जाने वाले परिधान हैं, जो मुस्लिम शासनकाल से भारत में

भी लोकप्रिय हुई। मध्यकालीन लघु-चित्रों में सभी मुगल राज 'जामा' पहने की दशाये गये हैं। राजाओं की रूचि के अनुसार समय-समय पर जामा की लम्बाई, घेरे इत्यादि में परिवर्तन होते रहे हैं। वस्तुतः जामा परिधान ऊपर से कसी हुई और नीचे से स्कर्ट की भाँति घेरदार होती थी और इसे वक्षस्थल पर बाँधने के लिये अनेक डोरियों का प्रयोग किया जाता था। कभी-कभी तो ये डोरियाँ इतनी लम्बी होती थी कि कमर तक लटकती थी। जामा के लिए ज्यादातर राजाओं ने सूती अथवा मलमल वस्त्र का प्रयोग किया, जिसका आयात निजाम परिवार मिस्त्र से करते थे, ताकि गर्मी में ये परिधान अधिक आरामदेह रहें। यूँ तो रेशम और जरी से बने ब्रोकेड वस्त्रों का उपयोग समय-समय पर, अवसर के अनुरूप किया जाता रहा है।



निजाम शासकों के चित्रों में उन्हें मलमल के घेरदार जामा और ब्रोकेड वस्त्रों को प्रदर्शित किया गया है। सम्भवतः इस समय तक आते-आते निजाम अपने धन-वैभव को दर्शाने लगे थे। निजाम महबूब अली पाशा का राज्याभिषेक सिर्फ सात वर्ष की उम्र में हुआ और उन्हें हरे रंग का मखमल का चोगा, जिस पर जरदोजी से कढ़ाई की गयी थी, पहना था। इसी प्रकार सातवें निजाम उस्मान अली ने सन् 1911 में अपने राज्याभिषेक के अवसर पर जो रेशम की लाल रंग की ब्रोकेड शेरवानी पहनी थी, वह अभी भी हैदराबाद के निजाम संग्रहालय में सुरक्षित है।

**जामा, अचकन या शेरवानी** के साथ **चूड़ीदार पजामा** ही निजाम शासकों की पसन्द रही। यद्यपि चूड़ीदार पजामा के अतिरिक्त चौड़े पाँवचे के पजामे का भी प्रयोग निजाम परिवार में हुआ है, जैसाकि चौमोहल्ला महल,

\* पी.एच.डी. असिस्टेंट प्रोफेसर (ड्राइंग एंड पेंटिंग) फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट श्री राम कॉलेज, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत  
\*\* एम.एफ.ए. IV<sup>th</sup> सेमेस्टर (टैक्सटाइल) श्री राम कॉलेज, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत



पुरानी हवेली एवं अन्य संग्रहालय के छवि-चित्रों में देखने को मिलता है।



मूल परिधानों के अतिरिक्त कमर पर कमरबन्द अथवा पटके का प्रयोग किया। छह फुट लम्बे और डेढ़ फुट चौड़े पटके को जामा के ऊपर दो से तीन बार कमर पर इस प्रकार लपेटा जाता था कि उसके पल्लू का एक हिस्सा सामने की ओर लटकता रहता था, जो पूरे परिधान को एक आकर्षक स्वरूप प्रदान करता था।

महबूब अली पाशा के समय से पटके के स्थान पर **बैल्ट** का प्रचलन अधिक हुआ, तभी तो उनके आभूषणों के संग्रह में सोने की बनी एक दर्जन से भी बैल्ट हैं। ये सभी बैल्ट सोने अथवा जरी के तार से बनी हुई हैं और बकल हीरे, मोती, पन्ना, माणिक से सुसज्जित हैं।



प्रारम्भिक निजाम शासकों ने सफेद रंग की पगड़ी का ही प्रयोग किया। कालान्तर में महबूब अली पाशा ने यूरोपीय हैट की ही भाँति सिली हुई पगड़ी पहननी प्रारम्भ की, जिसे '**दस्तार**' (तुर्की भाषा का शब्द) भी कहते हैं। अलग-अलग रंगों की दस्तार समाज के विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों की सामाजिक हैसियत की पहचान भी बनी। उदाहरणतः निजाम हमेशा **पीले रंग** की दस्तार पहनते थे, जिस पर मणियों से जड़ित '**सरपेंच**' लगा होता था, जिसे कोई अन्य व्यक्ति नहीं पहन सकता था। निजाम के पश्चात् सामाजिक स्तर पर पगाह परिवार को प्रायः गुलाबी पगड़ी में देखा जाता था और इसी प्रकार अन्य लोगों की भी पगड़ी का रंग निश्चित था।



**जामा-पजामा-पटका-पगड़ी** के प्रारम्भिक परिधान के अलावा महबूब अली पाशा के समय में यूरोपीय फैशन के अनुरूप कुछ परिवर्तन करते हुए दो नये परिधान फैशन में आये, जिन्हें **अचकन शेरवानी** कहते हैं। घेरदार जामा के स्थान पर कम घेर वाली इन दोनों परिधानों की लम्बाई भी कम की गई थी। जामा के सीधे कन्धे के कटाव के स्थान पर यूरोपीय कोट की भाँति अचकन एवं शेरवानी के कन्धे की कटाई थोड़ी झुकी हुई की गयी। चोगे के ढीले-ढाले परिधान की जगह टाइट फिटिंग वाली अचकन और शेरवानी का प्रचलन बढ़ा, जो आज भी बहुप्रिय परिधानों में से एक है।



निजाम के अनेक छाया-चित्रों, लघु-चित्रों एवं पुस्तकों की मद से ज्ञात होता है कि निजाम की बेगमों भी उन्हीं की तरह वस्त्र एवं जेवरात की शौकीन थी। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निजाम शासकों की पत्नियों ने भी उन्हीं की भाँति मुगल बेगमों से प्रभावित होकर **पेशवाज-चूड़ीदार पजामा-चोली-दुपट्टा** को ही ज्यादा पहना। यद्यपि अंगरखी, कुर्ता एवं कुर्ती के अतिरिक्त साड़ी, चोली अथवा ब्लाउज का उपयोग भी निजाम बेगमों ने किया। उन्होंने पैठन, बनारस, चन्देरी, कश्मीर इत्यादि स्थलों के अतिरिक्त चीन से भी रेशम के कपड़े का आयात कर अपनी पसन्द के परिधान भी बनवाये। ब्रोकेड वस्त्रों के अतिरिक्त जरी, गोटे, किनारी का काम उस समय काफी लोकप्रिय हुआ और बेगमों के वस्त्रों में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाया गया। मुस्लिम प्रभाव के अतिरिक्त पारम्परिक हिन्दू परिधानों जैसे-साड़ी, चोली का प्रयोग भी काफी हुआ। यहाँ पैठन, चन्देरी तथा बनारस से निरन्तर वस्त्रों का आयात हुआ करता था।



परिधान '**पेशवाज**' जामा की ही भाँति तंग चोली और खूब घेरदार स्कर्ट की भाँति बनी हुई होती थी, जिसे सम्भवतः निजाम बेगमों ने मुगल बेगमों से प्राप्त किया था। 'पेशवाज' की लम्बाई 'जामा' की भाँति अधिक नहीं बल्कि केवल घुटने तक ही हुआ करती थी। सफेद अथवा रंगीन मलमल की बनी हुई पेशवाज को प्रायः जरी की गोटा-किनारी इत्यादि से गले, कन्धे, घेरे एवं सामने की ओर आकर्षक ढंग से सजाने का प्रचलन काफी लोकप्रिय हुआ। चोली में सामने की ओर 'आई-हॉल' अर्थात् आँख के आकार का छेद हुआ करता था, जो अठारहवीं शताब्दी की पहाड़ी शैली के लघु-चित्रों में भी देखने को मिलता है।



निजाम बेगमों पेशवाज के अतिरिक्त '**अंगरखी**' परिधान भी पहना करती थी। पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाले परिधान '**अंगरखा**' की ही भाँति अंगरखी होती थी, जिसकी लम्बाई कुछ छोटी हुआ करती थी। तंग चोली और घेरदार इस परिधान का ऊपरी हिस्सा यानि चोली गोलाकार सजी होती थी और पेशवाज की तरह उसमें कोई छेद (आई-हॉल) नहीं होता था। बेगमों के चित्रों को देखने से और उपलब्ध साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि पेशवाज के साथ चूड़ीदार पजामा का चलन था। जरी-ब्रोकेड के इन चूड़ीदार पजामों पर प्रायः फूल-पत्ती के डिजाइन बने होते थे। बेगमों के पजामों में एक ओर खास बात होती थी कि उनके पाँवचे जरी की गोटा अथवा किनारी से सजे होते थे।

निजाम बेगमों का दुपट्टा ओढ़ने का तरीका भी अत्यन्त आकर्षक होता था। इस दुपट्टे की लम्बाई-चौड़ाई उत्तर भारत की ओढ़नी से दोगुनी हुआ करती थी। उत्तर भारत में औरतें ज्यादातर ओढ़नी से वक्षस्थल और सिर को ढका करती थी, लेकिन दक्षिण भारत में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है कि निजाम बेगमों प्रायः इस प्रकार दुपट्टा ओढ़ती थी कि उससे उनका पूरा शरीर एक प्रकार से ढक जाता था और दुपट्टे का एक छोर बंगाली साड़ी की भाँति सामने की ओर पूरी तरह खुला हुआ रहता था और अन्तिम छोर पर माणिक से जड़ित ब्रोच लटकन की भाँति जुड़ा रहता था। इस प्रकार से दुपट्टा ओढ़ने के तरीके को '**खड़ा दुपट्टा**' कहा जाता था। हाँलाकि कुछ चित्रों में उन्हें लहंगे पर दुपट्टे को साड़ी की ही भाँति लपेटे हुये दर्शाया गया है। कभी-कभी दुपट्टे को शॉल की तरह ओढ़े हुए भी दिखाया गया है। वर्तमान में भी इस फैशन का अनुसरण किया जा रहा है।



अठारहवीं-उन्नीसवीं शताब्दी में छोटी-छोटी और आगे से नुकीली एवं घुमावदार जूती का चलन आया था, तभी तो अनेक छाया-चित्रों में बेगमों को इस प्रकार की जूती पहने हुये दिखाया गया है। छोटी-छोटी जूतियाँ हों या बड़ा सा दुपट्टा या फिर वेलवेट के परिधान, जरदोजी का और सिल्क-

ब्रोकेड का काम सभी प्रकार के परिधानों में नजर आता है। उनमें रंगों एवं डिजाइनों का सुखचिपूर्ण संयोजन देखने को मिलता है। सुर्ख रंगों का प्रयोग एवं ज्यादा फूल-पत्ती के डिजाइनों का प्रचलन भी निजाम शाही परिवार के परिधानों में नजर आता है।

खूब सारे जेवरों और रंग-बिरंगे वस्त्रों से सुसज्जित निजाम एवं उनकी बेगमों के चित्रों को देखकर निजाम शासकों के वैभव एवं उनकी फैशन के प्रति रुचि का ज्ञान होता है, जिसे आज भी काफी हद तक अनुसरण

किया जाता है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. संग्रहाध्यक्ष, सुसज्जा एवं वस्त्र कला, राष्ट्रीय संग्रहालय, जनपथ, नई दिल्ली।
2. निजाम संग्रहालय, पुरानी हवेली, हैदराबाद (तेलंगाना)।
3. चौमोहल्ला महल संग्रहालय, हैदराबाद (तेलंगाना)।
4. 'ए गाइड टू हेरिटेज ऑफ हैदराबाद', मधु वोटे, 01 सितम्बर 2010।

\*\*\*\*\*



## भारत की अर्थव्यवस्था पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) का प्रभाव

**डॉ. राजीव कुमार झालानी\* माधुरी रोजड़े\*\***

**शोध सारांश** – माल एवं सेवाकर वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। जीएसटी में सभी प्रकार के करों जैसे – उत्पादन शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर और मूल्य वर्धित कर आदि को एक ही शासन के तहत लिया गया है। जीएसटी के तहत 3 टैक्स लागू हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। माल एवं सेवाकर कर का परिचय देश के एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में अपेक्षित किया गया है, जो भारत की आर्थिक विकास का नेतृत्व करेगा। प्रस्तावित अध्ययन विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के प्रभावों को जानने के लिए किया गया है। अध्ययन कि प्रकृति खोजपूर्ण है और अध्ययन के लिए माध्यमिक डेटा का उपयोग किया गया है। डेटा विभिन्न प्रकार के पत्रिकाओं, समाचार पत्रों से एकत्रित किया हुआ है।

**शब्द कुंजी** – माल एवं सेवाकर, दोहरा माल एवं सेवाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था, मूल्य वर्धित कर।

**प्रस्तावना** – जीएसटी एक विशाल अवधारणा है, जो किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि को समर्थन और बढ़ावा देकर विशाल कर संरचना को सरल बनाती है। जीएसटी सभी वस्तु और सेवाओं के विनिर्माण, बिक्री और उपभोग को एक व्यापक कर श्रेणी में लाती है। माल एवं सेवाकर विधेयक है, जिसे संविधान विधेयक 2014 के रूप में भी जाना जाता है। भारत में माल एवं सेवाकर एक राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने वाले मूल्यवर्धित कर की शुरुआत करता है। माल एवं सेवाकर उत्पादन के सभी चरणों पर अप्रत्यक्ष कर के रूप में वसूल किया जाता है जो कि कर प्रणाली में एकरूपता लाने के लिए है। इसमें जीएसटी का केन्द्र और राज्य करों के रूप में समामेलन किया गया है जो कि घरेलू बाजार एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार को बढ़ाने के साथ-साथ भारत की स्थिति को भी बढ़ाएगा। माल एवं सेवाकर उपभोक्ता स्तर पर भी कर का बोझ कम करेगा। इसके अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम में यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता द्वारा एक स्तर पर कर के भुगतान करने पर दूसरे स्तर पर इनपुट टैक्स रिबेट प्रदान की जाती है। विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष जैसे केन्द्रीय स्तर पर उत्पादन शुल्क और सेवा कर और राज्य स्तर पर वैट जैसे कुछ करों के भुगतान से बचने के लिये जीएसटी इन करों को एकीकृत करेगा और पूरे देश में एक समान बाजार बनाएगा।

**माल एवं सेवाकर का अर्थ** – अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में माल एवं सेवाकर एक नवीनतम अवधारणा के रूप में प्रस्तुत हुआ है। यह कर को माल एवं सेवाकर (GST) के रूप में भारत में प्रचलित हुआ है। इस कर के अंतर्गत जितनी बार भी माल बेचा जाता है या सेवाएँ प्रदान की जाती हैं इस पर यह कर वसूल किया जाता है अर्थात् किसी भी वस्तु एवं सेवाकर के लागत मूल्य में जो वृद्धि होती है उस पर यह कर वसूल किया जाता है एवं इस कर का अंतिम भार उपभोक्ता पर पड़ता है।

**माल एवं सेवाकर के प्रकार** –

1. **केन्द्रीय माल एवं सेवाकर (सीजीएसटी)** – यह भारत की केन्द्रीय सरकार के द्वारा वसूल किया जाता है एवं इस कर से वसूल की कर की सम्पूर्ण राशि पर केन्द्र का अधिकार होता है। माल एवं सेवाकर लागू होने से

पहले केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं विभिन्न प्रकार के उपकर जैसे विशेष उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क आदि कर वसूल किये जाते थे।

2. **राज्य माल एवं सेवाकर (एसजीएसटी)** – यह कर देश की विभिन्न राज्य की ओर से वसूल किया जाता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत राज्यों को माल की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार दिया गया। इस कर के लागू होने से वैट प्रवेश शुल्क अधिक कर समाप्त हो गये थे।

3. **एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी)** – अंतर्राज्यीय यानि दो राज्यों के बीच होने वाले माल एवं सेवाओं के आदान-प्रदान के साथ ही आयतों पर भी यह कर वसूल किया जाता है। यह कर केन्द्र सरकार के द्वारा एकत्रित किया जाता है और आगे इससे संबंधित राज्य की राज्य सरकार के बीच वितरित कर दिया जाता है। आईजीएसटी उस समय लगाया एवं वसूल किया जाता है जब किसी उत्पादन या सेवा को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाता है।

**भारत में माल एवं सेवाकर के सकारात्मक प्रभाव :**

1. माल एवं सेवाकर से भारत के राजस्व में वृद्धि होती है क्योंकि यह प्रत्येक व्यवहार में बढ़े हुए मूल्य पर कर वसूल किया जाता है और यह कर सरकार को मिलता है।
2. माल एवं सेवाकर अपनाने से कर के अपवंचन पर भी रोक लगी है।
3. माल एवं सेवाकर, उत्पादकों द्वारा माल एवं सेवा श्रृंखला में भुगतान किए गए करों के लिए क्रेडिट प्रदान करेगा। इससे उत्पादकों को विभिन्न पंजीकृत डीलरों से कच्चा माल खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

**भारत में माल एवं सेवा कर के नकारात्मक प्रभाव :**

1. माल एवं सेवा कर में रिटर्न प्रस्तुति कम्प्यूटरों के द्वारा की जाती है जिसके साथ ही बहुत से छोटे व्यापारी बीजक-पत्र व हिसाब-किताब रखने से व ऑनलाईन प्रक्रिया से बचने का हमेशा प्रयत्न करते हैं।
2. माल एवं सेवा कर के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्र व राज्य दोनों सरकारों को अपने स्तरों पर कर के प्रशासन के लिए कर्मचारियों को



ठीक तरह से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

3. माल एवं सेवाकर एक नई कर प्रणाली है जिसे लोगों को इसे पूरी तरह समझने में कुछ समय और लगेगा।

#### **साहित्य का पुनरावलोकन -**

1. **विश्व बैंक (2018)** - 'जीएसटी इन इंडिया' ने सभी शोध के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला है कि भारतीय माल एवं सेवाकर प्रणाली दुनिया की सबसे जटिल कर प्रणाली है। इसकी उच्च कर की दरें व बड़ी कर की दर इसकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।
2. **राठौड़ एम. (2019)** - इन्होंने अपने शोध में पाया कि जीएसटी एक भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है जो पूरे राष्ट्र को लाभान्वित करेगा।

**शोध प्रविधि** - प्रस्तुत शोध की प्रकृति एक वर्णनात्मक प्रकृति है क्योंकि इस शोध में विभिन्न क्षेत्रों पर माल एवं सेवा कर के प्रभावों के बारे में बताया गया है और इसके सम्बन्ध में विभिन्न आंकड़े जीएसटी के बारे में प्रकाशित विभिन्न लेखों, शोध पत्रों एवं पुस्तकों के माध्यम से एकत्रित किये गये हैं।

#### **अध्ययन का उद्देश्य :**

1. माल एवं सेवाकर की अवधारणा समझने व अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना इस शोध पत्र का उद्देश्य है।
2. माल एवं सेवा कर के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के लिए।

1. **आर्थिक गतिविधि पर प्रभाव** - माल एवं सेवाकर आर्थिक गतिविधि पर सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है या नहीं यह मूल्यांकन करना बहुत कठिन है। भारतीय प्रशासन की कर व्यवस्था यह मानती है। जीएसटी के साथ वह एक सही रास्ते पर कार्य कर रही है। भारतीय व्यापार कार्यकारी माल एवं सेवाकर के साथ एक आषावादी दृष्टिकोण से साझा करता है 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट में आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर से यह कहा है। माल एवं सेवाकर परिवर्तनकारी संस्थानात्मक सुधार है, जिसे कई प्रकार के फायदे हैं व इन लाभों से एक राष्ट्रीय बाजार की स्थापना सुगम होती है व बेहद उत्पादकता होती है। माल एवं सेवाकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा कदम साबित हो सकता है।

2. **ऑटोमोबाइल सेवा पर माल एवं सेवाकर के प्रभाव** - माल एवं सेवाकर लागू होने से पहले ऑटोमोबाइल उद्योग पर 30-45 प्रतिशत की बीच की कर का भुगतान किया जा रहा था। लेकिन यह कर प्रणाली लागू होने के बाद 18 प्रतिशत की निर्धारित दर से कर का भुगतान किया जो एक सकारात्मक प्रभाव डालती है। यह दर डीलरों, उपभोक्ताओं, निर्माता सबके लिए लाभदायक होगी। माल एवं सेवाकर लागू होने से ऑटोमोबाइल उद्योग

में भारी उछाल देखा गया है।

3. **उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवा पर प्रभाव** - माल एवं सेवाकर लागू होने से माल व उपभोग भी कई वस्तु एवं सेवा पर इसके प्रभाव को देख सकते हैं। यह कर प्रणाली लागू होने से कुछ खाद्य वस्तु जो कर मुक्त थी उन वस्तु को कर की श्रेणी में रखा गया है और वस्तु कर योग्य थी उन्हें कर मुक्त कर दिया गया है। कुछ खाद्य उत्पादों पर 0 प्रतिशत लगता है परंतु कुछ सेवाओं पर 15 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की वृद्धि देखी जा सकती है।

4. **दवा उद्योग पर माल एवं सेवाकर के प्रभाव** - मानव जीवन में दवायें एक जीवन दायनी औषधी का काम करती हैं। माल एवं सेवाकर लागू होने से दवा उद्योग पर प्रभाव देखा जा सकता है। कुछ दवाइयों पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है और कुछ दवाइयों पर 12 प्रतिशत की दर से। इस दर में वह उत्पादन शुल्क विभिन्न प्रकार के कर को शामिल किया जाता है।

5. **कपड़ा उद्योग पर प्रभाव** - कपड़ा उद्योग पर माल एवं सेवाकर की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। जीएसटी के अंतर्गत एक प्रभाव यह भी है कि यहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था इसके अंतर्गत आएगी। यदि कोई पंजीकृत करदाता कंपोजिशन स्कीम से इनपुट खरीदता है, जो इसकी अनुमति नहीं है। यह पुंजीगत वस्तुओं पर चुकाए गए कर के लिए उपलब्ध है।

6. **टेलीकॉम सेंटर पर माल एवं सेवाकर का प्रभाव** - टेलीकॉल सेंटर पर दूर संचार सेवाओं पर माल एवं सेवाकर की दर 18 प्रतिशत कर दी गई है। जो पहले की दरों से बहुत अधिक है। इसका असर आम आदमी के बजट पर पड़ता है।

**निष्कर्ष** - भारत देश की अर्थव्यवस्था में दक्षता और समानता एक अच्छी कर प्रणाली के द्वारा ही लाई जा सकती है। एक अच्छी कर प्रणाली की आय के वितरण के साथ सरकार को राजस्व उत्पन्न करना चाहिए। माल एवं सेवाकर प्रणाली लागू होने से कराधान प्रणाली में सरलता और पारदर्शिता बन गई है। यह कर प्रणाली भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक विकास के लिए मजबूती प्रदान करेगा। माल एवं सेवाकर प्रणाली अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में उपलब्ध सभी प्रकार की जटिलताओं को हल करेगा। यह विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं, उत्पादकों व सरकार को राहत प्रदान करेगा।

#### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. Model of GST law
2. [www.finmin.nic.in/report/model\\_gstow\\_draft.law](http://www.finmin.nic.in/report/model_gstow_draft.law)
3. दैनिक भास्कर
4. टाइम्स ऑफ इंडिया
5. इंडिया टुडे

\*\*\*\*\*

## Effects of mental health during Covid-19

Dr. Sonali Singh\*

**Abstract** - We all know that Covid-19 has an impact on the mental health of every person. As the coronavirus pandemic rapidly sweeps across the world, it is inducing a considerable degree of fear, worry and concern in the population at large and among certain groups in particular, such as older adults. Care providers and people with underlying health conditions. In public mental health terms, the main psychological impact to date is elevated rates of stress or anxiety. But as new measures and impacts are introduced – especially quarantine and its effects on many people's usual activities, routines or livelihoods – levels of loneliness, depression, harmful alcohol and drug use, and self-harm or suicidal behaviour are also expected to rise. In populations already heavily affected, such as Lombardy in Italy, issues of service access and continuity for people with developing or existing mental health conditions are also now a major concern, along with the mental health and well-being of frontline workers. As part of its public health response, WHO has worked with partners to develop a set of new materials on the mental health and psychosocial support aspects of COVID-19.

**Looking after our mental health** - As countries introduce measures to restrict movement as part of efforts to reduce the number of people infected with COVID-19, more and more of us are making huge changes to our daily routines. The new realities of working from home, temporary unemployment, home-schooling of children, and lack of physical contact with other family members, friends and colleagues take time to get used to. Adapting to lifestyle changes such as these, and managing the fear of contracting the virus and worry about people close to us who are particularly vulnerable, are challenging for all of us. They can be particularly difficult for people with mental health conditions. Fortunately, there are lots of things that we can do to look after our own mental health and to help others who may need some extra support and care.

**Worries For Future** - Peter Kinderman, a professor of clinical psychology at the University of Liverpool and a former chair and president of the British Psychological Society, has been researching into mental health and suffering. He believes that most people in Britain will be more concerned about their future, and the economy, opposed to the current pandemic.

"I think that the pandemic itself, the virus, is a significant challenge for people. But I think we understand that collectively and we're okay with that," Kinderman told Xinhua. He stresses that his main concern is how people will react to the future issues that arise - the knock-on effects of the pandemic: potential higher taxation, unemployment, and recession. These have all been factors in psychology studies on mental health after major world crises.

According to Kinderman, in previous pandemics like

Black Death that ravaged Europe between 1347 and 1351, the social and psychological structures were challenged by the aftermath of that particular disease event.

The 1918 influenza pandemic also seemed to have major impacts on mental health across Europe, albeit findings have been tied in with the consequences of the World War .

"My real fear is that as we come out of this with significant numbers of people unemployed, very significant changes to working practices, a lot of people in financial difficulties, massive investments by the government using taxpayers' money that people will have to pay back ... the consequences for the economy and the social disruption that that causes will be where the major mental health, emotional, behavioural consequences form," Kinderman said. The professor believes that this could give rise to fear and anxiety in people across Britain, possibly giving way to depression.

**Wellbeing Under Pressure** - Many people across Britain, like Mitchell, are appearing to adapt to lockdown relatively well.

Mitchell has stuck to a routine of making sure to exercise everyday, stay in touch with friends and family, and have all of his chores done by the end of each day. He believes this has been key to keeping him relatively positive.

"Lots of my colleagues are doing research into the question: What is it about the current situation that you find difficult, or indeed uplifting and positive?" Kinderman said.

He said in broad terms the three strongest predictors of wellbeing are physical health, relationships and the sense of meaning and purpose.

"The physical health is under threat at the moment - not only from the virus, but by lack of physical exercise," he said, adding that there is a strain on relationships as "we in lockdown are not seeing people nor can we talk about things in quite the same way".

"And the sense of meaning and purpose, and I think one of the things that is worrying about this period is a lot of people seem to be waiting."

**Exiting Lockdown -** Like many others, Mitchell said that he is conflicted in what he wants to happen next. He wants the lockdown to end, but also wants to make sure that it is safe to go out.

"As lockdown eases I think we're going to see a lot of very complicated but essentially normal human reactions to a really unusual situation," Kinderman said.

He believes that being in this conflicting state is emotionally difficult to process.

"When the lockdown does lift, I think those of us who've been paying attention will be worried about a second wave of infection. So we'll be keen to get out there and do things but we'll also be worried. We'll probably be making adjustments, so we'll probably be outdoors and interacting

with people but wearing face masks.

**Conclusion -** Currently there are a number of studies being undertaken by psychologists to try and better understand how people are being mentally affected by the coronavirus pandemic. Another study, which Kinderman is lending his expertise to, is surveying over 90,000 people across Britain to see how they can identify which groups are more at risk and understand the effects of any potentially protective activities people could be engaging in - this will help to inform the advice people are given about how to stay well at home. But throughout his research on mental health and lockdown, Kinderman is keen to emphasise that humans always find a way to work together when under threat.

#### References :-

1. Anushree Gupta Updated May 24, 2020 | 14:00 IST After-effects of COVID-19 pandemic may trigger mental health issues, and it is worrisome
2. WHO briefing note – Mental health and psychosocial considerations during COVID-19 outbreak [www.euro.who.int>healthtopic.
3. World health organization-Healthy At home-mental health,2020.

\*\*\*\*\*

## Management of Agricultural Waste

Dr. Sadhna Goyal\*

**Introduction** - Waste is a valuable raw material located at a wrong place. It can be converted into useful products by making use of appropriate processing technology. Agriculture wastes are non edible oil seeds, waste from fruit and vegetable processing, bagasse and pressmud from sugar factories. Modern advances in science and technology have led to very profitable utilization of wastes and many of the developed and industrialized countries have taken great strides in this field. Utilization and recycling of wastes is a complex field where there is a meet for continued techno economic studies as a base for policy development to advance the government for short term as well as long term policies for action oriented programs. Because of the tremendous magnitude of the problem in India, there is a tremendous need of research and development work in the field of waste utilization to a level that can be implemented so as to add to the national wealth.

**Observation** - In the 21<sup>st</sup> century rural environment in most parts of the world has been transformed. Government has encouraged the adoption of modern varieties of crops and modern breeds of life stock together with the associated packages of external inputs such as fertilizers, pesticides, antibiotics necessary to make them productive. Since agriculture has been modernized, inorganic fertilizers are being used on a large scale. As agriculture has developed there has also been an increase in the population of cattle and pigs. This has led to an increase in the number of cattle sheds. Poultry has also increased considerably. Intensive conversion of the solid wastes agricultural into compost manure by a process called vermiculture. Agriculture cellulosic waste such as bagasse and corn cobs can be converted into Glucose by a new technique developed in USA. In India for an efficient disposal of solids cellulosic waste in metropolitan cities to control soil pollution problems. Enzymatic degradation of agricultural waste is being carried out as the department of Microbiology Punjab university Chandigarh and department of Biochemistry Indian Agricultural Research Institute New Delhi. Indian plywood research institute Bangalore has developed a technology for manufacturing particle board from rice husk. The technology has emerged as one of the best solutions to

shortage of wood. The board is a versatile substitute for wood in a wide range of applications. Tomato and potato peels can be used in making adhesives that can replace adhesive such as fevicol and other chemical glues. Intensive agriculture has led to increased soil pollution. Extensive use of synthetic pesticides in pest control has had disastrous environmental side effects. Bio coal manufacture involves solidifying agriculture waste like bagasse and wheat straw through the process of Palletization. Other agriculture waste such as Soya bean, cotton and arhar stalks can also be used because they are also burnt away for want of an adequate technology to convert them into coal pellets for domestic and industrial use. The bio coal pellets are most suitable for paper mills, industrial boilers and brick kilns currently using hard cake. Banana leaves can be converted into the energy rich fuel. Banana leaves are source of renewable source of energy. In bio-methanation method leaves are digested with methane. Furfural is used as a medicine in insecticides is obtained from agriculture wastes such as corn cobs and oat hulls. Agriculture waste material like waste wool, pea nuts, skin walnut, tree barks and cotton effectively bind heavy metal like mercury and copper. Rice husk contains about 20% silica. When burnt silica content increases to about 90% and from this about 99% pure precipitated silica is obtained. Silica is used as a filter in the manufacture of tires, to enhance the strength of rubber and in the manufacture of pesticides as anti caking agents. Carbohydrates are used as energy source in daily life. Corn also used in manufacture of packing material. Recent research in Indonesia has shown that urban wastage and bagasse from sugar cane can be used to generate electricity. This would also help solving the problem of waste disposal and pollution created by sewage leakage.

**Conclusion** - Agriculture is a primary link between people and the environment. Biotechnology one of the many tools of agricultural result and development could support the mission of environmental protection, poverty, reduction and food security by helping to promote a sustainable agriculture centered on the small holder farms in the developing countries. Agriculture waste can be converted into useful material by simple technology.



**References :-**

1. Environmental studies Dr. S.M. Sexena, Dr. Seema Mohan , Pg 63, Kailash Pustak Sadan
2. Environmental education , Dr. R.N Rai, Pg 73, Goyal brother new Delhi
3. Environmental chemistry , B.K. Sharma ,2001
4. Environmental chemistry, A.K. Day 2010
5. Environmental chemistry, P.S. Sindhu, 2010

\*\*\*\*\*

# Overview Of Detection And Control Of Environmentally Toxic Gases From Human Health Perspective

Dr. Rashmi Ahuja\*

**Abstract** - Air is never found clean in nature due to natural and man-made pollution. Toxic gases are present in the atmosphere in concentrations that disturb the dynamic equilibrium in the atmosphere as well as causing damage to target and receptors. The inhalation of reactive gases and vapours can lead to severe damage of airways and lungs, compromising the function of respiratory system. Exposure to oxidizing, electrophilic, acidic or basic gases frequently occur in occupational and ambient environment. Corrosive gases and vapours such as chlorine, phosgene and chloropicrin were used as warfare agents and in terrorist acts. Chemical airways exposure is detected by the olfactory, gustatory and nociceptive sensory system. The utilization of advanced sensing techniques for detecting, indicating and monitoring toxic gases in industries and in the environment is very important for the health and safety. This review focuses on applications of electrochemical, semiconductors, catalytic field effect and catalytic gas sensors for the detection of toxic gases and discusses the recent discovery of receptors for reactive chemical. It is very important that precise and rapid detection, altering and monitoring of toxic gases should be available to prevent or minimize accidents involving poisoning and explosions.

**Introduction** - Noxious gases and other inhalation toxins are widely used and produced in the modern industrial world. The ease and low cost of manufacturing of these chemicals, their high toxicity and relatively short half-life, make them very beneficial as fumigants, nematocides, fungicides, disinfectants and sanitizers in agriculture, pest control, cleaning and water purification industries. Many toxic gases are important reactants in metallurgy and in the organic synthesis of plastics, pharmaceuticals, semiconductors and other materials. Chlorine gas is used for bleaching and chemical synthesis and large quantities of  $\text{NH}_3$  and  $\text{HNO}_3$  are used for production of fertilizers. These are created as byproducts of water purification, metal smelting and combustion as well as by the interaction combustion byproducts with UV light and oxygen in the air and water. This includes oxides and other toxins produced in welding and numerous other air pollutants from industry, automobiles, smelters, forest fires and volcanoes, cigarette smoke.

Due to elevated atmospheric pollution effective and inexpensive system for detection and quantification environmentally hazardous gases have been progressively more important. Currently, standard air pollution measurement is still based on time consuming and expensive analytical techniques such as optical spectroscopy and gas chromatography. Gas sensing properties of differently prepared metal oxides and loaded metal oxides towards environmentally hazardous gases have been individually compared and digested promising material for sensitive and

selective detection of each hazardous gas have been identified.

## Environmentally Hazardous Gases and Health Effects

- Environmentally hazardous gases include toxic gases such as  $\text{H}_2\text{S}$ , CO and  $\text{NH}_3$ , greenhouse gases such as  $\text{N}_2\text{O}$ ,  $\text{CH}_4$  and  $\text{CO}_2$ , and special gases such as  $\text{NO}_2$ , NO and  $\text{SO}_2$ . HF, HCN,  $\text{PH}_3$ , Benzene, Formaldehyde, Methyl Bromide, Arsine, Phosphine, Boranes, Silanes, Germane are found in wide variety of situations varying from industry, chemical, heavy petroleum, electronics, coal gas and mines.  $\text{NO}_2$  and NO are toxic gases produced through combustion chemical plants and automobiles.  $\text{NO}_2$  is most hazardous gas with a TLV of 3 ppm. It also plays major role in atmospheric reactions that produce ground level ozone, a major component of smog. NO causes acid rain, photochemical smog and production of ozone.

CO is a colourless toxic gas with no odor making it undetectable to human. It is produced due to incomplete combustion of fuels. The gas has been shown to bind reversibly to iron center of hemoglobin, the oxygen transport molecule, so oxygen can no longer be absorbed which causes damage to human body.

$\text{H}_2\text{S}$ , the most dangerous manure gas, is classified as a chemical asphyxiant because it chemically interacts immediately with blood hemoglobin and blocks oxygen from being carried to body's vital organs and tissues.

$\text{SO}_2$  is a colourless gas. It smells like burnt matches. It can be oxidized to  $\text{SO}_3$  which in the presence of water vapours is readily transformed to sulphuric acid mist. It can

be oxidized to form acid aerosols. Health effects are caused by exposure to high levels of  $\text{SO}_2$  including breathing problem leading to respiratory and cardiovascular disease. People with asthma or chronic lung and heart disease are most sensitive to  $\text{SO}_2$ . It also damages trees and crops.  $\text{SO}_2$  along with Nitrogen oxides are the main precursors of acid rain.

$\text{NH}_3$  is a colourless gas with a characteristic pungent odor. It contributes significantly to the nutritional needs of terrestrial organisms by serving as precursor to food and fertilizers. It is also a building block for synthesis of any pharmaceuticals and used in cleaning products. Despite of usefulness it is both caustic and hazardous to humans especially when its concentration exceeds TLV value of 25 ppm.

$\text{CO}_2$  is colourless, odorless, non-flammable gas and the most prominent greenhouse gas in the earth's atmosphere with contribution of 76% in the earth's atmosphere besides Methane (13%), Nitrous Oxide (6%) and Fluoro Carbon (5%). It is recycled through the atmosphere by the process of photosynthesis which makes human life possible. It is emitted into the air as human exhales, burnt fossil fuels for energy and deforestation.

$\text{CH}_4$  is an odorless flammable gas. It is used primarily as fuel to produce heat and light. It is also used to manufacture organic chemicals. It can be formed by decay of natural materials and is common in landfills, marshes, septic system and sewers. It can form an explosive mixture in air at levels as low as 5%. It is powerful greenhouse gas produced both naturally and through human intervention.  $\text{N}_2\text{O}$  laughing gas is extensively used for surgical operation as an anesthetic gas. It is not toxic like  $\text{NO}_2$  and  $\text{NO}$ , but a greenhouse gas with a very global warming coefficient which is about 300 times as large as that of  $\text{CO}_2$ , causing serious ozone layer disruption.

**Detectors for Toxic Gases** - Over the past decades several kinds of gas sensors have been developed based on different sensing materials and various transduction platforms. The main class of gas sensing materials includes metal oxides semiconductors, catalytic field effect and catalytic gas sensors for the detection of toxic gases. In the past certain colour changing reagents were adopted to detect these gases by tedious and time consuming colorimetric, or more complicated chromatographic methods. However, in last two decades techniques have progressed rapidly and more sensors have been developed for the precise detection of various toxic gases.

Now highly sensitive catalytic sensor is being developed which will be able to detect accurately toxic gases in concentration ranging from as low as 100 ppm to several thousand ppm.

Most toxic gas monitoring systems integrate permanently installed gas detectors in fixed location throughout a facility. Portable gas detectors based on several technologies found in the analysis function component section, provide an important complimentary

function to these permanently installed gas detectors. There are variety of gas detection technologies in use today for sensing or measuring the toxic gases. Among the most commonly employed are-

1. **Electrochemical Sensors**- Electrochemical sensors or cell are most commonly used in the detection of toxic gases like  $\text{CO}$ ,  $\text{Cl}_2$ , and Nitrogen oxides. They function via electrode signals when a gas is detected. The sensitive film reacts with gases, triggering the device when toxic levels are present. Colorimetric sensors array has been developed for the rapid and sensitive detection of 20 toxic industrial chemicals and their permissible exposure limits. The colour changes in an array of chemically responsive Nano porous pigments provided facile identification of toxic gases with an error rate below 0.7%
2. **Semiconductor Sensors**- Conducting polymer gas sensors are semiconducting gas sensors where the resistance of porous pellets or thin film of metal oxides to certain gas monitoring applications. The development of a general, low cost and scalable method for synthesizing nano wire structure made of different material for use in the fast and accurate detection of toxic and inflammable gases is extremely important or monitoring environmental polluting gases. Different metal oxides nano wires made of titanium oxide, tin oxide, zinc oxide, copper oxide and tungsten oxide could be easily synthesized and were found to be suitable for gas sensor application.
3. **Constant Potential Electrolysis Sensors**- The constant potential electrolysis sensor has very high sensitivity and selectivity and can detect gases to the ppm level or lower.
4. **Initially Catalytic Field Effect Sensors**- They are used to detect hydrogen only, however, gases such as  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{HCN}$  can also be determined. In catalytic sensors the toxic gas is oxidized catalytically on a coiled noble metal wire, which releases heat and cause an increase in the resistance of wire.

**Conclusion** - A toxic gas can cause damage to living tissues, the central nervous system, severe illness or even death. Some toxic gases are not visible, cannot be smelled and/or they may not have an immediate effect but can be the cause of fatality. The technology to recover natural gas and amount depends on undiscovered types of toxic chemicals. As discussed in this review in perspective, there are several important and potentially existing sensors arrays for selective and sensitive detection for each of the studied toxic gases. Therefore, such system can have a major impact on human health and safety for domestic use as well as various industrial and homeland security.

#### References :-

1. Dr. Chas and Srinivas, Mohan Kumar "Toxic Gases Detection and Monitoring Utilizing Internet" International Journal of Civil Engineering and Technology 8(12): 614-622 (2017)

2. C. Hou, J.Li, D. Huo, et al, "A Portable Embedded Toxic Gas Detection Device on a Cross Responsive Sensors Array" Sensors and Actuators B (2012)
3. Best F Bessac, et al "Sensory Detection and Responses to Toxic Gases" Proc. Am. Thorac. Soc. (2010)
4. Brown J.A., "Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases" (2009)
5. Binachi, M.E., et al "All We Need to Know About Danger" J. Leukoc. Biol. 81: 125 (2007)
6. Kim, I.J., Han, C.H., "Development of Micro Hydrogen Gas Sensors with  $\text{SnO}_2$ - $\text{AgO}_2$ - $\text{PtO}_x$  - Composite using MEMS Process", Sens&Actuat. B: Chem 127, 441-446 (2007)
7. Taylor Clark, T. Undem, B.J. "Transduction Mechanism in Airways Sensory Nerves" J. Appl. Physiol.- 101: 950-959 (2006)
8. Yunan. Jin. Lei. "Sensors for Toxic Gases" Platinum Metal Rev. 37(3): 146-150 (1993)

\*\*\*\*\*



## Remapping Social Narratives in Seven Steps Around The Fire

Dr. P. K. Jain\*

**Abstract** - The play, Seven Steps Around the Fire, is probably one of the best plays of Dattani that discusses the socio-psychological crisis of eunuchs who are torn between the social taboos and their personal desires. The dramatist presents the conflicts, anguish, dilemmas, insecurities, fears and frustration of eunuchs. They want freedom from age old fetters of social exclusion fastened around them and their cry for self identity.

The playwright with his image of iconoclast comes out openly with plurality of variants in the play to get alfresco for eunuchs. The effort of the dramatist is to bring them to the main stream of society and this will be the real salvation for them. The play is an august attempt of the dramatist to provide them strength of self affirmation. Their marginality, in the words of GayatriSpivak, can be acknowledged in the terms of "silence and speech".

**Key words** - Eunuchs, crisis of identity, oppression.

**Introduction** - Mahesh Dattani, the Sahitya Academy Award winner, is a playwright of versatile genius who brought Indian drama to new heights by exploring those issues which hitherto were covered under the carpet treating them to be taboos or infectious. In his plays issues like communal tension, homosexuality, child sexual abuse, gender discrimination, marriage and career, conflict between tradition and modernity, patriarchal social system, plight of eunuchs, child labour, interpersonal relationship, dichotomy of personal and moral choices, identity crisis, revelation of the past and the problems faced by HIV positives find candid and forceful articulation.

The play 'Seven Steps Around the Fire' is probably one of the best plays of Dattani that discusses the socio-psychological crisis of the eunuchs who are torn between the social taboos and their personal desires. It dramatizes the conflicts, anguish, dilemmas, insecurities, fears and frustration of the hijra community that is granted no honourable social space. In the first 'voice-over', Uma clears many doubts regarding the hijras and their social positioning: "Case 7. A brief note on the popular myths on the origin of the hijras will be in order, before looking at the class-gender-based power implications. The term hijra, of course, is of Urdu origin, a combination of Hindi, Persian and Arabic, literally meaning 'neither male nor female'. Another legend traces their ancestry to the Ramayana—  
———. (CP:10)

In the words of GayatriSpivak, marginality can be acknowledged in terms of "silence and speech". With the persistent annals of subordination, the marginalized groups were devoid of mental strength of self affirmation. They were forced to lead the life of subalterns. In 1980, Spivak

wrote of subalterns, "It denotes to the general attribute of subordination in South Asian Society whether this expressed in terms of caste, class, age, gender and office or any other way." (67) There have been organized and collective efforts to make the representation of the conditions of oppressions and to stir the consciousness about their suppressed self so that they might be inspired to seek spaces in the mainstream of life. In this process, the emphasis is not on political liberation only but also on the emancipation from the psychological impact of oppression. It anticipates the shift of margins and proclaims the emergence of 'new man' who can assert himself against irrational domination of 'elitists' ideologies.

Mahesh Dattani seems to wrestle with a problem that is the characteristic feature of the postcolonial writers. Eunuchs in India have practically no respectable public identity. They have no acceptance and no protection from prejudice and abuse. The discrimination against them is often translated into violence. The main factor behind the violence is that society is not able to come to terms with the fact that eunuchs do not conform to the accepted gender divisions. Male and female—these are the only sexual categories which have secured society's approval. Individuals, who do not fit into these two classes, have to bear social ostracism, isolation and contempt. Politically, legally and socially the community of eunuchs is marginalized and victimized. The invisible clutches of social forces do not permit them to carve their own design beyond the patterns recommended and accepted by society. Mahesh Dattani gives the eunuchs of India a voice to articulate their feelings and predicaments in the English theatre through his play Seven Steps Around the Fire. The

case of a eunuch is focused in the play who secretly marries the son of a minister and has to bear dire consequences. The role of the police, politicians and the society as a whole is questioned.

Dattani is probably the first playwright who has written a full length play about them. For the very first time they get a depiction in the theatre as human beings with their individuality who crave for space in the society. Remarking on the theme of the play, Dr. Beena Agarwal remarks: "Dattani in the process of engineering the current of Indian drama by bringing it closer to the real life experiences tried to articulate the voice of the oppressed sections of the society whose identity is shrouded in the cover of myths and social prejudices. They have been dragged in darkness, doomed to survive in perpetual silence bearing the oppressive burden of hegemony of the elitist class. Dattani within the framework of dramatic structure, tries to investigate the identities of those who occupy no space in social order." (34)

It is a protest play against the social exclusion of the eunuchs. Such exclusions can be found everywhere in the Indian society like the caste, class, religion or inclination based bias, but they suffer this on the basis of their neutral gender. Dattani underlines the fact that other than the social customs and bindings, they have a 'self' that longs for dignity and when it is denied the same, it tries to break free of such customs. When they protest, most of the times their voice is suppressed by the established order that prevails in the society. Dattani has added a new dimension to the theatre by taking up such themes in his plays. It is remarked: "Dattani has done a good job by introducing a new theme to Indian English drama. Conservatives and social activists should not turn a blind eye to reality... We have to accept the reality of life, however, painful that might be." (Das:17) Within the dramatic texts of Dattani, the voices of new marginalized groups like the community of Eunuchs, and the suffering of AID-victims are heard. He reconstructs the identity of gays and lesbians in *On A Muggy Night in Mumbai*, *Aid Victims in EkAagMausam* and the Community of Eunuchs in *Seven Steps Around the Fire*. It is not a process of romantic exhortation only but an effort to celebrate the true spirit of humanity. He accepts, "The function of drama, in my opinion, is not merely to reflect the malfunction of society, but to act like freak mirrors in a carnival and to project grotesque images of all that passes for normal in our world. It is ugly, but funny." (Roy)

The plot of the play revolves around the investigation of murder mystery of Kamla, a beautiful eunuch. Uma Rao, the daughter of vicechancellor and wife of superintendent of police, Suresh Rao is a student of sociology and doing her research on the life of eunuchs. She goes to the jail to meet Anarkali, another eunuch who is falsely accused as murderer. Uma gets interested in the murder mystery of Kamla and feels sympathy for Anarkali in particular and eunuch community in general. She is a very sensitive lady. She develops emotional affinity and bondage with the

eunuch. She is aggrieved at the maltreatment given to them in the jail. She asks her husband; Uma: Yes, why did you arrest her?

Suresh:(off) Didn't you go through the file? (Sound of gargling) Uma: Yes, I know she is arrested for the murder of her sister, but..... (CP: 9-10)

Suresh doesn't have any sympathy for the eunuch and advises her wife not to develop good relationship with Anarkali. He calls them liar and castrated degenerate men. But Uma is greatly interested and believes that Anarkali is not a liar. She hasn't killed Kamla. So she raises the very subtle and logical question.

Uma: What is the evidence against Anarkali? (CP:10) Suresh avoids answer as he is not interested in the release of Anarkali. The police had no proof against Anarkali but they arrest her. As Suresh puts it, "we only arrested her because there was no one else. There is no real proof against her. It could be any one of them." (CP:33) There is no separate prisons for the eunuchs and she is put in the male cell. The play reveals the chain of injustices that a eunuch has to encounter in the society that has inborn bias against them. Anarkali is physically, mentally, verbally and sexually abused in the lock up but nobody bothers about her. She herself is fed up with the false sympathies of the journalists who come to meet her to get a different type of news. She even refuses to meet Uma at first as she mistakes her for a journalist. But Uma is able to win her confidence and assures her of her release. She is the mouthpiece of the playwright and Dattani has projected an image of modern Indian woman through her who fights against the traditional useless values and questions the patriarchal system. It is attributed: "Dattani credits her with intelligence, sensitivity and determination enabling her to fulfil the task. Thus she becomes the agent of change. This social agent is cauterized by an open mind, a consciousness that dares to think differently, reacting against social conditioning, questioning the existing social norms and their rationality and merit." (George:147)

Uma is not only sincere to her research only but also towards the cause of eunuchs that she has undertaken and works tirelessly to achieve that. Gradually Uma gets so much concerned with the eunuch cause that her research gets subordinated and she starts thinking of leaving her research. Her conversation with her guide on the phone reveals: "I am wondering whether I could leave out the case study on the hijras... Well, it all seems a little too sordid and I find it more and more difficult to do through research..." (CP: 28) The eunuch is also human beings like us. They also long for human relationships. They want to bind themselves in the relationships of brother, mother, sister, father etc.

Anarkali: (Sympathetically) Oh. (smokes) if you were a hijra, I would have made you my sister.

Uma: Oh. Thank You. (CP: 13)

Uma symbolizes the centre and Anarkali symbolizes

the margin. The play presents social dichotomy through their characters in an interesting way. Anarkali is hopeless and frustrated. However, after befriending with Uma, she starts anticipating her release. She wants Uma's help in coming out of jail. She beseeches her for the support.

Anarkali: Get me out of here. (Pause) Sister, I did not kill Kamla. You believe me, No? (Pause) You don't believe me? You doubt your own sister?

Uma: Er-no. I do (CP: 13)

Anarkali believes that Uma has got wealth and power. So she can help her get herself released from the jail. She is disappointed when Uma expresses her inability to help her.

Anarkali: Then say that. Don't pretend to be my sister.

Uma: I don't have any power! (CP: 13)

In the play, Dattani explores plurality of subalternity. The two dimensions of marginalization-the one sexual subaltern and the other gendered subaltern are explored dexterously in the play. Anarkali and Uma Rao represent these two facets of subalternity. If Anarkali is biological subaltern, Uma is gendered subaltern. Uma wants to help and pay for the bail of Anarkali, but she has no money. She can't demand money from her husband for this purpose. She has no such liberty as such. She explains:

Uma: Here. That is all the money I have. Even if, I wanted to, I couldn't explain to my husband why I am paying for your bail. (CP: 15)

If we observe very minutely, we'll find that the condition of Uma is also not much better than that of Anarkali. Both of them are sailing in the same boat which is swayed by the winds of social myth and pride. Uma tries to unmask the real condition of Anarkali. But surprisingly, she unveils her own subaltern hood before her husband. Anarkali points it to her in a very subtlest way.

Anarkali: Maybe you are unhappy than I am.

Uma: Look, I want to help you but I don't know how.

Anarkali: If you give them money, they will release me.

Uma: But I can't bail you out! (CP: 14)

The play highlights the brutality and cruel treatment of our cops to the eunuch community. The helplessness of Anarkali is highlighted in the following dialogues:

Uma: You can't do that! You have to report to the police station.

Anarkali: They will kill me also if I tell the truth. If I don't tell the truth, I will die in jail. (CP: 14) During the process of unmasking the murder mystery of Kamla, Uma Rao displays various merits of head and heart. She is convinced that Anarkali is innocent. She has been falsely accused for the crime. Uma is investigating for academic pursuit. But now it is not merely academic venture. She is deeply attached to eunuch community and receives acute pain after knowing the pathetic plight of the eunuch community.

Dattani has exposed the multiple layers of realities that co-exist in the Indian society. The reality of their existence is invisible to the society. Isolated and humiliated, they are considered as the lowest of the low, but they crave for love

and family. The invisible chains of the society deny them family and love. The same thing happened with Kamla, who loved Subbu and secretly married him, but was eventually murdered on the bidding of Mr. Sharma, who is an influential politician and Subbu's father. The minister had the young hijra burned to death, and hastily arranged for his son to marry an acceptable girl. But at the wedding – attended of course by the hijras who sing and dance at weddings and births – Subbu produces a gun and kills himself.

The play is not only about the murder investigation of a eunuch but also about their social positioning and the social setup where a eunuch cannot crave his feelings and emotions beyond the patterns and boundaries recommended by the society. Those who try to break free have to face harsh consequences. Munswamy constantly requests Uma not to involve in the affairs of hijras. Despite this, she goes to Champa's house to know the truth. Since Uma is embodied with essential human goodness and qualities, she also develops emotional bondage with Champa. She takes money from her father and meets Champa and hands over money to Champa for getting Anarkali's bail. In the beginning, Uma doubts that the cause of murder is competition between Kamla and Anarkali. But later on, she realizes that it is not the real cause of the murder. When Uma and Champa are conversing, Salim comes over there for getting one particular portrait.

Salim: First give me her trunk.

Champa: I have the right to Kamla's clothes and jewellery even if you gave them to her.

Salim: You can keep all that. Let me first go through her trunk. And I didn't give her anything. (CP: 26). On knowing Uma being the daughter-in-law of the Deputy Commissioner of Police, Salim hurriedly leaves the place to avoid further inquiry. Uma has become very curious to know about Salim and the thing he was searching for. Champa informs her that Salim is the bodyguard of the minister, Mr. Sharma. He used to come for Kamla every day. Surrendering to the Uma's threat, Champa reveals that Salim was searching for the photograph. This adds more complexity and element of suspense to the plot of the play.

The end of the play is very depressing and disgusting. It reveals the truth of murder of Kamla. The dramatist unveils the mystery of Kamla's murder during the wedding ceremonies. It is revealed that Mr. Sharma got Kamla murdered as his son, Subbu loved her. Displeased by this, he got Kamla murdered. The last voice-over of Uma throws ample light on the callous attitude of society, media and police towards subalterns.

Uma (Voice-over): They knew. Anarkali, Champa and all the hijra people knew who was behind the killing of Kamla. They have no voice. The case was hushed up and was not even reported in the newspapers. Champa was right. The police made no arrests. Subbu's suicide was written off as an accident. The photograph was destroyed. So were the lives of two young people... (CP: 42).

The play gives the message that the eunuch is human

being as man and women can be. Their hearts are full of milk of human love and sympathy. It is a grave crime that they are denied human love and identity. Their hearts also throb for love and joy of life. Nature curses them with denial of sexual competency, but society curses them more cruelly with their social boycott. They are finished with social boycott and stigma. Human soul of the eunuch is bruised and bleeding. Longing for love and relationship is the keynote voice of this artistic work. Mahesh Dattani projects the pathetic plight of the eunuch community without offering any suitable solution. The treatment meted out to the eunuch reflects the social and cultural notions. The attitude of the elitist towards the subaltern is very mean and disgusting. Mr. Suresh Rao looks at them with disgusting attitude. The play is set in Indian metropolitan environment and scenes moves from posh area to peripheral parts of the city. These two localities symbolize the two concepts of 'centre' and 'margin'. The play highlights the creator's awareness of social hierarchical structure, scenario and changing perceptions. Nandy, the eminent postcolonial critic, postulates that the psychological liberation is more significant than social and political liberation. He views that "The colonialism colonizes minds in addition to bodies and releases forces within colonized societies to alter their cultural priorities once and for all. In the process, it helps to generalize the concept of the modern west from a geographical entity to a psychological category. The west is now everywhere within the west and outside in structures and in minds." (112)

Mahesh Dattani's play *Seven Steps Around the Fire* raises many questions regarding hijra identity, their

constitution, connotations, their social acceptability and tolerability. They are the 'invisibles' in the society, the lowest of the low on the steps of social hierarchy. They face a double jeopardy as they are the victims of nature as well as of the society. The bias against them is even worse than the class or caste or religious bias. They are not even recognised as the members of the society. There is an aura of disgust and dislike related to them. Their fears and frustrations are underlined in the play. They are human beings with no voice, no sympathies, no love, no consolations, no justice and probably no hope of acceptability in the society.

#### References :-

1. Dattani, Mahesh. *Collected Plays*. Delhi :Penguin Books, 2000. Print.
2. Spivak, Gayatri. *Subaltern Studies*. (ed.) R. Guha Vol. I, Delhi : Oxford University Press, 1982. Print.
3. Agarwal, Beena, *Mahesh Dattani's Plays: A New Horizon in Indian Theatre*. Jaipur India: Book Enclave, 2011. Print.
4. Das, Bijay Kumar. *Form And Meaning in Mahesh Dattani's Plays*. New Delhi: Atlantic, 2008. Print.
5. Roy, Elizabeth. "Freak Mirrors and Grotesque Images" *The Hindu*, 15 March, 2002.. George, Miruna. "Constructing the Self and the Other: Seven Steps Around the Fire and Bravely Fought the Queen." *Mahesh Dattani's Plays: Critical Perspective* Ed. Angelie Multani. New Delhi: Pencraft International, 2007. Print.
6. Nandy, A. *The Intimate Enemy : Loss and Recovery of Self Under Colonialism*, Oxford University Press, Delhi, 1983.

\*\*\*\*\*



# Intellectual property right in digital era special reference of copyright

Niti Nipuna Saxena\*

**Abstract** - This paper touches intellectual property right in digital Technological era, issues which are related to copyright. Characteristics of the copyright implications with digital Technologies and its adverse impact on Knowledge society and Library, fair use and not fair use right in digital and environment are discussed detail in this paper handling of the copyright implication in digital environment.

**Keywords** - Copyright, digital media, fair use, internet, multimedia, site licensing, software.

**Introduction** - In today's scenario literacy goes beyond just the basic ability to comprehend text. Digital literacy encompasses a wide range of skills, all of which are necessary to succeed in an increasingly digital world. As print medium begins to die out the ability to comprehend information found online becomes more and more important. Digital literacy may soon find themselves at just as much of the disadvantage you cannot read or write because digital literacy is so important.

We see the so many changes in library it undergone a transformation as we have incorporated computers into the structure of modern library.

Every libraries there was a dramatically Quantum jump in the Digital information resources made available networks particulars over the internet and the www publishers of scholarly academic and reference Works from almost all field of human knowledge started bringing them in digital form.

Number of issues and concerns are associated with the usage of Digital information. It is easy to create digital or digitalised copies of material including text image audio and video Digital information can be distributed across the world by email electronic bulletin boards websites and networks. primary and secondary mass storage media made possible to download store display and print. downloaded document can be modified forwarded without the knowledge of its rightful owner.

## Main characteristics of the digital Technology

**1. Reproduction** - Any work in digital form can easily and rapidly reproduced. There is no loss of the quality and very little expense. 1 copy of work in digital form can supply of copies. We have easily seen the original digital version of recorded music inform of the Cds.

**2. Storage** - Any work in digital form can easily store. Very big amount of data can stored it shows the development of information technology.

**3. Spread** - In this world technology so developed. We can send a message through the e-mail, websites and networks within a second all over the world.

## Main copyright issues

**Network and internet** - This is a perfect Technology for the pirates in digital Technological world, data to be copied without defect, data to be copied without defect, manipulated, sliced, Andre edited with great freedom.

The internet is free for all in using vast available resources is the great myth. If the information is created by the the Federal government or the copyright has expired or been abandoned by the holder, material found on the Internet may be copied freely in public domain.

Materials and information provided by the internet with the permission that is images including web graphics, photos, logos, digital art, graphic images.

**Millions of people linked though networks** - There are many national regional networks and intranet and extranet apart from internet Content distributed over the network is copyrighted or under contractual licensing.

**Site licensing** - Site licensing employed by educational institution and business organisation.

A site licence allows the institute to purchase the right to unlimited use of the product within the organisation or institution.

**Network server traced** - Breach of Copyright right done by single access or a single master copy to a product purchased downloaded or used on two or more computers. Information cannot be shared loaded from single access, it's sharing and login details also copyright infringement.

**Email** - Copyright act tonic male or female is greatest threat. Internet user expect more people to know their email address 50% users prefer to communicate using email rather than a telephone.

Between the parties email is private way to transfer the information.

\*Assistant Professor, Sage Institute Of Law And Legal Studies, Sage University, Indore (M.P.) INDIA

Copyright infringement committed if the recipient of email messages want to take print or forward these private mails it is too dangerous.

Messages fall into the category of literary work according to the copyright act the sender of copyright on the contents and recipient on the physical space the message up on his disc

Recipient does not have the right to copy publish, distribute the contents without permission.

**Conclusion** - All efforts need to be made to amend copyright laws for the protection of copyright and safeguard for the interest of the users to cover technological impact on associated legal issues to include latest provision .Many times user not familiar with copyright law and the activities which leads to copyright breaching . So user can be made aware through copyright awareness program and literacy program for the awareness. Most of the software program can be easily copied and recreate perfectly. Scanner Technology reproduce the photographs and pictures without decreasing the quality of the image reproduced images can be stored for future it can be used over and over and

modified. We can fight above problem with the help of the knowledge of copyright. And do copied and reproduction program with the permission of creator and licence

#### References :-

1. Intellectual property laws Anuj Garg Ali Hassan JD Alia law agency Allahabad Lucknow 2013.
2. Bharat mein baudhik sampda Adhikar AVN Vidhi Dr Y S Sharma University Book House Private Limited Jaipur 2013.
3. Baudhik sampda Adhikar Ek Parichay Jay Prakash Mishra Central law Publication 2010
4. Law relating to intellectual property Dr.B.L.Wadehra, Universal Law publishing company New Delhi 2011.
5. Besan Jak Cheyrl.2001. Copyright act Plain simple. Franklin lakes NJ :career press.
6. Singh JP 2007 copyright issues desi doc bulletin of Information Technology 27(6) PP 19 to 30
7. Lakshman Moorthy A and Kari Siddappa CR 2005 issues in digital environment paper presented in the two day's state level seminar on perspectives in intellectual property rights 13-14.

\*\*\*\*\*

# An extensive analysis on quality of Indexed Journal

Neha Agrawal\* Dr. Sagaya Aurelia\*\*

**Abstract** - The importance of any journal depends on how many indexing services covers that journal. Now a days most of the author searches for indexed journal to publish their articles. Indexing is considered major quality criteria for any journal. But only indexing in good data base is not sufficient to check the quality of any journal. The objective of this article is to analyse the information provided by different journal and classify predatory journals, describe its characteristics, and to extract empirical descriptions of potential characteristics of predatory journals. Here in this article quality measures of journal were discussed. Website of several indexed journal were analysed and found that some of the information was fake. In this work we found that apart from checking indexed journal, author should verify other information related to journal. These includes several other factors like editorial board, review process, number of article published per year and time taken to review the article. At the end we have discussed several characteristics which found common in spurious journal.

**Keywords** - quality of journal, indexed journal, spurious journal, predatory journal.

**Introduction** - Publication in good quality journal is a mandatory requirement for any author for their personal growth. It is a very challenging task to identify a good quality Journal. In Recent time author will search for good journal in any one of the indexing data base. Indexed journal is one of the primary factor for measuring the quality of journal. But Listing of journal in any of reputed database is not enough for making our choice. Predatory journal is a very popular research topic among scholars. Selection of good quality journal becomes a strenuous decision for the authors as there is no transparency on the affair. Publishing an article to an imprecise journal is one of the most usual mistakes made by both new researcher and experienced researchers. New author does not have more information about how to check the quality of journal. Experienced researchers, on the other hand, feel safe with publishing in the same journals again and again even when they can now find better publication choice and can reach to more audience through open-access or electronic-only journals. Publication a journal is a business. There are business goals associated with it like generating revenue and receiving funds from different authority.

**Related Work** - As early-career scholars, where you choose to publish your article will affect your career growth, funding opportunities and professional prominence for years to come [9]. Publication a journal is a business. There are business goals associated with it like generating revenue and receiving funds from different authority [16]. In recent time the number of predatory journal and article published by these journals has exponential growth [4]. Some

researcher may be swindled by submitting the article to spurious journal [5] while others may do this to increase the importance of their resume [6]. Among many other qualities, a predatory journal is known for its article processing charges (APC), suspicious editorial boards, and absence of a formal peer review process [7]. Most of the predatory journal was published in Asian countries [7]. Predatory publishers frequently use Google Scholar and Academia.edu systems to approach the author of recently published papers. Many also developed authorised websites and then send a 'call for papers' emails to different authors. Occasionally they also send complimentary and personalized emails to authors especially about one of their published article and show the interest that exactly same kind of thing their journal or conference is focusing [9]. It is found that so many journal will not mention acceptance rate for article in their website [10]. The one of the possible reason for exponential growth of predatory journal is growth in academic publishing in developing countries as they become more advanced in science and technology [8].

In this section first we will discuss about quality measures of journal, indexing agency and their history, impact factor, h index and review method adopted by different journal.

**Quality Measure of journals** - There are several other quality measures to be considered while making choice. We will discuss about different types of quality measures here:

1. Indexing & Indexing Agencies
2. Impact Factor

\*PhD Scholar (Computer Science) Christ Deemed to be University, Bengaluru (Karnataka) INDIA

\*\* Assistant Professor (Computer Science) Christ Deemed to be University, Bengaluru (Karnataka) INDIA

3. H- index
4. Cite Score
5. Review Method

**Indexing & Indexing Agencies** - The principles of indexing – study of text and task of subject headings and relationships – are the same for both books and journals. The most obvious difference is that a book index is a discrete product, created for one specific closed-end publication. A journal or periodical index whereas, is an existing structure, an openended index created over an extended period by one or more persons. Journals grow and change throughout their lifespan, and the indexes have to change with them, both in terminology and in format [2]. Indexing is a database of journals which will be known for good quality and publication ethics in publication. If any journal is listed in that database, it is said to be indexed journal. Indexing is considered as a quality parameter for journal. To get better visibility and broader readership publishing in indexed journal is mandatory requirement. In any data base indexing a journal is not an easy task. For getting indexed in any of the leading data base, journal has to maintain the quality of article. Also what review process they will use to review the article of authors will also be considered. Once journals meet core publishing standards, they'll be eligible for relevant indexes.

**History** - First science citation index was published in 1964 to provide the stage for different researchers to associate with each other. The purpose behind the indexing was to provide a common platform for researcher to share their knowledge. Soon it became the platform to access the quality of work done by researchers and the footprint of their work on the community. There are several indexing agency which will maintain the database and provide indexing for journal. Web of Science by Indian institute of Scientific research (ISI) and Scopus are the popular one. There are more than 13000 journal indexed in ISI. It covers journals from science, social science and arts and humanities. In Scopus more than 40,000 journals are indexed. Each of the data base have their own selection criteria to select the best quality journal. There are several other indexing agencies available like Google scholar, PubMed, EBSCO, EMBASE, DOAJ, SCIE, SCIMAGOJR, OAJI, IJIFACTOR, Index Copernicus, Open J Gate, Ulrich's International Periodical Directory, BASE. There are many indexing bodies but these are some of the most trusted and popular Journal indexing agencies referred by almost all researchers.

All academic indexes require journals to follow certain core publishing standards. To meet primary indexing requirements journals should have:

1. An International Standard Serial Number (ISSN)
2. Digital Object Identifiers (DOIs)
3. An established publishing schedule
4. A copyright policy
5. Basic article-level metadata

From there, indexes will have different inclusion

requirements such as Publication scope, Editorial board and policies, Level of publishing professionalization, archiving policy. Each indexing database has their own criteria to compare the quality of journal, like cite score used by Scopus and index factor used by ISI.

**Impact factor** - Impact Factor is very widely used parameter to check the quality of journal. It is a measure of frequency to which article in journals are cited within a particular period of time. If an impact factor for journal is high it is considered to be a good quality journal. A journal's impact factor is one of the estimate of its prominence, but not always the most salient. You need to consider the prestige of the authors that publish in the journal, and the size of the journal's readership.

**H- Index** - H – index is a quality measure for individual author as well as for journal also. It is the measured by h articles of an author/journal is cited h times. In other words we can say Journal/author has published h article that is cited h times. H- index consider both quality and quantity of publication.

**Cite Score**- Cite Score of an academic journal is an evaluation criteria for checking the yearly average number of citations to recent articles published in that journal. Cite score is calculated yearly once and showing the average citations for a full year. Cite score is more comprehensive and transparent.

**Review Methods** - There are various review method followed by journal. In Peer review, expert from same area review the article and give their feedback and comments. Generally one article will be reviewed by 1-3 reviewer based on the availability. Basically there are three kinds of peer review method: Single Blind, Double Blind and Open Review. In Single blind process author does not know about the reviewer but reviewer knows about the author. In double blind process author and reviewer both will be unaware of each other. In open access review process name of the author and name of the reviewer will be publicly available along with review comment. This process is more transparent but may have consequences.

#### Figure 1 (See in last page)

Now a days so many journal claims to be indexed journal. So many journal is indexed in reputed database also. But indexing in reputed data base does not guarantee quality of journal. Unfortunately so many journal is indexed in reputed data base and found to be spurious. They will collect money from author and without a proper review they will publish the article in 3 – 10 day. They will false claim for the indexed in different data base. They will claim to be listed in UGC Care List also which is actually not correct. UGC Care is the quality evaluation criteria for Indian journal. There are so many international journal which claims to be in UGC Care List. In UGC Care website, UGC will publish two list for journal: List I and List II. In List I UGC includes the journal which satisfies the quality criteria of UGC whereas in List II UGC includes the journal which is indexed in any of the reputed data base. Therefore if journal is



indexed by any of the reputed database they will be included in UGC Care II List. UGC Care II List does not guarantee that journal listed in that list satisfies the quality norm of UGC. Most of the journal listed in Group II, claims to be UGC Care approved in their website. Apart from false claim, they will not mention article processing charges for their journal and charges the huge amount from author. They send spamming/phishing mails/SMS. They collect publication fee in individual's accounts. Author should be very careful while selecting journal. With lot of dedication and hard work, author will come up with research paper. Publishing in this kind of journal, author will not get more visibility and his work will not be cited by many researchers. This kind of journal is not worth publishing your article.

In this article we have analysed the website of several indexed journal, their review method, review time and article processing charges. We have come up with several conclusion that how to identify such kind of journal which is not worth publishing your article.

**Methodology** - Data were collected from internet via search operation in indexed data base and also using Google form. Name of 50 indexed journal were collected. Data of around 30 journal were verified from their website. Random sampling was used for conducting survey. Primary data source was used in this work.

**Search Strategy** - Following search strategy was used. First we have logged into reputed indexing agency site and searched some journal name. Screening of information given on journal website was done. We checked the claim of journal to be indexed by different database, by checking the database website. Also the impact factor claimed by journal also verified.

Following content was checked in journal website:

- Their claim to be indexed in different data base or indexing agencies.
- Their coverage year in indexing agencies.
- Their editorial board members.
- Their review process.
- For some of the recent article time taken for review process is checked via date of acceptance and date of publication.
- Checked the countries of the authors whether most of them belong to same country or different.
- Checked the process of collecting article processing charge.
- Checked the number of article published in each issue.

Data was also collected using Google form which was circulated among various researcher to understand the awareness about predatory journals. This form were circulated in known contacts. Following questions were asked in Google form:

- Personal Information like name, age, qualification.
- Have you sent any paper for publication to Predatory journal?
- Whether you have published in indexed journal?

- Whether the policy for author is mentioned in journal website or not?
- Was the review process followed by journal mentioned in journal website
- How you approached to this journal?
- How much time it took to review the article?

**Results** - We have search the database for about 30 journals. Following observation was made. Journal with good quality had coverage in reputed data base. Their review process typically took 3 to 6 months. They had people from different country as a member of their editorial board. Their policy for author is clearly mentioned in their website. Their impact factor is correctly claimed. Whereas for spurious journal several observation was made: They have claimed wrong to be indexed in reputed data base. Impact factor claimed by journal was wrong. Article processing charge were mentioned in Indian currency even the journal was not Indian. Fake information for editorial board were given. Number of article published in single issue was very huge. Time taken for review process was less than one month. Publisher name and contact details were not transparent in journal website. Type of review process was not clearly mentioned in journal website. Also some journal used email address of free email supplier like Gmail.

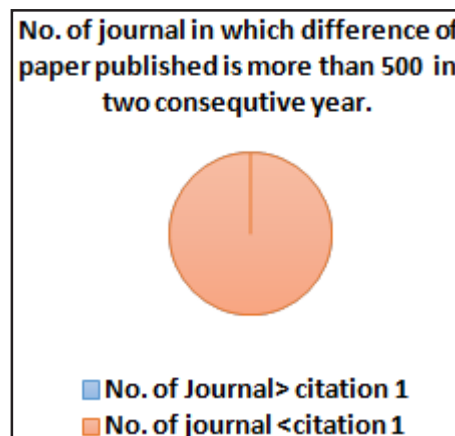


Figure 2

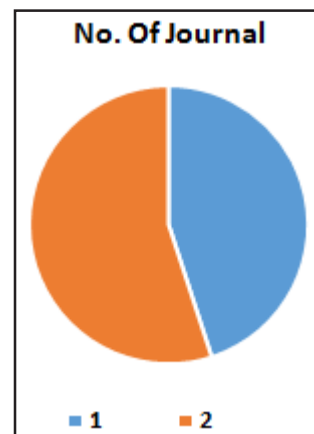


Figure 3

It is observed in figure 1 that journal where number of article published in two continuous year is huge (Sudden

spike) is having citation less than 1. Further analysis were made by analysing the journal website and found most of the information fake. Also when we approached these journal it is found to be paid journal. Figure 2 shown the review time taken by number of journal. Data for 40 journal were collected in which 18 journal, review and publication time was 3- 10 days where as in 22 journal it was 3 to 6 months. Again further analysis was made and website for this 18 journal was analysed. Again all these journal found to be spurious.

Data collected from Google form shows that 40% author accepted that they have published in predatory journal. For 30% author time taken for review was less than one month. 20% author have not found any clear policy for author in journal website. 50% author is not submitting their article directly to journal but sending through some reference. Further analysis was made and found that if author approached any journal via a reference 60 % time it was spurious where as if they approached directly they have published in good quality journal.

**Conclusion** - In the recent time there has been an exponential increase in the number of spurious journals which are also indexed in reputed data base. There are some observation based on our analysis to identify the spurious journal is given here. Most of the articles in these journal are from people of same country. They collect publication fee in individual's accounts. They provides fake information about editorial board. They claim wrongly about indexing and impact factor. Publication time for an article is very less (1 day to 1 month). Number of article for each issue suddenly grows. If you get a review report of your article that you can't confirm that it was prepared after reading your article, the journal is not worth publishing your article. Also the rejection rate of journal can be checked. High rejection rate shows journal is very particular about quality. Sometimes there might be different reasons for rejection also. Some journal will display their rejection rate in website where as some will not. Equipped with a better understanding of ways in which such practices harm and dishonour scholastic communication, people in the academic community now should be able to work together, beside government, institutional, and professional authorities, to tackle this unethical business. Every of us has got own brain and knows, where to publish results of research and every author has got a responsibility for own career and development of own personality.

#### References:-

1. <https://libraryguides.mcgill.ca/journalpublishing> accessed on 15/5/2020
2. Carolyn G. Weaver "The Gist of Journal Indexing" VOL. 10/NO.1 JANUARY/FEBRUARY 2002
3. Cobey, K. D., Lalu, M. M., Skidmore, B., Ahmadzai, N., Grudniewicz, A., & Moher, D. (2018). "What is a predatory journal? A scoping review". *F1000 Research*, 7, 1001. <https://doi.org/10.12688/f1000research.15256.2>
4. Shen C, Björk BC: 'Predatory' open access: a longitudinal study of article volumes and market characteristics. *BMC Med*. 2015;13:230. 10.1186/s12916-015-0469-2 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
5. Cobey K: Illegitimate journals scam even senior scientists. *Nature*. 2017;549(7670):7. 10.1038/549007a [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
6. Kolata G: Many Academics Are Eager to Publish in Worthless Journals. *New York Times*. 2017;1-4. Reference Source [Google Scholar]
7. Xia, Jingfeng; Li, Yue; and Situ, Ping (2017) "An Overview of Predatory Journal Publishing in Asia" *Journal of East Asian Libraries*: Vol. 2017 : No. 165 , Article 4.
8. Milan Kubiak, "Not Every Predatory Journal is Really Predatory Journal", *EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education*, DOI: 10.12973/eurasia.2017.00829a
9. <https://blog.typeset.io/choose-right-journal-early-stage-researchers-guide-ea2cf236dde4> accessed on 15/5/2020
10. <https://www.enago.com/academy/think-check-submit-a-new-approach-to-journal-selection/> accessed on 15/5/2020
11. <https://www.wiley.com/network/researchers/preparing-your-article/6-steps-to-choosing-the-right-journal-for-your-research-infographic> accessed on 15/5/2020
12. <https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/how-to-choose-a-target-journal/1396> accessed on 15/5/2020
13. Bavdekar, Sandeep. (2015). "Choosing the Right Journal for a Scientific Paper ". *The Journal of the Association of Physicians of India*. 63. 56.
14. <https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/choosing-the-right-journal/> accessed on 15/5/2020
15. Tony Brinn, Michael John Jones, Maurice Pendlebury "UK Accountants' Perceptions of Research Journal Quality" *Accounting and Business Research*, volume 26, issue 3
16. Bartosz Hudzik "What makes a good medical journal great? ", *CMAJ* April 19, 2016 188 (7) 531; DOI: <https://doi.org/10.1503/cmaj.1150100>
17. <http://journalijcar.org/review-procedure> downloaded on 20/5/2020

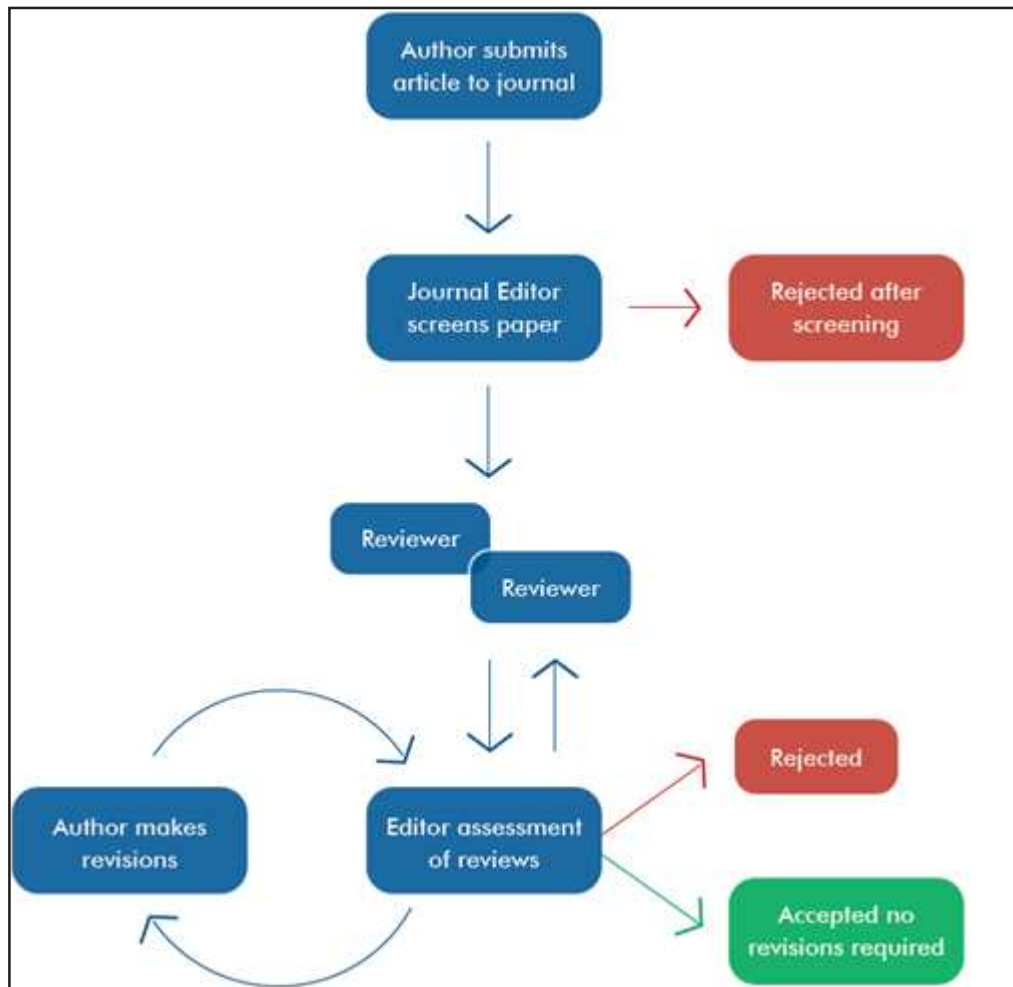


Figure 1: Review Process, Source [17]

\*\*\*\*\*

# Social Security benefits and measures for the Women Labour - A Legal Analysis

Dr. Sairam Patro\*

**Abstract** - Social security programmes are now increasingly being accepted as useful and necessary instruments for the protection and stability of the labour force. It is primarily an instrument of social and economic justice as it works for horizontal and vertical redistribution of incomes in society. Social security measures have a twofold significance for every developing country. They constitute an important step towards the goal of a welfare state, by improving living and working conditions and affording the people protection against the uncertainties of the industrial. Article 41 of the Constitution of India says that “the state shall within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for security the right to work, to education, and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of undeserved want

**Keywords** - Social security, Women, Protection, Act.

**Introduction** - *Social Security is an attack on five grants, viz., want, disease, ignorance, squalor and idleness.*” - Lord Beveridge

The concept of social security is essentially related to the high ideals of human dignity and social justice. In a modern welfare state comprehensive social security schemes take care of persons from “womb to tomb”. It is one of the pillars on which the structure of the welfare state rests.

Social security programmes are now increasingly being accepted as useful and necessary instruments for the protection and stability of the labour force. It is primarily an instrument of social and economic justice as it works for horizontal and vertical redistribution of incomes in society. It is a dynamic concept that contents of which change with social, economic and political system obtaining in a given country at a given time. It is a wise investment which yields good dividends in the long run.

To enjoy security, one must have confidence that the benefits will be available when required, and in order to afford security, the protection must be adequate in quality and quantity. It further emphasized the importance of comprehensive social security measures in the preamble to its constitution, in which it proclaimed “protection of the worker against sickness, disease and injury arising out of his employment, the protection of children, young persons and women, provisions for old age and injury.”

**Significance of the Social Security** - Social security is the security which the society especially state and employer, furnish through appropriate organization against the risks which an individual of small means cannot today, stand up himself or even in private combination with his fellow

countrymen. Thus, social security measures have a twofold significance for every developing country. They constitute an important step towards the goal of a welfare state, by improving living and working conditions and affording the people protection against the uncertainties of the industrial.

The new environments of urban setting had created for them unprecedented problems e.g. absence of pleasures of family life, malnutrition, food adulteration in cities, overcrowding in sub-standard houses and various types of industrial hazards all militating against the good physique and health of worker- which he originally possessed when he migrated from the village. It was therefore, essential that special measures were taken to guard against the dangers of all such factors as it adversely affecting the health of workers.

Article 41 of the Constitution of India says that “the state shall within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for security the right to work, to education, and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of undeserved want.”

These measures are also important for every industrilisation plan, for not only do they enable workers to become more efficient, but they also reduce wastage arising from industrial disputes. The mandays lost on account of sickness and disability also constitute a heavy drain on the slender resources of the worker and on the industrial output of the country. These measures also reduce absenteeism and labour turnover and help in the formation of stable and efficient labour force. Thus, lack of social security measures impedes production and prevents the formation of stable and efficient labour force. Social security is therefore, not a

\*Faculty Member, Lingaraj Law College, Berhampur University (Odisha) INDIA



burden but a wise investment which yield good dividends in the long run.<sup>1</sup>

**In an industrial economy, the workers have been subjected to periodic unemployment due to cyclical fluctuations in business, sickness, industrial accidents and old age. In fact, there is nothing more disconcerting to worker and his/her family than unemployment.**

Similarly, while sickness suspends earning capacity of a worker temporarily, industrial accidents may disable him/her partially or even permanently, and old age may put a stop to his/her ability to earn and support himself/herself and the family. The capitalist having sufficient resources have no problem in facing such risks of life. But, the worker does not have resources required to face the risks caused by sickness, accidents, unemployment and old age.

The need for social security to be provided to needy workers / people as the Government has the obligation to help provide them security to pass through in period of adversity.

The man-days lost on account of sickness and disability also constitute a heavy drain on the slender resources of the worker and on the industrial output of the country. Lack of social security impedes production and prevents the formation of a stable and efficient labour force. Social security is, therefore, not a burden, but a wise investment in the long run.

**Social security measures for women** - Social security is a basic need of all women regardless of employment in which they work and live. It is an important form of social protection. Generally social security refers to protection extended by the society and State to its members to enable them to overcome various contingencies of life. There is a greatest need to provide security and protection to women workers against various contingencies sickness, maternity, disablement, employment insecurities and risks. Thus, social security measures have a two-fold significance. They constitute an important step towards the goal of a welfare state, by improving living and working conditions and affording the women protection against the uncertainties of the future.

The economic independence of women is predominant cause of their subordination whereby women are assigned a major productive role would be a way to improve their status. Thus economic independence is a foundation on which any structure of equality for women can be built.

Indian society being a male dominated where women labours receive still face poor recognition and value the double burden of combining the tasks of production and reproduction is even more arduous despite the statutory provisions to ensure fair working conditions for women in India and also the specific provisions for the protection and welfare of women workers.<sup>2</sup>

According to the information provided by the Office of the Registrar General and Census Commissioner of India as per census 2011, the total number of female workers in India is 149.8 million comprising of 121.8 and 28.0 million

in rural and urban areas. Out of total 149.8 million female workers, 35.9 million females are working as cultivators a 61.5 million are agricultural labourers. Of the remaining 8.5 million are in household industry and 43.7 million are classified as other workers.

The work participation rate for participation rate for women is 25.51% as compared to 25.63% in 2001. However, the work participation rate of women is 22.27% in 1991<sup>3</sup>. 6% of the women workers are in formal sector and the remaining that is majority of the women workers are employed in rural area i.e., 87% amongst them are labourers and cultivators. Thus women constituted a significant part of the workforce of India<sup>4</sup>.

Most parts of the world today women are virtually absent from or the poorly represented in the decision making process as their household work is invisible which is performed inside four walls of the house and their work is not measured in quantitative terms and thus not valued in national accounts.<sup>5</sup> Women have shouldered a large part of the burden of developing countries in 1980s. In order to make up for lost family income, they have increased in employment for home consumption, worked long hours, slept less and often eat less to make substantial cost of structural adjustment that have gone largely unrecorded<sup>6</sup>.

Even after 73 years of its freedom despite the progress the war on inequality, discrimination, violence and also lack of empowerment is continuing. In addition to that there are various other manifestations of women's poverty in India which include hunger and malnutrition, ill health; increasing morbidity and mortality from illness; homelessness and inadequate housing; unsafe environments and their social discrimination and exclusion from the mainstream. It is mainly due to lower level of education, among the women workers that are so crucial in determining the quality of employment and the ability to secure reasonable wages. Low level of education creates vulnerability at two levels. It first denies to access "goods jobs" in organized sector. Secondly it confines the workers to mostly manual jobs. Especially, women labourers in rural areas are the worst victims of this double disadvantage.<sup>7</sup>

Apart from that the social norms and exigencies arising out of the double burden of work restrict their mobility. But the economic condition forces many women to be available for additional work as they wish to engage in productive activities if such work was available within the confines of their homes and also employer's preference for female employee.<sup>8</sup> The home based system is creating problem of invisibility of such enterprise as rural women workers in non-agricultural sector are even more likely to work at home than urban women.<sup>9</sup>

The participation of women's share in the labour force continues to rise and almost everywhere women are working more outside the household. In India, the sharing of economic activity by women is nothing new. From the time immemorial women have been working both in the home and the outside. Various studies conducted on the

level and type of female work participation in agricultural and other sectors in India scholars agree that these have often failed to take note of women's presence in or contribution to the labour force. Enumerating labour participation, there is a deliberate exclusion of a whole range of non-market activities produced by women.<sup>10</sup>

Women informal workers are mainly concentrated in agriculture as there are three quarters of all employed women are in informal employment in agriculture. 90% of those employed in manufacturing and construction are also unorganized sectors. The workers engaged in suffers from high incidence of marginalisation and instance of casual wage workers which make up them vulnerable to arrange of exploitative practices.<sup>11</sup>

Women in the unorganized sector require social security for addressing issues of leave, wages, working conditions, pension, housing, child care, health benefits, maternity benefits, safety and occupational health ensured by extending labour protection to those sectors in a manner that pays special attention to needs of women workers.<sup>12</sup>

As the need arises to make an in depth study of women workers employed in informal sector with a view to analyse the various issues concerning of women workers their wages, employment injury risks, maternity needs, extent of accessibility to social security measures and their vulnerability to exploitation. An attempt has been made to focus the study only on specific employments and specific categories of women workers in the to cover the vast segments.

The need arises to make an in-depth study of women workers employed in informal sector with a view to analyse the various issues and challenges of workers concerning their wages, employment injury risks, maternity needs, extent of accessibility to social security measures and their vulnerability exploitation. An attempt has been made to focus the study on specific employments and specific categories of the women workers cover the vast segments of workforce.

### **Social Security in India**

1. India has always had a Joint Family system that took care of the social security needs.
2. However with rise of migration, urbanization, nuclear families and demographic changes, Joint family system has declined. Hence we need a formal system of social security.

Social Security and labour welfare falls under Concurrent list; it means both union and state Government can make laws regarding these topics.

- Social Security and insurance,
  - Employment and unemployment.
1. Welfare of Labour including conditions of work,
  2. provident funds,
  3. employers' liability,
  4. workmen's compensation,
  5. Invalidity and old age pension and maternity benefits.
- The State is well known for its economic backwardness

and low level of human development with very high infant and maternal mortality rates and low life expectancy. Although it has registered impressive economic growth in the last decade, a major share of its population suffers from under-nutrition, health insecurity and old age vulnerability. In such a context, the State-sponsored social security schemes assume paramount importance. As part of a strategy of 'levelling-up', three schemes in particular were placed high on the agenda namely, (a) the provision of employment on public works, (b) a package of contingent social security including insurance against failing health, and (c) social benefits for the non-labouring poor. In 2008 the Unorganized Workers Social Security Act was passed by government. This act basically seeks to bring a modicum of relief for people at the bottom of the economy unable to take care of their own subsistence since they lack the means (property, assets) to do so and in addition have lost their labour power either temporarily or indefinitely. Thus, support made available is targeted on the non-labouring poor who should actually be classified as destitute. The idea was to establish a National Social Security Authority, consisting of a Board equipped with central funding from which the benefits granted would be dispensed to administrations and agencies operating at state or sub-state level. But what has been the impact of the social security schemes in operation at the national level on the targeted segments of the workforce in the informal economy

Social Security for employees is a concept which over time has gained importance in the industrialized countries. Broadly, it can be defined as measures providing protection to working class against contingencies like retirement, resignation, retrenchment, maternity, old age, unemployment, death, disablement and other similar conditions.

With reference to India, the Constitution levies responsibility on the State to provide social security to citizens of the country. The State, here, discharges duty as an agent of the society in order to help those who are in adverse situations or otherwise needs protection owing to above mentioned contingencies. Article 41, 42 and 43 of the Constitution do talk about the same. Also, the Concurrent List of the Constitution of India mentions issues like-

1. Social Security and insurance, employment and unemployment.
2. Welfare of Labour including conditions of work, provident funds, employers' liability, workmen's compensation, invalidity and old age pension and maternity benefits.

### **Social security and the National economy :**

1. Social security is regarded as a crucial element in industrialisation, economic development and growth. Social security programme will mainly depend upon the order of priority in which a number of variables are placed. Such variables include the structure of economic and industrial programme, the established

pattern of social and family life, the importance of medical services as against cash sickness benefit and so on. A social security benefit scheme is essentially personal service to cover persons and their dependants and its success is measured primarily in those terms.

2. Social security refers to protection provided by the society to its members against providential mishaps over which a person has no control. The underlying philosophy of social security is that the State shall make itself responsible for ensuring a minimum standard of material welfare to all its citizens on a basis wide enough to cover all the main contingencies of life. In other sense, social security is primarily an instrument of social and economic justice.

**Objectives of Social Security - The objectives of social security can be sub-summed under three, categories:**

a). Compensation (b) Restoration (c) Prevention

**(a) Compensation** - Compensation ensures security of income. It is based on this consideration that during the period of contingency of risks, the individual and his/her family should not be subjected to a double calamity, i.e., destitution and loss of health, limb, life or work.

**(b) Restoration** - It connotes cure of one's sickness, reemployment so as to restore him/her to earlier condition. In a sense, it is an extension of compensation.

**(c) Prevention** - These measures imply to avoid the loss of productive capacity due to sickness, unemployment or invalidity to earn income. In other words, these measures are designed with an objective to increase the material, intellectual and moral well-being of the community by rendering available resources which are used up by avoidable disease and idleness.

**Measures of Social Security :**

1. any of the measures established by legislation to maintain individual or family income or to provide income when some or all sources of income are disrupted or terminated or when exceptionally heavy expenditures have to be incurred (e.g., in bringing up children or paying for health care)
2. social security may provide cash benefits to persons faced with sickness and disability, unemployment, crop failure, loss of the marital partner, maternity, responsibility for the care of young children, or retirement from work
3. Social security benefits may be provided in cash or kind for medical need, rehabilitation, domestic help during illness at home, legal aid, or funeral expenses
4. It acts as a facilitator – it helps people to plan their own future through insurance and assistance.

The development of services for prevention and rehabilitation should receive the highest priority in social security policy. Prevention needs to permeate virtually all department of government, the actions of employers and employees, the activities of voluntary bodies and most important of all the actions of individuals and families.

Social security has wider aims than the prevention or

relief of poverty. Where social security programmes did have as an objective the fight against poverty, the effort was mainly concentrated on those not at work: family allowances and health services were the only instrument used to help those who were at work. Its fundamental purposes is to give individuals and families the confidence that their level of living and quality of life will not, in so far as is possible the greatly eroded by any social or economic eventuality. This involves not just meeting needs as and when they arise but also preventing risks from arising in the first place, and helping individuals and families to make the best possible adjustment when faced with disabilities and disadvantage which has not been or could not be prevented. In short, its aim has been widened to include the promotion of the whole quality of life.

Access to social security has become a fundamental human right to which every individual is entitled as a member of the society. This right has been embodied in the Universal Declaration of Human Rights adopted by the United Nations General Assembly in 1984 and also has been granted under numerous national constitutions. But it has been realized in differing degrees depending upon the tradition, history, level of economic development and the political and social philosophy of a country.

The fundamental rights that our Constitution guarantees to every citizen include the right to life, and as the Supreme Court has pointed out, the right to livelihood is inherent in the right to life. The ultimate object of social security is to ensure that everyone has the means of livelihood. It follows, therefore, that the right to social security is also inherent in the right to life.

The World Development Report of 1997, states that Social Security is an essential ingredient in the protection, development and full utilization of human resources, and should therefore be looked upon as an 'investment' both for the development of human resources and human development.

There are two main currents in the movement towards social security i.e., social assistance and social insurance. Though both of them differ in their evolutionary process and approach, they have been designed to serve the same ends, and both the complementary and supplementary to each other. They are two sides of the same coin and form an integral part of the social security system of a country.

**Legislative protections** - India has enacted several social security legislations. The law which could facilitate the cause of the unorganised sector may be divided under the general and special class. The former enactments cover both the organised and unorganised and the latter covers the special laws applicable for certain class of the unorganised workers their wages and earnings are slightly lower than men. In many units of the cotton mill industries, the earnings of women depend on two factors: (i) the availability of work ; and (ii) The number of hours they work. It is reported that both in coal mines and in the plantations, women workers are found to be as efficient as men although there is slight



difference in their wages. So far as labour legislation is concerned, women workers in Indian industries are concerned the principle of "Equal pay for Equal work" has been implemented under the Minimum Wages Act, 1948 and Equal Remuneration Act, 1976. Labour legislations have made several and sufficient provision to protect women workers from undue exploitation. Women workers in organized sectors attain facilities and amenities like equal pay for equal work, maternity benefits, prohibition of night duty, maximum permissible weight load, crèches facilities, prohibition of employment in dangerous occupations and several other welfare measures.

It may conclude that women workers have come out from their home and largely been joining their services in organized sector and social services. The old age barriers against women from upper and middle-class families have become very weak. The high cost of living in the metropolitan cities and society has led women to enter into the public life and they also do their work in the private and public sectors. The enactment of several laws in the factory sector has also stimulated women workers to work as employees in the industrial sector. Women workers also given protection and all facilities relating to their socio-economic welfare which is absolutely satisfactory still more efforts are needed towards this end.

**(a) The Plantations Labour Act, 1951** - It makes the provision for the health and welfare of the plantation workers. The need for provision of housing, medical aid, recreational and educational facilities required in accordance with the rules framed by State Governments. The workers are entitled to sickness allowance and maternity allowance under the prescribed conditions. The planters, are employing more than 150 workers are required to provide and maintain canteens. The crèches are to be maintained in plantations where more than 50 women workers are employed. The employers are required to make effective arrangements for supply of wholesome drinking water and protective clothing to the workers. Welfare officers are to be appointed where more than 300 workers are employed subjected to the state government rules. Tea, coffee, rubber and cinchona plantation, measuring 10,117 hectares or more is covered under this Act has since been extended to the cardamom plantations in Tamil Nadu and Kerala. The Act further lays emphasis on the medical care of workers and their families. Rules prescribed the State Governments; workers covered under this Act are eligible for cash benefits in sickness and maternity.

The government has approved the *Plantation Labour (Amendment) Bill, 2008* to amend the *Plantation Labour, Act 1951* to provide a mechanism for ensuring the safety, health and wealth of the about one million plantation workers in the country. The government plans to amend the definition of family to remove the distinction between a female and a male worker and the definition of worker would also be amended by enhancing the wage ceiling from 750 to Rs. 10,000.

**(b) The Maternity Benefit Act, 1961** - The Maternity Benefit Act, 1961 has been amended from time to time to make maternity benefit payable on the completion of 80 days working. The medical bonus has been enhanced from Rs. 250/- to Rs. 2500/-

The Maternity Benefit Act (1961) enacted with a view to achieving uniformity in matters relating to maternity protection, applies to all factories, mines and plantations except to those to whom the Employee's State Insurance Act applies.

The Maternity Benefit Act provides for the payment of cash Maternity Benefit for certain periods before and after confinement, and grant of leave and other facilities to women employees, on conditions prescribed in the Act. The qualifying period of service shall be eighty days during a span of 12 months. The benefit is payable for a maximum period of 12 weeks revised to 6 months. Apart from the Central Maternity Benefit Act, 1961 which permits the payment of a medical bonus, some states Acts include additional benefits, such as free medical aid, maternity bonus, provision of crèches and additional rest intervals. In order to safeguard the interests of pregnant women workers, both the Central and State Acts provide that such women shall not be dismissed; nor can a woman worker be discharged during the period of maternity leave.

The Supreme Court of India, in case of *Dhanwatey v. Commissioner of Income Tax*,<sup>13</sup> has formulated that the law is a social mechanisms to be used for the advancement of the society. It should not be allowed to be a dead weight on the society. While interpreting ancient texts, the courts must give them a liberal construction to further interest of the society. Our great commentator in the past bridged the gulf between law as enunciated in the Hindu law texts and the advancing society by wisely interpreting the original texts in such a way as to bring them in harmony with the prevailing conditions.

The court observed that the purpose of Maternity Act is to protect dignity of motherhood by providing for the full and healthy maintenance of the women and her child when she is not working. Since number of women employees grows, maternity leave and other maternity benefits are becoming, increasingly common in employment today. The Maternity Benefit Act has been of great value in social justice oriented welfare state in securing adequate rest and financial assistance to factory women workers. Maternity Act gives a special protection to the women and increase the dignity of motherhood.

**(c) The Mines Act, 1952** - Legislation for mining industry started with the aim of regulating labour conditions and safety in mines. These Acts were amended from time to time with a view to re-enforcing and were passed in 1952. The earlier Mines Act of 1923, the working hours were fixed at 60 for the workers above ground and 54 for underground workers. The weekly working hours for all categories of workers were 54 in a week or 9 per day. Elaborate provisions have been made in the Act for safeguarding the death and



safety of workers and promoting the welfare. Every mine is required to make arrangement for supply of wholesome drinking water to workers, maintaining first-aid boxes, construct required number of latrines and urinals and maintain first-aid room with suitable equipments. Since it paid more attention to safety measures and provision of medical facilities in the nature of first-aid rather than comprehensive medical aid to workers.

The Mines Act of 1952 further states that no person will be allowed to work in mines for more than 6 days in a week. The Act has reduced the working hours of all adult workers, both surface and underground to 48 per week respectively. It has also mentioned that no worker will be allowed to work for more than 9 hours, a day above ground, and 8 hours a day underground. The maximum spread over is fixed at 12 hours for surface workers and 8 hours for underground workers. It has been observed that surface adult workers will be entitled to avail of 30 minutes after interval of five hours work. Each person will be allowed to work more than 10 hours a day without overtime. However, by the Mines Amendment Act of 1959, the rate of overtime has been fixed at two times than the ordinary rate of wages for all categories of workers. The Mines Act, also deals with the maximum age limit of adolescent underground workers is raised from 17 to 18, limited the hours of work for adolescent (i.e., between 15 to 18 years of age) at 4.30 per day and prohibited their duty between 6 p.m. to 6 a.m. The duty of women is also restricted in underground work and at night between 6 p.m to 6 a.m. in the morning.

**(d) Payment of Gratuity Act, 1972** - The Payment of Gratuity Act, 1972 is applicable to factories, mines, oil fields, plantations, ports, railways, motor transport undertakings, companies, shops and other establishments. The Act provides for payment of gratuity at the rate of 15 days wages for each completed year of service subject to a maximum of Rs. 3,50,000/- In the case of seasonal establishments, gratuity is payable at the rate of seven day's wages for each season. The Act does not affect the right of an employee to receive better terms of gratuity under any award or agreement or contract with the employer. Gratuity is a reward for long and meritorious service in a Landmark judgement the Bombay High Court observed that *Bombay Union Dyeing and Bleaching Mills v. Narayan Tukaram More* (1980)<sup>14</sup>

In case of misconduct of the employee, which involves financial loss to the management, an amount equal to the loss directly suffered by the employer by reason of such misconduct is liable to be forfeited from the gratuity due to the employee. The Act also provides for the punishment of the employer who fails to pay gratuity to an employee. Thus, gratuity has now become a statutory service condition, and its quantum has no bearing on the size of the profit of the organization or similar extraneous considerations.

**(e) Employees' Pension Act, (1995)** - This Act was introduced for the industrial workers with effect from 16 November 1995. Under the scheme, pension at the rate of

50 per cent pay is payable to the employees on retirement / superannuation on completion of 33 years' contributory service. A minimum of 10 years' service is required for entitlement to pension. The scheme are financed by diverting a portion of the employers' and employees' contribution to the Employees' provident funds with an additional contribution by the Central Government.

**(f) Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act (1952)** - While provident fund schemes were common in some government employments and with enlightened employers, the first legislative measure to cover industrial workers was the Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act (1948). Though in the initial years the Act ran into opposition, both from employers and workers, after sometime the misgivings on both sides were dispelled and the Act got off to a good start.

The Act provides insurance against old age, retirement, discharge, retrenchment or death of the workers. It is against these risks that the schemes guarantee the necessary protection to workers and their dependents. The Act and the scheme are extended to the whole of India. It applies to factories and establishments falling under any notified industry employing 20 or more persons.

To become eligible for membership of the fund, a worker must have completed one years' continuous service or worked for 240 days during a period of 12 months.

The employees have to contribute at the rate 6 ¼ per cent of the basic wage, dearness allowance and retaining allowances if any including the cash value of food concessions given to them. The employers too, have to contribute at the same rate. Workers if they so desire, can contribute more, subject to a maximum of 814 per cent. With effect from January 1 1963 the statutory rate of provident fund contribution has been raised to 8¼ per cent in respect of certain industries / classes of establishments employing 50 or more persons in a few specified industries.

**(g) The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970** - Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 was enacted not only to regulate the contract labour but also to abolish it. To lessen their burden and to avoid liability towards regular employees, employer devised a Scheme of getting their work done through contract workers. Contract labour which forms a unorganised sector of employment were Subjected to lot of discriminations and expenses. Contract Labour Act came to mitigate their sufferings and to regulate their employment.

For the purpose of this Act a person is said to be employed as contract labour, in or in connection with the work of an establishment, when he is hired for such work by or through a contractor, with or without the knowledge of the principal employer.

**(h) The Minimum Wages Act, 1945** - Wages in the organised sector are determined through negotiations and settlements between employer and employees. In unorganised sector, where labour is vulnerable to exploitation due to illiteracy and lack of effective bargaining

power, minimum rates of wages are fixed both of Central and State Governments in the Scheduled employments falling within their respective jurisdictions under the provisions of the Minimum Wages Act, 1948.

The Minimum Wages Act, 1948 is also very relevant for women workers because it is primarily designed for the protection of workers in the unorganised sector, where majority of women work.

In *Madhya Pradesh Mineral Industry Association v. The Regional Labour Commissioner (Central Jabalpur and Others)*<sup>15</sup>, has held that it is true that the provisions of the Minimum Wages Act are intended to achieve the object of doing social justice to workmen employed in the scheduled employments by prescribing minimum rates of wages for them, and so in construing the said provisions, the Court should adopt what is sometimes described as a beneficent rule of construction.

**Conclusion** - India consists of about 487 million workers, the second largest after China. India has numerous labour laws for prohibiting discrimination and child labour. There are sufficient statutory provisions for regulating the working hours, particularly in industries, plantations and mines. However, unregulated factories and unorganized sectors need to be covered under such law. The 48 hours per week, as fixed under the Factories Act of 1948, are quite sufficient at the present time. The working hours cannot be suggested to be very long as the psychology of workers an climate makes them work leisurely and with less concentration in the Indian working condition. The working hours can be reduced to a limit where the production remains unaffected in the factories. The Act aims to guarantee fair and human conditions of work, provide social security, minimum wages, right to organize, form trade union and enforce collective bargaining.

Governments are bound to comply with the socio-economic laws, failure of which will be a violation of Article 21 of the Constitution of India. India is considered to be the highly regulated and most rigid labour laws countries in the world. They need to be flexible for their proper implementation and should be reviewed from time to time according to the need of labour and economy's dynamics. Labourers consist both men and women workers. Without labourers, there is no industry. Women alongwith men contribute their might for the industrial growth. In industries women are employed in light unskilled work. Women of poor families earn their living by manual work. The Vienna Declaration adopted in the world conference on Human Rights at Vienna in 1993 recognized women's rights as inalienable, and an integral and indivisible part of universal human rights. The Constitution of India contains several provisions for the protection and security for women. These provisions deal with equality before law, right to protective discrimination, right to equality of opportunity in public employment, right against exploitation, right to equal remuneration and maternity relief.

Hence it is necessary to take measures for effective implementation of all these welfare Legislations by

expanding their scope and application for protection of Rights of women workers.

#### References :-

1. Agarwal, D.R., Labour Problems, Social welfare and Security, Forward Publishing Company, New Delhi, 1996.
2. Bhattacharya, Vivek Ranjan, Some Aspects of Social Security Measures in India, Metropolitan Book Company, New Delhi, 1970.
3. Kumar, Anil, Labour welfare and social security, Deep and Deep Publication, New Delhi, 2003.
4. Mishra, S.N., An introduction to Labour and Industrial Law, Allahabad Law Agency, Allahabad, 2015.
5. Rai, Sunil Choudhury, Social Security in India and Britain, World Press (P) Ltd., Calcutta, 1962.
6. Sinha, P.K., Social Security Measures in India, Classical Publications, New Delhi, 1984.
7. Srivastava, S.C., Social Security and Labour Law, M/s. Eastern Book Company, Lucknow, 1985.

#### Footnotes :-

1. V.V. Giri – Labour problems in Indian Industry, p. 27
2. Dr.Rameswari Pandiya and M.S.Dhara Thakkar, Working Women: Issues and Challenges (Gurgaon: Madhav books) 2010 Edition p.10.
3. ILJ, "Special Article: Sixty Seven Years of Independence-A Kaleidoscopic View of Labour Activities", Vol.55, 9 (2014) p.932.
4. D.P. Singh, Women Workers in Unorganised Sector, (New Delhi: Deep and Deep Publications Pvt. Ltd.) 2008 Edition, p.2.
5. Vibhuti Patel, "Women Workers in Informal Sector" In: Ravi Prakash Yadav, Kumar Chandradeep, Barsa Editors, Women Workers in India (New Delhi: New Century Publication) 2012 edn. P.1.
6. Report of Second National Commission on Labour, 2002, p.937.
7. National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector, Report on Condition of Work and Promotion of Livelihoods in the Unorganised Sector, 2007, p.18.
8. Dr.S. Maria John and Dr.Mrs.A. Mary Grace, Women Labourers in unorganized sector, In: Dr.A.Selva Kumar editor, Plight of Unorganised Workers (New Delhi: Discovery Publishing House Pvt. Ltd), 2009 Edition, p.83
9. Ibid, at 20
10. Dr. Anita Dash, Women Industrial workers: Perception and Dynamic (New Delhi: Regal Publications), 2009 Edition, p. 25
11. Government of India, Report of the working Group on Empowerment of women, (2006), p. 35
12. Government of India, Report of the Working Group on social security for the Twelfth Five Year plan (2012-17), p. 169
13. AIR 1968 SC 683
14. 11 LLJ 424 (DB) (Bom.)
15. AIR 1960 SC 1068.

# Online Insurance Market in India : Opportunities and Challenges

Dr. Santosh Kumar Panigrahy\*

**Abstract** - The online Insurance in India to administer the system of operations shall be kept at utmost importance to keep them positioned to the foreign insurance providers competition. Records needs vis-a-vis various insurance products and services as assured by the Regulatory Body of Insurance setup under the Insurance Act are most important matter. The proliferation of innovative products and distribution channels and the raising of supervisory standards are good reasons for the growth momentum can be sustained. In particular, there is huge untapped potential in various segments in the market. Major changes in both national economic policies and insurance regulations will highlight the prospects of segments going forward. The present paper entails current state of development in India's online insurance market and enumerates the opportunities and challenges offered by this exciting market.

**Keywords** - Online insurance, E-commerce, E-insurance, IRDA.

**Introduction** - Insurance penetration in India accounts 3.9% as below the world average of 6.3% in 2013. However, during the year 2018 the insurance penetration in India increased at 3.70%. The insurance industry in India has undergone transformational changes over the last 13 years. Liberalization has led to the entry of the largest insurance companies in the world, who have taken a strategic view on India being one of the top priority emerging markets. The industry has witnessed phases of rapid growth along with spans of growth moderation, intensifying competition, with both life and general insurance segments having more than 20 competing companies and significant expansion of customer base. There have also been number of product innovations and operational innovations necessitated by increased competition, among the players. Changes in the regulatory environment had path-breaking impact on the development of the industry. Life insurers are trying to move more and more renewals to online channels. Currently online renewals are expected to be around 10-15% of overall individual business renewals, which means around Rs. 15000-25,000 crore worth of renewal premium is already coming through the online channel for the industry. By 2020, online renewals are expected to be 35-50% of individual renewal premiums, which will take online renewal premium to Rs. 1,75,000/- to Rs. 3,00,000/- crore.

Online insurance products might not resist the 'warm-smile' of a life insurance agent. There are also successful models in other financial and non-financial services business which are to be adapted to distribute life insurance products to examine from an 'ideating' perspective.

## Objectives of the study :

1. To study the emergence and growth of online insurance

market in India.

2. To find out the challenges ahead for online insurance.
3. To understand the Internet insurance model in the present scenario.
4. The real potential of India for Online insurance marketing in India.
5. The IRDA regulation for developing and promoting Online insurance.

**Methodology** - The paper is based secondary data provided by many research organisations. Some of the organisations are national level reputed statistical organisations regularly conducting structured and unstructured sample surveys. Annual report, insurance books, magazines etc. are collected from the respective websites. Report is based on the findings of different state level data banks. These data are correlated for the obvious purpose of finding conclusions.

**Present scenario** - Online life insurance sales are expected to grow at approximately 5% of the individual annualized new business premium by 2020, whereas the non-life insurance sales are expected to grow at more than 15% of non-life retail insurance business. This growth trend, expected to grow stronger in future, is primarily attributed to the increase in smart phone usage and internet penetration.

Insurers do like Online Insurance channel for the fact that the sales online are 20% to 25% cheaper compared to the one happening offline. The internet penetration in India has been on the rise, whereby increased number of people has access to Internet both through computes as well as through mobile phones, including population in tier-2 and tier-3 cities.

\* B. Tech., M.B.A., Ph.D. Software Engineer, IBM, Bangalore (Karnataka) INDIA

**Demographic Distribution** - Internet insurance business is growing well in India these two years according to a report published by Daily News and Analysis (DNA). Thanks to the rise of the Internet access and a young generation of working middle class professionals who are reaching the cusp of adult life in India. Nonetheless, young consumers who are Internet savvy are the key buyers for insurance online. "Online term plans and motor insurance policies are mainly picked up by youngsters and high net-worth individuals. As policies offered online are easy to understand, they enjoy much demand," Says A.S. Narayan Chief Distribution Officer of Bajaj Allianz Life Insurance. Bajaj Allianz has been rolling out Internet insurance initiatives targeting internet savvy young consumers these past 2 years, including its iGain online insurance plan. However, India's insurers are still keeping complex insurance products offline and sold through conventional channels.

**From E-commerce to E-insurance** - E-commerce adapts the principles of traditional commerce to support business processes over the Internet. It is the term used for the collective process consists of searching, procuring and purchasing goods over the Internet. A typical e-commerce transaction can be divided into the following phases:

**Search:** In this phase, a consumer searches for items from different online sellers.

**Valuation:** The consumer compares over from different sellers to select the item that best matches his needs.

**Logistics:** The details of the transaction are exchanged between the buyer and the seller. In this phase, the seller conveys the details of the item to the buyer and the buyer responds with specific requirements. Negotiation of price and other parameters take place during this phase. The protocol for the exchange is also determined in this phase. For example, the seller might accept a specific type of payment, or the buyer might prefer a specific mode of delivery.

**Transaction:** The actual exchange of the item takes place in this phase. The buyer pays the seller the required monetary amount decided in the previous phase. The seller then delivers the item to the buyer. Typically, this phase involves trusted third parties, like financial institutions issuing credit cards, and carriers delivering the item to the buyer.

**Post-sales services:** In this phase, seller provide services related to the item after it has been sold. This might involve setup of the item at the consumer's location, or repair or replacement of a defective item. This phase is sometimes based on goodwill and often overlooked and neglected in both traditional and e-commerce.

Online insurance requires the traditional methods of insurance to be replaced by online processes analogous to those in e-commerce. In this paper, we have referred to insurance processes conducted over the Internet by the term e-insurance.

The rest four stages of e-commerce described above

directly lend themselves to analogous steps for purchasing an insurance product online. Consumers search from different insurance companies for products that they are willing to purchase.

They evaluate the products from divergent companies to determine the one which best suit their needs. The terms of the insurance policy are then conveyed to the customer by the insurance company and the customer responds with details including a description of the entity being insured, the terms and the duration. When both the customer and insurance company agree to go ahead with the transaction, the buyer pays the initial premium to the insurance company and the policy certificate is sent to the buyer.

The post-sales phase of e-insurance is however considerably divergent from e-commerce. In e-commerce, human intervention is required for activities in the post-sales phases such as repair or replacement of parts. However, a major interaction between an insurer and the insurance company occurs in the post-sales phase if the insurer submits a claim for the amount insured. Online claim settlement involves complex interactions between the insurer, the insurance company and possibly legal and judicial authorities and in an automated environment. This phase is therefore the most midcult to implement over the Internet and Online insurance sites mostly rely on human intervention for this phase.

**Categories** - Websites almost every insurance company has a homepage providing information about the company and products. However, these homepages are little more than passive online versions of the company's brochures. For example, the Indian insurance leader in the non-life segment National Insurance Corporation (NIC) details the policies that it carries. On the other hand, New India Assurance only provides contact information on its website. These sites are used primarily for marketing support and do not support interactive dialog with interested clients. Product portals are sites that provide a collection of links to sites of interest. Examples of such sites are Assure India, and Bima Guru. Unfortunately, these sites are also equally passive as company WebPages.

Point-of-Sale portals unlike most other commodities, the sale of insurance products are initiated by the sellers. Certain sits exploit this approach by offering insurance products while selling insurable goods such as cars or while providing information on health or college education.

Intermediate brokers are intermediate sites that do not sell insurance products directly but assist clients in matching their requirements with the policies offered by insurance companies.

**Reverse Auction:** In this model, the client is usually an organisation interested in group insurance. The client announces its requirements and selects five best offer made by an insurance company.

**Aggregators:** are sites that compare quotes from different insurance companies. The service is often supplemented with general information on products as well. Examples of



such sites include Insweb, Quotes Smith and e-Health Insurance.

Selection of policy and recommendation insurance employs the internet to reach customers through advertisements more effectively since the internet integrates the traditional passive and active channels into one. Advertisement banners, e-mail notification and coupons are used to replace passive media where software agents replace their active human counterpart.

**Policy purchase and E-certificate** - With the internet the policy purchase phase has probably been influenced and improves to the greatest extent. After selecting a policy the best suits his needs the buyer fills up an online proposal form and sends it to the insurance company. The insurance agents and the underwriters of the insurance company then examine the entity to be insured, determine the premium for the policy and send the final terms of the policy back to the buyer. The buyer then examines the terms of the policy and confirms his acceptance. Next the buyer, who has now become the insurer, has to pay the first premium for the policy through a credit or debit card.

#### Online insurance in India

**Realigning the business model** - Life insurers have traditionally aligned themselves to models that are inherently conventional in its approach-individual agents, banks, corporate agents and insurance brokers instead of giving importance to either the customer or product segmentation. In fact, while many insurers have built customer relationship databases, the data itself is not mined or tracked to increase the positive interactions with the customer. This has resulted in lower persistency levels (poor customer loyalty) and even resulted in customers avoiding face-to-face interactions with insurance agents. Persistency was long ignored by the insurance companies when the growth in new business premium was high. However, with the growth slowing down, focus on retention of policies has gained focus. Explosion of technology backed with the increase in Internet and mobile telephony provides a low-cost opportunity as now life insurers can leverage some of the success of online banking and e-commerce to build an online product bouquet that engages the customer and enables him / her to buy.

**Technology-enabled model for urban India** - There is enough evidence from developed markets that internet penetration and usage have a positive correlation with the performance and activities of insurance companies at various levels – lower customer acquisition costs, improved access to information, product innovation that cater to the needs of the customers and enhanced convenience. Increasing Internet penetration (with the number of users in India expected to rise from 429 million in 2017 to 829 million by 2021 at the rate of 17.9%) will continue to influence the insurance business as well as other industries. However, there has been a surge in volume and value of retail transactions in the last decade that reflects the comfort of the internet users to conduct financial transactions online.

**Retail Electronic Transactions** - Online sales of insurance

products have one important distinction since the customer's needs and preferences have led to the purchase decision, the customer would ideally have made a properly informed choice. Also, since insurers do not have the opportunity to influence the customer's purchase decision, the design of the web portal needs to be easy to understand and interactive enough to make the transaction seamless. The products offered through this channel should meet the needs and offer benefits / features that differentiate the product from the offerings of their competitors.

In the past 2-3 years, a range of protection products that include health insurance as well have been offered to Indian consumers as against the pure term insurance policies that were sold earlier. Insurance companies in recent years have also witnessed that persistency and the proportion of claims being rejected is lower in case of the online customers making this segment an attractive and low cost channel. While the current size is marginal as compared to overall customer base and underwritten premium, the segment shall witness growth and reach a significant size in the future as the internet penetration increases and awareness of the customers also rise.

**Table-1 : Growth in retail electronic transactions**

Retail electronic transaction	FY 04	FY 12	Annualized return
Volume (Million)	157	1160	27.42%
Amount (INR billion)	521	22075	59.71%

Source: Reserve Bank of India Bulletin (2011-12)

Going forward, technology will have to be used effectively to provide means of allowing consumers make more educated choices. Technology will have to help identify and provide a set of results of a specific insurance requirement as a function of its features and compatibility that is driven by logical algorithms and not just revenue to the internet company. This would require insurers to design websites that are easy to use and ensure that transactions are seamless. In the era of consumer, the ways and means of connecting with them is undergoing a major shift. The Internet has been BIG game changer. The BIG change that Internet has been able to bring is that it is 'Being bought' by customers from 'Being Sold' to customers. A case in Point is New India Assurance which launched an 'online' platform for its products. The country's largest general insurer will offer products in motor, health, travel and personal accident space through this portal along with policy renewal facilities.

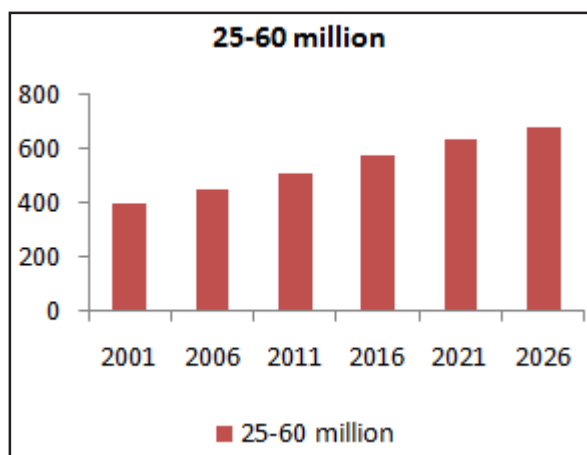
Today more than 165 million Indians have Internet connections. Indians spend more time on the Internet than watching television and are the third largest users of social networking sites like Face book. Already, most of the Indians are using net banking. From a modest beginning like the banking sector, with online transaction facilities for existing customers, insurance companies are now rapidly moving towards selling products online. It has been found that more than 54% of Internet users search for financial services and insurance as a category.

The online journey of insurance started with emergence

of comparison and research platforms. Around 20 other players such as Policy Bazaar, Zibika, Fintact, My insurance Club and Insuring India launched their own aggregation sites. After testing the aggregation model, start-ups forayed into selling leads to insurance companies and earned a commission on every lead conversion. A majority of them are currently focusing on term insurance and car insurance. They are considering the Internet as a future channel of distribution which can bring immense expansion to their business. There are three insurance companies i.e., Aegon Religare, Aviva Life Insurance and HDFC Life Insurance have included Internet and Online aggregators as a major focus in their distribution strategy. Over 65% of insurance based searches are dominated by one player. In India, with the required approvals in place, Policy Bazaar and my insurance club have gone beyond the aggregation model and have started selling policies online. The overall growth registered by start-ups in aggregation model is not encouraging; however, Policy Bazaar registered phenomenal 200% growth over the past two years.

**Online Insurance in India: The Road Ahead** - The demand for insurance products is likely to increase due to the exponential growth of household savings, purchasing power, the middle class and the country's working population. The working population (25-60 years) is expected to increase from 449 million 2006 to 676 million in 2026. Increased incomes are expected to result in large disposable incomes, which can be tapped and the insurance sector in particular. Online insurance is expected to follow the growth route of online travel in the next 2/3 years to come. United Kingdom and European markets have clearly shown the way.

**Fig.-2 : Working population assessment and GDP per capita till 2026**



Source: CMIE, Census of India, 2001.

Where online insurance started with aggregation model and now 70% of auto insurance in most of European countries is sold online. The industry expects similar trends here in products life term insurance and car insurance over the next 2/3 years. Some products which are highly complicated will take more time; however, products like

ULIPs which have low distribution margin would eventually move significantly to online distribution models. By 2018, the online insurance industry is expected to grab 25-30% of the overall insurance market; out of 50-60% of volume would be dominated by third party aggregators. Similarly, as e-commerce industry expects 23 players would emerge successful in this space.

**Online insurance in India: Challenges** - Online sales channel, while attractive and lucrative has its own challenges. Influencing the customer's buying decision online is a challenging task. It is probably the reason why several industry surveys reveal that online user experience with Indian life insurers has been poor. In Life Insurance, years of efforts by the India's insurance regulator IRDA to ensure insurance companies make their insurance products easily understood by customers does not seem to have yielded the desired results. Even though Internet insurance market seems promising and geared for greater growth. India's regulatory body insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) has been regulating the industry closely and poses some challenges to the online insurance business. The IRDA guidelines on insurance comparison websites are making the online channel unviable. Owing to issues like lack of transparency of information, lack of standardization of nomenclature of key terms, most of the online insurers were unable to make an impact. The aggregators have to overcome some problems before they can be accepted widely. These problems include:

1. It is sometimes difficult to extract enough information to write a policy just from online interactions. Some insurance products like annuity products and index-linked life products are two heterogeneous to be sold online.
2. Aggregators expect revenue from clients which the clients are possibly unwilling to pay.

Clients develop no brand loyalty towards aggregators. In spite of all their drawbacks, aggregators are the closest to automated on-line insurance and has been adopted most widely by online insurance companies.

The buying insurance online in India, the decision is entirely of the customer, based on the recommendation of facts and figures rather than that of a sales agent. Many insurance providers also believe that if the customer is literate and has made a choice based on proper research, he / she must be taking well informed decisions in life. This brings companies to the assumption that the life of the person who takes well informed decisions is at less risk, and hence lowers premiums. Even though they generally agree that the Internet channel is cost-effective and has great potential in sales and distribution of insurance products, they only offer simple products online for the time being. Besides regulations, policy-buys in India still require more information and advice compared to more informed consumers in developed countries like United Kingdom. Online sales channel, while attractive and rewarding has its own challenges. Influencing the customer's buying

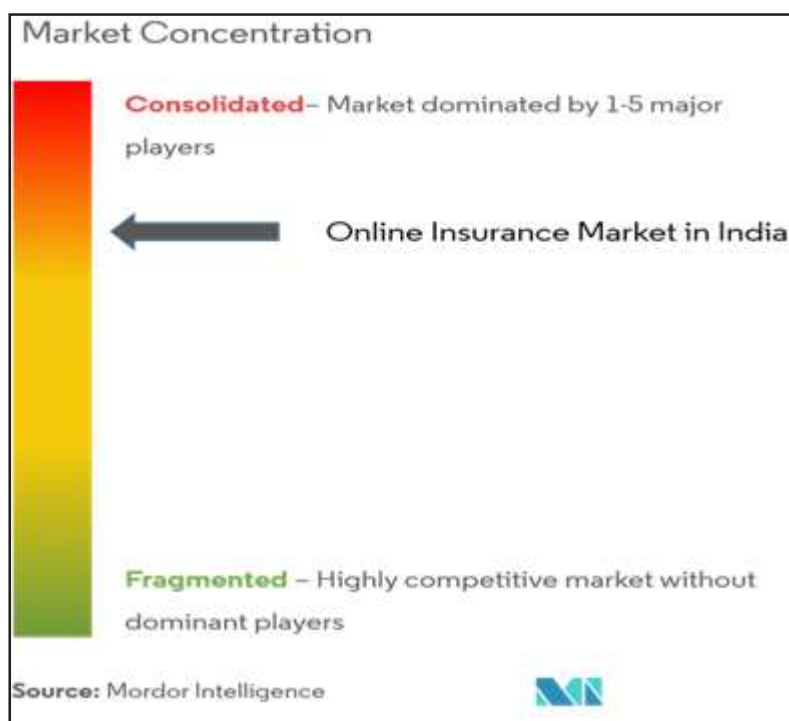
decision online is a challenging task. That is probably the reason why several industry surveys reveal that online user experience with Indian life insurers has been poor. In Life insurance, years of efforts by the India's insurance regulator IRDA to ensure insurance companies make their insurance products easily understood by customers does not seem to have yielded the desired results. When it comes to challenges with respect to aggregation model and selling of insurance policies via third party platforms (such as Policy Bazaar, My insurance club), the toughest challenge is to get IRDA's approval as it is a strictly regulated space. LIC and their agents have been the biggest resilient to online insurance because of the redundancy of insurance agents. LIC agents contribute to about 85% of the field force and they are guided by the unions, their views are considered quite seriously.

**Conclusion -** The demand for insurance products is likely to increase due to the exponential growth of household savings, purchasing power, the middle class and the country's working population. The working population (25-60 years) is expected to increase. Increased incomes are expected to result in large disposable incomes, which can be tapped and the insurance sector in particular. Online life insurance sales are expected to grow to 3-5% of the individual annualized new business premium by 2020; and non-life insurance sales are expected to grow to 15-20% of non-life retail business. The number of internet users in India is expected to grow from 200 million today to nearly 330 million by 2018, thanks to improving infrastructure, the spread of mobile phones to the most far-flung rural areas and affordable internet facilities. Behaviour in the e-

commerce space clearly corroborated that there is an ever-growing market for online financial products and online research for insurance is converting into sales. Currently, around 18,000 policies are purchased online every month. Though the given figure only constitutes 2% of overall offline sales, it grew 20% in from 2010 to 2020. However, it's an industry still in the emerging stage and has a long way to go.

#### References:-

1. IRDA Annual reports, various editions FY 2011 to 2018-19
2. IRDA Journals, in FY 2011 and 2012
3. Reserve Bank of India Annual Report, various editions from FY 2011 to 2018-19.
4. <http://www.cmie.com>
5. "World Insurance in 2011" – Swiss Re
6. "Addressing distribution challenges in Insurance" by Confederation of Indian Industry, Feb. 2012
7. "Fraud in insurance on Rise: Survey 2010-11" Ernst and Young, 2011.
8. "Indian Insurance sector: Stepping into the next decade of growth"- Ernst and Young, Sept. 2010.
9. Neha Tuli: Online Insurance Landscape in India: *The Road Ahead*, March 14, 2013.
10. P. Dasgupta and K. Sengupta – E-commerce in the Indian Insurance Industry.
11. Insurance Industry- Road Ahead: Path for sustainable growth momentum and increasing profitability, [www.kpmg.com/in](http://www.kpmg.com/in)
12. Lakhangaonkar Ms. Supriya M. Online Insurance in India A Long Way to Go (IJERA), ISSN : 2248-9622 (ICIAC12th and 13<sup>th</sup> April, 2014)



# Exploration of Pattachitra Paintings - A Reflection of Indian Culture and Traditions

Dr. Smita Jain\*

**Abstract** - In this paper, the researcher analyses the rich indigenous tradition of Pattachitra paintings of Odisha and throws light on the detailed tools, techniques, colours and processes involved in the creation of Pattachitra paintings and how these help make it unique among other traditional Indian art forms.

**Keywords** - Pattachitra, Indian Culture, Indigenous Colours, Artisanal Traditions.

**Introduction** - India has always been recognized for its vast cultural heritage and the same often manifests itself in the form of various art forms. The folk art of every region in India has its own style and pattern. Indian art is simple, and yet colourful and vivid enough to speak volumes about the country's rich and complex heritage. Folk paintings are diverse in India and reflect rich cultural heritage, they are the true examples of artistic expression.

Most of the Indian traditional art forms possess intense meanings apart from being a visual treat. Before the 20th century, only Mughal paintings were appreciated in India but gradually this Indian folk art emerged as a subject of study and appreciation.

These Indian paintings have their own style, designs, and colours. They were often made leading up to celebrations of festivals and religious rituals. Different Indian art forms are the result of a long history of rich cultural and artistic heritage. One such art form is Pattachitra of Odisha.

Pattachitra is a Sanskrit word; wherein, *patta* means cloth, and *chitra* means 'picture'. Therefore, *Pattachitra* means a picture painted on a piece of cloth. These Pattachitra paintings resemble the old murals of Odisha that were found in and around the religious centres of Puri, Konark, and Bhubaneswar. These murals go back to as early as 5th century BC. The most intricate Pattachitra work is done in Puri, especially in the village of Raghurajpur. Raghurajpur was selected to be developed as the state's first heritage village. It is 14 km away from the pilgrimage town of Puri, on the southern banks of river Bhargabi. This art is also done in Paralakhemundi, Chikiti, and Sonapur. Chitrakaras are the artists who do these paintings and they reside near temple areas of Puri. These artists use the titles Mohapatras, Maharanas, Sahoo, and Swains with their names. This art is passed on to the next generation by the head of the family.

## Painting Process

**Preparation of Canvas:** Preparation of canvas is the first

process of painting Pattachitra. Traditionally, cotton canvas was used; today cotton and silk canvas are being used to make these paintings. The fabric to be painted is dipped in a solution of powdered tamarind seeds and water for 4-5 days. The cloth is then taken out from this solution and dried in sun. After the fabric dries, a paste of chalk powder, tamarind, and gum is applied on both sides of the layered fabric and is dried in sun. In order to smoothen the fabric, khaddar stone is rubbed several times on the canvas followed by rubbing smooth surfaced stone to introduce shine.

**Preparation of Colour:** In earlier times the colours were extracted from a natural source, the most commonly used colours were black, white, yellow, and red. The process to prepare these natural colours was very elaborate and tough. Now, these colours are prepared by using a variety of stones and chemicals available in the market. Various hues and shades of colours are made by mixing primary colours, like, red mixed with white gives pink. The colours are made and poured in locally available coconut shells, in case these colours dry while painting, water is mixed in the colour and it is reused.

**Painting Process:** Immense patience, hard work and skilled craftsmanship are required to make Pattachitra paintings, as it is intricate work. Borders are an integral part of these paintings and are drawn first on the canvas on all the four sides consisting of two or three lines according to the size. Then the outlines of the figure are drawn with a sharp tip pencil. The next stage is to colour the body followed by colouring the attire of the figure. In the final stage, the figure outline is made in black colour.

**Tools Used:** The tools used in the process of painting are a brush, locally known as *tuli*, container, earthen pot, coconut shells etc. Brushes are used to apply paint on the fabrics which are of different sizes and are made by tufts of hair tied together to the ends of bamboo twigs with the help of thread. Over the knot, liquid lac is applied to bind it firmly. The soft quality of the brushes is due to them being made using rat and squirrel hair, coarse and hard brushes are



made by buffalo-hair. Bamboo tube container called *Baunsanali* is used to keep the brushes during the painting. Coconut shells called *Sadhei* are generally used as containers for mixing colours.

**Popular Themes:** The main themes of Pattachitra paintings have always been inspired by Lord Jagannath and the Vaishnava sect. Many Pattachitra paintings are amazing representations of stories of Lord Jagannath and Radha-Krishna, the ten incarnations of Vishnu, episodes from the Ramayana, the Mahabharata, Krishna Lila, Jain and Buddhist scriptures. The figures in an original Pattachitra is characterised by long beak-like noses, prominent chin, as may be seen in Figures 1, 2 and 3; and elongated eyes as seen in Figures 2 and 3.



Fig. 1 (from Odisha Tourism official website)



Fig. 2 (from www.jaypore.com)



Fig. 3 (from www.webneel.com)

Some important themes of Pattachitra paintings are as follows:

**Thia Badhia** - depicts the temple of Jagannath;

**Krishna Lila** - enactment of Jagannath as Lord Krishna displaying his powers as a child;

**Dasabatara Patti** - depicts the ten incarnations of Lord Vishnu;

**Panchamukhi** - depicts Lord Ganesh as a five-headed God.

Today, handicraft items are an integral part of Odisha's rich cultural heritage and the patta painting has been recognized as one of the popular art forms with distinctive colourful designs. These paintings have great potential in the International market because of its traditional aesthetic sensibility and authenticity. It is in much demand in countries like Australia, UK, and USA. This ancient art is being revived substantially to suit the requirements of modern times. For this new variety of products that have been introduced are in the market like bookmarks, greeting cards, folders, decorative pieces and many more articles to reach maximum people.

#### References:-

1. Folk Painting and linearity of Orissa: A profile of patachitras, p 13
2. Mahapatra, T. Patachitra an Indigenous Technique, Orissa Review, 2005
3. Pathy, D. Essence of Orissa Painting, Harman Publishing House, New Delhi: 2001, p.81-84
4. Sreenanda Palit & Dibyendu Bikash Datta, Transformation from Performative Art to Demonstrative Art: A Survival strategy for Patachitra, Asian Journal of Multidisciplinary Studies, February 2016
5. <http://www.craftmark.org/>
6. <http://shop.gaatha.com/Buy-Patachitra-Painting-Orissa8>
7. [https://www.facebook.com/OdishaTourismOfficial/?ref=page\\_internal](https://www.facebook.com/OdishaTourismOfficial/?ref=page_internal)
8. <https://in.pinterest.com/pin/826129125365771011/?lp=true>
9. <https://www.redbag.in/products/radha-krishna-patachitra-painting?variant=12882794184773>
10. [www.orissaart.com](http://www.orissaart.com)
11. [www.patachitrapaintings.com](http://www.patachitrapaintings.com)

\*\*\*\*\*

# CiteScore Analysis of IEEE Journals Indexed by Scopus

Moumita Roy\*

**Abstract** - Indexing scholarly articles and citations have become immensely important in the present time to make them available to the world and fellow researchers. A huge number of indexing agencies have shown their presence and are working incessantly in securing the documents and data and also defining metrics which help in evaluating quality the stored documents. Also, Open Access has proved to be very helpful and presently a lot of publishing houses are adopting this mode to provide unrestricted access to research documents. In this paper IEEE journals indexed by Scopus is considered for analysis. The average of CiteScore values of the journals are compared and results show that average CiteScore of Open Access journals is lesser than that of other journals.

**Keywords**— Indexing, Scopus, CiteScore, Open Access, IEEE Journal.

**Introduction** - Due to the rapid increase in the number of research related document, several indexing techniques and agencies are coming into existence today. Indexing helps in systematic archiving and easy retrieval of research related documents. If a journal is indexed, its articles get more visibility and are easily accessible by other fellow researchers. As a result, those articles will have a better chance at getting cited in succeeding publications. [1]Also, journal indexing helps in measuring a nation's scientific production [2]. Another approach to get better visibility is to publish in Open Access mode which will make the articles accessible freely without any cost. In this paper we will discuss Scopus indexing and Open Access indexing and also do a comparative analysis of open access and non-open access IEEE journals indexed by Scopus based on their citescore.

**Indexing and Open Access** - Indexing is a method of schematic data organization with the objective of quick reference or easy retrieval of the stored data [3]. We all use indexing in our daily lives in the smallest of things we do or see around us. It can be formally categorized into several types. The most common ones are Genealogical indexing, Geographical indexing, Periodical indexing, Newspaper indexing, Book indexing, Legal indexing, Pictorial indexing, Bibliographical indexing etc[4].

History of indexing traces back to the Greco-Roman Civilization when book summaries had ordered lists that looked like a table of contents. Indexing of scientific literature started much later. In 1960, Eugene Garfield, a linguist from America introduced citation index for research articles [5]. A journal article is written with the objective of creation and sharing of knowledge for the benefit of fellow researchers and the society at large. So, it is important that an article is found, accessed and cited with ease. Getting featured in a reputed academic indexed journal also is an indication of

the article's quality. That is why it is important that journal articles get indexed. Academic indexes like Web of Science, Scopus, Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), PubMed etc help scholars find and refer articles in their respective domains [6]. Web of science is a website that provides access to database of research articles of various domains, based on subscription. It was initially started by Eugene Garfield under the banner of Institute of Scientific Information (ISI) but now is maintained by Clarivate Analytics. Scopus is another very popular citation database maintained by Elsevier which has a huge repository of research journals from all prominent fields of research. Google Scholar is a bibliographic database that can be accessed using Google's web search engine free of cost. Google scholar database can be indexed using any metadata (Title, author name etc) that refers to one or a list of articles. The website of DOAJ, maintained by Infrastructure Services for Open Access, contains a list of open access journals. PubMed is a similar platform like google scholar that contains medical and life science domain journals. When it comes to indexing an article independently, the publishing journal should follow indexing standards like International Standard Serial Number (ISSN) and Digital Object Identifier (DOI). ISSN is used to identify a serial publication distinctly with the help of an eight-digit number. ISSN -can of two types: print ISSN (used for print media) and electronic ISSN (used for e-resources) [7]. DOI is a standard set by ISO which uniquely identifies objects like commercial videos, datasets, research articles etc.

In this paper as we will deal with Scopus indexing, CiteScore and Open Access. Before getting into the analysis part, we will discuss the terms in little bit of detail here.

**A. Scopus Indexing and CiteScore** - Scopus is a large database of scientific literature that is maintained by Elsevier since 2004. Elsevier, founded in 1880, is a Dutch

\*PhD Scholar (Computer Science) Christ (Deemed to be) University, Bengaluru (Karnataka) INDIA

organization working on information analytics and publishing of scientific research content. The Scopus database contains around 75 million peer-reviewed journals, proceedings from conferences and books from over 5000 publishing houses which makes it a huge collection of citable references. Figure 1 shows a symbolic representation of the Scopus database content. An article published in a Scopus indexed journal is believed to be of good research quality with important and innovative outcomes. Scopus also indexes patents and web pages in its database. Mongeon and Paul-Hus[8] mentioned that research evaluation using Scopus or WoS can lead to bias as they cover the fields of Engineering and Sciences more than Art and other Humanities domains.

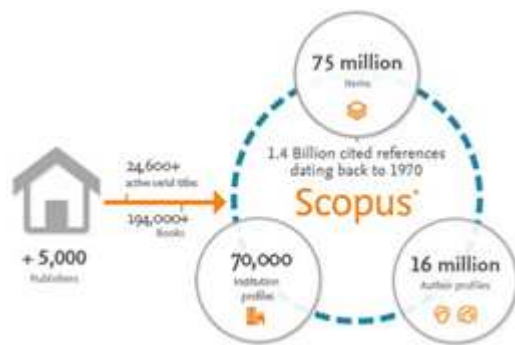


Fig 1. Scopus database content [10]

Fig 2. (see in last page)

The Scopus website provides an easy search option for journal titles and authors. When a particular journal is searched and selected, information like the journal's Scopus coverage span, publisher, ISSN, subject area, CiteScore, SJR (SCImago Journal Rank) score, SNIP (Source Normalized Impact per Paper) score, link to journal home page etc are provided. A year wise list of number of published documents that is indexed by Scopus is also made available. CiteScore, SNIP and SJP are metrics used to evaluate the quality of a research document. SNIP evaluates citation impact against the total number of citations in a particular subject context. In a field where chances of getting cited is less, the impact of one citation is considered to be more valuable. SJP not only counts the number of citations a journal got but also considers the reputation of the journals from where the citations came. CiteScore is a metric designed by Elsevier in 2016 for the purpose of journal evaluation. Before this metric, Impact Factor mentioned in Journal Citation Reports (JCR) was considered for evaluating journal quality, But JCR is not accessible by non-members and needs subscription. Probably due to unrestricted access, CiteScore gained popularity [9]. CiteScore depends on the number of citations received by the articles published in a journal. The metric is a ratio of the number of citations received by the journal in the fourth year by the number of documents published in the previous three years. So, it requires a minimum time period of four years for evaluation. Figure 2 demonstrates

the CiteScore calculation.

**B. Open Access Journals** - Open Access is a practice of letting online research outcomes like research articles or data accessible to anyone who wants to access, without a fee or any other technical barrier. The object of Open Access is to make research and related information visible to the reader who can work on it further doing good to the research fraternity and the society at large [11]. Drafted in 2003, The Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities contains the Open Access principles which, till present times, has been signed by many popular universities and research institutes [12]. Mainly there are two ways of Open Access publication: the gold open access and the green open access. Gold open access is when a research article is published in an Open Access journal. Such publications make the articles accessible immediately after publication. Green open access is when electronic copy of a research article is self-archived in an Open Access database. Green Open Access makes the archived manuscripts available without restrictions after a n embargo period. The article available through gold Open Access is the publisher's version of record but in case of green Open Access it is the author's final version of the document after review. Author is charged with a processing fee to provide gold Open Access but no charges are required in case of green Open Access articles. Gold Open Access requires authors to have a Creative Commons (CC) license to enable the reader to freely share or transform the research manuscript, but in green Open Access re-usability is restricted.

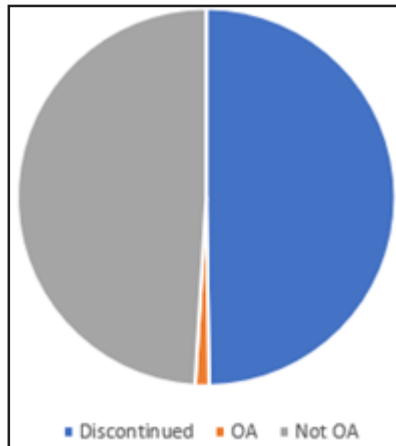
Scopus database has indexed a lot of Open Access journals. There are multiple ways of identifying Open Access journals in Scopus. In the Sources page in Scopus website there is a filter for "Display only Open Access journals". The source list will show only Open Access journals matching the entered keyword with the journal title. Also, in the source list, Open Access journals are marked with orange text label "Open Access" [13].

**Analytical Study and Findings** - A list of all IEEE journals and conference proceeding that are indexed by Scopus were collected. A total of 422 IEEE research documents were found. Out of these, 210 were discontinued from Scopus indexing. From the remaining 212, journals with Open Access tags were identified. 5 Open Access journals were found.

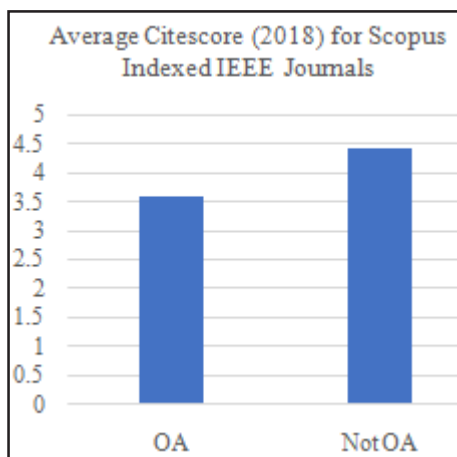
Table 1. IEEE Journals Indexed by Scopus

Scopus Indexed IEEE Journals and conference proceedings	422
Scopus Indexed IEEE Journals and conference proceedings with a citescore	212
Scopus Indexed OA IEEE Journals and conference proceedings with a citescore	5
Scopus Indexed IEEE Journals and conference proceedings (not OA) with a citescore	207
IEEE Journals and conference proceedings discontinued from Scopus indexing	210
Scopus Indexed IEEE Journals and conference proceedings	422





**Fig. 3 Status of IEEE Journals and Scopus coverage**  
The CiteScore values of the IEEE journals which are indexed by Scopus till date are collected and the CiteScore averages are computed for Open Access journals and other journals. The average CiteScore for Open Access journals are lesser compared to that of the other journals. For Open Access journals the average is 3.6 where as for other journals it is 4.41. The result does not justify the objective of Open Access as unrestricted access to a research article would logically mean more citations, but in this case the reason for lesser average citation could be the number of Open Access journals which is very less as compared to other journals. Fig. 2 shows a comparison of the CiteScore averages.



**Fig. 4 Comparison of CiteScore average**  
Few of the Open Access journals are indexed by Scopus since 2011 and the list grew till all 5 journals were added to the database in 2015. That is why the CiteScore values are shown from the year 2014 to 2019 as we know CiteScore gets calculated based on previous three years publication data. Table 2 and Table 3 shows the Open Access journal names and their year-wise CiteScores respectively.

**Table 2. IEEE OA Journals Indexed by Scopus**

S.	Journal Name
1	IEEE Access
2	IEEE Robotics and Automation Letters
3	IEEE Journal of Translational Engineering in Health

and Medicine

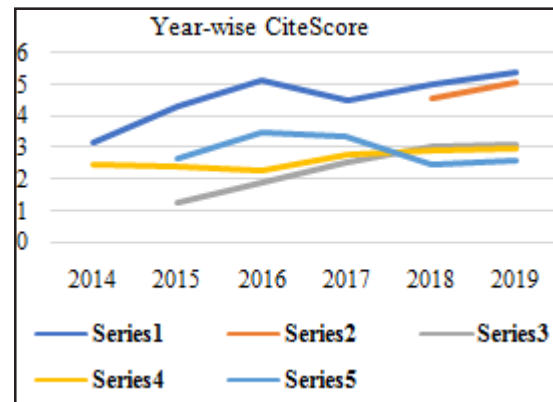
4 IEEE Photonics Journal

5 IEEE Journal of the Electron Devices Society

**Table 3. Year -wise Cite Score of IEEE OA Journals**

S.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	3.16	4.32	5.13	4.49	4.96	5.37
2					4.56	5.06
3		1.26	1.88	2.54	3.07	3.12
4	2.47	2.41	2.27	2.82	2.93	3
5		2.67	3.47	3.37	2.51	2.6

As we can see from the data, the CiteScore values for 4 out of 5 journals are increasing every year and for the fifth one it has maintained a plateau. Fig 3 shows a graphical comparison of the CiteScores. The result shows a hopeful progress and in future there is a very good chance that the average CiteScore of Open Access journals will be more than the other journals.



**Fig. 5 Comparison of year-wise CiteScore of Open Access journals**

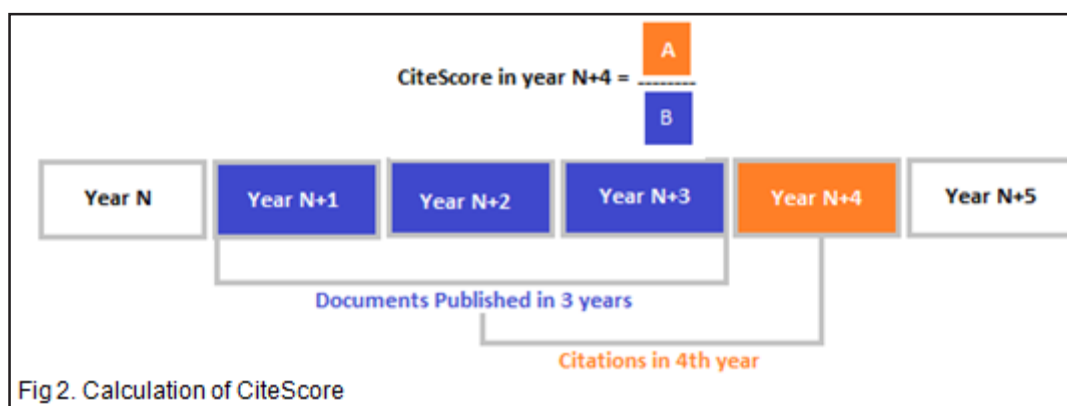
**Conclusion** - Indexing of academic literature is very much required in the present day given the amount of research work and data generation happening across the globe for easy identification of the documents and extraction of required knowledge. Also, the Open Access movement is gaining popularity in last couple of years due to its restriction free knowledge distribution and transforming capabilities. In this paper, Scopus indexed IEEE journals were considered. A major percentage of the journals and conference proceedings are discontinued from Scopus. Among the remaining, a small number are Open Access journals. The result of the comparison of their CiteScore shows that the average CiteScore of Open Access journals is lesser compared to that of the others. A probable reason could be the imbalance in the numbers and in future if the number of Open Access journals grow, the result can alter.

#### **References :-**

- Hu, Xiaojun & Rousseau, Ronald & Chen, Jin. (2011). On the definition of forward and backward citation generations. *J. Informetrics*. 5. 27-36. 10.1016/j.joi.2010.07.004.
- Schubert, A. (2002). The web of scientometrics: A statistical overview of the first 50 volumes of the journal. *Scientometrics*, 53(1), 3-20. <https://doi.org/>



- 10.1023/A:1014886202425
3. Balhara YP. Indexed journal: What does it mean?. *Lung India*. 2012;29(2):193. doi:10.4103/0970-2113.95345
  4. <https://www.anzsi.org/about-indexing/types-indexing/>
  5. <https://clarivate.com/webofsciencegroup/essays/history-of-citation-indexing/>
  6. <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/08/22/journal-indexing-core-standards-and-why-they-matter/>
  7. <https://www.issn.org/understanding-the-issn/issn-uses/use-of-issn-in-doi/>
  8. Mongeon, P., Paul-Hus, A. The journal coverage of Web of Science and Scopus: a comparative analysis. *Scientometrics* 106, 213–228 (2016). <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1765-5>
  9. Teixeira da Silva, J.A., Memon, A.R. CiteScore: A cite for sore eyes, or a valuable, transparent metric?. *Scientometrics* 111, 553–556 (2017). <https://doi.org/10.1007/s11192-017-2250-0>
  10. <https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content>
  11. <https://www.openaccess.nl/en/what-is-open-access>
  12. <https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration>
  13. <https://blog.scopus.com/topics/open-access>



\*\*\*\*\*

## खदान एवं पावर प्लांट के अवशिष्टों द्वारा संसाधन प्रबंधन

डॉ. कामता प्रसाद जायसवाल\*

**प्रस्तावना** – भारत में लगभग 90 तापीय विद्युत ग्रह हैं जो प्रतिवर्ष 300 मीट्रिक टन कोयला उपयोग कर 125 मीटर राखड़ उत्पन्न करते हैं। भविष्य में अतिरिक्त की ऊर्जा की मांग के अनुसार विद्युत ग्रह से अत्यधिक मात्रा में निकाकले वाला राख एवं उसका संधारण समस्या का कारण बनेगा।

कोयला उत्पादन के अत्यधिक गति से खोखली पड़ी खाली खदान भूमि एवं अवशिष्ट पदार्थ राख के संधारण हेतु हमारी बहुमुल्य संपदा भूमि के दुरुपयोग की समस्या एक ज्वलन विषय है। इन दोनों समस्या के लिये एक ही सिद्धांत उपयोगी होगा। जहां से आया वहां वापस भेज दिया जाए।

यह भूमि के पुनर्चर्चण सिद्धांत पर आधारित है। कोयला उत्खनन के पूर्व हम पृष्ठमृदा अलगकर कोयला निकालते हैं और खोखली खदान शेष रह जाती है। कोयला का उपयोग तापीय विद्युत ग्रह में विद्युत उत्पादन हेतु कर अवशिष्ट पदार्थ राख को राखड़ बांध में भेज दिया जाता है। जो भूमि की उर्वरता खत्म करने के साथ-साथ पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। घटिया कोयला के उपयोग से प्रदूषण और बढ़ता है। जिसके राख के संधारण हेतु नये-नये राखड़ बांध बनाकर भूमि के रकबा को कम किया जा रहा है। सिर्फ कोरबा जिला 20543 एकड़ भूमि खदान एवं प्लांट हेतु अधिग्रहित की गई है। जिसका 3068 हेक्टेयर भूमि सिर्फ राखड़ बांध के लिए है। यदि इस राख को हमारे परियोजना अनुरूप खोखली खदान में भरा जावे। तो वह सामान्य भूमि की तरह निर्मित हो जावेगा और भूमि का पुनर्चर्चण हो जावेगा।

इसके अंतर्गत हमने पांच प्रयोग किये। प्रथम प्रयोग में हमने स्कून मैदान में 3415 फीट का गड्ढा खोदा। जिसमें हमने राख एवं पानी 10 फीट तक भरा। फिर 3 फीट तक सीमेंट एवं अंतिम 2 फीट मिट्टी की पर्त बिछाकर उसमें एवं अन्य सामान्य भूमि पर गेंदा का पौधा के वृद्धि दर का अध्ययन पाया कि प्रयोगात्मक मिट्टी एवं सामान्य मिट्टी पर पौधा की वृद्धि दर एक समान थी।

इनही प्रयोग में हमने एक 15 सेमी लम्बाई एवं 3 सेमी त्रिज्या का पालीथिन लिया। हमने 10 सेमी तक राख 3 सेमी तक सीमेंट एवं अंतिम 2 सेमी मिट्टी डालकर कुछ घास रोप दिया। एक सप्ताह पश्चात पालीथिन को फाड़ने पर एक कठोर बेलनी आकृति वाला पदार्थ प्राप्त हुआ जो सामान्य ढाब सहन कर सकता है।

इसी तरह तीन अन्य प्रयोग कर भूमि पर राख के प्रभाव का अध्ययन किया एवं पाया कि राख भूमि की उर्वरता एवं उत्पादन क्षमता को नष्ट कर देता है।

इन पांचो प्रयोग के आधार पर हम कोयला खदान में उपयोग किया जावे तो वह सामान्य भूमि बन जावेगा। इस सिद्धांत पर हमने एक प्रयोजना बनाया यदि भूमिगत खुली खदान में राख को भरा जावे। जब खदान भू-

सतह से 25 मीटर गहराई तक भर जावे तो एलुमिना प्लांट बाल्की के अवशिष्ट पदार्थ एवं चूना खदान से प्राप्त अनुपयोगी चूना, पत्थर, राख एवं जल को मिश्रण 15 मीटर मोटाई तक भराव किया जावे तो यह स्टेज सीमेंट जैसे कार्य करता है यह 15 मीटर मोटाई का चट्टान स्वरूप सतह ढलदली राख के ऊपर बन जाता है। अंतिम 10 मीटर मोटाई में मिट्टी की पर्त बिछा दी जाये तो यह खदान की खोखली भूमि सामान्य भूमि जैसा निर्मित हो जावेगा। जिसमें वृक्षा रोपण, खेल मैदान चारागाह गार्डन आदि जैसे उपयोग कर भूमि उपजाऊ के रकबा को बढ़ा सकते हैं। यह भूमि पुनर्चर्चण है। इस प्रयोजना को यदि दृढसंकल्प के साथ केन्द्र सरकार लागू करती है तो खदान एवं राखड़ हेतु भूमि उपयोग जो लाखों हेक्टेयर है। पुनः हमारे पास उपयोग हेतु उपलब्ध रहेगा। यह हमें खर्चों रुपये की अधिक लाभ एवं पर्यावरण हदिर से उपर्युक्त परियोजना साबित होगा। भूमि संसाधन के संरक्षण में यह एक अभूतपूर्व उठाया गया कदम साबित होगा।

### यह प्रकल्प क्यों ?

आज पर्यावरण प्रदूषण एक वृहत समस्या बन गई है। जल आकाश भूमि सभी में प्रदूषण चरम स्थिति में है। ऊर्जा की बढ़ती मांग एवं कोयला का उपयोग एक वृहत समस्या है। पॉवर प्लांट से निकलने वाला राख संधारण एक भयावह समस्या है। जिससे जमीन वायु प्रदूषण बढ़ते जा रहा है इसी परिपेक्ष्य में मैंने समस्या के निराकरण के लिये यह प्रोजेक्ट की कल्पना की।

आज पूरे भारत में ऊर्जा की मांग की देखते हुये पॉवर प्लांट की संख्या एवं कोयला उत्खनन के पश्चात् खदान की खोखली जमीन के रकबा में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत के 75 प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन तापीय है जिसका 90 प्रतिशत हिस्सा कोयला आधारित है। जिससे 300 मिलियटन प्रतिवर्ष राख निकलता है। और 125 मिलियटन प्रतिवर्ष राख निकलता है। ऊर्जा की बढ़ती मांग अनुरूप अगले 10 वर्षों में 1 लाख मूल उत्पादन वृद्धि से 175 मिलियटन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। इसके राखड़ बांध हेतु 1.4 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि चाहिए जो केरल जैसे राज्य के बराबर हरियाणा के तीन चौथाई हिस्सा एवं बिहार के दो तिहाई हिस्सा जैसा है साथ ही खदान का लाखों एकड़ भूमि खाली अनुपयोगी है। यदि पॉवर प्लांट से निकलने वाला राख समुचित संधारण न किया जाए तो राखड़ के रूप में भूमि का दुरुपयोग तो होगा ही, साथ ही पर्यावरण असंतुलित हो जावेगा। राखड़ बांध के पास दुर्घटना घटने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी घटना एन.टी.पी.सी. राखड़ धनरास में घटित हो चुकी है।

हमने यह परिकल्पना राखड़ बांध धनरास कोरबा के आसपास के अनुपयोगी एवं अनुपजाऊ भूमि एवं मानिकपुर कोरबा के खली खदान के खाली भूमि को देखने के उपरांत भूमि के संरक्षण हेतु बनाने का संकल्प किया।

यदि हमारी इस परिकल्पना को सरकार लागू करती है। तो राखड़ बांध होने वाले पर्यावरणीय नुकसान से बचाव के अतिरिक्त भूमि की बचत भविष्य के लिए कर सकेंगे। साथ ही अनुपयोगी पड़े भूखदान की भूमि पुनः उपयोग कर भूमि संरक्षित किया जा सकता है।

#### उद्देश्य :

1. समस्या का अध्ययन।
  2. क्षेत्र में भूमि के कमी के प्रमुख स्रोत।
  3. हम इसका अध्ययन दो भागों में करेंगे।
- प्रथम खंड में पॉवर प्लांट्स से संबंधित घटनाएँ, कारकों का अध्ययन करेंगे

#### (अ) कारक :

1. एन.टी.पी.सी. विद्युत मण्डल द्वारा निर्मित राखड़ डेम हेतु भूमि अधिग्रहण।
2. राखड़ बांध तक पहुंचाने हेतु पाइप लाइन में अधिग्रहीत भूमि।
3. राखड़ बांध में समीपस्थ खेत। जमीन का अनुपजाऊ, बंजर के कारण, अनुपयोगी भूमि।
4. राखड़ बांध से पर्यावरणीय प्रदूषण।

**(ब) समस्या का विवरण** – कारखानों से निकलने वाले राख को भण्डारित करने हेतु राखड़ बांध निर्माण किया गया है। जिससे निम्न समस्याएं आ रही हैं।

1. एन.टी.पी.सी./सी.एस.ई.बी. के राखड़ बांध हेतु अधिकाधिक भूमि का उपयोग किया गया है। कोरबा जिले में लगभग 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया गया है। जिसमें 9.13 मिलियन टन प्रति वर्ष अर्थात् 54 प्रतिशत उपयोग किया गया है। शेष 46 प्रतिशत राखड़ बांध में भेज दिया जाता है। जिसमें लिए अभी तक 704 हेक्टेयर भूमि का बांध बनाया जा चुका है।
2. बाल्को के पॉवर प्लांट द्वारा 10800 टन प्रतिदिन कोयला उपयोग होता है। जिससे 600 मीटर प्रति बांध राखड़ निकलता है।
3. राखड़ डेम में पाईपलाइन द्वारा राखड़ पहुंचाने हेतु अत्यधिक भूमि पर पाईप बिछाई गई है।

राखड़ बांध के अतिरिक्त आसपास की भूमि अधिकृत/अधिग्रहीत भूमि के अतिरिक्त भी पूरी तरह प्रभावित है। जहाँ राखड़ के बहाव एवं सिपेज के कारण भूमि को उर्वर शक्ति नष्ट हो रही है। फसल उत्पादन गिर रहा है। खेत दलदल हो रहे हैं।

सिपेज जल भूमि को वर्ष भर सुखने नहीं देता। जिससे खरपतवार, किट पनप रहे हैं। दलदली क्षेत्र के कारण मलेरिया का प्रकोप राख के कारण आंख, त्वचा, नाक संबंधी स्वास्थ्यगत समस्या।

राख में उपस्थित क्रिस्टलीय झिलिका ब्रोकाइटिस सिलिकोसिस कैंसर एस्थमा आदि का कारण।

पानी में ..... जैसे भारी तत्व राखड़ बांध के आसपास ट्युबवेल में पाया जाता है।

4. पाइप लाइन के ठीक से रखरखाव न होने से बी से खेत की हालत राखड़ बांध जैसे हो गए हैं।

#### अधिग्रहीत भूमि :-

एन.टी.पी.सी.	-	3648 एकड़
सी.एस.ई.बी.ईस्ट	-	3338 एकड़
सी.एस.ई.बी.वेस्ट	-	1465 एकड़
ए.एस.पी.एम.	-	1098 एकड़
सिर्फ राखड़ बांध हेतु	-	3036 हेक्टे.

एस.ई.सी.एल. खदान हेतु

कोरबा क्षेत्र	-	9045 एकड़
कुसमुंडा	-	847 एकड़
गेवरा	-	1198 एकड़ भूमि

कृषक प्रश्नावली सर्वे

किसानों के मध्य

एन.टी.पी.सी. के राखड़ बांध के भूमिहक किसानों के मध्य सर्वेक्षण किया गया। किसानों के मध्य उनके भूमि के उपजाऊ राखड़ के पर्यावरणीय प्रभाव आदि 14 प्रश्न की प्रश्नावली तैयार कर जवाब एकत्र किया गया। सर्वे रिपोर्ट फाइल के साथ संलग्न है।

#### 2. समस्याबोध की कहानी गणमान्य नागरिक एवं जनप्रतिनिधियों की जुबानी –

ग्राम धनरास (एन.टी.पी.सी. राखड़ बांध) के ग्राम धनरास के ग्राम सरपंच, सचिव, आंगन बाड़ी कार्यकर्ता, प्रधान पाठक, मंडी सदस्य आदि से चर्चा किया गया। चर्चा के दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र की राखड़ डेम उपजी समस्याओं के बारे में विस्तृत विवरण दिए। सरपंच महोदय ने दलदली क्षेत्र, मच्छर प्रकोप, उत्पादन क्षमता का आधी हो जाना एवं जल स्रोत का प्रदूषित होना प्रमुखता से बताया वही पूर्व मा.शाला धनरास के प्रधान पाठक द्वारा ग्रामीण बच्चों में मनोवैज्ञानिक स्तर में गिरावट, चिड़चिड़ापन का पाया जाना बताया। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जच्चा-बच्चा पर होने वाली व्यापक प्रभाव पर चर्चा करते हुए बच्चों उम्र के हिसाब में वजन में कमी को बताया। मंडी सदस्य द्वारा उत्पादन का आधा रह जाना बताया गया।

वंदना लिमिटेड के प्रो. श्री जी. भारिया द्वारा फसल का नष्ट होना, खेत का उपजाऊ क्षमता में कमी एवं राखड़ से होने वाली ग्रामीणों में विभिन्न प्रकार के बीमारियों के बारे में बताया। सार यह है कि राखड़ बांध से पर्यावरणीय एवं समाजिक व्यवस्था चरमरा गई है।

**ग्राम सर्वे (धनरास) का विश्लेषण का निष्कर्ष –** एन.टी.पी.सी. के राखड़ बांध धनरास कोरबा में राखड़ बांध के आसपास स्थित खेत के किसानों का सर्वे का निष्कर्ष यह निकलता है।

1. 100 प्रतिशत किसान सिर्फ धान की खेती करते हैं।
2. राखड़ बांध बनने के पूर्व एवं वर्तमान समय में उत्पादन धान में 2/3 की कमी आई है।
3. लगभग 97 प्रतिशत किसानों का मत है कि उत्पादन में कमी राखड़ के कारण आई है।
4. 100 प्रतिशत किसान राखड़ बांध से परीक्षण प्रदूषण एवं खेत की उर्वरा शक्ति में कमी को इंगित कर रहे हैं।
5. 90 प्रतिशत व्यक्तियों को राखड़ प्रभावित खेत में किस प्रकार फसल लेनी चाहिए इसकी जानकारी नहीं है।
6. 98 प्रतिशत किसानों का मौखिक सुझाव है कि राखड़ बांध नहीं बनना चाहिए।

**द्वितीय खण्ड –** समस्या के अध्ययन के द्वितीय खंड में कोयला खदान से कोयला उत्खनन पश्चात् खदान की खाली/खोखली के अनुपयोगी होने का अध्ययन किया।

**(अ) कारक :-** द्वारा खदान से कोयला उत्खनन पश्चात् एस.ई.सी.एल. खदान की मीन को ज्यों का त्यों छोड़ देने से भूमि का उपयोगहीन होना/जैसे कोरबा जिला का मानिकपुर खदान बलगी खदान, सुराकछार खदान से निकालने वाला धुल।

#### (ब) समस्या का विवरण :-

1. कोयला उत्खनन उपरांत खदान की भूमि का कोई उपयोग नहीं किया जाता जिससे हजारों एकड़ भूमि अनुपयोगी हो रहा है।
2. भूमिगत जलस्तर में कमी।
3. खदान के ऊपरी हिस्से पर दरार आने जैसी कई घटनाओं का होना जिससे व्यापक जन-जन की हानि होती है।
4. खोखली जमीन के कारण भूकम्प का क्षेत्र निर्मित होता है। वैसे भी कोरबा को भूकम्प के अंडर जोन में रखा गया है। भूधसान की घटना कभी भी घट सकती है एक बार बलुई क्षेत्र के आस-पास भूधसान की घटना घट चुकी है।

**THEORY OF PROJECT** - The engineering property of fly ash such as compressibility permeability capillary grain size strength make it suitable for its use as stowing on mine filling material fly ash possesses good load bearing capacity and has excellent flow characteristics fine escaping it no subsequent settlement has good water percolation rate load on barricade is very low so we use ash as a mine filling material.

**प्रयोजना क्रियाकलाप** - ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ राखड़ की मात्रा में बढ़ोतरी से राखड़ बांध हेतु लाखों एकड़ भूमि की बर्बादी एवं भू-खदान से कोयला उत्खनन पश्चात् पड़े भूमि हमें भविष्य में भूमि की उपलब्धता हेतु प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। इसके समाधान हेतु निम्न उपयोग क्रियान्वित की जा सकती है।

1. सर्वप्रथम खाली खदानों में पावर प्लांट से निकली राख को पानी मिलाकर भरा जावे।
2. जब भू सतह से खदान की गहराई 25 मी. के आसपास रह जावे तो उसमें एल्युमिना प्लांट से निकली व्यर्थ पदार्थ एवं चूना पत्थर (पत्थर खदान का अनुपयोगी चूना पत्थर) और राखड़ को डाला जावे। जिसमें पानी की कुहार भेजी जावे। यह फिलिंग लगभग 15 मीटर मोटाई तक की जावे जिससे 15 मी. का यह भाग स्टे सिमेंट से पत्थर जैसा कड़ा हो जावेगा। जिससे भूगर्भ हो जावेगी।
3. भू सतह से खदान की गहराई लगभग 10 मी. रह जावे। तो उसने मिट्टी (भू-मण्डल का) बाह्य परत। डालनी होगी। इसमें पानी की कुहार डालनी होगी। इस प्रकार खोखली खदान समतल भूमि जैसा बनकर तैयार हो जावेगा।

**क्रियान्वित योजना हेतु सामाग्री उपलब्धता :**

1. **राखड़ :-** कोल बेस पॉवर प्लांट जैसे एन.टी.पी.सी./सी.एस.ई.बी./बाल्को एवं अन्य प्राइवेट कंपनी से निकलने वाला राख।
2. **धातुमल :-** बाल्को स्टा र लाईट कोरबा से निकली हुई स्टेज।
3. **चूना पत्थर :-** चूने की खदान से कम मात्रा में चूने वाले अनुपयोगी पत्थर।
4. **जल :-** बांगो बांध से आने वाला पानी।
5. **मिट्टी :-** खदान प्रारंभ के समय की बाह्य परत की मिट्टी (भंडारित) पृष्ठ मृदा

**क्रियान्वित परियोजना से संरक्षित भूमि का उपयोग :**

1. वृक्षारोपण (खासकर कम गहरे जड़ वाले वृक्ष व्यास फुल वाले)
2. विभिन्न फसल उत्पादन
3. सब्जी उत्पादन
4. खेल के मैदान का निर्माण
5. मनोरंजन पार्क/गार्डन/फूलवारी निर्माण

6. चारागाह निर्माण
7. सैन्य प्रशिक्षण शिविर
8. फूलों की खेती (खासकर काटेदार)

**प्रथम प्रयोग :-**

**स्थल** - विद्यालय के मैदान का एक कोना अवधि- 35 दिवस

**प्रयोग -**

1. इसके लिए 4315 फीट का गद्दा खोदा।
2. गद्दे के 10 फीट तक हमने राखड़ भर दिया
3. दो दिवस तक पानी देने के उपरांत सिमेंट को 3 फीट तक भरा। दो दिवस तक उसमें पानी दिया गया।
4. इसके ऊपर दो फीट अर्थात् पृथ्वी की सतह तक हमने मिट्टी डाली। पुनः दो दिवस तक पानी दिया।
5. तत्पश्चात् उसे लकड़ी के पट्टे से बार बार पीटा। बड़े पैमाने पर रोड रोलर का प्रयोग कर सकते हैं।
6. फिर उस मिट्टी में गेंदा का पौधा लगाया एवं कुछ दूर पर अन्य जगह पर पौधा लगाया।
7. तीस दिवस उपरांत गद्दे के पौधे एवं अन्य स्थल के पौधे का अध्ययन किया।

**2. द्वितीय प्रयोग**

**स्थल** - प्रयोगशाला कक्ष (विद्यालय परिसर)

**अवधि - 15 दिवस**

**प्रयोग** - एक प्लास्टिक को पन्नी जिसकी ऊंचाई 15 सेमी एवं त्रिज्या 3 सेमी लिया। इसमें 10 सेमी ऊंचाई तक राखड़ भरा। उसमें हल्का पानी मिलाकर धुप में 2-3 घंटे सुखाया सुखने उपरांत 3 सेमी तक सीमेंट 2 डाला। दो दिवस तक उसमें पानी दिया। पानी सूख जाने पर इसमें 2 सेमी मिट्टी की पर्ब बिछाई। इसमें पानी की कुहार डालकर दबाया गया एवं घास रोपित किया गया। 10 दिवस उपरांत प्लास्टिक को काड़ा तो पूरा हिस्सा एक कठोर गिलास आकृति ले चुका था।

**3. प्रयोग क्र. 3**

**स्थल** - राखड़ बांध धनरास के आसपास का क्षेत्र (खेत)

**अवधि - 02 माह**

**प्रयोग** - राखड़ बांध धनरास के कुछ-कुछ दूरी पर हमने सामान्य फसल धान लगाया। निम्न दूरी पर हमने फसल लगाया।

1. राखड़ बांध से लगा हुआ खेत में।
2. राखड़ बांध में 500 मी. की दूरी पर स्थित खेत।
3. राखड़ बांध से 1000 मी. की दूरी पर स्थित खेत।
4. राखड़ बांध से 1500 मी. की दूरी पर स्थित खेत।
5. राखड़ बांध से 2000 मी. की दूरी पर स्थित खेत।

फसल लगाने के 2 माह पश्चात् हमने धान की फसल का अवलोकन कर उसका छायाचित्र लिया।

**अवलोकन :-**

अबजर्वेशन टेबल

क्र.	राखड़ बांध से खेत की दूरी	2 माह पश्चात् फसल की स्थिति	उत्पादन क्षमता की स्थिति
1	0 मीटर (लगी हुई)	नहीं के बराबर पौधे में वृद्धि	अति निम्न
2	500 मीटर	नहीं के बराबर पौधों में वृद्धि नहीं	अति निम्न



3	1000 मीटर	सामान्य से कम वृद्धि लेकिन फसल प्राप्ति	निम्न/मध्यम
4	1500 मीटर	लगभग सामान्य वृद्धि	ऊर्वरा भूमि की तुलना में 1/2 भाग उत्पादन
5	2000 मीटर	अच्छी फसल	क्षेत्रानुरूप अच्छी उत्पादन

#### प्रयोग क्र. 4

**स्थल** - धनरास ग्राम का एक खेत

**अवधि** - 2 माह

**प्रयोग** - हमने एक खेत में एक ट्रेक्टर राख डाला। फिर एक सप्ताह तक उसे खेत में पड़ा रहने दिया। एक दिन उसमें पानी भी डाला। एक सप्ताह पश्चात् हमने राखड़ को पूरी तरह हटा लिया। तत्पश्चात् खेत की जुताई कर हमने धान का फसल लगाया। 2 माह पश्चात् हमने अवलोकन किया।

**अवलोकन** - खेत एवं फसल के अवलोकन पश्चात् देखा कि एक बार अत्यधिक राखड़ खेत में पड़ने के पश्चात् खेत की उर्वराशक्ति समाप्त हो जाता है एवं भूमि जली जैसी हो जाती है एवं फसल उत्पादन लगभग नहीं के बराबर होता है। सिर्फ घासफूस की पैदावार होती है। अर्थात् खेत बंजर हो जाता है।

#### प्रयोग क्र. 5

**स्थल** - स्कूल मैदान

**अवधि** - 1 माह

**प्रयोग** - हमने 10 बोरी राखड़ को स्कूल मैदान के एक किनारे पर रख दिया। उसी के बगल में एक क्यारी बनाई जिसमें धनियापत्ती का बीज बो दिया। जुलाई माह में बारिश के कारण धीरे-धीरे राखड़ का कुछ हिस्सा क्यारी में जाने लगा। बारिश के कारण बिना तत्बंध के राखड़ क्यारी में फैलकर उसे बंजर बना दिया। इस प्रकार हमने पाया यदि राखड़ बांध का तत्बंध ठीक से नहीं है या टूट जाए तो आसपास की पूरी भूमि बंजर बन जावेगी।

इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने धनरास में पाया जिसका छायाचित्र संलग्न है।

**प्रयोग का निष्कर्ष** - हमारे द्वारा किये गए पांच प्रयोगों के पश्चात् प्राप्त परिणाम से हमने यह निष्कर्ष निकाला

1. प्रथम प्रयोग के आधार पर हमने पया कि सामान्य भूमि एवं गड्ढे के ऊपर उप चरित भूमि पर गेंदा पौधा की विकास दर गुण सभी समान है। अर्थात् प्रयोग अनुरूप हम भूमिगत एवं ऊपरी खदान की खोखली भूमि पर राखड़ एवं स्टेज सीमेंट द्वारा उपचारित करें। जो प्राप्त भूमि साधारण भूमि जैसी स्थिति प्राप्त होगी अर्थात् उसमें वृक्षारोपण /खेती/ उद्यान/सब्जी उत्पादन/फलदार वृक्ष /काटेदार वृक्ष आदि आसानी से लगाकर भूमि का सदुपयोग कर सकते हैं।
2. हिनीय प्रयोग में प्राप्त आकृति को साधारणतः पत्कने या पीटने से उसमें कठोरता बनी ही रहती है। अतः यदि खदान में इस प्रकार का प्रयोग किया जाए तो दलदली भूमि न पाकर एक ठोस भूपर्पटी भूमि प्राप्त होती जिसका उपयोग किसी भी रूप में नगरीकरण/उद्यान/खेत मैदान कर सकते हैं।
3. तृतीय प्रयोग से यह निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि राखड़ बांध से करीब 2किमी त्रिज्या क्षेत्रफल में खेत की उत्पादन क्षमता कम होती है। इसके बाद ही इसका प्रभाव समाप्त होता है।
4. चतुर्थ प्रयोग के अनुसार एक बार यदि मिट्टी (जमीन) पर राखड़ बहुत दिनों तक पड़ा रहे, तो उसको निकल जाने के पश्चात् भी वह सामान्य उपजाऊ भूमि जैसा नहीं रह पाता। उसकी पृष्ठमृदा बंजर हो जाती है।

5. पाँचवें प्रयोग में हमने देखा कि बिना मजबूत तत्बंध के यदि राखड़ ऐम्पींग की जाए तो उसके भयानक परिणाम आसपास के जमीन/खेत पर पड़ते हैं। बरसाती पानी में बहकर राखड़ पूरे क्षेत्र को बंजर बना सकती है।

#### क्रियान्वित योजना के लाभ :

1. **भूमि के स्रोत में वृद्धि :-** भूमिगत एवं खुली खदान की खाली जमीन राखड़ बांधा एवं उसके पाइप लाइन के लिए उपयोग की जा रही भूमि जो वर्तमान समय में लाखों एकड़ है। पुनः हमारे पास उपलब्ध रहेगी। जिससे भविष्य के लिए हमारे पास भूमि की जरूरत पूरी करेगी।
2. पाँवर प्लांट, कोयला खदान, एलुमिना प्लांट के व्यर्थ पदार्थ के संधारण की समस्या से मुक्ति कोरबा जैसे जिले में इस प्रयोजना से एन.टी.पी.सी./सी.एस.ई.बी./एस.ई.सी.एल. एवं बाल्को स्टाईट ग्रुप जैसे बड़े-बड़े कम्पनियों की अपने वेस्ट मटेरियल की साधारण समस्या दूर हो जावेगी। जो इनके लिए अब तक सबसे बड़ा सिर दर्द बना हुआ है।
3. **आर्थिक लाभ :-** चूंकि भूमि सीमित है एवं इसकी मांग अनंत इसकी कीमत आसमान छू रही है। स्वरूप प्राप्त भूमि का बाजार मूल्य का सांकलन किया जावे तो खरबों रुपये होगी। वही इन फैक्ट्रीयों द्वारा अपने वेस्ट मटेरियल के संधारण हेतु खरबों रुपये खर्च करना पड़ता है। यदि ये खर्च घटा दिए जाए तो उनके शुद्ध लाभ में कई गुना वृद्धि हो जावेगी। फसल उत्पादन एवं अन्य कार्य से भूमि से बहुत अधिक आर्थिक लाभ कंपनियों का होगा।
4. **राखड़ से होने वाला पर्यावरणीय क्षति एवं भूमि की बंजरता से मुक्ति :-** राखड़ भूमिगत चले जाने से यह वायु मण्डल में नहीं जा पायेगा। जिससे पर्यावरण संरक्षित रहेगा। राखड़ बांध के आस-पास की भूमि बंजर होने से बच जावेगी। जिससे भूमि की उत्पादन क्षमता पूर्ववत् बनी रहेगी।
5. **स्वास्थ्यगत लाभ :-** कहा जाता है , स्वस्थ नागरिक ही राष्ट्र के विकास का प्रमुख आधार है। राखड़ बांध के आसपास फैलने वाली बीमारी आंख, त्वचा, नाम, गला, संबंधी बीमारी ब्रोकाइटिस, सिलिकोसिस, कैंसर, दमा, मलेरिया आदि से ग्रामीणों को राहत रहेगी। जिससे नागरिक स्वस्थ रहकर एक सबल एवं विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पायेंगे।
6. **समाजिक परिपेक्ष्य में भू-विस्थापन से मुक्ति :-** हमारे देश में भावुकता बहुत अधिक पायी जाती है। जिससे हम अपने समाज ग्राम पुस्तैनी जायदाद खेत एवं पर्यावरण से प्यार एवं पूजा करते हैं। कोई भी व्यक्ति इससे विलग होना नहीं चाहता। राखड़ बांध जैसे प्रोजेक्ट के लिए इन्हे भूविस्थापित कर दिया जाता है। जिससे इनको छुटकारा मिल जावेगा।
7. जल स्तर में वृद्धि एवं पर्यावरणीय सुरक्षा।
8. भूकम्प, भूस्खलन, खदान घसने की घटना से छुटकारा।
9. ऐश ऐपिंग स्पेस न होने से पाँवर प्लांट के चालू यूनिट बंद हो जा रहे हैं। जिसका असर वित्त पर पड़ता है, उससे छुटकारा।

#### समस्या के सामाधान हेतु सुझाई गई व्यवस्था/सामाग्री :

1. हमारे द्वारा सुझाई गई युक्ति से भूमि की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है।
2. इससे केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों को विभिन्न कम्पनियों में आपसी ताल-मेल एवं समन्वय स्थापित करने का कार्य करना होगा।

3. निजी कम्पनियों के लिए पर्यावरण मापदंड एवं रख-रखाव के कड़े नियमों को पालन करना होगा।
4. राख उत्पादन वाले प्लांटों को इसका उपयोग के लिए ग्रामीणों की कार्य शाला में प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता एवं प्रोत्साहन देने चाहिए, एवं इसका प्रचार प्रसार सीमित न रखकर गांव-गांव पहुंचना होगा।
5. गांवों में भूमि की मिट्टी (उपजाऊ) से ईट निर्माण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए इसे गैर कानूनी कार्य घोषित करनी होगी जिससे उपजाऊ मिट्टी संरक्षित रह सके।
6. वर्तमान में उपयोग में जाए जा रहे राख डेम से राख को पुनः खदान में लाकर राख बांधा की भूमि को उपचारित कर उसे सामान्य भूमि जैसे उपयोगी बनाना होगा।
7. ग्राम पंचायतों एवं नागरिकों को राख ईट निर्मित मकान बनाने हेतु प्रेरित करना होगा।
8. सीमेंट उत्पादन में अभी तक 25 प्रतिशत कुल राख का ही उपयोग किया जाता है इसकी मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। अतः पी.पी.सी.सीमेंट के निर्माण को प्राथमिकता देनी होगी। क्योंकि पी.पी.सी. सीमेंट में राख की मात्रा ज्यादा रहती है।
9. खुली खदान प्रारंभ करते समय भूमि की बाह्य परत की मिट्टी को संरक्षित करके रखना चाहिए ताकि हमारी इस प्रयोजना जैसे क लिए वह उपयोग की जा सके।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध एवं प्रयोग के आधार पर।

\*\*\*\*\*

## परम्पराएँ संगीत के धनी हो समुदाय के नारियाँ

ज्योति रानी सिंकु \*

**प्रस्तावना** - 'हो' का शाब्दिक अर्थ है- 'मानव' या 'मनुष्य' ! 'हो' उनकी भाषा है, उपजाति - 'हो' है। सृष्टि काल से सृजनात्मक प्रक्रिया में मानव जाति को सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। प्रकृति के नियमानुसार प्राणी विशेष को दो जाति में विभक्त किया गया है, नर और नारी। इस संदर्भ में नर स्थायी है और नारी अस्थायी। जैसा कि हम आदिवासी जनजाति हो कोलों में कहते हैं - 'कोड़ा होन बो जांड बिति-कुड़ी होन बो पेटे:ए बिति' तात्पर्य यह है कि नर जाति बीच रूप है और नारी जाति बीच को अपुष्ट रूप है। इससे अनुमान किया जाता है कि नर को बीच बोलने, बीज रोपने को अधिकार है और नारी को बीज को बीच धारण करने का अधिकार है। इसलिए जमीन पर बीच रोपने को प्रथम स्थान नर को ही प्राप्त है और नारी उसका संरक्षण करती है।

हो जन जीवन में संगीत का महत्व, भला कौन नहीं जानता ? हो परम्परा संगीत को जवन का प्रमू दर्शन कहा जाता है क्योंकि कहा भी गया है सेनगे सुसुन, कजिगे दुरड अर्थात कहा जा सकता है कि इनके जीवन में संगीत का कितना महत्व है। संगीत के माध्यम से ये अपने सुख-दुख को एक दूसरे से बंटते हैं आनंदवर्धन होकर अपने सारे दुख तकलीफ को भूला कर ये संगीत के माध्यम से जीवन को रसमय, आनंदमय बनाते हैं। संगीत मानव मन की कोमल अनुभूतियाँ हैं मनुष्य विरह बेदना में गाता है, खुशी से गाता है, जीवन के संस्कार बिना संगीत के बिना गीत के संभव नहीं हैं। जब हम हो नारियों की बात करते हैं, इनके संस्कृति की बात करते हैं तो पाते हैं कि इन आदिवासियों का जीवन, गीत, संगीत, नृत्य के बिना खोखला सा जान पड़ता है। संगीत इनके जीवन को गतिमान बनाता है। इन्हें पूर्णता प्रदान पहाड़ी नदियों को हंकार मारते हुए अग्रसर होना, जंगलों में पक्षियों के चहकती कलराव, जंगल में डरावने जंगली जानवरों के आवाज, फूलों पत्तियों से सजे, एवं मधुमक्खियों की गुनगुनाहट से जीवन को सरलता बनाने की प्रेरण मिलती है

गीतों में हम देखते हैं कि ये ही जीव-जन्तु उपमा के रूप में बार-बार आये हैं। इनके गीतों की संख्या असंख्या है, जो कि मौखिक परंपरा से अर्थात् माता से पुत्री एवम् पिता से पुत्र में आदि काल से मौखिक रूप से चले आ रहे हैं, और अब भी इनके बीच में ये परंपरा जीवित है।

शायद ही ऐसी कोई हो नारियों के कंठों में प्रकृति से जुड़े गीत-संगीत ना हो, जो कि हमेशा उनके कंठों से प्रस्फुटित होते रहते हैं संगीत के माध्यम से युवक-युवतियों अपने लोक गीतों को अखड़ों में सरल कंठ से गाते हुए दिखाई देते हैं। नृत्य के अखाड़ों में मस्त वातावरण में नये-नये गीत गाये और सीखे जाते हैं। गीतों के कुछ पंक्तियों भूल भी जाए परंतु जब फिर से अखाड़े में गाजे-बाजे के साथ आते हैं तो स्वतः ही वो पंक्तियों स्मरण में आ

जाती है इनमें गीतों को लिखने की परम्परा नहीं दिखती। अपने गीतों को पीढ़ी-दर पीढ़ी सिखते चले जाते हैं।

**निवास स्थल** :- हो के प्राचीन निवास स्थल के संबंधों में पहली जानकारी इनकी लोक कथा, लोक गीतों एवं पारंपरिक ऐतिहासिक मिथकों एवं आख्यानों में मिलता है। हो की सृष्टि कथा में गुरुओं द्वारा और लोक गीतों में इस प्रकार वर्णित है :-

आले गो दोले गोरीब तना -2

बिन्दी तेले कुटा तडा,

गांगई सेनोयोर -2

आपे ना दोपे मुण्डा गो तना

आपे दोपे नाई की तना

मेइ तेपे कुन्टा तडा -2

ओव: तापे जहाज लेका

रचा तापे सेलाटी लेका।

निमिन बुगिं रचा रेय: तापे बा: पे दुकान काड

किरिड पे रेयो कोपे एमे

खिड़की होरा: ले बोलोव: तापे बा: ले गोसोया -2

**अर्थात्** -ए सुन्दरी ! हम लोग गरीब है, मकई के लकड़ी से कुटा बनाये है। ऐ कुंआरी कन्या आप लोग तो मुण्डा घर के है, बहुत अमीर लोग है, लोहा के छड़ से घर बनाये है आप लोग का घर तो जहाज के तरह है। अंगन चिकना पत्थर से बनाये है, इतना अच्छा अंगन में आप लोग फूल का दुकान है, खरीदने से भी आप लोग नहीं देते हैं हम लोग खिड़की से धुस जाएगे और फूल मुरझा देंगे।

मुनु तंताड तेकी -2

सिदे तंताड तेकी -2

बुरु कोचा रेकी ओव: लेड़ा -2

बुरु कोचा रेकी बास तड़ा

कुला भालु को बोरो तेकी सेब षड़ा केना

देषउलि रे किड वोंगा को की: सेबा-षड़ा केना।

**अर्थात्** - हे सृष्टि दाता दोनो आप दोनों जंगल के किनारे आप दोनों घर बनाये है, और जंगल के किनारे वास गाये है, जंगल के जानवरों की डर से आप दोनों ने प्रकृति की पूजा-पाठ करना शुरूआत किए। और देशउलि में सिंहावोंगा की प्रकृति पूजा-पाठ किए।

1942 ई में 'हो दुरं डब्लू.जी' आचार्य द्वारा प्रकाशित हुई की कविता देवनगरी लिपि में इसकी लोक प्रियता का अहसास बूढ़े से अवसर कहने और ससने को मिलती है। इसके बाद अन्य कवितों ने भी समय-समय पर

अपनी अपनी गीतों के माध्यम से हो संगीत को लोक प्रिये बनाने में अपना योगदान देते आये हैं।

इस तरह से हम कह सकते हैं कि हो लोक गीतों का एक बहुत बड़ा भाग अभी भी छुटा हुआ है। जो कि हमारे सूदुर ग्रामीण इलाकों में बसने वाले हो युवक युवतियों के कंठों में आज भी जीवित हैं। इन लोक गीतों को सहेजने की आवश्यकता है, इन्हें लिखित रूप में प्रकाशित करने की अति आवश्यक है। जिससे की हो जन जीवन में मधुर संगीत के महत्व को भांलि-भांति समझा जा सके, और वर्षों तक इनके मधुर स्वर को जीवित रखने का अभियान

चलता रहे।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आदिवासी शोध पत्रिका (संत जेवियर्स कॉलेज, ट्राइबल रिसर्च सेन्टर रांची झारखण्ड द्वारा प्रकाशित)
2. हो दुरं 1942 डब्लू.जी. आर्चर
3. हो भाषा और साहित्य का इतिहास (डॉ. आदित्य प्रसाद सिन्हा)
4. हो भाषा साहित्य: एक संक्षिप्त परिचय (आदिकाल से अब तक) गुरु चरण पुरती

\*\*\*\*\*



## शारीरिक रूप से सामान्य एवं दिव्यांग (मूक-बधिर) विद्यार्थियों की सृजनात्मकता : एक तुलनात्मक अध्ययन

विनिता पालीवाल\*

**प्रस्तावना** - भारतीय दर्शन के अनुसार हम सभी प्राणी सर्व शक्तिमान परमात्मा के अंश हैं इसलिये हम सबमें सृजनात्मक योग्यता विद्यमान है। किसी में उच्च स्तर की सृजनात्मकता है तो किसी में निम्न स्तर की। किन्हीं व्यक्तियों में सृजनात्मकता का गुण प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध कार्य में शारीरिक रूप से सामान्य तथा दिव्यांग विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का अध्ययन किया गया है। अतः शोध कार्य के आरम्भ से पूर्व सृजनात्मकता एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के बारे में जानना आवश्यक है। यह जानना आवश्यक है कि सृजनात्मकता क्या है तथा दिव्यांग विद्यार्थी कौनसे होते हैं? तथा क्या ये बालक सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं?

मानव ईश्वर द्वारा रचित सबसे अद्भूत रचना है। उसमें भी बालक ईश्वर की सबसे मूल्यवान कृति है। संसार में कुछ बालकों में शारीरिक अक्षमताएं पाई जाती हैं, जिन्हें सामान्यतः विकलांग कहा जाता है परन्तु असल में वे विकलांग नहीं दिव्यांग होते हैं, जिनमें कुछ विशेष प्रतिभा होती है। यह बात हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रम 'मन की बात' में कही क्योंकि उनके पास एक अतिरिक्त शक्ति होती है।<sup>1</sup>

**क्रू शैंक** ने विशिष्ट बालकों को परिभाषित करते हुए बताया है कि 'एक विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक, शैक्षिक, संवेगात्मक, सामाजिक रूप से, सामान्य बुद्धि एवं विकास से इतना स्पष्ट रूप से विचलित होता है कि नियमित कार्यक्रमों से लाभान्वित नहीं हो सकता तथा जिसे विद्यालय में विशिष्ट देखरेख की आवश्यकता होती है।

अर्थात् विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं यह भिन्नता शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक इत्यादि किसी भी क्षेत्र में हो सकती है।

विभिन्न आयोगों ने दिव्यांग विद्यार्थियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें कही हैं :-**कोटारी आयोग (1964-66)** ने भी इस बात पर बल दिया कि विकलांग शिक्षा, शिक्षा नीति का अभिन्न अंग है।

**शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति (1968)** में यह सुझाव दिया गया है कि जहाँ तक सम्भव हो विशिष्ट बालकों को सामान्य विद्यालयों में ही रखा जाए। **राममूर्ति कमेटी (1992)**, मन्दबुद्धि बालकों के विकास हेतु इस कमेटी का गठन किया गया। इसका उद्देश्य ऐसे बालकों के शैक्षिक विकास तथा भारतीय प्रशासन द्वारा निर्धारित शिक्षानीति के कार्यों को सम्पन्न करने तथा नीतियों की समीक्षा देना था।

शोधार्थी द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों के अन्तर्गत मूक-बधिर विद्यार्थियों का चयन किया गया है। मूक-बधिर बालक वे होते हैं जो अपने जीवन के प्रारम्भिक 2 या 3 वर्षों में सुनने व बोलने में असमर्थ होते हैं। यह किसी भी

जन्मजात या वातावरण संबंधी कारक के कारण हो सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इनमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावात्मक रूप से दिव्यांग बच्चे भी सम्मिलित हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि बालकों में कुछ विशेष क्षेत्रों में जैसे - गायन, शिक्षा, चित्रकला, नृत्य आदि में विशेष प्रतिभा होती है तथा इन्हीं गुणों के साथ-साथ सृजनात्मकता भी पाई जाती है।

सामान्यतः सृजनात्मकता शब्द का प्रयोग मनुष्य की विशिष्ट योग्यता के लिए किया जाता है, किसी भी कार्य की यह विशिष्ट योग्यता दर्शक के पूर्व अनुभव पर निर्भर करती है कभी-कभी जिसे हम सृजनशील मानते हैं वह केवल औरों से अलग होता है सृजनात्मक व्यक्ति की मौलिकता नियत होती है जो व्यक्ति एक लम्बे समय तक विशिष्ट तथा मौलिकता प्रदर्शित करें उसे सृजनात्मक व्यक्ति कह सकते हैं।

**फ्रायड** के अनुसार, 'सृजनात्मकता अचेतन मन के अन्तर्द्वन्द्वों का परिणाम ही कभी न कभी अचेतन मन से द्वन्द्वों का उचित समाधान ढूँढने में सफल हो जाता है।'।

इसी संबंध में **बारहेट** लिखते हैं कि 'सृजनात्मकता से तात्पर्य है साहसिकता से सोचना सीधे मार्ग से हटकर चलना रूचि अथवा रूचि को तोड़ देना, अनुभव के लिए तैयार होना और एक के बाद दूसरे की ओर अग्रसर होना।'

सृजनात्मकता का यह गुण सभी बालकों में पाया जाता है, परन्तु इस गुण की अधिकता दिव्यांग अथवा सामान्य छात्रों में अधिक पाई जाती है, इसी जिज्ञासावश शोधार्थी द्वारा उक्त विषय का चयन किया गया।

**समस्या कथन - 'शारीरिक रूप से सामान्य एवं दिव्यांग (मूक-बधिर) विद्यार्थियों की सृजनात्मकता : एक तुलनात्मक अध्ययन।'**

**शोध प्रश्न :**

1. शारीरिक रूप से सामान्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का स्तर क्या है?
2. दिव्यांग विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का स्तर क्या है?
3. शारीरिक रूप से सामान्य तथा दिव्यांग विद्यार्थियों की सृजनात्मकता में अन्तर होता है?
4. दिव्यांग विद्यार्थी शारीरिक रूप से सामान्य विद्यार्थियों से अधिक सृजनात्मक होते हैं?
5. दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं की सृजनात्मकता में कोई अन्तर है?
6. शारीरिक रूप से सामान्य छात्र व छात्राओं की सृजनात्मकता में कोई अन्तर है?

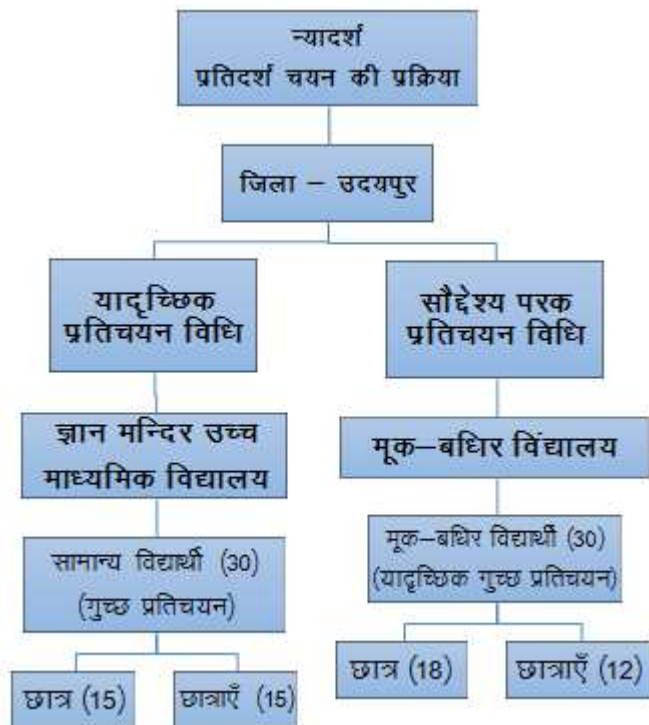
**शोध के उद्देश्य** – माध्यमिक स्तर पर शारीरिक रूप से सामान्य तथा दिव्यांग (मूक-बधिर) विद्यार्थियों की सृजनात्मकता (विस्तार, मौलिकता व कुल सृजनात्मकता) का अध्ययन करना।

1. दिव्यांग छात्र व छात्राओं की सृजनात्मकता का अध्ययन करना।
2. शारीरिक रूप से सामान्य छात्र व छात्राओं की सृजनात्मकता का अध्ययन करना।
3. दिव्यांग छात्र व छात्राओं की सृजनात्मकता की तुलना करना।
4. शारीरिक रूप से सामान्य छात्र व छात्राओं की सृजनात्मकता की तुलना करना।
5. शारीरिक रूप से सामान्य तथा दिव्यांग (मूक-बधिर) विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

**शोध अध्ययन की परिकल्पना :**

1. माध्यमिक स्तर पर शारीरिक रूप से सामान्य तथा दिव्यांग (मूक-बधिर) विद्यार्थियों की सृजनात्मकता (विस्तार व मौलिकता घटक) में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. दिव्यांग छात्र व छात्राओं की सृजनात्मकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. शारीरिक रूप से सामान्य छात्र व छात्राओं की सृजनात्मकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

**शोध समस्या का न्यादर्श :-**



**अनुसंधान विधि :-** सर्वेक्षण विधि

**उपकरण :-** डॉ. बाकर मेहंदी के मानकीकृत परीक्षण सृजनात्मक चिंतन परीक्षण

**शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी प्रविधियाँ :-**

- टी-स्कोर :-

$$T\text{-Score} = \frac{S.D. (X-M)}{10} + 50$$

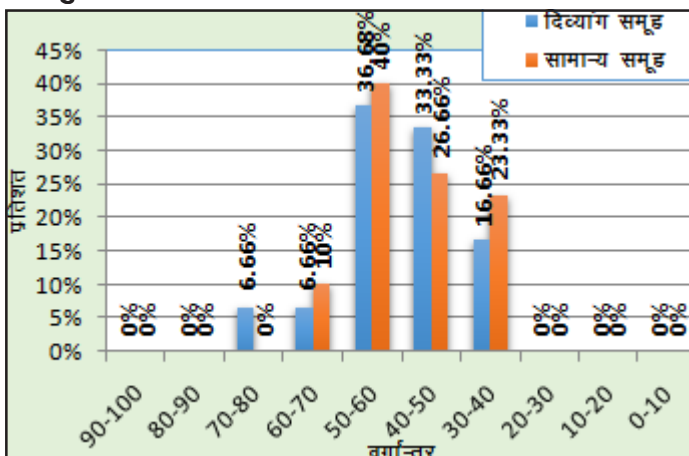
$$\text{मध्यमान} = \frac{\sum x}{n}$$

$$\text{मानक विचलन} = \sqrt{\frac{\sum d^2}{N}}$$

$$\text{टी परीक्षण} = \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{\frac{SD_1^2}{N_1} + \frac{SD_2^2}{N_2}}}$$

**दत्त विश्लेषण की प्रक्रिया**

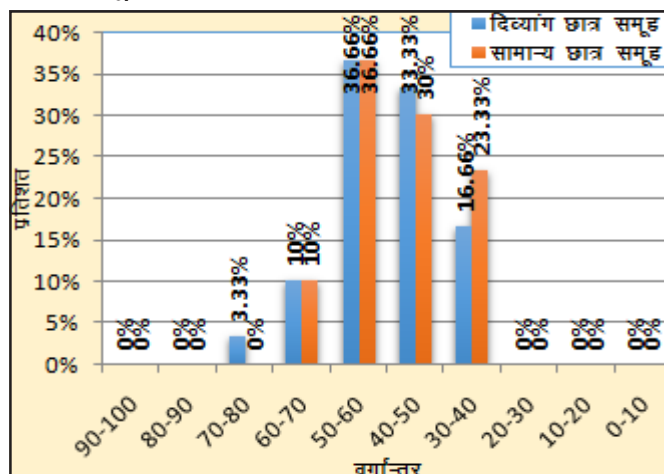
**शारीरिक रूप से सामान्य तथा दिव्यांग विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।**



विस्तार क्षेत्र के दिव्यांग (मूक-बधिर) तथा सामान्य छात्रों के सृजनात्मक चिन्तन फलान्क:-

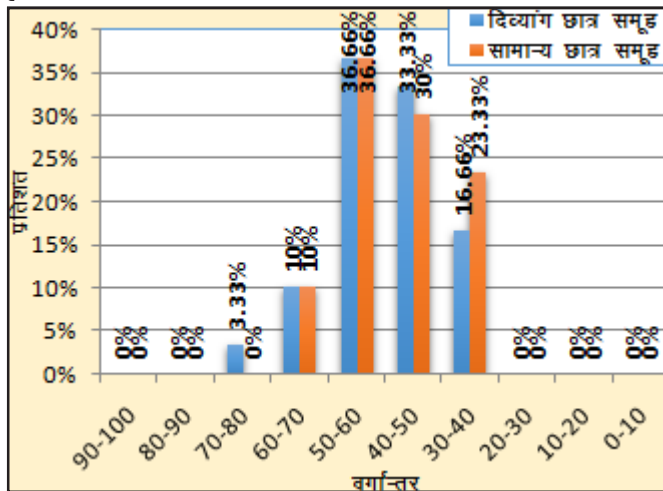
ग्राफ से यह प्रदर्शित होता है कि दोनों समूहों में औसत स्तर के छात्र तो है परन्तु उच्च स्तर के छात्र केवल दिव्यांग छात्रों के समूह में है। अतः दिव्यांग समूह वाला ग्राफ निश्चित रूप से उच्च फलान्कों की ओर है जो दिव्यांग छात्रों के सामान्य छात्रों की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है।

**दिव्यांग (मूक-बधिर) तथा सामान्य छात्रों के मौलिकता फलान्क:-**



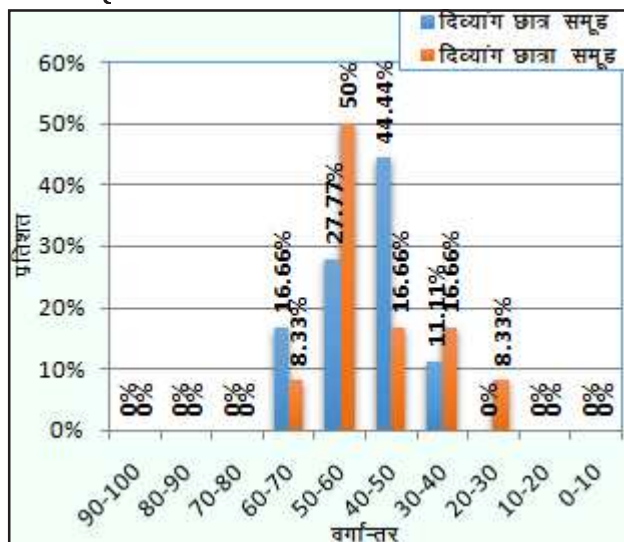
ग्राफ से यह प्रदर्शित होता है कि उच्च स्तर के छात्र केवल दिव्यांग छात्रों के समूह में हैं। अतः इस कारण दिव्यांग व सामान्य छात्रों में दिव्यांग छात्रों के फलांक स्पष्ट रूप से उच्च फलांकों की ओर है, जबकि सामान्य छात्रों से प्राप्त फलांक का बहुभुज औसत फलांकों की ओर दर्शाता है

### दिव्यांग (मूक-बधिर) तथा सामान्य छात्रों के सम्पूर्ण अशाब्दिक सृजनात्मकता के फलांक



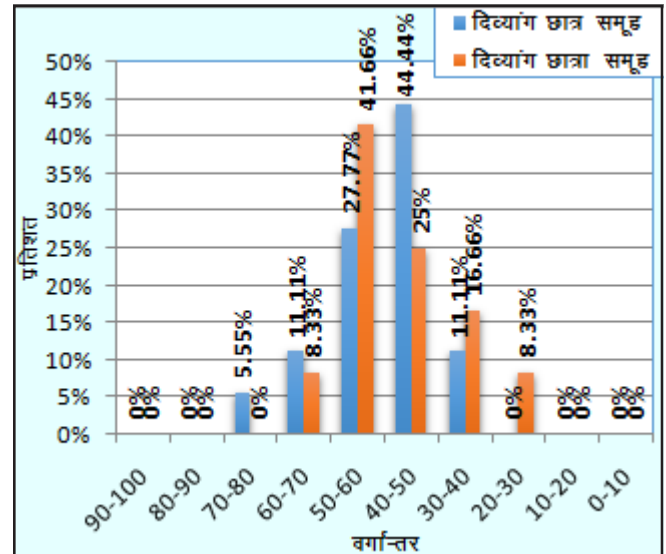
सृजनात्मकता के दो क्षेत्र-विस्तार एवं मौलिकता तथा सम्पूर्ण फलांकों का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अशाब्दिक सृजनात्मक चिन्तन परीक्षण में दिव्यांग छात्र शारीरिक रूप से सामान्य छात्रों की अपेक्षा उच्च सृजनात्मक हैं।

### विस्तार घटक के दिव्यांग (मूक-बधिर) छात्र एवं छात्राओं के अशाब्दिक सृजनात्मक चिन्तन फलांक :-



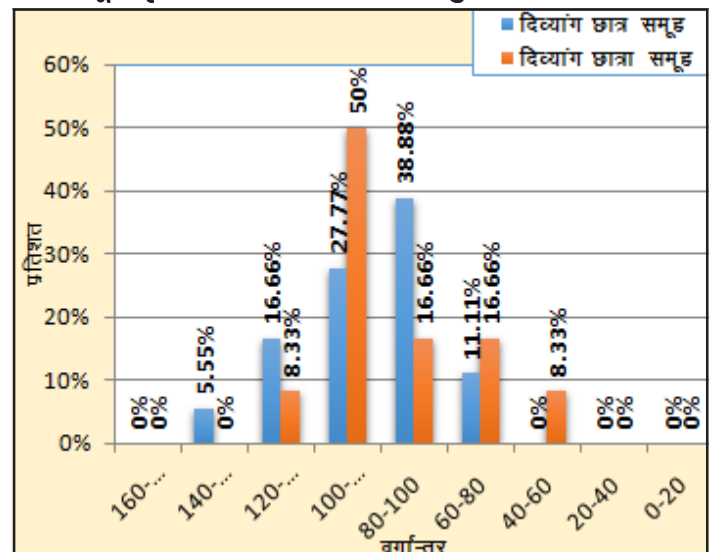
दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं द्वारा प्राप्त विस्तार फलांकों के ग्राफ से यह प्रदर्शित होता है कि दोनों समूहों में औसत स्तर के विद्यार्थी हैं तथा छात्राओं के समूह में निम्न स्तर पर केवल एक छात्रा है। अतः विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं के समूहों की सृजनात्मकता में अधिक अन्तर नहीं है।

### मौलिकता घटक के दिव्यांग (मूक-बधिर) छात्र एवं छात्राओं के अशाब्दिक सृजनात्मक चिन्तन फलांक :-



दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं द्वारा प्राप्त मौलिकता फलांकों के ग्राफ से यह प्रदर्शित होता है कि दिव्यांग छात्रों के समूह का 5.55 प्रतिशत छात्र उच्च मौलिकता स्तर पर पाए गए। जबकि दिव्यांग छात्राओं में सृजनात्मकता की मौलिकता का औसत स्तर पाया गया।

### अशाब्दिक सृजनात्मक चिन्तन परीक्षण के दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं के सम्पूर्ण सृजनात्मकता के फलांकों की तुलना :-

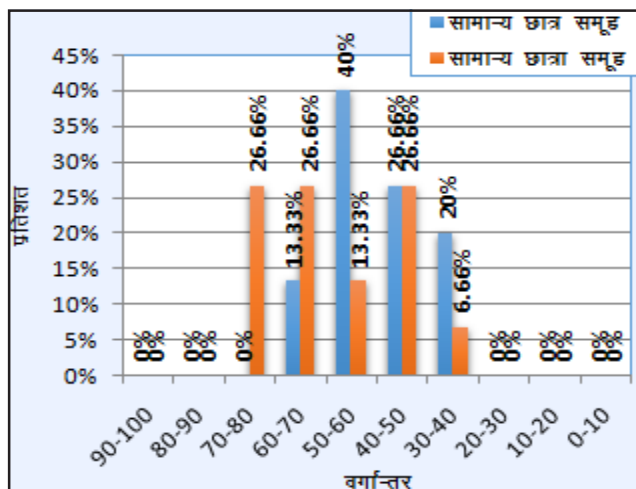


दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं के सम्पूर्ण सृजनात्मकता फलांकों के ग्राफ से यह स्पष्ट होता है कि दिव्यांग छात्राओं की अपेक्षा दिव्यांग छात्रों में उच्च स्तर की सृजनात्मकता है। अतः विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है दिव्यांग छात्र, दिव्यांग छात्राओं की अपेक्षा अधिक सृजनात्मक हैं।

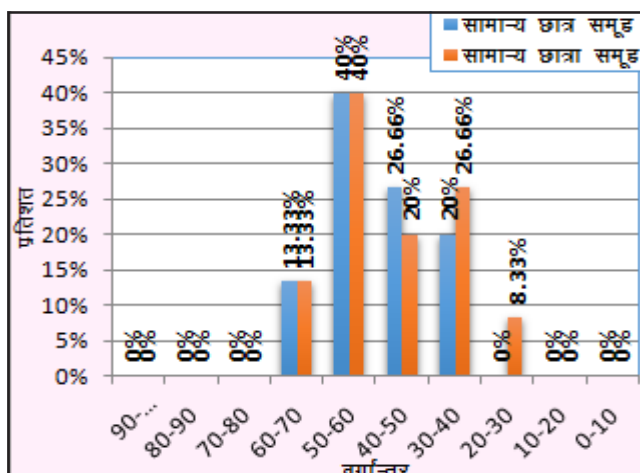
### शारीरिक रूप से सामान्य छात्र एवं छात्राओं की सृजनात्मकता की तुलना करना।

**विस्तार घटक के शारीरिक रूप से सामान्य छात्र एवं छात्राओं के अशाब्दिक सृजनात्मक चिन्तन फलांक :-** सामान्य छात्र एवं छात्राओं के विस्तार फलांकों के ग्राफ से यह स्पष्ट होता है कि सामान्य छात्रों के समूह में औसत विस्तार स्तर के छात्र अधिक हैं जबकि सामान्य छात्राओं के समूह में औसत व निम्न विस्तार स्तर की छात्राएँ पाई गईं। निष्कर्षतः सामान्य

छात्रों में विस्तार का प्रतिशत छात्राओं की अपेक्षा अधिक है।

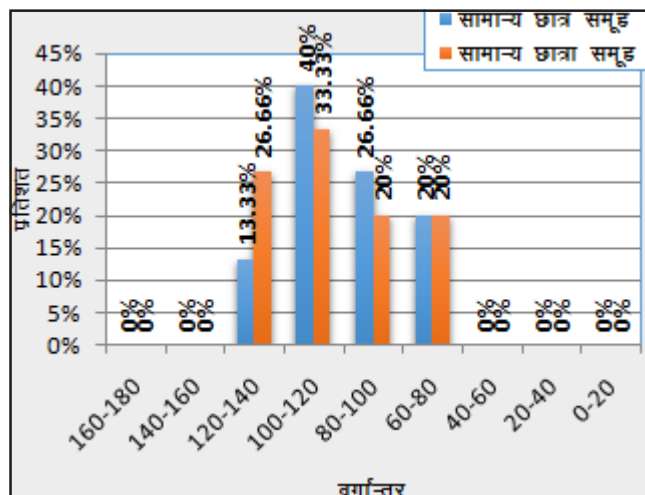


मौलिकता घटक के शारीरिक रूप से सामान्य छात्र एवं छात्राओं के अशाब्दिक सृजनात्मक चिन्तन फलांक :-



ग्राफ से यह प्रदर्शित होता है कि मौलिकता दोनों ही समूहों में औसत स्तर पर है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सृजनात्मकता के मौलिकता घटक के अन्तर्गत दोनों समूह समान स्तर पर पाये गये।

शारीरिक रूप से सामान्य छात्र एवं छात्राओं के सम्पूर्ण सृजनात्मकता के फलांकों की तुलना



सामान्य छात्र एवं छात्राओं दोनों ही समूह में उच्च व औसत सृजनात्मकता स्तर के विद्यार्थी हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि सामान्य छात्राओं में उच्च सृजनात्मकता का प्रतिशत अधिक है।

**शोध कार्य से प्राप्त निष्कर्ष -** शोधार्थी द्वारा शारीरिक रूप से सामान्य तथा दिव्यांग विद्यार्थियों की तुलना बाकर मेहदी के मानकीकृत उपकरण अशाब्दिक सृजनात्मक चिन्तन परीक्षण पर की गई। उपर्युक्त परीक्षण के आधार पर निम्नलिखित

**परिणाम (निष्कर्ष) प्राप्त हुए :**

1. माध्यमिक स्तर पर शारीरिक रूप से सामान्य व दिव्यांग विद्यार्थियों के अशाब्दिक सृजनात्मक चिन्तन परीक्षण के सम्पूर्ण सृजनात्मकता फलांकों के प्रतिशतानुसार दिव्यांग विद्यार्थियों में सृजनात्मकता उच्च स्तर की पाई गई। जबकि सामान्य विद्यार्थियों में सृजनात्मकता केवल औसत स्तर की पाई गई।
2. अशाब्दिक सृजनात्मक चिन्तन परीक्षण में सामान्य व दिव्यांग विद्यार्थियों के विस्तार घटक के फलांकों के प्रतिशतानुसार सामान्य विद्यार्थियों के समूह में केवल औसत विस्तार स्तर के विद्यार्थी पाए गए जबकि दिव्यांग विद्यार्थियों के समूह में औसत व औसत विस्तार स्तर के विद्यार्थी पाए गए।
3. अशाब्दिक सृजनात्मक चिन्तन परीक्षण में सामान्य व दिव्यांग विद्यार्थियों में मौलिकता का प्रतिशत सामान्य विद्यार्थियों की अपेक्षा दिव्यांग विद्यार्थियों में उच्च मौलिकता का स्तर पाया गया।
4. दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं के अशाब्दिक सृजनात्मक चिन्तन परीक्षण में उनके सम्पूर्ण सृजनात्मक फलांकों के प्रतिशतानुसार दिव्यांग छात्रों में सृजनात्मकता का स्तर दिव्यांग छात्राओं की अपेक्षा उच्च स्तर का पाया गया।
5. अशाब्दिक सृजनात्मक चिन्तन परीक्षण में दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं के विस्तार घटक के फलांकों का प्रतिशत दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं में समान है अर्थात् दोनों ही समूह में केवल औसत विस्तार स्तर के विद्यार्थी हैं।
6. दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं के मौलिकता घटक के फलांकों के प्रतिशतानुसार दिव्यांग छात्राओं का प्रतिशत उच्च मौलिकता स्तर को दर्शाता है, जबकि छात्रों में यह प्रतिशत औसत व निम्न स्तर का पाया गया।
7. शारीरिक रूप से सामान्य छात्र एवं छात्राओं के अशाब्दिक सृजनात्मक चिन्तन परीक्षण के सम्पूर्ण सृजनात्मक फलांकों में प्रतिशतानुसार सृजनात्मकता दोनों समूहों में केवल औसत स्तर की पाई गई।
8. शारीरिक रूप से सामान्य छात्र-छात्राओं के अशाब्दिक सृजनात्मक परीक्षण के विस्तार घटक के फलांकों में प्रतिशतानुसार छात्रों के समूह में केवल औसत विस्तार स्तर के छात्र पाए गए जबकि छात्राओं के समूह में औसत व निम्न विस्तार स्तर की छात्राएं पाई गई।
9. शारीरिक रूप से सामान्य छात्र व छात्राओं के अशाब्दिक सृजनात्मक चिन्तन परीक्षण के मौलिकता घटक के फलांकों के प्रतिशतानुसार दोनों ही समूहों में केवल औसत मौलिकता स्तर के विद्यार्थी पाए गए।
10. शारीरिक रूप से सामान्य व दिव्यांग विद्यार्थियों के अशाब्दिक सृजनात्मक चिन्तन परीक्षण के सम्पूर्ण सृजनात्मक फलांकों के अन्तर्गत दिव्यांग विद्यार्थियों में सृजनात्मक चिन्तन का स्तर अधिक पाया गया। अतः दिव्यांग विद्यार्थियों के फलांक सामान्य विद्यार्थियों



की अपेक्षा अधिक पाए गए। अतः दोनों समूहों में सार्थक अन्तर पाया गया।

11. अशाब्दिक सृजनात्मक चिन्तन परीक्षण के विस्तार घटकों के अन्तर्गत दिव्यांग विद्यार्थियों के समूह में विस्तार घटक के फलांक सामान्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक पाए गए। अतः दिव्यांग विद्यार्थियों में सृजनात्मक चिन्तन का स्तर उच्च पाया गया। अतः दोनों समूहों में सार्थक अन्तर पाया गया।
12. अशाब्दिक सृजनात्मक चिन्तन परीक्षण के मौलिकता घटक के फलांकों में दिव्यांग समूह के विद्यार्थियों में मौलिकता फलांक सामान्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक पाए गए। अतः दिव्यांग विद्यार्थियों में सृजनात्मकता के मौलिकता घटक का स्तर अधिक पाया गया। अतः दोनों समूहों में सार्थक अन्तर पाया गया।
13. दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं के अशाब्दिक सृजनात्मक चिन्तन परीक्षण में सृजनात्मकता के सम्पूर्ण फलांकों में दोनों समूहों में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
14. अशाब्दिक सृजनात्मक चिन्तन परीक्षण के विस्तार घटक के फलांकों में दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
15. दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं में अशाब्दिक सृजनात्मक चिन्तन परीक्षण के अन्तर्गत प्राप्त मौलिकता घटक के फलांकों में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
16. अशाब्दिक सृजनात्मक चिन्तन परीक्षण में शारीरिक रूप से सामान्य छात्र व छात्राओं के सम्पूर्ण सृजनात्मकता फलांकों में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
17. अशाब्दिक सृजनात्मक चिन्तन परीक्षण में शारीरिक रूप से सामान्य छात्र एवं छात्राओं में विस्तार घटक के फलांकों में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
18. सृजनात्मक चिन्तन के अशाब्दिक परीक्षण में शारीरिक रूप से सामान्य छात्र एवं छात्राओं के मध्य मौलिकता के फलांकों में सार्थक अन्तर पाया गया।

**सृजनात्मक चिन्तन विकास हेतु सुझाव** – विभिन्न विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की सृजनात्मक चिन्तन के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम तथा अनेक कक्षा-कक्ष परिस्थितियों को बनाया जा सकता है जो विद्यार्थियों के सृजनात्मक विकास चिन्तन के विकास हेतु उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर सके, उन अनेक सुझावों में प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं :-

1. विभिन्न समस्याओं पर समूह चर्चा का आयोजन करना चाहिए तथा उनमें प्रत्येक विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका पर बल देना चाहिए।
2. विभिन्न मौखिक लेख प्रतियोगिता, चित्र-निर्माण प्रतियोगिता, आशु भाषणों, कविता पाठ, स्वरचित कविता इत्यादिक गतिविधियों का समय-समय पर आयोजन करते रहना चाहिए।
3. नवीन विचारों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
4. विद्यार्थियों के वैयक्तिक भेद को स्वीकार कर उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप उनका मार्गदर्शन किया जाना चाहिए।
5. विद्यार्थियों के अपसारी चिन्तन के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
6. उनकी अपनी मौलिकता एवं नवीन सृजन क्षमता को पूर्ण आदर एवं सकारात्मक परिणाम मिलना चाहिए।
7. प्रायोगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए।
8. शिक्षक स्वयं यदि कार्य हेतु जिज्ञासित होगा तो वह विद्यार्थियों में भी नवीन सृजन हेतु जिज्ञासा उत्पन्न करेगा।

#### **सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-**

1. बेस्ट, जे.डब्ल्यू. (1983) शिक्षा में अनुसंधान, नई दिल्ली, प्रेन्टिस हॉल ऑफ इंडिया
2. कपिल, एच.के. व सिंह, एम. : सांख्यिकी के मूल तत्व, अग्रवाल पब्लिकेशन, जोनपुरा
3. सिंह, डॉ. रामपाल एवं शर्मा, डॉ. ओ.पी. (2014) : शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी, श्री विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-2,
4. परिहार, डॉ. अमरजीत सिंह (2014) : 'शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन', आर. लाल बुक

\*\*\*\*\*

# Jawaharlal Nehrus Identity and His Encounter with Socialism: A Historical Outlook

Rajeesh F\*

**Abstract** - It is veritable that the traditional Indian economy which was shattered by the onset of foreign capitalism represented by British rule. The British conquest differed from other foreign invasion. It proves that other foreign conquests did not touch the abundant wealth of India, therefore the untouched economic basis grew in India but British conquests shattered the economic basis and broke the economic growth of India, moreover aiming of profit - motive of British kept their administration in India draining the wealth. At these circumstances, the nationalist thinkers like Jawaharlal Nehru thought of India growing progressively in different dominions. Socialism is an economic ideology witnessed its growth at the end of nineteenth century in Indian soil. Nehru, whose western education paved better understanding of Socialism and experiments with Socialism in Russia, adopted in Indian economy. Finding his identity as an Indian, gaining multitude of ideologies of the world and dedicated his life to serving the nation, Jawaharlal Nehru advocated Socialism in India.

**Keywords** - Historical Background, Identity, Socialism, Economic Democracy, Democratic Socialism.

**Introduction** - Modern India is on her march to the new horizons of the possibilities of rapid transformation amid certain backward conditions. Turning the pages of Indian history, India was found to be called a Colonial country with vast territories colonized by the British Imperialism. The Indian scenario was pathetic during the English regime, for instance, the overwhelming situations such as illiterate and backward peasant majority of the populations, the regions inherited by series of races and nationalities at different stages of Indian history, the abundant natural resources undeveloped, the traditions of despotic rule with no democratic forms and decomposing village system were the outrageous prospect of the colonized India. It is not right to call Jawaharlal Nehru as the first propagator of Socialism. The socialist ideas had its roots in India at the later stages of nineteenth century. As a visionary and a dedicated personality in service of his motherland, Nehru observed in the struggle for India's independence as a part of universal antagonism. Nehru was a man of numerous ideologies which embodied in his personality. Socialism enormously influenced Nehru, thus he propagated and instated it as part of India, and therefore it proved that his life was full of action, ensuing from his dreams in his subconscious and linking it in the chain of India's prosperity and her role in the world.

**Historical Background-** The British conquest of India had repercussions of significances on India, unerringly entrenched politically, socially, economically and ideologically. Historically India faced the first alternative ideology since the coming of Muslims. Later the British

conquest and administration paved the way for spreading Western ideas which intruded into the lives of Indians through Western education, foreign officials and administrative methods. In the beginning the Indian ruling elites denied the Western ideology but the power installed by the British continued the administration whereas the Indian responses to new ideology were total rejection fallen inactive. At the other end of continuum, a small group of Indians witnessed total acceptance and even some were converted into Christianity. Following the better opportunities, many of the Brahmins, the Kashtryas and the Vaishyas joined the service of the East India Company from the similar services in the Mughal and Hindu Rajas because they were labeled as skilled. As witnessing new scenario, the British rule espoused new opportunities for employment and wealth to those who adopted linguistically and even culturally. Thus it caused the emergence of identity dilemma. In the early part of nineteenth century, Ram Mohan Ray, a Brahmin from Calcutta was remarkable in his way, found that the rights of an individual were equal both in Upanishads and Western thoughts, therefore he attacked the evil systems in the society and encouraged the study of English literature and science, thus to spread his ideas, he founded the Brahma Samaj in 1830. However Dayanand Saraswati who was orthodox advocated orthodox ideological possibilities for the identity problem. Fearing the Hindu convictions becoming westernized, Dayanand's Arya Samaj offered Indians the possibility of ideology they could respect which had the traditional roots. The responses of Indians were in two ways, most of the new Indian middle

\*Research Scholar (Ancient Indian History, Culture and Archaeology) Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

class consisting of doctors, lawyers, technicians, journalists and clerks joined neither Brahma Samaj nor Arya Samaj but they engaged in their selection and profession. The majority of the Indians who did not abandon their castes or religious customs adopted the Western ideas and social customs.

**Jawaharlal Nehru and His Identity-** Motilal Nehru, the father of Jawaharlal Nehru, belonged to new middle class family. As a distinguished Kashmiri Brahmin lawyer with western education, he appeared in many ways more western than Indian. His admiration for English education, literature, science and ideas made him with new horizons. As he was fond of English social manners and dress, he appeared to be an Anglican. However he followed the joint family system and even he did all religious duties of his household as he was the eldest son of the family. Jawaharlal Nehru, at his parental home, western style in many ways, had the Indian influence. As a child, he was told the stories of the Ramayana and the Mahabharata. As his father, at the age twelve, he underwent the Upanayana or sacred thread which initiated him the adult male rank of Brahmin and at the age of twenty six, he was married from his parental agreement.

Nehru characterized himself as an individual suspended between two worlds and belonging neither to India nor to West, therefore he was addressed 'the man of two cultures and one world'. An appreciative writer had observed, "There are many strands in the temperament, character and intellectual caliber of Nehru derived from India and Europe, which make his personality rather more like rich tapestry than like the homespun fabric." What makes him 'the man of two cultures and one world' is his effectual conscious with fruitful blend of his Western upbringing, a wide knowledge of world affairs, deep loyalty to the tradition of India and love for Indian ancient culture. His identity is proved as Nehru stated that probably his thoughts and approach to life were more a kin to what was called Western than Eastern but India clung to him as she did to all her children. Nehru had a triumphant influence on Indian renaissance and he formulated what India needed for her future, thus he was the embodiment of resurgent nationalism in India.

**Jawaharlal Nehru and His Responses -** Nehru was the greater son of a great father. In fact what his father dreamed he achieved. As his father was the source of his inspiration, Nehru drew inspiration and guidance from Mahatma Gandhi but he was not a dumb follower. On many occasions Nehru differed and made his own significant contributions. At certain occasions, the turning points for the Congress intrinsically were insinuated by Nehru with his stern stand in the crucial matters. These timely adapting ideas created a personality whose embodied attitude essentially proved that he was the man with a reason, therefore Gandhi named him as his successor knowing the fact that Nehru differed from him in some ideas and he firmly fixed in the underlying elements of his thoughts and ideas. Since Independence,

his role was felt significantly in framing the internal and external policies. At the abysmal circumstances, Nehru obviously involved in framing the firm foreign policies which evolved from the Indian age old principles of non violence and tolerance, thus creating the theory of Panchshil which later was accepted by many big and small countries, thereby his idealism stood with realistic demands of the circumstances.

**Modern Socialism at Glance-** The roots of modern socialism are to be found from the development of industries which took place in later part of the eighteenth century. The economical changes, unrestricted competitions among the industries, the technological discoveries later which adopted in the trade and commerce and the consequent modifications in social conditions were the reasons that carried forward so called modern socialism. Astonishingly narrated that the actual definition of Socialism differs from country to country and idea to idea but the so called civilized countries where the industries developed became the abode of Socialism. Doubtlessly Karl Marx is the chief founder of Modern Socialism and often addressed himself as a communist. It is at glance wherever Socialism exists today it is democratic aiming at reinforcing equality; therefore Socialism and Social democracy are termed as synonymous or else Socialism can be simply defined as Economic Democracy.

**Nehru's Encounter with Socialism-** Jawaharlal Nehru has accomplished noteworthy position in Indian history. His unique personality, coherent writings, estimable dedication and above all his sincerity have really made him his distinguished popularity known throughout India and the rest of the world. It is noteworthy to declare that his international outlook has been influenced by many ideologies of the world and Socialism which is one such influenced by his socialist experiments in Russia. But his developed Socialism was not merely an abstract and it had been cowardice to apply in India by not taking considerable understanding of prevailing situation in India, therefore Nehru took appropriate understanding of prevailing situation for the introduction of Socialism in India.

Nehru at the first time came across Socialism while he spent his college days in England. He was mainly attracted to Fabian ideas of George Bernard Shaw, Beatrice, Sidney Webb and G.H. Wells. These thinkers made stress that Socialism was an inevitable stage in the evolution of democracy. Nehru believed that these ideas were more humanitarian and scientific and he envisioned a logically ordered society. In 1930, Nehru had a direct contact with the peasants whose poverty stricken eyes, hardships and problems changed his mind because his experiences towards the peasants brought him a responsibility to uplift the peasants, thus it provided him a emotional base for later conversion of Socialism. A historical event of oppressed Nationalists was held Brussels in 1927. Until 1927, he was not a complete convert to the creed of Socialism but the meeting In Brussels, he came to contact

with the communist, socialist and left – wing socialist and radical nationalists across Asia and Africa. At that occasion, he thought of any reforms and policies that had to be introduced in India for her future progressive existence. He had the dream of converting people into Socialism, therefore he wished to propagate the ideas of Socialism through press, writings, pamphlets and speeches and even he challenged the people who disagreed to come out and discuss. Even Nehru admitted that there were two schools of thoughts within Congress, therefore they discussed and criticized and finally coming up with solutions for the people. On 19 May, 1936, while addressing the gathering, Nehru accepted that Congress did not accept his view on Socialism but he continued that he would make the majority of the people follow it because he found solutions for the vital problems that existed in India.

**Conclusion-** Nehru's propagation and creation of Socialism in India was appropriate. While adding Socialism by considering the prevailing circumstances in India, Nehru envisioned India's progressive future. In India, at present planned socialist production with innovative horizons shares the new principles of distribution of industry along lines of cooperative development and equality of nation. As India follows Democratic Socialism, while considering the new economic policies, the socialist ideas must be taken for the advantages of economic prosperity. The denial of socialist ideas is found in Indian economic policies at present in India. As Nehru stresses a socialist society is a

good society, let Socialism be accepted as an economic theory of Indian prosperity.

**References:-**

1. Cathrein, Victor. (1904). *Socialism: Its Theoretical Basis and Practical Applications*. New York: Benzgier Brothers.
2. Dutt, Palme, R. (1997). *India To-Day*. Calcutta: Manisha Granthalaya.
3. Gopal, S. (1975). *Selected Works of Jawaharlal Nehru*. New Delhi: Orient Longman.
4. Krishnamurthi, Y.G. (1948). *Jawaharlal Nehru: The man and His Ideas*. Bombay: The Popular Book Depot.
5. Malaviya, H.D. (1966). *Socialist Ideology of Congress A Study and Its Evolution*. New Delhi : A Socialist Congressman Publication.
6. Nafaiger, Nettie, Elefrieda. (1968). *The Development of Jawaharlal Nahru's Political World View*. Manhattan: Kansas State University.
7. Nehru, Jawaharla. (1938). *Eighteen Months in India 1936- 1937*. Allahabad: Allahabad Law Journal Press.
8. Pillai, R.C. (1986). *Jawaharlal Nehru and His Critics*. New Delhi: Gitanjali Publishing House.
9. Santhanam, K. (1940). *India's Road to Socialism*. Madras: Brindavan Prachuralayam.
10. Ulayanovasky, R. (1974). *Socialism and the Newly Independent Nations*. Moscow: Progress Publishers.
11. Zakaria, Rafiq. (1959). *A Study of Nehru*. Bombay; A Times of India Publication.

\*\*\*\*\*



## Bamboo and the environment - The grass grows in Balaghat

Dr. Aalok Kumar Yadav\* Poonam Mishra\*\*

**Abstract** - Bamboos play very important role in the socio economic and culture lives of Balaghat District there are bamboo resource available throughout the district in natural as well as plantation forest. Mostly planted by farmers in their own yards and by the community in communities forest lands.

Bamboo is an integral part of the lives of the tribal people living in the Balaghat district of Madhya Pradesh. Bamboo is crucial as material for very large number of house hold and utility items and also as a source of income (both in cash and kind) for same. For these reason bamboo is an ideal starting point for a people centered development approach. A craft tradition is in existence in the area and the resource is available locally at low cost there is local market for bamboo articles and scope for expanding the market for these goods. Starting with a better definition of the resource base indigenous knowledge about the resource and an improved understanding of the opportunities and constraints in processing and marketing bamboo products, the paper aims to use bamboo as a tool to strengthen tribal culture and provide a means to deal with market forces in a rapidly changing world.

The bamboos are an incredibly versatile and useful group of plants. Bamboos have been used by people in imaginative and widely varied ways where ever they are found they have long histories of use and play important roles in the daily lives of millions of people. Further more and especially important in these days of rapid environmental degradation they are highly renewable resource. Therefore research on bamboo can help improve the efficiency of production, processing and marketing of bamboo products and stimulate development.

"Development" and that ubiquitous term sustainable development have been defined in almost as many ways as bamboo is used without going into semantic, "development" in its essence means improving human welfare and "sustainable development" means improving human welfare without degrading environment.

**Introduction** - In Asia bamboo take the character of "poor men's timber" since for many people, bamboo growing, harvesting and processing are essentially subsistence activities. Bamboo is a fundamental part of people's overall livelihood strategies. In some cases, bamboo may be mainly for home consumption, as raw material for shelters, fences, bridges, fish pens or even water pipes. Bamboo products have high value in use. Without bamboo these products have to be constructed from another less suitable materials, or purchased, using scarce cash resources, from outside.

There are also millions of people who depend on bamboo for part or all of their income. For example, in India, it is estimated that there are two million traditional bamboo artisans. Their livelihoods depend almost entirely on the harvesting, processing and selling of bamboo and bamboo products such as basket, mats and handicrafts.

Balaghat is in the south eastern portion of the state of Madhya Pradesh. The district is situated within 21.19° to 22.24° North latitude and 79.31 to 81.3° East longitude. The total area of Balaghat is 9245 sq. km. According to 2011 census total population of district is 1701698. The important

resource of Balaghat is its forest land. The district is also rich in mineral deposits like Manganese, Bauxite and Copper. The important tourist places are Kanha National Park, Lanji Fort/Temple Dhuti dam Gangulpara Reservoir etc.

**Bamboo At The Rural Level** - There are several reasons why bamboo is so closely associated with the lives of many poor people. To begin with, raw material has been available at low cost. Large amounts of material still come from natural stands, often on state lands. Indeed, part of the problem encountered in managing bamboo resources is that they have often been treated as "free goods" and so have been over exploited. Bamboo is also relatively easy to cultivate and manage; it is especially good for sloping lands and other land that is unsuitable for agriculture - the kind of land that the poor are often related to.

Furthermore, there are traditional low -cost processing technologies available and ready markets for the many products which can be fashioned from these versatile plants. Entry into the industry is relatively easy with low overhead costs, and relatively low skill requirements, poor people can create job themselves. In many cases, the timing of the

\*Principal, Indira Gandhi Govt. Polytechnic College, Chhindwara (M.P.) INDIA  
\*\* Research Scholar, Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur (M.P.) INDIA

work can be synchronized with periods in which people would otherwise be unemployed or under - unemployed. Handicraft work can be done at home , making it ideally suitable for women's who must stay at home to perform domestic duties but who have period of spare time . For many, the sale of bamboo is one of very few opportunities to generate cash income in otherwise subsistence economies: it is the money that is needed to pay for school fees and supplies, agriculture inputs, medicine, and good from the cash economy.

#### **Bamboo In Small And Medium Scale Enterprises -**

Bamboo is important as a tool for development because it is not only a "poor man's crop", but also a raw material in an increasing number of high value consumer goods and building material. Some, including involvement large scale, and especially international, markets. However to be effective products which people abandon as soon as they have access to or can afford better substitute - "inferior goods" in the lexicon of the economist - bamboo provides an impressive range of products, for which there is a steady or increasing demand. Therefore, there are many possible points and types of intervention along the bamboo production - to consumption system which can be used to influence the system for the benefit of the target groups.

Overcoming poverty requires creating employment and income generating opportunities. In an increasingly market-oriented, cash based world, people need access to cash income. Bamboo is an important commodity in the cash economy. Growing demands translate into jobs within the processing sub-sector, and increase the demand and cash income in the raw material production sub-sector.

Research has shown that small and medium-scale forest based enterprises are very significant providers of employment and income, and within that sector bamboo industry is a major component. One of the major advantages of bamboo as an entry point to development is the fact that so many products can be produced from it, and most of them can be produced by small and medium scale enterprises. Such enterprises can be established with modest capital investment; the economies of scale are not nearly as high as in some other manufacturing industries. They are labour-intensive industries, and result in large-scale employment generation.

**Research For Development -** How can research help the people involved at various levels in the bamboo sector? How can one ensure that developments in the sector help poor people and do not leave them out?

To begin with, one needs to know much more about the bamboo industry, about who is involved and about the main problems they face. Unfortunately, bamboo has hitherto not been considered an important commodity and consequently, government bureaux of statistics have not kept good records. Gross inconsistencies exist in the data in terms of: the definition of categories (one year bamboo products are lumped together with wick ware, in another year they are placed with handicrafts, and it is impossible

to know what portion is actually bamboo); differing units of measurement (number of culms and tones); lack of standard grading and classification system for bamboo raw material; in complete and out of inventory data; large gaps in time series; non-existent data on the people involved in the sector. These inherent weaknesses in the statistics are compounded by the systematic under reporting of production and consumption information, especially with regard to the large volume of material traded in informal markets which are never recorded in official statistics.

Statistical information is just the beginning; it is necessary for strategic planning and, perhaps for marshalling political support for bamboo. But one also needs to know much more about the constraints and the opportunities which exist in the bamboo sector, and to devise approaches to take advantages of them. At any level in the economy people face a range of constraints from the technical through to the economical and political.

Research, and especially extension, in the bamboo sector has been limited. Perhaps, this is because of its status as "poor man's crop", or because it falls through that big crack between traditional disciplines of agriculture and forestry, or because the statistics do not reveal how important it is to Research so far has focused primarily on technical aspects; reproduction silviculture and management, post harvest preservation and processing engineering characteristics etc. Such research has had important impacts, and has supported the growth of bamboo industry. However, the benefits have not always reached the very poor.

There is also a need to improve the way research is transmitted to those who need and use research result. In same way, researchers need to improve their understanding of the real problem faced by the people working in the bamboo sector so that they ask the right questions. There is a large community of organizations - grassroots and NGO - which could become very effective partners in bamboo-based development.

**Conclusion -** Rural bamboo cannot be separated from people. Unlike bamboo in research stations or conservation areas, rural bamboo has no meaning unless it is useful to rural people. For village-based enterprises, bamboo is the means not an end; it is one element in a complex system of rural relationship where human beings are more important. It is a natural vehicle to encourage sustainable, integrated farming system. It is an excellent resource on which to build a variety of income and employment-generating opportunities. With its multiple uses, and high value in a range of products aimed at national and international markets, bamboo shows a great potential for value-adding operations.

Consequently, rural bamboo has to be understood in the context of overall farming system and not in isolation from them. It also has to be understood from a range of perspective: not just the producer but other groups such as traders, processors and consumers. Awareness of these

facts is important not just for3 social scientist but also for natural scientists and all development practitioners. Approaches to indentifying and solving problems should bring together a range of discipline;not to work on their own,but auto work with the different sections of society who have an interest in bamboo.

#### References :-

1. Banik, R.L.1994.Distribution and ecological status of bamboo forested of Bangladesh.Bangladesh journal of forest science,23(2)1-10
2. Chambers,R.;Ghildyal,B.P.1985.Agricultural research for resource-poor farmers:the farmer-first-and -last model.Agricultural Administration,20,1-30.
3. Tewari, D.N.1992.Amonograph on bamboo. International Book Distributors,DehraDun,INDIA.
4. Krishnakutty,C.N.1991.Development of bamboo resources in homestead;production,marketing and employment generation in Kerala India.

\*\*\*\*\*

# Soil Contamination And Need Of Public Awareness

Dr. Arun Sikarwar\* Dr. Vaishali Lal\*\*

**Abstract** - Soil pollution occurs when the presence of toxic chemicals, pollutants or contaminants in the soil is in high enough concentrations to be of risk to plants, wildlife, humans and of course, the soil itself. Soil being a “universal sink” bears the greatest burden of environmental pollution. It is getting polluted in a number of ways.

**Introduction** - There is urgency in controlling the soil pollution in order to preserve the soil fertility and increase the productivity. Pollution may be defined as an undesirable change in the physical, chemical and biological characteristics of air, water and soil which affect human life, lives of other useful living plants and animals, industrial progress, living conditions and cultural assets. A pollutant is something which adversely interfere with health, comfort, property or environment of the people. Generally most pollutants are introduced in the environment by sewage, waste, accidental discharge or else they are by-products or residues from the production of something useful. Due to this our precious natural resources like air, water and soil are getting polluted.

The basis of agriculture is Soil. All crops for human food and animal feed depend upon it. We are losing this important natural resource continuously. When the concentration of pollutants on the surface becomes so high that it harms land biodiversity and endangers health, particularly through food. Activities such as stock breeding and intensive farming use chemicals, pesticides and fertilisers that pollute the land, just as happens with heavy metals and other natural and man-made chemical substances.

Some of the most hazardous soil pollutants are xenobiotics – substances that are not naturally found in nature and are synthesized by human beings. The term ‘xenobiotic’ has Greek roots – ‘Xenos’ (foreigner), and ‘Bios’ (life).

## Main Causes Of Soil Pollution

**1. Industrial Activity** - Industrial activity has been the biggest contributor to the problem in the last century, especially since the amount of mining and manufacturing has increased. Most industries are dependent on extracting minerals from the Earth. Whether it is iron ore or coal, the by-products are contaminated and they are not disposed of in a manner that can be considered safe. Some common soil pollutants that can be sourced to industrial waste are listed below-

- (A) Chlorinated industrial solvents
- (B) Dioxins produced from the manufacture of pesticides and the incineration of waste.
- (C) Plasticizers/dispersants
- (D) Polychlorinated biphenyls (PCBs)
- (E) The petroleum industry creates many petroleum hydrocarbon waste products. Some of these wastes, such as benzene and methylbenzene, are known to be carcinogenic in nature.

**2. Agricultural Activities** - Chemical utilization has gone up tremendously since technology provided us with modern pesticides and fertilizers. They are full of chemicals that are not produced in nature and cannot be broken down by it. As a result, they seep into the ground after they mix with water and slowly reduce the fertility of the soil. Other chemicals damage the composition of the soil and make it easier to erode by water and air. Plants absorb many of these pesticides and when they decompose, they cause soil pollution since they become a part of the land.

**Pesticides** - Pesticides are substances (or mixtures of substances) that are used to kill or inhibit the growth of pests. Common types of pesticides used in agriculture include :

**Herbicides** – used to kill/control weeds and other unwanted plants, by using Herbicides soil may contaminated by Triazines, Carbamates, Amides, Phenoxyalkylacids and Aliphatic acids.

**Insecticides** – used to kill insects, by using Insecticides soil contaminated by Organophosphates, Chlorinatedhydrocarbons, Arsenic-containing compounds and Pyrethrum.

**Fungicides** – used to kill parasitic fungi or inhibit their growth by using Fungicides soil may contaminated by Mercury-containing compounds, Thiocarbamates and Coppersulfate.

unintentional diffusion of pesticides into the environment (commonly known as ‘pesticide drift’) poses a variety of

\*Department of Chemistry, Govt. Home Science P.G. College, Hoshangabad (M.P.) INDIA

\*\*Department of Chemistry, Govt. Home Science P.G. College, Hoshangabad (M.P.) INDIA



environmental concerns such as water pollution and soil pollution. Some important soil contaminants found in pesticides are listed below. These chemicals pose several health risks to humans. Examples of health hazards related to pesticides include diseases of the central nervous system, immune system diseases, cancer, and birth defects.

**3. Waste Disposal** - While industrial waste is sure to cause contamination, there is another way in which we are adding to the pollution. Every human produces a certain amount of personal waste products by way of urine and feces. While much of it moves into the sewer the system, there is also a large amount that is dumped directly into landfills in the form of diapers. Even the sewer system ends at the landfill, where the biological waste pollutes the soil and water. This is because our bodies are full of toxins and chemicals which are now seeping into the land and causing pollution of soil.

**4. Acid Rain** - Acid rain is caused when pollutants present in the air mix up with the rain and fall back on the ground. The polluted water could dissolve away some of the important nutrients found in soil and change the structure of the soil.

In agricultural soils, however, the concentration of one or more of these elements may be significantly increased in several ways, like through applications of chemicals, sewage sludge, farm slurries, etc. Increased doses of fertilizers, pesticides or agricultural chemicals, over a period, add heavy metals to soils which may contaminate them. Certain phosphatic fertilizers frequently contain trace amounts of cadmium which may accumulate in these soils. Soil that is not significantly polluted may still harm humans directly through bioaccumulation, which according to Pollution Issues, occurs when plants are grown in lightly polluted soil, which continuously absorb molecules of the pollutants. Since the plants cannot get rid of these molecules, they accumulate in the plant, causing higher amounts of pollution to exist in the plant than in the soil. Animals who eat many of these polluted plants take on all the pollution those plants have accumulated. Larger animals who eat the plant-eating animals take on all the pollution from the animals they eat. Humans who eat plants or animals that have accumulated large amounts of soil pollutants may be poisoned, even if the soil itself does not contain enough pollution to harm human health. Furthermore, the presence of heavy metals in soil in toxic amounts can cause irreversible developmental damage in children. Lead and mercury in soil may also be harmful to human health. Although lead and mercury may be found naturally in soil, high concentrations of either metal may cause damage to the developing brains of young children, which in turn may lead to neurological problems. Humans of any age may also suffer kidney or liver damage from exposure to excessive mercury in soil. In addition to endangering human health, soil pollution can also cause economic damage.

Soil pollution can negatively affect the metabolism of microorganisms and arthropods, which can destroy some layers of the primary food chain and have a harmful effect

on predator animal species. Also, small life forms may consume harmful chemicals in the soil which may then be passed up the food chain to larger animals, which may lead to increased mortality rates and even animal extinction.

### Experimental Work

**1. Sample Collection** - Soil sample should be taken from the field before sowing the next crop or after harvesting the standing crop. Remove organic materials like dried leaves and small pieces of woods etc. from the soil surface. Dig out a pit of "V" shape of 20 cm length and width, and 15 cm depth. Take out the soil-slice (like bread slice) of 'A' inch thick from both the exposed surface of the pit from top to bottom. This slice is also termed as furrow-slice. To collect soil slice spade may be used. We have collected 20 soil samples from DOLRIYA Tehsil, District Hoshangabad (MP) India.

### 2. Preparation of samples for analysis :

**Drying:** Wet soil sample should not be stored as changes may occur in the chemical nature of certain ions and organic matter. Samples are generally air dried at temperature (25-35°C) and relative humidity (20-60%) then after are stored. Fresh samples from the field without any drying are required. For certain determinations such as ammonium and nitrate N, exchangeable K, acid extractable P and ferrous iron fresh sample from the field without any drying are required. Results of soil analysis are expressed on oven dry weight basis. This necessitates determination of moisture percentage by drying a small sample in an oven at 105 °C for 2 hours.

**Sieving:** Field moist samples prior to drying can be made to pass through a 6 mm sieve (about 4 mesh per inch) by rubbing with fingers. The practice seems of much advantage in case of heavy soils. Soil in the right moisture condition can be passed through a 2 mm sieve (about 10 mesh per inch). The common practice of sieving a portion of the gross sample through a 2 mm sieve and discarding the rest is undesirable as it increases the concentration of most of the elements involved in soil fertility. When the gravels in the soil exceeds 2% limit over a 2 mm sieve their exact percentage should be recorded.

**Grinding:** A roller, rubber pestle in an agate mortar, or a motorized grinder is commonly used. Crushing of the gravel or primary sand particles should be avoided for heavy soils, it is better to pass these through a 2 mm sieve before allowing them to get completely air dried.

**Mixing:** Sample should be thoroughly mixed by rolling procedure. Place the dried ground and sieved sample on a piece of cloth. Hold all the four corners of the cloth and then up the one corner and down the other corner across the sample alternatively. Now repeat the process in the reverse direction to roll the soil from one corner to another. Continue this until thorough mixing is assured.

**Storage:** Store the soil in paper carton (soil sample box) using a polythene bag as in inner lining. Label the carton mentioning cultivators name, plot number, date of sampling and initials.

**3. Estimation of different parameters** have completed with

the help of "Mrida Parikshak" a mini lab developed by ICAR-Indian Institute of Soil Science, Bhopal, MP

**Result & Discussion** - We have determined various parameters pH value, EC, Organic Carbon (OC), Nitrogen, Iron, Manganese, Copper, potassium, Sulphur, Phosphorus and Boron. Which are given in the following table.

**Table 1**

pH value found maximum 8.60 for sample no.03 and minimum 8.18 for sample no. 16. Electrical conductivity reported maximum 0.90 for sample no.11 and Minimum 0.01 for sample no. 03. Organic carbon reported maximum 3.04% for sample no.04 and minimum 0.62% for sample no. 13. Nitrogen found to be maximum 550.8 kg/haq for sample no. 04 and minimum 207.6 kg/haq for sample no. 13. Similarly Maximum value for Phosphorus, Potassium, Sulphur, Iron, Boron, Manganese and Copper 195.70 kg/haq, 520.1 kg/haq, 90.8 mg/kg, 9.52 mg/kg, 2.20 mg/kg, 59.80 mg/kg, 37.80 mg/kg respectively.

**Conclusions** - Plants require soil nutrients such as nitrogen, calcium and phosphorous for growth and development. Also, crops come under attack from rodents, insects and bacteria, so farmers require pesticides to protect the plants. The use of fertilizers and pesticides in agriculture, however, leads to other problems. Some raw materials can contaminate the soil. For instance, copper and boron in fertilizers, and organochlorine in pesticides, can harm the environment and create health risks when products are used in wrong proportions or over a long period of time.

To prevent such damage, farmers should use composted manure and bio-fertilizers and biologically active products such as algae and bacteria that can help initiate nitrogen fixation in soil.

We can conclude with that, some element like Mn, and Phosphorus are more than required range, so have to stop add more such elements in Soil, on the other hand Boron, Potassium and Copper reported very low, so more amount of these elements required for Soil. pH value suggest that soil is Alkaline in nature while Electrical Conductivity have to improved.

**References :-**

- Okrent D., On intergenerational equity and its clash with intergenerational equity and on the need for policies to guide the regulation of disposal of wastes and other activities posing very long time risks. Risk Analysis 19: 877-901.
- Belluck, D.A., Benjamin, S.L., Baveye, P., Sampson, J., Johnson, B. 2003. Widespread arsenic contamination of soils in residential areas and public spaces: an emerging regulatory or medical crisis? International Journal of Toxicology 22: 109-128.
- Richardson, G.M., Bright, D.A., Dodd, M. 2006. Do current standards of practice in Canada measure what is relevant to human exposure at contaminated sites? II: oral bio accessibility of contaminants in soil. Human and Ecological Risk Assessment 12: 606-618.
- Dr. Arun Sikarwar, Dr. Usha Mudaliar, Dr. Vaishali Lal, Soil Fertility & Productivity in Hoshangabad District, Shodh Samagra (2016).
- <http://www.imnh.isu.edu/digitalatlas/hydr/basics/main/chmtxt.htm>
- Agriculture and Natural Resources (Soil and Land) Revised October 2011.
- Acharya SM, Collection and preparation of soil, water and plant samples for analysis, IJCS 2018.

**Table 1**

S.	pH	EC ms/cm	OC %	N kg/haq	P kg/haq	K kg/haq	S mg/kg	B mg/kg	Fe mg/kg	Mn mg/kg	Cu mg/kg
1	8.42	0.22	1.56	341.1	38.43	500.6	36.90	0.00	3.13	21.50	0.46
2	8.51	0.19	1.92	391.9	25.02	520.1	90.80	0.00	3.24	29.60	0.65
3	8.60	0.19	2.06	411	39.32	481.1	3.08	0.00	1.45	22.50	29.30
4	8.42	0.01	3.04	550.8	61.66	344.5	10.00	0.00	2.01	26.00	17.60
5	8.51	0.26	1.70	360.1	30.38	433.4	39.00	0.00	2.57	19.70	16.40
6	8.28	0.64	0.76	226.7	29.41	435.6	21.00	1.00	3.36	20.20	9.64
7	8.28	0.64	2.82	519	44.68	366.2	21.00	0.55	2.80	5.40	37.80
8	8.28	0.64	1.68	357	54.51	498.4	17.00	0.92	3.47	26.50	10.40
9	8.37	0.62	1.50	331.5	53.62	446.4	9.00	0.64	2.46	17.00	10.96
10	8.37	0.64	1.25	296.6	82.22	370.5	15.00	0.55	3.13	13.90	1.59
11	8.28	0.90	0.80	233.1	70.60	368.4	8.00	0.64	5.71	20.60	1.77
12	8.28	0.66	0.71	220.3	32.17	446.4	23.00	0.92	3.02	25.10	1.31
13	8.28	0.61	0.62	207.6	58.09	429.1	7.00	0.64	3.24	22.90	1.02
14	8.28	0.62	1.16	283.9	109.10	416.1	8.00	0.73	2.68	31.40	0.74
15	8.37	0.82	0.98	258.5	106.30	199.3	18.00	1.38	5.37	59.30	1.68
16	8.18	0.64	0.76	236.2	100.90	370.5	7.00	0.00	5.26	33.20	1.68
17	8.28	0.60	1.12	277.5	92.95	335.9	51.00	0.27	1.90	30.10	0.09
18	8.37	0.32	1.43	322	195.70	160.3	11.00	0.36	9.52	23.30	1.54
19	8.37	0.61	1.14	280.7	74.18	283.9	13.00	1.28	7.39	59.80	1.21
20	8.47	0.72	1.52	334.7	91.16	329.4	24.00	2.20	6.15	58.00	1.77

## Correlation Of Group Solar Flare With Sunspot Numbers

Dr. Lokendra Kumar Borker\* Dr.S.K. Khandayat\*\*

**Abstract** - Grouped solar flare is sum or group of solar flares. In present work we plotted the graph between Grouped solar flare and yearly mean values of sunspot numbers for the period of 1996 to 2007 and further correlated between monthly mean values of sunspot numbers and Grouped solar flare in same period. Correlation between solar parameters Grouped solar flare and sunspot numbers shows that all of them are highly correlated with each other.

**Keywords** - Grouped solar flare, sunspot numbers, solar parameters, solar Indices.

**Introduction** - The most frequent observed and reliable solar parameter is sunspot number. Beside the sunspot number, solar flare is also known as measure of solar activity. Solar flare is not only a dynamical process but it has also many important consequences resulting from the manner in which energy is released. The solar flare of higher importance normally produce a host of phenomena such as emission of soft thermal and hard non-thermal X-ray and different types of bursts in radio region, characterized by different frequency time evolution. To measure the solar activity on the basis of solar flares, a solar indices grouped solar flare (GSF) is formed. GSF is a sum or group of solar flares, which are counted by number. It is essential to measure the GSF and its association with sunspot numbers. We have plotted the yearly mean values of sunspot number (Rz) along with yearly mean of Grouped Solar Flares (GSF) for the period of 1996 to 2007 as shown in **Figure 1**. From the figure 1 it is seen that good relationship exists between these two solar parameters for the period of solar cycle 23. To show the relationship between these two solar parameters, we have done the correlative analysis between these two solar indices on yearly and monthly basis. **Figure 2** shows the cross plot between yearly mean values of sunspot number (Rz) and Grouped Solar Flares (GSF). Distribution of points indicates a positive and high correlation between Rz and GSF. Correlation coefficient between Rz and GSF the period found to be 0.967, during the period of 1996 to 2007.

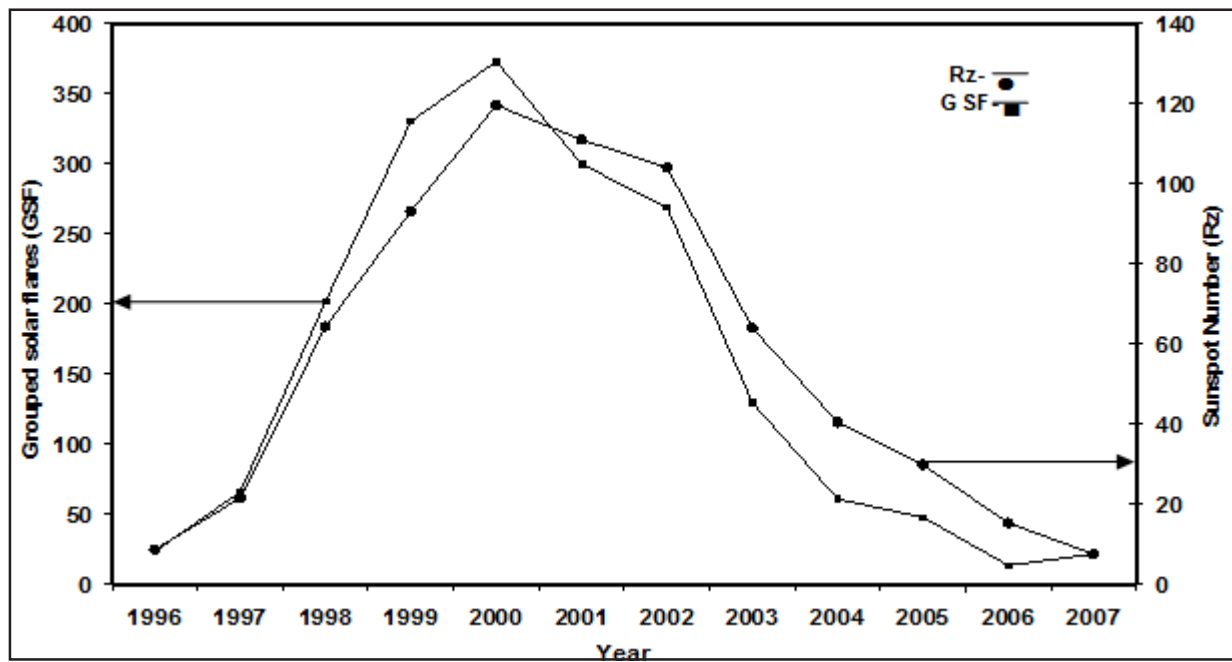
Further we have correlated the monthly mean values of sunspot number Rz with Grouped Solar Flares (GSF) for the period of 1996 to 2007 as seen in **Figure 3**. It is found from the figure 3 that the monthly mean values of Rz are highly correlated with GSF during the period of 1996 to 2007. The level of correlation on taking the yearly mean values are higher than analysis taken on the basis of monthly mean values of Rz and GSF. It is clear from the analysis that large number of solar flare occur during the high solar activity period.

**Conclusions** - We have done studies to draw the correlation with Grouped solar flares sunspot numbers. On the basis of analysis done conclusions are

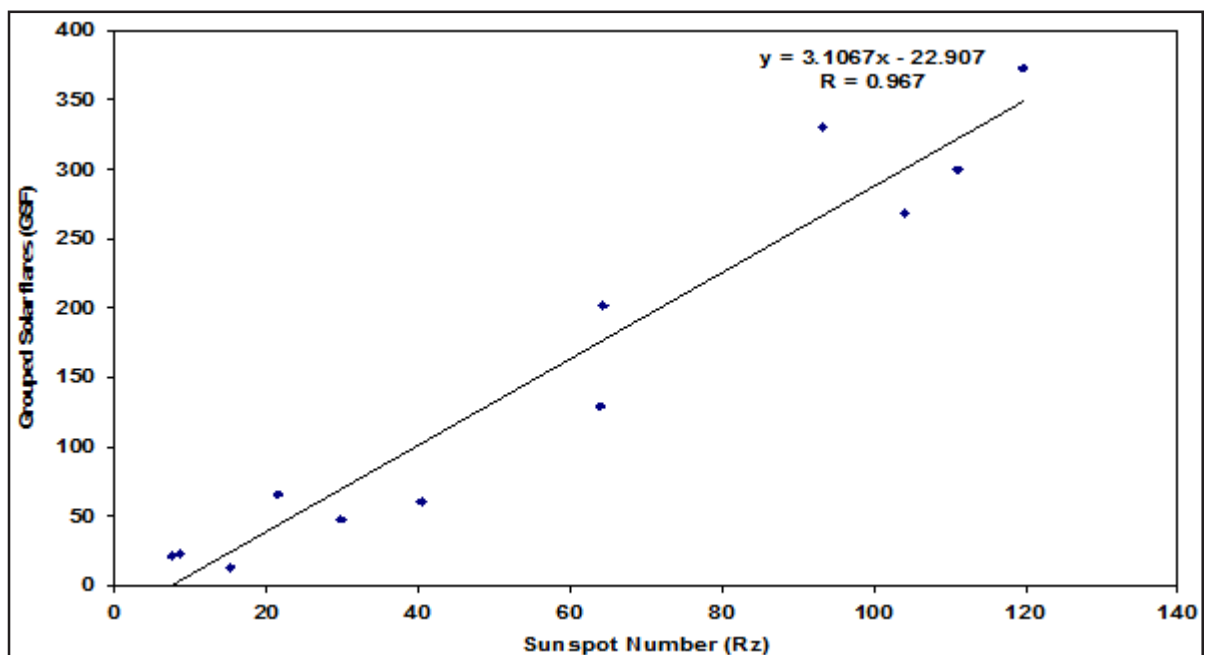
1. Positive and high correlation exists between the sunspot numbers and Grouped solar flares (GSF) for the period of 1996 to 2007.
2. Correlation between solar parameters Rz and GSF show that all of them are highly correlated with each other.
3. Sunspot numbers and grouped solar flares are examined as reliable solar parameters.

### References :-

1. Ness, N.F. and Wilcox, M 1967, Solar Physics, 2, 351
2. Gosling, J.T. 1993, J. Geophys. Res., 98
3. Khandayat, S.K. 2011, Solar source association with interplanetary disturbance and geomagnetic field disturbance.

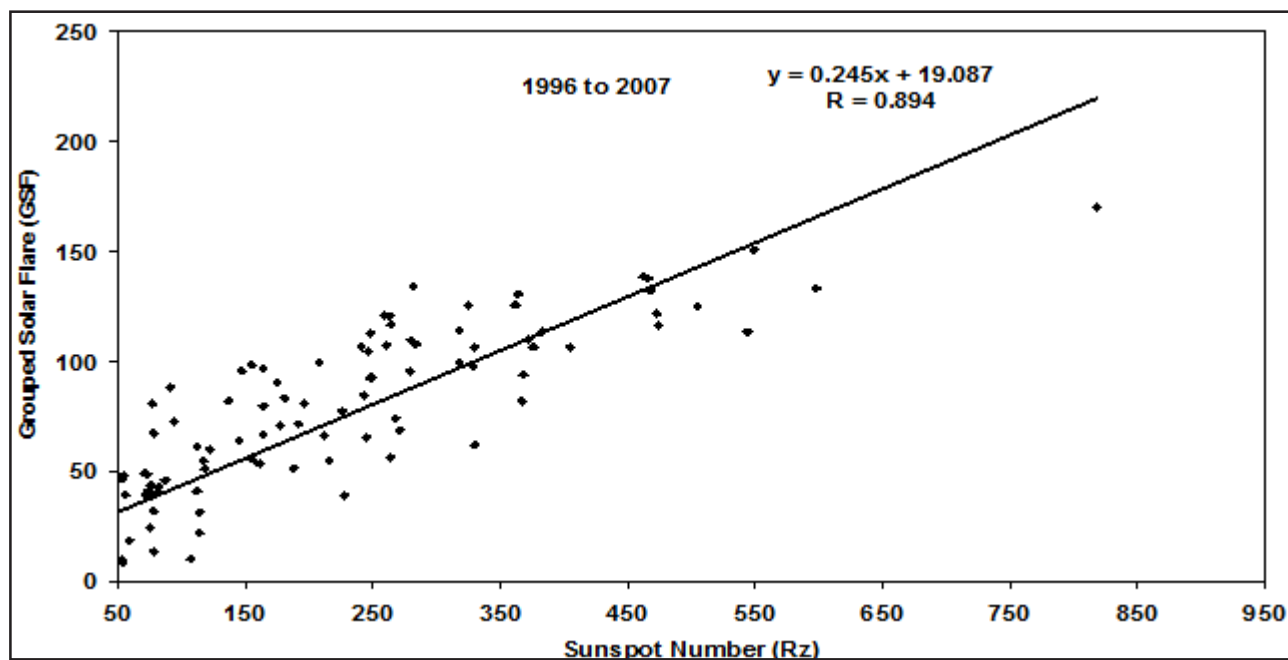


**Figure 1** Relation between the sunspot numbers and grouped solar flares for the period of 1996 to 2007.



**Figure 2** Grouped solar flares and sunspot numbers (yearly mean values) for the period of 1996 to 2007.





**Figure 3** Grouped solar flares and sunspot numbers (monthly mean values) for the period of 1996 to 2007

\*\*\*\*\*

# A Comparative Study Of Health Related Fitness Between International And Convent School Of Ujjain Division Madhya Pradesh

Punit Gupta\*

**Abstract** - The main aim of this study is to compare the health related fitness between high school players of Ujjain division. This study is indicated by testing health and fitness components. The study was showed on a sample of 50 players; in these twenty five players of international school and other were convent school players with mixed boys and girls. In the test, muscular endurance, muscular strength, respiratory endurance, flexibility and body composition were included for assessment. The samples were included with use of T test and statistics between players for final difference and compare ability of their health related fitness. Age grouping from 14 to 18 years was selected as the sample. The final result of this study showed that international school players had better and more fitness level and health related components than convent school players in most of the activity. It was also checked that the body composition was more reliable than convent school players.

**Keywords** - International school and convent school players, fitness checker tape, watch, and all compulsory equipments.

**Introduction** - The capacity to show daily activity with good quality and using it is suddenly necessary and when needed is called fitness. It is bear up and collects in rotational where unfit people couldn't work properly because unfit person are unhealthy. Fitness is ability to work and function of all parts of the body perfectly, it involves of respiratory system, heart system and physiology of the body. Health related fitness is to develop the energy supply system to take any activity. It is developed using continuous practice with daily workout. Endurance is the capacity to supply gases and food to muscle and clear wastes of maximum time periods. Strength is the capacity of body to put a power in the short period and re generated of next step with same effort, flexibility is the action and movement of body and joints with help of their maximum range of motion for long period of time. All the components of health related fitness needs use of oxygen supply, and work capacity increase without any diseases. It is also increase and gain immune power of body system for prevention communicable diseases like covid 19 because they work with body to kill virus and throw out useless item out of the body and never come near the system of the body. The healthy body without undue stress always has more energy and capacity because all parts of body are fit and fine with average ideal weight and height of the body. Low levels of health and fitness are both chance of maximum disease and problem surrounding the body. Many factor influencing health related fitness. Age is most effective factor that influences fitness and health, the body and capacity in term of physical fitness depends on the

development and function of their bones, muscle, organs. Health related fitness is very essential part of our body. Healthy body and fitness make a healthy environment. It is not only body fitness and health but much more activity and growth of body part. The power of country depends on the healthy population and for the progress of country. It is human demand and right of people to maintains their health related fitness for current demand of situation. Fitness is a trait of physical, psychological, cognitive, social and body well being. The real aim of health related fitness is to maintain and increase many activities related to life activity and principle of right style of living. It is work with soundness of part and health situation. Fitness is way of life for functioning of muscle properly and accurately in all difficult and vigor situation. When you are healthy your body system work properly and actively, in this cardio vascular endurance is the quality of heart to give a proper flow of oxygen to the respiratory system of more time period, in the muscular endurance shows that your muscles are fit and fine and work long time and involve muscular activity like push-ups, sit-ups maximum repetition to developing a given time. it also explain the quality and function of the muscle to extra repeated of power over a long period of time, muscular strength explain the quality of the muscles to pass power and strength at upper capacity over quick time period, flexibility is a function of the body to move and change their location with full boarder of movement, body composition can be explained as a lean body mass and fat body mass in a good body with perfect part of all body organ.

**Objectives Of The Study** - The hypothesis taken by the researcher is that the international school players are still better in health related fitness than convent school players in most of the activity and test. The study was conducted for checking fitness level and health condition of different high school players of Ujjain division in Madhya Pradesh. Sampling method was used to collect the data for the present study and test assessment.

#### Variables

**Independent-** Climate condition, food habit, family background, interest, motivational level and habit.

**Dependent** - t test, sit and reach box, running ground, stop watch, tape.

**Methodology** - It is to conduct this study in a proper way and sequence. 50 players were taken as sample for the study in which 25 students from international school and 25 from convent school level of Ujjain division, Madhya Pradesh. The selection age group was between 14 to 18 years in selected school for this study. The process of measuring data for testing samples were the score taken from the health related fitness test score of three test process. The fitness was measured by using sit-ups test, 600 yard run and Sit and reach test. In this we were checked health related fitness components like cardio vascular strength, strength endurance, flexibility and body composition. The following health related fitness criteria for measuring sample result.

**Table 1: selected item, their tests are given.**

S.	Measurements	Test	Unit
1	Strength Endurance	Sit Ups	Count Number
2	Respiratory Endurance	600 Yard Run	Time In Minute
3	Flexibility	Sit And Reach	C.M.

**Table 2 (see in next page)**

**Statistical Analyses** - Samples are presented as standard deviation and mean values and comparison of data for final result that t test were used to analyze for difference between both school player results. Data was analyzed with use of spss software. Table 2 show that significant difference was found between international school and convent school players in respect to all three test as in sit-ups test mean difference was found 11.38 with t test result was found 3.32, in 600 yard run mean difference was 0.98 with t value 1.22 and in sit and reach test mean difference were 9.56 with t test result 1.27 was showed at level of significance 0.05 level.

**Conclusion** - This study bring awareness during a present situation. The main aim of this was study understand the health related fitness essential for health at that time with importance of lifestyle with good living. It is helpful to clearly explain up and down level of body fitness in related to health. The more demand of fitness and healthy lifestyle in the present time. Fitness testing is mix up health related fitness there were increased fitness level and decreasing risk of injury and any communicable disease like covid 19 and

other harmful disease. The study shows all the fitness components are very useful and essential for fitness level. The test represents valid, reliable and successful assessment of related health and body system. Cardio vascular system shows the ability to tackle of big muscles and system in the demand of high speed with resistance of continuous workout. Flexibility is range of muscle increase with shortest time period. It shows that demand of different action with the Sit and reach test show develop, measure of validity and reliability. The present study shows and proof that significant difference was found between international school players and convent school players of Ujjain division, Madhya Pradesh in high school level health related fitness issues. The international school level players moving with better mean value because their diet chart and fitness level related to health was upward and better than convent school level players and they were more active and had good stamina in physical activity. Successful difference was found between international school players and convent school male students in most health related fitness, international school players were showing superb and fitted health related fitness comparison to convent players. This study shows relationship between fitness and health with positive impact of body stamina due to healthy living style. Today we are facing more danger as communicable disease with less of immune system result show more taken positive action in this type of body person so that time we need more capacity and good immune system for prevention and safety of body to fight against this type of virus. we understand all the things in the level of school is passed after primary grade so we should more aware of health related fitness in this age and also make aware all nearby person for their safety with use of proper fitness level and maintain health with use of exercise and physical activity. Regular physical workout and healthy diet can give better health and wellness, also free of all types' problems and tension. it is also beneficial for mental relaxation, it is also growing in children in all activity. This is real and true that human being are not aware to understand the meaning and importance of health related fitness and human being is not interested to health fitness. It is a must need to all community to take a part as soon as possible for their health related fitness. Good knowledge regarding health and immune help to fight again current diseases pandemic "covid 19".

#### References :-

1. Arvind V Patil, "Comparative Study of Cardiovascular Efficiency between National Cadet Corps and Physical Education Students at Undergraduate Level", Journal of Sports and Sciences, 2007, Vol.30 No.20. PP. 45-48
2. H. Clark, & D.H. Clarke, "Application of Measurement of physical Education, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc, p147 .1987
3. Baird D.W.E. (1977) Controlled Exercise For Physical Fitness, Washington: The Executive Club

4. Gupta A.K. (2003), Test and Measurment in Physical Education Sports Publication, Ashok Vihar, Delhi.
5. Mayhew, Jerry L. "Body Composition," JOPERD 52.7 (1981): 38-40.
6. Punit Vajubhai Teraiya, Sharirik Shixa Ke Siddhant, New Delhi, Jashveer Publication, 2011.
7. Dr. ajmer singh, essentials of physical education, New Delhi, Kalyani Publication, 2009.

**Table 2: comparison of health related fitness by different test with their result find.**

COMPONENTS	INTERNATIONAL		CONVENT SCHOOL		MEAN DIFFERENCE	TOTAL PLAYERS	T-RESULT
	MEAN	SD	MEAN	SD			
SIT-UPS	38.28	190.5	27.32	102.2	11.38	50	3.32
600 YARD	1.9	8.5	2.88	9.69	0.98	50	1.22
SIT AND REACH	36.28	750	26.72	667	9.56	50	1.27

\*level of significance at 0.05

\*\*\*\*\*



# Preventive Steps To Minimize, Soil Degradation By Fertilizers And Pesticides

Dr. Vaishali Lal\* Dr. Arun Sikarwar\*\*

**Abstract** - Fertilizers and Pesticides deteriorate the quality and mineral content of soil and disturb the biological balance of organisms in the soil. Causes of land pollution include an increase in urbanization, domestic waste, dumping industrial waste on land and improper agricultural activities. We can prevent land pollution by minimizing or eliminating waste at the source and substituting nontoxic options for hazardous materials.

**Introduction** - Plants require 16 essential elements for their normal growth and yield, out of which 13 are provided by soil. Nitrogen, phosphorus and potassium are referred as primary nutrients because they are required by the plants in highest quantities (Hodges 1995 ). Continuous crop cultivation leads to depletion of these nutrient reserves in the soil and thus they need to be regularly replenished in order to maintain their optimal supply for the crops. The most common mode adopted by man for supplying the nutrients in cultivated soils has been the use of chemical fertilizers , primarily nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K) fertilizers.

Fertilizer has been defined by soil science society of America as “any organic or inorganic material of natural or synthetic origin, other than liming materials that is added to soil to supply one or more plant nutrients essential to the growth of plants”.

In accordance with the rising food productions, chemical fertilizer supply has been continuously increasing with time. Global fertilizer consumption of arable and permanent crop area has increased from 79.29 tones/1000 Ha in 2002 to 98.20 tones/1000 Ha in 2010 and the demand for total fertilizer nutrients has been estimated to rise further at 1.9 % per annum from 2012 to 2016. China and India are the world's leading consumers of chemical fertilizers (N, P, K) while highest production of the same is reported in China, USA and India in that order (FAO 2012 ). So, fertilizers may be seen as an indispensable part of modern agriculture . The effects of chemical fertilizers on soil properties and microflora have been discussed in the following paragraphs.

### 8.3.1 Effects of Fertilizers on Soil Properties

Long-term application of nitrogen-phosphorus-potassium (NPK) based fertilizers has a pronounced effect on the biochemical properties of soil which in turn leads to shift in microbial populations. Changes in soil organic carbon (SOC), nitrogen (N) content, pH, moisture and thus

the variation in nutrient availability to microbes have been observed due to long-term fertilizer use in a variety of crops like wheat, corn and others (Bunemann and McNeill 2004 ; Bohme et al. 2005 ; Wu et al. 2012 ). In contrast to chemical inputs organic amendments in soil have been proven to favourably affect various soil properties and functions. For example organic inputs tend to enhance SOC and N content more significantly than chemical fertilizers and thus lead to higher microbial populations. Sradnick et al. ( 2013 ) established the variation in soil pH and SOC content due to fertilization as the basis of difference in the catabolic profiles of soil microorganisms of a sandy soil that had received long-term mineral fertilizer and cattle manure treatments. On the basis of community level physiological profile it was found that functional diversity of soil microorganisms was higher in manure treated soil as compared to mineral fertilized soil.

Activities of soil enzymes like dehydrogenase, α-glucosidases, alkaline phosphatases and proteases are important indicators of soil fertility and microbial activity (Casida et al. 1964; Nannipieri et al. 1990). Evidences are there that long-term application of organic manure enhances the dehydrogenase activity (DHA) as well as microbial biomass while NPK fertilizers do not have a positive influence on this.

Further, it has been observed that copper which is a normally found contaminant in soil as a result of irrigation or application of fertilizers and pesticides, adversely affects the soil dehydrogenase activity and this effect is more pronounced in NPK treated soils as compared to organic-manure treated soils (Xie et al. 2009b ). In contrast to this, application of microbial fertilizer based on *Azotobacter chroococcum* has been reported to increase the dehydrogenase activity and favourably alter the bacterial and fungal community diversity in the rhizosphere of wheat (Shengnan et al. 2011 ). Other soil enzymes like α-

\*Department of Chemistry, Govt. Home Science P.G. College, Hoshangabad (M.P.) INDIA

\*\*Department of Chemistry, Govt. Home Science P.G. College, Hoshangabad (M.P.) INDIA

glucosidases, alkaline phosphatases and proteases have also been found to be positively affected in organically treated soils as compared to treatments with inorganic fertilizers (Bohme et al. 2005 ).

Pesticides are generally toxic and xenobiotic in nature and a huge number of microbes die in their presence. However, continuous application of these toxic chemicals in the soil generates stress which leads to development of resistance and adaptation among the local microbial populations. Degradation of pesticides is the breaking down of toxic chemicals into non-toxic compounds and, in some cases, back to their original elements. Most commonly found mode of pesticide degradation in soil is through microbial activity particularly that of fungi and bacteria (Vargas 1975 ). A number of pesticides that may be used as a source of energy or Nutrient are transformed or degraded by soil microbes (Tancho et al. 1992 ;Ishaq et al. 1994 ; Megadi et al. 2010 ; Mohamed et al. 2011 ). At the same time many other pesticides which cannot serve as an energy or nutrient source for soil microflora may also be degraded by microorganisms through the process of cometabolism (Bollag and Liu 1990 ). Hence, in many cases where the applied pesticide is utilized as a source of carbon, energy and others nutrient elements by soil microorganisms, higher pesticide dosage tend to increase the bacterial and fungal population when applied for longer duration. For example, insecticide diazinon and herbicide linuron were reported to significantly improve the number of heterotrophic bacteria as well as fungi in soil after 28 days when concentration was gradually increased from 15 mg/kg of soil to 1500 mg/kg of soil (Cycon and Piotrowska-Seget 2007).

Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT), an organochlorine compound was once most popularly used agricultural pesticide world over. Though currently it has been banned in most of the countries still it is used in many developing countries for agricultural as well other usages such as mosquito control. Thus, high levels of this compound are many times found in soils.

Degradation and sorption are both factors which influence the persistence of pesticides in soil. Depending on the chemical nature of the pesticide, such processes control directly the transportation from soil to water, and in turn to air and our food. Breaking down organic substances, degradation, involves interactions among microorganisms in the soil. Sorption affects bioaccumulation of pesticides which are dependent on organic matter in the soil. Weak organic acids have been shown to be weakly adsorbed by soil, because of pH and mostly acidic structure. Adsorbed chemicals have been shown to be less accessible to microorganisms. Aging mechanisms are poorly understood but as residence times in soil increase, pesticide residues become more resistant to degradation and extraction as they lose biological activity.

According to a report of FAO, world population is growing at a rate of 160 persons per minute and we need

to produce 70 % more food for an additional 2.3 billion people by 2050. Agriculture is the fundamental mode to satisfy the food demands of mankind and soil is the only medium to practice agriculture. Maintenance of soil quality and fertility is thus most critical to satisfy the world food demands. In the last century extensive innovations and improvements have been made with respect to agricultural practices and productions. A basic approach for this has been the introduction of new and improved crop varieties and use of chemical based agents in order to enhance nutrient availability to crops as well as to protect the crops from all kind of pests. As a result of this, modern agriculture has become capital, chemical and technology intensive. While it has been successful to a large extent in keeping pace with the growing food demands, however this has ended up in a number of economic, environmental and social problems.

### Experimental Work

**1. Sample Collection** - Soil sample should be taken from the field before sowing the next crop or after harvesting the standing crop. Remove organic materials like dried leaves and small pieces of woods etc. from the soil surface. Dig out a pit of "V" shape of 20 cm length and width, and 15 cm depth. Take out the soil-slice (like bread slice) of a inch thick from both the exposed surface of the pit from top to bottom. This slice is also termed as furrow-slice. To collect soil slice spade may be used. We have collected 20 soil samples from a village district Hoshangabad (MP) India.

### 2. Preparation of samples for analysis

**Drying:** Wet soil sample should not be stored as changes may occur in the chemical nature of certain ions and organic matter. Samples are generally air dried at temperature (25°C to 35°C) and relative humidity (20-60%) then after are stored. Fresh samples from the field without any drying are required. For certain determinations such as ammonium and nitrate N, exchangeable K, acid extractable P and ferrous iron fresh sample from the field without any drying are required. Results of soil analysis are expressed on oven dry weight basis.

**Sieving:** Field moist samples prior to drying can be made to pass through a 6 mm sieve (about 4 mesh per inch) by rubbing with fingers. The practice seems of much advantage in case of heavy soils. Soil in the right moisture condition can be passed through a 2 mm sieve (about 10 mesh per inch). The common practice of sieving a portion of the gross sample through a 2 mm sieve and discarding the rest is undesirable as it increase the concentration of most of the elements involved in soil fertility. When the gravels in the soil exceeds 2% limit over a 2 mm sieve their exact percentage should be recorded.

**Grinding:** A roller, rubber pestle in an agate mortar, or a motorized grinder is commonly used. Crushing of the gravel or primary sand particles should be avoided for heavy soils, it is better to pass these through a 2 mm sieve before allowing them to get completely air dried.

**Mixing:** Sample should be thoroughly mixed by rolling

procedure. Place the dried ground and sieved sample on a piece of cloth. Hold all the four corners of the cloth and then up the one corner and down the other corner across the sample alternatively. Now repeat the process in the reverse direction to roll the soil from one corner to another. Continue this until thorough mixing is assured.

**Storage:** Store the soil in paper carton (soil sample box) using a polythene bag as in inner lining. Label the carton mentioning cultivators name, plot number, date of sampling and initials.

3. Different parameters have determined with the help of "Mrida Parikshak" a spectrophotometric instrument developed by Indian Council of Agricultural Research and Indian Institute of Soil Science, Bhopal, MP

**Result & Discussion** - We have determined various parameters pH value, EC, Organic Carbon (OC), Nitrogen, Iron, Manganese, Copper, potassium, Sulphur, Phosphorus and Boron. Which are in the table 1.

#### Table 1 (See in next page)

pH value found maximum 8.85 for sample no.20 and minimum 8.18 for sample no. 02. Electrical conductivity reported maximum 1.28 for sample no.16 and Minimum 0.17 for sample no. 20. Organic carbon reported maximum 1.94% for sample no.14 and minimum 0.64% for sample no. 07. Nitrogen found to be maximum 395.1 kg/haq for sample no. 14 and minimum 210.8 kg/haq for sample no.07. Phosphorus value found maximum 84.90 kg/haq for sample no.19 and minimum 9.83 kg/haq for sample no. 09., Potassium value found maximum 567.8kg/haq for sample no.05 and minimum 192.8kg/haq for sample no. 15, Sulphur value found maximum 117.00Mg/Kg for sample no.03 and minimum 5.0 Mg/Kg for sample no.20, Iron value found maximum 8.17 Mg/Kg for sample no.19 and minimum 1.90 Mg/Kg for sample no. 07, Boron value found maximum 2.11 Mg/Kg for sample no.03 and minimum 0.09 Mg/Kg for sample no. 12, Manganese value found maximum 61.10 Mg/Kg for sample no.03 and minimum 12.10 Mg/Kg for sample no. 17 and Copper value found maximum 3.65 Mg/Kg for sample no.12 and minimum 0.74 Mg/Kg for sample no. 01 respectively.

**Conclusions** - Reported data shows that Nitrogen and pH found in higher range, thus we need to educate farmers and organize awareness campaign. Thus Soil Pollution can be prevented with help of following methods -

**Reducing Chemical Fertilizers and Pesticides** - The use of fertilizers and pesticides in agriculture, however, leads to other problems. Some raw materials can contaminate the soil. For instance, copper and boron in fertilizers, and organochlorine in pesticides, can harm the environment and create health risks when products are used in wrong proportions or over a long period of time. To prevent such damage, farmers should use composted manure and bio-fertilizers — biologically active products such as algae and bacteria that can help initiate nitrogen fixation in soil.

**Reforestation** - Forests and grassland vegetation bind soil to keep it intact and healthy. They also support many habitats

that contribute to a complete ecosystem. Construction, cutting of timber and mining, on the other hand, leave the soil bare and expose land to contaminants. Restoring forests by planting more trees protects the land from floods and soil erosion. It also improves the fertility of the land and increases biodiversity.

**Solid Waste Treatment** - Dumping solid waste such as domestic refuse, garbage and industrial materials on land increases the level of toxicity and hazardous substances in soil. Waste also alters the chemical and biological properties of soil such as its alkalinity levels. Through chemical treatment methods such as acid-base neutralization, municipalities can alter the pH level of solid waste before dumping it in landfills. Degrading insoluble waste by using methods such as adding chemicals or enzymes under a controlled environment before disposing of it also reduces land pollution.

**Recovering and Recycling Material** - To reduce solid waste pollution on land, you can reuse materials such as cloth, plastic bags and glass in your home rather than disposing of them. By recycling, you reduce the amount of solid refuse going to landfills and also make a contribution toward saving natural resources. For example, according to the U.S. Environmental Protection Agency, when a company recycles 1 ton of paper, it saves an equivalent of 17 trees.

#### References :-

1. Bohme et al. Nat. Neurosci. 19(10), 1311-1320, 2016..
2. Belluck, D.A., Benjamin, S.L., Baveye, P., Sampson, J., Johnson, B. 2003. Widespread arsenic contamination of soils in residential areas and public spaces: an emerging regulatory or medical crisis? International Journal of Toxicology 22: 109-128.
3. Andre Srandnick et al. Biology and Fertility of Soil 50(1) 2013.
4. Dr ArunSikarwar, Dr. Usha Mudaliar, Dr.Vaishali Lal, Soil Fertility & Productivity in Hoshangabad District, Shodh Samagra (2016).
5. <http://www.imnh.isu.edu/digitalatlas/hydr/basics/main/chmtxt.htm>
6. Agriculture and Natural Resources (Soil and Land) Revised October 2011.
7. Acharya SM, Collection and preparation of soil, water and plant samples for analysis, IJCS 2018.
8. Richardson, G.M., Bright, D.A., Dodd, M. 2006. Do current standards of practice in Canada measure what is relevant to human exposure at contaminated sites? II: oral bio accessibility of contaminants in soil. Human and Ecological Risk Assessment 12: 606-618.
9. Okrent D., On intergenerational equity and its clash with intergenerational equity and on the need for policies to guide the regulation of disposal of wastes and other activities posing very long time risks. Risk Analysis 19: 877-901.
10. Chen Shengnan et al. African Journal of microbiology Research 5(2), 137-143, 2011.

Table 1

S.	pH	EC ms/cm	OC %	N kg/haq	P kg/haq	K kg/haq	S mg/kg	B mg/kg	Fe mg/kg	Mn mg/kg	Cu mg/kg
1	8.28	0.57	1.38	315.7	26.81	433.4	51.00	1.01	2.91	20.60	0.74
2	8.18	0.60	1.09	270.4	23.23	390	26.00	0.55	2.35	27.40	1.21
3	8.47	0.64	1.41	318.8	78.65	329.4	117.00	2.11	5.82	61.10	1.02
4	8.28	0.60	1.03	260.8	15.19	524.4	16.00	1.15	2.68	30.50	0.84
5	8.28	0.61	1.27	299.8	31.28	567.8	25.00	1.38	3.24	37.70	1.59
6	8.28	0.62	1.23	293.4	82.22	420.4	47.00	1.28	7.50	15.70	2.90
7	8.18	0.84	0.64	210.8	33.06	400.9	23.00	1.19	1.90	29.60	0.84
8	8.28	0.61	1.79	372.8	83.11	528.7	33.00	1.47	6.38	60.30	2.99
9	8.37	1.08	1.12	277.5	9.83	561.3	17.00	0.82	3.36	31.40	1.31
10	8.18	0.85	1.20	290.2	19.66	472.4	14.00	1.01	3.92	21.10	0.84
11	8.37	0.86	1.18	287.1	14.60	528.7	27.00	0.00	3.80	17.50	0.74
12	8.37	0.61	1.27	299.8	21.45	368.4	20.00	0.09	3.47	16.60	3.65
13	8.47	0.80	1.41	318.8	52.73	500.6	27.00	0.64	7.28	53.50	1.68
14	8.18	0.74	1.94	395.1	18.76	518.3	33.00	0.09	4.92	48.50	3.27
15	8.56	0.70	1.72	363.3	49.36	192.8	47.00	0.36	7.05	57.10	2.05
16	8.47	1.28	1.43	287.1	19.66	507.1	24.00	0.18	2.80	39.50	1.21
17	8.37	0.69	1.18	287.1	10.72	400.2	62.00	0.73	4.48	12.10	3.65
18	8.66	0.46	1.47	328.4	45.58	210.2	38.00	1.84	8.06	26.00	2.53
19	8.56	0.66	1.43	322	84.90	487.6	33.00	0.36	8.17	58.90	1.59
20	8.85	0.17	1.45	325.2	15.19	446.4	5.00	0.00	2.57	29.20	1.68

\*\*\*\*\*



## किशोरावस्था में समायोजन

श्रीमती कृष्णा शर्मा \*

**प्रस्तावना** – आधुनिक युग भौतिक सुख सुविधाओं का युग है। शिशु से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक प्रत्येक अनेकानेक सुख कि कामना करता है। इन सुखों के लिए उसे प्रत्येक क्षेत्र में समायोजन करना पड़ता है। यह समायोजन सभी के विकास के लिए अति-आवश्यक है। सामान्यतः किशोरावस्था के विद्यार्थियों के समायोजन में बड़ी कठिनाइयां होती हैं। वे इन कठिनाईयों के कारण अपना उचित समायोजन नहीं कर पाते।

आज आवश्यकता है भावी पीढ़ी आदर्शवान बने उनके समायोजन में परिवार एवं समाज का विशेष निःस्वार्थ सहयोग मिला। उन्हें समझे उनके सामने अपने आदर्श रखें। उनके क्षरा होने वाली छोटी-छोटी भूलों, त्रुटियों की ओर ध्यान न दें। हम स्वस्थ समाज का निर्माण करें। आवश्यकता है किशोरावस्था के विद्यार्थियों के समायोजन में हम अपने अहं का त्याग कर उनमें पनपते हुए नैतिक गुणों का विकास करें।

किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होता है इसी कारण सम्भवतः वह अपनी नई दिशा, नई अवस्था के नये रोल के साथ समायोजन नहीं कर पाता है। फलस्वरूप वह भ्रमित अनिश्चित चिन्तित और उत्सुक होता है। यह अवस्था अत्यंत जिज्ञासु होती है। अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति के लिए वह उत्साहपूर्वक श्रम करता है। जब इनकी पूर्ति नहीं होती तो वह समायोजन नहीं कर पाता, अर्थात् चिन्ताग्रस्त रहता है।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि समाज के बड़े-बड़े अध्यापक इन किशोरों की समस्याओं को भली-भांति समझे। इनके साथ मित्रवत व्यवहार करें। उनमें नैतिक मूल्य भली-भांति विकसित हों। उनके सामाजिक एवं शैक्षिक समायोजन में परिवार, समाज व शिक्षक की अहं भूमिका हो। हम जानते हैं कि आज का छात्र (किशोर) कल का भावी आदर्श नागरिक है। उनकी ऊर्जा को सही दिशा मिले ताकि समाज का उत्तरोत्तर विकास हो सके। न जाने इन किशोरों में कितने ऐसे श्रेष्ठ होंगे जिन पर हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र गौरव की अनुभूति करेगा। जब हम इन्हें नहीं समझ सकेंगे तो ये छात्र-छात्राएँ कल हमें और राष्ट्र को क्या समझ सकेंगे। इन्हें निष्चय या आश्चर्यजनक दृष्टि से देखकर अपना सहयोग व प्रोत्साहन दें, वास्तव में किशोरों का सही निमाण है।

अवयस्क और नाबालिग किशोरावस्था के विद्यार्थी जिन्हें राजनीति के भ्रष्टाचार से दूर रखना चाहिए। कुछ स्वार्थी राजनेता समाज-सुधारक इन्हें उठाने की बजाए और नीचे ढकेल रहे हैं।

उचित मार्गदर्शन का अभाव में किशोरों में घोर निराशा व अनुशासनहीनता पनप रही है। अतः वह अपना समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनके नैतिक मूल्य भी प्रभावित हो रहे हैं। किशोरावस्था के विद्यार्थियों को निराशा, अरुचि, अविश्वास पनप रहा है। वे कौन से

कारण हैं, जिनके कारण किशोरावस्था के विद्यार्थी अपना उचित समायोजन नहीं कर पा रहे हैं। इसी जिज्ञासा के कारण मैंने यह निश्चय किया है कि उन तथ्यों को जानें, जिनके कारण किशोरों के सामने समायोजन की विकराल समस्या उत्पन्न हो रही है।

**परिभाषा** – आइजेनेक और उनके साथियों (1972) ने किशोरावस्था को परिभाषित करते हुए लिखा है कि 'किशोरावस्था वयः संधि के बाद की वह अवस्था है, जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन होता है।' किशोरावस्था को दो भागों में बाँटा गया है:-

1. **पूर्व किशोरावस्था** – यह अवस्था 13-14 वर्ष से लेकर 16-17 वर्ष तक की है। लड़कियों में यह अवस्था तेरह वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है तथा लड़कों में यह लगभग एक साल बाद प्रारंभ होती है।

2. **उत्तर किशोरावस्था** – यह सोलह या सत्रह वर्ष से इक्कीस वर्ष के बीच की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक-बालिकाओं में विशेष नयापन मूल्यतः शारीरिक परिवर्तन (यौन, परिवर्तता) आता है, साथ में किशोरियों की अनेक समस्याएँ भी होती हैं। इस प्रकार के आयु के बच्चों को परिवार के साथ समायोजन, विद्यालय में समायोजन, संवेगात्मक तथा सामाजिक समायोजन की समस्याएँ आती हैं।

**किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएँ :**

1. पूर्व किशोरावस्था के किशोर की स्थिति अस्पष्ट होती है।
2. यह कमुकता के जागरण की अवस्था है।
3. निश्चित विकास प्रतिमान।
4. किशोरावस्था एक परिवर्तन अवस्था है।
5. किशोरावस्था अस्थिरता की अवस्था है।
6. किशोरावस्था समस्या – बाहुल्य की अवस्था है।
7. यह विकसित सामाजिकता की अवस्था है।
8. यह एक उमंगपूर्ण कल्पना की अवस्था है।
9. किशोरावस्था शैषवावस्था की पुनरावृत्ति है।
10. किशोरावस्था एक दुःखदायी अवस्था है।

किशोरावस्था में सामाजिक विकास का बहुत महत्व है। किशोर को समाज के आदर्शों और मूल्यों को समझने के साथ-साथ आवश्यक है कि वह समाज के विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों, विचारों और भावनाओं को समझना सीखे।

जब तक वह इनको नहीं सीखेगा, तब तक उसके लिए समाज की विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन करना कठिन होगा। यह समाज में सम्मान तभी प्राप्त कर सकता है, जब उसका व्यवहार समाज के आदर्शों और मूल्यों के अनुरूप हो तथा साथ ही साथ उसका व्यवहार समायोजित भी हो।

समायोजित और समाज के अनुरूप व्यवहार करने के लिए आवश्यक है कि किशोर में सामाजिक परिपक्वता हो।

**समायोजन-** प्रायः जीवन के समस्त पहलुओं में समायोजन आवश्यक होता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में शामिल होने के लिए व्यक्ति में स्वयं को भली-भांति समायोजित करने की क्षमता होना चाहिए।

तनावपूर्ण स्थितियों में वह किस प्रकार शामिल है, इसका उसे ज्ञान होना चाहिए, उसे ऐसी परिस्थितियों से दूर करना चाहिए जो असमायोजन को प्रोत्साहन देती हो।

अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि 'जीवन का दूसरा नाम ही समायोजन है।'

### समायोजन की प्रक्रिया के मुख्य तत्व :

1. जीवन की आवश्यकता।
2. इन्हे प्रभावित करने वाली परिस्थिति (कारक)।

जीवन की आवश्यकता समाज-जनित, जैव-जनित, व्यक्तिगत, समूहगत किसी भी प्रकार की हो सकती है। व्यक्ति की अपनी शारीरिक एवं मानसिक स्थितियाँ, सामर्थ्य अभिरूचियाँ आदि इन आवश्यकताओं को प्रभावित करता है।

समायोजन की समस्या का उद्भव प्रायः परिवेश में जन्म होता है। बालक अपने परिवेश में जिन व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं के सम्पर्क में आता है, उनसे रहन-सहन, बोल-चाल आदि सीखता है।

**बोरिंग के अनुसार (1962)** - 'समायोजन वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जीव अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में सन्तुलन रखता है।'

**आननेक के अनुसार** - 'यह वह अवस्था है, जिसमें एक और व्यक्ति की आवश्यकताएँ तथा दूसरी ओर वातावरण के अधिकारों में पूर्ण संतुष्टि होती है अथवा यह वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा इन दो अवस्थाओं में सामंजस्य प्राप्त होता है।'

### समायोजन के प्रकार :

1. **रचनात्मक समायोजन** - इस प्रकार के समायोजन में व्यक्ति परिस्थितियों से पलायन नहीं करता है बल्कि ऐसे उपाय करते हैं कि कठिनाईयाँ दूर हो जायें।
2. **स्थानापन्न समायोजन** - यह समायोजन अस्थिर प्रकृति का होता है। इस प्रकार के समायोजन से यह संतोष प्राप्त नहीं होता, जो कि रचनात्मक समायोजन से प्राप्त होता है।
3. **मनोरचनार्य समायोजन** - कठिनाईयों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने का एक ओर सामान्य ढंग मनोरचनार्य है।

### समायोजन कई प्रकार के क्षेत्र है :-

1. पारिवारिक समायोजन
2. स्वास्थ्य समायोजन
3. शैक्षणिक समायोजन
4. सामाजिक समायोजन
5. संवेगात्मक समायोजन

1. **पारिवारिक समायोजन** - सर्वप्रथम घर में ही बालक का समायोजन आरंभ होता है। माता-पिता बालक में उनकी समस्याओं को खोजते हैं और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं।

2. **स्वास्थ्य समायोजन** - बच्चों के शारीरिक समायोजन पर काफी अध्ययन किया गया, जो अच्छे स्वास्थ्य वाले होते हैं उनका शारीरिक

समायोजन भी अच्छा होता है।

3. **सामाजिक समायोजन** - टरमन ने 1919 में यह पाया कि जिन बच्चों की बुद्धि अच्छी है, उनमें निर्भरता की भावना काफी मात्रा में पाई जाती है। अच्छी बुद्धि वाले बालक समूह का नेतृत्व कर सकते हैं, जो मंद बुद्धि के बालक हैं, उनमें नेतृत्व का अभाव पाया जाता है।

4. **संवेगात्मक समायोजन** - विभिन्न बौद्धिक स्तर पर संवेगात्मक विशेषताओं को जानने के लिए विभिन्न बौद्धिक स्तर वाले बालकों में ज्यादा ज्ञान होता है उनमें तर्क शक्ति अधिक होती है वे अपनी समस्याओं को खुद हल कर लेते हैं।

5. **शैक्षिक समायोजन** - जो बालक अच्छी बुद्धि के होते हैं, वे अपनी कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। उनका शैक्षिक समायोजन अच्छा होता है शिक्षकों के सामने जाने से कतराते हैं।

### समायोजन को निम्न तत्व प्रमाणित करते हैं :-

1. आकांक्षा
2. सामाजिक आर्थिक स्तर
3. शहरी एवं ग्रामीण जीवन
4. चिन्ता
5. कुण्ठा
6. संवेगात्मकता
7. संरक्षकों की प्रतिष्ठा
8. पारिवारिक वातावरण
9. विद्यालय का वातावरण
10. व्यक्ति का स्वास्थ्य
11. मनसिक योग्यतायें
12. बुद्धि
13. शैक्षिक उपलब्धि
14. आत्म प्रत्यय

### समायोजन की प्रक्रिया :

1. समायोजन की प्रक्रिया के व्यक्ति अपने जैविक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। उसकी जो प्राकृतिक एवं द्वितीयक आवश्यकता है वे उसके प्रयत्नों से पूरी होती है लेकिन यह तभी संभव है जबकि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के विषय में जानकारी हो।
2. व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति सरलता से नहीं कर पाता इसके कारण उसके मन में निराशा उत्पन्न होती है अनेक बाधाओं के कारण वह अपनी बाधाओं कारण वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है। फलतः वह कुण्ठाग्रस्त हो जाता है व्यक्ति अपनी कुण्ठाओं को किस प्रकार दूर करता है।
3. यदि व्यक्ति की आंतरिक शक्ति एवं दृष्टिकोण परिस्थितियों के अनुसार है तो वह अपनी कुण्ठा एवं निराशा से मुक्त हो जाता है।

जब व्यक्ति में कठिन परिस्थितियों के कारण समायोजन की संभावना नहीं रहती तब व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। और उसके व्यक्तित्व में असमानता दिखाई पड़ती है। लोग कुण्ठाओं एवं द्वन्द्वों के कारण मनःस्तापी बन जाते हैं और उनका व्यवहार सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय माना जाता है।

### श्रेष्ठ समायोजन के लक्षण :

1. एक समायोजित व्यक्ति अपनी परिस्थिति का तिरस्कार नहीं करता है।

2. वह दूसरों के साथ सहानुभूति रखता है।
3. उसके विचार, प्रतिक्रियायें, भावनायें और व्यवहार एक समान्य व्यक्ति के अनुभव हैं।
4. वह अपनी समस्या के प्रति ध्यान केन्द्रित नहीं करता, वरन् अन्य बातों पर भी ध्यान देता है।
5. वह एक या दो व्यक्ति के सम्पर्क में नहीं रहता उसका सामाजिक क्षेत्र

विस्तृत होता है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. सीताराम जायवाल - 'समायोजनात्मक मनोविज्ञान'
2. डॉ. एच. के कपिल - 'अनुसंधान विधियां'
3. प्रीति वर्मा डॉ. एन. श्रीवास्तव - 'बाल मनोविस्सप एवं विकास'

\*\*\*\*\*

## बालश्रम एवं नियमन एक अलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन

**डॉ. विश्वास चौहान\* गीता परतेती\*\***

**प्रस्तावना** – विश्व के विकसित देशों में तो इस समस्या पर एक सीमा तक तो काबू कर लिया गया है लेकिन विकासशील देश अब भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। भारत भी उन्हीं विकासशील देशों में से एक है जहाँ बाल श्रम की समस्या बड़े पैमाने पर विद्यमान है क्योंकि विश्व का सर्वाधिक बाल श्रम भारतवर्ष में पाया जाता है।

बाल श्रम समस्या एक विश्वव्यापी संवृत्ति है और कमोवेश सभी जगह पाया जाने वाला रोग है। अधिकांश बच्चे कृषि में कार्य करते हैं तथा बाल श्रम अधिनियमों का उल्लंघन भी होता है और बाल श्रमिकों का शोषण होता है, वे रोजगार की खतरनाक परिस्थितियों के जोखिम उठाते हैं। कई घण्टे काम करने के बदले उन्हें अल्प वेतन दिया जाता है। शिक्षा को छोड़ने के लिए बाध्य होकर, अपनी आयु से कहीं अधिक दायित्वों का निर्वाह करते हैं, उस आयु में दुनियादार बनकर जब कि उनकी आयु के अन्य बालकों को अभी अपने माता-पिता की सुरक्षा के कवच को छोड़ना बाकी है, ये बच्चे कभी नहीं जान पाते कि बचपन क्या होता है।

संविधान में यह प्रतिष्ठापित है कि चौदह वर्ष के कम आयु के किसी बालक को किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए या किसी जोखिम वाले रोजगार में न्युक्त नहीं किया जाएगा (धारा 24), बाल्यावरस्था और किशोरावरस्था को शोषण और नैतिक एवं भौतिक परित्यक्त से बचाया जाएगा (धारा 39 (1) तथा संविधान के प्रारम्भ होने से 10 वर्षों की अवधि में सब बालकों की, जब तक वे 14 वर्ष की आयु को समाप्त नहीं कर लेते, राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का प्रयत्न करेगा (धारा 45)। इन सब प्रावधानों के बावजूद बाल श्रम आज भी आजादी के पश्चात् भारत की एक ज्वलंत समस्या बनी हुई है।

हमारे देश में बहुत से बच्चे आर्थिक परिस्थितियों के कारण विद्यालय नहीं जा पाते हैं और किसी न किसी काम-धन्धे में लग जाते हैं। ऐसा अनुमान है कि सम्पूर्ण देश में कामगार बच्चों की संख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग व भाग है अर्थात् यहाँ पर लगभग 30 मिलियन बच्चे विभिन्न प्रकार के व्यवसायों सेवाओं में कार्यरत हैं।

ये बच्चे घरों, होटलों, रेस्तराँ, स्कूटर एवं मोटरसाइकिलों की कार्यशालाओं, कालीन उद्योग, काँच उद्योग, माचिस उद्योग, बीड़ी उद्योग, कसीदाकारी, कृषि कार्यों आदि में कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, 'हमारे बच्चे देश का भविष्य हैं।' बाल श्रम का अभिप्राय बाल श्रम को दो प्रकार से परिभाषित किया गया है—

प्रथम, वैधानिक दृष्टि से तथा द्वितीय, अवैधानिक दृष्टि से, वैधानिक

दृष्टि से बाल श्रम में उन बाल श्रमिकों को सम्मिलित किया जाता है जो न्यूनतम आयु के अवयस्क बच्चे होते हैं। कारखाना अधिनियम, 1948 के अनुसार 14 से 15 वर्ष के श्रमिकों को बालक तथा 15 से 18 वर्ष के व्यक्तियों को किशोर माना गया है। 14 वर्ष से कम व्यक्तियों की श्रम के क्षेत्र में नियुक्तियाँ निषेध की जाने के कारण इस आयु के व्यक्तियों को बाल श्रमिक नहीं कहा जा सकता। खदानों में 15 से 16 वर्ष के श्रमिकों को बाल श्रमिक कहा जाता है। बागानों में 12 से 15 व्यक्तियों को बाल श्रमिक कहा जाता है।

बाल श्रम (निषेध और नियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार एक बच्चे की परिभाषा इन शब्दों..... में दी गई है—

'वह जो 14 साल की उम्र से कम का हो,' इस प्रकार किसी उद्योग, खान, कारखाने आदि में 14 वर्ष से कम आयु के मानसिक व शारीरिक श्रम करने वाले बच्चे बाल श्रमिक कहलाते हैं। चूँकि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे इतने बड़े नहीं होते हैं कि भुगतान या मुनाफे के लिए लाभदायक आधुनिक गतिविधियों में लग सकें, इसलिए बाल श्रमिक 5-14 वर्ष आयु वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

बाल श्रमिक आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद रोजगार को प्रकट करता है, जिससे परिवार की आय में वृद्धि होती है। भारतवर्ष अन्य देशों की नलना में निर्धन देश है, जहाँ प्रति व्यक्ति व प्रति परिवार औसत आय अत्यन्त कम है। परिणामस्वरूप बालकों को भी, जब उनकी आयु खेलने पढ़ने की होती है, कार्य पर लगाकर आय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। भारत में बच्चों को मजदूरी करने के लिए जो कारण मुख्य रूप से उत्तारदायी हैं, उनमें से निर्धनता, अशिक्षा, खेती की निम्न दशा, कुटीर उद्योगों का पतन, उद्योगपतियों की लाभकारी एवं मुनाफाखोरी की मनोवृत्ति तथा अधिनियमों एवं नियमों के पालन में शिथिलता आदि प्रमुख हैं।

श्रमिक उन बुराइयों अथवा शोषणों की अभिव्यक्ति है जो कि बालकों को रोजगार में लगाने के कारण पनपते हैं। आधुनिक समय में बाल श्रम शब्द सामाजिक बुराइयों को प्रकट करता है। जहाँ तक सामाजिक बुराई या दोष का सम्बन्ध है, वह प्रत्यक्ष रूप से बालक के व्यक्तित्व विकास से सम्बन्धित है। व्यक्तित्व के विकसित न होने का परिणाम यह होता है कि इससे व्यक्ति का खुद विघटन तो होता है, साथ ही समाज एवं राष्ट्र को भी विघटन की ओर मोड़ देता है। कहा भी गया है कि, 'विघटित व्यक्तित्व समाज एवं राष्ट्र के लिए कोढ़ है।'

भारत सरकार ने समय-समय पर श्रम आयोगों तथा समितियों का गठन किया है। जिन्होंने बाल श्रम के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर उसके उन्मूलन के सम्बन्ध में सिफारिशें की हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद

\* सहायक प्राध्यापक, शासकीय राज्य स्तरीय विधि महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत  
\*\* शोधार्थी (विधि) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत



बाल श्रम के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय सोच एवं संबद्धता पर प्रकाश डालते हैं—

**अनुच्छेद 23** - जबरन मजदूरी एवं मानव के व्यवसाय पर रोक - भिक्षा मंगवाना एवं इसी प्रकार के जबरन मजदूरी तथा मानव के व्यवसाय पर रोक है तथा किसी भी प्रकार का प्रावधान गहन का पालन न करना कानून के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

**अनुच्छेद 24** - कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक - कोई भी बालक जिसकी उम्र 44 वर्ष से कम है उसे किसी भी कारखाने या खदान या कोई अन्य खतरनाक रोजगार में कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है।

**अनुच्छेद 36 (ई और एफ)** - राज्य विशेषज्ञ रूप से अपनी नीति का इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्देशित करेगा - कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं और सुकुमार उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो और आर्थिक आवश्यकता के कारण नागरिकों द्वारा ऐसे व्यवसाय करने को बाध्य नहीं किया जाय जो उनकी आयु अथवा शक्ति के अनुकूल नहीं हैं बल्कि बच्चों को स्वस्थ तरीके और स्वाधीनता तथा गरिमापूर्ण परिस्थितियों में विकास करने के अवसर दिये जायें और बचपन तथा यौवन को संरक्षण मिले ताकि उनका शोषण और नैतिक तथा भौतिक परित्याग न होने पाये। अनुच्छेद 49 - राज्य 14 वर्ष की उम्र तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उचित उपाय करेगा और राष्ट्रीय श्रोतों की उपलब्धता के अनुरूप इस कार्य के लिए समयबद्ध कार्यक्रम चलाया जायेगा। स्कूलों में इस समय बच्चों की, खासतौर लड़कियों और कमजोर वर्ग के बच्चों की जो बरबादी और उनके विकास में जो ठहराव आ रहा है उसे कम करने के विशेष प्रयास किये जायेंगे। ऐसे ही वर्गों के बच्चों को स्कूल जाना शुरू करने से पहले अनौपचारिक शिक्षा देने का कार्यक्रम भी चलाया जायेगा।

अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा - राज्य यह उपाय करेगी कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिए सम्मान की भावना जागृत करके संविदा आधारित उत्तरदायित्वों को संगठित लोगों के पारस्परिक व्यवहार रूप में संलिप्त करेंगे।

**बालश्रम कानूनों का इतिहास - कारखाना अधिनियम 1948** - कारखानों में रोजगारी की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 14 वर्ष की गई।

**बच्चों को रोजगार (संशोधन) अधिनियम 1949** - इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित रोजगारों में न्यूनतम आयु रोजगार के लिए बढ़ाकर 14 वर्ष की गयी।

**बच्चों को रोजगार (संशोधन) अधिनियम 1951** - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में दिये गये उद्घोषणा नवयुवाओं के रात्रि पाली में कार्य करने के सम्बन्ध में रेलवे तथा बंदरगाहों में 45 तथा 17 वर्ष के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया तथा 17 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए रजिस्टर बनाने का प्रावधान भी किया गया।

**बागान श्रमिक अधिनियम 1951** - 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का बागानों - में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया।

**खदान अधिनियम 1952** - 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का खदानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया। अधिनियम ने जमीन के नीचे कार्य करने के लिए दो शर्तें भी रखी :

1. 46 वर्ष की उम्र को पूर्ण करने की आवश्यकता।
2. किसी सर्जन से शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण-पत्र।

**कारखाना (संशोधन अधिनियम) 1954** - 17 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों का रात्रि में रोजगार पर प्रतिबंध सम्मिलित किया गया। (रात्रि को लगातार 42 घंटे के समय के रूप में परिभाषित किया गया जिसमें रात्रि 10 बजे से सुबह 7 बजे तक के समय को सम्मिलित किया गया।)

**जहाजराणी अधिनियम 1958** - 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के तथा किसी भी जहाज पर कार्य में शामिल करने पर प्रतिबंध लगाया गया, किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर।

**प्रशिक्षु अधिनियम 1961** - 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे के अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पर प्रतिबंध।

**बीड़ी तथा सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्त) अधिनियम 1966** — 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे के किसी भी औद्योगिक स्थान पर सिगरेट तथा बीड़ी के उत्पादन के लिए रोजगार पर प्रतिबंध 44 तथा 48 वर्ष तक के बच्चों के रात्रि 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्य करने पर प्रतिबंध। **बच्चों को रोजगार (संशोधन अधिनियम) 1978** - 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रेलवे में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया। जैसे - राख के ढेर में काम करना या किसी निर्माण कार्य में जहां पर स्थापना की जा रही हो तथा कोई भी ऐसा कार्य जो कि रेलवे लाइन के समीप किया जा रहा है।

**बाल श्रम (प्रतिषेध एवं नियमन) अधिनियम 1986** — यह अधिनियम बाल श्रम अधिनियमों के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है, इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे खतरनाक उद्योगों एवं प्रक्रियाओं में ऐसे बालकों का नियोजन प्रतिबंधित किया गया है, जिन्होंने अपने उम्र का 14वां वर्ष अभी पूरा नहीं किया है। संशोधनों के पश्चात् ऐसे 43 खतरनाक उद्योगों तथा 51 प्रक्रियाओं की पहचान की गयी है, जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिबंधित किया गया है। इन उद्योगों में कालीन उद्योग, सीमेंट उद्योग, कपड़ा छपाई तथा रंगाई, इलेक्ट्रानिक उद्योग आदि प्रमुख हैं।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. डॉ. वी.सी. सिन्हा : आर्थिक संवृद्धि एवं नियोजन, साहित्य भवन पब्लिसर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 2008
2. दत्त एवं सुन्दरम् : भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी प्रा.लि., 2012-13
3. भारत 2015, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, सूचना भवन, नई दिल्ली
4. कानूनी उपचार, ओझा सुरेश, सर्जना बीकानेर, 2012
5. नागरिक एवं मानव सुरक्षा अधिकार गाइड, हिन्दी अनुवाद मोहम्मद अली, एपीसीआर, 2010

## मध्यप्रदेश के धार जिले में साक्षरता का एक भौगोलिक अध्ययन

प्रो. किरण मण्डलोई\* डॉ. एम.एल. नाथ\*\*

**प्रस्तावना** – प्राचीन समय से ही शिक्षा एक महत्वपूर्ण और सर्वव्यापी विषय के रूप में विकसित हुई है। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में एक अहम भूमिका निभाती है। प्रत्येक व्यक्ति की गुणवत्ता उसके विचारों, भावनाओं एवं कार्यों का विकास शिक्षा-शिक्षण के माध्यम से किया जा सकता है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। वह मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, व्यवसायिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास करती है। शिक्षा का रूप अत्यन्त व्यापक है।

किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनैतिक प्रगति उसके देश में निवास करने वाले नागरिकों की शिक्षा पर निर्भर करती है। शिक्षा ही व्यक्ति के सामाजिक तथा मानसिक पृथक्त्व को भी समाप्त करती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा जन्मदर, मृत्युदर, विवाह आयु, प्रवास तथा आर्थिक प्रतिरूपों को भी प्रभावित करती है।

राष्ट्र संघ के जनसंख्या आयोग के अनुसार किसी भाषा में एक साधारण संदेश को समझकर पढ़ व लिख सकने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति को साक्षर कहा जाता है।

**अध्ययन क्षेत्र** – धार मध्यप्रदेश के पश्चिमी भाग का आदिवासी बाहुल्य जिला है। इस जिले का धरातल भौगोलिक संरचना की दृष्टि से बहुत ही असमानता लिए हुए है। यहां पर कहीं उंचे पर्वत, कहीं पठार, तो कहीं समतल मैदान है। जिले के उत्तर में मालवा का पठार, मध्य भाग पर्वतीय (विंध्याचल पर्वत श्रेणी) तथा दक्षिण में नर्मदा घाटी व निमाड़ का मैदान स्थित है।

धार जिला 20° से 23°10' उत्तरी अक्षांश से 74°28' से 75°42' पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। समुद्र तल से औसत उंचाई 588 मीटर है।

**पूर्व शोध कार्य** – सिन्हा अतुल कुमार (1881-82) प्राचीन भारतीय वैक्तिक एवं सामाजिक मूल्यबोध, विनीता नायर (1987) 'यूथ ऑफ द ब्रिक', एस.पी. गुप्ता (1995) आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन, मेरे. जे. (2006) एटिव्यूड ऑफ सेकेण्डरी स्कूल स्टूडेंट्स टूवाइस द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी एण्ड दिग्दर्शन एक्वीवमेंट एजुकेशन ट्रेक, इन्तखान अंसारी (2002) ए स्टडी ऑफ कम्प्यूटर एजुकेशन इन द साउथ गुजरात रीजन, अपीयर जर्नल ऑफ एजुकेशन एसोसिएशन फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एक्टिविटीज एण्ड रिसर्च इलाहाबाद आदि शोध कार्यों एवं आलेखों द्वारा शिक्षा के लिए एक आधारशिला का कार्य किया।

**उद्देश्य** – आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में प्राचीन समय से ही शिक्षा का अभाव रहा है। धार जिले में शिक्षा के स्तर में आये परिवर्तनों का अध्ययन करना है।

**विश्लेषण** – प्राचीन समय से ही आदिवासी लोग पहाड़ों, जंगलों एवं गुफाओं में छुपकर रहते थे। और उनका संपर्क शहरी क्षेत्रों से अछूता था। यही कारण

है कि आज भी धार जिले की 81 प्रतिशत जनसंख्या गावों में एवं 19 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है। जिले की भौगोलिक असमानता एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण शासन की विभिन्न योजनाओं से वर्तमान में साक्षरता में वृद्धि हुई है। धार जिले में वर्ष 2011 के अनुसार कुल साक्षर 1,077,338 व्यक्ति है। जिनमें से 638,479 पुरुष एवं 438,859 महिलाएँ है और कुल निरक्षर 1,108,455 व्यक्ति है। जिनमें से 474,246 पुरुष एवं 634,209 महिलाएँ है।

**तालिका क्रमांक - 1 जिला धार : साक्षरता का विवरण (प्रतिशत में)**

वर्ष	कुल	पुरुष	महिला	पुरुष-महिला साक्षरता में अंतर
1981	20.26	29.91	10.27	17.64
1991	34.54	47.62	20.71	26.91
2001	52.45	65.74	38.56	27.18
2011	59.00	68.95	48.77	20.18

स्रोत : जिला जनगणना पुस्तिका, धार 2009 एवं 2011

तालिका क्रमांक 1 से स्पष्ट है कि वर्ष 1981 में 20.26 प्रतिशत औसत साक्षरता थी जो बढ़कर 2011 में 59 प्रतिशत हो गयी है। विगत 40 वर्षों में जिले की औसत साक्षरता में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पुरुष साक्षरता 1981 में 29.91 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 68.95 प्रतिशत हो गयी है। महिला साक्षरता 10.27 प्रतिशत से बढ़कर 48.77 प्रतिशत हो गई है। साक्षरता का स्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। वहीं पुरुष-महिला साक्षरता में अंतर भी कम हो रहा है।

धार जिले की कुछ 8 तहसीलों में शिक्षा के स्तर में परिवर्तन का अध्ययन किया गया है।

**तालिका क्रमांक 2 जिला धार : तहसीलवार साक्षरता का वितरण, 2011**

क्रं.	तहसील	कुल	पुरुष	महिला	पुरुष-महिला साक्षरता में अंतर
1	बदनावर	65.88	78.23	52.34	25.89
2	सरदारपुर	53.25	65.05	41.2	23.85
3	धार	68.55	78.43	57.81	20.62
4	गंधवानी	43.27	50.15	36.5	13.65
5	कुक्षी	51.42	59.3	43.6	15.7
6	डही	46.02	53.21	38.77	14.44
7	मनावर	59.05	69.33	48.69	20.66

\* सहा. प्राध्यापक (भूगोल) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़नगर (म.प्र.) भारत

\*\* पूर्व निर्देशक, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल (म.प्र.) भारत

8	धरमपुरी	64.08	73.4	54.51	18.89
	जिला धार	59.00	68.95	48.77	20.18

स्रोत : जिला जनगणना पुस्तिका, धार, 2011

उपर्युक्त तालिका क्रमांक - 2 से स्पष्ट है कि वर्ष 2011 में औसत साक्षरता 59.00 प्रतिशत है। कुल पुरुष साक्षरता 68.95 प्रतिशत एवं कुल महिला साक्षरता 48.77 प्रतिशत है। तहसीलवार अध्ययन में बदनावर (65.55 प्रतिशत), एवं धार (68.55 प्रतिशत) तहसील पठारीय भाग में स्थित होने के कारण यहां की मिट्टी ऊपजाऊ तथा आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होने से साक्षरता भी अन्य तहसीलों की तुलना में अधिक है। वहीं मनावर (59.05 प्रतिशत) एवं धरमपुरी (64.08 प्रतिशत) तहसील मैदानी भागों में स्थित होने के कारण यहां की साक्षरता भी अधिक है, परंतु सरदारपुर (53.25 प्रतिशत), गंधवानी (43.27 प्रतिशत), कुक्षी (51.42 प्रतिशत) एवं डही (46.02 प्रतिशत) तहसील पहाड़ियों एवं घाटियों में स्थित होने तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी तहसीलों के कारण साक्षरता का स्तर बहुत कम है।

साक्षरता में कमी के कारण एवं प्रभावित करने वाले कारक - रूढ़ीवादी समाज, गरीबी, अंधविश्वास, आर्थिक स्थिति, रहन-सहन का स्तर, बोली एवं भाषा का अंतर, बिखरे आवास, शिक्षण संस्थाओं का असमान वितरण, आवागमन के साधनों का अभाव आदि कारणों से जिले में कुछ तहसीलों में साक्षरता कम है, परंतु शासन की विभिन्न नीतियों और योजनाओं जैसे -

माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा, पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के बच्चों को छात्रवृत्ति, निःशुल्क पुस्तकें एवं गणवेश, छात्रावास, साइकिल वितरण आदि योजनाओं के माध्यम से जिले में साक्षरता में आशातीत वृद्धि हुई है।

अंत में कहा जा सकता है कि मानव जीवन में शिक्षा का कार्य समाज के सदस्यों की उन सब शक्तियों, क्षमताओं और गुणों का विकास करना है, जो उनमें है, जिससे कि वे निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। एमरसन ने उचित ही लिखा है - 'शिक्षा इतनी विशद होनी चाहिए, जितना कि मनुष्य। उसमें जो भी शक्तियां हैं, शिक्षा को उन्हें पोषित और प्रदर्शित करना चाहिए।'

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. त्यागी डॉ. गुरसनदास एवं डॉ. विजय कुमार नन्द : उदीयमान भारत में शिक्षा-अग्रवाल पब्लिकेशन्स आगरा, 2009
2. कुमार डॉ. प्रमिला एवं शर्मा डॉ. श्रीकमल : मध्यप्रदेश : एक भौगोलिक अध्ययन- मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2015
3. कहार रितेश कुमार - 'आदिवासी एवं सामान्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा का विकासात्मक परिवर्तन : मध्यप्रदेश के छिन्दवाड़ा जिले के संदर्भ में एक भौगोलिक अध्ययन' 2018
4. जिला जनगणना पुस्तिका, धार, 2009 एवं 2011

\*\*\*\*\*

## पत्रकारिता : अर्थ और स्वरूप

डॉ. दाशरथी बेहेरा\*

**शोध सारांश** – आज ‘पत्रकारिता’ शब्द हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। सुबह होते ही हमें अखबार की आवश्यकता होती है, फिर पूरे दिन रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से समाचार प्राप्त करते रहते हैं। साथ ही साथ रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया सुबह से लेकर रात तक हमारे मनोरंजन के अतिरिक्त अन्य कई जानकारीयों से परिचित कराते हैं। इसके साथ ही विज्ञापन ने हमें उपभोक्ता संस्कृति से जोड़ दिया है। कुल मिलाकर पत्रकारिता के विभिन्न माध्यम जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया ने व्यक्ति से लेकर समूह तक और देश से लेकर सारे विश्व को एकसूत्र में बांध दिया है। इसके परिणाम स्वरूप पत्रकारिता आज राष्ट्रीय स्तर पर विचार, अर्थ, राजनीति और यहाँ तक कि संस्कृति को भी प्रभावित करने में सक्षम हो गई है।

**शब्द कुंजी** – पत्रकारिता अर्थ, स्वरूप, परिभाषा, कर्म, पत्रकारिता और पत्रकार, पत्रकार की योग्यता एवं उत्तरदायित्व, पत्रकारिता का क्षेत्र।

**प्रस्तावना** – मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेला नहीं रह सकता है। वह संप्रेषण के जरिए ही समाज से जुड़ा है। उसे व्यक्तिगत जरूरत पूरी करने, व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने, सूचना प्राप्त करने, आपस में बातचीत करने, किसी के प्रति किसी चीज के लिए आग्रह पैदा करने तथा मनोरंजन यानि हँसना, हँसाना, दूसरे के दुख-सुख में हिस्सा लेना के लिए संप्रेषण की जरूरत पड़ती है। यह संप्रेषण एक प्रक्रिया के तहत काम करता है। इसमें नौ तत्व होते हैं-स्रोत, वक्तृत्व क्षमता, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्ति, प्रतिक्रिया, संदर्भ एवं जीवन मूल्य और दृष्टिकोण।

स्रोत किसी भी संदेश को जन्म देता है। यह स्रोत कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वह अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है। इसके लिए वह अपने अनुभव और भाषा ज्ञान का उपयोग करता है। स्रोत या व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों में ढालता है। मौखिक संप्रेषण के संदर्भ में इस स्रोत को वक्ता कहते हैं। लिखित संप्रेषण के संदर्भ में इस स्रोत को लेखक, पत्रकार, रचनाकार कहते हैं। संचार माध्यम के संदर्भ में इस स्रोत को रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र, समाचार पत्र-पत्रिकाएँ, होर्डिंग, बिल, इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल, विज्ञापन, यातायात संकेत आदि इसके कई रूप हैं।

भाषा एक तरह का संचार माध्यम ही है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति तक अपना संदेश पहुँचाना चाहते हैं तो भाषा की सहायता लेते हैं। भाषा का पहला प्रयोग बोलकर ही किया गया होगा। उसे लिखकर भी प्रयोग किया जा सकता है। इसी से लिपि का आविष्कार हुआ होगा। आज बोलने और लिखे जाने के इस काम को समय और स्थान दोनों स्तरों पर सुरक्षित रखा जा सकता है, उसका पुनरु निर्माण किया जा सकता है। इसी उपलब्धि ने संचार माध्यमों को जन्म दिया है। जब रेडियो का आविष्कार हुआ तो बोली जानेवाली भाषा उसी रूप में सुरक्षित रखकर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान और एक समय से दूसरे समय तक ज्यों का त्यों भेजना मुमकिन हो सका। समाचार पत्र-पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन, होर्डिंग, बिल, पैम्फलेट, इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया, कंप्यूटर, फिल्म, वीडियो आदि ने संचार की प्रक्रिया को इतना व्यापक बना दिया है कि अब केवल मुद्रित रूप ही नहीं बल्कि आवाज और दृश्य रूप में भी संदेशों को संप्रेषित किया जा सकता है। कंप्यूटर

एवं स्मार्ट फोन ने हर तरह के संचार माध्यमों को एक ही स्थान पर उपलब्ध करा दिया है। संचार के क्षेत्र में जो भी बदलाव देखने को मिला है उसने लेखन को भी प्रभावित किया है। यहाँ तक कि लेखन का एक नया क्षेत्र भी खोल दिया है।

पत्रकारिता का अर्थ, परिभाषा, कर्म, पत्रकारिता और पत्रकार, पत्रकार की योग्यता एवं उत्तरदायित्व, पत्रकारिता का क्षेत्र के द्वारा ही पत्रकारिता के स्वरूप को समझा जा सकता है। तो आइए पत्रकारिता के अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र के बारे में विस्तार से जानें।

**पत्रकारिता का अर्थ** – अपने रोजमर्रा के जीवन की स्थिति के बारे में थोड़ा गौर कीजिए। दो लोग आसपास रहते हैं और कभी बाजार में, कभी राह चलते और कभी एक-दूसरे के घर पर रोज मिलते हैं। आपस में जब वार्तालाप करते हैं उनका पहला सवाल क्या होता है? उनका पहला सवाल होता है क्या हालचाल है? या कैसे हैं? या क्या समाचार है? रोजमर्रा के ऐसे सहज प्रश्नों में कोई खास बात नहीं दिखाई देती है लेकिन इस पर थोड़ा विचार किया जाए तो पता चलता है कि इस प्रश्न में एक इच्छा या जिज्ञासा दिखाई देगी और वह है नया और ताजा समाचार जानने की। वे दोनों पिछले कुछ घंटे या कल रात से आज के बीच में आए बदलाव या हाल की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से हमेशा उनकी आसपास की घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। मनुष्य का सहज प्रवृत्ति है कि वह अपने आसपास की चीजों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताजा जानकारी रखना चाहता है। उसमें जिज्ञासा का भाव प्रबल होता है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की जरूरत नहीं रहेगी। पत्रकारिता का विकास इसी जिज्ञासा को शांत करने के प्रयास के रूप में हुआ है जो आज भी अपने मूल सिद्धांत के आधार पर काम करती आ रही है।

इस जिज्ञासा से हमें अपने पास-पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में बहुत कुछ सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। ये सूचनाएँ हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। ये सूचनाएँ हमारा अगला कदम



क्या होगा तय करने में सहायता करती है। यही कारण है कि आधुनिक समाज में सूचना और संचार माध्यमों का महत्व बहुत बढ़ गया है। आज देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारीयाँ हमें समाचार माध्यमों से मिलती हैं।

विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए दुनियाभर के समाचार हमारे घरों तक पहुँचते हैं चाहे वह समाचार पत्र हो या टेलीविजन और रेडियो या इंटरनेट या सोशल मीडिया। समाचार संगठनों में काम करनेवाले पत्रकार देश-दुनिया में घटनेवाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित कर हम तक पहुँचाते हैं। इसके लिए वे रोज सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर पेश करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही 'पत्रकारिता' कहते हैं।

व्यक्ति को, समाज को, देश-दुनिया को प्रभावित करनेवाली हर सूचना समाचार है। यानी कि किसी घटना की रिपोर्ट ही 'समाचार' है। या यूँ कहें कि समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास होता है।

पत्रकारिता शब्द अंग्रेजी के 'जर्नलिज्म' का हिन्दी रूपांतर है। शब्दार्थ की दृष्टि से 'जर्नलिज्म' शब्द 'जर्नल' से निर्मित है और इसका अर्थ है 'दैनिकी', 'दैनिकी', 'रोजनामचा' अर्थात् जिसमें दैनिक कार्यों का विवरण हो। आज जर्नल शब्द 'मैगजीन', 'समाचार पत्र', 'दैनिक अखबार' का द्योतक हो गया है। 'जर्नलिज्म' यानी पत्रकारिता का अर्थ समाचार पत्र, पत्रिका से जुड़ा व्यवसाय, समाचार संकलन, लेखन, संपादन, प्रस्तुतीकरण, वितरण आदि होगा। आज के युग में पत्रकारिता के अभी अनेक माध्यम हो गये हैं, जैसे-अखबार, पत्रिकाएँ, रेडियो, दूरदर्शन, वेब-पत्रकारिता, सोशल मीडिया, इंटरनेट आदि।

हिंदी में भी पत्रकारिता का अर्थ भी लगभग यही है। 'पत्र' से 'पत्रकार' और फिर 'पत्रकारिता' से इसे समझा जा सकता है। वृहत हिंदी शब्दकोश के अनुसार 'पत्र' का अर्थ चिट्ठी, कागज, वह कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो, वह कागज या धातु की पट्टी जिस पर किसी व्यवहार के विषय में कोई प्रामाणिक लेख लिखा या खुदवाया गया हो (दानपत्र, ताम्रपत्र), किसी व्यवहार या घटना के विषय का प्रमाण रूप लेख (पट्टा, दस्तावेज), यान, वाहन, समाचार पत्र, अखबार है। 'पत्रकार' का अर्थ समाचार पत्र का संपादक या लेखक। और 'पत्रकारिता' का अर्थ पत्रकार का काम या पेशा, समाचार के संपादन, समाचार इकट्ठे करने आदि का विवेचन करनेवाली विद्या। वृहत शब्दकोश में साफ है कि पत्र का अर्थ वह कागज या साधन जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो जो प्रामाणिक हो, जो किसी घटना के विषय को प्रमाण रूप पेश करता है। और पत्रकार का अर्थ उस पत्र, कागज को लिखनेवाला, संपादन करनेवाला। और पत्रकारिता का अर्थ उसका विवेचन करनेवाली विद्या।

उल्लेखनीय है कि इन सभी माध्यमों से संदेश या सूचना का प्रसार एक तरफा होता है। सूचना के प्राप्तकर्ता से इनका फीडबैक नहीं के बराबर है। यानी सभी माध्यमों में प्रचारक या प्रसारक के संदेश प्राप्तकर्ता में दोहरा संपर्क नहीं स्थापित कर पाते हैं। प्राप्तकर्ता से मिलनेवाली प्रतिक्रिया, चिट्ठियों आदि के माध्यम से संपर्क नहीं के बराबर है। पिछले कुछ सालों में जनसंचार के अत्याधुनिक पद्धतियों के प्रचलन से दोहरा संपर्क रखा जाने लगा है।

**पत्रकारिता की परिभाषा** - किसी घटना की रिपोर्ट समाचार है जो व्यक्ति, समाज एवं देश दुनिया को प्रभावित करती है। इसके साथ ही इसका उपरोक्त से सीधा संबंध होता है। इस कर्म से जुड़े मर्मज्ञ विभिन्न मनीषियों द्वारा पत्रकारिता को अलग-अलग शब्दों में परिभाषित किया गया है। पत्रकारिता

के स्वरूप को समझने के लिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का उल्लेख किया जा रहा है।

### (क) पाश्चात्य चिंतन

1. **न्यू वेबस्टर्स डिक्शनरी** : प्रकाशन, संपादन, लेखन एवं प्रसारणयुक्त समाचार माध्यम का व्यवसाय ही पत्रकारिता है।
2. **विल्वर श्रम** : जनसंचार माध्यम दुनिया का नक्शा बदल सकता है।
3. **सी.जी. मूलर** : सामयिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन एवं ठीक-ठाक प्रस्तुतीकरण होता है।
4. **जेम्स मैकडोनाल्ड** : पत्रकारिता को मैं रणभूमि से ज्यादा बड़ी चीज समझता हूँ। यह कोई पेशा नहीं वरन् पेशे से ऊँची कोई चीज है। यह एक जीवन है, जिसे मैंने अपने को स्वेच्छापूर्वक समर्पित किया।
5. **विखेम स्टीड** : मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता कला भी है, वृत्ति भी और जनसेवा भी। जब कोई यह नहीं समझता कि मेरा कर्तव्य अपने पत्र के द्वारा लोगों का ज्ञान बढ़ाना, उनका मार्गदर्शन करना है, तब तक उसे पत्रकारिता की चाहे जितनी ट्रेनिंग दी जाए, वह पूर्ण रूपेण पत्रकार नहीं बन सकता।

इस प्रकार न्यू वेबस्टर्स डिक्शनरी में उस माध्यम को जिसमें समाचार का प्रकाशन, संपादन एवं प्रसारण विषय से संबंधित को पत्रकारिता कहा गया है। विल्वर श्रम का कहना है कि जनसंचार माध्यम उसे कहा जा सकता है जो व्यक्ति से लेकर समूह तक और देश से लेकर विश्व तक को विचार, अर्थ, राजनीति और यहाँ तक कि संस्कृति को भी प्रभावित करने में सक्षम है। सीजी मूलर ने तथ्य एवं उसका मूल्यांकन के प्रस्तुतीकरण और सामयिक ज्ञान से जुड़े व्यापार को पत्रकारिता के दायरे में रखते हैं। जेम्स मैकडोनाल्ड के विचार अनुसार पत्रकारिता दर्शन है जिसकी क्षमता युद्ध से भी ताकवर है। विखेम स्टीड पत्रकारिता को कला, पेशा और जनसेवा का संगम मानते हैं।

### (ख) भारतीय चिंतन

1. **हिंदी शब्द सागर** : पत्रकार का काम या व्यवसाय ही पत्रकारिता है।
2. **डॉ. अर्जुन तिवारी** : ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाना ही पत्रकारिता है। यह वह विद्या है जिसमें सभी प्रकार के पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और लक्ष्यों का विवेचन होता है। पत्रकारिता समय के साथ साथ समाज की दिग्दर्शिका और नियामिका है।
3. **रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर** : ज्ञान और विचार शब्दों तथा चित्रों के रूप में दूसरे तक पहुँचाना ही पत्रकारिता है। छपने वाले लेख-समाचार तैयार करना ही पत्रकारी नहीं है। आकर्षक शीर्षक देना, पृष्ठों का आकर्षक बनाव-ठनाव, जल्दी से जल्दी समाचार देने की त्वरा, देश-विदेश के प्रमुख उद्योग-धंधों के विज्ञापन प्राप्त करने की चतुराई, सुंदर छपाई और पाठक के हाथ में सबसे जल्दी पत्र पहुँचा देने की त्वरा, ये सब पत्रकार कला के अंतर्गत रखे गए।
4. **डॉ. बट्टीनाथ कपूर** : पत्रकारिता पत्र-पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख आदि एकत्रित करने, संपादित करने, प्रकाशन आदेश देने का कार्य है।
5. **डॉ. शंकर दयाल शर्मा** : पत्रकारिता एक पेशा नहीं है बल्कि यह तो जनता की सेवा का माध्यम है। पत्रकारों को केवल घटनाओं का विवरण ही पेश नहीं करना चाहिए, आम जनता के सामने उसका विश्लेषण भी करना चाहिए। पत्रकारों पर लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करने और शांति एवं भाईचारा बनाए रखने की भी जिम्मेदारी आती है।

**6. इन्द्र विद्यावाचस्पति :** पत्रकारिता पाँचवाँ वेद है, जिसके द्वारा हम ज्ञान-विज्ञान संबंधी बातों को जानकर अपना बंद मस्तिष्क खोलते हैं।

हिंदी शब्द सागर में पत्रकार के कार्य एवं उससे जुड़े व्यवसाय को पत्रकारिता कहा गया है। डॉ. अर्जुन तिवारी के अनुसार ज्ञान और विचार को कलात्मक ढंग से लोगों तक पहुँचाना ही पत्रकारिता है। यह समाज का मार्गदर्शन भी करता है। इससे जुड़े कार्य का तात्त्विक विवेचन करना ही पत्रकारिता विद्या है। रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर मानते हैं कि यह एक कला है जिसके माध्यम से पत्रकार ज्ञान और विचारों को शब्द एवं चित्रों के माध्यम से आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करता है। डॉ. बद्रीनाथ कपूर का कहना है कि समाचार माध्यमों के लिए किए जानेवाले कार्य समाचार संकलन, लेखन एवं संपादन, प्रकाशन कार्य ही पत्रकारिता है। डॉ. शंकर दयाल शर्मा मानते हैं कि यह सेवा का माध्यम है। यह एक ऐसी सेवा है जो घटनाओं का विश्लेषण करके लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करने के साथ ही शांति एवं भाईचारा कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहण करती है। इन्द्र विद्यावाचस्पति का मानना है कि पत्रकारिता वेदों की तरह है जो ज्ञान-विज्ञान के जरिए लोगों की मस्तिष्क को खोलने में काम करता है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर पत्रकारिता को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है :-

यह एक ऐसा कलात्मक सेवा कार्य है जिसमें सामयिक घटनाओं को शब्द एवं चित्र के माध्यम से जन जन तक आकर्षक ढंग से पेश किया गया हो और जो व्यक्ति से लेकर समूह तक और देश से लेकर विश्व तक के विचार, अर्थ, राजनीति और यहाँ तक कि संस्कृति को भी प्रभावित करने में सक्षम हो। उस कला का विवेचन ही पत्रकारिता है।

**पत्रकारिता के मूल्य -** चूंकि यह एक ऐसा कलात्मक सेवा कार्य है जिसमें सामयिक घटनाओं को शब्द एवं चित्र के माध्यम से पत्रकार रोज दर्ज करते चलते हैं तो इसे एक तरह से दैनिक इतिहास लेखन कहा जाएगा। यह काम ऊपरी तौर पर बहुत आसान लगता है लेकिन यह इतना आसान होता नहीं है। अपनी पूरी स्वतंत्रता के बावजूद पत्रकारिता सामाजिक और नैतिक मूल्यों से जुड़ी रहती है। उदाहरण के लिए सांप्रदायिक दंगों का समाचार लिखते समय पत्रकार प्रयास करता है कि उसके समाचार से आग न भड़के। वह सच्चाई जानते हुए भी दंगों में मारे गए या घायल लोगों के समुदाय की पहचान नहीं करता। बलात्कार के मामलों में वह महिला का नाम या चित्र नहीं प्रकाशित करता है ताकि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को कोई धक्का न पहुँचे। पत्रकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे पत्रकारिता की आचार संहिता का पालन करें ताकि उनके समाचारों से बेवजह और बिना ठोस सबूत के किसी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान न हो और न ही समाज में अराजकता और अशांति फैले।

सामाजिक सरोकारों को व्यवस्था की दहलीज तक पहुँचाने और प्रशासन की जनहितकारी नीतियों तथा योजनाओं को समाज के सबसे निचले तबके तक ले जाने के दायित्व का निर्वाह ही सार्थक पत्रकारिता है।

पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। इसने लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण स्थान अपने आप हासिल नहीं किया है बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति पत्रकारिता के दायित्वों के महत्व को देखते हुए समाज ने ही यह दर्जा दिया है। लोकतंत्र तभी सशक्त होगा जब पत्रकारिता सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति अपनी सार्थक भूमिका निर्वहण करे। पत्रकारिता का उद्देश्य ही यह होना चाहिए कि वह प्रशासन और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निर्वहण करे।

समय के साथ पत्रकारिता का मूल्य बदलता गया है। इतिहास पर नजर

डालें तो स्वतंत्रता के पूर्व की पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति ही लक्ष्य था। स्वतंत्रता के लिए चले आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता ने अहम और सार्थक भूमिका निभाई है। उस दौर में पत्रकारिता ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के साथ साथ पूरे समाज को स्वाधीनता की प्राप्ति के लक्ष्य से जोड़े रखा।

आजादी के बाद निश्चित रूप से इसमें बदलाव आना ही था। आज इंटरनेट और सूचना अधिकार ने पत्रकारिता को बहु आयामी और अनंत बना दिया है। आज कोई भी जानकारी पलक झपकते उपलब्ध कराई जा सकती है। पत्रकारिता वर्तमान समय में पहले से कई गुना सशक्त, स्वतंत्र और प्रभावकारी हो गया है। अभिव्यक्ति की आजादी और पत्रकारिता की पहुँच का उपयोग सामाजिक सरोकारों और समाज की भलाई के लिए हो रहा है लेकिन कभी कभार इसका दुरुपयोग भी होने लगा है।

आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव भी पत्रकारिता पर खूब पड़ा है। विज्ञापनों से होनेवाली अथाह कमाई ने पत्रकारिता को एक व्यवसाय बना दिया है। और इसी व्यावसायिक दृष्टिकोण का नतीजा यह हो चला है कि उसका ध्यान सामाजिक जिम्मेदारियों से कहीं भटक गया है। आज पत्रकारिता मुद्दा के बदले सूचनाधर्मी होता चला गया है। इंटरनेट एवं सोशल मीडिया की व्यापकता के चलते उस तक सार्वजनिक पहुँच के कारण उसका दुष्प्रयोग भी होने लगा है। इसके कुछ उपयोगकर्ता निजी भड़ास निकालने और आपत्ताजनक प्रलाप करने के लिए इस माध्यम का गलत इस्तेमाल करने लगे हैं। यही कारण है कि इस पर अंकुश लगाने की बहस छिड़ जाती है। लोकतंत्र के हित में यही है कि जहाँ तक हो सके पत्रकारिता को स्वतंत्र और निर्बाध रहने दिया जाए। पत्रकारिता का हित में यही है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग समाज और सामाजिक जिम्मेदारी निर्वहण के लिए ईमानदारी से निर्वहन करती रहे।

**पत्रकारिता और पत्रकार -** अब तक हमने जान लिया है कि पत्रकारिता एक ऐसी कला है जिसे शब्द और चित्र के माध्यम से पेश किया जाता है। इसे आकार देनेवाला पत्रकार होता है। ऊपर से देखने से यह एक आसान काम लगता है लेकिन यह उतना आसान नहीं होता है। उस पर कई तरह के दबाव हो सकते हैं। अपनी पूरी स्वतंत्रता के बावजूद उस पर सामाजिक और नैतिक मूल्यों की जवाबदेही होती है।

लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना गया है। इस हिसाब से न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका जैसे तीन स्तंभ को बांधे रखने के लिए पत्रकारिता एक कड़ी के रूप में काम करती है। इस कारण पत्रकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उसके सामने कई चुनौतियाँ होती हैं और दबाव भी। सामाजिक सरोकारों को व्यवस्था की दहलीज तक पहुँचाने और प्रशासन की जनहितकारी नीतियों तथा योजनाओं को समाज के सबसे निचले तबके तक ले जाने के दायित्व का निर्वहन करना पत्रकार और पत्रकारिता का कार्य है।

एक समय था भारत में कुछ लोग प्रतिष्ठित संस्था एवं व्यवस्था को समाज के विकास में सहायक नहीं समझते थे। यह लोग अपने नए विचारों के प्रचार प्रसार के लिए पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन करते थे। यह उनकी प्रकृति एवं प्रवृत्ति को लोगों तक पहुँचाने का माध्यम बना था। तकनीकी विकास एवं उद्योग एवं वाणिज्य के प्रसार के कारण एक दिन यह एक कमाऊ व्यवसाय में परिवर्तित हो जाएगा की बात उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था। समाज के कल्याण, नए विचार के प्रचार प्रसार के लिए पत्रकारिता को समर्पित माना जाता था। यह एक दिन पेशा में बदला जाएगा और इसके

लिए डिग्री, डिप्लोमा के पैमाने पर योग्यता एवं दक्षता मापा जाएगा यह कोई सोचा भी नहीं होगा।

लोकतंत्र व्यवस्था में पत्रकारिता भाव की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक माध्यम के रूप में स्वीकृत है। इसलिए पत्रकारिता या मीडिया को राष्ट्र का चौथा स्तंभ कहा जा रहा है। लेकिन खुली हवा के अभाव में इसका विकास भी अवरुद्ध हो सकता है।

आजादी के बाद लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत आगे बढ़ने के कारण समाचार पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन, प्रसारण में वृद्धि हुई है। इसका सामाजिक सरोकार होने के बावजूद यह एक उद्योग के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। पत्रकारिता ने एक विकसित पेशा के रूप में शिक्षित युवाओं को आकर्षित किया है। देश में जिन कुछ क्षेत्रों में प्रवृत्ति एवं वृत्ति यानी पेशा में मिलान एवं जुड़ाव की आवश्यकता है उनमें से पत्रकारिता अन्यतम है।

पत्रकारिता के लिए किताबी ज्ञान की तुलना में कुशल साधना की जरूरत अधिक होती है। क्योंकि यह एक कला है। साधना के बल पर ही कुशलता हासिल किया जा सकता है। किताब पढ़कर डिग्री तो हासिल की जा सकती है लेकिन कुशलता के लिए अनुभव की जरूरत होती है। इसके बावजूद चूंकि यह अब पेशे में बदल चुकी है इसलिए योग्यता का पैमाना विचारणीय है। उस प्राथमिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान के लिए इस विषय में कुछ सामान्य नीति नियम जानना और समझना अत्यंत जरूरी है।

एक बात और अतीत में जितने भी पत्रकारों ने श्रेष्ठ पत्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त की है उन्होंने किसी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता विषय में कोई डिग्री या डिप्लोमा हासिल नहीं किया है। उन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर और साधना के बल पर पत्रकारिता के क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

**पत्रकारिता कर्म** – प्रारंभिक अवस्था में जब पत्रकारिता को एक उद्योग के रूप में नहीं गिना जाता था तभी पत्रकारिता को एक पेशा या कर्म के रूप में नहीं समझा जाता था। जब डाक एवं तार, परिवहन व्यवस्था में विकास नहीं हुआ था, विज्ञापन से सामान्य आय हुआ करता था, शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ था तब एक सप्ताह में या पंद्रह दिन में एकबार एक समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का एक संस्करण प्रकाशित करने का कुछ लोगों में जुनून था। कुछ खास नीति एवं आदर्श के प्राचार हेतु एवं सीमित लक्ष्य हासिल के लिए पत्रकारिता को एक माध्यम समझकर कुछ लोग इसके लिए असीम शक्ति एवं समय लगा देते थे। उन लोगों ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका जुनून एक दिन कमाऊ व्यवसाय बन जाएगा। तकनीकी विकास, परिवहन व्यवस्था में विकास, उद्योग एवं वाणिज्य के प्रसार के कारण आज यह एक उद्योग बन चुका है। पत्रकारिता आज की स्थिति में केवल प्रवृत्ति या जुनून न होकर एक पेशा बन गया है। जिसके हृदय में समाज के प्रति संवेदना का भाव है और समाज का कल्याण चाहता है और नए विचार का प्रचार प्रसार करना चाहता है तो वह इस पेशे से जुड़ सकता है। दूसरी बात यह कि आज की स्थिति में हर क्षेत्र में चुनौती है। पत्रकारिता में भी पत्रकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके वर्तमान में पत्रकारिता एक पेशा या कर्म बन चुका है। यह एक पेशा में बदला चुका है और इसके लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा औपचारिक डिग्री, डिप्लोमा प्रदान किया जा रहा है।

**पत्रकार की योग्यता और उत्तरदायित्व** – समाचार पत्र-पत्रिकाएँ हो या अन्य माध्यम में कार्य कर रहे पत्रकारों को दुहरी भूमिका निर्वाह करनी पड़ती है। उसे अपने स्तर पर समाचार भी संकलन करना होता है और उसे लिखना भी पड़ता है। समाचारों के संकलन, व्याख्या और प्रस्तुतीकरण के लिए पत्रकार

में गुप्तचर, मनोवैज्ञानिक और वकील के साथ साथ एक अच्छे लेखक के गुण होने चाहिए। प्रत्येक पत्रकार को अपने समाचार का क्षेत्र निर्धारित कर लेना चाहिए ताकि विशेषता हासिल होने पर वह समाचार को सही ढंग से पेश कर सकता है। पत्रकार में कुछ गुण ऐसे होने चाहिए जो उसे सफल पत्रकार बना सकता है उसमें सक्रियता, विश्वासपात्रता, वस्तुनिष्ठता, विश्लेषणात्मक क्षमता और भाषा पर अधिकार।

**1. सक्रियता** – एक सफल पत्रकार के लिए अत्यंत जरूरी है कि वह हर स्तर पर सक्रिय रहे। यह सक्रियता उसे समाचार संकलन और लेखन दोनों में दृष्टिगोचर होनी चाहिए। सक्रियता होगी तो समाचार में नयापन और ताजगी आएगी। अनुभवी पत्रकार अपने परिश्रम और निजी सूत्रों से सूचनाएँ प्राप्त करते हैं और उन्हें समाचार के रूप में परिवर्तित करते हैं। वह पत्र और पत्रकार सम्मानित होते हैं जिसके पत्रकार जासूसों की तरह सक्रिय रहते हैं और अपने संपर्क सूत्रों को जिंदा रखते हैं।

**2. विश्वासपात्रता** – विश्वासपात्रता पत्रकार का ऐसा गुण है जिसे प्रयत्नपूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। संपर्क सूत्र से पत्रकार को समाचार प्राप्त होते हैं। पत्रकार को हमेशा उसका विश्वासपात्र बने रहने से ही समाचार नियमित रूप से मिल सकता है। संपर्क सूत्र हमेशा यह ध्यान रखता है कि उसका जिस पत्रकार के साथ संबंध है वह उसके विश्वास को कायम रखता है या नहीं। अगर सूत्र का संकेत देने से उस व्यक्ति का नुकसान होता है तो उसे कभी भी उससे संपर्क नहीं रखना चाहेगा।

**3. वस्तुनिष्ठता** – वस्तुनिष्ठता का गुण पत्रकार के कर्तव्य से जुड़ा है। पत्रकार का कर्तव्य है कि वह समाचार को ऐसा पेश करे कि पाठक उसे समझते हुए उससे अपना लगाव महसूस करे। चूंकि समाचार लेखन संपादकीय लेखन नहीं होता है तो लेखक को अपनी राय प्रकट करने की छूट नहीं मिल पाती है। उसे वस्तुनिष्ठता होना अनिवार्य है। लेकिन यह ध्यान रखना होता है कि वस्तुनिष्ठता से उसकी जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। पत्रकार का उत्तरदायित्व की परख तब होती है जब उसके पास कोई विस्फोटक समाचार आता है। आज के संदर्भ में दंगे को ही लें। किसी स्थान पर दो समुदायों के बीच दंगा हो जाता है और पत्रकार सबकुछ खुलासा करके नमक-मिर्च लगाकर समाचार पेश करता है तो समाचार का परिणाम विध्वंसात्मक ही होगा। ऐसी स्थिति में अनुभवी पत्रकार अपने विवेक का सहारा लेते हैं और समाचार इस रूप से पेश करते हैं कि उससे दंगाइयों को बल न मिले। ऐसे समाचार के लेखन में वस्तुनिष्ठता और भी अनिवार्य जान पड़ती है।

**4. विश्लेषणात्मक क्षमता** – पत्रकार में विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है तो वह समाचार को रोचक ढंग से पेश नहीं कर पाता है। आज के पाठक केवल तथ्य पेश करने से संतुष्ट नहीं होता है। समाचार का विश्लेषण चाहता है। पाठक समाचार की व्याख्या चाहता है। समाचार के साथ विश्लेषण दूध में पानी मिलाने की तरह गुंथा हुआ रहता है। लेकिन व्याख्या में भी संतुलन होना चाहिए। पत्रकार की विश्लेषण क्षमता दो स्तर पर होता है – समाचार संकलन के स्तर पर और लेखन के स्तर पर। समाचार संकलन में पत्रकार की विश्लेषण क्षमता का उपयोग सूचनाओं और घटनाओं को एकत्र करने के समय होता है। इसके अलावा पत्रकार सम्मेलन, साक्षात्कार आदि में भी उसकी यह क्षमता उपयोग में आता है। दूसरा स्तर लेखन के समय दिखाई देती है। जो पत्रकार समाचार को समझने और प्रस्तुत करने में जितना ज्यादा अपनी विश्लेषण क्षमता का उपयोग कर सकेगा, उसका समाचार उतना ही ज्यादा दमदार होगा। इसे व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग भी कहा जाता है।

उदाहरण के लिए, सीधी खबर है कि भारत सरकार ने किसानों का

कर्ज माफ करने का निर्णय लिया है। योजना लागू करने की तिथि की घोषणा अभी नहीं की गई है। किंतु पत्रकार अपने स्रोतों से पता करता है कि यह कर्ज माफी किस दबाव के तहत किया जा रहा है और इससे देश की अर्थ व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। समाचार का यह रूप व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग का रूप होगा।

**चुनावी वादा निभाने किसानों का कर्ज माफ** – भारत सरकार ने किसानों के विकास का ध्यान रखते हुए उनका कर्ज माफ करने का निर्णय लिया है। इससे राजकोष पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार यह निर्णय पार्टी द्वारा चुनाव के समय किए गए वायदे को पूरा करने के लिए लिया गया है।

**5. भाषा पर अधिकार** – समाचार लेखन एक कला है। ऐसे में पत्रकार को लेखन कला में माहिर होना होगा। उसे भाषा पर अधिकार होना चाहिए। इसके साथ ही पत्रकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि उसके पाठक वर्ग किस प्रकार के हैं। समाचारपत्र में अलग अलग समाचार के लिए अलग अलग भाषा दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि अपराध के समाचार, खेल समाचार या वाणिज्य समाचार की भाषा अलग अलग होती है। लेकिन उन सबमें एक समानता होती है वह यह है कि सभी प्रकार के समाचारों में सीधी, सरल और बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक बात और है कि पत्रकार को एक क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता निर्धारित कर लेना चाहिए। इससे उससे संबंधित शब्दावली से पत्रकार परिचित हो जाता है और जरूरत पड़ने पर नए शब्दों का निर्माण करना आसान हो जाता है। इसबारे में विस्तृत रूप से आगे चर्चा की गई है।

**पत्रकारिता के क्षेत्र** – आज की दुनिया में पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। शायद ही कोई क्षेत्र बचा हो जिसमें पत्रकारिता की उपादेयता को सिद्ध न किया जा सके। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि आधुनिक युग में जितने भी क्षेत्र हैं सबके सब पत्रकारिता के भी क्षेत्र हैं, चाहे

वह राजनीति हो या न्यायालय या कार्यालय, विज्ञान हो या प्रौद्योगिकी हो या शिक्षा, साहित्य हो या संस्कृति या खेल हो या अपराध, विकास हो या कृषि या गाँव, महिला हो या बाल या समाज, पर्यावरण हो या अंतरिक्ष या खोज। इन सभी क्षेत्रों में पत्रकारिता की महत्ता एवं उपादेयता को सहज ही महसूस किया जा सकता है। दूसरी बात यह कि लोकतंत्र में इसे चौथा स्तंभ कहा जाता है। ऐसे में इसकी पहुँच हर क्षेत्र में हो जाता है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. मीडिया के विविध आयाम, योगेश कुमार गुप्ता, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, राजस्थान
2. रेडियो और दूरदर्शन पत्रकारिता, डॉ. हरिमोहन, तक्षशिला प्रकाशन, दिल्ली
3. समाचार लेखन और संपादन, एनसी पंत, कनिष्क पब्लिशर्स, डिस्ट्रिब्यूटर्स, दिल्ली
4. हिंदी पत्रकारिता, कृष्ण बिहारी मिश्र, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली
5. मीडिया लेखन के सिद्धांत, एनसी पंत, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली
6. पत्रकारिता की कालजयी परंपरा, कमलेश्वर, बीबीसी हिंदी
7. मीडिया लेखनरू सिद्धांत और व्यवहार, डॉ. चंद्रप्रकाश मिश्र, संजय प्रकाशन, दिल्ली
8. गाँधी जी, पत्रकारिता और स्वतंत्रता आंदोलन, मीडिया का मैजिक
9. भाषा शिक्षण, रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1978
10. जनसंचार माध्यमों का सामाजिक चरित्र, जवरीमल्ल पारख, अनामिका प्रकाशन, दिल्ली
11. The ecology of language, Stanford University Press, E, Haugen, 1972

\*\*\*\*\*



# Institutionalization of Social Audit and its impact on MNREGA in Himachal Pradesh- A case study of Kangra and Hamirpur district

Dr. Shivani Sabharwal\* Naresh Kumar\*\*

**Introduction** - In the present scenario unemployment is become the main reason of poverty in rural areas of India. Therefore Govt of India has always been making efforts to ameliorate the lives of unskilled labourers by creating infrastructure and establishing institutional set up for removal of poverty in rural areas. To achieve the objective, government of India has implemented many rural development schemes such as, MANREGA, The work for food programme, The Sampoorna Gramin Rojgar Yojna etc. Some of these programmes could not yield the desired results due to inconsistencies between aims of schemes, poor quality of infrastructure, lack of resources and manipulation of the records in few schemes. Now people of the country demanded from governments for more transparent, accountable and socially responsible programmes and the people are becoming more assertive about their rights to be informed which influence government's decision making process. People of the country no longer want their role in the democracy to be limited to electing their representatives but want to participate in the process of policy making and governance. To overcome these problems the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA), 2005 was launched by Govt of India. This act provides for enhancement of livelihood security of the households in rural areas as well as urban area of the country by providing at least 100 days guaranteed wage employment. Such employment is generated in every financial year to year to every household whose adult members voluntarily offers to do unskilled manual work. Government of India is also promoting people's participation in the policy making through consultation at various stages and also in implementation of MNREGA through bottom-up participatory planning, community monitoring and social audit.

**MNREGA and Social Audit** - MNREGA play tremendous role in the field of short employment in the rural area. In pandemic period majority of people of the rural area get

employment through MNREGA. It provides for enhancement of livelihood security in rural areas of the country by providing at least 100 days guaranteed wage employment in every financial year. According to this Act every household whose adult members voluntarily offers to do unskilled manual work by way of creating durable assets and strengthening the livelihood resource base of the rural poor. MNREGA enhancing the livelihood security of rural people in rural India by generating wage employment. It create infrastructural base for protection of environment, empowerment of women and reduce the social equality. Before the MNREGA came into operation, there was not any institutional mechanism to check irregularities, pilferage, extravagance and misuse of funds. Hence to ensure transparency and accountability Govt of India has made a provision of Social Audit under the MNREGA.

Few years ago Social Audit was a procedure which involving participation of any organization to identify the needs and provides monitoring the progress and measuring social performance in comprehensive manner. Now a day's social Audit is done by the VRP's. (Village Resource Person) Social audit is a systematic procedure involving participation of VRP to identify needs and provides monitoring of progress and measuring social performance of MNREGA. This Act (MNREGA) was implemented across the country in a highly decentralized manner and Panchayati Raj institutions have been given essential role in planning and implementing the scheme whereas Social audit is a continue process in which, financial and non financial resources used by public agencies for development initiatives. These initiatives are shared with the people, through a public platform i.e. Gram Sabha in rural India.

## **Objective of the study :**

1. To study the concept of Social Audit under MNREGS
2. To study the implementation process of social audit under MNREGS in Himachal Pradesh
3. To evaluate the responses about the information

\* Assistant Professor (Commerce) Government P.G.College, Dharmshala (H.P.) INDIA

\*\* Assistant Professor (Commerce) Sidharth Government College, Nadaun, Hamirpur (H.P.) INDIA

provided at the time of Social Audit

4. To suggest measures that would help in enhancing the effectiveness and streamlining the social audit under MNREGS.

**Research Methodology** - The present study was based on the primary as well as secondary data. The methodology of data collection has been discussed on 1008 respondents. It includes 720 programme beneficiaries (30 respondents from each Gram panchayat), 120 non-beneficiaries (5 respondents from each panchayat), 96 Panchayat Office Bearers, which includes Members of Gram Panchayats (4 respondents from each Gram Panchayat), 72 programme implementation officials (which include Panchayat Secretaries/Sahayaks, Gram Rozgar Sevaks and Technical Assistants).

#### Review of Literature

**Baisakh (2008)** has tried to assess the impact of social audit in Orissa. According to author social audit is probably the best form of generation of awareness and mobilization of people. The impact of social audit process has been both immediate and long term. The platform of social audit has also been used to redressing other grievances of the people. However, the long term impact of social audit in terms of increased awareness of people accompanied by assertion of their entitlement under the act and the response of the authorities towards better implementation of the scheme is encouraging.

**Ramesh (2011)**, has conducted a study in Karimnagar district of Andhra Pradesh to assess the impact of the National Rural Employment Guarantee Programme (NREGP) and his study suggested that wages should be paid to workers in time, social audit should be made effective to eliminate bogus beneficiaries and government should take measures to provide 100 days of employment to all workers.

#### Tools and Techniques Applied for Analysis and Interpretation of Data

The data collected from the primary and secondary sources have been properly arranged and tabulated with the help of statistical tools such as mean, standard deviation, skewness and chi-square test.

#### Analysis and Interpretation

##### Table 1) Responses about the Gram Sabha Meetings for Social Audit (see in last page)

The Table 1 reveals that in majority of cases (64.78 per cent) Gram Sabha meetings were not held exclusively for social audit in the area under study. Whereas 15.28 per cent of respondents reported that Gram Sabha meetings were held exclusively for social audit. The sample beneficiaries and non-beneficiaries responded differently from the POBs and PIOs. Out of total sample programme beneficiaries and non-beneficiaries, 10.69 per cent of beneficiaries and 15.83 per cent of non-beneficiaries agreed that Gram Sabha meetings were held exclusively for social audit in their respective gram Panchayats, whereas 25.14 per cent of sample beneficiaries and 16.67 per cent of non-

beneficiaries did not know about such meetings.

District-wise data shows that out of total respondents, 61.11 per cent of respondents in Kangra district and 68.45 per cent of respondents in Hamirpur district were of the opinion that Gram Sabha meetings have not been conducted exclusively for social audit, whereas 22.02 per cent of respondents in Kangra district and 17.86 per cent of respondents in Hamirpur district didn't know about such meetings. Further, the percentage of those respondents who agreed that Gram Sabha meetings were held exclusively for social audit was found very less, that is, 16.87 per cent in Kangra district and 13.69 per cent in Hamirpur district.

##### Table 1 Responses of respondents in Gram Sabha Meeting especially social audit

The highest percentage where the Gram Sabha meetings were held exclusively for social audit was found in Kangra block (20.24 per cent) of Kangra district and Bhoranj block (16.67 per cent) of Hamirpur district, whereas the lowest percentage in this regard was found in Bijhari block (11.31 per cent) of Hamirpur district and in Fatehpur block (12.50 per cent) of Kangra district. Thus on the basis of feedback given by the sample respondents it can be concluded that in majority of cases specific meetings of Gram Sabha for social audit have not been held in the selected gram Panchayats.

##### Table 2) a & b Responses about the information provided at the time of Social Audit

At the time of Gram Sabha, especially, social audit, Gram Panchayats have to put all the relevant documents and information before the Gram Sabha members. Further, Gram Sabha members should have the easy access to all these documents. The opinion in this regard has been collected from those respondents (programme beneficiaries and non-beneficiaries) who have attended/participated the Gram Sabha meetings either always or sometimes. The opinion of respondents in this regard has been given in Table 2 (a) exhibit that in all the blocks of Kangra district and Hamirpur district, majority of respondents were partially agreed with all the statements given in Table. In this regard the highest percentage was found in Nagrota Bagwan block of Kangra District and in Bhoranj block of Hamirpur district. However, the percentage of those respondents who were disagreed with these statements cannot be ignored. This percentage was found highest in Fatehpur block of Kangra district and in Bijhari block of Hamirpur district.

##### Table 2(a) Responses about the information provided at the time of Social Audit (see in last page)

The opinion of the respondents with regard to the information provided during Gram Sabha meetings, especially, for social audit, has been statistically analyzed in Table 2 (b) reveals that in overall, as much as 49.52 per cent of respondents were partially agreed that there was an easy access to all the relevant documents related to MNREGS at the time of Gram Sabha and Social audit. While 42.39 per cent of respondents disagreed that there was an

easy access to all the relevant documents. With regard to the statement that 'Gram Panchayat provides all the information at the time of social audit' it was found that 54.58 per cent of respondents partially agreed with it and 39.86 per cent of respondents found disagreed with this statement.

Statistical analyses of the opinion of the respondents with regard to statements shown in Table 2 (b) reveal that the mean scores (1.657, 1.657, 1.598 and 1.627) of aggregate responses are falling between two choices, that is, partially agree and not agree. Whereas the positive values of skewness indicate that the opinion of the respondents is distributed towards lower side of the mean score. The variations in their opinion are noted below 0.63 in all the statements mentioned in the Table. The application of  $X^2$  test (goodness of fit) shows that the calculated values of  $\chi^2$  are more than the table value at 5 per cent level of significance. Thus, the null hypothesis is rejected that the opinion of the respondents is equally distributed and leads to the conclusion that sufficient information during the Gram Sabha meetings has not been provided.

#### Table 3 (see in last page)

District-wise opinion of the respondents also shows the same trend. As in both the districts the mean scores of the responses is less than the standard average mean score, that is, 2 at 3 point scale. The values of standard deviation (which is recorded less than 0.61 in Kangra district and less than 0.64 in Hamirpur district) and the positive values of skewness in both the districts related to all the statements show that the variation in their opinion is minimum and views of the respondents are more tilted towards lower side of mean. Further, the calculated values of  $\chi^2$  in both the districts are more than the table value at 5 per cent level of significance. Hence, the null hypothesis is rejected that the opinion of the respondents is equally distributed. The above analysis reveals that during the Gram Sabha and social audit required information disclosed up to some extent and the proceedings of Gram Sabha meeting was not fully transparent. Further, the rural people do not have easy access to relevant information and documents under MNREGS.

**Conclusion** - With regard to the Social Audit, it was found that in majority of cases (64.78 per cent) Gram Sabha meetings were not held exclusively for social audit in the study area. Even the gram panchayat members as well as officials at the gram panchayat level have accepted it. It was only in 15.28 per cent of cases that the Gram Sabhas were held exclusively for social audit. Furthermore, the gram Panchayats have shown their apathy towards telling the rural people whether a particular Gram Sabha is for social audit or not. In case of disclosing of information about MNREGS, it has been observed that in majority of cases the gram Panchayats did not disclose anything before the Gram Sabha. Even if gram Panchayats were asked (by the Gram Sabha members) to disclose information, they disclosed information partially. In majority of cases (49.52

per cent) rural people have partial access to the MNREGS documents at the time of Gram Sabha and Social audit. While in 42.39 per cent of cases, there was an easy access to all the relevant documents. In case of disclosing of information about MNREGS, it was observed that gram Panchayats did not disclose anything before the Gram Sabha. Whenever the gram panchayat asked (by the Gram Sabha members) to disclose information then gram panchayat partially disclosed the information

**Recommendations** - To overcome these barriers gram Sabha should be exclusively convened to discuss the findings of the aforesaid verification exercise and to review the compliance on transparency and accountability, fulfillment of rights and entitlements of labourers and proper utilization of funds. The village community at large shall be informed about the social audit gram Sabha meeting (agenda, time, place and date). The resource person as well as programme implementation officer should ensure full participation. Social audit report should be prepared in local language to ensure full participation. All elected members of Panchayats and programme implementation officials should be presented at the social audit gram Sabha meeting to answer the queries raised in the meeting.

Social audit should be a regular feature of the schemes to strengthen vigilance, transparency and accountability. Social audit should be linked with release of funds. The gram panchayat that are not conducting social audit should be punished.

#### References :-

1. Social Audit Rules, 2011 and CAGI(2016), "Report on MNREGA".
2. REGP in India, 2011 "An analytical review of Rural Employment Programme in India"
3. Ministry of Rural Department Govt of India 2018, Department of Rural department,
4. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 Rural.nic.in,"<https://rural.nic.in/departments/departments-rural-development>.
5. Pradeep Baisakh (2008, August), Social Audit Scenario in Orissa, in Yojana, Vol. 5, Special Issue, Ministry of Information and Broadcasting, Publication Division, GOI, New Delhi, pp. 22-25.
6. Anupma Hazara (2009, December), Transforming Rural India, in Kurukshetra, Vol. 58, No. 2, Ministry of Information and Broadcasting, Publication Division, GOI, New Delhi, pp. 7-10.
7. Namita Gupta (2010, April-June), An Analysis of NREGA: A Case Study of Punjab (District Mohali), in Indian Journal of Public Administration, Vol. LVI, No. 2, Indian Institute of Public Administration, New Delhi, pp. 233-244.
8. Valmiki Rama Krishna (2010, October-December), Poverty Alleviation Policies: Implementation of National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) in Karnataka, in The Indian Journal of Political Science, Vol. LXX, No. 4, Indian Political Science Association,

- Merut, pp. 1131-1143.
9. P.C. Sikligar (2010, September), Rural Employment Guarantee Scheme in Assam: An Appraisal, in Man and Development, Vol. XXXII, No. 3, Centre for Research in Rural and Industrial Development, Chandigarh, pp. 1-12.
  10. Gundeti Ramesh (2011, April), NREGP and Inclusive Growth-A Study of Karimnagar District in Andhra Pradesh, in Commerce and Management Explorer, Catholicate College, Pathanamithitta, Kerala, pp. 122-126.
  11. P.C. Sikligar (2012, January-March), Impact Assessment of Wage Employment (MGNREGS): A Study in Tripura, Indian Journal of Public Administration, Vol. LVIII, No. 1, Indian Institute of Public Administration, New Delhi, pp. 91-109.

**Responses about the Gram Sabha Meetings, especially, for Social Audit**

Respondents	Blocks of Kangra District											
	Fatehpur				Kangra				Nagrota Bagwan			
	Exclusively	Not Exclusively	Don't Know	Total	Exclusively	Not Exclusively	Don't Know	Total	Exclusively	Not Exclusively	Don't Know	Total
PBs	12 (10.00)	64 (53.33)	44 (36.67)	120 (100.00)	18 (15.00)	78 (65.00)	24 (20.00)	120 (100.00)	17 (14.17)	69 (57.50)	34 (28.33)	120 (100.00)
NBs	2 (10.00)	14 (70.00)	4 (20.00)	20 (100.00)	3 (15.00)	15 (75.00)	2 (10.00)	20 (100.00)	4 (20.00)	13 (65.00)	3 (15.00)	20 (100.00)
POBs	4 (25.00)	12 (75.00)	0 (0.00)	16 (100.00)	8 (50.00)	8 (50.00)	0 (0.00)	16 (100.00)	6 (37.50)	10 (62.50)	0 (0.00)	16 (100.00)
PIOs	3 (25.00)	9 (75.00)	0 (0.00)	12 (100.00)	5 (41.67)	7 (58.33)	0 (0.00)	12 (100.00)	3 (25.00)	9 (75.00)	0 (0.00)	12 (100.00)
Total	21 (12.50)	99 (58.93)	48 (28.57)	168 (100.00)	34 (20.24)	108 (64.28)	26 (15.48)	168 (100.00)	30 (17.86)	101 (60.12)	37 (22.02)	168 (100.00)
Respondents	Blocks of Hamirpur district											
	Bhoranj				Bijhari				Nadaun			
	Exclusively	Not Exclusively	Don't Know	Total	Exclusively	Not Exclusively	Don't Know	Total	Exclusively	Not Exclusively	Don't Know	Total
PBs	13 (10.83)	85 (70.84)	22 (18.33)	120 (100.00)	8 (6.67)	81 (67.50)	31 (25.83)	120 (100.00)	9 (7.50)	85 (70.83)	26 (21.67)	120 (100.00)
NBs	5 (25.00)	14 (70.00)	1 (5.00)	20 (100.00)	1 (5.00)	12 (60.00)	7 (35.00)	20 (100.00)	4 (20.00)	13 (65.00)	3 (15.00)	20 (100.00)
POBs	5 (31.25)	11 (68.75)	0 (0.00)	16 (100.00)	6 (37.50)	10 (62.50)	0 (0.00)	16 (100.00)	6 (37.50)	10 (62.50)	0 (0.00)	16 (100.00)
PIOs	5 (41.67)	7 (58.33)	0 (0.00)	12 (100.00)	4 (33.33)	8 (66.67)	0 (0.00)	12 (100.00)	3 (25.00)	9 (75.00)	0 (0.00)	12 (100.00)
Total	28 (16.67)	117 (69.64)	23 (13.69)	168 (100.00)	19 (11.31)	111 (66.07)	38 (22.62)	168 (100.00)	22 (13.10)	117 (69.64)	29 (17.26)	168 (100.00)

Table continued .....



Continued .....

Respondent	Kangra District				Hamirpur District				Grand Total			
	Exclusively	Not Exclusively	Don't Know	Total	Exclusively	Not Exclusively	Don't Know	Total	Exclusively	Not Exclusively	Don't Know	Total
PBs	47 (13.06)	211 (58.61)	102 (28.33)	360 (100.00)	30 (8.33)	251 (69.73)	79 (21.94)	360 (100.00)	77 (10.69)	462 (64.17)	181 (25.14)	720 (100.00)
NBs	9 (15.00)	42 (70.00)	9 (15.00)	60 (100.00)	10 (16.67)	39 (65.00)	11 (18.33)	60 (100.00)	19 (15.83)	81 (67.50)	20 (16.67)	120 (100.00)
POBs	18 (37.50)	30 (62.50)	0 (0.00)	48 (100.00)	17 (35.42)	31 (64.58)	0 (0.00)	48 (100.00)	35 (36.46)	61 (63.54)	0 (0.00)	96 (100.00)
PIOs	11 (30.56)	25 (69.44)	0 (0.00)	36 (100.00)	12 (33.33)	24 (66.67)	0 (0.00)	36 (100.00)	23 (31.94)	49 (68.06)	0 (0.00)	72 (100.00)
Total	85 (16.87)	308 (61.11)	111 (22.02)	504 (100.00)	69 (13.69)	345 (68.45)	90 (17.86)	504 (100.00)	154 (15.28)	653 (64.78)	201 (19.94)	1008 (100.00)

Source: Primary Probe.

Note: i) 'PBs' denotes 'Programme Beneficiaries'; 'NBs' denotes 'Non-beneficiaries'; 'POBs' denotes 'Panchayat Office Bearers' and 'PIOs' represent 'Programme Implementation Officials'.

ii) Figures in parentheses represent percentage.

#### Statistical Analysis of the Opinion of the sample respondents about the information provided at Gram Sabha, especially for Social Audit

	Statement	SA	PA	NA	Total	$\bar{X}$	$\sigma$	$S_k$	$\chi^2$
Kangra District	Easy access to all the relevant documents	29 (7.02)	210 (50.85)	174 (42.13)	413 (100.00)	1.649	0.608	0.360	133.370
	GP provide all the information at the time of social audit	15 (3.63)	244 (59.08)	154 (37.29)	413 (100.00)	1.663	0.545	0.002	193.370
	GP is answering (feedback) your question without any manipulations	16 (3.87)	215 (52.06)	182 (44.07)	413 (100.00)	1.598	0.564	0.259	165.245
	GP provide Information about the action taken on the complaints	27 (6.54)	230 (55.69)	156 (37.77)	413 (100.00)	1.688	0.589	0.207	153.332
Hamirpur district	Statement	SA	PA	NA	Total	$\bar{X}$	$\sigma$	$S_k$	$\chi^2$
	Easy access to all the relevant documents	38 (9.16)	200 (48.19)	177 (42.65)	415 (100.00)	1.665	0.638	0.429	111.070
	GP provide all the information at the time of social audit	31 (7.47)	208 (50.12)	176 (42.41)	415 (100.00)	1.651	0.615	0.383	128.622
	GP is answering (feedback) your question without any manipulations	25 (6.02)	198 (47.71)	192 (46.27)	415 (100.00)	1.598	0.602	0.456	139.407
Grand Total	Statement	SA	PA	NA	Total	$\bar{X}$	$\sigma$	$S_k$	$\chi^2$
	Easy access to all the relevant documents	67 (8.09)	410 (49.52)	351 (42.39)	828 (100.00)	1.657	0.623	0.398	243.703
	GP provide all the information at the time of social audit	46 (5.56)	452 (54.58)	330 (39.86)	828 (100.00)	1.657	0.580	0.224	314.464
	GP is answering (feedback) your questions without any manipulations	41 (4.95)	413 (49.88)	374 (45.17)	828 (100.00)	1.598	0.583	0.367	302.891
Grand Total	GP provide Information about the action taken on the complaints	46 (5.56)	427 (51.57)	355 (42.87)	828 (100.00)	1.627	0.588	0.322	296.891

Source: i) Primary Probe. ii) Data Compiled from Table 7.41 (a).

Note: i) For  $\chi^2$ , d.f. = 2 in all cases;  $p < 0.05$ ; Table value = 5.991 in all cases

ii) 'SA' represents 'Strongly Agree'; 'PA' represents 'Partially Agree'; and 'NA' represents 'Not Agree'.

**Responses about Information provided at the Time of Gram Sabha, especially, at the Time of Social Audit**

Statement	Blocks of Kangra district											
	Fatehpur				Kangra				Nagrota Bagwan			
	SA	PA	NA	Total	SA	PA	NA	Total	SA	PA	NA	Total
Easy access to all the relevant documents related to MNREGS	7 (5.10)	68 (49.64)	62 (45.26)	137 (100.00)	13 (9.35)	73 (52.52)	53 (38.13)	139 (100.00)	9 (6.57)	69 (50.36)	59 (43.07)	137 (100.00)
GP provide all the information at the time of social audit	2 (1.46)	78 (56.93)	57 (41.61)	137 (100.00)	9 (6.47)	83 (59.72)	47 (33.81)	139 (100.00)	4 (2.92)	83 (60.58)	50 (36.50)	137 (100.00)
GP is answering (feed back) your questions without any manipulations	5 (3.64)	68 (49.64)	64 (46.72)	137 (100.00)	6 (4.32)	73 (52.52)	60 (43.16)	139 (100.00)	5 (3.65)	74 (54.01)	58 (42.34)	137 (100.00)
GP provide Information about the action taken on the complaints	9 (6.56)	75 (54.74)	53 (38.69)	137 (100.00)	11 (7.91)	85 (61.15)	43 (30.94)	139 (100.00)	7 (5.11)	70 (51.09)	60 (43.80)	137 (100.00)
Statement	Blocks of Hamirpur district											
	Bhoranj				Bijhari				Nadaun			
	SA	PA	NA	Total	SA	PA	NA	Total	SA	PA	NA	Total
Easy access to all the relevant documents related to MNREGS	12 (8.70)	69 (50.00)	57 (41.30)	138 (100.00)	9 (6.48)	64 (46.04)	66 (47.48)	139 (100.00)	17 (12.32)	67 (48.55)	54 (39.13)	138 (100.00)
GP provide all the information at the time of social audit	10 (7.25)	71 (51.45)	57 (41.30)	138 (100.00)	7 (5.04)	68 (48.92)	64 (46.04)	139 (100.00)	14 (10.14)	69 (50.00)	55 (39.86)	138 (100.00)
GP is answering (feed back) your questions without any manipulations	9 (6.52)	63 (45.65)	66 (47.83)	138 (100.00)	5 (3.60)	61 (43.88)	73 (52.52)	139 (100.00)	11 (7.97)	74 (53.62)	53 (38.41)	138 (100.00)
GP provide Information about the action taken on the complaints	8 (5.80)	68 (49.27)	62 (44.93)	138 (100.00)	7 (5.04)	51 (36.69)	81 (58.27)	139 (100.00)	4 (2.90)	78 (56.52)	56 (40.58)	138 (100.00)

Source: Primary Probe.

Note: i) 'SA' represents 'Strongly Agree'; 'PA' represents 'Partially Agree'; and 'NA' represents 'Not Agree'.

ii) Figures in parentheses represent percentage.

\*\*\*\*\*

## भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में लोक कला की भूमिका

डॉ. निशा गुप्ता\*

**शोध सारांश** – लोककला ग्रामीण अंचल में बसे भोले-भाले चित्रकार या सामान्यजन की कला है। इस कला में मूलतः शुभ विचार होता है। इस कला का प्रयोग विशेष रूप से शुभ अवसरों पर या धार्मिक अनुष्ठानों को सम्पन्न कराने के लिए किया है। भारत के विभिन्न अंचल की अपनी एक विशिष्ट आदिवासी एवं लोककला है। इस कला का प्रयोग मुख्य रूप से विश्वासों एवं मान्यताओं के अनुरूप जीवन को सुखी एवं शान्तिमय बनाने हेतु दिव्य शक्तियों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस कला में चित्रकार की आत्मा बसती है। इस कला के दर्शन मात्र से ही मन को एक शान्त एवं दिव्य अनुभूति होती है।

**शब्द कुंजी** – दिव्य शक्ति, प्रतिबिम्बित, राष्ट्र धरोहर, संस्कृति, अभिव्यक्ति।

**प्रस्तावना** – लोक कला सदा से ही एक सामुदायिक और सामूहिक अभिव्यक्ति के रूप में अग्रणी रही है। मानव के दैनिक जीवन से इसका गहरा सम्बन्ध है। लोक कला प्रकृति की नकल नहीं करती और न ही उसका यथार्थ रूप सामने रखती है। यह सामान्य सृजक की चेतना पर पड़ी छाप को कल्पना और अभिव्यक्ति के स्तर पर प्रतिबिम्बित करती है। अब यह कला घर आँगन तक सीमित नहीं रही, अपितु खिलौनों, नक्काशी, पूजाग्रहों, भित्ति चित्रों एवं वस्त्रों आदि तक पहुँच गयी है। लोक कला के सृजकों की सामग्री भी स्वाभाविक रूप से मिट्टी और मिट्टी से बने पदार्थों से ही प्राप्त हुई। कला की उन्नति में लोककला का बहुत महत्व रहा है। कला का विकास तो राजाश्रयो में पेशेवर कलाकारों द्वारा हुआ है परन्तु लोककला का विकास घरों के आंगनो में, ग्रामों में, अशिक्षित जातियों में बिना कोई प्रसिद्धि के शांत व अबोध रूप से धार्मिक तथा सांस्कृतिक व पारिवारिक परम्पराओं के साथ बिना बौद्धिक पुट के होता रहा है।<sup>1</sup>

लोक चित्रकला में कभी हमारे पारस्परिक प्रतीक उभर कर आते हैं, तो कभी उसमें से धार्मिक आस्था प्रकट होती है। यह कला समूहगत भावना से उपजी कला है। लोक कला हमारे देश के लोक जीवन, लोक परम्पराओं व लोक संस्कृति का दर्पण है। लोक कला किसी एक प्रदेश की विरासत नहीं है बल्कि यह राष्ट्र की धरोहर है। भारत के किसी भी प्रान्त में जाये, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी जगह लोक कला जीवित है। हर प्रान्त में बस नाम अलग-अलग हैं। जैसे अल्पना, माँडना, रंगोली, ऐपण, चौक पूरना नामों से प्रचलित है। लोक कला एक ऐसी परम्परागत कला के रूप में स्थित है जिसकी जड़े हमारी संस्कृति के साथ आरम्भ से जुड़ी हुई है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ ऐसे अंकन प्रत्येक उपक्रम के साथ कर दिये जाते हैं जिनके पीछे एक धार्मिक भावना का ही अंकन है।

लोक कला ने भारतीय समाज को एक सूत्र में बाँधने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। क्योंकि लोक कला की जड़े लोक जीवन में गहराई से विद्यमान रहती है। समाज व परिवार को बाँधने के लिए लोक में एक विशेष गुण होता है। जिसके तहत समाज, पीढ़ी उसका निर्वाह करती है। लोक कला भारतीय संस्कृति की विशिष्टता है। लोक कला आज मानव की देन नहीं बल्कि प्राचीनकाल की देन है। किसी समय की लोककला अपने युग की सभ्यता

का प्रतीक होती है। लोक कला की परम्परा प्राचीनकाल से भारत में देखी जाती थी। इसी के द्वारा आज भी हम समाज की परम्परा, विश्वासों, संकेतों एवं संस्कारों पर आधारित है।

लोक संस्कृति की जड़े माटी से जुड़ी होती हैं और शिष्ट संस्कृति से सम्बद्ध होती है। जीवन की सीधी, सरल नगरी जीवन के परिकरण से दूर धार्मिक विश्वास और ईश्वरीय विधान पर आधारित लोक संस्कृति के लोक कला रूपों में भी अपनी अनगढ़ता और भोलापन है। लोककला में कोई ऐसी शक्ति अवश्य है जो कलाकार को दिशाहीन नहीं होने देती, उसे जनहित और लोक कल्याण के लिए प्रेरित करती रहती है, समाज को विछिन्न होने से बचाती है, उसके आदर्शों को दृढ़ करती है। जनविरोधी कला लोककला नहीं हो सकती।<sup>2</sup>

लोक कला आज व्यावसायिक स्तर पर भी अपनी पकड़ बना चुकी है। लोग इसे खुले मन से स्वीकार कर रहे हैं। व्यावसायिक स्तर पर किसी भी रूप में प्रयोग करने से लोग हिचकिचा नहीं रहे हैं आज रीति-रिवाज लोक कला से ही प्रेरित हैं, व्यक्ति चाहे कितना भी आधुनिक हो जाये किन्तु वह लोक कला से ही प्रेरित रहेगा। लोक कला को जीवित रखने में महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। जो आज राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय स्तर पर पहुँच चुकी है। हमारी भारतीय संस्कृति को भी लोक कला अपने साथ ही लेकर आगे बढ़ रही है। भारतीय संस्कृति और लोक कला दोनों का आपस में गहन सम्बन्ध रहा है जो आज लोक कला के चित्रों में दिखाई पड़ता है।

लोक कला हमारे विरोधी प्रवृत्तियों का समन्वय कर हमारे व्यक्तित्व की एकरूपता को दृढ़ करती है। लोक कला सामाजिक मान्यताओं व परम्पराओं से अलग नहीं रह सकती। लोक कलायें संस्कृति का शृंगार करती हैं। सच्ची कलाकृतियों का सौन्दर्य शाश्वत होता है, सार्वभौम होता है, देश काल के परिवर्तनों से परे होता है। उसका उत्कृष्ट सौन्दर्य सचमुच नयनाभिराम होता है।<sup>3</sup> चुनौतियों से जूझते हुए समाज को लोक कलायें उर्जा और चेतना प्रदान करती है। भारतीय संस्कृति मंगल भावना के स्वरो से परिपूर्ण है। सांस्कृतिक परम्परा का एक दीर्घ अंश लोक संस्कृति से सम्बद्ध है। धर्म और संस्कारों में यह जल में शक्कर की तरह घुली मिली हुई है, जिसे अलग कर पाना असम्भव है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त धार्मिक अनुष्ठान होते हैं।

मृत्यु पश्चात श्राद्ध, वसी, तेरहवीं व जन्म से पूर्व 'साथ' पूजन तथा विवाह अवसर आदि के रूप में लोक कला प्राचीन संस्कृति को आधुनिक संस्कृति से मिलाने की एक कड़ी है। कला को समाज और संस्कृति से कभी भी काटा नहीं जा सकता।<sup>4</sup>

भारतीय संस्कृति को जीवित रखने में लोक कला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये एक सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। क्योंकि इनको अलग नहीं किया जा सकता। हर देश व क्षेत्र की अपनी-अपनी संस्कृति व परम्परा होती है। लोक कला का अपने क्षेत्रों की संस्कृति व परम्परा के अनुरूप ही चित्रण किया जाता है। संस्कृति और कला दोनों साथ-साथ चलती है। इन्हें अलग न तो माना जा सकता है और न ही अलग किया जा सकता। लोक कला का भारतीय संस्कृति को जीवित रखने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

आज सरकारी, गैर सरकारी संस्थायें एवं संगठन सभी मिलकर इसमें निहित संभावनाओं से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्हें उत्पादों का प्रचार-प्रसार उनकी ब्रांड छवि बनाने जैसे:- अनेक कदम उठाने होंगे। प्रायः देखा जा रहा है कि उत्तर-प्रदेश के हस्तशिल्प में लोक कला का प्रयोग दीवारों पर, भूमि पर, मूर्ति निर्माण में, जैसे कुम्भकारी, कसीदाकारी, बढईगिरी के रूप में हो रहा है।

इसके अतिरिक्त इसका व्यापक रूप निम्न प्रकार से लोक निर्माण बाजारों में देखा जा सकता है। जोकि बिन्दी, रूप सज्जा, मेंहदी, आर्ट डायरेक्शन, ग्राफिक, लिथोग्राफर, फैशन डिजाइनिंग, पॉट मेकिंग, फिल्म, न्यूज पेपर, मेंगजीन, कढ़ाई आदि सभी क्षेत्रों में हस्तशिल्प लोककला का

प्रयोग बड़े-बड़े क्षेत्रों में अवसर प्रदान कर रहा है। बदलते परिवेश में आज गाँवों में ही नहीं वरन् शहरों में भी अपनी लोक संस्कृति के सम्मान स्वरूप हस्तशिल्पी नित नूतन प्रयोग के द्वारा लोगों की माँग के अनुसार चारपाई बुनकर, दरवाजों के, डिजाइन, पंखों पर आर्ट एण्ड क्राफ्ट आदि में बाजारों की माँग के अनुसार लोक कला का उपयोग भी कर रहे हैं। अपने फुर्सत के समय चटाई, टोकरी, कालीन, कपड़े, स्वेटर, तकिया, रुमाल, भित्तिचित्र, बिटोड़ों आदि पर शोभार्थ अनेक अलंकरण बनाती है।<sup>5</sup>

लोक कला ने विश्व बाजार को न केवल चमत्कृत किया है बल्कि वे अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाने में सफल हुई है। हमारे यहाँ की हस्तशिल्प कला और लोक कलाओं से निर्मित वस्तुओं के प्रति विश्व पर्यटकों में एक विशेष रुचि आकर्षण व लगाव देखने को मिलता है। जिससे सहज रूप से आज बाजारों में हस्त निर्मित कला, मेलों में हाटों में, कार्यशालाओं में और शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों सभी जगहों पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग का दर्जा भी लेती जा रही है।

### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. लोकेश चन्द्र शर्मा - भारत की चित्रकला का इतिहास
2. डॉ० एस०एन० सक्सेना - दृश्य कला एवं दृष्टिकोण
3. डॉ० राजेन्द्र प्रसाद वाजपेयी - सौन्दर्य
4. प्रकाश वीरेश्वर, नूपुर शर्मा - कला दर्शन
5. डॉ० आर०ए० अग्रवाल - कला विलास

\*\*\*\*\*



## जीवन बीमा नियमन , नियंत्रण कानून एवं शिकायत निवारण

**डॉ.महेश शर्मा\* मोनिका सिंघल\*\* डॉ.डी.के सिंघल\*\*\***

**शोध सारांश** - हमारे देश में जीवन बीमा व्यवसाय के नियमन एवं नियमन करने हेतु कई अधिनियमों को लागू किया गया ताकि बीमा व्यवसाय को सफलता पूर्वक किया जा सके। क्योंकि बीमा जोकि व्यवसायिक हानि एवं संभावित व्यक्तिगत हानि से सुरक्षा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है अतः बीमा क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख अधिनियम इस प्रकार है। भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का श्रीगणेश वर्ष 1818 से माना जाता है।

भारत में वर्ष 1912 में सर्वप्रथम बीमा अधिनियम पारित किया गया। मल्होत्रा समिति के सुधार के लिए सुझावों के आधार पर सम्पूर्ण बीमा क्षेत्र के नियमन व नियन्त्रण हेतु संवैधानिक संस्थान का बीमा नियमन एवं विकास अधिनियम गठन 1999 में किया गया। बीमा व्यवसाय पर अनेक प्रकार के अधिनियम लागू होते हैं। बीमा संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण में एक शिकायत निवारण कक्ष बनाया गया है।

**शोध प्रविधि**- विभिन्न शोध पत्रों एवं पुस्तकों से संकलन तथा द्वितीयक संमकों से संकलन एवं विश्लेषण।

**कुंजी शब्द** - हानि , जोखिम, नियम , शिकायत, कर।

**प्रस्तावना** - हमारे देश में जीवन बीमा व्यवसाय के नियमन एवं नियमन करने हेतु कई अधिनियमों को लागू किया गया ताकि बीमा व्यवसाय को सफलता पूर्वक किया जा सके। क्योंकि बीमा जोकि व्यवसायिक हानि एवं संभावित व्यक्तिगत हानि से सुरक्षा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है अतः बीमा क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख अधिनियम इस प्रकार है।

भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का श्रीगणेश वर्ष 1818 से माना जाता है जब इस वर्ष में अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में ओरियण्टल लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी की स्थापना के माध्यम से सर्वप्रथम जीवन बीमा कारोबार की शुरुआत की गई, इसके बाद वर्ष 1823 में बम्बई में बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी तथा वर्ष 1829 में मद्रास इन्सुरेंस लाइफ इंश्योरेंस सोसायटी की गई तब से लगातार वर्ष 1870 छोटी-बड़ी कम्पनियों की स्थापना हुई। 19 वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में दो अन्य भारतीय कम्पनियाँ भारत (1896) और एम्पायर (1897) भी की गई।

भारत में वर्ष 1912 में सर्वप्रथम बीमा अधिनियम पारित किया गया।

### तालिका 1 - (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

**बीमा अधिनियम 1938** - बीमा अधिनियम 1938 भारत में विविध प्रकार की बीमा संस्थाओं के कार्यकलाप को विनियमित और नियंत्रित करने के उद्देश्य से पारित किया गया एक महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है। इस अधिनियम के पारित होने के पहले भारत में बीमा व्यवसाय को शासित करने के लिये कोई उपयुक्त कानून नहीं था। सन् 1912 में दो अधिनियम बनाए गये थे -

1. प्रावीडेंट इंश्योरेंस सोसायटी अधिनियम 1912
2. इण्डियन लाइफ इंश्योरेंस कम्पनीज अधिनियम 1912

किन्तु ये दोनों ही अधिनियम लोगों का विश्वास अर्जित करने के लिए बीमा व्यवसाय से संबंधित कानूनी खामियों को दूर नहीं कर सके। यद्यपि

उक्तकथित 1912 के अधिनियम को पुनः सन् 1928 में भारतीय जीवन बीमा अधिनियम 1928 द्वारा संशोधित किया गया और तत्पश्चात् सन् 1928 में बीमा अधिनियम पारित हुआ, किन्तु वह भी प्रयोगात्मक ही था। जनता यह चाहती थी कि बीमा व्यवसाय पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया जाय। अस्तु तीव्र जनान्दोलन को देखते हुये तत्कालीन भारत सरकार ने बीमा अधिनियम 1938 पारित किया। इसलिए सन् 1938 में पारित बीमा अधिनियम को ही बीमा व्यवसाय संबंधी प्रभावशाली विधान कहा जाता है। इस अधिनियम में सन् 1950 और 1968 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए जिनके फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार को जीवन बीमा कम्पनियों के ऊपर अनेक नियंत्रण संबंधी अधिकार प्राप्त हुए।

किन्तु सन् 1956 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ और जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 लागू हुआ अतएव बीमा अधिनियम के कतिपय नियमों को छोड़कर शेष नियम जो जीवन बीमा कारोबार से संबंधित थे, प्रभावहीन हो गए।

बीमा अधिनियम में सन् 1968 में पुनः महत्वपूर्ण संशोधन करके साधारण बीमा के कारोबार पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने की व्यवस्था हुई। इसके पश्चात् सन् 1972 में साधारण बीमा का संपूर्ण कारोबार भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी चार सहायक कम्पनियों के अधिकार में आ गया। साधारण बीमा के कारोबार में संलग्न इन सभी कम्पनियों को बीमा अधिनियम 1938 के अनेक नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

सन् 1956 में जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ और इस क्षेत्र में इस व्यवसाय को करने का एकाधिकार भारतीय जीवन बीमा निगम को प्राप्त था परन्तु विगत दशक में वित्त व्यवस्था में उदारीकरण की नीति अपनाई गई और बीमा व्यवसाय में प्राइवेट सेक्टर का प्रवेश आवश्यक

\* प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय कालीदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

\*\* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

\*\*\* प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय कालीदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

पाया गया। अतः जीवन बीमा व्यवसाय में भारतीय जीवन बीमा निगम को प्राप्त यह एकाधिकार अप्रैल 2000 में समाप्त हो गया।

‘बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999’ के बन जाने के बाद बीमा अधिनियम, 1938 में काफी संशोधन किये गये हैं जिनके द्वारा कुछ उपबन्धों को अंतर्विष्ट, प्रतिस्थापित तथा लोप कर दिया गया है। **बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999** – देश के बीमा उपभोक्ताओं के हित में बीमा सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में वृद्धि के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने बीमा व्यवसाय का उदारीकरण का फैसला किया जिसके आधार पर बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 बनाया गया है इस अधिनियम को संक्षेप में इरडा भी कहते हैं। इस अधिनियम के बनने से जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम का बीमा क्षेत्र से एकाधिकार समाप्त हो गया है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 का वर्णन करने से पहले यह जानना आवश्यक कि इस अधिनियम के बनने के पीछे क्या परिस्थितियां थी और इसके बनने का क्या औचित्य था।

बीमा व्यवसाय का निजीकरण करने के संबंध में राय जानने के लिये भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1993 में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर आर.एन.मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गयी थी उसकी संस्तुतियां मुख्यतः देश के बीमा उपभोक्ताओं के हित में बीमा सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में वृद्धि के दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गयी थी। समिति का मानना था कि यद्यपि राष्ट्रीयकरण के बाद से बीमा क्षेत्र का काफी विकास हुआ है परन्तु कई कारणों से बीमा उद्योग को निजी कम्पनियों के लिये खोला जाना ही उचित समझा गया।

‘मल्होत्रा कमेटी’ की संस्तुतियों के आधार पर ‘बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999’ बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत एक बीमा नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गयी, जिसका मुख्य कार्य बीमाधारक के हित की सुरक्षा करना, बीमा कारोबार को विनियमित करना, प्रोन्नत करना और उसकी सुव्यवस्थित वृद्धि करना और उससे सम्बंधित या अनुषंगिक मामलों को देखना हैं। इसके अतिरिक्त बीमा अधिनियम 1938 जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 में संशोधन किए गए हैं। यह अधिनियम अप्रैल 2000 से प्रभावी हो गया है।

### उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

**उपभोक्ता संरक्षण** – आज उपभोक्ता सावधान के स्थान पर उपभोक्ता के प्रभुत्व ने स्थान ले लिया है परंतु व्यवहार में देखे तो उपभोक्ता आज भी उत्पादकों के शोषण का शिकार हैं। आज भी उपभोक्ता मिलावट कम मापतौल, घटिया वस्तु, भ्रामक विज्ञापन आदि का शिकार हैं। अतः आवश्यकता है कि उपभोक्ताओं को इन शोषणों से बचाया जाये। इसके लिए सरकार व सामाजिक संठनों का उत्तरदायित्व सर्वाधिक है। सरकार एवं संगठनों द्वारा उपभोक्ता को इन बुराईयों या शोषणों से बचाने के जो वैधानिक व सामाजिक उपाय किये गये हैं, वास्तव में वह उपभोक्ता संरक्षण कहा जा सकता है। आज मांग में तेजी से वृद्धि, एकाधिकारी प्रवृत्तियों का विकास, विज्ञापन आदि के कारण बाजार में जो कुछ भी पेश किया जा रहा है उसे हम स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं अतः आवश्यकता है कि व्यवसाय को अधिक उत्तरदायी बनाया जाये तथा उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा की जाये।

यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं पर लागू होता है। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की

स्वीकृति 24 दिसम्बर 1986 को दी गई लेकिन अधिनियम 15.04.1987 को लागू हुआ। यद्यपि उपभोक्ता निदान संस्थाओं का विषय 01.07.1987 को ही लागू हो पाया।

**नरसिंम्हा विरुद्ध भारतीय जीवन बीमा निगम** – इस मामले में एक प्रश्न उठा कि क्या मृतक पॉलिसी धारक की विधवा को इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता माना जाए। आन्ध्रप्रदेश राज्य आयोग ने उसे उपभोक्ता माना क्योंकि उपभोक्ता शब्द में शामिल हैं उस व्यक्ति के अतिरिक्त सेवा का कोई उपोगकर्ता जिसने प्रतिफल के लिए उस सेवा को किराये पर लिया है और इस प्रकार विधवा सेवा की उपयोगकर्ता होने के कारण ‘उपभोक्ता’ हैं जो एल.आई.सी की भूल के कारण उसको हुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति पाने की पूरी अधिकारी है। **‘सेवा’ (सर्विस)** – अधिनियम की धारा 2(1)(ओ) के अनुसार सेवा का अर्थ है किसी विवरण की सेवा जो सम्भावित उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध की जाती है सेवा के अंतर्गत बैंकिंग, वित्त प्रबंधन, बीमा, परिवहन विद्युत या अन्य ऊर्जा की सप्लाई खाना अथवा ठहरना या दोनों, आवास निर्माण, मनोरंजन आदि शामिल है।

उस मामले में अनेक विवाद न्यायालयों के समक्ष आये हैं तथा निरन्तर आते रहते हैं जिनमें कुछ निम्नानुसार हैं –

जीवन बीमा निगम द्वारा बार-बार मांगे जाने पर भी पॉलिसी धारक को बोनस, समर्पण मूल्य तथा विशेष समर्पण मूल्य आदि की सूचनाएँ न देना ‘सेवा में कमी’ मानी जाएगी। (चेयरमैन जीवन बीमा निगम बनाम अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आई.एफ. न. 41/1990 निर्णीत 09.10.1990)

डिविजनल मैनेजर, भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम भावनाम श्रीनिवास रेड्डी एफ.ए.न.79/1990 निर्णय (05.06.1991) के मामले में राष्ट्रीय आयोग ने पाया कि किसी बीमा दावे के निपटान के बारे में भूल अथवा लापरवाही (महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाकर) बीमा कम्पनी की आरे से ‘सर्विस में कमी’ हैं तथा पीड़ित पक्षकार को न्याय का द्वारा खटखटाने का पूरा अधिकार है। बीमा नियमन एवं विकास अधिनियम एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 तथा अन्य अधिनियमों के नियम के परिपालन करने पर निम्नानुसार शिकायतें विभिन्न जीवन बीमा कम्पनियों को प्राप्त हुई एवं उनका निराकरण हेतु कार्यवाही की गई। बीमा संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण में एक शिकायत निवारण कक्ष बनाया गया है, जो उपभोक्ता से प्राप्त शिकायतों /परिवादों की जाँच करता है। यह कक्ष निवारण के लिए संबंधित बीमाकर्ताओं के साथ शिकायतों को उठाता है।

### तालिका 2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

**आयकर अधिनियम** – 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप घाटे की पूर्ति के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा दण्डात्मक रूप से लगाया गया आयकर आज भारतीय राजस्व का एक अनिवार्य एवं सर्वाधिक, महत्वपूर्ण अंग बन गया है। आयकर अधिनियम 1961 संपूर्ण भारत (जम्मू कश्मीर सहित) में 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ। सिक्किम में यह 1.4.1990 से लागू हुआ।

**आयकर अधिनियम में बीमा संबंधी प्रावधान निम्नानुसार है** – जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए आय से कटौती (धारा 80 सी) – अपने अथवा अपने जीवन साथी अथवा अपने बच्चों (वयस्क या अवयस्क, आश्रित या अनाश्रित, विवाहित या अविवाहित) के जीवन पर कराए गए बीमों का प्रीमियम। हिन्दु अविभाजित परिवार की दशा में सदस्यों की जीवन बीमा प्रीमियम। यदि पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 पूर्व ली गयी हो तो पॉलिसी की

राशि के 20 प्रतिशत से अधिक प्रीमियम कटौती योग्य नहीं होगी। वर्ष 2019-20 में ली गयी पॉलिसी की दशा में बीमित राशि के 10 प्रतिशत राशि ही कटौती योग्य होगी। यदि पॉलिसी 1 अप्रैल 2019 के पश्चात् जारी की गई हो, तथा ऐसे व्यक्ति के जीवन पर जारी की गई हो जो -

- 1) धारा 80 यूमें वर्णित अपंग या गंभीर अपंगता से पीड़ित हो।
- 2) धारा 80 डीडीबी के अंतर्गत बनाए नियमों में निर्दिष्ट बीमारी या रोग से पीड़ित हो, इस धारा में मान्य कटौती वास्तविक पूंजीगत बीमा राशि के 15 प्रतिशत तक की सीमा तक ही है।

जीवन बीमा निगम आदि के पेंशन फण्ड में अंशदान के संबंध में कटौती (धारा 80) - जब कोई व्यक्ति करदाता भारतीय जीवन बीमा निगम या अन्य मान्य बीमाकर्ता की वार्षिकी योजना में पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई अंशदान देता है, तो उसे सकल कुल आय में से ऐसे अंशदान की कटौती निम्न शर्तों के अधीन प्राप्त होगी-

- 1) अंशदान की राशि या अधिकतम 1,00,000 रु प्रतिवर्ष, जो कम हो उसकी कटौती प्राप्त होगी।
- 2) जीवन एवं चिकित्सा बीमा पॉलिसी में चुकायी प्रीमियम पर धारा 80 सी एवं धारा 80 डी की छूट मिलती है।

**माल एवं सेवा कर अधिनियम -** 01 जुलाई 2017 को 'एक देश , एक कर, एक बाजार' की धारणा के साथ सम्पूर्ण देश में माल एवं सेवा कर अमल में आया। इसमें सेवाओं की पूर्ति पर कर लगाया गया। इसमें सेवा की परिभाषा माल एवं सेवा कर की धारा 2 (102) में इस प्रकार दी है-

'सेवाओं से आशय माल, मुद्रा और प्रतिभूतियों से भिन्न कोई वस्तु से है जिसके लिए पृथक प्रतिफल प्रभारित किया गया है। इसमें धन का उपयोग या नकद या किसी अन्य रीति से एक करेंसी या अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप, करेंसी या अंकित मूल्य में उसका ऐसा परिवर्तन जिसके लिए पृथक, प्रभारित हो, सम्मिलित से सम्बन्धित क्रिया कलाप हैं।'

माल एवं सेवा कर जीवन बीमा पर 25 प्रतिशत लागू किया गया है। पारंपरिक एंडोमेंट इंश्योरेंस पर प्रथम वर्ष 25 प्रतिशत एवं अगले वर्ष से कर 12.5 प्रतिशत कर लगाया जाता है।

बीमा व्यवसाय पर अनेक प्रकार के अधिनियम लागू होते हैं। बीमा को व्यवस्थित तरीके से करने, अरबों रुपये की प्रीमियम प्राप्त करने एवं बीमा दावों का निपटारा के लिए भारत में अनेक कानून बनाये गये हैं ताकि बीमा व्यवसाय का नियमन एवं नियंत्रण किया जा सके। बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण जैसा प्रमुख संस्था का कार्य यही है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2018.-19
2. बीमा के मूलतत्व-डॉ.आर.एल.नौलखा ,रमेश बुक डिपो जयपुर
3. आयकर डॉ.एच.सी मेहरोत्रा साहित्य भवन आगरा
4. माल एवं सेवा कर डॉ.श्रीपाल सकलेचा सतीश प्रिंटर्स इन्दौर
5. प्रतियोगिता दर्पण
6. एम.आब्लद , भारतीय बीमा उद्योग, चैनलिंग ग्रोथ ए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनानिस्ट
7. अनिल भट्टा चार्य , 'लाइफ इंश्योरेंस से पहले चुनौतियां' ,जीवन बीमा व्यवसाय
8. वी. राजगोपाल, 'लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों का अभाव : कुछ कारक कारण'
9. बैकिंग एवं बीमा के मूलतत्व सन्नियम एस.एम.शुक्ला साहित्य भवन , आगरा
10. बोडला,बी.एस.गर्ग, के.पी.सिंह, बीमा-फंडामेंटल्स, इंवार्मिन्ट एवं प्रासिजर्स,दीप एंड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली
11. life insurance Websites
12. <http://www.researchandmarkets.com>
13. <http://www.irdaindia.org> res
14. <http://www.LIC.co.in/about.htm>
15. <http://www.economywatch.com/indianeconomy/> Indian insurance sector
16. <http://www.irda.gov.in>
17. <http://www.insuranceicai.org>

#### तालिका 1 - बीमा क्षेत्र से संबंधित प्रमुख अधिनियम एवं संस्थाएँ

क्र.	अधिनियम	वर्ष	प्रमुख उद्देश्य
1.	भारतीय जीवन बीमा अधिनियम	1912	भारत में जीवन बीमा के नियमन हेतु कानूनी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना
2.	बीमा अधिनियम	1938	भारत में बीमा व्यवसाय से संबंधित कानूनी प्रावधानों का निर्धारण करना
3.	भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम	1956	भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किये जाने हेतु कानून को पास करना
4.	जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण	1956	जीवन बीमा व्यवसाय को केवल सरकारी क्षेत्र में रखे जाने के प्रावधान सुनिश्चित करना
5.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) का गठन	1988	प्रतिभूतियों तथा बीमा आदि क्षेत्रों के निवेशकों के हितों की रक्षा करने हेतु संवैधानिक संस्था की व्यवस्था करना
6.	आर.एन.मल्होत्रा समिति का गठन	1993	अप्रैल 1993 में गठित इस समिति द्वारा 7 जन . , 1994 को बीमा आदि क्षेत्रों में सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए
7.	बीमा नियमन एवं विकास अधिनियम	1999	मल्होत्रा समिति के सुधार के लिए सुझावों के आधार पर सम्पूर्ण बीमा क्षेत्र के नियमन व नियन्त्रण हेतु संवैधानिक संस्थान का गठन करना

स्रोत- बैकिंग एवं बीमा के मूलतत्व सन्नियम एस.एम.शुक्ला साहित्य भवन , आगरा

**तालिका 2 –जीवन बीमाकर्ताओं के साथ शिकायतों की स्थिति (2017-18 एवं 2018-19)**

बीमाकर्ता	2017-18			2018-19		
	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान हल की गई	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान हल की गई
बिरला सन लाइफ क.	10	6793	6786	17	2963	2978
एजोन रैलीगेयर लाइफ इंश्योरेन्स	0	1764	1764	0	1049	1049
एविवा लाइफ इंश्योरेन्स कम्पनी	0	2282	2282	0	2076	2076
बजाज एलाइन्ज	0	3439	3421	18	2269	2285
भारती ए.एक्स.ए.	8	4148	4156	0	6360	6360
केनरा एच.एस.बी.सी	0	665	663	2	717	716
डी.एल.एफ.प्रमेरिका	1	1592	1589	4	972	976
एडेलवेसिस टोकियो	0	329	329	0	441	441
एक्साइड लाइफ	0	4201	4201	0	3470	3470
फ्यूचर जेनेरली इन्डिया	15	4447	4462	0	4132	4132
एच.डी.एफ.सी.स्टेन्डर्ड	10	7257	7256	11	6026	6035
आई.सी.आई.सी.आई.प्रोडेंशल	3	7700	7701	2	6393	6393
आई.डी.बी.आई.फेडरल	0	742	742	0	788	788
इंडिया फर्स्ट	19	3219	3201	37	3080	3097
कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्यूच. लाइफ	105	3400	3480	25	926	940
मेक्स न्युयार्क लाइफ	0	5544	5544	0	4038	4038
पी.एन.बी.मेट	70	4228	4226	72	3558	3591
रिलायन्स लाइफ	0	1615	1614	1	2052	2053
सहारा इण्डिया लाइफ	3	82	74	11	110	120
एस.बी.आई.लाइफ	2	7640	7642	0	4649	4649
श्री राम लाइफ इंश्योरेन्स क.	1	406	406	1	577	576
स्टार यूनियन लाइफ	0	2556	2556	0	2045	2045
टाटा ए.आई.जी.इंश्योरेन्स	0	3134	3134	0	2446	2446
निजी कम्पनी की शिकायतों का योग	247	77183	77229	201	61137	61254
लाइफ इंश्योरेन्स कापॉरेशन	0	77184	77184	0	102127	102127
महायोग	247	154367	154413	201	163264	163381

स्रोत-बीमा नियमन एवं विकास अभिकरण वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

\*\*\*\*\*



## राष्ट्रवाद के विकास में आदिवासियों की भूमिका

### प्रेमिका पंत \*

**प्रस्तावना** - आदिवासी शब्द का अर्थ ऐसे मानव जो आदि परंपरा को लेकर जंगल में वास करते हैं। भारतीय इतिहासकारों द्वारा सन् 1857 की क्रान्ति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। परन्तु इससे पूर्व भी आदिवासियों ने स्वतंत्रता आन्दोलन शुरू किया था 'कृषि क्रान्ति के लेखक श्री कृष्ण सरल ने राष्ट्रीय आंदोलन आदिवासियों की भूमिका को माना है।'<sup>1</sup> 1757 ई. में प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें बंगाल का नबाव सिराजउद्दौला को ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने हराकर बंगाल में भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव डाली अंग्रेजों द्वारा भारत का शासन हाथ में लेने के बाद अंग्रेजों ने समय-समय पर अनेक अधिनियम पास किये गये जिनसे शासन की बागडोर ओर मजबूत हो।<sup>2</sup> ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा स्थाई बन्दोबस्त, रैयत वाडी माहालबाडी व्यवस्था को भारतीय कृषकों पर दबाव के द्वारा लागू किया गया।<sup>3</sup>

आमतौर पर आदिवासी शेष समाज से अपने अलग जंगलों में वास करते थे उनकी आजीविका का साधन झूम कृषि करना, लकड़ी इकट्ठा करने, पशुओं को चराना वे पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर रहते थे।<sup>4</sup> जिन्हें वन अधिनियम लागू होने से जंगलों से बाहर कर दिया गया उनकी जमीनों पर जंगलों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया गया इन अधिनियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड या जुर्माना लगा दिया गया जिससे आदिवासियों समाज पूर्ण रूप से बेराजगार हो गया जबकि जंगलों पर आदिवासी अपना पितृत्व अधिकार मानते थे। सम्पूर्ण भारत में आदिवासी निवास करते थे।<sup>5</sup> जिससे आदिवासियों में रोश उत्पन्न हुआ ब्रिटिश शासकों को कोई कानून लागू करवाना होता तो इन्हीं के सामंतों और जमींदारों से करवाते थे। राजस्व वसूली भी इसलिए आदिवासियों की सीधी लडाई जमींदारों और सामंतों से होती थी।<sup>6</sup> ऐसी स्थिति में आदिवासियों को स्वयंतता और स्वतंत्रता के हर आन्दोलन में अंग्रेजों हुकूमत के साथ-साथ सामंतों और साहूकारों से भी संघर्ष करना पडा था अंग्रेजी सरकारों द्वारा जमकर शोषण अत्याचार किये गये अब वे अपनी ही जमीन पर मजदूर बन कर रहे गये थे और उन्हें खानों, बागानों और फैक्ट्रियों में कार्य करने के लिए तथा कुलीगिरी करने के लिए विवश किया गया अतः आदिवासियों द्वारा सम्पूर्ण भारत में अपने को वर्ग के आधार पर संगठित कर विद्रोह किये।<sup>7</sup> जिससे आदिवासियों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया गया हालाँकि यह प्रारम्भिक रूप स्थानीय स्तर पर हुये धीरे-धीरे पूरे भारत में फैल गये। सबसे सन् 1772 ई. पहला विद्रोह राजमहल की पहाड़ियों में स्थित उन जनजातियों का विद्रोह था जिनके क्षेत्रों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया था आदिवासियों को स्वतंत्रता आन्दोलनों खूनी कीमत चुकानी पडी अंग्रेजों के पास भारी संख्या में सुसज्जित सेना थी आधुनिक हाथियारों बंदूक, तोपे, गोला और बारूद या प्रशिक्षित सेना थी

इसके मुकाबले में आदिवासियों के युद्ध के परम्परागत साधन तीर-कमान, भाले, फरसे और गण्डासे थे। आदिवासी आर्थिक रूप से कमजोर थे। इसमें आदिवासियों को भारी जानमाल को क्षति उठानी पडी।<sup>8</sup> (सन् 1780 ई.) संधाल विद्रोह आदिवासियों का सर्वाधिक जबरदस्त विद्रोह था यह विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच केन्द्रित था जो प्रारम्भ में दो आदिवासियों वीरो तिलका और मांझी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था इसे दामिनी विद्रोह कहते हैं। बाद में इसी अन्दोलन का नेतृत्व सिद्ध और कान्हू नामक दो संधालों ने नेतृत्व प्रदान किया सन् 1832 में खोड विद्रोह चक्र बिसोई नेतृत्व में किया गया राधकृष्ण दण्डसेन ने भी इस विद्रोह में अपना योगदान दिया, कोल विद्रोह राकची सिंह भूमि हजारीबाग के क्षेत्रों में फैला। सन् 1832-37 ई. चला।<sup>10</sup> खाखाड विद्रोह संधालों के विद्रोह के दमन के बाद 1870 ई. में हुआ वह भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था के विरुद्ध हुआ इसी प्रकार भील विद्रोह राजस्थान के बासवारा में हुआ, नैकडा आंदोलन मध्यप्रदेश और गुजरात के आदि मुण्डा विद्रोह बिरसा मुण्ड के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ जो बहुत अधिक उग्र हुआ।<sup>11</sup> अंग्रेज अधिकारियों को इस आन्दोलन का कुचलने में अंग्रेजी सरकार को बहुत मेहनत करनी पडी यह बहुत सशक्त विद्रोह हुआ सभी आदिवासी स्त्री पुरुष द्वारा विद्रोह का झण्डा बुलंद कर दिया गया और राष्ट्रवाद की भावना को उग्र रूप प्रदान किया दक्षिण भारत भी तानाभगत आंदोलन की शुरुआत छोटा नागपुर बिहार में हुई इस आंदोलन को भगत आंदोलन इसलिए कहा गया क्योंकि इसका नेतृत्व आदिवासियों के बीच के उन लोगों ने किया जो फकरिया धर्माचार्य जतरा भगतु बलराम भगत देवमेनिया भगत ने अपना नेतृत्व दिया।<sup>12</sup> चैचू आंदोलन (आंध्रप्रदेश) के गुंटूर जिले में 1920 में जंगल सत्याग्रह के रूप में शुरू किया गया, खांसी विद्रोह अहमो विद्रोह, नागा आंदोलन, इस आंदोलन को 17 वर्षीय नागा महिला गौडिनलियु ने नेतृत्व प्रदान किया सभी आदिवासी विद्रोह के द्वारा राष्ट्रीय विलमत प्रारम्भ हुआ जो आगे भारतीय लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना बिना आदिवासी विद्रोह राष्ट्रवादी क्रान्ति सन् 1857 ई. की क्रान्ति भावना का विकास किया राष्ट्रीय आंदोलन को आधार आदिवासियों के इन्हीं आंदोलनों ने दिया भारत में राष्ट्रवाद राष्ट्रीय आंदोलन को खड़ा करने में आदिवासी आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।<sup>13</sup>

### संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. विपिन चन्द्र आधुनिक भारत का इतिहास 2009 पृ. 178
2. वही पृ. 178
3. ए. आर. देसाई भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठ भूमि पृ. 31

- |   |  |
|---|--|
| 2016  | 8. दिनेश चन्द्र भारद्वाज- पृ. 13                         |
| 4. वही पृ. 31   | 9. बी.एन. लुणिया पृ. 129                                 |
| 5. पी.एन. चौपडा, वी.एन पुरी, एम.एन. दास, 1990 पृ. 177 भारत का सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास | 10. वही पृ. 132  |
| 6. वही पृ. 177  | 11. ताराचन्द्र भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास खण्ड-2 |
| 7. वही पृ. 178  | 12. वही पृ. 431  |
|   | 13. वही पृ. 431  |

\*\*\*\*\*

## कृषि विकास की दिशा में ई-तकनीकी का योगदान

**डॉ. प्रभु प्रकाश पाण्डेय\* बिन्दु बहादुर कुशवाहा\*\***

**शोध सारांश** - देश में कृषि विकास को विकसित करने एवं कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विविध प्रकार की नीतियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी क्रम में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के साथ-साथ सूचना एवं संचार तकनीकी की उपयोगिता को समझते हुये कृषकों तक नवीनतम कृषि सम्बन्धी वैज्ञानिक जानकारीयों के प्रचार-प्रसार हेतु कई महत्वपूर्ण तकनीकी पहल की गई है। वेब-आधारित पोर्टल का भी निर्माण किए गये हैं। आईसीओएओ के संस्थानों के विषय में जानकारीयों प्रदान करवाने हेतु आईसीओएओ पोर्टल एवं कृषि शिक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचनाएँ देने के लिए एबी यूनिवर्सिटी पोर्टल को विकसित किया गया है। उसके अलावा कृषि उत्पादों के बाजार भाव की सूचना प्रदान करने हेतु विकसित किया गया मोबाइल एप या फिर बीमा योजना से सम्बन्धित मोबाइल एप, सभी प्रकार की कृषि से सम्बन्धित सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर है। वास्तविकता तो अब यह है कि हमारे देश में कृषि विकास की कुंजी अब सूचना तकनीकी सृजित कर रही है। विभिन्न कार्यक्रमों एवं उदाहरणों से यह तो स्पष्ट है कि सूचना तकनीकी भविष्य में कृषि गवर्नेंस के मार्ग को ओर ज्यादा से ज्यादा आसान बना सकाती है।

**शब्द कुंजी** - कृषि विकास, किसान, ई-तकनीकी, योजनाएं।

**प्रस्तावना** - देश की आधी से भी ज्यादा जनसंख्या ग्रामीण अंचलों में रहती हैं जिसकी रोजी-रोटी तथा जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि का कार्य है इसीलिए शायद भारत देश को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। देश का विकास तथा खुशहाली का मार्ग ग्रामों से होकर गुजरता है। यदि भारत को खुशहाल बनाना है तो गाँव को विकसित करना होगा और गाँव तभी विकसित हो सकता है जब कृषि के विकास पर अत्यधिक बल दिया जायेगा। सामाजिक विकास में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका काफी अहम मानी गई है। परन्तु सूचनाओं का आदान-प्रदान सम्प्रेषण स्थापना तथा विविध युक्तियों में सूचना तकनीकी के अनुप्रयोग से विकास के सूत्रों की तलाश करना तब तक सम्भव नहीं, जब तक हम नवीनता को प्रोत्साहित नहीं कर लेते नवीनता को प्रोत्साहन एवं कृषि के आधुनिकीकरण से लेकर फसल सुरक्षा, कृषि विपणन और जागरूकता के प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित कृषि एवं कृषकों की तमाम समस्याओं के समाधान हेतु सूचना तकनीकी प्रभावी साबित हो सकती है।

**कृषि विकास** - किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण योगदान होती है यदि इसे आर्थिक सिस्टम की रीढ़ की हड्डी कहा जाये, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तविक रूप से कृषि क्षेत्र खाद्यान्न और कच्ची सामग्री तो उपलब्ध कराती ही है साथ ही यह आबादी के एक बड़े हिस्से को राजगार के अवसर भी प्रदान करती है। भारत में हमारी कार्यशील आबादी की प्रमुख व्यवसाय कृषि है। 125 करोड़ से अधिक आबादी वाले विशाल देश में अधिकांश कृषक आज भी परम्परागत खेती कर रहे हैं। खेती ही नहीं अधिकतर कृषक वर्तमान दौर में पशुपालन और कृषि से सम्बन्धित अन्य बहुत से व्यवसाय परम्परागत तरीके से ही किये जा रहे हैं।

आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं कृषि नवीन उपकरणों की उपलब्धता के बावजूद विशेषतौर पर तंग-हाल छोटे एवं मध्यम किसान उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वे घाटे की कृषि व्यवसाय करते हुये ऐसे दुष्चक्र में फसे हुये हैं कि नवीन ज्ञान और कौशल से वंचित रह जाते हैं। खेती तथा कृषि से जुड़े हुये अन्य व्यवसायों को समेकित रूप से अत्यधिक लाभकारी बनाने हेतु कौशल विकास पर सरकार संजीदा है। जरूरत इस बात ही है कि सरकारी योजनाओं तथा उनके लाभों की उन्हें सही और समय पर जानकारी उपलब्ध करायी जाये। कृषि उत्पादन में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करने के लिए उत्तम बीज की उपलब्धता, मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उर्वरकों से जुड़ी सरकारी नीतियाँ, विपणन, बीमा, लैंड लीजिंग और पूर्वोत्तर भारत पर अत्यधिक फोकस, विविध मर्दों में कृषकों एवं ग्रामीण लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी बी टी) जैसे कार्यक्रमों के तहत कृषकों को लाभ पहुंचाने की पहल की गई है। हमारे देश में कृषि विकास को बढ़ाने और किसान की आय को वर्ष 2022 तक डबल करने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं और नीतियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सरकारों द्वारा निरन्तर जारी इन प्रयास के सकारात्मक परिणाम अब कुछ देखने को मिल रहे हैं। इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान सरकारों द्वारा पिछले कुछ वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र को निरन्तर प्राथमिकता दी गई है। इस क्रम में सरकार द्वारा न सिर्फ कृषि विकास पर आधारित नवीन योजनाओं तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया है बल्कि इस हेतु पर्याप्त धनराशि भी उपलब्ध करायी गयी है।

**सारणी- 1 : क्षेत्रवार गत पाँच वर्षों के बजटीय आयोजन**

\* प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, अमरपाटन, सतना (म.प्र.) भारत  
\*\* शोधार्थी (वाणिज्य) अवधेष प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

क्षेत्र	बजटीय आयोजन (करोड़ रु में)		वृद्धि प्रतिशत में
	2009- 2014	2014- 2019	
फसल बीमा	6,182	33162	436
कृषि यांत्रिकरण	254	2408	846
माइक्रो इरिगेशन	3193	12711	298
कृषि विस्तार उपमिशन	3163	4046	28
सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट	162	1573	871
कृषि विपणन	2666	6150	131
वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास	189	1322	700
कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं विस्तार	12225	13746	12
नीली क्रान्ति	1772	2913	64

**कृषि एवं सूचना तकनीकी** – भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य घटक कृषि मानी जाती है। भारत देश की लगभग 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि रूपी रोजगार में सम्मिलित है। देश में बढ़ते सूचना तकनीकी के उपयोगिता को कृषि से जोड़ना एक अतिमहत्वपूर्ण कार्य है। इसी क्रम में वर्तमान में केन्द्र सरकार की डिजिटल इण्डिया तथा ई-क्रान्ति जैसी योजनाएं सूचना प्रौद्योगिकी ग्रामीण अंचलों में विकास को सुनिश्चित कर रही हैं। डिजिटल मिडिया का कृषि विभाग द्वारा विस्तृत रूप से प्रयोग किया जा रहा है। विभाग द्वारा विभिन्न कृषि विकास सम्बन्धी ऑनलाइन पोर्टल संचालित किये जा रहे हैं। जिसके माध्यम से कृषि से जुड़ी विभिन्न जानकारी किसानों को मुहैया कराई जा रही है। देश की विविध कृषि पुनर्वास कार्यक्रमों का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। साथ ही साथ नवीन योजनाओं को तकनीकी से जोड़कर लागू किया जा रहा है। आज इंटरनेट रोटी, कपड़ा और मकान के जैसे दैनिक जीवन की प्रमुख जरूरत बन चुकी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुये ग्रामीण अंचलों को तीव्र गति से इंटरनेट से कनेक्ट किया जा रहा है। 'एम-किसान संदेश सेवा' हो या 'किसान कॉल सेंटर' सभी डिजिटल मिडिया की देन हैं। सूचना-संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि के समग्र विकास को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के जरिए विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों को जोड़ा गया है। कृषि को तकनीकी से जोड़कर उन्नत फसल की पैदावार हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने इससे सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया है सरकार ने ई-गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर सम्पूर्ण देश में लागू कर रही है। इस योजना का उद्देश्य सम्पूर्ण भारत में सूचना तकनीकी के माध्यम से कृषि विकास को गति प्रदान करना है।

**कृषि विकास में ई-तकनीकी की बढ़ती उपयोगिता** – कृषि सम्बन्धित पोर्टल अथवा वेबसाइट टेलीविजन, स्मार्टफोन, एप्लीकेशन इत्यादि की डिजिटल तकनीकी का कृषि में उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। कृषि विकास, बागवानी, पशुपालन, कृषि शिक्षा, भूमि रिकार्ड जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ई-तकनीकी का प्रयोग करके कृषि विकास को नवीनतम आयाम प्रदान किया जा रहा है। तकनीकी के बढ़ते निरंतर प्रचलन से देश के कृषि क्षेत्र में तीव्र गति से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कृषि को ई-तकनीकी से जोड़कर अच्छी फसल की पैदावार हेतु सरकार ने इससे सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी इसी क्रम में प्रारम्भ किया है। यही नहीं, भारत सरकार द्वारा 'नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर' को

राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य सम्पूर्ण देश में सूचना संचार तकनीकी के द्वारा कृषि विकास को तीव्र गति प्रदान करना है। इसके माध्यम से कई कृषि योजनाओं का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। कृषि से जुड़े समस्त शोध कार्यों को अग्रसर करने हेतु सभी कृषि अनुसंधान संस्थानों को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से कनेक्ट किया जा रहा है।

**पूसा कृषि मोबाईल ऐप** – केन्द्र सरकार के प्रयोगशाला से खेत (लैंड टू लैंड) तक के सपने को हकीकत करने हेतु पूसा कृषि मोबाईल ऐप कृषकों की सहायता के लिए प्रारम्भ किया गया। इससे भारती कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित तकनीकी के बारे में किसान जानकारी प्राप्त कर सकती है इसके अंतर्गत विकसित एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी को कृषकों तक पहुंचाने के लिए जोर देने की आवश्यकता है जिससे किसान नवीन तकनीकी को अपना कर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें तथा अपना जीवन निर्वाह खुशहाल पूर्वक कर सकें।

**एम किसान पोर्टल** – एम किसान पोर्टल कृषि विज्ञान संस्थानों द्वारा लाखों किसानों को परामर्श प्रदान किया जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 100 कृषि विज्ञान केन्द्रों पर स्वचालित मौसम केन्द्र जोड़े गये हैं।

**किसान कॉल सेंटर** – सहकारिता तथा कृषि विभाग द्वारा सम्पूर्ण देश में किसानों की कृषि सम्बन्धित समस्याओं, जिज्ञासाओं के समाधान हेतु किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई। प्रत्येक दिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक एक टोल फ्री नं० 1800-180-1551 पर स्थानीय भाषा में किसानों की जिज्ञासा एवं समस्या का समाधान करने के लिए टेली एडवाइजर उपलब्ध रहते हैं। ये टेली एडवाइजर कृषि सम्बन्धित विषयों जैसे- कृषि इंजीनियरिंग, कृषि मार्केटिंग, जैव-प्रौद्योगिकी, बागवानी, पशुपालन इत्यादि में दक्ष होते हैं।

**इपको लाइव पोर्टल** – कृषि से जुड़ी देश-विदेश की महत्वपूर्ण जानकारीयों इस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। यह पोर्टल यही तक सीमित नहीं है बल्कि यह कृषि से सम्बन्धित तस्वीरों, वीडियो और सफलता की कहानियों के द्वारा भी नई-नई तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाता है।

**फार्मर पोर्टल** – इस पोर्टल के माध्यम से किसानों को स्मार्ट फोन पर संदेश द्वारा कृषि विषयों से जुड़ी समस्याओं का समाधान या उन्नत कृषि सुझाव तथा सूचनाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। पोर्टल से केन्द्र सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, मौसम विभाग आदि के अधिकारियों तथा वैज्ञानिकों को जोड़ा गया है।

**ई-नाम योजना की स्थापना** – इलेक्ट्रॉनिक – राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना का प्रारम्भ वर्ष 2016 में की गई जिसमें 585 मण्डियों को वर्ष 2018 तक इस योजना में जोड़ा जा चुका है। इनमें से कुछ मंडियों में ऑनलाइन कृषि बाजार व्यापार का भी कार्य संचालित हो रहा है। इसी तरह वर्ष 2018 के बजट में नवीन बाजार संरचना के विषय में विभिन्न ऐसे तथ्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है और धनराशि भी उपलब्ध करावाई गई है। जिनकी काफी समय से मांग हो रही थी। विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों द्वारा उपज विक्रय की व्यवस्था नजदीकी मंडी में कर पाने हेतु रियायतों एवं सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विभिन्न तरह के पहल की गई हैं।

**फसल बीमा पोर्टल** – यह पोर्टल फसल बीमा से सम्बन्धित समस्त जानकारीयों को कृषकों तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है। इससे सम्बन्धित फसल बीमा स्मार्ट फोन ऐप को भी प्रारम्भ किया गया है। जो बीमा सम्बन्धित समस्त सूचना जैसे- प्रीमियम कैलकुलेटर, बीमित राशि



आदि का विवरण प्रदान करने में सक्षम है इतना ही नहीं नष्ट हुई फसलों की फोटो भेजकर दावा भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

**निष्कर्ष**—वास्तविक रूप से यदि कृषि विकास की उपलब्धियों पर नजर डाला जाये तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस क्षेत्र में कई नये-नये कीर्तिमान स्थापित किये गये हैं। ऐसे में कृषि सम्बन्धित योजनाओं का डिजिटलाइजेशन एक महत्वपूर्ण कदम प्रतीत होता है। कृषि विकास के समावेशी रथ को गति देने हेतु भारत सरकार जहां एक तरफ इंटरनेट की पहुंच को ग्रामीण अंचलों के दूर-दूर क्षेत्रों तक सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वहीं दूसरी तरफ कृषि कार्य में इसके इस्तेमाल करने को सुनिश्चित किये जा रहे हैं। हाल ही में स्वीकार की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या कृषि विभाग द्वारा चलाये जा रहे किसान कॉल सेंटर, सभी डिजिटल तकनीकी कृषि में अपनी योगदान को प्रदर्शित करते हैं। इसी क्रम में कृषि उत्पादों के बाजार भाव की सूचना देने के लिए बनाया गया मोबाईल ऐप या बीमा योजना से सम्बन्धित मोबाइल ऐप सभी कृषि से जुड़ी सूचना आवश्यकताओं को

पूरा करने के लिए तत्पर है। वास्तविकता तो यह कि देश में कृषि विकास की कुंजी अब ई- तकनीकी बन रही है। विभिन्न योजनाओं तथा उदाहरणों से यह तो स्पष्ट है कि डिजिटलीकरण भविष्य में कृषि विकास की राह को और अधिक सुलभ बना देगी।

#### संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. कुरुक्षेत्र, सूचना और प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली।
2. योजना, सूचना और प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली।
3. ओझा एस.के.(2018), कृषि एवं प्रौद्योगिकी, बौद्धिक प्रकाशन, इलाहाबाद उत्तर-प्रदेश।
4. अग्रवाल पी.के. (2003), भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, जर्नल ऑफ प्लॉट बायोलॉजी।
5. भटनागर एस.एण्ड श्वेयर आर.(2000), 'सूचना और ग्रामीण विकास में संचार प्रौद्योगिकी, केस स्टडीज भारत से', ऋषि प्रकाशन, नई दिल्ली ।

\*\*\*\*\*

## नवीन कर प्रणाली जी.एस.टी. के स्वरूप का भारत के परिपेक्ष में अध्ययन

**डॉ. देवेन्द्र प्रसाद पाण्डेय\* आशीष सिंह\*\***

**प्रस्तावना** – वस्तु एवं सेवाकर (GST) यह एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य करों को मिलाकर एक कर बनाया गया है। जी.एस.टी. कर के कास्केडिंग प्रभाव को हटायेगा जैसे 'करों पर कर' और राष्ट्रीय बाजार में सामान्य तौर पर चुकाया जायेगा।

जी.एस.टी. भारत में अप्रत्यक्ष कर के लिए बड़ा परिवर्तन है और एक राष्ट्र एक कर जी.एस.टी. के लिए सही युक्ति है। भारत में वर्तमान अप्रत्यक्ष कर संरचना केन्द्रीय करों एवं राज्य करों का कठिन मिश्रण है। वर्तमान प्रणाली के अनुसार निर्माताओं पर उत्पादन कर, केन्द्रीय बिक्री कर लगाया जाता है जो माल की बिक्री एक राज्य से दूसरे राज्य में करते हैं। प्रवेश शुल्क राज्य द्वारा राज्य में माल के प्रवेश के समय पर लगाया जाता है। राज्य मूल्यवर्धित कर राज्य में बेचे जाने वाले माल पर लगाया जाता है तथा सेवा कर सेवाओं पर लगाया जाता है। यहाँ पर अलग-अलग चरणों पर अलग-अलग प्रकार के कर लगाये जाते हैं जिससे कि कर संरचना कठिन हो जाती है तथा अधिकांश करों का समायोजन नहीं होता है। इसका अर्थ है जैसे कि एक कर को दूसरे कर से समायोजित नहीं कर सकते हैं, जैसे – उत्पादन कर को केन्द्रीय बिक्री कर से समायोजित नहीं किया जा सकता है तथा इसे राज्य के मूल्यवर्धित कर से भी समायोजित नहीं किया जा सकता है। यह प्रणाली कर में कास्केडिंग प्रभाव को बढ़ाती है जैसे – करों पर कर जो उत्पाद तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि करता है।

जी.एस.टी. के अंतर्गत अधिकांश कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर, जैसे – उत्पादन कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर, सेवा कर तथा विभिन्न प्रकार के राज्य के कर, जैसे – प्रवेश शुल्क, राज्य मूल्यवर्धित कर, लगजरी कर आदि सभी को मिलाकर एक कर बना दिया गया है जो कि जी.एस.टी. है। जी.एस.टी. की विशेषता है कि व्यवसाय चक्र में एक चरण पर भुगतान करने पर इस कर को अगले चरण पर समायोजित किया जायेगा जिससे कि कर केवल मूल्य वृद्धि पर लगाया जायेगा जिससे करों का गुणन नहीं होगा।

**जी.एस.टी. का इतिहास और इसकी अभी तक की यात्रा या स्थिति** – राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का प्रस्ताव 1 अप्रैल 2010 को रखा गया, वित्तीय वर्ष 2006-07 में पहली बार बजट भाषण में इस पर विचार किया गया था। प्रस्ताव में यह भी शामिल था कि अप्रत्यक्ष कर केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा ही नहीं लगाया जायेगा बल्कि राज्य सरकार द्वारा भी लगाया जायेगा। जी.एस.टी. लागू करने के लिए इसके डिजाइन तथा रोडमैप की तैयारी का उत्तरदायित्व एम्पावरड/अधिकृत कमेटी के राज्य वित्त

मंत्री का था। एम्पावरड कमेटी ने भारत में वस्तु एवं सेवा कर के लिए मॉडल एवं रोडमैप की रिपोर्ट पेश की। जी.एस.टी. के डिजाइन तथा संरचना के बारे में कोन्टेनिंग बोर्ड ने अपनी अनुमति दी। रिपोर्ट के संदर्भ में आगम विभाग ने प्रस्तावित जी.एस.टी. के डिजाइन एवं संरचना के संबंध में कुछ सुझाव दिए।

देश के लिए जी.एस.टी. मॉडल एम्पावरड कमेटी द्वारा प्रस्तावित किया गया जिसे केन्द्र ने स्वीकार कर लिया। जी.एस.टी. मॉडल के अंतर्गत दो तत्व हैं – प्रथम, केन्द्रीय जी.एस.टी. केन्द्र द्वारा लगाया एवं संग्रहित किया जायेगा तथा दूसरा, राज्य जी.एस.टी., राज्य द्वारा लगाया एवं संग्रहित किया जायेगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क (उत्पादन के समकक्ष), राज्य मूल्यवर्धित कर, मनोरंजन कर, लॉटरी पर कर, जुआ और सट्टा कर एवं प्रवेश कर (स्थानीय निकाय द्वारा नहीं लगाए जायेंगे) ये सभी जी.एस.टी. में समाहित हो जायेंगे।

**जी.एस.टी. की विशेषताएं :**

1. माल के निर्माता पर कर की वर्तमान अवधारणा के विरुद्ध सेवाओं या माल की आपूर्ति पर जी.एस.टी. लागू होता है। माल के विक्रय के लिए उत्पादन कर, केन्द्रीय बिक्री कर/वैट या सेवाओं के प्रावधान पर सेवा कर।
2. कराधान के वर्तमान सिद्धान्त के प्रारंभ में आधार के विरुद्ध उपभोग कराधान आधार, विक्रय के अंतिम बिन्दु के सिद्धान्त पर जी.एस.टी. आधारित है। इसका अर्थ है कि कर वसूल करके कर को राज्य द्वारा वापस किया जहां पर माल या सेवा का अंतिम उपभोग हुआ है।
3. यह दोहरा जी.एस.टी. केन्द्र और राज्य द्वारा साथ-साथ सामान्य आधार पर लगाया जाता है। केन्द्र द्वारा लगाया जाने वाला जी.एस.टी. केन्द्रीय जी.एस.टी. कहलाता है और राज्य (विधान के साथ संघ अधिकार क्षेत्र सहित) द्वारा लगाया जाने वाला जी.एस.टी. राज्य जी.एस.टी. कहलाता है। संघ अधिकार क्षेत्र द्वारा लगाया जाने वाला जी.एस.टी. संघ अधिकार क्षेत्र जी.एस.टी. (UTGST) कहलाता है।
4. एकीकृत जी.एस.टी. (IGST) राज्य के बाहर दी गई सेवाओं या अन्तर्राज्यीय माल की आपूर्ति (स्टॉक हस्तान्तरण सहित) पर लगाया जाता है। यह केन्द्र द्वारा वसूला जाता है जिससे कि क्रेडिट श्रृंखला नहीं टूटती है।
5. माल के आयात को अन्तर्राज्यीय आपूर्ति की तरह माना जाता है और यह सीमा शुल्क लागू होने के कारण आई.जी.एस.टी. (IGST) के अंतर्गत आता है।

6. आयात की गई सेवाएं भी अन्तर्राज्यीय सेवाओं की तरह ही मानी जाती हैं। यह भी आई.जी.एस.टी. (CGST) के अंतर्गत आती हैं।
7. जी.एस.टी. परिषद् द्वारा निर्धारित की गई दरों के अनुसार केन्द्र और राज्य सी.जी.एस.टी. (CGST) /यू.टी.एस.टी. (UTST) और आई.जी.एस.टी. (IGST) के रूप में लगाते हैं।
8. जी.एस.टी. में निम्नलिखित करों का समावेश किया गया है और यह केन्द्र द्वारा लगाया एवं वसूला जाता है :-
  - केन्द्रीय उत्पाद कर
  - केन्द्रीय बिक्री कर
  - उत्पादन कर (मेडिलीनकल और टायलेट तैयारी पर)
  - अतिरिक्त उत्पादन कर
  - अतिरिक्त सीमा शुल्क
  - विशिष्ट अतिरिक्त सीमा शुल्क
  - सेवा कर
9. राज्य कर जिन्हें जी.एस.टी. में समाहित किया गया है -
  - राज्य मूल्यवर्धित कर
  - क्रय कर
  - लगजरी कर
  - प्रवेश कर (सभी रूपों में)
  - मनोरंजन कर (स्थानीय निकाय द्वारा लगाए जाने वाले कर को छोड़कर)
  - विज्ञापन पर कर
  - लॉटरी, जुआ और सट्टे पर कर
10. मनुष्यों द्वारा उपभोग की जाने वाली एल्कोहल को छोड़कर सभी मालों तथा सेवाओं पर जी.एस.टी. लागू होगा।
11. जी.एस.टी. द्वारा स्वीकृत तिथि से जी.एस.टी. पांच विशिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों (फ्रूड, पेट्रोल, डीजल, ए.टी.एफ. और प्राकृतिक गैस) पर भी लागू होगा।
12. केन्द्रीय जी.एस.टी. और राज्य जी.एस.टी. पर सामान्य आरंभिक कर मुक्ति लागू होगी। करदाता जिनका वार्षिक एकीकृत आवर्त रु. 20 लाख (रु. 10 लाख विशेष श्रेणी राज्य, उत्तर-पश्चिम राज्य, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि के लिए) जी.एस.टी. से करमुक्त होंगे। ऐसे करदाता जिनका वार्षिक आवर्त रु. 50 लाख तक है, उन्हें एक संयुक्त विकल्प (इनपुट कर क्रेडिट को छोड़कर एक फ्लैट रेट से कर चुकाने) का छोटे करदाताओं के लिए उपलब्ध होगा। आरंभिक कर मुक्ति और संयुक्त योजना वैकल्पिक होगी।
13. निर्यात पर 0% अर्थात् कोई जी.एस.टी. नहीं लगाया जायेगा यदि माल का निर्यात या सेवाओं का निर्यात किया जाता है।
14. इनपुट पर जी.एस.टी. (केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर) के भुगतान के क्रेडिट का प्रयोग केवल आउटपुट पर भुगतान सी.जी.एस.टी. से किया जा सकता है और इनपुट पर एस. जी.एस.टी. /यू.टी.जी.एस.टी. (राज्य वस्तु एवं सेवा कर/संघ अधिकार क्षेत्र) भुगतान के क्रेडिट का प्रयोग केवल आउटपुट पर भुगतान एस.जी.एस.टी. /यू.टी.जी.एस.टी. के लिए किया जा सकता है। अन्य शब्दों में इनपुट क्रेडिट का उपयोग एक दूसरे के लिए (क्रास) नहीं किया जा सकता है (अन्तर्राज्यीय आपूर्ति भुगतान की दशा को छोड़कर) क्रेडिट को निम्न के लिए उपयोग करने की अनुमति है -
  - सी.जी.एस.टी. एवं आई.जी.एस.टी. के भुगतान के लिए सी.जी.एस.टी. का इनपुट टैक्स क्रेडिट स्वीकृत है।
  - एस.जी.एस.टी. एवं आई.जी.एस.टी. को भुगतान के लिए एस.जी.एस.टी. का इनपुट टैक्स क्रेडिट स्वीकृत है।
  - यू.टी.जी.एस.टी. एवं आई.जी.एस.टी. को भुगतान के लिए यू.टी.जी.एस.टी. का इनपुट टैक्स क्रेडिट स्वीकृत है।
  - आई.जी.एस.टी., सी.जी.एस.टी. एवं एस.जी.एस.टी. /यू.टी.जी.एस.टी. को भुगतान के लिए आई.जी.एस.टी. के इनपुट टैक्स क्रेडिट स्वीकृत हैं।
15. इनपुट टैक्स क्रेडिट बोर्ड के आधार पर बनाया जायेगा। यह कर भुगतान के संबंध में माल की आपूर्ति या सेवाओं पर उपलब्ध हैं और दोनों का उपयोग व्यवसाय के उद्देश्य के लिए योजना बनाकर किया जायेगा।
16. जी.एस.टी. में इलेक्ट्रॉनिक आय विवरणी दाखिल करने की उपलब्धता है, यहां पर कोई मैनुअल फाइलिंग नहीं होगी।
17. निश्चित व्यक्तियों, सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरण और सरकारी एजेंसियों सहित, जो कि आपूर्ति के प्राप्तकर्ता हैं, उन्हें 1% की दर से कर की कटौती भुगतान करते समय करनी चाहिये। या रु. 2.5 लाख से अधिक होने पर यदि आपूर्ति का कुल मूल्य अनुबंध के अंतर्गत है, तब आपूर्तिकर्ता के खाते में क्रेडिट की जायेगी।
18. इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संचालक (पिलक कार्ट, अमेजन, स्नैपडील आदि) पर कानूनी बाध्यता है कि उन्हें आपूर्ति के शुद्ध कर योग्य मूल्य पर 1% स्रोत पर कर की वसूली अपनी वेबसाइट के द्वारा करनी चाहिये।
19. पंजीकृत व्यक्ति स्वयं कर निर्धारण प्रणाली के द्वारा कर चुका सकेंगे।
20. रजिस्टर्ड व्यक्तियों को चार्टर्ड एकाउण्टेंट या लागत एकाउण्टेंट से अंकेक्षण करना होगा यदि उनका आवर्त रु. 1 करोड़ से अधिक हो तब अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अंकेक्षण कराना होगा।
21. एक गैर लाभ विशिष्ट वाक्य है जो यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता को सेवाओं और माल या दोनों का लेन-देन पर कर कम करके लाभ को व्यवसाय के लिए प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक चरण के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता होने पर जी.एस.टी. प्रणाली के अंतर्गत सेवाओं या उत्पादों की सम्पूर्ण कीमत में की जायेगी और करों के कास्केडिंग प्रभाव को हटाया जाता है। इस प्रकार, लाभ उपभोक्ता को दिया जा सकेगा और इसे बिजनेसमैन द्वारा अपने लिए नहीं रखा जा सकेगा।
22. हल्के परिवर्तन के लिए उपलब्धता की परिवर्तनों के प्रावधान की विस्तार से व्याख्या हुई है। यहां एक नया कानून है जो परिवर्तन के प्रावधानों की उपलब्धता वर्तमान कानून को नए कानून में परिवर्तन नहीं कर सकता और यही उपलब्धता जी.एस.टी. कानून में है जैसे वेट से मुक्ति, जी.एस.टी. से सेवा कर की उपलब्धता, वर्तमान वेट में स्टाक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को जी.एस.टी. कानून में उपलब्ध किया जा सकता है।

#### जी.एस.टी. के लाभ :-

#### उद्योग एवं व्यवसाय के लिए

1. सरल अनुपालन - भारत में जी.एस.टी. की बुनियाद की व्यवस्था या शासन प्रणाली के लिए आई.टी. प्रणाली का व्यापक एवं स्वस्थ (तगड़ा) होना आवश्यक है। इसलिए करदाताओं को उनकी सेवाओं के लिए पंजीयन,

विवरणी, भुगतान आदि की ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध होगी जो कि आसान अनुपालन एवं पारदर्शी बनाई जायेगी।

**2. कर की दरों एवं संरचना में एकरूपता** - जी.एस.टी. से यह सुनिश्चित होगा कि पूरे देश में अप्रत्यक्ष कर की दरें एक समान होंगी जिससे कि व्यवसाय करना आसान तथा निश्चिततापूर्ण होगा। अन्य शब्दों में जी.एस.टी. देश में व्यवसाय के लिए सामान्य कर बनायेगा जिससे कि व्यवसाय को करने के स्थान का चयन करना भी आसान होगा।

**3. कास्केडिंग प्रभाव का निराकरण/हटाना** - राज्य की चारदीवारी के अंतर्गत और मूल्य शृंखला के द्वारा सीमलैस टैक्स क्रेडिट प्रणाली जो कर की कास्केडिंग को न्यूनतम करना सुनिश्चित करता है। यह व्यवसाय करने की छुपी हुई लागत को कम करेगा।

**4. प्रतियोगिता को प्रोत्साहन** - व्यवसाय के लेन-देन लागत को कम करके उद्योग एवं व्यापार के लिए प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करेगा।

**5. निर्माताओं एवं निर्यातकों को लाभ** - जी.एस.टी. में केन्द्र और राज्य का मुख्य भाग होने से माल और सेवाओं के इनपुट का सम्पूर्ण एवं व्यापक समायोजन, केन्द्रीय बिक्री कर को बंद करना, स्थानीय माल और सेवाओं के निर्माताओं की लागत को कम करेगा। यह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के माल और सेवाओं की प्रतियोगिता को बढ़ायेगा और भारतीय निर्यातकों को प्रोत्साहन देगा। देश में कर की दरों की एकरूपता और प्रक्रिया लागत को कम करने का अनुपालन करेगा।

#### केन्द्र और राज्य सरकार के लिए

**1. प्रशासन के लिए सरल एवं आसान** - विभिन्न केन्द्र और राज्य के अप्रत्यक्ष करों को हटाकर जी.एस.टी. द्वारा एक सुदृढ़ आय कर प्रणाली दी जायेगी। केन्द्र और राज्य द्वारा लगाए जाने वाले अन्य अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर जी.एस.टी. को सरल एवं आसानी से प्रशासित किया जायेगा।

**2. लीकेज पर उत्तम नियंत्रण** - जी.एस.टी. ने उत्तम कर अनुपालन तथा आय कर इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने का परिणाम दिया। मूल्य वृद्धि की शृंखला में इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक चरण से अन्य को हस्तान्तरण देय होगा। डीलर द्वारा कर अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए जी.एस.टी. को अच्छी प्रणाली के लिए डिजाइन किया गया है।

**3. उच्च आगम कार्य क्षमता** - जी.एस.टी. से अपेक्षा है कि वह सरकार के कर आगम के संग्रह की लागत को घटा देगा इसलिए उच्चतम आगम कार्यक्षमता को बढ़ायेगा।

#### उपभोक्ताओं के लिए

**1. माल और सेवाओं के मूल्य का अनुपातिक एकल एवं पारदर्शी कर** - केन्द्र और राज्य द्वारा विभिन्न अप्रत्यक्ष करों के लगाए जाने के कारण आज देश में माल और सेवाओं की अधिकतम लागत, मूल्य वृद्धि के प्रत्येक चरण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अपूर्ण या उपलब्ध नहीं है। जी.एस.टी. के अंतर्गत उपभोक्ताओं को निर्माताओं को केवल एक कर देना होगा। इससे अंतिम उपभोक्ता द्वारा कर चुकाने की पारदर्शिता बढ़ेगी।

**2. सम्पूर्ण कर में राहत** - कार्यक्षमता लाभ के कारण तथा लीकेज को रोकने के लिए सभी वस्तुओं पर एक कर लगाया जायेगा जिससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

**शोध प्रविधि** - यह शोध पत्र 'नवीन कर प्रणाली जी.एस.टी. के स्वरूप का भारत के परिपेक्ष में अध्ययन', एक प्रकार का द्वितीयक सामग्री का प्रयोग किया गया है। उपलब्ध स्रोतों को संकलित एवं अध्ययन करके उनका विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। अध्ययन के लिए शोध-जर्नल,

पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, इंटरनेट से प्राप्त जानकारियों एवं विद्वानों का मार्गदर्शन लेते हुए, एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया गया है।

#### शोध -पत्र का उद्देश्य :

1. नवीन कर प्रणाली जी.एस.टी. के प्रति व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति न रहे।
2. जी.एस.टी. के स्वरूप को सरल एवं सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।
3. व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं द्वारा इस नवीन कर प्रणाली के सकारात्मक सोच के साथ अपनाया जाये, ऐसा प्रयास प्रस्तुत शोध में किया गया है।
4. जी.एस.टी. संबंधी विसंगतियों की ओर सरकार का ध्यानाकर्षित करने का प्रयास किया गया है।
5. विभिन्न विद्वानों एवं संस्थाओं का जी.एस.टी. के संबंध में क्या विचार है? उनके विचारों को प्रस्तुत शोध में प्रकट करने का प्रयास किया गया है।
6. जी.एस.टी. के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को प्रस्तुत शोध में प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है।

**जी.एस.टी. का स्वरूप** - 1 जुलाई 2017 से लागू इस कर प्रणाली के स्वरूप को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है :-

1. **सी.जी.एस.टी.** - सी.जी.एस.टी. के अंतर्गत राजस्व की वसूली केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।
2. **एस.जी.एस.टी.** - राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता है।
3. **आई.जी.एस.टी.** - अन्तर्राष्ट्रीय बिक्री के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता है।

उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश का कोई व्यापारी मध्य प्रदेश की सीमाओं के अंदर ही माल की बिक्री करता है तो ऐसी स्थिति में चूंकि माल राज्य की सीमाओं के अंदर विक्रय हुआ, इसलिए ऐसी स्थिति में माल के विक्रय पर सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. दोनों चार्ज किया जायेगा। यदि जी.एस.टी. की दर 12% है तो 6% CGST + 6% SGST लगाया जायेगा। यदि माल की बिक्री राज्य की सीमाओं के बाहर (अन्तर्राष्ट्रीय बिक्री) की जाती है तो ऐसी स्थिति में आई.जी.एस.टी. लगाया जायेगा। यदि GST की दर 12% हो तो 12% IGST लगाया जायेगा।

#### सम्बन्धित चार्ट क्रमांक -01 (देखें अंतिम पृष्ठ पर)

**GST की दरें** - पूरे विश्व के अधिकांश देशों में जहां भी GST लागू है, ज्यादातर देशों में GST की केवल एक दर निर्धारित है। भारत एक विशाल एवं विविधताओं वाला देश है। यहां 28 राज्य और 8 केन्द्रशासित प्रदेश हैं। करों के स्वरूप में परिवर्तन करने के लिए इन राज्यों से सहमति एवं सुझाव की आवश्यकता होती है। GST की एक दर पर सहमति बनाना कठिन कार्य है क्योंकि राज्यों को प्राप्त होने वाली करों की राशि का प्रभाव इन दरों पर निर्भर करता है, यही कारण है कि भारत में GST की दरों को 5 भागों में बांटा गया है। 0%, 5%, 12%, 18% एवं 28%

#### कुछ महत्वपूर्ण उत्पादों पर जी.एस.टी. की दरें

**शून्य दर के अंतर्गत माल** - मीट, अण्डा, दूध, फूडग्रेन, मछली, प्राकृतिक शहद, ताजा एवं अप्रक्रियागत सब्जियां, शिक्षण पुस्तकें आदि।



**5% दर के अंतर्गत माल** - एमआरपी रु. 500 से कम के जूते, 1000 से कम के कढ़ाई किये गये वस्त्र, सब्जियों को अच्छी प्रकार से रखने के लिए दूध का व्यवहार आदि।

**12% दर के अंतर्गत माल** - रु. 1000 से अधिक के कढ़ाई किये गये वस्त्र, मोबाइल्स, फ्रूट जूस एवं सब्जियां, मार्बल एवं ग्रेनाइट ब्लाक्स, फाउन्टेन पेन, कलरिंग एवं ड्राइंग बुक्स आदि।

**18% दर के अंतर्गत माल** - कम्प्यूटर्स एवं लैपटॉप, प्रिंटर रु. 500 से अधिक एम.आर.पी. के जूते, कार्बन पेपर, नोट-बुक, शानदार कांच, कार्य अनुबंध सेवा एवं, वाणिज्यिक कोचिंग सेवाएं।

**28% दर के अंतर्गत माल** - च्चीगम एवं बबलगम, चॉकलेट्स, पान मसाला, सोफ्ट ड्रिंक्स, मार्बल एवं ग्रेनाइट के अतिरिक्त ब्लाक्स, पेंड्स एवं वॉर्निश, परफ्यूम्स, लज्जरी कार आदि।

विश्व बैंक ने मार्च 2018 में GST के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की वस्तु एवं सेवाकर (GST) प्रणाली दुनिया की सबसे जटिल कर प्रणालियों में से एक है। इसमें न केवल सबसे उच्च कर दर शामिल है बल्कि इस प्रणाली में सबसे अधिक कर के स्लैब भी हैं। वर्ल्ड बैंक ने आगे कहा कि भारत उच्च मानक GST दर मामले में एशिया में पहले एवं चिली के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा, 'भारतीय जी.एस.टी. प्रणाली में कर की दर दुनिया में सबसे अधिक है, भारत में उच्चतम जी.एस.टी. दर 28% है। जो विश्व के 115 देशों में दूसरी सबसे ऊँची दर है।'

#### सम्बन्धित चार्ट क्रमांक -02(देखें अंतिम पृष्ठ पर)

**विश्व के अन्य देशों में टैक्स की दरें** - जुलाई 2017 से लागू होने के बाद भारत उन चुनिन्दा देशों में शामिल हो गया है जहां टैक्स का रेट उच्चतम स्तर पर है। कनाडा में लागू जी.एस.टी. को अपना रोल मॉडल मानते हुए भारत ने देश में इसे लागू किया। जहां कनाडा में टैक्स रेट बहुत कम है वहीं भारत में दर बहुत अधिक है। विश्व के कई देश जैसे आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, कनाडा, जार्डन, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर आदि देशों में जी.एस.टी. की दर भारत के मुकाबले काफी कम है। जहां इन देशों में GST की दर 5% से लेकर 20% के बीच है और केवल एक दर है वहीं भारत में GST के 0-28% तक के स्लैब हैं जो इस प्रणाली को काफी जटिल रूप में प्रस्तुत करते हैं।

#### सम्बन्धित चार्ट क्रमांक -03(देखें अंतिम पृष्ठ पर)

नितिन कुमार (2014) में अपने शोध पत्र "Goods and Service Tax Reforms and Intergovernment in Consideration in India" में GST के बारे में विचार व्यक्त करते हुए कहा, "Goods and Service Tax - A Way forward", अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को GST एक नई दिशा देता है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है यदि इसे सही तरीके से लागू किया जाये। पिकी, सुप्रिया और ऋचा वर्मा ने अपने शोध पत्र में GST पर विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है कि 'वस्तु एवं सेवाकर भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए पैनिया है' (Goods and Service Tax - Panacea for Indirect Tax System)

भारत सरकार का GST के प्रति सकारात्मक रुख है। हमारी अर्थव्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए लाभप्रद है, यदि देश की आई.टी. संरचना को मजबूत कर दिया जाये। जी.एस.टी. के सही क्रियान्वयन के लिए आई.टी. की संरचना का मजबूत होना अति आवश्यक है।

आकांक्षा खुराना एवं आस्था शर्मा (2016) द्वारा प्रस्तुत शोध पत्र "GST A Positive Reform for Indirect Taxation System", में

अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि GST प्रणाली से निर्माता और उपभोक्ता को काफी राहत मिलती है। विभिन्न प्रकार की जटिल कर प्रणालियों से मुक्ति मिलेगी। हितेश के. प्रजापति द्वारा अपने शोध अध्ययन "Challenges and Implementation of GST in India", में GST के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के विषय में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आई.टी. क्षेत्र में प्रगति न होने के कारण GST के क्रियान्वयन में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। GST के क्रियान्वयन को गति नहीं मिल पा रही है।

भारत में जहां आधे से अधिक आबादी गांवों में निवास करती है वहां आई.टी. का स्वरूप काफी कमजोर है। GST के क्रियान्वयन को गति तभी प्राप्त होगी जब हमारा आई.टी. का स्वरूप मजबूत होगा।

**निष्कर्ष एवं सुझाव** - स्वतंत्रता के बाद जी.एस.टी. भारत में एक बड़ी क्रान्ति है, इससे प्रणाली में पारदर्शिता आयेगी, सरल अनुपालन सुनिश्चित होगा, करों की क्रेडिट होगी, इसलिए एक निश्चित स्तर पर लागत को कम करेगा। जी.एस.टी. के लागू होने से व्यवसायियों में अनुशासन आयेगा। यह काले धन के विरुद्ध बहुत बड़ा हथियार है। जी.एस.टी. के लागू होने से भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था विश्व में उच्चतम स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। प्रस्तुत शोध में जी.एस.टी. का अध्ययन करने के पश्चात इसके निष्कर्षों को हम निम्न बिन्दुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे -

1. जी.एस.टी. के बारे में गलत एवं भ्रामक प्रचार-प्रसार होने के कारण व्यापारियों को इसे लागू करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। सरकार द्वारा हर व्यापारी को जी.एस.टी. के संबंध में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये।
2. प्रशिक्षित कर सलाहकारों एवं लेखापालों की कमी जी.एस.टी. के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न कर रही है। वर्तमान समय में अधिकांश विद्वान इस कर प्रणाली की रूपरेखा से अनभिज्ञ हैं। कर प्रणाली के क्रियान्वयन में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है।
3. जी.एस.टी. का पूरा स्वरूप आई.टी. के माध्यम से क्रियान्वित होता है। भारत में आई.टी. का ढांचा शहरीय क्षेत्र में तो कुछ ठीक है किन्तु ग्रामीण क्षेत्र में इसकी स्थिति बहुत दयनीय है। जमीनी स्तर पर आई.टी. के ढांचे को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है तभी हम जी.एस.टी. का सही प्रकार से क्रियान्वयन कर सकेंगे।
4. प्रस्तुत शोध की तालिका क्रमांक - 3 यह प्रदर्शित करती है कि अधिकांश देशों में जी.एस.टी. की एक दर है। जो इसके स्वरूप को सरल बनाती है जबकि भारत में जी.एस.टी. की दर 0%, 5%, 12%, 18%, 28% है, जो इसे लागू करने के उद्देश्य को ही समाप्त कर देती है।
5. सरकार द्वारा इसके प्रावधानों में समय-समय पर परिवर्तन किया जाता रहा है जिससे इसका स्वरूप दिन-प्रतिदिन और भी जटिल होता जा रहा है। एक निश्चित अंतराल में ही इसके नियमों में परिवर्तन किया जाना चाहिये।
6. भारत में जी.एस.टी. की ऊँची दर व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के मन में नकारात्मकता उत्पन्न करती है। सरकार को इसके संबंध में विचार करना चाहिये।

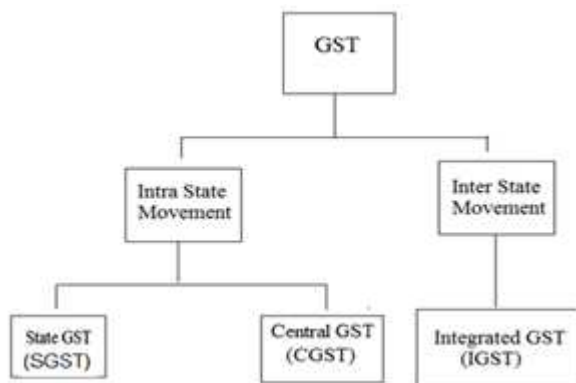
अप्रत्यक्ष करों के मामले में भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया है जो आधुनिक भारत के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। सरकार द्वारा समय-समय पर सकारात्मक कदम उठाये जाते रहे हैं। हमें सरकार की मंशा पर कोई संदेह नहीं है किन्तु उठाये गये कदम पर्याप्त नहीं हैं। सरकार, व्यापारी एवं उपभोक्ता तीनों को सकारात्मक भूमिका के साथ इस नवीन कर प्रणाली

को अपनाना चाहिये तभी राष्ट्र का सही प्रकार से नवनिर्माण कर सकेंगे।  
**उपसंहार –** स्वतंत्रता के बाद जी.एस.टी. भारत में एक बड़ी क्रान्ति है, जिससे प्रणाली में पारदर्शिता आयेगी, सरल अनुपालन सुनिश्चित होगा, करों की क्रेडिट होगी, इसलिए यह निश्चित स्तर पर लगातार को कम करेगा। जी.एस.टी. के लागू होने से व्यवसायियों में अनुशासन आयेगा। यह काले धन के विरुद्ध बहुत बड़ा हथियार है। प्रारंभ में इसके आने से कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान सेवा कर के संबंध में माइग्रेशन, वैट डीलर्स का जी.एस.टी. पोर्टल, एक छोटे व्यवसायी को भी प्रत्येक वर्ष कम से कम 37 विवरणी जमा करनी होगी जो एक व्यवसायी पर अतिरिक्त भार होगा। जी.एस.टी. के लागू होने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व में उच्चतर होगी जहां पहले से ही जी.एस.टी. लागू हो चुका है।

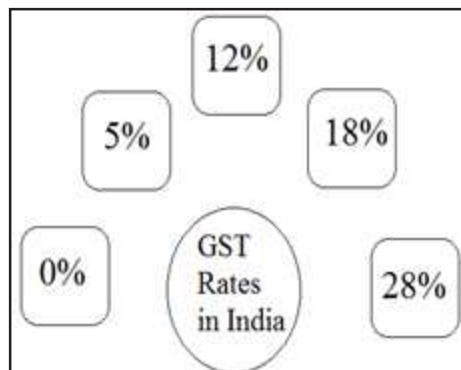
#### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. Hitesh H. Prajapati - Research Paper "Goods and Service Tax Implementation of GST in India". Indian Journal Research 2016
2. C.A. Nikhil Gupta 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) Books, SBPD Publication 2017
3. <https://cleartaxin/s/GST-Law-2008> Service Tax
4. Nitin Kumar - Research Paper "Goods and Service Tax Reform and Inter Government Consideration in India". - Global Journal of Multidisciplinary Studies" Vol-3, Issue 6, May 2014.
5. Pinki, Supriya Kamna, Richa Verma Reserach Paper, "Goods on Service Tax - Panacea for Indirect System in India", "Tactifful Management Reserach Journal", vol - 2, July 2014
6. <https://blog.saginfoth.com/GST-India-VS-foreign-gst>.
7. Monika Sehrawat, Upasana, Danda, Research paper, "GST in India : A Key Tax Reform" International Journal of Researc - Granthaalayah - Vol-3 Dec - 2015
8. Ahansh Khuran, Astha Sharma, Reserach paper, "Goods and Services Tax in India - A positive reform for Indirect Tax System". Externational Journal of Advance Reserach, Vol - 1, 2016
9. Anant paliwal, Article, Amarujala.com, Date-19 Jun 2017

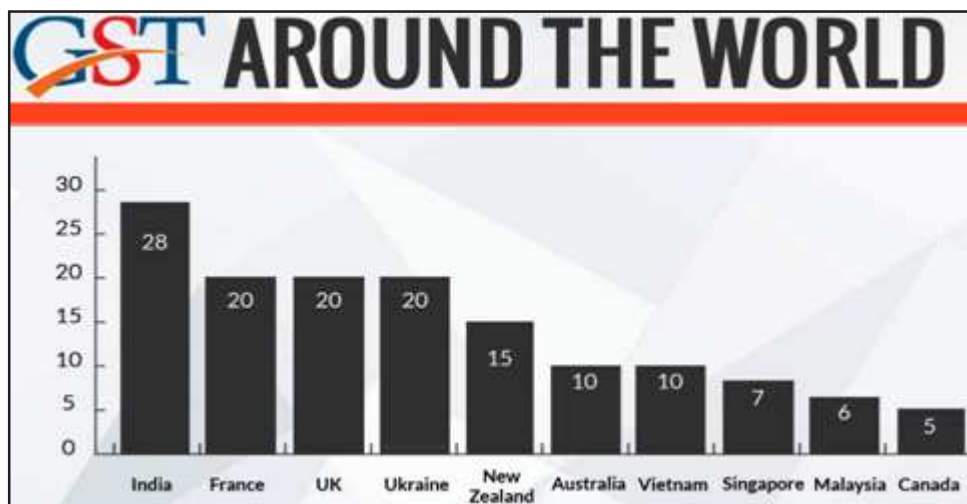
**चार्ट क्रमांक -01 जी.एस.टी. का स्वरूप**



**चार्ट क्रमांक -02 जी.एस.टी. की दरें**



**चार्ट क्रमांक -03 विश्व के अन्य देशों में टैक्स की दरें**



\*\*\*\*\*

## Human Rights And Terrorism

Mohammad Yusuf\* Dr. Shyam Sunder Choudhary\*\*

**Introduction** - The emergency, growth and development of organised 'terrorism – systematic use of terror during the last few decades has completely changed the thrust of the struggle for human rights. Terrorism and human rights cannot co-exist. They are mutually destructive of each other. Where there is terrorism, there can be no human rights. Where there are no human rights, there can be no respect for human dignity, life and democratic values. One must not the growing brutality of power in the form of state terror suppressing all dissent, and individual as well as group terrorism in destroying human values and human rights to a very great extent. The question is whether international terrorism and state terror on one hand and human rights on the other can co-exist in the present system of world order. There is a close link between human rights and terrorism. Terrorism obviously abuses the fundamental rights of its victims, whether it is individual terrorism or state terrorism. The victims of terrorism are arbitrarily deprived of the fundamental human rights of life and liberty. Terrorism, in all its forms is the greatest violator of human rights. It causes unlimited miseries to the hapless innocent and ordinary people in the form of death, injury and agony. It challenges the security of the state, undermines pluralistic civil societies and has adverse consequences on social and economic development of state.

At the same time it is also alleged that the human rights are being violated encounter terrorism operations. It is often alleged that many innocent persons have been killed in fake encounters and their dead bodies have not been returned to their bereaved families. Many innocent people have been kidnapped and abducted in unidentified vehicles by police and not produced before the court. Many people are missing and nobody knows where they are. The law of human rights does not permit the police to kill persons in custody or permit them to abduct or allow them to commit torture as the only method of interrogation.

We are, therefore faced with a delicate question as to what are the responsibilities of governments while responding to terrorist activities within their territories. It is interesting to note that human rights violation works both ways, for as well as against the government. In fact, the problem of accommodating the control of terrorism with

the protection of human right is one of balance. The crucial question is that where car that balances be struck. Having seen the above, dilemma, let us examine the concept of human rights as applicable to armed forces.

**Basic Concept** - The concept of human rights devices from the dignity and worth inherent in the human person, who is the central subject of human rights and fundamental freedom. The evolution and crystallization of the concept has taken a long time. The term "human rights" was introduced in the united states declaration of independence in 1776 and the US Constitution embodied a bill rights. The French revolution gave birth to the declaration of rights of man and citizen in 1789. In 1929, the institution of international law, New York, USA, prepared a Declaration of Human Rights and Duties. In 1945, the inter American conference passed a resolution, seeking the establishment of an international forum for the furtherance of human rights of mankind.

The constitution of India, which came into effect in 1950, incorporated apart on "Fundamental Rights" However, the definition of the term, still eluded all. In India, we did not have any statutory organization dealing directly with human rights till the promulgation of the human rights ordinance 1993. Prior to this the supreme and high courts were tasked to act as watchdogs against human rights violations. In India, the 1993 protection of human rights act defined human rights as "rights relating to liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the Indian constitution as embodied in the fundamental rights and the international covenants". The relevant international covenants are:-

1. The Universal Declaration of Human Rights(1948)
2. The International Covenants on Civil and Political Rights (1966).
3. The International Covenants of Economic, Social and Cultural Rights(1966).
4. The Optional Protocol.

The promulgation of the constitution by the people of India in January 1950 is water shed in the history of development of the concept of human rights in India. The preamble, fundamental rights and the directive principles of state together provided the basic human rights for the people of India. The democratic socialism spelt out in the

\*Research Scholar, BLP Govt PG College, Mhow (M.P.) INDIA

\*\* Deptt. Of Military Science, SKP Govt PG College, Dewas (M.P.) INDIA

preamble and the Directive Principles are meant to provide the context in which fulfilment of fundamental rights has to be achieved. While fundamental rights stress on the existing rights. Directive Principle provide the dynamic movement towards the goals of providing human rights for all.

**International Humanitarian Law** - International Humanitarian law is not applicable outside armed conflicts. In peacetime, terrorist acts must and can generally be dealt with under the domestic laws of status. Only one set of problems must be solved by international law; the problems of international judicial cooperation in dealing with terrorism. One of these problems concerns question of the exemption from the extradition of those claiming a political motivation for their terrorist acts. The exemption from the extradition in favour of political offenders is a traditional principle recognized many municipal legal systems and in extradition treaties. But the concept of 'political crime' is not easy to define. Furthermore, there is no consensus as to what all categories fall under the exemption. However, there should be a broad consensus that perpetrators of terrorist acts should not be allowed to plead that exemption.

**Dilemma** - But the controversial question is how to define the terrorist acts which should not be covered by the exemption. It is precisely in this connection that consideration, by analogy, of a notion of international humanitarian law could be useful. The notion of grave breaches of international humanitarian law is commonly referred to as war crimes. War crimes include all grave violations of the laws of war committed by the agents of a belligerent state against citizens or property of the enemy. The terrorists attack civilians, launch indiscriminate attacks and take hostages. If committed in wartime by combatants, these acts would be war crimes; however, such a definition restricts the meaning of the term terrorist. It would have been justified has they been committed in wartime by combatants. Such acts, of crime which must be punished. But in so far as people have committed such crimes with a political motivation, they may fall under the exemption from extradition for political offenders ( which of course does not mean that they must not be punished). Conversely, terrorist acts as defined above should never be acknowledged as political offences granting exemption from extradition. The legal foundation for this statement is that fact that in the Geneva Convention and in protocol I, States have formally undertaken either to prosecute or to extradite war criminals. Consequently, how could they refuse to prosecute or to extradite persons who, as private individuals, committed such acts in peacetime?

Politically such an exception to the exemption from extradition for political offenders should be justified even in the eyes of states which consider that the objectives pursued by the terrorists are to some extent legitimate. Indeed, one hundred and sixty two states have acknowledged being party to the Geneva Convention that not even a soldier's perfectly legitimate objective to defend his country can possibly justify war crimes, and they have even accepted

the obligation to punish their own soldiers for their war crimes. Even from the terrorist's point of view, it should be perfectly justified that he, claiming to be engaged in a just war, is expected at least to comply with the laws of war, failing which he cannot expect any lenience because of his objectives.

**Dealing with terrorism** - International human laws are applicable both to international and non-international armed conflict. In the last few decades, a new type of conflict, which does not belong to either of these categories, has emerged. Cross-border terrorism has acquired the character of undeclared war between the sovereign imperial of the victim states and the organised militancy of international terrorism. Police and security forces called upon to deal with this kind of conflict are often under great pressure to achieve results. Unable to hit the unseen enemy, who is carrying on a campaign of attrition, they fall a victim to a sense of revenge and irrational impulses, consequently committing grave violations of human rights. The basic question posed by them is, are the human rights of outlaws more important than the human rights of the peace loving and law abiding citizens. The answer is that as agents of the state, security personnel are to uphold the constitution and the rule of law.

In addition to human right laws Common article 3 of the four Geneva Conventions and Protocol II lay down the parameters to be followed in all situations including proxy wars. They prohibit murder, torture, corporal punishment, outrage upon personal dignity, hostage taking, collective punishment, execution without regular trial and cruel or degrading punishment. Under the provisions of the international covenant on civil and political rights, when the security of the state is threatened, the state can declare a state of emergency and suspend, for a limited period, certain human rights. This can be done by the state following the procedure for "derogation" contained in article 4. While certain rights can be amended during the existence of the state of emergency, the following cannot be amended or taken away:-

1. Right to life.
2. Right against torture.
3. Right against slavery and servitude.
4. Right to be not imprisoned for the failure to meet contractual obligations.
5. Right to be spared from retroactive legislation.
6. Right to be recognized as a person before law.
7. Right to freedom of thought, conscience and religion.

Police and Security forces, by maintaining their legal and ethical standards and by observing the human rights of the people, will gain respect of the people. By constantly violating the rights and freedoms of the people, the outlaws lose the respect and support of the people. Their mask of idealism gets torn and their true colours as criminals will get exposed. It can be construed from the above, that terrorism can be combated and human right violations prevented effectively by religiously following the under



mentioned legal provisions available at the disposal of the counter terrorists:-

**Legal Framework to combat terrorism** - There are various legal legislations which are enacted by the country to combat terrorism. The legal acts available have been elaborated in part VI of this book.

**Legal Framework of Human Rights** - There are certain human right acts enacted at the international and national level which lays down the guidelines to be followed to promote and encourage respect for human rights and fundamental freedoms for all without distinction. All operations undertaken in counter terrorism environment should follow these guidelines to prevent violation of human rights. Few of the important acts as applicable to our country have been included in part VI of this book.

**Human Rights Concerns of the Army** - The importance on human rights is fully realised by the army and a number of actions have been taken to safeguard human and rights while undertaking operations. These actions include the following:-

**Human Rights** - A Special Army Training Manual No 29 has been issued which comprehensively covers all aspects of human rights training. The subject is taught in all appropriate courses of instruction and unit level training schedules starting from basic recruit training.

**Do's and Don'ts** - Instructions in the form of 'Dos' and Don't's to troops while operating under armed forces (special power act)

**COAS Commandments** - these are issued to each individual operating in the Low Intensity Conflict Environment.

**Human Right Courses** - Officers are sponsored on special courses on human rights and media management in the school of Criminology and Forensic Sciences and Institute of Mass communication.

**Action on Human Rights Allegations** - The Army takes serious courses on human rights allegations against members of the Armed Forces/Units. Some of the steps taken in this regards are:-

A human rights cell has been constituted in Army HQ (Adjutant General's Branch) to investigate, monitor, analyse and record all allegations of human rights.

Every human rights allegation is scrutinised, investigated and replied to.

On investigation, if the allegation are found to be true, exemplary punishment is meted out to the defaulters and redressal to the aggrieved, to the extent possible.

Invitation to independent bodies like the press council of India to investigate into the allegations.

**Visit to the ICRC teams** - Consequent to the signing of a memorandum of understanding between the government of India and the ICRC in 1995, the ICRC teams have been allowed to visit various detention camps in J&K including the Additional Police lockups that the army is manning on behalf of the local police. It was considered a positive step to exhibit the transparency of operations by the army and

its concern for human rights. During the seven visits so far, the ICRC teams have been seemingly satisfied with the basic amenities and the health of the detainees.

**Travesty of justice** - the apparent silence of many human rights activists and groups on the abuses and the excesses of armed political terrorists have led to the popular perception that human right bodies are apathetic, unfair and sympathizers of the armed political groups. It is incorrect to brush away the excesses and violation of the human rights by the terrorist/insurgent groups in the name of revolution. The army has to perform its duties pertaining to the security of the country and some human rights problems arise because modern terrorist activities do not recognise clear boundaries and the absence of definition of combatants and non-combatants. During operations against armed terrorists, the army feel compelled in treating the entire population in their zone of operations as legitimate when civilian population provides protection and support to such terrorist groups. The issue related to human right abuses by terrorists/political opposition groups are both real and pressing and it is essential that a broader consensus on the issues of political norms and accountability can be built up from both sides in clear terms.

Human rights violations by the army need to be seen in the proper national perspective and the supremacy of state sovereign authority over terrorists and criminals. It is better to perform one's duty even if some mistakes are committed than not to perform the duty at all. Human rights organisations have to have a balanced outlook on human rights violations, for example, the spirit behind which the security force resort to 'extended detention' of apprehenders – operational exigencies and other handicaps (terrain, mobility, chances of arbitrary releases) needs to be well understood. Moreover, we cannot continue to turn a blind eye to atrocities perpetrated by terrorists through indiscriminate violence against innocent civilians. Frequent visits and cross-training of human rights activists will prove beneficial.

**Reasons of human Right Violations** - Human rights being dynamic, inalienable and invisible are fundamental to the dignified existence of individuals. They have direct impact on quality of life in society. Human rights ensure prosperity in society by having satisfied and productive people. However in spite of all positive aspects violation of human rights occur in a society. The reasons for the same in India are as enumerated below:-

**Feudalism** - The mindset of an average Indian is feudal. As feudalism believes in the inequality of man, the principles of human rights which uphold the universality of the human being are not acceptable to the higher echelons in society.

**Colonial Past** - Our colonial past has taught us to obey authority without question. The law enforcement functionaries and bureaucracy expect unquestionable submission to their authority by the citizen. When confronted with the basic principles of human rights and questioned about their legitimacy and justification. They react in anger and

used violence against people.

**Social Mores** - When lower castes, untouchables and the economically backward try to assert their rights, they face retribution and retaliation from the upper caste and the rich.

**Poverty** - the majority of indians live below poverty line when there is agrim struggle for existence, many of the principles of human rights appear to them to be impractical and devoid of merit. Poverty aid s and abets the violation of human rights in making the viticms collaborate with the exploiters.

**Illiteracy** - It prevents proper appreciation of the egalitarian principles involved in human rights. Lack of awareness prevents people from exercising their rights.

**Legal Procedures** - Victims are unable to get quick redressal. Thus they loose faith in the profession and concern for human rights.

**Instability** - when stability is threatened, society sanctions the use of force to quell the dissidence. This invariably leads to violation of human rights.

**The effects of violence** - The reasons for violation of human rights as enlisted above have an adverse impact on society. The aim here is to describe the consequence of violence in humanitarian terms, from the point of view of the victim, leaving aside the question as to whether the violence is the result of lawful acts and who is responsible. As all form of violence does have adverse effects on the psychological integrity of the victims and their families. In general terms, and without claiming to be exhasustive, following effects may be identified:-

**Physical Damage** - It involves illness, disability or causing death.

**Inhuman Treatment** - Torture and ill-treatment of people.

**Disappearances** - These may be the result of adeliberate state policy, or the doing of para military groups or opposition movements. Those who disappear may be held captive at secret locations, more often than not, however, they are killed, either to terrorize the population or to avoid the stigma of national or international disapproval resulting from the arrest and detention of certain opposition figures.

**Deprivation of freedom** - The classic form of detention is incarceration in a closed place designed for the purpose (prisons, camps, or – in some countries – psychiatric hospital etc), but there are others, such as confinement to residence or in another region of the country, often far away, isolated and insalubrious.

**Displaced Person** - A person's inability to satisfy his vital needs (security, material survival, psychological needs), when he has lost his means of subsistence, has been displaced within the country or has had to seek refuge abroad.

**Isolation** - It involves separation of families, whose members are without news of their relatives on account of the hostilities or unrest.

**In direct-sufferings** - The suffering of individuals or communities indirectly affected by the strife, such as families with no means of support, communities whose precarious

economic situation is threatened by the additional burden represented by refugees or displaced populations, and persons who are suspect on account of their kinship with someone involved in the violence.

**Human Right Organisations in India** - Till 1993, there was no statutory organization dealing directly with human rights. The supreme and high courts acted as watchdogs in consonance with our constitution. However, they were to speak only if their matter was brought before them for adjudication. The promulgation of the human rights ordinance of 1993 put and end to this. Thereafter organisations at central and state levels were created. The relevant provisions are given below:-

**Aim** - the aim of the national and state human rights commissions is to establish statutory organs throughout the country for detection of human rights violations, protection and their enforcemnt.

**Objective** - National Human Rights commission at the national level and the state human rights commissions at the state level are for better protection of life, liberty, equality and dignity of an individual guaranteed by the constitution of india, which are further embodied in the international conventions to which india is a signatory.

**Scope** - The following aspects merit attention:-

1. The human rights ordinance of 1993 makes the constitution of the national human rights commission mandatory, while at the state level it is optional.
2. The powers of the NHRC and the SHRC are not absolute when dealing with the Armed Forces.
3. The commissions shall not enquire into any matter after the expiry of one year from the date of commissions.

**Power of Human rights commissions** - Salient aspects of the powers of the human rights commissions are enumerated below:-

1. They have the powers of a civil court trying a suit under Code of Civil Procedure 1908.
2. They enjoy the powers to summon and enforce the attendance of witnesses and examine them under oath.
3. Powers to visit any jail after informing the state govt.
4. Powers to review the safeguards provided by or under the constitution or any law in force for the protection of human rights and recommend measures for their implementation.
5. Power to review the functions including acts of terrorism, which restrict enjoyment of human rights.
6. Power to suggest recommendations on international institutes of human rights.

**Restrictions** - there are certain restrictions imposed on the human rights commissions when dealing with the security forces. They are :-

1. The human rights commissions can deal with armed forces, for an infringement of human rights only through the central government.
2. On receipt of a petition or complaint of violations of human rights by armed forces, it shall seek a report from the central government.

3. On receipt of the report, the commission will, if it decides to proceed against it, make recommendation to the central government within three months.
4. The aforesaid recommendations and action taken shall be published by the commission and a copy of such a report be provided to the petitioner or his representative.

**Organisation** - The organization of the various human rights commissions to deal expeditiously and effectively with proven cases of human right violations, exclusive human rights courts have been set up all over India and thus joined the advanced nations in implementing human rights in letter and spirit. In a country of continental dimensions with great diversity of language, traditions and practice, it will be unrealistic to expect and overnight change in attitudes congenial to employment of human rights. However, we have initiated steps towards making our nation and society more humane.

**Conclusion** - It is only through discipline, and by making the law enforceable, more visible, more identifiable, more practical, that we can regulate conduct in war like situations. It is only in conduct formation and acceptance of this conduct as binding that we can have humanitarian law applied and imposed. Enforcement is nevertheless difficult. Acceptance is the process of enforcement, because breaches are difficult to establish and redress.

**Reference: -**

1. KM Mathur – Law and Order Administration with special reference to terrorism.
2. Lt Col Smith Andrew – Combating Terrorism.
3. Lt Gen Vijay Oberoi – Security challenges of india.
4. B Raman – Terrorism, Yesterday, Today and Tomorrow.
5. DM Mitra – Understanding Indian insurgencies.
6. KPS Gill –Terror and Containment Perspective of India's Internal Security.
7. Dr AP Maheshwari – Craft of Counter insurgency.

\*\*\*\*\*

## महिलाओं में मद्यपान की प्रवृत्ति (उदयपुर जिले के संदर्भ में)

**डॉ. सुनीता खण्डेलवाल\***

**प्रस्तावना** - मद्यपान किसी एक व्यक्ति की ही नहीं अपितु एक परिवार की सामाजिक- सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और विकास की समस्या है। यह एक उत्तेजक पेय पदार्थ है, जिस पर नियन्त्रण नहीं किया गया तो यह व्यक्ति और शारीरिक विघटन का बहुत बड़ा कारक सिद्ध होगा। वर्तमान में इसके बढ़ते प्रयोग ने सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। सामाजिक- धार्मिक उत्सवों, तीज-त्यौहारों, अतिथि-सत्कार, मित्र से मिलन या विदाई के दौरान, शुभकामनाएं प्रदर्शित करने आदि अवसरों पर तो मद्यपान करना आम होता जा रहा है, इसके अतिरिक्त भी व्यक्ति दिनभर की थकान मिटाने, तनाव दूर करने, हाथ-पैरों में कम्पन, कार्यक्षमता बढ़ाने आदि में भी एक उत्तेजक पेय पदार्थ के रूप में इसका उपयोग कर रहा है। मद्यपान न केवल मद्यसेवन करने वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है अपितु सामाजिक परिस्थितियों और सांस्कृतिक परम्पराओं को भी प्रभावित करता है।

नियन्त्रित मात्रा में इसका प्रयोग किया जाए तो कोई नुकसान नहीं परन्तु अनियन्त्रित मात्रा व्यक्ति, पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। मदिरा व्यवहार में स्व-नियन्त्रण को कम कर देती है। मदिरा सेवन करने वाला व्यक्ति स्वच्छन्द व्यवहार करने लगता है। कभी-कभी मद्यसेवन करने वाला व्यक्ति भी इसका आदी होने लगता है और प्रतिदिन इसका सेवन करने वाला और अधिक मात्रा में पीने लग सकता है। यह उसे शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, काम करने की क्षमता कम या नष्ट कर सकती है और उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। मदिरा व्यक्ति के पूरे जीवन को नष्ट कर सकती है।

आज मदिरा लाखों स्त्री-पुरुषों की आवश्यकता बनती जा रही है। कुछ समाजों में इसे बुरा समझा जाता है तो कुछ समाजों में इसे आवश्यक रूप से स्वीकार किया जाता है। मद्यपान किसी जाति, धर्म, प्रान्त, व्यवसाय आदि तक ही सीमित नहीं है। अमीर-गरीब, ग्रामीण-शहरी, स्त्री-पुरुष बालक-बालिकाएं सभी श्रेणी के व्यक्ति इसकी ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। एक समय था जब धनाढ्य वर्ग, पूंजीपति, पश्चिमी सभ्यता का लबादा ओढ़े सम्भ्रान्त वर्ग ही मदिरा सेवन करते थे, मगर आज यही मदिरा उस छोटे से दायरे से होती हुई बड़े दायरे में फैल चुकी है। मदिरा पीना-पिलाना आज फैशन बनता जा रहा है। अभिजात्य वर्ग जो मदिरा पीता भी है और शान से जीता भी है, मगर गरीब तबका जो मदिरा खरीदकर पीने में समर्थ तो नहीं है मगर किसी तरह खरीदकर पी रहा है और बेमौत तिल-तिलकर मर भी रहा है। मद्यसेवन मादकता, उन्माद तो प्रदान करता ही है साथ ही व्यक्तित्व के विकास में कमी तथा निर्धनता व मृत्युदर में भी वृद्धि करता है। मद्यपान से व्यक्ति कुछ देर के लिए अपने आपको व समाज को भूल जाता है और अपराध की ओर आसानी से खींचा चला जाता है।<sup>2</sup>

**अध्ययन की आवश्यकता** - उदयपुर जिला जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। जनजातीय क्षेत्रों में अवैध रूप से मदिरा निर्माण किया जाता है। सरकार द्वारा निर्मित एवं वितरित मदिरा की तुलना में स्वयं द्वारा घर में बनी कच्ची देशी मदिरा सस्ती पड़ती है। अतः महिला-पुरुष द्वारा समान रूप से मद्यसेवन किया जाता है, जिसके कारण इनके जीवन पर सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। समाज में गरीबी, बेरोजगारी, विभिन्न तरह की बीमारियां, अपराध, अपहरण, बलात्कार जैसी गम्भीर समस्याएं भी मद्यसेवन के कारण बढ़ती जा रही हैं। महिलाओं में मद्यपान की प्रवृत्ति अत्यन्त चिन्ताजनक है। जबसे मदिरा अथवा शराब अस्तित्व में आई, तभी से महिलाओं ने इसका सेवन प्रारम्भ कर दिया था। सरकार एवं विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा दूरसंचार माध्यमों, विज्ञापनों, समाचार पत्र-पत्रिकाओं आदि के माध्यम से मदिरा के दुष्प्रभावों की जानकारी देने के उपरान्त भी कतिपय समाजों को छोड़कर अन्य सामाजिक समूहों में इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जिससे महिलाओं में तनाव, गर्भधारण में कठिनाई, कैंसर, खांसी आदि बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, जो कि चिन्ताजनक है। महिलाओं में मद्यसेवन के दुष्परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त शोध कार्य किया गया है। महिलाओं में मद्यपान के क्या कारण हैं, मद्यपान के लिए उन्हें कौन प्रेरित करता है, मद्यपान से उनके जीवन पर क्या प्रभाव व परिणाम पड़ता है, मद्यपान छोड़ने में उन्हें किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मद्यपान नियन्त्रण हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के प्रयास सार्थक हैं अथवा नहीं आदि प्रश्नों के उत्तरों की प्राप्ति हेतु इस विषय का चयन अध्ययन हेतु किया गया है।

राजस्थान राज्य के 33 जिलों में से एक उदयपुर जिला है, जोकि आदिवासी बहुल जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार उदयपुर की कुल जनसंख्या 3068420 है जिसमें 1566801 पुरुष एवं 1501619 महिलाएं हैं। उदयपुर जिले की कुल साक्षरता 62.74 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षरता दर 75.91 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 49.10 प्रतिशत है।<sup>3</sup>

### अध्ययन के उद्देश्य

1. उत्तरदाता की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक पृष्ठभूमि को जानना,
2. उदयपुर जिले में मद्यपान किए जाने की प्रवृत्तियों को जानना,
3. मद्यपान करने के कारणों को जानना,
4. मद्यपान के परिणामों का मूल्यांकन करना एवं
5. मद्यपान को बढ़ावा देने वाले कारकों का अध्ययन करना।

### अध्ययन की प्राकल्पनाएं

1. अशिक्षित महिलाओं में शिक्षित महिलाओं की अपेक्षा मद्यपान की प्रवृत्ति



- अधिक है।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवनव्यापन करने वाली महिलाओं में मद्यपान की प्रवृत्ति अधिक है।
  - अनुसूचित-जाति एवं जनजाति की महिलाओं में मद्यपान की प्रवृत्ति अधिक है।
  - कामकाजी एवं स्वरोजगार करने वाली महिलाओं में मद्यपान की प्रवृत्ति कम पाई जाती है।
  - मद्यपान रोकने हेतु सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रयास सिर्फ वार्तालाप एवं कागजों तक ही सीमित है।
  - मद्यपान करने वाली महिलाओं की अपेक्षा मद्यपान नहीं करने वाली महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति अधिक सुदृढ़ होती है।

**शोध प्रविधि** - प्रस्तुत अध्ययन महिलाओं में मद्यपान की प्रवृत्ति विषय से संबंधित है। स्नोबॉल निदर्शन प्रणाली द्वारा 300 मद्यपान करने वाली व 200 मद्यपान नहीं करने वाली उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। उत्तरदाताओं के शिक्षित एवं अशिक्षित अथवा कम पढ़े-लिखे होने के कारण साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्य एकत्रित किए गए हैं। तथ्य संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्त्रोतों के माध्यम से किया गया है।

**मद्यपान: कारण एवं अवसर** - कार्य और कारण के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जब भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य निहित होता है। मद्यपान एक ऐसी आदत, लत या प्रवृत्ति है जिसके पीछे भिन्न-भिन्न कारण एवं प्रणालियाँ हैं। नियन्त्रित मात्रा में मद्यपान अपराध उत्पन्न नहीं करता परन्तु इसकी अनियन्त्रित मात्रा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तरीके से मानव व्यवहार को अपराध की ओर धकेलती है। प्रस्तुत शोध में क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान महिलाओं में मद्यपान के निम्न कारण सामने आए-

#### सारणी संख्या 1 : मद्यपान के कारण

क्र.	महिलाओं में मद्यपान के कारण	संख्या	प्रतिशत
1	सामाजिक परम्परा	123	41.00
2	शारीरिक अथवा मानसिक थकावट	182	60.66
3	मनोरंजन अथवा आनन्द के लिए	166	55.33
4	फैशन अथवा शौक के लिए	84	28.00
5	पारिवारिक कलह	100	33.33
6	बीमारी के कारण	54	18.00
7	नशा करने की आदत	148	49.33
8	सस्ती और आसानी से उपलब्धता	172	57.33
9	कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु	139	46.33
10	सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य	99	33.00
11	विज्ञापनों से प्रेरित होकर	132	44.00

स्रोत-क्षेत्रीय अध्ययन

उपरोक्त सारणी संख्या 1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 300 मद्यपान करने वाली महिला उत्तरदाताओं में से 123 (41%) उत्तरदाताओं के परिवार अथवा समाज में शादी-विवाह, तीज-त्यौहारों पर, अतिथि सत्कार तथा जन्म से मृत्यु तक के संस्कारों आदि अवसरों पर मद्यपान करने की परम्परा है, 182 (60.66%) उत्तरदाता प्रतिदिन होने वाली शारीरिक व मानसिक थकावट दूर करने के लिए मदिरा का सहारा लेती है, 166 (55.33%) उत्तरदाता जीवन में मनोरंजन अथवा आनन्द पाने के लिए मद्यपान करती है, 84 (28%) उत्तरदाता फैशन अथवा शौक के लिए मद्यपान करती है ताकि

वे अपने मित्रों के बीच सहज महसूस कर सकें, 100 (33.33%) उत्तरदाता पारिवारिक कलह के कारण मद्यपान करती है, 54 (18%) उत्तरदाता खांसी, जुकाम, बुखार आदि बीमारियों से निजात पाने के लिए मद्यपान करती है, 148 (49.33%) उत्तरदाताओं को नशा करने की आदत है जिसके कारण उन्हें मदिरा का सहारा लेना पड़ता है, 172 (57.33%) उत्तरदाता मदिरा की आसानी से उपलब्धता के कारण मद्यपान करती है, 139 (46.33%) उत्तरदाता कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु मद्यपान करती है। मद्यपान के बाद वे अधिक सक्रियता से कार्य कर पाती है, 99 (33%) उत्तरदाता सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के कारण मद्यपान करती है, 132 (44%) उत्तरदाता विज्ञापनों से प्रेरित होकर मद्यपान करती है। अध्ययन में सर्वाधिक 182 (60.66%) उत्तरदाता प्रतिदिन होने वाली शारीरिक व मानसिक थकावट दूर करने के लिए मदिरा का सहारा लेती हैं जबकि सबसे कम 54 (18%) उत्तरदाता खांसी, जुकाम, बुखार आदि बीमारियों से निजात पाने के लिए मद्यपान करती हैं।

#### सारणी संख्या 2 : परिवार में मद्यपान के अवसर

क्र.	मद्यपान करने के अवसर	उत्तरदाता	प्रतिशत
1	सामाजिक रीति-रिवाजों (जन्म से मृत्यु तक के संस्कारों में)	109	36.33
2	धार्मिक अवसरों पर उपयोग	55	18.33
3	मेलों/त्यौहारों पर उपयोग	88	29.33
4	अतिथि सत्कार पर उपयोग	48	16.00

स्रोत-क्षेत्रीय अध्ययन

उपरोक्त सारणी संख्या 2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 300 मद्यपान करने वाली महिला उत्तरदाताओं में से 109 (36.33%) उत्तरदाता प्रतिदिन मद्यपान करती है, 55 (18.33%) उत्तरदाता धार्मिक अवसरों पर मदिरा सेवन करती है, 88 (29.33%) उत्तरदाता तीज-त्यौहार, मेलों आदि के अवसर पर मद्यपान करती है, 48 (16%) उत्तरदाताओं के परिवार में अतिथि-सत्कार मद्यपान के बिना अधुरा माना जाता है अतः वे घर में अतिथि के आगमन पर उनके सत्कार के दौरान मद्यपान करती हैं।

**मद्यपान: प्रभाव एवं परिणाम** - मदिरा न केवल व्यक्ति अपितु उसके परिवार के साथ-साथ समाज को भी भावनात्मक और आर्थिक रूप से प्रभावित करती है। प्रारम्भ में व्यक्ति इसे दुख, तनाव, शारीरिक एवं मानसिक थकावट दूर करने, मनोरंजन एवं आनन्द की प्राप्ति हेतु, मौज-शौक आदि में सेवन करता है किन्तु यह कब उसके जीवन में महत्वपूर्ण हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। मदिरा आनन्द प्राप्ति की अपेक्षा बुराइयों को अधिक जन्म देती है। मद्यपान लड़ाई-झगड़ा, गाली-गलौच, परिवार एवं समाज के वातावरण को दूषित करती है। आरम्भ में मद्यपान जोश, उत्साह व आनन्द की अनुभूति देता है पर भीतर ही भीतर व्यक्ति को खोखला करता जाता है जिससे वह दीन-हीन, कमजोर, तनावग्रस्त एवं विभिन्न प्रकार के मानसिक एवं शारीरिक रोगों से ग्रस्त होने लगता है।

#### सारणी संख्या 3 : मद्यपान के प्रभाव

क्र.	मद्यपान के प्रभाव	संख्या	प्रतिशत
1	कार्यों और प्रक्रियाओं पर प्रभाव	139	46.33
2	स्वास्थ्य पर प्रभाव	111	37.00
3	आर्थिक स्थिति एवं खान-पान पर प्रभाव	209	69.66
4	आपसी संबंधों पर प्रभाव	47	15.66

स्रोत-क्षेत्रीय अध्ययन

उपरोक्त सारणी संख्या 3 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 300 मद्यपान करने वाली महिला उत्तरदाताओं में से 139 (46.33%) उत्तरदाताओं के कार्य और प्रक्रियाएं मद्यपान करने के कारण प्रभावित होती हैं, उन्हें काम पर जाने में देरी हो जाती है तथा वे अपने कार्य को सुचारु रूप से नहीं कर पाती हैं। 111 (37%) उत्तरदाताओं के स्वास्थ्य पर मद्यपान का बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिकांश उत्तरदाता टी.बी. से ग्रस्त हैं। इसके अतिरिक्त भी उन्हें भूख कम लगती है, नींद नहीं आती व कमजोरी महसूस होती है। 209 (69.66%) उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति और खान-पान पर मद्यपान से प्रभाव पड़ा है। वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में स्वयं को असमर्थ मानती हैं। 47 (15.66%) उत्तरदाताओं के अपने परिवार और रिश्तेदारों से अच्छे संबंध नहीं हैं। कभी-कभी अधिक मात्रा में मद्यसेवन करने के कारण वे अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ अभद्र व्यवहार करती हैं जिसके कारण उनके परिवार और रिश्तेदारों से संबंध अच्छे नहीं हैं। अध्ययन में सर्वाधिक 209 (69.66%) उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति और खान-पान पर मद्यपान से प्रभाव पड़ा है।

#### सारणी संख्या 4 : मद्यपान के परिणाम

क्र.	मद्यपान के परिणाम	संख्या	प्रतिशत
1	गांव/परिवार में मृत्यु	219	73.00
2	लोगों से मिलने से बचना	136	45.33
3	आलोचना	97	32.33
4	घर में तनाव	126	42.00

स्रोत-क्षेत्रीय अध्ययन

उपरोक्त सारणी संख्या 4 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 300 मद्यपान करने वाली महिला उत्तरदाताओं में से 219 (73%) उत्तरदाताओं के परिवार अथवा गांव में मद्यपान के कारण मृत्यु हुई है, 136 (45.33%) उत्तरदाता मद्यपान के बाद लोगों से मिलने से बचती हैं। उन्हें भय रहता है कि उनके मद्यपान की आदत का लोगों को पता नहीं चल जाए अतः वे मद्यपान के बाद किसी से नहीं मिलती हैं, 97 (32.33%) उत्तरदाताओं की मद्यपान करने के कारण परिवार व समाज में आलोचना की जाती है, 126 (42%) उत्तरदाताओं के घर में मद्यपान के कारण तनाव का माहौल रहता है।

**निष्कर्ष एवं सुझाव** - मद्यसेवन अथवा मदिरापान आदिकाल से ही हमारे समाज में किसी-न-किसी रूप में प्रचलन में रहा है। मद्यसेवन करने वाला व्यक्ति अपने परिवार एवं समाज के लिए एक अभिशाप है क्योंकि उसकी इस प्रवृत्ति के कारण उसके परिवार की सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक स्थिति प्रभावित होती है। घर का वातावरण दूषित होता है, रिश्तेदारों से संबंध प्रभावित होते हैं तथा स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। मदिरा के खतरनाक प्रभावों से परिचित होने के बावजूद भी गली, मोहल्लों व चौराहों पर शराब की दूकानों पर मद्यसेवन करने वाले व्यक्ति मदिरा खरीदते हैं और इसका सेवन इस प्रकार करते हैं जैसे कोई शीतलता प्रदान करने वाला पेय हो। सरकार एक ओर तो मदिरा पर प्रतिबन्ध लगा रही है और दूसरी तरफ अपनी राजस्व आय बढ़ाने के लिए नए-नए ठेकों के लिए आवेदन आमन्त्रित करती है। वर्तमान समाज में शराब को सामाजिक मान्यता प्राप्त होने के कारण युवावर्ग व महिलाएं मद्यसेवन की ओर अनायास ही आकर्षित हो रहे हैं। महिलाओं में मद्यपान की प्रवृत्ति एक गम्भीर चिन्ता का विषय है, चाहे मदिरा का सेवन कम मात्रा में किया जाए अथवा अधिक मात्रा में किया जाए। महिलाएं अपने मित्रों की संगत, फैशन अथवा शौक-शौक में मद्यपान करती हैं। यदि यह कहा जाए कि महिलाओं ने मद्यपान की प्रेरणा अपनी मित्र मण्डली से

ग्रहण की है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुधा उन्हें हाई-फाई सोसायटी में, अपने मित्रों की पार्टियों में अनाड़ी, अशिष्ट एवं गवांर नहीं समझ लिया जाए इस हेतु अपनी शान-शौकत बनाए रखने के लिए वे मद्यसेवन करती हैं। कुछ समाजों में वंशानुगत परम्परा के कारण भी महिलाएं बचपन से ही मद्यसेवन की ओर अग्रसर होने लगती हैं।

#### मद्यपान: नियन्त्रण के सुझाव :

1. मदिरा के सार्वजनिक उत्पादन, भण्डारण एवं विक्रय पर सरकारी नियन्त्रण रखा जाना चाहिए।
2. वर्तमान शिक्षा पद्धति में सुधार कर युवा वर्ग को मद्यनिषेध हेतु जागरूक चाहिए।
3. मद्यपान की प्रवृत्ति को कम करने हेतु सरकारी स्तर पर जगह-जगह नशा मुक्ति हेतु चिकित्सा केन्द्र खोले जाएं, जहां पर पीड़ित व्यक्ति को मानसिक उपचार के साथ-साथ भविष्य में मादक द्रव्यों से दूर रहने के लिए जागरूक किया जावे।
4. वर्तमान युवा जनसंचार माध्यमों से प्रेरित होकर नशे की ओर उन्मुख हो रहा है अतः सरकार को नशे से संबंधित विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।
5. शराब की कीमतों में वृद्धि करनी चाहिए ताकि इसको खरीदने में मुश्किलें आने लगे।
6. सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर शराब पीना, शराब पीकर वाहन चलाना व काम पर जाना इत्यादि कार्यों को गैर-कानूनी बनाकर कठिन से कठिन सजा का प्रावधान होना चाहिए।
7. शराब के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए और युवाओं में मानसिक सेहत संबंधी समस्याओं में मदद के लिए माता-पिता के लिए दिशा-निर्देश दिए जाने चाहिए। माता-पिता व अन्य रिश्तेदारों को बच्चों के सामने मद्यपान नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें बच्चों को मदिरा क्रय करने हेतु भेजा जाना चाहिए।
8. मनोचिकित्सा केन्द्रों में नशा विमुक्ति केन्द्र होते हैं जहां डी-टोक्सीफिकेशन द्वारा शराब छुड़ाने तथा उसके उपरान्त मोटिवेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी तथा ग्रुप थेरेपी द्वारा इससे निजात पाने की कोशिश की जाती है। इसकी जानकारी आमजन को देनी चाहिए।
9. मनोरंजन के अन्य सस्ते साधन जैसे-सिनेमा, क्लबों आदि का उचित विकास भी मद्यपान निषेध में सहायक हो सकता है तथा सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा फीचर फिल्म एवं डॉक्यूमेन्ट्री के द्वारा जनमानस को नशीले द्रव्यों की बुराईयों की जानकारी देकर उन्हें नशा मुक्त होने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
10. आबकारी विभाग और मद्यनिषेध विभाग को यदि अलग-अलग कर दिया जाए तो भी मद्यपान की प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है।
11. मद्यनिषेध कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय बजट की राशि को बढ़ाया जाए ताकि मदिरा पीने से होने वाली बुराईयों के प्रचार-प्रसार और यशगान में कमी की जा सके।
12. होली, दीपावली जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सप्ताह पूर्व सूखा दिवस घोषित किया जाना चाहिए तथा चोरी-छिपे मदिरा निर्माण एवं विक्रय पर औचक निरीक्षण किया जाना चाहिए।
13. मद्यपान नियन्त्रण हेतु विद्यालय से ही विद्यार्थियों को मद्यपान से होने वाले नुकसान की जानकारी दी जानी चाहिए। बालकों को आरम्भ से ही मद्य निषेध के संस्कारों से अवगत कराया जाना चाहिए।

14. राज्य सरकारों को बेरोजगारी, गरीबी, तनाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए जिससे युवा वर्ग को अधिक से अधिक रोजगार प्रदान कर उनकी क्षमता को देशहित में प्रयोग किया जा सके।
15. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मद्यपान से संबंधित शोध कार्य किया जाना चाहिए। शोध के द्वारा अधिक मात्रा में मद्यपान करने के कारण एवं प्रभावों की जानकारी प्राप्त कर उन्हें दूर करने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए।
16. मद्य निषेध हेतु प्रचार शिविर, पद्यात्राओं, सभाओं आदि का आयोजन कर आमजन को मद्यपान के विरुद्ध प्रेरित किया जाना चाहिए।
17. विश्व मादक पदार्थ विरोधी दिवस 26 जून को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नाटक, कव्वाली, कठपुतली, जादू आदि विभिन्न मनोरंजनात्मक विधाओं का प्रयोग कर मद्य निषेध का प्रचार-प्रसार करना चाहिए।
18. सार्वजनिक स्थलों पर वॉल पेंटिंग व होर्डिंग के द्वारा मद्य निषेध से संबंधित प्रेरक कार्य किया जाना चाहिए।
19. मद्य निषेध से जुड़े व्यक्तियों एवं संगठनों से सहयोग कर ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों, मोहल्लों में नशा निषेध सतर्कता समितियों का गठन कर नशा मुक्ति हेतु सामाजिक, धार्मिक दबाव बना कर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
20. विश्व स्तर पर की जा रही मादक द्रव्य तस्करी के लिए प्रख्यात देश जैसे-पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, थाइलैण्ड, नेपाल और लागौस जैसे देशों से समुद्री मार्ग या अन्य मार्गों से आने वाले नशीले पदार्थों पर रोक लगाई जानी चाहिए तथा जब्त नशीले पदार्थों को नष्ट कर उनपर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।
21. मद्यनिषेध से संबंधित न्याय प्रक्रिया को त्वरित किया जाना चाहिए ताकि अपराध एवं दण्ड के प्रति सामाजिक उपयोगिता बनी रहे।
22. 1985 में बना कानून 'द नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंसेज एक्ट' कानून के उल्लंघन पर दो लाख रु जुर्माना तथा कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है, उसे कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए।
23. मद्यपान पर नियन्त्रण हेतु पुलिस विभाग को केशबार् प्रेरणा शुल्क प्रदान करना चाहिए जिससे वे मद्यपान करने वालों पर नियन्त्रण रखने में अधिक से अधिक प्रेरित हो सके।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Jhonson, Elmer H. (1973) Social Problems of urban man: The Dorsey press homewood illinois, p519
2. दीक्षित, पुष्पेन्द्र (2008), 'नशे में घुलता युवा भारत'
3. कार्यालय जिला सांख्यिकी अधिकारी, उदयपुर

\*\*\*\*\*

## बाग गुफाओं और भित्ति चित्र का पुरातात्विक महत्व - पर्यटन के संदर्भ में

प्रेमविजय पाटिल \*

**प्रस्तावना** - मध्य प्रदेश के धार जिले के बाद क्षेत्र में प्राचीन बौद्ध गुफाएं स्थित हैं। यह बौद्ध गुफाएं कभी बौद्ध काल में अपने मठ, भित्ति चित्र, मूर्तिकला और बौद्ध साधकों के निवास और साधना के मठ के रूप में विश्व विख्यात थीं। अजंता की गुफाओं के समान ही उनका महत्व है। साथ ही यहां के भित्ति चित्र भी एक महान संस्कृति को बताते हैं। मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल धार जिले जहां मांडू जैसी ऐतिहासिक धरोहर है तो वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुफाएं भी हैं। पर्यटन का केंद्र बनने की संभावना वाली ये गुफाएं जानकारी के अभाव के दौर से गुजर रही हैं। जो बुद्ध सर्किल से जुड़ी हैं तो उसका एक अपना विशेष महत्व बढ़ जाएगा। वर्तमान में यहां पर कई तरह की सुविधाएं हैं।

लेकिन इन सुविधाओं में इजाफा करके पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। न केवल स्थानीय पर्यटन बल्कि यहां पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों देशों से आने वाले अंतरराष्ट्रीय जगत से भी एक नाता जोड़ा जा सकता है।

### उद्देश्य :

1. बाग गुफाओं की वर्तमान दशा का अध्ययन किया जाना।
2. गुफाओं का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्व।
3. बाग में पर्यटन सुविधाओं की स्थिति स्पष्ट करना।
4. पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक सुझाव देना।
5. पर्यटन के क्षेत्र में बाग गुफाओं की संभावनाएं खोजना।

**परिचलनाएं** - मध्यप्रदेश में सांची स्तूप बौद्ध परंपरा की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। इसी को सीधे मांडू और बाग से जोड़ा जा सकता है। हमें पता है कि बाग गुफाओं के प्रचार प्रसार के अभाव में यह उपेक्षित है। जबकि यहां पर कई तरह की प्रबल संभावनाएं हैं। जब पर्यटक यहां पहुंचता है तो उसे स्थल सब खास देखने को मिलता है। जो कि प्राकृतिक रूप से एक बहुत ही समृद्ध स्थान के नजदीक प्राचीन इतिहास को जानने का मौका देता है।

**क्षेत्र व सीमाएं** - धार जिले के बाग क्षेत्र की गुफा।

**अध्ययन** - बाग गुफाओं की वर्तमान दशा के साथ प्राचीन महत्व के साथ— मध्य प्रदेश के धार जिले के बाग क्षेत्र में प्राचीनकालीन बाग की गुफाएं स्थित हैं। जो कभी बौद्धकाल में अपने मठ, भित्ति चित्र, मूर्तिकला और बौद्ध साधकों के निवास और साधना मठ के रूप में विश्व विख्यात थी।

इस धरोहर के समीप ही बाघनी नदी और विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान भी स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार ईसापूर्व तीसरी और सातवीं शताब्दी के मध्य जब भारत के पश्चिमी भारत के भाग में बौद्ध धर्म अपनी उच्च पारखी कला के लिए विख्यात था, उस समय चीन के बौद्ध धर्म के महान विद्वान् यात्री हुएनसांग, सुआनताई आदि लोगों ने इस स्थान पर का भ्रमण किया था।

पुरातत्व शास्त्रियों के अनुसार इन गुफाओं को यहां बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन पत्थरों की विंध्य घाटियों पर तराश कर बनाया गया था। वैसे भी भारत के प्राचीन इतिहास में चट्टानों को तराश कर कई भव्य स्थलों का निर्माण किया गया था। जैसे एलोरा स्थित कैलाश मंदिर, महावलीपुर, बादामी गुफाएं आदि। पुरातत्वशास्त्री एस आर्प्टे के अनुसार गुफाओं के निर्माण के आदर्श मॉडलों को हम महाराष्ट्र की अजंता की गुफाएं, मध्य भारत की बाग गुफाएं, भीम बैठका के गुफाचित्र, दक्षिण की हिरेंगुव और श्रीलंका देश की सिगिरि स्थल के माध्यम से गहराई से समझ सकते हैं। कुछ पुरातत्वशास्त्रियों ने बाग गुफा कि रंगमहल गुफा की छत पर मुर्गी के साथ चूजों के आकर्षक भित्तिचित्रों कि गणना भी कि है, जिसे पुरातत्वशास्त्रियों ने मन्डैन थीम का नाम दिया है।

प्रख्यात पेंटिंग आर्टिस्ट और पुरातत्वशास्त्री अंकित कुमार हलदार ने बाग गुफाओं की वाल पेंटिंग्स की प्रतिकृतियां बनाकर उन्हें सन 1926 में ग्वालियर में संरक्षित भी किया था।

ब्रिटिश काल में बाग गुफा और उसके वाल पेंटिंग्स का गहन शोध ब्रिटिश पुरातत्वशास्त्री डंगर फील्ड ने लिटरेरी सोसाइटी ऑफ मुंबई के माध्यम से किया था। उसके बाद ब्रिटिश पुरातत्वशास्त्री डॉक्टर इम्पी ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से किया। बाद में इंडियन एंटीक्वेरी के जनक सर कोलोनेल लुआर्ड ने भी बाग गुफा पर गहन शोध का कार्य किया था। बाग गुफाओं में बारिश, नमी, क्षरण आदि के कुप्रभाव से यहां स्थित भित्ति चित्रों को बहुत नुकसान पहुंचा था। इस कारण इनके रेस्टोरेशन और संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ग्वालियर द्वारा यहां से वाल पेंटिंग्स रूपी भित्ति चित्रों को सावधानी पूर्वक निकालकर ग्वालियर स्थित म्यूजियम पर शिफ्ट कर दिया था।

इतिहासकार इन प्राचीन गुफाओं का निर्माण और संबंध 5-7वीं सदी के बीच यहां निवास करने वाली सांतवाहना साम्राज्य से भी दर्शाते हैं। जिनके समय बुद्ध धर्म उच्च कोटि के शिखर पर पहुंच गया था। बाग गुफाओं में नौ गुफाये हैं। जिनमें गुफा क्रमांक 1, 7, 8, 9 नष्टवान हैं। गुफा क्रमांक 2 पांडव गुफा के नाम से जानी जाती है। जबकि तीसरी गुफा हाथीखाना और चुटहि रंगमहल के नाम से जानी जाती है। इन गुफाओं का उपयोग 5 से 6वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षु चेतना, प्रार्थना, ध्यान आदि के रूप में एक मठ विहार के रूप में करते थे।

इंडियन सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार बाघनी नदी से लगभग 150 फीट की ऊंचाई पर स्थित बाग की गुफाओं को सैंड स्टोन की घाटियों को तराश कर एक पंक्तिबद्ध ढांचे के रूप में स्थापित किया गया था। जहां अधिकतम बेसाल्ट चट्टानों की भरमार थी। इन गुफाओं में कुछ में बौद्ध साधकों



द्वारा पूजन स्थल के स्तूप, भित्ति चित्र, साधना करती हुई बुद्ध की वरदमुद्रा मूर्ति, आकर्षक खंभे आदि स्थित है।

इतिहासकारों के अनुसार बाघ गुफाओं में नौ गुफाएं कभी नौ कक्ष अस्तित्व में हुआ करती थी। वर्तमान में केवल छह गुफाएं ही अच्छी स्थिति में हैं। इसके प्रथम क्रमांक 1 वाले गुफा कक्ष को पुरातत्व शास्त्रियों ने गृह कक्ष का नाम दिया है। इसका बरामदा भी लगभग नष्टवान हो चुका था। जिसे पुरातत्व विभाग के रेस्टोरेशन द्वारा संरक्षित किया गया है। इसके पीछे स्थित बौद्ध चौंवर की लंबाई लगभग 23.14 फीट की है। जो कि चार खंभों पर टिका हुआ है। इसके अगले कक्ष को पांडव या भीम की गुफा भी कहा जाता है। जो स्थानीय लोगो ने नाम दिया है। पुरातत्वशास्त्रियों के अनुसार इस गुफा के अंदर स्थित वाल पेंटिंग्स को धुंए और चमगादड़ों की बैठ कॉलोनी द्वारा अधिक नुकसान पहुंचा था। जिससे कई प्राचीन वाल पेंटिंग्स नष्ट भी हो गई थी। बाघ गुफा के कक्षों में चट्टानों को तराश कर बनाये हुए आकर्षक बरामदे, खिड़किया, प्रवेश द्वार, खंभे बहुत ही भव्य रूप में निर्मित हैं। यह प्राचीन बौद्धकाल के भिक्षु मठ और उनके आवास का एक अनमोल आयाम है। इस गुफा के अंदर हम एक गलियारों में चट्टानों को तराश कर बनाई गई पंक्तिबद्ध रूप से भगवान बुद्ध और बौद्धसत्त्व की आकर्षक प्रतिमाएं भी देख सकते हैं। जो भगवान बौद्ध के परम उपासक माने जाते थे। इसके साथ ही इसमें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पूजा किए जाने वाले चक्रीय स्तूप भी निर्मित है। जिसे चौत्य भवन भी कहा जाता था। इससे आगे जाने पर कक्ष क्रमांक तीन की गुफा आती है। इसे हाथीखाना भी कहा जाता है। यह गुफा भी क्रमांक 2 वाली गुफा के समान ही बौद्ध मठवासियों के निवास करने का स्थान ही प्रतीत होती है। जिसमें बौद्धकाल की सुंदर वास्तुकला से सज्जित बरामदे, प्रवेश द्वार और खंभे देखे जा सकते हैं। इस गुफा के दक्षिण-पूर्वी स्थान पर हम एक धार्मिक कक्ष भी देख सकते हैं। जिसमें भगवान बुद्ध का दीवार पर एक भित्ति चित्र का चित्रण था। जिसमें उनके अनुयाई उनको श्रद्धा पूर्वक नमन कर रहे हैं। इस कारण इसे बौद्ध पूजा स्थल का दर्जा भी दिया गया है। इस गुफा में कई प्रकार के आकर्षक भित्ति चित्र स्थापित थे। जिसमें बौद्धसत्त्व पदमिनी के चित्र को अजंता में स्थित गुफाओं की चित्रकला के रूप में एक आदर्श प्रतिमान के रूप में भी जाना जाता है। इसके आगे चलने पर गुफा क्रमांक 4 है। जिसे रंगमहल कहा जाता है। इस गुफा में कई प्रकार के आकर्षक भित्ति चित्र स्थापित हैं। इसमें बौद्धसत्त्व पदमिनी के चित्र को अजंता में स्थित गुफाओं की चित्रकला के रूप में एक आदर्श प्रतिमान के रूप में भी जाना जाता है।

इसके बाद गुफा क्रमांक पांच दिखाई देती है जो कि गुफा क्रमांक 4 से सीधे जुड़ी हुई है। इतिहासकारों के अनुसार इसमें बौद्ध उपासकों का प्रार्थना स्थल स्थित था। यह एक समकोणीय कक्ष है। जिसमें अलग अलग पंक्तियों में खंभे स्थित हैं। आगे चलने पर हम कक्ष क्रमांक 6 देख सकते हैं। जिसके अंदर जाने पर हमें छोटे-छोटे छह छोटे कक्ष मिलते हैं। जो सम्भवतः बौद्ध साधकों का साधना के स्थल हुए करते थे। इस गुफा की अग्रिम दीवार के सामने एक द्वार और दो खिड़कियां दिखाई देती हैं। जिससे बाहरी प्राकृतिक परिदृश्य भी देखे जा सकते हैं। इसमें छतर्वीं सदी के फूल पत्ति और बेलबूटों की अद्भुत संरचना भी देखी जा सकती थी। इन प्राकृतिक गुफाओं में प्राकृतिक हलचल, चट्टानों के दरकने और बारिश के प्रभाव से बाघ गुफा क्रमांक 4 में कई भित्ति चित्रों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा है। जिसके कारण ग्वालियर स्थित म्यूजियम में यहां की नष्टवान चित्रकला को पर्यटकों के लिए बहुत समय सन 1982 में ही संरक्षित कर लिया गया था। धार जिले

की बाघ गुफा में प्रमुख रूप से बौद्धकाल की बौद्धसत्त्व, मशरूम, पद्मपानी, जातक, फूल, पत्तियों की पंखुड़ियों की आकृति, हाथी, घोड़े, गाय आदि के सुंदर भित्ति चित्र रूपी म्यूरल्स एक अनमोल चित्रकला के प्रतिमान हैं। ब्रिटिश पुरातत्वशास्त्री इलियट के अनुसार बाघ गुफा क्रमांक 4 में भी हम बौद्ध भगवान के अनुयायियों की एक आकर्षक भित्ति चित्र रूपी वॉल पेंटिंग थी। जिसमें बौद्ध के उपासक श्रद्धापूर्वक झुक कर भगवान बुद्ध को कमल पुष्प समर्पित कर रहे हैं तो वहीं कुछ उनके अनुयायी चित्रण में हवन सामग्री पकड़े हुए दिखाई देते हैं। जो कि प्राचीन महायान परंपरा की एक अनमोल कड़ी भी मानी जाती है।

बाघ की गुफाओं के सन्दर्भ में ब्रिटिश पुरातत्वशास्त्री डॉक्टर इम्पी के अनुसार बाघ गुफा क्रमांक 4 रंगमहल में दक्षिणी छोर पर स्थित भित्तिचित्र चित्रकला के बहुत ही सुंदर परिदृश्य देखने को मिलते हैं। जिसे उन्होंने विभिन्न प्लेट्स में विभाजित किया है। हालांकि उनका ये डॉक्यूमेंटेशन आजादी के पूर्व का है और वर्तमान में इन बाघ गुफाओं में प्राकृतिक रूप से नुकसान हुआ है और कई भित्ति चित्रों को सन 1982 में आर्किओलॉजिकल म्यूजियम ग्वालियर द्वारा सावधानीपूर्वक निकालकर ग्वालियर स्थित म्यूजियम में संरक्षित कर लिया था।

ब्रिटिश पुरातत्वशास्त्री डॉक्टर इम्पी ने ब्रिटिशकाल के समय धार जिले में स्थित बाघ की गुफाओं को विभिन्न प्लेट्स में विभाजित कर अपना डिस्कप्शन दिया था। ब्रिटिश पुरातत्वशास्त्री डॉक्टर इम्पी के अनुसार बाघ गुफा क्रमांक 4 में स्थित प्रारंभ की प्लेट ए में म्यूरल्स को बहुत ही अनमोल ढंग से चित्रित किया गया। जिसमें दो महिलाएं सुन्दर वस्त्रों को पहने हुए हैं और एक मंडप में बैठी हुई है। एक महिला ने दुःख भरी मुद्रा धारण की हुई है। वहीं द्वितीय प्लेट ब में चित्रित भित्ति चित्र में चार संभ्रात जन किसी विषय को लेकर संवाद करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जिनके हाथ और चेहरे कि मुद्रा भी इसी भाव में दिखाई दे रही है। यह सभी लोग एक गोल घेरे में आल्की-पालकी मारकर गोल, नीले और सफेद तकिये पर बैठे हुए हैं और धोती के अतिरिक्त अन्य कुछ भी धारण नहीं किया हुआ है। भित्तिचित्र में प्रदर्शित इन लोगों ने अपनी पदवी के अनुसार बहुमूल्य वस्त्र और रत्नों को भी धारण किए हुए थे।

तीसरी प्लेट सी के भित्तिचित्रों में मनुष्यों के दो पृथक समूह एक दूसरे के ऊपर नीचे दिखाई पड़ते हैं। इसमें ऊपर के समूह में पांच पुरुष ऊपर कि ओर उड़ते दिखाई देते हैं। जिसमें चौथा पुरुष बादलों की तरफ जा रहा है और एक प्रधान की भांति अपने समूह को निर्देशित करता हुआ दिख रहा है।

प्लेट सी में संगीतज्ञ महिलाओं के दो समूहों को पृथक रूप से भित्ति चित्र में चित्रित किया गया है। इनमें दाहिने ओर में सात महिलाएं, एक महिला के आसपास घेरा बनाये हुए दिखाई देती हैं। जो एक नर्तकी हैं और एक विशेष वस्त्र को धारण किये हुए हैं। जिसमें लंबी बांह वाला सफेद वस्त्र और हरे रंग का कुर्ता भी दिखाई देता है। इसके साथ ही उसने नीले रंग के बहुमूल्य रत्न के आभूषण भी धारण किये हुए हैं। इस महिला समूह के भित्ति चित्र में महिलाएं कई आकर्षक वाद्य यंत्रों जैसे नगाड़ा, मृदंग, मंजीरा, डंडी आदि को बजाते हुए चित्रण में प्रतीत होती हैं। पुरातत्वशास्त्रियों के अनुसार इस प्रकार के चित्रण के आभूषण न केवल सांची में देखे जा सकते हैं बल्कि ये अजंता गुफा के भित्ति चित्रों में भी देखा जा सकता है। इन प्लेट्स के अतिरिक्त ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री डॉक्टर इम्पी ने बाघ गुफा की म्यूरल्स वाल पेंटिंगों में चित्रित एक परिदृश्य दर्शाया है। जिसमें एक आम के झाड़ के नीचे एक धर्म-चक्र दिखाई दे रहा है और यहां बुद्ध भगवान की साधना करती हुई आकृति दिखाई

दे रही है। जो कि उनके शिष्यों को धार्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

**समस्याएं** – वर्तमान में यह स्थान मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर से करीब 150 किलोमीटर दूर है। इंदौर में रेल सुविधा है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए इस पहाड़ी वाले क्षेत्र में रेल सुविधाओं का अभाव है। आदिवासी अंचल के इस स्थान पर पहुंचने के लिए स्थानीय परिवहन व्यवस्था भी नहीं है। ऐसे में पर्यटकों को अपने खुद के द्वारा किराए से लिए गए वाहन से ही पहुंचना होता है। परिणाम स्वरूप एक ऐसा वर्ग है जो कि पर्यटन में रुचि रखता है। लेकिन आर्थिक रूप से बहुत अधिक खर्च नहीं कर सकता है, उसकी पहुंच से यह पर्यटन क्षेत्र बाहर हो जाता है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इस ऐतिहासिक स्थान को बहुत ही आकर्षक रूप से सुरक्षित किया गया है। वहां पर पर्यटकों की आवाजाही कम होने के कारण स्थानीय स्तर पर गाइड का अभाव है। यदि गाइड की सुविधा उपलब्ध होती है तो पर्यटकों को उसकी महत्ता भी समझ में आएगी।

**सुझाव** – बाघ गुफाएं बुद्ध सर्किट के रूप में पर्यटक केंद्र बन सकती हैं :

1. धार जिले में स्थित बाघ गुफाएं भी महाराष्ट्र के अजंता गुफाओं के समान ही पूरे विश्व के लिए बुद्धिज्म का एक बड़ा पर्यटन केंद्र बन सकती हैं। जिससे सांची आने वाले बौद्ध धर्म के लोग विशेषकर जापान, चीन, थाईलैंड, कम्बोडिया, कोरिया, श्रीलंका आदि देशों के पर्यटक बाघ गुफाओं की बौद्ध काल की कला और संस्कृति को निहारने इस स्थान पर आ सकते हैं। इससे यहां के सुदूर क्षेत्र में बसे ग्रामीण अंचल

के लोगों को भी रोजगार का साधन इसी क्षेत्र में प्राप्त हो सकता है।

2. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से यहां लाइट एंड साउंड शो का भी संचालन भी किया जा सकता है। जिससे यहां की वॉल पेंटिंग्स और प्रतिमाओं के साथ ही बौद्ध साधकों के साधना मठों के विषय में भी पर्यटकों को जानकारी प्राप्त हो सकती है।
3. इसके साथ ही यह स्थल बौद्ध धर्म का एक विश्वविख्यात प्रतिमान अजंता की गुफाओं से भी पूर्व के समय से रहा है। इसलिए बाघ गुफाओं का भी डोजियर बनाकर यूनेस्को को भेजकर इसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में बनाया जा सकता है। जिससे देश-विदेश के पर्यटक इन्हें निहारने के लिए अत्यधिक संख्या में यहां आ सकते हैं।
4. इन सब में यहां पर यातायात के साधन की बड़ी आवश्यकता है। रेल मार्ग से इसकी दूरी 150 किलो मीटर है। धार जिला मुख्यालय से 90 किलो मीटर दूर इस स्थान पर पर्यटन विभाग या जिला प्रशासन के माध्यम से वाहनों यानी लोकल परिवहन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
5. यह स्थान बाघ गुफा और बाघ चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां की एक हस्तशिल्प कला दुनिया भर में महत्वपूर्ण है। इस तरह से इन दोनों को संयोजित किया जाता है तो और भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. धार की प्राचीन गजेटियर ।
2. भोज शोध संस्थान लाइब्रेरी पुस्तक संग्रह ।













## महामारी प्लेग का भारतीय जन-मानस पर प्रभाव

डॉ. वन्दना अग्रिहोत्री \*

**प्रस्तावना** - वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है। विश्व के अधिकांश देशों को इसने अपनी चपेट में ले रखा है। इसके पूर्व भी हमारे देश में प्राचीनकाल से अनेक महामारियों का संक्रमण होता रहा। जिसमें न जाने कितनी जाने गई। प्लेग, हैजा, चेचक, आदि।

प्लेग की महामारी 1896 में शुरू हुई और 1930 तक आते-आते एक करोड़ बीस लाख लोगों की जाने इसमें चली गई। भयानक रूप से फैली इस महामारी के राजनीतिक और सामाजिक परिणामों पर बहुत प्रभाव पड़ा, साथ ही समाज और संस्कृति पर भी इसका व्यापक प्रभाव दिखाई दिया। 'भारत में प्लेग से अगस्त 1896 में बम्बई में पहली मौत हुई और तीन-चार वर्ष में यह रोग भारतीय समाज के हर सूबे में पहुँच गया।' <sup>1</sup> आरम्भिक वर्षों में इसकी पुष्टि नगरों व शहरों में केन्द्रित गहन प्लेग अभियानों से हुई, इसके रोकथाम के उपायों का भी प्रतिरोध किया गया 'शुरुआती दशकों में यह भी कहा गया कि अधिकतर टीका-करण का महत्तर विरोध देहातो की अपेक्षा शहरो में हुआ।' <sup>2</sup> प्रशासनिक झिझक और चिकित्सा के अनिश्चय की छोटी अवधि के बाद भारत सरकार की शह पर बम्बई की प्रान्तीय सरकार ने कुछ कठोर कदम उठाये।

बम्बई नगर पालिका ने एक कानून पास किया जिसके अन्तर्गत छूतग्रस्त सम्पत्ति को नष्ट करने की योजना को मंजूरी दी गई। चार महिने बाद महामारी रोग कानून ने सरकार को यह अधिकार दिया कि वह ताउन (प्लेग) के संदिग्ध मरीजों को कैद और अलग-अलग कर सके, छूतग्रस्त सम्पत्ति को नष्ट कर सके, प्लेग की शंकावाले मकानों की जाँच पड़ताल कर सके, उन्हें तोड़ सके, मेलो और तीर्थ यात्राओं पर रोक लगा सके। सड़क और रेलयात्रियों की जाँच करा सके। 'संक्षेप में वह सब कुछ कर सके जो चिकित्सको और अधिकारियों की राय में रोग को खत्म करने के लिए आवश्यक था।' <sup>3</sup> बम्बई, पूणे, कराची कलकत्ता जैसे शहरों में स्वास्थ्य और सफाई की जिम्मेदारी नगर-परिषदों से लेकर यूरोपीय डाक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों की छोटी-छोटी समितियों को सौंप दी गई थी।

'बम्बई के नगर आयुक्त द्वारा 6 अक्टूबर 1896 को जारी की गई घोषणा में कहा गया कि ताऊन के सारे मरीज हस्पतालों में भरती किए जाएँ, और जरूरत हो तो इसके लिए बल का भी इस्तेमाल भी किया जाए। यह नहीं बतलाया गया कि रिश्तेदारों को मरीजों से मिलने की इजाजत दी जाएगी, न ही यह कि हस्पताल व्यवस्था में जात-पाँत का सम्मान किया जाएगा।' <sup>4</sup>

यह ऐसा आक्रामक रोग था जिस पर नियन्त्रण नहीं किया गया तो यह वाणिज्य और उद्योग के लिए खतरा तो था ही भारतीय व्यापार पर यूरोप का प्रतिबन्ध लग सकता था।

चिकित्सा सिद्धान्त व्यवहार और अस्पताल में भर्ती करने की जो नीति

थी उसके प्रति आम-जनता में घृणा का भाव था। 18 अक्टूबर 1898 को बम्बई के एक पत्र गुजराती ने लिखा 'सही या गलत, के खिलाफ देशज समुदाय की भावनाएँ बहुत प्रबल हैं। सामाजिक रीति-रिवाज, धाखमक भावनाएँ और स्नेह के मजबूत बन्धन सभी तो इसके खिलाफ हैं। किसी के अपने स्नेही बन्धु-बान्धवों से अलग कर दिए जाने और सामान्य धाखमक संस्कार किए बिना ही दुनियाँ से कूच कर जाने का विचार ही देशी जनमानस को कष्ट पहुँचाता है।' <sup>5</sup> जनता का यही विचार समाचार पत्रों के सम्पादकीय लेखों, सम्पादक के नाम पत्रवाले स्तम्भों और प्रार्थना पत्रों में व्यक्त किया गया। पश्चिमी इलाज और प्रशासन के कार्यों की उदासीनता से भारतीय जीवन-मूल्यों और भावनाओं को ठेस पहुँच रही थी।

अस्पतालों में परिवार के व्यक्तियों, रिश्तेदारों के अलावा अन्य अजनबी लोगों के द्वारा देखभाल करना जनमानस स्वीकार नहीं कर पा रहा था। क्योंकि अस्पताल खून-मल-मूत्र से दूषित, अशुद्ध, धर्म और पर्दे के लिए विनाशकारी स्थान था। छुआछूत का इतना डर था कि अस्पताल में मरीज कई-कई दिन सिर्फ दूध पीकर निकाल देते थे किसी अन्य के हाँथ का खाते नहीं थे। <sup>6</sup> अप्रैल 1897 में केसरी ने धर्मविरोध के लिए और 23 मई 1897 को, मराठा ने जात-पाँत के नियमों के उल्लंघन के बार में लिखा। <sup>6</sup>

जनता के विरोध की शक्ति को जब सरकार ने महसूस किया तब बम्बई और बाद में बड़े शहरों में विशेष अस्पतालों की स्थापना करके आपत्तियों और भय को दूर करने की कोषिष की। स्त्रियों को अस्पताल में भर्ती करने का तीव्र विरोध हुआ।

भारतीय प्लेग की बीमारी को ईश्वरीय प्रकोप समझते थे, और मानते थे कि इस विपत्ति में पश्चिमी दवाओं का प्रयोग विधर्मी होगा इसलिए वे पश्चिमी दवाओं का विरोध कर रहे थे। अस्पताल की असफलता के बाद कुछ लोगों ने इलाज के लिए आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति का सहारा लिया। सबने रोग के अलग-अलग कारण बताये किसी ने तामसी भोजन, किसी ने नम बिस्तर, न जाने क्या-क्या प्लेग से पीड़ित शहरों और कस्बों से आए यात्रियों की जाँच पड़ताल विशेषकर स्त्रियों की, लोगों के विरोध का कारण थी। जब हिन्दुस्तानियों की संवेदनाएँ उग्र होकर सामने आई तब पर्दों का इंतजाम किया गया और महिला डाक्टरों की व्यवस्था की गई। सड़कों पर सरे आम जाँच-पड़ताल और घरों की तलाशी से जनता का गुस्सा फूट पड़ता था। मुरादाबाद के निजामुल्क ने 16 अप्रैल 1900 को लिखा 'रेल्वे स्टेशन पर ताऊन के डाक्टरों को देखने भर से मुसाफिरो का खून खौल जाता था।' <sup>7</sup> उनके शरीर के अंगों को बेरहमी से टटोला जाना, उन पर पशुवत बर्ताव करना व प्लेग विरोधी उपायों को लागू करना जनता को पसंद नहीं आ रहा था।

प्लेग की महामारी में लाशों की जाँच-पड़ताल पर भी जोर दिया जा रहा था 'मरीज की लाश छूत का केन्द्र होती है। खासतौर पर तब जब मरीज हस्पताल के बाहर मरा हो। मतलब यह था कि तमाम धार्मिक कृत्यों और अनुष्ठानों पर जहाँ तक सम्भव हो, रोक लगाई जानी चाहिए।'<sup>8</sup> शव परीक्षण की इस नीति से भी भारतीयों में भारी क्षोभ पैदा हो रहा था। जब तक जाँच से यह न पता चले कि वह प्लेग से तो नहीं मरा उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता था इसमें बहुत देरी हो रही थी अतः इनकी आलोचना और विरोध होता रहा।

'प्लेग के मरीज को तलाषी से बचाने के लिए किसी सुरक्षित क्षेत्र में भेज दिया जाता था या फिर अटारियों, अलमारियों, फर्नीचर के पीछे या गुप्त कमरों में छिपा दिया जाता था प्लेग से मरने वालों को कभी-कभी तो घर या अहाते के अन्दर भी दफन कर दिया जाता था।'<sup>9</sup>

भारतीय जनता में प्लेग विरोधी उपायों के विरोध का कारण यह भी था कि उन्हें अपनी सम्पत्ति के नष्ट होने की चिंता भी थी साथ ही गरीबों को अस्पताल में भर्ती कर उसको सबसे अलग-थलग करने से वह वर्ग मजदूरी और रोजगार से भी हाथ धो रहा था। व्यापारी अपनी आवाजाही और अन्न भण्डारों पर लगी रोक, सम्पत्ति की तबाही से अप्रसन्न थे। किन्तु मुख्यतः शरीर पर होने वाले वास्तविक या काल्पनिक अतिक्रमण आम जनता के भय का कारण थे और यही छुपाने-छुपाने और विरोध का आधार भी था। पाश्चात्य चिकित्सा, टीको और अस्पतालों के प्रति जनता में डर बैठ गया था।

भारतीय संस्कृति में प्लेग से जुड़ी अनेक अफवाहों में सबसे प्रमुख उनकी धार्मिकता थी उनका मानना था कि सरकार का इरादा जनता के धर्म और जाति में दखलंदाजी करना था, उनकी जाति और उनके धार्मिक रीति-रिवाजों को नष्ट करता है।

भारतीय लोक संस्कृति में अनेक प्रकार की अफवाहें फैली थी कि अस्पताल के कर्मचारी, डाक्टर व अन्य सरकारी माध्यमों द्वारा लोगों को जहर दिया जा रहा है। 21 फरवरी 1897 को पूना वैभार की रिपोर्ट में लिखा था- 'कुछ गाँवों में लोग यह मानने लगे हैं कि सरकार अपनी प्रजा को वष से बाहर समझ कर उसकी तादाद कम करने के उपाय ढूँढ़ रही है। वे अकाल षिविरों में दी जानेवाली रोटीयाँ भी लेने में हिचकते हैं कि कहीं रोटीयों में जहर न मिलाया गया हो।'<sup>10</sup>

भारतीय जनता की यह सोच थी कि अस्पताल में भर्ती कर के फिर शरीर की चीरफाड़ करने के लिए डॉक्टर उन्हें मार देगे वे अस्पताल को शैतानी स्थान मानते थे। अपने बचाव के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान भागने लगे थे। लोगों ने अस्पताल के सामने वाली सड़कों से निकलना बंद कर दिया था। बम्बई से हजारों मिल मजदूर इसी डर से भाग गए थे। 14 मार्च 1897 को गुजरात मित्र ने लिखा कि 'सूरत जिले के उड़वाड कस्बे के अनपढ़ दुबाले (दुबले, एक आदिवासी समुदाय) इस विश्वास से ग्रस्त थे कि ताऊन के स्थानीय पृथक्करण वाई में मरीजों का ज़िगर, निकालकर ताऊन से हिफाजत के लिए बम्बई भेजा जा रहा था।'<sup>11</sup> कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी उन्हें मनमाने ढंग से लूटने के लिए जबरन अस्पताल का डर दिखा रहे हैं जबकि उन्हें कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं।

प्लेग की रोकथाम के लिए सन् 1897-98 में हैफकिन टीका इस्तेमाल किया जाने लगा तब उसकी प्रकृति उद्देश्य और प्रभावों के बारे में भी अनेक अफवाहें फैली- 'आपरेशन के फौरन बाद मर जाओगे, छः माह बाद राम नाम सत हो जाओगे, मर्दों की मर्दानगी चली जाती है या औरते बाँझ हो

जाती है।'<sup>12</sup> 'चारों ओर गहरी उत्तोजना थी कि क्या प्लेग के कारण उनके घरों में जबरन घुस पैठ होगी उनकी बीबी-बेटियों को ब्रिटिश सैनिक ले जायेंगे, प्लेग-निरोध वाकई किया जायेगा। क्या सबको जबरन टीके लगाये जायेंगे।'<sup>13</sup>

जनता के मन में पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति पर अनेक आशंकाएँ थीं। अस्पतालों, शल्यक्रिया, शव परीक्षा तथा टीका आदि ने भय और विरोध को जन्म दिया। लेकिन कुछ समय पश्चात् जब चिकित्सा के बारे में अधिक जानकारी मिली, प्रशासन का बल-प्रयोग कुछ कम हुआ तब अस्पताल व टीके का डर कुछ कम हुआ। लोक विमर्श तो ये भी था कि अंग्रेजों का साथ देनेवाले भारतीय भी उनके साथ हैं। प्लेग सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाकर शिवाजी और गणपति उत्सव बन्द कर दिए गए। महामारी कानून के अन्तर्गत नगर परिषद् को अनदेखा कर ब्रिटिश अधिकारी रैंड ने असामान्य शक्तियों के साथ तीन सदस्यों की एक समिति बनाई। ये ऐसे अलोकप्रिय कार्य थे जिसे करने के लिए कोई भी मध्यवर्गीय भारतीय आगे नहीं आना चाहता था इसलिये सफाई का कार्य यूरोपिय नियन्त्रण में था उन्हें डर था कि कहीं उनकी उपलब्धियाँ भारतीयों के निकम्मेपन से समाप्त न हो जाये।

गहन सुरक्षा के बावजूद भी महामारी चारों ओर फैल रही थी और प्लेग विरोधी कार्यों की अलोकप्रियता उनका प्रतिरोध तथा जनता के निष्चय के प्रमाण सामने आ रहे थे। 'प्रमुख नागरिकों, नगर पार्षदों, तथा जातियों व धर्मों के अगुवों के प्रतिनिधिमंडलों ने सरकार से भारतीय भावनाओं व प्रथाओं के प्रति और अधिक संवेदनशीलता दिखाने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि अगर उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई तो और अधिक विरोध और खून खराबा सम्भव है।'<sup>14</sup> जनता का असन्तोष और उथल-पुथल सरकार के लिए महामारी से भी गम्भीर समस्या बन रही थी। पुलिस और चिकित्सा विभाग के अधीनस्थों कर्मचारियों के द्वारा लोगों को परेशान करने के अनेक अवसर पैदा हो रहे थे। जिसका जनता द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था।

नागरिक प्रशासन और प्रमुख चिकित्सा सलाहकारों को भी सन्देह था कि प्लेग का शीघ्रता से कोई इलाज मिल सकता है। रोग पर धीरे-धीरे ही काबू पाया जा सकता है इसके लिए बल प्रयोग की बजाय सहयोग की आवश्यकता थी। भारत सरकार ने 1898-99 में जनता के प्रतिरोध, राजनीतिक प्राथमिकताओं और प्रशासनिक सीमाओं के पुर्न मूल्यांकन के पश्चात् महामारी की नीति में अनेक समझौते किए और रियायते की। प्रशासन ने माना कि बलप्रयोग हानिकारक हो सकता है इससे लोग उनसे छिपेगे और विरोध भी करेंगे इसके कारण चिकित्सा के उपाय बेकार हो जायेंगे। तदनुसार शासन ने अपेक्षाकृत अधिक बल आधारित प्रयोग अलोकप्रिय पक्षों, जैसे घरों और शरीर की जाँच पड़ताल, अनिवार्य पृथकरण, अस्पताल में भर्ती, शव-परीक्षण और सेना के प्रयोग आदि को या तो त्याग दिया था उनमें भारी बदलाव किया गया। ऐसे उपायों को आगे बढ़ाया जाये। जिनको जनता स्वेच्छा से अपनाने को तैयार थी। तिरस्कृत वैधों और हकीमों आदि पर भी भरोसा किया गया। गाँवों को अस्थायी रूप से खाली करवाने में भी कुछ सफलता मिली। घरों की इस तरह सफाई करवाई गई जो पाश्चात्य चिकित्सा के बजाय परम्परागत भारतीय विचार के अनुकूल हो टीकाकरण की अनिवार्यता से जोरदार इनकार करते हुए भी डाक्टरों और प्रशासकों ने जनता को स्वेच्छा से टीके लगवाने के लिए तैयार करने की हर कोशिश की। खासकर पंजाब में 20 वीं सदी के पहले दशक तक हर साल हजारों लोग टीके लगवा रहे थे।'<sup>15</sup> ऐसे गणमान्य नागरिकों पर अधिक भरोसा किया

जाने लगा जो अपने प्रभाव से लोगों को प्लेग के बचाव के उपायो को स्वीकार करा सके। अब तलाशी दस्ते के बजाय ऐसे लोगों की सहायता ली जो मोहल्लों में अपना प्रभाव रखते थे और जो जनता को रोकथाम व इलाज के लिए प्रोत्साहित करें। इस नए दृष्टिकोण के कारण जनता में भी परिवर्तन आया। महामारी के दूसरे दौर में अधिक विरोध नहीं देखा गया।

औपनिवेशिक राजसत्ता और भारतीय मध्यवर्ग के बीच तालमेल की सम्भावना हुई। अंग्रेज कॉफी हड़ तक भारतीय मध्यवर्ग के इस दावे को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए कि देशी नेताओं के रूप में इन वर्गों की मध्यस्थता का सहारा लेकर ही वे जनता के शरीर तक कारगर दंग से पहुँच सकते हैं। जनता पर प्रभाव रखने वाले राजाओं, जमींदारों अधिकारियों व अन्य नेताओं की सहायता और प्रभाव का उपयोग वैक्सीन के प्रयोग के लिये करना उनकी कार्यनीतियों का हिस्सा था।

प्लेग की महामारी के समय जनता के विचारों और प्रतिक्रियाओं में अपमान, भय और क्रोध के भाव पाये जाते थे। समाचार पत्र भी प्रेस कानून के कारण दंगाइयों और प्रतिरोधियों के प्रति अधिक सहानुभूति नहीं दिखा सकते थे। महामारी के पूर्व वर्ष बल-प्रयोग और सहयोग, प्रतिरोध और वर्चस्व, वर्ग और नस्ल के बीच जटिल घात-प्रतिघात का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस समय औपनिवेशिक राज्यसत्ता की शक्ति तथा पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र के दर्शन हुए। भारतीय प्रतिक्रिया के कारण आरोग्य सम्बन्धी मुद्दों पर सामंजस्य की नीति अपनाई गई जिसका उद्देश्य मध्यवर्ग की सहायता और सहयोग पाना था। सहमति के साथ बल-प्रयोग कम किया गया। इसमें निम्नवर्गीय प्रतिरोध की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी समय शासक और शासित के बीच महत्वपूर्ण जातियें और राजनीतिक रवाई पैदा हुई वही भारतीय मध्यवर्ग का वर्चस्व मुखर होकर सामने आया। पूर्व में शहरों और ग्रामों का निम्नवर्ग, मध्यवर्ग को अंग्रेजों का सहयोगी मानकर सन्देह की दृष्टि से

देखता था किन्तु दीर्घकालिय परिप्रेक्ष्य में मध्यवर्ग के, उच्चवर्ग के रहन-सहन और तौर-तरीकों के अनुसरण ने पाश्चात्य चिकित्सा के सन्देह को मिटाने, अस्पतालों में भर्ती होने, तथा टीकाकरण के प्रति स्वीकृति को देने के लिये जनता को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. 4.5 देह पर दस्तदराजी प्लेग के परिप्रेक्ष्य में डोविन आर्नल्ड प्र. 34,36,38,40।
2. रिटर्न आफ वैक्सीनेशन फार दि नार्थ वेस्टर्न (इलाहबाद 1893) प्र. 29,30।
3. एकाउंट आफ दि प्लेग एडमिनिस्ट्रेशन इन दि बाम्बे सिन 1896 एम.ई. कोड मैन।
4. गुजराती - 18 अप्रैल 1897
5. कांक्वेस्ट आफ प्लेग हल्ट ..... प्र. 115,21
6. बंगाल म्यूनिसिपल (मेडिकल) 89 फरवरी 1897 कलकत्ता।
7. साप्लीमेंट टू दि एकाउण्ट आफ प्लेश एडमिनिस्ट्रेशन प्र. 7, 179,80 बाम्बे प्लेग कमेटी प्र.56
8. लाइफ इन दि इंडियन सिविल सर्विस (लंदन 1926) ई. मौकोनोशी प्र. 83
9. रिपोर्ट आन दि प्लेब इन दिपंजाव विल किंसन ..... प्र. 28
10. रिपोर्ट आन प्लेग इन कैलकटा कुक ..... प्र.10
11. महस्टा - 4 अप्रैल 1897 मुस्लिम हेराल्ड, 24 मार्च 1897 बंगाल म्यूनिसिपल (मेडिकल) 88 फरवरी 1898
12. रिपोर्ट आन प्लेग एंड इनोक्यूलेशन इन पंजबा फ्रम अक्टूबर 1902 टू सेप्टेम्बर 1903 (लाहौर 1904) ई. विलकिंसन प्र. 48,60।

\*\*\*\*\*

## किशोर/किशोरियों के व्यवहार तथा समायोजन पर किये गये विभिन्न शोध – एक अध्ययन

नीतू छिनीवाल\* डॉ. दिव्या दुबे\*\*

**शोध सारांश** – प्रस्तुत समीक्षा साहित्य में कार्यशील गृहणी माताओं के किशोर बच्चों के व्यवहार तथा समायोजन का अध्ययन रूप किशोर के व्यवहार से सम्बन्धित जैसे तनाव, व्यक्तित्व अवसाद, चिन्ता, शैक्षणिक उपलब्धि, समायोजन से सम्बन्धित पूर्व में जितने भी शोध हुए हैं, का अध्ययन किया गया इसके अतिरिक्त कार्यशील व गृहणी माताओं के बच्चों की भावनात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सांवेगिक परिपक्वता उनकी उपलब्धि प्रेरणा पर शोध हुआ। सभी शोधार्थियों के अध्ययन करने का तरीका अलग-अलग था, अतः सभी शोधार्थियों के शोध का विषय तथा निष्कर्ष भी भिन्न थे।

**शब्द कुंजी** – कार्यशील महिला, गृहणी महिला, किशोर, किशोरी समायोजन, व्यवहार।

**प्रस्तावना** – मानव जीवन में किशोरावस्था सर्वाधिक विचलन वाली अवस्था है, इसी अवस्था को बाल्यवस्था की समाप्ति तथा युवावस्था का प्रारंभिक काल माना जाता है यही अवस्था होती है जब बालक अपने बारे में विचार करने लगता है, सही गलत का निर्णय लेने में खुद को सक्षम समझने लगता है और यही विचार उसे परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने में बाधा डालता है, क्योंकि तब वह वास्तव में निर्णय लेने के लायक नहीं होता है, यहीं परिस्थितियों बालकों में कुसमायोजन, तनाव, कुण्ठा का कारण बनता है। ऐसी परिस्थितियों में बालक का परिवार ही उसे सही मार्ग दिखा सकता है चूंकि माँ बालक की प्रथम पाठशाला होती है अतः इसका दायित्व माँ पर अधिक होता है। आज के विकसित, और तकनीकी युग में महिलाएँ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं वह अपनी गृहस्थी के साथ-साथ परिवार की आय बढ़ाने का जरिया भी बनती हैं तथा वही कुछ महिलाएँ अपने बच्चों का बराबर मार्गदर्शन करती हैं गृहणी माताएँ घर में रहने के कारण बच्चों की आवश्यकता हर समय पूरा करती रहती हैं। फलस्वरूप उनके बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बन पाते, उसके विपरीत कामकाजी महिलाएँ घर एवं बाहर दोनों स्थानों पर समायोजन करने का भरपूर प्रयास करती हैं, परन्तु कभी-कभी इसमें असफल भी हो जाती है, इसका सर्वाधिक प्रभाव उनकी संतानों पर पड़ता है कुछ कार्यशील, महिलाएँ जो सामंजस्य स्थापित करने में सफल हो जाती हैं, उनके बच्चे छोटा कार्य स्वयं करने लगते हैं, तथा वह अपेक्षाकृत जल्दी आत्मनिर्भर बन जाते हैं तथा हर परिस्थिति में स्वयं को समायोजित कर लेते हैं।

**खान, महमूद अहमद (2017)** – के शोध का शीर्षक 'कामकाजी व गैर कामकाजी माताओं के किशोरों का समायोजन का अध्ययन' था।

अध्ययन के लिए शोधकर्ता ने बडगाम तथा श्रीनगर जिले के विद्यालयों में से 800 बच्चों का समूह लिया जिसमें 400 किशोर कामकाजी माता के तथा 400 किशोर गैर कामकाजी माता के शामिल थे अध्ययन के डेटा संग्रहण के लिए इन्होंने कादरी द्वारा उर्दू में अनुवादित बेल्स एडजस्टमेंट इन्वेन्टरी को नियोजित किया।

अपने अध्ययन के निष्कर्ष में इन्होंने पाया कि कामकाजी व गैर

कामकाजी माताओं के किशोरों के समायोजन में बहुत अंतर था। कामकाजी माताओं के बच्चों के तुलना में गैर कामकाजी माताओं के बच्चों के पास बेहतर सामाजिक, भावनात्मक व घर का समायोजन है तथा अध्ययन के आगे उन्होंने बताया कि समायोजन के समग्र स्कोर पर कामकाजी व गैर कामकाजी माताओं के बच्चों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है।

**चतुर्वेदी, प्रकृति; शर्मा, सविता (2017)** – के अध्ययन का शीर्षक 'भोपाल शहर की कामकाजी व गैर कामकाजी महिलाओं के बच्चों के समायोजन का अध्ययन' था। इस अध्ययन हेतु शोधार्थी ने भोपाल शहर के 5 विद्यालयों से 60 विद्यार्थियों को चुना जिसमें 30 कामकाजी तथा 30 गैर कामकाजी महिलाओं के बच्चों का समूह था। आकड़ों के संकलन के लिए ए.के. सिंह का समायोजन मापनी का प्रयोग किया गया।

अध्ययन के निष्कर्ष में शोधार्थी ने पाया कि कामकाजी व गैर कामकाजी महिलाओं की बालिकाओं के समायोजन में सार्थक अन्तर होता है तथा बच्चों में सार्थक अंतर होता है इससे यह परिणाम प्राप्त होता है कि कामकाजी महिलाओं के बच्चे समय से पूर्व समझदार, गंभीर हो जाते हैं तथा बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा अधिक समायोजन का गुण होता है।

**अग्रवाल, श्वेता (2017)** – शोधार्थी ने 'स्कूली बच्चों के साथ व्यवहार सम्बंधी समस्याओं पर कामकाजी तथा गैर कामकाजी माताओं तथा उनके बच्चों के स्वभाव की मूल शैली के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया।'।

अध्ययन के नमूने के लिए 400 बालक बालिकाएँ (उम्र 10 - 15 वर्ष) लिए गए जिसमें 200 बालक बालिकाएँ कामकाजी तथा 200 बालक बालिकाएँ गैर कामकाजी माताओं के थे। डाटा संग्रहण के लिए बच्चों को पेरिटिंग स्टाइल प्रश्नावली और द अर्ली एडोलसेंस टेम्परेमेंट प्रश्नावली माताओं को उनकी पेरिटिंग शैली तथा बच्चों के स्वभाव का आकलन करने को दी गयी।

अध्ययन के शोध का निष्कर्ष यह था कि कामकाजी व गैर कामकाजी माताओं के बच्चों में व्यवहार सम्बंधी समस्याएँ होती हैं लेकिन गैर कामकाजी माताओं के बच्चों में गंभीर व्यवहार स्कोर पाया गया। जो कामकाजी माताओं के बच्चों की तुलना में चिक्त्सीय रूप में महत्वपूर्ण था। अनुसंधान ने निष्कर्ष

\* शोधार्थी, करियर पाईन्ट विश्वविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

\*\* शोध पर्यवेक्षिका एवं विभागाध्यक्ष, अलख स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, कोटा (राज.) भारत



निकाला कि माँ की कामकाजी स्थिति का बच्चों के व्यवहार संबंधी समस्याओं पर प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि अन्य बाहरी तथा सामाजिक कारक तथा सामाजिक संबंधी व बातचीत का बच्चे के व्यवहार पर अधिक प्रभाव पड़ता है विशेष रूप से जब वे किशोरावस्था में होते हैं।

**साइमंस, स्मृति किरण (2016)** – इन्होंने कामकाजी तथा गैर कामकाजी माताओं के किशोरों के भावनात्मक परिपक्वता का तुलनात्मक अध्ययन किया जिसके लिए नमूने के रूप में 200 छात्रों को लिया गया। जिन्हें कश्मीर के जिला अननंतांग के माध्यमिक स्कूलों से लिया गया (उम्र 13- 15 वर्ष) जिसमें 100 छात्र कामकाजी माता के साथ 100 छात्र गैर कामकाजी महिलाओं के साथ शामिल थे किशोरों की भावनात्मक परिपक्वता मापने के लिए सिंह व भार्गव की भावनात्मक परिपक्वता स्केल का उपयोग किया गया।

जिसके परिणामों में पाया गया कि गैर कामकाजी माताओं के बच्चे कामकाजी माताओं के बच्चों की तुलना में भावनात्मक रूप से परिपक्व हैं। गैर कामकाजी, माताओं के बच्चों के भावनात्मक रूप से स्थिर, प्रगतिशील व समायोजित पाया गया। जबकि कामकाजी माताओं के बच्चे को भावनात्मक रूप से असमायोजित पाया गया।

**खान, महमूद अहमद, रियाज सैयद तथा शाह (2015)** – उपरोक्त अध्ययन में शोधकर्ताओं ने कामकाजी तथा गैर कामकाजी महिलाओं के किशोरों के भावनात्मक परिपक्वता के बीच अंतर का पता लगाया। इसके लिए शोधकर्ताओं ने 800 छात्र जिसमें 400 छात्र कामकाजी महिला तथा 400 छात्र गैर कामकाजी महिला के शामिल थे जो श्रीनगर व कश्मीर घाटी के शोपियां के स्कूलों से लिया गया। जिनकी आयु सीमा 13- 15 वर्ष थी। बच्चों की भावनात्मक परिपक्वता मापने के लिए भावनात्मक परिपक्वता स्केल का उपयोग किया गया।

उपरोक्त अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया कि गैर कामकाजी माताओं के बच्चे कामकाजी माताओं के बच्चे की तुलना में भावनात्मक रूप से परिपक्व हैं, गैर कामकाजी माताओं के बच्चों को भावनात्मक रूप से स्थिर, समायोजित पाया गया। जबकि कामकाजी महिलाओं के बच्चे कुसमायोजित पाए गए।

**रिचर्डसन, हन्ना (2015)** – बीबीसी न्यूज एजुकेशन रिपोर्ट हावर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि घरेलू महिलाओं के मुकाबले कामकाजी महिलाओं के बच्चों का कैरियर अधिक बेहतर होता है इस शोध की मुखिया कैथलीन मैकगिल के अनुसार कामकाजी महिलाएँ अक्सर अपने बच्चों के लिए भविष्य के खतरे को भांप जाती हैं।

**जुगल, श्यामलता (2015)** – इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि गृहणी माताओं के बच्चों की तुलना में जो कार्यशील महिलाएँ हैं, उनके बच्चों में आत्मविश्वास तथा आत्म संकल्पना अधिक उच्च स्तर पर पायी जाती है।

**चतुर्वेदी, प्रकृति (2015)** – ने भोपाल शहर के कामकाजी व गैर कामकाजी महिला के किशोरों के समायोजन का अध्ययन किया गया जिसमें यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि कामकाजी व घरेलू महिलाओं के किशोर बालक व बालिकाओं के समायोजन में सार्थक अंतर होता है तथा कामकाजी महिलाओं के बच्चे समय से पूर्व समझदार गम्भीर व उत्तरदायी हो जाते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में अकेले तथा आत्मविश्वासी पूर्वक जूझने की दृढ़ता उनमें आ जाती है तथा वह अपने आप को समायोजित कर लेते हैं।

**झाझरिया, मनोज; प्रसाद, राजेन्द्र (2015)** – का शोध बिन्दू 'कामकाजी तथा गैर कामकाजी महिलाओं के बालकों की अध्ययन आदते तथा समायोजन का अध्ययन' था।

प्रस्तुत शोध के लिए कामकाजी व गैर कामकाजी माताओं के 120 छात्रों को लिया जो कक्षा 9वीं से 12वीं स्तर के झुझुनू जिले से थे। जिसके डाटा संग्रहण के विश्लेषण के लिए डा. एस. के.पी. तथा एम. मुखोपाध्याय के उपकरण उपयोग किए गए। इन्होंने अध्ययन के निष्कर्ष में यह पाया कि कामकाजी व गैर कामकाजी महिलाओं के बालकों के समायोजन में कोई सार्थक अंतर नहीं है, इसका कारण यह है कि कामकाजी महिलाएँ भी समय के अनुसार अपने बालकों को चलने योग्य बनाने के लिए कुछ समय निकाल कर उनका पथ प्रदर्शन करती हैं।

**अग्रवाल, सोनाली (2014)** – इस शोध में शोधार्थी ने उन समस्याओं का उल्लेख किया है जिन समस्याओं का सामना कार्यशील माता के बच्चों को करना पड़ता है इन्होंने अध्ययन में पाया कि बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में माँ की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है।

**सिंह, अन्नू (2014)** – 'किशोरों के व्यक्तित्व पर माँ की कार्यस्थिति का प्रभाव' का अध्ययन करने के लिए शोधार्थी द्वारा अध्ययन किया गया। अध्ययन के नमूने लखनऊ के शारदा नगर व आशियाना क्षेत्र से अनियामित रूप से चुने गए 120 बच्चे (60 बच्चे कामकाजी माता के तथा 60 बच्चे गैर कामकाजी माताओं के शामिल थे।)

इस हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग, डाटा संग्रहण के लिए किया गया डाटा के विश्लेषण के लिए परीक्षण का उपयोग नहीं किया गया परिणामों को पारदर्शी बनाने के लिए कोलमोग्राफ को तैयार किया गया अध्ययन के परिणाम में पाया कि कामकाजी माताओं का व्यक्तित्व गैर कामकाजी माताओं के बच्चों के व्यक्तित्व से अधिक होता है।

**सविता (2014)** – ने 'कार्यकारी व गृहणी महिलाओं के बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि व समायोजन पर परिवार की प्रेरणा के प्रभाव का अध्ययन' शीर्षक पर P.hd शोध कार्य किया इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि गृहणी महिलाओं के बच्चों की अपेक्षा कामकाजी महिलाओं के बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि उच्च स्तर की होती है ग्रामीण क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं के बच्चों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र की गृहणी महिलाओं के बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि निम्न स्तर की होती है कार्यकारी महिलाओं के बच्चों की अपेक्षा गृहणी महिलाओं के बच्चे कम समायोजित होते हैं।

**निष्कर्ष** – उपरोक्त कार्यशील व गृहणी माताओं के किशोर किशोरियों के समायोजन, तथा व्यवहारों के भिन्न रूपों का अध्ययन किया गया, सभी अध्ययनों के निष्कर्ष भिन्न-भिन्न हो।

कुछ शोधार्थियों ने पाया कि गैर कामकाजी महिला के बच्चे कामकाजी महिलाओं के बच्चों की अपेक्षा भावनात्मक रूप से अधिक परिपक्व होते हैं उनका समायोजन भी उच्च स्तर का पाया जाता है वही कुछ शोधार्थियों ने अपने परिणामों में पाया कि कामकाजी महिलाओं के किशोर स्वयं को हर परिस्थिति में अपने को ढाल लेते हैं तथा उनके आत्मविश्वास का स्तर अपेक्षाकृत उच्च होता है।

कई शोधार्थी ने अपने परिणामों की व्याख्या में यह बताया कि कार्यशील व गृहणी माताओं के बालकों के व्यवहारों में महत्वपूर्ण अंतर नहीं होता है। उनका समायोजन तथा व्यवहार लगभग समान रहता है।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-**

1. Khan Mahmood Ahmad (2017), "Children of Working and Non-working Mothers & their Adjustment, <https://www.researchgate.net/publication/328137323> \_
2. Sayed, Ambreen (2017), [https://www.academia.edu/38688144/children\\_of\\_working\\_and\\_non-working\\_mother](https://www.academia.edu/38688144/children_of_working_and_non-working_mother)

- their adjustment
- 3. Bhatiya, Anshu (2012), Academic achievement of working and non-working mothers, Aarhat Multidisciplinary International Education Research Journal.
- 4. Aggarwal, Sonali (2014), Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies.
- 5. The International Journal of Indian Psychology, ISSN 2348-5396(e).
- 6. Rani Sunita, [https://www.academia.edu/37297427/A\\_Comperative\\_Study\\_of\\_adjustment\\_among\\_children\\_of\\_working\\_and\\_non-working\\_mothers](https://www.academia.edu/37297427/A_Comperative_Study_of_adjustment_among_children_of_working_and_non-working_mothers)
- 7. International journal of advanced scientific and technical research. <http://www.rspublication.com/ijst/index.html>
- 8. Asian Journal of Home Science. <http://www.researchjournal.co.in>

\*\*\*\*\*

## गिरवा तहसील के व्यवसायिक संरचना में ग्रामीण महिलाओं का योगदान

डॉ. युवराज सिंह राठौड़ \* धीरज पालीवाल\*\*

**प्रस्तावना** – किसी भी क्षेत्र का विकास सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक आधार पर होता है। उसी प्रकार किसी गांव का या नगर का आधार सामाजिक एवं आर्थिक तत्वों पर परिलक्षित होता है। इसके अन्तर्गत सामाजिक (जनसंख्या, शिक्षा, कृषि) आर्थिक (अर्थव्यवस्था व क्रियाकलाप) सम्मिलित किये जाते हैं। उदयपुर शहर एक ऐतिहासिक नगर है जिसकी स्थापना सन् 1551 में महाराणा उदयसिंह जी द्वारा की गई थी। यद्यपि आयड़ उदयपुर की सबसे पुरानी आबादी है। जो 10 वीं ईस्वी की मानी जाती है और अब यह पुरातत्व की दृष्टि से संरक्षित क्षेत्र है। उदयपुर शहर का उद्भव भारतीय इतिहास के सुनहरे काल की याद दिलाता है।

**शोध अध्ययन क्षेत्र गिरवा तहसील का सामान्य परिचय** – राजस्थान राज्य की कुल जिलों की संख्या वर्तमान में 33 है। जिसमें से झीलों का शहर कहा जाने वाला जिला उदयपुर राजस्थान राज्य के दक्षिणपूर्वी भाग में अवस्थित है। उदयपुर जिले में कुल तहसीलों की संख्या वर्तमान में 11 है। जो कि निम्न है – गिरवा, बड़गांव, मावली, भीण्डर, गोगुन्दा, कोटडा, झाडोल, सराडा, सलुम्बर, खेरवाडा, लसाडिया। गिरवा या गिरवा शब्द की व्युत्पत्ति यही की स्थानीय भू-आकृति के कारण हुआ है। क्योंकि गिरवा का अर्थ स्थानीय भाषा में घिरा हुआ होता है। अरावली श्रेणी के चारों ओर घिरी हुई कटोरनुमा आकृति बन जाने से गिरवा नाम से जाना जाता है। इस तहसील का अक्षांशीय विस्तार 24°58' उत्तरी अक्षांश एवं देशान्तरीय विस्तार 73°68' पूर्वी देशान्तर के मध्य अवस्थित है। इस भू-भाग की औसत ऊँचाई 550 मीटर (1770 फीट) है। यह तहसील पश्चिमी सीमा उदयपुर शहर से, पूर्वी सीमा भीण्डर तहसील, सराडा तहसील दक्षिणी सीमा एवं उत्तरी सीमा बड़गांव से आबद्ध है। तहसील का औसत तापमान 310 सेन्टीग्रेड से 440 सेन्टीग्रेड के मध्य रहता है तथा जनवरी माह का औसत तापमान 190 व मई माह का औसत तापमान 360 सेन्टीग्रेड है।

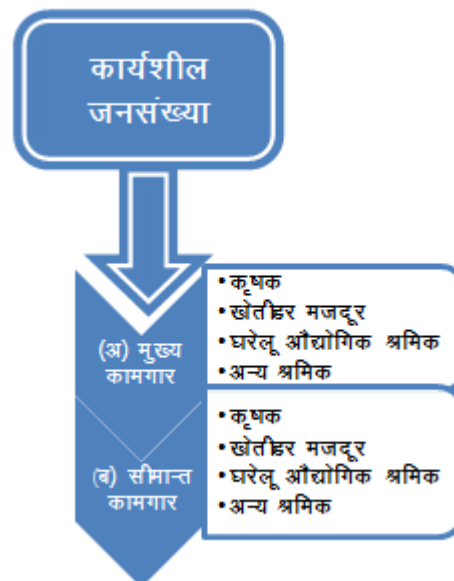
कुल विकासखण्ड - 2, ( गिरवा गाँव - 217, बड़गांव गाँव - 108 )

कुल गाँवों की संख्या - 217



**शोध अध्ययन क्षेत्र गिरवा तहसील का व्यवसायिक संरचना** – इसमें कुल जनसंख्या संरचना में से विभिन्न व्यवसायों या कार्यों में संलग्न जनसंख्या को सम्मिलित करते हैं। इसे श्रमजीवी जनसंख्या कहते हैं। सामान्यतः 15 से 59 वर्ष के मध्य आयु वर्ग को ही श्रमजीवी माना जाता है। सन 1981 व 2001 की जनगणना के अन्तर्गत मुख्य कामगारों को चार श्रेणियों में विभक्त किया गया। सन् 2011 की जनगणना के अन्तर्गत कार्यशील जनसंख्या को दो भागों में – (अ) मुख्य कामगार व (ब) सीमान्त कामगार में विभक्त किया गया।

**(अ) मुख्य कामगार** – इस श्रेणी में वे श्रमिक रखे गए हैं जो कि एक वर्ष में 183 दिनों से आर्थिक दृष्टि से लाभकारी कार्यों में संलग्न हैं।



**(ब) सीमान्त कामगार** – इस श्रेणी में वे श्रमिक रखे गए हैं जो कि एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिनों में आर्थिक दृष्टि से लाभकारी कार्यों में संलग्न हैं।

चयनित तहसील गिरवा के द्वितीयक आकड़े जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, जनगणना 2011 भारत सरकार के आधार पर विश्लेषण किया गया है। जिसके द्वारा व्यवसायिक संरचना में महिलाओं के योगदान की जानकारी प्राप्त की गयी है।

**सारणी 1 : मुख्य कामगारों के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं की स्थिति**

जनसंख्या	कार्यशील जनसंख्या	अकार्यशील जनसंख्या
ग्रामीण	119143	165632

\* सह-आचार्य, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड) विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत  
 \*\* शोधार्थी (भूगोल) जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड) विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

नगरीय	1470	2825
जनसंख्या संख्या में	120613	168457
प्रतिशत में	42	58
<b>जनसंख्या</b>	<b>ग्रामीण पुरुष</b>	<b>ग्रामीण महिला</b>
ग्रामीण	77705	41438
प्रतिशत में	65	35
<b>जनसंख्या</b>	<b>नगरीय पुरुष</b>	<b>नगरीय महिला</b>
ग्रामीण	1191	279
प्रतिशत में	81	19
<b>जनसंख्या</b>	<b>ग्रामीण पुरुष</b>	<b>ग्रामीण महिला</b>
ग्रामीण	60075	16039
प्रतिशत में	79	21
<b>कृषक (मुख्य श्रमिक)</b>	<b>ग्रामीण पुरुष</b>	<b>ग्रामीण महिला</b>
ग्रामीण	18211	7853
प्रतिशत में	70	30
<b>खेतीहर मजदूर (मुख्य श्रमिक)</b>	<b>ग्रामीण पुरुष</b>	<b>ग्रामीण महिला</b>
ग्रामीण	3371	2082
प्रतिशत में	62	38
<b>घरेलू औद्योगिक श्रमिक (मुख्य श्रमिक)</b>	<b>ग्रामीण पुरुष</b>	<b>ग्रामीण महिला</b>
ग्रामीण	952	311
प्रतिशत में	75	35
<b>अन्य श्रमिक</b>	<b>ग्रामीण पुरुष</b>	<b>ग्रामीण महिला</b>
ग्रामीण	37541	5793
प्रतिशत में	87	13

स्रोत : District census Handbook, Udaipur, Village And Town Directory, Census of India 2011, Series-09, Part XII-B

**सारणी 2 : सीमान्त कामगारों के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं की स्थिति**

<b>सीमान्त श्रमिक</b>	<b>ग्रामीण पुरुष</b>	<b>ग्रामीण महिला</b>
जनसंख्या संख्या में	17630	25399
प्रतिशत में	41	59
<b>कृषक (सीमान्त श्रमिक)</b>	<b>ग्रामीण पुरुष</b>	<b>ग्रामीण महिला</b>
जनसंख्या संख्या में	5438	10063
प्रतिशत में	35	65
<b>खेतीहर मजदूर (सीमान्त श्रमिक)</b>	<b>ग्रामीण पुरुष</b>	<b>ग्रामीण महिला</b>
जनसंख्या संख्या में	4186	8557
प्रतिशत में	33	67
<b>घरेलू औद्योगिक श्रमिक (सीमान्त श्रमिक)</b>	<b>ग्रामीण पुरुष</b>	<b>ग्रामीण महिला</b>

जनसंख्या संख्या में	328	432
प्रतिशत में	43	57
<b>अन्य श्रमिक (सीमान्त श्रमिक)</b>	<b>ग्रामीण पुरुष</b>	<b>ग्रामीण महिला</b>
जनसंख्या संख्या में	7678	6347
प्रतिशत में	55	45

स्रोत : District census Handbook, Udaipur, Village And Town Directory, Census of India 2011, Series-09, Part XII-B

**विश्लेषण** - उपरोक्त सारणी विश्लेषण से यह जानकारी प्राप्त होती है कि शोध का भौगोलिक क्षेत्र उदयपुर जिले की गिरवा तहसील में महिलाओं का व्यवसायिक संरचना में मुख्य श्रमिक श्रेणी के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं का क्रमशः कृषक श्रेणी में 30 प्रतिशत, खेतीहर मजदूर श्रेणी 38 प्रतिशत, घरेलू औद्योगिक श्रमिक श्रेणी 25 प्रतिशत, अन्य श्रमिक श्रेणी 13 प्रतिशत योगदान है तथा सीमान्त श्रमिक श्रेणी के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं का क्रमशः कृषक श्रेणी में 65 प्रतिशत, खेतीहर मजदूर श्रेणी 67 प्रतिशत, घरेलू औद्योगिक श्रमिक श्रेणी 57 प्रतिशत, अन्य श्रमिक श्रेणी 45 प्रतिशत योगदान है।

सर्वाधिक उदयपुर जिले की गिरवा तहसील में महिलाओं का व्यवसायिक संरचना में मुख्य श्रमिक श्रेणी के अन्तर्गत खेतीहर मजदूर श्रेणी 38 प्रतिशत है तथा सीमान्त श्रमिक श्रेणी के अन्तर्गत भी खेतीहर मजदूर श्रेणी 67 प्रतिशत पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान में महिलाओं द्वारा किया जा रहा यह योगदान राज्य व राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक रूप से विकास का द्योतक है।

**सारांश** - सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि महिलाओं द्वारा जो भागेदारी पोषण स्तर व व्यवसायिक संरचना में निरन्तर रूप से बढ़ रही है। इससे परिवार का सर्वांगीण विकास होता है फलतः उसका प्रभाव जिले के सर्वांगीण विकास में ही नहीं वरन् राज्य व राष्ट्र का सर्वांगीण विकास अवश्यसम्भावी होगा।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. <http://www.vivacepanorama.com/womens-development-plans-and-programs/>
2. District census Handbook, Udaipur, Village And Town Directory, Census of India 2011, Series-09, Part XII-A
3. District census Handbook, Udaipur, Village And Town Directory, Census of India 2011, Series-09, Part XII-B
4. <http://nrhmrajasthan.nic.in/POSHAN.asp>
5. Sharma Richa : Working Of Malnutrition Treatment Centers % An assessment of MTCs in Rajasthan, Public Advocacy Initiatives for Rights and Values In india, New Delhi, May 2013
6. डॉ. गुर्जर रामकुमार एवं डॉ. जाट बी. सी. : भारत का भूगोल, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, संस्करण (ग्यारहवां) 2016, पृष्ठ संख्या-201-202
7. शर्मा एच. एस. प्रो. एवं शर्मा एम. एल. डॉ. : राजस्थान का भूगोल, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, संस्करण (बाहरवां) 2016, पृष्ठ संख्या-403-404



# Sexual Violence Against Women in India

Dr. Nilesh Sharma\* Asish Kumar\*\*

**Abstract** - This paper deals with the rampant growth of Sexual Violence against women and female child in all around the India. Today when moral values is on verge of decline, incidents of Sexual Violence against Women and Female Child is very common all around the world and Our country is not exception. This paper discuss the status of female gender in different periods, Concept of Violence with female, Violence during life cycle, Definitions of Sexual Violence, Types of sexual violence with Women, Different Laws related to Sexual Violence and also paper reveals on the basis of NCRB data the impact of available Laws. The study concludes that we have done many amendments in existing laws also made new laws to improve law and order, but it does not success to decline crimes related to Sexual Offences. Efficient management of the investments on the crime-control instruments and along with that improvement in the social indicators, viz., female education, favourable sex ratio, etc., are required for efficient control of sexual offences.

**Introduction** - India is honoured as matribhumi means mother land. The renowned concept is Indian people respect women very much. Absolutely, in India women are worshipped like Goddess as a symbol of Shakti (power) - Sri Aurobindo once spoke of *shakti* simply as “**the female principle in Nature which is at the root of all action**”, Maa nurtures her Children as a lakshmi in one side and kills the demons on the other as a kali. Indian people have faith that “**Where the women are honoured, there all deities are pleased and where they are dishonoured, there all religious acts become fruitless.**” Every year Indian people celebrate Durga Puja all around the country with beliefs that Maa resolve all their problems.

Indian Society has always revered women. They are considered the first architects and future builders of the society being the first teachers of children. In Hinduism, man and woman represent the two halves of the divine body. There is no question of superiority or inferiority between them.

**Status of women in Indian society** - Status of women in Indian society was not same since the ancient period till the modern age. The position of women in Indian society has seen many great changes. The present condition of women cannot be properly understood without reference to the antecedent, for the purpose of analysis we can divide the period as follows:-

## 1. The Ancient Period:

**During the vedic period-** women enjoyed fair amount of freedom and equality. Women actively participated in all spheres like men. They studied in gurukuls and enjoyed the equality in learning the Vedas. Great women like Gargi, ghosa, Apala, Lopamudra, Atreyi acquired excellence in art,

music, dance etc. They were also free to choose their marriage partner. In the matrimonial home, they were treated as ‘grihalaksmi’ and having important place in family. the word “Dampati”, so often used in the Vedas characterises both wife and husband. Men also could not perform any religious ceremonies without wife. The system of polygamy was mainly confined in the ruling class. Girls were allowed to undergo Upanayana or thread ceremony, ‘Sati’ was unknown. Dowry system also did not exist. Some gifts were given to son-in-law at the time of marriage only in rich and royal families but they were given by parents or relatives of bride or bride groom out of love and affection, not as a compulsion. In short, both boys and girls treated equally.

**During Epic Period** - The two great epics Ramayana and Mahabharata have a strong influence on Indian society. Even today a girl is advised to follow the footsteps of Sita. Sita is considered as the ideal Hindu woman because she surrendered all her personal desires and followed her husband Rama to the forest. Draupadi is the symbol of independence and courage. The self imposed blindness of Gandhari as a mark of her blind husband did not lower her status as a queen.

**In The Age of Dharmashastras** - women became depended on men in this period. The Dharmashastras prescribed codes of conduct, which regulated the whole society. The two most important law codes of this period were Manu Smriti and Yagnavalkya Smriti. According to Manu Smriti there was no permission to the women to enjoy liberty in their lives. Manu's view was that ‘a woman, in her childhood is dependent on her father, in her youth on her husband, and in her old age on her son.’ According to

Yagnavalkya Smriti the proper time of marriage of a girl was the age of puberty. In the age of Dharmashastra girls had to be married at a very tender age. The husband was given the right to use physical punishment over his wife. During this period, child marriage was encouraged and widow marriage neglected.

**2. The Medieval Period:** Medieval India was not women's age. It was the 'dark age' for the women. Medieval India saw many foreign conquests. The foreign conquerors brought with them their own culture. Polygamy was widely practiced especially among Hindu Kshatriya and Muslim rulers. Women were deprived from enjoying any kind of rights.

#### **Social evils like-**

**1. Sati:** the ritual of dying at the funeral pyre of the husband is known as "Sati" or "Sahagaman".

**2. Jauhar:** Jauhar was prevalent in the Rajput societies. When people of Rajput clan became sure that they were going to die at the hands of their enemy then Rajput women committed suicide with their children and valuables in massive fire, while their husbands used to fight the last decisive battle known as "Shaka", with the enemy.

**3. Child Marriage:** Girls were married off at the age of 8-10. They were not allowed access to education and were treated as the material being.

**4. Restriction on Widow Remarriage:** the condition of widows in medieval India was very bad. They were not treated as human beings and were subjected to a lot of restrictions. They were supposed to live pious life after their husband died. Sometimes heads of widows were also shaved down. They were not allowed to remarry.

**5. Purdah System:** Purdah, in Hindi **Parda**, 'Purdah' system was used in medieval Indian society to protect Women folk from the eyes of foreign rulers who invaded India. But this system **diminished** the freedom of women.

**6. Girl Education:** The girls of medieval India and especially Hindu society were not given formal education. They were given education related to household chores. According to Indian philosopher 'Vatsyayana' Women were supposed to be perfect in sixty four acts which included cooking, spinning, grinding, knowledge of medicine, recitation and many more.

**7. Devadasis:** In some parts of India, the Devadasi or the temple women were sexually exploited. In this system girls were dedicated to temples in the name of Gods and Goddesses. 'Devadasis' meaning servant of god.

#### **3. Women In Modern Society:**

**During British Period :** When the British took over India, the position of women in Indian society was in a very bad state due to inhuman socio-religious practices. However the attitude, behavior and living pattern of society changed drastically during the British regime due to education and Western impact on the socio-cultural life of India. Due to Western impact on the Indian society, two major movements took place: (1) Social Reform Movement of the 19th century and (2) Nationalist movement. of the 20th century. Both

these movements raised the question of equal status of women, the problem of Sati, child marriage, Polygamy, women's property right, Purdah, prohibition on widow remarriage denial of education etc. However, as a result of the constant pressure of the Indian reformist, several legislations were enacted by the Britishers like Widow's Remarriage Act, 1856, Child Marriage Restraint Act, 1929, Hindu Women's Right to Property Act, 1937.

**Post Independence Period :** India got its independence on 15th August, 1947. We got the charter of our country i.e the Constitution of India wherein the principles of equality, liberty and social justice are enshrined. Our Constitution ensures equality to men and women and also gives special protection to women to comprehend their interests effectively. Articles 14, 15 and 16 of the Indian Constitution guarantee that there will be no discrimination on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth. However, Article 15(3) empowers the state to make special provisions for the advancement of women and children. Article 32 also deserves special mention in this regard. Article 32 of the Indian Constitution gives the right to individuals to move to the Supreme Court to seek justice when they feel that their right has been 'unduly deprived'. The right to life is guaranteed under Article 21 of the Constitution of India gives meaning to the life of human being.

Our Government has also enacted multiple legislations for the protection of the right and interest of women in different field. Some of them are: the provisions contained in the Indian Penal Code, 1860; the Indian evidence Act, 1872; the Criminal Procedure Code, 1973; the Factories Act of 1948; Equal Remuneration Act, 1976; Maternity Benefit Act, 1961; the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971; the Dowry Prohibition Act, 1961; the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986; Immoral Traffic (Prevention) Act, 1986, Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994; Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005; the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, **The Criminal Amendment Act 2013 or Nirbhaya Act or anti rape law** etc.

**Concept of Violence Against Women :** In present time there has been shocking decline in moral values all around the World and India is not an exception of it. Now India is facing proliferation in Violence against Women and Female Child. Violence against women is present across the world cutting across boundaries of culture, class, education, income, ethnicity and age. Violence against women does not simply refer to the physical violence which a woman has to bear, but also verbal abuse, emotional torture, economic deprivation and social disregard. No women are born to be treated in an inhuman manner and to be deprived of her right to life.

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), also known as the Treaty for Women's Equality, is a landmark international

agreement that affirms principles of fundamental human rights and equality for women around the world. CEDAW is a practical blueprint for each country to achieve progress for women and girls. India ratified this convention in the year 1993. Even after the adoption of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women by the United Nations General Assembly in 1979, important progress has been made in almost all major countries for establishing gender-based violence as a human rights concern. But the current scenario defines that the mere adoption of conventions and policies has not served the purpose that it ought to. There is still widespread and deep rooted problem that requires attention because the instances of female victimization have been growing tremendously.

The acts of abuse like eve-teasing, molestation, sexual abuse, domestic violence and rape have become very common forms of offences which are reported almost every day. It is also pertinent to consider that any form of violence, whether verbal or physical, may be forced against a woman either by a complete stranger, or by people who are known to them. There have been many instances where the suspected offenders are either family members themselves, or relatives, or even family friends. Considering such circumstances, it will not be wrong to presume that a woman is not safe in today's time even at her own home. Women face Violence during each and every stage of her life.

**Women And Violence During Life Cycle** - Women continue to be subjected to crimes/violence over the entire life cycle. Before birth they are condemned to sex selection and female foeticide; during infant and childhood stage they are subject to infanticide or undernourishment; if they do manage to pass the age of five, they are neglected in medical care and education as well as subjected to sexual or physical violence; in adolescence and adulthood, they are faced with situations of early marriage, early pregnancy, sexual violence, domestic violence, harassment for dowry, desertion, dying during deliveries and as older women and widows condemned to a life of desertion and neglect etc.

**Showing that gender violence in different stages of women's life.**

Pre-birth Stage	- Female Foeticide
Infancy Stage	- Female Infanticide and Gender Discrimination (health care, nutrition, Love Affection).
Childhood Stage	- Gender Discrimination (Health, Nutrition, Food, Education and other social benefits)
The adolescent Stage	- At the stage of adolescence (early marriage, rape, incest rape, discrimination in health care, dress code, use of information technology like mobile phones, their movements are restricted, prostitution, trafficking, eve-teasing etc).

Reproductive stage of women - At reproductive age (Domestic Violence in the form of sexual (marital rape), psychological, emotionally and physically tortured by intimate partner and his family members).

Old Age - In old age women generally faces elderly abuse. (Abused in terms of physical, emotional, psychological and financial abuse).

In India, if a male child is born it is almost like a festival, but if a female child is born all happiness ends. A female child is given less care than male child in terms of facilities like- meal, education, money, consultancy etc. Parents tends to hurry their marriages. So we can see that harassment on sex basis starts rights from birth of female child and it ends only with her death. Male child is considered necessary for expansion of father's name. But female child is considered as "Praya Dhan", "Amanat".

**Sexual Violence against Women and Female Child** - The term violence derives from the Latin word vis, which means force and refers to the notions of constraint and using physical superiority on the other person. Sexual violence is an rampant since long time and women and Female Child have been always the favorable target of such exploitation. For better understanding of Sexual Violence against Women and Female Child we may categories Sexual Violence in two heads :-

**Sexual Violence against Adult Women** : Women are important pillar in our society. 'Every woman has her own job or duty in this modern society. We can't forget that a woman's life is a lot more complicated than a man's life. A woman has to take care of her own personal life and if she is a mother, she has to take care also of her children's life too. Worse still, if she is married, additional stress can be on her shoulders. Yet they will still perform very well in the work environment in some cases better than their male counterparts.' There is no any ambiguity in the fact that women in India have made a considerable progress in the last fifty years but yet they have to struggle against many hindrance and social evils in the male dominated society. Violence against women is one of the most widespread abuses of human rights worldwide, every one third of all women became victim in their lifetime. Sexual violence is a brutal reality of women's lives, stigma on the face of civilized human society. Today Women and Female Child can be Sexually harassed in places like in home, school, offices, metros, buses, trains and crowded places like festivals, fairs, etc.

**WHO** defined Sexual violence as "any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic women's sexuality, using coercion, threats of harm or physical force, by any person regardless of relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work". Sexual violence includes sexual exploitation and sexual abuse. It refers to



any act, attempt, or threat of a sexual nature that result, or is likely to result in, physical, psychological and emotional harm. Sexual violence is a form of gender-based violence.

**According to Wikipedia 'Sexual violence** is any sexual act or attempt to obtain a sexual act by violence or coercion, acts to traffic a person or acts directed against a person's sexuality, regardless of the relationship to the victim.<sup>[1][2][3]</sup> It occurs in times of peace and armed conflict situations, is widespread and is considered to be one of the most traumatic, pervasive, and most common human rights violations'.

Broader definitions of sexual violence are found within international law. The **Rome Statute of the International Criminal Court (ICC)** has established in article 7(1)(g) that "rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity" constitutes a crime against humanity.<sup>[16]</sup> Sexual violence is further explained in the ICC's Elements of Crimes, which the Court uses in its interpretation and application of Article 7. The Elements of Crime establishes that sexual violence is:

"An act of sexual nature against one or more persons or caused such person or persons to engage in an act of sexual nature by force, or by threat of force or coercion, such as that caused by fear of violence, duress, detention, psychological oppression or abuse of power, against such person or persons or another person, or by taking advantage of a coercive environment or such person's or persons' incapacity to give genuine consent."

According to **merriam-webster Dictionary sexual assault** "illegal sexual contact that usually involves force upon a person without consent or is inflicted upon a person who is incapable of giving consent (as because of age or physical or mental incapacity) or who places the assailant (such as a doctor) in a position of trust or authority".

**Sexual Violence against Female Child :** Indian Children, who account for a staggering 42% of the country's population, have long been the victims of some of the most brutal sexual crimes known to humanity. Sexual abuse is defined as the 'involvement of a child in sexual activity that he or she does not fully comprehend, is unable to give informed consent to, for which the child is not prepared, or else that violates the law or social taboos of society. Actual sexual intercourse may not be very common but other forms of abuse like incest, sodomy, caressing, exhibitionism, masturbation and voyeurism occur with disturbing frequency. Unlike as in adults, in children the use of force is not an essential part of the abuse. Since children are incapable of understanding the implications of the act, their willingness has no meaning whatsoever. In fact most instances of abuse would be where she is not even aware of being abused and treats it as play. Countless are the instances, wherein elderly relative makes sexual advances on unsuspecting children especially girls. Many such instances are not even recognized for what they are, let

alone reported. Male and female servants, in whose care small children are left are the most common offenders adolescent boys playing with younger girls even in socially sanctioned play can indulge in such acts.' Sexual acts with children may be performed by a parent, guardian, relative, and acquaintance of anyone else. When the violence occurs within home, the abuse is effectively condoned by the tacit silence and the indifference by the instruments of the state and the law-enforcing machinery. Female Child face all forms of sexual assault in India and offences against female child have reached an epidemic proportion.

In the **United Nation Convention** on the Rights of Child, a child has been defined as one who is under the age of eighteen years. This includes infancy, early childhood, middle and adolescence. According to the Indian Penal Code, 1860, the age limit of child is less than seven years and and above twelve years for the purpose of criminal responsibility. With a view to providing protection against kidnapping, abduction and related offences the age limit has been fixed at sixteen years in case of boys and eighteen years in case of girls. A girl is considered minor in rape if she has not completed the age of eighteen years. Under the Immoral Trafficking (Prevention) Act, 1956, child is a person who has not completed the sixteen years of age. Under the Protection of Children from the Sexual Offences Act, 2012, child means any person who is below the age of eighteen years. The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 defines child as a person who is below the age of eighteen years.

According to **World Health Organization**, "child sexual abuse is the involvement of a child in sexual activity that he or she does not fully comprehend, is unable to give informed consent to, or for which the child is not developmentally prepared and cannot give consent or that violates the laws or social taboos of society. Child sexual abuse is evidenced by this activity between a child and an adult or another child who by age or development is in a relationship and responsibility, trust or power, the activity being intended to gratify or satisfy the needs of the other person. This may include but is not limited to :-

1. The inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity;
2. The exploitative use of a child in prostitution or other unlawful sexual practices;
3. The exploitative use of children in pornographic performance and materials."

Sexual violence, apart from causing immediate physical harm, leaves a permanent wound mark in the memory of the victim, which destroys her emotional psyche tremendously. Female Child are not secured any where children are molested by home also by Family persons called -Incest Sex. 'One of the five women has been physically and mentally abused by a man at some point in her life. Incestful risks come from close relatives, neighbours and known persons. From their father, neighbours, husband and other near by mans rather from



strangers'. A majority of sexual offences committed against female child are not even reported, let alone prosecuted. Sexual abuse of child has not been recognized as a separate category of crime. The definition of rape under Section 375 of IPC, applies equally to an adult woman and a girl-child/minor.

#### **Types of sexual violence with Women**

1. Sexual Harassment
2. Eve- Teasing:
3. Molestation
4. Rape :
5. Attempt to Rape
6. Marital Rape
7. Outraging Modesty of a women,
8. Kidnapping; and Child Trafficking;
9. Selling and Buying of minor girls for prostitution
10. Child Prostitution
11. Child Rape
12. Sex Tourism
13. Pornography, etc.

**Laws relating to Sexual Offences against Women and Female Child** - In, India, provisions for protection of Women and female child are made in different legislation codes etc. like POCSO Act, IPC, Cr.P.C., Indian Evidence Act, Vishakha Guidelines. Even in Grundnorm of our country i.e. Constitution of India, various articles are provided for protection of women.

The following laws are having special provisions to protect women and their safety:

1. Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986
2. The Immoral Traffic (Prevention) Act 1986
3. The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
4. Information Technology Act 2000
5. The Sexual Harassment of Woman at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
6. The Prohibition of Child Marriage Act, 2006

**Protection of Women and Female Child from Sexual Offences** - Now a days India has become the most dangerous place for women and female child. In every corner of the country the females are harassed, sexually abused raped, gang raped, raped with murder etc. For the Protection of child from Sexual Violence Government Of India (GOI) passed the following Specific Laws :

**A. POSCO Act 2012: The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012** has been drafted to strengthen the legal provision for the protection of children from sexual abuse and exploitation. For the first time, a special law has been passed to address the issue of sexual offences against children. The POCSO Act, 2012 defines a child as any person below the age of 18 years and provides protection to all children under the age of 18 years from the offences of sexual assault, sexual harassment and pornography. These offences have been clearly defined for the first time in law. The Act provides for stringent punishments, which have

been graded as per the gravity of the offence. The punishment range from simple to rigorous imprisonment of varying periods. There is also provision for fine, which is to be decided by the Court.

**B. Amendments made in Law of Rape vide Act 13 of 2013 (Nirbhya Act)** - In an incident which was happened on 16 December 2012 in Country's Capital Delhi where a female student intern was beaten and brutally gang raped and after few days later in spite of receiving medical treatment, the victim was no longer alive. The incident led to condemnation by the United Nations and other International women organizations, and called upon government of India "to do everything in their power to take up radical reforms, ensure justice and reach out with robust public services to make women's lives more safe and secure".

**Due to this Government Of India (GOI)** on December 22, 2012, appointed a three-member judicial committee headed by the former Chief Justice of India, Justice J.S. Verma. "A 631-page report consisting of 14 chapters include recommendations on laws related to rape, sexual harassment, trafficking, child sexual abuse, medical examination of victims, police, electoral and educational reforms. Based on some of the recommendations of the Justice Verma Committee (JVC) report, an anti-rape Ordinance was enacted and signed by the Honourable President of India, Mr. Pranab Mukherjee on February 03, 2013. The Criminal Law (Amendment) Bill, 2013, passed in the parliament".

The Criminal Law (Amendment) Act, 2013, an Indian legislation passed by the Lok Sabha on 19 March 2013, and by the Rajya Sabha on 21 March 2013, provides for amendment of Indian Penal Code, Indian Evidence Act, and Code of Criminal Procedure, 1973 on laws related to sexual offences. The Bill received Presidential assent on 2 April 2013 and deemed to come into force from 3 February 2013. It was originally an Ordinance promulgated by the President of India, Pranab Mukherjee, on 3 February 2013. By the Amendment Act section 375 and 376, IPC were extensively amended and certain more penal provisions were incorporated for punishing those who molest a woman under their custody or care. .

**Some of the important changes brought about by the Act 13 of 2013 and other provisions are listed below:**

- (i) Consent of a woman of unsound mind: or under intoxication etc.,
- (ii) Burden of Proof of innocence on accused.
- (iii) Prohibition of disclosure of identify of the victim.
- (iv) President Vegetative State.
- (v) Trial in Camera
- (vi) Custodial Rape.
- (vii) Intercourse with wife during judicial separation prohibited.
- (viii) Minimum punishment for rape.
- (ix) Consent of a girl under eighteen years not valid in law.

**Current Scenario - After Delhi Gang Rape Government Of India (GOI) Passed Criminal Law (Amendment) Act,**

2013 to protect Indian Females from Sexual Violence. But still now result is very horrible.

### **CNN publish news as “ India the most dangerous country to be a woman, US ranks 10th in survey**

By Angela Dewan, CNN

Updated 1051 GMT (1851 HKT) June 26, 2018

**The Thomson Reuters Foundation** released its results Tuesday of a survey of 550 experts on women's issues, finding India to be the most dangerous nation for sexual violence against women, as well as human trafficking for domestic work, forced labor, forced marriage and sexual slavery, among other reasons.

It was also the most dangerous country in the world for cultural traditions that impact women, the survey found, citing acid attacks, female genital mutilation, child marriage and physical abuse. India was the fourth most dangerous country for women in the same survey seven years ago.

### **Another attempt to protect Indian Women and Female Child by doing - “THE CRIMINAL LAW (AMENDMENT) ACT, 2018 NO. 22 OF 2018” :**

“The Criminal Law Amendment Act, 2018 is also a consequence of such barbaric incidents which shook the conscience of the entire nation. The demand for making anti-rape laws more stringent had started developing due to various child rape incidents. The infamous **Kathua rape case** and the **Unnao rape case** triggered this demand and this gave birth to the amendment of 2018.”

“If there is humanity in this country, this case has to be seen with such eyes. It's not just me that has lost a daughter. Hindustan ki beti bhi thi woh (she was a daughter of India)”

Muhammad Yusuf Pujwala, father of the eight years old girl **Asifa Bano**.

**Brief facts of Kathua rape case:** Asifa Bano was an eight years old girl of Rasana village near Kathua in the Indian state of Jammu and Kashmir, when she was gang-raped and then murdered by the culprits. This horrible incidence occurred in between 10th to 12th January 2018. “Nirbhaya” rape incident on 16<sup>th</sup> December, 2012, was an eye opener to the government of India who then assured its citizens that it should be the last case of that list. The “brutal” “Nirbhaya” rapists were hanged till death with an intention to stop crime of this intensity. But, unfortunately, for millions of Indian women ‘Nirbhaya’ was not the last example of brutality. India saw a new chapter of brutality by the name of ‘Asifa Bano’. Unfortunately, these are not the only two serious cases of crime against women and/ or girls in India.

**Brief facts of Unnao rape case -** The Unnao rape case was another shock to the nation where a teenage girl accused an MLA of raping her in the year 2017. She tried to set herself on fire in front of the MLA's residence in Unnao, northern Uttar Pradesh

Unnao rape case Victim Dies: ‘The 23-year-old died late on Friday after suffering cardiac arrest at a Delhi hospital. She had 90% burns.

She was attacked on Thursday as she was walking to a hearing in the rape case she filed against two men in March in Unnao, in northern Uttar Pradesh state.

**THE CRIMINAL LAW (AMENDMENT) ACT, 2018** Bill was passed by the Parliament on 6th August 2018. The President gave assent to the Bill and thus, the Criminal Law (Amendment) Act, 2018 came into force.

### **PART A: HIGHLIGHTS OF THE BILL**

**Context -** Rape of women and minor children is an offence under the Indian Penal Code (IPC), 1860, and the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012. In 2016, 21% of the total 39,068 cases of rape were against minor girls below the age of 16 years.[1] Over the last year, several states have introduced or passed Bills to allow death penalty for rape of girls below the age of 12 years.[2] On April 21, 2018, the government promulgated the Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2018.

**Key Features -** The Ordinance amends the IPC, 1860, POCSO Act, 2012 and other laws related to rape of women. The POCSO Act states that the punishment which is higher between the POCSO Act and the IPC will apply to rape of minors.

### **Table 1 (see in last page)**

1. Under the Code of Criminal Procedure, 1973 investigation into the rape of a child must be completed within three months. The Ordinance reduces this time period to two months for all rape cases.
2. The Ordinance bars anticipatory bail in cases of rape of minor girls below 16 years of age. Further, any appeal against a sentence for rape cases must be disposed of within six months.

### **PART B: KEY ISSUES AND ANALYSIS**

#### **Gender-based differences in the definition of rape and punishment**

**Definition of rape is not gender neutral -** In the case of rape of minors, according to the POCSO Act, the victim may either be male or female (and the offender could also be of either gender). However, in cases of adults under the IPC, rape is as an offence only if the offender is male and the victim is female. The Law Commission of India (2000) and the Justice Verma Committee (2013) had recommended that this definition of rape should be made gender neutral and should apply equally to both male and female victims.[3][4] The Ordinance does not address this issue.

**Widening difference in punishment between rape of girls and boys -** The POCSO Act states that the higher punishment specified in it or in the IPC will apply for rape of minors. The POCSO Act has the same penalty for rape when the victim is a boy or a girl. However, the IPC provisions which apply only to rape of female victims carry a higher punishment. The Ordinance further widens this difference. Table 2 summarises the differences in punishment for rape of minor boys and girls.

### **Table 2 (see in last page)**

**Conclusion -** Sexual Violence -rape, Child Sexual Violence

( CSA ) mainly with female Child, and domestic violence are prevalent in India. According to the National Crime Records Bureau (NCRB) for the year 2017, there were **3.59** lakh registered cases of crimes against women in 2017, which means a crime was committed against women every one and a half minutes during the year. Where the Rape Cased- **32,559**, the number of victims was **33,658**, Attempt to Commit Rape- **4154**, the number of victims was **4372**. According to the report, 93.1% rapes were committed by offenders known to the victims. The victims of rape were girls under the age of 18 in a shocking 30.9% of the cases. Children from Sexual Violence (**POCSO**) Act that had female victims accounted for 8.8% of all crimes against women. The number of cases across India was 31,668. Cyber Crimes- sexual exploitation cases are 1,460 cases, Voyeurism—1090 cases, Stalking- 8145

Report revealed that the number of crimes committed against women have increased in 2017 by 6 per cent compared to 2016 and by 9 per cent compared to 2015. Contrast this with the fact that conviction rates have remained low and not more than 25 per cent of the reported rape cases. We made various tough laws to protect women and children from sexual violence, but as per NCRB data suggests still we are struggling to **protect** half the members of societies. Many women do not come out and report, simply because justice is not just delayed, it is more often than not, denied.

We have many tough laws to protect women and female children. However, existing research shows persistent gaps in enforcing the laws, relevant policies, and guidelines aimed at justice for victims of sexual violence. It is urged that comprehensive studies should be undertaken at the earliest in India to provide a basis for measures taken to fight this big problem. It is only through research that one can hope to get insight into the genesis of this and afford protection to women. It is essential to provide women with an environment, where they are mentally and physically safe. Any society, in which half the members live in perpetual fear, need to re-evaluate its claim of being civilised.

#### Suggestions:

1. Today only strict laws are not enough to protect, but higher conviction rates will make India safer for Women. It can be achieved by- police reforms, educational reforms, training of personnel in the criminal justice system, services such as well equipped rape-crisis centres. The new amendments are only a start and a law is nothing if it's not enforced.
2. Today need of legal-judicial system will be made more responsive and gender sensitive to women's needs, especially in cases of Sexual Violence. New laws will be enacted and existing laws reviewed to ensure that justice is quick and the punishment must be awarded to culprits to ensure justice.
3. Along with the tough laws and fast justice system we need improvement in the social indicators, viz., female education, favourable sex ratio, etc., are required for

efficient control of sexual offences.

**Mr. Amir Khan**, a prominent actor and social worker in his programme 'Satymeve Jayate' based on the scientific research, has stressed that almost 80% of the women in India are suffering with the domestic violence. It is not the wife only facing the agony of domestic violence by husband but daughter is facing the domestic violence by father, sister by brother, granddaughter by grandfather etc. Male preference is a dominant feature of Indian society which resulted in 'foeticide' consequently disturbing the sex ratio in Indian social structure. In fact, the men want to control and regulate the life of the women at their whims. Proper attention on education, nutrition, food and other social benefits is not given for the women.

**In this horrible situation where each and every female child to old are on the verge of danger to become victims of Sexual Offences.**

#### References :-

1. (CWSA, Vol. 13, pp. 27-28).
2. Manusmriti;- III,56
3. Subhamoy Basu, „Position of Women in Pre-Independence Era: A Socio-Political Perspective in Rathin Bandopadhyay, Sanjay Kumar Singh et al (eds), „Women Rights Human Rights , R. Cambray & Co Pvt Ltd, Kolkata, 2010, pp 76-85 at pp 77.
4. Willem de Haan, Violence as an essentially contested concept, 2008, Retrieved from: [http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-0-387-74508-4\\_3](http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-0-387-74508-4_3)
5. Kapoor and Dhingra / OIDA International Journal of Sustainable Development 06: 10 (2013)
6. <https://www.linkedin.com/pulse/women-work-environment-victor-tembo-mcips-cipp-miapm>
7. WHO:-[https://www.who.int/violence\\_injury\\_prevention/resources/publications/en/guidelines\\_chap2.pdf](https://www.who.int/violence_injury_prevention/resources/publications/en/guidelines_chap2.pdf)
8. Wikipedia: [https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual\\_violence#cite\\_note-15](https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_violence#cite_note-15)
9. Wikipedia: Rome Statute of the International Criminal Court (ICC)
10. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/sexual%20assault>
11. Sexual Abuse of the Girl Child – Dr. Ashok Bhiman
12. Article 1, the Convention on the Rights of Child, 1989.
13. Section 82 , the Indian Penal Code, 1860.
14. Section 83 ,Id.
15. Section 361, Id.
16. Section 375 ,Id.
17. Section 2(a) ,the Immoral Trafficking (Prevention) Act, 1956
18. Section 2(d) , the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.
19. Section 12(12) , the Juvenile Justice(Care and Protection of Children) Act,2015.
20. 7 Child Sexual Abuse – World Health Organization, available at [www.who.int>guidelines\\_chap7](http://www.who.int>guidelines_chap7)
21. The world health organization
22. Sexual Offences against female Child in India: Dr. Raj

- Kumar Yadav Tundak LL.M., NET, Ph.D. (Law)
23. Sexual Offences against female Child in India Dr. Raj Kumar Yadav Tundak LL.M., NET, Ph.D. (Law)
  24. UN Women condemns gang rape of Delhi student, <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2012/12/un-women-condemns-gangrape-of-Delhi-student/>, last accessed on 3rd February, 2014
  25. The Gazette of India, Department of Publication, Ministry of Urban Development, Government of India, <http://egazette.nic.in/RecentUploads.aspx?Category=1> (accessed April 16, 2013)
  26. (CNN)India is the most dangerous country in the world to be a woman because of the high risk of sexual violence and slave labor, a new survey of experts shows. (<https://edition.cnn.com/2018/06/25/health/india-dangerous-country-women-survey-intl/index.html>) By Angela Dewan, CNN Updated 1051 GMT (1851 HKT) June 26, 2018
  27. <https://blog.ipleaders.in/criminal-law-amendment-act-2018/>
  28. Times of India, 15/04/2018.
  29. Journal of International Women's Studies Vol. 20, No. 2 January 2019 )
  30. <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50697139>
  31. Sources: POCSO, 2012; Indian Penal Code, 1860; The Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2018; PRS.

**Table 1: Major changes proposed in Criminal Law (Amendment) Bill, 2018**

Age of woman	Offence	Punishment under IPC, 1860	Criminal Law (Amendment) Bill, 2018
Below 12 years	Rape	Minimum: 10 years Maximum: life imprisonment	Minimum: 20 years Maximum: life imprisonment or death
	Gang Rape	Minimum: 20 years Maximum: life imprisonment	Minimum: life imprisonment Maximum: life imprisonment or death
Below 16 years	Rape	Minimum: 10 years Maximum: life imprisonment	Minimum: 20 years Maximum: no change
	Gang Rape	Minimum: 20 years Maximum: life imprisonment	Minimum: life imprisonment Maximum: no provision
16 years and above	Rape	Minimum: 7 years Maximum: life imprisonment	Minimum: 10 years Maximum: no change

**Table 2: Differences in punishment for rape between minor boys and girls**

Age (in years)	Boys	Girls (Before 2018 Ordinance)	Girls (After 2018 Ordinance)
Below 12	10 years to life imprisonment	10 years to life imprisonment	20 years to life imprisonment/death
12-16	7 years to life imprisonment	10 years to life imprisonment	20 years to life imprisonment
16-18	7 years to life imprisonment	7 years to life imprisonment	10 years to life imprisonment

\*\*\*\*\*



## कोरोना, भूगोल एवं समाज

डॉ. सौरभ त्यागी \*

**प्रस्तावना** – मानव सभ्यता के साथ महामारियों का बहुत प्राचीन संबंध रहा है। सत्य तो यह है कि जैसे-जैसे मानव सभ्यताएं विकसित होती गईं वैसे-वैसे समाज में संक्रामक रोगों की संख्या भी बढ़ती गई। बढ़ती संख्या में लोगों के एक साथ रहने के कारण तथा जानवरों के साथ उनके निकट सम्पर्क ने प्रसवच्छता उत्पन्न कि और किसी भी प्रकार की बिमारी के लिए उर्वरक आधार प्रदान किया। इसके साथ ही नये विदेशी व्यापारिक मार्गों की खोज ने इसे दूर-दूर तक दूसरे देशों में फैलने में मदद की।

बिमारियों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया है। इनमें पहला प्रकार Endemic या स्थानीयमारी का है। ऐसी बिमारी जो किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष में लगातार बनी रहती है। उन्हें EPedimics या स्थानीयमारी की संज्ञा दी गयी। जिसका दूसरा प्रकार EPedimics या महामारी के नाम से जाना जाता है। महामारी की संज्ञा उस बिमारी को दी गयी जो अप्रत्याशित रूप से एक निश्चित समय में भिन्न-भिन्न स्थानों पर व्यापक रूप से फैल जाए। तीसरे प्रकार को Pandemic, देशान्तरगामी व वैश्विक महामारी के नाम से जाना गया। ऐसी महामारी जो विश्व के प्रायः महाद्वीपों व देशों में फैल जाए उसे वैश्विक, देशान्तरगामी या Pandemic की संज्ञा दी गई। जैसे फरवरी से पहले तक कोरोना बीमारी चीन के 'वुहान' शहर तक सीमित थी किंतु मार्च 2020 के आते आते इसने विश्व के लगभग 196 देशों को अपने गिरफ्त में ले लिया।

महामारियों का इतिहास अत्यन्त पुराना है। प्रागैतिहासिक काल से ही इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आज से लगभग तीन हजार ई.पू. चीन के पुरातात्विक स्थल 'यमनगंगा' में एक महामारी द्वारा उस ग्राम के नष्ट होने के साक्ष्य मानवशास्त्रियों को प्राप्त हुए हैं। वहाँ विशाल संख्या में हुए अकाल मृत्यु के कारण शवों को एक घर के अंदर भर कर जलाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसमें किशोर, युवा, व्यस्क तथा मध्यम आयु वर्ग के लोगों के कंकाल समान रूप से मिले हैं। लगभग उसी अवधि में पूर्वोत्तर चीन के एक अन्य पुरातात्विक स्थल 'भियाओइंगो' में भी भारी संख्या में लोगों के दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ईसा पूर्व युग में 41 महामारियों के अभिलेख मिलते हैं। ईसा के समय से सन् 1500 ई. तक 109 बड़ी बीमारियों के बारे में पता चलता है। स्पष्ट है कि इन महामारियों का इतिहास बहुत प्राचीन है। स्पष्ट है कि मानव सभ्यता के साथ साथ महामारियों का भी स्थान है। उस समय से लेकर आज तक हर बार इन महामारियों के कारण आर्थिक स्थिति सर्वाधिक प्रभावित हुई। भूखमरी और बेरोजगारी के कारण देश व समाज की स्थिति काफी खराब हो गई। वैश्विक वित्तीय परिणाम को ठीक होने में बहुत समय लगा। वर्तमान समय के कोरोना वायरस कोविड 19 ने भारत सहित संपूर्ण विश्व को आतंकित करके रखा है। इसके प्रसार की व्यापकता को देखते हुए

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी बोधित किया।

चीन के एक छोटे से स्थान वुहान से निकला यह वायरस आज लगभग सम्पूर्ण विश्व को जकड़ चुका है। आशा करता हूँ कि जल्द ही हम इस से पार पा लेंगे। भूगोल पृथ्वी का स्थानिक एवं सामयिक अध्ययन है और कोरोना के भौगोलिक पक्ष को नकारा नहीं जा सकता है। भूगोल की एक अवधारणा है निश्चयवाद, जिसके समर्थको द्वारा प्रकृति को मानव से अधिक शक्ति शाली माना गया है। प्रकृति, मानव की क्रियाओं, संस्कृति, व्यवहार को नियंत्रित करती है। कोरोना के कारण शायद प्रकृति, अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश दे रही है कि प्रकृति, को उसे कुचल कर दिया गया विकास मंजूर नहीं है। कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक दूरी की बजाय भौगोलिक दूरी (Geographical distance) शब्द अधिक प्रासंगिक एवं मानवीय प्रतीत होता है। 35° से 45° उत्तरी अक्षांश तक कोरोना के अधिक मामले और 45° से ऊपरी अक्षांश पर स्थित देशों में भी कोरोना का कुप्रभाव देखा गया है। जैसे- **न्यूयॉर्क** 40°73 **इटली** 38° से 45° उत्तरी अक्षांश, **स्पेल** 36° से 42°, **चीन** अधिकतर जनसंख्या 35° से 45° के मध्य, **ईरान** के उत्तरी इलाके में अधिक केस 350 के आसपास इन देशों में संक्रमण अधिक होने के कारण अधिक ठंडा होना है। ध्यातव्य रहे कि गरम जलवायु इस वायरस के प्रभाव को कम तो करती है परन्तु पूर्णतः खत्म नहीं करती है। जनसंख्या घनत्व (Population Density) कम होना भी संक्रमण को कम करता है जैसा कि पहले भी जिक्र किया है कि भौगोलिक दूरी जरूरी है इसलिए राजस्थान जैसे बड़े राज्य में, विशेषतः मरुभूमि में इसके बहुत कम मामले सामने आ रहे हैं। केरल की सड़को पर विचरण करते जीव 1990 के बाद से देखा नहीं गया था। प्रकृति का मानव को संदेश यह है कि जैव विविधता को बनाए रखना अत्यंत जरूरी है। मर्किडर और महान जैसे भू-राजनीतिज्ञों के सिद्धान्तों को भी इस परिप्रेक्ष्य में चुनौती मिली है कि जल शक्ति (भौगोलिक शक्ति) के साथ साथ यदि विज्ञान का इस्तेमाल कूटनीति, छद्म युद्ध या अप्रत्यक्ष युद्ध में किया जाए तो यह पूरे विश्व के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।

माल्थस के जनसंख्या सिद्धान्त के अनुसार यदि जनसंख्या में वृद्धि सीमा से अधिक होती है तो उसे युद्ध, महामारी या अकास स्वतः कम कर देते हैं। आशा करता हूँ कि ऐसा ना हो परन्तु कुछ ऐसा ही हो रहा है। प्रवास (Migration) के फलस्वरूप ही कोरोना वायरस हमारे देश में आया है। अतः हमें हमारी प्रवास नीति में महामारी से निपटने हेतु प्रावधान रखे जाने चाहिए। Reverse migration भी देखने को मिल रहा है। लोग शहरों से गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। भूगोल पृथ्वी का स्थानिक (Spatial) के

साथ साथ सामयिक (Temporal) अध्ययन भी है 1720 प्लेग 1820 हैजा 1920 स्पेनिश फ्लू 2003 सार्स, 2009 स्वाइन फ्लू, 2014 ईबोला 2020 कोरोना सामयिक अध्ययन यह बताता है कि समय के साथ ऐसी महामारी बढ़ती जा रही हैं और (zoonotic diseases) पशुजन्य रोगों को रोकना जरूरी है। प्रकृति से संतुलन जरूरी है। किसी स्थान का अधिवास प्रारूप (settlement pattern) महामारी को बढ़ा सकता है। जैसे की बस्तियों में इसका संक्रमण बढ़ने की ज्यादा संभावना है। Gated community होने के कारण चीन कोरोना संक्रमण को कम करने में कामयाब रहा है। GIS भौगोलिक सूचना तंत्र इस महामारी को रोकने में काफी हद तक मददगार साबित हो रहा है जैसे Map making

कोरोना Hot spot (तप्त स्थल) की पहचान कर Geo-fencing कर इसके संक्रमण को रोका जा सकता है। आरोग्य सेतु एप इसी प्रयोजन हेतु लॉन्च किया गया है। समय regional approach की बजाय, systematic approach अपनाने का है क्योंकि एक ही महामारी से विश्व स्तर पर हर किसी को लड़ना है। रीटर के सिद्धांत Unity in diversity को यदि इस संदर्भ में लागू किया जाए तो आज सभी देशों में जैविक और अजैविक रूप से भिन्नता होने के बावजूद, एक इकाई के रूप में काम कर रहे हैं। मुसीबत के समय में हमें ऐसा करना भी चाहिए। सभी देश एक दूसरे को मदद करेंगे तभी हम इस महामारी से उभर पाएंगे।

इस संक्रामक बीमारी को रोकने नियंत्रित व पराजित करने का एकमात्र तरीका लोगों द्वारा सामाजिक दूरियों का पालन करना और सामाजिक संपर्क से बचने के लिए उन्हें बाहर आने से रोकना था। इस उद्देश्य को प्रभावित ढंग से प्राप्त करने के लिए संपूर्ण देश में लॉकडाउन करना पड़ा इसलिए देश को अनिवार्य रूप से लॉकडाउन के तहत लाया गया। भारत सरकार ने इस महामारी व इसके खिलाफ कड़ा रूप अपनाना शुरू कर दिया।

कोविड 19 महामारी के व्याख्या किए गए लॉकडाउन का संपूर्ण विश्व पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े।

इसका सकारात्मक पक्ष यह रहा कि स्वच्छता के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए हाथों को बार-बार साबुन से धोना या सेनेटाइजर करना अति आवश्यक माना गया। अतः लोग स्वच्छता के प्रति सचेत हुए। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर थूकने, खासने, छीकने की मनायी व मास्क लगाकर घर से निकलना कानूनीत किया गया। बाहर से लाई गई वस्तुओं को सेनेटाइजर करके रखना, घर की स्वच्छता, साफ सफाई के प्रति कोविड 19 के प्रभाव स्वरूप प्रकृति स्वच्छ हो गयी। नदियां निर्मल व आकाश नीला दिखाई देने लगा। दुर्लभ पशु, पक्षी विचरण करते दिखने लगे। हवा शुद्ध हो गयी प्रदूषण का स्तर घट गया। ओजोन परत में सुधार हो रहा है।

लोगों को भाग दौड़ की यंथावत जिंदगी से निजात मिली। लॉक डाउन के कारण हर व्यक्ति को अपने परिवार के साथ समय बिताने का आनन्ददायी अवसर मिला। बदलाव और मनोरंजन के नाम पर होटल, रेस्टोरेट के जांच व अस्वास्थ्य प्रद फूड के स्थान पर शुद्ध बने विविध प्रकार के स्वादिष्ट, पौष्टिक व स्वास्थ्य वर्दक भोजन ने लिया। रसोई और ग्रहकार्य में परिवार के सभी सदस्यों की भागीदारी की स्वच्छ परम्परा का आरंभ हुआ।

समाज में दिखावे के स्थान पर सादगी ने प्रभाव दिखाया। लोगों को अहसास हुआ कि जीवन के आवश्यक खर्च बहुत कम है। ज्यादा खर्च अनावश्यक खरीदारी, विलासिता व दिखावा के नाम पर होता है। अतः जीवन के प्रति लोगों की सोच में परिवर्तन आया।

समाज के बहुत से लोग समाज के निर्धन, गरीब, श्रमिक या मुसीबत में फंसे लोगों को हर प्रकार से मदद पहुँचाने की चेष्टा में दिन से लगे रहे। अनेक समाज सेवी संस्थाओं, दान व्यर्थों ने जरूरत मंदों के लिए हर प्रकार से अपनी झोली खोल तन मन और धन से उन्होंने अपनी सेवाएं दीं।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के तहत ऑन लाईन कार्यों का महत्व रहा। घर से ही कार्यालयों, स्कूल की पढ़ाई और वेबीनार होने लगे। अर्थात काम-काज रूका पर उनका रूप बदल गया। आज और अभी हम सभी इस वेबीनार के माध्यम से ही जुड़े हैं। टू लर्निंग की तरफ लोगों का सम्मान बढ़ा।

किन्तु सिक्के के दो पहलू की तरह इस महामारी के नकारात्मक पक्षों से इंकार नहीं किया जा सकता कोविड 19 का सकारात्मक प्रभाव प्रायः साधन सम्पन्न वर्ग पर पड़ा किन्तु समाज के निर्धनतम और निर्बलतम वर्ग के लोगों के लिए काफी विनाशकारी सिद्ध हुआ है। व्यवसाय, यात्रा, पर्यटन व अन्य सेवा क्षेत्रों के बंद होने से दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों, सड़क किनारे के छोटे विक्रेताओं तथा छोटे व्यापारियों के अस्तित्व को इसके कारण गहरी चोट पहुँची है। बेरोजगारी में अप्रत्याक्षित वृद्धि व उनके काम के बंद स्रोतों ने उनकी आर्थिक स्थिति को गहरी चोट पहुँचाई है। अपनी आजीविका खोने वाले लोगों के सामने कठिन समस्या है। कोविड 19 महामारी के बीच भारत की देश व्यापी लॉकडाउन ने प्रवासी कारोवारी को गंभीर रूप से विस्थापित कर दिया है। रोजगार और धन की कमी तथा सार्वजनिक परिवहन से जाने के कारण लाखों प्रवासियों का अपने घर गांवों के लिए सैंकड़ों मिल पैदल चलने के लिए मजबूर किया है। इसमें अनेक मजदूरों की मृत्यु भी हो गयी। आज मजदूर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके अधिकारों को पहले से कहीं अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। उन्हें भोजन और धन के संदर्भ में तत्काल ठोस मदद की आवश्यकता है।

लॉकडाउन पिरियड से अब तक लगभग सभी बच्चे स्कूलों से बाहर है। कुछ विद्यालय अपने विद्यार्थियों को Distance Learning के द्वारा शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। किन्तु सभी स्कूली बच्चों को यह उपलब्ध नहीं है। धीमी तथा महंगी इंटरनेट सेवाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों व दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थी ज्ञान से वंचित साबित हो रहे हैं। साथ ही Wold Health Organisation ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि दुनिया के लगभग 31 करोड़ स्कूली बच्चे अपने नियमित दैनिक पोषण के स्रोत के लिए स्कूलों पर निर्भर हैं। स्कूलों के बंद होने से उनकी निर्भरता अपने परिवार पर आ गयी है।

किन्तु इस महामारी के कारण परिवार की आय में भी कमी होने के कारण आवश्यक छोटे खाद्य प्रदार्थों की उपलब्धता से वंचित रहना पड़ रहा है। महामारी के कारण स्वास्थ्य सेनाओं के बढ़ते बोझ के कारण बीमार बच्चों के लिए भी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता कम हो गई है लॉकडाउन इसके दौरान अनुश्रमिक स्वास्थ्य संबंधी कई अन्य चिंताओं जैसे गंभीर रोगी महिलाओं प्रशुताओं के स्वास्थ्य, टीकाकरण की अनदेखी की गई। यह सभी चिंता का विषय है। वैश्विक आर्थिक मंदी तेजी पकड़ रही है। जिसके कारण 2020 के दौरान लाखों बच्चों की मौत की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

भारत के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण है। शिक्षा, स्वस्थ आचरण के प्रति जागरूकता की कमी देश के अनेक हिस्सों और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली की विकट समस्या है। भारत के बड़े शहरों के अनियंत्रित आबादी के घनत्व के कारण सार्वजनिक संसाधनों और सेवाओं पर बहुत दबाव की स्थिति रहती है।

ऐसे समय में जब विश्व घातक विश्वव्यापी महामारी से जूझ रहा है। और लोगों की जिंदगीयों को बचाने के लिए स्पष्ट तथ्यों की तलाश चल रही है। तभी सोशल मिडिया द्वारा गलत और भ्रामक जानकारीयों ने जनसाधारण के समक्ष मनोवैज्ञानिक रूप से भय और खौफ का वातावरण उत्पन्न कर दिया है।

इस चुनौती को की संज्ञा दी गई है। अतः लोगो में, जनसाधारण में भरोसा और विश्वास उत्पन्न करने की अनावश्यकता है। श्रमिकों का शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर पलायन इसी misinto-Lemic का परिणाम था।

कोरोना के भय से कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्भाव और कृतज्ञता दिखाने के बजाय उनके मकान मालिकों द्वारा अपने किराए के घरों को खाली करने के लिए कहा गया। डाक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स नर्सज व पुलिस के खिलाफ हिंसा की घटनाएँ भी देखने को मिली।

लॉकडाउन के दौरान 'पैनिक वार्निंग' की घटनाएँ भी देखने को मिली। दूसरो की चिंता किये बगैर लोगों के रसद व अन्य आवश्यक वस्तुओं की अनुचित खरीद और स्टार्किंग की गयी।

यह समय हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। हमें आज सामाजिक रूप से अधिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। मानवीयता के को बढ़ाने की आशा एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनने की आवश्यकता है। एक लचीला समाज बनाने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम समान विकास को प्रोत्साहित करें। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, इमोशनल या ह्युमन डिस्टेंसिंग नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब यहा इस बीमारी के दौर से लोगों के सम्पर्क से दूर रहना है न कि सामाजिक रिश्ते को खत्म करना है। World Health Organization ने भी अपने प्रेस रिलीज में सोशल डिस्टेंसिंग की जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द के उपयोग की बात कही

है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग से समाज में गलत संदेश जा रहा है और लोगों में परस्पर प्रेम, अपनत्व और सहयोग की भावना कम होती जा रही है।

कोविड- 19 के खिलाफ जंग अभी जारी रहेगी। संभव है कि कुछ क्षेत्रों, स्थानों में धीरे धीरे छूट की वजह से संक्रमण की पुनरावृत्ति हो जाए। यह प्रक्रिया अगले कई महिनो या साल तक जारी रह सकती है जब तक कि इसकी असरदार वैक्सीन और दवाईयाँ उपलब्ध नहीं हो जाती।

कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए आवश्यक है कि हम स्वास्थ्य अधिकारियों, चिकित्सकों द्वारा सुझाए गए साधारण मगर कारगर उपायों का पालन करें। इस बीमारी के सम्बन्ध में हमें डराने, डरने या तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है बल्कि सजग रहना है। स्वच्छता का सर्वोपरि स्थान देते हुए स्वच्छ आहार और व्यवसाय द्वारा शरीर को स्वस्थ रखना है ताकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो और हम सभी प्रकार की बीमारीयों से बचे रहे। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक तनाव, चिंता और खौफ के वातावरण से स्वयं को मुक्त रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें। जिससे हमारे आत्म विश्वास में वृद्धि हो, शक्ति और उर्जा प्राप्त कर हम अधिक गतिशील बनें। पूरे समाज को यह समझाना होगा कि कोरोना का सम्बन्ध किसी एक धर्म, जाति से नहीं है अतः सभी को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कौशिक, एच.डी. रस्तोगी पब्लिकेशन्स मेरठ 2001
2. जाट, बी.सी. पंचशील प्रकाशन, जयपुर 2016
3. नेगी, पी. एस. रस्तोगी पब्लिकेशन्स मेरठ 2006-07
4. हुसैन, माजिद रावत पब्लिकेशन्स दिल्ली 2004
5. सक्सेना, एल. के. राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 2003
6. समाचार पत्र-पत्रिकायें व इनटरनेट

\*\*\*\*\*

## माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य, स्वच्छता सम्बन्धित आदतों एवं योगा के प्रति अभिवृत्ति का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. प्रीति शोवर \* आरती \*\*

**शोध सारांश** – प्रस्तुत शोध कार्य में माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य, स्वच्छता सम्बन्धित आदतों एवं योगा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया है। अध्ययन में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किए हैं। इस हेतु मानसिक स्वास्थ्य मापनी – ए.के. सिंह व अल्पना सेन गुप्ता, योग के प्रति अभिवृत्ति – महेश कुमार मुच्छल तथा स्वच्छता मापनी – स्वनिर्मित का उपयोग किया गया है। प्रति अभिवृत्त व स्वच्छता सम्बन्धित आदतों में सकारात्मक सहसम्बन्ध पाया गया है।

**प्रस्तावना** – 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देशभर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की परिकल्पना को स्वीकार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का मंत्र 'न गंदगी करेंगे, ना करने दें' दिया। किशोरावस्था और व्यस्कता के प्रारम्भिक वर्ष जीवन का एक ऐसा समय होता है जब कई बदलाव होते हैं, उदाहरण के लिए स्कूलों का बदलना, घर छोड़ना और विश्वविद्यालय या एक नई नौकरी शुरू करना। कुछ मामलों में यदि समस्या को पहचाना और प्रतिबन्धित नहीं किया जाता है तो ये भावनाएं मानसिक बीमारी का रूप ले सकती हैं। विद्यालय स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। योग विज्ञान एक गहन विज्ञान है, जो मानव के पूरे अस्तित्व और जीवन में तालमेल बनाए रखने की क्षमता देता है।

हमारी संस्कृति में स्वच्छता और योग का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका महत्व वर्तमान में न केवल भारत बल्कि विश्व ने भी समझा है। डी.एस.टी के सचिव और आई.आई.टी. कानपुर के सीनियर प्रोफेसर डॉ. आशुतोष शर्मा ने बताया कि योग, ध्यान के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभाग में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योगा एंड मैडिटेशन (सत्यम) योजना की शुरुआत की है। इन सभी योजनाओं की मजबूत नींव विद्यालयों से ही है तथा वर्तमान परिवेश की सभी स्वच्छता तथा स्वास्थ्य सभी समस्याओं का निपटारा विद्यालय स्तर पर किया जाना अति आवश्यक है।

प्रस्तुत शोध के अंतर्गत शोधकर्ता द्वारा यही जानने का प्रयास किया गया है कि क्या मानसिक स्वास्थ्य व स्वच्छता आदतों व योगा के प्रति अभिवृत्ति आपस में सहसम्बन्धित है या नहीं तथा इनका आपसी सह-सम्बन्ध किस सीमा तक मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं।

**समस्या कथन** – 'माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य, स्वच्छता सम्बन्धित आदतों एवं योगा के प्रति अभिवृत्ति का विश्लेषणात्मक अध्ययन'

**शोध के उद्देश्य :**

1. माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर स्वच्छता सम्बन्धी आदतों तथा योगा के प्रति अभिवृत्ति के प्रभाव का अध्ययन करना।

### शोध की परिकल्पनाएं :

1. माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य व स्वच्छता सम्बन्धी आदतों में सकारात्मक सहसम्बन्ध है।
2. माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य व योग के प्रति अभिवृद्धि में सकारात्मक सहसम्बन्ध है।
3. माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की स्वच्छता सम्बन्धी आदतों व योग के प्रति अभिवृत्ति में सकारात्मक सहसम्बन्ध है।

### न्यादर्श

कुलविद्यार्थी 600

ग्रामीण शहरी  
300 विद्यार्थी 300 विद्यार्थी

### उपकरण – शोध में प्रयुक्त उपकरण

1. मानसिक स्वास्थ्य मापनी – ए.के. सिंह, अल्पना सेन गुप्ता
2. योग के प्रति अभिवृत्ति – महेश कुमार मुच्छल
3. स्वच्छता मापनी – स्वनिर्मित

### अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी

1. माध्य
  2. मानक विचलन
  3. सह-सम्बन्ध
1. माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य व स्वच्छता सम्बन्धी आदतों के सकारात्मक सहसम्बन्ध है।

विद्यार्थी	मध्यमान	मानक विचलन	सहसम्बन्ध गुणांक
मानसिक स्वास्थ्य	91.5	45.57	0.71
स्वच्छता आदतें	37.5	15.11	



उपर्युक्त परिकल्पना का परीक्षण करने पर पाया गया कि माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सम्बन्धी आदतों से सम्बन्धित सहसम्बन्ध गुणांक ( $\gamma$ ) मान 0.71 है जोकि उच्च सहसम्बन्ध को दर्शाता है। अतः इस आधार पर निर्मित शून्य परिकल्पना को स्वीकृत किया जाता है तथा निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सम्बन्धी आदतों में सकारात्मक सहसम्बन्ध है।

2. माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य व योग के प्रति अभिवृत्ति में सकारात्मक सहसम्बन्ध है।

विद्यार्थी	मध्यमान	मानक विचलन	सहसम्बन्ध गुणांक
मानसिक स्वास्थ्य	91.5	45.57	0.68
योग	46	26.75	

उपर्युक्त परिकल्पना का परीक्षण करने पर पाया गया कि माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य तथा योग के प्रति अभिवृत्ति से सम्बन्धित सहसम्बन्ध गुणांक ( $\gamma$ ) मान 0.68 है जोकि उच्च सहसम्बन्ध को दर्शाता है। अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य तथा योग के प्रति अभिवृत्ति में सकारात्मक सहसम्बन्ध है।

3. माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की स्वच्छता सम्बन्धी आदतों व योग के प्रति अभिवृत्ति में सकारात्मक सहसम्बन्ध है।

विद्यार्थी	मध्यमान	मानक विचलन	सहसम्बन्ध गुणांक
मानसिक स्वास्थ्य	37.5	15.11	0.70
योग	46	26.75	

उपर्युक्त परिकल्पना का परीक्षण करने पर पाया गया कि माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्वच्छता सम्बन्धी आदतों व योग के प्रति अभिवृत्ति से सम्बन्धित सहसम्बन्ध गुणांक ( $\gamma$ ) मान 0.70 है जोकि उच्च सहसम्बन्ध को दर्शाता है। अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की स्वच्छता सम्बन्धित आदतों व योग के प्रति अभिवृत्ति में सकारात्मक सहसम्बन्ध है।

**भावी शोध हेतु निम्न सुझाव है :**

1. राजस्थान के अन्य जिलों के साथ तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है।
2. भावी शोध अध्ययन बी.एस.टी.सी. व बी.एड प्रशिक्षणार्थियों पर किया जा सकता है।

**संदर्भ ग्रन्थ सूची :-**

1. पी.डी. पाठक (2005) - 'शिक्षा मनोविज्ञान', पृष्ठ संख्या (410-415)
2. श्रीवास्तव, डॉ. डी. एन - 'सांख्यिकी एवं मापन', पृष्ठ संख्या (210-218)
3. जी.पी. शैरी - 'स्वास्थ्य शिक्षा' पृष्ठ संख्या (220-225)
4. डॉ. साधना आर्य - 'योगशिक्षा' राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, डॉ. परिमल देवनार्थ, नई दिल्ली पृष्ठ संख्या (25-50)
5. क्रोनोलॉजी - मई 2018

\*\*\*\*\*

# Position and Structure of Human Management

Dr. Saurabh Dubey\*

**Abstract** - Human asset the board division obligations can be extensively arranged by individual ,sorting out ,and profession territories. People the executives involves helping workers indentify their qualities and shortcomings “right their weaknesses ; and make their best a commitment to the endeavors. Helped out through an assortment of exercises, for example, execution surveys, preparing and testing. HRM technique looks to achieve such administration by applying a company’s work force needs with the objectives/goals of the organization.

**Key Words** - Human Resource Management , People, Organization.

**Introduction** - Hierarchical advancement in the interim ,center as a feature of bigger business of a change program. Which permits to the association to react to advancing outside and inside impacts. HR the executives capacities are in a perfect world situated close of the theoretic focus of the hierarchical ,with access to all regions of her business . Since the SRM office or director is accused of dealing with the profitability and improvement of laborers at all dimensions ,human asset personal ought to approach and the help of key leaders ,furthermore ,the HRM office ought to be arranged so that ills can successfully speak with all territories of the organization. Mischief structures shift generally from business to business, molded by the sort ,size ,and overseeing methods of insight of the association that they serve. Yet, most associations ,arrange. Mischief groups around the bunches of individuals to be helped they direct enlisting, managerial and different obligations in a focal find. Distinctive utilizes advancement bunches for every office are important to prepare or executing teaching. Interestingly some Harm offices are totally free and are composed simply by capacity. A similar preparing office ,for precedents ,serves all divisions of the association. As of late ,howler ,watches have refered to a chosen treed toward crucial reassessments of human resource structures and positions,” SA course of changing business conditions, changing hierarchical structures mind changing administration business conditions .changing initiative has been compelling human asset offices to adjust their points of view on their job a capacity practically over-night, “composed Johm Johnson in Business Quarterly.” Previously, organizations organized themselves on a brought together What’s more, compartmentalized premise head office, promoting, fabricating, shipping, and so on. They currently look to decentralize and to coordinate their tasks, creating cross utilitarian groups. Today, senior administration anticipates that HR should move past its customary, compartmentalized “shelter’ way to deal with a

progressively coordinated, decentralized help work. “Given this adjustment in desires, Johnston noticed that “an undeniably basic pattern in HR is to decentralize the HR capacity and make it responsible to explicit line the board. This improves the probability that HR is seen and included and activities partners. Notwithstanding, HR will hold a unified utilitarian relationship in regions where specific skill is genuinely required, “for example, pay and enlistment obligations.

**Human Resource Management-Basic Responsibility** - Human asset the board is worried about the improvement of the two people and the association in which they work. HRM, at that point, is locked in not just in verifying and building up the gifts of individual laborers, yet additionally in actualizing programs that improve correspondence and collaboration between those individual specialists so as to sustain hierarchical advancement. The essential obligations related with human asset the board incorporate occupation investigation and staffing, association and use of work drive estimation and evaluation of work constrain execution, usage of remuneration frameworks compel execution, implantation of remuneration frameworks for representatives, proficient advancement of laborers, and support of work drive.

Occupation investigation comprises of deciding frequently with the assistance of other organization territories the nature and obligations of different business positions. This can include assurance of the aptitudes and encounters important to sufficiently perform in a position, recognizable proof of occupation and industry patterns, and expectation of future work levels and expertise prerequisites. “work investigation is the foundation of HRM practice since it gives substantial data about occupations that is use to employ and advance individuals, build up wages, decide preparing necessities, and make other essential HRM practice since it gives legitimate data about jobs that is use to enlist and advance individuals, set up

wages, decide preparing requirements, and settle on other vital HRM choices, "expressed Thomas S. Bateman and Carl P. Zenithal in Management. Capacity and Strategy Staffing, in the interim, is the real procedure of dealing with the stream of faculty into, inside (through exchanges and advancement,) and out of an association. When the enrolling some portion of the staffing procedure has been finished, choices achieved through employment posting, interviews, reference checks, testing, and different devices.

Association use and support of an organization's work compel is another key capacity of HRM. This include structuring a hierarchical system that makes most extreme utilization of an undertaking's HR and setting up that makes greatest utilization of an endeavor's HR and building up frameworks of correspondence that assistance the association work in a brought together way. Different obligations around there incorporate wellbeing and wellbeing and laborer the board relations. Human asset support actuates identified with security and wellbeing more often than not involve consistence with government laws that shield representatives from risks in the work environment. These direction are passed on from a few government organizations, including the word related Safety and Health Administration (OSHA) and the Environmental security Agency (EPA), and different state offices, which execute laws in the domains of laborer's pay, representative assurance, and different territories. Involve: working with trade guilds; dealing with complaints identified with offense, for example, burglary or lewd behavior; and demising correspondence framework to encourage collaboration and shared feeling of mission among representatives. Execution examination is the act of surveying worker work execution and giving input to those 3employees about both positive and negative parts of their execution. Execution estimations are essential both for the association and the person for they are the essential date utilized in deciding pay builds, advancements, and, on account of laborers who perform unacceptably, rejection. Reward frameworks are regularly overseen by HR territories too. This part of human asset the board is critical. For it is the system by which associations furnish their workers with remunerations for past accomplishments and motivating forces for elite later on. It is likewise the instrument by which associations address issues inside their work compel, through organization of disciplinary measures. Adjusting the work drive with organization objectives, expressed Gubman, "requires offering specialists a business relationship that rouses them to take responsibility for field-tested strategy." Representative improvement and preparing is another essential duty of HR work force. HR is in charge of examining an association's preparation needs, and for starting and assessing worker advancement programs intended to address those requirements. These preparation projects can go from introduction programs, which are intended to adjust new contracts to the organization to goal-oriented training programs expected to acquaint specialists

with another product framework.

"In the wake of getting the correct ability into the association," composed Gubman, "the second customary test to HR is to adjust the workforce to the business – to always assemble the limit of the workforce to execute the marketable strategy. "This is done through execution evaluations, preparing, and different actuates. IN the domain of execution examination, HRM experts must devise uniform evaluation guidelines; create reexamine strategies, train administrators to oversee the examination, and work to guarantee that government directions are watched. Duties related with preparing and improvement exercises, in the interim, incorporate the assurance, plan, execution, and examination of instructive projects the HRM expert ought to be grant of the essentials of learning and inspiration, and should cautiously structure and screen preparing and advancement programs that advantage the general association just as the person. The significance of this part of a business' activity can barely be over-expressed. As Roberts, Seldom, and Roberts demonstrated in Human Resources Management "the nature of workers and their improvement through preparing and training are central point in deciding long haul gainfulness of an independent venture. Research has indicated explicit advantages that a private company gets from preparing and building up its laborers, including: expanded profitability; diminished worker turnover; expanded proficiency bringing about monetary profits; [and] diminished requirement for supervision. "

**Conclusion** - Important commitments to business forms are progressively perceived as inside the domain of dynamic human asset the executives rehearse. Obviously, human asset chiefs have dependably added to by and large business forms in specific regards by dispersing rules for and observing representative conduct, for example, or guaranteeing that the association is obeying work we-related administrative rules yet expanding quantities of organizations are fusing human asset administrators into different business forms also. Previously, human asset supervisors were thrown in a help job in which their contemplations on cost/advantage defenses and other operational parts of the business were once in a while requested. However, as Johnston noticed, the changing of business structures and the commercial center are making it progressively fundamental for entrepreneurs and officials to give careful consideration to the all around characterized and tight sets of responsibilities or job definitions. Sometimes totally new work relationship have created; working from home lasting low maintenance jobs and redistributing major non-vital capacities are winding up increasingly visit." All of these changes, which human asset directors are intensely engaged with, are essential factors in forming business execution.

#### References :-

1. Employee on boarding check list. "Human Resource

- Management". Human Resource Management. Retrieved 2019-12-14.
2. Chugh, Ritesh (January 2014). "Role of Human Resource Information Systems in an Educational Organization". Journal of Advanced Management Science.
3. "HRMS Software increase efficiency". artifyhcm.com. Retrieved 2020-06-
4. "HRMS for recruitment: everything you need to know". www.hrmsworld.com. Retrieved 2018-09-12.
5. <http://www.scribd.com/doc/39382840/HRM-in-Indian-Defence#scribd> MohitKabra on Oct15, 2010
6. [https://en.wikipedia.org/wiki/Indian\\_Armed\\_Forces](https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Armed_Forces)
7. <http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2003/htar-chapter13>.
8. <http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2003/htar-chapter13.pdf>
9. Principals and practices of management SCDL, Pune
10. www.itsa.org
11. www.iteris.com
12. www.emotionalintelligence.com
13. www.tc.gc.ca
14. <http://www.shrm.org>
15. <http://www.chforum.org>

\*\*\*\*\*



## समतामूलक समाज और बालिका शोधार्थियों में तनाव स्तर संबंधी अध्ययन

विनीता मुजाल्दे\* डॉ. मंजू शर्मा\*\*

**प्रस्तावना** – वर्तमान में व्यक्ति को अनेक मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तनों का सामना करना पड़ रहा है। यदि व्यक्ति इनके साथ समायोजन करने में सफल होता है तो उसका जीवन सुख, शान्तिमय हो जाता है। किन्तु असफल होने पर कुसमायोजन का शिकार होकर जीवन कुण्ठामय हो जाता है और वह अनेक प्रकार की चिन्ता करने लगता है। चूंकि शोध कार्य करने में अनेक संसाधनों की आवश्यकता होती है उन्हें जताना शोधार्थी के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। शोधार्थी की रुचि मेहनत के साथ-साथ समय, धन की उपलब्धता, पर्याप्त मात्रा में आवश्यक है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में राजीव गांधी शोध छात्रवृत्ति लेने वाली (40) बालिका शोधार्थियों को निदर्शन के रूप में लिया गया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकांश बालिका शोधार्थी दूरस्थ ग्रामीण अंचल के निवासी होते हैं तथा अधिकांश बालिका शोधार्थी के परिवार कृषि करते हैं जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। उनके पास संसाधनों की अति सीमित मात्रा में उपलब्धता होती है, और बगैर छात्रवृत्ति के शोधार्थी शोध कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं। छात्रवृत्ति संबंधी जागृति न होने से अनेक वर्षों तक वह शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में भी असमर्थ रहे हैं। वर्तमान में शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार में इस वर्ग के विद्यार्थी भी जागृत है तथा शोध कार्य में राजीव गांधी शोध छात्रवृत्ति का लाभ लेने हेतु अग्रसर हुए हैं।

तनाव की अवस्था में बालिका शोधार्थियों को समय एवं विशेष स्थिति के साथ समायोजन की आवश्यकता होती है। शोध कार्य करते समय जब संसाधनों की आवश्यकता होती है तो वह संसाधन न मिल पाने से शोधार्थियों का शोध कार्य प्रभावित होता है और शोध कार्य समय पर नहीं हो पाता है, जिससे बालिका शोधार्थी अक्सर तनाव में ही रहती है। कुछ बालिका शोधार्थियों में अत्यधिक तनाव होने पर उनकी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है और वह आत्मघाती फैसले लेते हैं क्योंकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बालिका शोधार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से होने के कारण प्रत्येक बालिका शोधार्थी की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति समान नहीं होती है और आर्थिक स्थिति भी ठीक न होने से बालिका शोधार्थी छोटी-छोटी बातों से परेशान हो जाती है और अत्यधिक तनाव की स्थिति में आ जाती है।

तनाव को किसी ऐसे शारीरिक, रासायनिक या भावनात्मक कारक के रूप में समझा जा सकता है जो बालिका शोधार्थियों में शारीरिक एवं मानसिक बैचेनी उत्पन्न करता है और वह रोग किसी अन्य बीमारी का कारण बन

सकता है।

वे बालिका शोधार्थी जो राजीव गांधी शोध छात्रवृत्ति का लाभ ले रहे हैं को ऑफिस कार्य में देरी, भ्रष्टाचार के कारण बालिका शोधार्थियों को समय-समय पर छात्रवृत्ति न मिल पाने के कारण शोध कार्य करने में अनेक बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। यही कारण है इस वर्ग के बालिका शोधार्थी कार्य करने में अत्यधिक कठिनाई अनुभव करते हैं। जिसके कारण उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिससे उनमें तनाव की स्थिति देखी जाती है।

सरकार द्वारा इस वर्ग के विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर कर पर्याप्त आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से राजीव गांधी शोध छात्रवृत्ति आरम्भ की गई है यह छात्रवृत्ति विशेषतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शोधार्थियों को दी जाती है।

**तनाव का अर्थ** – आधुनिक युग में बालिका शोधार्थी लक्ष्य प्राप्ति और इच्छापूर्ति के लिए लगातार प्रयासरत रहती है इस प्रयास में वह अमर्यादित स्पर्धा में सम्मिलित हो जाती है तो उसके कारण बालिकाओं में चिन्ता, दबाव, कुण्ठा इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं यदि बालिकाएँ शुरूआत से ही तनाव प्रबन्ध कर ले तो वह तनावग्रस्त नहीं होगी। प्रत्येक बालिका की कुछ न कुछ समस्याएँ और परेशानियाँ होती हैं। प्रत्येक बालिका शोधार्थी की व्यक्तिगत प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर नहीं करती की वह कितनी समस्याओं और परेशानियों का सामना करती है बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि वह इन समस्याओं और परेशानियों के प्रति किस प्रकार से समायोजन करती है।

तनाव के अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं और तनाव के अलावा स्ट्रेस का एक और अर्थ है वह है 'जोर देना' देखा जाये तो इस शब्द में ही इसका कारण और निवारण छिपा हुआ है। यानि जिस चीज पर हम जोर देते हैं जरूरत से ज्यादा हम जिसकी चिन्ता करते हैं वह चीज हमें तनाव देती है और किसी चीज पर हम जोर तभी देते हैं जब हम उस चीज को सहज भाव से स्वीकार नहीं करते हैं या स्वयं को उसके अनुकूल नहीं पाते हैं। तब हम खुद पर चाहे-अनचाहे, जाने अनजाने जोर देते हैं, दबाव डालते हैं यही प्रेशर हमारे सुख-चैन में बाधा बनता है और हमें तनाव देता है।

**वैज्ञानिकों के अनुसार :-**

'यदि छात्र थकान या वास्तविक थकान की भावनाओं से अपनी रक्षा करना चाहता है तो उसके लिए अपने मानसिक या शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।' - (क्रो एवं क्रो)

'कोई भी परिस्थिति जो व्यक्ति पर दबाव डालती है तथा जिसके कारण

\* शोधार्थी, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत  
\*\* प्रोफेसर, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत

व्यक्ति को समायोजन करना पड़ता है यही प्रतिबल है।' - (कोलमैन 1981)  
**तनाव की अवस्थाएँ** - आपातकालीन अनुक्रियाएँ :- जब बालिका शोधार्थी तनाव से ग्रस्त होती है और उस अवस्था में बालिकाओं के शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं उन्हें आपातकालीन अनुक्रियाएँ कहते हैं। इस अवस्था में बालिकाओं का यकृत अधिक मात्रा में ग्लूकोज का उत्सर्जन करता है हृदय की गति बढ़ जाती है, श्वास की गति बढ़ जाती है।

**सामान्य अनुकूलन संरक्षण** - इस अवस्था के अन्तर्गत 3 अवस्थाएँ हैं जिसमें पहली अवस्था में तनाव के कारण सबसे पहले होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को चेतावनी प्रतिक्रिया कहते हैं।

(रैथस, 1984) ने इस अवस्था को संकट की सूचना का नाम दिया है इस अवस्था में शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है, श्वास गति तेज हो जाती है, मांसपेशियों में तनाव बढ़ जाता है। जब पहली अवस्था से तनाव नियंत्रण नहीं होता है तब बालिका शोधार्थी दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है इस अवस्था में उनके शरीर से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिससे बालिकाएँ तनाव की अवस्था में आ जाती हैं जब दूसरी अवस्था में भी तनाव पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाती है तो वह समापन की अवस्था में पहुँच जाती है। इस अवस्था में भी तनाव जारी रहने पर बालिका शोधार्थी की शारीरिक क्षमताएँ घटने लगती हैं, आँतों में घाव होना, मधुमेह, हृदय रोग, एलर्जी, दमा होने के साथ-साथ कैंसर होने की सम्भावना बढ़ जाती है।

**तनाव के कारण -**

**बदलती जीवन शैली** - जब बालिका शोधार्थियों के पास कोई निश्चित दिनचर्या नहीं होती या उसका पालन करने में वह सफल नहीं हो पा रही है तो उससे उनको ऐसी समस्याएँ हो रही हैं जो तनाव का कारण बन जाती हैं उदा. - अगर आप देर से जागते हैं तो नाश्ता नहीं कर पाते हैं। जिसके भूख के कारण ध्यान केन्द्रित करने में परेशानी होती है।

**मानसिक तनाव** - जब बालिका शोधार्थियों को पर्याप्त नींद नहीं मिलती है तो उनके शरीर को उचित आराम नहीं मिल पाता है और वह थकान महसूस करती है। जिससे वह अपनी दैनिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम नहीं हो पाती है।

**आर्थिक परेशानी** - जब बालिकाओं को आर्थिक रूप से धन की परेशानी होती है तो बालिका शोधार्थियों को शोध कार्य करने में परेशानी आती है। यह भी चिंता का दैनिक कारण बन जाता है।

**खराब रिश्ते** - अच्छे दोस्तों की कमी होना, शिकायत करने वाले पति/पत्नी, और माता-पिता द्वारा बार-बार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने से बालिकाओं के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। खराब संबंध तनाव का एक प्रमुख कारण हो सकते हैं।

**अस्वस्थ आहार का सेवन** - स्वस्थ आहार लेने से भी व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। यदि बालिकाएँ अत्यधिक मीठा भोजन लेती हैं तो उनका शरीर असंतुलन के माध्यम से उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। चाय और कॉफी का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से मानसिक अशांति हो सकती है क्योंकि इनमें कैफीन होता है इसलिए जब हम अधिक मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो यह हमें तनाव की ओर ले जाता है।

**वातावरण का प्रभाव** - आप जिस मकान में रहते हैं वो आपको पसंद न आया हो या आप लम्बे समय से बिमार चल रही हैं, अधिक शोर, यह आपके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जिससे बालिका शोधार्थियों में तनाव उत्पन्न होता है।

**तनाव के लक्षण :**

- अकेले रहना और समाज के व्यक्तियों से बात न करना
- किसी भी काम पर ध्यान एकत्रित न कर पाना।
- कमजोर स्मरण शक्ति
- भोजन संबंधी आदतों में परिवर्तन।
- मन में आत्महत्या के विचार आना।
- छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा होना।
- अत्यधिक तनाव के कारण स्वास्थ्य बिमार जैसे - मधुमेह, उच्च रक्तचाप, सिर दर्द, बाल झड़ना, त्वचा संबंधित समस्याएँ आदि होने लगती हैं।
- तनाव बालिका शोधार्थियों के जीवन में हस्तक्षेप करता है और बालिका शोधार्थी की दैनिक गतिविधियों को बाधित करता है।
- तनाव हमें एक से अधिक तरीकों से प्रभावित करता है यह निश्चित रूप से बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

**तनाव प्रबंधन :-**

● **व्यायाम करना** - हमारी शारीरिक व मानसिक स्थिति कैसी भी हो रोज व्यायाम करने से लाभ होगा और शरीर व मन स्वस्थ होगा।

**नशा मुक्त परिवार एवं समाज** - इन पदार्थों का सेवन करने से यह तनाव को बढ़ाते हैं इसलिए इनका सेवन नहीं करें तो यह बालिका शोधार्थियों के स्वास्थ्य के लिए ठिक होगा।

● **उत्तम पोषण** - अनेक प्रकार की सब्जियाँ और फल तथा संतुलित आहार लेने से यह तनाव के समय प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाएँ रखने में मदद करता है। और सही पोषण न लेने से तनाव और अधिक बढ़ेगा।

● **स्वयं को पहचानना** - अपने लिए थोड़ा समय निकालें और इस समय का उपयोग आराम करने और अपने मन-पसंद कार्य करने के लिए करें।

● **रुचियों का विकास** - परिवार दोस्तों से बातचीत करें और उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताएँ जिससे आपको तनाव दूर करने में सहायता मिलेगी।

● **सामाजिकरण** - कई बार बालिकाएँ अपनी समस्याओं के बारे में सोचकर अधिक तनाव ले लेती हैं जिससे वह उनके शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों की ओर ध्यान ही नहीं दे पाती हैं। अतः उन्हें अपने शरीर पर पड़ने वाले लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए।

**स्वयं की अभिव्यक्ति :**

- पुस्तक पढ़ना
- भ्रमण
- संगीत सुनना
- दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना
- जिम जाना।

**शोध पत्र का उद्देश्य** - राजीव गांधी शोध छात्रवृत्ति की बालिका शोधार्थियों में तनाव के स्तर को ज्ञात करना।

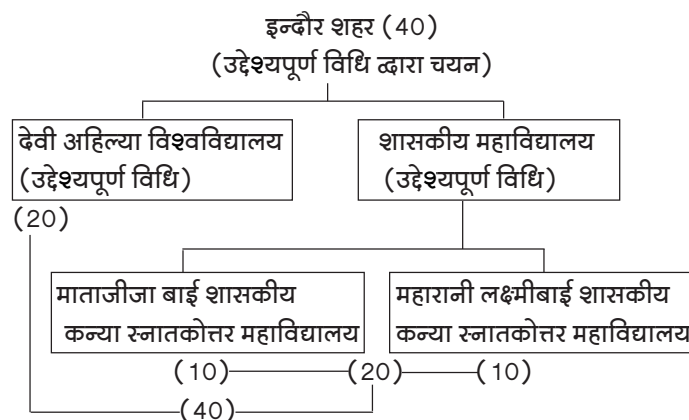
**शोध पत्र की उपकल्पना** - राजीव गांधी शोध छात्रवृत्ति की बालिका शोधार्थियों में तनाव के स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

**शोध अध्ययन का क्षेत्र** - शोध अध्ययन में इन्दौर शहर को लिया गया है जिसके अंतर्गत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, माता जीजा बाई शासकीय कन्या महाविद्यालय, महारानी लक्ष्मी बाई कन्या महाविद्यालय की बालिका शोधार्थियों का चयन किया गया है।

**शोध अध्ययन का समग्र** - इन्दौर शहर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, माता जीजाबाई शासकीय कन्या महाविद्यालय, महारानी लक्ष्मी बाई कन्या

महाविद्यालय में अध्ययनरत बालिका शोधार्थी जो राजीव गांधी शोध छात्रवृत्ति का लाभ ले रहे हैं को सम्मिलित किया गया।

### निर्देशन चयन पद्धति –



### शोध अध्ययन ईकाई का चयन निम्नलिखित मानकों के अनुसार –

- शोधार्थी इन्दौर शहर में अध्ययनरत होना चाहिए।
- शोधार्थी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, माताजीजा बाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अध्ययनरत हो।
- ऐसी बालिका शोधार्थी जो राजीव गांधी शोध छात्रवृत्ति का लाभ ले रही हैं।

**शोध इकाई का चयन** – शोध अध्ययन में ईकाई के रूप में कुल (40) बालिका शोधार्थियों का चयन उद्देश्यपूर्ण विधि द्वारा किया गया है।

**उपकरण का चयन** – राजीव गांधी शोध छात्रवृत्ति प्राप्त कर रही बालिका शोधार्थियों में तनाव स्तर का अध्ययन करने के लिए डॉ. प्रेरणा पुरी डॉ. तेजिन्दर कौर, प्रो. मंजू मेहता की तनाव मापनी का प्रयोग किया गया। प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण कर निम्नलिखित सारणी में प्रयुक्त किया गया है

क्रं.	तनाव का स्तर	संख्या प्रतिशत में
1.	निम्न स्तर	निरंक
2.	औसत से कम	निरंक
3.	औसत	90 प्रतिशत
4.	औसत से अधिक	10 प्रतिशत
5.	अति उच्च स्तर	निरंक

### टी-टेस्ट

$$\text{सूत्र} - \frac{M_1 - M_2}{SED}$$

$M_1$  – पहले प्रतिदर्श का माध्य

$M_2$  – दूसरे प्रतिदर्श का माध्य

SED – दोनों माध्यमानों के मध्य मानक त्रुटि

सार्थकता स्तर 0.01 पर स्वतन्त्रता डिग्री (FD) 1 पर T का मान 31.821 है जो वास्तविक T मान 16.72 से अधिक है अतः हमारी उपकल्पना 'राजीव गांधी शोध छात्रवृत्ति की बालिका शोधार्थियों में तनाव के स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।' स्वीकृत की जाती है अर्थात् प्रस्तुत शोध समतामूलक समाज और बालिका शोधार्थियों में तनाव के स्तर में अंतर पाया गया है।

अर्थात् राजीव गांधी छात्रवृत्ति की बालिका शोधार्थियों में तनाव का स्तर लगभग समान रूप से औसत 90 प्रतिशत पाया गया है अर्थात् उपकल्पना स्वीकृत की जाती है।

राजीव गांधी छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे बालिका शोधार्थियों को लगभग समान समस्या से जूझना पड़ता है। उनकी सामाजिक, मानसिक, आर्थिक एवं पारिवारिक दशायें समान रहती हैं अतः उनमें औसत तनाव स्तर पाया गया है। जबकि 10 प्रतिशत किशोर शोधार्थियों में औसत तनाव से अधिक तनाव स्तर देखा गया है।

**निष्कर्ष** – प्रस्तुत शोधपत्र में किये गये सर्वेक्षण के परिणाम से यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान समय में बालिका शोधार्थियों में तनाव की स्थिति पायी गयी है। बालिकाओं में 90 प्रतिशत औसत तनाव तथा 10 प्रतिशत औसत से अधिक तनाव की स्थिति देखी गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की अधिकांश बालिका शोधार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं तथा उनके परिवार कृषि करते हैं जिसके कारण बालिकाएँ शोध कार्य करने में असमर्थ होती हैं। कई बालिका शोधार्थियों को राजीव गांधी शोध छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी न होने के कारण वह इस छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले पाती हैं जिसके कारण बालिका शोधार्थी शोध कार्य करने में असमर्थ होती हैं। इसके अलावा और ऐसे कई कारण हैं जिससे बालिकाओं में तनाव की स्थिति देखी गई है।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. <https://www.myupchar.com>
2. <https://www.lifealth.com>
3. Research Methodology – C.R. Kothari & Gaurav Garg, Publication New Age International (P) LTD., Publishers.
4. <https://www.webmd.com>
5. <https://www.helpguide.org>
6. अनुसंधान विधियाँ – डॉ. एन.के. सोलंकी, 2012, पृष्ठ क्रं.-69
7. सामाजिक शोध व सांख्यिकी – डॉ. रवीन्द्र नाथ मुखर्जी, 2014, पे. 283

\*\*\*\*\*

# HR Practitioners Role : HR Specialists Deals with Job Satisfaction, Loyalty and Commitment

Dr. Saurabh Dubey\*

**Abstract** - The HR managers have keen role in the effective Planning and implementation the policies and decisions that in tune with the business changes. They should act as strategic partners and be proactive in their role than mere reactive passive spectators. The HR managers should understand how far the decisions contribute to business surplus incorporating human competency and performance to the organization.

**Key Words** - Role, Human, Planning, Organization.

**Introduction** - HR managers need a change in their outlook from seeing themselves as relationship manager to strategic resource managers. Kossek (1987, 1989) argues that major HRM innovations occur when senior management takes the lead and adoption of innovative SHRM practices is dependent on the nature of relationship of the HR Department with the CEO and the line managers Legge (1978) commenting on the actions of the personnel practitioner in the innovation process suggests that adoption of innovation by an organization depends largely on HR practitioners, credibility with information and resource providers, HR Department and HR managers in these innovative organizations play a strategic role (Ulrich, 1997), linking the HR strategy with the business strategy of fit and flexibility. The degree of fit determines the human resource system's integration with organization strategy. It is the role of HR Managers to ensure this fit in between Human Resource System with the organization Strategy.

**Factor Linkages of HR Plans and Strategies:** Given diagram presents various factors that have an impact on HR plans and Strategy and how are they interlinked with each other. Their interactions and impact on each other. Their interactions and impact on each element and the resulting change in HR Plan and policy is also indicated clearly. The table given above takes into consideration two of the generic strategies and the strategic focus required to generate each of these competitive advantages along with HR strategy and activities needed to be done by HR Department to help the organization in generating these strategic. Advantages and to move successfully towards desired goals and objectives. To understand these linkages we can look at them as tasks and steps needed to be taken in order to complete the tasks. The selected strategic focus should be very clear and well integrated into organizational policy and clearly communicated to HR Department to help in drafting suitable HR strategy and last in carrying out all activities.

Liberalization and industrialization has paved an

increasing pressure on organizations in India to change from indigenous, costly, sub-optimal levels of technology to performance based, competitive and higher technology provisions. The response to liberalization has created opportunities for technology upgrading and sophistication, resource mobilization from new sources, highly competitive input/output market, high growth and buoyant environment and HRM issues associated with strategic initiatives of diversification, mergers and acquisitions, restructuring, joint ventures, strategic alliances and for overall internationalization of the economy. An area that demands greater understanding is that of Strategic Human Resource Management (SHRM).

SHRM is concerned with affecting firm performance; which is the objective of this stickle. Human resource role enhances productivity and the effectiveness of organizations. Their implementation in organizations has proven that when organizations employ such personnel practices (mentioned in this paper) they are more able to achieve their goals and objectives. This article first describes what the word strategy means and shifts its focus on HRM at a strategic level highlighting its importance in the present decay organizations. The paper then highlights what best practices (as a result of strategic planning) the organizations can adopt that would ensure them of success. Human resource management is a complex process which is constantly evolving and being studied and discussed by academics and commentators. Human Resource role is an area that continues to evoke a lot of debate as to what it actually embraces. Human resource role is a concept that integrates traditional human resource management activities within a firm's overall strategic planning and implementation, SHRM integrates human resource considerations with other physical, financial, and technological resources in the setting of goals and solving complex organizational problems SHRM also emphasizes the implementation of a set of policies and practices that will build employee pool of skill, knowledge, and abilities



that solutions for solving organizational problems are provided and the likelihood that business goals of the organization will be attained is increased

Human Resource Management is an area that continues to evoke a lot of debate as to what it actually embraces. Organization to achieve its goals. Difference are considerable. Where in the first deference between these two seems subtle, the implications of the difference are considerable. Where in the first definition human resource management is a reactive management field in which human resource management becomes a tool to implement strategy, in the latter definition it has a proactive function in which human resource activities actually create and shape the business strategy HRM can be regarded as a general approach to the strategic management of human resources in accordance with the intentions of the organizational the future direction it wants to take. It is concerned with longer-term people issues and macro-concerns about structure, quality, culture, values, commitment and matching resources to future need, it has been defined as: All those activities affecting the behavior of individuals in their efforts to formulate and implement the strategic needs of business. The role of human resource developing the people intended to enable the forms to achieve its goals.

#### Approaches of the SHRM

1. Attempts to link Human Resource activities with competency based performance measures.
2. Attempts to link Human Resource activities with business surpluses or profit.

These two approaches indicate two factors in an organizational setting. The first one is the human factor, their performance and competency and the later is the business surplus An approach of people concerns based on the belief that human resources are uniquely important in sustained business success An organization gains competitive advantage by using its people effectively, drawing on their expertise and ingenuity to meet clearly defined objectives. Integration of the business surplus to the human competency and performance required adequate strategies. Here the role of strategy comes into picture. The way in which people are managed, mot5ivatede and deployed, and the availability of skills and knowledge will all shape the business strategy? The strategic orientation of the business then requires the effective orientation of human resource to competency and performance excellence.

1. To guarantee that individuals advancement issues are tended to methodically.
2. To supply data with respect to the organization's inside qualities and shortcomings.
3. To meet the desires for the clients adequately.
4. To guarantee high efficiency.
5. To guarantee business surplus through competency

Obstructions of SHRM Obstructions to effective SHRM execution are mind boggling. The principle reason is an absence of development procedure or inability to actualize

one. Other significant obstructions are outlined as pursues:-

- Inducing the vision and mission of the change exertion.
- High obstruction because of resistance from the primary concern.
- Interdepartmental strife. The duty of the whole senior supervisory crew.
- Plans that incorporate inside asset with outer necessities.
- Limited time, cash and the assets.
- The statuesque methodology of workers.
- Fear of incompetency of senior dimension administrators to make up vital strides.
- Diverse work-force with focused ranges of abilities.
- Fear towards exploitation in the wake of disappointments.
- Improper vital assignments and administration strife over power.
- Ramifications for power relations.
- Vulnerability to authoritative changers.
- Resistance that gets through the authentic work foundations. Presence of an activity worker's organization. Rapid auxiliary changes.
- Economic and market weights affected the selection of vital HRM.
- More various, outward looking methodology.

**Conclusion** - The HR role starts with laying functions in it, and it provides the basis for Manpower planning and internal mobility. The Manpower planning will lead to the function of acquiring right people for the right job and in accordance recruitment as well as selection exercise will be designed and tools selected. Perhaps the most radical change e in HR's job today is its developing association in creating and actualizing the organization's procedure. Involves adjusting activities including how individuals are made do with hierarchical mission and goals.

#### References :-

1. Chugh, Ritesh (January 2014). "Role of Human Resource Information Systems in an Educational Organization". Journal of Advanced Management Science.
2. "HRMS Software increase efficiency". artifychm.com. Retrieved 2020-06-05.
3. Schuler, R.S. 1992 strategic human resource management: linking people with the needs of the business. Organizational dynamics. Vol. 21, no 1. Pp 18-32.
4. "HRMS for recruitment: everything you need to know". www.hrmsworld.com. Retrieved 2018-09-12.
5. <http://www.scribd.com/doc/39382840/HRM-in-Indian-Defence#scribd> MohitKabra on Oct15, 2010
6. [https://en.wikipedia.org/wiki/Indian\\_Armed\\_Forces](https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Armed_Forces)
7. <http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2003/htar-chapter13>.
8. <http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2003/htar-chapter13.pdf>
9. Principals and practices of management SCDL, Pune
10. www.itsa.org
11. www.iteris.com
12. www.emotionalintelligence.com
13. www.tc.gc.ca
14. <http://www.shrm.org>
15. <http://www.chforum.org>

## प्रवासी साहित्य की भाषा-शैली (मॉरीशस की विशेष संदर्भ में)

डॉ. ज्योति मिश्रा \*

**प्रस्तावना** - प्रवासी शब्द 'वस' धातु में 'प्र' उपसर्ग लगाने से बनता है। 'वस' धातु का प्रयोग रहने के अर्थ में किया जाता है। प्रवास शब्द का अर्थ है विदेश गमन, विदेश यात्रा, घर पर न रहना, किसी दूसरे देश या बेगानी धरती पर वास करने वाला व्यक्ति प्रवासी है। शब्दकोशों में प्रवास शब्द के लिए वासी, प्रवासी, अप्रवासी, विदेशी, भारतवंशी और एन.आर.आई जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे वासी 'Native' वासी वे हैं जो पीढ़ियों से संबंधित खज्म भूमि, धरती पर वास कर रहे हैं। इनकी जन्म भूमि ही इनका निवास स्थान है।<sup>1</sup>

अप्रवासी - 'अप्रवासी व्यक्ति उस देश में रह रहा होता है जो उसका अपना नहीं है। यह स्थान उसकी जन्मभूमि से दूर होता है।'<sup>2</sup> वास्तव में अप्रवासी व्यक्ति वह होता है जो निश्चित समय के लिए अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश बेगाने देश में जाकर रहता है और समय बीत जाने के पश्चात पुनः लौट आता है।<sup>3</sup> अप्रवासी व्यक्तियों के पास किसी बेगाने देश में रहने का कानूनी अधिकार नहीं होता। फ्रांसीसी भाषा में प्रवासी शब्द के लिए 'हंटेजरम' शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का चार अर्थों में प्रयोग किया जाता है- विदेशी, अजनबी, बाहरवाला, बेगाना। प्रवासी की स्थिति अनिश्चित होती है। संबंधित धरती पर वह किसी न किसी उद्देश्य से आया है। प्राप्ति कर लेने पर उसका लौटना निश्चित होता है। प्रवासी शब्द से अर्थ उस व्यक्ति से है जो किसी देश में निवास करता है जबकि अप्रवासी से भाव उस व्यक्ति से है जो उस देश में प्रवेश करता है। प्रवास किसी एक व्यक्ति का या समूह के रूप में देश परिवर्तन है। अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय शास्त्री उस व्यक्ति को भी प्रवासी की श्रेणी में रख लेते हैं जो किसी बाहर देश में एक साल रहने की इच्छा जाहिर करता है। और प्रवास खानाबदोश, प्रवासी मजदूर और भ्रमण इन तीनों से पूर्ण रूप से अलग है।

बीसवीं सदी के प्रारंभ में भारतीय रोजगार तथा अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए यूरोपीय और अमेरिकी महाद्वीपों के अतिरिक्त थाईलैंड, न्यूजीलैंड, वर्मा, मॉरीशस, फिजी, त्रिनिदाद और सूरीनाम आदि देशों की धरती को अपनाया। अपने प्रवास के दौरान ये अपनी आर्थिक स्थिति से ऊपर भी उठे। भारतीयों के प्रवास के संबंध में साक्षात्कार पत्रिका के प्रवासी विशेषांक में लिखा गया है- 'भारत का विदेशों से संबंध का इतिहास पुराना है। हजारों वर्षों से धर्म प्रचार तथा व्यापार के लिए भारतीय विभिन्न देशों में जाते रहे हैं, और विदेशी आक्रमणकारी लुटेरे, व्यापार और धर्म प्रचारक तथा यात्री इस देश में आते रहे हैं।'<sup>4</sup> 18वीं शताब्दी में भारत विदेशी शासन के अधीन था। उनके अत्याचारों से त्रस्त होकर भारतीयों को अपनी मातृभूमि छोड़कर दास रूपों में विदेशों में जाना पड़ा जिसमें मजदूर, खेतों में काम करने वाले किसान और श्रमिक अधिक थे। ये अशिक्षित थे,

कम पढ़े लिखे थे। इन्हें यह पता नहीं था कि वहां जाकर गोरे मालिकों के हाथ उन्हें बेच दिया जाएगा। धन और सोने का लालच देकर धोखे से विदेशी जातियाँ उन्हें अपने साथ ले गईं और यही उनकी संघर्ष की यात्रा शुरू हो गई किंतु इनके बाद जिन लोगों का प्रवास शुरू हुए वे शिक्षित थे पढ़े लिखे थे। उनमें से अधिकांश डॉ.क्टर, इंजीनियर, वकील और विद्यार्थी थे। भारतीयों में किसी भी परिस्थिति में ढालने की अद्भुत शक्ति होती है। इन्होंने अपने आप को वहाँ की परिस्थितियों में अच्छी तरह से ढाल लिया। 1960 में पहले पहुंचे प्रवासियों को भाषा और संस्कृति से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रवासी शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया जो लोग शौकिया तौर पर या मजबूरी वश रोजगार की तलाश में या आर्थिक उच्चता के लिए अपने देश से बाहर विदेशों में गए।

प्रवासी शब्द हिंदी साहित्य जगत में एक नई चेतना, एक नया मनोविज्ञान और अर्न्तदृष्टि को लेकर आता है। प्रवासी लेखकों का मनोविज्ञान एवं उनकी संवेदनाएँ अपने उस नए परिवेश को संस्कार के रूप में ग्रहण करती हैं। वह अपनी जन्मभूमि की मिही से अलग होकर एक भिन्न देश काल और वातावरण तथा परिवेश में चला जाता है उसी वातावरण में जीवन के रंगीन सपने देखता है। परिवेश बदल जाने के कारण उसके जीवन में अनेक जटिलताएँ और विशेषताएँ तो आती हैं लेकिन वह अपने आप को उन परिस्थितियों में ढाल लेता है फलस्वरूप उसके नए संस्कार, दृष्टिकोण, विचार, एक नई सोच नई मान्यताएँ बनने लगती हैं। वह पुरानी सोच और पुराने मूल्यों को एक नए दृष्टिकोण से सोचने लगता है। इन स्थानों में बसे हिंदी लेखक अपने इस बदले हुए नए परिवेश से प्रभावित भी होते हैं और अपने इस नए परिवेश में रचे-बसे विविध विषयों को अपने साहित्य का विषय बनाते हुए सहित का सृजन करते हैं। इनके द्वारा रचित साहित्य प्रवासी साहित्य कहलाता है। 'भारत में अंग्रेज, फ्रेंच, डच आदि शासक अपने-अपने उपनिवेश देशों में हजारों भारतीय मजदूरों को छल-कपट से गिरमिटिया मजदूर बनाकर ले गए और इन भारतीयों ने तुलसीदास की 'रामचरितमानस' 'हनुमान चालीसा' जैसे धार्मिक सांस्कृतिक ग्रंथों से अपने अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा करते हुए अपने श्रम से कायाकल्प कर दिया यह भारतीय मजदूर जो 'इंडियन इंडेन्डर-लेबर सिस्टम' अर्थात् शर्तबंदी प्रथा के अंतर्गत गए थे अधिकांश रूप से पूर्वी उत्तरप्रदेश, बिहार आदि प्रदेशों से गए थे, जिनकी मातृभाषा भोजपुरी थी और अवधि में रचि गई 'रामचरितमानस' श्वेत मालिकों की क्रूरता, अत्याचार और शोषण के बची जीवन शक्ति का अजस्र स्रोत थी।<sup>5</sup>

आज विश्व की प्रायः सभी देशों में भारतीयों के चरण पड़े हैं और भारतीय चाहे जहाँ कहीं भी बसे क्यों न हो वे अपनी सभ्यता संस्कृति और भाषा को

नहीं छोड़ते। इसलिए वे चाहे विश्व के किसी भी कोने में क्यों न चले जाएँ अपने लिए एक अलग व्यक्तित्व और अलग वातावरण का निर्माण कर लेते हैं। विश्व के उन देशों में जहाँ भारतीय बसते हैं वहाँ वे अपना एक समाज या समुदाय का निर्माण करते हैं जिसको देखकर एक लघु भारत की कल्पना मन में आकार लेने लगती है। प्रवासियों द्वारा हिंदी में ही साहित्य सृजन करने का कारण बताते हुए सुभाष पंत कहते हैं- 'लेखक साहित्य में उसी भाषा का चुनाव करता है जिस भाषा के साथ उसका आत्मीय रिश्ता हो और जिसमें वह अपने छोटे-बड़े और जटिल अनुभवों को सहजता और विश्वसनीयता के साथ व्यक्त कर सके। प्रवासी होने के बावजूद इन लेखकों की चेतना में आज भी वह भाषा धड़क रही है जिस भाषा के माध्यम से इस विराट जीवन को जाना और समझा था।'<sup>6</sup> नारायण कुमार लिखते हैं- 'हिंदी चूंकि संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजभाषा है अतः विश्व भर के बुद्धिजीवी वर्ग निश्चय ही इसे सम्मान की दृष्टि से देखता है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जपान, जर्मनी, चेकगणराज्य, रूस, नीदरलैंड, पोलैंड, रोमानिया, इटली, दंगरी तथा पूर्वी यूरोप के अनेक देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी में अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान हो रहे हैं। हिंदी को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने में उन भारत वाशियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है जो गिरमिटिया मजदूर के रूप में मॉरीशस (1834), गुयाना (1838), त्रिनिदाद (1845), सूरीनाम (1873), फिजी (1871), दक्षिण अफ्रीका (1860), गए तथा उन्होंने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करते हुए हिंदी और भारतीय संस्कृति को औपनिवेशिक दासता के विरुद्ध लड़ने के लिए अमोघ अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया।'<sup>7</sup> 'भारतीय चेतना से आल्पावित मॉरीशस के हिंदी साहित्य में स्वभावतः भारतीय संस्कार एवं जीवन मूल्य अंतर्निहित हो गए हैं। वर्षों पूर्व भारत भूमि से आए भारतीयों ने अपने संस्कारों से मॉरीशस के हिंदी साहित्य में विविध रंग भरे हैं।'<sup>8</sup> भारत की भांति ही 'मॉरीशस में भी विविध जाति, संस्कृति और भाषा के लोग रहते हैं। वहाँ साहित्य, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम। मॉरीशस के सतत भौतिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में भारतीय भारतीय मजदूरों की तपस्या है। उसे सामाजिक सांस्कृतिक का देश भी कहा जाता है।'<sup>9</sup> मॉरीशस में सबसे पहले डच, फ्रांसीसी और उसके बाद अंग्रेजी शासन रहा। जिस प्रकार भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग भाषाएँ बोली और लिखी जाती है। उन भाषाओं का अपना उत्कृष्ट साहित्य भी है ठीक उसी प्रकार मॉरीशस में अंग्रेजी, फ्रेंच, भोजपुरी, क्रियोल, चीनी, तमिल, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं का प्रयोग होता है। किंतु बोलचाल और लिखने में फ्रेंच, अंग्रेजी और हिंदी इन तीन भाषाओं का बर्चस्व है। फ्रेंच उच्चवर्ग या आभिजात्य वर्ग की भाषा है। फ्रेंच भाषा का अध्ययन प्राथमिक कक्षाओं के लिए अनिवार्य है। मॉरीशस की सर्वाधिक पत्र-पत्रिकाएँ फ्रेंच भाषा में ही छपती हैं। इस दृष्टि से देखा जाय तो वहाँ फ्रेंच वहाँ के जन-जीवन में समृद्ध और सशक्त रूप में उपस्थित है। मॉरीशस की दूसरी प्रचलित भाषा फ्रेंच का ही तद्भव या बिगड़ा हुआ रूप क्रियोली है। क्रियोली ही फ्रांसीसी और अफ्रीका लोगों के बीच संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। फ्रांसीसी जमींदारों और अफ्रीकी मजदूरों के बीच बोली जाने वाली यह भाषा फ्रेंच का अपभ्रंश रूप है। तीसरी प्रमुख भाषा भोजपुरी है। क्रियोली के बाद हिंदी की यह बोली सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली जनभाषा है। भारतियों मूल के लोगों में पुरानी पीढ़ी के लोग भोजपुरी का और नई पीढ़ी के लोग क्रियोली भाषा का प्रयोग करते हैं। ठाकुर दत्ता पांडेय कि कथन है- 'भोजपुरी यहाँ की हिंदी की जननी है क्योंकि

इसी बोली में हमारे अधिकांश लोग भोजपुरी ही बोलते हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि उसी के माध्यम से हम अपने अज्ञात रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश में आ गए हैं। आगे चलकर भोजपुरी का विकसित रूप ही हमारे यहाँ की हिंदी में परिणत हो गया।'<sup>10</sup>

मॉरीशस में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी ही है। मॉरीशस का अधिकांश हिंदी साहित्य खड़ी बोली में लिख आ गया है। रेडियो एवं टेलीविजन के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को बढ़ावा दिया गया। भारत के उच्चकोटि के साहित्यकार समय-समय पर अपने मॉरीशस प्रवास के दौरान हिंदी जगत को प्रोत्साहित किया। अनेक पत्र-पत्रिकाएँ जैसे बसंत, पंकज, आर्योदय, जनता, स्वदेश, आक्रोश आदि का प्रकाशन खड़ी बोली हिंदी में ही होता है। बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में आर्य समाज के द्वारा खड़ी बोली का मॉरीशस में प्रचार-प्रसार हुआ। अन्य भाषाओं में तमिल, तेलगू, मराठी, गुजराती, चीनी एवं उर्दू भी प्रचलित हैं। इनमें चीनी भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। प्राथमिक स्तर पर उर्दू मातृभाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। उर्दू में साहित्य भी उपलब्ध है। मॉरीशस में तमिल भाषी लोग भी हैं और संध्याकालीन पाठशाला में तमिल भाषा भी पढ़ाई जाती है। मॉरीशस में गुजराती बोलने वालों की संख्या भी अधिक है। मॉरीशस के कहानियों में खड़ी बोली के अतिरिक्त भोजपुरी भाषा का भी सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। यहाँ की कहानियों में परिष्कृत खड़ी बोली संस्कृत के तत्सम शब्द, देसज शब्द, फ्रेंच, क्रियोली, अंग्रेजी एवं उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग मिलता है। कहानीकार अथवा उपन्यासकार भारत के जिस क्षेत्र विशेष संबंध रखते थे वहाँ अपने उसी बोली का प्रयोग करते थे फलस्वरूप उनकी कहानियों-उपन्यासों की भाषा में क्षेत्रीय बोली के शब्दों का प्रयोग भी दिखलाए पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो क्षेत्रीय भाषा की महक और मिही की खुशबू उनके साहित्य में दिखलाई पड़ता है। डॉ. तनूजा चौधरी का कथन है- 'पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बहुसंख्य गिरमिटिया मजदूरों की मातृभाषा भोजपुरी थी अतएव जब भी संवेदना को गहराई देने का अवसर आता है कहानीकारों ने भोजपुरी का प्रयोग किया है। शब्दों के देसज रूप, कहावतें, बिम्ब एवं सुंदर प्रतीकों की योजना कहानियों में मिलती है।'<sup>11</sup> भोजपुरी शब्दों के प्रयोग ने जहाँ एक ओर कहानी के संदर्भ को तथा कहानी के उद्देश्य प्राप्ति को गहराई प्रदान किया है वही अर्थ गाम्भीर्य को भी अत्यंत गहराई के साथ प्रकट किया है। ये कहानी कहानीकार के शब्द सामर्थ्य को भी प्रकट करते हैं। कुछ शब्द द्रष्टव्य हैं-

‘छूँछा भात (केवल चावल)  
मरनी अगोरना (मृत्यु की प्रतीक्षा)  
पनछोछर (स्वादविहिन)  
बिसार नहीं सकी (भूल नहीं सकी)  
गावत रलहन (गाता था)  
राधना (भोजन बनाना)  
गोड़ (पांव)  
उकसावे ला (भड़काना)  
किरया खाता हूँ (कसम खाना)'<sup>12</sup>

इसी प्रकार भोजपुरी के विविध क्रिया रूपों, देशज शब्दों का प्रयोग भी मॉरीशस के कहानियों में मिलते हैं। संस्कृत निष्ठ शब्दों के प्रयोग, उर्दू एवं संस्कृत के प्रचलित शब्दों का प्रयोग, हिंदी के तत्सम शब्द के साथ हिंदी के अति प्रचलित कहावतों एवं मुहावरों का प्रयोग भी इन कहानीकारों ने किया है। भावों को विस्तार देने के लिए प्रचलित उक्तियों और सटिक

दृष्टांतों का प्रयोग भी कहानियों में मिलता है-

जैसे- 'आदमी को रसोई से रुसा फूली क्यों होनी चाहिए'

'धिमलीदा भी पन छोछर होता है।' (पसीने की कमाई)

'इज्जत से झुकजाना, बेइज्जत होकर झुकने से बेहतर है' (अभिमन्यु अनंत वह बीच का आदमी)

'गहरी सांठ गांठ थी' (जयदत्त जिउत, गिखी रखी आत्मा)

'सब्र का फल मीठा होता है' (जयदत्त जिउत, गिखी रखी आत्मा)<sup>13</sup>

इसी प्रकार अंधे की लाठी, ऊंट के मुंह में जीरा, घोंघे की चाल, समरथ को नहीं दोष गुसाई, बिछुरत एक प्राण हरिले ही जैसे अनेक मुहावरों का प्रयोग भी कहानीकारों ने किया है।

फ्रांसीसी प्रयोग-

'पा ब्लीये एकूत रोजा'

'को नू आ ले जोरजी' (अभिमन्यु अनंत मातम पुरसी)

'बोजूर बाँ मुसेय' (वेणी माधव रामखेलावन)<sup>14</sup>

इसी प्रकार बिम्ब एवं प्रतीकों का भी प्रयोग किया गया है। कहानियों के विषय वस्तु जीवन से संबंधित होने के कारण जीवंत बन पड़ी है। कुछ कहानियाँ आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई हैं। छोटे-छोटे संवादों का प्रयोग किया गया है जो अत्यंत स्पष्ट होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मॉरिशस के कथा साहित्य में खड़ीबोली के साथ-साथ अंय भाषाओं का प्रयोग कहावतें, मुहावरे, दृष्टांत, भोजपुरी भाषा के शब्द, वाक्य, चाक्षुक बिम्ब, सुंदर प्रतीकों का प्रयोग आदि अपने सहज और शुद्ध रूप में प्रयोग लाए गए हैं। डॉ. कमल गोयनका का कहना है - 'हिंदी का प्रवासी साहित्य हिंदी का ही साहित्य है, बस अंतर इतना है कि वह परदेश में रचा गया है।'<sup>15</sup> 'हिंदी के प्रवासी साहित्य का रंग रूप, उसकी चेतना और संवेदना भारत के हिंदी पाठकों के लिए एक नई वस्तु है, एक नए भाव बोध का साहित्य है, एक नई व्याकुलता और बेचेनी का साहित्य है जो हिंदी साहित्य को अपनी मौलिकता एवं नए साहित्य संसार में समृद्ध करता है।'<sup>16</sup> मॉरिशस का कथा साहित्य जिसकी रचना की भावभूमि विदेशी धरती है अगर पीड़ा के स्तर पर, या भावनाओं के स्तर पर इसका आकलन करें तो पता ही नहीं चलता की इसके रचनाकार प्रवासी भारतीय हैं। यही कारण है कि भारतीय त्यौहारों - महाशिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, ईद, दीपावली, कावड़ी के दिन यहां आमतौर पर सरकारी अवकाश घोषित के जाते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रवासी भारतीयों ने मॉरिशस में हिंदी भाषा और संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित किया है। मॉरिशस के रचनाकारों ने हिंदी साहित्य को फ्रेंच भाषा में अनुदित कर फ्रेंच भाषा भाषी देशों में पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया। 'विश्व हिंदी सचिवालय' की स्थापना भी मॉरिशस में की गई है। मॉरिशस वासी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए अंग्रेजी को आवश्यक नहीं मानते। उनके खान-पान, रहन-सहन, रीति-रिवाज पर भारतीयता की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है प्रवासी भारतीय चाहे दुनियाँ के किसी भी स्थान पर क्यों न हो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रति अटूट आस्था है। अभिमन्यु अनंत का कहना है- 'संस्कृति न तो रातों रात बनती है और न ही रातों रात खत्म होती है। हम सभी प्रवासी भारतीय मूल रूप से दो देशों के नागरिक हैं एक तो जननी जन्मभूमि के और दूसरा अपनी संस्कृति भूमि के।'<sup>17</sup> मॉरिशस के कथा साहित्य में वहाँ के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन को प्रतिबिम्बित किया गया है। डॉ. तनुजा चौधरी के शब्दों में- 'कहानियों ने मॉरिशस में बसे प्रवासी भारतीयों की पीड़ा, संघर्ष, बलिदान, शोषण, अत्याचार, घुटन और व्यथा, भारतीय संस्कार, रीति-रिवाज, अंधविश्वास,

दासता से स्वतंत्र होने की लालसा इत्यादि को प्रस्तुत किया गया है।'<sup>18</sup> जीवन के कठिन से कठिन संघर्ष के समय में भी इन भारतीय प्रवासियों ने भारतीय धर्म, भाषा एवं संस्कृति की डोर पकड़े रखी। संघर्षों के बीच भी उन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति को बचाए रखा। डॉ. अभिमन्यु अनंत लिखते हैं- 'आज मॉरिशस में हिंदुस्तानी तहजीब अगर घर-घर, आँगन-आँगन बुलंदी के साथ नजर आती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह भाषा के प्रति समर्पण ही है। भारतीय जुबानों ने इस जजीरों में मजहब को जिंदा ही नहीं रखा बल्कि उनको विकसित भी करती रही है। मेरे दिव्य में, हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की रीढ़ की हड्डी है। मॉरिशस में जिस दिन हिंदी कमजोर होने लगेगी, उस दिन कोई भी भारतीय भाषा अपनी हिफाजत नहीं कर पाएगी।'<sup>19</sup> मॉरिशस की जमीन पर हिंदी कथा साहित्य उत्तरोत्तर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मॉरिशस में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु भारतीय धर्म और संस्कृति के संरक्षण हेतु दो विश्व हिंदी सम्मेलन कराए गए साथ ही हिंदी अध्यापक संघ, आर्य समाज, सनातन धर्म, हिंदी प्रचारिणी सभा, हिंदी लेखक संघ, हिंदी यूनियन एवं मॉरिशस साहित्य अकादमी, हिंदी पत्र-पत्रिकाएँ निरंतर प्रयास रत हैं।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डी एस.ऑक्सफोर्ड, एडवांस लर्सर्स डिक्शनरी, सांतावा संस्करण, 2005 पृ.- 105
2. वही पृ.-776
3. अर्चना पैन्थूली रू प्रवासी हिंदी साहित्यरूप अपेक्षाएँ वर्तमान साहित्य प्रवासी साहित्य विवरण- 1 जनवरी-फरवरी 2016 पृ.-45
4. कमल किशोर गोयनकार हिंदी का प्रवासी साहित्य, साक्षात्कार (अंक- 329,330,331) प्रवासी भारतीय हिंदी लेखन विशेषांक, मई-जुलाई 2007 पृ.- 13
5. कमल किशोर गोयनकार हिंदी का प्रवासी साहित्य पृ.- 13
6. संपादकीय से शब्द योग (अंक- 1) प्रवासी साहित्य विशेषांक अप्रैल- 2008 पृ. 4
7. गडानांचल, जुलाई-दिसम्बर 2007 पृ.35
8. मॉरिशस की कहानियों में भारतीय संस्कार-जीवन मूल्य, डॉ. तनुजा चौधरी, भूमिका हिंदी साहित्य अकादमी, आराधना ब्रदर्स, कानपुर उत्तर प्रदेश-2015
9. मॉरिशस का कथा साहित्य और अभिमन्यु अनंत, डॉ. सुनील विक्रम सिंह, प्राच्य प्रकाशन वाराणसी 2006 पृ. 11
10. वही पृ.- 13
11. डॉ. तनुजा चौधरी, मॉरिशस की कहानियों में भारतीय संस्कार-जीवन मूल्य, कानपुर पृ.84
12. वही पृ.-84
13. वही पृ.-85
14. वही पृ.-85
15. कल्पांत फरवरी 2009 पृ.-38
16. कल्पांत फरवरी 2009 पृ.-38
17. डॉ. तनुजा चौधरी, मॉरिशस की कहानियों में भारतीय संस्कार-जीवन मूल्य, कानपुर पृ.89 (वसंत- 124 पृ.9)
18. डॉ. तनुजा चौधरी, वही पृ.-89
19. डॉ. तनुजा चौधरी, वही पृ.-87 (वसंत- 124 पृ.9)



## उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का सामाजिक जागरूकता के साथ उसके बाधक तत्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन उज्जैन नगर के संदर्भ में

श्रीमती करुणा तिवारी \*

**शोध सारांश** – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं के हित में बनाया गया एक सरकारी नियंत्रण है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के शोषण को रोकना, उसे बेहतर संरक्षण प्रदान करना व जागरूक संतुष्ट उपभोक्ता का विकास करना है जो अपने समाज में इस अधिनियम के आधार पर आमजन को प्राप्त अधिकारों के प्रति जागरूक हो। वर्तमान उपभोक्ता समाज में उपभोक्ताओं के सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक हितों की रक्षा में इस अधिनियम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज उपभोक्ता निश्चित ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो कर उपभोक्ता फोरम में जाने से परहेज नहीं करता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि, इस अधिनियम के लागू होने से उपभोक्ता में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रतिशत बढ़ा है अधिनियम की व्यापकता में बाधक तत्वों ने भी अपनी भूमिका निभाई है पर इस अधिनियम के उपयोग से उपभोक्ता को सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

**शब्द कुंजी** – उपभोक्ता, उपभोक्ता फोरम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, आवेदक, अनावेदक।

**प्रस्तावना** – सामाजिक जीवन से अलग स्वतंत्र मनुष्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। समाज में वही मनुष्य जीवित रह सकता है जो अपनी मानवता का विकास समाज के सदस्य के रूप में रहकर कर सके, समाज में ही वह जन्म लेता है और समाज ही उसकापालन-पोषण करता है। समाज ही वह सामग्री और परिस्थितियां उपलब्ध करवाता है, जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिये उपयोगी ही नहीं वरन् महत्वपूर्ण है।

इसी को सरल और संक्षिप्त शब्दों में विश्व के महान दार्शनिक अरस्तु ने इस प्रकार बताया है कि, 'मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है' इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि, समाज के अभाव में मनुष्य की अवधारणा सार्थक नहीं है।

समाज के प्रत्येक वर्ग, समूह से सम्बन्धित हर उस व्यक्ति को जो अपने जीवन-यापन, सुख-सुविधाओं के लिये वस्तुओं एवं सेवाओं का, या तो उपभोग करता है, या अपनी दैनिक दिनचर्या में उपयोग में लाता है, उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। व्यक्तियों का समूह मिलकर ही समाज का निर्माण करता है और समाज का प्रत्येक सदस्य अपनी दिनचर्या का प्रारम्भ करने से लेकर समाप्ति तक दैनिक उपयोग-उपभोग में आने वाली विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करता है। इस प्रकार समाज का प्रत्येक सदस्य/व्यक्ति जो अपने उपयोग-उपभोग के लिये वस्तुओं का क्रय करता है, उपभोक्ता कहलाता है।

मनुष्य अपनी दिनचर्या का प्रारम्भ ही एक उपभोक्ता के रूप में करता है और दिन के अंत तक भी वह उपभोक्ता होता है। अर्थात् वर्तमान परिदृश्य में उपभोक्ता के बिना समाज की अवधारणा निरर्थक ही कही जा सकती है।

उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो वस्तुओं अथवा सेवाओं को अपने अथवा अपनी ओर से अन्य के प्रयोग अथवा उपभोग के लिये खरीदता है। वस्तुओं में दैनिक उपभोग की स्थाई वस्तुएँ सम्मिलित हैं वहीं जिन सेवाओं के लिये भुगतान किया जाता है, उसमें यातायात, बिजली, टेलीफोन, मोबाईल एवं

सिनेमाघर आदि में सिनेमा देखना आदि सम्मिलित है।

समाज और उपभोक्ता के परिप्रेक्ष्य में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यदि उपभोक्ता को कहा जाए तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इसका कारण यह है कि, यदि समाज में उपभोक्ता ही नहीं रहेगा तो वस्तुओं का क्रय-विक्रय ही समाप्त हो जायेगा और यदि यह स्थिति निर्मित होती है तो अर्थव्यवस्था पर सीधा इसका प्रभाव होना निश्चित है।

जब कोई उपभोक्ता किसी उत्पाद का उपयोग करता है तो वह भी बाजार का एक भागीदार बन जाता है। उपभोक्ता के बगैर हम किसी भी उद्योग, व्यापार व कम्पनी के अस्तित्व के विषय में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उपभोक्ता ही वह व्यक्ति है, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित, अनियंत्रित या कहा जाए तो प्रभावित करने की सीधी शक्ति रखता है। अतः यह सर्वविदित है कि, उपभोक्ता ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। उपभोक्ता के अभाव में अर्थव्यवस्था की कल्पना करना ही निरर्थक है। इस प्रकार उपभोक्ता, समाज और अर्थव्यवस्था एक दूसरे का पर्याय हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने भी यह व्यक्त किया है कि, 'उपभोक्ता हमारे पास आने वाला महत्वपूर्ण आगन्तुक है। वह हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। हम उस पर निर्भर हैं। वह व्यवसाय में बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि हमारे व्यवसाय का हिस्सा है। हम उसकी सेवा करके उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह हमें सेवा का अवसर दे कर हम पर एहसान कर रहा है।' अर्थात् उपभोक्ता अर्थव्यवस्था की वह महत्वपूर्ण कड़ी है जिसकी इच्छाओं का सम्मान करना उत्पादक एवं विक्रेता दोनों का ही मुख्य कर्तव्य है।

उत्पादन की नई तकनीकी और विकास के अवसरों के बढ़ने के साथ ही अनुचित लाभ प्राप्ति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपभोक्ताओं के शोषण को भी प्रोत्साहन मिला है। विपणन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न कम्पनियों अपने अपने उत्पादन को लुभावनी योजनाओं के नाम पर, उपभोक्ताओं का शोषण करती हैं। उत्पादक जब अपने उत्पाद को उसके द्वारा बताए गये

मानक स्तर पर विक्रय नहीं करता है तो वही भी उपभोक्ता के साथ छल करता है।

आज उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापन, जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, बिना मानक की वस्तुओं की बिक्री, अधिक दाम, ग्यारंटी के बाद सर्विस नहीं देना, हर जगह ठगी, कम नापतौल आदि संकटों से घिरा है। कभी-कभी इस शोषण के पीछे उपभोक्ता की स्वयं की अज्ञानता, अशिक्षा, उपभोक्ताओं का संगठित नहीं होना, वस्तुओं सेवाओं से संबन्धित आवश्यक तथ्य, गुणवत्ता का मापक स्तर व उसके मानक के साथ उपभोक्ताओं के स्वयं अधिकारों के पीछे उपभोक्ता की सचेतना का अभाव होता है। अतः उपभोक्ताओं को इस शोषण से निजात दिलाने व संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से एक ऐसे विशेष कानून की आवश्यकता थी जो उन्हें पूर्ण रूप से राहत प्रदान कर सके। उपभोक्ता शिक्षा एवं उपभोक्ता जागरुकता से उपभोक्ता को उसके अधिकारों के प्रति जागरुक कर, एक शक्तिशाली उपभोक्ता के रूप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विपणन की प्रक्रिया में लाना आवश्यक है। जिससे उपभोक्ता जागरुक हो कर ना केवल स्वयं का शोषण से बचाव कर सके बल्कि उत्पादक एवं विक्रेता की सभी स्थितियों को पारदर्शिता के साथ समझ भी सके। सरकार ने उपभोक्ता को आत्मनिर्भर बनाने के लिये समय समय पर सार्थक प्रयास किये हैं और निरन्तर इस दिशा में कार्यरत हैं। इसी क्रम में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के शोषण को रोकना, उसे बेहतर संरक्षण प्रदान करना, उपभोक्ता को होने वाली आर्थिक क्षति की भरपाई करने के साथ ही जागरुक संतुष्ट उपभोक्ता का विकास करना है जो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो। इस अधिनियम को उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु सरल और सुलभता के साथ ही सशक्त बनाने के लिये आवश्यकानुसार सन् 1991, 1993 एवं 2002 में और अब 2019 में कई महत्वपूर्ण संशोधन भी किये गये हैं। उपभोक्ता के हित संरक्षण की दिशा में कई सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएँ भी प्रयासरत हैं जो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करने की दिशा में निरन्तर कार्य कर रही हैं।

शोध अध्ययन क्षेत्र के रूप में उज्जैन नगर का चयन कर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, सामाजिक जागरुकता के साथ ही इसके बाधक तत्वों का विशलेष्णात्मक अध्ययन किया है।

**अध्ययन का उद्देश्य** - उपभोक्ताओं की सामाजिक जागरुकता और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रभावशीलता में बाधक तत्वों का अध्ययन।

**शोध कार्य की परिकल्पना** - प्राकल्पना, शोधकर्ता के कार्य को दिशा प्रदान करती है व शोध के क्षेत्र को स्पष्ट करती है जिससे आगे का मार्ग व दिशा स्पष्ट होते हैं। शोधकार्य में शोधार्थी ने उद्देश्यों के आधार पर निम्नलिखित प्राकल्पना परीक्षण हेतु निर्धारित की गई थी।

उपभोक्ताओं की सामाजिक जागरुकता में कमी के पीछे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पर बाधक तत्वों की प्रभावशीलता का प्रभाव देखा गया है।

**अध्ययन का क्षेत्र** - शोधार्थी के द्वारा शोध अध्ययन हेतु क्षेत्र के रूप में उज्जैन नगर का चयन किया गया है।

**अध्ययन की ईकाई** - प्रस्तुत शोध कार्य में अध्ययन की ईकाई के रूप में उज्जैन जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज/निराकृत याचिकाओं में से 300 उपभोक्ताओं का चयन किया गया है।

**परिणाम एवं व्याख्या** - आयु, शिक्षा एवं व्यवसाय के आधार पर प्राप्त आंकड़ों के अध्ययन से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुआ है जो इस प्रकार है -

**तालिका क्रमांक 1 : आयु के आधार पर उपभोक्ता जागरुकता संबन्धित प्राप्त आंकड़ों की स्थिति का अध्ययन**

क्र.	आयु	संख्या	प्रतिशत
1	18-30	15	5 %
2	31-40	120	40 %
3	41-50	90	30 %
4	51-75	75	25 %
योग		300	100 %

आयु के आधार पर उपभोक्ता जागरुकता संबंधी प्राप्त आंकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि, 31-40 वर्ष तक की आयु वर्ग वाले उपभोक्ताओं में उपभोक्ता अधिनियम के प्रति सबसे अधिक जागरुकता देखी गई है। जिसका प्रतिशत 40% है। इसके विपरीत 18-30 वर्ष तक की आयु वर्ग वाले उपभोक्ताओं में अधिनियम के प्रति सबसे कम जागरुकता देखी गई है जिसका प्रतिशत केवल 5% है। इसी क्रम में द्वितीय स्थान पर 41-50 वर्ष तक की आयु वर्ग वाले उपभोक्ताओं में जागरुकता का प्रतिशत 30% और तृतीय स्थान पर 51-75 वर्ष तक की आयु वर्ग वाले उपभोक्ताओं में जागरुकता का प्रतिशत 25 % रहा। आयु के आधार पर प्राप्त परिणामों को निम्न ग्राफ क्रमांक 1 के माध्यम से दर्शाया गया है।

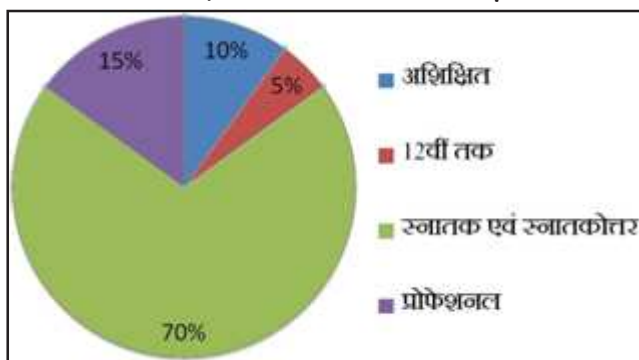


**तालिका क्रमांक 2 : शिक्षा के आधार पर उपभोक्ता जागरुकता संबन्धित प्राप्त आंकड़ों का अध्ययन**

क्र.	शिक्षा का स्तर	संख्या	प्रतिशत
1	अशिक्षित	30	10 %
2	12वीं तक	15	05 %
3	स्नातक एवं स्नातकोत्तर	210	70 %
4	प्रोफेशनल	45	15 %
योग		300	100 %

शिक्षा के आधार पर उपभोक्ताओं में अधिनियम के प्रति जागरुकता का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि, स्नातक से स्नातकोत्तर तक शिक्षा प्राप्त उपभोक्ता, अधिनियम के प्रति सर्वाधिक जागरुक है जिनका प्रतिशत 70 % जबकि सबसे कम जागरुकता 12<sup>वीं</sup> तक शिक्षा प्राप्त उपभोक्ताओं में देखी गई है जिनका प्रतिशत मात्र 5 % है साथ ही अशिक्षित उपभोक्ताओं में जागरुकता का प्रतिशत 10 % तथा प्रोफेशनल वर्ग में जागरुकता का प्रतिशत 15 % रहा है। शिक्षा के आधार पर प्राप्त परिणामों को निम्न ग्राफ क्रमांक 2 के माध्यम से दर्शाया गया है।

### ग्राफ क्रमांक - 2 शिक्षा के आधार पर प्राप्त आंकड़ों की स्थिति

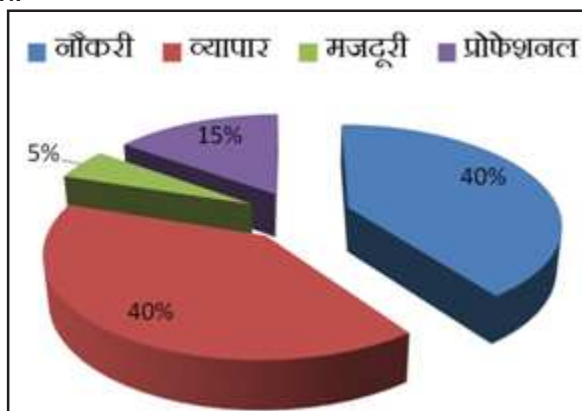


### तालिका क्रमांक -3 : व्यवसाय/कार्य के आधार पर जागरूक उपभोक्ताओं से प्राप्त आंकड़ों का अध्ययन

क्र.	व्यवसाय/कार्य	संख्या	प्रतिशत
1	नौकरी	120	40 %
2	व्यापार	120	40 %
3	मजदूरी	15	05 %
4	प्रोफेशनल	45	15 %
योग		300	100 %

व्यवसाय एवं कार्य के आधार पर जागरूकता संबंधी प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि, नौकरी एवं व्यापारी वर्ग में समान रूप से अधिनियम के प्रति जागरूकता देखी गई है। जिनका प्रतिशत 40 % है इसी क्रम में प्रोफेशनल एवं मजदूर वर्ग में जागरूकता का प्रतिशत क्रमशः 15 % एवं 5 % रहा है। कार्य/व्यवसाय के आधार पर प्राप्त परिणामों को निम्न ग्राफ क्रमांक 3 के माध्यम से दर्शाया गया है।

### ग्राफ क्रमांक - 3 : व्यवसाय/कार्य के आधार पर प्राप्त आंकड़ों की स्थिति



समाजिक जागरूकता के परिप्रेक्ष्य में आयु, शिक्षा एवं कार्य व्यवसाय के उपर्युक्त अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि, 31 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों में जागरूकता का सर्वाधिक प्रतिशत देखा गया है वहीं शिक्षा के स्तर के आधार पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा प्राप्त समाज का वर्ग इस अधिनियम के प्रति अधिक जागरूक है इस आधार पर कार्य एवं व्यवसाय के आधार पर प्राप्त जानकारी के अनुसार नौकरी एवं व्यापार में संलग्न समाज का वर्ग अधिनियम के प्रति अधिक जागरूक देखा गया है।

**अधिनियम की प्रभावशीलता में बाधक तत्व - उपभोक्ता संरक्षण**

अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु बनाया गया एक सशक्त व प्रभावशाली कानून है। 1991, 1993 तथा 2002 में इस अधिनियम में व्यापक संशोधन होने से इसकी जड़े और मजबूत हुई है फिर भी न्याय प्राप्ति हेतु उपभोक्ताओं को कानूनी प्रावधान व प्रक्रिया के मार्ग से गुजरना पड़ता है। हालांकि कई समस्याओं को दूर करने का प्रयास नवीन संशोधन 2019 में भी किया गया है जिसके परिणाम अभी देखने में नहीं आए हैं। उपर्युक्त संशोधनों के बाद भी उपभोक्ताओं को कभी-कभी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है जिससे न्याय प्राप्ति में अनावश्यक विलम्ब होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की प्रभावशीलता में निम्न बाधक तत्वों को प्रायः देखा जाता है जो इस प्रकार हैं :-

1. जिला उपभोक्ता फोरम में एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राज्य शासन के द्वारा की जाती है लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि, सदस्यों के नियुक्तियां समय पर नहीं किये जाने से लम्बे समय तक उनके पद खाली पड़े रहते हैं, जिससे जिला उपभोक्ता फोरम का कार्य प्रभावित होने के साथ ही उपभोक्ताओं को न्याय मिलने में अनावश्यक विलम्ब होता है।
2. कई राज्यों में ऐसे भी जिले भी हैं जिनके उपभोक्ता फोरम के साथ संयुक्त रूप से अन्य जिले के फोरम को जोड़ा गया है। ऐसे में देखने में यह आया है कि, मुख्य जिले में तो नियमित रूप से सदस्यों को बैठने से मुख्य जिला तो प्रभावित नहीं होता है परन्तु संयुक्त जिले में फोरम की सुनवाई हेतु बैठक की तिथियां राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने से वहां अल्प समय ही सुनवाई के लिये निर्धारित हो पाता है ऐसे में संयुक्त जिले के उपभोक्ताओं को न्याय मिलने में अनावश्यक विलम्ब का सामना करना पड़ता है।
3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जिला फोरम, राज्य एवं राष्ट्रीय आयोग में न्यायिक क्षेत्र से नियुक्त अध्यक्ष के अतिरिक्त अशासकीय सदस्य नियुक्त किये जाते हैं ताकि वे जनता या उपभोक्ताओं की समस्याओं का अनुभव कर सकें क्योंकि वे सीधे आम जनता अर्थात् समाज से सीधे आते हैं परन्तु वास्तविकता यह नहीं है, कई बार यह देखने में आता है कि, कुछ अशासकीय सदस्य जो उपभोक्ता समस्याओं के निराकरण में अपना हस्तक्षेप तो करने का प्रयास करते हैं पर उनकी आवाज को न्यायिक क्षेत्र से आए अध्यक्षों द्वारा दबा दिया जाता है क्योंकि फोरम या आयोग के अध्यक्ष एवं दोनों पक्षों के अधिवक्तागण न्यायिक एवं तकनीकी कार्यविधि में पारंगत होते हैं साथ ही इस संपूर्ण प्रक्रिया में अपनी अप्रत्यक्ष भूमिका का निर्वहन करने वाला पूरा कार्यालय भी कहीं न कहीं अपनी सहभागिता करता है, जो उपभोक्ता विवाद के निराकरण में विलम्ब करने में ही अपने कानूनी ज्ञान का दुरुपयोग करता है। कई बार यह भी देखने में आता है कि, पीड़ित उपभोक्ता, फोरम के समक्ष जाता तो बड़े उत्साह से है पर जैसे ही वह फोरम कार्यालय या वकीलों के संपर्क में आता है वह कानूनी पेंचीदगियों को देख कर निरुत्साहित हो जाता है।
4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत जिला फोरम, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग के गठन में अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति में जिसमें कि एक महिला सदस्य का होना आदेशात्मक है उनकी नियुक्तियों में, राजनीति का प्रभाव देखने में आता है जबकि अधिनियम के अंतर्गत सदस्यों के चयन के लिये योग्यता का वर्णन किया गया है।
5. कानूनी प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ ग्रामीण अंचल का पीड़ित उपभोक्ता

इस अधिनियम की जानकारी के अभाव में, उसे प्राप्त अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाता है और मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाता है। हमारे देश में अनेकों ऐसे लोक कल्याणकारी कानून तो प्रभावशील हैं परन्तु उनका ज्ञान व तत्संबंधी शिक्षा जनपद तथा ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण अंचल तक नहीं पहुंच पाती है जिससे उन्हें इसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता।

6. शोध के दौरान सदस्यों से चर्चा करने तथा पीड़ित उपभोक्ताओं से चर्चा करने से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया है कि, प्रत्येक जिला स्तर पर शासन ने फोरम की स्थापना तो की है पर आज भी कई फोरमों में कर्मचारियों, पक्षकारों आदि के बैठने की उपयुक्त व्यवस्था नहीं होने के साथ ही पर्याप्त संसाधनों जिनमें संचार साधन जैसे इंटरनेट, कम्प्यूटर, आधुनिक उपकरण एवं ऑनलाईन प्रकरणों को दर्ज करने की सुचारु व्यवस्था नहीं है।

7. अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है कि, उपभोक्ता अपने हितों के प्रति निरुत्साहित है। उपभोक्ता अधिकांशतः दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीद-फरोख्त करते हैं और देखने में आया है कि, वे इस रोज-मर्रा की खरीदी में ठगे भी जाते हैं पर वे इस प्रकार की ठगी की स्थिति में उपभोक्ता जिला फोरम में संरक्षण प्राप्त करने का साहस नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि जिला फोरम में दैनिक उपयोग की वस्तुओं के संबंध में न्यायिक प्रक्रिया की कानूनी पैचीदगियों को देख कर, उपभोक्ता हतोत्साहित हो जाता है और सामग्री के मूल्य की तुलना में न्यायिक प्रक्रिया पर होने वाले व्यय और समयाभाव, अधिनियम से न्याय प्राप्ति की दिशा में बाधक बन जाता है।

8. शोध के दौरान किये गये अध्ययन एवं प्रकरणों के अवलोकन से यह तथ्य भी सामने आया है कि, ऐसे बहुत से मामले जिनका संबंध उपभोक्ता फोरम से नहीं होकर जो सिविल प्रकृति या सर्विस मेटर है उन्हें भी उपभोक्ता फोरम में आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाता है जिस पर कोई प्रारम्भिक

रोक की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार फोरम में ऐसे भी मामले प्रस्तुत कर दिये जाते हैं जो अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं।

9. शोध के दौरान किये गये अध्ययन से यह महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आया है कि, जन साधारण उपभोक्ता फोरम की सुविधाजनक प्रक्रिया का दुरुपयोग भी करने का प्रयास करते हैं। प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर लाभ लेने की प्रवृत्ति के व्यक्ति जो यह जानते हैं कि, फोरम के माध्यम से कार्यवाही न्यूनतम शुल्क एवं कानूनी पैचीदगियों के अभाव में आसानी से हो जाती है ऐसे में वे सरकारी एजेन्सियों को फोरम में बुलवाकर अपने अहम कि तुष्टि करने में विश्वास रखते हैं। वहीं कुछ उपभोक्ता अपने अहम के चलते दुकानदारों को उपभोक्ता अदालत की धमकी दे कर अपने सामान को दो बार बदलवाने के बाद भी वारंटी बढ़ाने के लिये या वस्तु वापस करके उसे मूल्य वापस देने की मांग से भी फोरम के समक्ष जाने में विश्वास रखते हैं।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उपभोक्ता अधिकार संतोष खन्ना, प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण, मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपभोक्ता संरक्षण-एक परिचय, वीरेन्द्र नाथ मिश्र एवं अमित कुमार सिंह, उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र, भारतीय लोकप्रशासन संस्थान नई दिल्ली।
3. उपभोक्ता के अधिकार-एक विवेचन, संकलनकर्ता डॉ. ललित मोहन जोशी एवं वीरेन्द्र नाथ मिश्र, उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र, भारतीय लोकप्रशासन संस्थान इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली, 110002
4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, राजस्थान लॉ हाउस, अनिल सचदेवा, 2004

\*\*\*\*\*



## अभ्यास शिक्षण के दौरान शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व

डॉ. नीलम निगम\* श्रीमती सुषमा शर्मा\*\*

**शोध सारांश** - वर्तमान संचार क्रांति के युग में शिक्षक का कार्य केवल बालक को सूचनायें प्रदान करना था ज्ञान अभिवृद्धि ही नहीं है अपितु उसके व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास करना है। शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु नित नवीन साधनों का प्रयोग करता है। वे सभी साधन जो शिक्षण-प्रक्रिया को रोचक आकर्षक लाभप्रद ग्राह्य तथा प्रभावशाली बनाते हैं श्रव्य-दृश्य सामग्री कहलाते हैं। इनकी सहायता से शिक्षण-उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति होती है। श्रव्य-दृश्य सामग्री न केवल शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं बल्कि शिक्षण की प्रविधियाँ अथवा युक्तियों को भी प्रभावशाली बनाती हैं।

अधिगम की परिस्थितियों को उत्पन्न करने तथा अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सम्प्रेषण शिक्षण-युक्तियों तथा आव्यूह का चयन किया जाता है। इनको प्रभावशाली बनाने में दृश्य-श्रव्य सहायक सामग्री के प्रयोग से अधिगम की परिस्थितियों को अधिक प्रभावशाली रूप में उत्पन्न किया जा सकता है और उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति की जा सकती है। ई.सी.डेन्ट के अनुसार- श्रव्य-दृश्य सामग्री का अर्थ उस समस्त सामग्री से है जो कक्षा में अथवा अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य-सामग्री को समझाने में सहायता देती है।

**प्रस्तावना** - एरिक एशबी ने 1967 में चार क्रांतियों का उल्लेख किया तो उन्हें इस बात का आभास भी नहीं होगा कि चौथी क्रांति शैक्षिक क्षेत्र में पांचवी क्रांति को जन्म देगी।

पहले मौखिक शिक्षा प्रचलित थी बाद में शिक्षा उपकरण के रूप में लिखित शब्दों का प्रयोग होने लगा। यह दूसरी क्रांति थी जिसके फलस्वरूप स्कुलों में मौखिक शिक्षा के साथ लिखित शिक्षा ने भी स्थान बना लिया।

तीसरी क्रांति मुद्रण के आविष्कार के साथ आई तथा पुस्तकें उपलब्ध होने लगी। इलेक्ट्रानिक्स तकनीकी के क्षेत्र में आए विकासशील परिवर्तन चौथी क्रांति के सूचक थे रेडियो तथा टेलीफोन आदि का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में होने लगा।

कम्प्यूटर ई-मेल डिजिटल वीडियो तथा इन्टरनेट के आने पर शिक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ। इन साधनों ने शिक्षा के क्षेत्र में पुरानी अवधारणों में आधुनिक संदर्भ के साथ अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन करके उन्हें एक नया स्वरूप प्रदान किया। लेकिन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज सरल सक्षम तथा प्रभावशाली बनाने के लिए सहायक सामग्री का उचित प्रयोग उचित समय पर करना आवश्यक होता है। एडगर डेल द्वारा कोन के माध्यम से सहायक सामग्री के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है इनके द्वारा बताया गया है कि मौखिक शब्दों का प्रभाव सबसे कम तथा प्रत्यक्ष साधनों का प्रभाव शिक्षण दौरान सबसे अधिक पड़ता है।

जीन पियाजे द्वारा भी बहुइन्द्रिय अनुदेशन द्वारा बताया गया है कि अधिगम प्रक्रिया दौरान प्रत्यक्ष वस्तुओं के उपयोग द्वारा विद्यार्थी उचित तरीके से अधिगम करते हैं प्रत्यक्ष वस्तुओं के द्वारा शिक्षक और छात्र दोनों के मध्य अन्तःक्रिया संभव होती है वर्तमान समय में कम्प्यूटर डिजिटल वीडियो तथा इन्टरनेट के प्रयोग से विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं साथ ही वर्तमान में शिक्षण सामग्री चार्ट मांडल के स्थान पर स्मार्ट बोर्ड स्मार्ट कक्षा आदि का प्रयोग होने

लगा है। लेकिन शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व आज भी विद्यमान है क्योंकि बी.एड. प्रशिक्षु शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा शिक्षण में प्रभावशीलता लाने के लिए आज भी कर रहे हैं क्योंकि प्रत्येक समय प्रत्येक जगह स्मार्ट बोर्ड स्मार्ट कक्षा उपलब्ध नहीं हो सकती है।

वर्तमान संचार क्रांति के युग में शिक्षक का कार्य केवल बालक को सूचनायें प्रदान करना था ज्ञान अभिवृद्धि ही नहीं है अपितु उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु नित नवीन साधनों का प्रयोग करता है। वे सभी साधन जो शिक्षण-प्रक्रिया को रोचक आकर्षक लाभप्रद ग्राह्य तथा प्रभावशाली बनाते हैं श्रव्य-दृश्य सामग्री कहलाते हैं इनकी सहायता से शिक्षण-उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति होती है श्रव्य-दृश्य सामग्री न केवल शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं बल्कि शिक्षण की प्रविधियाँ अथवा युक्तियों को भी प्रभावशाली बनाती हैं। इस हेतु ही शोधकर्ता द्वारा अभ्यास शिक्षण के दौरान बी.एड. प्रशिक्षु द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्या शिक्षण को प्रभावशाली एवं ग्राह्य बनाता है जानने का प्रयास किया गया है।

**उद्देश्य**- अभ्यास शिक्षण के दौरान शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके शिक्षण की प्रभावशीलता में वृद्धि का अध्ययन करना।

1. क्या अभ्यास शिक्षण के दौरान शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग आवश्यक है।
2. शिक्षण सहायक सामग्री से शिक्षण में प्रभावशीलता आती है।
3. आकर्षक शिक्षण सामग्री से द्वारा विद्यार्थी शिक्षण के प्रति आकर्षित होते हैं।
4. स्मार्ट कक्षा द्वारा अध्ययन से विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता में विकास हो रहा है।

**परिक्ल्पना :**

1. अभ्यास शिक्षण के दौरान शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व का अध्ययन करना
2. अभ्यास शिक्षण के दौरान सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करके शिक्षण की प्रभावशीलता में वृद्धि का अध्ययन करना।

**प्रादर्श एवं प्रयोज्य**—प्रादर्श के अंतर्गत बी.एड.के 100 विद्यार्थियों पर स्वनिर्मित प्रश्नावली के माध्यम से चर्चा की गई यदि उनके द्वारा प्रभावशाली सहायक सामग्री उपयोग की जाती है तो उसका प्रभाव विद्यार्थियों पर किस तरह पड़ता है एवं नहीं की जाती तो उसका प्रभाव विद्यार्थियों पर किस तरह पड़ता है।

**उपकरण**—इस कार्य हेतु स्वनिर्मित मापनी का प्रयोग किया गया शिक्षण मापनी में 35 प्रश्नों को तैयार किया गया विषय विशेषज्ञों की जांच पश्चात् 25 प्रश्न सही पाए गए जिन्हें अध्ययन दौरान उपयोग किया गया।

**प्रस्तावित समस्या**—प्रस्तुत अध्ययन में अनुसंधान का प्रमुख लक्ष्य है कक्षा शिक्षण बिना सहायक सामग्री के उपयोग द्वारा करना एवं सहायक सामग्री के साथ करना एवं तत्पश्चात् यह देखना कि विद्यार्थियों की क्षमता में कितनी वृद्धि होती है।

**प्रदत्तों का संकलन**—प्रस्तुत शोध में प्रदत्तों का संकलन हेतु स्वनिर्मित मापनी का उपयोग किया गया।

**अध्ययन चर**— शिक्षण सहायक सामग्री

**सांख्यिकीय प्रविधियाँ**—सांख्यिकीय यदि देखा जाए तो शोध का मूल आधार होता है आंकड़ों के संकलन के पश्चात् ही अनुसंधानकर्ता विभिन्न चरों के मध्य संबंध स्थापित करता है प्रस्तुत अध्ययन में सहसंबंध सांख्यिकीय का प्रयोग किया गया है

**तालिका क्रमांक 01 शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के विभिन्न आयामों द्वारा शिक्षण की प्रभावशीलता में वृद्धि का अध्ययन करना।**

क्रं	आयाम	प्रतिशत	
		हाँ	नहीं
1	अभ्यास शिक्षण के दौरान नवाचार का उपयोग	53%	47%
2	आर्कषक शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग से अधिगम का विकास	70%	30%
3	नवाचार से शिक्षण प्रभावशीलता में वृद्धि	65%	35%
4	स्मार्ट कक्षा द्वारा सीखने की क्षमता का विकास	56%	44%

उपयुक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि अभ्यास शिक्षण के दौरान नवाचार का उपयोग 53 बी.एड. प्रशिक्षु करना हेतु सहमति व्यक्त करते हैं लेकिन 47 प्रतिशत इसकी आवश्यकता पर जोर नहीं देते। आर्कषक शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग से अधिगम का विकास के लिये 70 प्रतिशत बी.एड. प्रशिक्षु सही मानते हैं लेकिन 30 प्रतिशत कहते हैं कि इसके उपयोग से अधिगम का विकास नहीं होता। नवाचार से शिक्षण प्रभावशीलता में वृद्धि हेतु 65 प्रतिशत बी.एड. प्रशिक्षु कहते हैं कि निम्न प्रकार की शिक्षण सामग्री के उपयोग से प्रभावशीलता में वृद्धि होती है जबकि 35 प्रतिशत कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता। स्मार्ट कक्षा द्वारा सीखने की क्षमता का विकास के बारे में 56 प्रतिशत बी.एड. प्रशिक्षु कहते हैं कि विद्यार्थियों की क्षमता का विकास होता है। लेकिन 44 प्रतिशत कहते हैं कि यदि जहाँ स्मार्ट कक्षा नहीं होती तो क्या विद्यार्थियों की क्षमता का विकास नहीं होता।

**तालिका क्रमांक 02 प्रस्तुत अध्ययन में अनुसंधान का प्रमुख लक्ष्य है शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके शिक्षण की प्रभावशीलता में वृद्धि का अध्ययन करना।**

चर	एन	सहसंबंध गुणांक	सहसंबंध गुणांक का विश्लेषण
शिक्षण सहायक सामग्री के साथ	100	0.886	सार्विक एवं उच्च धनात्मक सहसंबंध
प्रभावशाली कक्षा शिक्षण	100		

उपयुक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि प्रभावशाली कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके अध्ययन द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि इन दोनों में 0.886 धनात्मक सहसंबंध पाया गया जोकि यह सिद्ध करता है कि सहायक शिक्षण सामग्री के उपयोग द्वारा कक्षा शिक्षण प्रभावी होता है एवं विद्यार्थी की सीखने की क्षमता में वृद्धि भी होती

**शैक्षिक महत्व**—शोधकार्य से प्राप्त परिणाम द्वारा यह ज्ञात होता है कि सफल शिक्षण की कसौटी पाठ का बालकों की समझ में ठीक-ठाक आना है किसी भी पाठ को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को समझाने के लिये दो प्रकार के साधन अपनाये जाते हैं प्रथम वह साधन जैसे—श्यामपट्ट चॉक डस्टर आदि दूसरा साधन—मॉडल चित्र चार्ट फूल पौधे पत्तियाँ स्मार्ट क्लास आदि। शिक्षण को प्रभावी बनाने की दृष्टि से दृश्य-श्रव्य सामग्री के प्रयोग से छात्र पाठ में अधिक रूचि लेते हैं और सीखने में अधिक रूचि लेते हैं।

**निष्कर्ष**—विश्लेषण एवं विवेचन से यह ज्ञात होता है कि शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग द्वारा परंपरागत तरीके से होने वाले अध्ययन की निरसता एवं बोझिलता की जगह प्रभावशाली कक्षा शिक्षण रोचकता खेल-खेल में सीखना आदि ने ले ली है साथ ही शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस तरह करना चाहिये यह भी महत्वपूर्ण है एक अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री के गुण क्या होते हैं उपयुक्त समस्त बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है।

**अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री के गुण :**

1. सहायक सामग्री पाठ की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए।
2. सहायक सामग्री विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए।
3. सहायक सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो सरलता से उपलब्ध हो सके।
4. सहायक सामग्री को प्रयोग में लाने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए।
5. सहायक सामग्री प्रेरणादायक होनी चाहिए।
6. सहायक सामग्री के प्रदर्शन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
7. स्व निर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग जहाँ तक सम्भव हो करना चाहिए।
8. विद्यार्थियों को भी इसके प्रयोग का अवसर प्रदान करना चाहिए।
9. सहायक सामग्री ऐसी जगह सेट हो जहाँ सभी विद्यार्थियों की दृष्टि जा सके तथा उससे सम्बन्धित प्रश्नों का वे उत्तर दे सके।
10. सहायक सामग्री में विविधता होनी चाहिए।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. प्रीति गुप्ता /क्रान्ति वर्मा, सूक्ष्म शिक्षण, 2018, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा।
2. स्मिता श्रीवास्तव, कम्प्यूटर एवं संचार तकनीकी, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा।
3. आर.ए.शर्मा, शिक्षा के तकनीकी आधार, 2004, आर.लाल. बुक डिपो मेरठ।
4. बी.एन.शर्मा, हिन्दी शिक्षण, साहित्य प्रकाशन आगरा।

## भारत में महिला शिक्षा एवं रोजगार

डॉ. ए.के. पाण्डेय \*

**प्रस्तावना** - संस्कृत में एक प्रसिद्ध श्लोक है- 'नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति मातृ समोगुरु' इसका अर्थ यह है कि इस दुनिया में विद्या के समान नेत्र नहीं है और माता के समान गुरु नहीं है। यह बात पूरी तरह सत्य है। बालक के विकास में प्रथम और सबसे अधिक प्रभाव माता का ही पड़ता है। माता ही अपने बच्चों को पाठ पढ़ाती है, बालक का यह प्रारंभिक ज्ञान पत्थर पर बनी अमिट लकीर के समान जीवन का स्थायी आधार बन जाता है। इस प्रकार प्रत्येक विकसित समाज के निर्माण में स्त्री एवं पुरुष दोनों की सहभागिता आवश्यक है। भावी पीढ़ी के रूप में व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज तथा राष्ट्र तक के चहुंमुखी विकास की जिम्मेदारी में पुरुषों के साथ स्त्रियों की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी है। इस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ही परिवार की धुरी महिला का सशक्तिकरण जरूरी है और सशक्तिकरण के लिए शिक्षा।

शिक्षा आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पहला और मूलभूत साधन है। शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त, समान व उपयोगी भूमिका दर्ज करा सकती है। दुनिया के जो भी देश आज समृद्ध और शक्तिशाली हैं, वे शिक्षा के बल पर ही आगे बढ़े हैं। इसलिए आज समाज की आधी आबादी अर्थात् महिलाएं जो कि विकास की मुख्य धारा से बाहर हैं, उन्हें शिक्षित बनाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस संदर्भ में राधाकृष्णन् आयोग ने कहा है कि- 'स्त्रियों के शिक्षित हुए बिना किसी समाज के लोग शिक्षित नहीं हो सकते। यदि सामान्य शिक्षा स्त्रियों या पुरुषों में से किसी एक को देने की विवशता हो, तो यह अवसर स्त्रियों को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर निश्चित रूप से वह शिक्षा उनके द्वारा अगली पीढ़ी तक पहुंच जाएगी। इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह बात स्वीकार की गई है कि महिला शिक्षा का महत्व न केवल समानता के लिए, बल्कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए भी जरूरी है।

भारत में स्वतंत्रता के बाद सन् 1947 में 'विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग' का गठन किया गया। जिसकी मुख्य सिफारिश महिला शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। भारत सरकार ने महिला साक्षरता के लिए साक्षर भारत मिशन की शुरुआत की। इस मिशन में महिलाओं की शिक्षा दर को ऊपर लाने की कोशिश की गई। महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार स्वतंत्रता पश्चात् विशेषकर 1991 से आर्थिक उदारीकरण के पश्चात् आया। देश में सरकार, महिला संगठनों, महिला आयोगों आदि के प्रयासों से देश में महिला समाज के लिए तेजी से विकास के द्वार खुले, शिक्षा का प्रसार बढ़ा, जिससे उनमें जागृति आई, और उनके भीतर आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ।

**चुनौतियां** - आज महिलाएं राजनीति, समाज सुधार, शिक्षा, पत्रकारिता,

साहित्य, विज्ञान, उद्योग, व्यावसायिक प्रबंधन, शासन-प्रशासन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पुलिस, सेना, कला, संगीत, खेलकूद आदि क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रही हैं। एक ओर यह परिदृश्य अत्यधिक उत्साहवर्धक है परंतु वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य पर दृष्टि डाले तो पता चलता है कि आज भी शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

आज भी देश में महिलाओं की आधी आबादी शिक्षा जैसी बुनियादी अधिकार से वंचित है। आजादी के पश्चात् महिला साक्षरता में वृद्धि हुई है किंतु यह संतोषजनक नहीं रही है। महिला साक्षरता की स्थिति को निम्न सारिणी में प्रदर्शित किया गया है-

### महिला साक्षरता की स्थिति

वर्ष	महिला साक्षरता (प्रतिशत में)	महिला साक्षरता में दशक वृद्धि
1951	8.86	—
1961	15.34	6.48
1971	21.97	6.63
1981	29.29	7.88.
1991	39.29	9.44
2001	54.16	14.87
2011	65.46	18.12

स्रोत-कुरुक्षेत्र, अगस्त 2013

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है, कि महिला शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन उदारीकरण (1991) के पश्चात् आया। जब साक्षरता (1991-2001) 39.29 प्रतिशत से बढ़कर 54.16 प्रतिशत हो गई। अर्थात् दशक वृद्धि 9.44 प्रतिशत से बढ़कर 14.87 प्रतिशत (5.43 अंको) हुई। जबकि 1961 से 1991 की तुलना में अर्थात् 30 वर्षों में यह वृद्धि मात्र 2.96 प्रतिशत रही।

उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के पश्चात् भारतीय समाज का बुनियादी ढांचा भी तेजी से बदलने लगा। सामाजिक वर्जनाएं टूटने लगी। परम्पराओं एवं रूढ़ियों की पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। जिसका प्रमुख कारण बाजारवाद का प्रसार तथा आधुनिक तौर-तरीके एवं पश्चिमीकरण रहा है। ऐसी स्थिति में महिलाओं की शिक्षा, उनकी कार्यक्षमता एवं उन्हें रोजगार के साधन (मानव साधन) के रूप में देखने का नजरिया तेजी से बदलने लगा। जिसका प्रभाव महिला शिक्षा एवं रोजगार के प्रति महिलाओं की बढ़ती रुचि एवं आत्मविश्वास के रूप में भी देखा गया।

1991 के पश्चात् महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि एवं महिलाओं में आत्मनिर्भरता एवं रोजगार के प्रति बढ़ते रुझान का प्रभाव महिला रोजगार

पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 1991 से 2010 के मध्य देश में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में महिलाओं में रोजगार के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। जिसे निम्न सारिणी में प्रदर्शित किया गया है -

**सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में महिलाओं में रोजगार परिदृश्य**

वर्ष	सरकारी क्षेत्र में महिला रोजगार (प्रतिशत में)	निजी क्षेत्र में महिला रोजगार (प्रतिशत में)
1991	23.47	14.34
2000	28.57	20.66
2004	28.90	20.44
2006	30.03	21.18
2008	30.4	24.72
2009	30.91	24.98
2010	31.96	26.63

स्रोत- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, आर्थिक समीक्षा 2011-21

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि 1991 से 2010 के मध्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में महिला रोजगार (प्रतिशत में) में वृद्धि क्रमशः ( + 8.49 प्रतिशत एवं क्रमशः + 12.29 प्रतिशत) हुई है। जबकि इसी अवधि में दोनों क्षेत्रों में पुरुषों में रोजगार की दर में गिरावट हुई है। आज देश में महिलाएं पारम्परिक वर्जनाओं को ताड़ते हुए लैंगिक मान्यताओं को चुनौती देते हुए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता की राह में तेजी से आगे बढ़ रही हैं।

उदारीकरण के पश्चात् ही बालिका शिक्षा में उत्साहजनक परिणाम आए हैं। जिससे लिंग भेद सूचकांक (GPI) की प्राथमिक स्तर पर 0.94 प्रतिशत तथा उच्चतर, माध्यमिक स्तर पर 0.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्राथमिक स्तर पर तथा उच्चतर प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ा है। 5-14 वर्ष के आयु समूह में विद्यालयों में लड़कियों की संख्या 2004-05 में 79.6 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 87.7 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार 15-19 वर्ष के आयु समूह में शिक्षा प्रणाली में लड़कियों की संख्या 40.3 प्रतिशत से बढ़कर 54.6 प्रतिशत हो गई। तथा 20-24 वर्ष के आयु समूह में इसी अवधि के दौरान 7.6 प्रतिशत से बढ़कर 12.8 प्रतिशत हो गई। प्राथमिक स्तर के मुकाबले उच्च प्राथमिक स्तर पर उपस्थिति कम थी। इसलिए चुनौती उच्च नामांकन को उच्च उपस्थिति दरों में परिवर्तित करने की है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अथवा साक्षर भारत में स्त्री साक्षरता के लक्ष्य को महिला सशक्तिकरण हेतु एक महत्वपूर्ण साधन माना है। इससे महिलाओं में साक्षरता दर 53.67 प्रतिशत (2001) से बढ़कर 65.46 प्रतिशत (2011) हो गई। पहली बार इस दशक के दौरान 217.70 मिलियन साक्षरों में महिलाओं की संख्या (110.07 मिलियन) पुरुषों से अधिक है। महिला साक्षरता में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में भारी असमानता दिखाई देती है। नगरीय क्षेत्र की महिला साक्षरता 72.99 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 46.58 प्रतिशत है। इसी प्रकार प्राथमिक स्तर पर प्रवेश लेने वाली बालिकाओं में से 24.82 प्रतिशत कक्षा 5 तक की पढ़ाई पूरी

नहीं कर पाती और उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 50.76 प्रतिशत बालिकाओं को बीच में ही विद्यालय छोड़कर घरेलू कार्यों में संलग्न होना पड़ता है जिसका मुख्य कारण स्कूल का दूर होना, यातायात की अनुपलब्धता, घरेलू काम, छोटे भाई-बहनों की देखरेख, आर्थिक व विभिन्न सामाजिक समस्याएं आदि कुछ ऐसे कारण हैं जो कि बालिका शिक्षा की राह में बाधा उत्पन्न करते हैं।

**समाधान -** आज देश में बालिका शिक्षा का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में करने की महती आवश्यकता है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। देश की विकासशीलता के परिवेश में यह विचार करना आवश्यक है कि महिलाओं की शिक्षा किस प्रकार की हो ? महिलाओं को मात्र साक्षर न बनाया जाए बल्कि उन्हें ऐसी व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए जो उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में मददगार सिद्ध हो। यदि महिलाएं शिक्षित होकर आत्मनिर्भर होंगी तो उनको स्वयं का महत्व समझते देर नहीं लगेगी तथा धीरे-धीरे दूसरों की नजरों में भी उनका स्थान महत्वपूर्ण हो जाएगा। शिक्षित, आत्मनिर्भर एवं सशक्त महिलाओं के द्वारा ही भारत का एक सशक्त व विकसित देश के रूप में निर्माण कर पाना सम्भव हो सकेगा।

शिक्षा प्राप्त करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का अर्थ यह नहीं है कि नारी शिक्षित होकर पुरुष को अपना प्रतिद्वन्दी मानते हुये उसके सामने ही मोर्चा लेकर खड़ी हो जाये। बल्कि वह आर्थिक क्षेत्र में भी पुरुष के बराबर समानता का अधिकार प्राप्त करके उसके साथ मैत्रापूर्ण सम्बन्ध बनाए। जिस प्रकार शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मानसिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। अगर नारी ही शिक्षित नहीं होगी तो वह न तो सफल गृहणी बन सकेगी और न ही कुशल माता। समाज में बाल-अपराध बढ़ने का कारण बालक का मानसिक रूप से विकसित न होना है। अगर माँ ही अशिक्षित होगी तो वह अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करके उनका मानसिक विकास कैसे कर पाएगी ? और एक स्वस्थ समाज का निर्माण एवं विकास सम्भव नहीं हो सकेगा। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षित नारी ही भविष्य में निराशा एवं शोषण के अंधकार से निकलकर परिवार, समाज व राष्ट्र के विकास एवं उत्थान में अपना दायित्व सही अर्थों में स्थापित कर पाएगी।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. मिश्र एवं पुरी, 'भारतीय अर्थव्यवस्था' हिमालया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2009।
2. डॉ० माहेश्वरी पी०डी० एवं डॉ० गुप्ता शीलचंद्र, 'भारतीय आर्थिक नीति', कैलाश पुस्तक सदन, 2006।
3. प्रतियोगिता दर्पण 'भारतीय अर्थव्यवस्था' विशेषांक 2013।
4. आर्थिक समीक्षा 2011-12
5. आर्थिक समीक्षा 2010-11
6. मानव विकास रिपोर्ट 2011-12,
7. कुरुक्षेत्र, अगस्त 2013



## बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों द्वारा नवाचार एवं अच्छी आदतों के उपयोग का अध्ययन

डॉ. नीलम निगम\*

**प्रस्तावना** – वर्तमान शिक्षा प्रणाली पुनर्रचना के दौर में है उसका उद्देश्य मात्र कक्षा उन्नति रह गया है कक्षा की शैक्षिक सामग्री को आत्मसात करना नहीं है। हमारे अधिकांश विद्यार्थियों की उपलब्धि क्या है और क्या होनी चाहिए इसके बारे में किसी की भी सोच नहीं है समस्त शिक्षक पाठ्य-पुस्तकों में जो भी लिखा है उसे पढ़ाने रटाने में सतत क्रियाशील है बस विद्यार्थी रटन्त प्रक्रिया को अपना लें और कक्षा में टॉप कर लें। लेकिन उसने क्या सीखा इस पर किसी का ध्यान नहीं है अभिभावक भी चाहते हैं कि उनका बच्चा आई.ई.एस डॉक्टर आदि बने। शिक्षा को भी रटन्त प्रक्रिया से पूर्ण किया जा रहा है कुछ नवाचार किया जाए संस्कार रोपित किए जाये इन सभी बातों पर किसी का भी ध्यान नहीं गया है।

यदि देखा जाये तो शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम महात्मा गाँधी द्वारा बेसिक शिक्षा का प्रारूप तैयार किया गया था महान वैज्ञानिक रूसो ने भी कहा था करके सीखो वर्तमान समय में विद्यार्थियों में कौशल का विकास करना चाहिए उनकी बेसिक शिक्षा मजबूत होना चाहिए इस पर ध्यान देना चाहिए लेकिन हम बरसों पुरानी मैकाले पद्धति को ही हम अपनाकर चल रहे हैं बाबू तैयार करना।

विश्व में हो रही गतिविधियों पर यदि नजर जाती है तो पता चलता है कि विद्यार्थी वर्ग संस्कारविहीन गुरुसे वाला चिडचिडा होता जा रहा है आखिर क्यों क्या कारण है बात-बात पर आपा खो देना जरा सी बात पर आत्महत्या जैसे कदम उठा लेना आदि। आखिर किन मनोवैज्ञानिक कारणों से विद्यार्थी जूझ रहा है मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति भी ठीक नहीं है उक्त अनेकानेक कारणों की खोज हेतु ग्रीन वैली कॉलेज के विद्यार्थियों पर एक केस स्टडी की गई पहले कक्षा में उन्हें नवाचारिक प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया गया दैनिक जीवन में अच्छी आदतों के इस्तेमाल करने के बारे में पढ़ाया गया सिखाया गया तत्पश्चात् बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अभ्यास शिक्षण के समय नवाचारिक प्रयोग एवं अच्छी आदतों का उपयोग करते हुए शिक्षण कार्य करने कहा गया।

उपयुक्त विषय हेतु निम्नांकित उद्देश्यों का निर्माण किया गया एवं इन्हीं के आधार पर अध्ययन किया गया।

### उद्देश्य:

1. नवाचारिक प्रयोग द्वारा शिक्षण एवं परंपरागत तरीको से शिक्षण करने वालों का अध्ययन करना।
2. अच्छी आदतों का उपयोग सिखाने से मानसिक स्वास्थ्य एवं संस्कारों में परिवर्तन का अध्ययन करना।

### परिकल्पना:

1. नवाचारिक प्रयोग द्वारा शिक्षण एवं परंपरागत तरीको से शिक्षण करने वालों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. अच्छी आदतों का उपयोग सिखाने से मानसिक स्वास्थ्य एवं संस्कारों के परिवर्तन में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

**अध्ययन का न्यादर्श**– ग्रीन वैली कॉलेज ऑफ एजुकेशन के 50 प्रशिक्षणार्थियों को केस स्टडी हेतु चुना गया।

**शोध विधि**– ग्रीन वैली कॉलेज ऑफ एजुकेशन के 50 प्रशिक्षणार्थियों को अभ्यास शिक्षण द्वारा अवलोकन किया गया केस स्टडी प्रत्येक प्रशिक्षु की कि गई यह देखा गया कि नवाचारिक प्रयोग एवं परंपरिक पद्धति से पढ़ाने में क्या परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। अभ्यास शिक्षण के दौरान बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों द्वारा विभिन्न शालाओं में शिक्षण कार्य किया गया प्रत्येक प्रशिक्षु की कक्षाओं को अवलोकन किया गया कि उनकी द्वारा किस तरह के नवाचारिक प्रयोगों का उपयोग किया जा रहा है साथ ही कौन सी अच्छी आदतों को सिखाया जा रहा है।

**ऑकड़ों का मूल्यांकन**–शोध का मूल आधार सांख्यिकीय विप्लेषण होता है आंकड़ों के संकलन पश्चात् चरों के मध्य संबंध स्थापित करके विश्लेषण करता है। प्रस्तुत अध्ययन में टी सांख्यिकीय का प्रयोग किया गया है।

### परिकल्पना क्रमांक- 1

#### सारणी क्रमांक - 1

समूह	प्रतिदर्श	मध्यमान	मानक विचलन	मुक्तांश	टी स्तर	सार्थकता
शिक्षण के समय नवा-चारिक पद्धति प्रयोग करने वाले प्रशिक्षु	25	17.98	3.80	48	2.1	सार्थक अंतर
शिक्षण के समय पुरातन पद्धति प्रयोग करने वाले प्रशिक्षु	25	13.56	2.50			

उपरोक्त सारणी क्रमांक 1 से स्पष्ट है कि शिक्षण के समय नवाचारिक पद्धति प्रयोग करने वाले प्रशिक्षु एवं शिक्षण के समय पुरातन पद्धति प्रयोग करने वाले प्रशिक्षु का मध्यमान 17.98 एवं 13.56 पाया गया। शिक्षण के समय नवाचारिक पद्धति प्रयोग करने वाले प्रशिक्षु का मानक विचलन 3.80

तथा शिक्षण के समय पुरातन पद्धति प्रयोग करने वाले प्रशिक्षु का मानक विचलन 2.50 है अन्तर की सार्थकता के लिए निकाले गए टी अनुपात का मान 2.1 है जो 0.05 विश्वास के स्तर के लिए न्यूनतम निर्धारक मान 1.99 से अधिक है। अतः इन दोनों समूहों में सांख्यिकी दृष्टिकोण से सार्थक अन्तर है अतः गणना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षण के समय नवाचारिक पद्धति प्रयोग करने वाले प्रशिक्षु अधिक है इस प्रकार उक्त परिकल्पना असत्य है एवं अस्वीकृत होती है।

### परिकल्पना क्रमांक-2

#### सारणी क्रमांक -2

समूह	प्रतिदर्श	मध्यमान	मानक विचलन	मुक्तांश	टी स्तर	सार्थकता
शिक्षण के समय अच्छी आदतें सिखाने वाले प्रशिक्षु	25	19.6	3.54	48	3.75	सार्थक अंतर
शिक्षण के समय अच्छी आदतें नहीं सिखाने वाले प्रशिक्षु	25	15.54	2.02			

उपरोक्त सारणी क्रमांक 2 से स्पष्ट है कि शिक्षण के समय अच्छी आदतें सिखाने वाले प्रशिक्षु एवं शिक्षण के समय अच्छी आदतें नहीं सिखाने वाले प्रशिक्षु का मध्यमान 19.6 एवं 15.54 पाया गया। शिक्षण के समय अच्छी आदतें सिखाने वाले प्रशिक्षु का मानक विचलन 3.54 तथा शिक्षण के समय अच्छी आदतें नहीं सिखाने वाले प्रशिक्षु का मानक विचलन 2.02 है अन्तर की सार्थकता के लिए निकाले गए टी अनुपात का मान 3.75 है जो 0.05 विश्वास के स्तर के लिए न्यूनतम निर्धारक मान 1.99 से अधिक है। अतः इन दोनों समूहों में सांख्यिकी दृष्टिकोण से सार्थक अन्तर है अतः गणना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षण के समय अच्छी आदतें सिखाने से विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य आदतों कार्यों में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है इस प्रकार उक्त परिकल्पना असत्य है एवं अस्वीकृत होती है।

### परिणाम

**नवाचार -** नवाचार नई रीति नई विचारों का प्रचलन या नवप्रवर्तन है नवाचार के दो रूप होते हैं। समस्या समाधान नवाचार स्थापित प्रणाली में सुधार लाना उत्पन्न समस्या के निराकरण में किसी नवीन पद्धति विधि तकनीक का प्रयोग किया जाता है।

द्वितीय रूप के अंतर्गत शिक्षा के किसी उपकरण विद्यालय के शिक्षकों से विचारकों के समुदाय आदि के विचारार्थ या वाद-विवाद से किसी नवाचार की जानकारी शामिल की जाती है।

नवाचारिक प्रयोग-सी.बी.एस.ई. दिल्ली द्वारा भी कहा गया है कि विद्यार्थियों को क्रिटिकल थीकिंग सिखाये सी.बी.एस.ई. ने सुझाव दिया है कि क्लासरूम एक्टिविटीज में हफ्ते में कोई ऐसा सवाल बच्चों को दें जिसका उत्तर वे मिलकर ढूँढें। सप्ताह के अंत में उन्हें सही जबाब बताया जाये ताकि जिन बच्चों के जवाब गलत थे वे इस पर चर्चा करें और समझें कि आखिर इस सवाल के जवाब तक किस तरह पहुंचना था।

इसी प्रकार ग्रीन वैली कॉलेज के बी.एड. प्रशिक्षु द्वारा नवाचारिक शिक्षण के प्रयोग दौरान विद्यार्थियों को आकार के बारे में पढ़ाना है तो कक्षा

में विभिन्न तरह के आकार ढूँढकर बतायें उदा. 1-ब्लैक बोर्ड की लं.चौ. बतायें। उदा.2-यदि कक्षा में कलर करना है तो कितने पेंट के डिब्बे लगेंगे इस तरह विद्यार्थी लं.चौ. क्षेत्रफल के बारे में अच्छी तरह सीखेंगे इसी तरह यदि हिन्दी में व्याकरण पढ़ाना है तो विद्यार्थियों को जैसे डांस पेंटिंग आपस में चर्चा करना आदि कार्य को करवाना और फिर पूछना कि आप यह क्या कर रहे थे विद्यार्थियों ने बताया कि क्रिया कर रहे थे तो आज हम व्याकरण में क्रिया पढ़ेंगे।

इसी तरह विज्ञान में बल चुंबकीय तत्व के बारे में पढ़ाने हेतु कुर्सी उठाना भारी वस्तु में बल लगाना गैस के बारे में पढ़ाना तो अगरबत्ती के धुएँ के द्वारा बताना सजीव निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताना तो पर्ची बनाकर उनमें सजीव निर्जीव नाम लिखकर विद्यार्थियों से पूछना कि क्या लिखा है इस तरह विभिन्न तरह के सजीव निर्जीव के बारे में विद्यार्थियों को खेल-खेल में सिखा दिया साथ ही पर्यावरण के बारे में बताने पर पोस्टर /पेंटिंग आदि का आयोजन किया उदा.ओजोन लेयर के नुकसान के बारे में।

कहानी पढ़ाने समय चार्ट पर इस प्रकार कहानी के विभिन्न भागों के चित्र बनायें फिर कहानी बनाने कहा गया।

इस प्रकार नवीन प्रयोगों का उपयोग करके पाया कि विद्यार्थी अच्छे से सीख रहे हैं उन्हें उक्त विषय अतिशीघ्र समझ आ रहा है।

अच्छी आदतें (Best Practices) हेतु बी.एड. प्रशिक्षु को अभ्यास शिक्षण के पहले अच्छी आदतों के बारे में चर्चा की गई और उन्हें प्रेरित किया गया कि अच्छी आदतें बताने का प्रयास करें प्रतिदिन कक्षा प्रारंभ करने के पहले एक अच्छी आदत (Best Practices) को सिखाना है। जैसे-

1. योगा-प्राणायाम ध्यान
2. स्वच्छता-अपने आस-पास सफाई रखना कचरा इस्टबिन में डालना खाने के पहले शौच के बाद साबुन से हाथ धोना। स्वयं की सफाई पर ध्यान देना स्वच्छ वस्त्र और स्वतः की सफाई पर भी ध्यान देना।
3. पानी व्यर्थ न बहायें -उन्हें एक नारा दिया कि **पानी बचाया जा सकता है बनाया नहीं जा सकता** कही भी नल चालू देखें बंद करें।
4. बिजली बचायें-बिजली घर-बाहर व्यर्थ जलते हुए देखे तो बंद करें।
5. कागज को व्यर्थ न फेंके-एक तरफ खाली पेपर का भी उपयोग करें।
6. Single Use Plastic का उपयोग न करें।
7. गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करें।
8. बुर्जुओं का सम्मान करें।
9. असहायों की मदद करें।
10. महिलाओं की इज्जत करें।
11. सोशल मीडिया /मोबाइल से दुरी पर चर्चा की गई।
12. कक्षा में आपस में समायोजन/सामंजस्य बनाना सिखाया गया।
13. परीक्षा के डर पर भी चर्चा की गई।

उक्त प्रकार से नवाचारिक पद्धति एवं अच्छी आदतें सिखाने के बाद परिणामस्वरूप में यह पाया गया कि इस तरह के प्रयासों द्वारा विद्यार्थी मन लगाकर सीख रहे हैं क्योंकि कुछ रोचक प्रभावशाली कार्य उन्हें मिल रहा है जिससे उनकी क्षमताओं में वृद्धि हो रही है रटन्ट प्रक्रिया की जगह समझने की प्रक्रिया का विकास हो रहा है अच्छी आदतों को प्रतिदिन सिखाने के कारण यह पाया गया कि कुछ अच्छी आदतें अभ्यास करवाने के कारण उनमें रोपित कर सके हैं।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

## Skills Related Physical Fitness Variables of Tribal School Children

Ramadhhar Pipladiya\*

**Introduction** - Prevention of diseases is the main emphasis of any fitness programs which emphasized should be on health-related fitness and as these are skill-related fitness is crucial for success in sports and athletics, and it also contributes to wellness Physical fitness or defined as a physiological state of well-being that the foundation for the tasks of daily living, it also helps two protect against hypo kinetic disease, and a prepare a base for Health Physical Education, Recreation and Dance which includes non performance components of physical fitness that relate to system that are influenced by one's level of habitual physical activity. Children are the wealth of any nation as they constitute one of the important segments of the population. Children in the age group of 5-14 years are often considered as school age. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) since 1972, for the purpose of statistics consider 6-11 years as primary school age and 12-17 years as secondary school age. It is recorded that in India one fifth population comprises of children between 5-14 years, the age group covering primary and secondary school age. The foundation of good health and sound mind is laid during the school age period. So it is basic milestone in the life of an individual and responsible for many changes that take place during later life.

### Measurement of Skill Related physical fitness Component

**Speed**- 50mts dash in  $1/10^{\text{th}}$  of a sec., **Agility**- Shuttle run in  $1/10^{\text{th}}$  of a sec, **Dynamic Balance** – Modified based test., **Reaction time** -Nelson hand reaction test, **Power** - Standing broad jump in meters.

### Statistical Analysis

1. According to objectives of the study to gathering the data Analysis of descriptive statistics were used. (Mean Standard Deviation)
2. One-way Analysis of variance (ANOVA) was applied with the help of Post Hoc Test (Schaffer test) Mean Difference (MD), Critical Difference (CD) were applied for SPSS-21 software to analyze and compare of the skill relative and among the various groups (under nutrition, normal nutrition and over nutrition) of school boys of 16 to 20 years from Govt. school of Alirajpur and Jhabua district

tribal students of Madhya Pradesh the level of significant was set at 0.05

### Results and finding of the study:

#### Descriptive statistics tables.

#### Findings and Results of the Study

**Table 1** (see in last page)

**Graph 1** (see in last page)

**Graphically Representing. For Mean and Standard Deviation of speed Government School of Tribal District, Madhya Pradesh.**

**Table 1** shows skill related physical fitness component speed of Government School of Tribal District, Madhya Pradesh. with the help of descriptive statistics (Mean and standard deviation) of all three groups Under nutritional group, Normal nutritional group and Over nutritional group for this study. Skill related physical fitness component of speed were  $7.7007 \pm .48477$ ,  $7.7444 \pm .82361$ ,  $7.7439 \pm .54011$ .

**Table 2** (see in last page)

**Graph 2** (see in last page)

**Graphically Representing. For Mean and Standard Deviation of agility Government School of Tribal District, Madhya Pradesh.**

**Table 2** shows skill related physical fitness component speed of Government School of Tribal District, Madhya Pradesh. with the help of descriptive statistics (Mean and standard deviation) of all three groups Under nutritional group, Normal nutritional group and Over nutritional group for this study. Skill related physical fitness component agility were  $8.3769 \pm .61823$ ,  $8.3982 \pm .56966$ ,  $8.6084 \pm .63073$ .

**Table 3** (see in last page)

**Graph 3** (see in last page)

**Graphically Representing. For Mean and Standard Deviation of Balance Government School of Tribal District, Madhya Pradesh.**

**Table 4** (see in last page)

**Graph 4** (see in last page)

**Graphically Representing. For Mean and Standard Deviation of Reaction Time Government School of Tribal District, Madhya Pradesh.**

**Table 4** shows skill related physical fitness component speed of Government School of Tribal District, Madhya

Pradesh. with the help of descriptive statistics (Mean and standard deviation) of all three groups Under nutritional group, Normal nutritional group and Over nutritional group for this study. Skill related physical fitness component Reaction Time were  $.0943 \pm .00827$ ,  $.0942 \pm .00868$ ,  $.0945 \pm .00828$ .

**Table 5 (see in last page)**

**Graph 5 (see in last page)**

**Graphically Representing. For Mean and Standard Deviation of power Government School of Tribal District, Madhya Pradesh.**

**Table 6** shows skill related physical fitness component speed of Government School of Tribal District, Madhya Pradesh. with the help of descriptive statistics (Mean and standard deviation) of all three groups Under nutritional group, Normal nutritional group and Over nutritional group for this study. Skill related physical fitness component power were  $2.3859 \pm .16492$ ,  $2.3536 \pm .15001$ ,  $2.4829 \pm .12170$ .

**Table 6 (see in last page)**

**Table-6** It was reveal that the calculated f- value (**.017**) was greater than the tabulated value is **3.05** (2, 177), so there was no significant difference between the skill related physical fitness variable (**Reaction time**) and all three groups Under nutritional group, Normal nutritional group and Over nutritional group for this study of government school Children of Tribal District of Madhya Pradesh.

**Table 7 (see in last page)**

**Table-7** It was reveal that the calculated f- value (**9.292\***) was less than the tabulated value is **3.05** (2, 177), so there was significant difference between the skill related physical fitness variable (**power**) and all three groups Under nutritional group, Normal nutritional group and Over nutritional group for this study of government school Children of Tribal District of Madhya Pradesh

**Discussion of findings** - It was found to have a significant difference in all three groups under nutritional, normal nutritional and over nutritional from govt. schools of Alirajpur and Jhabua district students of Madhya Pradesh, India. in their skill related physical fitness and skill related physical fitness variables. The reason of these differences can be associated with above results this is probably due to the different nature of the physical components training and pre-requisite for students. Number of participation and level of participation. The reason may be attributed that the physically trained student or level of achievements and taken deferent types nutrition food. These results may be due to a small sample of size and other factors such as different types of body, differences in body composition. These results may be nutrition diet schedule deference. The reason may be psychological variables stress, anxiety, aggression, fear, motivation confidence, attention concentration etc. Multiple Comparisons between the skill related and skill related physical fitness variables Balance, power, flexibility, muscular strength, Abdominal muscular

strength, and IQ level and all three groups Under nutritional group, Normal nutritional group and Over nutritional group of government school Children of Tribal District of Madhya Pradesh.

**Conclusions:-**

**According to objectives of the study the following conclusions were drawn:**

1. The govt.school boys students of under nutrition, normal nutrition and over nutrition groups from Alirajpur and Jhabua district of Madhya Pradesh, all three groups showed significant mean difference in their skill related physical fitness variables namely balance and power variables.
2. To camper the skill related physical fitness variable and govt. boys students of Alirajpu and Jhabua, district of Madhya Pradesh. all three groups (under nutrition, normal nutrition and over nutrition) showed a significant difference their skill related physical fitness variables of power.
3. To camper the skill related physical fitness variable and govt. boys students of Alirajpu and Jhabua, district of Madhya Pradesh. all three groups (under nutrition, normal nutrition and over nutrition) showed a significant difference their skill related physical fitness variables of balance.

**References:-**

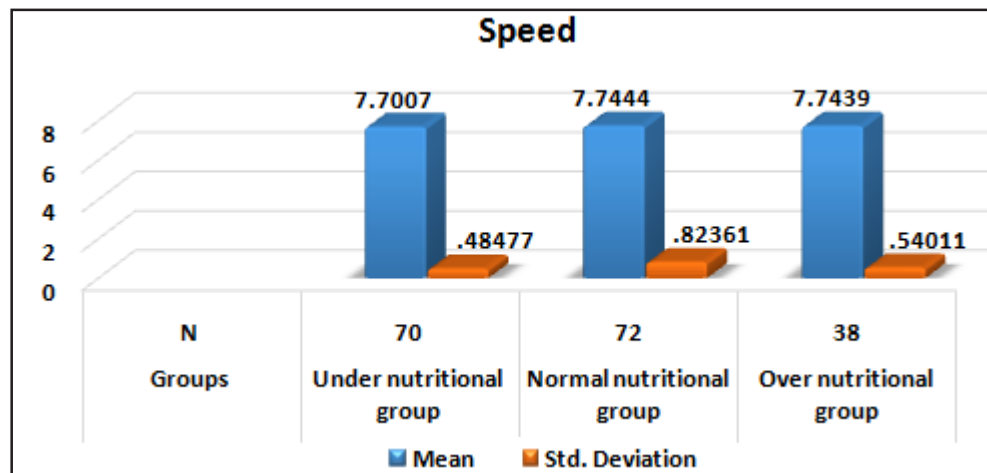
1. Agarwal, K. N., Agarwal, D. K., Upadhyaya, S. K., 1995, **Impact of chronic malnutrition on higher mental functions in Indian boys aged 10-12 years.** *Acta Pediatr*, 84 : 1340-1360.
2. Agarwal, D. K., Upadhyaya, S. K., Tripathi, A. M., Agarwal, K. N., 1987, **Nutritional status, physical work capacity and mental function of school children.** Scientific report 6, Nutritional Foundation of India.
3. Bnefice E, gamier, D, Diaya GN (2008). Assement of physical activity among rural Senegalese adolescent girls influence of age sexual maturation and body composition journal of adolescent health volum 28.
4. E.A. Rice, J.L. Hutchison and M. Lee; A Brief History of Physical Education (New York: Ronald Press, 1958), p. 73.
5. H. Kraus and R.P. Hirschland, "Minimal Muscular Fitness Test in School Children", *Research Quarterly* 25 (1954): 177-88.
6. J.F. Kennedy, "The Soft American", *Sports Illustrated* (December 1960): 15.
7. Lecturer, Physical Education Department, Malwa College of Physical Education, Bhatinda, Punjab, INDIA.
8. Philip Carter, **THE COMPLETE BOOK OF INTELLIGENCE TESTS**(2005). P.1-7
9. Researchonline.nd.eu
10. www.health.govt.in



**Table- 1: Descriptive Statistics Mean and Standard Deviation for the all three groups Under nutritional, Normal nutritional and over nutritional Government School of Tribal District, Madhya Pradesh.**

**Table 1 : Speed**

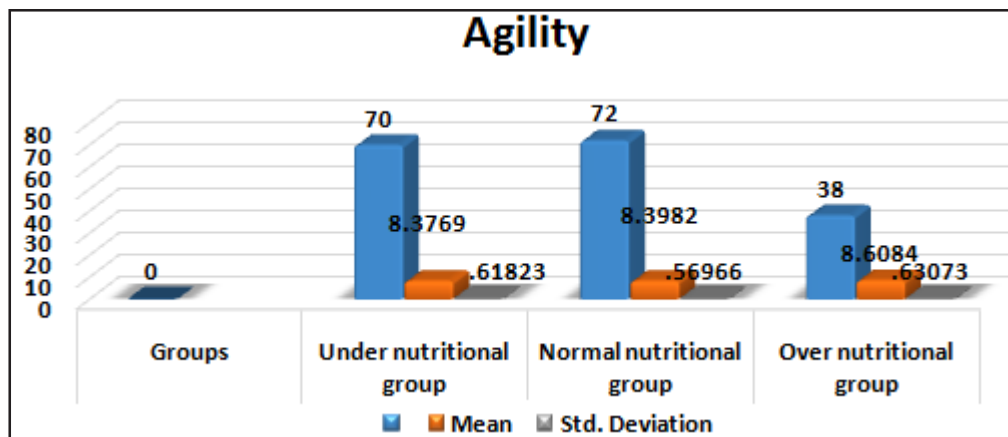
S.	Groups	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
1	Under nutritional group	70	7.7007	.48477	7.00	9.10
2	Normal nutritional group	72	7.7444	.82361	6.34	11.20
3	Over nutritional group	38	7.7439	.54011	7.05	9.10



**Table- 2: Descriptive Statistics Mean and Standard Deviation for the all three groups Under nutritional, Normal nutritional and over nutritional Govt. School of Tribal District, Madhya Pradesh.**

**Table- 2 : Agility**

S.	Groups	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
1	Under nutritional group	70	8.3769	.61823	7.07	10.00
2	Normal nutritional group	72	8.3982	.56966	7.10	10.10
3	Over nutritional group	38	8.6084	.63073	7.77	10.77



**Table- 3: Descriptive Statistics Mean and Standard Deviation for the all three groups Under nutritional, Normal nutritional and over nutritional Govt. School of Tribal District, Madhya Pradesh.**

**Table- 3 : Balance**

S.	Groups	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
1	Under nutritional group	70	86.8857	2.40496	2.40496	10.00
2	Normal nutritional group	72	88.0139	2.88997	2.88997	10.10
3	Over nutritional group	38	85.7105	4.70140	4.70140	10.77

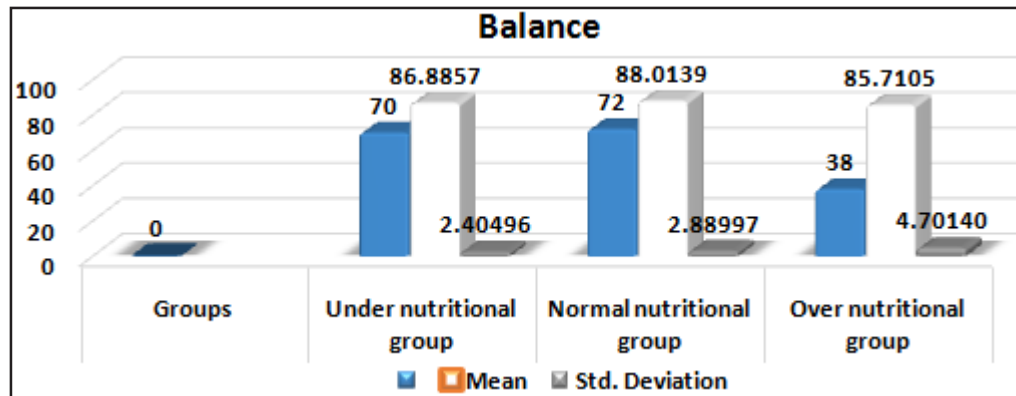


Table- 4: Descriptive Statistics Mean and Standard Deviation for the all three groups Under nutritional, Normal nutritional and over nutritional Govt. School of Tribal District, Madhya Pradesh.

Table- 4 : Reaction Time

S.	Groups	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
1	Under nutritional group	70	.0943	.00827	.08	.11
2	Normal nutritional group	72	.0942	.00868	.08	.11
3	Over nutritional group	38	.0945	.00828	.08	.11

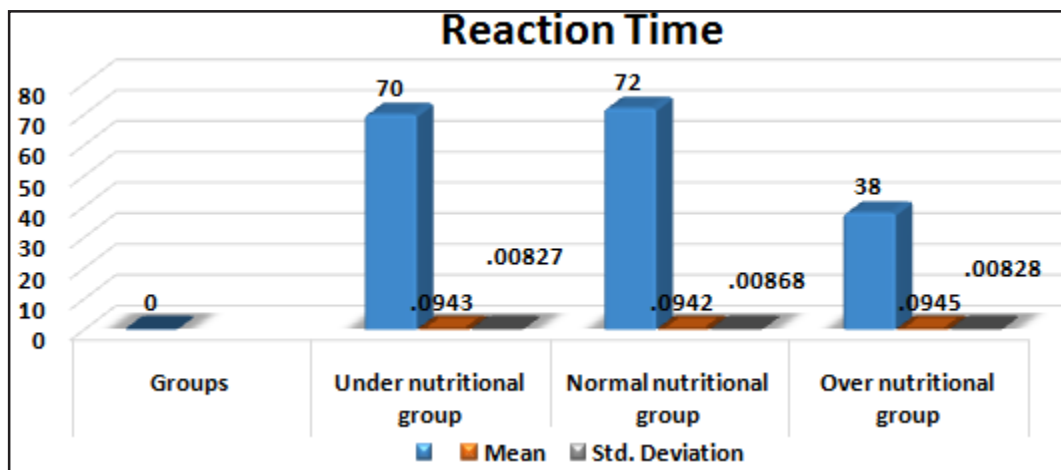
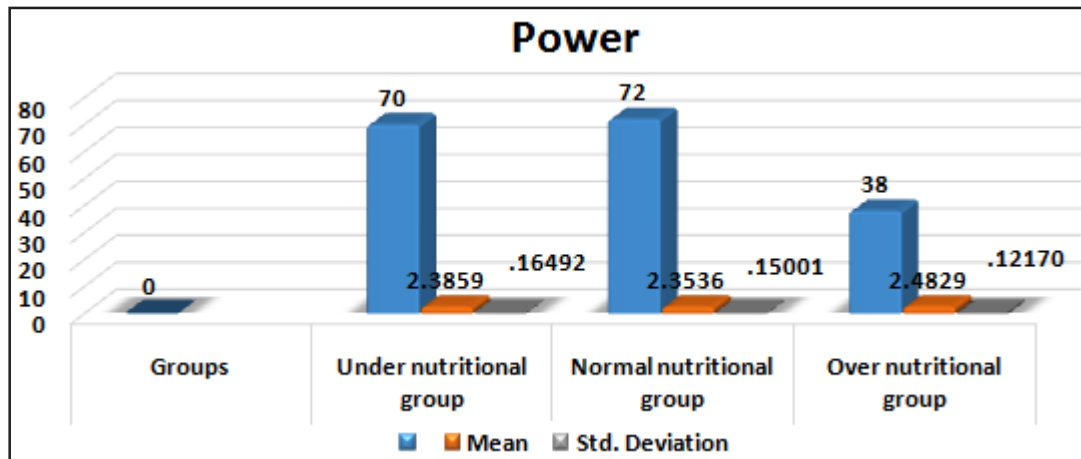


Table- 5: Descriptive Statistics Mean and Standard Deviation for the all three groups Under nutritional, Normal nutritional and over nutritional Govt. School of Tribal District, Madhya Pradesh.

Table- 5 : Power

S.	Groups	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
1	Under nutritional group	70	2.3859	.16492	1.40	2.67
2	Normal nutritional group	72	2.3536	.15001	2.10	2.70
3	Over nutritional group	38	2.4829	.12170	2.27	2.74



**TABLE -6 Analysis Of Variance For Skill Related Component For (Reaction Time) Triable Children On The Basis of Nutrition**

Source of Variance	SS	DF	MSS	Calculated F-value	Tabulated F- value
Between Groups	.000	2	.000	.017	3.05
Within Groups	.013	177	.000		

N=180

\*Significant at .05 Level

**TABLE -7 Analysis Of Variance For Skill Related component For (Power) Triable Children On The Basis of Nutrition**

Source of Variance	SS	df	MSS	Calculated F- value	Tabulated F- value
Between Groups	0422	2	.211	9.292*	3.05
With in Groups	4.022	177	.023		

N=180

\*Significant at .05 Level

\*\*\*\*\*

# The Significance of Teaching English Language to the Students of Hospitality and Tourism Industry

Ms. Monika Choudhary\*

**Abstract** - Many multi-linguistic and multi ethnic countries are there in all over the world. Promoting tourism has taken a vital place in nation's economy policy. English has become a global language for communication in trade and media. This language has joined whole world in the form of a family. It plays a very vital role in the delivery of quality service in the hospitality and tourism industry. Improper knowledge of the communication skills results in miscommunication between employees and the employers which causes a big drawback of this Industry. Communication skill is an integral element in providing a high set of service. Unluckily focus of teaching English language is still very less in hospitality and tourism industry. It needs many affirmative changes and up gradation in this direction for advancement of this industry's services.

**Key Words** - global language, Communication skills, tourism, hotel industry, employee - employer behavior, English.

**Introduction** - There are many career opportunities in Hospitality and tourism industry but most of the times they cannot be taken unless or until a person who is practicing them is a proficient and a confident user of English language. Verghese has rightly said, "It is the common means of communication between the persons of different nations."<sup>1</sup> English is universally accepted global language and easy to learn in comparison to other languages. Once someone becomes skillful in English language, no matter where he is working, chances of promotion in job will be more. English language is a medium which allows to interact with people from different countries. Students studying hospitality and tourism management should give more emphasis to communication skills (Listening, speaking, reading, writing) in English language.

Oral communication has more importance than written communication but still written communication should also be given importance because all the international correspondence is done in English language. An exam in English language is conducted to study in foreign universities or to get a study visa.

English is a language of entertainment, tourism and business etc. Today 75 percent of information is provided by newspapers, books, radio, television etc is in English only. Verghese has rightly said, "...world's knowledge is enshrined in English."<sup>2</sup> All the instruction manuals are in English. On internet 90 percent of the information is in English language only.

According to *Journal of Hospitality and Tourism Education*, "...possessing English language skills are seen as highly relevant to working in tourism and hospitality industry."<sup>3</sup> Bilingualism assists to outshine the opportunities

in these sectors. Tourism and hospitality industry's supply and demand departments need effective communication skills in order to supply quality service. That's why communication skills should be given more importance.

**Some obstacles in teaching and learning English language to the hospitality and tourism management students:-**

1. Communication skills is not considered as an important part of academic education by the students and do not realize a need to improve their communication skills.
2. English is taught to the students but special attention is not given to spoken part which leads to separation of learning and use.
3. Those students who are good in written English language and grammar also do not have assurance in speaking English language owing to not getting any chance to use their communication skills that's why they are hesitant in using English in front of others.
4. The students do not get proper motivation to improve their English language.
5. In many private institutions of hospitality and tourism management English subject has been allotted very less time. Only one or two semesters have this subject. That's why students do not become able to learn proper English.
6. In India English is a second language and while speaking English mother tongue interference takes a major role.
7. The students who try to speak in English and speak wrong English, are mocked by other students and sometimes by teachers also, so the students who are not good at English hesitate and do not even try to



speak in English.

### Some ways to defeat the difficulties of improving English language skills:

1. It is advised to start special English spoken courses for the students of hospitality and tourism management in the institutions. The course should be comprehensive and interrelated to the respective managements so that the students also take interest.
2. Interaction in the classroom should also be restricted in English language only. The students must use English language as much as possible, so they can get a place to use their communication skills with teachers and other students.
3. Students should be motivated to use English language because it not only improves one's skill but also makes one a confident speaker.
4. "Council on Hotel, Restaurant and Institutional Education" also opines about English language advantages, "...other anticipated advantages were to get exposure to western thinking, industry and an appealing life style." <sup>4</sup>
5. Students must be motivated to increase vocabulary in English. They should try to use the vocabulary in day to day life and at work place also to improve the English language.
6. Spoken part should be emphasized more than written English language and grammar.
7. Reading improves the speaking skills to a great extent. Newspaper, Journal and magazines in English language should be provided to the students by the institutions itself.

8. Role plays and literary activities should also be organized to improve the language.
9. Competitions like debate, extempore, poem writing and recitation, slogan writing, essay writing on topics of hospitality and tourism sector should be organized by the English teachers to arise interest in the students towards English language.
10. Renowned hotel managers of international hotels, experts from industry and managers of tourist agencies should be welcomed to the institution and their boosting speech on the importance of English in the industry should be held by the English professors.

As mentioned in the *Current Issues in Hospitality and Tourism*, -"Ability of foreign language use could be linked to likes and dislikes towards the language." <sup>5</sup>By implementing these ways a teacher can create interest in the students for English language.

### References :-

1. C. Paul Verghese, *English as a Second Language*, (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 2007), p. 01.
2. C. Paul Verghese, p.02.
3. *Journal of Hospitality and Tourism Education*, (Council on Hotel, Restaurant and Institutional Education, 2008), Vol. 20-21, p 35.
4. *Journal of Hospitality and Tourism Education*, p. 35.
5. A. Zainal, S. M. Radzi, R. Hashim and C.T. Chik eds. *Current Issues in Hospitality and Tourism: Research and Innovations*, (London: Taylor and Frances Group, 2012), p. 637.

\*\*\*\*\*

## अवनद्ध वाद्य तबले का विकास

डॉ. प्रवीण कुमार शर्मा \*

**प्रस्तावना** - वर्तमान युग में 'तबला' शब्द, हिन्दुस्तानी संगीत में दो ऊर्ध्वमुखी वाद्यों की जोड़ी के रूप में दोनों हाथों की उँगलियों व हथेलियों के आघात से बजाए जाने वाले एक उन्नत अवनद्ध वाद्य या कभी-कभी उसके दाहिने भाग के लिये व्यवहार किया जाता है।

उत्तर भारत में साधारणतः ऐसा जनप्रवाद है कि मध्ययुग में मृदंग अर्थात् पखावज को बीच से काट कर दो हिस्सों में ऊर्ध्वमुखी स्थिति में रखकर बजाने से तबला वाद्य की उत्पत्ति हुई है। इस तरह पखावज दो भागों में बँट कर भी नए वाद्य के रूप में बजाया जाना सम्भव हुआ। अर्थात् पखावज दो भागों में बँट कर भी नए वाद्य के रूप में बोला। अतएव 'तब भी बोला' शब्दों का अपभ्रंश होकर तब (भी) + बोला = तबबोला तबबोला तबोला तबला शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। इस परिकल्पना के अनुसार यह हिन्दी भाषा का देशज शब्द सिद्ध होता है।

यह ऐतिहासिक तथ्य है कि तबला वाद्य की वादन प्रक्रिया के विकास में मध्ययुग के अनेक पखावज वादकों का बहुत योगदान रहा है। तबला वाद्य के आविष्कारक के रूप में समझे जाने वाले सुधार खाँ दाद्री को भी लोग मूलतः पखावजी ही मानते हैं। इसके अतिरिक्त तबले के पंजाब बाज की शाखा का प्रारम्भ भी लगभग अठारहवीं शताब्दी में भवानी दास पखावजी के शिष्य फकीर मुहम्मद द्वारा माना जाता है। सुप्रसिद्ध पखावज वादक कुदरुसिंह ने अवध के तत्कालीन शासक वाजिद अली शाह के लगनऊ दरबार में आबिद अली दाद्री तबलिए के संदर्भ में तबला वादकों को पखावज वादकों का 'गुलाम व सिख्याकार (शिष्य)' कहा था।

तबला वादन प्रक्रिया के विकास में पखावज वादकों का विशेष योगदान होने पर भी पखावज को दो भागों में विभक्त करके तबला वाद्योत्पत्ति और 'तबबोला' से 'तबला' शब्द की व्युत्पत्ति का तर्कसंगत वैज्ञानिक समाधान नहीं होता। क्योंकि बनावट की दृष्टि से पखावज को दो भागों में काट देने पर उसका प्रत्येक भाग, विदेशी अवनद्ध वाद्य 'बांगो' के दोनों भागों की भाँति नीचे से खुला होना चाहिए, जबकि वस्तुतः तबला वाद्य के पूर्वरूप 'तबबोला' या 'तबोला' नाम के किसी अवनद्ध वाद्य का किसी भी संदर्भ में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। बल्कि उसके स्थान पर 'तबल' या 'तबल' शब्दों का उल्लेख मध्यकालीन संस्कृत, फारसी, हिन्दी, असमिया और उर्दू साहित्य में अवश्य मिलता है। अतएव इन आधारों पर पखावज को दो भागों में काट कर तबले की उत्पत्ति और 'तब (भी) बोला' शब्दों से 'तबला' शब्द की व्युत्पत्ति एक काल्पनिक किंवदंती मात्र सिद्ध होती है। उल्लेखनीय है कि आज के सुप्रसिद्ध तबलावादक पं. किशन महाराज भी पखावज (मृदंग) को काट कर दो भाग करने से तबला वाद्योत्पत्ति की धारणा को असंगत मानते हैं।

मध्य एशिया में, दजला और फ़रात नदियों के मैदानी भाग में स्थित

मेसोपोटेमिया (वर्तमान ईराक) की प्राचीन सुमेरियन, बैबिलोनियन, असीरियन इत्यादि सभ्यताओं के साहित्य में 'बलग' और अक्कादियन साहित्य में उसके पर्याय (बलगू) नाम के एक महत्वपूर्ण अवनद्ध वाद्य का उल्लेख मिलता है, जो कि लगभग दो हजार वर्ष ईसा पूर्व के प्राचीन युग में 'इया' अथवा 'इन-की' नामक देवता के मंदिर में विशेष अवसरों पर बजाया जाता था।

'बलग' या 'बलगू' शब्दों का पहला अंश 'बल' क्रियापद है, जिसका अर्थ 'प्रहार करना या पीटना' होता है। अतः बहुत सम्भव है कि प्रहार से या पीटकर बजाए जाने के कारण, उस अवनद्ध वाद्य का नाम 'बलग' या 'बलगू' पड़ा होगा। संस्कृत भाषा में 'बल' का अर्थ 'शक्ति' होता है, जो कि प्रहार या पीटने की क्रिया के लिए अनिवार्य है। अतः इस दृष्टि से 'बलग' शब्द के अन्य अर्थ हर्ष, आनंदपूर्ण कोलाहल ध्वनि, चिल्लाना, गुराना या गर्जना है।

इससे श्री अरिवन्द मुलगाँवकर ने अपने ग्रंथ 'तबला' में उच्चार व अर्थसाम्य के आधार पर 'बलग' शब्द के प्रथम और 'तबल' शब्द के अंतिम अंश 'बल' क्रियापद अथवा 'बलाग' शब्द के प्रथम और 'तबला' के अंतिम अंश 'बला' क्रियापद को शब्द विकास की मूल कड़ी मानते हुए, 'बल' से 'तबल' या 'बला' से 'तबला' शब्द के व्युत्पत्ति की संभावना अभिव्यक्त की है। श्री मुलगाँवकर की यह परिकल्पना ध्वनि के उच्चारण और अर्थसाम्य पर आधारित होने पर भी, उसमें भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से 'बल' या 'बला' क्रियापद के पूर्व 'त' उपसर्ग के योग व अर्थ विकास का कोई निश्चित और प्रामाणिक आधार नहीं मिलता। अतः 'बल' या 'बला' से 'तबल' या 'तबला' शब्द की व्युत्पत्ति होने की संभावना संदेहास्पद प्रतीत होती है।

ईरान (फारस) में तबल बलदी, तुर्की, तबल जंग, तबल, सामी, तबल मिगरी, तबल अल-मरकब, तबल अलगाविग या तबल अल साविस और तबलो अलम नामक अनेक अवनद्ध वाद्य प्रचलित हैं, जो ऊर्ध्वमुखी रूप में बजाए जाते हैं।

अतएव अनेक विद्वान 'तबला' शब्द की व्युत्पत्ति फारसी भाषा का न होकर अरबी भाषा का शब्द है और यह शब्द अरबी भाषा से फारसी भाषा में आकर प्रचलित हुआ।

एक किंवदंती के अनुसार अरबी संगीत परंपरा के सुप्रसिद्ध व्यक्ति 'लमक' के पुत्र 'टुबल (तुबल)' ने 'तबल' वाद्य का आविष्कार किया। अतः उससे सम्बद्ध होने के कारण इस अवनद्ध वाद्य का नाम 'तबल' पड़ा। अनबी 'तबल' के विषय में अरबी संगीत के सुप्रसिद्ध विद्वान डॉ. हेनरी जॉर्ज फार्मर का कथन है कि बैबिलोनियन-असीरियन अवनद्ध वाद्य 'तबबुल' की तुलना अरमेक-हिब्रू 'तिबेला' और अरबी 'तबल' से की जा सकती है। अतः इन शब्दों में पारस्परिक सम्बंध और उनसे अरबी 'तबल' शब्द के विकास की

संभावना हो सकती है।

कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ओरियंटल डिपार्टमेंट के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉ. जेफ्रे के मतानुसार 'तबल' या 'तबुल' शब्द वस्तुतः अरबी मूल का शब्द न होकर लैटिन 'टेबुल' (Tabula) शब्द से लिया गया है। इस प्रकार अरबी भाषा के 'तबल' शब्द का विकास भी मूलतः लैटिन शब्द 'टेबुल' (Tabula) शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ चिकना चौरस व समतल होता है।

इस विषय में एक विशेष तथ्य यह है कि अधिकतर यूरोपीय भाषाओं के विकास का सम्बंध लैटिन भाषा से रहा है। अतः अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटैलियन तथा स्पैनिश इत्यादि भाषाओं में चौरस, चिकने, समतल या लकड़ी की चौरस, समतल मेज के अर्थ में इस्तेमाल होने वाले 'टेबल' (Table) शब्द या उसके विभिन्न शब्द रूपों के मूल विकास का सम्बंध भी लैटिन भाषा के 'टेबुल' (Tabula) शब्द से है। इसीलिए यूरोपीय भाषाओं में 'टेबल' (Table) या उससे ध्वनिसाम्य वाले समानार्थी शब्द प्रायः ऊर्ध्वमुखी समतल वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।

मलिक मुहम्मद जायसी कृत 'पद्मावत' महाकाव्य के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि उस समय, अर्थात् सोलहवीं शताब्दी तक धौंसा या नक्कारानगाड़ा जैसे एक वृहद् ऊर्ध्वमुखी अवनद्ध वाद्य को लोकभाषा में 'तबल' कहा जाता था, जो कि प्रायः युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था। चूँकि 'तबल' शब्द, अरबी 'तबल' शब्द का ही अपभ्रंश है। अतः वाचनाचार्य सुधाकलश, गुरु नानकदेव और मलिक मुहम्मद जायसी के उल्लेखों के आधार पर ज्ञात होता है कि प्रायः चौदहवीं शताब्दी से लेकर सोलहवीं शताब्दी तक युद्ध में मुस्लिम वादकों द्वारा बजाए जाने वाले दुंदुभि, धौंसा या नगाड़ा जैसे एक अनुन्नत, ऊर्ध्वमुखी अवनद्ध वाद्य के लिए 'तबल' या 'तबल' शब्द का इस्तेमाल होता रहा। आगे चलकर लगभग सत्रहवीं शताब्दी से उत्तर भारत के कलात्मक संगीत में दो हिस्सों की जोड़ी के रूप में हाथों से बजाए जाने

वाले एक सुप्रसिद्ध उन्नत अवनद्ध, ऊर्ध्वमुखी अवनद्ध वाद्य का नाम 'तबला' मिलता है। आज भी उर्दू भाषा में बड़े नगाड़े के अर्थ में 'तबल' और तबला नामक वाद्य के अर्थ में 'तबलः (तबला)' शब्द व्यवहार किया जाता है। 'तबला' शब्द, मूलतः अरबी शब्द 'तबल' से विकसित 'तबलः = तबलह' शब्द का अपभ्रंश रूप है, जो कि भारतीय भाषाओं में प्रचलित है।

अतएव ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर विदित होता है कि भारत में ऊर्ध्वमुखी अवनद्ध वाद्य के अर्थ में 'तबल' व 'तबल' शब्द लगभग छह सात सौ वर्षों से प्रचलित हैं। प्रारंभ में ये शब्द युद्ध या उत्सव के अवसर पर एकत्रित विशाल जनसमूह को प्रभावित करने के लिए बजाए जाने वाले धौंसा या नगाड़ा जैसे अविकसित ऊर्ध्वमुखी अवनद्ध वाद्यों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। परंतु बाद में मनोरंजन प्रधान देशी संगीत की कलात्मक विधाओं के साथ दो नगों की जोड़ी के रूप में हाथों से बजाए जाने वाले एक विशेष अवनद्ध वाद्य के लिए 'तबला' शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। आज भी यह शब्द इसी अर्थ में प्रचलित है।

उत्तर भारत कलात्मक संगीत में जोड़ी के रूप में बजाए जाने वाले एक विशेष अवनद्ध वाद्य के अर्थ में 'तबला' शब्द का प्रयोग अभी तक प्राप्त उल्लेखों के अनुसार लगभग सत्रहवीं अठारहवीं शताब्दी से मिलता है और आज भी इसी अर्थ में प्रचलित है। अतएव इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में 'तबला' शब्द अपने वर्तमान अर्थ में प्रायः ढाई-तीन सौ वर्षों से प्रचलित है।

### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. संगीत समयसार,
2. ताल प्रकाश
3. The History of Musical Instrument

\*\*\*\*\*

## जल का उपयोग एवं माँग: रीवा जिले के संदर्भ में एक भौगोलिक अध्ययन

डॉ. भास्कर प्रसाद तिवारी \*

**प्रस्तावना** - भारत वर्ष का हृदयस्थल मध्यप्रदेश के उत्तरी पूर्वी किनारे में 24°18' से 25°12' उत्तरी अक्षांश एवं 81°02' पूर्वी देशान्तर से 82°20' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। रीवा जिले का नामकरण नर्मदा नदी के प्राचीन नाम 'रेवा' पर आधारित है। रीवा जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 6287.5 वर्ग किमी<sup>0</sup> है, प्रशासकीय दृष्टि से इस जिले में 11 तहसील एवं 9 विकासखण्ड हैं।

**राजनीतिक सीमांकन** :- रीवा जिले के उत्तरी सीमा में उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद एवं बौदा जिले, दक्षिण में मध्यप्रदेश का सीधी जिला तथा पूर्व में उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला एवं पश्चिम में मध्यप्रदेश राज्य का सतना जिला सीमा निर्धारित करते हैं।

**ऐतिहासिक पृष्ठभूमि** :- सफेद शेरों की जननी के नाम से विश्व प्रसिद्ध रीवा जिला प्राचीन रीवा रियासत की राजधानी तथा वर्तमान में रीवा संभाग का संभागीय मुख्यालय है। ईसा पूर्व एवं दूसरी एवं तीसरी शताब्दी में यह क्षेत्र मौर्य शासकों के आधीन रहा। इस क्षेत्र में कई राजवंशों ने शासन किये जिसमें कलचुरी, परिहार, राजपूत, एवं बघेल प्रमुख रहे। स्वतंत्रता के पूर्व रीवा बघेल के अधीन रहा। स्वतंत्रता के बाद रीवा रियासत म०प्र०शासन को सौंप दी गयी और एक जिला के रूप में तब्दील हो गया।

**जल का उपयोग** :- जल एक अमूल्य संसाधन है जिसके बिना वनस्पति, जीव एवं वातावरण की कई क्रियाएँ संभव नहीं हैं। मानव का इतिहास जल प्राप्ति एवं अप्राप्ति पर निर्भर करता है। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में वायु के पश्चात जल द्वितीय अनिवार्यता है। जिसका उपयोग विविध रूपों में किया जाता है। जल का घरेलू उपयोग मुख्यतः पीने, नहाने, खाना बनाने, कपड़ा धोने, सिंचाई, पशुपालन, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में दैनिक उपयोग में अपनाने वाला जल कुआ, तालाब, ट्यूबवेल, नहर एवं नदियों में पूर्ति होती है।

अध्ययन क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में 55ली० एवं नगरीय क्षेत्रों में 70 से 135 ली० प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग का आधार मानकर गणना की गयी है।

**सारणी क्रमांक- 1.1 : रीवा जिले में जल की वार्षिक मांग घरेलू उपभोग के लिए वर्ष 2012 (मि०ली०)**

क्रं.	तहसील	ग्रामीण क्षेत्रों में	नगरीय क्षेत्रों में	कुल उपयोग
1	हुजूर	4084.45	4929.33	9013.78
2	गुढ़	1917.30	317.96	2235.26
3	सिरमौर	8125.03	1128.87	9253.90
4	सेमरिया	4025.02	303.02	4328.04

5	त्योथर	7405.40	622.19	7467.59
6	जवा	3540.03	415.2	3955.23
7	नईगढ़ी	2540.3	310.2	2850.23
8	रायपुर कर्चु०	2335.66	214.03	2549.69
9	हनुमना	3827.98	380.02	4207.98
10	मऊगंज	5294.66	811.36	6106.02
11	मनगवां	3047.32	613.2	3660.52
	योग-	-	-	55627.88

स्रोत-कार्यालय अभियंता- लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी रीवा

शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं यथा नगर-निगम, नगर पालिका, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकीय, नलकूप विभाग एवं अन्य निजी क्षेत्रों से होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में निजी कुएं, सरकारी एवं निजी नलकूप एवं अन्य संस्थाओं द्वारा की जाती है। अध्ययन क्षेत्र में सकल जल भाग 55627.88.मी.ली. है। कुल माँग का 85% सतही एवं शेष भाग भूमिगत जल से होती है। जनसंख्या वृद्धि के साथ जल की माँग भी बढ़ती जाती है।

**सिंचाई के रूप में** :-आधुनिक युग में कृषि के विकास में सिंचाई के साधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। जिले में विभिन्न सिंचाई क्षमता लगभग 87600हे० है। प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल की 0.008 मि० क्यू०मी० जल की आवश्यकता होती है। आधार मानकर गणना की गई है।

**सारणी क्रमांक- 1.2**

रीवा जिले में विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्र एवं जल की वार्षिक खपत

क्रं.	विवरण	2000	2002	प्रतिशत	जल की खपत मि०क्यू०मी०
1	नहर	12000	17800	17.52	122.46
2	नलकूप	19550	21850	27.34	191.60
3	कुआ	27950	27950	30.34	215.60
4	तालाब	3370	3370	3.38	27.20
5	नदी नाले	18100	18100	20.49	143.60
6	योग	67925	89070	100.00	700.46

स्रोत- कार्या० उपसंचालक, कृषि विभाग रीवा (म०प्र०)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से 27.34% एवं सबसे कम सिंचाई तालाबों से 3.88% होती है। जबकि अध्ययन क्षेत्र में समस्त स्रोतों से सिंचाई में उपयुक्त जल 700.46 मी० क्यू०मी० है। जो सारणी क्र०- 1.2 से स्पष्ट है।

\* अतिथि विद्वान (भूगोल) शासकीय महाविद्यालय, सेमरिया, रीवा (म.प्र.) भारत



**पशुपालन में जल का उपयोग :-** रीवा जिले में समस्त प्रकार के पशुधन की संख्या 1113436 है। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था एवं कृषि के सहायक उद्यम के रूप में पशुपालन किया जाता है। अतः दुग्ध उत्पादन, भारवाहन, माँस, रोमे, खाल के लिए पशुओं का विशेष महत्व है। पशुधन के लिए प्रतिदिन प्रति पशुधन भैंस वंशीय पशुओं के लिए 155ली0 एवं गोवंशीय पशुधन के लिए 135 ली0, बकरे वकरियों के लिए 8 ली0, घोड़े, टट्टू, ऊँट, खच्चर आदि के लिए प्रतिदिन 45 ली0 मान कर गणना की गई है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में प्रतिवर्ष जल की वार्षिक खपत 5145470 मि0ली0 है। जो कुआ, तालाब, नहर, नदी नाले आदि से पूर्ण होती है।

**सारणी क्रमांक-1.3 : रीवा जिले में पशुधन के लिए जल की वार्षिक खपत 2001**

क्रं.	विवरण	पशुधन	खपत
1	गौवंशीय पशु	835742	411811.00
2	भैंस वंशीय पशु	166334	94103.00
3	बकरे-बकरियों	169687	4954.00
4	घोड़े, टट्टू, खच्चर	22403	3679.00
5	अन्य पशुधन	14306	514547.00

**अन्य जल कृषि :-** तालाबों में मत्स्य पालन के अतिरिक्त जलज कृषि का प्रचलन है। जलज कृषि के अन्तर्गत सिंघाड़ा, मखाना, की कृषि की जाती है। जबकि तालाबों की मेढ़ में पान की खेती की जाती है। सिंघाड़ा, पान, मखाना आदि के लिए जल की आवश्यकता होती है। जिसकी आपूर्ति तालाबों, नदी-नालों से की जाती है।

**उद्योग में जल का उपयोग :-** रीवा जिले में बढ़ते हुए औद्योगीकरण के साथ स्वच्छ जल का महत्व भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिले में विद्यमान प्रायः समस्त उद्योग यथा सीमेंट उद्योग, कत्था निर्माण उद्योग, टमस फैक्टरी, ईट निर्माण, मोटर साइकिल सर्विस सेन्टर, डेयरी उद्योग आदि

के लिए बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इन संसाधनों के जल की आपूर्ति हेतु कई महत्वपूर्ण जलाशयों, नहर-नदियों एवं अन्य साधनों से की जाती है।

**जल शक्ति के रूप में उपयोग :-** जल ऊर्जा का स्थायी स्रोत है। जैसा कि ज्ञात है कि यदि 12 घनफिट जल को प्रति सेकेण्ड की गति से मात्र एक फुट ऊँचाई से गिराया जाय तो उससे एक किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न होगी। जिले में कई नदियाँ हैं जिस पर जलाशयों के निर्माण से इन संभावनाओं को सकार किया है। जिले में सिरमौर तहसील में टोन्स जल विद्युत परियोजना 1991 से संचालित है। 'इस विद्युत गृह से 108 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है।' विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कुल जल की खपत 1414.8 टन प्रति घंटा है। इस प्रकार मात्र 108 मेगावाट विद्युत ऊर्जा तैयार करने में प्रति घंटा 369.36 टन जल की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं अपितु इस वाष्प को ठण्डा करने के लिए 100 गुना जल की आवश्यकता होती है। अर्थात् 369.36 टन जल वाष्प को ठण्डा करने के लिए 36936 टन जल की खपत प्रतिघंटे है। अतः इस विद्युत गृह केन्द्र में 37305.36 टन की प्रतिघंटे की खपत है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची:-**

1. बी0एस0नेगी, संसाधन भूगोल केदारनाथ रामनाथ मेरठ, दिल्ली पृ0 128
2. Highsnlth. R.M. and Jan. Son. J.G. Gto of Ecomodify Production J.B. Lippicatl. Co. Chicogo 1958 PP. 272
3. गौतम शिवानन्द - बाघेलखण्ड पठार के संसाधनों का मूल्यांकन एवं क्षेत्रीय नियोजन, अप्रकाशित शोध प्रबंध अ0प्र0वि0वि0 रीवा, 1990
4. जिला सांख्यिकी पुस्तिका जिला रीवा 2001
5. कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकीय, रीवा।

\*\*\*\*\*

## ग्रामीण जीवन के विविध आयाम

डॉ. आर. एस. वाटे \*

**प्रस्तावना** - इस संसार में सबसे पहले-पहल सिर्फ प्रकृति का ही अस्तित्व था, जब से जीव-जंतु निर्मित हुए, प्रकृति ही उनकी आश्रय स्थल बनी, आज भी हम देखते हैं कि कई पशु-प्राणी वनों का आश्रय लेकर अपना उदर-निर्वाह करते हैं, इस प्रकार की स्थिति पहले सभी प्राणियों की थी, लेकिन इनमें से मनुष्य प्राणी अलग होने के कारण उसने प्रकृति को संस्कार दिया अर्थात् उसने विश्राम के लिए लकड़ियों की कुटी बनाई, वह कुटियों में रहने लगा, इस प्रकार के विश्राम स्थल जगह-जगह पर निर्मित हुए और मनुष्य अपना उदर-निर्वाह करने लगा। मनुष्य ने जहाँ कुटिया बनवाई थी उसके आस-पास वह खेती करने लगा। इस प्रकार की स्थिति में परिवर्तन हुआ और अनेक स्थानों में गाँवों की निर्मिति हो गई, यही मूल रूप आज के गाँवों का है।

मुंशी प्रेमचंद का मानना है कि - दबूपन भारतीय किसान के व्यक्तित्व का स्वाभाविक गुण नहीं है, बल्कि समकालीन समाज व्यवस्था के लम्बे अनुभव से किसान इसी निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उनकी कुशलता दबे रहने से ही है। वास्तव में सम्पूर्ण समाज व्यवस्था किसान के साहस का संगठित रूप में विरोधाभासी है। इस विरोध से किसान का साहस दब जाता है लेकिन साहस की यह ज्योति बुझते हुए दीपक के समान होती है। किसान की यथार्थ की समझ इसे यही कहती है कि उसके जीवन में बहादुरी के लिए कोई स्थान नहीं है।

किसानों की विद्यमान चेतना तो असमानता की परम्परागत संस्कृति को वैध मानती है। अपनी बदहाली की जिम्मेदारी अपने भाग्य पर डालकर संतोष कर लेती है। इस तरह अपने शोषकों को दुश्मन के रूप में नहीं पहचान पाती। प्रेमचंद के कहानी का पात्र 'होरी' इसलिए विद्रोह नहीं करता कि उसे अपना शोषण अन्यायपूर्ण नहीं लगता, उसे वह वैध मानता है। शोषण की अवैधता पर बल देने के लिए राष्ट्रीय और जनतांत्रिक चेतना की जरूरत पड़ती है।

प्रेमचन्द ने समकालीन किसान की जो समवेत प्रतिमा खड़ी की है उसमें किसान इसी कारण विद्रोही नहीं। किसान चेतना में परिवर्तन की आवश्यकता पर बल देने के लिए उसके इस 'मानसिक पिछड़ेपन' को उभारकर सामने रखा गया है। इस तरह उन्होंने यह दिखाया है कि परिवर्तन की शुरुआत कहाँ से की जा सकती है। उन्होंने जिस परिवर्तनशील रूप में ग्रामीण जीवन को उपस्थित किया है उससे यह भी लगता है कि यह ग्रामीण जीवन की तस्वीर तो है लेकिन शाश्वत तस्वीर नहीं है। ग्रामीण जीवन में पीड़ा सहने की जितनी शक्ति है वह पीड़ा को दूर करने के संगठित संघर्ष में भी लग सकती है। अभी समानता का प्रचार ग्रामीणों में होना अभी बाकी है। और इसके प्रचार से भारतीय ग्रामीण जीवन के व्यक्तित्व में परिवर्तन होगा।

समकालीनता के संदर्भ में डॉ० जूही शुक्ला ने प्रो० राजेन्द्र कुमार के व्याख्यान का उद्धरण करते हुए यह मानती हैं कि - 'समकालीनता संवाद के मौके प्रदान करती है। रचनाकारों का आपस में सम्बन्ध स्थापित करती है। सूरदास और तानसेन का संबंध आगे पीछे का है, लेकिन भीमसेन जोशी और हुसैन एक ही मंच पर जुगलबंदी प्रस्तुत करते हैं वे एक साथ ही एक ही क्षण में गा रहे हैं और ब्रश चला रहे हैं। यह रिश्ता समकालीनता का उद्घाटन है जबकि मध्यकाल में ऐसा संभव नहीं था।'

काल के स्तर पर सूरदास और तानसेन में समकालीनता थी परन्तु एक दरबार के बाहर का था और दूसरा दरबार के भीतर का। उनमें अन्तर था। वे एक मंच पर एक साथ नहीं जा सकते थे। परन्तु हुसैन या जोशी एक मंच पर एक साथ होने से इन्कार नहीं कर सकते। यह रिश्ता समकालीनता का है।

कहना न होगा कि 'साहित्य समाज का दर्पण है' यह कहावत जितनी प्राचीन है उससे कहीं अधिक सत्य है। हर साहित्य में अपने समय की परछाई ही नहीं होती बल्कि समय स्वयं को जीता भी है। रचनाकार अपनी रचनाओं में अपना भोगा हुआ यथार्थ, अपनी कल्पनाएँ ही नहीं अपना अतियथार्थ भी प्रस्तुत करता है। समकालीनता से तात्पर्य है अपने समय का। परन्तु यदि कोई आज के समय में मध्यकालीन जीवन मूल्यों को जीता है तो उसको हम वैचारिक रूप से समसामयिक कदापि नहीं मान सकते।

संवेदनाएँ हर युग में होती हैं। यदि इंसान है तो संवेदनाएँ रहेंगी। यह अलग बात है कि आज के युग को या जिस युग में हम जी रहे हैं उसे संवेदना शून्य या कठोर युग कह सकते हैं। मानव संवेदनाओं का सीधा संबंध मशीनों के साथ हो रहा है मसलन अपने बच्चे को डिलीवरी तक कैमरे में प्रसूता देख पा रही है। या फिर भावनाओं का आदान-प्रदान इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर तेजी से हो रहा है। लेकिन इस दौरान एक दूसरे की निःस्वार्थ मदद करना या मानवीय जीवन मूल्यों का सर्वथा अभाव दिखता है। आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना और चुनौती है, मानव का मशीन का गुलाम होना। इस संदर्भ में कल्लोल चक्रवर्ती का यह कथन उल्लेखनीय है कि - 'पृथ्वी में मानव विकास जिस हद तक सम्भव हुआ है, वह मनुष्य के ही पुरुषार्थ से हुआ है। मनुष्य ने पथरों में प्राण फूँके, असमान में चिड़ियों की तरह उड़ाने भरी, समुद्र के नीचे की दुनिया को खंगाल डाला। और तो और क्लोनिंग जीनोम डिकोडिंग के जरिये वह ईश्वर के क्रिया कलापों में भी सेंध लगा चुका है। लेकिन सबसे पहले वह कभी अपने ही विकास का बंधक नहीं बना था, जिस तरह आज है।'

गैर तलब है कि इस तरह की घटनाओं की बयानी भी आज के साहित्य का मुख्य विषय बन चुकी है। स्त्री शोषण एवं दलित शोषण से उपजी संवेदनाएँ किसी न किसी रूप में हिन्दी साहित्य के साहित्यकारों का प्रिय विषय प्रारम्भ से ही रही हैं। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से लेकर आज तक किसी न किसी

रूप में स्त्री अधिकारों की बात, जाति, धर्म, भेद, राजनैतिक दंगे आदि से जुड़ी संवेदनाओं को साहित्य में प्रस्तुत किया जाता रहा है। परन्तु वर्तमान का सबसे बड़ा खतरा अपनों का अपनों से दूर हो जाना और बच्चों का समय से पूर्व बूढ़ा होना है।

साहित्य ने इन खतरों को जब पहचाना होगा, तभी साहित्य की प्रमुख चिन्ता दुनिया भर की कोमलता बचा लेने की है। यह बात अलग है कि अब कविता के बच्चे, पेड़, माँ, पिता, गाँव आदि मूल संवेदना प्रायः नहीं रहे, बल्कि ज्यादातर मुहावरे या फैशन में बदल गये हैं। मूल पर नकल बड़ी जल्दी हावी हो जाती है। अच्छादन की प्रक्रिया के जारी रहते हुए भी एक उम्मीद मनुष्य नहीं छोड़ता कि संभव है कहीं न कहीं यह संवेदन मूल में भी बचा हो।

कोई भी साहित्य अपने समय की अवज्ञा नहीं कर सकता। साहित्य के सामने तो सबसे बुनियादी जिम्मेदारी रहती है कि वह इस बात पर गौर करे कि हमारे समय में मनुष्य किस हाल में है और जिस हाल में है, उस हाल में क्यों है? मनुष्य में अनेक परिवर्तन हुए। सामाजिक प्राणी होने से लेकर टेक्नोलॉजिकल प्राणी और फिर साइबर प्राणी बना। इतनी परिभाषाओं में उसे घेरा गया। यह मनुष्य है कि हर परिभाषा को छोटा करता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। कई असम्भव सम्भव हो गये। अब किसी असम्भव का सम्भव बनना विस्मय का विषय नहीं बनता, बल्कि सूचना मात्र बनकर सामने आता है।

प्रो० राजेन्द्र कुमार का मानना है कि किसी भी काल का साहित्य हो, उसकी इतनी चिन्ता तो रहती है कि थोड़ा विस्मय अपने समाज के लिए चुरा कर रखे। हम विस्मय विहीन समाज की ओर बढ़ रहे हैं। विस्मृत होने की संवेदना ही चुक गयी है। सूचनाओं के इतने आदी हो गये हैं कि यह सोचने की फुरसत ही नहीं है कि हम कहाँ पहुँचे हैं? गालिब का शेर है कि -

‘हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी अब हमारी खबर नहीं आती।’

आज हम चाँद पर पहुँच गये हैं। जमीन पर पानी का संकट है, पर चाँद पर पानी ढूँढ़ रहे हैं। एक जिम्मेदारी आन पड़ी है साहित्य पर कि आज मनुष्य विकास के जिस छोर तक पहुँच गया है, उस मुकाम पर ठहर कर सोचे कि वह आदमी कितना बड़ा बन सका है।

वरन् अब तो ज्ञान भी कृत्रिम हो गया है। भ्रूणडलीकरण के जादू के कारण कृत्रिमता के सामने समर्पण करना पड़ रहा है। अवधारणों का विस्फोट चल रहा है। मनुष्य निर्भिक प्रायः प्राणी बनता जा रहा है। ऐसे में भारतीय समाज के साहित्यकारों की दिक्कत है कि उनकी प्रेरणाएँ तात्कालिकता के प्रति हैं। अविच्छिन्नता समाप्त हो गयी है। हमारी सुदीर्घता उजाड़ हो चुकी है।

हमारे इतिहास-ज्ञान-व्यवहार का रोज चीरहरण हो रहा है, तो क्या हमारा साहित्य हमारी असहायता का शोक-गीत बनकर रह जाएगा या असहायता को सेलीब्रेट करने लगेगा। यों दोनों स्थितियाँ नकारात्मक हैं। इस बदलाव को चुनौती के रूप में संवेदना के पक्ष में कैसे मोल्ड किया जाए, संवेदनशीलता से कैसे जोड़ा जाए, इन प्रश्नों से जो लड़ेगा वही समकालीन साहित्य होगा। उसमें जो संवेदना होगी वह मनुष्यता के पक्ष में होगी। इस बदलते हुए समय में अपने इन्सान होने को बनाये रखने का प्रयास जो साहित्य करेगा वही समकालीन होगा।

समकालीनता की अवधारणा और उसके स्वरूप को विस्तृत फलक में समझाते हुए शैलजा जी कहती हैं कि - ‘समकालीनता’ सामान्य अर्थ प्रसंग में कालवाचक लगता है। है भी। समय से वह बहुत दूर तक जुड़ा हुआ भी है। लेकिन साथ ही यह एक अवधारणा भी है। इतिहास-प्रवाह में, युग-विश्लेषण में यह उसी तरह सहायक होता है जैसे मध्ययुगीनता, पुनर्जागरण और

आधुनिकता। यह ऐतिहासिक या इतिहास की अवधारणा जब साहित्य और कला में आती है तो इसके अर्थ आयाम विराट हो जाते हैं। युग बोध की ऐतिहासिकता के साथ ही इसका संबंध मनुष्य और उसके जीवन कर्मों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ जाता है। भविष्य दृष्टि से सम्पृक्त होकर यह अवधारणा यहाँ अन्य सभी अवधारणाओं से अधिक सार्थकतावाची हो जाती है।

‘समकालीनता’ और ‘समसामयिकता’ को आधुनिकता के संदर्भ में विविध रूपों में व्याख्यायित किया गया है। कहीं-कहीं तो इसे आधुनिकता का पर्याय भी माना गया है। अपने मूल अर्थ में ‘समकालीनता’ और ‘समसामयिकता’ अंग्रेजी के ‘कन्टेम्पोरेनिटी’ तथा ‘कोइबल’ शब्दों का समतावाची है, जिसका अर्थ है उसी समय या कालखंड में होने वाली घटना या प्रवृत्ति या एक ही कालखण्ड में जी रहे व्यक्ति। यही भ्रम हो जाता है कि एक ही काल में साथ रहने वाले लोग समकालीनता के दायरे में आते हैं। इससे यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या जड़ या अचेत व्यक्ति को भी समकालीनता की संज्ञा-क्षेत्र में स्थान दिया जाएगा?

समकालीनता एक काल में साथ-साथ जीना नहीं है। समकालीनता अपने काल की समस्याओं और चुनौतियों का मुकाबला करना है। समस्याओं और चुनौतियों में भी केन्द्रीय महत्व रखने वाली समस्याओं की समझ से समकालीनता उत्पन्न होती है।

इस प्रकार समकालीनता तात्कालिकता नहीं है। समकालीनता में मानवीय हित और प्रगतिशील चेतना समाहित रहती है। समय-सत्य की परख रखने वाला व्यक्ति ही समकालीन हो सकता है। जड़ व्यक्ति अपने काल अपने समय के व्यक्ति और प्रवृत्तियों की परवाह नहीं करता। वह एक गतिहीन मूर्च्छा में जीता रहता है। जड़ता या अबोधता से यह भी संभव है कि वह किसी संस्कार के बल पर, वर्तमान काल में रहकर भी भूतकाल में ही जी रहा हो। वे अपने काल में अपनी स्थितियों और व्यवस्थाओं की स्थितियों के कष्ट से अपने को बचाये रखते हैं। भविष्यजीवी, किसी सुनहरे खयाल में डूबे रह सकते हैं। सचेतन समकालीन व्यक्ति का कालबोध, देशबोध, व्यक्ति और समूहबोध संग्रथित बोध होता है। वह काल के किसी बिंदु को निरपेक्ष और अलग-अलग नहीं मानता। इसलिए समकालीन सचेतन व्यक्ति ही अपने युग के अंतर्विरोध-असंगतियों को उजागर कर सकता है।

डॉ० नरेन्द्र मोहन समकालीनता को काल परक अर्थ में इसलिए नहीं मानते हैं कि वह तात्कालिक हो जाएगी। ‘समकालीनता का अर्थ किसी काल-खंड या दौर में व्याप्त स्थितियों और समस्याओं का चित्रण, निरूपण या बयान भर नहीं है, बल्कि उन्हें ऐतिहासिक अर्थ में समझना, उसके मूल स्रोत तक पहुँचना और निर्णय ले सकने का विवेक अर्जित करना है।’ समकालीन सच्चाई बिना राजनीतिक ज्ञान के अप्रामाणिक और अधूरी होगी। राजनीति ने आज आम आदमी के बीच इतना जहर बो दिया है कि सारा समाज विषाक्त हो गया है।

‘समकालीनता राज्य विरोध में है क्योंकि राज्य ही आम आदमी के हितों के विरुद्ध खाल-उल-खास के स्वार्थों की पूर्ति में लगा हुआ है। और इस प्रक्रिया का संगठित विरोध होने पर राज्य अपनी साम्राज्यवादी परंपरा का उत्तराधिकारी होने के नाते नृशंश दमन और जनोत्पीड़न का मार्ग अपना रहा है।’ राजनीतिज्ञों के भ्रष्ट आचरण ने आज शासन तंत्र और व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार को व्यापक रूप से पनपने का अवसर प्रदान किया है। इस प्रकार के दमन और जनोत्पीड़न का विरोध समकालीनता ही कर सकती है। आशय यह कि समकालीनता एक प्रकार से बोध भी है, दर्शन

भी है। मनुष्य जाति की बेहतरी की दिशा में किये जाने वाले प्रयत्नों की विचार प्रणाली है-समकालीनता। इसकी सोद्देश्यता मनुष्य जाति के विकास की दिशा में किये जाने वाले सार्थक प्रयासों के लिए अपार संभावनाओं का द्वार खोलती है।

गाँवों के उदय के संदर्भ में कहा जाता है - प्रारंभ में ग्राम का आदि रूप 'कुल' था। मनुस्मृति से विदित होता है कि बारह बैलों और दो हलों से जितनी पृथ्वी जोती जाती थी 'कुल' कहलाती थी। दस ग्रामों का अधिपति एक 'कुल' का भोग करने का अधिकारी था और बीस ग्रामों का अधिपति पाँच 'कुलों'

के भोग का अधिकारी था। कुछ समय पश्चात कुल से ग्राम, ग्राम से विश और विश से जन का विकास होकर राष्ट्र ने रूप धारण किया।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अनिल विश्वनाथ काले - रामदरश मिश्र के उपन्यासों में ग्रामीण परिवेश
2. प्रो. रामबक्ष - प्रेमचंद और भारतीय किसान
3. विष्णु प्रभाकर श्रोत्रिय - सौंदर्य का तात्पर्य
4. विश्वभरनाथ उपाध्याय - समकालीन सिद्धान्त और साहित्य

\*\*\*\*\*



## हिन्दी कविता में आदिवासी स्त्रियों के सवाल और संघर्ष चेतना

डॉ. त्रिभुवन कुमार साही \*

**प्रस्तावना** - झारखण्ड आधारित हिन्दी कविता में आदिवासी स्त्रियों के प्रश्न पिछले कुछ वर्षों से लगातार यह चर्चा का विषय बनता जा रहा है कि आदिवासी साहित्य में आदिवासी स्त्रियों के सवाल उपेक्षित क्यों हैं ? आदिवासी समाज में स्त्री पुरुष समानता के बावजूद उनके संबंध में मौलिक लेखन आज भी काफी कम मात्रा में मौजूद है। झारखंड समेत देश दुनिया के कई हिस्सों में आदिवासी समाज पितृसत्तात्मक है इस नाते स्त्रियां पुरुष की तुलना में कमतर आंकी जाती हैं। इसलिए अपने उपर आरोपित इस कमतर की भावना के खिलाफ हर जगह पर स्त्रियां संघर्षरत हैं चाहे वह आदिवासी समाज हो या फिर गैर आदिवासी समाज। उनका यह संघर्ष पितृसत्तात्मक मनोसंरचना को उखाड़ फेंकने का रुख अख्तियार किए रहता है। आदिवासी स्त्री विमर्श देह केंद्रित विमर्श नहीं है बल्कि पुरुष को अपने समकक्ष रखकर स्त्री-विमर्श चलाने के दायित्वों का निर्वहन करती है। आलोचना के इस टूल के आधार पर हम झारखण्ड आधारित हिन्दी कविता में आदिवासी स्त्रियों के कुछ प्रश्नों से रुबरु होंगे।

आदिवासी समाज में नशाखोरी की प्रताड़ना सबसे ज्यादा आदिवासी स्त्रियाँ ही झेलती हैं। नशे में धुत होने के कारण पुरुष काम नहीं कर पाता है और गृहस्थी का सारा बोझ स्त्री पर आ पड़ता है। नशाखोरी गृहस्थी में ऐसा जड़ जमा लेता है कि कई सारी छोटी-छोटी समस्याएँ इससे पैदा होने लगती हैं। आदिवासी समाज में पुरुष नशाखोरी का शिकार तो है ही इसमें कुछ हद तक महिलाएँ भी हैं और कहीं न कहीं नशे के व्यापार में सबसे बड़ा हाथ महिलाओं का ही है। आप झारखण्ड के बाजारों या सड़क के किनारे महिलाओं को हंडिया बेचते देख पाएंगे। आदिवासी कवयित्री निर्मला पुतुल की कविताएँ उन निगाहों को पहचानती हैं जो आदिवासी स्त्रियों को वस्तु में बदलने को आतुर है। आदिवासी समाज की विकृतियों से टकराती हुई ये कविता जब सजोनी किस्कू की व्यथा-कथा कहती ह तो पूरा का पूरा झारखण्ड चिंतित हो जाता है और चुड़का सोरेन के पिता को हंडिया पीकर बेखबर होने के खतरों से सचेत करती है -

'तुम्हारे पिता ने कितनी शराब पी यह तो मैं नहीं जानती  
पर शराब उसे पी गयी यह जानता है सारा गाँव।'<sup>2</sup>

आदिवासी समाज में जो बुरी लत है उससे दूर रहने कि कवयित्री हिदायत देती है। आदिवासी समाज में नशे की लत है जो वर्तमान समय में आदिवासियों के लिए एक अभिशाप है जो उनकी कमर तोड़ रहा है। नशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक असर डालती है। बाप और बेटा दोनों को एक साथ तबाह कर सकती है जैसा की हर कोई जानता है कि नशा परिवार को बर्बाद कर देता है जिसके घर में दो-चार पीने वाले हो गए तो समझो कि उसका घर का खैर नहीं। यह मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आदिवासी समाज में परिवार के

अधिकांश लोग पीते हैं इसमें महिलाएँ भी शामिल हैं। सच कहें तो आदिवासी समाज में नशे का सारा कारोबार महिलाएँ ही संभालती हैं हंडिया और शराब लेकर महिलाएँ सड़क के किनारे और बाजारों में बैठी मिलेंगी जो अपने बच्चों के उम्र तक के लड़कों को हंडिया पिलाती हैं। महिलाएँ हंडिया बेचने को आय का स्रोत मानती हैं। यह बात उनके दिमाग में कभी नहीं आता है कि जिसे वह आय का स्रोत मानती हैं वह कारोबार अपने ही समाज को बर्बाद कर रहा है। नशे का प्रभाव समाज में इतना विकराल है कि आदिवासी गाँव में कोई भी काम होता है तो जब-तक नशा-पान की व्यवस्था न हो तब-तक वह काम होता ही नहीं है, चाहे वह छोटा काम हो चाहे बड़ा काम, लोग घर का छप्पर छाने तक के लिए हंडिया-दारू की व्यवस्था करते हैं। इस नशाखोरी से सबसे ज्यादा कोई प्रभावित होता है तो वे बच्चे-बच्चियाँ हैं। स्कूल जाने की उम्र में जब उनका दिमाग पूरी तौर पर निर्मल होता है उन्हें जो कुछ पढ़ाया, बताया जाए वे सीख सकते हैं। इस सीखने की उम्र को नशा दूषित करने लगता है। पिये हुए माँ-बाप, भाई, पड़ोसी आदि की लड़ाई-झगड़ा और उनके द्वारा बनाए गए माहौल से बच्चे बुरी तरह प्रभावित होते हैं और अंत में यही बच्चे परिपक्व न होने के कारण खुद भी नशापान करने लगते हैं और नशा का सेवन करते ही उनकी सारी संभावनाएँ टूट जाती है यही लोग बड़े होकर या कच्चे उम्र में ही दिल्ली, मुम्बई भाग जाते हैं, जहाँ उनको अंतहीन कष्टों का सामना करना पड़ता है। नशा के चक्र में उनका खेत-खलिहान सब बिक जाता है खास कर शहरी क्षेत्र के आदिवासियों को इसी नशे का झांसा देकर बाहरी लोगों ने उनको उनकी जमीनों से बेदखल किया। शहरी क्षेत्र का आदिवासी इस नशा के चलते सबसे ज्यादा लूटा हुआ है। असल में आदिवासियों की दुर्दशा का बड़ा जड़ नशाखोरी है।

आदिवासी जीवन में स्त्री की सामाजिक स्थिति के साथ-साथ आर्थिक स्थिति का सजीव वर्णन भी आदिवासी कविताओं के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। रोटी इन आदिवासियों के लिए शायद पहला और आखिरी प्रश्न है आज भी पुरुषों की तुलना में स्त्री को कम मजदूरी दी जाती है। पत्ताल बनाना, झाड़ू बनाना, चटाई बुनना, तेंदुपत्ता, महुआ चुनना उनका जीवन रोटी की खोज में भागता नजर आता है। आदिवासी जीवन की कठिनाई स्त्रियों को सामने रखकर देखा जा सकता है स्त्रियाँ बच्चों को पीठ पर बांध कर काम करती हैं। खेतों में काम करना हो या शहरों में सामान बेचने जाना हो छोटे बच्चे को पीठ पर बांध कर आदिवासी स्त्रियाँ काम करती हैं। आदिवासी क्षेत्रों में बड़े-बड़े खदानों के खुलने से वे महिलाएँ खदानों में जी तोड़ मेहनत करती हैं। माईन्स में विस्फोट होते रहते हैं और जान जोखिम में डालकर किस प्रकार मेहनत करती हैं ग्रेस कुजूर की कविता 'आग' इसे स्पष्ट करती है -  
'एतवरिया सुन नहीं पाती,

अपनी चूड़ियों की खनक  
नहीं बिठा पाती सही जगह,  
पसीने से भींजी माथे की बिन्दी।<sup>13</sup>

शहरीकरण और फिल्मी प्रभाव आदि के चलते आदिवासी स्त्री-पुरुषों के संबंध में जो दरारें पड़ रही हैं उसे भी आदिवासी कवयित्री पहचान रही हैं और अपनी कविता में दर्ज करने की कोशिश में हैं। आधुनिक समय में कॉलेजों में पढ़ाई-लिखाई, नौकरी जैसे कामों में आदिवासी स्त्री-पुरुष भी एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। सूचनाक्रांति जिसमें एक बड़ा सहयोगी है। इन परिस्थितियों में शादी से पहले और शादी के बाद भी स्त्री-पुरुष कई रिश्तों में एक-दूसरे के सामने आ रहे हैं जो वैवाहिक संबंध में शक के रूप में बदल कर आते हैं। जो आपसी संबंधों के टकराहट का कारण बनते हैं। कभी पुरुष इन मनोग्रंथी से उलझकर रह जाता है तो कभी स्त्री। किन्तु ज्यादातर स्त्री ही इसका शिकार होती हैं जिसे समेटते-समेटते उसकी उम्र ही गुजर जाती है -  
'हर सुबह उठकर वो  
बिस्तर पर पड़ी सिलवटों से  
टूटे रिश्तों के टुकड़े चुनती है।'<sup>14</sup>

आदिवासी स्त्रियों के जीवन की बहुत बड़ी हकीकत है। डर का अनाम साया उन्हें हर वक्त घेरे रहता है। कैसी हैवानियत की शिकार होती हैं ये स्त्रियाँ। घर का दरवाजा खोलकर सोने में डरती हैं। दरवाजे बंद होने पर भी बाहर की आवाजें असुरक्षा के बोध को कम नहीं होने देती। टेलीविजन और अखबार के पन्ने रंगे रहते हैं ऐसी वारदातों के बयान से। निर्मला पुतुल अपनी अनेक कविताओं में कभी सीधे कभी सांकेतिक रूप में ऐसी घटनाओं का वर्णन करती हैं। पीड़ा इस बात की है कि आततायियों के चेहरे अलग से पहचाने जाने वाले चेहरे नहीं हैं। कौन किस भेष में उनका सौदा कर देगा यह साफ नहीं। पूरी आदिवासी पट्टी के लिए ट्रैफिकिंग एक बड़ी समस्या है। जिसके तह में जाने पर कई कारण दिखाई देते हैं। आदिवासी समाज की अशिक्षा, गरीबी उनका सहज व्यक्तित्व किसी पर जल्द विश्वास कर लेने का गुण मानव तस्करी के मूल कारण हैं। पूरे आदिवासी पट्टी के हर गाँव से कोई न कोई आदिवासी युवती ट्रैफिकिंग का शिकार हुई है। यह भी सच है कि हर गाँव में एक-दो दलाल जरूर हैं जो इन क्षेत्रों से आदिवासी युवक-युवतियों को दिल्ली, बॉम्बे जैसे महानगरों तक पहुँचाने का काम करते हैं। इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य बात है कि यह दलाल सिर्फ दिकू समाज का नहीं है। बल्कि आदिवासी समाज से भी ऐसे लोग हैं जो आदिवासी युवतियों को प्रलोभन देकर महानगरों तक पहुँचाते हैं। निर्मला पुतुल की कविता 'चुड़का सोरेन' की स्टेला कुजूर इसका उदाहरण है -

'दिल्ली के किस कोने में हो तुम माया ?  
मयूर विहार, पंजाबी बाग या शाहदरा में ?  
कनाट प्लेस की किसी दुकान में  
या किसी घरेलू कामगार महिला संगठन से जुड़कर  
बन गई हो किसी के घर की आया?'<sup>15</sup>

अपने घर की तलाश करती-करती कवयित्री दिल्ली तक पहुँच जाती है क्योंकि जिसका घर है वो खुद घर में नहीं है और उसका घर में नहीं होना एक साथ कई सवाल को खड़ा करती है। एक मजबूरी एक प्रलोभन और एक धोखा धड़ी उस 'माया' के घर के चारों ओर विद्यमान है जो कभी लालच देकर तो कभी मजबूरी में उसे अपने घर से दूर ले जाती है दुख की बात है कि वह जहाँ जाती है वहाँ भी उसे वह सब-कुछ नहीं मिलता है जो सोचकर वह घर से निकली होती है। वहाँ उसे कई अमानवीय यातनाओं का सामना करना

पड़ता है। कई ऐसे काम करने पड़ते हैं जो उसने कभी किया न हो और वह ऐसा करने की कभी सोच भी नहीं सकती है। लेकिन पेट की आग और षड्यंत्रों का शिकार में 'माया' क्या कुछ नहीं करती। उसे बहुत कम पैसों में थई क्लास काम करने पड़ते हैं, कहीं टेलीफोन ऑपरेटर बनती है तो कहीं कॉस्मेटिक दुकान में सेल्सगर्ल। इन कामों का प्रकृति-प्रिय स्वच्छंद आदिवासी युवती के लिए कोई समानता नहीं है। इन वादों और प्रलोभनों से गुजरती हुई माया कब किसी के घर की बंधक बन जाती है उसे खुद को भी पता नहीं चलता।

आदिवासी स्त्री की सामाजिक स्थिति दयनीय एवं करुण है। आर्थिक अभाव, अशिक्षा, अंधविश्वास के कारण उसे अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन करना पड़ता है। अशिक्षा, अज्ञान के कारण आदिवासी समुदाय में रूढ़ि-प्रथाओं के कारण स्त्री को त्रासदी का सामना करना पड़ता है। 'डायन प्रथा' आदिवासी समाज में व्याप्त ऐसी ही प्रथा है जिसके कारण आदिवासी स्त्री को आर्थिक और शारीरिक, दोनों प्रकार के दण्ड दिए जाते हैं। जिस औरत को बच्चा नहीं होता है, जो औरत कई बार शादी करके विधवा हो चुकी हो, उसे डायन करार दिया जाता है। गाँव में कोई हादसा हो जाने पर उसकी सारी जिम्मेदारी ऐसी ही किसी 'डायन' औरत के ऊपर मढ़ दी जाती है उसे इतना शारीरिक दण्ड दिया जाता है कि कभी-कभी उसकी मृत्यु तक हो जाती है। स्त्री जीवन की इस विडंबना को उभारती हुई निर्मला पुतुल कहती हैं।

विकास के नाम पर षड्यंत्रों का शिकार होते हुए इन आदिवासियों को बार-बार विस्थापन का दंश झेलना पड़ा है। निर्मला पुतुल अपनी कविताओं में आदिवासी समाज के अंतर्विरोधों को उकेरते हुए यथास्थिति के प्रतिकार के लिए कविता का अभियान छेड़ती हैं। वे अपने आदिवासी बहनों और भाइयों को विद्रोह के वीर इतिहास की याद दिलाती हैं। बार-बार सचेत करती हैं कि अपने शोषण को पहचानो एवं उदासीन समर्पण की राह छोड़कर संघर्ष की राह चुनो। इस सारे सामाजिक संघर्ष की पृष्ठभूमि में स्त्रियों की स्थिति और भी विकट है। जीवन के अभावों से सतत संघर्ष, कड़ी-मेहनत, दैहिक-आर्थिक शोषण, स्त्री को डायन बना देने वाली कुप्रथाओं का बोझ सब मिलकर स्त्री के लिए ऐसी व्यूह-रचना करते हैं कि उसका जीवित रहना भी मुश्किल जान पड़ता है।

निर्मला पुतुल एक जागरूक कवयित्री हैं उन्हें बदलते आदिवासी समाज की सही जानकारी है इसलिए वह आदिवासी समाज में पुरुष सत्ता की धमक को सुन पा रही है और एक जिम्मेदार कवयित्री होने के नाते समूचे आदिवासी स्त्री समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रही है। और आदिवासी महिलाओं के संघर्ष, उनकी चीख, उसकी दर्द, मदद के लिए पुकारती आवाजें और उनके उठते सवालों को व्यापक चर्चा में बदल रही हैं -

'कटी-फटी देह की दरारों से झांकती  
स्त्री की भींगी आँखें सवाल पूछ रही हैं  
इंसानियत का धर्म जो भूल गए हैं  
उनकी 'घर वापसी' कौन कराएगा?'<sup>17</sup>

यह कविता यौन दासियों की व्यथा-कथा कहती है। यौन कर्म में लगी स्त्री जो मजबूरी में यह किसी की झांसे में आकर किसी के द्वारा बेची गई महिलाएँ हैं। इन महिलाओं में बहुत सी आदिवासी स्त्रियाँ भी हैं जो देश के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों से दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता जैसे महानगरों की अंधेरी कोठियों में पहुँचा दी गई हैं। इनमें से किसी को जब कोई एन.जी.ओ. या सरकार उन अंधेरी गलियों से खोज कर वापस अपने गाँव में लाती है तो

उसे लोग हिकारत की नजर से देखते हैं, उस पर कई तरह के कमेंट किए जाते हैं। उसका काम बाहर की दुनिया में जीने का कोई हक नहीं देती। लेकिन जब वह महिला वह काम कर रही होती है तब यही लोग उसका भरपूर उपभोग करते हैं। किन्तु जब वह उस काम को छोड़ देती है या वह वृद्ध हो जाती है तो यही लोग उससे घृणा करने लगते हैं। इस कविता में वही उपेक्षित महिला समाज में अपनी और स्त्रियों के जैसा समानता का हक मांग रही है। वर्तमान आदिवासी कविताएँ क्रांतिदर्शी हैं। इनमें अंधविश्वास के प्रति विरोध है ये कविता पुरुषों की स्त्री विरोधी मानसिकता को बदलने में समर्थ हैं।

आदिवासी समाज की महिलाएँ अपने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही हैं। पुरुष अगर जंगल में काम से गया हो तो वे घर के और बाहर के पशु-पक्षी, खेती-बाड़ी से जुड़े सभी कामों को संभालती है। हाट-बाजार में महिला और पुरुष समान रूप से जाते हैं। इन सारी समानताओं के बावजूद भी कहीं न कहीं विषमता है -

‘क्या इसी दिन के लिए इतने जतन से  
घर-गृहस्थी संभाली तुम्हारी?  
कि मन भर जाते ही फटे-पुराने धोती की तरह  
उतार फेंको मुझे?’<sup>8</sup>

यह हमारे समाज का बहुत बड़ा दोष है कि बेटा और बेटी के बीच हमने बहुत अन्तर बना रखा है। इस तरह की जो कुप्रथाएँ हैं ये स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं हैं। जैसा कि हम जानते हैं भारत विभिन्न सभ्यता, संस्कृतियों वाला देश है। ये सभ्यताएँ और संस्कृतियाँ एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं इसलिए जब सभ्यता में कुरीतियाँ होंगी चाहे वह कोई भी समाज हो एक-दूसरे पर गलत प्रभाव डालेगा। इस तरह से स्त्रियों को लेकर भेद-भाव जो मुख्यधारा के समाज में कई स्तरों पर बना हुआ है वर्तमान समय में आदिवासी समाज पर भी गलत प्रभाव डाल रहा है। इसलिए आदिवासी समाज की सचेत कवयित्री वंदना टेटे उन समस्याओं की ओर ध्यानाकर्षण कराती है -

‘इंसानियत से बेदखल  
समाज कत्ल कर देता है तुम्हें  
और जब जबान खुलती है तुम्हारी  
तुम्हें बदचलन करार दे दिया जाता है।’<sup>9</sup>

आदिवासी संघर्ष में स्त्रियों ने वीरता का परिचय दिया है। संधाल हूल के नायक सिद्धो-कान्हू, चाँद-भैरव के साथ उनकी दो बहन फूलो और झानो ने योद्धा की भांति अंग्रेजों से मुकाबला किया। रात को तलवार लेकर निकली फूलो और झानो ने अंग्रेजों के शिविर जाकर इक्कीस सिपाहियों की हत्या की। आदिवासी अस्मिता का प्रश्न हो या जंगल, जमीन पर परंपरागत हक व सांस्कृतिक जीवन मूल्यों की रक्षा का सवाल या फिर साम्राज्यवाद विरोध की अगुवाई का मुद्दा आदिवासी स्त्रियों ने उलगुलान में बराबर की भूमिका निभाई-

‘भोगनाडीह में तुम दोनों ने कसमें खायी  
तुमने महाजनों सुदखोरों के अत्याचार को नहीं सहा  
तुमने दोनों हाथों से तलवार उठायी  
अंग्रेजों व दरोगा के जुल्म के खिलाफ आवाज उठायी।’<sup>10</sup>

क्रांतिकारी कहने से प्रचलित रूढ़ि के अनुसार पुरुष व्यक्ति का बोध होता है किन्तु आदिवासी समाज में क्रांति का एक पाठ आदिवासी महिलाएँ हैं जिनकी शक्ति और स्वर प्रदर्शन से समाज अपने को सुरक्षित रखता रहा है। आदिवासी इतिहास उठाकर देखें तो इस मिशाल की कई घटनाएँ मिलेंगे, जहाँ आदिवासी महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर क्रांति का बिगुल फूँका था। इनको

पूर्ण सफलता भले नहीं मिली लेकिन इन आन्दोलनों ने आदिवासी महिला नेतृत्व की धाक जमा दी। आदिवासी महिलाएँ पुरुष से किसी भी मामले में कमतर नहीं हैं।

ग्रेस कुजूर आदिवासी महिलाओं के युगांतकारी क्रांतिकारी भूमिका को याद दिलाते हुए वर्तमान समय में दुहराने की बात कहती है। अपने पुरुष साथी से वर्तमान की कुव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज बुलन्द करने को कहती है ठीक वैसे जैसा कभी उसने शेरशाह के जुल्म के खिलाफ विद्रोह के लिए प्रेरित किया था और आदिवासी पुरुषों के हार जाने पर महिलाओं ने कमान संभाला था ऐसा ही वह वर्तमान समय में शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार दिखती है -

‘और अगर अब भी तुम्हारे हाथों की अंगुलियाँ धरथराई  
तो जान लो मैं बनूँगी एक बार और ‘सिनगी दई’  
बांधूँगी फेंटा और कसेगी फिर से ‘बेतरा’ की गाँठ।’<sup>11</sup>

इस कविता की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका बिम्ब विधान बहुत ही बेजोड़ है आदिवासी महिला का फेंटा बांधना, पीठ में बच्चा को बेतराना हमारे सामने एक संघर्षशील महिला की तस्वीर पेश करती है। वह वीरता और स्त्री सुलभ ममता से सराबोर है। सिर में पगड़ी और हाथों में तीर-धनुष उसकी वीरता के सूचक हैं और पीठ में बेतरा बांधा हुआ बच्चा स्त्री हृदय का विस्तार। जब भी कोई झाँसी की रानी को याद करता है तो उसके अन्दर शौर्य का समन्दर उफान मारता है। वैसे ही ‘सिनगी दई’ की कहानी उसकी वीरता के किस्से स्त्री-पुरुष दोनों में एक समान शोषण के खिलाफ जयघोष करती है।

कोयला खदान में काम करने वाली आदिवासी महिलाओं की दयनीय स्थिति पर रमणिका गुप्ता की बेहतरीन कविता है, उनकी कविता ‘मैं जीऊँगी’ इस समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षण कराती है। आदिवासी महिला को अपने परिवार का भरण-पोषण के लिए कोयला खदान जैसे खतरनाक जगहों में काम करना पड़ता है। चाहे उसे चोट लगे, चाहे बीमार हो उसे काम करना ही पड़ता है क्योंकि उसके पति का कमाई से पूरे परिवार को चलाना मुश्किल होता है इसलिए वह परिवार की आर्थिक बोझ को हल्का करने के लिए खुद भी श्रम करने लगती है। श्रम कोई बुरी बात नहीं है। परिश्रम करना ही चाहिए लेकिन जिस तरह से जिन जगहों पर आदिवासी महिलाओं से काम कराया जाता है, वह कतई भी ठीक नहीं है। इस श्रमिक महिलाओं के प्रति मुंषी और ठेकेदार का रवैया बहुत ही बेरहम होता है। इन तमाम मजबूरियों को रमणिका गुप्ता ने रेखांकित किया है -

‘नौकरशाही लालफीतों का मुंशी  
तेरी चोट-खाई रीढ़ को नहीं पहचानता  
वह तो जानता है केवल  
तूने कितने झोड़े कोयला उठाया, कितने झोड़े गिराया  
तू कराहती है फिर भी खटती है  
झुकती नहीं, टूटती नहीं तू।’<sup>12</sup>

यह पंक्ति एक आदिवासी मजदूरीन की व्यथा-चित्र पाठक के सामने उकेर देती है चाहे वह ईंट-भट्टा हो चाहे कोयला खदान या फिर पत्थर तोड़ने का साईट, सभी जगहों पर आदिवासी महिलाएँ काम करती हैं। इनमें से कई महिलाएँ बीमार और काम करते-करते चोट खाई होती हैं, फिर भी वे मजबूरी में काम करती हैं। काम करने में उसकी असमर्थता ठेकेदार को दिखाई देता है फिर भी वह इसका परवाह नहीं करता। उसे अपना काम निकालने से मतलब रहता है वह सिर्फ अपना फायदा देखता है काम होना चाहिए। इन महिलाओं

की पीड़ा चाहे बड़ी चाहे छोटी इसका वह हिसाब नहीं रखता है।

जसिन्ता केरकेटा की एक महत्वपूर्ण काव्यपंक्ति है -

‘मुझे गोद में लेकर उस दिन

माँ ने बस इतना कहा-

‘हम लड़ रहे हैं, अपनी जमीन

और अपना वजूद बचाने के लिए

मेरे बाद तुम्हें भी लड़ना होगा’

अगले दिन माँ तीर कमान लिए निकल पड़ी फिर...।<sup>13</sup>

जसिन्ता केरकेटा की यह कविता पाठकों में उलगुलान का शोला भर देती है। यह कविता आदिवासी संघर्ष में स्त्रियों की भागीदारी के उत्साह को दर्शाती है। शोषण के खिलाफ लड़ती महिला अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी संघर्ष का मशाल जलाते जाती है। कविता में दो लोग हैं एक ‘माँ’ और एक ‘बच्ची’। माँ किसी मोर्चा पर रोज-दिन संघर्ष करने जाती है। एक दिन वह दिकूओं के औजार से चोट खा कर लहुलुहान घर आती है उसे देखकर घर में रह रही उसकी बच्ची के मन में भी विद्रोह का भाव उमड़ने लगता है। उस बच्ची के मन में लहू का उतर आना स्वाभाविक है। माँ, घर-परिवार में विद्रोह का बीज तैयार करती है और वह अपनी बच्ची से कहती है कि मेरे बाद तुम्हें लड़ना होगा। और ऐसे ही एक दिन उसकी माँ अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए निकलती है सो फिर लौट कर नहीं आती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि माँ तो लौट कर नहीं आती है। वह वहीं वीर गति को प्राप्त होती है किन्तु मारे जाने से युद्ध खत्म नहीं होता है उसके आगे की पीढ़ी युद्ध को बनाये रखती है। यह आदिवासी जीवन संघर्षों की विशेषता का सूचक है।

आदिवासी समाज के इतिहास में स्त्रियों के कई सवाल हैं और संघर्ष के कई उदाहरण भी जिसे आदिवासी स्त्रियाँ हरदम जिंदा रखती हैं क्योंकि सवाल ही पहला आंदोलन है और उस सवाल को जिंदा रखना उलगुलान की चिंगारी है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. निर्मला पुतुल - ‘नगाड़े की तरह बजते शब्द’ भारतीय ज्ञानपीठ,

लोदी रोड नयी दिल्ली, प्र. सं. -2005, पृ. सं. - 19

2. वही. पृ. सं. - 17

3. जसिन्ता केरकेटा - ‘अंगोर’, आदिवाणी प्रकाशन, कोलकाता, प्र. सं. -2016, पृ. सं. -130

4. निर्मला पुतुल - ‘नगाड़े की तरह बजते शब्द’, भारतीय ज्ञानपीठ, लोदी रोड नयी दिल्ली, प्र. सं. -2005, पृ. सं. - 19

5. सं. रमणिका गुप्ता - ‘कलम को तीर होने दो’, वाणी प्रकाशन, दरियागंज नयी दिल्ली, प्र. सं. -2015, पृ. सं. -85, 86

6. जसिन्ता केरकेटा - ‘अंगोर’, आदिवाणी प्रकाशन, कोलकाता, प्र. सं. -2016, पृ. सं. -136

7. निर्मला पुतुल - ‘अपने घर की तलाश में’, रमणिका फाउण्डेशन, शाहदरा दिल्ली, प्र. सं. -2004, पृ. सं. -31

8. जसिन्ता केरकेटा - ‘अंगोर’, आदिवाणी प्रकाशन, कोलकाता, प्र. सं. -2016, पृ. सं. -130

9. जसिन्ता केरकेटा - ‘जड़ों की जमीन’, भारतीय ज्ञानपीठ, लोदी रोड नयी दिल्ली, प्र. सं. -2018, पृ. सं. -104

10. निर्मला पुतुल - ‘अपने घर की तलाश में’, रमणिका फाउण्डेशन, शाहदरा दिल्ली, प्र. सं. -2004, पृ. सं. -37, 38

11. वंदना टेटे - ‘कोनजोगा’, प्यारा केरकेटा फाउण्डेशन, राँची, प्र. सं. -2015, पृ. सं. -50, 51

12. केदार प्रसाद मीणा - ‘क्रांतिकारी आदिवासी’, साहित्य उपक्रम, दिल्ली, प्र. सं. -2012, पृ. सं. -131

13. सं. रमणिका गुप्ता - ‘कलम को तीर होने दो’, वाणी प्रकाशन, दरियागंज नयी दिल्ली, प्र. सं. -2015, पृ. सं. -101

14. रमणिका गुप्ता - ‘भीड़ सतर में चलने लगी हैं’, रमणिका फाउण्डेशन, हजारीबाग (झारख.ड), प्र. सं. -2002, पृ. सं. -12

15. जसिन्ता केरकेटा - ‘अंगोर’, आदिवासी प्रकाशन, कोलकाता, प्र. सं. -2016, पृ. सं. -60

\*\*\*\*\*



## कलचुरियों का विंध्य भूमि से सम्बन्ध

डॉ. सरोज सिंह \*

**प्रस्तावना** – स्वतंत्रता के पश्चात बनाये गए विंध्य प्रान्त का इस रूप में अस्तित्व इस भाग के ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक काम में कहीं नहीं मिलता। वर्तमान रूप में तो तत्कालीन राजनैतिक स्थिति के कारन प्राप्त हुआ था। इसका उद्देश्य था, इस क्षेत्र के देशी राज्यों का शासकीय दृष्टि से एक समूह में बांधना। मुस्लिम इतिहासकारों ने विंध्य भूमि के बघेलखण्ड क्षेत्र को भाटा या भटगोरा और बुंदेलखंड क्षेत्र को कालिंजर सरकार का नाम दिया है। इसके पहले यह महाकौशल चेदि देश और डाहल देश के एक भाग के रूप में रहा आया है।

कलचुरि नरेशों का इस क्षेत्र पर अधिकार ईशा की दशवीं शताब्दी के प्रारम्भ से पाया जाता है। कृष्णराज कलचुरि ( 550 – 575 ) के शासनकाल से इस सत्ता का सूत्रपात हुआ। उसके शासनकाल में दक्षिणी बघेलखण्ड का अधिकांश भू –भाग त्रिपुरी राज्य में शामिल था।

कोकलदेव ( 850 – 890 ) और उसके पुत्र मुग्धतुंग ने इस देश के इस देश के अधिकांश भू –भाग पर अधिकार कर लिया।

वामराजदेव ने भी कालिंजर के किले को जीत लिया था। इसके बाद पुनः इन नरेशों ने उस पर अधिकार किया। युवराज देव प्रथम ने गुर्गी और उसके पुत्र लक्ष्मणराज प्रथम ने चन्देह में शिवमठो और देवालयों का निर्माण कराया। बैजनाथ (रीवा सतना रोड पर रीवा से 8 मील दूर पर ) में भी उसने एक शिवमठ की स्थापना की और उसकी व्यवस्था के लिए गावों की आमदनी लगा दी थी। उसके पश्चात लक्ष्मणराज द्वितीय ने गुर्गी के वृहद् मंदिरों का भी निर्माण कराया।

गांगेयदेव ( 1015 – 1041 ) जो एक महान पराक्रमी राजा था का एक शिलालेख (सिरमौर तहसील में ) दूसरा सन 1020 ( कलचुरि संवत् 772 ) का मुकुंदपुर में हुआ है। इनसे यह जानकारी प्राप्त होती है कि यह प्रदेश गांगेयदेव के राज्य का भाग था। इसके शासनकाल में मंदिर आदि अमरकंटक सोहागपुर और महई आदि में बने हुए हैं।

गांगेयदेव के पुत्र कण्ठदेव ( 1041 – 1073 ) ने कालिंजर के किले पर पुनः अधिकार कर लिया, जो इस बीच में चंदेल राजा कीर्तिवर्मा के हाथ में चला गया था। इसका एक ताम्रपत्र सन 1041 ( कलचुरि संवत् 793 ) का प्राप्त हुआ है। जिससे पता चलता है कि अमरकंटक का कर्णमंदिर जो तत्कालीन स्थापत्यकला का एक अच्छा उदाहरण है, उसी का बनवाया हुआ है, इतना ही नहीं इसके ही द्रव्य से बहन ने तुंडेश्वर महादेव ( रीवा से 6 मील दूर ) के महान मंदिर का निर्माण कराया था, जो आज बहुत ही अस्त व्यस्त दशा में है, फिर भी आश्रय की अतीत विशालता, सभ्यता और मेहनत का परिचायक है। साढ़े पांच मील के घेरे में 12 फुट भाता परकोटा खिंचवाकर इसने गुर्गी में एक विशाल दुर्ग और अनेक भव्य महलों का

निर्माण कराया।

कर्ण के पश्चात यश कर्ण, जगकरणदेव, नरसिंग देव, जय सिंह, विजय सिंह तथा अजय सिंह हुए जो विक्रमी सम्वत् की 12 वीं और 13 वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में शासन करते रहे। इस बीच कालिंजर का किला पुनः इनके हाथ से निकल गया।

14 वीं शताब्दी के आते आते कलचुरियों का शासन इस क्षेत्र से छट गया, पर दक्षिण में रत्नपुर और रायपुर में यह अक्षुण्य रहा। वहीं की एक शाखा के संदल कलचुरी ने जो रत्नपुर के कलचुरी राज्य के अंतर्गत एक भाग सोहागपुर का शासक था, अपनी पुत्री यश कुँवरि का विवाह गुजरात के बघेल नरेश कण्ठदेव से करके बांधवगढ़ का अपना किला दहेज में दे दिया। इस प्रकार कलचुरि सम्बन्ध के कारन इस क्षेत्र में बघेलों के राज्य की नींव पड़ी।

इस शताब्दी के अंतिम भाग में तत्कालीन रत्नपुर नरेश परवत सिंह देव के चचेरे भाई नीलकंठ देव राज्य की शासन व्यवस्था से असंतुष्ट होकर अपने परिवार और साथियों सहित रत्नपुर छिड़कर सोहागपुर की ओर चले आये।

तत्कालीन रीवा नरेश महाराज भाव सिंह ने उन्हें रहने के लिए रीवा से 9 मील पश्चिम वर्तमान रीवा सतना मार्ग के निकट मालगढ़ गांव दिया। इसी बीच महाराज भाव सिंह के देहांत के पश्चात उनके दत्तक पुत्र महाराज अनिरुद्ध सिंह को यहाँ के सेंगर ठाकुरों ने मार डाला। राज्य की स्थिति दयनीय हो गयी। उनके पुत्र अवधूत सिंह को जो केवल 6 महीने के शिशु थे, राजमाता लेकर अपने मायके प्रतापगढ़ चली गयी। राज्य का प्रबंध चित्रकूट के राजा हृदयराज सुरकी को सौंपा हुआ था, अवसर पाकर महाराज छत्रासाल के पुत्र हृदयशाह बुंदेले ने रीवा पर आक्रमण कर दिया। रीवा की ओर से कोई प्रतिरोध नहीं हुआ और बिना युद्ध के ही यहाँ के किले पर हृदयशाह बुंदेले ने अधिकार कर लिया और अपनी विजय स्मृति स्वरूप स्वर्गीय बुंदेला का दरवाजा बनवाने लगा। पर वह पूरा न हो पाया था तभी उसे महाराज छत्रासाल का आदेश पन्ना लौटने को मिला। फलतः वह एक हजार सैनिकों को किले पर अधिकार जमाये रखने के लिए छोड़कर चला गया।

**कलचुरियों का बुंदेलों से सम्बन्ध** – नीलकंठ देव कलचुरि अपने परिवार के साथ मोलगढ़ गांव में रह रहे थे। उन्हें रीवा नरेश और उनके परिवार की इस दयनीय दशा का समाचार मिला। उन्होंने अपने चारों पुत्रों (हिम्मताराय, साहेबराय, चिन्तामणिाराय और हिमंचालशाह) पौत्र तथा अन्य साथियों को स्थिति का अध्ययन करके राज्य की रक्षा का प्रयत्न करने के लिए रीवा भेजा। उन्होंने स्थिति का अध्ययन किया और अचानक छापा मारकर किले पर अधिकार करने का निर्णय किया। यह घटना सन 1703 की है।

इन वीरों की 46 आदमियों की एक टुकड़ी सूर्योदय से पहले कुठुलिया की ओर से बिछिया नदी पार करके महामृत्युंजय महादेव मंदिर के पास के दरवाजे से किले में घुसी और बुंदेले सैनिकों पर जिनकी संख्या एक हजार के लगभग थी, टूट पड़ी, भीषण युद्ध हुआ। पर अंत में बुंदेले सैनिकों के पैर उखड़ गए। वे लड़ते हुए किले के बाहर निकल आये और वर्तमान घोघर मोहल्ले वाले मार्ग से चले। बीहड़ नदी के किनारे वर्तमान लाल भारत शरण सिंह आदि के मकान के पीछे के मैदान में फिर से घमासान युद्ध हुआ। जिसमें आये सभी कलचुरि वीर गति को प्राप्त हुए और बुंदेले सैनिक रीवा छोड़कर प्रत्यावर्तन कर गए।

इस युद्ध में साहेबराय के बड़े पुत्र मर्दनशाह जो एक दिन पहले ही विवाह करकर लौटे थे, किले के वर्तमान उत्तर दरवाजे के भीतर वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनकी स्मृति में बानी छतरी अब भी इस फाटक के भीतर दाहिनी ओर विद्यमान है। यह उल्लेखनीय है कि किले के भीतर यही एक छतरी है, बाकी वीरों में से हिम्मतराय, साहेबराय और चिन्तामणिराय कि छतरियां घोघर मुहल्ले में वर्तमान विवेकानंद मार्ग के दाहिनी ओर कालिंदी प्रसाद ज्योतिषी के घर के निकट बनी हुई हैं।

बुंदेलों को खदेड़कर साहेबराय के पुत्र सुमेशशाह राजकुमार अवधूत सिंह और राजमाता को प्रतापगढ़ से लाये और पुनः गद्दी पर बिठाया। साहेबराय और उनके साथी बड़े उच्चकोटि के वीर थे। साहेबराय कि अच्युत

वीर वृत्ति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी मृत्यु के समय उनके शरीर में 72 घाव लगे थे।

तत्कालीन शासन ने इन वीरों की बलिदान की स्वीकृत के रूप में उनके वंशजों का बड़ा सम्मान किया और मानदेय के रूप में उनके रहने के लिए जोन्ही, रायपुर, खुज और डिहिया के गांव दिए तथा राज्य की तत्कालीन स्थिति के अनुसार जागीरें भी प्रदान की। इस प्रकार चार शताब्दियों के पश्चात कलचुरि एक बार पुनः विंध्य क्षेत्र में पहुंचे। यद्यपि इस बार ये शासन के रूप में नहीं, बल्कि आश्रय की खोज में भटकते हुए वीर सैनिक के रूप में आये। परन्तु अपनी वीरता की छाप जमाकर राज्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया।

#### **सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-**

1. पंडित गया प्रसाद त्रिपाठी –ग्राम रायपुर (रीवा से प्राप्त हस्तलिपि , परिशिष्ट प्रथम
2. डॉ. वा. वि. मिराशी, कलचुरि नरेश और उनका काल, पृष्ठ 13 , 18
3. गुरु रामायार अग्निहोत्री –रीवा राज्य का इतिहास, पृष्ठ 30
4. पंडित गया प्रसाद त्रिपाठी –ग्राम रायपुर (रीवा) से प्राप्त हस्तलेख , सरस्वती मासिक पत्रिका के तत्कालीन अंक में प्रकाशित (परिशिष्ट खसटम )
5. गुरु रामायार अग्निहोत्री –रीवा राज्य का इतिहास , पृष्ठ 65

\*\*\*\*\*

## हिंदी कविता के विकास में दलितों और गैर- दलितों की भूमिका

**कल्पना शेवाळे \***

**प्रस्तावना** - हिंदी दलित कविता का मूल स्वर वर्ण व्यवस्था से पीड़ित समुदाय की वेदना है। जिसका तेवर कविता आंदोलन की चेतना के स्तर पर बहुत गहराई से जुड़ा है, जिसकी जड़ में सदियों से अन्याय, अत्याचार और शोषण का इतिहास है। इसलिए हिंदी की दलित कविता समय के दौर में दलित आंदोलन को स्थायित्व प्रदान करनेवाली कविता है। यह वर्ण व्यवस्था के सामाजिक, संस्कृति एवं राजनीतिक वर्चस्व के खिलाफ प्रतिशोधात्मक रूप में अपना नया मोर्चा निर्मित करती है। यह सदियों की यातना है जो आक्रोश एवं विद्रोह के रूप में फूट रही है। दलित कविता अपने यातनाओं के अतीत के साथ अपने समसामयिक जीवन और परिवेश के साथ गहराई से जुड़ी है। जिससे उसकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है। आए दिन होने वाले अत्याचारों, जुल्मों को वह बखूबी से पेश करती है। भक्ति काल में संतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही जो दलित थे। भक्ति आंदोलन में निम्न जातियों के संतों और कवियों द्वारा चलाया गया आंदोलन था। जिसका मुख्य स्वर जातिवाद-विरोध और अपनी अस्मिता की छटपटाहट थी। यह कहना गलत ना होगा कि भक्ति काल के संत कवियों ने अपनी रचना के माध्यम से तथाकथित दलितों में जागृति लाने का प्रयास किया। भले ही इन की वाणी में भक्ति का स्वर प्रधान रहा हो, लेकिन उसके साथ ही जाति व्यवस्था को तोड़ने का अनुरोध और समानता का भाव भी रहा है। इन संतों को हिंदी समाज में पर्याप्त सम्मान मिला। हिंदी साहित्य इतिहास में भी इन्हें गर्व के साथ मरण किया जाता है। तुलसीदास भी इस चेतना से सम्पृक्त दिखाई देते हैं। निषाद के गले मिलना, नारी-उद्धार तथा समाज से उपेक्षितों-तिरस्कृतों की सेना द्वारा राम की विजय इनमें स्वाभिमान-आत्मसम्मान का भाव तो जागृत करता ही है, साथ ही इन्हें मानव-समानता का संदेश भी दे जाता है।

भक्तिकाल के बाद का काल दलित लेखन के लिए शून्य ही कहलाएगा। 14 वीं सदी में कविराज का ही उल्लेख प्राप्त होता है। डॉ. एन. सिंह ने रैदास को दलित कविता का आदि कवि कहा है, इस संदर्भ में उनके विचार दृष्टव्य हैं। - 'रैदास पहले दलित कवि ही नहीं हैं, वह दलित चेतना के प्रथम कवि भी हैं।' डॉ. प्रेमशंकर ने राहुल जी का हवाला देते हुए कहा है- 'चौरासी तीस शुद्ध कवि थे जो अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा जाति व्यवस्था एवं संस्कृति के विरोध में संघर्षरत थे। यह तीस सिद्ध कवी इस प्रकार है- ककालिया, मनिपा, चमरिपा, खड़गपा, घगनपा, शांतिपा, छत्रपा, तंतपा, कुचिपा, महिपा आदि। इन शुद्ध सिद्ध कवियों ने अपने इस संघर्ष के द्वारा साधनात्मक एवं सांस्कृतिक रूप से निम्न-जातियों के परवर्तीकाल के लिए एक ठोस जमीन तैयार की थी।' आधुनिक युग में दलितों का चित्रण करने वाली रचना कुछ अंश में प्राप्त होती है। इसी क्रम में महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में निकलने वाली पत्रिका 'सरस्वती' में 1914 में हीरा डोम की कविता 'अछूत की शिकायत' छपी थी, जो मूलतः भोजपुरी बोली में थी, जो विषमता परक

समाज पर चोट भी करती है। जिसे हिंदी की पहली दलित कविता माना जा सकता है। हिंदी नवजागरण के समय प्रेमचंद, निराला, राहुल सांकृत्यायन ऐसे साहित्यकार हुए हैं, जिन्होंने अपने लेखन और चिंतन में हिंदी क्षेत्र की दलित समस्या को चित्रित करने की कोशिश की है। लेकिन उसे हम सहानुभूति का ही साहित्य मानते हैं। विमल थोरात लिखती है की- 'दलित कविता व्यक्तिगत अनुभवों से सम्पृक्त होने के साथ ही समूह-मन के अनुभवों की अनुभूति भी है।'<sup>3</sup>

आज दलित कविता का साहित्य के क्षेत्र में लेखन, पठन-पाठन प्रचुर मात्रा में हो रहा है। इन दलित कवियों तथा गैर-दलित कवियों ने अपनी कविताओं में परंपरागत रूप से चली आई वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, हिंदुओं के धार्मिक कर्मकांड, दलितों और सवर्णों के बीच की असमानता के प्रति दलित तथा गैर-दलित कवि आक्रोश व्यक्त करता है। इनकी कविताओं में दलितों का उत्पीड़न सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक और इस व्यवस्था के प्रति खुला विद्रोह व्यक्त हो रहा है। आम आदमी की समस्याओं को लेकर दलित वर्ग के द्वारा अभी तक बहुत कम लेखन हुआ है पर अब दलित वर्ग की व्यथाओं एवं समस्याओं का कथ्य बनाकर प्रचुर मात्रा में कविताएं लिखी जा रही हैं। दलित कविताओं में जहां तक एक ओर व्यवस्था के प्रति आक्रोश दिखाई देता है वहीं दूसरी ओर व्यवस्था को बदलने के लिए दलित कवि आह्वान करता है और उसी के लिए संघर्षरत है।

दलितों की दशा पर ध्यान केंद्रित करने वाले कवियों में नाथूराम शंकर, रूपनारायण पांडेय, रामचंद्र शुक्ल, मैथिलीशरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, भगवती शरण वर्मा, सियारामशरण गुप्त, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' तथा माखनलाल चतुर्वेदी आदि अनेक कवियों तथा लेखकों ने दलितों पर रचनाएं की हैं। छायावादी तथा प्रगतिवाद के दौर में निराला, पंत, महादेवी वर्मा, दिनकर आदि की रचनाओं में दलित भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। इसी दौर में प्रेमचंद, यशपाल, अमृतलाल नागर, भैरव प्रसाद गुप्त आदि ने दलित जीवन को केंद्र में रखकर रचनाएं की हैं। दलित चेतना वर्ण और जाति व्यवस्था और तदनुगत मान्यताओं के विरोध की बात करती है। और मानती है कि गैर-दलित चाहे कितने भी प्रगतिशील हो, उनमें दलितों के भोगे हुए यथार्थ की पीड़ा और अनुभूति की प्रामाणिकता नहीं आ सकती। ऐसे में बुद्ध और महावीर जो स्पष्टतः गैर-दलित (क्षत्रिय) थे। इन्हें तो दलित चेतना अपना मसीहा मान लेती है, पर गांधी को नहीं। गांधीजी को गुजरात की परंपरा में भले ही सवर्ण मान लिया जाए, किंतु भारतीय वर्ण व्यवस्था उन्हें वैश्य ही मानती आयी है। जाहिर है, वैश्य की सहानुभूति दलितों के प्रति उच्च शीर्ष पर विराजमान ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णों की अपेक्षा अधिक रही है। फिर क्या कारण है कि गांधी दलित-विरोध के मुख्य टारगेट है, पर बुद्ध दलितों के बड़े

मसीहा?

यदि अनुभूति और भोगे हुए यथार्थ की बात की जाए, तो महावीर और बुद्ध तो राज परिवार से आते थे। उनके पास कौन-सी भोगी हुई पीड़ा का यथार्थ और अनुभूति की प्रामाणिकता की? उन्होंने तो केवल दृष्ट की सहानुभूति को लेकर ही इतना बड़ा परिवर्तन कर डाला। इसके विपरीत गांधी ने श्वेतों द्वारा अश्वेत भावना की त्रासद पीड़ा और प्रताड़ना दी थी और 'रंगभेद' तथा छुआछूत के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चलाया था। फिर गांधी के प्रति दलितों की टेढ़ी दृष्टि का कारण क्या है? ऐसे सहानुभूति और स्वानुभूति का सवाल बेमानी-सा लगता है। स्वतंत्रता पूर्व काल में कई दलित साहित्यकारों ने भी दलित साहित्य को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया, जिनमें बिहारी लाल हरित, बुद्ध संघ प्रेमी, जैसराम गौतम, चंद्रिका प्रसाद, गया प्रसाद प्रशांत, स्वामी बोधानंद, बदलूराम, संत रामन्यायी, गोकर्ण लाल, नंदलाल जैसव, छेदीलाल साथी आदि ने काव्य के साथ-साथ अन्य विधाओं में भी दलित साहित्य लिखा।

स्वतंत्र भारत में कई प्रगतिवादी कवियों की रचनाओं में दलित भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। इनमें बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' कि 'झूठे पत्तोय, रांगेय राघव की 'अजेय खंडहर', शिवमंगल सिंह सुमन की 'प्रलय सृजन', नरेंद्र शर्मा की 'रोटियों की जंजीर', रामेश्वर शुक्ल 'अंचल की मंजिल', रामविलास शर्मा की 'सदियों के सोये जाग उठे' और नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, धूमिल आदि की तमाम ऐसी कविताएँ हैं, जिनमें दलित मुक्ति के लिए क्रांतिकारी स्वर गुंजरित हुए हैं। नागार्जुन की 'हरिजन गाथा' और धूमिल की 'मोचीराम' तो इस धारा की बहुचर्चित कविताएँ हैं। स्वाधीनता काल में प्रबंध कविता में भी दलित व परंपरा के इतिहास प्रसिद्ध गायक-नायिकाओं को लेकर खंडकाव्य तथा महाकाव्य का सृजन हुआ है। आलोच्य युगीन दलित अस्मिता के प्रतीकों 'बुद्ध', 'एकलव्य', 'शंबूक', 'शबरी', 'बिरसा', 'मुंडा' एवं डॉ. अंबेडकर को विषय बनाकर अनेक रचनाएँ हुईं। इनमें रामकुमार वर्मा का 'एकलव्य' दिनकर का 'रश्मिरेखी', जगदीश गुप्त तथा नरेश मेहता कृत 'शबरी', बिहारीलाल हरित का 'भ्रिमायण', गोकर्ण लाल, वरुण कर एवं माता प्रसाद सागर का 'भीमरचित मानस' आदि उल्लेखनीय हैं। स्वयं दलितों द्वारा पिछले दो दशकों में जो रचनाएँ रची गई हैं उनमें आक्रोश के स्वर प्रबल हैं। इन कवियों में- ओमप्रकाश वाल्मीकि, प्रेम शंकर, सोहनपाल, सुमनाक्षर, सुशीला टाकभौर, लालचंद राही, पुरुषोत्तम, सत्यप्रेमी, कालीचरण स्नेही, कंवल भारती, श्याम सिंह शशि, जयप्रकाश कर्दम, माता प्रसाद, बिहारी लाल हरित, लक्ष्मी नारायण सुधाकर, माखनलाल सिंह, बुद्ध संघ प्रेमी, नैमिशराय, डॉ. दयानंद बटोही, श्यौराज सिंह बेचौन, डॉ. कुसुम वियोगी, पारसनाथ, बिहारी, डॉ. शांति यादव, ओमप्रकाश मेहरा, गौरी शंकर नाग दंश, सुदेश तनवर, चिरंजीलाल कटारिया, सूरजपाल चौहान, बाबूलाल मधुकर, असंगघोष, हरि कृष्ण संतोषी, रणजीत सिंह, विनोद कुमार उइके, श्याम लाल शर्मा, शत्रुघ्न कुमार, हेमलता महेश्वर, बुद्ध शरण हंस, गुरु प्रसाद मदन आदि ने अनेक दलित कविताएँ लिखी हैं। विषय चौधरी 'देव', पवन करण, मोहन सगोरिया, असंग घोष, बाबूलाल दाहिया, संगीता नौटियाल, पारसनाथ, राकेश प्रियदर्शी आदि दलित साहित्य में बीसियों कवि चर्चित और सक्रिय हैं।

आधुनिक दलित कविताओं के स्वर और उनकी संवेदनाएँ इतनी मारक, सीधी और आम जीवन के निकट हैं कि उनकी अर्थ-व्यंजना में सामान्य से सामान्य पाठक को भी कोई कठिनाई नहीं होती। इनके विषय दलित जीवन

की त्रासदी, छुआछूत, दलित बोध, अपमान, जाति और वर्ण व्यवस्था की विसंगतियाँ, दलितों का गांवों से शहर की ओर पलायन, धर्मांतरण, भूख, गरीबी, उदासी, पीड़ा, आक्रोश, समाज व्यवस्था और परिवर्तन आदि की अभिव्यंजना है। यहां पर हम कुछ गिने-चुने चर्चित कविताओं को ही शामिल कर रहे हैं। दलित कविता की आक्रोशपूर्ण और विरोध जनित भाषिक अभिव्यंजना अर्थपूर्ण है। सामाजिक संदर्भों से जुड़कर वह अपनी अभिव्यक्ति में एक आंदोलन का आह्वान करती है। उदाहरण के लिए- 'चुनौती' शीर्षक दलित कविता में छिपी वेदना को देखा जा सकता है-

'हमारी भागीदारी के लिए योग्यता की शर्त कब तक फेंकोगे तुम अपना मकड़जाल हम पर ? '

सूरजपाल चौहान की कविता दलित जीवन की संवेदनाओं को मार्मिक अभिव्यंजना देते हैं। जिसे हम कविता की पंक्तियों से जान सकते हैं। दलित जीवन के संपूर्ण यथार्थ और नियति-प्रकृति को समेट लिया गया है- गांव में मैं होता हूँ दलित समाज के विभिन्न रूपों में टुकड़े-टुकड़े अलग-थलग शहरों में हम होते हैं सिर्फ हम 'शेड्यूल कास्ट' धन्यवाद शहर, तुमने-मुझे मैं से हम बनाया।<sup>15</sup> धन्यवाद शहर : सूरजपाल चौहान सदियों से सामाजिक व प्रपंचों को झेलने के कारण दलित कवि का स्वर कटु हो गया है। यहां मुक्ति की छटपटाहट अभिव्यंजित हुई है। दलित कविता 'मैं' ही 'हम' हैं, जिसमें समस्त दलित समाज की पीड़ा ध्वनित होती है। दलित साहित्य में मिथकों की भी पर्याप्त योजना दिखाई पड़ती है। यहाँ पौराणिक मिथकों की पुनर्वाख्या हुई है। जन्म-मरण के मिथक, प्रलय और सृजन के मिथक, देव और दानव के मिथक, शम्भूक, कर्ण, एकलव्य, सीता, द्रौपदी, राम कथा, कृष्ण कथा आदि सभी के मिथक दलित साहित्य के नए संदर्भ और अर्थ पाते हैं। यहां कर्ण, एकलव्य और शम्भूक जैसे वंचित-प्रवंचित पौराणिक पात्र नायक और महानायक के रूप में चित्रित हुए हैं। दयानंद बटोही की कविता 'द्रोणाचार्य सुनेय में व्यक्त विरोध और विद्रोह के स्वर को द्रोणाचार्य और एकलव्य के मिथक द्वारा बड़ी ही मार्मिकता के साथ व्यक्त किया गया है। यहां कवि एकलव्य की पीड़ा को अतीत से लेकर वर्तमान तक अविच्छिन्न परंपरा के रूप में देखता है- 'अंधेरे की गहन गुफा को 'घाव सहने दो' जाओ द्रोण जाओ दर्द को हरिया ने दो। एकलव्य मैं पहले था। आज भी हूँ। अब जान गया हूँ। अंगूठा दान क्यों मांगते हो ?'<sup>16</sup> द्रोणाचार्य सुने, उसकी परंपराएं सुने: दयानंद बटोही आधुनिक दलित कविता में विद्रोह आक्रोश का स्वर सर्वप्रथम मराठी दलित कविता से प्रस्फुटित होता है। जिसका प्रभाव भारत के सभी भाषा के साहित्य पर पड़ता है। मराठी के कवि किशन फागु को इस व्यवस्था के प्रति घृणा है। क्योंकि सवर्णों ने उन्हें कभी भी मनुष्य के रूप में नहीं स्वीकारा अछूत कहकर शिक्षा-दीक्षा से वंचित रखा इसलिए अपनी कविता में कहते हैं-

'है हरि मुझे पशु भले बना दे

महार मत बनाना

क्योंकि महार को अस्पृश्य बनाकर  
वंचित किया जाता है शिक्षित होने से।

इसलिए पशु योनि में

जन्म दे मुझे।'<sup>17</sup>

इस तरह आधुनिक दलित कविताओं का तेवर उत्तेजनापूर्ण दिखाई देता है। अपने समाज ने आज तक जो जीवन जिया है, जिन रीति-रिवाजों को निभाते रहे हैं इन सबका तिरस्कार करते हुए कवी कहते हैं-

'जूठन पर बनने वाले मेरे भाई



धिक्कार है तुम्हें  
जो सह रहे हो यह नारकीय जीवन  
मैं थूकता हूँ  
तुम्हारे मुँह पर।<sup>8</sup>

इस तरह आधुनिक दलित कविताओं का तेवर उत्तेजना पूर्ण दिखाई देता है। ओमप्रकाश वाल्मीकि भी अनादि काल से यातना भोगते समाज को देखकर तिलमिला उठते हैं- जैसे-

‘जब भी देखता हूँ मैं  
झाड़ू या गंदगी से भरी बाल्टी- कनस्तर  
इसी हाथ में मेरी रगों में  
दहकने लगते हैं  
यातनाओं के कई हजार वर्ष एक साथ  
आंखों में उतर आता है  
इतिहास का स्याहपन  
अपनी आत्मघाती कुटिलताओं के साथ।’<sup>9</sup>

बरस ! बहुत हो चुका- ओमप्रकाश वाल्मीकि  
‘शब्द ही तो थे  
जो मनुस्मृति में लिखे गए  
राम राज चला गया  
पर शम्भूक की चीख अभी बाकी है  
जैसे दलितों की पीठ पर  
चोट के निशान  
शब्द सिसकते नहीं बोलते हैं  
चोट कहते हैं  
जैसे दलित से हरिजन  
और हरिजन से दलित’<sup>10</sup>

मोहनदास नेमिशराय ‘शब्द’ समाज में चेतना जगाने का काम अनेक कवियों ने किया है, जिसकी कड़ी में नरेश चंद्र सचान की एक रचना देखिए-

‘कब तक झुके रहोगे, सीधी कमान हो ।  
डर कर फेंक दो, असमता के बापा को ।।  
टूट जाये घेरा, शोषकों की भीड़ का ।  
छूट जाए पक्षी, बंदी स्वयं नीड़ का ।।  
नीति शोषकों की है, आ रही है, आइ आ रही है ।  
शोषितों उठो तुम्हें जागरूकता बुला रही।’<sup>11</sup>

दलितों ने केवल अपनी पीड़ा, त्रासदी को ही अपने साहित्य में अभिव्यक्त नहीं किया अपितु कुछ संकल्प भी किया दिखाई देता है। दलित कवि भजनलाल मानवता के कृत्रिम विभाजन को धर्म संगत मानने से इनकार करते हुए लिखते हैं-

‘जाति के आधार पर ऊँचा और नीचा,  
यह धर्म नहीं, अधर्म है, तुमने कभी सोचा?  
इस धर्म के पाखंडता, हम जड़ से मिटायेंगे।’<sup>12</sup>

‘सुलक्षण व्यथित’ की एक रचना में जो महाजनी सभ्यता के दुष्परिणाम अर्थसत्ता की अनुदारता लोकतंत्र की अव्यवस्था बखूबी देखी जा सकती है- ‘भारत का लोकतंत्र, शोषण का ओढ़कर असंवैधानिक सेज पर, सुहागरात मना रहा है नेताजी ने लूट की, दुल्हन के हाथ पीले किए सेठ जी ने तिजोरी के नोट गीले किए।’<sup>13</sup> दलित कविता में निराशा और हताशा ही नहीं अपितु आशा और उत्साह के पात्र भी मिलते हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति और

उन में दलित लड़कियों की स्थिति और उनमें दलित लड़कियों की स्थिति बहुत भयावह है। क्योंकि दलित समाज को निरंतर आर्थिक अभाव का सामना करना पड़ता है और समाज में फैली दहेज प्रथा जैसी बीमारी के कारण दलितों की लड़कियों का विवाह होना मुश्किल होता है। ऐसी अनेक समस्याओं के कारण लड़की की उम्र बढ़ने लगती है। उसकी आंखों में एक तरह की दहशत निर्माण होती है। उसके साथ कोई शादी नहीं करता इसलिए उसके सपने आंखों में ही रह जाते हैं। ऐसे दलित लड़कियों के जीवन का जीवंत दस्तावेज ओमप्रकाश वाल्मीकि की कविताओं में दिखाई देता है।

उनकी ‘कच्ची मुंडेर’ पर कविता का भाव कुछ इस प्रकार है-

‘कबूतर की तरह बैठी लड़की  
सपनों भरी आंखों में  
बुनती है दहशत  
हथेली की ओट से  
ताकता है दूर जाते  
पाहुने को  
बूढ़े दिनों का प्रलाप।’<sup>14</sup>

बरस ! बहुत हो चुका-ओमप्रकाश वाल्मीकि आधुनिक दलित कविता धारा मराठी से निर्मित होकर जिसका प्रभाव सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि दलित कविता की धारा प्राचीन काल से ही प्रतिक्रिया के रूप में सिद्ध और नाथ कवियों के रूप में प्रस्फुटित होती रही है। जिसने निरंतर इस वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है। आगे चलकर आधुनिक काल में भी हिंदी के साहित्यकारों ने दलितों के संबंधित रचनाएं की हैं। पर वह गहराई इनकी काव्य रचनाओं में दिखाई नहीं देती और न ही इनकी कविताएं दलितों के जीवन को पूरी तरह से अभिव्यक्त करती हैं।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दर्द के दस्तावेज- डॉ. एन. सिंह, पृष्ठ-4, आनंद साहित्य सदन, 1992
2. युद्धरत आम आदमी, दलित चेतना कविता विशेषांक-31, पृष्ठ-184
3. मराठी दलित कविता और साठोत्तरी हिंदी कविता में सामाजिक और राजनीतिक चेतना:-विमल धोरात, पृष्ठ-142, हिंदी बुक सेंटर, नई दिल्ली
4. सिसकता आत्म सम्मान : डॉ. सी.बी. भारती, युद्धरत आम आदमी, पृष्ठ-83, अंक-31, जुलाई-सितंबर-1995
5. धन्यवाद शहर : सूरजपाल चौहान, पृष्ठ-354, दलित साहित्य (वार्षिकी), 2005
6. द्रोणाचार्य सुने, उसकी परंपराएं सुने: दयानंद बटोही, युद्धरत आम आदमी, पृष्ठ-93, अंक-31, जुलाई-सितंबर, 1995
7. हिंदी काव्य में दलित काव्य धारा- संपा माता प्रसाद, पृष्ठ-240
8. हिंदी काव्य में दलित काव्य धारा- संपा माता प्रसाद, पृष्ठ-240
9. बरस ! बहुत हो चुका- ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृष्ठ-79-80 वाणी प्रकाशन, 1997
10. दलित साहित्य का समाजशास्त्र-हरिनारायण ठाकुर, पृष्ठ-411, जनपथ संस्थान, 2009
11. निर्णायक भीम मासिक- शंकन रामशास्त्री पृष्ठ-14
12. निर्णायक भीम मासिक-भजनलाल, पृष्ठ-80-16
13. सुखद पत्रिका-श्यामराज सिंह बैचन-16 मई, 1982
14. बरस ! बहुत हो चुका-ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृष्ठ-25, वाणी प्रकाशन, 1997

## Violation of Right of Privacy in COVID 19 Pandemic Scenario

Mr. Bijay Kumar Yadav\* Dr. Gurpreet Singh\*\*

**Introduction** - In March 2020, the World Health Organization declared COVID-19 a pandemic. This has caused employers around the world to take measures to protect and screen their employees and business contacts. These measures include checking employees' temperatures, obtaining their health and travel data, collecting medical certificates, etc. Indian Privacy Laws do not provide an exemption on privacy practices during emergencies. So far, no special dispensation or exemption has been issued by the government either. As such, even during this time, compliance with Indian Privacy Laws remains mandatory. Medical data is quite clearly SPDI. If an employee/ consultant/ other business contact informs you that they are unwell, and provides you any data, be mindful to not publish their identity and health records. Disclosures of SPDI may be unlawful if you don't have specific consent. In the past, Indian courts have also recognised that persons with diseases, victims of sexual assault, etc. have the right to keep their identity confidential.

Article 31B says that any acts and regulations included in the Ninth Schedule of the constitution by the Parliament **can** override the **fundamental rights** and such laws cannot be repealed or made void by the judiciary on the grounds of violating **fundamental rights**. **Fundamentals rights** such as **right to life and equality** and freedom of speech enshrined under the Constitution are **enforceable against** the State and its instrumentalities and the **private** parties, performing state actions, have been taking the plea that they cannot be held accountable for breach of such **rights**. The **right to privacy** is protected as an intrinsic part of the **right to life and personal liberty** under Article 21 and as a part of the freedoms guaranteed by Part III of the Constitution. The **right to privacy** in **India** has developed through a series of decisions over the past 60 years. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law, nor shall any person be denied equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

As India progresses through its 'unlock' phases, we can expect to see a proliferation of digital technologies to

contain the novel coronavirus's spread. In these efforts, conserving patient privacy would be critical. The **right to privacy** refers to the concept that one's personal information is protected from public scrutiny. U.S. Justice Louis Brandeis called it "the **right** to be left alone." While not explicitly stated in the U.S. Constitution, some amendments provide some protections.

However, many government bodies in India have somewhat deprioritised this issue; some state governments even mandate selfies and facial recognition. Other countries have performed these same functions in a way that preserves the users' privacy, using de-identified, aggregated data and without exporting data from the users' phones.

We live in a WhatsApp-friendly housing society, chances are you know who the COVID-19 patients near you are. Residents' welfare associations often play fast and loose with patient data, just like quite a few public institutions. The Kerala government has been relatively more conscientious; it released its third notification regarding handling personally identifiable information recently. However, even it made a few missteps at first.

In similar ways and others, people suspected to have COVID-19 as well as those who have tested positive have often been stigmatized and been subject to harassment. There are many situations where the preservation of patient identity is impossible and unadvised. For example, courts have ruled in favour of limiting the right to privacy of an HIV patient if the patient posed a risk of transmission to their spouse-to-be. However the nature of personal information that needs to be shared should be carefully considered.

People whose health status, identities and location are publicly exposed are at greater risk of stigma and discrimination, which can have detrimental effects on their private and family lives and social and professional situations. Tracking without violating the right to privacy *is* possible. There are currently genuine efforts underway by scientists, health authorities, tech companies and civil societies to build privacy-preserving solutions for managing the pandemic.

This is an open protocol application of COVID-19 proximity tracing, which will use Bluetooth Low Energy

\*Research Scholar (Law) Tania University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

\*\* Research Supervisor (Law) Tania University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

functionality on mobile devices to ensure personal data stays entirely on an individual's phone. **Estonia, Austria, and Switzerland** have already announced they will only adopt a de-centralized approach using this protocol.

Right to privacy, including data protection, is a fundamental human right, articulated in major international human rights instruments.

We must ensure that a health crisis of this magnitude is not used as a pretext for mass surveillance and violation of privacy, especially when less intrusive alternatives do exist. At the same time, it's important to continue support to citizen's voices and strengthen rule of law and checks and balances systems in the countries. Such measures can ensure the legitimate, necessary, proportionate, and non-discriminatory use of surveillance powers by governments, in exceptional circumstances such as COVID-19 pandemic.

*UNDP offices across the world have quickly responded to requests for support from Member States to assist in containing the spread of Covid-19. As part of this work, UNDP guides national counterparts in addressing privacy, data protection and broader human rights issues they are encountering while using digital technologies to combat COVID-19.*

In 2012, Justice K.S. Puttaswamy (Retired) filed a petition in the Supreme Court challenging the constitutionality of Aadhaar on the grounds that it violates the **right to privacy**. During the hearings, the Central government opposed the classification of **privacy** as a fundamental **right**

Recently, the Ministry of Home Affairs revised the guidelines from mandating everyone to use the Aarogya Setu app to asking employers to ensure employees use it on a 'best effort basis'. In India, there are no such standard operating procedures. Both states and the Centre have been operating with little legislative backing. The Aarogya Setu app's privacy policy mentions that data will only be shared with 'the government' but doesn't say which departments – nor is there a clearly defined purpose. The app assists with self-assessment, contact tracing, health messaging and with obtaining E-passes. There is little explanation for why data will be stored for a certain amount of time. For example, the data of people with COVID-19 will be stored for 60 days. Some expert have argued .it should just be 21 days.

While the Personal Data Protection Bill is still being tabled in parliament, interpreting the existing set of laws to determine the proper course of action is very involved. The IT Act 2000 now includes rules for sensitive personal data or information, and punishes those who disclose information

without the information provider's consent. Physical, physiological and mental health conditions, and medical records and history are classified as SPDI.

The Supreme Court's 2017 judgement, that privacy is a fundamental right, set out four tests – legality, necessity or legitimacy, proportionality and procedural safeguards – that the government must pass if it wants to infringe on privacy. The problem is that multiple states have used the Disaster Management Act 2005 to frame their COVID-19 response. The Act gives states considerable flexibility to act "as it may consider necessary" (Section 6(2) (i)). Not that the PDP Bill promises to be much better, with its broad exceptions ("... in the interest of sovereignty and integrity of India, the security of the State..."). This allows personal data to be processed without consent for, among other things, responding "to any medical emergency involving a threat to life".

States and the Centre must also process personal information with statutory backing such as ordinances. Such laws must respect the principles of data protection, such as minimalistic collection, purpose limitation, access limitation, limited secondary use, safeguards, sunset clauses and third-party audits. Transparency is desirable in and of itself – but it's also useful to receive the trust and participation of citizens and civil society.

A person has the right to determine what sort of information about them is collected and how that information is used. In the marketplace, the FTC enforces this right through laws intended to prevent deceptive practices and unfair competition.

The Privacy Act of 1974 prevents unauthorized disclosure of personal information held by the federal government. A person has the right to review their own personal information, ask for corrections and be informed of any disclosures.

The Financial Monetization Act of 1999 requires financial institutions to provide customers with a privacy policy that explains what kind of information is being collected and how it is being used. Financial institutions are also required to have safeguards that protect the information they collect from customers.

The Fair Credit Reporting Act protects personal financial information collected by credit reporting agencies. The act puts limits on who can access such information and requires agencies to have simple processes by which consumers can get their information, review it and make corrections.

#### Reference:-

1. Personal Research.

# Media Vehicle Preference, Likings and Influence on Purchase and Loyalty of Customers : A Study of the Urban Gujarats Customers of E-Retail Market

Dr. Himanshu Vaidya\* Ayushi V Sutaria\*\*

**Abstract** - The examination creates and experimentally tests a model for finding the inclination about different media vehicle of the clients of E – retailing in metropolitan Gujarat .media vehicle alludes to explicit techniques for media utilized by online retailers to convey promotions or mission message to the intended interest group. Each media vehicle has own qualities and shortcoming. In this examination media vehicle, for example, print, television, radio, email, online media and occasions are mulled over for the investigation. The point of the investigation is to recognize the clients' inclination about media vehicle through which they need to get promotions or missions .the review strategy was utilized as the exploration technique. Poll was utilized to accumulate the data from respondents in Ahmedabad , Vadodara , Surat, and Rajkot in Gujarat. Bunch inspecting was utilized to choose an example size 400 and gathered information was the SPSS. T-test examination way set up the idea of the connection between media vehicle (Print, TV, Radio, E-mail, occasions) and client inclination.

**Key Words** - Media vehicle, preference, likings, influence, purchase, loyalty.

**Introduction** - Media arranging and media determination are progressively getting intricate because of innovation headways. Principle factors which can impact media determination are item type , target gathering , kind of mission , spending accessibility of media space. Media vehicle alludes to explicit strategies for media utilized by sponsors to convey publicizing message to the intended interest group .media vehicle takes you to your objective clients. Media vehicles include regular, new age media yet additionally pledges .the part of any media could be to convey brand message , make brand relationship , continue brand relationship , fortify brand relationship and interface organizations with clients. Message conveyance is just the initial phase in associating as it makes the way for contact a client in a significant manner with brand message .each media channel and media vehicle with their scope and viewership have a huge task to carry out. Right blend of vehicles guarantees meeting the promoting and media destinations eg, print – creates mindfulness and support , TV-fabricate mindfulness and influence, radio – is appropriate as an update medium, occasions – building introductory mindfulness during item dispatches, email – it help you to draw in with clients . promoting would thus be able to become compelling when reasonable media is utilized to convey the message . once , media researcher Marshall McLuhan has said “the medium is the message “. What he implied was that medium or way, through which

the message is communicated, individuals see media from their eyes and join hugeness dependent on their life and height. In this way their feelings , sentiments data gathering is joined to essentialness they provide for particular media .Each media has own qualities and shortcoming . distinctive media accessible to publicists are communicated media like TV, Radio, Print, E-sends, Social media , occasions and so forth In a nation like India the different media vehicle accessible for promoting falls into various classifications , in this examination we are stressing on print, television, radio , mail , web-based media and occasion vehicle of media for crusade . tell us about these various mediums to sum things up .

**1. Print as a media vehicle for brand campaign** - Print media publicizing is a type of promoting that utilizes actually printed media, for example, magazines and papers, to arrive at buyers, business clients and possibilities. Sponsors can look over a wide scope of various sorts of papers, including neighborhood, provincial or public titles distributed in day by day, night, week by week or Sunday versions. Papers target various readerships with a blend of substance, frequently including sports, diversion, business, design and governmental issues notwithstanding neighborhood, public or world news. Sponsors can purchase various sizes of promoting space, from little arranged advertisements with text just, to show advertisements highlighting text, photos, outlines and designs in sizes up to a full page or even a

\*Research Guide & Associate Professor, Rai University, Ahmedabad (Gujarat) INDIA

\*\* Research Scholar, Rai University, Ahmedabad (Gujarat) INDIA



twofold page spread. Magazines offer sponsors broad decisions of readership and recurrence. Purchaser magazines cover a wide scope of interests, including sport, pastimes, style, wellbeing, current issues and neighborhood points. Numerous business and exchange magazines give inclusion of explicit ventures, for example, money or hardware. Others cover cross-industry subjects, for example, interchanges or HR, while still others center around work explicit zones, for example, distributions for heads, promoting experts or specialists. Distributing recurrence is regularly week after week, month to month or quarterly. Similarly as with papers, sponsors can take publicizing spaces from arranged promotions to full page advertisements clearly or colour. Advertising on boards and banners offers sponsors the chance to arrive at customers progressing. Placing banners in retail shopping centers, for instance, assists publicists with arriving at buyers near the purpose of procurement. Banners or bulletins in train stations, air terminals or occupied town habitats can possibly arrive at huge gatherings of purchasers. Publicists can change the messages on announcements and banners at a recurrence of their decision.

**2. Television advertising** - TV promoting offers the advantage of arriving at enormous numbers in a solitary presentation. The purpose behind having enormous numbers is that this publicizing technique can arrive at the family unit level clients. However in light of the fact that it is a mass medium equipped for being seen by almost anybody, TV comes up short on the capacity to convey a commercial to profoundly focused on clients contrasted with other news sources. Telecom companies are endeavoring to improve their focusing on endeavors. Specifically, networks working in the compensation to-get to field, for example, those with stations on link and satellite TV, are presenting all the more barely themed programming (i.e., TV shows outfitted to explicit vested parties) intended to speak to particular crowds. In any case, TV stays an alternative that is best for items that focused to a wide market. The geographic extent of TV publicizing may shift, from neighborhood or provincial promoting through to public inclusion, contingent upon whether public telecom or endorser based link administrations are utilized.

**3. Radio advertising** - Advancement through radio has been a reasonable promoting alternative for more than 80 years. Radio publicizing is generally neighborhood to the transmission scope of a radio broadcast, notwithstanding, at any rate three choices exist that offer public and possibly worldwide inclusion. To begin with, in numerous nations there are radio organizations that utilization numerous geologically particular stations to communicate at the same time. In the United States such organizations as Disney (youngsters' customizing) and ESPN (sports programming) broadcast broadly either through a gathering of organization claimed stations or through a partnership plan (i.e., business concurrence) with accomplice stations. Second, inside the most recent couple of years the development of radio

programming conveyed by means of satellite has become a possibility for public publicizing. At long last, the potential for public and global promoting may turn out to be more appealing as radio broadcasts permit their signs to be transmission over the Internet.

From various perspectives radio endures similar issues as TV, to be specific, a mass medium that isn't profoundly focused on and offers little occasion to follow reactions. Yet, in contrast to TV, radio presents the extra hindrance of restricting promoters to sound just publicizing. For certain items publicizing without visual help isn't powerful.

**4. Email advertising** - Promoting your items or administrations by email can be a quick, adaptable and savvy method of arriving at new clients and holding existing clients by empowering rehash site visits.

Email advertising can permit you to make focused on and customized messages. This can assist you with building significant associations with your clients. It can likewise improve reaction rates to your immediate showcasing efforts.

Nonetheless, it is significant not to abuse email showcasing. Accepting advertising messages can disturb individuals in the event that it is immaterial, excessively regular or undesirable.

**5. Social media** - Online media promoting is the utilization of web-based media stages to interface with your crowd to assemble your image, increment deals, and drive site traffic. This includes distributing incredible substance on your web-based media profiles, tuning in to and connecting with your devotees, breaking down your outcomes, and running web-based media notices.

The significant online media stages (right now) are Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, YouTube, and Snapchat.

Online media promoting is the way toward making content that you have custom-made to the setting of every individual web-based media stage to drive client commitment and sharing. You picking up traffic is just the consequence of online media promoting. Interpersonal interaction sites depend on building virtual networks that permit customers to communicate their requirements, needs and qualities, on the web. Web-based media advertising at that point interfaces these shoppers and crowds to organizations that share similar necessities, needs, and qualities. Through person to person communication locales, organizations can stay in contact with singular adherents. This individual cooperation can ingrain a sentiment of dedication into devotees and expected clients. Additionally, by picking whom to follow on these destinations, items can arrive at a tight objective crowd. Person to person communication destinations likewise incorporate a lot of data about what items and administrations forthcoming customers may be keen on. Using new semantic examination advancements, advertisers can recognize purchasing signals, for example, content shared by individuals and questions posted on the

web. A comprehension of purchasing signs can assist deals with peopling objective applicable possibilities and advertisers run miniature focused on missions.

**6.Event** - occasion advertising is viewed as a piece of experiential promoting and substance showcasing. Experiential promoting follows the cycle of corporate narrating, and expects to additionally draw in the crowd. Experiential follows a straightforward recipe of consolidating a brand's message and intelligent parts. This method of advertising places the intended interest group in a live climate that will support the ideal result. Occasion promoting generally depends on feelings and the action of the human mind. Occasion promoting utilizes feelings and depends on the way that individuals recollect what they are encountering. Enthusiastic improvement essentially influences the picture of the offered administration or item. Analysts demonstrated that while animated by feelings, the mind recalls certain realities and snippets of data better. Encountering something makes it more memorable.[4] In this condition, almost certainly, the brand will remain in the beneficiary's mind and make a durable image.

#### Literature Review

Interpersonal organizations assume a significant function in the appropriation of data and verbal exchange and permit clients to arrange , impart (through informing or something else ) and collaborate (Constadines , 2014 ). The intensity of online networks in building brand notorieties and client connections is expanding (Harris and Rae , 2009 ). Online media vehicle helps in expanding client traffic and decreasing showcasing costs .publicists can pick the online media channel dependent on accessibility and openness of the intended interest group . the organization can make the business page on the ideal online media channel. Routinely posting the relavant and fascinating the natural reach among the intended interest group .organizations typically rouse the buyers to share their email on their site, online media pages and look for consent to send the mail for the updates. (Chittenden and Rettie 2003 ). The organization consistently send messages to their endorsers as it a conservative method of arriving at the possibilities and clients on normal premise (Raulas2004 ). Email media vehicle is one of the fastest and customized approach to arrive at countless forthcoming shoppers. Kumar and Raju (2013) in their paper "the function of promoting in buyer dynamic" have discovered that commercials can change the shopper's sentiment on a specific item. Promoting has consistently known to be one of the key factors that influence purchaser's dynamic cycle. The web is a more captivating medium than print due to its different leveled structure. Contrasted with peruser of papers and magazines, the web gives more control to clients for watching their preferred substance (Bezjian Avery, Calder and Lacobucci , 1998 ). In this examination , the term web envelops computerized channels , to be specific Facebook , Twitter , Instagram , You tube , Email to give some examples (Ducoffe ,1996 , Gilaninia , Taleghani, and Karimi

, 2013 , Mishra and Vashiath,2017 , Trivedi , 2017 ). In the light of the shifted impact of differencnt media stages ,Opeodu and Gbadebo (2017 ) demonstrated that a commercial on different media stages assumes an imperative function in affecting customers' decision . subsequently savvy decision of media stage for ad is key for the advancement of items and administrations (Singh , 2012). Ads are broadly acknowledged wellspring of data among the shoppers when contrasted with different sources,and consequently, media blend choices are vital for publicists (Shrivastava, 2014 ). Different hypotheses of purchaser conduct set that there is a connection among notices and various phases of customer conduct .(Ranjbarian, Shaemi, and Jolodar 2011 ) set up that TV commercials influence consideration, expectation, and want. Nysveen and Breivik 2005 expressed that the impacts of radio commercial are less on changing shoppers' mentality and conduct .

**Methodology** - Field of the Research and Sample This examination utilized quantitative technique. In the quantitative procedure, fundamentally, the creators utilize an overview study which utilizes poll for the information assortment. Study field is both TV advertisement and purchasing conduct. In this, for the study, it utilized 400 surveys covering Ahmedabad, Vadodara, Surat and Rajkot in Gujarat. Strategy for advantageous testing is utilized for this review. Exploration Approach As the target of this examination is to investigate inclination of media vehicle of the clients .a quantitative methodology is used. A quantitative exploration is used to quantify a specific marvel, so they can be changed to numbers. Quantitative examination looks at mathematical relations between at least two quantifiable characteristics. Such a methodology is normally connected with enormous scope examines and is identified with the objectivity of the specialist. Quantitative exploration then again depends on changing the noticed marvels to composed words rather than numbers. A blend of a comprehensive viewpoint and explicit point of view is ideal in this examination to quantify the respondents buying expectation and understanding their mentalities. A combinational methodology (triangulation) sees a marvel through alternate points of view and it could be said prompts higher exact outcomes. With respect to the examination approach, a poll is directed for a quantitative assortment of information. A contextual analysis is barred considering the way that a contextual analysis centers around singular examples as opposed to more extensive ranges. An analysis and perception are likewise barred as a result of the absence of time and assets. Order of Data Used Primary information. Surveys are intended to gather data that is utilized in this manner as information for examination. The survey being used comprises of various significant inquiries concerning the respondents' perspectives and shopper's conduct. The survey is semi-organized, and has a blend of shut and open inquiries. The course of action of the poll comprises of three sections. An example of 400 was picked

and data was gathered through methods for comfort. Google structure strategy was utilized to get higher pace of reaction. A conveyed survey might have been used, yet the hour of the investigation is restricted and the result is a low pace of reaction. Optional information. Auxiliary information will be data that has been recently accumulated for certain reasons other than the momentum research venture. An enormous extent of the information utilized in this investigation are named essential information. Generally, data was accumulated from individual meetings, google structures, telephonic meetings and through messages. With respect to the development of the web utilization, a great deal of the information gathered were broadly accessible in electronic arrangement. Unwavering quality and Validity Reliability. Dependability is frequently alluded to an estimation that is steady and has not been presented to unplanned impacts. The examination instrument should create a similar information whether it is done today or re-done at some other point. Legitimacy. The term legitimacy frequently alludes to the significance of the information comparable to the examination marvels. The examination instrument utilized as an estimation of wonders should quantify precisely measuring. It might be said, a high legitimacy implies that the information and strategies are correct and pertinent.

#### Data Analysis

**The Survey and Data** - The poll was sent by means of Email and WhatsApp among 400 respondents chose from Ahmedabad Vadodara Surat And Rajkot to assemble information on media vehicle inclination among the clients of metropolitan Gujarat.

This examination is about attention to media vehicle , inclination of media vehicle , effect of media vehicle on deals, and effect of media vehicle on devotion of buyers . media vehicle, for example, television advertisements, print promotions , radio, online media, email and occasions are thought about. In this examination media vehicle picked by online retailers, for example, amazon ,flipkart , snapdeal, enormous container and myntra are thought about .

#### Objects of the Examination:

1. To examination the most probable media vehicle among the buyers
2. To examination the inclination of media vehicle
3. To investigation which media vehicle have most mindfulness among the buyers
4. To examination do media vehicle impact acquisition of the purchasers , if yes which media vehicle have most impact
5. To examination do media vehicle impact devotion of the buyers, if yes which media vehicle have the most impact

#### Hypothesis of the Study :

- H1.0 : There is no relationship between media vehicle and brand awareness among the customers  
H1.1: There is a relationship between media vehicle and awareness among the customers

H2.0: There is no relationship between media vehicle and sales

H2.2 : There is a relationship between media vehicle and sales

H3.0 : There is no relationship between media vehicle and loyalty of customers

H3.3 There is a relationship between media vehicle and loyalty of customers

#### Research and Findings :

##### Table 1 and chart (see in last page)

From the table 1 and chart we can say that individuals like television and web-based media the most as the media vehicle .email and occasions are very little famous among the shoppers as per this examination . as per the investigation numerous individuals don't care for sends as the media vehicle . individuals additionally favor radio after television and web-based media .

##### Table 2 and chart (see in last page)

From the table 2 and chart we can say that commercial on television print and online media of amazon profoundly affected the acquisition of the purchasers as per this overview. From we can likewise reason that media vehicle television print and web-based media have effect on buyer's buy.

##### Table 3 and chart (see in last page)

From the table 3 and chart we can say that media vehicle television, print and online media have impact on steadfastness of the client. In this amazon and flipkart and myntra are in top 3.

##### Table 4 and chart (see in last page)

From the table 4 and chart gives the information about the media vehicle of occasions . there are numerous individuals falls in have not seen any , this prompts infer that this media vehicle isn't favored much as television, print and online media , it might have impact in future by changing time .

##### Table 5 and chart (see in last page)

From the table 5 and chart gives the information about the media vehicle of occasions .there are numerous individuals falls in have not seen any , this prompts infer that this media vehicle isn't favored much as television, print and online media , it might have impact in future by changing time .

##### Table 6 and chart (see in last page)

From the table 5 and chart we can say that occasion have very little impact on faithfulness of purchasers .individuals don't show a lot of unwaveringness towards this media vehicle .

##### Table 7,8 and 9 (see in last page)

**Conclusion and Recommendations** - In the wake of doing investigation it very well may be said that different media vehicle have to some degree effect on clients. The investigation was restricted to the commercials on television , print web-based media , messages and occasions. In view of hypothetical foundation and writing just as the presumptions made by the scientist, the investigation figured the theoretical edge work. In this cycle, just couple of properties were thought about. The scientist guessed

that there is a connection between the different media vehicle and inclination, buy and steadfastness of clients . Further, this relationship can shift as per the center segments of the autonomous variable. Under the pointers estimation, measures were created to distinguish the exploration factors. The examination tried three speculations dependent on the autonomous variable and its center parts to look at the impact of the buyer purchasing goal. The information were gathered through organized poll. An example of 400 respondents was chosen for the study from Ahmedabad VdodaraSurat and Rajkot. The respondents were chosen by the irregular testing strategy. In the information examination identified with above speculations, it was uncovered that promotions through Tv, and web-based media have most noteworthy likings and most noteworthy effect on buy and reliability of clients .print media and radio media vehicle have to some degree likings and impact on client's buy and reliability yet recurrence is lesser then television and online media . on the off chance that we talk about occasion media it has likings yet generally individuals have seen and caught wind of occasions of amazon flikpkart and myntra individuals are not that much mindful about occasion media nor have super effect on buy and devotion . huge numbers of individuals generally prefer to buy on celebration deal and offers so occasion as a media vehicle has fairly impact on acquisition of clients . each media vehicle has its own range to the clients and has own effect on buy and dedication , however with the changing of time this pattern may not be show the steady outcomes . we can see that print media and radio media has least likings where web-based media is driving in likings, inclination and impact . this are the away from of digitalization. No media vehicle can be totally attracted out yet to remain in a relentless rivalry crusades on television and online media is a lot of valuable .

The exploration inspected superstar support based on three determinants. It very well may be intriguing to expound more on one of these roundabout determinants, to acquire a more extensive establishment of information concerning the media vehicles. Also, joining the previously mentioned differentiations could give different experiences in this field of information. The customers can review the notices on account of the different elements. On the off chance that the advertisers need to keep the promotion in the buyer's brain the appealing they should pick the media vehicle admirably.

**Limitations And Further Scope Of The Study** - Just few media vehicles are contemplated. The examination is restricted to four significant urban communities of Gujarat just . The investigation is restricted to specific section of

time ,geology and individuals . results may contrast every once in a while . thiscan not be the consistent outcome. This examination accentuates the need that future analysts should give more consideration on this field. This is a fascinating field for specialists; . This investigation didn't inspect impact of customer purchasing expectation as indicated by the buyer's segment factors. Further exploration must be expected to discover the connection between the impact of buyer purchasing expectation and segment factors comparable to media vehicle .

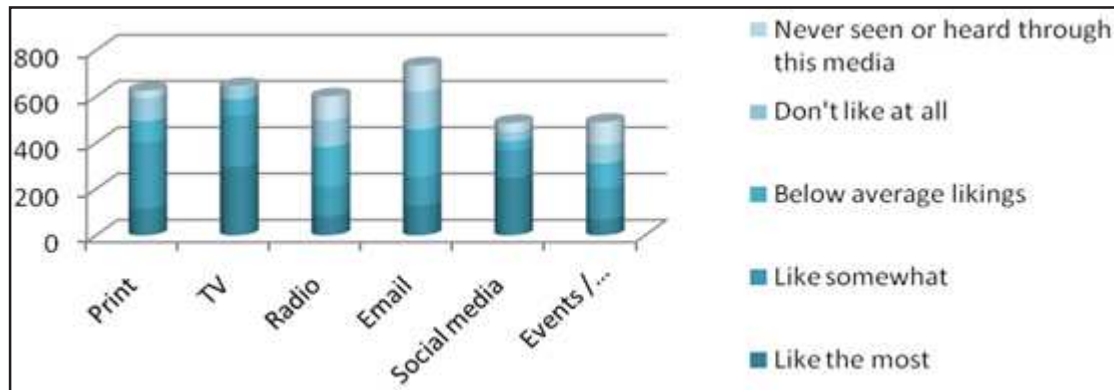
#### References :-

1. Andrews&currim (2004 ) in international journal of internet marketing and advertising - studied and tested that the difference in choice behaviour of consumer who purchase online and traditional store.
2. Blech, G.E &Blech, M.A (2012). Advertising and promotion an integrated marketing communications perspective. (the d. Boston,McGraw Hill Higher Education
3. Berndt, A (2007). Media habits among Generation Y consumers. Proceedings of the 19<sup>th</sup> Annual Conference of the southern institute of management .south Africa 19-12 sep.
4. Bhargava M (1994) improving the effectiveness of outdoor advertisement 43(2) 46-55 Mar-Apr
5. Brassington F and Pettitt S (2000) Principles of marketing , 2<sup>nd</sup> edition
6. Clow , C.E &baack D (2010) integrated advertising promotion, and marketing communication 4<sup>th</sup>ed upper saddle river
7. Ernest F. Larkin (1978) – ‘consume perceptions of the media and their advertising content ‘ – journal of advertising
8. Safura Mohamed Kallier (2017 ) – the focus of marketing communication efforts of SMEs within South Africa
9. Dr.S.Saravanan and K. Brindha Devi (2015)- “ A study on online buying behaviour with special reference to Coimbatore city “
10. Schiffman and Kanuk (2010) mentioned that the consumer made the purchase decision is influenced by several measurement and psychological measurements
11. Sudha M and Sheena K (2017 ) studied the impact of influencers like blogs , facebook , youtube , instagram , twitter , pinterest , Google+ , vine in consumer decision process in Fashion industry
12. Wells et al (2003 ) – assessment of advertising effectiveness.



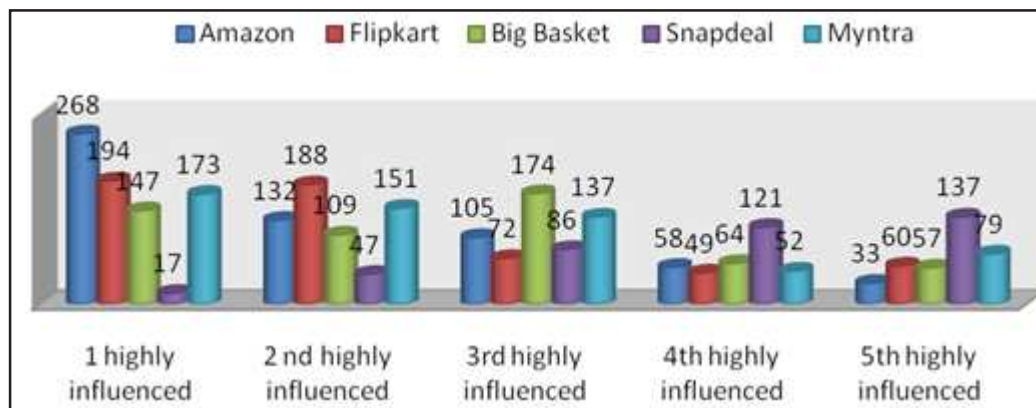
**Table 1 :** Through which media vehicle do you prefer to see / heard ads or campaigns ? (MutpalAns)

Ans	Responds				
	Like the most	Like somewhat	Below average likings	Don't like at all	Never seen or heard through this media
Print	116	284	94	100	32
TV	295	221	71	53	5
Radio	84	125	174	115	103
Email	128	126	204	165	112
Social media	249	117	41	39	40
Events / interview/ success stories	68	137	106	82	97



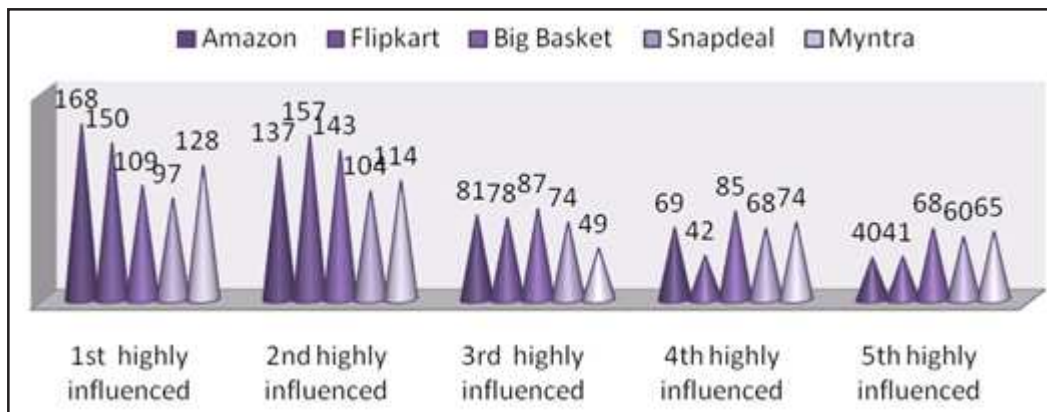
**Table 2 :** How much do you think the advertisement on TV, Radio or on social media influenced your purchasing from online retailers?

Ans	1 highly influenced	2 nd highly influenced	3rd highly influenced	4th highly influenced	5th highly influenced
Amazon	268	132	105	58	33
Flipkart	194	188	72	49	60
Big Basket	147	109	174	64	57
Snapdeal	17	47	86	121	137
Myntra	173	151	137	52	79



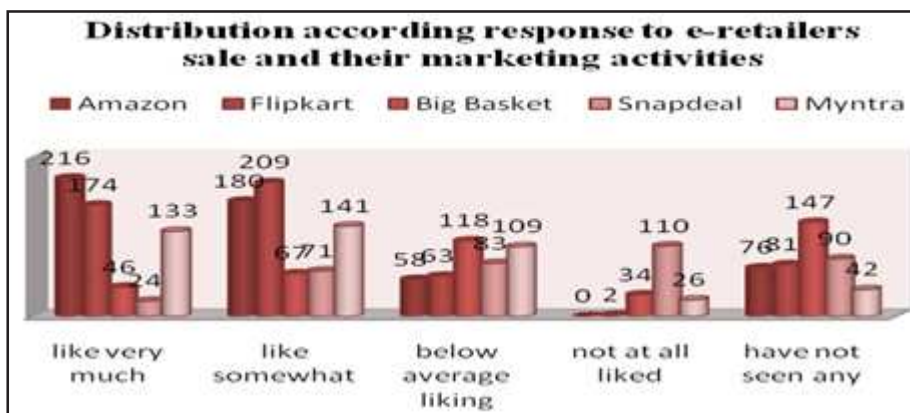
**Table 3 :** How much do you think the advertisement on TV, Radio, or social media influenced your loyalty towards the following e-retailers?

Ans	1 highly influenced	2 nd highly influenced	3rd highly influenced	4th highly influenced	5th highly influenced
Amazon	168	137	81	69	40
Flipkart	150	157	78	42	41
Big Basket	109	143	87	85	68
Snapdeal	97	104	74	68	60
Myntra	128	114	49	74	65



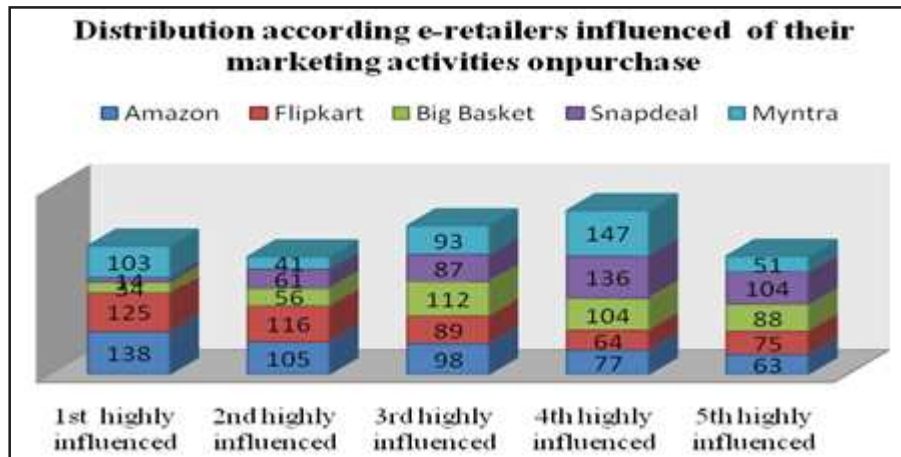
**Table 4 :** With regards given e-retailers please share your response to their events such as festival sales, promotional activities award nights, talk shows, launch of new product or services etc.

Ans	like very much	like somewhat	below average liking	not at all liked	have not seen any
Amazon	216	180	58	0	76
Flipkart	174	209	63	2	81
Big Basket	46	67	118	34	147
Snapdeal	24	71	83	110	



**Table 5 :** How much do you think the events such as festival sales, award night, talk shows, promotional activities, launch of new products or services of following e-retailers influenced your purchase

Ans	1 highly influenced	2 nd highly influenced	3rd highly influenced	4th highly influenced	5th highly influenced
Amazon	138	105	98	77	63
Flipkart	125	116	89	64	75
Big Basket	34	56	112	104	88
Snapdeal	14	61	87	136	104
Myntra	103	41	93	147	51



**Table 6 :** How much do you think the events such as festivals sales, award nights, promotional activities, launch of new products or services of following e-retailers influenced your loyalty towards them?

Ans	1 highly influenced	2 nd highly influenced	3rd highly influenced	4th highly influenced	5th highly influenced
Amazon	129	82	152	61	108
Flipkart	87	76	147	54	114
Big Basket	41	51	109	71	123
Snapdeal	29	24	94	112	147
Myntra	74	32	87	119	126



**Table 7 : t-Test: Paired Sample for Means**

	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5
Mean	75.78947368	76	74.48372	73.548239	74.25468
Variance	4051.064327	5894.666667	4021.058324	5235.48521	5348.3762
Observations	18	18	18	18	18
Pearson Correlation	0.942231896	0.942242355	0.942821896	0.942227895	0.942232459
Hypothesized Mean Difference	3				
Df	18				
t Stat	-0.515505229				
P(T<=t) one-tail	0.306236784				
t Critical one-tail	1.734063607				
P(T<=t) two-tail	0.612473567				
t Critical two-tail	2.10092204				

**Table 8 : t-Test: Paired Two Sample for Means**

	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5
Mean	151.8947368	151.7894737	150.4582	145.4863	146.7581
Variance	17457.09942	19154.50877	19254.52	184753.68	17458.42
Observations	19	19	19	19	19
Pearson Correlation	0.941052523	0.944205252	0.941026523	0.9448526	0.941075758
Hypothesized Mean Difference	3				
Df	19				
t Stat	-0.269307098				
P(T<=t) one-tail	0.395378097				
t Critical one-tail	1.734063607				
P(T<=t) two-tail	0.790756194				
t Critical two-tail	2.4206424				

**Table 8 : t-Test: Paired Two Sample for Means**

	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5
Mean	73.548239	75.2458	75.78947368	74.3584	73.78476
Variance	5235.48521	5894.666667	5649.625	5894.666667	5638.895
Observations	18	18	18	18	18
Pearson Correlation	0.942227895	0.942242355	0.942231896		0.942821896
Hypothesized Mean Difference	3				
Df	18				
t Stat	-0.502305229				
P(T<=t) one-tail	0.304476722				
t Critical one-tail	1.746063607				
P(T<=t) two-tail	0.612473567				
t Critical two-tail	2.10064935				

\*\*\*\*\*



# Status of Traditional Collections in State University Libraries : Special References of Gujarat State

Dr. Saiyed Faheem Ali\* Alka Jaidatt Gajre\*\*

**Abstract** - India has a large higher education system. The growth rate of educational institutions in India was very slow before independence in 1947. Education aims to impart knowledge and makes good citizens. Libraries are the repositories of knowledge and form an integral part of education. Libraries have a long history, starting with the chained and closed-access libraries of earlier times to the present-day hybrid, digital, and virtual libraries that use the latest technology for provision of information through various services. Traditionally the library as a storehouse of books and other reading materials and learning resources and the librarian as a custodian of these resources has been a significant skill of any educational institutions. Data is required regarding respondents 'information of non-printing resources. This data is collected using questionnaire. Scope of this study is University Libraries and it is limited to such universities which are running its courses. The proposed universities are not part of this study. At present Gujarat state have 68 universities as per the record of UGC website. Out of 68 universities researcher took 8 educational universities for this study.

**Keywords** - Traditional collection, Printing Collection, Traditional Collections of Gujarat State University Libraries.

**Introduction** - Generally resources are included a person, asset, material, or capital which is support to fulfill the task or any assignment. Similarly library resources consist of manpower of library and reading material like printed and electronic resources which are meet the users requirement. But the manpower of library is only providing service to the users. So, generally library resources are consider as the reading materials such as print and e-resources.

A traditional library is emphasis on storage and preservation of physical items, particularly books and periodicals cataloging at a high level rather than one of detail, for example author and subject indexes as opposed to full text browsing based on physical proximity of related materials, e.g., books on sociology are near one another on the shelves, passivity; information is physically assembled in one place; users must travel to the library to learn what is there and make use of it.

**Advantages of Traditional Library Resources** - There is lot of advantages while using traditional library resources. Because its some features like the format, size, quality, easy to handling and etc.

1. Traditional print resources are able to take by the users because of its portability. Compactness, light in weight and comfortable to read.
2. Traditional print resources are able to read. Even if computers are failure.
3. Users can turn the pages comfortably the traditional

print resources. Because of the familiarity.

4. One of the traditional formats of print resources is very convenient for the users. Bob Balay, in an article praising print reference sources that he facetiously titled Notes from the Jurassic, claimed that, with print reference sources, you always know where you are and have a sense of the entirety of the source.
5. Before publish all the print format resources are followed by processes like editing, and peer reviewing. The print resources are usually more authoritative than their E-resources. Healey points out that the expense of publishing, combined with an extensive reviewing system and the relatively fixed™ nature of printed materials, all help the librarians to find quality materials, and avoid shoddy, biased, or misleading works
6. There is no need of any technology for read the print resources.
7. User can spend long time for using print resource
8. A traditional format of print resources is very convenient for the reading. Traditional format Printed resources are printed and bound in the different size for make use conveniently.
9. A traditional format of print resources is more portable, easier to read, and better to handle.
10. There is no specific places are required for store a printed format resources.
11. Printed resources are more environmental than e-

\*Research Guide and Associate Professor (Library and Information Science) Madhav University, Pindwara, Sirohi (Raj.) INDIA

\*\* Research Scholar (Library and Information Science) Madhav University, Pindwara, Sirohi (Raj.) INDIA

resources. The printed resources are not creating any pollution in the environment.

12. Traditional Printed resources remain readable for many years.
13. The user can feel physically, cover, paper and binding from the original work while using the traditional Printed resources.
14. The user unable to use the print resources only the reason maybe damaging. The damage may happen after many decades of print.
15. Users can be able to buy used copies at significant discounts, as they can now easily do with printed resources.

#### **Disadvantages of Traditional Resources:**

1. The maximum number of printed reference books is available at high price. Even there are number of free search engines and search directories and websites available online for users reference purpose.
2. Only one user can use a printed resource at one time. The user may lose the opportunity if the resources is misplaced or lost in library.
3. As reporter May Wong states, Once-a-year updates for printed editions means that Some information can be stale even before the books get out of the box
4. If users want a traditional print resource he/she should visit the library during the working hours only.



**Objective of This Study** - To know the present status of printing resources in the state university libraries of Gujarat State.

#### **Literature Reviews**

**Salve, Mr & Kalbande, Dr. Dattatraya & Chavan, Subhash. (2018).** This study commits to examine the Policy of the getting of print resources in University libraries from the state of geographical area. In Library getting policy it's target written Books, Print e-journals (Indian) and print e-journals from the foreign countries. For this study there have been ten university libraries from the state of geographical area hand- picked. From this study it absolutely was found that libraries don't have same getting policy to get print resources.

**Ajayi.N.A & Adetaya, J.O (2005),** in their work "Utilization of Library books to Enhance Academic Excellence in Nigeria Tertiary Institution: A case Study of Hexejiah Oluwasanmi library" they have found that the students and staff members

have fully utilized the library. There was a progressive increase in the number of printed books borrowed and consultation of library users from 159,134 in 1997-98 session to 37 295,121 in 2000-2001 session. The progressive increase in the utilization of printed books is an indication that the library is meeting its primary role of supporting the objective of its institution.

**P, Divya & Haneefa K, Mohamed. (2020).** This study investigates students' preference of reading print and digital resources. A questionnaire survey with a stratified random sample of 700 postgraduate students of the universities in Kerala state of India was used to conduct the study. Comparison on media provided a fascinating insight into the way students read. The students reported a better comprehension, concentration, higher content absorption and comfort levels, if they read on print resources as opposed to digital resources. Majority of the students download the documents, take notes, and copy and paste contents while reading digital resources. There is no significant gender difference in their level of comprehension while reading both print and digital resources. However, there is significant gender difference in the choice of reading media under the circumstance like depth and concentrated reading, casual reading, reading lengthy documents, one-time reading, speed reading, relaxed reading, and reading something very important. This study provides useful information for developing improved interfaces for online reading and enhancing the online reading skills of students.

**Gupta, Sujata. (2016).** This study was carried out by conducting a survey using questionnaire as a tool to explore student preferences regarding print and e-resources for academic purposes. A well structured questionnaire was prepared and distributed to 55 faculty members and students of Vasanta College for Women out of which 50 responses were received. The analysis revealed the preference, frequency of usage, degree of users' satisfaction and challenges faced in accessing both materials print and e-resource.

**Gupta (2011)** carried out a study on use pattern of print and electronic journals. The study was based on the result of a questionnaire distributed to all the teachers and research scholars of the two departments. The purpose of this study was to analyse the use of electronic journals from the INFONET consortium by faculty and research scholars of physics and chemistry at Kurukshetra University, India.

**King, Tenopir, Choemprayong & Wu (2009)** worked on scholarly journal information seeking and reading patterns of faculty. It was found that faculty prefer print for personal subscriptions, although library electronic collections provide a majority of readings and most readings from library collections were from electronic sources; older articles were also more commonly from electronic library collections.

**Akhtar Hussain & Krishan Kumar (2006)** conducted a survey on the use, collection and services of IIRS (Indian Institute of Remote Sensing) Library. Their major findings were 41.25% of the respondents used the library services

daily, 81.25% of the respondents used the library mainly to borrow books or other materials, 87.50% of the respondents preferred the print collection over the electronic collection (68.75%), and 86.25% of the respondents use current periodicals, most of the respondents were satisfied with the library services.

**Research Methodology** - The study is mainly focused on status of Traditional collection of Gujarat state university libraries, survey method was found more suitable for the study. Hence, Survey method was endorsed for the present work. There are two commonly used tools for collecting the data in survey research; the Questionnaire method, and the Interview method. Primarily questionnaire is used as a major tool in this study. However, this has been complemented with the informal interviews as and when required. The questionnaire were distributed to 8 libraries of State Gujarat Universities out of 68 State Gujarat Universities libraries.

### Data Analysis

**Traditional Collections:** The effectiveness of the library administrations relies upon assortment of library/information sources. Such kinds of traditional collections of library are assuming an indispensable job while giving information to their clients. This assortment is books, diaries and magazines, bound volumes, propositions and thesis, reference sources, ventures reports, government publications, manuscripts, research papers and others. In this regard, this inquiry was presented to the library professionals to give the information with respect to their traditional collections. Table 5.9 speaks to the information given underneath.

#### Table 1 (see in last page)

#### Graph 1 (see in last page)

**Books:** 447592 of total collection of Books were available in Maharaja Sayajirao University (M.S. University), followed by 360322 in Gujarat University, 237557 in Sardar Patel University, 195413 in Saurashtra University, 190103 in Veer Narmad South Gujarat University, 126500 in Maharaja Krishnakumarsinhji Bhavnagar University, 72125 in Hemchandracharya North Gujarat University (NGU) and 14500 in KrantiguruShyamji Krishna VarmaKachha University.

#### Graph 2 (see in last page)

**Journals & Magazines (National + International):** 7234 of total collection of journals and magazines is available in Maharaja Sayajirao University (M.S. University), 443 in Sardar Patel University, 282 in Gujarat University, 237 in Maharaja Krishnakumarsinhji Bhavnagar University, 211 in Saurashtra University, 193 in Veer Narmad South Gujarat University, 110 in KrantiguruShyamji Krishna VarmaKachha University and 110 in Hemchandracharya North Gujarat University (NGU).

#### Graph 3 (see in last page)

**Bound Volumes:** 77189 of total collection of bound volumes were available in Maharaja Sayajirao University (M.S. University), followed by 39000 collection of bound volume

available in Gujarat University, 15705 in Veer Narmad South Gujarat University, 14000 in Maharaja Krishnakumarsinhji Bhavnagar University, 2557 in Hemchandracharya North Gujarat University (NGU), 1880 in Sardar Patel University, 1300 in Saurashtra University and KrantiguruShyamji Krishna VarmaKachha University is not having collection of bound volumes.

#### Graph 4 (see in last page)

**References Sources:** 31000 of total collection of references sources were available in Gujarat University, followed by 12600 collections of references sources available in Veer Narmad South Gujarat University, 7500 in Maharaja Sayajirao University (M.S. University), 2750 in KrantiguruShyamji Krishna VarmaKachha University, 2133 in Saurashtra University, 11 in Maharaja Krishnakumarsinhji Bhavnagar University and other 2 state university libraries are not having collection of references sources. These universities are Hemchandracharya North Gujarat University (NGU) and Sardar Patel University.

#### Graph 5 (see in last page)

**Theses & Dissertations:** 17000 of total collection of theses & dissertations were available in Gujarat University, followed by 13493 collection of theses & dissertations available in Maharaja Sayajirao University (M.S. University), 4627 in Sardar Patel University, 3005 in Saurashtra University, 2443 in Hemchandracharya North Gujarat University (NGU), 1500 in Maharaja Krishnakumarsinhji Bhavnagar University, 1450 in KrantiguruShyamji Krishna VarmaKachha University and Veer Narmad South Gujarat University is not having collection of theses & dissertations.

#### Graph 6 (see in last page)

**Projects Reports:** 402 of total collection of projects reports were available in Hemchandracharya North Gujarat University (NGU), followed by 140 in KrantiguruShyamji Krishna VarmaKachha University and other 6 state university libraries are not having collection of projects reports. These universities are Maharaja Krishna kumarsinhji Bhavnagar University, Saurashtra University, Maharaja Sayajirao University (M.S. University), Veer Narmad South Gujarat University, Sardar Patel University and Gujarat University.

#### Graph 7 (see in last page)

**Government Publications:** 1119 of total collection of government publications were available in Veer Narmad South Gujarat University, 225 in KrantiguruShyamji Krishna VarmaKachha University, 73 in Sardar Patel University and other 5 state university libraries are not having collection of government publications. These universities are Hemchandracharya North Gujarat University (NGU), Maharaja Krishnakumarsinhji Bhavnagar University, Gujarat University, Maharaja Sayajirao University (M.S. University) and Saurashtra University.

#### Graph 8 (see in last page)

**Manuscripts:** 420 of total collection of manuscripts were available in Gujarat University and other 7 state university libraries are not having collection of manuscripts. These



universities are Hemchandracharya North Gujarat University (NGU), Veer Narmad South Gujarat University, Krantiguru Shyamji Krishna Varma Kachha University, Sardar Patel University, Maharaja Krishnakumarsinhji Bhavnagar University, Maharaja Sayajirao University (M.S. University) and Saurashtra University.

**Findings** - Highest collection of Books were available in Maharaja Sayajirao University (M.S. University) also Gujarat university has good book collection comparer to remaining other university of Gujarat state, Krantiguru Shyamji Krishna Varma Kachha University has only 14500 books its very low then other university.

**Journals & Magazines (National + International):** 7234 of total collection of journals and magazines is available in Maharaja Sayajirao University (M.S. University), 443 in Sardar Patel University, 282 in Gujarat University, 237 in Maharaja Krishna kumarsinhji Bhavnagar University, 211 in Saurashtra University, 193 in Veer Narmad South Gujarat University, 110 in Krantiguru Shyamji Krishna Varma Kachha University and 110 in Hemchandracharya North Gujarat University (NGU).

**Bound Volumes:** 77189 of total collection of bound volumes were available in Maharaja Sayajirao University (M.S. University), followed by 39000 collection of bound volume available in Gujarat University, 15705 in Veer Narmad South Gujarat University, 14000 in Maharaja Krishnakumarsinhji Bhavnagar University, 2557 in Hemchandracharya North Gujarat University (NGU), 1880 in Sardar Patel University, 1300 in Saurashtra University and Krantiguru Shyamji Krishna Varma Kachha University is not having collection of bound volumes.

**References Sources:** 31000 of total collection of references sources were available in Gujarat University, followed by 12600 collections of references sources available in Veer Narmad South Gujarat University, 7500 in Maharaja Sayajirao University (M.S. University), 2750 in Krantiguru Shyamji Krishna Varma Kachha University, 2133 in Saurashtra University, 11 in Maharaja Krishnakumarsinhji Bhavnagar University and other 2 state university libraries are not having collection of references sources. These universities are Hemchandracharya North Gujarat University (NGU) and Sardar Patel University

**Theses & Dissertations:** 17000 of total collection of theses & dissertations were available in Gujarat University, followed by 13493 collection of theses & dissertations available in Maharaja Sayajirao University (M.S. University), 4627 in Sardar Patel University, 3005 in Saurashtra University, 2443 in Hemchandracharya North Gujarat University (NGU), 1500 in Maharaja Krishnakumarsinhji Bhavnagar University, 1450 in Krantiguru Shyamji Krishna Varma Kachha University and Veer Narmad South Gujarat University is not having collection of theses & dissertations.

**Projects Reports:** 402 of total collection of projects reports were available in Hemchandracharya North Gujarat University (NGU), followed by 140 in Krantiguru Shyamji Krishna Varma Kachha University and other 6 state

university libraries are not having collection of projects reports. These universities are Maharaja Krishna kumarsinhji Bhavnagar University, Saurashtra University, Maharaja Sayajirao University (M.S. University), Veer Narmad South Gujarat University, Sardar Patel University and Gujarat University.

**Government Publications:** 1119 of total collection of government publications were available in Veer Narmad South Gujarat University, 225 in Krantiguru Shyamji Krishna Varma Kachha University, 73 in Sardar Patel University and other 5 state university libraries are not having collection of government publications. These universities are Hemchandracharya North Gujarat University (NGU), Maharaja Krishnakumarsinhji Bhavnagar University, Gujarat University, Maharaja Sayajirao University (M.S. University) and Saurashtra University.

**Manuscripts:** 420 of total collection of manuscripts were available in Gujarat University and other 7 state university libraries are not having collection of manuscripts. These universities are Hemchandracharya North Gujarat University (NGU), Veer Narmad South Gujarat University, Krantiguru Shyamji Krishna Varma Kachha University, Sardar Patel University, Maharaja Krishnakumarsinhji Bhavnagar University, Maharaja Sayajirao University (M.S. University) and Saurashtra University.

#### Suggestion :

1. Krantiguru Shyamji Krishna Varma Kachha University need increase collection of books.
2. University need increase journals and magazine collection.
3. Saurashtra University and Krantiguru Shyamji Krishna Varma Kachha University is not having collection of bound volumes so this universities need this collections.
4. Sardar Patel University, Maharaja Krishnakumarsinhji Bhavnagar University need reference resources.
5. Veer Narmad South Gujarat University is not having collection of theses & dissertations so this university need this collections
6. Hemchandracharya North Gujarat University (NGU), and Krantiguru Shyamji Krishna Varma Kachha University having collection of projects reports reaming university's don't have this collection , so reaming university need this collections .
7. Veer Narmad South Gujarat University, Krantiguru Shyamji Krishna Varma Kachha University, Sardar Patel University having collection of government publication, others universities need this collections .
8. Hemchandracharya North Gujarat University (NGU), Veer Narmad South Gujarat University, Krantiguru Shyamji Krishna Varma Kachha University, Sardar Patel University, Maharaja Krishnakumarsinhji Bhavnagar University, Maharaja Sayajirao University (M.S. University) and Saurashtra University need development collection of *Manuscripts*.

#### References :-

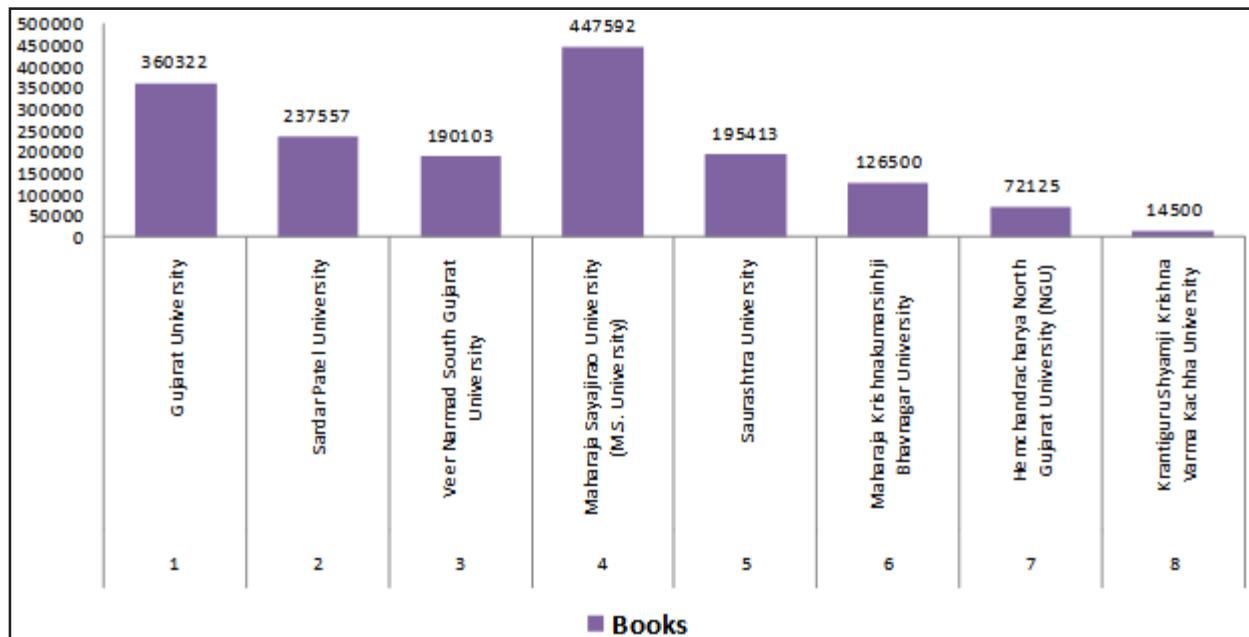


1. Gupta, D.K. (2011). Use pattern of print and electronic journals at the Kurukshetra University, India.
2. Gupta, Sujata. (2016). Preference and Usage of Print and E-Resources among Faculties and Students: A Study of Vasanta College for Women.
3. Little Geoffrey (2011). Collection development in library and information science. Emerald Group Publishing Limited. Collection Building, Vol. 30, NO. 3, Pp. 135–139.
4. Lucky O. Akpojotor (2016). Awareness and Usage of Electronic Information Resources among Postgraduate Students of Library and Information Science in Southern Nigeria, Library Philosophy and Practice (e-journal)
5. MamunMostofa SK. (2013) Use and Impact of E-Resources at Some Selected Private Universities in Bangladesh, Research Journal of Library Sciences, 1(1), 10-13.
6. P, Divya&Haneefa K, Mohamed. (2020). Students' Preference of Reading Print and Digital Resources: A Study in Universities in Kerala, India. Library Philosophy and Practice.
7. Stoller, M. (2006). A decade of ARL collection development: A look at the data. Collection Building. 25(2). 45-51.
8. Street, L. A. & Runyon, A.M. (2010). Finding the middle ground in collection development how academic law library can shape their collection in response to the call for more practice. Oriented Legal education. Law Library Journal. 102(3).399-427.

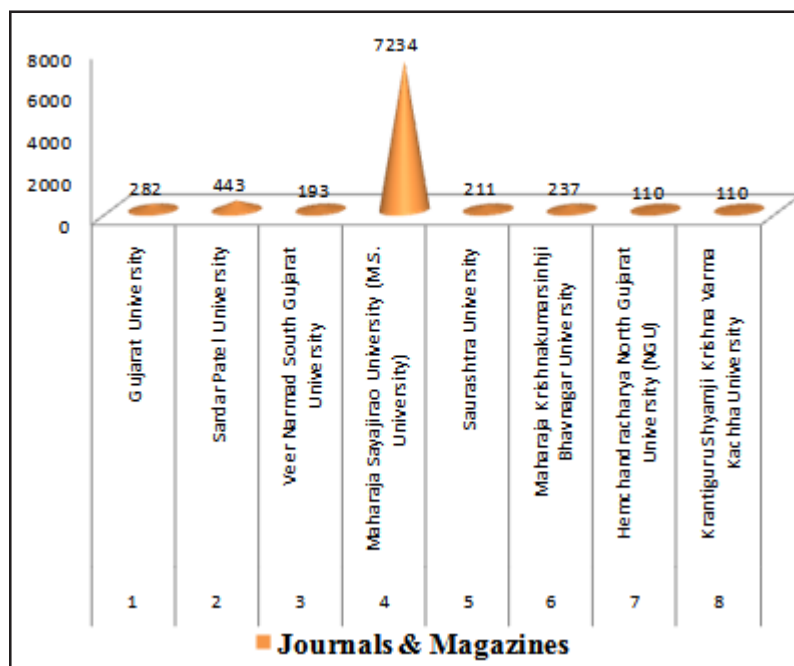
**Table 1: Availability of Traditional Collections in State University Libraries**

Sr.No	No. of State Universities Library	Books	Journals & Magazines	Bound Volume	References Sources	Theses & Dissertations	Projects Reports	Government Publications	Manuscripts
1	Gujarat University	360322	282	39000	31000	17000	0	0	420
2	Sardar Patel University	237557	443	1880	0	4627	0	73	0
3	Veer Narmad South Gujarat University	190103	193	15705	12600	0	0	1119	0
4	Maharaja Sayajirao University (M.S. University)	447592	7234	77189	7500	13493	0	0	0
5	Saurashtra University	195413	211	1300	2133	3005	0	0	0
6	Maharaja Krishnakumarsinhji Bhavnagar University	126500	237	14000	11	1500	0	0	0
7	Hemchandracharya North Gujarat University (NGU)	72125	110	2557	0	2443	402	0	0
8	KrantiguruShyamji Krishna VarmaKachha University	14500	110	0	2750	1450	140	225	0

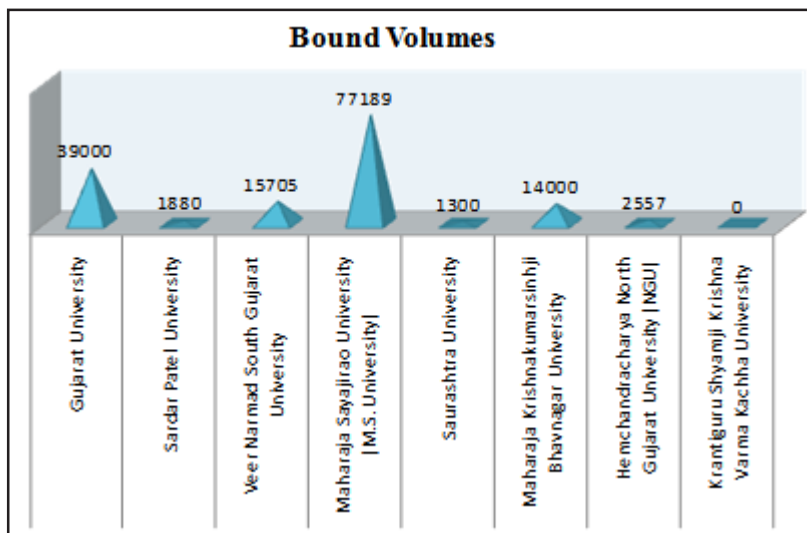
Graph 1



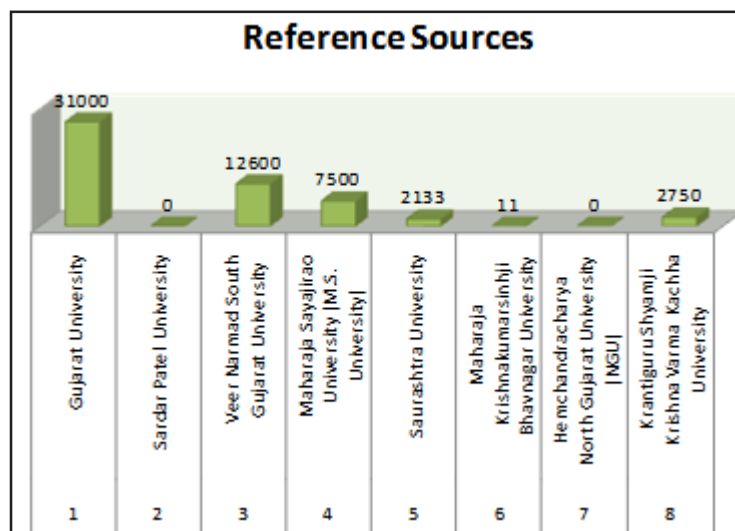
Graph 2



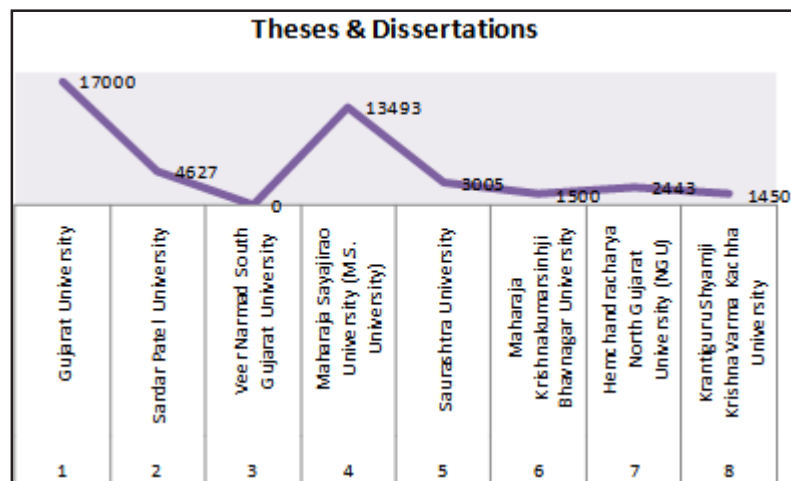
Graph 3



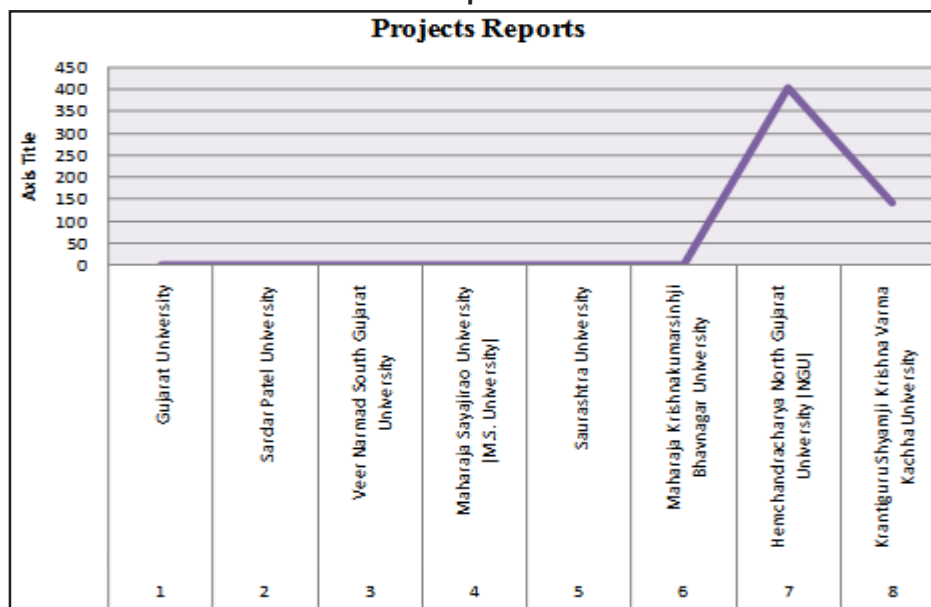
Graph 4



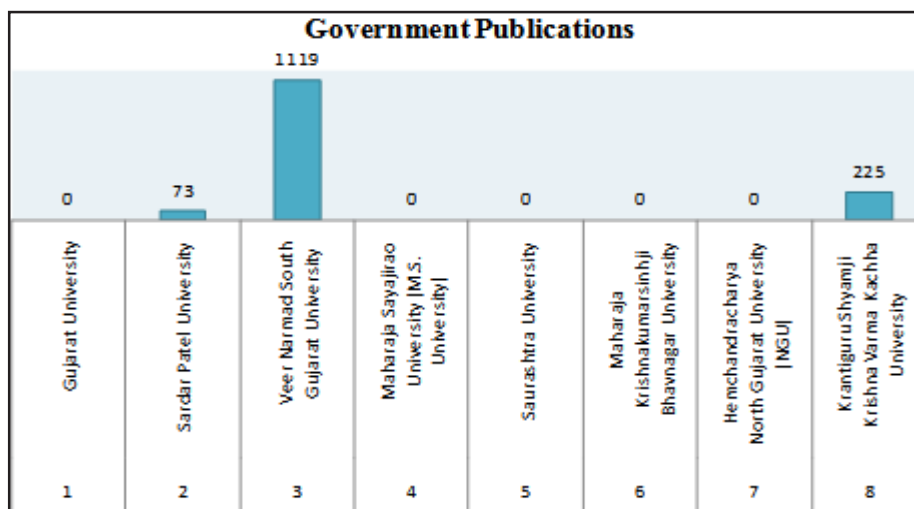
Graph 5



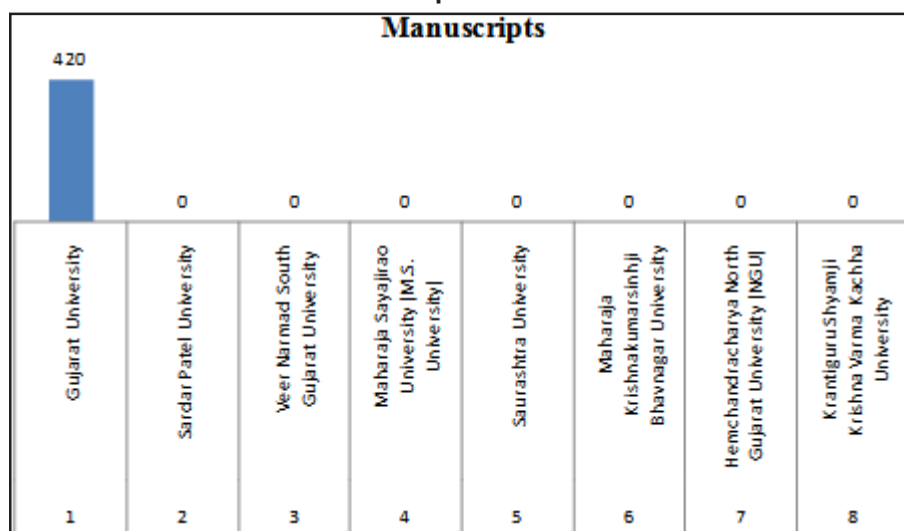
Graph 6



Graph 7



Graph 8





## मध्यप्रदेश में कृषकों के आर्थिक विकास में लघु सिंचाई परियोजनाओं का योगदान एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (सतना जिले के विशेष संदर्भ)

सुशब्रू त्रिपाठी\* डॉ. ए. के. पाण्डेय\*\*

**शोध सारांश** – प्रस्तुत शोध अध्ययन मध्य-प्रदेश सिंचाई परियोजनाओं का योगदान एक विश्लेषणात्मक अध्ययन से यह बात उभरकर सामने आती है कि लघु सिंचाई परियोजनाओं का जितना अधिक (विस्तार) विकास होगा लघु एवं सीमांत कृषकों के आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर होगी यदि लघु सिंचाई परियोजनाओं से सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमि को सुविधा उपलब्ध हो जाए तो आज भी भारत सोने की चिड़ियाँ अर्थात् किसानों की आत्मनिर्भरता का लक्ष्य पूरा हो सकता है।

**शब्द कुंजी** – सिंचाई परियोजनाएँ लघु सिंचाई मध्यम सिंचाई विकास अर्थिक विकास।

**प्रस्तावना** – भारत एक कृषि प्रधान देश है कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक सिंचाई है। देश में कृषि एवं कृषकों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण प्रत्येक खेतों तक सिंचाई का पहुँच न होना है। यह देखा गया है, कि सामान्य एवं गरीब सीमान्त कृषक भी अपने परिवार का भरण-पोषण बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यदि उसके खेत में सिंचाई के साधन हैं।

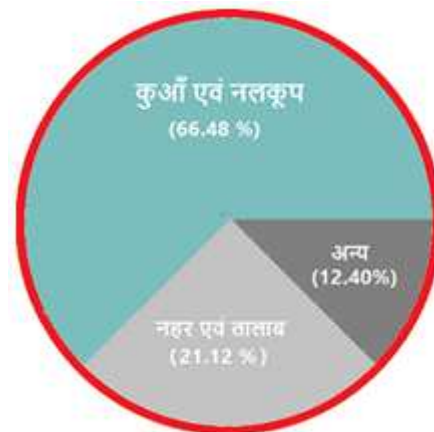
मध्य-प्रदेश में वृहद सिंचाई परियोजनाओं का विकास हुआ है। जैसे भाखड़ा, हीराकुण्ड, बाणसागर, कोसी आदि किन्तु इनका लाभ सभी क्षेत्रों को नहीं मिल पाया है। इनका क्षेत्र सीमित रहा, जिसके कारण देश में असंतुलन रहा है। तो बाद के वर्षों में यह सोचा गया कि लघु तथा मध्यम परियोजनाओं पर ध्यान दिया जाए लगभग 10वीं पंचवर्षीय योजना से मध्यम एवं लघु सिंचाई पर अधिक जोर दिया गया विगत दस वर्षों में मध्य-प्रदेश में सिंचाई का स्वरूप क्रांतिकारी ढंग से बदल रहा है।

प्रस्तावित शोध कार्य में कृषकों में लघु सिंचाई परियोजना का योगदान में मेरा मुख्य उद्देश्य यह रहा कि नगरीय विकास कृषकों को भी कुछ योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके।

**शोध का उद्देश्य** – कृषि विकास के लिए सिंचाई एक आधारभूत साधन है। आजादी के 77 वर्षों बाद भी सिंचित रकबा अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ा किन्तु विगत 10-15 वर्षों से लघु सिंचाई परियोजना पर अधिक जोर दिया जा रहा है। और इससे 100 प्रतिशत भूमि की सिंचित करने का महत्वाकांक्षी उद्देश्य है अतः – इस विषय में शोध की अत्यन्त संभावना है।

1. मध्य-प्रदेश में लघु सिंचाई परियोजनाओं के सम्बंध में शासन की नीति क्या है।
2. लघु सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन अतः उसके विस्तार की जमीनी हकीकत क्या है।
3. लघु सिंचाई परियोजनाओं का किसानों के आर्थिक दशा में क्या परिवर्तन हुआ है।
4. प्रदेश में लघु सिंचाई परियोजनाओं से सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य कैसे पूरा हो सकता है।

### विषय विश्लेषण



**मध्यप्रदेश में विभिन्न सिंचाई के साधनों का प्रतिशत** – मध्य-प्रदेश राज्य विगत वर्षों में कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। बावजूद इसके लघु एवं सीमांत कृषक कृषि मजदूर प्ररूप में परिवर्तित होता जा रहा है। विशेषकर सिंचाई हो रही है। जो छोटे एवं लघु किसानों के लिए मंहगा एवं जोखिमपूर्ण साधन है। इसलिए कृषि का सम्यक विकास के लिए लघु एवं मध्यम सिंचाई सुविधाओं का महत्व बढ़ जाता है।

सिंचाई के प्राचीन स्रोतों द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत जैसे देश में आज भी कुँआ तथा नलकूपों से 66.48 प्रतिशत सिंचाई की जाती है। जबकि नहर तथा तालाब से 21.12 प्रतिशत तथा अन्य सिंचाई के स्रोत 12.12 प्रतिशत है।

कृषि क्षेत्रों के लिए सिंचाई परियोजना मानव शरीर के रक्त वाहिनियों के समान है। आज भारत का अन्यदाता अनेकों जोखिमों एवं शंकाओं से घिरा हुआ है। देश में कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लोग आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। समाचार पत्रों में किसानों की आत्महत्या सड़क दुर्घटना जैसी सामान्य खबर बनती जा रही है समय बितने के साथ निरंतर कृषक परिवार की संतान कृषक बनना नहीं चाहती है। ऐसे तमाम सुलगते सवाल का सही

जवाब लघु सिंचाई परियोजनाओं का सधन जाल बिछाकर ही पाया जा सकता है।

1. विकास में सक्रीय एवं प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना।
2. दीर्घकालीन एवं दुरगामी विकास नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया जायेगा।
3. परियोजना का प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाए कि कृषक इससे लाभ लेने के लिए हमेशा अग्रसर रहे इसके लिए सुझाव देना वित्तिय स्रोतों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों का निर्माण काने में सहायता तथा प्रस्तावित शोध विषय पर आर्थिक शोध से सिंचाई परियोजनाओं के विकास की नीति निश्चित कर विकास के पहलुओं पर विचार एवं सुझाव प्रस्तुत करने से कृषक तथा अन्य उपभोगी का हित संवर्धन होगा।
4. वित्तिय स्रोतों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों का निर्माण करने में सहायता तथा प्रस्तावित शोध विषय पर आर्थिक शोध से सिंचाई परियोजनाओं के विकास की नीति निश्चित कर विकास के पहलुओं पर विचार एवं सुझाव प्रस्तुत करने से कृषक तथा अन्य उपभोगी का हित संवर्धन होगा।

**निष्कर्ष** - प्रस्तुत शोध में यह बात सामने आयी है कि लघु सिंचाई परियोजनाओं का वर्तमान में सरकार द्वारा जो विस्तार किया गया है। क्या उनका लाभ उन कृषकों तक पहुँच रहा है या नहीं यदि भारत जैसे कृषि

प्रधान देश में सिंचाई की व्यवस्था पर्याप्त रूप से प्राप्त हो जाये तो कृषि क्षेत्र में विकास आज भी हो सकता है। और जिन क्षेत्रों को सिंचाई की मुख्य आवश्यकता है उन तक इस योजना व्यवस्था को पहुँचाने तथा परियोजनाओं के बारे में कृषकों को जागरूक बनाने की आवश्यकता है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थ शास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था, डॉ. जे.पी. मिश्रा, डॉ. जे. सी. पंथ, सहित्य भवन पब्लिकेशन
2. शोध कार्य प्रणाली, रंजीत कुमार, सहित्य भवन पब्लिकेशन
3. भारतीय अर्थव्यवस्था, चतुर्भुज मामोरियाँ, सहित्य भवन पब्लिकेशन
4. रिसर्च गेट (मिनिंग एण्ड टाईपस ऑफ रिसर्च हाईपोथिसिस, पंताजलि मिश्रा, दिसम्बर 2016
5. मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग, सिंचाई निर्देश पुस्तिका, 2013
6. संख्यिकी के सिद्धांत, डॉ. एम. एस. शुक्ल, डॉ. शिवपूजन सहाय, सहित्य भवन पब्लिकेशन संस्करण 2019
7. उच्चतर आर्थिक सिद्धांत व्यष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण, डॉ. एच. एल. आहुजा, एस चंद एण्ड कम्पनी प्रा. लि. रामनगर, नई दिल्ली
8. अर्थिक विकास आयोजन तथा पर्यावरण, प्रो. एस. एन. लाल, डॉ. एस. के. लाल, शिवम् पब्लिशर्स अलोपीबाग रोड, इलाहाबाद

\*\*\*\*\*

## मध्यप्रदेश के कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण का योगदान सतना के सन्दर्भ में

प्रभा सिंह \* डॉ. ए. के. पाण्डेय\*\*

**शोध सारांश** – कृषि के यंत्रीकरण से अभिप्राय भूमि पर मशीनों द्वारा उन कार्यों को करने से जो आसाधारणतया मानव शक्ति व बैल घोड़े या अन्य किसी प्रकार के वाहन पशुओं के द्वारा किये जाते हैं। 'श्रम को पूँजी में बदल देना ही कृषि का यंत्रीकरण है।'

कृषि विकास में नवीन प्रौद्योगिकि में प्रवेश के साथ ही कृषि यंत्रीकरण के कार्य में तेजी आना प्रारंभ हो गया भारत में इसे दो रूप में अपनाया गया।

**प्रथम** – परंपरागत पशुचालित कृषि उपकरणों को स्थान पर डीजल, पवन उर्जा तथा सौर उर्जा से चलने वाले उपकरणों का प्रयोग करना।

**द्वितीय** – देश में विभिन्न कृषि जलवायु तथा अर्थिक समाजिक स्थिति के संदर्भ में भारवाही पशुओं के महत्व एवं उनकी अनिवार्यता को दृष्टि में रखते हुए पशु चालित उपकरणों का प्रतिस्थापन करना है। कृषि उत्पादन में 10 से 15 प्रतिशत क्रापिंग इन टेनसिटी में 5 से 20 प्रतिशत बीज में बचत 15 से 20 प्रतिशत उर्वरक एवं कृषि रसायन में 15 से 20 प्रतिशत और समय एवं श्रम में 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में कृषि यंत्रीकरण की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा कृषि शक्ति की कम एवं अनियमित उपलब्धता और कम होता हुआ जोत का आकार है। देश के कृषि क्षेत्रों के लिए खेत का औसत बिजली उपलब्धता 1975 से 1976 में 0.48 किलोवाट हेक्टेयर से वर्तमान में बढ़कर 1.73 किलोवाट हेक्टेयर जिससे 2015 तक बढ़कर 2.0 किलोवाट हेक्टेयर हो जाने की संभावना थी। अर्थिक समीक्षा 2014-15 के अनुसार भारत में बिजली के वार्षिक उपलब्धता 2013-14 में 162.0 किलोवाट प्रतिघण्टा थी।

**शब्द कुंजी** – यंत्रीकरण, मशीनीकरण, कृषि में कृषकों का योगदान, कृषि नीति, उर्वरक कृषि यंत्र, नई किस्म के उन्नत बीज।

**प्रस्तावना** – प्राचीनकाल से भारत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है। कृषि मूलतः मानव क्षमता पर आधारित है। तब प्रत्येक कृषि कार्य इन्हीं पर आधारित है। जिसमें अधिक समय एवं लागत लगती थी पर उत्पादन कम होता था औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात भारत में लगभग 100 वर्ष बाद 1960 से 1965.66 कृषि में कृषि यंत्रीकरण प्रारंभ हुआ।

भारत में किसानों द्वारा कृषि कार्य पुराने औजार लोहे तथा लकड़ी के स्थानीय कारीगरों द्वारा बानाये जाते थे जिनमें किसी भी प्रकार का शक्तिकरण इंजन नहीं होते थे इनका प्रयोग मनुष्य या पशुओं के माध्यम से किया जाता था। इन औजारों का प्रयोग सीमित माध्यम में किया जाता था किन्तु कृषि यंत्रीकरण अर्थात् शक्तिचालित इंजन के माध्यम से कृषि में तीव्रगति से वृद्धि हुई क्योंकि कृषि यंत्रीकरण में कृषि कार्य में काफी विस्तार हुआ। कृषि यंत्रों के कारण बंजर भूमि को भी कृषि योग्य बनाया गया और कृषि में वृद्धि होने की वजह से यह विश्वास हो गया कि कृषि यंत्र के बिना अच्छी कृषि करना संभव नहीं।

कृषि यंत्र का अर्थ है कि पशुओं तथा मानव द्वारा हो रही शक्ति को मशीनों के रूप में परिवर्तित किया जाये जहाँ किसानों को 6-7 घंटों में मेहनत करके हल से खेती करते पड़ती थी। वहीं पर ट्रैक्टर से आधे घंटे में जोताई और बोवाई हो जाती है।

जहाँ पर उर्वरक खाद डालने के लिए हाथों का इस्तमाल करते थे वहाँ पर ड्रिल द्वार खेतों पर काम करे तो और भी अच्छी तरह पूर्ण किया जा सकता है।

उसी प्रकार फसल काटने का भी कार्य हाथों की अपेक्षा मशीनों से करने पर कम समय में ही आसानी से खेती की काटाई हो जाती है।

भारत में 60 एवं 70 के दशक में कृषि एवं खाद निर्भरता का अत्याधिक दबाव रहा। इसी कारण 1965-66 में देश में हरितक्रांति का शुभारंभ हुआ जिसमें कृषि यंत्रों का आधुनिक यंत्रों को प्रयोग एक महत्वपूर्ण तर्क रहा और इसी का परिणाम रहा है। कि देश तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या की आदि की आवश्यकता को पूरा करने में संक्षम हुआ है। साथ श्रमिकों की अर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। आज स्थिति यह है कि मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास कृषि यंत्रीकरण को विशेष योगदान रहा है। परिणाम स्वरूप विगत वर्षों में कृषि कार्य को पुरस्कार प्राप्त हुआ। यंत्रीकरण का अर्थ खेती के सभी क्रियाओं में खेती करने से लेकर काँटने तथा बेचने तक यंत्रों का प्रयोग होने से भारत में कृषि विकास के लिए यंत्रों का सहयोग महत्वपूर्ण हो जाता है।

### भारतीय कृषि में मशीनीकरण का स्तर

खेती का संचालन	मशीनीकरण का प्रतिशत
मृदा का काम और बीज चयन प्रपात	40 प्रतिशत
चयन प्रपात	29 प्रतिशत
बीज रोपण और रोपाई पौधे संरक्षण	34 प्रतिशत
काटई या थ्रेसिंग	37 प्रतिशत
	गेहूँ और चावल के लिए 60 से 70 प्रतिशत कम व्यय के लिए 5 प्रतिशत

स्रोत, अर्थिक समीक्षा, 2015-2016

कृषि यंत्रीकरण में प्रगति कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टरों सिचाई तेल इंजन पंप सेटों को जा चाहे डिजल से चालाये या बिजली के प्रयोग से इसके अतिरिक्त ट्यूब वेल अधिक मात्रा में लगाये गये इस प्रकार कृषि में पशुओं

या मानव शक्ति का प्रतिस्थापन संचालन शक्ति के द्वारा किया गया है। जिसमें प्रति हेक्टेयर कृषि क्षेत्र उपभोग बढ़ा है जो निम्न है।

**ट्रेक्टर** - कृषि के लिए ट्रेक्टर का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ा है 1961 से 1962 में 3.887 ट्रेक्टरों की बिक्री हुई है जो बढ़कर 2019-13 में 5.45,757 हो गया है। ट्रेक्टर यह प्रगति विदेशों की तुलना में अब भी कम है 1000 हेक्टेयर भूमि पर भारत केवल 4.45 ट्रेक्टर है जबकि चीन में 9035 तथा पाकिस्तान में 8.79 है।

**पावरड्रिल** - भारत में 1961-62 में मात्र दो पावर ड्रिल थे। 2013-13 में 47000 पावर ड्रिल विक्रय हुए।

सिंचाई की प्रगति में आज भी बाये जाने वाले 1413.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र 781 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अर्थात् 33 प्रतिशत भाग मानसून पर निर्भर है। फिर भी योजनाकाल में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि हुई है। 1950-51 में 2.3 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित था जो कि बढ़कर 2013-14 में 9.58 करोड़ हेक्टेयर हो गया सिंचाई हेतु दो प्रकार के पंप सेटों प्रयोग में लाये जाते हैं एक विद्युत चलित दूसरा डीजल चलित कृषि में 1950-51 में 0.77 लाख पंप देश में प्रत्येक 7 लाख नये पंप सेट लग जाते हैं।

उर्वरकों कृषि में महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रयोग अधिक करने लगा है। 1960-61 में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग 2.9 लाख टन हो गया है। यदि उर्वरकों को उचित मात्रा में पार्याप्त सिंचाई सुविधा के साथ प्रयोग किया जाये तो उत्पादन में दो से चार गुना वृद्धि संभव हो जाती है। भारत में हरितक्रांति के अन्तर्गत 1966-67 में अधिक उपज देने वाले किस्मों के बीजों का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ समय अधिक उपज देने वाले किस्मों के अन्तर्गत 1.9 फसलों को कीटाणु व रोगों से बचाकर पौधे संरक्षण द्वारा उत्पादन होने वाली बड़ी हानि को रोका जा सकता है। पौधे संरक्षण हेतु कीटनाशक का उपयोग किया जा सकता है। वर्ष 2006-07 के दौरान कीटनाशकों का उपयोग 48000 टन हुआ।

### उद्देश्य :

1. कृषि यंत्रीकरण का विकास व आधुनिकीकरण का अध्ययन करना।
2. कृषि यंत्र नवीनीकरण में उपयोग में लाये जाने वाले साधनों का गहराई से अध्ययन करना।
3. कृषि यंत्रीकरण में उपयुक्त उन्नतबीज जैविक एवं रासायनिक खाद सिंचाई विभिन्न मशीनीकरण का अध्ययन।
4. कृषि यंत्रीकरण का परिस्थिति की पर प्रभाव का गहन अध्ययन।
5. कृषि यंत्रीकरण से किसान भाईयों के सामाजिक अर्थिक स्तर पर आये बदलाव को ज्ञात करना।
6. क्षेत्र में कृषि यंत्रीकरण के लिए आधारभूत सुविधाओं को अध्ययन।
7. कृषि यंत्रीकरण की प्रक्रिया की कमियों को ढूँढना तथा दूर करके सूझाव देना।

**शोध प्रविधि** - प्रस्तुत शोध पत्र विवराणात्मक प्रवृत्ति का है जिसमें तथ्य संकलन के द्वितीय स्रोतों का प्रयोग किया गया है। इस शोध पत्र में समाचार पत्र पत्रिकाएँ, एवं इंटरनेट का प्रयोग किया गया है।

**विषय का विश्लेषण** - कृषि यंत्रीकरण को दो रूपों अपनाया गया है। प्रथम परंपरागत पशुचालित कृषि उपकरणों के स्थान पर डीजल पवन उर्जा तथा सौरउर्जा से चने वाली यंत्रों का प्रयोग किया गया है।

द्वितीयक देश में विभिन्न कृषि जलवायु तथा सामाजिक अर्थिक स्थितियों के संदर्भ में पशुओं के महत्व एवं उनकी अनिवार्यता को दृष्टि में रखते हुए पशु चालित उपकरणों की जगह कृषियंत्रीकरण में सबसे अधिक ट्रेक्टरों उत्पादन साथ भारत में इस उत्पादन में विश्व में सबसे आगे है।

आर्थिक समीक्षा 2012-13 के अनुसार कृषि एवं यंत्रीकरण उत्पादन और कृषि उत्पादन में 10 से 15 प्रतिशत एवं 5 से 20 प्रतिशत बीज में खपत उर्वरक एवं कृषि रसायन में 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में कृषि यंत्रीकरण की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा कृषि शक्ति कम एवं अनियमित उलब्धता और कम होता हुआ जोत का आकार है। देश में कृषि क्षेत्रों के लिए औसत बिजली उपलब्धता 1975-76 में 0.48 वॉट हेक्टेयर हो गया है। जिससे 2015 तक बढ़ाकर 2.0 किलोवॉट हेक्टेयर हो जाने की संभवना है। 2014-15 के अनुसार भारत के बिजली के प्रति वार्षिक उपलब्धता में 162.0 किलोवॉट है। भारत में मशीनीकरण का स्तर विकसित देशों में 90 प्रतिशत की तुलना में औसतन 25 प्रतिशत है।

**कृषि यंत्रीकरण से लाभ** - कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि में यंत्रीकरण का बहुत योगदान है। यंत्रीकरण उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों बढ़ती है। यंत्रीकरण में कम समय में अधिक कार्य कुशलता के साथ किया जा सकता है। कृषि यंत्रीकरण से निम्न लाभ हो सकते हैं।

1. कृषि उत्पादकता में 12 से 34 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हो सकती है।
2. बीज -खाद ड्रिल से 20 प्रतिशत बीज तथा 15 से 20 प्रतिशत खाद की बचत होती है।
3. फसल संघनता को 05-12 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
4. कृषकों की कुल आमदनी 30-50 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है।
5. कृषियंत्रीकरण में बहुफसली को प्रोत्साहन मिलता है। जिसे कृषि वर्ष में दो से तीन विभिन्न प्रकार की फसले उत्पादित कर पाते हैं।
6. कृषि यंत्रीकरण में उत्पादन लागत कम लगती है जिससे उपभोक्ताओं के कृषि उपज के मूल्य कम देने पड़ते हैं।
7. कृषि यंत्रीकरण में किसानों की आय में वृद्धि होती है। एवं भारी कार्यों को सरल व सुगम बनाता है और उनके समय की भी बचत हो जाती है।

### निष्कर्ष :

**कृषि यंत्रीकरण में समीक्षा के आधार पर निम्न निष्कर्ष है।**

1. यंत्रीकरण का विकास बड़ा प्रभावी प्रतीत होता है। यह संक्षेप रूप से इतना प्रभावशाली नहीं है। विशेषकर जब इसकी तुलना उन्नत देशों में यंत्रीकरण के साथ या भारतीय कृषि के आधार के संदर्भ में किया जाय।
2. यंत्रीकरण भारतीय कृषि हुआ भी है वह मुख्यतः समृद्ध किसानों तक सीमित है। छोटे किसान जो भारतीय किसान जनसंख्या का मुख्य भाग है। यंत्रीकरण की प्राप्ति से आछुते ही है। यह बात निन्दनीय है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप किसानों जनसंख्या असमानता में वृद्धि होती है।
3. यंत्रीकरण की प्रक्रिया का अभिप्राय उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन है। अर्थात् प्रसाधन रहने की अपेक्षा पूँजीप्रधान बन जाती है। भारतीय कृषि के विकास की वर्तमान अवस्था में जो की बहुत अधिक मात्रा में बेरोजगार श्रम उपलब्ध है। यंत्रीकरण में जल्दबाजी करने से आवाच्छनीय अर्थिक विकृतियाँ और आसामाजिक तानाव उत्पन्न हो जाते हैं। किन्तु इस संबंध में उल्लेखनीय अपवाद है।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कृषि अर्थशास्त्र, ऋषि कुमार गोविल, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ आकदमी
2. भारतीय अर्थव्यवस्था, रुद्रदत्त के.पी.एम. सुन्दरम्, एम. चन्द्र कम्पनी लि., रामनगर, नई दिल्ली
3. भारतीय अर्थव्यवस्था, डॉ. के मिश्र एवं बी.के. पूरी, हिमालया पब्लिशिंग हाउस
4. समाचार पत्र- दैनिक भास्कर, पत्रिका दैनिक जागरण पत्रिकाये मध्यप्रदेश, संदेश, कुरुक्षेत्र



## बृहस्पति की दृष्टि के आधार पर उसके केन्द्राधिपति दोष का विश्लेषण

### अभिषेक आर्य \*

**प्रस्तावना** - बृहस्पति नवग्रहों के क्रम में पाँचवा ग्रह माना गया है। इसे शुभ ग्रहों की श्रेणी में स्वीकार किया गया है, किंतु ये सदा शुभकारी हो यह आवश्यक नहीं। कुंडली में केन्द्रभावों का स्वामी होने पर उसे कुछ दोषयुक्त माना गया है। प्रस्तुत शोध बृहस्पति की दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में, इसके इसी केन्द्राधिपति दोष के अध्ययन पर आधारित है।

**उद्देश्य** - बृहस्पति के केन्द्राधिपति दोष में उसकी पूर्णदृष्टि की भूमिका ज्ञात करना।

**परिसीमा** - जन्मचक्र के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम तथा दशम भावसमूह को केन्द्र की संज्ञा दी गयी है। प्रथम भाव को लग्न भी कहा जाता है एवं इसके स्वामी को सदा शुभ माना गया है। इस कारण प्रस्तुत शोध हेतु केन्द्राधिपति दोष विचार में प्रथम भाव का अध्ययन नहीं किया गया है।

केन्द्राधिपति दोष तब प्रबल माना जाता है जब केन्द्र का स्वामी केन्द्र (प्रथम भाव को छोड़कर) में ही स्थित हो। अतः शोधकार्य में बृहस्पति की दृष्टि का विचार उसके केन्द्र में स्थित होने के उपरांत ही किया गया है।

बृहस्पति की दृष्टि से तात्पर्य है उसकी पूर्ण दृष्टियाँ अर्थात् पंचम, सप्तम एवं नवम।

बृहस्पति का केन्द्राधिपति दोष विचार

**बृहस्पति की दृष्टि की विशेषता** - बृहस्पति जिस भी भाव में स्थित होता है उस भाव से गिनने पर क्रमशः पंचम, सप्तम एवं नवम भाव पर उसकी पूर्णदृष्टि मानी जाती है। इस ग्रह की दृष्टि की यह विशेषता है कि यह जिस भाव पर होती है उस भाव को पुष्ट कर उसके फलों में वृद्धि करती है।

**केन्द्राधिपति दोष** - बृहत्पाराशरहोराशास्त्र एवं लघुपाराशरी नामक ग्रंथों में इस दोष का विशेष उल्लेख है। इसके अनुसार यदि सौम्य ग्रह (गुरु, शुक्र, निष्पाप बुध एवं पूर्ण चंद्र) केन्द्र स्थानों के स्वामी होने पर तो शुभफलदायक नहीं होते हैं।

**बृहस्पति का केन्द्राधिपत्य** - बृहस्पति धनु एवं मीन राशि का स्वामी है। मिथुन, कन्या, धनु एवं मीन लग्न में बृहस्पति केन्द्र का स्वामी बनता है। मिथुन लग्न में सप्तम तथा दशम भाव का स्वामी होने से बृहस्पति केन्द्राधिपति होता है। कन्या लग्न में चतुर्थ तथा सप्तम भाव का स्वामी होने से बृहस्पति केन्द्राधिपति होता है। धनु लग्न में प्रथम भाव के अतिरिक्त चतुर्थ भाव का स्वामी होने से बृहस्पति केन्द्राधिपति कहलाता है। मीन लग्न में प्रथम भाव के साथ-साथ दशम भाव का स्वामी होने से बृहस्पति केन्द्राधिपति कहलाता है।

**केन्द्रस्थ बृहस्पति की दृष्टि के दुष्परिणाम** - मिथुन लग्न की कुंडली में यदि बृहस्पति चतुर्थ भाव में हो तो वह कन्या राशि में स्थित होगा। उसकी

पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी जिससे अष्टम भाव को बल मिलेगा। फलस्वरूप भाग्यस्थान से द्वादश होने के कारण अष्टम भाव की वृद्धि भाग्यस्थान के लिये हानिकारक सिद्ध होगी। इसकी सप्तम दृष्टि अपनी ही राशि मीन पर होगी फलतः यह दशम भाव से संबंधित शुभफल देगा किंतु एकादश (लाभ) भाव की हानि करेगा। इसी प्रकार इसकी नवम दृष्टि लग्न से द्वादश पर होगी अतः द्वादश भाव की वृद्धि होगी, फलतः प्रथम भाव का हास होगा। अतएव इस प्रकार स्थित बृहस्पति प्रथम एवं नवम भाव के शुभफलों का हास करेगा। चूंकि यह परिस्थिति शुभ भावों के लिये हानिप्रद है अतः दोषयुक्त मानी जायेगी।

अब, यदि बृहस्पति सप्तम में स्थित हो तो धनु राशि में स्वगृही होगा। इस कारण इसे विशेष बल मिलेगा। यहाँ से इसकी पूर्णदृष्टि एकादश, प्रथम एवं तृतीय भाव पर होगी। इस स्थिति पर बृहस्पति प्रथम भाव के लिये वृद्धिकारक है किंतु नैसर्गिक रूप से द्वितीय भाव का कारक होते हुए उससे छठे अर्थात् सप्तम भाव में स्थित होकर उससे द्वादश अर्थात् प्रथम भाव को देखने से धान एवं कुटुंब के सुख हेतु हानिप्रद है। साथ ही साथ इसकी दृष्टि तृतीय भाव एवं एकादश भाव पर भी है जिसके फलस्वरूप यह सुखभाव अर्थात् चतुर्थ से द्वादश (लग्न से तृतीय) एवं चतुर्थ से अष्टम (लग्न से एकादश) की वृद्धि कर रहा है। इस प्रकार यह चतुर्थ भाव के फलों के लिये हानिकारक सिद्ध होगा। अतः यह कहा जा सकता है कि सप्तमस्थ सप्तमेश बृहस्पति जीवन में सुख का हास करेगा।

अब, यदि मिथुन लग्न में बृहस्पति दशम भाव में हो तो वह स्वराशि में होगा एवं उसकी दृष्टि द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठ भाव पर होगी। धान-कुटुंब एवं सुखभाव हेतु यह शुभ होगी किंतु चतुर्थ पर दृष्टि होने से यह पंचम भाव हेतु अशुभकारक सिद्ध होगी चूंकि चतुर्थ भाव पंचम भाव से द्वादश स्थान है। साथ ही इसकी दृष्टि षष्ठ भाव पर भी होगी जिसके कारण यह इस भाव के अशुभ कारकत्वों की भी वृद्धि करेगा। षष्ठ भाव सप्तम भाव से भी द्वादश है अतः बृहस्पति की दृष्टि के कारण उसकी वृद्धि होने पर वैवाहिक समस्याएं भी प्रकट होंगी। इस प्रकार यह स्थिति पंचम-सप्तम भावों के शुभ फलों को स्थगित कर देगी, अतः दोषयुक्त है।

कन्या लग्न में चतुर्थ भाव में स्थित बृहस्पति अपनी मूल-त्रिकोण राशि पर स्थित होकर दिशाबल प्राप्त करेगा। इस कारण उसकी दृष्टि विशेष बलवती होगी। सप्तम भाव में स्थित होने पर बृहस्पति स्वराशिस्थ ही होगा अतः इस स्थिति पर भी उसकी दृष्टि बलवती होगी किंतु दशम भाव में स्थित होने पर उसकी दृष्टि में अपेक्षाकृत कम बल होगा क्योंकि मिथुनस्थ बृहस्पति शत्रुराशिस्थ है अतः उसका व उसकी दृष्टि का बल कुछ कम हो जायेगा।

भावो पर इन दृष्टियों से संबंधित पूर्वोक्त फल (4.4.1) यहाँ भी दृष्टिगोचर होंगे।

धनु लग्न तथा मीन लग्न में बृहस्पति केन्द्रेश के साथ-साथ लग्नेश भी होता है अतः उसके केन्द्राधिपति दोष का कुछ ह्रास होगा, तथापि केन्द्र में उसकी दृष्टि और स्थिति के संयोग से उत्पन्न दुष्फल अल्पमात्रा में ही सही दृष्टिगोचर अवश्य होंगे क्योंकि उसकी दृष्टि सदैव वृद्धिकारक होती है एवं अशुभ स्थानों की वृद्धि करने की अवस्था में यह दृष्टि हानिकारक सिद्ध होगी।

**निष्कर्ष** – बृहस्पति के केन्द्राधिपति दोष में उसकी दृष्टि की विशेष भूमिका होती है। जब बृहस्पति केन्द्र में स्थित होता है तब उसकी दृष्टि अशुभ भावों पर भी पड़ती है जिसके कारण वह अशुभ फलों का वृद्धिकारक बन जाता है। इस

कारण दोषयुक्त माना जाता है।

चतुर्थ भावस्थ बृहस्पति भाग्य और लग्न के फलों का ह्रास करता है, सप्तम भावस्थ बृहस्पति सुखभाव का ह्रास करता है एवं दशम भावस्थ बृहस्पति पंचम और सप्तम भाव के शुभफलों का ह्रास करता है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. लघुपाराशरी/रंजन पब्लिकेशन्स, दिल्ली/वर्ष 2010/पृष्ठ 18,21,34.
2. उत्तरकालामृत/रंजन पब्लिकेशन्स, दिल्ली/वर्ष 2010/पृष्ठ 242.
3. बृहत्पाराशरहोराशास्त्र/चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी/वर्ष 2009
4. फलदीपिका /रंजन पब्लिकेशन्स, दिल्ली/वर्ष 2009/पृष्ठ 51

\*\*\*\*\*

## मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन पर कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव एवं परिवर्तन की संभावनाएं

डॉ. आशीष नीलकंठ \*

**शोध सारांश** - वर्तमान समय में कोरोना वायरस महामारी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। संक्रमण के प्रभाव से बचने के लिए सामाजिक दूरी, व्यक्तिगत सुरक्षा आदि अनेक सुरक्षात्मक साधनों को अपनाते हुए व्यक्ति के जीवन जीने के तरीकों में परिवर्तन आया है। वर्तमान परिदृश्य में उच्च शिक्षा की दृष्टि से मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के काम करने के तरीकों में भी परिवर्तन होना संभावित है। इसी परिवर्तन की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता ने 'मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन पर कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव एवं परिवर्तन की संभावनाओं' पर अध्ययन कर एक उचित निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास किया है।

**शब्द कुंजी** - कोरोना वायरस महामारी, कार्य-निष्पादन।

**प्रस्तावना** - सेंट्रल फॉर डिमोज कंट्रोल एण्ड प्रीवेंशन के अनुसार कोरोना वायरस, वायरस का एक समूह है जिसके संक्रमण से फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं और व्यक्ति निमोनिया जैसी स्थिति में भी पहुंच सकता है। कोरोना शब्द लेटिन भाषा का है जिसका अर्थ 'क्राउन', 'मुकुट' या 'ताज' होता है। कोरोना वायरस की सतह पर काटे जैसी आकृति होती है जो देखने में ताज जैसी लगती है, इसी कारण इसे कोरोना वायरस नाम दिया गया है। 2019 नोवेल कोरोना वायरस, कोरोना वायरस का एक प्रकार है जिसे सर्वप्रथम चीन के वुहान शहर में देखा गया था। इस कारण इसे शुरुआत में वुहान वायरस या वुहान कोरोना वायरस कहा गया। किन्तु विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जगहों के नामों के आधार पर नाम के स्थान पर 11 फरवरी 2020 को इसे एक नया नाम कोविड-19 (coronavirus disease-19) दिया। यह बीमारी सर्वप्रथम चीन के वुहान शहर में मध्य दिसंबर 2019 में हुई थी। वर्तमान समय में इस बीमारी के लिए कोई भी टीका या दवाई खोजी नहीं जा सकी है। कोविड-19 एक व्यक्ति के छींकने या खासने से हवा में बूंदों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है साथ ही संक्रमित व्यक्ति से वस्तुओं और वस्तुओं से अन्य व्यक्तितक पहुंच जाता है। अतः इसकी संक्रमण की अत्यधिक तीव्रता के कारण मनुष्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

वर्तमान समय में कोरोना वायरस बीमारी ने पूरे विश्व में अपने पैर पसार दिए हैं और उसने एक महामारी का रूप धारण कर लिया है। इसके कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं में अनेक परिवर्तन देखने को मिले हैं।

वर्तमान परिदृश्य में उच्च शिक्षा की दृष्टि से मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के शैक्षणिक कर्मचारियों को भी कार्य के दौरान उनके सहकर्मी व छात्रों से निश्चित दूरी बनाए रखना, टेबल-कुर्सियों, किताबों, दस्तावेजों, उत्तर पुस्तिकाओं आदि ऐसी अनेक सामग्रियों के प्रयोग व आदान-प्रदान से संक्रमण की संभावनाओं के साथ कार्य को पूर्ण करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। इन्हीं परिस्थितियों के कारण शैक्षणिक कर्मचारियों को कार्य के

दौरान अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जिससे उनके कार्य-निष्पादन पर कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव और परिवर्तन की संभावना होगी।

**कार्य-निष्पादन का अर्थ** : किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए किया जाने वाला प्रयत्न 'कार्य' कहलाता है तथा किसी आज्ञा, आदेश, नियम, निश्चय आदि के अनुसार कोई कार्य ठीक तरीके से पूरा करना 'निष्पादन' कहलाता है।

**अध्ययन के उद्देश्य** : शोध अध्ययन के निम्न उद्देश्य हैं-

1. कोरोना वायरस को जानना एवं उसके प्रभाव का अध्ययन करना।
2. मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन पर कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव एवं परिवर्तन की संभावनाओं का अध्ययन करना।

**शोध पद्धति** :

● **निदर्शन पद्धति** : शोधकर्ता द्वारा स्वउद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति का उपयोग शोध कार्य हेतु किया गया।

● **अध्ययन का समग्र** : मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के शैक्षणिक कर्मचारी (प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अतिथि विद्वान) अध्ययन का समग्र है।

● **निदर्शन की इकाई** : स्वउद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति के द्वारा चयनित मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों के शैक्षणिक कर्मचारियों को निदर्शन की इकाई के रूप में चुना गया।

● **निदर्शन का आकार** : स्वउद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति के द्वारा मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के 95 उत्तरदाता (शैक्षणिक कर्मचारी) निदर्शन का आकार है।

● **तथ्यों का संकलन** : तथ्यों के संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्य संकलन पद्धति के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया है।

1. **प्राथमिक स्रोत** : लॉकडाउन की अवधि में प्रश्नावली का निर्माण कर गूगल फॉर्म के माध्यम से प्राथमिक तथ्यों को संकलित किया गया है।

**2. द्वितीयक स्रोत :** किताबें, पत्र-पत्रिकाएं, इंटरनेट एवं मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर जारी जागरूकता संदेशों से द्वितीयक तथ्यों को एकत्रित किया गया है।

**शोध के परिणाम एवं उनकी व्याख्या -** शोध कार्य हेतु शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित प्रश्नावली के माध्यम से संमको का संकलन किया गया था। जिसमें कुल 20 प्रश्नों का निर्माण किया गया था। इस शोध का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों के शैक्षणिक कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन पर कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव एवं परिवर्तन की संभावनाओं का आंकलन करना था। शोध के निम्न परिणाम सामने आये जिनकी व्याख्या इस प्रकार है- शोध कार्य में कुल 15 प्राध्यापक, 13 सह प्राध्यापक, 34 सहायक प्राध्यापक एवं 31 अतिथि विद्वानों ने भाग लिया। जिनकी उम्र 20 से 65 वर्ष के मध्य थी। प्रश्न क्रमांक 05 के उत्तर में सर्वाधिक 08 उत्तरदाता मधुमेह रोग से ग्रस्त पाये गये। प्रश्न क्रमांक 06 के उत्तर में 48.4% कर्मचारियों ने संक्रमण के बचाव पर अधिक ध्यान देने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदर्शित की। प्रश्न क्रमांक 07 के उत्तर में 56.8% कर्मचारियों का मानना है कि उनकी कार्य के प्रति निष्ठा पूर्ववत् ही रहेगी। प्रश्न क्रमांक 08 के उत्तर में 27.4% कर्मचारियों का मानना था कि उनकी कार्य कि गुणवत्ता पर कोरोना वायरस महामारी का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 09 के उत्तर में 55.8% कर्मचारियों का मानना है कि उनके कार्य का समय रोस्टर के अनुसार होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 10 के उत्तर में 43.2% कर्मचारियों का मानना है कि वह कोरोना वायरस महामारी से बचाव हेतु व्यक्तिगत सुरक्षात्मक साधनों को अपनाते हुए अपने कार्य के साथ सामान्यस्थ स्थापित करने में उन्हें लगभग 30 दिनों का समय लग जायेगा। प्रश्न क्रमांक 11 के उत्तर में 27.4% कर्मचारियों का मानना है कि वे कोरोना वायरस महामारी से बचाव हेतु सुरक्षात्मक तरीकों को ध्यान में रखकर कार्य कर सकेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 के उत्तर में 82.1% कर्मचारियों का मानना है कि यदि उनके सहकर्मी में सर्दी, खासी व जुकाम आदि के लक्षण दिखाई देते हैं तो वह उन्हें चिकित्सकिय सलाह हेतु प्रेरित करेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 के उत्तर में 71.6% कर्मचारियों का मानना है कि वे संकाय विकास कार्यक्रमों में सुरक्षात्मक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सहभागिता करेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 के उत्तर में 45.3% कर्मचारियों का मानना है कि महाविद्यालय में आयोजित होने वाले सेमिनार, वर्कशॉप, सिंपोजियम आदि का आयोजन ऑनलाईन आधार पर करेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 के उत्तर में 77.9% कर्मचारियों का मानना है कि एनएसएस, एनसीसी, वार्षिकोत्सव आदि गतिविधियों का आयोजन कोरोना वायरस महामारी को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण करवाना चुनौतिपूर्ण होगा। प्रश्न क्रमांक 16 के उत्तर में 56.8% कर्मचारियों का मानना है कि महाविद्यालय में छात्र हित हेतु कि जाने वाली शासन कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में समय अधिक लगेगा। प्रश्न क्रमांक 17 के उत्तर में 82.1% कर्मचारियों का मानना है कि छात्रों की अधिक संख्या, सामाजिक दुरी के नियमों व तय समय में कार्य को पूर्ण करना चुनौतिपूर्ण होगा। प्रश्न क्रमांक 18 के उत्तर में 41.1% कर्मचारियों का मानना है कि वे अपना मुल्यांकन कार्य घर पर रहकर पूर्ण करना पसंद करेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 के उत्तर में 52.6% कर्मचारियों का मानना है कि पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु उन्हें

ऑनलाईन कक्षाएं भी संचालित करना पड़ेगी। प्रश्न क्रमांक 20 के उत्तर में 68.4% कर्मचारियों का मानना है कि वे विद्यार्थियों की समस्या का समाधान सोशल मिडिया के माध्यम से करेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 के उत्तर में 38.9% कर्मचारियों का मानना है कि कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव से बचने के लिए विद्यार्थियों से सुरक्षा संबंधी तरीकों का पालन करवाना अत्यधिक कार्य होगा।

**शोध का निष्कर्ष :** शोध के परिणाम को देखे तो कोरोना महामारी के प्रभाव से शैक्षणिक कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन पर प्रभाव एवं परिवर्तन अवश्य देखे गए हैं। शैक्षणिक कर्मचारियों में अधिकतर किसी रोग से ग्रसित नहीं होने के कारण संक्रमण का खतरा उन पर कम होगा परन्तु कर्मचारियों को कार्य के दौरान मनोवैज्ञानिक रूप से संक्रमित होने का भय रहेगा जो उनके कार्य-निष्पादन को प्रभावित करेगा। कर्मचारियों के कार्य के प्रति निष्ठा पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से कर्मचारी रोस्टर के अनुसार महाविद्यालय में कार्य करना चाहते हैं जिसके कारण उनका कार्य का समय कम हो जाएगा। इसी प्रकार कर्मचारियों का सभी सुरक्षात्मक साधनों का प्रयोग करते हुए कार्य से सामंजस्य स्थापित करने के साथ-साथ सुरक्षा में चूक होने की संभावना भी बनी रहेगी। कर्मचारियों को महाविद्यालय में सेमिनार, वर्कशॉप, सिंपोजियम आदि करवाने के लिए नए तरीकों का प्रयोग करना होगा। इसी प्रकार संकाय विकास कार्यक्रमों में भी सुरक्षा व परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही उपस्थित हो पाएंगे जो संकाय विकास को प्रभावित करेंगे। इसी प्रकार प्रवेश, परीक्षाएं, छात्र हित की विभिन्न योजनाएं, एनसीसी, एनएसएस, वार्षिकोत्सव आदि को सुरक्षा की दृष्टि से पूर्ण करने में कर्मचारियों को अत्यधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सुरक्षा का ध्यान एवं छात्रों से सुरक्षात्मक साधनों का प्रयोग करवाना आदि कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त कार्यभार होगा। अतः उपरोक्त नवीन परिस्थितियों में कार्य करना कर्मचारियों के लिए अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है। इस कारण उनके कार्य-निष्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावनाएं अधिक है।

### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

#### **किताबें :**

1. डॉ. अवस्थी, अमरेश्वर एवं महेश्वर, श्रीराम, (2011), लोक प्रशासन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा.
2. मित्तल, राकेश कुमार (2009), लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार, अनामिका पब्लिकेशन, नई दिल्ली.
3. पुनिया, किरण (1997), भारत में प्रशासनिक अभिजन, वलासिक पब्लिकेशन, जयपुर.

#### **पत्र-पत्रिकाएं :**

1. 2020, मार्च 30, इंडिया टुडे.
2. 2020, अप्रैल 02, दैनिक भास्कर.

#### **वेबसाइट्स :**

1. [www.who.int](http://www.who.int)
2. [www.mp.health.gov.in](http://www.mp.health.gov.in)



## दबाव समूहों का बदलता स्वरूप

देवेश कुमार\*

**शब्द कुंजी** – राजनीतिक दल, अनौपचारिक, संस्थागत एवं संगठनिक।

**प्रस्तावना** – राजनीतिक भागीदारी एवं राजनीतिक चेतना का विकास हो जाने के कारण जनता राजनीति का केन्द्र हो गयी है। इसके लिए हमें संस्थाओं के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं जो व्यक्ति को शासन के साथ जोड़ती हैं। यहाँ व्यक्ति का मतलब समूह से होता है। बहुलवादियों ने सर्वप्रथम समूहों का महत्व बताया है। हित समूह शब्द का प्रयोग आमण्ड करते हैं। आमण्ड हर समूह का आधार एक विशेष हित मानते हैं। इसलिए हित समूह नाम अच्छा है। ओ०बी० की दबाव समूह शब्द का प्रयोग ज्यादा ठीक मानते हैं क्योंकि ये समूह ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। ये ज्यादा ठीक मानते हैं ओ०बी० की। फाइनेर दबाव समूह एवं हित समूह दोनों को ठीक मानते हैं यह कार्यपरक है। दबाव समूह ज्यादा राजनीतिक सक्रियता दिखाते हैं जबकि हित समूह एक निश्चित कार्य करते हैं। दबाव समूह सिर्फ दबाव डालते हैं वे शासन में भाग लेने की चेष्टा नहीं करते हैं। राजनीतिक दल भी समग्रित रूप है दबाव समूहों को। दबाव समूह एक विशेष औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से संगठित हो सकते हैं। ये मुख्यतया अपने विशेष हितों के संरक्षण के लिए समूह वैधानिक एवं अवैधानिक तरीके अपनाते हैं। राजनीति में दबाव डालना मुख्य कार्य है। सारे दबाव समूह हमेशा गलत रास्ता नहीं उठाते हैं। दबाव समूह सार्वत्रिक प्रकृति के होते हैं क्योंकि व्यक्ति अकेले में नहीं रह सकता वह सामाजिक होता है। कुछ बड़े मुद्दे लेकर बनते हैं उन्हें हम स्वार्थी नहीं कह सकते। कुछ का क्षेत्र संकीर्ण होता है। कुछ एक हित उठाते हैं, हित खत्म होने पर वे खत्म हो जाते हैं। दबाव समूह प्रकृति, परिस्थिति, संस्थिति के आधार पर गठित होते हैं। इनकी विशेषतायें निम्नलिखित हैं:-

1. दबाव समूह हित रखते हैं जबकि राजनीतिक दल शासन की नीति बनाते हैं।
2. राजनीतिक दल के पीछे कई दबाव समूहों का हाथ होता है।
3. कुछ राजनीतिक दल अप्रत्यक्ष रूप से दबाव समूहों द्वारा बनते-बिगड़ते रहते हैं। फाइनेर ने विधायिका के पीछे अज्ञात विधायिका की बात की है।

**वर्गीकरण** – आमण्ड और बाल निम्नलिखित आधार मानते हैं:-

1. संरचना।
  2. सदस्यों के बीच सम्बन्ध।
- क्या मतलब है?

**काण्डेल का वर्गीकरण:-**

1. साम्प्रदायिक – जिसका आधार सामुदायिक सामाजिक आधार होते हैं, ये जाति के आधार पर हैं।
2. सांगठनिक औपचारिक समूह – ये औपचारिक रूप से गठित होते

हैं, इनमें लक्ष्य, सदस्यता इत्यादि होते हैं।

(1) परम्परागत – परम्परा पर आधारित।

(2) संस्थागत – संख्या पर आधारित

**(इ) सांगठनिक संगठन:**

(1) संरक्षणात्मक – हितों की सुरक्षा, शिक्षक समूह, विद्यार्थी समूह, मजदूर समूह।

(2) उत्थानात्मक – गांव, महिला, आदिवासी, जानवरों का समूह।

**आमण्ड का वर्गीकरण** – यह निम्नलिखित है:-

1. **संस्थात्मक/संरचनात्मक** – विभिन्न संस्थाओं में सक्रिय होते हैं। वे विभिन्न संस्थाओं के कार्यों को प्रभावित करते हैं।

2. **सांगठनिक** – सदस्यों के आपसी सम्बन्धों के आधार पर बनते हैं। ये औपचारिक/ अनौपचारिक होते हैं।

3. **गैर-सांगठनिक** – इसमें लक्ष्य प्रमुख होता है विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये संगठित होते हैं।

4. **चमत्कारी समूह** – ये चमत्कारिक रूप से राजनीति को प्रभावित करते हैं। ये विशेष मुद्दे पर हावी होते हैं। ये व्यापक रूप से राजनीति पर प्रभाव डालते हैं। ये अकस्मात् ढंग से गायब भी हो जाते हैं। यह आमण्ड की आलोचना का कारण बना है क्योंकि विभिन्न समूह का जो गलत कार्य है उनको विधान प्रदान कर रहे हैं। यह समूह नहीं है यह तो दबाव डालने का एक तरीका है।

**राबर्ट बोन का वर्गीकरण** – समूह की प्रकृति, कार्य करने का तरीका, सदस्यों का दृष्टिकोण के आधार पर दो तरीके में बांटा –

1. **परिस्थितिजन्य** – ये अपने सदस्यों की परिस्थिति में सुधार लाने की चेष्टा करते हैं।

2. **अभिवृत्तिजन्य** – ये एक विशेष दृष्टिकोण रखते हैं इसी के आधार पर वे पूरे समाज को प्रभावित करने का कार्य करते हैं।

**उदाहरणार्थ** – मानवाधिकार, महिलाधिकार, ट्रेड यूनियन राजनीतिक दल भी दबाव समूह से जुड़ जाते हैं।

**दबाव समूह के तरीके – ये निम्नलिखित हैं:**

**(क) शान्तिपूर्ण तरीके:**

1. प्रचार, मीडिया।
2. सम्पर्क।
3. मंच/गोष्ठी एवं
4. लाबिंग – ये व्यवस्थापिका के अन्दर होती है। ये कानून निर्माण को प्रभावित करती है।

**(ख) अशान्तिपूर्ण तरीके –**

1. धरना

2. हड़ताल एवं
3. भूख हड़ताल

**(ग) आतंकवादी तरीके** – बमबारी, किडनैप इत्यादि।

आतंकवादियों का लक्ष्य नागरिक होते हैं जबकि नक्सवादीयों का लक्ष्य शोषक वर्ग होता है।

**डेविड टूमैन** – ये व्यवहारवादी विचारक हैं। ये समूह की भूमिका एवं समूह के व्यवहार पर ज्यादा जोर दिया है। हमें राजनीतिक समूह को समझने के लिए समूह को समझना होना। प्रक्रिया इन्हीं समूह की गतिविधियों के समुच्चय को कहते हैं। आज हम राज्य से ज्यादा आशा नहीं करते हैं आज समूह की भूमिका बढ़ जाती है। आज युद्ध से भी राज्य की शक्तियों में वृद्धि हो रही है। जैसे:-

1. कार्यपालिका पर अविश्वास ध्यान रोको प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव इत्यादि रोक लगाये जाते हैं।
2. व्यवस्थापिका में समितियों में भी दबाव समूह प्रभावित करते हैं। वे कुछ समितियों के सदस्यों को अपनी तरफ कर लेते हैं। लार्बिंग प्रविधि से वे अपना हित साधती है।
3. न्यायपालिका में दबाव समूह याचिका द्वारा कानून को प्रभावित करते हैं। वे जजों को खरीदते भी हैं। वे न्यायाधीशों के 'सीनियरिटीज' को भी प्रभावित कर पदोन्नति को करवाते हैं।
4. लोक सेवक एक विशाल कानून का क्रियान्वयन करते हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन, निर्णय लेना एवं विधि बनाना इत्यादि को भी प्रभावित करते हैं। कार्यों को क्रियान्वित करते हैं। वे नौकरशाही से सहयोग आसानी से पा जाते हैं। वे भ्रष्ट तरीकों से भी प्रभावित करते हैं।
5. राजनीतिक दलों के चुनाव प्रक्रिया में दबाव समूह, धर्म प्रचार एवं वोटों के लिए राजनीतिक दल प्रभावित करते हैं। वे प्रत्याशियों के चयन को प्रभावित करते हैं।
6. जनमत को दबाव समूह अपने पक्ष में करने के लिए मीडिया, मीटिंग/ गोष्ठी, संचार एवं विभिन्न माध्यमों से जनता से सम्पर्क बनाये रखते हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दबाव समूह की भूमिका महत्वपूर्ण है यह दो प्रकार की होती है-

- नकारात्मक एवं
- सकारात्मक।

आज दबाव समूह नकारात्मक तरीके ज्यादा अपनाते हैं। दबाव समूह क्षेत्रीय, संकीर्ण हितों के प्रणेता एवं खण्डित राजनीति को प्रेरणा देते हैं। वे जनहित, राष्ट्रहित की अवहेलना करते हैं। अस्थिर शासन, शासक को बदलना इनका मुख्य है। वे आज गतिरोध ज्यादा डालते हैं। ये जातिवाद, साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार फैलाते हैं। ये हिंसा की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। ये लोकतंत्र के भक्षक हो सकते हैं।

दबाव समूह के बिना राजनीति में सक्रियता संभव नहीं है। सरकार बनाना, निरंकुश बनने से रोकना एवं जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना इनका कार्य है। ये शासन एवं जनता के बीच सम्प्रेषण का कार्य करती हैं। ये विकासात्मक कार्य को प्रोत्साहित करते हैं। ये शासन की शक्तियों को संतुलित करते हैं। वे शक्तियों का बंटवारा करवा दे तो ये शासन में भूमिका निभाती है। सभ्य समाज की कल्पना दबाव समूहों के बिना संभव नहीं है।

ये सरकार को प्रभावित, बिना सामना किये करते हैं। राजनीति से ज्यादा वे औद्योगिक समाज में सक्रिय है। लोकतंत्र में भी वे सक्रिय हैं। अमरीका में

इन्हें/इसे अदृश्य सरकार या अनौपचारिक सरकार कहते हैं। ये राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर भी काम करते हैं। जाति, धर्म, क्षेत्र में भी पाये जाते हैं। अर्थस्तीन एवं एण्टर कहते हैं कि जितना ही समाज आधुनिक होगा दबाव समूह उतना ही महत्वपूर्ण होता जायेगा।

**दबाव समूह की प्रकृति एवं विशेषतायें :**

1. जब से हमने असंगठित एवं फैले हुए राजनीतिक दल को पाया है तब से दबाव समूह ज्यादा फैल गये हैं। यह भारत में पाया जाता है। महत्व कम ज्यादा बढ़ता रहता है। टूट एवं नयी प्रकृतियां चलती रहती है। उनकी भक्ति बदलती रहती है। मायरन वीनर कहते हैं कि 'राइबल यूनियनियज्म' पाया जाता है कभी-कभी बाहरी तत्व भी प्रभावित करते हैं। वीनर ट्रेड यूनियन को अनिश्चित टूटे हुए मानते है।
2. कम्प्यूनिस्ट्स के सिवाय लोग ट्रेड यूनियन को गैर-राजनीतिक कहते हैं। उद्योगपति, मजदूर एवं सभी लोग ट्रेड यूनियन को सक्रिय रखते हैं। राजनीति को लोग ठीक नहीं मानने लगे हैं। दबाव समूह का राजनीतिक व्यक्तित्व में राजनीतिक द्वि-संस्कृति काल पाया जाता है। अर्थात् कुछ परम्परागत चीजों के कारण राजनीतिक संघर्ष कमजोर पड़ा है। आधुनिकता एवं परम्परागत पाया जाता है। भारतीय समाज में एक साथ दो विचारे चलती है। यद्यपि दबाव समूह अपने लाभ के लिए आधुनिक तरीके अपनाते हो एवं मांगों में कमजोरी आ जाती है।
3. राजनीतिक सहभागिता एवं सिद्धान्त की कमी तथा नीतिगत विश्वास तथा नीतियां समस्या पैदा करती है। उद्योगपति ज्यादातर चुनी सरकार को सहयोग करती हैं। 'बिजनेस ग्रुप' भी भारत में बिखरे रहे हैं। ट्रेड यूनियन कभी-कभी ज्यादा जोश दिखाते हैं परन्तु समझौते बहुत कम पर कर लेते हैं। अराजकता का भी निर्माण नीतिगत आधार पर किया जाता है। भारत में समझौते प्रथम चरण में ही हो पाते हैं। अन्य जगहों में चर्चा के बाद ही बन्द होती है जबकि भारत में बन्द तुरन्त हो जाता है। खास लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है।
4. दबाव समूहों के अस्तित्व स्वतंत्र नहीं हैं। कृषकों का ग्रुप कुछ ज्यादा ही कमजोर है जबकि बिजनेस एवं ट्रेड यूनियन की कुछ ठीक है। ये प्रत्यक्षतः राजनीतिक दलों को सपोर्ट या विरोध करें यह निश्चय नहीं कर पाते हैं जबकि कम्प्यूनिस्ट के ग्रुप ज्यादा ठीक हैं। कांग्रेस का यूनियन 10-15 सालों में कमजोर पड़ा है। दबाव समूहों का ज्यादा योगदान नहीं रहा है। ये भी दल-बदल की राजनीति करने लगे हैं दबाव समूह छोटे लाभ के लिए बड़ा लाभ खो देते हैं।

**कृषक समूह** – भारत किसानों का देश है। यहाँ किसान गांवों में रहते हैं लगभग 60 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं लेकिन उनका राजनीतिक संस्कृति कमजोर है। इनका राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा समूह नहीं है। बड़े किसान सिर्फ अपने हितों के लिए खुद को संगठित करते हैं। प्रथम लोकसभा में लगभग 1/7 ही कृषक थे। दूसरी में 1/3 हो गयी है। जो किसान लोकसभा में जा रहे हैं वे बड़े अमीर हैं। जो खुद चुनाव लड़ सकते हैं। जबकि 70-80 प्रतिशत उद्योगपति हैं। बड़े किसान राज्य स्तर पर भी ज्यादा संगठित नहीं है। ये राजनीतिक दलों को ज्यादा सहयोग भी नहीं कर पाते हैं। 'सीलिंग' एवं कराधान बचाना बड़े किसानों का लक्ष्य होता है।

ये समूह ज्यादा राजनीति में सक्रिय भी नहीं थे। ये आजादी में उद्योगपतियों की अपेक्षा अंग्रेजों के ज्यादा प्रिय थे। उद्योगपतियों ने ज्यादा सक्रियता रखी थी। जबकि जमींदार उतने सक्रिय नहीं रहते थे। सिर्फ कुछ

सूझबूझ वालों ने ही राजनीतिक दलों का साथ दिया था। कांग्रेस ने जमींदारी हटाने की योजना शुरू से ही रखी थी। जमींदारी उन्मूलन इस दल को पहला धक्का था। जमींदारों को हटाकर कांग्रेस ने जनमत प्राप्त किया। कांग्रेस ने इनको मिलाने का भी कार्य किया। बड़े जमींदार भूमि 'सीलिंग' पर दबाव डालने लगे। जमींदार सीलिंग को परिवार के ऊपर व्यक्ति को इकाई मानकर प्रत्येक व्यक्ति को देने की मांग की। तथा कराधान को भी हटाने की मांग की। बागवान, सहकारी फार्म इत्यादि में भी जमीन को छुपाने का प्रयास किया। एक तरह से जमींदारी उन्मूलन ठीक से लागू नहीं हुआ। छोटा किसान पहले काफी प्रभावित हुआ कांग्रेस से परन्तु बाद में कांग्रेस ने इसे ठीक से लागू नहीं किया। विभिन्न दासों के नाम भी जमीन कर दी गयी। डेयरी, बागवानी, सहकारी फर्मों का सारा लाभ बड़े किसानों ने पाया। कांग्रेस गरीब की बात पर खरी नहीं उतरी। अपनी 'गरीबी हटाओ' के अनुसार कांग्रेस कानून को लागू न करवा सकी। 'ज्वाइंट कोऑपरेटिव' पर सीलिंग कानून नहीं बनाया गया।

राल्फ सी वीयर ने 30 प्र०, बिहार का अध्ययन करके बताया कि सहभागी कृषि सिर्फ कानूनी बात है। यह सिर्फ 20 प्रतिशत ही लागू हुआ 80 प्रतिशत दुरुपयोग ही हुआ है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र में यह सफल रहा है। हरित क्रांति के कारण भी जमींदारों को काफी फायदा हुआ। 1980 में सीमान्त कर भी लगाया गया। सरकार को अरबों का घाटा हुआ था क्योंकि सरकार की अवधारणा थी कि संसद, विधानसभा में जमींदार

ही होता है क्योंकि वही चुनाव जीत पाते हैं। मोरारजी देसाई, निजलिंगथा इत्यादि को सिंडीकेट कहा जाता था जो कांग्रेस को नियंत्रित करते थे। इंदिरा गांधी द्वारा विभिन्न 'प्रिवीपर्स' राष्ट्रीयकरण किया गया। भूमि वितरण पुनः शुरू किया गया राज्य सूची के बिगड़े विषयों पर केन्द्र सूची में डालने की बात कही। परन्तु जमींदारी उन्मूलन में कोई भी परिवर्तन करने में सफल नहीं रही। पश्चिम बंगाल में भूमि वितरण काफी प्रभावी रहा है। मध्य भूमि जमींदार ज्यादा भ्रष्टता फैलाते हैं। स्थानीय स्तर के किसान भूमिहीन तथा संगठनहीन है। सरकार कृषि क्षेत्र में कम से कम छूट दी जा रही है। जिसकी पोल अब खुल रही है। परन्तु भारत में यह अब छूट कम होती जा रही है।

#### संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. फ्रैंक टी० मुंगर, फ्रैंक जे० मुंगर एण्ड फ्रैंक वेबर मुंगर : रीडिंग इन पॉलिटिकल पार्टीज एण्ड प्रेशर ग्रूप्स, 1964
2. क्रिस्टी डब्ल्यू कीफर, जी० राल्फ फाल्कारी, माग्रेट ए० मैक्कीन : सोशल चेंज एण्ड कम्युनिटी पॉलिटिक्स इन अर्बन जापान, 1976, इन्स्टीट्यूट फार रिसर्च इन सोशल साइंस।
3. क्रिस्टी डब्ल्यू कीफर : हेल्थ वर्क विथ द पूवर : ए प्रैक्टिकल गाइड, रूटगर यूनिवर्सिटी प्रेस, 2000
4. यूसिटो किनोसीटा : रिक्व्यूज ऑफ द आनर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, 1993
5. क्लार्क सी० गिब्सन : पीपुल एण्ड फारेस्ट एम०आई०टी० प्रेस, 2000

\*\*\*\*\*

## आत्मा की अमरता के विविध आयाम

के. के. सिंह\*

**मूल शब्द-** अमरता, धार्मिक, गीता एवं नैतिकता।

**भूमिका-** आत्मा की अमरता एक महत्वपूर्ण धार्मिक विश्वास है जो जीवन और जगत के प्रति धार्मिक व्यक्ति के एक विशिष्ट दृष्टिकोण को इंगित करता है। आत्मा को प्रायः शरीर, इंद्रिय, बुद्धि आदि से भिन्न अभौतिक स्वतंत्र आध्यात्मिक सत्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है। अतः शरीर इंद्रिय आदि के विनाश के पश्चात् भी आत्मा की निरन्तरता या सत्यता का बने रहना ही आत्मा की अमरता है। यहाँ एक उल्लेखनीय है कि सेमेटिक धर्म (इस्लाम, ईसाई, यहूदी) में आत्मा की अवधारणा अंतिम रूप में भी शरीर के साथ जुड़ी हुई है। यही कारण है कि सेमेटिक धर्म मृत्यु के उपरान्त शरीर को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है ताकि 'न्याय दिवस' के अवसर पर आत्मा को शरीर जन्नत या जहन्नम भेजा जा सके। स्पष्ट है कि सेमेटिक परम्परा में शुद्ध आत्मा का अवधारणा में विश्वास नहीं किया गया है।

यहाँ आत्मा की अमरता के संबंध में ध्यातव्य (ध्यान रखने योग्य) बात यह है कि आत्मा की अमरता का आशय केवल भविष्य में जीवन का बने रहना मात्र नहीं है। बल्कि उच्चतर एवं परम जीवन से है। जिसमें सत्य, शुभ और सौन्दर्य की प्राप्ति होती है।

पाश्चात्य दर्शन में आत्मा की अमरता का समर्थकों का तर्क देकार्त, लाइबनिज आदि है। जबकि भारतीय दर्शन में चार्वाक एवं बौद्ध को छोड़कर समस्त भारतीय दर्शन आत्मा की अमरता का समर्थन करते हैं।

**आत्मा की अमरता के संबंध में निम्नलिखित तर्क दिखाई देते तत्वमीमांसी तर्क-** प्लेटो के अनुसार आत्मा सरल है सरल होने के कारण आत्मा निवयव है निरवयव होने के कारण सह अविनाशी है अजर है, अविभाज्य है और अविभाज्य होने के कारण अविनाशी है, अमर है। प्लेटो के इस मत का समर्थन देकार्त भी करते हैं। यह इस तर्क में पहले से ही यह मान लिया गया है कि आत्मा एक सरल द्रव्य है। यहाँ इसे सिद्ध करने के प्रयास नहीं किया गया है। प्लेटो अपनी पुस्तक 'फीडो' में कहते हैं कि मनुष्य जीवन और मृत्यु का समन्वय (संयोग) है यहाँ जीवन का स्रोत आत्मा है जबकि मृत्यु शरीर से संबंधित है अतः मृत्यु से केवल शरीर का नाश होता है उसके विरोधी आत्मा का नहीं।

यहाँ दो परस्पर विरोधी तत्वों की (जीवन, मृत्यु) एक साथ एक ही तत्व (जीवन शरीर) में स्वीकार किया गया है। परन्तु इन परस्पर विरोधी तत्वों को एक ही समय में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त दोनों तर्क तत्वमीमांसीय तर्क है।

**ज्ञानमीमांसीय तर्क -** प्लेटो के अनुसार आत्माज्ञाता है और वही ज्ञान का भंडार है ज्ञान नित्य शाश्वत एवं अपरिवर्तनशील होता है। ऐसे ज्ञान का आधार कोई नित्य शाश्वत एवं चेतन तत्व ही हो सकता है। यह चेतन तत्व

आत्मा है। प्लेटो यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारा समस्त ज्ञान पूर्व जन्म के ज्ञान का अनुश्रमण मात्र है। यह तर्क सर्वप्रथम आत्मा ने किस प्रकार ज्ञान प्राप्त किया इसकी विवेचना नहीं करता क्योंकि सर्वप्रथम ज्ञान अर्जित करते समय कोई पुनर्जन्म नहीं था।

**नैतिक तर्क-** समीक्षावादी दार्शनिक कांट के अनुसार परम शुभ की प्राप्ति नैतिकता का आदर्श है इसे किसी एक जीवन के प्रयासों के कारण नहीं पाया जा सकता अतः परम सुख की व्याख्या करने के लिए आत्मा को अमरता को मानना आवश्यक है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कांट यद्यपि शुद्ध बुद्धि के आधार पर आत्मा की अमरता का सिद्ध करने वाले तर्कों का खंडन करते हैं परन्तु व्यवहारिक बुद्धि की माँग के अनुयय नैतिकता की पूर्व मान्यता के रूप में आत्मा की अमरता को स्वीकार करते हैं।

**परामनोवैज्ञानिक तर्क-** परामनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें-

1. मृत व्यक्ति की आत्माओं से सम्पर्क।
  2. कुछ बालकों द्वारा पूर्व जन्म की बातों को बताया जाना।
  3. कुछ बच्चों का कुछ विशेष कार्यों में निपुणता।
- आदि के आधार पर आत्मा की अमरता को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है।

**शक्ति या ऊर्जा पर आधारित तर्क-** इस तर्क के अनुसार शक्ति का कभी विनाश नहीं होता आत्मा भी एक अध्यात्मिक शक्ति (ऊर्जा) है।

मूल्यों के संरक्षण के दृष्टिकोण से- दया करुणा, प्रेम, त्याग इत्यादि मूल्यों को शाश्वत एवं नित्य माना जाता है इन मूल्यों का आधार कोई अनित्य अथवा भौतिक तत्व नहीं हो सकता। कोई नित्य शाश्वत मूल्यपूर्ण चेतन तत्व ही इसका आधार हो सकता है। यही चेतन तत्व आत्मा है, इस रूप में आत्मा की अमरता सिद्ध है।

गीता में आत्मा के सिद्धि हेतु तर्क- गीता के अनुसार आत्मा अजर-अमर अविनाशी है। इस आत्मा का शरीर के साथ अनिवार्य संबंध नहीं है। गीता में आत्मा की अमरता के संबंध में निम्नलिखित तर्क है-

1. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत्  
नासतो त्र न + असतो  
नाभावो त्र ना + अभावो

**अर्थ-** जो असत्य है उसका कभी भाव (अस्तित्व) नहीं हो सकता है और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। आत्मा सत्य है अतः उसका कभी अभाव नहीं हो सकता और इस रूप में आत्मा अमर है।

2. न जायते म्रियते वा कदाचित्  
नायं भूत्वा भविता वा न भूय।



अजो नित्य शश्वतोऽयं पुराणो

न हन्यते हन्यमाने शरीरि॥

अर्थात् यह आत्मा कभी जन्म ग्रहण नहीं करता या मरता भी नहीं अथवा ऐसा भी नहीं है कि एक बार होकर फिर नहीं होता जन्म रहित मृत्यु रहित नित्य तथा सनातन यह आत्मा देह के हित (नष्ट) होने पर अर्थात् नष्ट होने पर भी हत नहीं होता है इस रूप में आत्मा की अमरता सिद्ध है।

3. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।

न चैनं बलेद्धनन्त्योपो न शोषयति मारुतः॥

अर्थात् शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकती तथा जल इसे गीला नहीं कर सकता, वायु इस आत्मा को सुखा नहीं सकती।

**कर्म नियम पर आधारित तर्क** – कर्म नियम की सम्यक रूपेण व्याख्या करने के लिए भी आत्मा की अमरता को स्वीकार किया जाता है। कर्म नियम के अनुसार अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा फल अवश्य मिलता है। परन्तु व्यवहारिक जीवन में व्यक्ति के एवं उनके कर्मफल के मध्य विरोधाभास की स्थिति दिखाई देती है। यहाँ धार्मिक व्यक्ति विभिन्न व्यक्तियों में भिन्नता तथा उनके कर्म एवं उनके कर्मफल में विरोधाभास की व्याख्या आत्मा की अमरता को मानकर करता है। वहीं आत्मा जिसमें अतीत जीवन में अच्छा कर्म किया था वर्तमान जीवन में बुरे कर्मों को करते हुए भी अच्छा फल पा रहा है। यहाँ धार्मिक व्यक्ति साथ ही यह भी कहता है कि भविष्य में उसके वर्तमान जीवन का फल अवश्य मिलेगा।

**आलोचना** – ये निम्नलिखित हैं:-

1. चार्वाकों के अनुसार शरीर से भिन्न स्वतंत्र आत्मा का अस्तित्व नहीं है। शरीर विनाश से आत्मा का भी विनाश हो जाता है।
2. बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा पंच स्कंधों (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार) का संघात है जिसमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है।
3. पाश्चात्य अनुभववादी दार्शनिक ह्यूम भी आत्मा की सत्यता का समरता का खंडन करते हैं।
4. भाषा विश्लेषणवादियों के अनुसार आत्मा की अमरता को मानने में विरोधाभास से इन दार्शनिकों के अनुसार मर जाना और बच जाना परस्पर विरोधी बातें हैं। अतः यह कहना है कि मृत्यु के पश्चात भी व्यक्ति की आत्मा जीवित रहती है व्याघात (विरोध) को जन्म देता। गांधी का भी कहना है कि हम जितना शुद्धि का प्रयास करते हैं अपने को ईश्वर के उतना ही करीब पाते हैं।

**ईसाई धर्म बनाम गीता**

ईसाई धर्म	गीता
1 शुद्ध आत्मा की कल्पना नहीं है। इसमें अंतिम स्थिति में भी आत्मा को संदेही माना गया है।	1 शुद्ध आत्मा (विशुद्ध) की अवधारणा में विश्वास है गीता के अनुसार मानव का असली स्वरूप शुद्ध आध्यात्मिक है शरीर मानवीय आत्मा का वाह्य या आकस्मिक गुण है।
2 आत्मा में पुनः जन्म (पुनर्जन्म) की बात को स्वीकार नहीं किया गया है इसमें पुनरुत्थान अवधारणा है अर्थात् न्याय दिवस के अवसर पर मृत्यु	2 गीता में पुनर्जन्म की अवधारणा है इसका आशय है कि आत्मा जब तक मोक्ष की प्राप्ति न कर ले पुनः जन्म धारण करती है।

आत्माओं को एक बार पुनः शरीर के साथ जीवित कर उन्हें सदा के लिए जहनुम या जन्नत में भेजने की बात की गई है।

3 ईसाई धर्म में 'मूल पाप' की अवधारणा है। यहाँ यह माना गया है कि आदम एवं ईव द्वारा किया गया पाप उनके वंशजों में संचारित हो गया है अतः पाप सार्वभौम है अर्थात् सभी पापी हैं जन्म से।

3 गीता में भी यद्यपि ईश्वर के भक्ति की बात की गई है परन्तु यहाँ ज्ञान और कर्म के आधार पर भी समस्त बंधनों से छुटकारा पाने की बात बतायी गयी है।

**समानता** – गीता और ईसाई दोनों जगहों पर यह बताया गया है कि किस प्रकार मानव अपने वास्तविक स्वरूप से भटक गया है गीता में इस संदर्भ में अज्ञानता की बात की गयी है जबकि ईसाई धर्म में मूल पाप की बात की गयी है। दोनों ही धर्मों में ईश्वर को अपने को पूर्णतया समर्पित कर देने से मानव अपने असली स्वरूप को जान लेता है। दोनों में ही यह स्वीकार किया गया है कि व्यक्ति के सीमित कर्म आत्मा की अमरता की प्रकृति को निर्धारित करती है।

दोनों यह मानते हैं कि आत्मा इहलौकिक (इस संसार में) में शरीर के साथ रहती है। अतः हम देखते हैं कि गीता और ईसाई धर्म में पर्याप्त अन्तर होते हुए भी कई जगह समानता विद्यमान है।

**धार्मिक दृष्टिकोण से आत्मा की अमरता का महत्व** –

1. कर्म नियम की सम्यक रूपेण व्याख्या करने के लिए।
2. पुनर्जन्म एवं पुनर्जन्म (अतीत जीवन) की व्याख्या करने के लिए।
3. सद्कर्मों के प्रोत्साहन एवं दुष्कर्मों में हतोत्साहन हेतु।
4. मोक्ष की व्याख्या हेतु।
5. मृत्यु के भय को कम करने के लिए के संदर्भ में।

**नैतिकता के दृष्टिकोण से आत्मा की अमरता का महत्व** –

1. कर्म नियम की रक्षा के दृष्टिकोण से।
2. मूल्यों (दया, प्रेम, करुणा) के संरक्षण के रूप में।
3. निश्चित एवं निर्भीक होकर कर्म करने के दृष्टिकोण से।
4. दुष्कर्मों के हतोत्साहन एवं सद्कर्मों को प्रोत्साहन के दृष्टिकोण।
5. नैतिक परिपूर्णता की प्राप्ति के दृष्टिकोण से।

आत्मा की अमरता एक सुखकर परन्तु अतार्किक अवधारणा है। तर्कता इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर भी इसका महत्व है।

**अशारीरिक अमरता** – भारतीय दर्शन में अधिकांश विचारक आत्मा को अशरीर और अमर मानते हैं। गीता में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है साथ ही शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है। पुनः गीता में कहा गया है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति पुराने जीर्ण वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र पहन लेता है उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है जब तक उसे मोक्ष नहीं प्राप्त होता। पाश्चात्य दार्शनिक कांट ने भी आत्मा को अशरीरी और अमर कहा है। परन्तु भविष्य में सेमेटिक धर्म के प्रभाव में पश्चिमी ईश्वरवादियों के बीच देह विहीन आत्मा की कल्पना नहीं रही।

**शारीरिक अमरता** – शारीरिक अमरता को सेमेटिक धर्म (नवी मूलक) में मान्यता मिली है। यूहदी, ईसाई, इस्लाम आदि धर्म परस्पर में ऐसा माना

गया है कि एक दिन न्याय दिवस आशावाद जिसमें सभी मृतकों को शरीर सहित जिन्दा किया जाएगा फिर उन्हें उनके कर्मों के अनुसार या तो स्वर्ग में भेजा जाएगा या उनके नरक में दुःख भोगना होगा।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सेमेटिक धर्म में आत्मा का अस्तित्व शरीर के सा ही अलग किया गया है जबकि भारतीय परम्परा में शरीर और आत्मा दोनों।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सुभाष लखोटिया : आत्मा के लिए अमृत, 2017
2. प्रो० राजेन्द्र प्रसाद : दर्शनशास्त्र की रूपरेखा, 2007, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन, ISBN-812083206X।
3. जदुनाथ सिन्हा : भारतीय दर्शन, 2008, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन, नयी दिल्ली, ISBN-978-81-208-2151-61
4. मैक्स मूलर : द सिक्स सिस्टम ऑफ इण्डियन फिलासफी, 2007, रीड बुक्स प्रकाशन।
5. थियोस बर्नार्ड : हिन्दू फिलासफी, 1999।

\*\*\*\*\*

# Mauryan Administration and It's Influence On Present Administrative System

Dr. Madhusudan Choubey\*

**Abstract** - The Mauryan dynasty has an important place in the history of ancient India. the Mauryan Government was enlightened despotism. It was completely centralized and bureaucratic. The centralized monarchy became a paternal despotism under the able guidance of emperor Ashoka. Most of the Maurya emperors used their powers for the welfare of the subject. The emperor was the axis of Mauryan administration. He was assisted by a council of the ministers. There was a organized secretarial for the conduct of State affairs and a very well managed civil service to run the government smoothly. The criminal code of the Mauryas was very severe and was sternly administered. A large number of Gudhapurushas [detectives] kept a vigil over the entire administration. Maurya had a large army. Very big Maurya empire was divided in provinces for effective administration. The provinces were further divided into districts. There was local administration in cities and villages. After the war of kalinga, Ashoka introduced many reforms in administration and made it more liberal. Administration of today's India is having almost features of Mauryan era. The influence is clear and deep.

**Tools** - Reference books, Inscriptions, Administrative reports.

**Key Words** - nature of the Mauryan Government, despotism, centralized, bureaucratic, provinces, local administration.

**Introduction** - The Mauryan dynasty has an important place in the history of ancient India. With the help of Chanakya, Chandragupta Maurya established Maurya Empire in 322 BC. Total ten emperors ruled in this dynasty up to 187 BC. Chandragupta, Bindusara and Ashoka were main emperors of them. Brihadratha was the last king. The Maurya administration has earned a lot of praise from historians. Present administration system was established in 1947, and gradually it developed.

**Nature Of The Government** - The nature of the Mauryan Government was enlightened despotism. It was completely centralized and bureaucratic. The centralized monarchy became a paternal despotism under the able guidance of emperor Ashoka. Most of the Maurya emperors used their powers for the welfare of the subject. In independent India, we find the same motive of the government, which is welfare of people. Though monarchy has been replaced with democracy.

**Structure Of Administration** - Structure of the Mauryan administration had following parts:-

- A. Central Administration.
- B. Provincial Administration.
- C. District Administration.
- D. Local Administration.

The Constitution of India forms same administrative structure at present.

**A. The Central Administration** - The following were main parts of the central administration:-

**1. The Emperor:** - The emperor was the axis of Mauryan administration. He was taken to be the representative of God. He was the head of all powers. He was the head of the justice, law and army. Though the king had such extensive despotic powers, yet he was guided by the noblest ideals. He considered himself as the servant of the people. Patliputra was his capital.

**2. Council of Ministers :** - The king was assisted by a council of the ministers. Purohit, Senapati and Yuvraj were the most important ministers. The Purohit advised the king on the matters of Dharma and justice. Senapati was responsible for conducting battles. Yuvraj was the heir. Yuvraj had to stay in the capital for gaining administrative experience.

**3. The Secretariat:** - There was a organized secretarial for the conduct of State affairs. There were several departments and each was under and adhyaksha or superintendent. The adhyaksha were equated with the present secretaries. Chanakya or kautilya mentioned the duties of 32 adhyaksha in several departments. Some of them were- Koshadhyaksha, Lauhadhyaksha, Lavanadhyaksha, Swarnadhyaksha, Sitadhyaksha etc.

**4. Civil Service :** - There was a very well organized civil service to run the government smoothly. The officers were called Amatya. The Amatya were equated with the present civil servants. Main Amatyas were- Sannidhata [In charge of treasury], Samharta [Collector of revenue], Dandpala [Chief of police], Durgapala [Governor of the fort], Antapala

[Governor of the frontier] etc.

**5. Administration of Justice** : - The king was the head of justice administration. There was two types of court-

**I. Dharmasthiya**- Civil court.

**II. Kantaka Sodhan**- Criminal court.

The judges of civil court and the criminal courts were called Vyavaharika and Pradestha respectively. The chief justice was called Dharmadhikarin.

The criminal code of the Mauryas was very severe and was sternly administered. Due to the harsh punishment the crimes were few. The security of life and property was guaranteed by the state.

**6. Detective System** : - A large number of Gudhapurushas [detectives] were posted all over the empire. They kept a vigil over the entire administration.

The detective system was divided into two parts –

**I. Sansthan** :- Used to stay at a place.

**II. Sanchari** :- Used to wander here and there.

Kautilya wrote about a number of detectives such as Vishkanya or poisonous girls, house holders, merchants, ascetics etc.

The spies had to perform their duties very carefully, secretly and skillfully.

**7. Military organization** : - Maurya had a large army. It consisted of 6 lacks infantry, 30 thousands cavalry, 9 thousand war elephants and 1 thousand chariots.

The king was the supreme commander of the armed force. He personally supervised the army in both peace and war.

The army was efficiently organized by a council of thirty members which was further divided into six boards.

**8. Revenue System** : - According to Kautilya, the most important duty of a king was to keep his treasury full at all time for all works. The chief source of revenue was the land tax, which varied from one sixth to one fourth of the produce. Other taxes were sales tax, municipal tax, taxes on liquor shops and gambling houses etc. several fines and presents to the king were other sources of revenue. If we compare present central administrative system with above features, we find the existence of many of them. The prime minister has taken place of the emperor. The P.M. has many powers. President of India is a nominative chief of the administration. Council of ministers, secretariat, bureaucracy, revenue system are significant features of today's administrative structure. Of course we are living in 21st century and in a democratic world, so style of working has changed a lot, but structure has not.

**B. The Provincial Administration** - The Maurya empire was very big. It was not possible to rule effectively all over from central capital Patliputra. That is why the empire was divided in provinces. At the time of Ahoka there were five provinces-

**1. Uttarapath [The Northern province]**, Capital – Taxila/ Takshshila.

**2. Dakshinapath [The Southern province]**, Capital – Suvarnagiri.

**3. Prachya [The Eastern province]**, Capital – Tashali/ Kalinga

**4. Avantipath [The Western province]**, Capital – Avantika/ Ujjain.

**5. Central Province**, Capital – Patliputra.

Central province was looked after by the king himself.

Other provinces were under the princes of royal family. They were designated as 'Kumar'. Some times other official also became the head of the province and was known as 'Pradeshika'.

The heads of the provinces were bound to work according to the instructions of the emperor.

At present we have 28 states and 8 union territories. Center plays dominating role now a days too. States also have authority to make law on various subjects. They are not as dependent on central government, as they were in the past.

**C. District Administration** - The provinces were further divided into districts.

Rajka or Mahamatra was the head officer of the district.

Yuktas were the officers who carried on the administrative duties.

Today's states and union territories are also divided in many districts for effective administration. Collectors and other officials are ruling over the districts.

**D. Local Administration** - There was local administration in cities and villages-

**I. Administration of City** - The chief of city administration was called 'Nagrik'.

At Patliputra, a council of 30 members administered the city. Six boards were made for administration. Every board had 5 members.

**1. First Board** – Looked after commerce and industries.

**2. Second Board** – Took care of foreign ambassadors and other foreigners.

**3. Third Board** – Kept the record of birth and death.

**4. Fourth Board** – Looked after the weights and measures, buying and selling of goods.

**5. Fifth Board** – Responsible to stop mixing of goods.

**6. Sixth Board** – Responsible for education, sanitation etc.

**II. Administration of Village** - Village was the smallest unit of the administration. Following were responsible for its administration-

**1. Gramik** – Gramik was the head of village. He was elected. He did not receive salary.

**2. Gramsabha** – It used to assist Gramik and worked for the welfare for the people.

**3. Gope** – He was the officer appointed by the government. There were several villages under him.

By 72th and 73rd constitutional amendments, we have clear provisions for local administration at village, block and district levels.

**Conclusion** - We can say that the Mauryan administration was indeed the first attempt in India to do administrative centralization on an extended scale. The government worked for the welfare of people. The government devoted itself to control the productive and commercial activities. It



was a significant change from earlier systems. After the war of kalinga, Ashoka introduced many reforms in administration and made it more liberal. Present administrative system has adopted many characteristics of Mauryan administration.

#### References :-

1. Kautilya, Arthshastra, Penguin books, New Delhi, 2019.
2. Ancient India as described by Megasthenes and Arrian, Forgotten books, London, 2015.
3. Sharma R.S., India's ancient past, oxford University press, London, 2005.
4. Mahajan V.D., Ancient India, S. Chand, New Delhi, 1992.
5. Pandey J.N., Constitution of India, Central Law Agency, Prayagraj, 2020.
6. Fadia B.L., Public Administration, Sahitya Bhawan, Agra, 2012.
7. Bhandarkar D.R., Ashoka, S. Chand and Company, New Delhi, 1960.

\*\*\*\*\*

## आर्थिक विकास को अवस्थाएं तथा प्रक्रिया

डॉ. पी. डी. ज्ञानानी\*

**प्रस्तावना** – अर्थशास्त्रियों का विचार है कि आर्थिक विकास की कुछ अवस्थाएँ होती हैं। जो एक-दूसरे के बाद क्रम से आती हैं। इसी को वे आर्थिक विकास की प्रक्रिया कहते हैं लेकिन अर्थशास्त्रियों में इस सम्बन्ध में एक राय नहीं है कि विकास की अवस्थाएँ कौन-कौन सी हैं या विकास प्रक्रिया का ढंग क्या है। कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि विकास की तीन अवस्थाएँ होती हैं: (1) वस्तु विनिमय अवस्था (2) मौद्रिक अवस्था (3) साख अवस्था।

कुछ अर्थशास्त्री आर्थिक विकास की अवस्थाओं का वर्णन जनसंख्या के पेशेवर विभाजन के आधार पर करते हैं और उनका कहना है कि आर्थिक विकास के साथ-साथ कृषि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत घटता जाता है और औद्योगिक जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः बढ़ता जाता है। अतः उनकी दृष्टि में कृषि आर्थिक पिछड़ेपन का द्योतक है जबकि उद्योग आर्थिक विकास का सूचक है।

**प्रो. कॉलिन क्लार्क** ने अपनी पुस्तक 'Condition of Economic Progress' में आर्थिक विकास की तीन अवस्थाएँ बतायी हैं: (i) प्रारम्भिक अवस्था, (ii) मध्यवर्ती अवस्था, व (iii) उन्नत अवस्था। लेकिन प्रसिद्ध अमरीकी अर्थशास्त्री प्रो. रोस्टोव ने अपनी पुस्तक 'The Problems- of Economic Growth' में आर्थिक विकास की निम्न पाँच अवस्थाएँ बतायी हैं :-

**(1) परम्परावादी अवस्था** – इस अवस्था में देश के अधिकांश साधन कृषि व्यवसाय में लगे होते हैं तथा उद्योग-धन्धे भी बहुत ही पिछड़ी हुई अवस्था में होते हैं। कृषि उत्पादन-साधन भी पुराने होते हैं तथा वैज्ञानिक साधनों को काम में नहीं लाया जाता है। इससे कृषि उत्पादन एक सीमा पर भी स्थिर रहता है। किसी भी क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी का उपयोग नहीं दिखायी देता है। समाज में राजनीतिक सत्ता बड़े-बड़े भूमिपतियों के हाथ में केन्द्रित होती है। इन सबके परिणामस्वरूप इस अवस्था में (i) उत्पादन का स्तर निम्न एवं प्रति व्यक्ति आय न्यून होती है, (ii) समाज का संगठन जातिवाद एवं पारिवारिक सम्बन्धों पर आधारित होता है, (iii) देश की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था दुर्बल एवं अविकसित स्थिति में होती है।

**(2) आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था** – यह वह अवस्था है जिसमें समाज वैज्ञानिक विधियों एवं तकनीकों का प्रयोग करने लगता है और परम्परावादी विधियों को छोड़ने लगता है। इससे कुछ परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखायी देने लगते हैं। इस अवस्था में समाज द्वारा बचत करने, उसको विनियोग करने एवं लाभ वृद्धि करने का प्रयत्न किया जाता है। इससे वाणिज्य व व्यापार का विस्तार होता है। नये-नये निर्माण कार्य होने लगते हैं तथा नये-नये प्रकार की संस्थाएँ स्थापित होने लगती हैं। भूमिपतियों का प्रभुत्व कम होने

लगता है। राजनीतिक चेतना आने लगती है। सामाजिक रुचियों में भी परिवर्तन होने लगते हैं।

प्रो. रोस्टोव के अनुसार, इस अवस्था में :-

- 1) पूंजी निवेश की मात्रा 10 प्रतिशत तक पहुँच जाती है तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन भी बढ़ जाता है।
- 2) ग्रामीण जन संख्या सड़कों व अन्य साधनों में वृद्धि होने के कारण शहरों में आकर बसने लगती है।
- 3) इस अवस्था में खाद्यान्नों का उत्पादन आवश्यकतानुसार होने लगता है।
- 4) औद्योगिक कच्चे माल का उत्पादन भी बढ़ने लगता है।
- 5) कृषि क्षेत्र की बचत उद्योगों में विनियोजित होने लगती है।
- 6) सरकार द्वारा भी जन कल्याण के कार्यों में अधिक योगदान दिया जाने लगता है।

**(3) आत्मस्फूर्ति अवस्था** – यह आर्थिक विकास की तीसरी अवस्था है। प्रो. रोस्टोव के अनुसार, 'आत्मस्फूर्ति अवस्था को उस मध्यान्तर काल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें विनियोग की दर इस प्रकार बढ़ती है कि जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पादन में वृद्धि होती है। इस प्रारम्भिक वृद्धि के साथ उत्पादन विधियों में आमूल परिवर्तन होने लगते हैं तथा आय का विनियोग इस प्रकार प्रभावित होता है कि जिससे विनियोग की नवीन धाराएँ प्रभावित होती हैं तथा जिसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि हो जाती है।' इससे यह बात साफ हो जाती है कि :- इस अवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन होते हैं तथा विकास अपने आप नहीं होने लगता है।

- 1) कृषि व उद्योग में विज्ञान का प्रभाव स्पष्ट दिखायी देने लगता है।
- 2) निर्माणी उद्योगों में विकास तेजी से होने लगता है।
- 3) देश के उत्पादन में वृद्धि तेजी से होती है।
- 4) राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ता है।
- 5) प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बढ़ती है।

प्रो. रोस्टोव के विचारों के अनुसार आत्मस्फूर्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए निम्न बातों का पूरा होना आवश्यक है :

- (i) शुद्ध विनियोग राष्ट्रीय आय के 10% या इससे अधिक होना चाहिए।
- (ii) कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए।
- (iii) निर्यातों में वृद्धि व आयातों में सीमितता होनी चाहिए।
- (iv) आधारभूत एवं पूंजीगत उद्योगों का विकास होना चाहिए।
- (v) परिवहन एवं शक्ति साधनों का विस्तार होना चाहिए।
- (vi) उत्साही एवं साहसी वर्ग का विकास होना चाहिए जो जोखिम सहन

करने को तैयार हो।

(vii) समाज की राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए।

प्रो. रोस्टोव ने विभिन्न राष्ट्रों द्वारा आत्मस्फूर्ति अवस्था को प्राप्त करने की तिथियाँ इस प्रकार बतायी हैं ब्रिटेन 1783-1802, फ्रांस 1820-1860, अमरीका 1843-1860, जापान 1878-1900, रूस 1890-1914, कनाडा 1896-1914, भारत 1952।

**(4) परिपक्वता की अवस्था** - इस अवस्था को स्वप्रेरित विकास की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में साधनों का उपयोग इस सीमा तक होने लगता है कि देश में सभी आवश्यक वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में बनने लगती हैं और अन्य देशों पर निर्भरता समाप्त हो जाती है। देश का व्यवसाय आर्थिक आधार पर किया जाने लगता है। इसका अर्थ है कि आर्थिक दृष्टि से जिन वस्तुओं का उत्पादन लाभकारी होता है केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है शेष को आयात करके ही काम चलाया जाता है। इस अवस्था में विकास की औसत दर एक-सी रहती है। उद्योगों का पर्याप्त विकास होते व कृषि में आधुनिक तकनीकी को काम में लाते रहने के कारण कृषि पर जनसंख्या का भार कम हो जाता है तथा विदेशी व्यापार के स्वरूप में भारी परिवर्तन हो जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में 15 से 20 प्रतिशत तक राष्ट्रीय आय का विनियोजन किया जाता है। ग्रामीण जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहना अधिक पसन्द करती है, अतः शहरी जनसंख्या में वृद्धि होती है। प्रो. रोस्टोव ने विभिन्न राष्ट्रों की परिपक्वता की ओर पहुँचने की तिथियाँ इस प्रकार बतायी हैं। ब्रिटेन 1850, फ्रांस 1910, अमरीका 1900, जापान 1940, रूस 1950।

**(5) अधिकाधिक उपयोग की अवस्था** - यह आर्थिक विकास की अन्तिम अवस्था है। इसमें जनता की सामान्य आवश्यकताएँ आसानी से पूरी हो जाती हैं और सामान्य उपभोग स्तर ऊपर उठ जाता है तथा समाज का प्रत्येक

व्यक्ति उपभोग की उच्चतम सीमा पर पहुँचना एवं विशिष्ट वस्तुओं को काम में लाना चाहता है। इसी का परिणाम होता है कि इस अवस्था में आरामदायक व विलासिता की वस्तुओं का भरपूर उपभोग होता है तथा प्रत्येक व्यक्ति उन वस्तुओं के नये-नये मॉडल प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है। इसका कारण यह होता है कि इस अवस्था में प्रति व्यक्ति आय काफी ऊँची होती है। इस अवस्था में वस्तुओं में अधिक तकनीकी सुधार करने की गुंजाइश नहीं होती है। सिर्फ सुविधाओं में वृद्धि की जाती है।

**आर्थिक विकास की अवस्थाओं के सन्दर्भ में भारत की स्थिति** - विद्वानों का कहना है कि भारत तृतीय अवस्था- आत्मस्फूर्ति अवस्था में है। इसके लिए वे निम्न कारण देते हैं : (1) भारत में पूंजी निवेश की दर सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय की 15.3 प्रतिशत है जो निश्चय ही इस बात का प्रमाण है कि भारत में आत्मस्फूर्ति अवस्था है। (2) कृषि व उद्योगों में विज्ञान का प्रभाव दिखायी देने लगा है जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन एवं उद्योगों में उत्पादन बढ़ा है। (3) निर्माण उद्योगों में भी विकास हो रहा है। (4) कुल राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ रहा है। (5) प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय भी बढ़ रही है। (6) निर्यातों में भी वृद्धि हो रही है। (7) समाज के सामाजिक, राजनैतिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हुआ है। (8) उत्साही एवं साहसी वर्ग भी उठ रहा है जो जोखिम सहने को तत्पर है।

**निष्कर्ष** -यह निर्विवाद सत्य है कि भारत प्रथम अवस्था को पार कर चुका है तथा द्वितीय अवस्था में चलते हुए भी इसको लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यदि भारत तृतीय अवस्था में नहीं पहुँच पाया है तो निश्चय ही दूसरी अवस्था पार करके तृतीय अवस्था में प्रवेश करने की स्थिति में है। इसका कारण यह है कि अब भारत में तृतीय अवस्था की कुछ विशेषताएँ पायी जाने लगी हैं।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

\*\*\*\*\*

## दक्षिणी राजस्थान वर्षा की प्रवृत्ति, कृषि भूमि का उपयोग का वर्गीकरण एक भौगोलिक विश्लेषण 2010-11

रोहित लौहार\*

**शोध सारांश** - दक्षिण राजस्थान में आज भी वर्षा की अनिश्चितता, विरलता, अनियमितता के कारण कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तनशीलता देखने को मिल रही है। जिसका प्रभाव फसल प्रारूप पर पड़ रहा है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल व्यर्थ बहकर चला जाता है, उस व्यर्थ जल का प्रभावी उपयोग कृषि के अन्तर्गत किया जा सकता है। कृषि के विकास में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाना, प्रयोग में वृद्धि, गोबर और हरी खाद के उपयोग को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। किस मिट्टी किस खाद की कितनी मात्रा की आवश्यकता है, इसका तकनीकी ज्ञान अधिकांश किसानों को नहीं है। उन्नत बीजों से अच्छी उपज की आशा की जा सकती है। दक्षिणी राजस्थान में विशेषकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों में मुख्य जीविकोपार्जन का साधन कृषि है, जो मुख्य रूप से वर्षा की प्रवृत्ति से प्रभावित रहती है। क्षेत्र में विषम भौगोलिक परिस्थितियों में जनसंख्या पहाड़ी, ढलू, असंचित एवं कर्म उर्वरता वाली कृषि भूमि पर छोटे-छोटे खेतों में कृषि फसलों का उत्पादन करते हैं।

**प्रस्तावना** - राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थिति भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ (2008) वाला यह क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को मेवाड़ के नाम से भी जानते हैं। क्षेत्र के पूर्व में मालवा पश्चिमी एवं उत्तरी सीमा पर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। क्षेत्र में बनास, माही एवं साबरमती नदियों का अपवाह तंत्र है। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों की सीमा लगती है। अध्ययन क्षेत्र का विस्तार 23° 10' उत्तरी अक्षांश से 26° 15' उत्तरी अक्षांश तथा 73° 10' पूर्वी देशान्तर से 75° 43' 30" पूर्वी देशान्तर तक स्थित है। क्षेत्रफल 47397 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या सेन्सस 2011 के अनुसार 1,22,36,014 है। जो राजस्थान की कुल जनसंख्या (6,86,21,012) का 17.83 प्रतिशत हिस्सा है। क्षेत्र की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 240 किलोमीटर है। जबकि उत्तर से दक्षिण की लम्बाई 210 किलोमीटर है। अध्ययन क्षेत्र में 2011 के अनुसार 54 तहसीलें सम्मिलित हैं।

**कृषि भूमि उपयोग** - अध्ययन क्षेत्र में कृषि के परम्परागत उपकरणों का ही प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर उबड़-खाबड़ धरातल हो के कारण खेतों का आकार बहुत छोटा है तथा ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक कृषि तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण यहाँ पर कृषि चकबन्दी प्रणाली का अभाव है। साथ ही साथ मिट्टी की उत्पादन क्षमता का भी ह्रास हो रहा है। जिसके पीछे मुख्य कारण क्षेत्र के किसानों की उदासीनता रही है। जिन क्षेत्रों में कृषि के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, वहाँ गहन कृषि द्वारा उर्वरकों, रासायनिक खाद, उन्नत बीजों, कीटनाशकों, जैव खाद, हरी खाद (गोबर खाद) अधिक प्रयोग करके क्षेत्र में कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। साथ ही फसलों की सघनता का अध्ययन प्राकृतिक दशाओं, सामाजिक, आर्थिक क्रियाओं से प्रभावित एवं निर्धारित होता है। वर्षा की प्रवृत्ति के फलस्वरूप कृषि भूमि उपयोग, जोत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका अध्ययन किया गया है। वर्षा की प्रवृत्ति धनात्मक रहती है, तो कृषि जोत क्षेत्र बढ़ेगा। जिसमें खरीफ की फसलों का उत्पादन बढ़ेगा साथ ही भूमिगत

जल स्तर ऊँचा रहने से रबी की फसलों का जोत क्षेत्र भी बढ़ेगा, क्योंकि भूमिगत जल स्तर ऊँचा रहने से सिंचाई की पर्याप्त सुविधा मिल जायेगी। कभी-कभी अतिवृष्टि होने से खरीफ की फसलों में मक्का, उड़द, ज्वार, अरहर की फसलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ चावल की फसलों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि चावल की फसल के लिए उसकी जड़ों में हमेशा पानी की आवश्यकता रहती है। रबी की फसलें विशेषकर गेहूँ, जौ एवं चना का जोत क्षेत्र भी बढ़ेगा, क्योंकि गेहूँ की फसल के लिए सिंचाई की पर्याप्त आवश्यकता होती है, जिसके लिए भूमिगत जल स्तर का ऊँचा हरना अतिआवश्यक है। वर्षा की प्रवृत्ति नकारात्मक रहती है, तब भी खरीफ की फसलों के साथ-साथ रबी की फसलों का जोत क्षेत्र तो घटेगा ही साथ ही साथ क्षेत्र की आर्थिक क्रियाएँ भी प्रभावित होगी।

यह पूरा क्षेत्र बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है, इसकी समुद्रतल से ऊँचाई 150 मीटर से 300 मीटर के मध्य है, ढाल पूर्व दिशा की ओर है। यह मैदानी भाग कहीं पूर्ण समतल है, तो कहीं कटा-फटा है। सम्पूर्ण क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का जमाव है, जो कृषि पैदावार के लिए उपयुक्त है। यह क्षेत्र माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश से निकलकर इस प्रदेश से गुजरती हुई खम्भात की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर धरातल असमतल एवं कीहं छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों के मध्य संकीर्ण घाटियाँ हैं।

**अध्ययन के उद्देश्य** - दक्षिणी राजस्थान में वर्षा की विषमता, विरलता, विविधता एवं अनियमितता का कृषि भूमि उपयोग पर पड़ने वाले प्रभावों ज्ञात कर दीर्घकालिक योजनायें बनाने में मदद मिल सकेगी।

1. दक्षिणी राजस्थान में वर्षा की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना।
2. अध्ययन क्षेत्र में कृषि भूमि उपयोग के प्रारूप का अध्ययन करना।

**विधि तंत्र** - वर्तमान शोध कार्य दक्षिण राजस्थान के 7 जिलों के अंतर्गत 54 तहसीलों को आधार मानकर किया गया है। आंकड़ों का संकलन द्वितीयक स्रोतों से किया गया है। आंकड़े जिला भू-अभिलेख, तहसील स्तर से लेकर राजस्व विभाग अजमेर, जिला सांख्यिकी रूपरेखा, अध्ययन में मुख्यतया द्वितीयक समंक का प्रयोग किया गया है। जो विभिन्न सरकारी



प्रतिवेदनों भारत एवं राजस्थान सरकार कृषि विभाग, राजस्व विभाग से प्राप्त किये हैं। सांख्यिकी उपागम द्वारा आंकड़ों का संकलन भू-राजस्व विभाग, मौसम विभाग, राजस्व विभाग अजमेर, योजना भवन जयपुर, जिला सांख्यिकी रूपरेखा से प्राप्त किये हैं।

**दक्षिणी राजस्थान में वर्षा की प्रवृत्ति** – अध्ययन क्षेत्र में विगत दशकों में वनों का अंधाधुंध, अनियंत्रित कटाई के कारण वर्षा की प्रवृत्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। प्रदेश की सामाजिक व्यवस्थाएँ भी कृषि जोत के आकार को लघु करती जा रही है। खातेदार की कृषि भूमि का बिखराव भी मानव श्रम व समय का उचित उपभोग करने में बाधक है। वर्तमान समय में कृषि प्रारूप का गहन विश्लेषण कर भविष्य की दीर्घकालीन योजनाएँ बनाई जा सकती है।

**दक्षिणी राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की प्रवृत्ति 1981 से 2011**

क्र.	वर्ष	औसत वर्षा (से.मी.)	धनात्मक/ऋणात्मक
1.	1981	65-12	-0.97
2.	1982	51.92	-14.17
3.	1983	82.56	16.47
4.	1984	68.25	2.16
5.	1985	57.80	-8.29
6.	1986	48.21	-18.88
7.	1987	43.85	-22.24
8.	1988	63.11	-2.98
9.	1989	66.82	0.73
10.	1990	87.73	21.64
11.	1991	63.53	-2.56
12.	1992	76.66	10.57
13.	1993	63.31	-2.78
14.	1994	99.21	33.12
15.	1995	47.08	-19.01
16.	1996	67.76	1.67
17.	1997	65.22	-0.87
18.	1998	66.73	0.64
19.	1999	43.42	-22.67
20.	2000	39.99	26.10
21.	2001	63.33	-2.76
22.	2002	37.77	-27.32
23.	2003	65.80	-0.29
24.	2004	63.99	-2.10
25.	2005	82.55	16.46
26.	2006	127.24	61.15
27.	2007	64.26	-1.83
28.	2008	58.44	-7.65
29.	2009	64.54	1.55
30.	2010	85.60	19.51
31.	2011	65.99	-0.01
	औसत	2048.79/31 =66.09	धनात्मक 12 वर्ष एवं ऋणात्मक 19 वर्ष

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में विगत 31 वर्षों की औसत वार्षिक वर्षा का विश्लेषण किया गया जिससे ज्ञात हुआ कि 12 वर्ष (38.71 प्रतिशत) में घनात्मक वर्षा हुई है तथा 19 वर्ष (61.29) प्रतिशत ऋणात्मक वर्षा की प्रवृत्ति ज्ञात हुई। इससे कह सकते हैं कि क्षेत्र में आज भी वर्षा की विरलता अनिश्चितता, अनियमितता देखने को मिल रही है। जिसका मुख्य कारण जनाधिक्य में वृद्धि कृषि भूमि का आवासीय भूमि में नि परिवर्तन तथा पेड़-पौधों, वनस्पतियों का अतिक्रमण एवं कटाई होना है।

**कृषि भूमि उपयोग** – कृषि भूमि उपयोग का वर्गीकरण :

- (1) वन क्षेत्र
- (2) कृषि अयोग्य भूमि
  - 2.1 गैर कृषि उपयोग भूमि
  - 2.2 बंजर एवं अकृषित भूमि
- (3) अन्य अकृषित भूमि
  - 3.1 स्थायी चरागाह तथा अन्य गोचर भूमि
  - 3.2 वृक्षों के झुण्ड तथा बाग आदि से युक्त भूमि
  - 3.3 बज्र
- (4) पड़त भूमि
  - 4.1 अन्य पड़त भूमि
  - 4.2 चालू पड़त (एक वर्षीय)
- (5) वास्तविक बोया हुआ कुल क्षेत्र (दूपज घटाकर)
- (6) समस्त बोया हुआ क्षेत्र
- (7) एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र (दूपज क्षेत्र)

अध्ययन क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान में 2010-11 कृषि भूमि उपयोग के आंकड़ों का विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र में कुल भौगोलिक क्षेत्र 4893568 हैक्टेयर है। जिसमें से वन 893279 (18.25 प्रतिशत), गैर कृषि उपयोग भूमि 334156 (6.83 प्रतिशत), बंजर एवं अकृषित भूमि 784580 (16.03 प्रतिशत), स्थायी चरागाह तथा अन्य गोचर भूमि 403663 (8.25 प्रतिशत), वृक्षों के झुण्ड तथा बाग आदि से युक्त भूमि 2804 (0.06 प्रतिशत), बंजर कृषि योग्य खाली भूमि 536899 (10.97 प्रतिशत), अन्य पड़त भूमि 234467 (4.79 प्रतिशत) चालू पड़त एकवर्षीय 78573 (1.61 प्रतिशत), वास्तविक बोया हुआ क्षेत्र 1625147 (33.21 प्रतिशत), समस्त बोया हुआ क्षेत्र 2511551 (51.32 प्रतिशत), एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र 900904 (18.41 प्रतिशत) है।

अध्ययन क्षेत्र में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33 प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए। जबकि अध्ययन क्षेत्र में 18.25 प्रतिशत है जो (-14.75) ऋणात्मक प्रतिशत को दर्शाता है। कृषि योग्य खाली पड़ी भूमि का प्रतिशत भी 10.97 है, जिसको कृषि की नवीन विधियाँ अपनाकर तथा वर्षा के जल का संग्रहण कर क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर को ऊँचा करके कृषि योग्य खाली पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाना जिससे क्षेत्र में खाद्यान्नों, अनाजों, दालें रबी एवं खरीफ की फसलों की पैदावार बढ़ायी जा सके। अध्ययन क्षेत्र में वास्तविक बोया गया क्षेत्र 33.21 प्रतिशत है। जिसको बढ़ा कर 50 से 70 प्रतिशत तक किया जा सकता है। यह तभी संभव है जब क्षेत्र में निवास करने वाले कृषक जीवन निर्वाहक मजदूर, मुख्य श्रमिक आदि मानव संसाधन जब पड़त तथा कृषि योग्य खाली पड़ी भूमि का उपयोग कृषि उपजों के उत्पादन में करने लगेंगे तब स्वतः ही क्षेत्र में खाद्यान्नों के उत्पादन की समस्या का स्थायी समाधान मिला सकेगा। नवीन कृषि विधियाँ,

उपकरण, संकर किस्म के बीजों का प्रयोग, हार्वेस्टर, ट्रेक्टर, डीजल इंजन, थ्रेसर आदि कृषिगत तकनीकी उपकरणों का प्रयोग जब पहाड़ी उबड़-खाबड़, पठारी एवं कठोर धरातलीय भूमि में कृषि की फसलों के उत्पादन के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिये। जिससे वहाँ के किसानों के द्वारा उत्पादित अनाजों को, मिश्रित जिन्सों को मण्डियों तक पहुँचाया जा सके। अध्ययन क्षेत्र में निवास करने वाले किसानों भविष्य उज्ज्वल एवं भावी विकास की योजनाओं का स्थायी समाधान मिल सके।

**निष्कर्ष** - अध्ययन क्षेत्र में आज भी भौगोलिक, जलवायु, उच्चावच, धरातलीय ढाल, मिट्टी की उपजाऊपन, जलोढ़ एवं काली मिट्टी का क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर हर जिले में फसलों में परिवर्तनशीलता एवं प्रारूप में बदलाव देखने को मिल रहा है। यदि हम खाद्यान्नों का अध्ययन करें तो ज्ञात होता है कि क्षेत्र में गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन आदि फसलें अधिक क्षेत्र में बोई जाती है। जो वर्षा की प्रवृत्ति पर निर्भर रहती है। जिन फसलों में पैदावार कम हो रही है या कम क्षेत्र में बोई जा रही है, उनका क्षेत्र बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकी, संकर किस्म के बीज कृषि उपकरण हार्वेस्टर, थ्रेसर एवं रासायनिक खाद फास्फोरस, पोटैस, नाइट्रोजन, डी. ए. पी. एवं जैव रासायनिक खाद, गोबर, सड़ी-गली पत्तियाँ आदि का प्रयोग अधिक करके क्षेत्र में सभी फसलों का सामंजस्य या समन्वय या तालमेल बनाया जा सकता है जिससे क्षेत्र के लोगों का आर्थिक एवं कृषि भूमि उपयोग का अधिकतम अनुकूलतम उपयोग हो सके जिससे रबी की फसलों का जोत क्षेत्र बढ़े ताकि व्यर्थ बह रहे पानी का भी समुचित उपयोग हो सकेगा और

इसी पानी से रबी की फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी और क्षेत्र में खरीफ के साथ-साथ रबी की फसलों का क्षेत्र तो बढ़ेगा ही और भूमिगत जल स्तर भी ऊँचा रहेगा जिससे भविष्य में सिंचाई की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा।

#### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. S.L. Kayastha & M.B. Singh (1979) : An analysis of rainfall and production of wheat in the drought prone Gwalior & Chambal regions of M.P.
2. कटियार बी. एस. 1987 : 'भारतीय मानसून और इसकी सीमाएँ', नई दिल्ली, अन्तर भारत प्रकाशन
3. क्रिचफील्ड हॉवर्ड जे. (2000) : 'सामान्य जलवायु विज्ञान', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
4. शुक्ला, जे. (1987) : मानसून की अंतरवार्षिकी परिवर्तनशीलता
5. स्वामीनाथन एम. एस. (1987) : 'मानसून की भविष्यवाणी, चेतावनी एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव'।
6. युवा जावदे (1987) : 'वर्षा तापमान का वर्तमान दृश्य'।

#### **वेबसाइट :**

1. <http://en.wikipedia.org/wiki/meteorology>
2. [www.weatherbase.com](http://www.weatherbase.com)
3. <http://www.absc.net.au/science/slab/elmino/story.html>
4. [http://www.cia.gov/library/publication/the\\_world\\_factbook](http://www.cia.gov/library/publication/the_world_factbook)

\*\*\*\*\*

# Role of Information Technology in Insurance Industry

Dr. Nilesh Gangwal\*

**Abstract** - Insurance industry is facing a major economic and competitive challenge. To succeed in the rapidly developing business climate insurers are forced to investigate ways by which they can improve end product efficiency and drive topline growth, and still meet and go beyond the expectations of their customers. The use and application of information technology in insurer's operations has a direct impact on the productivity of resources, and huge impact on reducing the cost of various activities, this paper focus on the uses of Information technology in Insurance Industry.

**Keywords** - Information Technology, organisation, Resources.

**Introduction** - In the current scenario as we know very well that the volume of transaction is very large in insurance organization. The data and information are to be stored for a longer period because insurance contracts are long term. The insurance organization have the network all over the countries even in The foreign countries. Moreover the transactions are of recitative nature. Therefore it has become necessary to seek the help of machines to process the data.

## Objectives :

1. Explain the application of information technology in insurance Industry.
2. Describe the need for information technology in insurance Industry.
3. Discuss the role of information technology insurance Industry.

**Application of Information Technology in Insurance Industry** - Today, information technology is applied in almost all the sectors, such as, engineering, medicines, and soon. One such sector is the insurance sector. The evolutionary technological changes in the last decade has revolutionised the entire insurance sector. With greater competition among insurers, providing a better service has become a matter of concern. Additionally, customers are getting more and more sophisticated and inclined towards technology, so they do not want to accept the current value proposals, and prefer personalised interactions and better service.

Managing the customer intelligently is extremely significant for the insurer, especially in the competitive environment of today. Different set of rules and strategies need to be applied by the companies for different customer segments. Insurers need to capture customer information in an integrated system, for enhancing personalised interactions. With the increased use of internet and better access to direct policy information, better techniques need to be developed to provide customers a truly personalised experience. Personalisation facilitates organisations in

producing new revenue through cross selling and up selling activities, and in reaching their customers with more impact. Many organisations incorporate knowledge database repositories of content to ensure that the customers receive personalised information. This is done by installing a search engine. Which helps the customers to locate all document and information related to their queries. Customers use the database to manage their products or the company information, claim records, and histories of the service inquiry. These products also use the customer's information, when determining the significance of the customer's search request. Information technology enhances the speed and competence with which underwriters assess new applicants, and analyse aspects of their lives affecting the carrier's proposed financial risk.

## Need for Information Technology in Insurance Industry

- Today insurance industry is heading towards an exciting phase. Liberalisation and globalisation started allowing international players in the insurance sector. As many private and international players enter the insurance business, customers have a wide choice of insurance companies to do business with. Fundamental changes taking place in customer profile, is changing the life style of brand loyalty. In order to survive in insurance industry, modern insurers are focusing mainly on customer-centric relationship.

The insurance sector which was nationalised in 1950s was also liberalised in 1999, by Malhotra committee. After Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) Act in 1999, the first private sector business was started in 2001. Currently 15 players are ruling life insurance sectors, and 11 players are ruling non life insurance sectors. This expansion is mainly due to the technological enhancements in insurance sector. In 1985, information technology represented 52 percent of the total capital investments made by insurance sectors.

Effective utilisation of information technology is very

important for the success of insurance sector. Insurers adopt technology for information revolution. Customers can choose from a wide range of innovative products. The insurance companies use the applications of information technology for better customer service, cost reduction, product design and development. New technology offers insured persons, a faster access to products. Insurance sectors are being modernized by new technologies. Computing technology and network technology together form today's information technology. Advanced computer devices provide multimedia facilities in this sector. The need of information technology in insurance business is growing day by day. Insurers need to use information technology for the following reasons –

**Developing New Products** - Insurers must develop new products, which are based on forward-looking designs. Insurers must address their challenges by introducing innovative products. Companies must constantly develop products, in order to meet the upcoming changes in consumer requirements. Understanding the customer better enables the insurance organisations to develop the correct products, determine the rates correctly, and increase the profits. Presently, life insurers are focusing on the new pension plans, and non-life insurers are trying to enrich the market shares. **Management of Client Data** - Insurance companies need to use new technologies to maintain accurate client information records. They need to use information technology to store and retrieve client personal details, policy details, claim details.

**Marketing of Policies** - Insurance companies can market their policies using new technology like the mobile phone and internet. They can describe the salient features of their products and enable customers to choose products they need. They can expand their customer base using information technology.

**Claims Management** - For any company, paying recording claim's data is a crucial responsibility for maintaining its financial stability. Information technology plays a critical role in insurance, for recording claim's particulars and sharing information with claims inspectors and beneficiaries. Advanced computer devices ensure that significant data remains reachable and updated.

**Payment of Premiums** - Insurance companies can use information technology like internet and ECS system to collect premiums from their customers. Improve the efficiency of their operations - By using information technology, insurance companies can quickly process proposals and dispatch policy documents. Computerisation of payment related modules pertaining to loans and claims can help to reduce time-lag and ensure accuracy.

**Role of Information Technology in Insurance Industry** - The rapid development in information technology are posing serious challenges for insurance organisations. The use of information technology in insurance industry has an impact on the efficiency of the organisation as it reduces the operational costs. After many private players entered

the insurance industry the competition in the insurance sector has become immense. Information technology has helped in enhancing the insurance business. Insurance industry uses information technology for internal administration, accounting, financial management, reports and so on. Indian insurance organisations are rapidly growing as 'technology-driven' organisations, by replacing billions of files with folders of information. Insurers are heading towards the technological enhancements, in order to focus on the key areas of insurance business. Apart from this the role of IT in different fields of insurance like:

**Actuarial Investigation** - Insurers depend on the rates of actuarial models to decide the quantity of risks which create loss. Insurance organisations are using new technology to analyse the claims and policyholder's data for providing connection between risk characteristics and claims. Development in technology allow actuaries to examine risk more precisely.

**Policy Management** - Most of the insurance policies are printed and conveyed to policy owners through mail every year. The method of creating documents is accomplished by technicians and typists. In most of the cases, this task is generally completed by using new technology. Customer data is accessed by computer systems and maintained in huge folders in order to renew each policy. To assemble the policies complex software packages are used and to print policies high speed printers are utilised.

**Underwriting** - Underwriters can use knowledge based expert systems to make underwriting decisions. By using automated systems, underwriters can compare an individual's risk profile with their data and customize policies according to the individual's risk profile.

**Front and Operations** - CRM (Customer Relationship Management) Package are used to integrate the different function processes of the insurance company and provide information to the personnel dealing with the front end operations. CRM facilities easy retrieval of customer data. LIC is using CRM packages to handle its front end operations.

**Conclusion** - IT is playing important role in insurance sector and not only this the developments in telecommunication, have enable networking of various computer systems. The computers have been interlinked same office through Local Area Network (LAN). As the company has many offices all over the country and to facilitate the customers in network called Metro Area Network (MAN) is installed. Through this networking all the branches located in large cities have been interlinked. It is generally done branches. This system has enabled the data policy irrespective of the branch where the policy is underwritten. In this way policyholder is enable to make the payment of premium in any branch to get the receipt immediately.

As the technology is developing very fast the crime rate IT is also increasing and to protect the public interest the Govt. has implemented Indian Information Technology Act 2000 to avoid any crime in IT sector.



# References:-

1. Arumuga Vijaykumar (2009), Indian Insurance Sector in 21ST Century: An outlook, Kalpaz Publication India
2. Geroge E Rejda (2009), Risk Management and insurance, Dorling Kindersley, NewDelhi, India
3. Gupta PK. Insurance and Risk management, Himalaya Publishing House, India
4. Sethi Jyostna, Bhatiya Nishwan (2007), Elements of Banking and Insurance, First edition, PHIL earning Private Ltd. NewDelhi

5. Palande.P.S. ShahR.S. Lunawat.M.L. (2003), Insurance in India :Changing Policies and Emerging opportunities, NewDelhi.

# E-References :-

1. <http://www.objectwin.com/insurance.aspx>
2. <http://www.icaai.org/resource-file13528Module-IV.pdf>
3. <http://www.objectwin.com/Insurance.aspx> Retrived on 8th november,2010
4. <http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Cos-Des/DatabaseManagementSystem.html>

\*\*\*\*\*

## Custodial Deaths: Concept and Prospective

Ratna Bhattachrjee\* Dr. B.K. Yadav\*\*

**Introduction** - Custodial violence primarily refers to violence in police custody and judicial custody. It may be mental or physical in nature. Custodial death is defined as the death of a person due to any form of torture or cruel, inhuman or degrading treatment by the police officers, whether it occurs during investigation, interrogation or otherwise.

Custodial torture is universally held as one of the cruelest forms of human rights abuse. The Constitution of India, the Supreme Court, the National Human Rights Commission (NHRC) and the United Nations forbid it. But the police across the country defy these institutions. Therefore, there is a need to strike a balance between the individual human rights and societal interests in combating crime by using a realistic approach (Joginder Kumar v. State of Uttar Pradesh, (1994) 4 SCC 260)

A father and son -P Jeyaraj, 58, and his son Fenix, 38 -running a mobile accessory shop in Sathankulam town in Tuticorin district were arrested by some policemen allegedly for keeping the shop open past permitted hours. Tamil Nadu has imposed a strict lockdown to curb COVID-19.

The duo was taken to the police station where, as has been alleged by the family members, they were brutally assaulted. A few days later they were pronounced dead in jail. Hence, section 176 Criminal Procedure Code was amended and a special procedure created for investigating custodial deaths.

**RATE OF CUSTODIAL DEATHS:** On average, 96 persons die in **custody** every year. According to the India Annual Report on Torture 2019, there were a total of 1,731 **custodial deaths** in India. Out of those, 1,606 people died under judicial **custody** and 125 people died under police **custody**. This works out to almost five such **deaths** daily. "Out of the 125 **deaths** in **police custody**, Uttar Pradesh **topped** with 14 **deaths**, followed by Tamil Nadu and Punjab with 11 **deaths** each and Bihar with 10 **deaths**," said the report published by the National Campaign against Torture (NCAT).

This year alone, in the seven months up to July 2020, the National Human Rights Commission, **India** (NHRC) reported 914 **deaths** in custody, 53 of these in police

custody. As per their data, 714 people were reported to have **died** in police custody in cases registered between 2013-14 and 2017-18

In the last 10 years, the majority (69%) of 1,004 deaths in police custody have been attributed to either illness or natural causes (40%), or to alleged suicide (29%), in National Crime Records Bureau data.

Details on whether deaths by illness are due to a prolonged or sudden illness, or whether hospitalization is linked to conditions/ circumstances in custody, or due to assault in custody, are not provided in the NCRB's annual Crime in India reports, the key central government database.

More deaths by suicide in police custody have been reported over the past decade, with 36% reported as suicides during 2015-2019. In some cases, however, families have alleged foul play, or that suicides were prompted by custodial torture, a review of media reports suggests.

**NO OF CASES REPORTED:** Physical assault by police has been recorded only from 2014 onward and in just 6% of cases. In 2019, only 2.4% of the 85 deaths in police custody were attributed to assault by police in the report for that year. However, 76% of 124 deaths in police custody documented during the same year by the NGO platform National Campaign against Torture were attributed to torture or foul play.

The law requires that every death in custody be enquired into individually. Crime in India data on inquiries into death in police custody, however, does not specify if one person died in a given case or more, which leads to some discrepancy in the records. For instance, in the case of the two traders P Jayaraj and J Bennicks who died in police custody in Thoothukudi, Tamil Nadu, in June, one case pertains to two deaths.

Our review of 124 such cases from 2019 compiled by National Campaign Against Torture shows that 97% of the cases related to the death of one person. However, since 2017, 255 persons have died in police custody but 144 cases have been registered in this regard, per Crime in India data. (84 police personnel have been arrested, and charge sheets have been filed in 56 cases.) For the purpose

of this story, we have worked with the presumption that each case pertains to one death.

This second and concluding part of our series on deaths in police custody reveals non-compliance with mandatory post-death inquiry processes in 30% of cases, and gaps and ambiguity in Crime in India data on reasons for and enquiries into such deaths.

**RESPONSIBILITY:** The police department is responsible for custodial deaths. The **reasons** for the rise in **custodial deaths** are manifold. It is the **responsibility of** the police to look after the health and safety of a detained person under **custody**. The Human Rights Commission must be informed within 24 hours in the case of **custodial death** and 48 hours in an encounter **killing**.

#### REASONS :

**1. Deaths due to assault** - Only in 2014 did physical assault by police begin to be reported as a cause of death in police custody. In the last six years (2014 to 2019), 33 persons (6.1% of the 537 who died in police custody) died due to injuries sustained during custody due to physical assault by police, according to Crime In India reports. These numbers may be higher if the deaths due to illness/hospitalization.

**2. Mandatory inquiries foregone-** Mandatory judicial inquiries are critical in identifying reasons for deaths in police custody, but are not conducted in every case, experts said. The Crime in India reports also do not specify how the cause of death was ascribed, or which authority certified the stated cause in cases where enquiries were not ordered, or were ordered but not conducted, or were conducted but not completed in the same year. Many cases of custodial deaths are lodged as suicides.

**3. Poor health facilities in prisons** - The conditions in jails pose a health risk for prisoners, noted the India Justice Report (IJR) 2019. There should be at least one medical officer for every 300 prisoners and in central prisons one doctor should always be available, as per the Model prison Manual 2016. Twelve of the 20 states and union territories (UTs) studied in the report had a shortfall of 50% or more medical officers.

#### LANDMARK JUDGEMENTS ON CUSTODIAL DEATH: -

**1. Joginder Kumar v. State Of U.P and Others 1994 AIR 1349: 1994 SCC (4) 260:** The rights are inherent in Articles 21 and 22(1) of the Constitution and require be recognising and scrupulously protecting. For effective enforcement of these fundamental rights, Hon'ble Court issued the following guidelines:

The police officer shall inform the arrested person when he is brought to the police station of this right. An entry shall be required to be made in the diary as to who was informed of the arrest. These protections from power must be held to flow from Articles 21 and 22(1) and enforced strictly. It was further directed that, it shall be the duty of the Magistrate, before whom the arrested person is produced, to satisfy himself that these requirements have been complied with.

#### 1. *J. Prabhavathiamma v/s The State of Kerala & Others WP(C). NO. 24258 OF 2007 (K) AND CRL. R.P.2902 OF 2007* -

The two serving police personnel were awarded the death sentence by a CBI court, after hearing the case for over a decade, in Thiruvananthapuram, over the death of a scrap metal shop worker, who the court believes was murdered in custody. While sentencing the two, Judge J Nazar had said: "This is a brutal and dastardly murder by accused (number) one and two... The acts of the accused persons would definitely adversely affect the very institution of the police department... If the faith of the people in the institution is lost, that will affect the public order and law and order, and it is a dangerous situation.

#### 3. *Munshi Singh Gautam v State of Madhya Pradesh, Appeal (Crl.) 919 of 1999* -

Summarizes their grief concern about this problem of torture in Indian prisons by police. The supreme court stated that:

"The dehumanising torture, assault and death in custody which have assumed alarming proportions raise serious questions about the credibility of the rule of law and administration of the criminal justice system. The concern which was shown in Raghbir Singh case more than two decades back seems to have fallen on deaf ears and the situation does not seem to be showing any noticeable change. The anguish expressed in the cases of Bhagwan Singh v State of Punjab, Pratul Kumar Sinha v State of Bihar, Kewal Pati v State of UP, Inder Singh v. State of Punjab, State of MP v Shyamsunder Trivedi and the by now celebrated decision in the landmark case of D K Basu vs. State of West Bengal seems 'not even to have caused any softening of attitude in the inhuman approach in dealing with persons in custody'."

#### 4. *Yashwant And Others v. State of Maharashtra (2018) 4MLJ (Crl)10(SC)* -

The Supreme Court on September 4 upheld the conviction of nine Maharashtra cops in connection with a 1993 custodial death case and extended their jail terms from three to seven years each. Reportedly, a bench of Justices NV Ramana and MM Shantanagoudar upheld the order and said that incidents which involve the police tend to erode people's confidence in the criminal justice system. While enhancing the prison term of the cops, the apex court said, "With great power comes greater responsibility,". The police personnel were found guilty under Section 330 of the Indian Penal Code which involves voluntarily causing hurt to extort confession or to compel restoration of property.

#### 5. *D.K. Basu Versus State of West Bengal (1997 (1) SCC 416)* -

The Court issued a list of 11 guidelines in addition to the Constitutional and Statutory Safeguards to be followed in all cases of arrest and detention. The guidelines are as follows: -Details of all personnel handling the interrogations of the arrested person must be recorded in a register. a memorandum of arrest at the time of the arrest should be prepare. It must also be signed by the detainee and must contain the time and date of the arrest. Police must notify a detainee's time, place of detention,

and place of custody. Police of the affected area telegraphically within the period of 8 to 12 hours after the arrest. An entry must be made in the Case Diary at the place of detention.

The "Inspection Memo" must be signed by both the detainee and the arresting police officer and a copy must be provided to the detainee. The detainee must undergo a medical examination by a trained physician every 48 hours while in custody.

Copies of all documents, including the arrest memo, must be sent to the Magistrate for registration.

Information about the arrest and the place of custody of the arrested, within 12 hours after the arrest and in the Police Control Room Board, must be displayed on a visible notice board.

#### **REMEDIES AGAINST CUSTODIAL TORTURE:**

**1. CONSTITUTIONAL SAFEGUARD:** It has been held in a catena of judgments that just because a person is in police custody or detained or under arrest, does not deprive of him of his basic fundamental rights and its violation empowers the person to move the Supreme Court under Article 32 of the Constitution of India.

**2. Article 20 of the Constitution of India:** Article 20 primarily gives a person the rights against conviction of offences. These include the principle of non-retroactivity of penal laws (Nullum crimen sine lege) '**No crime, no punishment without a previous penal law**', **Article 22 of the Rome Statute of the International Criminal Court** i.e. ex-post facto laws thereby making it a violation of the persons fundamental rights if attempts are made to convict him and torture him as per some statute.

Article 20 also protects against double jeopardy (**Nemo Debet Pro Eadem Causa Bis Vexari**) **No one ought to be twice troubled or harassed [if it appears to the court that it is] for one and the same cause** This Article most importantly protects a person from self-incrimination. The police subject a person to brutal and continuous torture to make him confess to a crime even if he has not committed the same.

**3. Article 21 of the Constitution of India:** This article has been understood in the Indian judiciary to protect the right to be free from torture. This view is held because the right to life is more than a simple right to live an animalistic existence. The expression "life or personal liberty" in Article 21 includes a guarantee against torture and assault even by the State and its functionaries to a person who is taken in custody and no sovereign immunity can be pleaded against the liability of the State arising due to such criminal use of force over the captive person. (**D.K. Basu v. State of W.B., (1997) 1 SCC 416**)

**4. Article 22 of the Constitution of India:** Article 22 provides four basic fundamental rights with respect to conviction. These include being informed of the grounds of arrest, to be defended by a legal practitioner of his choice, preventive detention laws and production before the nearest Magistrate within 24 hours of arrest of the person. Thus,

these provisions are designed to ensure that a person is not subjected to any ill-treatment that is devoid of statutory backing or surpasses prescribed excesses.

#### **Other Statutory Safeguards:**

**Indian Evidence Act, 1872:** A confession to police officer cannot be proved as against a person accused of any offence (Sec. 25 Evidence Act) and confession caused by threats from a person in authority in order to avoid any evil of a temporal nature would be irrelevant in criminal proceedings as, inter-alia, provided in Sec. 24. Thus, even though custodial torture is not expressly prohibited by law in India, the evidence collected by illegal means, including torture is not accepted in courts.

**Code of Criminal Procedure, 1973:** Sec. 46 and 49 of the Code protect those under custody from torture who are not accused of an offence punishable with death or imprisonment for life and also during escape. Sec. 50-56 are in consonance with Article 22. Sec. 54 of the Code is a provision that to a significant extent corresponds to any infliction of custodial torture and violence

**Indian Police Act:** Sections 7 and 29 of the Act provide for dismissal, penalty or suspension of police officers who are negligent in the discharge of their duties or unfit to perform the same. This can be seen in the light of the police officers violating various constitutional and statutory safeguards along with guidelines given

**Indian Penal Code (IPC), 1860:** After the controversial (**Mathura Rape case (1979) 2 SCC 143**), an amendment was brought about in Sec. 376 of the IPC. Sec. 376(1)(b) penalises custodial rape committed by police officers.

This was a welcome change made to the section in question as it finally condemns the acts of police officers who take advantage of their authority.

Sections 330, 331, 342 and 348 of the IPC have ostensibly been designed to deter a police officer, who is empowered to arrest a person and to interrogate him during investigation of an offence from resorting to third degree methods causing 'torture'.

**Conclusion -** India should ratify the UN Convention against Torture: It will mandate a systematic review of colonial rules, methods, practices and arrangements for the custody and treatment of persons subjected to any form of arrest, detention or imprisonment.

It will also mean that exclusive mechanisms of redress and compensation will be set up for the victim besides institutions such as the Board of Visitors.

**Police Reforms:** Guidelines should also be formulated on educating and training officials involved in the cases involving deprivation of liberty because torture cannot be effectively prevented till the senior police wisely anticipate the gravity of such issues and clear reorientation is devised from present practices.

**Access to Prison:** Unrestricted and regular access to independent and qualified persons to places of detention for inspection should also be allowed.

CCTV cameras should be installed in police stations



including in the interrogation rooms.

Surprise inspections by Non-Official Visitors (NOVs) should also be made mandatory which would act as a preventive measure against custodial torture which has also been suggested by Supreme Court in its landmark judgment in the DK Basu Case in 2015.

Implementation of Law Commission of India's 273rd Report: The report recommends that those accused of committing custodial torture – be it policemen, military and paramilitary personnel – should be criminally prosecuted instead of facing mere administrative action establishing an effective deterrent.

#### **References:-**

1. Crime In India reports 2010-19, National Crime Records Bureau

2. Crime in India report, 2019 National Crime Records Bureau

#### **Leading Cases:**

1. Joginder Kumar v. State Of U.P and Others 1994 AIR 1349: 1994 SCC (4) 260.
2. J. Prabhavathiamma v/s The State of Kerala & Others WP(C). NO. 24258 OF 2007 (K) AND CRL. R.P.2902 OF 2007
3. Munshi Singh Gautam v State of Madhya Pradesh, Appeal (Crl.) 919 of 1999.
4. Yashwant And Others v. State of Maharashtra (2018) 4MLJ (Crl)10(SC).
5. D.K. Basu Versus State of West Bengal (1997 (1) SCC 416).

\*\*\*\*\*

# Printed Hindi Characters: Pattern Recognition and Classification

Prof. Rafi Mohammed Shaikh\*

**Introduction** - Pattern Recognition is defined as the field concerned with machine recognition of meaningful regularities in noisy and complex environments. There are various applications of pattern recognition such as character recognition, online signature verification, and face recognition and so on. Character Recognition is the electronic conversion of scanned images of printed or handwritten text into machine readable text. Character recognition system is the base for many different types of applications in various fields, many of which we use in our daily lives. Hindi character recognition is the challenging problem in Pattern Recognition and Neural Networks is one of the most commonly used techniques for character recognition and classification due to their learning and generalization abilities. Various part of this paper describes and discusses the classification and recognition of printed Hindi characters using Artificial Neural Networks. Some of the previous approaches related to this work are given in Paper. The entire recognition process is explained in this paper gives the training procedure of neural networks. Testing, Results and final conclusions also given in this paper.

**Review of Previous Approaches** - A good text recognizer has many commercial and practical applications such as processing cheques in banks, documentation of library materials, extracting data from paper documents, searching data in scanned book, automation of any organization like post office, which involve lot of manual task of interpreting text. The problem of text recognition has been attempted by many different approaches; some of them are Template matching, Feature extraction, Geometric approach and neural networks. Template matching approach is one of the most simplistic approaches. This is based on matching the stored data against the character to be recognized.

Various image pre-processing, feature extraction, classification algorithms, to design high performance OCR software for handwritten Hindi alphabets. Image pre-processing included Median filtering, Background removal, Threshold and sparsity removal. In feature selection and extraction, histograms of oriented gradients were used.

Template matching involves determining similarities between the given template and stored database and output the image that produces the higher similarity measure. This

technique works effectively with recognition of standard fonts, but gives poor performance with handwritten characters, noisy characters and deformed images.

The objective of feature extraction is to capture the essential characteristics of the symbols and this is one of the most difficult problems of pattern recognition. In this approach, statistical distribution of points is analyzed and orthogonal properties are extracted. For each symbol a feature vector is calculated and stored in database, and recognition is performed by finding distance of feature vector of input image with those stored in the database and giving the symbol with minimum deviation. This is very sensitive to noise and edge thickness, but performs well on handwritten character set.

**Recognition Process** - Character recognition is one of the important tasks in pattern recognition. The complexity of the character recognition problem depends on the character set to be recognized. Character recognition process is dependent upon number of factors like various font sizes, noise, broken lines or characters etc. and these factors influence the results of recognition system. Artificial Neural Network is one of the techniques widely used for character recognition problem and considered as a powerful classifier on account of their high computation rate accomplished by massive parallelism. There are four different phases in character recognition processes namely Character acquisition, pre-processing stages, grouping of characters and Character Recognition.

**Thinning Operation** - Thinning is a morphological operation that is used to remove selected foreground pixels from binary images. Thinning extracts the shape information of the characters. Thinning is also called skeletonization. Skeletonization refers to the process of reducing the width of a line from many pixels to just single pixel. This process can remove irregularities in letters and in turn, makes the recognition algorithm simpler because they only have to operate on a character stroke, which is only one pixel wide. It also reduces the memory space required for storing the information about the input characters and also reduces the processing time too. The final stage in pre-processing is thinning. Image thinning extracts a skeleton of the image without loss of the topological properties [13]. The thinning algorithm consists of both boundary pixel analysis and

connectivity analysis. The binary image before and after thinning is given in the figure 3. The above pre-processing steps are applied to all vowels and consonants of Hindi characters.

**Neural Network** - Recognition of printed Hindi character is performed by giving the input image of the character. The given image is first converted into a gray scale image. Then the gray level image is converted into a binary image using threshold. Afterwards noise is eliminated by using filters. The next step is size normalization followed by thinning which extracts the skeleton of the image without any loss of the topological properties. After pre-processing of character, features of character are extracted. This step helps in classifying the characters based on their features. In this work, Hindi characters can be classified into three subgroups. Hence three feed forward neural networks are designed to recognize the characters in each sub group. The back propagation learning algorithm is used to train each network with the characters in that group as input examples to that network. This network takes input-output vector pairs during training. During training the weights of the network are iteratively adjusted to minimize error. The input image, number of neurons in each layer, learning rate, momentum and error value is given as input. The integrated module takes its input from the output of any one of the three networks and with the help of the subgroup, it recognizes and classifies character.

**Accuracy and Efficiency** - The vowels and consonants of Hindi character set are divided into 3 subgroups based on certain significant characteristics. For each subgroup, a separate feed forward neural network is designed to recognize the character which belongs to that group. Back propagation algorithm is used to train each network with examples. Finally, after training the neural networks with proper set of examples of each sub group, the performance of the system is tested with various test patterns with and without noise. The system recognized the character which had a noise up to 40%. Overall performance of network is tested with test samples. It achieved a recognition rate in the range of 76% - 95% for various samples. The results also show that the recognition accuracy and efficiency of the network increases with more number of training samples.

**Conclusion** - Character recognition is one of the important applications of pattern recognition. Instead of using only one neural network for recognizing and classifying Hindi vowels and consonants, we divided the characters into three subgroups based on certain significant features and three feed forward neural networks are designed and trained to

recognize the character in each subgroup. It is observed that recognition accuracy is increased by using the concept of subgroups instead of single network. This work is limited to recognition of Hindi vowels and consonants. Good recognition rate is achieved for the following characters since these characters are of simplistic in nature.

#### References :-

1. Line Eikvil (1993) Optical Character Recognition , December.
2. A.K.Jain, Mohiuddin (1996) Artificial Neural Networks: A Tutorial, IEEE Computers, 29, 31-44.
3. Anil K. Jain, Orivind Due Trier and TorfinnTaxt (1996) Feature Extraction Methods For Character Methods- A survey, Pattern Recognition, Vol. 29. No 4, PP 641-662.
4. Swamy Saran Atul and Swapneel Prasanth Mishra (2007) Hand-Written Devnagari Character Recognition, NIT, Rourkela.
5. B. Indira, (2008) Artificial neural networks and its use in Automatic Recognition of Vehicle Registration Numbers, Ph.D. thesis.
6. PoojaAgarwal, M. Hanmandlu, BrejeshLall, (2009) Coarse classification of Handwritten Hindi Characters , International Journal of Advanced Science and Technology, Vol. 10, September.
7. Latesh Malik, P. S. Deshpande (2009) Recognition of Printed Devanagari Characters with Regular Classification and Recognition of Printed Hindi Characters Using Artificial Neural Networks 21 Copyright © 2012 MECS I.J. Image, Graphics and Signal Processing, 2012, 6, 15-21 Expression in Finite State Models , proceedings of International workshop on Machine Intelligence Research.
8. Aditi Goyal, Kartikay Khandelwal, piyush Keshri, (2010) Optical Character Recognition for Handwritten Hindi , Stanford University, CS229 Machine Learning, Fall.
9. Raghuraj Singh, C. S. Yadav, Prabhat Verma, Vibhash Yadav, (2010) Optical Character Recognition (OCR) for Printed Devnagari Script using, Artificial Neural Network , International Journal of Computer Science & Communication Vol. 1, No. 1, PP. 91-95.
10. Veena Bansal and R.M.K. Sinha (2010) Segmentation of Touching and Fused Devanagari Characters IIT, Kanpur.
11. Dyashankar Singh, Sajay Kr. Singh, Dr. (Mrs) Mitreyee Dutta (2010) Hand Written Character Recognition Using Twelve Directional Feature Input and Neural Network International Journal of Computer Applications (0975 – 8887) vol. 1 – No. 3.

# Development of Teaching-Learning Materials

Dr. Pritam Kaur\*

**Abstract** - In educational institutions, the development of teaching-learning materials is regarded as one of the major aspects that would promote student learning and help in the achievement of academic goals and objectives. The educators need to focus upon bringing about developments in the teaching-learning materials. They need to conduct research and promote modern and innovative methods to enrich the system of education. The advancements in teaching-learning materials are brought about on the basis of number of aspects. These are, grade levels of students, academic goals and objectives and subjects and concepts. When these are introduced, the educators need to ensure that they prove to be beneficial to the students in achieving academic goals. Research has indicated that the introduction of modern and innovative methods and teaching-learning materials have led to developments of the overall system of education. The main aspects that have been taken into account in this research paper are, significance of teaching-learning materials, objectives of teaching-learning materials, types of teaching-learning materials, designing and development of teaching-learning materials, and recommendations.

**Keywords** - Classroom Setting, Development, Educators, Students, Teaching-Learning Materials.

**Introduction** - Teaching-Learning Materials (TLMs) are the tools that are used by teachers and instructors within schools to facilitate learning and understanding of concepts among students. These are the educational materials that are used within the classroom setting to support the learning objectives, as set-out within the lesson plans (Teaching Learning Materials, n.d.). Within the education system, there has been use of TLMs since ancient times. With the classroom setting, the major role that has been rendered by the TLMs is to make learning real, practical and pleasurable for the students. The teachers also make use of TLMs to illustrate or reinforce a skill, viewpoint, perspective or an idea. TLMs also render a significant contribution in bringing novelty and freshness within the classroom environment (Unit 7: Teaching Learning Materials, n.d.). It is essential for the educators to possess adequate knowledge and information regarding the use of TLMs. In other words, they should be skilled and well-aware of what TLMs are required to be made use of. The major aspects that need to be taken into account regarding the use of TLMs are, grade levels of students, subjects, learning abilities and academic goals.

**Significance of Teaching-Learning Materials** - The major significance of teaching-learning materials is recognized within the classroom environment by providing support and assistance to the educators with the presentation and transmission of educational content and the achievement of educational objectives. The teaching-learning materials are put into practice by the educators with the primary objectives of imparting learning among students regarding the academic concepts and enabling them to achieve their

goals and objectives. The significance of teaching-learning materials is usually recognized in terms of five aspects. These are, student motivation, developing creativity, evoking prior knowledge, encouraging the processes of interpreting, understanding, organizing and amalgamating the educational content, logical thinking, reasoning, and communication and contributing to the development of different skills, values and attitudes among students, and enabling them to acquire an efficient understanding of the academic concepts. The teaching-learning materials are defined as the instruments of presentations and transmission of the prescribed educational material (Busljeta, 2013).

The teaching-learning materials can be differentiated in terms of various characteristics that are apparent at first glance. When these are used in different classroom environments, then the students are required to possess various skills. For instance, when they are making use of technology to prepare their assignments, reports or projects, then it is vital for them to acquire efficient knowledge. In the field of didactic theory, as well as in teaching practice, the classification of teaching-learning materials into visual, auditory and audio-visual is universally acknowledged (Busljeta, 2013). Furthermore, it is essential for the educators as well as the students to possess effective communication skills, especially when they are making use of any types of teaching-learning materials. When the educators will be able to communicate in an effective manner, then they would facilitate understanding among students. Whereas, when students augment their communication skills, then they will be able to acquire an

\*Principal, Swami Vivekanand Teacher's Training College, 14 KSP Shergarh, Hanumangarh (Raj.) INDIA



efficient understanding of the academic concepts. The educators and the students need to collaborate with each other in the development of teaching-learning materials.

**Objectives of Teaching-Learning Materials** - The primary objective of teaching-learning materials is to motivate students towards acquisition of education. These are primarily used by teachers to provide assistance and support to the learners to achieve academic outcomes. The major objectives have been stated as follows: (Unit 7: Teaching Learning Materials, n.d.).

**Motivate Learners** – The teachers make use of not only one, but various forms of teaching-learning materials within the classroom setting. When they are making use of them, they ensure that students are able to feel pleasurable and get motivated towards learning. Therefore, students develop interest and enthusiasm and develop motivation towards learning.

**Development of Knowledge and Skills among Teachers** – Through the implementation of teaching-learning methods in an effectual manner, the teachers are able to develop their knowledge and skills. They are able to generate awareness, regarding how to make use of this knowledge in performing their job duties well. They need to make use of these skills and knowledge in the achievement of educational objectives.

**Help in Longer Retention of Information** – The TLMs, when implemented should ensure that they help in the longer retention of information. When learners pay appropriate attention towards TLMs, then they are not only able to acquire an effective understanding of the concepts, but also are able to promote longer retention of information.

**Facilitate Holistic Learning** – Through TLMs, the learners are not only able to acquire an efficient understanding of the academic concepts, but the teachers also assist and support them in augmentation of psycho-motor, cognitive and intellectual development. As development of these aspects are regarded as essential for promoting effective decision making processes and rational thinking.

**Help in Organizing Classroom Teaching** – The teachers are able to generate awareness in terms of implementation of lesson plans and concepts. When they are using teaching-learning methods in an appropriate manner, then they are able to plan and organize the teaching methods too within the classroom. In addition, they are able to generate awareness in terms of concepts.

**Promoting Effective Communication** – The use of adequate teaching-learning methods help in promoting effective communication processes between the teachers and students and among students themselves. The communication processes between them takes place in verbal and written forms. Therefore, both forms of communications get promoted among the teachers and students and students themselves.

**Facilitating Change in Attitudes** – The teachers as well as students are able to bring about changes in attitudes and behavioural traits through the use of teaching-learning

methods. Primarily, when modern and innovative methods are made use of, then students feel motivated towards learning and are also able to bring about changes in attitudes.

**Practical Applications** – TLM promotes the application of theoretical knowledge into practical applications. The theoretical knowledge that is studied in classes are depicted in the concrete form through TLMs for effective teaching. The application of theoretical knowledge into practical applications enables the students to achieve academic outcomes in an effective manner.

**Designing and Development of Teaching-Learning Materials** - In the designing and development of teaching-learning materials, there are three major aspects that need to be taken into account. These are, collection, preparation and maintenance. These have been stated as follows: (Unit 7: Teaching Learning Materials, n.d.).

**Collection** - The individuals within educational institutions belong to diverse backgrounds. They are different from each other in terms of factors, such as, caste, creed, race, ethnicity, religion, gender, age, educational qualifications, skills and socio-economic background. The viewpoints and perspectives of individuals differ from each other. In the designing and development of teaching-learning materials, when the collection step is taken into consideration, then it primarily is referred to collection of materials. These materials can include, sticks, bamboo, plastic, rubber, wood, wires, pins, papers, stationary items, colours, paints etc. The collection step is the first and foremost step in the preparation of any teaching-learning materials or any project. For example, when researchers are engaged in research projects, they are required to collect data from the sample population. When the data is collected, only then, it can be analysed to obtain the results. Before the collection method is put into practice, it is essential for the individuals to generate awareness in terms of what they are preparing. In other words, they need to be aware of their goals and objectives. The participation of students in collection is meaningful and useful in the achievement of desired goals and objectives.

**Preparation** - After the collection of materials, the next step is the preparation of teaching-learning materials. When the preparation of teaching-learning materials takes place, then various aspects need to be taken into account. These are the grade levels of the students, subjects and concepts, learning abilities and academic goals. One of the major aspects is to ensure is, students are able to enhance their learning and acquire a better understanding of the academic concepts. The teachers need to guide and instruct the students to develop simple TLMs. In the preparation of TLMs, it is vital to ensure that they comprise of all the points that are relevant to the concepts. As it has been stated above that posters and charts are also various forms of TLMs, the preparation of posters and charts are common. When the teachers teach a lesson plan to the students regarding mathematics, English, Hindi, science or social

science, they normally assign them the task of preparing a chart or a poster.

**Maintenance** - Once the TLMs have been designed and developed, it is vital to maintain them for future use. When one is engaged in the preparation of TLMs, they make use of skills, abilities, financial resources and time. When one feels that TLMs are required to be used in future as well, then the educators even instruct their students to maintain them. When they are making use of them, they need to be careful that they do not get damaged. In the case of maintenance, there are certain principles that need to be taken into account. These are, proper space should be made available for storing them, these should be neatly arranged and maintained, they should be checked from time to time and repairs need to get carried out, when required. When the TLMs are prepared or purchased, it is vital to maintain their entry within the stock registers. When students find that any part of TLMs or anything is damaged or broken, they need to bring that immediately to the attention of the teacher.

**Recommendations** - The main objective of highlighting recommendations is to provide information in terms of strategies and measures that are used to promote teaching-learning materials within educational institutions at all levels. These have been stated as follows:

When the educators are putting into operation the teaching-learning methods, they need to ensure that they are in accordance to the needs and requirements of the students and grade levels. Research has indicated that due to lack of proper teaching-learning methods, the students are unable to acquire an efficient understanding of the concepts, nor are able to develop the basic literacy skills of reading, writing and numeracy. From the stage of early childhood, it is vital to ensure that teaching-learning materials should be implemented in such a manner that students feel motivated and augment interest and enthusiasm towards acquisition of education. When the teaching-learning methods will be in accordance to their needs and requirements, only then they will be able to augment their learning.

Preparation of a framework of textbook revision and renewal in accordance to the phase of emergency. During emergency it is essential to maintain a production of textbooks as a priority. During the early reconstruction phase, a national plan of action is prepared, which includes, the training of the staff members, needs assessment, training of the individuals, procurement of necessary equipment, textbook revision workshops and so forth (Chapter 4.8, n.d.). To implement these tasks and functions, it is necessary for the individuals to form communication and collaborative terms and relationships with the other individuals in other educational institutions. Generating awareness in terms of modern and innovative methods and approaches regarding other educational institutions is essential for achieving the desired academic goals.

In order to implement the teaching-learning methods

in an appropriate manner, it is vital for the educators to be well-prepared and aware. When the educators come to the classrooms to give their lectures, then it is vital for them to possess adequate information in terms of lesson plans, concepts and other questions that may be put forward by the students. They need to ensure that students acquire an efficient understanding of the concepts, before they get promoted in the next class. The main reason behind stating this recommendation is, it has been researched upon that students, studying in class five are unable to read class three textbooks, nor they are able to solve numerical problems involving division by two digits. Therefore, previous concepts regarding all subjects need to be understood better, before seeking admission in the next class.

Development of an equitable distribution mechanism and to make provision for the maintenance and replenishment of materials is also important. In this case, there are certain aspects, which are considered vital. These are, geographic locations, socio-economic considerations, and linguistic inclusions. Furthermore, it is vital to consider the ways that would promote the participation of community members in designing and implementation of the distribution system for the materials, as this would help in making the system more transparent. Another important point that needs to be highlighted is, through the development of the information campaign, the individuals and families can be informed of the materials that would be provided to them (Chapter 4.8, n.d.). In other words, when the individuals will acquire knowledge in terms of appropriate teaching-learning materials in schools, then they would encourage enrolment of their children.

Another recommendation is, using teaching and learning evaluation schedule. The teaching and learning evaluation schedule is used to assist the individual teachers and groups of teachers to identify the areas of teaching. In addition, they are also able to identify the pedagogy and practice units that would be most appropriate for teaching. The individuals are able to make use of teaching-learning materials in a best manner by sharing it with others (Pedagogy and Practice, 2004). Others mainly include, other teachers, and colleagues. When other individuals are able to acquire knowledge, then further improvements can also take place by obtaining ideas and suggestions. The head mistress in schools and the heads of the departments in higher educational institutions are the individuals, who evaluate the teaching-learning methods and materials.

Implementation of study units are regarded indispensable as they can be used by teachers with different competence and skills. The study units need to be designed with the maximum flexibility in mind. They do not require attendance at external courses. The educators with varying skills and competence can make use of them. They can be used in a best way by the teachers of varying skills and competencies. Classroom lectures are regarded important, as individuals possess this viewpoint that through classroom

lectures, professional development of the students can be promoted. The study units offer the means through which the educators can conduct research and develop a teaching competence or skill in a practical manner that will have an immediate impact upon classroom activity and student learning (Pedagogy and Practice, 2004).

It is essential for the educators to act as leaders, guides and counsellors to the students. In some cases, with the use of modern and innovative teaching-learning materials, the students feel vulnerable and apprehensive and are not able to understand academic concepts. In such cases, it is the job duty of the educators to instruct them adequately, so they are able to make use of teaching-learning methods in an appropriate manner to enhance academic outcomes. On the other hand, there have been cases of students, who experience learning disabilities and are not able to understand the teaching-learning methods used. In such cases, it is vital on the part of the educators to provide them sufficient support and assistance. It is necessary for educators employed in educational institutions at all levels to possess leadership skills, needed to guide and direct students.

**Conclusion** - In the system of education, teaching-learning materials are regarded to be of utmost significance. When promoting enrichment of the overall system of education, it is essential to make improvements in teaching-learning materials. In all levels of education from pre-schools to universities, the educators need to pay adequate attention towards the implementation of teaching-learning materials. It is through the availability of proper teaching-learning materials that educational institutions can render an effective contribution in achieving the desired educational objectives and promoting effective growth and development of students. The major objectives of teaching-learning materials are to motivate learners, development of knowledge and skills among teachers, help in longer retention of information, facilitate holistic learning, help in organizing classroom teaching, promoting effective communication, facilitating change in attitudes, practical applications, making learning pleasurable and concept formation. These objectives can be achieved through the possession of adequate skills and abilities and efficacious implementation of teaching-learning materials.

The different types of teaching-learning materials are, audio and video TLMs, textbooks, maps, charts, posters, models, overhead projector, Power Point slides, computers and other reading materials. When the educators are making

use of these teaching-learning materials, then it is vital for them to possess adequate skills and generate awareness in terms of which materials need to be made use of in imparting understanding of academic concepts among students, belonging to what grade levels and subjects. In the designing and development of teaching-learning materials, there are three major aspects that need to be taken into consideration. These are, collection, preparation and maintenance. The individuals, need to make use of proper materials and put into practice appropriate methods and strategies, when they are designing and developing the teaching-learning materials. When the individuals are not aware, then it is vital for them to attend workshops or training programs or seek ideas and suggestions from experts and professionals. Finally, it can be stated that to bring about developments in teaching-learning methods, the individuals need to work in integration and collaboration with others and conduct research to augment their skills and abilities.

#### References :-

1. Busljeta, R. (2013). Effective Use of Teaching and Learning Resources. Czech-Polish
2. Historical and Pedagogical Journal, 5(2), 55-69. Retrieved June 27, 2019 from
3. <https://www.ped.muni.cz/cphpjournal/520132/06.pdf>
4. Chapter 4.8. (n.d.). Textbooks, Educational Materials and Teaching Aids. International
5. Institute for Educational Planning. Retrieved June 28, 2019 from
6. [http://www.iiep.unesco.org/sites/default/files/Guidebook%20Chapters/GB\\_2009\\_4.8\\_final.pdf](http://www.iiep.unesco.org/sites/default/files/Guidebook%20Chapters/GB_2009_4.8_final.pdf)
7. Pedagogy and Practice: Teaching and Learning in Secondary Schools. Leadership guide.
8. (2004). Retrieved June 28, 2019 from
9. <https://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/130423-pedagogy-and-practice-teaching-and-learning-in-secondary-schools-en.pdf>
10. Teaching Learning Materials. (n.d.). Promoting Quality of Education in Flood Affected
11. Areas. Retrieved June 27, 2019 from
12. <http://itacec.org/itadc/phase2/document/dissemination/4.pdf>
13. Unit 7: Teaching Learning Materials. (n.d.). Retrieved June 27, 2019 from
14. <http://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/8511/1/Unit-7.pdf>

\*\*\*\*\*

# The Impact of Technology on the Environment and How Environmental Technology Could Save Our Planet

Nitesh Sharma\*

**Introduction** - This article takes a look at the paradoxical ideology that while the impact of technology on the environment has been highly negative, the concept of environmental technology could save our planet from the harm that has been done. This idea is supported by WWF who have stated that although technology is a solution enabler it is also part of the problem.

The term 'technology' refers to the application of scientific knowledge for practical purposes and the machinery and devices developed as a result. We are currently living in a period of rapid change, where technological developments are revolutionizing the way we live, at the same time as leading us further into the depths of catastrophe in the form of climate change and resource scarcity.

This article will begin by discussing the negative impact of technology on the environment due to the causation of some of the world's most severe environmental concerns, followed by the potential that it has to save the planet from those same problems.

**The Impact of Technology on the Environment** - The industrial revolution has brought about new technologies with immense power. This was the transition to new manufacturing processes in Europe and the United States, in the period from about 1760 to 1840. This has been succeeded by continued industrialization and further technological advancements in developed countries around the world, and the impact of this technology on the environment has included the misuse and damage of our natural earth.

These technologies have damaged our world in two main ways; pollution and the depletion of natural resources.

**1. Air and water pollution** - Air pollution occurs when harmful or excessive quantities of gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitric oxide and methane are introduced into the earth's atmosphere. The main sources all relate to technologies which emerged following the industrial revolution such as the burning of fossil fuels, factories, power stations, mass agriculture and vehicles. The consequences of air pollution include negative health impacts for humans and animals and global warming, whereby the increased amount of greenhouse gases in the air trap thermal energy in the Earth's atmosphere and cause

the global temperature to rise.

Water pollution on the other hand is the contamination of water bodies such as lakes, rivers, oceans, and groundwater, usually due to human activities. Some of the most common water pollutants are domestic waste, industrial effluents and insecticides and pesticides. A specific example is the release of inadequately treated wastewater into natural water bodies, which can lead to degradation of aquatic ecosystems. Other detrimental effects include diseases such as typhoid and cholera, the destruction of ecosystems which negatively affects the food chain.

**2. Depletion of natural resources** - Resource depletion is another negative impact of technology on the environment. It refers to the consumption of a resource faster than it can be replenished. Natural resources consist of those that are in existence without humans having created them and they can be either renewable or non-renewable. There are several types of resource depletion, with the most severe being aquifer depletion, deforestation, mining for fossil fuels and minerals, contamination of resources, soil erosion and overconsumption of resources. These mainly occur as a result of agriculture, mining, water usage and consumption of fossil fuels, all of which have been enabled by advancements in technology.

Due to the increasing global population, levels of natural resource degradation are also increasing. This has resulted in the estimation of the world's eco-footprint to be one and a half times the ability of the earth to sustainably provide each individual with enough resources that meet their consumption levels. Since the industrial revolution, large-scale mineral and oil exploration has been increasing, causing more and more natural oil and mineral depletion. Combined with advancements in technology, development and research, the exploitation of minerals has become easier and humans are therefore digging deeper to access more which has led to many resources entering into a production decline.

Moreover, the consequence of deforestation has never been more severe, with the World Bank reporting that the net loss of global forest between 1990 and 2015 was 1.3 million km<sup>2</sup>. This is primarily for agricultural reasons but also logging for fuel and making space for residential areas,



encouraged by increasing population pressure. Not only does this result in a loss of trees which are important as they remove carbon dioxide from the atmosphere, but thousands of plants and animals lose their natural habitats and have become extinct.

**Environmental Technology** - Despite the negative impact of technology on environment, a recent rise in global concern for climate change has led to the development of new environmental technology aiming to help solve some of the biggest environmental concerns that we face as a society through a shift towards a more sustainable, low-carbon economy. Environmental technology is also known as 'green' or 'clean' technology and refers to the development of new technologies which aim to conserve, monitor or reduce the negative impact of technology on the environment and the consumption of resources.

The Paris agreement, signed in 2016, has obliged almost every country in the world to undertake ambitious efforts to combat climate change by keeping the rise in the global average temperature at less than 2°C above pre-industrial levels. This section will focus on the positive impact of technology on the environment as a result of the development of environmental technology such as renewable energy, 'smart technology', electric vehicles and carbon dioxide removal.

Renewable energy, also known as 'clean energy', is energy that is collected from renewable resources which are naturally replenished such as sunlight, wind, rain, tides, waves, and geothermal heat. Modern environmental technology has enabled us to capture this naturally occurring energy and convert it into electricity or useful heat through devices such as solar panels, wind and water turbines, which reflects a highly positive impact of technology on the environment.

The cost of renewable energy technologies such as solar panels and wind turbines are falling and government investment is on the rise. This has contributed towards the amount of rooftop solar installations in Australia growing from approximately 4,600 households to over 1.6 million between 2007 and 2017. Smart home technology uses devices such as linking sensors and other appliances connected to the Internet of Things that can be remotely monitored and programmed in order to be as energy efficient as possible and to respond to the needs of the users.

The Internet of Things is a network of internet-connected objects able to collect and exchange data using embedded sensor technologies. This data allows devices in the network to autonomously 'make decisions' based on real-time information. For example, intelligent lighting systems only illuminate areas that require it and a smart thermostat keeps homes at certain temperatures during certain times of day, therefore reducing wastage.

This environmental technology has been enabled by increased connectivity to the internet as a result of the increase in availability of WiFi, Bluetooth and smart sensors

in buildings and cities. Experts are predicting that cities of the future will be places where every car, phone, air conditioner, light and more are interconnected, bringing about the concept of energy efficient 'smart cities'. The technology of the internet further demonstrates a positive impact of technology on the environment due to the fact that social media can raise awareness of global issue and worldwide virtual laboratories can be created. Experts from different fields can remotely share their research, experience and ideas in order to come up with improved solutions. In addition, travel is reduced as meetings/communication between friends and families can be done virtually, which reduces pollution from transport emissions. The environmental technology of the electric vehicle is propelled by one or more electric motors, using energy stored in rechargeable batteries. Since 2008, there has been an increase in the manufacturing of electric vehicles due to the desire to reduce environmental concerns such as air pollution and greenhouse gases in the atmosphere. Electric vehicles demonstrate a positive impact of technology on the environment because they do not produce carbon emissions, which contribute towards the 'greenhouse effect' and leads to global warming. Furthermore, they do not contribute to air pollution, meaning they are cleaner and less harmful to human health, animals, plants, and water.

For a slightly more ambitious technology to conclude with, the idea of pulling carbon dioxide directly out of the atmosphere has been circulating climate change mitigation research for years, however it has only recently been implemented and is still in the early stages of development. The environmental technology is known as 'Direct Air Capture' (DAC) and is the process of capturing carbon dioxide directly from the ambient air and generating a concentrated stream of CO<sub>2</sub> for sequestration or utilization. The air is then pushed through a filter by many large fans, where CO<sub>2</sub> is removed. It is thought that this technology can be used to manage emissions from distributed sources, such as exhaust fumes from cars. Full-scale DAC operations are able to absorb the equivalent amount of carbon to the annual emissions of 250,000 average cars. Many argue that DAC is essential for climate change mitigation and that it can help reach the Paris Climate Agreement goals, as carbon dioxide in the air has been the main cause of the problem after all. However, the high cost of DAC currently means that it is not an option on a large scale and some believe that reliance on this technology would pose a risk as it may reduce emission reduction as people may be under the pretense that all of their emissions will simply be removed.

Although we cannot reverse the negative impact of technology on the environment caused by industrialization, many believe that new environmental technology, such as renewable energy combined with smart logistics and electric transport, has the potential to bring about the rapid decarbonization of our economy and the mitigation of further

detrimental harm.

# References :-

1. <https://simple.m.wikipedia.org/wiki/Environment>
2. [https://www.brainspire.com/blog/positive-effects-of-](https://www.brainspire.com/blog/positive-effects-of-technology-making-everyday-life-better)
3. Environmental technology and Sustainability by Basant Kumar and Ram Parsad
4. Environmental Education By Archana Tomar

\*\*\*\*\*

# Mass Media Exposure of Dairy Farmers in North Gujarat

Dr. Yogesh Chandra Joshi \*

**Abstract** - Banaskantha and Mehsana district were purposively selected for study. Banaskantha district comprises of fourteen talukas out of which, two talukas viz:- Palanpur and Deesa, while Mehsana district comprises of nine talukas out of which, two talukas viz:- Vijapur and Kheralu were selected randomly. For selection of villages from each selected taluka, a list of villages was obtained from BANAS and DUDHSAGAR dairy. Thereafter, five villages were randomly selected from selected each taluka. Ten dairy farmers were randomly selected from each selected village. It is observed that majority (64.00 per cent) of the dairy farmers had use television as a regular source of mass media exposure, followed by 59.00 per cent of them had use television as a regular source of mass media exposure.

**Key Words**- Mass media exposure, Dairy farmers.

**Introduction** - The mass media is a diversified collection of media technologies that reach a large audience via mass communication. The technologies through which this communication takes place include a variety of outlets. It is defined as the nature and the frequency of use of different mass media such as Television, Radio, Newspapers and Agricultural Magazines made by the dairy farmers. Dairy farming is one of the important activities of the rural people of our country. The importance of the dairy, as a subsidiary enterprise to agriculture has been stressed by the National Commission on Agriculture. Dairy Enterprise, next to agriculture, not only provides continuous income and improves dietary standards of family, but also supplements the income and reduces unemployment to a large number of the rural poor. Keeping in view present study was conducted with following objective:

1) To study the mass media exposure by the dairy farmers in operating dairy enterprise.

**Methodology:** This study was conducted in North Gujarat. Ex-post facto research design was used for the study. Banaskantha and Mehsana district were purposively selected for study. Banaskantha district comprises of fourteen talukas out of which, two talukas viz:- Palanpur and Deesa, while Mehsana district comprises of nine talukas out of which, two talukas viz:- Vijapur and Kheralu were selected randomly. For selection of villages from each selected taluka, a list of villages was obtained from BANAS and DUDHSAGAR dairy. Thereafter, five villages were randomly selected from selected each taluka. Ten dairy farmers were randomly selected from each selected village. The data were collected in the light of the objectives of the study with the help of well structured, pre tested Gujarati version interview schedule. For measurement of

dependent and independent variables included in study, different scales and scoring techniques developed by previous researchers were used with slight modifications, wherever necessary. The data so collected were coded, classified, tabulated and analyzed in order to make the finding meaningful. The statistical tools used were percentage and mean score. This refers to the frequency of reading news paper, farm magazine and as well as, frequency of use of internet, radio and television by the dairy farmers. In order to assess the mass media exposure of the respondents in exposure, the different exposure were listed and they were asked to indicate their participation as regularly, occasionally and never. The scores assigned as 2, 1 and 0, respectively. The final score was worked out by summing scores obtained by respondent for all activities. Based on the responses, the frequency and the percentage were worked out against each item.

## Results And Discussion:

**Mass media exposure** - The nature and frequency of use of different mass media like; newspapers, agriculture magazines, radio, television, & internet vary from person to person. Keeping this in view, mass media exposure of the respondents was studied and the data are presented in Table 1.

**Table 1: Distribution of the respondents according to their mass media exposure**

(n=200)

Sr.	Mass Media	Use of mass media		
		Regular	Occasional	Never
1	News paper	118(59.00)	53(26.50)	29(14.50)
2	Farm Magazine	47(23.50)	70(35.00)	83(41.50)
3	Radio	73(36.50)	81(40.50)	46(23.00)
4	Television	128(64.00)	63(31.50)	09(04.50)
5	Internet	39(19.50)	61(30.50)	100(50.00)

Figures in parenthesis indicate percentage

From Table 1, it is observed that majority (64.00 per cent) of the dairy farmers had use television as a regular source of mass media exposure, followed by 59.00 per cent of them had use television as a regular source of mass media exposure. While, 50.00 per cent and 41.50 per cent of them had never use farm magazine and internet as a source of mass media exposure. Further, 40.50 per cent and 35.00 per cent of them had occasional use radio and farm magazine as a source of mass media exposure, respectively.

The probable reason for this might be better economic condition and medium education level of dairy farmers leads them to purchase TV, Radio and Newspapers to use mass media.

**Conclusions** - Majority (64.00 per cent) of the dairy farmers

had use television as a regular source of mass media exposure, followed by 59.00 per cent of them had use television as a regular source of mass media exposure. It is concluded that television is the most effective source of mass media for dairy farmers.

#### References:-

1. Patil, V. G., Mahadik, R. P. and Patil, A. S. (1999). Entrepreneurial behaviour of little gourd growers. *Maharashtra Journal of Extension Education*. XVIII: 240-243.
2. Patel, M. M., Sanoria, Y. C. and Amit Chatterjee. (2003). Communication factors and entrepreneurial behaviour of sugarcane growers. *Journal of Research*. Acharya N. G. Ranga Agricultural University, Hyderabad, 31(3): 62-67.

\*\*\*\*\*



## मध्यकाल में मध्यवर्ती भारत में तालाबों व बावड़ियों द्वारा जल संग्रहण

डॉ. अलीमा शहनाज सिद्दीकी \*

**प्रस्तावना** – मध्यकाल में सेण्ट्रल इण्डिया में दो प्रमुख देशी राज्य थे।  
एक – गढ़ा राज्य और दूसरा – चांदा का राज्य।

ये राज्य मध्यकाल में लंबे समय तक मौजूद रहे। इनके आय का मुख्य साधन कृषि था और उसके लिए इन राज्यों में जल संरक्षण के पारंपरिक प्रणाली का बखूबी उपयोग किया गया।

इन राज्यों के अंचल में उस जमाने में सैकड़ों तालाब खोदे गये। उन तालाबों में से आज भी कई तालाब मौजूद हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि तालाबों के जरिये जल संरक्षण कितना लोकप्रिय और उपयोगी था?

भारत में जल संचय की पुरानी प्रणालियों और परंपराओं का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। पानी और समाज के संबंधों की कहानी का सबसे पुराना और पुख्ता प्रमाण वैदिक साहित्य में मिलता है।<sup>1</sup>

भारतीय राजाओं को मालूम था कि राष्ट्र के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए खेती की समृद्धि बहुत जरूरी है, इसलिए वे खेती के लिए नई जमीन जुटाने, तालाब, कुएं और नहरें बनवाकर खेती की उत्पादकता बढ़ाने पर जुटे रहे, जिससे राज्य का राजस्व बढ़ सके।<sup>2</sup>

जल संचय की परंपरागत विधियां काल की कसौटी पर खरी उतरी हैं और जिस खास माहौल में उनका विकास हुआ है उसके अनुकूल ही साबित हुई है। उन्होंने एक दम अलग सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक माहौल में और अलग पीढ़ी के लोगों के बीच प्रभावी ढंग से काम किया है।<sup>3</sup>

परंपरागत प्रणालियां पूरी तरह स्थानीय इकोलॉजी पर निर्भर थी, जबकि नई प्रणालियों की स्थानीय इकोलॉजी पर निर्भरता उतनी नहीं थी।<sup>4</sup>

भारत में सतही जल संचय की प्राचीन प्रणालियों के बारे में कई स्थानों पर ऐतिहासिक प्रमाण मिला है। सबसे पहला प्रमाण धौलावीरा में मिला है।<sup>5</sup>

चौदहवीं सदी के अंत में गढ़ा का राजा अपने राज्य के प्रशासन के बाद भी साढ़े तीन सदियों में राज्य के आर्थिक क्षेत्र में दखल दिया। फिर ग्रामीण तालाब (ताल-तलैया) के अतिरिक्त राजा के प्रयास से जल आपूर्ति के लिए तालाब खोदे गये जो संग्रामशाह (1510 से 1543) के काल से प्राप्त होते हैं। हृदयशाह के समय (1734 से 1771) तक में तो अनेक तालाब उसकी पत्नी ने बनवाये।<sup>6</sup>

गढ़ा राज्य के वृहत तालाब राज्य के अस्तित्व के बाद ही बनाये किन्तु इसके पूर्व तकनीकी क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हो चुकी थी, जो अतिरिक्त जल के निकास की व्यवस्था में दृष्टव्य है।<sup>7</sup>

राजधानी चंद्रपुर के पास जल आपूर्ति बढ़ाने का प्रयास सर्वप्रथम खांडक्या बल्लालशाह ने किया। उसने रामाला तालाब (1472-1497) बनवाया।<sup>8</sup> (सर्जा बल्लालशाह ने कोईली समाज को घटबोरी क्षेत्र में बसाया

था, जहां इस समाज ने बांध बनाकर राज्य के समृद्धि की नींव डाली)

इसके अलावा संग्रामशाह के राज्यकाल में बड़े अनुपात में जल आपूर्ति क्रियाकलाप प्रारंभ हुये। इस समय नर्मदा नदी तथा वैनगंगा नदी के घाटी में वाणिज्य क्रियाकलापों का पुनरुज्जीवन हुआ। वेन्ड के लेख में भी जल आपूर्ति राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की तमाम विशेषताओं को वर्णित करता है।<sup>9</sup>

लेकी और कोलब्रुक दोनों ने ही इस बात का विवरण दिया है। भूगोल की नैसर्गिक आकृति अनेक बड़े तालाबों में उपयुक्त सिद्ध हुई। उनके स्थानों पर बांधों का काल कम से कम करने के लिए भौगोलिक रचना का सूक्ष्मता से विचार किया गया। मध्यप्रदेश के संभाग जबलपुर, गोंडसलपुर तथा बूढ़ागढ़ इस प्रवीणता का सर्वोत्तम उदाहरण है। भूमि की भौगोलिक विशेषताएं और बांध के लिए उपयुक्त सामग्री सर्वे जल संधारण की उच्च तकनीकी ज्ञान का संकेत है।<sup>10</sup>

जी.के. अविनोद्री ने अपनी किताब जबलपुर, गोंडराज्य के 16वीं, 17वीं व 18वीं शताब्दी के उन तालाबों को शोधपूर्ण तरीके से खोज निकाला है, जो गढ़ा मण्डला के गोंड राजाओं के समय निर्मित हुये थे। मदनमहन, पिसनहारी और बरगी के पहाड़ियों के कमान क्षेत्र में उन्होंने 40 तालाबों की सूची दी है।<sup>11</sup> जो निम्न हैं –

बाबा ताल, टेरिया ताल, बाबा तलैया, ककरैया ताल, गौरवताल, गंगा सागर, गुरहा ताल, देव ताल, कोला ताल, महाराज ताल, सूपा ताल, बघा ताल, गुलौवा ताल, नौवा ताल, जिंदल तलैया, फुलहारी तलैया, फूल सागर, इमरती ताल, शाही ताल, साईं ताल, बसा ताल, मछरहाई ताल, सुरजला तलैया, सूरज ताल, बाल ताल, अवस्थी ताल, संग्राम सागर, ठाकुर ताल, गनेश ताल, पाण्डू ताल, सगड़ा ताल, रामनगरा ताल, हिनीता ताल, कुडवन ताल, बाण सागर, तेवर ताल, चौकी ताल, कंचनपुर, मढ़कई ताल, गुल्लू की तलैया, बघशेरा ताल।

इसी तरह लालमाटी, करिया पाथर और मदार टेकरी के कमान क्षेत्र में उन्होंने 23 तालाबों की सूची बतायी है।<sup>12</sup>

भंवरताल, मढ़ाताल, मुड़-गुड़ चरहाई, जूड़ी तलैया, तिलकभूमि तलैया, अलफ खां की तलैया, श्रीनाथ की तलैया, कदम तलैया, गलगला ताल, भान तलैया, फूटा ताल, गोपालबाग ताल, हनुमान ताल बाग, बेनीसिंह की तलैया, आधार ताल, कंचनपुर ताल, अमखेरा ताल, रानी ताल, चेरी ताल, उखरी ताल, छोटी उखरी मोढ़ो ताल, सूखा ताल, गोकलपुर जबलपुर तलैया।

सेंट्रल रिजलाइन की तरफ उन्होंने चार तालाबों की सूची दी है। इस तरह उन्होंने कुल 67 तालाबों की सूची दी है, जो जबलपुर और गढ़ा के

इलाके में किसी न किसी रूप में आज भी मौजूद हैं। इनमें से कुछ तालाबों की जगह कॉलोनियां बन गई हैं।

पंद्रहवीं सदी के बाद की साढ़े तीन सदियों में चांदा राज्य ने आर्थिक क्षेत्र में कुछ ठोस काम करने का प्रयास किया। राजा के प्रयास से जल आपूर्ति के लिए तालाब खोदे गये। ऐसे तालाब हीरशाह (1497-1522) के काल से मिलते हैं।<sup>13</sup> तथापि नवे गांव बांध का तालाब जो कवडू पाटिल ने बनवाया था, पानी की जरूरत पूरा करने की तकनीकी में नया अध्याय प्रस्तुत करता है और जल संग्रहण क्षेत्र 23 वर्ग मील और उसकी क्षमता 2250 एकड़ है।<sup>14</sup>

जबलपुर शहर में मध्यकाल में बहुत से बावड़ियों का भी निर्माण हुआ। जी.के. अग्निहोत्री ने 31 बावड़ियों की खोज जबलपुर में की है जिनके अवशेष आज भी हैं।<sup>15</sup> जिनके नाम ये हैं - महाराजपुर बावड़ी एन.एच.-7, घोड़ा नक्कास बावड़ी (हाजी हबीबुल्ला के आखाड़े में हनुमानताल), गोपालबाग बावड़ी, तमरहाई उपरैनगंज नाला के किनारे, क्षेत्रीय बसस्टैंड बावड़ी, उजार पुरवा बावड़ी (रानीताल), स्नेहनगर बावड़ी, चोर बावड़ी (ब्लूम चौक, बस स्टैंड के पास), बसोर मोहल्ला बावड़ी (महर्षि विद्या मंदिर के सामने), बावड़ी बन्दरिया तिराहा, शाहनाला मोड़ (नर्मदा रोड, कमली वाले बाबा), बादशाह मंदिर बावड़ी, शिव मंदिर बावड़ी, लालकुंआ बजरिया (पोली पाथर), ग्वारीघाट, शारदा मंदिर (मदन महल बावड़ी), गढ़ा बजरिया बावड़ी, बाजनामठ बावड़ी, बदनपुर बावड़ी, सगराग्राम बावड़ी, तिलवारा रोड (स्टोन क्रेसर के पास), आरटीओ गोविंद भवन बावड़ी, दुर्गा मंदिर बावड़ी (धमापुर), तेवर बावड़ी, भान तलैया, कुड़कुड़ की बावड़ी, गंगासागर बावड़ी, देवताल बावड़ी (रानी दुर्गावती बावड़ी अयोध्या बस्ती में), जयप्रकाश वाई बावड़ी, विद्यासागर वाई बावड़ी, मेडिकल कॉलेज बावड़ी, सूर्य मंदिर के पास ये 31 बावड़ियों की संख्या है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार शासन के प्रयास से 9 तालाब बनाए गए, किन्तु निजी प्रयास से बनाए गए तालाबों की संख्या कम नहीं है। बल्कि उनकी संख्या सरकारी तालाबों से अधिक है। इन निजी तालाबों में कोहली समाज के द्वारा बनाए तालाबों की संख्या काफी है। राजकीय तालाब तथा कोहली समाज द्वारा निर्मित सामाजिक तालाबों की मरम्मत में प्रधानता दी जाती थी और वर्षाकाल में तालाब पर पहरा देकर संकट के समय सारे गांव को संकट की सूचना दी जाती और मदद का आह्वान किया जाता था।<sup>16</sup>

राज्य द्वारा प्रायोजित जल आपूर्ति कार्य निजी कार्य से अधिक प्रभावशाली नहीं था, तथापि वह विशाल श्रम साध्य दिखायी देता है।<sup>17</sup>

जल आपूर्ति के क्षेत्र में एक वर्ष में कई फसलें लेने की संभावना बढ़ी और कृषि के इस नये ढांचे की स्थिरता के कारण उत्पादन में भी नये संबंध बने। इस कारण जल आपूर्ति की गतिविधियों के क्षेत्र में सामाजिक तथा

आर्थिक दृष्टि से अधिक गतिमान क्षेत्र मानना संभव है।

अतः ये कहा जा सकता है कि तत्कालीन राजाओं में जल आपूर्ति के क्रियाकलाप इसलिए हाथ में लिए क्योंकि उन्हें इससे राजस्व बढ़ने की उम्मीद थी।

इस प्रकार मध्यकालीन मध्यवर्ती भारत के गढ़ा के गोंड राजाओं एवं चांदा के राजाओं द्वारा जल संग्रहण से कृषि व राजस्व में वृद्धि व विकास हेतु तालाबों एवं बावड़ियों का बृहत संख्या में निर्माण कराया गया।

### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. व्यास, कृष्ण गोपाल : पानी समाज और सरकार, गौरव मेमोरियल फाउण्डेशन, भोपाल, पृ. 23
2. अग्रवाल अनिल व सुनीता नारायण (प्रधान संपादक) : बूंदों की संस्कृति, सेंटर फार साईंस एण्ड इनवायरमेंट, नई दिल्ली, 1998, पृ. 269
3. वही, पृ. 318
4. व्यास, कृष्ण गोपाल : पूर्वोल्लिखित कृति, पृ. 34-35
5. वही, पृ. 27
6. गढ़े, प्रभाकर : मराठा आधिपत्य में गढ़ा-मण्डला, गोंडी पब्लिक ट्रस्ट प्रथम संस्करण, मण्डला, 2007, पृ. 176
7. वही, पृ. 177
8. रसेल : ट्राईव्स एण्ड कास्ट्स आफ सेंट्रल प्राविन्स एण्ड बरार, 1916, पृ. 56
9. वेन्ड, एच.जे.: द इस्ट्रक्चर आफ साउथ-ईस्ट एशियन हिस्ट्री : सम प्रिलीमनरी आब्जर्वेशन, लंदन, 1969, पृ. 25
10. लेकी अर्ली, कोलब्रुक : एशियाटिक एन्युअल रजिस्टर, पृ. 32
11. अग्निहोत्री, जी. के. : जबलपुर - ए जुबैल आफ सेंट्रल इण्डिया, सोसायटी फार बॉयो डायवर्सिटी कंजर्वेशन एण्ड सशटेनेबल डेवलपमेंट, प्रथम संस्करण, जबलपुर, जुलाई 2012, पृ. 20,21,22
12. वही, पृ. 23-24
13. रसेल, भंडारा : ट्राईव्स एण्ड कास्ट्स आफ सेंट्रल प्राविन्स एण्ड बरार, 1916, पृ. 92
14. वही, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर भंडारा, पृ. 92
15. अग्निहोत्री, जी.के. : पूर्वोल्लिखित कृति, पृ. 27-30
16. बेग्वी : गजेटियर आफ चांदा, 1909, पृ. 179 य ल्यूसी स्मिथ, सेटेलमेंट रिपोर्ट, पैरा 224
17. वही, पृ. 189

\*\*\*\*\*

## मर्यादित राम

डॉ. तृष्णा शुक्ला \*

**शोध सारांश** – भारतीय समाज और संस्कृति के आधार स्तंभ के रूप में दो प्रमुख महाचरित्र प्रचलित हुए हैं श्रीराम एवं श्रीकृष्ण। इनकी जीवन गाथा और लीलाओं का विशद विवेचन धार्मिक ग्रंथ रामायण, महाभारत, गीता में उपलब्ध है। रामकथा भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी दूर-दूर तक प्रचलित है। आज हजारों वर्ष के बाद भी श्री राम का यशोगान किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति का प्रतिमान श्री राम की प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है। राम कथा की शीतल छांव में प्रेम मानव की मूल प्रकृति में निहित हो जाता है। राम कथा में पशु पक्षी के प्रति भी सम्प्रीति रखते हैं एवं पशु पक्षी भी राम के प्रति समर्पित हैं। राम के बिना हिंदू जीवन नीरस है – फीका है। राम नाम रूपी अमृत पीकर हिंदू धर्म एवं इसे घर-घर पहुंचाने वाली तुलसी भी अमर हो गए। गोस्वामी ने समस्त हिंदू जीवन राममय कर दिया। संपत्ति में, विपत्ति में, घर में, वन में, रण में, आनंदोत्सव में जहां देखिए वहां राम है। आज भी हिंदू भक्त अवसर के अनुसार राम सौंदर्य पर मुक्त होता है, महत्व पर श्रद्धा करता है और शोल की और प्रवृत्त होता है, सम्मान पर पैर रखता है। विपत्ति में धैर्य धारण करता है, कठिन कर्म में उत्साहित होता है, दया से आर्द्र होता है, बुराई पर ग्लानी करता है, शिष्टता पर अवलंबन करता है और मानव जीवन के महत्व का अनुभव करता है। तनावग्रस्त जीवन के लिए परमौषधि है। श्रीराम का जीवन चरित्र सदियों तक भारतीय समाज का पथ आलोकित करता रहेगा। राम वह पारसमणि है जिनके स्पर्श मात्र से लौह भी स्वर्ण बन जाता है। आज प्रत्येक मनुष्य अधीर और आकुल है चिंतित और व्यग्र है तथा भविष्य की आहट के प्रति संशक भी, कारण अपने-अपने हो सकते हैं। यह प्रतिक्रिया संपूर्ण मानव लोक की है। सत एवं असत इन्हीं दो द्वंद्वों के बीच प्रत्येक मनुष्य भीतर ही भीतर घुट रहा है एवं इसी द्वंद्व से मनुष्यता को मुक्त कर समरसता का वातावरण कैसे बनाया जाए? हमने आज भौतिक प्रगति के लिए प्रयास तो किए किंतु नीति निष्ठा के प्रति अपेक्षा बरती गई। आज के भौतिकवादी दौर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के चरित्र की संजीवनी की आवश्यकता है। रामचरित्र एक कथा मात्र नहीं बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाने वाली कथा है। राम स्वयं धर्मनिष्ठ, नीतिनिष्ठ है एवं भाइयों को भी प्रेरित करते हैं। सारा परिवार नीति निष्ठा की परीक्षा में सफल होता है इसलिए संसार उन्हें आदर्श मानकर प्रेरणा ग्रहण करता है। प्रभु राम का उज्ज्वल स्वरूप सूर्य के तेज से भी अधिक प्रकाशमान है, राम का नाम सभी को भवसागर से पार लगा देता है। राम की भक्ति ही जीवन का आधार है एवं उनकी भक्ति में लीन होकर जीवन को सदाचार रूप में व्यतीत करना है तथा अंत में मोक्ष पाना है। अंत में राम का ही चरित्र मेरुदंड है, हमें स्वर्ण बनाने वाला पारस मणि दो अक्षरों में निहित है 'राम'।

**प्रस्तावना** – भारतीय समाज और संस्कृति के आधार स्तंभ के रूप में दो प्रमुख महाचरित्र प्रचलित हुए हैं श्रीराम एवं श्रीकृष्ण। इनकी जीवन गाथा और लीलाओं का विशद विवेचन धार्मिक ग्रंथ रामायण, महाभारत, गीता में उपलब्ध है। रामकथा भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी दूर-दूर तक प्रचलित है। आज हजारों वर्ष के बाद भी श्री राम का यशोगान किया जा रहा है। संपूर्ण भारतीय समाज के समान आदर्श के रूप में राम उत्तर भारत से दक्षिण भारत, पूर्व से पश्चिम भारत के सभी भागों में स्वीकार हुआ है। भारत की हर एक भाषा की अपनी राम कथाएं हैं। बाहर के देशों फिलीपींस, थाईलैंड, लाओस, मंगोलिया, साइबेरिया, मलेशिया, बर्मा, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, चीन, जापान, श्रीलंका, वियतनाम आदि में भी राम कथा प्रचलित है। भारत में तो जन-जन में कथा के प्रति अगाध आस्था है। भारतीय संस्कृति का प्रतिमान श्रीराम की प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है। राम का चरित्र भारतीय संस्कृति का प्रतिमान है। उन्होंने अपनी नर-लीला के दौरान एक श्रेष्ठ भाई, पुत्र, पति और सखा की आदर्श भूमिका का निर्वह करते हुए शांतिपूर्ण समाज और परिवार की स्थापना के लिए मापदंड स्थापित किया। राम कथा की शीतल छांव में प्रेम मानव की मूल प्रकृति में निहित हो जाता है। राम सभी संबंधों को छोड़कर केवल प्रेम से नाता रखते हैं-

'जानत प्रीति रीती रघुराई

नाते सब हाते करी रावत, राम सनेह सगाई।  
ऐसेहु पितुते अधिक गिध पर ममता गुरुवाई।  
तिय बिरही सुग्रीव सखा लखि प्राणप्रिया बिसराई।  
स परमो बंधु विभीषण को सोच हृदय अधिकाई।'<sup>1</sup>  
राम कथा में पशु पक्षी के प्रति भी सम्प्रीति रखते हैं एवं पशु पक्षी भी राम के प्रति समर्पित हैं। प्रेम की इस बांसुरी के स्वर में संपूर्ण राम कथा निनादित है।

राम जीवन के हर कोने में व्याप्त हैं विवाह अवसर पर राम के मंगल गीत गाए जाते हैं, कुटिलता के प्रसंग में कैकई की कहानी, दुख में राम वनवास, धनुष की टंकार, वीरता में राम, प्रातः राम-राम, माला फेरे में राम हर जुबां पर चौपाई रटी हुई। अंत समय की सांसें में राम नाम ही उद्धार करता है, असाध्य रोगों में रामबाण दवा, पत्ता भी राम की मर्जी से हिलता है। राम के बिना हिंदू जीवन नीरस है – फीका है। राम नाम रूपी अमृत पीकर हिंदू धर्म एवं इसे घर-घर पहुंचाने वाली तुलसी भी अमर हो गए।

'वस्तुतः भगवान राम स्वयं मंगल भव अमंगलहारी हैं। संपूर्ण कल्याण, उपकार, त्याग, सेवा और साक्षात धर्म के विग्रह हैं। उनका चरित्र मुक्ति अर्थात् वासना और मोह पाश से छुड़ाने वाला, दरिद्रता को दूर कर संपदा प्रदान करने वाला धर्म और मर्यादा के पालन के लिए प्रेरित करने वाला है।'<sup>2</sup>

‘गोस्वामी ने समस्त हिंदू जीवन राममय कर दिया। संपत्ति में, विपत्ति में, घर में, वन में, रण में, आनंदोत्सव में जहां देखिए वहां राम है। आज भी हिंदू भक्त अवसर के अनुसार राम सौंदर्य पर मुक्त होता है, महत्व पर श्रद्धा करता है और शील की और प्रवृत्त होता है, सम्मान पर पैर रखता है। विपत्ति में धैर्य धारण करता है, कठिन कर्म में उत्साहित होता है, दया से आर्द्र होता है, बुराई पर ग्लानी करता है, शिष्टता पर अवलंबन करता है और मानव जीवन के महत्व का अनुभव करता है।’<sup>3</sup>

विश्व मानव परिवार की परिवार व्यवस्था को सुगंध में और सुखमय बनाने के लिए संजीवनी है। राम की चारित्रिक शील समाज की रीढ़ है। रावणत्व का विनाश रामत्व की स्थापना से समाज में सद्वृत्तियों का पोषक होता है। तनावग्रस्त जीवन के लिए परमौषधि है। श्रीराम का जीवन चरित्र सदियों तक भारतीय समाज का पथ आलोकित करता रहेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन चरित्र लोगों को सही राह पर चलने की शिक्षा देता आ रहा है क्योंकि भगवान श्रीराम विषम परिस्थितियों में नीति सम्मत रहे। उन्होंने वेदों और मर्यादा का पालन करते हुए सुखी राम राज्य की स्थापना की स्वयं की भावना व सुखों से समझौता कर न्याय और सत्य का साथ दिया। राम वह पारसमणि है जिनके स्पर्श मात्र से लौह भी स्वर्ण बन जाता है।

‘राम वनवासी होते हैं सीता नहीं पर वह राम के साथ छाया की तरह रहना चाहती है। जहां सांसारिक लोग अधिकार के लिए भाइयों का हक हड़पने का प्रयास करते हैं वही राम उचित अधिकार भी स्वीकार करने में दुख पाते हैं। रामराज्य अर्थात् धर्मराज्य। धर्म को प्रथम और धान को तृतीय स्थान देकर रामराज्य में सतयुग में सुखी वातावरण बनाया था राम ने एवं भविष्य में यही श्रेष्ठ समाधान अपनाया पड़ेगा।’<sup>4</sup>

क्योंकि आज प्रत्येक मनुष्य अधीर और आकुल है चिंतित और व्यग्र है तथा भविष्य की आहट के प्रति संशक भी, कारण अपने-अपने हो सकते हैं। यह प्रतिक्रिया संपूर्ण मानव लोक की है। यही कारण है कि संबंध-संवेदना शिथिल पड़ती जा रही है और किसी के पास उधार दृष्टि निक्षेपित करने के लिए अवकाश तक नहीं है यही कारण है कि आज वैश्विक संदर्भ में कर्तव्य-कर्तव्य में अंतर करने की विवेकशीलता का क्षरण होता जा रहा है और मनुष्य आत्ममुखता की भक्ति में रमा हुआ है जो किसी नई आह और संवेदना की अभिनव पटकथा लिख रहा है अथवा महाविनाश को निमंत्रित कर रहा है। उस अवसादी और उन्मादी वृत्ति को क्रमशः नष्ट किया जाना चाहिए हतोत्साह करना चाहिए अथवा उसकी मति पर छोड़ देना चाहिए यह एक गंभीर विषय है। सत एवं असत इन्हीं दो द्वंद्वों के बीच प्रत्येक मनुष्य भीतर ही भीतर घुट रहा है एवं इसी द्वंद्व से मनुष्यता को मुक्त कर समरसता का वातावरण कैसे बनाया जाए? भटकता युवा वर्ग, डोलती व्यवस्था, गिरता चरित्र और टूटते परिवार आधुनिक समाज के दर्पण है। ‘आज मानव चेतना स्वार्थ पर केंद्रित होकर हैवान हो रही है। धर्म और मोक्ष से हटकर काम तक ही सीमित होती जा रही है। परिणाम यह हो रहा है कि आज का विश्व रागात्मक सत्ता के विस्तार पर समाधृत पर दुःखकातरता के पर्याय धर्म से विमुख होता जा रहा है।’<sup>5</sup>

हमने आज भौतिक प्रगति के लिए प्रयास तो किए किंतु नीति निष्ठा के प्रति अपेक्षा बरती गई। आज के भौतिकवादी दौर में मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम के चरित्र की संजीवनी की आवश्यकता है। रामकथा सभी धर्मों का सार और रामायण अपने आप में संपूर्ण ग्रंथ है। इस पावन ग्रंथ से सीख ले कर अपने जीवन में उतारा जाए तो तमाम मानवीय समस्याएं ही मिट जाएंगी और धरती स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगी। रामचरित्र एक कथा मात्र नहीं

बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाने वाली कथा है। ‘सच्ची आध्यात्मिकता को जनसाधारण के गले उतारना और सज्जनोचित मानवतावादी रीति-नीति व्यवहार में समाविष्ट करना यही इस कथा का उद्देश्य है। राम युग कुतर्क, कुमार्ग, गलत गतिविधियों, कलयुग के कपट, घमंड और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन को जलाने के लिए अग्नि। प्रेम व्यवहार, मधुर वाणी और विजय प्राप्त करने के लिए सिंह जैसा शौर्य है अपनी बात पर अटल रहते हैं। राम स्वयं धर्मनिष्ठ, नीतिनिष्ठ है एवं भाइयों को भी प्रेरित करते हैं। सारा परिवार नीति निष्ठा की परीक्षा में सफल होता है इसलिए संसार उन्हें आदर्श मानकर प्रेरणा ग्रहण करता है।’<sup>6</sup>

भारतवर्ष के कण-कण में भगवान श्रीराम का वास है। आज वर्षों से राम का पावन चरित्र लाखों लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन है। विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ, राजा, पिता, पुत्र, पति, स्वामी, सेवक, शिष्य अथवा भाई के रूप में सर्वत्र एक नियमित जीवन दिखाई देता है। विकारों, विचारों अथवा व्यवहार में श्रीराम ने कहीं भी मर्यादा का परित्याग नहीं किया। उनके इन्हीं गुणों की वजह से उन्हें मर्यादापुरुषोत्तम राम के नाम से पूजा जाता है। राम कथा में चेतना की व्यापकता, युगदृष्टि की शाश्वत दीप्ति एवं अनुभूति की गहनता है। रामचरित्र में आशा- विश्वास, आस्था का संगम है। कर्तव्यपरायणता, मर्यादा, त्याग, प्रगतिशीलता, सजगता का शंखनाद है। इसके साथ ही युगबोध आदर्श नैतिक मूल्यों, मानव मूल्यों की सतत साधना है एवं राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, दार्शनिक युगबोध है। त्रेता युग में अवतरित हुए राम भारतभूमि पर अद्भुत स्वरूप के गुणी है। प्रभु राम का उज्ज्वल स्वरूप सूर्य के तेज से भी अधिक प्रकाशमान है, राम का नाम सभी को भवसागर से पार लगा देता है। राम की भक्ति ही जीवन का आधार है एवं उनकी भक्ति में लीन होकर जीवन को सदाचार रूप में व्यतीत करना है तथा अंत में मोक्ष पाना है।

अंत में राम का ही चरित्र मेरुदंड है, राम के गुण समूह को समझना एवं व्यवहारिक जीवन में समावेश करने के लिए राम की तरह श्रेष्ठ आचार करें रावण की तरह अनाचारी ना बने। ‘भारतभूमि एक दिन स्वर्णभूमि कहलाती थी इसलिए कि भारतवासी स्वर्णरूप से थे। भूमि तो वही है पर आदमी बदल गए हैं इसे पुनः स्वर्ण बनाने के लिए सद्गुणों का स्वर्ण रूप बनाना है। हमें स्वर्ण बनाने वाला पारसमणि दो अक्षरों में निहित है ‘राम’।’<sup>7</sup>

### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. विनय पत्रिका
2. तुलसी साधना, भोपाल भूमिका अंक 4, 2007
3. आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास अनन्य प्रका. सन् 2007 ‘तुलसीदास की भक्ति पद्धति’ पृ. 10 से 14
4. श्रीराम शर्मा आचार्य वाङ्मय - ‘रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं’ प्रका. अखंड ज्योति संस्थान वित्तीय संस्करण 1998 ‘रामराज्य, धर्मराज्य की शासन पद्धति’ पृ. 2.110 से 2.111
5. धर्म और आज का विश्व, आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी, पृ. 10
6. श्रीराम शर्मा आचार्य वाङ्मय - ‘रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं’ प्रका. अखंड ज्योति संस्थान वित्तीय संस्करण 1998 ‘रामराज्य, धर्मराज्य की शासन पद्धति’ पृ. 2.110 से 2.111
7. मोहनदास करमचंद गांधी - ‘राम नाम असाध्य रोगों की रामबाण दवा’ प्रका. साहित्य सागर, संस्करण 2011 पृ. 3 से 5



# Cephalosporin $\beta$ - Lactam Antibiotics - A Review

R. K. Prajapati \*

**Abstract** - Cephalosporins are the most common class of antibiotics used to treat bacterial infection, which belong to  $\beta$ -lactams class of antibiotics. These drugs have proven to be safe, clinically effective, and the most commonly prescribed antibiotics among other classes of antibiotics because showing minimum risk of allergic reactions compared to penicillins with nearly 6–8% of the population is allergic to  $\beta$ -lactam antibiotics and cephalosporin allergy have been reported 1–3% of the population, despite of its wide clinical utility and general tolerability. For the first time, it was derived from the moulds *Acremonium*, which was initially known as *Cephalosporium*. Although cephalosporins are safer to patients and exhibit the low potential for cross-reactivity, are very little being prescribed by clinicians for those patients who show penicillin allergies. Chemically, cephalosporins, oxacephems, carbacephems and cephamycins belong to a subgroup of  $\beta$ -lactam antibiotics called cephems. Cephalosporins drugs are prohibited to those in patients which have a case history of major hypersensitivity, diarrhea, leukopenia and thrombocytopenia; pain in few patients have been reported at the IM injection site so it may be given intravenously. Since cross-sensitivity between cephalosporins and penicillins are rare, so if needed, cephalosporins can be prescribed, carefully to patients with a history of delayed hypersensitivity to penicillin but should not be given to those patients who have already an anaphylactic reaction to penicillin. It is also important for prescription of cephalosporins to exhibit minimal cross-sensitivity among other  $\beta$ -lactams shown on the basis of specific chemical and structural features and expressing allergy to other  $\beta$ -lactams. The groups R1 in side chain of cephalosporins of its structures are responsible for the cross-reactivity potential and so, it becomes important for clinicians to know about the side chain R1 while prescribing alternate  $\beta$ -lactams in allergic individuals. Risk factors with cephalosporin allergies have been found to be moderate and vary from gender, little more in older patients. In this review, the classification, pharmacokinetics, uses in treatment of bacterial infection, its side effect its side effect, risk factors, and comparative studies of cephalosporins with other antibiotics especially with penicillins have been described.

**Introduction** - Cephalosporins belongs to a large group of  $\beta$ -lactam antibiotics having  $\beta$ -lactam rings in its core structure which was derived from the mould *Acremonium* in 1945 and for the first time it was marketed in 1964.  $\beta$ -lactams ring possesses a secondary amino group to which side chains attached through an amide linkage. These  $\beta$ -lactam antibiotics, with the same fundamental structural requirements as penicillins, the main difference between the two is that cephalosporin contain dihydrometathiazine ring while penicillin contains a tetrahydrothiazole (thiazolidine) (Figure 1). Cephalosporins are antibacterial which kill bacteria and its mechanism of action similar to penicillins.[1-4]

They bind to and block the activity of enzymes peptidoglycan trans peptidase responsible for making peptidoglycan, which are an important component of the bacterial cell walls. These are used as broad-spectrum antibiotics because they are effective against a wide range of gram positive and negative bacteria.

In 1945, G. Brotzu, in sea near Sardinia, Italy, isolated an aerobic moulds cephalosporin-producing strain, *Cephalosporium acremonium* and discovered

cephalosporins. He observed that cultures of *Cephalosporium acremonium* had produced a chemical substance called Cephalosporin C which was used in treatment of the typhoid fever, also effective against bacteria *Salmonella typhi*. [5] Later on in Oxford, in 1950, it has been reported that several antibiotics had been produced by this mould *Cephalosporium acremonium* and one of which was penicillin with a new side-chain, penicillin N. Cephalosporin C compound with a weak antibiotic activity against penicillin-resistant cultures was isolated by Newton *et al.* [6] In modern era, chemical/enzymatic (chemoenzymatic) hydrolysis of the cephalosporin C gives rise 7-aminocephalosporanic acid (7-ACA) (Figure 2) which is the core chemical structure for the synthesis of cephalosporins and intermediates, which is the starting material for the synthesis of synthetic cephalosporins analogs. Instead of fermentation of cephalosporin C to prepare (7-ACA) which is expensive, economically cephalosporins analogs are prepared from penicillin G by chemical synthesis which complete in seven-step 7-ACA [6-8]. Most of the cephalosporins analogues used by clinicians worldwide are semi-synthetic derivatives of cephalosporin

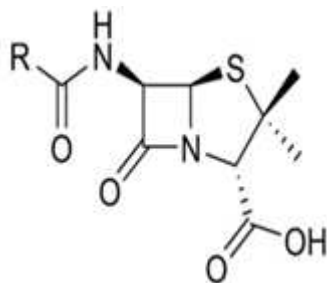
\*Department of Chemistry, Digambar Jain College, Baraut, Baghpat (U.P.) INDIA

C. Most of the available cephalosporins are semi-synthetic derivatives of cephalosporin C, obtained after molecular modification in it. These  $\beta$ -lactam antibiotics, with the same fundamental structural requirements as penicillins, the main difference between the two is that cephalosporins contain dihydrometathiazine ring while penicillins contain a tetrahydrothiazolidine (thiazolidine) (Figure 1).

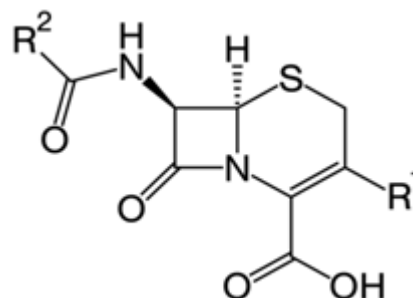
Like the newer penicillins, the use of the cephalosporins as antibiotics have shown very low toxicity and remarkably extended range in chemotherapy. After the discovery of the first cephalosporins, scientists across worldwide had tried and succeeded in improving the structure of cephalosporins by chemical synthesis which are more effective against a wide range of bacteria. Change in structure of cephalosporins every times produced, a new "generation" of cephalosporins and till now there are five generations of cephalosporins. The expanded-spectrum cephalosporins (e.g., cefotaxime, ceftriaxone, and ceftazidime), either alone or in combination with other antibiotics, are the most common antibiotics used as initial antibiotics for treating serious infections.

Medical Practitioners often use the cephalosporins as an alternative in those patients who are sensitive to penicillin and are a commonly prescribed class of antibiotics and are frequently used beta-lactam drugs in a number of infectious disease states, against a broad range of microorganisms. These antibiotics are generally well-tolerated and are easy to administer. Allergic reactions e.g. *urticaria*, *anaphylaxis*, *interstitial nephritis* by cephalosporins have been reported in 1–3% of the total patients. [9-11] It is necessary to avoid the use of cephalosporins and other  $\beta$ -lactam drugs in those patient which have been identified as prone to allergic from other  $\beta$ -lactam drugs and it has also been reported that immunoglobulin E mediated allergies are relatively rare [7-10].

Since biochemical mechanism of cephalosporins are very similar to penicillins which involve formation of a covalent bond with peptidoglycan synthetases and penicillin binding proteins (PBPs) and causing cell lyses of bacteria, so the metabolism of cephalosporins is similar to penicillins. Susceptible cephalosporins can be hydrolyzed by  $\beta$ -lactamases, and in fact some  $\beta$ -lactamases are more efficiently hydrolyses cephalosporins as compared to penicillins itself. [12-16]



Penicillins (thiazolidine ring)



Cephalosporins (dihydrometathiazine ring)

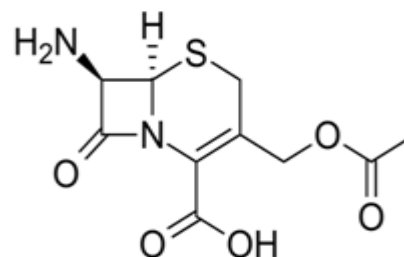
Figure 1. Comparative chemical structure of Penicillins and cephalosporins. **Classification of cephalosporins.**

Cephalosporins (onwards 1970s), the major derivative of cephems, which are well tolerated parallel of the penicillins have been used by medical practitioner among the most potent and most widely anti-microbial agents, are a sub-group of antibiotics including cephalosporins and cephamycins containing one of the most common 4-membered  $\beta$ -lactam heterocyclic ring. [17] On the basis of their optimal use cephems have been classified in various classifications such as chemical, microbiological, and pharmacokinetic and immunological. [18]

**General properties of cephalosporins** - The physical and chemical properties of the cephalosporins are similar to those of the penicillins, although the cephalosporins are somewhat more stable to pH and temperature changes. Cephalosporins are weak acids derived from 7-aminocephalosporanic acid. They are used either as the free base form for PO administration (if acid stable) or as sodium salts in aqueous solution for parenteral delivery (sodium salt of cephalothin contains 2.4 mEq sodium/g). Cephalosporins also contain a  $\beta$ -lactam nucleus susceptible to  $\beta$ -lactamase (cephalosporinase) hydrolysis. These  $\beta$ -lactamases may or may not also target penicillins. Modifications of the 7-aminocephalosporanic acid nucleus and substitutions on the side chains by semisynthetic means have produced differences among cephalosporins in antibacterial spectra,  $\beta$ -lactamase sensitivities, and pharmacokinetics.

**Chemical classification** - Chemically cephems have been classified into five different classes:

1. Cephalosporins.
2. Cephamycins. It contains the *cephems* nucleus (Figure 2) similar to cephalosporins, and are cephamycins are a very efficient antibiotic against anaerobic microbes as to cephalosporins (Figure 3) and examples of cephamycins derivatives are cefoxitin, cefotetan and cefmetazole. [19-21]



Acetylcephalosporic acid (ACA)

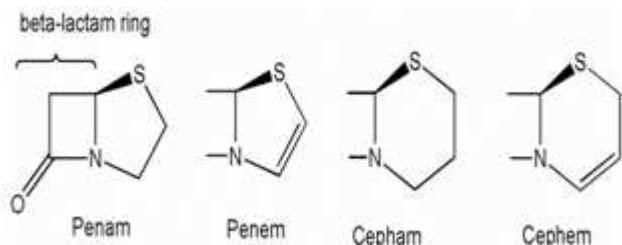
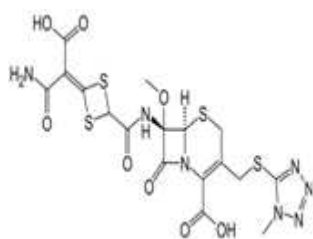
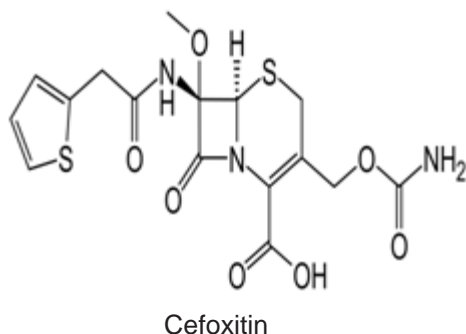
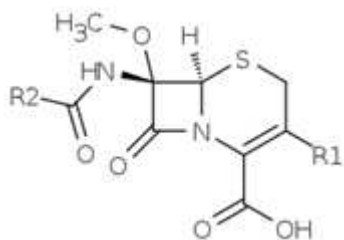


Figure 2. Structure of Aminocephalosporanic acid (7-ACA) and cephem nucleus.



Cefmetazole

Figure 3. Core structure of cephamycins, cefoxitin, cefotetan and cefmetazole.

3. Oxa-1-cephems are synthetic compounds not found in nature used as  $\beta$ -lactam antibiotics possessing a cephem nucleus in its structure but the sulfur atom has been substituted with oxygen. (Figure 4) The sulphur to oxygen atom shifts increases antibacterial activity and the rate of hydrolysis, because it enhances the acetylating power. Ring becomes more reactive, hydrophilicity also increases so these drugs are more able to penetrate into the bacterial cell. Examples of oxa-1-cephems derivatives are latamoxef and flomoxef. [22, 23]

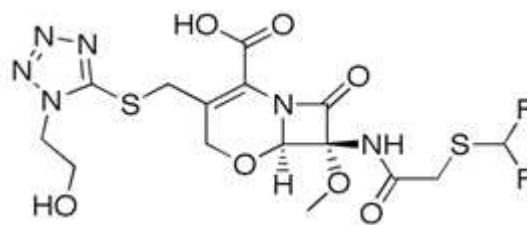
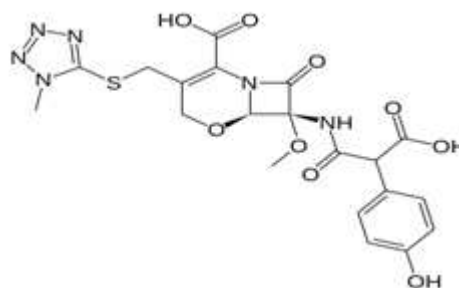


Figure 4. Structure of oxa-1-cephems derivatives latamoxef and flomoxef.

4. Carbacephems- Structurally it also contains cephem nucleus but the sulfur atom has been replaced by carbon in cephem nucleus and example of carbacephems is loracarbef. The smaller carbon atom instead of sulphur in loracarbef increases its potency. (Figure 5)

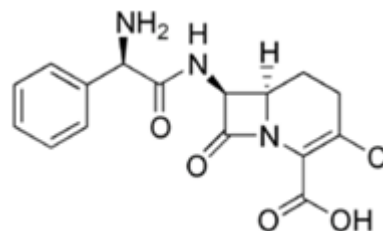


Figure 5. Structure of Loracarbef.

#### Microbiological classification.

On the basis of their antibacterial activity cephalosporins have been classified into first generation (1960-70), second generation (1970-80), third-generation (1980s) fourth generation (1984-93), and fifth generation which are summarized in Table 1. The first cephalosporins were classified as first-generation cephalosporins. Modifications in structure of first cephalosporins give more extended-spectrum cephalosporins, which were classified as second-generation cephalosporins and so on. Cephalosporin antibiotics of each generation exhibit different antimicrobial spectrum, stability towards  $\beta$ -lactamase, absorption, metabolism, stability and side-effects. Limited activity narrowed spectrum were reported in antibiotics of First-generation members as compared to second and third-generation while fourth-generation or fifth-generation cephalosporins are broad-spectrum antibiotics. The structural-activity relationships in the cephalosporins responsible for its various properties, e.g. oral activity, stability towards enzyme are similar with the penicillins. [

24] Each newer generation has significantly greater Gram-negative antimicrobial properties than the preceding generation, in most cases with decreased activity against Gram-positive organisms. Antibiotics belonging to Fourth-generation cephalosporins, are found to be a real broad-spectrum activity. [25]

Table 1 (see in last page)

(a) Given parenteral and (b) Given oral.

#### First-generation cephalosporins.

The first generation cephalosporins antibiotics e.g. cephalexin, cephaloridine, cephalothin, cephapirin, cephalazolin etc are highly active against gram-positive and the lowest against gram-negative bacteria *primarily Escherichia coli, Proteus, and Klebsiella and Anaerobic cocci* are often sensitive. These drugs have excellent activity against Gram-positive cocci, e.g. *staphylococci*, and *streptococci*, including *S. pyogenes*, *S. faecalis*, *pneumonia* and have been orally prescribed for uncomplicated skin and soft-tissue infections while parenteral cefazolin is mainly used for endocarditis due to methicillin-sensitive *S. aureus*, Group A streptococcus (GAS) pharyngitis, outpatient treatment and for prophylaxis before cardiothoracic, orthopedic, abdominal, and pelvic surgery. Limitations of drugs belonging to this generation of cephalosporins are mainly lack of activity against enterococci, no activity against methicillin-resistant staphylococci. [26-31] These drugs are poorly absorbed from gut, administered by injection, metabolized to give a free 3-hydroxymethyl group (deacetylation) and their metabolite is less active.

#### Second-generation cephalosporins.

Second-generation cephalosporins, e.g. cefaclor, cefamandole, cefoxitin, cefuroxime etc. are slightly less active against gram-positive cocci and more active against certain enteric gram-negative bacilli than first generation. Second generation cephalosporins are further divided into two sub classes-true second generation cephalosporins which include cefuroxime and cefprozil and the cephamycins in clude cefoxitin, cefotetan, and cefmetazole. Cephamycins are more active against polymicrobial infections caused by anaerobes, such as *Bacteroides* species, including *Bacteroides fragilis*, *H. influenza*. Because cephamycins are active against *Bacteroides* species, they are used when anaerobes bacteria cause infection which have been reported in intra-abdominal sepsis, decubitus ulcers, or diabetic foot infections. Cefoxitin is used prophylactically in multiple surgeries, including cardiac, biliary, appendectomy, small intestine, colorectal, head and neck, hysterectomy, and urologic. Second generation cephalosporins have also been found to be effective in the treatment of outpatient treatment of community-acquired pneumonia (CAP), endometritis, GAS pharyngitis, and Lyme disease with central nervous system (CNS) involvement but without parenchymal involvement. [32-34]

#### Third-generation cephalosporins.

Antibiotics belonging to third generation cephalosporins e.g. are cefsulodin, cefoperazone, ceftriaxone, cefodxime, ceftazidime/ avibactam and ceftazidime etc. They have broader spectrum of antibacterial activity and are active against the microbes which are resistant to 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> generation of cephalosporin. Third-generation cephalosporins are the real in the sense first generation to be considered with an extended-spectrum cephalosporin, but have decreased activity against gram-positive cocci, and enterococci often produce super-infections during their clinical uses. Most of third-generation cephalosporins are active against staphylococci; moderate coverage against MSSA, ceftazidime has in vitro activity against *Pseudomonas aeruginosa* and is found to be weakly active. It has been found that they are more stable to common  $\beta$ -lactamases produced by gram-negative bacilli, and because of it they are more useful against enteric gram-negative bacilli. But, third generation cephalosporins are easily hydrolyzed by broad-spectrum  $\beta$ -lactamases, such as extended-spectrum  $\beta$ -lactamases (ESBLs), and Amp C-producing organisms. A major advantage of third-generation drugs is their enhanced activity against gram-negative bacteria whereas second-generation drugs have found to be of very little use against *P. aeruginosa*, ceftazidime or cefoperazone. [35-39]

#### Fourth-generation cephalosporins.

*Fourth-generation cephalosporins* are cefepime and ceftipime which are available in the market and have been found to be highly potent antibiotics against several serious human infections. They have enhanced activity against *Enterobacter* and *Citrobacter* species and which are mainly to resistant with the third-generation cephalosporins. Cefepime is mainly active against MSSA, *Streptococcus* spp., *P. aeruginosa*, enteric gram-negative bacilli. It is mainly prescribed by the clinician in the treatment of empiric febrile neutropenia, HAP/VAP, severe DFIs, *P. aeruginosa* isolated in CAP, severe intra-abdominal infections, cholecystitis, cholangitis, HCA biliary infections, PJI, and also as an alternative therapy for community-acquired meningitis, as definitive therapy for vertebral osteomyelitis and culture-negative infective endocarditis and HCA meningitis/ ventriculitis. Activity of cefepime is comparable with ceftazidime against *P. aeruginosa*, greater against streptococci and methicillin-susceptible staphylococci. But activity of cefepime is almost equal to the other third-generation compounds. [40-44]

#### Fifth-generation cephalosporins.

Fifth-generation cephalosporins include ceftaroline and ceftobiprole, mainly active against resistant strains of bacteria. The activity of this generation cephalosporins have been found to be against gram-positive cocci and gram-negative bacilli which are similar to that of third-generation cephalosporins but are not active against *Pseudomonas* species. These antibiotics show broader coverage, enhanced activity against gram-positive cocci. g., MSSA, methicillin-resistant *S. aureus* (MRSA),



*Streptococcus* spp., enteric gram-negative rods. But little activity against the extended-spectrum beta-lactamase producers, e.g. *Acinetobacter baumannii*, and *Stenotrophomonas maltophilia*. Ceftaroline, which is an oxazolidinone cephalosporin, is effective against MRSA but ineffective against extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) producers or active AmpCs. While, ceftaroline is effective against infective endocarditis and is more effective against broad spectrum beta-lactamases (ESBLs and AmpCs) when it is used together with amikacin. Ceftibiprole is mainly effective against *Enterococcus faecalis* and *Pseudomonas aeruginosa*. It is also used in treatment of pyomyositis, skin and soft tissue infections in febrile neutropenia. Fifth-generation cephalosporins also include cefotetan and cefoxitin, which are effective against anaerobic Gram-negative bacilli but ineffective against enterococci bacteria. It is also used in the treatment of pyomyositis, skin and soft tissue infections in febrile neutropenia, and HAP/VAP. [33, 37, 45-50]

### Pharmacokinetics and Biotransformation of cephalosporins.

Cephalosporins are easily distributed into most of the body fluids and tissues, including kidneys, lungs, joints, bone, soft tissues, and the biliary tract, but in general, the volume of distribution is <0.3 L/kg. Cephalosporins penetrate well into most body fluids and the extracellular fluid of most tissues, especially when inflammation is present, which enhances diffusion. But, poor penetration into the CSF, even in inflammation, is a prominent feature of the standard cephalosporins which are substrates for P-glycoprotein efflux from the CNS and the third-generation cephalosporins e.g. moxalactam penetrate significantly into the CSF. The degree of plasma-protein binding is variable (e. g., 20% for cefadroxil and 80% for cefazolin). Only a few cephalosporins are acid stable (e. g. cephalexin, cephadrine, cefadroxil, cefpodoxime, and cefaclor) thus they are effective when most of the cephalosporins drugs are administered parentally. The others are administered either intravenously (IV) or intramuscularly (IM), with plasma concentrations reaching peak value in ~30 min after injection. After absorption from gastrointestinal tract bio availabilities are nearly 80-90% of cefroxadine, cefadroxil, cefsumide, cephalexin, cephadrine, cephacetrile, and cefazafur. Most of them are eliminated rapidly having serum half-life roughly 1-2 hours but generally are longer than those of penicillins and half-life of ceforanide, cefotetan, cefonicid, cefpiramide, ceftriaxone are 2.8, 3.5, 4.4, 5.0, and, 8 hours, respectively. [51-53]

The degree of plasma-protein binding is 20% for cefadroxil and 80% for cefazolin which shows variability. Cephalosporins belonging third- or fourth-generation are mostly able to penetrate the blood-brain barrier and so often, they are causing bacterial meningitis by susceptible pathogens. Cephalosporins including cefpodoxime and cefovecin are eliminated mostly by the kidneys, some with a substantial contribution from active tubular secretion,

which is blocked by probenecid, although in some cases e.g. cephalexin and cefazolin is filtered by glomerular filtration. The degree of metabolism varies. The newer cephalosporins e.g. cefoperazone are eliminated by high biliary elimination when administered intravenously and about 70% appears in bile. High biliary eliminations are also reported in cefmenoxime, ceftriaxone, cefbuperazone, and latamoxef (moxalactam) which are not appreciably absorbed from the gastrointestinal tract. So, the concentration of these cephalosporins drugs is high within intestine and consequently diminishes the normal micro flora of intestine with simultaneous emergence of resistant bacteria and may lead to *Clostridium difficile*-associated enterocolitis. Generally, cephalosporins antibiotics maintain effective blood concentrations for only 7–9 hours with a few exceptions found in cases of ceftiofur, cefpodoxime, and cefovecin.

Several cephalosporins are actively de-acetylated into de-acetylated derivatives, primarily in the liver but also in other tissues e.g. cephalothin, cephradine, ceftiofur, cephacetrile and cefotaxime. These derivatives are much less active, but de-acetylated derivatives of ceftiofur are active which are further metabolized to several active metabolites including an acetylated metabolite contributing significantly to efficacy. Some of the other cephalosporins are also found to metabolize to an appreciable extent. [54-56]

### Mechanism of action of Cephalosporins -

Cephalosporins kill the bacteria i.e. they are bactericidal and mechanism of action is similar to penicillins and other beta-lactam antibiotics by disrupting the synthesis of the peptidoglycan layer which is an important protein for bacterial cell wall by cross-linking which gives the cell wall its structural rigidity and strength specially of gram positive bacteria. [57-59] But Cephalosporins are less susceptible to beta-lactamases enzymes. Beta-lactams inhibit a bacterial enzyme called the transpeptidase enzyme which is involved in the synthesis of the bacterial cell wall. Penicillins, cephalosporins and like other beta-lactam antibiotics covalently linked to the enzyme's active site leading to inhibition of final cross linking stage of cell wall synthesis which weakens the bacterial cell wall. A bactericidal property of penicillin drugs arises because it interferes with the synthesis after attaching to penicillin-binding proteins (PBPs). The final transpeptidation step in the synthesis of the peptidoglycan is facilitated by DD-transpeptidases, also known as penicillin binding proteins [PBPs]. PBPs vary in their affinity for penicillin and other beta-lactam antibiotics. The number of PBPs varies between bacterial species. [60-63]

Consequently bacterial cells swell due to water entering the cell, leading to its lysis. Cephalosporin like Penicillins possibly acts as an analogue of the L-Ala—D-Glu portion of the pentapeptide chain residues on the precursor NAM/NAG-peptide subunits of the nascent peptidoglycan layer. The structural similarity between the

lactam antibiotics and D-alanyl-D-alanine facilitates their binding to the active site of PBPs. The  $\beta$ -lactam antibiotics generally exert their antibacterial activity by interfering with synthesis of the cell wall in susceptible organism. However, the carboxylate group that is essential to penicillin activity is not present in this portion. [64-68]

#### References :-

- Zaffiri, Gardner, and Toledo-Pereyra, *Clinical Microbiology and Infection*, 2000, 6, 6-8.
- E. P. Abraham, *Reviews of Infectious Diseases*, 1979, 1, 99-105.
- Richard S. Griffith and Henry R. Black, *JAMA*, 1964, 189, 823-28.
- Abraham, *Antimicrobial Drugs*, 2019.
- Tilli Tansey; Lois Reynolds, eds. (2000).
- Newton GG, Abraham EP, *Nature*, 1995, 26, 175, 548.
- Velasco J, Adrio LJ, Angel Moreno M, D'yez B, Soler G, Barredo J. L. *Nat Biotechnol*, 2000, 18, 857-861.
- Tan, Qiang; Song, Qingxun; Wei, Dongzhi (2006). *Enzyme and Microbial Technology*, 39 (5), 1166-1172.
- Tan Qiang, Zhang Yewang, Song, Qingxun, Wei, Dongzhi, *Journal of Microbiology & Biotechnology*, 2010, 26 (1), 45-152.
- MacFadden, D.R., LaDelfa A, Leen J., Gold W.L., Daneman N., Weber E., Al-Busaidi I., Petrescu D., Saltzman, I., Devlin M., et al., *Clin. Infect. Dis.* 2016, 63, 904-910.
- Sakoulas G., Geriak M., Nizet V., *Clin. Infect. Dis.*, 2019, 68, 157-164.
- Lee C.E., Zembower T.R., Fotis M.A., Postelnick M.J., Greenberger P.A., Peterson L.R., Noskin G.A., *Arch. Intern. Med.* 2000, 160, 2819-2822.
- Pichichero M., Casey J., *Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis.* 2006, 25, 354-364.
- Pilzer J.D., Burke T.G., Mutnick A.H., *Am. J. Health Syst. Pharm.* 1996, 53, 2970-2975.
- Veve M.P., January S.E., Kenney R.M., Zoratti E.M., Zervos M.J., Davis S.L., *J. Pharm. Pract.* 2019.
- Yuson C.L., Katelaris, C.H., Smith, W.B. *Aust. Prescr.* 2018, 41, 37-41.
- Chaudhry SB, Veve MP, Wagner JL, *Pharmacy (Basel)*, 2019, 7(3), 103, 2019.
- Collins CD, Scheidel C, Anam K, et al., *Clin Infect Dis.* 2020, 232.
- Little PJ, Peddie BA). *N. Z. Med. J.* 1978, 88, 616, 46-9.
- Clarke AM, Zemcov SJ, *J. Antimicrob. Chemother.*, 1983, 11, 67-72.
- Benlloch M, Torres A, Soriano F. *J. Antimicrob. Chemother.*, 1982, 10, 4, 347-50.
- Yazawa K, Mikami Y, Uno J, Otozai K, Arai T. *J. Antimicrob. Chemother.* 1989, 24, 6, 921-5.
- Cazzola M, Brancaccio V, De Giglio C, Paternò E, Matera MG, Rossi F. *Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol.* 1993, 31, 3, 148-52.
- Benlloch M, Torres A, Soriano F. *J. Antimicrob. Chemother.* 1982, 10 (4): 347-50.
- Yazawa K, Mikami Y, Uno J, Otozai K, Arai T., *J. Antimicrob. Chemother.*, 1989, 24, 6, 921-5.
- Cazzola M, Brancaccio V, De Giglio C, Paternò E, Matera MG, Rossi F. *Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol.* 1993, 31 (3): 148-52.
- Page MG. Emerging cephalosporins. *Expert Opin Emerg Drugs* 2007, 12, 511-524.
- Cephalosporins : Infectious Diseases Merck Manuals Professional Edition". Merck Manuals Professional Edition. 2018.
- Vidaillac C, Leonard SN, Sader HS, Jones RN, Rybak MJ. *Antimicrob Agents Chemother.*, 2009, 53, 2360-2366.
- Mackeen, A.D., Packard, R.E., Ota, E., Speer, L. *Cochrane Database Syst. Rev.* 2015.
- Kusumoto, F.M., Schoenfeld, M.H., Wilkoff, B.L., Berul, C.I., Birgersdotter-Green, U.M., Carrillo, R., Cha, Y.M., Clancy, J., Deharo, J.C., Ellenbogen, K.A., et al. *Heart Rhythm* 2017, 14, 503-551.
- Shulman, S.T., Bisno, A.L., Clegg, H.W., Gerber, M.A., Kaplan, E.L., Lee, G., Martin, J.M., Van Beneden, C., *Clin. Infect. Dis.* 2012, 55, 1279-1282.
- Lipsky B.A., Berendt A.R., Cornia P.B., Pile J.C., Peters, et al. *Clin. Infect. Dis.*, 2012, 54, 132-173.
- Solomkin J.S., Mazuski, J.E., Bradley, J.S., Rodvold, K.A., Goldstein, et al. *Clin. Infect. Dis.* 2010, 50, 133-164.
- Wormser, G.P.; Dattwyler, R.J.; Shapiro, E.D.; Halperin, J.J.; Steere, A.C., et al., *Clin. Infect. Dis.* 2006, 43, 1089-1134.
- Mandell, L.A., Wunderink R.G., Anzueto, A., Bartlett, J.G., Campbell, G.D., Dean N.C., Dowell et al., *Clin. Infect. Dis.*, 2007, 44, S27-S72.
- Robert C. Moellering, *The American Journal of Medicine*, 1985, 79, 104-9.
- Lionel A. Mandell et al., *The Journal of Infectious Diseases*, 1989, 160, 433-41.
- Verbist, *Clinical Pharmacy*, 1984, 3, 351-73.
- Bennett PN, Brown MJ., *Clinical pharmacology*, 9th ed. Toronto, Ontario, Churchill Livingstone, 2009.
- Livermore, D.M.  $\beta$ -Lactamases in laboratory and clinical resistance. *Clin. Microbiol. Rev.* 1995, 8, 557-584.
- Runyon, B.A. *Hepatology* 2013, 57, 1651-1653.
- L. S. Young, *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*, 1981, 8, 349-52.
- Norberto J. Palleroni, *Environmental Microbiology*, 2010, 12, 1377-83.
- Taplitz R.A., Kennedy E.B., Bow E.J., Crews J., Gleason C., Hawley D.K., Langston A.A., Nastoupil L.J., Rajotte M., Rolston K.V., et al. *J. Clin. Oncol.* 2018, 36, 3043-3054.
- Paladino JA, Sunderlin JL, Singer ME, Adelman MH, Schentag J.J., *Am J Health Syst Pharm*, 2008, 65, 1154-1159.
- Freifeld A.G., Bow E.J., Sepkowitz K.A., Boeckh M.J., Ito J.I., Mullen C.A., Raad I.I., Rolston K.V., Young J.A., Wingard J.R., et al. *Clin. Infect. Dis.*, 2011, 52, 56-93.

48. Kalil A.C., Metersky, M.L., Klompas M., Muscedere J., Sweeney D.A., Palmer L.B., Napolitano, L.M., O'Grady N.P., Bartlett J.G., Carratala J., et al. *Clin. Infect. Dis.*, 2016, 63, 61-111.
49. Gould IM, David MZ, Esposito S, Garau J, Lina G, Mazzei T, Peters G., *Int J Antimicrob Agents*, 2012, 39, 96-104.
50. Vidailly C, Leonard SN, Sader HS, Jones RN, Rybak MJ. *Antimicrob Agents Chemother.*, 2009, 53, 2360-2366.
51. Bergan, T. Pharmacokinetic Properties of the Cephalosporins. *Drugs*, 1987, 34, 89-104.
52. Pacifici GM. Pharmacokinetics of cephalosporins in the neonate, a review. *Clinics*. 2011, 66, (7), 1267-1274.
53. Deguchi Y, Koshida R, Nakashima E, Watanabe R, Taniguchi N, Ichimura F, et al. *J Pharm Sci.* 1988, 77, 674-8..
54. Regazzi MB, Chirico G, Cristiani D, Rondini G, Rondanelli R. Cefoxitin in newborns. *Eur J Clin Pharmacol.*, 1983, 25, 507-9.
55. Bint AJ, Yeoman P, Kilburn P, Anderson E, Stansfield E., *J. Antimicrob Chemother.*, 1981, 8, 47-51.
56. Mulhalla A, de Louvois J, James J. *Eur J Pediatr.* 1985, 144, 379-82.
57. W B Hugo, A D Russell. *Journal of Pharmacy and Pharmacology*, 1961, 13, Issue 1, 705-722.
58. Pandey, N.; Cascella, M. "Beta lactam antibiotics". *Stat Pearls*. 2020
59. Rossi S (ed.) *Australian Medicines Handbook* 2004. Adelaide: Australian Medicines Handbook.
60. Miyachiro, M. M.; Contreras-Martel, C.; Dessen, A. *Sub-Cellular Biochemistry*. 2019, 93, 273-289.
61. Cushnie, T. P.; O'Driscoll, N. H.; Lamb, A. J. *Cellular and Molecular Life Sciences*. 2016, 73 (23), 4471-4492.
62. Wise, E. M., and Park, J. T. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 1965, 54, 75-81.
63. Tipper, D. J., and Strominger, J. L. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 1965, 54, 1141.
64. Waxman, D. J., and Strominger, J. L. *J. Biol. Chem.* 1980, 255, 3964-3976.
65. Linnett, P. E., and Strominger, J. L. (1974) *J. Biol. Chem.* 249, 2489-2496.
66. Knott-Hunziker, V., Waley, S. G., Orlek, B., and Sammes, P. G. *FEBS Lett.* 1979, 99, 59-61.
67. Fisher, J. F., Meroueh, S. O., Mobashery, S. (2005). *Chemical Reviews*. 105 (2), 395-424.
68. Kasten, B., Reski, R. *Journal of Plant Physiology*. 1997, 150 (1), 137-140.

Table1. Classification of cephalosporins according to their antimicrobial activity.[25]

Generation of cephalosporins	Examples	Effective/ Ineffective against microorganism	Therapeutic Uses
First Generation	1.Cephalothin, Cefazolin, Cephapirin <sup>(a)</sup> 2.Cephalexin, Cephadrine, Cefadroxil <sup>(b)</sup>	Highly active against gram-positive and the lowest against gram-negative bacteria. Activity against <i>Proteus mirabilis</i> , some <i>Escherichia coli</i> , and <i>Klebsiella pneumoniae</i> (PEK). No activity against methicillin – resistant <i>Staphylococcus enterococci</i> .	Used for endocarditis due to methicillin-sensitive <i>S. aureus</i> , Group A <i>Streptococcus</i> (GAS) pharyngitis, outpatient treatment and for prophylaxis before cardiothoracic, orthopedic, abdominal, and pelvic surgery.
Second Generation	1.cefuroxime, cefoxitin, Cefamandole, Cefonicid Ceforanid <sup>(a)</sup> 2.Cefaclor <sup>(b)</sup> ,	Slightly less active against gram-positive cocci and more active against certain enteric gram-negative bacilli than first generation. <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Enterobacter aerogenes</i> , <i>Neisseria</i> (HEN)	Prophylactically in multiple surgeries, including cardiac, biliary, appendectomy, small intestine. Cephamycins are more active against polymicrobial infections caused by anaerobes.
Third Generation	1.Cefotaxime, Ceftibutin, Ceftriaxone, Cefoperazone, Cefitizoxime, Ceftazidime <sup>(a)</sup> Cefsulodin 2.Cefixime, Cefdoxime, Cefdinir <sup>(b)</sup>	Broader spectrum of antibacterial activity, active against staphylococci, decreased activity against gram-positive cocci, and enterococci.	stable to common $\beta$ -lactamases produced by gram-negative bacilli, as prophylactic against spontaneous bacterial peritonitis (SBP), biliary or colorectal or liver transplant SSIs, UTI
Fourth Generation	Cefepime, cefpirome <sup>(a)</sup>	Enhanced activity against <i>Enterobacter</i> and <i>Citrobacter</i> species and which are mainly resistant with the third-generation cephalosporins. Cefepime is mainly active against MSSA, <i>Streptococcus</i> spp.	empiric febrile neutropenia, HAP/VAP, severe DFIs, <i>P. aeruginosa</i> isolated in CAP, severe intra-abdominal infections, cholecystitis, cholangitis, HCA biliary infections
Fifth Generation	Ceftaroline, ceftobiprole.	Broader coverage, enhanced activity against gram-positive cocci, i.e. MSSA, methicillin-resistant <i>S. aureus</i> (MRSA). <i>Streptococcus</i> spp., ineffective against extended-spectrum $\beta$ -lactamase.	pyomyositis, skin and soft tissue infections in febrile neutropenia, and HAP/VAP, UTI

\*\*\*\*\*



## योगदर्शने वृत्तयः

डॉ. नरेन्द्रकुमारः\*

**प्रस्तावना** - योगदर्शनानुसारं समाधिपादे चित्ती संज्ञाने। चित्ति स्मृत्या<sup>2</sup> धातुभ्यः क्तः प्रत्ययत्वात्सिद्धयति। इत्यनेन चित्त पदे ज्ञानत्वं निरन्तर स्मरणस्य साधनत्वस्य भावो निहितः कस्यचिदर्थ तत्त्वस्य निश्चयात्मकं मुख्यसाधनं बुद्धित्वाद्वा चित्तपदेनोक्तम्। वृत्तिः शब्दस्य धात्वर्थः वृञ् वरणे<sup>3</sup> धातोः क्तिन् प्रत्यय इत्यनेन निष्पद्यते। मूलसूत्रमस्ति “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः”<sup>4</sup>

वृत्तिः गुणैः युक्तः चित्तस्य व्यापारः वृत्तिः एतदेव निरोधव्यः। यजुर्वेदे चित्तं समाहित करणस्योपदेशः दत्तः।

“युज्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः।

अग्नेर्ज्योतिर्निर्वाण्य पृथिव्याऽध्याभरत्॥”<sup>5</sup>

यो ऐश्वर्यकांक्षी मनुष्यः परमेश्वरादि पदार्थानां विज्ञानार्थ आदौ मननात्मकान्तः करणस्यवृत्तिं तथा धारणात्मकान्तः करणस्य वृत्तिः योगाभ्यासे समायोजयन्तः योगवेत्ता भवेयुः।

अत्र परमेश्वरकाम्येच्छुक मनुष्याय चित्तवृत्तिः सर्वप्रथमं निरोधार्थमु शोऽस्ति कस्मै ? तत्त्वार्थं, ब्रह्मज्ञानार्थं तथा तस्य फलं स परमात्मनः दिव्य प्रकाशं निश्चयात्मकरूपेण ज्ञात्वा यथावद्धारणं कुर्यात् एवं परमात्मा तस्य योगिनः बुद्धिं स्वकीयया कृपया स्वान्तिकं समायोजयति। अतः योगस्यारम्भः सर्वप्रथमं वृत्तिनिरोधेन एव भवति।

अत्र स्पष्टमस्ति यत् चित्तस्य वृत्तयः सत्त्वादिगुणाधारे सात्त्विक वृत्तयः राजसिक वृत्तयः एव वृत्तयः सन्ति। एता वृत्तीः निरोधः एवं योगावस्था अत्र ज्ञायते-केवलं राजसिकः, केवलं तामसिक केवलं सात्त्विक वा वृत्तीनां निरोधः योगश्रेण्यां ना गच्छति। यतोहि-अत्र राजसिक राजसिक वा तामसिक वा उभयोविध वृत्तयः जायमानात् प्रवृत्तिः चाञ्चल्यं दुःखं ज्ञानञ्च समुपस्थितत्वात् कैवल्यं सम्भवं न।

राजसिक सात्त्विकञ्च वृत्तीनां निरोधोऽपि योगश्रेण्यां नागच्छति। यतोहि तमोगुण प्रभावाद् दुःखाज्ञानं निरन्तरं भवति। तामसिक सात्त्विकञ्च वृत्तीनां निरोधोऽपि योगश्रेण्यां नागच्छति। यतोहि रजोगुण प्रभावेण प्रवृत्तिः चाञ्चला निरन्तरं भवति।

राजसिक तामसिकञ्च वृत्तीनां निरोध योगश्रेण्यां आगच्छति। यतोहि सात्त्विक वृत्तीनां उदयात्, संप्रज्ञात समाधिः सम्भवोभवति एवं विवेकख्यात्याः प्राप्ति सम्भवा। त्रिधा वृत्तीनां निरोधोऽसम्प्रज्ञातसमाधिं एवं निम्नोत्तमफलं मोक्षग्राह्यति।

अतः चित्तं प्रख्या, प्रवृत्ति स्थितिशीलञ्च वर्णयन्तः त्रिगुणात्मकमुक्तम्। चित्तं प्रकृत्याः परिणामत्वात् त्रिगुणात्मकमेवास्ति। चित्तं सत्त्वगुण प्रधानतयारेव प्रख्या- प्रकाश- ज्ञानबहुलमस्ति। चित्ते रजोगुण प्रभावेण प्रवृत्तिः एवं रजोगुणस्यान्यानि लक्षणानि परितापः शोकः रोगः द्वेषा निरन्तर विषय सेवायां मग्नताऽदयोऽपि व्यक्ताः भवन्ति तथा तमोगुण प्रभावेण स्थितिस्तथा तमोगुणस्थान्यानि लक्षणानि गुरुता, कामः क्रोधः लोभ आलस्य क्रूरता धैर्यनाशः एवं नास्तिकतायाः उत्पत्त्यादयोऽपि उद्गच्छन्ति।

### सन्दर्भः

1. धातुपाठ भ्वादिगणः - 39
2. धातुपाठ चुरादिगणः - 01
3. धातुपाठ स्वादिगणः - 08
4. योगदर्शनम् - 1.2
5. यजुर्वेदः - 11.1

## मुस्लिम परिवारों में शिक्षा की प्रगति में महिलाओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन (रीवा शहर के विशेष संदर्भ में)

निगार फातिमा \*

**शोध सारांश** – मुस्लिम समाज में परम्परागत व अति कट्टर मानसिकता होने के कारण मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रभाव अन्य भारतीय समाज की अपेक्षा गौण रहा। इस्लामिक संस्कृति भले ही कितनी गतिशील हो। अब भी परिवर्तन के विरुद्ध रुढ़िवाद एवं अपनी पुरानी मूल व्यवस्था को बनाये रखने का प्रयास करती है जिसके परिणाम में मुस्लिम बालिकाओं की शैक्षणिक प्रगति में बाधा पहुँची है। पर्दे के कारण शिक्षा भी प्रभावित हुई। कुरान पढ़ने लायक साक्षरता प्राप्त करने के बाद उनको घरेलू कामकाजी में दक्ष बनाया जाता रहा है। वस्तुतः पर्दा प्रथा मुस्लिम समाज की एक प्रमुख समस्या है। मुस्लिम स्त्रियों को घर से बाहर निकलते समय बुरका ओढ़ना पड़ता है। मुस्लिम महिलाओं में पिछड़ापन रुढ़िवादिता एवं अंधविश्वास पाये जाते हैं। शिक्षा की कमी मुस्लिम महिलाओं की एक प्रमुख समस्या है शिक्षा की कमी के कारण ही मुस्लिम महिलाएँ सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं।

**प्रस्तावना** – मुस्लिम समुदाय भी पित्रसत्तात्मक समाज है जहाँ पुरुषों को शक्तिशाली बना दिया गया है। स्त्रियों को दबाने के लिये कुरान पाक में विद्यमान पित्रसत्तात्मक तत्वों को बढ़ा-चढ़ा कर इस्तेमाल किया जाता है। पर्दा प्रथा के गलत ढंग से प्रयोग करने के बारे में जे.आई.स्मिथ ने अपनी लेख में बताया है कि कुरान में स्त्रियों को शहरी लोगों के सामने खुले बदन आने की मनाही है परन्तु स्वयं सिर से पाँव तक बुर्के से ढकने की पाबंदी नहीं है। उनमें शिक्षा का अभाव है वे स्कूल तो जाती हैं पर चौथी पाँचवी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं इनकी पढ़ाई छोड़ने का कारण यह नहीं है कि मुस्लिम औरत पर्दा में रहती हैं। स्कूल सह-शिक्षा के ज्यादा हैं ये कारण बहुत मामूली हैं मुस्लिम औरत का हिन्दुस्तान में नहीं पढ़ने का मूल कारण गरीबी है। उनकी स्थिति अनुसूचित जाति की तरह है। जिस वजह से अनुसूचित जाति की औरत नहीं पढ़ पाती है। उन्हीं वजह से मुस्लिम औरत भी नहीं पढ़ पाती है। धर्म और पर्दा उतना बड़ा कारण नहीं है शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाने के बाद भी सामाजिक व पारिवारिक स्थितियों के चलते वह आगे नहीं बढ़ पा रही है। मुस्लिम लड़किया स्कूल जाने से वंचित ही रह जाती हैं।

**शोध प्रविधि** – प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मुस्लिम परिवारों में शिक्षा के प्रगति में महिलाओं की आर्थिक स्थिति का आर्थिक अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक समकों का संकलन व्यक्तिगत पहुँच की सीमा के भीतर करने का प्रयास किया गया है। समक संग्रहण के समय इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि सम्बन्धित समक एवं सूचनाएँ अध्यात्मिक हो शोध में सामाजिक आर्थिक सैद्धान्तिक पक्षों के लिए इसमें ग्रंथालियों पूर्वी शोध साहित्य ग्रंथों तथा प्राथमिक समकों और आकड़ों के संकलन के लिए उपकरण के रूप में स्व निर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

**उद्देश्य** – प्रस्तुत अध्ययन मुस्लिम परिवारों में शिक्षा के प्रगति में महिलाओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन रीवा शहर के विशेष संदर्भ में केन्द्रित है। इसका प्रमुख उद्देश्य वर्तमान में तेजी से बदल रही महिलाओं की स्थिति का आर्थिक विवेचन है। तेजी से बढ़ते औद्योगिक क्रांति वैज्ञानिक प्रगति और वैश्विक बदलाव ने भारतीय जन मानस को गहराई से प्रभावित किया है।

जिसका प्रभाव भारतीय जन मानस पर स्पष्ट दिखाई देता है। एक और जहाँ पारंपरिक मूल्य बदल रहे हैं वही दूसरी ओर समाज को दिशा देने वाला पुरुष समाज एक विचित्र अंतर्द्वंद्व में है। वह होने वाले सामाजिक परिवर्तनों को व्यक्तिगत स्तर पर स्वीकार नहीं कर पाता लिहाजा उसके महिला हेतु मानदंड दोहरे हो जाते हैं। जो महिलाओं की सामाजिक स्थिति को प्रभावित करता है।

1. अनुसंधान क्षेत्र की मुस्लिम महिलाओं की जनांकिकीय स्थिति का पता लगेगा।
2. मुस्लिम महिलाओं के सांस्कृतिक सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का अध्ययन प्रस्तुत होगा।
3. मुस्लिम महिलाओं के शैक्षिक स्तर का पता चलेगा।
4. मुस्लिम समाज के विषय की जानकारी प्राप्त करना।
5. आधुनिक तकनीक व शिक्षा के कारण मुस्लिम महिलाओं में सामाजिक बदलाव का पता चलेगा।
6. मुस्लिम परिवारों की धार्मिक स्थिति उनकी पारिवारिक संरचना विवाह परम्पराएं एवं अंधविश्वास के विषय में जानकारी प्राप्त करना।

**उपकल्पना** – किसी भी सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना अनुसंधान को एक उचित एवं स्वस्थ दिशा प्रदान करती है वास्तव में एक उपकल्पना को दो या दो से अधिक चरों के मध्य स्थापित संबंध एक काल्पनिक या अनुमानित विवरण है। अनुसंधानकर्ता अपना अनुसंधान प्रारम्भ करने के पूर्व ही कुछ अनुमान या पूर्वानुमान लगा लेते हैं। ये पूर्वानुमान अनुसंधान के दिशा निर्धारण में महत्वपूर्ण एवं प्रभावी भूमिका निभाते हैं वर्तमान अध्ययन का केन्द्रीय विषय मुस्लिम परिवारों में शिक्षा के प्रगति में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन मुस्लिम समुदाय की महिलाओं में शिक्षा के संदर्भ में जानकारी हासिल करने के लिए उपकल्पनाओं का निर्माण किया। आगे चलकर ये उपकल्पनाएँ अनुसंधान को प्रभावित करने में काफी कारगर साबित हुई।

1. मुस्लिम परिवारों की महिलाओं में शिक्षा का स्तर अत्यन्त ही निम्न है।
2. निम्न शिक्षा स्तर के कारण शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी उन्हें नहीं होती।

3. मुस्लिम परिवारों की महिलाओं के विकास हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाएँ पर्याप्त एवं उपयोगी हैं।
4. मुस्लिम परिवार की महिलाओं में स्वास्थ्य हेतु पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उन्हें प्राप्त नहीं होती।

**विषय विवरण-** मुस्लिम परिवारों में शिक्षा की प्रगति में महिलाओं की स्थिति में बाधा पहुंचाने में इस्लामिक जगत कट्टरपंथियों के कारण इस्लाम की छवि एक पिछड़े किस्म के धर्म के रूप में बदनाम हुई है। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण महिला शिक्षा पर अंकुश लगाना है। मुस्लिम बालिका शिक्षा मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है जागरूकता की कमी अभिभावकों की संकुचित मानसिकता को बदलना होगा और यह सोचना होगा कि शिक्षित बालिका ही एक अच्छी माँ एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू और अच्छी सास और शिक्षित नागरिक बनकर देश के विकास के मार्ग में अपना योगदान दे सकती है। मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रभाव अन्य भारतीय समाज की अपेक्षा गौण रही है। इस्लामिक सांस्कृतिक भ्रले ही कितनी गतिशील हो। अब भी परिवर्तन के विरुद्ध रूढ़िवाद एवं अपनी पुरानी मूल व्यवस्था को बनाये रखने का प्रयास करती रही है। जिसके परिणाम में मुस्लिम महिलाओं की शैक्षणिक प्रगति में बाधा पहुँची है।

#### **सुझाव:**

1. मुस्लिम परिवारों में शिक्षा को प्रगति देने में महिलाओं का भययुक्त वातावरण देने में प्रशासन की भूमिका प्राथमिक स्तर पर तय की जाय।
2. प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भारतीय नारी के सेवा समर्पण त्याग और बलिदान जैसे उत्कृष्ट स्वरूप का सम्मिलित कर पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बचपन से ही महिलाओं के प्रति एक अच्छा विचार स्थापित किया जा सके।
3. प्रशासन की सक्रिय भूमिका के लिए सामाजिक संगठनों स्वयं सेवी

संस्थाओं और आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सूचना पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश हो।

4. प्राथमिक शिक्षा को ऐच्छिक नहीं अनिवार्य कर दिया जाये, उपेक्षा करने वाले अभिभावकों को दण्ड का प्रावधान है।
5. बच्चियों के साथ भेदभाव न हो। शिशु अवस्था में माँ का दूध पर्याप्त मिले इसके लिए माताओं को जानकारी देना आवश्यक है।
6. महिलाओं को पर्यावरण सम्बन्धी शिक्षा भी देना आवश्यक है।

**निष्कर्ष-** प्रस्तुत शोध कार्य को शोधार्थी ने इस आशय के चयन किया है कि महिलाओं को शिक्षित करने के लिए किया गया है। मुस्लिम महिलाओं के शिक्षा में प्रभावशीलता के अध्ययन का चुनाव किया था उसके पीछे एक कारण यह भी था कि माना जाता है कि मुस्लिम समाज में महिलाओं को ज्यादा स्वतंत्रता और स्वयत्ता है पर देखने में यह है कि मुस्लिम महिलाओं का सुविधाएँ मात्र तलाक लेने और देने की है शेष बाते सब अन्य धर्म समाज और समुदाय जैसी ही है। मुस्लिम समाज और परिवार की सामाजिक अर्थिक स्थिति के आंकलन से स्पष्ट होता है कि उनकी शैक्षिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके प्रमुख कारण एक ओर जहाँ परम्परावाद है वही दूसरी ओर उनका नवीन आर्थिक क्षेत्र से जुड़ना है जिसके कारण अधिकार मुस्लिम परिवार श्रम आधारित जीवन जीने के बावजूद अशिक्षा रूढ़िवादिता जनसंख्या बाहुल्य है जो ग्रसित है।

#### **संदर्भ ग्रंथ सूची:-**

1. आहूजा सामाजिक समस्याएँ : आहूजा रावत पब्लिशेशन, जायपुर 2000
2. अवस्थी इन्दिरा रुरल वीमेन ऑफ इण्डिया : वी.आर.पी. ब्लैशिंग कारपोरेशन, दिल्ली - 1982
3. प्राथमिक समंक साक्षात्कार प्रश्नावली, रीवा शहर, म0प्र0

\*\*\*\*\*

## प्रसादोत्तर हिन्दी नाटक और समसामयिक जीवन का स्वर (चरित्र स्थापन के संदर्भ में)

डॉ. ओमवती देवी \*

**प्रस्तावना** - नाटक जीवन के वैयक्तिक और सामाजिक सन्दर्भों से जुड़ा होने के कारण दोनों ही पक्षों की भावात्मक प्रतिक्रियाओं का अभिव्यक्त रूप है क्योंकि यह अमूर्त विश्लेषण प्रस्तुत न कर जीवन्त और मूर्तिमान व्यक्तियों की वास्तविक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से व्यक्त होता है। नाटक का कथ्य चाहे कितना भी व्यक्तिपरक हो, परन्तु वह एक समाज को साथ लेकर चलता है। अर्थात् एक से अधिक व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास द्वारा ही दृश्यता को प्राप्त होता है। नाटक प्रदर्शन के सनातन धर्म के कारण व्यक्ति से समूह और समूह से व्यक्ति की ओर संचरण करता है। नाटककार अतीत के गर्भ में झांकते हुए भी वर्तमान से दृष्टि नहीं हटा सकता क्योंकि सामाजिक मूलतः वर्तमान में ही जीता है और आवश्यकता इसी बात की बनी रहती है कि नाटककार वर्तमान जीवन को किस सीमा तक अपनी कृति में मूर्त एवं साकार रूप प्रदान कर पाया है। नाटककार बाह्य जीवन के संघात और संघर्षों को झेल कर उनका आत्मा के स्तर पर साक्षात्कार कर अपनी अनुभूति को नाट्य-रूप प्रदान करता है। यही कारण है कि नाटक में युगीन जीवन की अभिव्यक्ति तथा सामाजिक सम्बन्ध एवं उनसे प्रकट होने वाले मूल्यों में नाटककार अपने मानसिक संसार को भी व्यक्त करने से नहीं झिझकता। विश्व का उत्कृष्टनाट्यसाहित्य विवेचित धारणा का सबल प्रमाण है।

प्रसादोत्तर नाट्य-साहित्य में चित्रित समसामयिक जीवन के स्तर का विवेचन करने से पूर्व यह अपेक्षित होगा कि आलोच्यकालीन नाट्य-साहित्य की परिस्थितियों का अवलोकन कर लिया जाए यह साहित्य अपने ऐतिहासिक परिवेश में विदेशी दासता से मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा था।

सन् 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पद से पं० जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की घोषणा की और अपने को पूर्ण समाजवादी घोषित किया।<sup>1</sup> इसी वर्ष लखनऊ में प्रेमचन्द जी की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक भी हुई जहाँ मार्क्सवादी स्वर मुखरित हुआ और साहित्य आदर्श का आंचल त्याग सामान्य व्यक्ति के चित्रण हेतु यथार्थवादी बौद्धिक धरातल की ओर नत हुआ। कविता के क्षेत्र में पंत और निराला ने काव्य को नवीन मोड़ दिया। पं० रामचन्द्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में नवीन प्रतिमानों और मानदण्डों को जगा दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय पृष्ठभूमि में बड़े बदलाव हो रहे थे और वाजपेयी जी के अनुसार, 'इस व्यापक राष्ट्रीय जागृति की हलचल में ही हमारा साहित्य पनपा और फला-फूला है।'<sup>2</sup>

1937 में प्रथम बार भारत भर में आम चुनाव हुआ और इंडियन नेशनल कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ, परन्तु 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध में भारत को झोंकने के विरोध में कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी भारतीय राजनीति के रंगमंच पर अपनी पूर्ण प्रतिष्ठा कर चुके थे और

1942 के 'भारत छोड़ो देशव्यापी आन्दोलन में उन्हें जननायक बापू बना दिया। भारतीय जनता का यह विरोध क्रान्ति के स्वर में परिवर्तित हो गया। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतन्त्र हुआ, परन्तु देश विभाजन के कारण साम्प्रदायिक अविन की प्रचण्ड ज्वाला ने स्वतन्त्रता के उल्लास को ग्रस लिया और एक नई समस्या शरणार्थियों के पुनर्वास एवं विस्थापन की हुई।

चीन (20 अक्टूबर सन् 1962) तथा पाकिस्तान (1 सितम्बर 1965) के आक्रमणों ने पुनः देश की एकता के साथ शत्रु का मुकाबला करने की शक्ति को जागृत किया और साहित्यकारों ने भी अपनी कलम के बल पर दुश्मन को ललकारा। इस ऐतिहासिक पीठिका के अनुरूप ही साहित्य में नवीन मोड़ आए और विशेष कर नाट्य-साहित्य सामूहिक दायित्व का निर्वाह करता हुआ इन्हीं के साथ पग-मेल करता हुआ अग्रसारित हुआ।

प्रसादोत्तर काल के नाटकों में चित्रित समसामयिक जीवन का स्वर एवं नाटककारों के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त होगा कि नाटकों का विवेचन चेतनागत आधार पर किया जाए इसी दृष्टि से देखें तो स्वतंत्रता पूर्व के नाटकों में स्त्री-स्वातंत्र्य का स्वर है और स्त्री पुरुष की समस्याओं का मूल्यांकन नैतिक धरातल पर किया गया है। मिश्र और अश्व के नाटक इस दृष्टि से अवलोकनीय हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश को इस क्षेत्र में अधिक विकास करने का अवसर मिला। जीवन-मूल्यों और मर्यादाओं में द्रुत गति से परिवर्तन परिलक्षित हुआ। इस परिवर्तन ने मानव जीवन को अनेक समस्याओं में उलझा दिया। पति-पत्नी के सम्बन्ध, पारिवारिक मर्यादाएँ, परम्पराएँ एक-एक करके विशृंखलित होने लगी। व्यक्ति ने अपने आपको बहुत एकाकी और टूटा हुआ महसूस किया।

हिन्दी नाटककारों ने जीवन के व्यापक स्तर पर इसी प्रकार की अनेक घटनाओं को अपनी कृतियों का प्रतिपाद्य बनाया, जहाँ जीवन की इस द्वन्द्वमूलक स्थिति के बीच ही इसका विकास निहित है।

नाटककार अपनी भावनाओं और मान्यताओं के अनुरूप कुछ कथागत चरित्रों में अपनी स्थापनाओं की छाप लगा देता है तो कुछ का निर्माण ही स्वतंत्र भित्ति पर समसामयिक परिप्रेक्ष्य में ही करता है। इन्हीं के साथ नाटक जीवन का परिदृश्य होने के कारण ऐसे मूल्यों का सृजन करता है जिनसे जीवन का दिशा बोध हो सके। इन्हीं मूल्यों के आधार पर उस काल की सांस्कृतिक, नैतिक एवं व्यक्ति चेतना का स्पर्श एवं ज्ञान सम्भव हो पाता है और अन्ततः इन्हीं मूल्यों का सफल निर्वाह नाट्य कृति को काल की सीमा से मुक्त कर कालातीत बना देता है। अतः आवश्यकता है कि नाटककारों के चरित्रगण दृष्टिकोण एवं जीवनगत मूल्यों के मूल में निहित भावनाओं का भी अवलोकन कर लिया जाए।



'चरित्र-स्थापन' से तात्पर्य यह है कि नाटककार पूर्व प्रतिपादित कथा-चरित्रों में अपनी भावना, विचारों और दूरदर्शी मेधा के बल पर एक नया रूप दे देता है तो वह चरित्र को एक नवीन रूप में स्थापित कर देता है, इस प्रक्रिया को आधुनिक नाट्य-शब्दावली में चरित्र-स्थापन की संज्ञा दी गई है। चरित्र की इस स्थापन प्रक्रिया के मूल में नाटककार का परिवेश, समसामयिक परिस्थितियाँ मुख्य होती हैं और उसकी सफलता इसी में है कि वह किस प्रकार इन सबका उपयुक्त समावेश कर पाता है। 'आवश्यकता इस बात की निरन्तर बनी रहती है कि उनके स्थापन में स्वाभाविकता का निर्वाह हो, जिससे प्रतीत हो कि उनका जीवन है और वह जीवन में अनुभव-साम्य व्यवहार करते हैं, जैसा कि अभिनय द्वारा अभिनेता दर्शाता है।'<sup>3</sup> नाटक चरित्र-चित्रण और जीवन्त पात्रों की रचना करने से जो हमें सदा परिचित लगे, नाटककार को सच्चे अर्थों में नाटककार बनाता है।<sup>4</sup> अतः स्पष्ट है कि चरित्रगत स्थापनाएँ जीवन्त हों और लगे कि उन सबके माध्यम से इसी लोक के अनुभवों का सम्प्रेषण हो रहा है क्योंकि कला का मूल्य उसकी सूक्ष्म सम्प्रेषणीयता में निहित है।<sup>5</sup>

प्रसादोत्तर काल के नाट्य-साहित्य में चरित्र-स्थापन के माध्यम से समसामयिक सन्दर्भों का पर्याप्त निर्वाह दृष्टिगत होता है, विशेषकर ऐतिहासिक नाटक तो इसी पद्धति के निर्वाह का अनुगमन करते हैं। प्रसाद से पूर्व भी नाटककार भारतेन्दु के 'अन्धेर नगरी' के माध्यम से शासक वर्ग के अन्धे शासन एवं तत्पश्चात् स्वयं प्रसाद ने अपने ऐतिहासिक नाटकों में भारतीयता तथा स्वदेशी राष्ट्र स्थापना की भावना को व्यक्त किया है।

प्रसादोत्तर काल का नाट्य-साहित्य ऐतिहासिक और सामाजिक दो नाट्य-चेतनाओं पर संचरण करता है। ऐतिहासिक नाटकों में इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन में आधुनिक भाव बोध और विभिन्न सामयिक समस्याओं का नाटककारों ने अपनी दृष्टि के अनुरूप स्थापन किया है। वितस्ता की लहरेय में नाटककार ने पुरु के चरित्र की स्थापना भारतीय आदर्शों के अनुरूप की है और नाटककार ने तत्कालीन गांधीवादी प्रभाव के अनुरूप ही नाटक का अन्त भी किया है। नाटककार के शब्दों में, 'वितस्ता के तट पर दो विभिन्न जातियों और संस्कृतियों की टक्कर हुई थी जो अपने विधि-विधानों और जीवन-दर्शन में एक दूसरे के विपरीत थी। 'वन सैनिकों में विजय का उन्माद था तो पुरु और केकय जनपद के नागरिकों में देश के धर्म और पूर्वजों के आचरण की रक्षा का भार।'<sup>6</sup> वस्तुतः मिश्र जी का पुरु उस समय की एक चेतना है जो एक ओर बाह्य शक्तियों का मुकाबला करने के लिए कटिबद्ध है परन्तु वह अपने मानवीय संस्कारों को भी नहीं भूला है और नाटक का अन्त मित्रता और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होता है। 'कुछ ऐसा होता कि मानवता के घाव पर धीतल विलेपन लगे और वितस्ता की लहरों में अनुराग का जल हो।'<sup>7</sup> मिश्र जी के नाटक 'अशोक', 'गरुडध्वज', 'वत्सराज', 'दशाश्वमेध' इत्यादि भी उनके इसी प्रकार के विचारों का प्रतिपादन करते हैं।

सेठ गोविन्ददास के 'हर्ष', 'शेरशाह' और 'शशिगुप्त' नाटक के प्रमुख पात्र अपनी-अपनी विशेषताओं के साथ युगीन सन्दर्भों से समन्वय स्थापन करते हैं। 'हर्ष' ने संगठन की भावना कुशल प्रशासन, सार्वजनिक हित, देश-विदेश के साथ पारस्परिक हित के हेतु सम्बन्ध और सम्पर्क स्थापन द्वारा आज की इस आवश्यकता पर बल डाला है।<sup>8</sup> शेरशाह कट्टर मुस्लिम युग का होते हुए भी हिन्दू-मुस्लिम एकता पर बल देता हुआ आज के जीवन में साम्प्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता को पुनः पुष्ट करता है। 'शशिगुप्त' में सिकन्दर सम्बन्धी ऐतिहासिक खोजों को चुनौतियाँ देते हुए भी उसके माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को फूँका है। 'कुलीनता' में राष्ट्रोद्धार की भावना

प्रमुख है।

वृन्दावनलाल वर्मा ने भी अनेक अच्छे चरित्रों की स्थापना की जिनमें 'ललित विक्रम' का ललित और कर्पिजल, 'झांसी की रानी' की 'रानी' तथा काश्मीर का कांय का ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह मुख्यतः स्मरणीय हैं। 'ललित विक्रम' जीवन में पुरुषार्थ की भावना को वैदिक काल से उठा आधुनिक काल में लाता है जहाँ आवश्यकता है देश को इस सत्य को आत्मसात् करने की, कि 'पुरुषार्थ दायें हाथ में हो, धर्म हृदय में हो तो विजय बायें हाथ में रहती है।'<sup>9</sup> कर्पिजल शूद्र होते हुए भी ऋषिपद का अधिकारी बनता है, यह तथ्य गांधी जी की कर्म में श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए आज वर्ण भेद के कारण बढ़ती हुई खाई को पाटने का भी सुन्दर प्रयास है। महादेवी वर्मा के शब्दों में 'हमारी संस्कृति-वाहिनी ऊपर से सम और शान्त है परन्तु उसके तल में अनेक ज्वालामुखियाँ जली बुझी हैं, असंख्य तूफान जागे सोये हैं। दर्शन, धर्म, साहित्य, कर्म सभी क्षेत्रों में विद्रोहियों की स्थिति रही है, पर तोड़ने वाले हथौड़े को मूर्तिकार की छेनी बना लेने की विशेषता हमारी अपनी है। इसी कारण विद्रोह ने हमारी जीवन-प्रतिमा को पूर्णता दी है। विद्रोही धौम्य ऋषि भावी पीढ़ी के शिल्पी हैं और विद्रोही रोमक वर्तमान है। उन दोनों के विद्रोह ने तत्कालीन रूढ़ जीवन को प्रशस्त क्षितिज देकर सफलता प्राप्त की। नाटक में भारतीय जीवन की मूलभूत विशेषताएँ सुरक्षित रह सकी हैं, इसका श्रेय नाटककार की सूक्ष्म परिलक्ष्य-बद्ध दृष्टि को दिया जाएगा।'<sup>10</sup>

ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से प्रेमी जी ने भी ऐसे चरित्रों की स्थापना की है जिससे राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। 'प्रेमी जी के इन चरित्रों में मूल-स्थापना प्रेरणा वर्तमान है। वर्तमान का निर्माण ही उनका उद्देश्य है, वर्तमान साध्य है, भूत साधन।'<sup>11</sup> 'इतिहास हमारा, भूत हमारा, बीता हुआ काल हमारे आज की बुनियाद है।.... बिना दृढ़ आधार के हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारी राष्ट्रीयता और हमारी मानवता खड़ी कैसे रह सकती हैं मैं तो अपने राष्ट्र के पैरों को इतिहास का बल देना चाहता हूँ।'<sup>12</sup>

'हम अभी स्वतन्त्र हुए हैं और हमें अपनी स्वाधीनता की रक्षा करनी है, इसलिए हमें अपना इतिहास इस दृष्टिकोण से भी पढ़ना है कि हम अपनी दुर्बलाओं को जान सकें जिसके कारण हम पराधीन हुए थे, ताकि भविष्य में हम उन भूलों को न दुहरावें।'<sup>13</sup> एक अन्य स्थान पर कहते हैं 'भारतीय इतिहास के उन कथानकों पर जिनसे इस विशाल देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की प्रेरणा प्राप्त हो, कुछ नाटक लिखने का प्रयास मैंने किया है।'<sup>14</sup>

इतिहास तो हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं- किस तरफ जाने में पतन है, किधर जाने में उत्थान- कहाँ मरण है, कहाँ जीवना।'<sup>15</sup> इन सभी के आधार पर प्रेमी जी की राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत दृष्टि स्पष्ट हो जाती है।

प्रेमी की कृति 'रक्षा बन्धन' हुमायूँ का जीवन सामाजिक एकता के प्रति समर्पित है वह कहता है 'हिन्दुस्तानी ही नहीं, इन्सान हैं, हमें उस दुनिया की हर किस्म की तब्दीली के खिलाफ जिहाद करना चाहिए हमारा काम भाई के गले पर छुरा चलाना नहीं, गले लगाना है।'<sup>16</sup> 'दारा' का चरित्र भी इसी प्रकार का है जहाँ नाटककार ने अपनी स्थापनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि दारा का जो स्वप्न था, वही कुछ परिष्कृत रूप में महात्मा गांधी का भी था। 'धर्म, जाति, सम्प्रदाय, देश और सामाजिक एवं राजनैतिक विचार धाआएँ और इसी प्रकार की अनेक बातें मानव को शत्रु बनाए हुए हैं .... मैं चाहता हूँ - हिन्दुस्तान ही नहीं सम्पूर्ण संसार स्वर्ग बन जाए।'<sup>17</sup> इसी प्रकार के स्वप्नों को लेकर नाटककार ने अनेकानेक चरित्रों की स्थापना की है। जिसमें उन्हें

समसामयिक जीवन का स्वर बुलन्द करने में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

उपर्युक्त विवेचन का सारांश यह है कि चरित्र-स्थापन का निर्वाह ऐतिहासिक नाटकों में अधिक हुआ है क्योंकि नाटककार की दृष्टि इतिहास के संरक्षण पर भी उतनी ही जमी है जितनी कि उसकी चरित्र-स्थापना एवं कथाचयन में अपेक्षित रही है। इन स्थापनाओं के माध्यम से समसामयिक जीवन स्वतंत्रता-आन्दोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति तथा उसके उपरान्त उत्पन्न समस्याएँ नाटकों में मूर्त हो पाई हैं। नाटककारों ने इस माध्यम से सृजक के दायित्व का कुशल निर्वाह किया है।

अतः कहा जा सकता है कि इस काल के नाटककारों ने बहुत ही कुशलता के साथ युगधर्मिता का निर्वाह किया है और समकालीन युग को नाट्य सीमा में बद्ध कर सजीव अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए सम्प्रेषणीय बनाया है जो निश्चित रूप से सार्थक एवं मूल्यवान है।

#### **सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-**

1. History of Indian National Congress- Pattabi Sita Ramya, Vol. II, p.15
2. आधुनिक साहित्य- नन्ददुलारे वाजपेयी, पृ० 21 भारती भण्डार इलाहाबाद, 2013 वि०।
3. "... We must be careful that an judgement depends not on whether the character life like but as whether they serve to embody experience which actor has shown to be a true." – Drama From ibsen to Eliet – Raynold

Williams, p.21

4. नाटक साहित्य का अध्ययन – ब्रेडर मैथ्यूज, पृ० 81 (अनु० इन्दुजा अवस्थी) आत्माराम एण्ड संस, संस्करण 1964
5. "All values of art depend upon the power of communication then making them wholly fell bresthing forcasts receipient. – Elements of Drama – J.L. Styan, p. 165
6. वितस्ता की लहरें – लक्ष्मीनारायण मिश्र, पृ० ग, द्वितीय संस्करण – 1957
7. वही, पृ० 123, द्वितीय संस्करण – 1957
8. हर्ष – सेठ गोविन्ददास – भारती साहित्य मंदिर, 1957
9. ललित विक्रम – वृन्दावनलाल वर्मा, पृ० 117, संस्करण 1958
10. ललित विक्रम – वृन्दावनलाल वर्मा (दो शब्द : महादेवी वर्मा, पृ० 1-2)
11. हिन्दी नाटककार – जगन्नाथ नलिन – पृ० 138
12. शतरंज के खिलाडी – हरिकृष्ण प्रेमी, भूमिका, संस्करण – 1955
13. संरक्षक – हरिकृष्ण प्रेमी, भूमिका, संस्करण – 1958
14. विदा – हरिकृष्ण प्रेमी, भूमिका, संस्करण – 1958
15. शपथ – हरिकृष्ण प्रेमी, भूमिका, संस्करण – 1951
16. रक्षाबन्धन – हरिकृष्ण प्रेमी, भूमिका, संस्करण – 1940
17. स्वप्न भंग – हरिकृष्ण प्रेमी।

\*\*\*\*\*

## रणकपुर-पर्यटन स्थल : एक भौगोलिक अध्ययन

डॉ. उममेद कुमार चौधरी\*

**प्रस्तावना** – भारत अपनी विविध जलवायु विशेषताओं और संस्कृतियों के लिए हर साल बड़ी संख्या में आगंतुकों के साथ दुनिया का आशाजनक पर्यटक स्थल बन गया है। पिछले दो दशकों में पर्यटन का नाटकीय विकास हुआ, यह सबसे उल्लेखनीय आर्थिक परिवर्तनों में से एक है।

भारत में पर्यटन अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। भारत अपनी भौगोलिक विविधता, समृद्ध इतिहास एवं संस्कृति इसकी सुंदरता हर साल दुनिया के कोने कोने से पर्यटकों को आकर्षित करती है। ऐतिहासिक व आध्यात्मिक पर्यटन के विश्व प्रसिद्ध स्थानों जैसे महलों, मंदिर, दुर्ग, किलों से लेकर गुफाओं और शिल्पकला तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक विश्व की सबसे उंची पर्वत चोटियों से लेकर मैदानों तक, इसके सबसे शुष्क स्थान, सबसे आर्द्र स्थान एवं सबसे गर्म और सबसे ठण्डे हिस्सों तक, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक विशाल व सुन्दर समुद्री तट, विशाल रेगिस्तानी भाग और भारतीयों की विविध संस्कृति परम्पराएं, रिति-रिवाज, मेले त्यौहार आदि दुनिया के लोगों के लिए भारत में पर्यटन की यात्रा का कारण प्रदान करता है। भारत के आर्थिक विकास और समग्र विकास के साथ पर्यटन का मजबूत संबंध है। यह न केवल देश के सकल घरेलू उत्पादन और विदेशी मूद्रा में महत्वपूर्ण योगदान देता है, बल्कि देश की आर्थिक सृद्धि और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में न केवल देश में अपितु विश्व पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से जाना जाता है। इसकी शानदार विरासत, ऐतिहासिक गौरव गाथा, रंगीन जीवित परम्पराएं और जीवंत संस्कृति, तीर्थ स्थल, प्राकृतिक सौन्दर्य, वन्य जीव अभ्यारण्य आदि घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। राज्य के मूर्त और अमूर्त पर्यटन उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं प्रदान करते हैं, अतः पर्यटन संसाधनों का विकास एवं बुनियादी सुविधाओं का विस्तार राज्य सरकार के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है।

**अध्ययन क्षेत्र** – रणकपुर राजस्थान राज्य के पाली जिले में सादड़ी शहर के समीप जोधपुर मार्ग प 25° 6' 27" उत्तरी अक्षांश से 78° 28' 21" पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यह अरावली पर्वत की घाटियों के बीच चारों ओर अपार प्राकृतिक सुंदरता से घिरा ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल है। जहां प्रकृति को निहारने और मन की शांति के लिए प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक यहां पहुंचते हैं। रणकपुर प्राचीन काल से (15वीं सदी) से ही पर्यटकों का आकर्षण केन्द्र रहा है। यहां प्रमुख पर्यटक स्थलों में भगवान ऋषभदेव का चतुर्मुखी मंदिर, सूर्य मंदिर, शक्ति माता मंदिर, नलवानिया बांध, रणकपुर बांध, इसके अलावा जंगल सफारी राज्य सरकार द्वारा आयोजित रणकपुर महोत्सव आदि।

**शोध विधि तंत्र** – रणकपुर पर्यटन स्थल के अध्ययन हेतु अवलोकन व वर्णनात्मक विधियों का उपयोग किया गया है, इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित सूचना ब्रोशर, समाचार पत्र, अन्य दस्तावेज एवं पर्यटन विभाग की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट 2013, 2016, 2020 में प्रकाशित द्वितीय सामग्री को उपयोग में लिया गया है।

**शोध के उद्देश्य** – प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य मानव समाज के लिए आर्थिक एवं सामाजिक लाभ प्राप्त कर रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आय का सृजन, राजस्व की प्राप्ति विदेशी विनिमय प्राप्त करना है। प्रस्तुत शोध के उद्देश्य इस प्रकार हैं।

1. पर्यटन क्षेत्र के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन करना।
2. पर्यटन की दृष्टि से अछूते ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सुरुष्य प्राकृतिक स्थलों में पर्यटन की नई संभावनाओं का पता करना।
3. पर्यटन स्थल पर आने वाले घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों से पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।

**प्रस्तुत शोध कार्य की चर्चा** – रणकपुर प्राचीन काल से ही पर्यटन का आकर्षण केन्द्र रहा है, यहां के प्रमुख पर्यटन स्थलों में भगवान ऋषभदेव का चतुर्मुखी जैन मंदिर, सूर्य मंदिर, नलवानिया बांध, रणकपुर बांध प्रमुख हैं। इसके अलावा जंगल सफारी व राज्य सरकार द्वारा आयोजित रणकपुर महोत्सव आदि।

**रणकपुर जैन मंदिर** – राजस्थान में अरावली पर्वत की घाटियों के मध्य चारों ओर जंगलों से घिरे रणकपुर में भगवान ऋषभदेव का चतुर्मुखी जैन मंदिर है। भारत के जैन मंदिरों में शिल्प एवं विशालता की दृष्टि से सम्भवतः इसकी इमारत सबसे भव्य एवं विशाल है। यह गोडवाड़ के जैन पंचतीर्थों में प्रमुख माना जाता है। इसका निर्माण आज से करीब 600 वर्ष पूर्व महाराणा कुम्भा के काल में सेठ धरणशाह ने संवत् 1446 ई. में प्रसिद्ध शिल्प विशेषज्ञ 'देपा' की देखरेख में करवाया था। सेठ धरणशाह ने कुम्भलगढ़ से मालगढ़ जाने वाले रास्ते में मादड़ीपर्वत की छाया में बसे मादड़ी गांव को मंदिर निर्माण स्थल हेतु चुना, बाद में धरणशाह ने मादड़ी गांव का नाम बदलकर रणकपुर कर दिया। रणकपुर के इस चौमुखा मंदिर की इमारत का निर्माण लगभग 48000 वर्गफीट जमीन पर किया गया, जिसमें कुल 24 मण्डप, 84 शिखर और 1444 स्तम्भ हैं। इस मंदिर में चार कलात्मक प्रवेश द्वार हैं, मंदिर के मुख्य गृह में तीर्थंकर आदिनाथ की संगमरमर से बनी चार विशाल मूर्तियां हैं, करीब 72 इंच उंची ये मूर्तियां चार अलग अलग दिशाओं की ओर उन्मुख हैं। इसी कारण इसे चतुर्मुख मंदिर कहा जाता है। मुख्य मंदिर के चारों तरफ उत्कीर्ण मूर्तियों में जनजीवन की झांकियां दिखाई देती हैं, उंचे तोरणद्वार, सभामंडप गर्भ गृह, देवकुलिकाय, विभिन्न मुद्राओं में उत्कीर्ण नृत्यांगनाएं

संगीत के विभिन्न वाद्य प्राकृतिक दृश्यावलिया, पौराणिक दृश्य समकालीन वेशभूषा आभूषण आदि अत्यंत सुंदरता के साथ प्रस्तुत किए गए हैं।

**सूर्य मंदिर** – यह जैन मंदिर के पास ही स्थित है, जिसे सूर्य नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नागारा शैली में सफेद चूने पत्थर से सूक्ष्म आभूषणों का काम किया गया है। 13वीं सदी में बने इस मंदिर के ध्वस्त होने के बाद 15वीं शताब्दी में इसका पुर्ननिर्माण किया गया। सूर्य मंदिर का मुख पूर्व दिशा की ओर है, जिसमें भगवान सूर्य की रथ पर सवार मूर्ति दिखाई गई है, मंदिर की दीवारों पर योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्गीय पिंडों की अदभुत नक्काशी हुई है, जो विगत युग के लोगों की कलात्मक उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करती है। मंदिर के गर्भ गृह से पहले एक अष्टकोणीय मण्डप है, जिसमें छः बरामदे हैं, सूर्य मंदिर का प्रबंधन उदयपुर के शाही परिवार ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

**शक्ति माता मंदिर** – यह मंदिर रणकपुर व नलवानिया बांध के किनारे पर स्थित हैं, चारों ओर अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों के बीच मंदिर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। नवरात्रि के दिनों में यहां अच्छी खासी भीड़ व चहल पहल रहती है। सड़क के दोनों ओर हरियाली होने से यहां 'साइकिल ट्रेनिंग' का भी पर्यटक आनंद लेते हैं।

**रणकपुर बांध** – मघाई नदी पर बना रणकपुर बांध (सादडी बांध) पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। इस बांध का निर्माण जोधपुर रियासत के महाराजा सर प्रतापसिंह ने वर्ष 1942-48 में अरावली पर्वतमाला की तलहटी में करीब छः महाड़ियों को मिलाकर बनाया था। यह बांध सागरतल से 221 मीटर कि उच्चाई पर बना है, इसकी भराव क्षमता 62.70 फीट (205 MCFT) है। इस बांध पर शाम के समय सूर्यास्त का दृश्य प्राकृतिक सुंदरता के साथ पर्यटकों को आकर्षित करता है।

**नलवानिया बांध** – रणकपुर बांध के निकट ही नलवानिया बांध बना हुआ है, इसका निर्माण राज्य सरकार द्वारा 1979-83 में किया गया, 20.74 हेक्टेयर में फैले इस बांध की कुल भराव क्षमता 14.40 (50 MCFT) है। नलवानिया बांध पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है, बांध की पाल पर मंच व पर्यटकों के बैठने के लिए स्थान बना है। यहां प्रतिवर्ष रणकपुर महोत्सव (फेस्टिवल) में 'दीपदान' कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

**रणकपुर महोत्सव** – पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित रणकपुर उत्सव राजस्थान के सबसे लोकप्रिय पर्वों में से एक है। आमतौर पर यह हर वर्ष 21 और 22 दिसंबर को आयोजित त्योहार स्थानीय संस्कृति और विरासत का सुंदर परिचय देता है। रोचक गतिविधियां जैसे योग, अरावली पर्वतमाला के जंगलों में प्रकृति की सैर पर चलना, रणकपुर जैन मंदिर के दर्शन हॉट एयर बैलून की सवारी, दिलचस्प गतिविधियों जैसे – टंग ऑफ वॉर, शानदार सज्जा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सूर्य मंदिर में ओपन एयर एमपिथियेटर में प्रत्येक शाम आकर्षण लोक और शास्त्रीय प्रस्तुतिकरण और भी बहुत कुछ रणकपुर महोत्सव ऐसा रोमांच है जिसे लोग कभी भूला नहीं सकते हैं।

**सारणी - 01 रणकपुर आये देशी विदेशी पर्यटकों का विवरण 2010-2019 (पर्यटकों की संख्या लाखों में)**

क्र.	वर्ष	रणकपुर में आये देशी पर्यटक	रणकपुर में आये विदेशी पर्यटक	राज्य में आये देशी पर्यटक	राज्य में आये विदेशी पर्यटक
1	2010	6.14	1.07	25.54	12.78
2	2011	5.73	1.07	27.13	13.51

3	2012	6.16	1.10	28.61	14.51
4	2013	5.73	9.37	30.29	14.37
5	2014	5.56	1.22	33.07	15.25
6	2015	5.32	1.02	35.18	14.75
7	2016	5.25	1.14	41.49	15.13
8	2017	4.94	1.05	45.91	16.09
9	2018	4.93	1.17	50.23	17.54
10	2019	4.58	1.05	52.22	16.05

सारणी 01 में वर्ष 2010 से 2019 तक रणकपुर आने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटकों के आंकड़ों को दिखाया गया है, जैसा की ऊपर दी गई सारणी से पता चलता है कि वर्ष 2010 से 2019 तक घरेलू पर्यटकों का आगमन 614 लाख से घटकर 458 लाख हो गया और विदेशी पर्यटकों का भी उतार चढ़ाव रहा है। वर्ष 2010 में जहां विदेशी पर्यटकों की संख्या 107 लाख थी, और इसमें वर्ष 2012, 2014, 2016, 2018 में बढ़ोतरी हुई, बाकी के वर्ष में पर्यटकों के आगमन में निरंतर कमी देखने को मिली।

सारणी 01 के आंकड़ों से पता चलता है कि जहां राजस्थान राज्य में वर्ष 2010 से 2019 तक घरेलू व विदेशी पर्यटकों के आगमन में निरंतर वृद्धि देखने को मिली, इसके विपरीत रणकपुर में पर्यटकों के आगमन में गिरावट के रुझान का पता चलता है, इसका प्रमुख कारण पर्यटक स्थल पर पर्यटकों के आवागमन की उत्तम परिवहन सुविधा का अभाव, पर्यटकों के ठहरने की दरों का अधिक होना, घरेलू और विदेशी पर्यटकों को बढ़ाने के लिए सरकारी प्रयासों में कमी प्रमुख कारण है।

सारणी 01 के आंकड़ों से पता चलता है कि पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकारी और स्थानीय प्रशासन व लोगों को पहल करने की बहुत आवश्यकता है। जिससे सरकारी राजस्व बड़े स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हो और पर्यटन हेतु बुनियादी सुविधाओं व ढांचे का विकास हो सके।

**पर्यावरणीय प्रभाव** – पर्यावरण में केवल प्राकृतिक घटक ही सम्मिलित नहीं हैं बल्कि मानव निर्मित उसकी कृतियां समाज अर्थव्यवस्था संस्कृति आदि सभी समाहित होते हैं। इस तरह पर्यावरण एवं पर्यटन में घनिष्ठ अंतर्संबंध पाया जाता है, प्रकृति तथा मानव कृति निर्माण पर ही पर्यटन आधारित है। इसी से किसी स्थान विशेष पर पर्यटन का विकास होता है, साथ ही मानव एवं प्रकृति निर्मित आकर्षण को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र द्वारा संरक्षण के व्यापक एवं सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया जाता है। पर्यटन स्थल पर होटलों का निर्माण, भौतिक सुख सुविधाओं के विकास के दौरान स्थानीय वनस्पति, जीव जंतुओं, मृदा, वायु, जल आदि के पारिस्थिकी में परिवर्तन होने लगता है यदि हम अध्ययन क्षेत्र की बात करें तो वहां पर्यटन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव निष्कर्ष इस तरह देखा गया है।

1. पहले से स्थापित अच्छी प्राकृतिक दशाओं में बदलाव आया है मुख्य रूप से होटलों के निर्माण परिवहन मार्गों के विकास के कारण वहां प्राकृतिक भू दृश्य व भूमि उपयोग में स्वाभाविक परिवर्तन आया है।
2. रणकपुर पर्यटन स्थल सुरक्षित वन क्षेत्र में स्थित है जहां विभिन्न प्रजातियों की प्राकृतिक वनस्पति व वन्यजीवों का आवास स्थल है यहां पर पर्यटकों के आवागमन, परिवहन साधनों, जंगल सफारी, महोत्सव आदि के कारण जीव जंतुओं के जीवन में व्यवधान पैदा हुआ।
3. पर्यटन क्षेत्र में पर्यटकों द्वारा ले जाए जाने वाले सामान के अंतर्गत



पॉलीथिन कागज आदि के रूप में विभिन्न सामानों को छोड़कर जाने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप स्थान विशेष पर कचरे आदि की समस्या भी पैदा हो रही है।

4. होटलों का सीवरेज, डिस्पोजल, आवागमन के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के धुएं से भी वातावरण में प्रदूषण पैदा हो रहा है।
5. पर्यटक पर्यटन नियमों की अवहेलना कर वन्यजीवों के आवास स्थल तथा विचरण क्षेत्र में व्यवधान पैदा करते हैं, इससे धीरे-धीरे स्थान विशेष पर जंगली जीव जंतुओं के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न खड़ा होने लगा है।

#### **समस्याएं:**

1. राज्य के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों की तुलना में विशेष रूप से पहिचान और बेहतर संचार के साधनों का अभाव है, अधिकांश सार्वजनिक परिवहन हैं। रेलमार्ग का अभाव, सड़के बहुत खराब स्थिति में हैं, दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
2. दूरसंचार के बुनियादी ढांचे का अभाव है, सीमित इंटरनेट पहुंच और अंतरराष्ट्रीय कॉलिंग की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
3. आवास व ठहरने की सुविधा का अभाव विशेष रूप से स्थानीय पर्यटक को हेतु उत्तम वह सस्ते सुविधाजनक आवास का अभाव है।
4. प्रायः यह देखा गया है कि विदेशी पर्यटक विशेष रूप से प्राचीन वस्तुओं कलात्मक वस्तुओं और दैनिक उपयोग की चीजों से आकर्षित होते हैं, जैसे राजस्थानी वस्त्र पहनने, हस्तशिल्प वस्तुओं आदि इनका पूर्ण अभाव देखने को मिलता है।
5. प्राकृतिक संपदा व भूदृश्य में आवश्यक परिवर्तन होटलों सीवरेज डिस्पोजल पॉलिथिन कचरे आदि की समस्या।
6. वन्यजीवों के आवास में व्यवधान से उनके प्राकृतिक विचरण में समस्या पैदा हो रही है।
7. उच्च शिक्षित प्रशिक्षित कुशल टूरिस्ट गाइड का अभाव है।

**सुझाव** – उपरोक्त समस्याओं से उबरने और पर्यटकों के प्रवाह को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि पर्यटन विभाग व स्थानीय प्रशासन पर्यटन सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास करें। जिससे परिवहन और ठहरने की सुविधाओं के लिए उपर्युक्त रणनीति तैयार कर सकें।

1. पर्यटकों के आकर्षण हेतु रणकपुर बांध नलवानिया बांध व शक्ति माता मंदिर परिसर में पार्क स्थलों का विकास किया जाए।
2. रणकपुर बांध में बोट संचालन की अनुमति प्रदान करें जिससे पर्यटकों का आकर्षण बढ़े।

3. अजायबघर/चिड़ियाघर की स्थापना की जाए।
4. सड़क परिवहन का आधुनिकीकरण किया जाये।
5. होटल उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए इसके लिए सरकार को स्थानीय पर्यटकों हेतु छोटे आकर के व सस्ते होटल और लॉज के निर्माण के लिए सरकार को उपर्युक्त भूमि वित्तीय सहायता और अन्य सब्सिडी आवंटित करनी चाहिए।
6. उच्च शिक्षित प्रशिक्षित गाइड नियुक्त करें ताकि अपने पैसे के मापदंडों का पालन करें और पर्यटन क्षेत्र की प्राकृतिक व सांस्कृतिक जानकारीयों सही उपलब्ध करा सके ताकि पर्यटक आकर्षित हो सके।
7. प्राकृतिक भूदृश्य संपदा में अनावश्यक परिवर्तन से बचा जाए।
8. होटलों की सीवरेज डिस्पोजल तथा पॉलिथिन कचरे के लिए राष्ट्रीय हेरिटेज के स्वस्थ मानकों को अपनाया जाए वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नियमों को लागू किया जाए।
9. वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास स्थलों में पर्यटकों के अनावश्यक विचरण को प्रतिबंधित किया जाए।

#### **संदर्भ ग्रंथ सूची:-**

1. डॉ. सूरेश चंद्र बंसल (2016-17) पर्यटन भूगोल एवं यात्रा प्रबंधन, मीनाक्षी प्रकाशन मेरठा।
2. डॉ. राजेश कुमार व्यास (2011) सांस्कृतिक पर्यटन, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर।
3. डॉ. राजेश कुमार व्यास (2013) पर्यटन उद्वेग एवं विकास, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर।
4. डॉ. मोहन लाल गुप्ता (2011) जोधपुर संभाग का जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, राजस्थानी ग्रंथाकार जोधपुर।
5. Dr. Laveena T. Dharmwani– Tourism in Rajasthan : challenges and opportunities, (University of Kota)
6. Dr. MD. Mahmood Alam– Tourism in rajasthan contrubution in it's economy, (Associate Professor of Economic D.S. College Aligarh)
7. M.S. Ranjana Tiwari– Sustainable rural development through tourism practices : A case of Ranakpur Rajasthan, (Research Scholer MLSU Udaipur)
8. Study on 20 year perspective plan for sustainable touism in Rajasthan – Ministry of tourism art and culture Govt. of India.
9. समाचार पत्र दैनिक भास्कर 17 अक्टूबर, 2020
10. वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट (2013, 2016, 2020), पर्यटन विभाग जयपुर राजस्थान।

\*\*\*\*\*

# Physical Education Facility in Secondary Schools of Rajasthan

Pawan Kumar Regar\* Dr. B. S. Chauhan\*\*

**Introduction** - Education, in the broad sense, means preparation for life, it aims at all round development of individuals. Thus education is concerned with developing optimum organic health and emotional vitality such as social consciousness, acquisition of knowledge, wholesome attitude, moral and spiritual qualities. Civilized societies have always felt the need for physical education for its members except during the middle ages, when physical education as is typically known today found almost no place within the meagre educational pattern that prevailed. The rapid development of physical education within the present century and the weighted influence accruing to some of its more spectacular activities suggest the imperative need, a clean understanding of unequal role, a well-balanced programme in the field may give rise to the optimum growth and development of the youth. Dissolution of the dichotomy of mind and body, and acceptance of the individual as a unified and respected personality, belong to an evolution of physical education that has used this programme to serve military ends as an instrument for the relief of tensions associated with academic pursuits and finally leading to the essential medium of complete development.

**Objectives and Methodology** - The present paper examines the physical education facilities in Secondary School of Rajasthan. For the fulfilling research objective, research work presented is mainly based on primary information. Primary information was collected from selected 20 schools across the State in respect of sports facilities available in secondary in the State of Rajasthan. This research work is analytical in the sports facilities available in secondary schools in the State. For this, information relating to physical education facilities from secondary schools of the State has been compiled. The analysed information are presented in tables and graphs.

**Discussion** - This part is based on result of analysis of collected information through five statements on physical education facilities in secondary schools govt. and private. The collected information analysed through the number and percentage. The analysed information represented in tables and diagrams.

**Table 1 : Availability of Physical Education Facility in Sec. School Govt. and Private**

S.	Statement	Responses in percentage	
		Govt.	Private
1	Availability of Athletic track in School	55.00	30.00
2	Availability of Kabaddi court in School	80.00	65.00
3	Availability of Kho-Kho field	80.00	50.00
4	Availability of sports infrastructure development committee in school	60.00	40.00
5	Availability Physical Education teacher	90.00	50.00

**Figure: 1 (See in next page)**

From the perusal of the table and diagram, it is clear that the availability of physical education facility has been indicated in selected Government Secondary Schools and Private Secondary Schools from the study area. From the perusal of the data, it is clear that athletic track is available only in 55 percent Government Secondary Schools and 30 percent private secondary schools. The Kabaddi Courts is plays an important role in a school for the physical education so information also collected and analysed. According to data represented in table that the availability of Kabaddi Courts in 80 percent Government Secondary Schools and 65 percent Private Secondary Schools. Likewise kho-kho field also play a significant role in physical education. The study show that in 80 percent government secondary schools and 50 percent private secondary schools have kho-kho field is available. In any school sports infrastructure development committee playing the important role for the development of sport facility in the school. The data shown in table and graph indicated that there is 60 percent government secondary schools and 40 percent private secondary schools has sports infrastructure development committee is available. From the perusal of the data, it is clear that physical education teacher is available in 90 percent government secondary schools and 50 percent private secondary schools.

**Conclusion**- Analysis shows that the Govt. Schools have higher Physical education facility comparatively private schools at secondary level in terms of availability of all physical education facility. Comparatively speaking, the facility of physical education is more in government secondary schools as compared to private secondary

\*Research Scholar (Physical Education) MLSU, Udaipur (Raj.) INDIA

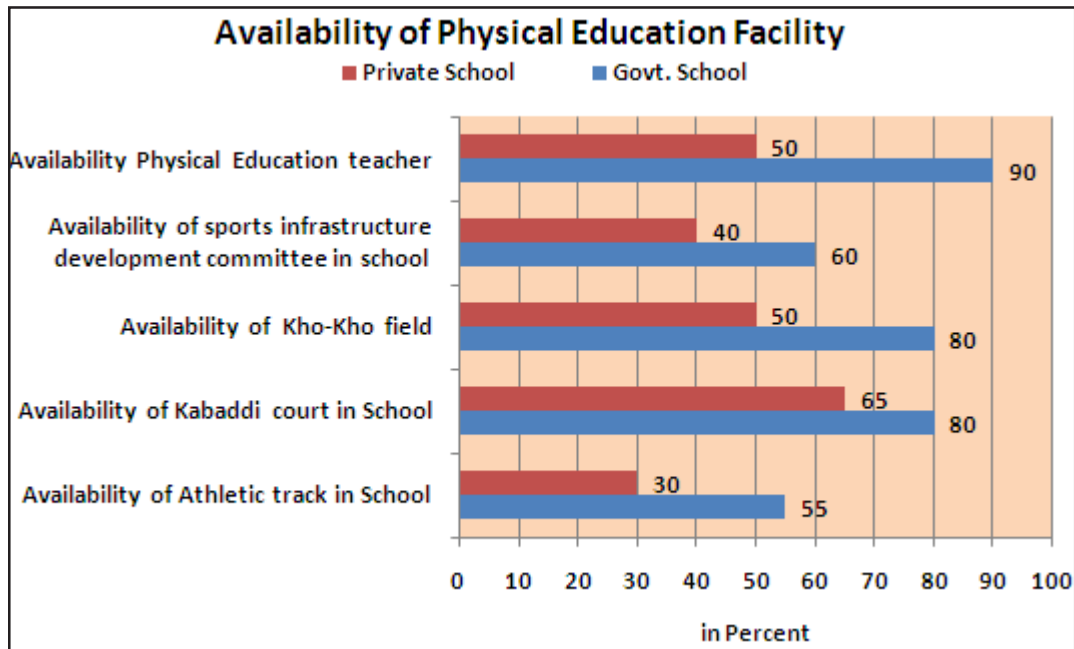
\*\* Principal, B.N. College of Physical Education, Udaipur (Raj.) INDIA

schools in selected schools.

**References:-**

1. Bhukar J.P. (2012), Survey Of Sports Facilities In Rajasthan State Universities, International Journal of Behavioral Social and Movement Sciences Vol. 01, Jan 2012, Issue 01
2. Dabas Chandra Sarkar”The survey of facilities and equipments of sports in engineering colleges in West Bengal”, (Unpublished Master’s Thesis, Jiwaji University, 1982).
3. J. P. Bhukar, “Survey of Sports Facilities In Rajasthan State Universities”, International Journal of Behavioral Social and Movement Sciences, Vol.01, (Jan2012), Issue 01.

**Figure: 1**



\*\*\*\*\*

## वैश्वीकरण का भारतीय सभ्यता व संस्कृति पर प्रभाव

डॉ. विनीता मिश्रा \*

**प्रस्तावना** – आज का युग वैश्वीकरण का युग है वैश्वीकरण भूमंडलीकरण को सामान्य अर्थ में परिभाषित किया जाए तो कहा जा सकता है कि समस्त संसार का एक साथ एक मंच पर इकट्ठा होना है। इस प्रक्रिया में समस्त देश परस्पर निर्भर हो जाते हैं और बीच की दूरियां सिमट जाती हैं। यदि आज के संदर्भ में कहा जाए तो इतनी विसंगतियों के बावजूद भी वैश्वीकरण एक अनिवार्य शर्त बन गया है और इसी वैश्वीकरण के प्रभाव को हम ग्लोबल संस्कृति की संज्ञा प्रदान कर सकते हैं। वैश्वीकरण को समझने के लिए उसके उद्भव को समझना आवश्यक है, 1970 के दशक के मध्य में दुनिया में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा शुरू हुई इसके साथ ही राष्ट्रीय सीमाओं को आर्थिक आधार पर परिभाषित करने की परंपरा प्रारंभ हुई इसे भूमंडलीकरण का नाम दिया गया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिसमें दुनिया के सभी देश एक दूसरे से राजनैतिक व सांस्कृतिक रूप से जुड़े होते हैं जिससे विश्व में एकरूपता तथा क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति बढ़ती है परंतु मुख्य तौर पर आर्थिक गतिविधियां ही विद्यमान रहती हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव को जानने के लिए संस्कृति को परिभाषित करना आवश्यक हो जाता है।

संस्कृति एक मूलतः किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र रूप का नाम है जो तत्कालीन समाज के सोचने, विचार करने के स्वरूप में अंतर निहित होती है इसी प्रकार संस्कृति के चार अध्याय में रामधारी सिंह दिनकर ही लिखते हैं कि संसार भर में जो सर्वोत्तम बातें जानी या कही गई हैं उनसे अपने आपको परिचित करना संस्कृति है यह मानसिक व शारीरिक शक्तियों का प्रशिक्षण है, यह विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है, यह सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो जाना है। आगबर्ने व निमकाफ ने अपनी संस्कृति के दो प्रकारों की चर्चा की उनके अनुसार अभौतिक संस्कृति सामाजीकरण एवं सीखने की प्रक्रिया द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है, इसका कोई मूर्त रूप नहीं होता जबकि भौतिक संस्कृति मापी जा सकती है इसका मूर्त रूप होता है, इसके उपयोग व उपयोगिता का और लाभ का मूल्यांकन किया जा सकता है। इस प्रकार हम भौतिक संस्कृति को सभ्यता का भी नाम दे सकते हैं। सभ्यता व संस्कृति एक दूसरे के पूरक होते हैं, सभ्यता शरीर है तो संस्कृति उसकी आत्मा है। भारतीय संस्कृति को दृष्टिगत रखते हुए यदि वैश्वीकरण की अवधारणा पर विचार करें तो हमारी प्राचीनतम संस्कृति में ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना विद्यमान है। यजुर्वेद में लिखा गया है संघे शक्ति कलियुगे अर्थात् सामूहिक शक्ति पर विश्वास जताया गया है। इसी प्रकार भक्तिकाल में कबीर, तुलसी, ज्ञानेश्वर भी विश्व की समस्त मानव जाति के लोक मंगल की बात को ही स्पष्ट करते हैं। इस भावना में भी वैश्वीकरण या संपूर्ण पृथ्वी को एक गांव

की तरह या एक परिवार की तरह माना गया है। गांधी जी ने भी कहा कि हर तरफ से खिड़कियों को खुली रखना चाहिए ना जाने किस रूप में नए विचार अंदर प्रवेश कर जाएं। यह विचार अध्यात्म के धरातल को आधार मानकर सोचे गए थे जिसमें मानवीय प्रेम मानवता को ही एक मात्र स्थान दिया गया।

17 वीं शताब्दी में पुर्तगाल का बड़े पैमाने पर अफ्रीका व भारतीय तटों पर विस्तार वैश्वीकरण का पहला प्रमुख व्यापार था। 17 वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी पहला बहुराष्ट्रीय निगम था। यहीं से धीरे-धीरे उपनिवेशवाद फलने फूलने लगा जिसने हमारी संस्कृतियों को प्रभावित किया 19वीं शताब्दी को कभी-कभी वैश्वीकरण का प्रथम चरण भी कहा जा सकता है जिसका नेतृत्व इंग्लैंड ने दक्षिण एशिया में अपनी उपनिवेशवादी नीति को विस्तार करके किया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वैश्वीकरण का दूसरा दौर प्रारंभ हुआ जिसमें हिरोशिमा नागासाकी में बम वर्षा के पश्चात मानव अधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ एवं संस्थाओं की स्थापना हुई। इसी के पश्चात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1960 में कनाडा साहित्य के आलोचक मार्शल लोहान ने वैश्विक ग्राम शब्द को लोकप्रिय बनाया और भारत भी इस महत्वपूर्ण ग्राम का सदस्य बन गया।

21 वीं शताब्दी तक आते-आते इंग्लैंड के जॉन किन्स व अमेरिका के जॉन व्हाइटन ने युक्ति निकाली जिसे उदारीकरण कहा गया। भूमंडलीकरण का मुख्य आशय आर्थिक गतिविधियों पर केंद्रित हो गया। इसीलिए इसे दो भागों में बांट कर देखा जा सकता है पहला उदारीकरण दूसरा निजीकरण। उदारीकरण का अर्थ है एक ऐसी आर्थिक नीति जिसमें जिसमें देश के अंदर ऐसा वातावरण स्थापित हो जिससे उद्योग धंधों का उत्पादन व्यवसाय व वाणिज्य में कोई बाधा ना उपस्थित हो। उदारीकरण नई औद्योगिक नीति का परिणाम है जो लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर देता है। इसी के साथ निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्रीय उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सकता है जिससे वह सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो जाएं।

वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य आर्थिक पहलू होते हुए भी इसने हमारे जीवन के सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक पहलुओं को विशेष रूप से प्रभावित किया है जिसके सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणाम उभर कर सामने आने लगे। नई सूचना तकनीक अंतरराष्ट्रीय सहायता केंद्र मानवाधिकार आयोग यूरोपीय संघ कॉमर्स को बढ़ावा मिला जिसमें व्यापार और वाणिज्य को सरल बना दिया गया। वैश्वीकरण ने कुछ अधिक कुशल कारीगरों को अधिक अवसर प्रदान किये हैं। रामशरण शर्मा लिखते हैं कि दूरसंचार प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है तब श्वेत देशों से यह उम्मीद कैसे न की जाये की वह अपने उत्पादों का प्रचार नहीं करेंगे। भूमंडलीकरण



के आर्थिक प्रभाव पर विवेचना करें तो संशयवादी वैश्वीकरण को मिथक मानते हैं। 19वीं शताब्दी में व्यापार में अधिक तेजी से राज्यों के एकीकरण का आर्थिक महत्व देते हुए इनका मानना है कि बाजार शासन नहीं करता बल्कि बाजार के नियमन का कार्य शासन करता है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो सकल घरेलू उत्पाद और सेवा क्षेत्र की बढ़ती देख भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित देशों की अर्थव्यवस्था प्रतीत होती है। परंतु, वैश्वीकरण के 20 साल बाद भी रोजगार के अवसर, किसानों की गरीबी, वह पूंजीनिर्माण आदि से निजात नहीं मिली। इन्होंने कमियों पर ध्यान आकर्षित करते हुए जॉर्ज सोरस ने लिखा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठित लोकतंत्र की बजाय निरंकुश शासन व्यवस्था को अधिक प्राथमिकता देता है इसीलिए इसका प्रभाव विपरीत पड़ सकता है, इसी प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों भी सार्वजनिक व्यय में प्राथमिकता देने तथा अल्प विकसित देशों की समस्याओं में सुधार करने की बजाय प्रबंधक वर्ग एवं वर्ग विशेष के कर्मचारियों को अधिक महत्व देती हैं।

वैश्वीकरण में भारत की जब बात आए तो यह जरूर जोड़ सकते हैं कि जैसे - जैसे सांस्कृतिक वैश्वीकरण हुआ उससे आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा मिला और 1991 के बाद हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारतीय दूरदर्शन मीडिया सबसे सुरक्षित मंच मिल गया जिसमें अंतरराष्ट्रीय विज्ञापनों की होड़ होती थी। उदारीकरण संस्कृति में बाजार को बढ़ावा मिला व भारत में माल संस्कृति को बढ़ावा मिला इससे रोजगार के अवसर तो उपलब्ध हुए परंतु दूसरी ओर छोटे व्यापारी दुकानदारों के व्यापारिक व्यवसाय पर प्रश्न चिन्ह लग गया। मॉल संस्कृति ने मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं के शौक को जरूरत में बदल दिया। भारतीय संस्कृति के अनुसार यदि कहा जाए तो उसके केंद्र में सबसे पहले नागरिक होता है परंतु वैश्वीकरण के प्रभाव में नागरिक को भूमंडलीय उपभोक्ता बना दिया इसमें उपभोक्ता पर नई सत्ता थोपी जा रही है। आशीष नंदी कहते हैं कि संस्कृति अपने आप में प्रतिरोध का दूसरा रूप है इसीलिए संस्कृति को वैसे ही साफ रखना चाहिए जैसे प्राणवायु को स्वच्छ रखा जाता है। हमारा पैर भूमंडलीय आंधी में टिक नहीं पा रहा है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज आए दिन कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र में किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं और कृषि क्षेत्रों में कूटनीतिक तंत्रों का जाल बनता जा रहा है।

भूमंडलीयकरण का अमानवीय चेहरा रोजगार के क्षेत्र में स्पष्ट दिखाई देता है, इनका श्रम से कोई भावनात्मक लगाव नहीं होता, कारपोरेट जगत हायर और फायर की संकल्पना पर कार्य करता है जिससे वहां के कर्मचारी अपने रोजगार के भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना से पीड़ित रहते हैं।

वैश्वीकरण ने मानव जीवन में आधुनिकता लाने का प्रयास किया। बाजार में आई हर वस्तु अब मनुष्य को पसंद आने लगी है, उपभोक्तावाद ने चका चौंधि भरी दुनिया व रंग बिरंगे दृश्य प्रस्तुत किए हैं। आधुनिकता बहुआयामी हो गई, इस आधुनिकता के दो पहलू थे विकास व विनाश, जो इन दोनों में सामानजिक बैठा ले गया वह वैश्विक दुनिया में नई उंचाइयों को छू लेगा। वैश्वीकरण से भारतीय समाज में दो धाराएं चलती हुई नजर आ रही हैं, एक धारा में भू-उपग्रह, कंप्यूटर, पांच सितारा होटल, पिज़्ज़ा हट, हवाई जहाज, यातायात और इनसे जुड़ी आकांक्षाएं हैं तो दूसरी तरफ आजीविका व रोजमर्रा का जीवन जीने की समस्या और रैन बसेरे की तलाश अर्थात् मजदूरों व गरीबों को अपनी आवश्यकताओं के लिए भी रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। कंप्यूटर ने श्रम की उपेक्षा की है और साथ ही इसने कला कौशल को भी बर्बाद कर दिया, खानदानी हस्तशिल्प बेकार हो

गए हैं उनकी कीमत कम हो गई या उचित पारिश्रमिक ना मिलने से कलाकार मजदूरी करने के लिए विवश होने लगे हैं।

आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी आतंकवादी व अलगाववादी संगठन फल फूल रहे हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं कारण वैश्वीकरण ही है। वैश्वीकरण की चकाचौंध भरी दुनिया और निजीकरण के कारण रोजगार के अवसर नहीं मिलते, जिससे मोटी तनखाह की लालच में युवा आतंकवाद की ओर मुड़ने लगा है, तथा सम्पूर्ण विश्व में आतंकवाद वैश्विक समस्या बन गया है। इसी का परिणाम है कि आमजनता को कम व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। सच्चिदानंद सिन्हा कहते हैं कि अलगाव वर्तमान वैश्वीकरण का अनिवार्य पहलू है और इसी अलगाववाद का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया भर में बड़े नामी-गिरामी आतंकवादी संगठन उत्पन्न हो चुके हैं जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अलकायदा, बोको हराम इत्यादि आतंकवादी संगठन लगातार आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसमें अधिकतर वही युवा हैं जो कहीं न कहीं बेरोजगारी - गरीबी के शिकार हैं। अमेरिकी समाजशास्त्री और फ़ास्ट फूड उद्योग के व्याख्याकार कहते हैं कि स्पीड जिसका अर्थ है कि तेजी से बाजार तक पहुंच जाना और ग्लोबल गतिशीलता को बढ़ावा देना। आज रुपए के तेजी से आवागमन ने पूंजीवाद की नई व्याख्या को प्रस्तुत किया है, यह वर्चुअल मनी ही तो स्पीड का उदाहरण है जिससे 24 घंटे में कुछ भी लेना-देना व्यापार और उद्योग चलता रहेगा और यही बाजारवाद का जीता जागता उदाहरण भी है। नई व्यवस्था ने सेवा, ज्ञान श्रम और पूंजी का निर्बाध गति से स्थानांतरण किया है। ग्लोबल मीडिया के जरिए अमेरिका उपभोक्ता संस्कृति की वर्षा हो रही है। 30,000 से ज्यादा मैकडोनाल्ड की शाखाएं पूरे विश्व भर में स्थापित हो चुकी हैं और प्रतिदिन प्रतिवर्ष लगभग 2000 शाखाएं विश्व में खुलती जा रही हैं। वैश्विक तौर पर जितने हम सक्षम होते जा रहे हैं सामाजिक जीवन में हमारी उतनी ही असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। आत्म रक्षात्मक उपभोग की बाढ़ सी आ गई है, यह तार्किक है अथवा अतार्किक है यह बात बेमानी है, इसका राजनीति से किस तरह का संबंध है किंतु बाजार की बिक्री सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, संपूर्ण भावनाओं का बाजारीकरण हो चुका है, सभी कुछ आर्थिक गणित के रूप में पेश किया जाता है और विशेषता यह है कि सामाजिक तौर पर विदेशी माल को खूब उछाला जाता है और उसे ऐसे फिनोमिना के रूप में पेश किया जाता है जिसका प्रबंधन भविष्य में कर लिया जाएगा।

नए विचारक कह रहे हैं कि हम पोस्ट ह्यूमन युग में दाखिल हो रहे हैं। समाजीकरण की ह्यूमन प्रक्रिया प्रसांगिक नहीं रह गई। श्रम सामुदायिकता वर्ग आज की पुरानी कैटेगरी हो गई है। दक्षिणपंथी इन चीजों के बारे में खुलकर नहीं बोलते जबकि उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति इसको मन में सोचते हैं और हम कह सकते हैं कि हमारे ही रोज के जीवन में एक रहस्य भर गया है। नए प्रतिमान रोज दाखिल हो रहे हैं, स्वतंत्रता में कमी आई है फिर भी कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नए किस्म की स्वतंत्रता आ रही है। आप अपने रोजगार को बदल रहे हैं, लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, स्थाई नौकरी के आभाव में भ्रम की स्थिति बन गई है।

ग्लोबलाइजेशन ने राष्ट्र राज्य की अवधारणा को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाया है साथ ही सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को भी जन्म दिया है इसका सबसे पहला मंत्र है स्थानीय संस्कृति को अपदस्थ करके पश्चिमी आधुनिकता को पेश करो। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद चीजों को माल बनाता है तो हम सिर्फ माल ही नहीं खाते बल्कि समूची प्रकृति, जमीन, संस्कृति,

प्रस्तुतियां यहां तक कि मानवीय शरीर का भी उपभोग करते हैं, यह एक तरह का प्रतीकात्मक है जब हम सांस्कृतिक उपभोग कर रहे होते हैं तो आत्मसात कर रहे होते हैं और यही सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का सबसे भयावह रूप है। इन सब से हमारे अंदर एक नैतिक भय पैदा हो रहा है। उस समय यह भय और बढ़ जाता है जब हम नई तकनीक के माध्यम से पोर्नोग्राफी देख रहे होते हैं।

वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव के रूप में देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है और शिक्षा में वृद्धि हुई है परंतु दूसरी ओर उनके साथ एक नए तरह का शोषण आरंभ हो गया है अब महिलाओं को बाजार में एक सामान की तरह परोसा जाता है और उनको उपभोग की वस्तु माना जाता है जबकि हमारे यहां महिलाओं को पूजने की परंपरा रही है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण ने भारत के सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की अवधारणा को किनारे रखते हुए उपभोक्तावाद को आगे बढ़ाया है। नव साम्राज्यवाद का यह नया रूप जिसे वैश्वीकरण का नाम दे सकते हैं इसके आर्थिक केंद्रीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप औद्योगिक देश संपन्न हो गए हैं और गरीब देश अलग-थलग पड़ गए हैं। प्राकृतिक संपदा एवं पर्यावरण को लगातार नुकसान होता जा रहा है चाहे हम जितने भी सम्मेलन करते रहें जिसका उदाहरण हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जंगल की आग और आने वाली प्राकृतिक अपदाएं हैं। वैश्वीकरण ने मानवता हमसे छीन ली है जिसका ताजा उदाहरण वैश्विक महामारी कोविड-19 है जिसे चीन ने जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और यह एक वैश्विक

महामारी बन गया जिसने पूरे संसार की अर्थव्यवस्था को और सामान्य जनजीवन को ठप कर दिया। हमें अपने माननीय राष्ट्रपति के कथन को ध्यान में रखना होगा, अब आर्थिक वैश्वीकरण के साथ स्वास्थ्य वैश्वीकरण को भी ध्यान में रखना होगा पर अंत में एक प्रश्न और उभरकर आता है कि क्या इस महामारी के बाद वैश्वीकरण की अवधारणा को धक्का लगेगा यह आने वाला भविष्य तय करेगा।

#### References :-

1. Dinkar, Ramdhari, Sanskritikechaaradhyay, Lok Bharti Prakashan, 2017, Pg. 11
2. [www.scottbuzz.org](http://www.scottbuzz.org)
3. [www.7chapterbitsstream.com](http://www.7chapterbitsstream.com)
4. [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)
5. Ibid
6. [www.accountinghindi.com](http://www.accountinghindi.com)
7. vaishvikaran ka ek samanyaparichay, shodhganga
8. kaise aka jayevaishvikaranko, [www.azadi.me](http://www.azadi.me)
9. Chaturvedi J., Sinha S., Bhumandalikaran aur global media, Anamika Publication, 2008.
10. vaishvikaran ka ek samanyaparichay, shodhganga
11. Bhumandalikaran aur global media
12. Ibid

\*\*\*\*\*

# Non Performing Assets in Indian Banking Sector

Dr. Rajesh Shroff \*

**Abstract** - The assets of the banks which don't perform are called nonperforming assets or bad loans. Banks assets are the loans and advances given to customers. If customers don't pay either interest or part of principal or both the loan turn into bad loans. At the annual review meeting of the Union Finance minister with the CEO of banks held in New Delhi (2015) concern were raised over the increase in non-performing assets which were impacting credit growth of banks. Banks improve the allocation of resources by landing money to many sector of the economy. In present time Indian banking sector facing the problem about Non-performing assets. In the wake of the financial reforms. Undertaken by the government of India based on the Narasimhan Committee report, prudential norms were introduced by reserve bank of India to address the credit monitoring process being adopted and pursued by the banks and financial institutions. The Reserve Bank has from time to time also issued regulatory guidelines on other areas such as Corporate Governance, Fit and Proper, Know Your Customer/Anti Money Laundering, Credit Information Sharing Services in addition to specific guidance on credit, market and operational risk management etc. to strengthen the over-all-risk management environment in Indian Banks.

**Key Words**- Lending Money, Monitoring, Bad Loans, resources, nonperforming assets.

**Introduction** - Today NPA's is the common problem of the Indian Banks. With the advent of liberalization and globalization, resulting in market development there has been tremendous change in the intermediation role of banks in India. The pace of transformation has been more significant in recent times with technology acting as a catalyst. Consequently, we are noticing the cut throat competition in the banking industry these days. NPA has assumed great importance terms of risk management. Bankers thus have realized to have effective NPA management on their priority list. Non performing assets are problematic for financial institutions since they depend on interest payments for income.

**Literature Review** - Many researchers have been studied to the issue of non performing assets in Indian banking sector.

1. Usha Arora, Bhavna Vashisht & Monica Bansal (2009) in the research on "An Analytical Study of Growth of Credit Schemes of Selected Banks" analyzed and compared the performance (in terms of loan disbursement and non-performing assets) of credit schemes of selected banks for the last five years.
2. Narasimham Committee identified the NPAs as one of the possible effects of malfunctioning of public sector banks (Ramu, N., 2009).
3. It has been examined that the reason behind the falling revenues from traditional sources is 78% of the total NPAs accounted in public sector banks (Bhavani Prasad and Veena 2011)
4. The accounting treatment also failed to project the

problem for NPA, as interest on loan accounts were accounted on accrual basis (Siraj K.K. and P. Sudarsanan Pillai, 2012)

5. A Committee on Banking Sector Reforms known as Narasimham Committee was set up by RBI to study the problems faced by Indian banking sector and to suggest measures revitalize the sector. The committee identified NPA as a major threat and recommended prudential measures for income recognition, asset classification and provisioning requirements. These measures embarked on transformation of the Indian banking sector into a viable, competitive and vibrant sector. The committee recommended measures to improve 'operational flexibility' and 'functional flexibility' and functional autonomy' so as to enhance 'efficiency, Productivity and profitability' (Chaudhary, & Singh, 2012).

## Objectives of Study :

1. To know about Gross 'NPA' in Indian Banks.
2. To know about Net 'NPA' in Indian Banks.
3. To comparison of NPA's of public and private sector banks.
4. To know about types of NPA's.

**Research Methodology**- Present study uses the available published secondary data for the year 2009-10 to 2013-14 from reports on trends and progress of Banking in India, RBI reports, various research journals, news paper etc. The data has been analyzed using percentage method.

**Concept of NPA** - A Non-Performing Asset (NPA) is defined as a credit facility in respect of which the interest and /or installment of Bond finance principal has remained 'past

due' for a specified period of time. NPA is used by financial institutions that refer to loans that are in jeopardy of default. Once the borrower has failed to make interest or principle payments for 90 days the loan is considered to be non-performing asset. are problematic for financial institutions since they depend on interest payments for income. Troublesome pressure from the economy can lead to a sharp increase in non-performing loans and often results in massive write-downs. Accordingly, with effect from March 31, 2004, a non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

1. Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 91 days in respect of a term loan.
2. The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days, in respect of an overdraft/cash credit (OD/CC).
3. The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
4. Interest and/or installment of principal remains overdue for two harvest seasons but for a period not exceeding two half years in the case of an advance granted for agricultural purposes.
5. Any amount to be received remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.
6. Non submission of Stock Statements for 3 continuous Quarters in case of Cash Credit Facility.
7. No active transactions in the account (Cash Credit/ Over Draft/EPC/PCFC) for more than 91 days.

#### Treatment of Accounts as NPS's :

**1. Record of Recovery** - The treatment of an asset as NPA should be based on the record of recovery. Banks should not treat an advance as NPA merely due to existence of some deficiencies which are of temporary in nature such as non-availability of adequate drawing power, balance outstanding exceeding the limit, non-submission of stock statements and the non-renewal of the limits on the due date, etc. Where there is a threat of loss, or the recoverability of the advances is in doubt, the asset should be treated as NPA. However, where the accounts of the borrowers have been regularized by repayment of overdue amounts through genuine sources (not by sanction of additional facilities or transfer of funds between accounts), the accounts need not be treated as NPAs. In such cases, it should, however, be ensured that the accounts remain in order subsequently and a solitary credit entry made in an account on or before the balance sheet date which extinguishes the overdue amount of interest or installment of principal is not reckoned as the sole criteria for treatment the account as a standard asset.

**2. Treatment of NPAs – Borrowers-wise and not facility-wise :-** In respect of a borrower having more than one facility with a bank, all the facilities granted by the bank will have to be treated as NPA and not the particular facility or part thereof which has become irregular.

However, in respect of consortium advances or financing

under multiple banking arrangements, each bank may classify the borrowable accounts according to its own record of recovery and other aspects having a bearing on the recoverability of the advances.

#### 3. Agricultural Advances – Default in repayment due to natural calamities :-

- (i) Where natural calamities impair the repaying capacity of agricultural borrowers, as a relief measure, banks may decide on their own to :
  - (a) Convert the short-term production loan into a term loan or re-schedule the repayment period, and
  - (b) Sanction fresh short-term loans
- (ii) In such cases of conversion or re-schedulement, the term loan as well as fresh short-term loan may be treated as current dues and need not be classified as non performing asset (NPA). The asset classification of these loans would, therefore, be governed by the revised terms and conditions and these would be treated as NPA under the extant norms applicable for classifying agricultural advances as NPAs.

**4. Housing Loan to Staff** - In the case of housing loan or similar advances granted to staff members where interest is payable after recovery of principal, interest need not be considered as overdue from the first quarter onwards. Such loans/advances should be classified as NPA only when there is default in repayment of installment of principal or payment of interest on the respective due dates. the central government though overdue should not be treated as NPA.

#### Type of NPAs :-

**Gross NPA** : Gross NPAs are the sum total of all loan assets that are classified as NPAs as per RBI Guidelines as on Balance Sheet date. Gross NPA reflects the quality of the loans made by banks. It consists of all the nonstandard assets like as sub-standard, doubtful, and loss assets. It can be calculated with the help of following ratio:

**Formula - Gross NPAs Ratio = Gross NPAs/Gross Advances**

**Net NPA**: Net NPAs are those type of NPAs in which the bank has deducted the provision regarding NPAs. Net NPA shows the actual burden of banks. Since in India, bank balance sheets contain a huge amount of NPAs and the process of recovery and write off of loans is very time consuming, the banks have to make certain provision against the NPAs according to the central bank guidelines. It can be calculated by following :

**Formula - Net NPAs = Gross NPAs – Provisions/Gross Advances – Provision**

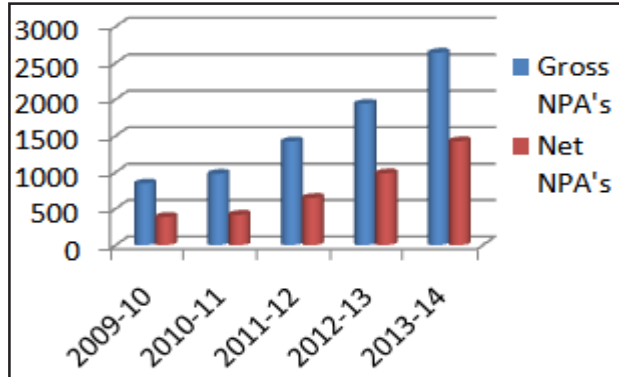
#### NPA's of Indian Banking Sector :-

Amounts in Billion Rs.

Year	Gross NPA's	% Changes	Net NPA's	% Changes
2009-10	847	—	387	—
2010-11	979	15.58	418	8.01
2011-12	1423	45.35	649	55.26
2012-13	1940	36.33	986	51.92
2013-14	2642	36.18	1427	44.73



**Sources :-** RBI Report on trend and progress of banking in India 2009-10 to 2013-14.

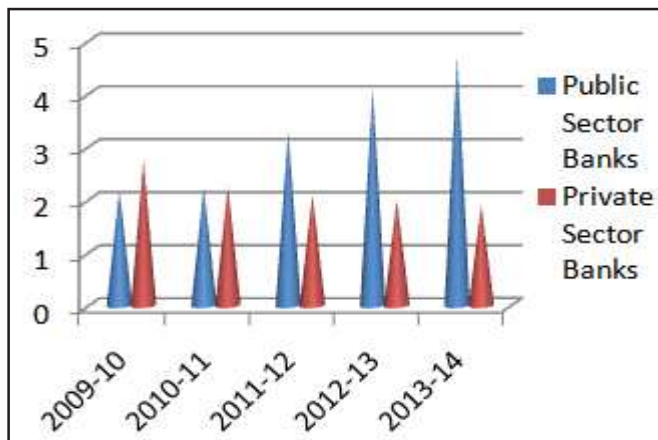


The above table shows the amount of Gross NPA's in Indian banking sector increase by 311.92% in last five years and Net NPA's increase by 368.73% in last five years. Gross NPA's increase by 15.58%, 45.35%, 36.33% and 36.18% in 2010-11 to 2013-14. Net NPA's increase by 8.01%, 55.26%, 51.92% and 44.73% in 2010-11 to 2013-14.

**Gross NPA's % of Gross Advances :-**

Year	Public Sector Banks	Private Sector Banks
2009-10	2.19	2.74
2010-11	2.23	2.25
2011-12	3.30	2.1
2012-13	4.1	2.0
2013-14	4.7	1.9

**Sources :-** RBI Report on trend and progress of banking in India 2009-10 to 2013-14

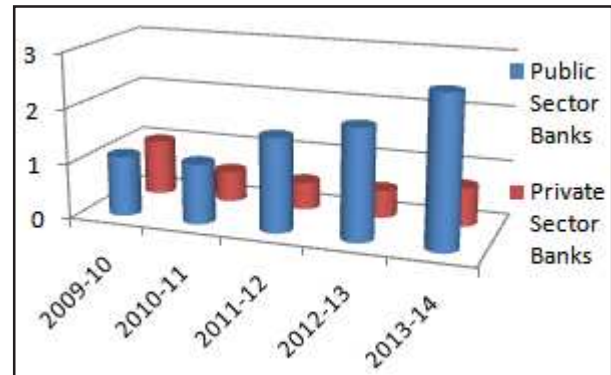


The Above table shows the % of Gross NPA's in Public & Private Sector Banks. In public sectors banks % of Gross NPA's increase by 2.19% to 4.7% in 2009-10 to 2013-14. private sectors banks % of Gross NPA's Decrease by 2.74% to 1.9% in 2009-10 to 2013-14.

**Net NPA's % of Net Advances :-**

Year	Public Sector Banks	Private Sector Banks
2009-10	1.09	1.01
2010-11	1.09	0.56
2011-12	1.7	0.50
2012-13	2.0	0.50
2013-14	2.7	0.7

**Sources :-** RBI Report on trend and progress of banking in India 2009-10 to 2013-14.



The Above table shows the % of Net NPA's in Public & Private Sector Banks. In public sectors banks % of Net NPA's increase by 1.09% to 2.7% in 2009-10 to 2013-14. private sectors banks % of Net NPA's Decrease by 1.01% to 0.7% in 2009-10 to 2013-14.

**Conclusion -** NPA's reflect the overall performance of the banks. The NPA's have always been a big worry for the banks in India. The Indian banking sector faced a serious problem of NPA's. A high level of NPA's suggests high probability of a large number of credit defaults that affect the profitability and liquidity of banks. The extent of NPA's has comparatively higher in public sectors banks. To improve the efficiency and profitability, the NPA's have to be scheduled. Various steps have been taken by government to reduce the NPA's. It is highly impossible to have zero % NPA's. In present scenario NPA's are at the core of financial problem of the banks. Concrete efforts have to be made to improve recovery performance. Measures required to be undertaken are mainly two fold. Banks should make efforts first to avoid fresh addition on NPA's by their effective presentation appraisal and secondly the amount from accounts which have already turned bad. RBI make more difficult credit policy and create strong recovery system to control NPA's in Indian Banking System.

**References :-**

1. RBI Reports on trend and progress of Banks in India (2009-10 to 2013-14)
2. "A study on the performance of non-performing assets of Indian Banking during post millennium period" International Journal of Business and Management Vol. 2 or 3pp 2012 - (Siraj & Pillai)
3. "NPAs Reduction strategies for commercial banks in India" International journals of management business studies issues 2011 – (Prasad & Veena).
4. Impact of reforms on the assets quality in Indian banking, international journal of multidisciplinary research Vol. 2 2012 – (Choudhary & Singh).
5. Narasimham Committee Reports.

# Effect of Foliar application of Boron and Zinc on Growth, Yield and Quality of Tomato cv. Arka Rakshak

Sanjay Kumar\* Arvind Kumar\*\* R.N. Singh\*\*\* Subhash Chandra\*\*\*\* P.K. Rathi\*\*\*\*\*

**Abstract** - The present experiment was conducted by KVK, Farrukhabad (U.P.) during rabi season-2019-20 to find out the effect of foliar application of B and Zn on growth, yield and quality parameters of tomato (*Solanum lycopersicum* L.) cv. of Arka Rakshak. The experiment was laid out in RBD with five treatments and three replications in different locations. The treatments combinations involved were T<sub>1</sub>-Farmers practice (FP-100%NPK as RDF)-(Boron-0ppm+Zinc-0ppm), T<sub>2</sub>-FP (Boron-50ppm+Zinc-50ppm), T<sub>3</sub>-FP (Boron-100ppm+Zinc-100ppm), T<sub>4</sub>-FP (Boron-150ppm+Zinc-150ppm) T<sub>5</sub>- FP (-Boron-150ppm+Zinc-100ppm). The boron and zinc was applied as foliar spray as per treatments on tomato variety Arka Rakshak. A total three sprays were given at before start flowering, time of fruit setting and at 15 days after fruit set. From the experiment, it was observed that application of T<sub>3</sub> recorded maximum Flower cluster/plant (5.45), Number of branches (12.4), Plant height (119.70cm), Fruit length & girth, Number of locules (3.60), Fruit weight (65.15g), Number of fruit / plant (63.37) and highest Yield per ha (480.50 qt) with minimum Days of first Fruit maturity (62.80). The fruit quality of T<sub>3</sub> was found good that was also judged by hedonic scale such appearance, colour and taste. The treatment T<sub>3</sub> was also recorded highest gross income Rs 336350/ha with net return Rs 249150/ha and maximum benefit cost ratio (3.85) in comparison to T<sub>1</sub> Farmers practice (3.21) that was indicating an economically better response of T<sub>3</sub> to the among farmers.

**Key words**- Boron, Zinc, quality and Economics.

**Introduction**- Tomato (*Lycopersicon esculentum* Mill.) is one of the most popular solanaceous widely cultivated vegetable crop in India. Tomato is a high yielding crop but a rich and fertile soil is necessary. India is a prime country in vegetable production by occupying the second position next to China and the production level of tomato in the country is next to potato. The production of tomato in India is about 18 million tonnes from an area of 0.8 million hectares (NHB). In Uttar Pradesh, average area under tomato for last 5 years is 10.6 thousand hectares with average annual production of 540.67 thousand metric tonnes (Anonymous, 2017). The well ripe tomato (per 100 g of edible portion) contains water (94.1%), energy (21 calories), calcium (1.0 g), magnesium (7.0 mg), vitamin A/âcarotene (1000 IU), ascorbic acid (22 mg), thiamine (0.09 mg), riboflavin (0.03 mg) and niacin (0.81 mg).

The tomato crop requires good amount of nutrients for its growth and development. Various nutrients play an important role in enhancing the yield and quality of tomato fruits. It is well responsive to micronutrient also. Micronutrients are required by plants very small quantities, yet they are very effective regulating plant growth due to

enzymatic action (Sandhya *et al.*, 2010). The micronutrient improve the chemical composition of fruits and general condition of plants and are known to acts as catalyst in promoting organic reaction taking place in plants. The availability of boron and Zink in soil is very low and less available to plant in Farrukhabad district due to sandy loam soil with high soil pH. Boron plays a crucial role in improving the growth, yield and quality of tomato. At cellular level, it supports the development of cell wall, occurrence of cell division, formation of the vascular bundle, protein synthesis, root system development, fruit and seed formation, water relations and transport of sugar. Moreover, it is also encourages the uptake of calcium by plants. Boron deficiency can cause serious yield reduction, uneven ripening, splitting and cracking of tomato. Zinc is essential for synthesis of carbohydrates, protein metabolism and sexual fertilization, synthesis of nucleic acid and protein. It helps in seed production and maturation. It also helps in the utilization of phosphorus and nitrogen in plant. It is also essential for the synthesis of tryptophan, the precursor of Indole Acetic Acid (IAA). The deficiency of zinc causes shortened internodes due to non-availability of IAA.

\*Scientist -Horticulture, Krishi Vigyan Kendra, Farrukhabad (U.P.) INDIA

\*\* Scientist -Agronomy, Krishi Vigyan Kendra, Farrukhabad (U.P.) INDIA

\*\*\* Scientist -Soil Science, Krishi Vigyan Kendra, Farrukhabad (U.P.) INDIA

\*\*\*\* Associate Director, Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur (U.P.) INDIA

\*\*\*\*\* Associate Director, Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur (U.P.) INDIA

Considering the benefits of these micronutrients, an experiment was conducted to find the effect of foliar spray of B and Zn on growth, yield and quality parameters of tomato cv. of Arka Rakshak.

**Materials and Methods-** The experiment (On Farm Trial) was conducted by Krishi Vigyan Kendra, Farrukhabad (U.P.) to study the effect of foliar application of boron and zinc on growth, yield and quality of tomato cv. Arka Rakshak in rabi season-2019-20. The experiment was laid out in RBD with five treatments and three replications in different locations. The treatments combinations involved were  $T_1$ -Farmers practice (FP-100%NPK as RDF)-(Boron-0ppm+Zinc-0ppm),  $T_2$ -FP (Boron-50ppm+Zinc-50ppm),  $T_3$ -FP (Boron-100ppm+Zinc-100ppm),  $T_4$ -FP (Boron-150ppm+Zinc-150ppm)  $T_5$ - FP (-Boron-150ppm+Zinc-100ppm). The boron and zinc was applied as foliar spray as per treatments on tomato variety Arka Rakshak. The first spraying of all the treatments was done at before start flowering, 2nd spraying at time of fruit setting and 3rd spraying was done at 15 days after fruit set. A total three sprays were given during entire period of experiment.

The planting materials were produced by KVK in pro-tray system of nursery production. The planting materials and chemicals were given to the farmers for experiment. The farmers were applied 10tonnes FYM and recommended dose of fertilizers (NPK-180:60:60 kg/ha) in tomato planned field. The land was tilled through ploughing and tillage. Organic manures were applied one week before transplanting. Full dose of phosphorus, potassium and half dose of nitrogen as per treatments were applied just before transplanting. The remaining half dose of nitrogen was applied twenty five days after sowing. Irrigation channels and bunds were prepared according to experiment layout. The twenty five days old seedlings of tomato were planted in the field with a spacing of 60x45cm in raised bed directly. Light irrigation was given just after transplanting. Immediately after transplanting light watering was given to avoid transplanting shock.

All the cultural practices were followed regularly during experiment period in all locations of the trial. The observations were made regularly on vegetative growth, fruiting, yield and quality of fruits. The data on days to first fruit maturity after transplanting was recorded in each treatment to get earliness in bearing. The flower initiation, number of flower / cluster, 50% of flowering, plant height etc. were counted. The fruit quality in term of physical characters (Fruit length, girth, number of locules, fruit weight) was determined by following the standard procedures (AOAC, 2000). The appearance, colour and taste were also judged by using hedonic scale. The data were statistically analysed to draw a logical conclusions.

**Results and Discussion** - It was observed that yield as well as yield attributing characters was influenced by different treatments. Application of nutrients by foliar application was proved beneficial increasing growth and yield of tomato. Table 1 showed that maximum number of

branches was observed in  $T_3$  (12.4) followed by  $T_2$  (11.0) and  $T_5$  (10.8) respectively. Minimum number of branches was found in  $T_1$  (10.2). The plant height was found maximum in  $T_3$  (119.70 cm) when boron-100ppm+ zinc-100ppm was applied was at before start flowering, 2<sup>nd</sup> spraying at time of fruit setting and 3<sup>rd</sup> spraying was done at 15 days after fruit set. Treatment  $T_3$  was significantly differed from all other treatments. The plant height was found lowest in  $T_1$  (95.52cm). The present findings corroborate with the findings of Abdel wahab et al. (2019) in red radish, Ekinici et al. (2012) in tomato. Similarly,  $T_8$  also produced maximum flower cluster/plant (5.45) as compared to the other treatments. It was also observed that micronutrient (Zn and B) induced earliness in 50% flowering (Table 1). The control plants showed flowering at late (39.70) as compared to others treated with micronutrients. Significantly, the plants under treatment  $T_3$  took the minimum days (31.60) to produce flowers followed by  $T_4$  and  $T_2$ . Similar finding was found in days to first fruit maturity that took early in  $T_3$  treatment (62.80) as compared to the other treatments.

It was noticed (Table 2) that the fruit size in term of length and girth was affected by the application of Zn and B. The highest fruit length (7.05cm) and fruit girth (5.25cm) were observed in  $T_3$  whereas lowest fruit length (5.82 cm) and fruit girth (4.22cm) were recorded in  $T_1$ . But for fruit length and fruit girth  $T_5$  and  $T_2$  were found at par. The treatment effect was found non-significant regarding to number of locules however, maximum locule (3.11) was found  $T_3$  followed by  $T_4$  (3.05). The result on fruit weight has been presented in (Table 2). indicated that the application of boron-100ppm+zinc-100ppm as in  $T_3$  have maximum fruit weight (65.15g ) as compared to the minimum (58.60g) in  $T_1$  as control. Same type of result has been reported by Yessen et al. (2017) in cucumber. Maximum number of fruits per plant were observed in  $T_3$  (63.37) followed by  $T_2$  (61.68),  $T_4$  (61.50) respectively. So far as fruit number is concerned there was no significant difference among the treatments. This increase might be due to greater accumulation of carbohydrates owing to greater photosynthesis which caused the fruit to increase in length. This increase in fruit weight might be assigned to mixture of all, since by its characteristics virtue (cell elongation) it has promoted the growth of all vegetative parts and consequently more food material for fruit development was produced by such plants and fruits with higher weight were obtained. The increasing fruit weight as results mixture of all application has also been obtained by Kumar et al. (2009) in okra.

As a result, the fruit yield was depends upon the number of fruits and weight of fruits. These both the characters are higher in treatment of mixture of micro-nutrients for the yield attributes. Accordingly, fruit yield was obtained maximum (480.50 q/ha) in the plants treated with the  $T_3$ - boron(100 ppm)+zinc(100 ppm) followed by  $T_4$  (429.14 q/ha)  $T_5$  (424.20q/ha),  $T_2$  (421.54 q/ha) respectively.



Lowest yield was found in  $T_1$  (395.92 q/ha).  $T_3$  was significantly differed from all other treatments. The improvement of yield is also associated with better flowering as recorded in the present investigation. Yadav et al. (2001) also found the improvement in flowering with application of zinc and boron. The result corroborated with the finding of Singh and Tiwari (2013). They found increase in maximum number of flowers/plant, number of fruits/plant and fruit yield with the application of boric acid+zinc sulphate +copper sulphate @ 250 ppm each. Organoleptic quality of fruits such as physical appearance, quality, taste and aroma was judged by using 9 point hedonic scale.

**Economics-** The data showed in Table 3 the maximum gross return of Rs.336350/ ha were obtained in treatment  $T_3$ - boron(100 ppm)+zinc(100 ppm) whereas lowest of Rs. 276878 / ha were obtained in  $T_1$ . Similarly highest net return of Rs. 249150/ ha were obtained in  $T_3$  and was followed by  $T_4$  (Rs 212898/ ha). Whereas, lowest of Rs.190878/ ha were obtained in  $T_1$ . The maximum cost of cultivation of Rs.87500/ ha was obtained in  $T_4$  while minimum cost of Rs. 86000/ ha incurred in  $T_1$ . But added variable cost not affected the cost of cultivation and yield increased by  $T_3$  treatment. This might be due to that application of boron and zinc for higher yield, which resulted in higher economic return. The highest benefit cost ratio (3.85) was observed in  $T_3$  followed by  $T_4$  (3.43 and  $T_5$  (3.42). The lowest B: C ratio of 3.21 was observed in  $T_1$  (Farmer practice). The increase in B: C ratio and other crop economic parameters might be due to increase in yield which fetched more prices in market. The additional cost incurred on this account was added to the expenditure on all treatments. The cultivation of tomato turned labour intensive and created an employment from nursery raising to soil preparation as well as up to the harvesting and marketing of fruits to dispose the produce in main market for getting higher price. Common variable cost and fixed cost made up cost of cultivation and when with added variable cost through nutrient sources that are total cost of cultivation.

**Conclusion** - Considering the above discussion it may be concluded that the treatment ( $T_3$ ) was performed the best in term of yield attributes, fruit yield and economical for the cultivation of tomato. Foliar application of Boron@ 100ppm+Zinc@100ppm applied at before start flowering,

2nd spraying at time of fruit setting and 3rd spraying was done at 15 days after fruit set was found the best treatment that that improve growth, yield and fruit quality of tomato cv. Arka Rakshak.

**Tables:1, 2 & 3 (see in next page)**

#### References:-

1. Abdel, W. M. M., Abdelaziz, S. M., El-mogy, M. M., & Adeldaym, E. A. (2019). Effect of foliar ZnO and FeO nano particles application on growth and nutritional quality of red radish and assessment of their accumulation on human health Agriculture (Pol, nohospod arstvo), 65(1): 16-29.
2. Anonymous. (2017). National Horticulture Board, Area and Production of Vegetables for the year 2016-2017.
3. AOAC. (2000). Official Methods of Analysis of Association of Official Analytical Chemists, 16th ed. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA.
4. Ekinci, M., Dursun, A., Yildirim, E., & Parlakova, F. (2012). The effects of nano technological liquid fertilizers on plant growth and yield in tomato. 9 Ulusal Sebze Tarimi Sempozyumu, 326-329, 14-12 Eylul, konya, (Turkish).
5. Kumar, Sanjay., Chankhar, S.K., Rana, M.K., (2009). Response of okra to zinc and boron micronutrients. Vegetable Sciences 36(3), 327-331.
6. Sathya, S., Mani, S., Mahendran, P.P., Arulmozhi selven, K., (2010). Effect of application of boron on growth, quality and fruit yield of PKM 1 tomato. Indian Journal of Agriculture Research 44(4), 274-280.
7. Singh, H.M., Tiwari, J.K., (2013). Impact of micronutrient spray on growth, yield and quality of tomato (*Lycopersicon esculentum* Mill.). Hort Flora Research Spectrum 2(1), 87-89.
8. Yadav, P.V., Abha Tikkoo S., Sharma, N.K., 2001. Effect of zinc and boron application on growth, flowering and fruiting of tomato (*Lycopersicon esculentum* Mill.). Haryana Journal of Horticulture Science 30(1/2), 105-107.
9. Yassen, A., Abdallah, E., Gaballah, M., & Zaghloul, S. (2017). Role of silicon dioxide nano fertilizer in mitigating salt stress on growth, yield and chemical composition of cucumber *Cucumis sativus* L. International Journal of Agricultural Research. 12, 130-135.



**Tables:1 Effect of foliar application of Boron and Zinc on growth, flowering, fruiting behaviour of tomato cv. Arka Rakshak.**

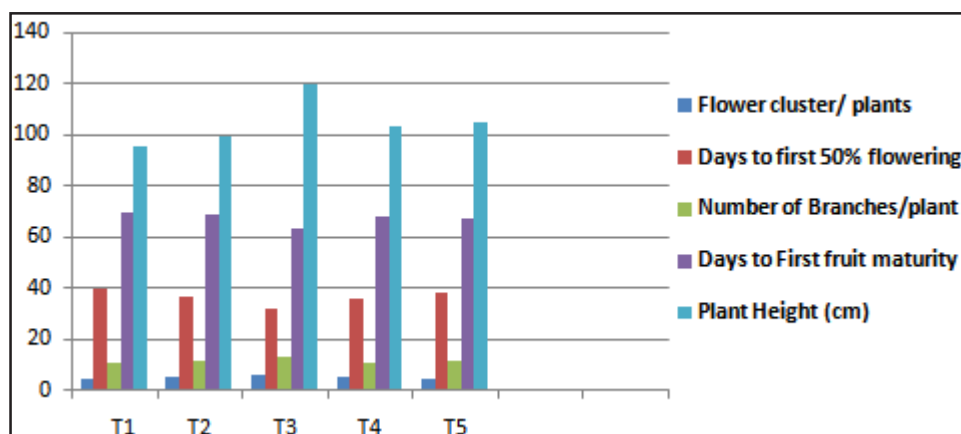
Treatments	Flower cluster/ plants	Days to first 50% flowering	Number of Branches/ plant	Days to First fruit maturity	Plant Height (cm)
T <sub>1</sub> - Farmers practice (FP) (Boron-0+Zinc-0 ppm)	3.95	39.70	10.2	69.20	95.52
T <sub>2</sub> - FP (Boron-50ppm+Zinc-50 ppm)	4.80	36.55	11.0	68.75	99.25
T <sub>3</sub> - FP (Boron-100ppm+Zinc-100 ppm)	5.45	31.60	12.4	62.80	119.70
T <sub>4</sub> - FP (Boron-150ppm+Zinc-150 ppm)	4.88	35.55	10.5	67.75	103.35
T <sub>5</sub> - FP (Boron-150ppm+Zinc-100 ppm)	3.75	38.00	10.8	66.90	104.40
SEm±	0.613	0.537	0.410	0.481	1.022
CD AT 5%	1.35	1.67	1.21	1.78	3.89

**Tables:2 Effect of foliar application of Boron and Zinc on growth and yield of tomato cv. Arka Rakshak.**

Treatments	Fruit length (cm)	Fruit girth (cm)	Number of Locules	Fruit weight (g)	Number of Fruits /plants	Fruit yield (qt/ha)
T <sub>1</sub> - Farmers practice (FP) (Boron-0ppm+Zinc-0 ppm)	5.82	4.22	3.01	58.60	60.35	395.92
T <sub>2</sub> - FP (Boron-50ppm+Zinc-50 ppm)	6.56	4.72	3.03	58.98	61.68	421.54
T <sub>3</sub> - FP (Boron-100ppm+Zinc-100 ppm)	7.05	5.25	3.11	65.15	63.37	480.50
T <sub>4</sub> - FP (Boron-150ppm+Zinc-150 ppm)	6.75	4.85	3.05	60.20	61.50	429.14
T <sub>5</sub> - FP (Boron-150ppm+Zinc-100 ppm)	6.84	4.88	3.04	60.35	61.45	424.20
SEm±	0.10	0.12	0.413	0.65	0.88	2.86
CD AT 5%	0.43	0.41	0.78	1.86	3.09	9.33

**Tables:3 Economics of Tomato cv. Arka Rakshak as affected by foliar application of Boron and Zinc.**

Treatments	Cost of Cultivation (Rs/ha)	Gross Return (Rs/ha)	Net Return (Rs/ha)	B:C Ratio
T <sub>1</sub> - Farmers practice (FP) (Boron-0+Zinc-0 ppm)	86000	276878	190878	3.21
T <sub>2</sub> - FP (Boron-50+Zinc-50 ppm)	86500	295078	208578	3.41
T <sub>3</sub> - FP (Boron-100+Zinc-100 ppm)	87200	336350	249150	3.85
T <sub>4</sub> - FP (Boron-150+Zinc-150 ppm)	87500	300398	212898	3.43
T <sub>5</sub> - FP (Boron-150+Zinc-100 ppm)	87400	298940	209540	3.42



**Fig. 1 Effect of foliar application of Boron and Zinc on growth, flowering, fruiting behaviour of tomato cv. Arka Rakshak.**

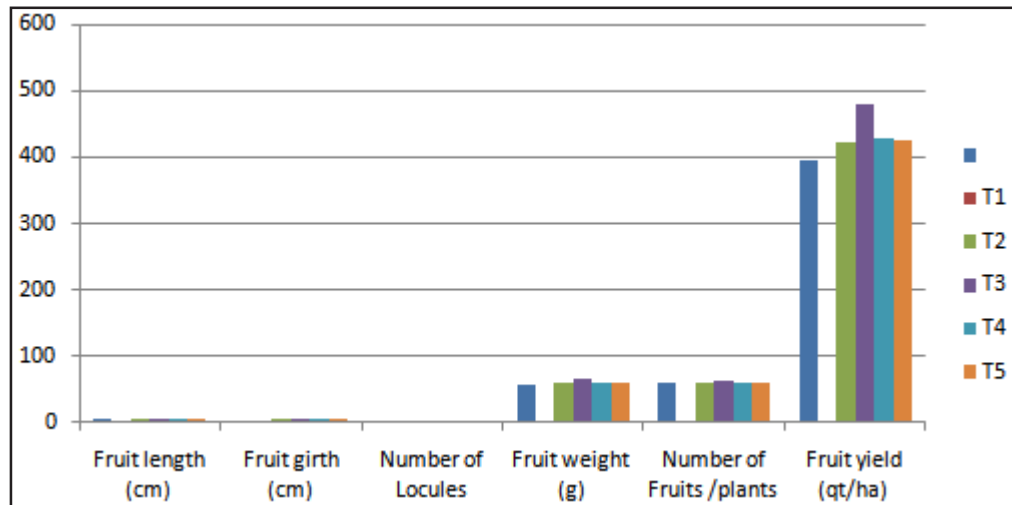


Fig. 2 Effect of foliar application of Boron and Zinc on growth and yield of tomato cv. Arka Rakshak.

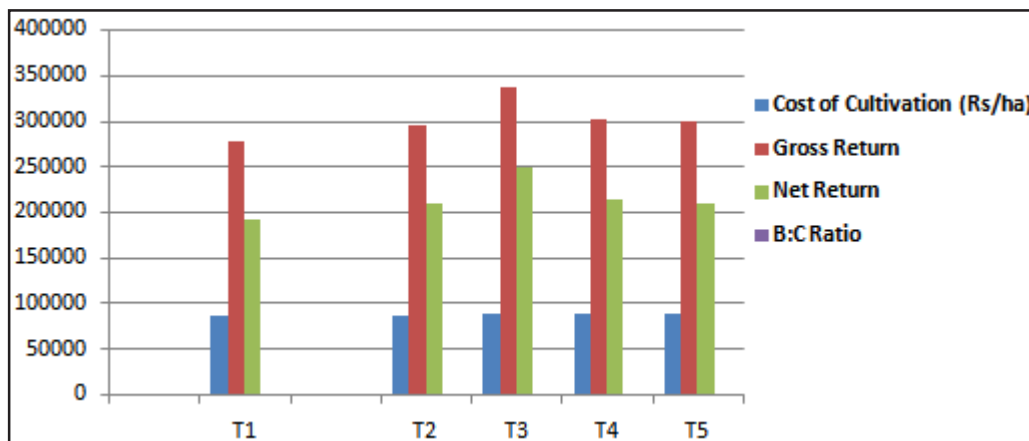


Fig. 3 Economics of Tomato cv. Arka Rakshak as affected by foliar application of Boron and Zinc.

\*\*\*\*\*

## स्त्री विमर्श और आज की हिंदी कविता

उमेश कुमार विश्वकर्मा \*

**प्रस्तावना** - भारत में स्त्रीवादी विचारों की शुरुआत साहित्यकारों और इतिहासकारों ने बौद्ध-थ्योरी गाथाओं और भक्ति आन्दोलन में देखी है। लेकिन व्यवस्थित स्त्री समर्थन उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध और बीसवीं सदी के आरंभिक समाज सुधार आन्दोलनों में देखा जा सकता है। दयानंद सरस्वती, केशव चन्द्र सेन, आत्माराम पांडुरंग, महात्मा गांधी, रमाबाई, दोंडो केशव कर्वे, कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, आदि अनेक समाज सुधार व स्वतंत्रता कर्मियों ने राष्ट्रीय आन्दोलन में स्त्री की समान सहभागिता के लिए समाज सुधार कार्यक्रम चलाए, इसीलिए राजनीतिक परिदृश्य पर स्त्रीवाद जैसी अवधारणा के तले मताधिकार के लिए स्त्रियों को कोई आन्दोलन नहीं करना पड़ा और न ही शिक्षा के लिए कोई राजनीतिक और कानूनी संघर्ष करना पड़ा। साहित्यिक स्त्रीवाद समाज में स्त्री दमन के विरोधा के साथ-साथ इतिहास, दर्शन, संस्कृति, और सौन्दर्य बोध में स्त्री संबंधी पूर्वाग्रहों का विरोध करने को भी प्रतिबद्ध है। आज के उत्तर-आधुनिक स्त्रीवादी परिदृश्य पर स्त्री लेखन और स्त्रीवादी लेखन की बहसे भी आम हैं। अनुभव की प्रामाणिकता के आधार पर क्या केवल स्त्री द्वारा लिखा साहित्य ही स्त्रीवादी हो सकता है। अथवा पुरुष भी स्त्रीवाद के प्रवक्ता हो सकते हैं। यह प्रश्न स्त्रीवाद में महत्व पर रहे हैं। स्त्री लेखन और स्त्रीवादी लेखन की तरह स्त्रीवादी आलोचना की शुरुआत भी हो चुकी है। जिसमें उपलब्ध टेक्स्ट्स को नई स्त्री दृष्टि से अर्थ करने की प्रक्रिया -विकसित की जा रही है। उत्तर-आधुनिक आलोचना पद्धति में पाठ विमर्श का यह स्त्रीवादी संस्करण है। वस्तुतः परिवर्तन के आलोक में जीवनानुभवों से उत्पन्न नये जीवन-संदर्भ का साहित्य रच रही है। स्त्री का यह संघर्ष और उसकी अस्मिता की तलाश निरा प्रतिक्रियावाद नहीं है, बल्कि यह एक सुलझी हुई शांत, सुव्यवस्थित दृष्टि है। उत्तर आधुनिकता में जो नारी चेतना विकसित हुई, उसका संबंध फ्रांस के नारीवादी सिद्धांत से है। लाका ने जिसे पुरुष प्रधान प्रतीकात्मक व्यवस्था कहा है-उसका-प्रतिकार इसमें स्त्रियों की स्वतंत्रता की स्वतंत्रता, अस्मिता के लिए आवश्यक माना गया है। यह प्रतिकार कम से कम भाषिक स्तर पर प्रायः हर महत्वपूर्ण महिला रचनाकार करती है। फ्रांस की लेखिकाओं ने इस प्रतिकार पर अपनी टिप्पणी दी है। हरेगरी के अनुसार भाषा, उसकी यौन की तरह बहुकेन्द्रीय होती है। उनका सारा संघर्ष इस इकहरे एकांकी सत्य से है जिसे देरीदा 'इंटेन्शनल यूनिटरी मीनिंग आफ सिम्बालिक आईड' कहते हैं। हरेगरी का मानना है कि - द्वित्व विलोमों में एक को दूसरे पर तरजीह न देकर उनका अन्तर समझते हुए दोनों को बराबरी की, अपने ढंग की विशिष्ट और तरल अर्थवत्ता देनी चाहिए। स्त्रियों की दमित कल्पनाओं, वाक्य खण्डों, शब्द क्रमों आदि की उद्भावना भी आवश्यक है। उन्होंने स्त्रियों की दैहिक संवेदनाओं और विशिष्ट अनुभूतियों (प्रजनन, ऋतुचक्र,

दूध पिलाना आदि) के स्पष्ट उल्लेख पर बल दिया है। हरेगरी का यह दर्शन वस्तुतः कलम को स्थायी नहीं बल्कि दूध में डुबोकर लिखने का दर्शन है। वस्तुतः आज की हिंदी कविता में स्त्री ने अपनी निर्णायक उपस्थिति दर्ज की विषय और विधेय दोनों के स्तर पर एक बदले हुए स्वरूप में। उनकी कविता उनके निजी अनुभवों की कविता है। किंतु महत्वपूर्ण यह है कि उनका अनुभव क्षेत्र सीमित नहीं है। वे अपने आस-पास और इस अनुभव को व्यक्त करने के लिए वे अपनी भाषा की खोज करती हैं। जो मेल डोमिनेट नहीं होती। उनके इस संघर्ष को हासिए के केन्द्र से दृष्टि लेन का प्रयास किया जा सकता है। गर्म रातों ने दिनचर्या को ठंडा कर दिया है। पहले कुरुवा की लड़कियाँ देने, पत्तल, चटाई, झाड़ू, पंखे आदि बनाया करती थी। बनाने से काम चलता था। अब यह सब बनाने की कोई जरूरत नहीं रही। दूसरों की रातें गर्म करने का जो पैसा मिलता है उसके सामने मेहनत से आए पैसे की कोई हैसियत नहीं बची। हैसियत ही नहीं बची तो वह जिंदगी से अपने आप बाहर हो गया।

शहर बिलासिता के साधन भी कुरुवा में ले आया और जीने के शार्टकट रास्ते भी। एक सीमा तक यह सच है, मॉडलिंग, फैशन, डिजायनिंग, आदि के रूप में स्त्री के सामने नए कर्म-क्षेत्र खुले हैं। ये ऐसे कर्म-क्षेत्र हैं, जो लोक-लॉज, मर्यादा आदि पुराने संस्कारगत मूल्यों को तोड़ते हैं, स्त्री को पड़ी गुलामी की आदत में सेंधा लागते हैं। उसे पहले से ज्यादा खुले स्पेस देते हैं। उसकी आँखों में सेलिब्रिटी बनने की संभावना रखते हैं। शरीर के प्रति उसके नजरिये को बदलते हैं। इसी का नतीजा है कि उसका शरीर अब केवल छिपाने के लिए नहीं रहा। वह शर्म का नहीं, गर्व का विषय है। मध्य वर्गीय परिवार की औरतों में उनकी कुण्ठा, निराशा, अपमान, दुख, अधःपतन, परेशानियाँ आदि नहीं रहता, आर्थिक तौर पर पुरुष आश्रित व्यवस्था उनको और अधिक कमजोर बना दे बाहर से पैसे कमाती के नहीं आती, यदि पैसे कमाकर लाती तो वे समाज में सम्माननीय एवं वंदनीय होती। पैसे न कमाना ही उनके जीवन की परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। विधवा या बाँझ होने पर या दहेज में पति के सहायतार्थ कम सामान या राशि लाने पर उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है। लेकिन कुछ हद तक निम्न वर्ग की स्त्रियाँ जहाँ एक ओर मर्द के साथ मिलकर या अकेले ही, खेत-खलिहान या फैक्ट्री, खदान आदि से कमाकर लाती हैं, वहीं दूसरी ओर उनसे मिलकर गृहस्थी जीवन भी चलाती हैं और परिवार का बोझ नहीं बनती। परिणाम स्वरूप, स्वतंत्र भारत का समय बदला, विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा भी हो रही है। पाश्चात्य सभ्यता भी हावी होने लगी है, तथा स्त्री विकास के लिए कई योजनाएँ भी चलाई जा रही है। फिर भी यह कोरी कल्पना मात्र लग रही है। उनके जीवन के लिए अब भी घरेलू ब्रिटिश सत्ता विद्यमान है, जो स्त्री को न तो बोलने की स्वतंत्रता और न

घूमने-फिरने की स्वतंत्रता वह एक दबी कुचली मानसिक जीवन जीने को मजबूर हो रही है। ऐसी परिस्थिति में रंचमात्र की प्रगति नहीं हो सकती। भारतीय समाज का यह परिदृश्य तभी बदलेगा जब स्त्री पूर्ण रूप से स्वावलम्बी होगी। अपने को पूरी तरह पहचानना पूरी तरह जीना है। अधिकांश स्त्री जीवन में न यह पहचान है, न तैयारी। मूलतः इसका कारण स्त्री नहीं। कारण है-स्त्रीत्व-विरोधी ऐतिहासिक होते हैं स्त्री-पुरुष, सभी को इसी में साँसें लेनी हैं। इससे बाहर ही ताजादय जीवन हो सकता है। यह संवेदन अभी बन रहा है। ज्यादातर स्त्रीत्व-विरोधी हालात से टकराते हुए। टकराने के जोखिम उठाते और उसकी तकलीफ सहते हुए। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है कि सन् 2011 में हुई भारत की महिलाओं का अनुपात 940 है। इस सच की सूचना है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते... का उद्घोष करने वाले देश में आज भी स्त्रियों को जीवित रहने का पुरुषों जितना अधिकार नहीं है। जीवित रह लेने और जीवन को पूरी तरह जीने में अंतर है। यह ध्यान रखा जाए तो स्त्री-पुरुष विषमता कर विष और गाढ़ा और भयावह और सर्वग्रासी नजर आता है। स्त्री इस विषय की प्रत्यक्ष शिकार है। इन अवधारणाओं ने बहुत जल्दी ही विश्व के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। इनके प्रभावों से भारतीय जगत भी अछूता न रह सका, जल्दी ही चौतरफा इनके प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगे। यूँ तो भारतीय कृषि और किसानों को विश्व फलक से जोड़ने की मुहिम काफी पहले से चल रही थी। लेकिन 1996 के बाद यह अल्पधिक तीव्र हो गई।

कविता के मंच पर चलने वाली बंदूकें नेपथ्य में चली गई थी। उनकी आवाजे दूर होती जा रही थी मगर सुनाई दे रही थी। समर गाथा सुनने के लिए अब किसी के कान अधीर नहीं थे। 1967 के नक्सलवादी आंदोलन के प्रभाव में लिखी जाने वाली मुखर, उग्र वामपंथी कविताएँ जैसे 'गोली दागो पोस्टर' (आलोक धन्वा) अब नहीं लिखी जा रही थीं। स्वयं आलोक धन्वा जैसे कवि कुछ मध्यम स्वर में जीवन की दूसरी विसंगतियों को भी काव्य-विषय बना रहे थे। 'वेणुगोपाल' की लेखनी लगभग रुक चुकी थी।

विरोधा अब संयत दिख रहा था, क्रोधा कुछ समझदारा। कविता की नदी अब शोर करती नहीं बह रही थी। उसका प्रवाह शांत और गहरा हो चला था। यह नवें दशक में उभर कर आए कवियों की कविता थी। लेकिन यह कविता सिर्फ नवें दशक की कविता नहीं थी। कवि भी ये सिर्फ नवें दशक के नहीं थे। कोई भी कविता या कवि केवल दशक विशेष का नहीं होता। दशकवार विभाजन ही गलत है। समाज-संप्रति को वास्तविक पहचान भाषा से की जा सकती है। इस कविता में प्रायः लोकभाषा और नागर समाज के बोलचाल के शब्दों को, वाक्यों, मुहावरों को व्यापक स्थान मिला। इससे यह कविता सहज ही पूर्ववर्ती कविता से पृथक हुई प्राचीन काव्य पथ पर नया पाथेय यही था-नई काव्य वस्तु के साथ नई काव्य-भाषा 'नए चित्र के साथ नई देता हूँ भाषा' - 'त्रिलोचन' ने जो कभी लिखा था, उसका कुछ सत्य तो यहाँ भी चरितार्थ होता दिखता ही है। बीहड़ प्रदेश के पत्थर और फूल उसी की झोली में हो सकते हैं जो वहाँ के ऊबड़ खाबड़ रास्तों में भटकता रहा है। लोक के शब्दों के साथ भी यही बात है। जैसे 'ज्ञानेद्रपति' की कविता में बनारस का लोक और उसका सूक्ष्म विवरण पूरे देश के लोक में बदलता दिखाई देता है। यह गहरी जन-संवेदना और संप्रति के बिना संभव ही नहीं। तो झगड़ा नागर और ग्रामीण लोक के बीच नहीं वल्कि असली और कृत्रिम कविता के बीच है। कार्यशालाओं में दीक्षा लेकर, गुरु की नसीहतें सुनकर काव्याभ्यास से कविता संभव नहीं है। यह तो एकलव्य साधाना है। 'केदारनाथ सिंह' ने अनौपचारिक बात-चीत से एक बार कहा था कि 'कवि या तो होता है या नहीं होता।' कहा जा सकता है कि कविता भी होती है या नहीं होती। प्रकृति

की तरफ भी इस दौर में कविता की वापसी पुनः दिखाई देती है। मगर यह पंत की प्रकृति नहीं थी-मनुष्य विहीन प्रकृति के शुद्ध रूप का यहाँ निषेध था। वह जीवन के कार्यव्यापार और विभिन्न सुखद, दुखद और त्रासद अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने का एक मंत्र मात्र थी। गद्य कविता की मरुभूमि में कविता का नखलिस्तान पुनः हरा-भरा दिखाई देने लगा। घास जनता का, पानी संवेदना और मनुष्यता का और फूल प्रायः प्यार और स्वप्न के प्रतीक बनकर कविता में आए। इस कविता में अपने स्थापत्य के प्रति एक चौकझापन दिखाई देता है। प्रायः लघुकाय, मित भाषी और सुगंठित शिल्प यह कविता, कविता के गद्यात्मक स्वरूप का शांत प्रतिवाद करती दिखाई देती है। शब्दों को सरकारी धन की तरह खरचने में इस कविता का विश्वास नहीं था। कुछ लोगों ने, प्रायः व्यंग्य से इसे मंत्र और श्लोक की भाषा में लिखी जाने वाली कविता भी कहा। अमेरिका यहाँ उस जीवन शैली का नाम है, जो बाजार की है, सर्वव्यापी होने का सम्बद्ध इसके लिए मुस्कराना लड़की का उल्लास नहीं काम है। ऐसा काम जो सोचने तक की छूट नहीं देता। उदास होने और रोने की तो दूर, वह कुछ याद तक करने की छूट नहीं देता। एक क्षण भी लड़की अगर अपना जी लेती है तो बाजार के काम की नहीं रहती। काम की वह तभी तक है जब तक यंत्र की तरह काम करती रहे। सहजता नहीं यांत्रिकता, बाजार की नैतिकता है। स्त्री मनुष्य नहीं वस्तु है। उसके समय को खरीदना और उसे खरीद लेना है और बिक जाने के बाद सब कुछ ग्राहक का होता ही है।

स्त्री और स्त्री धर्म व मर्यादा का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध होता है कि, वह उससे अलग नहीं हो सकती, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों न हो, पति के लिए, बच्चे के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए कई व्रत, उपवास, पूजन आदि करती है तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है। लेकिन जब कभी अनजाने में भी मर्यादा से डिगती है तो उन्हें अबला का शिकार बना दिया जाता है। यहाँ तक की हमने कई बड़े-बड़े पदों पर काम करने वाली स्त्रियों को भी अपने पूर्वाग्रह या परम्परावादी, दबी कुचली मानसिक सोच वाले अपने पतियों से पिटते देखा है। समाज में बदनामी के डर से स्त्रियाँ फिर भी चुप रहती हैं। क्योंकि स्त्रियों की मानसिक सोच यह करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाती है कि यह पुरुष प्रधान समाज है, और अपने को हीन भावना से ग्रसित कर लेती है।

स्त्रियों के हितों, रक्षा एवं समानता तथा संविधान में प्रावधान है, महिला विकास के लिए देशभर में महिला दिवस मनाया जाता है। संसद पर 33 प्रतिशत आरक्षण की माँग की जा रही है। महिला आयोग बनाया गया, अन्य अनेक प्रावधान किए जा रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद महिला, प्रतिदिन, अत्याचारों, एवं शोषणों का शिकार हो रही है, मानवीय क्रूरता एवं हिंसा से ग्रसित है पर अमानवीय व्यवहार का हमला है। आवश्यकता एवं आर्थिक न्याय प्रदान किया जाए तभी समाज का वास्तविक चहुमुखी विकास संभव है। अनुचित से घृणा के लिए जरूरी है कि अनुचित को पहचाना जाए। स्त्री जीवन में जहाँ-जहाँ जो-जो अनुचित हो रहा है, उसको रेखांकित किया जाए उस दुःख, कष्ट को जान, समझ और अनुभव कर उजागर किया जाए, जिसने स्त्रियों की जगह घेर रखी है। इतनी ज्यादा कि उसके बिना उनका जीवन सुना-सुना सा लगता है। वह उन्हें दिखलाई दे, इसके लिए जरूरी है, वह जीवन से अलग हो। पर वह बहुत है, बहुत सघन, बहुत गहरा, बहुत रमा हुआ। 'गगन गिल' ने इसीलिए कहा-

'कभी दिख कभी दिख  
कभी दिख दुख साँसों से



निकल कभी दिखा।<sup>13</sup>

हँसना और काजल लगाना सुखी होने का दिखावा करना है। दिखावा इसलिए की लड़कियों से ऐसी ही उम्मीद की जाती है। अपने घर की स्त्रियों को दारुण दुख देने वाला भी नहीं चाहता कि वे दुखी दिखलाई दे। हँसने के लिए होंठ भी है, और लगाने के लिए काजल भी। फिर कैसा दुख, पर दुःख है कि काजल भिगोता है। 'सर्वेश्वर दयाल सक्सेना' ने लिखा था—

'उँगलियों में चुभें काँटे  
गोद में सितार भीतर  
तार-तार हाहाकार'<sup>14</sup>

हाहाकार को संगीत की तरह प्रस्तुत करना स्त्री-जीवन का विशेष दुख है। इसी दुख की खबर देती, 'प्रगति सक्सेना' के शब्दों में —

'फूलों की सुगंधा के साथ  
आती है उनके तकियों से  
आसुओं की गंधा'<sup>15</sup>

दमन के बाद फूलों की सुगंध और तीव्र होती है। उनका रस आँसुओं के साथ मिलकर जो नया रसायन बनाता है उसकी गंध के रूप में स्त्री के दुःख को सूँघा जा सकता है। यह गंध और यह दुःख, दोनों का कहना है कि स्त्री जीवन स्वयं पिसकर भी सुगंध देने वाला जीवन है। विशिष्ट है, विशेष रूप से शिष्ट है। कूल्हे मटकाऊ और वासना भड़काऊ रीमिक्स गानों की भरमार वाले इस दौर में कविता ही है, जो विलखते हुए गाने को भी सुनने-सुनाने का, गायन में रुदन की बदली मिक्सिंग भी देखने-दिखाने का दम रखती है। यह जीवन और समय का कविता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और ईमानदारी तो है ही, निरी सफलता को परम मूल्य मानने से सुहृद् इन्कार भी है। सच और नैतिकता के दो पाँवों को जीवन की धरती पर अच्छी तरह जमाकर खड़े होना भी है। लड़की का हथेली पर जीभ लेकर लौटना यह दिखाता है कि अब वह तकनीकी तौर पर भी अपना सच कहने के अयोग्य होगी दिखाना इसलिए कि पुरुष की बनाई दुनिया आश्वस्त रहे। उसने जो गूँगापन उसे पुरस्कार में दिया, अब वह आश्वस्त हो गया है। भगवान की तरह, पुरुष सत्ता की तरह, अब उसकी बर्बरता जारी रहेगी। जारी रहेगी स्त्री की यातना सहते रहने। स्त्री जीवन के लिए यातना अनिवार्य है जैसे उसके बिना जीवन संभव ही न हो। इसीलिए स्त्रियों में गालियाँ सुन लेने की तीव्रता इतनी है कि हर यातना स्वाभाविक लगने लगती है। 'कात्यायनी' ने 'अपराजिता' कविता में ठीक

ही लिखा —

'उन्होंने यही सिर्फ यही दिया हमें अपनी वहशी वासनाओं की तृप्ति के लिए

xxx

दिया एक बिस्तर

और हमारी आत्मा को पराजित करने के लिए  
लाद दिया उस पर तमाम अपवित्र इच्छाओं और दुष्कर्मों का भार।

पर नहीं कर सके पराजित वे हमारी अजेय आत्मा को  
उनके उत्तराधिकारी और फिर उनके उत्तराधिकारियों के

उत्तराधिकारी भी नहीं पराजित कर सके

जिस तरह मानवता की अमर-अजय आत्मा को  
उसी तरह नहीं पराजित कर सके वे हमारी अजेय आत्मा को

आज भी वह संघर्षरत है नित-निरंतर

उनके साथ जिनके पास खोने को सिर्फ जंजीरें ही हैं

बिल्कुल हमारी ही तरह।<sup>16</sup>

21वीं शताब्दी की स्त्री आज अपनी भागीदारी दारी प्रस्तुत कर रही है।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. (नई सदी) पानी का स्वाद, नीलेश रघुवंशी, प्रकाशक - किताबघर प्रकाशन नई दिल्ली पृष्ठ - 61
2. संशय आत्मा, कवि ज्ञानेंद्रपति प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, 1- बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली - 110002, पृष्ठ- 33
3. थपक थपक दिल थपक थपक, गगन गिल, प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, 1- बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली 110002, पृष्ठ - 59
4. खूंटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, 1- बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली 110002, पृष्ठ - 47
5. पल - प्रतिपल (पत्रिका) जुलाई - सितम्बर 1980, आधार प्रकाशन एस सी एफ - 16, पंचकुला पृष्ठ 47
6. कात्यायनी 'अपराजिता' कविता <http://kavitakosh-org>

\*\*\*\*\*

## E-Waste, Problems, Consequences and Disposal Practices in India : A Review

Dr. Amar Kumar\*

**Abstract** - The aim of the study was to generate the data base of the E waste and disposal practices among residents of smaller cities city. It was revealed that general, the consumer awareness in smaller cities city is very poor and are not aware of the collection centres, the E-waste rules, and correct disposal practices. Consumers either mix-up the E-waste generated along with municipal solid waste or keep them in their homes as such, thereby leading to unsustainable way of disposal practices. In India, Ministry of Environment and Forests (MoEF) has played a key role by formulating the E-waste policy, but the influence of this policy in smaller cities is nonexistent. There is an urgent need to explore unlimited business opportunities and scope for developing sustainable models for E-waste management in smaller cities to deal with electronic waste.

**Keywords**- E-waste, consumers, awareness, disposal, management.

**Introduction** - Electrical and electronic equipment, known as e-waste, is a rapidly growing global problem. However, E-waste contains precious materials that have an economic value if recycled properly. The majority of e-waste is recycled in the unregulated informal sector and results in significant risk for toxic exposures to the women and children as they are mostly recyclers in developing countries (Brune *et al.*, 2013). The 2012 UN report revealed that by 2017 global e-waste will increase a further 33% from 49.7 million to 65.4 million tons per annum (MIT, 2014). E-waste from cell phones is expected to increase 18-fold by 2020 in India (Schluep *et al.*, 2009). The total amount of e-waste produced is exponentially increasing due to multiple factors. Consumer demand and a high obsolescence rate lead to frequent and unnecessary purchases of EEE (Gagliardi and Mirabile, 2011).

The per capita PC ownership between 1993 and 2000 has grown by 604% as against the world average of 181% during the same period in India (Sinha-Khetriwal *et al.*, 2005). The total PC base during this period has grown from an estimated 450,000 to 4,200,000 PCs (Sinha, 2004). However, Dwivedy and Mittal (2010) stated that contrary to the world average of 27 computers per 1000 people and over 500 computers per 1000 people in the US, India in the year 2004 had one of the lowest PC penetration rate at just 9 computers per 1000 people.

Nonetheless, the size of India's market in absolute terms is larger than most of the high income countries (Sinha-Khetriwal *et al.*, 2005) and hence although considered among the countries with lowest PC penetration rate, the generation of E-waste in the form of computer-waste could be significant. For example, India had about 20 million computers in 2007 and 2.2 million computers

had become obsolete in the same year (Chatterjee and Kumar, 2009).

Ministry of Environment and Forest (2008) stated that ten states generate 70% of the total E-waste generated in India. Maharashtra ranks first in the list of E-waste generating states in India followed by Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, West Bengal, Delhi, Karnataka, Gujarat, Madhya Pradesh and Punjab. Moreover, it has been reported in the document that sixty-five cities in India generate more than 60% of the total E-waste generated in India. Further, it listed ten major E-waste generator cities in the country. Among them, Mumbai ranks first followed by Delhi, Bangalore, Chennai, Kolkata, Ahmedabad, Hyderabad, Pune, Surat and Nagpur. Complementing this, a study conducted by MPCB (2007) states that Mumbai and Pune fall under the top ten cities that are generating maximum quantities and Mumbai alone generates maximum among all the cities of India. The city of Smaller cities is under going rapid transition and has adopted the digital culture very quickly and as such the electronic gadgets have become the part and parcel of life in the city of Smaller cities.

However, Individual consumer's awareness in smaller cities is one of the major challenges in the e-waste management as it is not only sufficient to frame and implement the regulatory framework which defines clearly the roles of various stakeholders.

Lack in consumer awareness and basic civic sense among the smaller cities residents may cause hurdle to manage the E-waste. The people who are mostly ignorant about the management of E-waste are becoming the easy victims to the pollutants from the electronic gadgets. Hence, the main aim of the present research is to generate

\* Associate Professor, Department of Physics, KR (PG) College, Mathura (U.P.) INDIA

information about the E-waste and its challenges in smaller cities.

**A. Management of e-waste: a Challenge** - Solid waste management, which is already a mammoth task in India, is becoming more complicated by the invasion of e-waste, particularly computer waste. There exists an urgent need for a detailed assessment of the current and future scenario including quantification, characteristics, existing disposal practices, environmental impacts etc of e waste in Smaller cities.

Institutional infrastructures, including e-waste collection, transportation, treatment, storage, recovery and disposal, need to be established, at national and/or regional levels for the environmentally sound management of e-wastes. Establishment of e-waste collection, exchange and recycling centers should be encouraged in partnership with private entrepreneurs and manufacturers.

The increase of electrical and electronic products consumption rates and higher obsolescence rate leads to higher generation of e-waste in Smaller cities. The increasing obsolescence rate of electronic products also adds to the huge import of used electronics products. Electrical and electronic waste (E-waste) is one of the fastest growing waste streams in the world. The increasing "market penetration" in developing countries, "replacement market" in developed countries and "high obsolescence rate" make e-waste one of the fastest growing waste streams in the world. The E-waste inventory based on the obsolescence rate in India for the year 2005 has been estimated to be 1, 46, 000 tonnes, which is expected to exceed 8, 00,000 tonnes by 2012.

Despite the fact that the E-Waste (Management & Handling) Rules were effective from 2012, there are still many challenges for environmentally Sound Management of e-waste in India, especially in small cities like smaller cities. There are several reasons for this including Government Apathy to implement rules, lack of authorized e-waste Recyclers, lack of awareness and inadequate implementation initiative. One of the major barriers in implementation legislation effectively is the consumer (both bulk and individual) awareness. Bulk consumers under the legislation are compelled to manage e-waste but the individual consumers are completely neglected.

Few people in smaller cities store cell phones at home as they believe that personal information in mobile phone could not be discarded immediately. In the case of other electronic gadgets people think that it is better to purchase new as the repair shops generally do not give any guarantee for repaired electronic gadgets.

The observations at the study area and in depth interviews with stakeholders revealed that general consumer awareness about e waste is very poor in Smaller cities and the disposal practices are not implemented as it was seen that E Gadgets are mixed with solid waste. Further, they are not aware of the rules, correct disposal practices and fail to dispose it in an environmental friendly

way. The awareness of the consumer is of most importance in the entire supply chain of E-waste as it will generate awareness of reuse, repair and recycle for sustainable e-waste management to protect the livelihood, health and environment. This study has limitations but the sample size considered indicates the fact that there is a urgent requirement to handle the e-waste and hence control its source of generation. The consumer awareness about the ill effects, benefits of reuse and recover approach may help to achieve the goals by develop a feelings to that precious metals can be obtained when recycled properly. This is the responsibility of every citizen by following Cradle to Grave approach. The Government needs to play its role as a regulatory agency by framing and implementing the rules that must be monitored very closely, especially in cities like smaller cities. The efficient collection of E waste is possible in smaller cities by the establishment of network system for collecting E-wastes with several collection agencies that must be built for adjoining producers, recycling companies, and local governments to exchange collecting E wastes information.

Beneficial recycling practice of E-Waste in Smaller cities can be improved by developing the recycling technologies. However, sustained efforts to develop the technologies to recycle E-wastes as secondary resources for recovering materials as well as to procure raw materials need to be developed and implemented in smaller cities.

**B. E-waste scenario in India** - Electronic waste or E-waste comprises of old, end-of-life electronic appliances such as computers, laptops, TVs, DVD players, refrigerators, freezers, mobile phones, MP3 players, etc., which have been disposed of by their original users. The growth in electrical and electronic equipment (EEE) production and consumption has been exponential in the last two decades. This has been as a result of the rapid changes in equipment features and capabilities, decrease in prices, and the growth in internet use. This creates a large volume of waste stream of obsolete electrical and electronic devices (e-waste) in developed countries.

There is high level of trans-boundary movement of these devices as second and electronic equipment into developing countries in an attempt to bridge the 'digital divide'. E-waste contains many hazardous constituents that may negatively impact the environment and affect human health if not properly managed. An assortment of apparatuses is engaged with the disassembling procedure for expelling the parts and recuperation of reusable or important parts and materials. Essentially the mechanical/ physical reusing forms honed include screening, shape partition, attractive division, electric conductivity-based detachment, thickness based division, and such different systems relying on the amount, sort, size and state of the material and part in E-waste (MPCB, 2007). Despite the fact that endeavors have been made to record E-waste reusing exercises in huge urban areas like Bangaluru, Chennai, Mumbai, New Delhi, and Pune by different natural

associations, contamination control sheets, regions, and so on with a specific end goal to feature the genuine ramifications of casual reusing to the earth as well as human wellbeing, still parcel of ground to be canvassed in this issue. The greatest disadvantage of the present E - waste framework in India is the uncontrolled emanation of toxins that are going into the air, water what's more, soil, which are neither evaluated nor checked. The wellbeing perils from vapour, fiery debris and unsafe chemicals influence not just the laborers who come into contact with the E-waste, yet additionally other people who are presented to the E-waste condition. The aggregate E-waste administration framework is work concentrated and the majority of the reusing what's more, recuperation activities are done utilizing obsolete advances what's more, forms, that may prompt arrival of uncontrolled outflow of poisons (EU, 2000), (SVTC, 2006). Based on the investigation and examination of the present E-waste arrangement of India, the drivers are brought up, that can decidedly (named 'facilitators') or contrarily (named 'limitations') adjust an existing E - waste administration framework in India.

The first phase of economic liberalisation, the problems associated with E-waste in India has started manifesting since 1990. The initial estimates carried out by National WEEE task force in 2005 recommend that total Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), generation in India is approximately 146,000 tonnes per year. The top states in order of highest contribution to WEEE include Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal, Delhi, Karnataka, Gujarat, Madhya Pradesh and Punjab. The ranked list of cities as WEEE generators are Mumbai, Delhi, Bangalore, Chennai, Kolkata, Ahmadabad, Hyderabad, Pune, Surat and Nagpur in the order (IRGSSA, 2005). A GTZ-MAIT Study in 2007, had put the approximation to 330,000 tonnes (GTZ-MAIT, 2007) and in 2009 various sources including (Heimbuch, 2009) has put the figures to 420,000 tonnes.

While the current (of 2010) E-waste production equipment wise as per the estimates of UNEP report 2010, is over 100,000 tonnes from refrigerators, 275,000 tonnes from TVs, 56,300 tonnes from personal computers, 4700 tonnes from printers and 1700 tonnes from mobile phones. The data only includes equipment generated nationally but does not include waste imports (both legal and illegal) which are extensive in emerging economies like India and China (UNEP report, 2010). Whereas, a report by Toxics Link (2004) said that at recycling units in New Delhi (India) itself, 70% of the total electronic waste collected was actually exported or discarded by developed countries (Toxic Link, 2004). While the GTZ-MAIT Study in 2007 estimates that around 50,000 tonnes of WEEE were imported to India every single year (GTZMAIT, 2007). There is a vital need to decide a plan for E-waste problem in developing country like India, as the UNEP 2010 report predicts that by 2020, E-waste from old computers in India will jumped by 500%; from discarded mobile phones will be about 18 times high;

from televisions will be 1.5 to 2 times higher; from discarded refrigerators will double or triple in future.

**Conclusion** - The paper proposed a national uniform E-waste administration framework for India in view of the present, social, temperate, word related and ecological situation, needs and prerequisites investigation in light of different effective practices, approaches followed in different nations. The proposed framework may prompt more formal and thorough control of the administrative specialist over the E-waste gatherers, merchants, recyclers, produces and importers- exporters of electronic machines. It might increase the E-waste gathering and prompt more proper utilization of assets including specialized aptitude and advances for better E-waste administration. The Indian E-waste framework requires a few changes for the naturally solid and directed logical handling of E -waste. Further, studies, contemplations and research are required for changing the strategies, council and laws identified with E-waste to suit the Indian situation. Additionally there exists a requirement for discovering the most ecological cordial reusing/transfer procedures and treatment choices for taking care of the E-waste containing the different poisonous and risky materials. Administration of E - waste, if appropriately completed, is an open door as it is regularly called as "urban mining." The part of open private organization (PPP) assumes a key part in creating and sorting out a sound E-waste administration procedure in India.

#### References:-

1. Brune MN, Goldizen F, Neira M, *et al.* (2013). Health effects of exposure to e-waste. *Lancet Glob Health*; 1:e70.
2. Chatterjee, S. and Kumar, K., (2009). Effective electronic waste management and recycling process involving formal and non-formal sectors. *International Journal of Physical Sciences*. 4(13): 893-905.
3. Dwivedy, M. and Mittal, R. K., (2010). Future trends in computer waste generation in India. *Waste Manage*. 30: 2265-2277.
4. Amoyaw-Osei Y., Agyekum O. O., Pwamang J. A., Mueller E, Fasko R, Schluep M. (2011). Ghana E-Waste Country Assessment. SBC E-waste Africa Project. Available: [http://ewasteguide.info/files/Amoyaw-Osei\\_2011\\_GreenAd-Empa.pdf](http://ewasteguide.info/files/Amoyaw-Osei_2011_GreenAd-Empa.pdf) [accessed 10 October 2014].
5. GTZ-MAIT, (2007). A study on E-waste assessment in the country. The German Technical Cooperation Agency (GTZ) and Manufacturer's Association for Information Technology Industry (MAIT) press release on date December 13, 2007. Available at: [http://www.mait.com/admin/press\\_images/press77-try.htm](http://www.mait.com/admin/press_images/press77-try.htm) (Last accessed on 4th May, 2008).
6. Heimbuch J. (2009). An article entitled India Struggling with Nearly Half a Million Tons of e-Waste and Growing, 2009. Published on date March 11, 2009. <http://www.treehugger.com/files/2009/11/india-struggling-with>



- nearly-half-a-million-tonsof-e-waste-and-growing.  
phpN.
7. IRGSSA. (2005). International Resource Group, Delhi. Country level WEEE assessment study by IRGSSA 2005
  8. Massachusetts Institute of Technology (MIT), (2013). National Center for Electronics Recycling (NCER). World e - waste map reveals national volumes, international flows. 2013. Available at: <https://www.vie.unu.edu/file/get/11505.pdf>. Accessed October 14, 2014.
  9. MOEF, (2008). Guidelines for Environmentally Sound Management of E-waste (as approved vide Ministry of Environment and Forests (MOEF) letter No. 23-23/2007-HSMD; 2008. dated March 12, 2008.
  10. MPCB, (2007). Report on Assessment of Electronic Wastes in Mumbai -Pune Area Maharashtra. Maharashtra Pollution Control Board.
  11. Schluep, M Christian Hageluekenb, Ruediger Kuehrc, Federico Magalinic, Claudia Maurerc, Christina Meskersb, Esther Muellera, Feng Wang. e-Waste generation and management in Uganda. 2008.
  12. Sinha, D., (2004). The management of electronic waste: A Comparative Study on India and Switzerland. (Master's Thesis, University of St. Gallen, 2004).
  13. Sinha-Khetriwal, D., Kraeuchi, P. and Schwaninger, M., (2005). A comparison of electronic waste recycling in Switzerland and in India. *Environ. Impact Assess. Rev.* **25**: 492-504.
  14. Toxic Link. Scrapping the hi-tech myth; computer waste in India; (2003). February 1, 2003 bhttp://www.toxiclink.org/pub-view.php?pubnum=37N.
  15. UNEP. (2010). A report — recycling — from E-waste to resources, 2010. Released by United Nations Environment Programme (UNEP); 2010 on date February 22, 2010.

\*\*\*\*\*

## विभाजन पर आधारित हिन्दी उपन्यासों का परिचयात्मक विवरण

डॉ. जयराम त्रिपाठी \*

**प्रस्तावना** – स्वतन्त्र भारत का उदय विभाजन के साथ हुआ। यह प्रथम अवसर था, जब धर्म के नाम पर संस्कृति को बाँटने का प्रयत्न किया गया और कहा गया कि मुसलमानों के लिए एक पृथक् राष्ट्र 'पाकिस्तान' होगा।<sup>1</sup> भारत ने धर्म निरपेक्ष स्वरूप अपनाया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिये गये।<sup>2</sup> विभाजन ने सदियों से साथ-साथ रहते लोगों के लिए अपना अलग राष्ट्र चुनने का विकल्प दिया था, जो व्यावहारिक स्तर पर बेमानी सिद्ध हुआ।<sup>3</sup> विभाजन की विभीषिका के बाद भारत में हिन्दू-मुसलमान सम्बन्धों में नये आयाम देखे गये।<sup>4</sup> ये आयाम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर रेखांकित किये गये।<sup>5</sup> हिन्दी के कई साहित्यकारों ने अपने उपन्यासों की कथावस्तु ऐसे वातावरण से ग्रहण की<sup>6</sup> और इन सम्बन्धों के विविध रूपों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया।<sup>7</sup> स्वतन्त्र भारत के कुछ प्रमुख उपन्यासों में अभिव्यक्त हिन्दू-मुसलमान सम्बन्ध एवं विभाजन को इस पृष्ठभूमि में देखना और भी प्रासंगिक होगा।<sup>8</sup> स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद लिखे गये कुछ प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं, जिनमें हिन्दू-मुसलमान सम्बन्धों का विविध स्तरों पर चित्रण हुआ है-

1. और इन्सान मर गया : रामानन्द सागर ( 1948 ई.)
2. झूठा सच : यशपाल ( 1958 ई.)
3. सती मैया का चौरा : भैरवप्रसाद गुप्त ( 1959 ई.)
4. लौटे हुए मुसाफिर : कमलेश्वर ( 1961 ई.)

**1. और इन्सान मर गया** – स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद विभाजन के दर्द एवं हिन्दू-मुसलमान द्वन्द्व की विभीषिका को रेखांकित करता हुआ हिन्दी का प्रथम उपन्यास रामानन्द सागर ने 'और इन्सान मर गया' नाम से लिखा इससे पूर्व वे उर्दू में लिखते थे। 'सागर उर्दू के लिए पुराने चाहे पर हिन्दी के लिए नये हैं।'<sup>10</sup> इस उपन्यास में विभाजन के बाद लाहौर में हुए दंगों, उनके प्रभाव एवं विस्थापन के दौरान मानवीयता को स्वार्थ-तले दबते-कुचलते दिखाया गया है। 'यह कथा भारत-पाक विभाजन के समय की यथार्थ स्थिति का चित्रण करती है। चारों ओर फैली हिंसा, घृणा, घायल मानवता, शारीरिक, मानसिक व आत्मिक रूप से टूटन आदि वस्तुस्थितियों का सजीव अंकन किया गया है।'<sup>11</sup>

इस उपन्यास में साम्प्रदायिकता के मूल तत्त्व को पहचानने की कोशिश की गयी है एवं अपनी सुरक्षा के लिए अभिजात वर्ग के लोगों द्वारा अपनाये जाने वाले हथकण्डों की ओर इशारा किया गया है। रामानन्द सागर ने अराजक नौजवानों द्वारा तांगेवाले को जिन्दा जला दिये जाने के वर्णन से यह दिखाने की कोशिश की है कि इन दंगों से वह वर्ग अधिक प्रभावित होता है, जिसका उन विवादों से कुछ लेना-देना नहीं होता और जो धर्म एवं मजहब को मानवीयता के आड़े नहीं आने देता। रामानन्द सागर के इस

उपन्यास में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार को एकांगी करके दिखाया गया है। अभिजात वर्ग के षड्यंत्र को क्लार्क पहचान लेता है- 'मैं जानता हूँ कि कोई भी यहाँ सच्चे दिल से कौम की खातिर नहीं बैठा हुआ है। सब अपने-अपने स्वार्थ से मजबूर हैं और अगर कोई सचमुच ही यह समझता है कि वह कौम के लिए कुछ कर रहा है, तो वह मूर्ख है, इन पूँजीपतियों के हाथों में खेलकर दूसरों की धन-सम्पत्ति बचाने के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल रहा है।'<sup>12</sup> क्लार्क की इस मानवीय और व्यापक समझ के बावजूद दंगे होते हैं, लोग विस्थापित होते हैं और मानवीयता मरती रहती है। आनन्द इस भयावह माहौल में मानवीयता के मसीहा की भूमिका निभाता है। यद्यपि उपन्यास में मुसलमान आतातायी दिखाये गये हैं, लेकिन मौलाना एवं रहमान इन आतातायी मुसलमानों के बीच भी मानवीयता की मिसाल बनकर आते हैं। मौलाना साहब तो अपनी जान पर खेलकर कई हिन्दुओं की रक्षा करते हैं। तमाम अमानवीय वातावरण में ये पात्र प्रेम और सौहार्द का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

रामानन्द सागर का यह उपन्यास रोमानी भावुकता के बीच यथार्थ की तस्वीर प्रस्तुत करता है और मानवीयता की हत्या होते हुए चित्रित करता है। चमनलाल इसे 'हिन्दी फ़िल्मों की कहानी-जैसा सामान्य उपन्यास'<sup>13</sup> मानते हैं। रामानन्द सागर की ख्याति वैसे भी एक फ़िल्मकार और धारावाहिक निर्माता की है। इनके इस उपन्यास में भी फ़िल्मी पुट है। यह उपन्यास स्वतन्त्रता-प्राप्ति के तुरन्त बाद लिखा गया था इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्त्व ज़्यादा है।

**2. झूठा सच (1958ई.)** – यशपाल रचित दो खण्डों में झूठा सच भारत के विभाजन की त्रासदी एवं हिन्दू-मुसलमान सम्बन्धों की व्याख्या करने वाला महत्त्वपूर्ण उपन्यास है। हरिमोहन शर्मा इसे 'विभाजन की त्रासदी की महागाथा' के अतिरिक्त 'बीसवीं शताब्दी के चौथे-पाँचवें दशक के हिन्दुस्तानी जीवन की लय, उसकी मार्मिक और प्रामाणिक छवि प्रस्तुत'<sup>14</sup> करने वाला उपन्यास मानते हैं। यशपाल ने इस उपन्यास में देश के बँटवारे के समय और उसके पहले तथा बाद में साम्प्रदायिक विभीषिका में जलते लोगों का मार्मिक चित्रण किया है।

लाहौर के भोला-पांथे की गली से झूठा सच की कथा शुरू होती है और आजादी की विभीषिका का साक्षात् कराती तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक जीवन का आईना बनती है। इस उपन्यास का प्रथम खण्ड 'वतन और देश' तथा द्वितीय खण्ड 'देश का भविष्य' नाम से आया। 'वतन और देश' नाम सम्भवतः दिया ही इसलिए गया है कि वतन लाहौर में लम्बे समय से रह रही हिन्दू-मुसलमानों की पीढ़ियाँ, एक-दूसरे के दुःख-दर्द में काम आती, एक-दूसरे से घुलती-मिलती, एक ऐसे स्वतः स्फूर्त समग्र समाज का

\* सहा. प्रोफेसर, हेमवती नंदन बहु. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नैनी, प्रयागराज (उ.प्र.) भारत

निर्माण किये हुए थीं- जिससे अलग होने की कल्पना स्वप्न में भी नहीं की जा सकती थी।<sup>15</sup> लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनीं कि 'वतन' तो छूटा ही, लम्बे समय से साथ-साथ जीते आ रहे सहअस्तित्व एवं भाईचारे का सूत्र भी टूट गया। लाहौर की भोला पांथे की गली, जहाँ हिन्दू-मुसलमानों के घर आपस में सटे हुए थे और जिनके सामाजिक सबन्ध मधुर थे, उसी गली में दो औरतें हिन्दू रक्षा कमेटी से आती हैं और कलकत्तो में हो रहे दंगों का अतिरंजनापूर्ण वर्णन करती हैं<sup>16</sup> तथा लोगों में मुसलमानों को लेकर फैली अफवाहों को हवा दे जाती हैं।<sup>17</sup>

यशपाल अनेकशः इंगित करते हैं कि हिन्दू-मुसलमान साथ-साथ रहते हैं, लेकिन उनमें बुनियादी विषमताएँ हैं और ये बुनियादी विषमताएँ कहीं गहरे अन्तर्मन में जाकर बैठ गयी हैं। 'झूठा सच की मौलिकता इस तथ्य में अन्तर्निहित है कि इसका कथा वृत्तान्त विभाजन के उस महाआख्यान को ही ध्वस्त करता है, जो उसे महज अंग्रेजों की चाल और मुस्लिम लीग की मजहबी माँग तक सीमित करता है।' यशपाल हिन्दू-मुस्लिम भाईचारे की ऊपरी सतह को खुरचकर उन कुरूप सच्चाईयों को उजागर करते हैं, जिनके बिना विभाजन के आख्यान को नहीं समझा जा सकता। लाहौर की भोला पांथे की जिस गली की हलचलों से झूठा सच के पृष्ठ खुलते हैं, वहाँ हिन्दू रक्षा समिति की महिलाओं के मुस्लिम विरोधी प्रचार का सफल होना गली की भोली महिलाओं की भोली समझ का परिणाम मात्र नहीं है। इसके मूल में है हिन्दू-मुसलमानों के बीच आशंका, घृणा और ऊँच-नीच की वह दीवार जो हिन्दू धर्म की श्रेष्ठता और मुस्लिम उत्पीड़न की ग्रन्थि पर टिकी है।<sup>18</sup>

यशपाल झूठा सच में हिन्दू-मुसलमान सम्बन्धों के सौहार्दपूर्ण न हो सकने के लिए हिन्दुओं की सवर्ण मानसिकता एवं आर्थिक सम्पन्नता को जिम्मेदार तो मानते ही हैं<sup>19</sup>, वे यह भी रेखांकित करते हैं कि रोटी एवं बेटी के स्तर तक इन सम्बन्धों की व्याप्ति न हो सकने के लिए समुदाय के प्रगतिशील लोगों की रूढ़िवादी मानसिकता आड़े आ जाती है। पुरी अपनी प्रेम की सफलता के लिए अपनी बहन तारा का सहयोग तो लेता है, लेकिन तारा के असद के प्रति आकर्षण जानकर तिलमिला उठता है। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी दौंव पर लगती दिखायी देती है। वह उधेड़बुन में है- जोड़ लगाया भी तो मुसलमान से और सामने कैसी घृष्टता से बोली। हमारा मुँह काला करायेंगी? 'कनक ने सामाजिक स्तर के भेद के आधार पर अपना प्रणय लौटाकर उसे अपमानित किया था और उसके परिवार पर कलंक लगा रही थी। उसके पास घर नहीं था, वैभव नहीं था, पद नहीं था, केवल बदनामी न होने का सम्मान था। तारा उसी को कलंकित कर रही थी।'<sup>20</sup>

यशपाल के इस महाकाव्यात्मक उपन्यास में हिन्दू-मुसलमान सम्बन्धों में घृणात्मक आचरण के लिए अन्धविश्वास, मूढ़ता और धर्म के आधार पर निर्मित होने वाले संस्कारों से उत्पन्न अमानवीयता, असंवेदनशीलता, चारित्रिक अवसरवादिता को जिम्मेदार ठहराया गया है। यशपाल विभिन्न पात्रों के माध्यम से इसे प्रस्तुत करते हैं। उपन्यास का एक प्रमुख पात्र प्रो. प्राणनाथ साम्प्रदायिक घृणा एवं विद्वेष का मूलगामी विश्लेषण करता है और इस व्यवहार के मूल कारण में हिन्दू समाज की असहिष्णुता और मुसलमानों के प्रति घृणा को देखता है। डॉ. हरदयाल मानते हैं कि 'मुसलमान अगर न होते, तो यह समस्या अस्पृश्यता के स्तर पर देखने को मिलती। 'मुसलमान न सही अद्वैत ही समस्या बन जायेंगे।'<sup>21</sup>

झूठा सच में यशपाल ने विभाजन की महागाथा को प्रामाणिक बनाए एवं कथा-संयोजन के लिए कई हिन्दू पात्रों के साथ मुसलमान पात्रों की रचना की है। असद-जैसे पात्र प्रगतिशील विचारधारा से ओत-प्रोत हैं और

साम्प्रदायिकता के मुद्दे पर बेबाक टिप्पणी करते हैं। जुबेर, जुबैदा आदि पात्र हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए प्रयासरत हैं। असद की सुलझी दृष्टि द्रष्टव्य है- 'अगर धर्म या सम्प्रदाय के विश्वासों की पृथक्ता के बावजूद हिन्दू-मुसलमानों के सामाजिक सम्बन्ध होते रहें, तो आपसी झगड़ा कितना कम हो जाये। वास्तव में हिन्दू या मुसलमान साम्प्रदायिक विश्वास को ग्रहण करने का कुछ अर्थ भी तभी होगा।'<sup>22</sup> हिन्दू-मुसलमान का भेद न माननेवाला असद शरणार्थी कैम्प में तारा की स्थिति जानते हुए भी विकट परिस्थितियाँ खड़ी करता है- 'अपने-आपको हिन्दू कहकर तो तुम लाहौर में रह नहीं सकती।'<sup>23</sup> वह भी तारा को उसके हाल पर छोड़ देता है। यशपाल ने नब्बू एवं हाफिज-जैसे पात्रों की सृष्टि भी की है। नब्बू, तारा से यह कहते हुए बलात्कार करता है कि हिन्दू औरत ही तो खराब है।<sup>24</sup> जैसे हिन्दू औरत न हो या कि बलात्कार के लिए उसे सिर्फ इसलिए छूट मिल जाती है कि वह हिन्दू है। हाफिज जी तारा पर मुसलमान हो जाने के लिए दबाव डालते हैं।<sup>25</sup> लेकिन जैसा कि नासिरा शर्मा मानती हैं- 'हिन्दू-पंजाबी समाज से किरदार उठाते हुए यशपाल जी ने विविधता का विशेष ध्यान रखा है। मगर मुसलमान पात्रों के चयन में यशपाल जी से कहाँ पर चूक हुई है कि उन्हें एक भी ऐसा पात्र नज़र नहीं आया जो गाँधी जी के कथनानुसार देशभक्त होता या रफी अहमद किदवाई या अबुल कलाम आज़ाद का अवस होता या फिर पुरी की तरह ही कोई छत्र इंकलाबी होता या फिर ऐसा कोई वैचारिक संगठन होता जिसमें हम बच्चे भाई, अली सरदार ज़ाफरी, कैफ़ी आज़मी को झलकेता-उबला देख पाते, खासकर जब उपन्यास का काफी हिस्सा लखनऊ को समेटता है। मण्टो की तरह वह (तोबा टेकसिंह) एक भी किरदार ऐसा न दे सके, जो मुसलमान हो और उसे बँटवारा नहीं चाहिए।'<sup>26</sup>

यशपाल के झूठा सच में यह बात भी महसूस की जाती है कि पंजाब की हिन्दू-मुसलमान एकता की संस्कृति भी नहीं देखने को मिलती- 'सदा से यह कहा जाता है कि पंजाब के हिन्दू-मुसलमानों में बड़ा एका था। यह देखने को भी मिला, जब पाकिस्तान में भारतीय हिन्दू पंजाबी, पाकिस्तानी मुस्लिम पंजाबी से मिलता है और उसी तरह मुसलमान पाकिस्तानी पंजाबी हिन्दुस्तान में हिन्दू पंजाबी से जिस तरह मिलते हैं, उनकी खुशी और उमंग छिपी नहीं रहती। उससे उनका शीर व शक्कर होना झलकता है। मगर वह अपनापन जो उस दौर के पंजाब का गुण हुआ करता था, पूरे उपन्यास में कहीं दर्शाया नहीं गया।'<sup>27</sup>

यशपाल ने दंगों का वर्णन करते हुए भी तारा एवं बन्तो सरीखी हिन्दू लड़कियों पर होते हुए अत्याचार का तो विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन मुसलमान चरित्रों की ओर सूचना देकर रह गये हैं। उनके विवरण में संवेदनात्मक स्पर्श का अभाव परिलक्षित होता है। उन्होंने दंगे के शिकार लोगों के विषय में चर्चा करते हुए हिन्दू-मुसलमान दोनों समुदायों की बात की है, लेकिन सम्बन्धों की आर्थिक विषमताओं को उभारने में ज़्यादा सफल रहे हैं- 'हिन्दू सिख लाये हैं बक्से, सन्दूक, नकदी, ज़ेवर और बाण्ड। यह लोग मिट्टी के हुक्के, टूटी चारपाइयाँ, चूल्हे, चक्की, मुर्गियाँ लिये चल रहे हैं। यही इनकी गृहस्थी थी। जिसके पास जो कुछ होगा उसी से ममता करेगा, वहीं तो उठाकर ले जायेगा। ठीक ही कहते थे, होते का नाम हिन्दू, मुफसिली का मुसलमान।' लेकिन विभाजन की इस महागाथा में मुसलमान पात्र सहानुभूति से अछूते रह गये हैं।

**3. सती मैया का चौरा (1950 ई.)** - भैरवप्रसाद गुप्त का यह उपन्यास मन्ने एवं मुन्नी दो पात्रों के बहाने एक गाँव की तीन पीढ़ियों की कथा कहता है और सामन्ती व्यवस्था के विघटन एवं नयी समाजवादी व्यवस्था के निर्मित

की कथा कहता है। 'सती मैया का चौरा' मन्ने एवं मुन्नी दो मित्रों की कथा है। मन्ने मुसलमान है और सामन्ती व्यवस्था का भग्नावशेष, मुन्नी हिन्दू है और एक सुलझा हुआ समाजवादी। दोनों की मित्रता एक ऐसी गुथी सुलझाते हुए होती है, जो हिंदुओं एवं मुसलमानों में अलग-अलग अवधारणाओं के साथ व्यास है। यह गुथी है तम्बाकू की फसल को लेकर। उनके पहले परिचय का वार्तालाप हिन्दू-मुसलमान मनोग्रन्थि को सहजता से प्रकट करता है-  
'दुत ! वे तो रोएँ हैं-कहकर वह हँस पड़ा।  
-नयी, ये गाय के बाल हैं।-उस लड़के ने आँखें मटकाते हुए कहा।  
-लेकिन मैं तो सुअर के बाल खोज रहा हूँ।  
-तो क्या तुम मुसलमान हो? उस लड़के ने कहा।'<sup>29</sup>

मन्ने के पिता मियाँ गाँव की छीजती ज़मींदारी व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं। उनके लिए मनुष्यता का बोध सर्वोपरि है इसलिए हिन्दू-मुसलमान ज़्यादा महत्त्व नहीं रखता है। वे मन्ने एवं मुन्नी की मित्रता को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं और मन्ने की 'हिन्दी' पढ़ने की इच्छा को धार्मिक संकीर्णता के दायरे से बाहर रखकर देखते हैं। कैलसिया की इज़ज़त ख़राब होने पर वे न सिर्फ उसे शरण देते हैं, सम्मान का पात्र बनाते हैं, अपितु अन्याय के प्रतिकार हेतु मानवीयता का साथ धर्म के मामले से ऊपर उठकर देते हैं। अपने जीवन के उतार-चढ़ाव के मध्य मन्ने गाँव में एक स्कूल खोलता है और शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण पहल करता है। मुन्नी का इसमें सहयोग मिलता है। इस स्कूल पर कब्ज़ा करने के उद्देश्य असफल रहने पर गाँव के कुछ लोग जिनमें जुबली मियाँ-जैसे मुसलमान भी शामिल हैं, उपेक्षित पड़े सती मैया के चौरा के बहाने गाँव में साम्प्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। 'मुन्नी साम्प्रदायिकता की दहकती आग में उसे शान्त करने कूद पड़ता है। वह अपनी ऐतिहासिक भौतिकवादी समझ के आधार पर उन्हें बताता है-असल में यह लड़ाई ऊपर तबको की है और हमारे देश को सामन्तवाद की देन है।'<sup>30</sup> मुन्नी साम्प्रदायिकता की समस्या को धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक मानता है और उसके मत में- 'सही राजनीति ही साम्प्रदायिकता का अन्त कर सकती है।'<sup>31</sup> उसके मत में सही राजनीति-समाजवादी व्यवस्था में है। उसके अनुसार- 'साम्प्रदायिकता इलाज केवल वर्ग-चेतना है। उपदेश नहीं, सुधार नहीं, धर्मों का समन्वय नहीं।'<sup>32</sup> साम्प्रदायिक उन्माद को वर्ग-चेतना से मन्ने दबाने में तो सफल हो जाता है। उसके प्रयास में ग्रामीण विकास के प्रतीक रूप में नहर भी निकालने की सरकारी परियोजना शुरू हो जाती है, लेकिन मन्ने को इसकी कीमत घायल होकर चुकानी पड़ती है।

भैरवप्रसाद गुप्त ने 'सती का चौरा' उपन्यास में हिन्दू-मुसलमान सम्बन्धों को प्रसिद्ध विचारक कार्ल मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी सिद्धान्त पर देखने-परखने की कोशिश की है। वस्तुतः 'भैरवप्रसाद गुप्त ने अपने उपन्यासों में सामन्तवादी अर्थोत्पादन और सामाजिक सम्बन्धों पर चोट की है। फलस्वरूप साम्प्रदायिक वैमनस्य की बुनियादी स्थितियाँ अपेन-आप ही सामने आ गयी हैं।'<sup>33</sup> भाषा-समस्या, सामन्ती व्यवस्था, कांग्रेसी राजनीति आदि के बहाने भैरवप्रसाद गुप्त ने हिन्दू-मुसलमान द्वन्द्व को सफलता से चित्रित किया है उसके प्रयास में दोनों समुदायों में फैल रही वैमनस्यता के मूल उत्स की पहचानने की कोशिश की है। सही राजनीति को वे समुदायों के सह-अस्तित्व के लिए जरूरी मानते हैं। वस्तुतः वर्गभेद के आधार पर सम्बन्धों को देखने की भैरवप्रसाद गुप्त की दृष्टि इतनी फार्मूलाबद्ध है कि पूरा उपन्यास सैद्धान्तिक आख्यान बनकर रह जाता है।

**4. लौटे हुए मुसाफ़िर (1961 ई.)** - कमलेश्वर रचित 'लौटे हुए मुसाफ़िर' साम्प्रदायिकता पर चोट करनेवाला अपने ढंग का एक अनूठा

उपन्यास<sup>34</sup> है। इस उपन्यास में कमलेश्वर ने एक ऐसी बस्ती में रहनेवाले लोगों को लेकर कथानक बुना है, जिसने 'अट्टारह सौ सत्तावन में अंग्रेजों से लोहा लिया था। हर कौम और मज़हब के लोगों ने कन्धे-से-कन्धा मिलाकर गोलियों की बौछार सीनों पर झेली थी।'<sup>35</sup> इस बस्ती का सामाजिक ताना-बाना कुछ ऐसा था कि 'जब रामलीला का विमान उठता था, तो मुसलमान औरतें दरवाज़ों की चिकें या बोरों के पर्दे उलटकर मूर्तियों के शृंगार की तारीफ़ करती थीं और उनके बच्चे विमान के साथ दूर तक शोर मचाते हुए आया करते थे-बोल राजा रामचन्द्र की जै! लेकिन सिर्फ नफ़रत की आग ने इस बस्ती को जलाया था।'<sup>36</sup> यह नफ़रत की आग कतिपय कट्टरपन्थी लोगों ने लगायी थी और आतंक का वातावरण पैदा कर दिया था, जिससे वर्षों से चली जा रही सहिष्णुता समाप्त हो रही थी।

कमलेश्वर इस उपन्यास के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि विभाजन के लिए राजनीति उत्तरदायी है। मुस्लिम धुवीकरण वस्तुतः विभाजन के प्रश्न पर ही होता है। बस्ती के अधिकांश लोग अपने 'मुलुक' के लिए ही पलायन करते हैं। उपन्यासकार ने विभाजन के दौरान बस्ती छोड़कर चले गये लोगों को अन्त में वापस लौटते हुए दिखाया है, हालाँकि 'विभाजन की स्थिति और उसके कारणों को स्पष्ट करने के लिए उसमें मुसाफ़िरों का लौटना उतना ज़रूरी नहीं है जितना लेखक का यह कहना- 'गरीबी, अपमान, भूख और बेबसी में भी वे हारे नहीं थे पर नफ़रत की आग और शंकापूर्ण धुआँ ये बर्दाश्त नहीं कर पाये और उनके काफिले एक अनजान देश की ओर चले गये।'<sup>37</sup> लौटे हुए मुसाफ़िर' बेहद सामान्य तरीके से हिन्दू-मुसलमान द्वन्द्व को तीखे स्तर पर उभारता है और साम्प्रदायिकता के निहितार्थ को बेनकाब करता है।

#### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इण्डिया विनस फ्रीडम, उद्धृत-असगर अली इंजीनियर, भारत में साम्प्रदायिकता : इतिहास और अनुभव, पृ. 103
2. असगर अली इंजीनियर, भारत में साम्प्रदायिकता : इतिहास और अनुभव, पृ. 104
3. राम पुनियानी, साम्प्रदायिक राजनीति : तथ्य एवं मिथक, पृ. 77
4. असगर अली इंजीनियर, भारत में साम्प्रदायिकता : इतिहास और अनुभव, पृ. 15
5. अभय कुमार दुबे, क्षेत्रीय समर्थन की तलाश में हिन्दुत्व, साम्प्रदायिकता के ख़ोत, पृ. 119
6. विपिनचन्द्र, आज़ादी के बाद का भारत, पृ. 57
7. असगर अली इंजीनियर, भारत में साम्प्रदायिकता : इतिहास और अनुभव, पृ. 115
8. राही मासूम रज़ा, सिनेमा और संस्कृति, पृ. 124-125
9. भूमिका, उपेन्द्रनाथ अशक, और इन्सान मर गया, पृ. 14
10. संतोष गोयल/उषा कस्तूरिया, हिन्दी उपन्यास कोश, पृ. 699
11. रामानन्द सागर, और इन्सान मर गया, पृ. 82
12. चमनलाल, कथा आलोचना, शताब्दी कथा साहित्य, पृ. 165
13. हरिमोहन शर्मा, विभाजन की त्रासदी की महागाथा, वर्तमान साहित्य, पृ. 340
14. हरिमोहन शर्मा, विभाजन की त्रासदी की महागाथा, वर्तमान साहित्य, पृ. 340
15. हरिमोहन शर्मा, विभाजन की त्रासदी की महागाथा, वर्तमान



- साहित्य, पृ. 340
16. 'सुनो कुड़ियों, बहिन जी कह रही हैं, कलकत्तो के बंगाल में मुसलमानों ने दस हजार हिन्दू भाई कत्ल कर दिये हैं। बाजारों में बहन-बेटियों के कपड़े उतारकर सौ-सौ बेईमान मुसलमानों ने हिन्दू औरतों.... झूठा सच, खण्ड-1, पृ. 52
  17. 'मुसलमान मरे खूब तैयारी कर रहे हैं। पानी के नल कटवा-कटवाकर बन्दूकें बना रहे हैं। मुसलमानियों ने भी छूरे रख लिये हैं। हमी लोग सोये हुए हैं।' पृ. 52
  18. वीरेन्द्र यादव, झूठा सच : राष्ट्रवाद मुस्लिम अलगाववाद और नारी प्रश्न, तद्भव-1, पृ. 22
  19. 'लाहौर में मुसलमान इक्यावन फीसदी हैं तो क्या हुआ जमीन-जायदाद तो अस्सी फीसदी से ज्यादा हिन्दुओं की है।' झूठा सच, खण्ड-1, पृ. 195
  20. यशपाल, झूठा सच, खण्ड-एक, पृ. 188
  21. यशपाल, झूठा सच, खण्ड-एक, पृ. 2100
  22. यशपाल, झूठा सच, खण्ड-एक, पृ. 67
  23. यशपाल, झूठा सच, खण्ड-एक, पृ. 407
  24. यशपाल, झूठा सच, खण्ड-एक, पृ. 317
  25. यशपाल, झूठा सच, खण्ड-एक, पृ. 323
  26. नासिरा शर्मा, भारतीय मुस्लिम समाज और झूठा सच, भारतीय साहित्य, यशपाल विशेषांक, पृ. 271
  27. नासिरा शर्मा, भारतीय मुस्लिम समाज और झूठा सच, भारतीय साहित्य, यशपाल विशेषांक, पृ. 272
  28. यशपाल, झूठा सच, खण्ड-एक, पृ. 412
  29. भैरवप्रसाद गुप्त, सती मैया का चौरा, पृ. 16
  30. कुँवरपाल सिंह, सती मैया का चौरा, जनसंघर्ष के आयाम, पृ. 169
  31. सती मैया का चौरा, पृ. 377
  32. सती मैया का चौरा, पृ. 414
  33. राजेश्वर सक्सेना, इतिहास कथा और भैरवप्रसाद गुप्त के उपन्यास, विद्याधर शुक्ल (सं.), भैरव प्रसाद गुप्त व्यक्ति और रचनाकार, पृ. 800
  34. डॉ० वीरेन्द्र सक्सेना, कमलेश्वर की औपचारिक यात्रा, (सं.) मधुकर सिंह-कमलेश्वर, पृ. 192
  35. कमलेश्वर, लौटे हुए मुसाफिर, पृ. 1
  36. कमलेश्वर, लौटे हुए मुसाफिर, पृ. 2
  37. डॉ० वीरेन्द्र सक्सेना, कमलेश्वर की औपन्यासिक यात्रा, पृ. 193

\*\*\*\*\*

# Mineral Consumption in Different Socio- Economic Status of Urban Population in Moradabad City

Dr. Shobha Gupta\*

**Introduction** - Mineral intake is the most important factor affecting nutritional status of a community and it varies among people belonging to different economic status(1). Diversified dietary pattern and better mineral intake has been found in well to do population groups as compared to low income groups(2,3). Purchasing power or economic factors are one of the major factor influencing food consumption of people (4,5). The usual diet intake in India, may be classified as cereals, pulses, vegetables, fruits, milk and milk products and flesh foods (fish, meat and poultry)(6). Since all foods are not of same quality from a nutritional point of view, man's ability to meet his nutritional needs and maintain good health depends upon the type and quantity of food stuffs(7,8,9). For sustaining healthy and active life, diet should be planned on sound nutritional principles(10). Studies have shown that quantity and quality of food intake has been improved as income of people increased. Therefore, the present study was undertaken to study the dietary intake and food expenditure of urban families in relation to their income.

**Subjects and Methods:** Six colonies of Moradabad city were selected at random. A list of 61 families consisting of 385 individuals were selected. These families were then classified according to the income. The respondents were assured that information provided by them would be kept confidential. The food expenditure pattern of the families was evaluated from the record of quantity of food items consumed by them per month. The local prices were recorded to calculate total money spent on food purchased. The dietary survey was conducted by 24 hour recall method. One day's dietary intake of all the food items of families was recorded personally after questioning the respondent who was actually cooking and serving the food. The information regarding family members and guests who shared the meals, wastage and leftover was recorded.

The nutrient value of raw foods consumed by the members was calculated using Food Composition Table (11). Food and nutrient intake was compared with ICMR recommendations. Results were statistically analysed.

**Result and Discussion:** Food Expenditure Pattern, total money spent on diet ranged from rs 5000 to rs 30000 per family as given in table 1. The lower class families spent 80 percent of income on food whereas middle and high

class families spent 37 and 20 percent of their income on food.

**Income and Food:** The daily intake of various food-stuffs per consumption unit is depicted in Table 2. The intake of cereals was inadequate as compared to suggested least cost balanced diet by ICMR(10) by all the income groups. It was highest in lower income group and decreased as the income increased but not consistently. The average intake of all the food groups by the various income groups was adequate except for the low income group who was taking low amount of pulses, root and other vegetables than the values as suggested by least cost balanced diet. An inverse but non-significant correlation was found between income and the quantity of cereal consumed. A positive but non-significant correlation between income and pulses, green leafy vegetables, root vegetables, other vegetables and sugar & jiggery was obtained as given in Table 2.

The consumption of milk was adequate in all the income groups and was significantly correlated with the income. The intake of fats and oils was lower in all the income groups than the suggested values. However there was a positive correlation between the income and intake of fats and oils. The intake of meat, fish and eggs was nil by the lowest income group, however the intake increased as presented in Table 2.

**Income and Nutrient:** The average intake of energy and protein increased with the increase in income as given in table 3. The intake was found to be positively and significantly correlated with income. The overall energy intake was deficient in all the income groups whereas protein intake was adequate in respect of various income groups as compared to recommended dietary intake of ICMR (10).

The intake of iron and calcium and magnesium by the various income groups was adequate as compared to its recommended dietary intake. There was a positive and highly significant correlation between income and calcium intake as depicted in Table 3. The intake of Zinc was lower than recommended by ICMR.

**Table 1,2 & 3 (see in next page)**

**References:-**

1. Cristiane h Sales et al : Inadequate dietary intake of minerals: prevalence and association with socio-

\*Associate Professor (Chemistry) D.A.K. College, Moradabad (U.P.) INDIA

- demographic and life style, British Journal of Nutrition 2017
- Sen A. and Himanshu : Poverty and Inequality in India: Economic and Political weekly. Vol. 39 No. 38 2004 pp- 4247-4263
  - Atibudhi H.N. : A comparative analysis of food consumption and monthly percapita expenditure of Orissa vis a vis all India. Indian Journal of Agriculture Economics. Vol. 61 No. 3. 2006 pp 309-316.
  - Deshmukh Tasker P., Niklas T.A., Yang S.J.: Does food consumption vary by differences in socioeconomic, demographic and life style factors in young adults? The Bangladesh Heart Study. Journal of American Diet Association Vol 107 No. 2 2007 pp 223 – 234.
  - Radhakrishna R: Food consumption and nutritional status in India: Emerging Trends and perspectives. Indira Gandhi Institute of development Research, Mumbai, 2006 pp 1-18
  - Arun P : A study on Food consumption pattern by the consumers. International Research Journal of Engineering and Technology, Vol 07 Issue 04, 2012 pp 4205-4209
  - Chadha R and Mathur P : A text Book on Nutrition, A Lifecycle Approach. Published by Orient Blackswan Private Limited, New Delhi. 2015.
  - Hoddinot J. Measuring dietary diversity: A guide, Food and Nutrition Technical Assistance Academy for Educational Development. International Food policy Research Institute, Washington D C. 2002.
  - Vakili M, Abedi P, Shrif M and Hosseini M: Diet Diversity and its Related Factors among Adolescents, A survey in Ahvaz-Iran. Global Journal of Health Science Vol 5 No. 2 2013
  - ICMR Recommended Dietary Intakes for Indians published by ICMR. New Delhi 1981:52
  - Narsinga Rao BS, Deosthale YG and Pant KC, Nutrient composition of Indian Foods. National Institute of Nutrition ICMR, Hyderabad, 1989

**Table 1- Income and Food expenditure incurred by families**

Income group Rs	Average Income Rs	Expenditure on food Rs	% of income spent on food
5000	4000	3200.9	80.0
5001 - 10000	8120	5724.1	70.5
10001- 15000	13120	7192.2	54.8
15001-20000	18240	8795.2	48.2
20001- 30000	25280	9458.9	37.4
30001- above	47670	9947.5	20.1

**Table 2- Daily intake of food items per CU according to income groups**

Food groups	Income groups Rs						Average RDI	
	5000	5001- 10000	10001- 15000	15001- 20000	20001- 30000	30000- above	Intake	
Cereals gm	468±32	381±26	392±20	389±36	338±27	334±22	384±27	520
Pulses gm	33±10	54±5	54±3	65±6	59±7	61±4	54±6	50
Green leafy veg. g	75±22	85±12	77±15	81±10	115±17	109±15	90±15	40
Root vegetables g	53±16	99±17	99±5	96±16	97±14	86±15	88±16	60
Other vegetables g	38±14	71±20	103±41	95±14	110±20	112±15	88±16	70
Fruits gm	12±3	29±4	31±3	70±6	65±3	126±3	56±3	-
Milk and milk products ml	321±40	375±29	403±26	528±46	467±29	505±30	433±33	200
fats and oils g	12±3	28±2	32±2	37±3	34±2	42±3	31±3	45
sugar & jiggery g	56±6	69±3	73±3	81±5	65±4	67±4	69±4	35
Meat, fish or egg	-	1.5±5	1.7±3	2.0±1	3.2±1	4.0±2	±	-
Nuts & oil seeds g	-	-	-	1±1	2±2	5±1	1.0±5	-

**Table 3- Mean daily intake of nutrients per CU according to income groups**

Nutrient	Income groups Rs						Average RDI	
	5000	5001- 10000	10001- 15000	15001- 20000	20001- 30000	30000- above	Intake	
Energy Mj	10.±0.5	10.1±0.3	10.8±0.3	11.7±0.5	11.5±0.4	11.3±0.3	10.9±0.4	12.0
Protein gm	74±9	79±5	82±5	87±8	96±8	97±8	86±6	60
Iron mg	27±2	29±1	32±2	31±2	33±2	32±3	31±2	28
Calcium g	0.3±0.	0.3±0.1	0.4±0.1	0.4±0.2	0.5±0.1	0.5±0.2	0.4±0.1	0.4
Magnesium g	0.2±0.1	0.2±0.1	0.3±0.1	0.3±0.2	0.4±0.2	0.4±0.1	0.3±0.1	0.3
Zinc mg	13±1	13±1	14±2	14±2	14±2	15±2	14±2	15

\*\*\*\*\*

## कला एवं संगीत का अन्तरंग सम्बन्ध

**डॉ. नीतू वशिष्ठ\* नेहा गुप्ता\*\***

**प्रस्तावना -**

**'साहित्य संगीत कला विहिनः॥**

**साक्षात् पशुपुच्छ विपाणहीनः॥'**

'कलाओं की उत्पत्ति आदिम अवस्था में आत्मकाभिव्यक्ति, अलंकरणप्रियता, प्रकृति की शक्तियों की उपासना, कौतुहल तथा आनन्दानुभूति और अध्यात्मिकता आदि किसी एक या समस्त प्रवृत्तियों से हुई थी। आज के युग में यह निश्चित करना बहुत ही कठिन है कि इनमें कौन सी प्रवृत्ति सर्वप्रथम कला निर्माण में सहायक सिद्ध हुई केवल यही कहा जा सकता है कि आदिम मनुष्य आरम्भ में बहुत समय तक कलात्मक माध्यमों के प्रति सजग नहीं था, प्रकृति से संघर्ष करते हुए सभ्यता के विकास क्रम में मनुष्य ने सौन्दर्यानुभूत और आध्यात्मिकता के नये प्रतिमान स्थापित किये।

'कलाकार का सबसे बड़ा धर्म और जाति उसकी कला है और यह कला परम शक्ति के प्रति समर्पित होनी चाहिए क्योंकि संगीत एक ईश्वरीय देन है।'<sup>2</sup>

आदिम मनुष्य के पास प्रकृति की सबसे बड़ी देन उसका अपना शरीर था। इस माध्यम के विभिन्न अवयवों हाथ, पैर, कण्ठ, नेत्रों आदि को उसने भावाभिव्यक्ति में विशेष सक्षम पाया जिनसे क्रमशः अभिनय, नृत्य, साहित्य तथा संगीत आदि विभिन्न कलाओं का विकास हुआ।

मानव का इतिहास जितना प्राचीन है उतना ही कला का इतिहास, भारतीय चित्रकला हो या संगीत कला प्राचीन कला से लेकर वर्तमान तक विभिन्न रूपों में दृष्टिगत होती है। जोगीमारा, अजन्ता, बाघ, सित्तनवासल, एलोरा आदि के केन्द्र भारतीय चित्रकला इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ रहे हैं।

'मानव प्राचीन कला से ही अपनी अन्तर्त्मा की तृप्ति के लिए इस असीम सौन्दर्य का सृजन करता आया है। मनुष्य ने जिस समय प्रकृति की गोद में नेत्रोन्मिलन किया उस समय से ही उसने निर्माण के तारतम्य से अपने जीवन को सुखी तथा समृद्ध बनाने की चेष्टा की और इस निर्माण के फलस्वरूप उसने ऐसी कृतियों का सृजन किया जो उसके जीवन को सुखद व सुचारु बना सके। यदि प्राचीन काल की कलाकृतियों का आज भी अध्ययन किया जाये तो अनुभव होता है कि मनुष्य को सौन्दर्य सृजन में असीम आनन्दानुभूति होती थी और इसी आनन्दानुभूति के लिए वह कला सृजन करता था।'<sup>3</sup>

'भारतीय परम्परा के अनुसार उन समस्त क्रियाओं को कला कहते हैं जिनमें कौशल अपेक्षित हो। यूरोपीय शास्त्रियों ने भी कला में कौशल को महत्वपूर्ण माना है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शायद 'भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में ही मिलता है। वात्स्यायन और उष्णीष ने भी अपने ग्रन्थ कामसूत्र और शुक्रनीति में इसका वर्णन किया है। शुक्रनीति में तो कहा भी

गया है 'मूक भी जिसका रसास्वादन कर ले वही कला है।'<sup>4</sup>

'कला जीवन को 'सत्य शिवं सुन्दरम्' में समन्वित करती है। कला उस क्षितिज की भाँति है जिसका कोई ओर है ना छोर इतनी विशाल, इतनी विस्तृत, अनेकों विद्याओं को अपने में समेटे हुए। तभी तो कवि मन भी सहज ही कह उठा -

**पत्थर में भी प्राण फूँक दे शिल्पी मेरे।**

**इन्द्रधनुष की छटा बिखेरे यहाँ चितेरे॥**

**घरती का शृंगार रंगोली से होता।**

**चरवाहा भी रसभीना संगीत बिखेरे॥'<sup>5</sup>**

पाषाण युग अर्थात् आदिम कला से भी जो चित्र प्राप्त होते रहे हैं वे मात्र विधा नहीं है अपितु मानवता के विकासक्रम का एक निश्चित सोपान प्रस्तुत करते हैं। चित्रों के माध्यम से ही आखेट करने वाले आदिमानव ने न केवल अपने सवेगों को बल्कि रहस्यमयी प्रवृत्ति और जंगल के खूंखार प्रवासियों के विरुद्ध अपने अस्तित्व के लिए किये गये संघर्ष की कहानी को भी अभिव्यक्त किया है, दृष्टव्य है कि कलाकार प्राचीन काल में भी अपने भावों की अभिव्यक्ति हेतु कला सृजन का सहारा लेता था।

चित्रकला के साथ ही संगीत कला भी भावों की अभिव्यक्ति का एक सबल माध्यम है और देखा जाये तो एक दूसरे से परस्पर सम्बन्धित है। दोनों ही भावों की अभिव्यक्ति व अध्यात्म तक पहुँचने का माध्यम है। अध्यात्मवाद का मूल रूप आनन्द प्रदान करना है और आनन्द की प्राप्ति के माध्यमों में चित्रकला व संगीतकला का नाम सबसे अग्रणी है। हम भक्ति की जिस रस धारा में प्राचीन काल से आज तक बते आ रहे हैं वहाँ संगीत सर्वोपरि है। साहित्य व संगीत के बाद चित्रकला ही भावाभिव्यक्ति में प्रथम है।

संगीत दर्पण के लेखक श्री दामोदर पण्डित के मतानुसार संगीत का जन्म ब्रह्माजी से आरम्भ होता है। उन्होंने लिखा है-

**'दहिणेत् यदन्विष्टं प्रयुक्तं भरते न च**

**महा देवस्य पुरतस्त-मार्गस्थं विभुक्तम॥'<sup>6</sup>**

सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से भारत की चित्रकला संस्कृति व संगीत संस्कृति समृद्ध व पौराणिक दृष्टि से वैभवशाली है। कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि चित्रकला व संगीतकला हमारे देश की परम्परागत संस्कृति के अभिन्न अंग हैं जो कि मनुष्य के दिन प्रतिदिन की जीवनचर्या से उत्पन्न नीरसता को दूर कर जीवन में आनन्द व मनोरंजन का संचार करते हैं। इन विधाओं से हमारे देश की लोकतत्व की अभिव्यक्ति होती है। चित्रकला व संगीतकाला से भारत को अद्भुत सांस्कृतिक समन्य प्राप्त हुआ है तथा यह राष्ट्रीय एकता का सूचक है। अलग-अलग प्रान्तों की चित्रकला, लोकनृत्य

\* एसोसिएट प्रोफेसर (चित्रकला विभाग) श्री कुन्द कुन्द जैन (पी0जी0) कालेज, खतौली, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

\*\* प्रवक्ता (चित्रकला विभाग) श्री कुन्द कुन्द जैन (पी0जी0) कालेज, खतौली, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत



व संगीत कलाओं का भारत में अनोखा संगम है। अतः हा जा सकता है कि चिकला व संगीत में इस देश की संस्कृति व जीवन के सजीव रंग हैं। भारतीय कला की अस्मिता को बनाये रखने के लिए कला व संगीत को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। यद्यपि इन दोनों ही विधाओं पर पाश्चात्य संस्कृति की झलक देखने का मिलती है जो देश की सांस्कृतिक कला अस्मिता के लिए खतरा है।

‘कला विभिन्न रसों से मिलकर ही बनी है जैसे – शृंगार रस, भक्ति रस, रौद्र रस, आध्यात्मिक रस, शांत रस इन सबको गायन के परिप्रेक्ष्य में अर्थात् संगीत के दृष्टिकोण से भाषा स्वर एवं ताल के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है।’<sup>17</sup>

‘प्राचीन काल की कलाओं का यदि हमस मयक अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि कलाओं, विशेषकर चित्रकला व संगीत कला के क्षेत्र में गुप्त काल में भी सराहनीय कार्य हुआ है। संगीत व कला में जितनी रूचि गुप्त सम्राटों को भी उतनी अन्य किसी काल के सम्राटों को नहीं रही। समुन्द्रगुप्त तो स्वयं बहुत बड़ा संगीत व कला प्रेमी राजा था। इस युग में संगीत कला में वीणा, वेणु तथा मृदंग प्रमुख वाद्य यंत्र थे। भास ने वीणा को समुद्र से निकला हुआ रत्न कहा है। वुणे की प्रशंसा में वात्स्यायन ने कहा है कि वेणु प्रियतमा को आकर्षित करने का मूल मंत्र है। रघुवंशम तथा शाकुन्तलम में तो अनेक स्थानों पर संगीत कला पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। गुप्तकाल के शान्तिमय वातावरण में संगीत व चित्रकला दोनों ही विधाएँ अपने चरमोत्कर्ष पर थी।

संगीत कला को गुप्त काल में पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हुआ तथा संगीत व चित्रकला दोनों विधाओं का यह युग स्वर्ण युग कहा गया। सामान्य रूप से देखने पर ऐसा विदित होता है कि भारतीय संगीत एक त्रिवेणी है। जिसमें एक ओर गायन वादन तथा नृत्य का संगम है तथा दूसरी ओर गायन में शास्त्रीय उपशास्त्रीय (सुगम) एवं लोक संगीत की त्रिवेणी का संगम है।’<sup>18</sup>

वास्तव में संगीत प्रकृति का एक अनुपम उपहार है संगीत कला जगत की सर्वोत्कृष्ट कृति है कला जगत का एक अभिन्न अंग है। संगीत ईश्वरीय वाणी है अतः यह ब्रह्म रूप ही है। वस्तुतः सम्पूर्ण संसार ही नादमय है। नाद से ही वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य तथा वाक्यों से ही भाषा उद्भूत होती है तथा इसी सृष्टि का व्यवहार चलता है अतएव सम्पूर्ण सृष्टि नाद के अधीन है।

आचार्य लालमणि मिश्र ने संगीत की परिभाषा देते हुए कहा है कि – ‘संगीत जीवन के ताने बाने का वह धागा है जिसमें बिना जीवन सत चित का अंश होकर भी आनन्द रहित होता है तथा नीरस प्रतीत होता है यह न तो सामान्य शिक्षण व्यसन पूर्ति की वस्तु है और न ही कठिन परिश्रम की परिहारार्थ साधरण सा मनोरंजन मात्र।’<sup>19</sup>

संस्कृति समाज का दर्पण होती है कला और संस्कृति को एक दूसरे से पृथक करके देखा ही नहीं जा सकता। कला सदैव संस्कृति को रूप प्रदान करती है और संस्कृति कला का प्राण तत्व है भारतीय संगीत और कला दोनों में हमारी संस्कृति के दर्शन होते हैं।

‘भारतीय संगीत व चित्रकला दोनों ही मानव मन में चेतना का संचार करते हैं। ये जन्मतः ही हमारे जीवन में बस जाते हैं। बचपन में ही लोरी के संगीत का बच्चा महसूस करता है और उसमें खो जाता है इसी तरह कला भी बालक को बचपन से ही प्रभावित करती है संगीत व कला दोनों ही विधाएँ एक अलौकिक शक्ति रखती हैं जो हँसते हुए व्यक्ति को रूलाने तथा रोते हुए व्यक्ति को हँसा देती हैं। प्रत्येक प्राणी के जीवन में संगीत व कला दोनों ही विधाएँ शरीर में आत्मा के समान

विद्यमान हैं।’<sup>10</sup>

भारतीय संगीत सृष्टि का पूरक है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार माना गया है। संगीत तथा कुछ हद तक तक भी इस लक्ष्य की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। सभी धर्मों के आध्यात्म से संगीत पूर्णरूपेण जुड़ा हुआ है और कुछ धर्मों में कला भी। भारतीय संगीत का स्वरंगमा में अवगाहन करने से अपूर्व शान्ति का अनुभव होता है।

सृष्टि के कण-कण में संगीत विराजमान है यून कहें कि सृष्टि में ही संगीत का जन्म हुआ है और मानव जब सृष्टि में जन्म लेता है तो उसका सम्बन्ध जन्म से मृत्यु तक संगीत से बना रहता है।

‘संगीत में मानसिक चित्र पर कलाकार अपनी अभिव्यक्ति के रंग भरता है। इसी प्रकार इन्हीं शृंगारिक भावों की यादें चित्रकार कैनवास पर उतारकर उनके हाथ-भाव, साक्षात् रूप में प्रस्तुत करता है, तब एक तृप्ति तथा आनन्द का भाव अलग ही दिखाई देता है। अर्थात् दोनों कलाओं को अनुभव करके आनन्द की प्राप्ति विभिन्न माध्यमों से की जा सकती है। तथा भावों को हम संगीत तथा चित्रकला दोनों कलाओं से प्रदर्शित कर सकते हैं।’<sup>11</sup>

‘सम्पूर्ण कलाक्रम पर एक दृष्टि डाली जाये तो देखेंगे कि भारतीय कलाएँ उत्कृष्ट जीवन मूल्यों से अनुप्राणित रही हैं। ये कलाएँ मात्र मनोरंजन ही नहीं बल्कि लोक मंगल के लिए लोक जीवन में उल्लास का संचार करती हैं। भारतीय कलाओं का दर्शन ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ पर आधारित है। यहाँ के संगीत, चित्रकला, नाट्यकला, मूर्तिकला आदि सभी ललित कलाओं में आध्यात्मिकता और भारतीय संवेदना की मूलभूत अभिव्यक्ति होती है।’<sup>12</sup>

‘भारतीय कला साधना का चरम उद्देश्य आनन्द की प्राप्ति है। भारतीय कलाएँ चाहे वह चित्रकला हो अथवा संगीत प्रारम्भ से ही आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई हैं और इसी की छाया में पल्लवित व पुष्पित होती रही हैं, उसके अंग प्रत्यंग पर आध्यात्मिकता की स्पष्ट छाप दिखाई देती है।

‘संगीत बिना काव्य के भी जड़ चेतना को आकर्षित कर सकता है जबकि काव्य बिना संगीत के मननशील, प्रखर बुद्धि वाले तथा साहित्यिक वर्ग तक ही सीमित होकर रह जाता है। लेकिन संगीत अपनी गहनता सुक्ष्मता तथा माधुर्य के बल पर श्रेष्ठ है।’<sup>13</sup>

‘आध्यात्मवाद का मूल आनन्द है और आनन्द की उपलब्धि का मूल संगीत व कला है। कला व संगीत दोनों का ही कार्य मानव की भावाभिव्यक्ति तथा आनन्द की प्राप्ति कराना है। इसका उच्चतम तथा अन्तिम लक्ष्य आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार है। कला व संगीत एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं जिस प्रकार ताने बाने के धागे एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं होता है।’<sup>14</sup>

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-**

1. भारतीय चित्रकला व मूर्तिकला का इतिहास, रीता प्रताप।
2. संगीत का कला पथ और शिक्षा पथ, डॉ० संगीता, संजय प्रकाशन नई दिल्ली, 2018, पृ०सं०80
3. कला सौन्दर्य और समीक्षा शास्त्र – अशोक, संजय पब्लिकेशन्स, पृष्ठ सं० 119-120
4. डॉ० शर्मा, डॉ० श्रोत्रिय, चित्रण विधान एवं सामग्री, छवि प्रकाशन, मुजफ्फरनगर, 1988 (लेखकीय व्यक्तव्य)।
5. कला कुंज भारती, मार्च 2013 पृष्ठ सं० 13-14
6. भारतीय संगीत का इतिहास, उमेश जोशी, कल्पना प्रकाशन, दिल्ली,

- 2014, पृ028
7. चित्रकला और उसके अंतः अनुशासनिक सम्बन्ध, पं0 विष्णु नारायण भातखण्डे क्रमिक, पुस्तक मालिका-2, 2016, पृ0 110
8. भारतीय चित्रकला व मूर्तिकला का इतिहास, रीता प्रताप।
9. विनोद चन्द्र पाण्डे एवं के0 सिंह, प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास, प्रकाशन केन्द्र न्यू बिल्डिंग्स, अमीनाबाद, लखनऊ, 1916, पृष्ठ सं0 158
10. कला कुंज भारती, मार्च 2013, पृष्ठ सं0 13-14
11. स्वरार्पण , डॉ0 पूर्वी निमगांवकर, 2012, पृ0सं0 32
12. रोमिला थापर, प्राचीन भारत, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, 1987, पृष्ठ सं0 95
13. अवधी ग्रन्थावली खण्ड तीन, जगदीश पीयूष, वाणी प्रकाशन, 2008, पृ0सं0 37
14. कला कुंज भारती, ललित कला, अंक फरवरी 2005, पृष्ठ सं0 17

\*\*\*\*\*

## मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास 'चाक' में अभिव्यक्त नारी-चेतना

रंजीता राय\* अमित कुमार\*\*

**प्रस्तावना** – मैत्रेयी पुष्पा ने अपने स्त्री पात्रों के माध्यम से ग्रामीण जीवन के कटु संघर्ष एवं यथार्थ का रहस्योद्घाटन किया है। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में बुंदेलखण्ड के ग्रामीण जीवन का संघर्ष लोकमंगल की रंगत लिये हुए उभरता है। मैत्रेयी पुष्पा एक ऐसी साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से स्त्री की मानसिकता को परिवर्तित करने एवं उसे एक नयी दिशा प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

परमानन्द श्रीवास्तव के अनुसार- 'मैत्रेयी में मानवीय मूल्यों की सघन अन्तरंगता और सम्मेलनधर्म की जटिलता को चित्रित करने की अनोखी क्षमता मौजूद है।'

मैत्रेयी जी के उपन्यास में नारी चेतना एक मानवीय दृष्टि है जो स्त्री पुरुष का भेद मिटाकर दोनों में प्रतिष्ठा लाने की बात करता है वे नारी को अपने अधिकारों को जानने के साथ ही अबला नारी नहीं बल्कि सबला बनकर स्वयं समाज का नेतृत्व करने की बात करती हैं।

मैत्रेयी जी के 'चाक' उपन्यास के बारे में राजेन्द्र यादव का कथन है- " 'चाक' सामंती समाज के भीतर व्याप्त हिंसा और स्वार्थ के टकराहट की प्रमाणिक कहानी है। इस समाज का ताना-बाना हिंसा और सेक्स से बना हुआ है। मैत्रेयी इन दोनों को एक ही कथाकार की निगाह से पात्रों के आचार-विचार और सोच के रूप में प्रभावशाली ढंग से पकड़ती है। 'चाक' में बिना बड़बोलेपन के उन्होंने गाँव की स्त्री की जिस चेतना का विकास किया है वह उपन्यासकला पर उनकी पकड़ को रेखांकित करता है।"

'चाक' उपन्यास एक नारी ग्राम कथा है। गाँव की समस्या पर शहरी मध्यवर्ग की दृष्टि से काल्पनिक समाधान प्रस्तुत करने वाला यह एक प्रयोगकारी उपन्यास है। 'चाक' स्त्री-पात्रों का एक सजीव संग्रहालय है यह एक ऐसा आख्यान है जिसमें स्त्री-पात्रों की आवृत्ति न होकर विशिष्ट किस्म के नारी-पात्रों की विविधता है और अलग-अलग प्रकार के सामाजिक प्रसंगों में उनकी भूमिकाएँ भी अलग-अलग किस्म की हैं। अर्थात् चरित्र-निर्माण में बहुरंगी वैविध्य के कारण यह उपन्यास बार-बार नये सिरे से गम्भीर विवेचन की चुनौती पेश करता है। मैत्रेयी पुष्पा ने ग्रामीण परिवेश के घटनापूर्ण परिवेश प्रस्तुत किया है और बताया है कि अतरपुर गाँव की अधिकांश स्त्रियाँ अनपढ़ हैं जो पढ़ी-लिखी हैं, वे भी गोबर-पानी के काम में खपकर अपनी विद्या भूल चुकी हैं।

उपन्यास की कथा का मुख्य केन्द्र इन्हीं स्त्री-पात्रों में से एक सारंग नैनी है, जिसके इर्द-गिर्द सम्पूर्ण आख्यान का ताना-बाना बुना गया है। यह एक ऐसी लड़की रही है जो आर्य समाजियों द्वारा स्थापित गुरुकुल कन्या विद्यालय के आश्रम (छात्रावास) में रहकर ग्यारहवीं कक्षा तक शिक्षा पा

चुकी है। भारतीय संस्कृति, स्त्री-मर्यादा और नैतिक पाखंड के प्रवचनों की असलियत से वह परिचित है। गुरुकुल के वातावरण में रोज व रोज होने वाली यौन संबंधों के हादसे भी उसकी स्मृति को आछन्न किये हुए हैं। तभी से वह यह भी जानती है कि ऐसे संबंधों के भांडाफोड़ के बाद सारा ढण्ड स्त्री को ही दिया जाता है। वह स्वयं इन घटनाओं के बीच एक छोटे-मोटे संघर्ष की अगुवाई भी कर चुकी है। चाक उपन्यास में सारंग की छोटी फुफेरी बहन रेशम की हत्या उसके जेठ डोरिया द्वारा कर दी जाती है यह घटना सारंग को भीतर ही भीतर खूब सालती है। वह इस घटना से दुखी है और अपने पति रंजीत, जो पढ़ा-लिखा अनुभवी किसान है, से कहती है- तुम जागो रंजीत ! उठो ! तुम्हारे शिवा मेरा कौन-----!'

वह रात-रात भर जब रेशम को याद करती है तो वह सो नहीं पाती क्योंकि रेशम की जन्म-जन्मांतों की 'जीने की इच्छा कुचल' दी गयी। क्यों? क्योंकि उसने निडरता प्रदर्शित की। क्यों? क्यों कि वह अपने ऊपर भरोसा कर बैठी? यह सब प्रश्न सारंग के मन को बार-बार परेशान करते हैं। नया इतिहास लिखने के लिए नया प्रश्न उठाना जरूरी है। रेशम की हत्या के बाद सारंग प्रश्न उठाती है-

'तमाम बूढ़े-बड़े गुमसुम क्यों रह गये? इनकी जिह्वा क्यों लकड़ा गयी? ये पुरुष व महापुरुष शाबासी के पात्र हैं या धिक्कार के? इनकी लाज-लिहाज हम क्यों करते हैं? हमें ऐसा लगता है कि सारंग के रूप में महाभारत की द्रोपदी बोल रही है। 20 वीं शती के उत्तरार्ध में आठवें या नौवें दशक में विकास, प्रगति, परिवर्तन एवं तमाम मानवीय सरोकारों की दुहाई देने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था की आँखों के सामने जिंदा रहने का मौलिक अधिकार रेशम से छीन लिया गया। सारा गाँव चुप सारी स्त्रियाँ चुप। किसी ने 'भाग' को सराहा। किसी ने करम की दुहाई दी। रेशम के बंध को चुपचाप पचा जाने वाले 'अपने संरक्षकों' की भूमिका देखकर सारंग की चेतना करवट लेती है। विफरते हुए कहती है-

दादी, तुम भी चंदना वाला गीत गाना छोड़ दो या उस गीतकथा का अंत..... ?

'चाक' उपन्यास में अतरपुर गाँव बड़ा नहीं। कुल आबादी एक हजार। ब्राम्हण, बनिया, जाट जैसी ऊँची कही जाने वाली कौमे हैं तेली, कुम्हार, गड़रिया, खिटिक, चमार और नाई जैसी छोटी जातियाँ भी हैं। सक्का मुसलमान भी हैं। सन् 1980-90 तक आते-आते अतरपुर में विकास का मूर्तिमान रूप दिखाई दिया। इस उपन्यास में स्त्री स्वातन्त्र्य के साथ-साथ एक अन्य पक्ष पर भी चर्चा हुई है वह है स्त्री का राजनीति के क्षेत्र में योगदान।

चुनाव नजदीक आने पर गाँव का समीकरण बदल जाता है। गाँव का

प्रधान भ्रष्ट तथा गुंडा तत्वों के साथ मिलकर एक प्रकार से वास्तविक शक्ति का केन्द्र बन जाता है। गाँव में बच्चों को पढ़ाने वाला श्रीधर मास्टर सारंग की आँखों का अनकहा दर्द पहचानकर उसे समझाता है-

‘जब घर-परिवार में औरत का दखल हो सकता है तो राजकाज में क्यों नहीं ? तुम पढ़ी-लिखी हो, खूब जानती हो हमारे संविधान में औरतों को बराबरी का दर्जा मिला है। xxxxxxxxxxxx’

इसी तरह के अन्य अनेक जटिल घटनाक्रमों के बीच प्रधान पद के लिए सारंग का परचा भरना तमाम दकियानूस और भ्रष्ट ताकतों के विरुद्ध एक चुनौती के समान है। लेखिका ने इस जटिल यथार्थ को सम्पूर्ण विम्ब में सँभाल एक नयी दिशा, भविष्य की सकारात्मक शक्ति के रूप में सारंग के चुनाव लड़ने के फैसले को प्रस्तुत करती है। यह एक ऐसी परिस्थिति है, जिसमें नकारात्मक यथार्थ को पलटने वाली शक्ति के रूप में सारंग आशा का केन्द्र बन जाती है।

गाँव में उभर रहे यथार्थ के अर्न्तविरोधी पक्षों की पृष्ठभूमि में यदि ठीक से पड़ताल करें तो पता चलेगा कि सारंग नारीवादी आग्रहों में गढ़ी हुई कोई फार्मूला नहीं है वह लेखिका की मनगढ़ंत उड़ान के अनुसार ढली कोई कठपुतली भी नहीं है।

‘चॉक’ में स्त्रियों की जिजीविषा के संघर्ष को उनके आर्तनाद में केवल स्त्रियाँ ही नहीं सुनती और समझती हैं बल्कि अन्य उनके लोग भी शामिल हैं। मनोहर के बहू की दर्दनाक हालत पर श्रीधर की यह टिप्पणी उल्लेखनीय है कि-

‘जिरौली वाली की यातना व्यर्थ नहीं जायेगी। लपटें भी उठेंगी, जो छीन लेंगी अपने हक को।’

उपन्यास के प्रारम्भ में छपी रेड इंडियन कवयित्री ज्वाय हार्जी की कविता के उद्धरण को इस उपन्यास की प्रस्तावना के रूप में लेना अनुचित न होगा-

‘मैं मुक्त करती हूँ तुम्हें  
मेरे सुन्दर भीषण भय  
मैं मुक्त करती हूँ तुम्हें, तुम थे  
मेरे प्रिय और मेरे घृणित जुड़वाँ, पर  
अब नहीं पहचानती तुम्हें, जैसे कि  
खुद को।’

यह उपन्यास एक स्वस्थ जीवन दृष्टि विकसित करता है जिसमें कुछ दृढ़निश्चयी, लगनशील तथा संघर्षशीलता के दर्शन होते हैं। मैत्रेयी जी स्त्रियों को आत्मनिर्भर तथा समाज में विशिष्ट स्थान दिलाने का प्रयास करती हैं। स्त्री जीवन के सभी पक्षों को मैत्रेयी जी ने उजागर किया है चाहे उसकी सामाजिक, राजनैतिक या आर्थिक स्थिति हो, कोई भी पक्ष अछूता नहीं रहा सभी उनके नारी चेतना के केन्द्र में समाहित है। मैत्रेयी पुष्पा का यह उपन्यास इन नई धारा की एक अनिवार्य कड़ी है।

#### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. विजय बहादुर सिंह- मैत्रेयी पुष्पा: स्त्री होने की कथा, नई दिल्ली, किताब घर प्रकाशन संस्करण, 2016
2. चाक- मैत्रेयी पुष्पा: राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली- 110002
3. वही पृ0- 88, 92
4. वही पृ0- 14
5. वही पृ0-400
6. हिन्दी उपन्यास का इतिहास- गोपाल राय

\*\*\*\*\*



## Parents Intervention to Help Their Mentally Disabled Children

Dr. Mani Bansal\*

**Abstract** - Present study reports research that investigated parental support for children's reading of Hindi in a school of Moradabad. A quasi-experimental trial with a sample of five children was accompanied to assess the relative effectiveness of two approaches to parents supporting reading: Paired Reading and Hearing Reading. Interviews and observations of parents and children were utilized to further explore the implications of the trial data. This was very effective with modeling technique. Paired Reading and Hearing Reading were found to be equally effective in enhancing children's beginning Hindi reading skills, reading accuracy and comprehension, relative to controls. Parents engaged in a variety of mediation behaviours to enhance their children's Hindi reading development. Parents felt that participating in their children's reading was both enriching and empowering. In view of the evidence that Hearing Reading can be, and was, implemented by parents with little or no Hindi language proficiency, it is concluded that implementing Hearing Reading on a wider scale across the city could impact beneficially on children's Hindi reading development.

**Keywords**- Intervention, Parent – child Interactions, parental Involvement, reading skills.

**Introduction** - The usual challenges of parenting are compounded for parents and primary caregivers of children with special needs. Among the many challenges are:

1. Learning about their children's disability.
2. Researching, finding and accessing actual treatments and resources.
3. Managing with the expressive and physical demands of caring for an individual with a disability.
4. Receiving to the countless appointments with medical providers, therapists, advocates, and school personnel.
5. Advocating for suitable school interventions.
6. Paying for the many treatments and interventions not covered by health insurance or the school system.

The present work aimed to develop Hindi reading skills of mentally retarded children through parents. This naturally involved parental training in various techniques of teaching mentally retarded children to develop Hindi reading skills. The need of present work arose because there is no institution or school for the training of mentally retarded in Moradabad and around. And also, in comparison to the developed countries, the research literature in India is focused mainly on theoretical work or oriented by IQ. The main objective of the project was to find out which parental training technique was effective, economical and therapist's time saving? Five hypotheses were taken as a challenge and it included Hindi reading skill.

In the present study behavioral shaping and modeling is used as independent variables. The target behavior that is self-help skills of developmental disabled children will constitute as the dependent variables in the present

study. After selection of subjects, only five moderate mentally retarded children and their parents were to serve as subjects. After doing the clinical examination of each case, interviewed the parents to know the actual problems. Along with the parents were interviewed to obtain relevant information about the observation child's level of functional Hindi reading skills. Child target behaviors were selected according to the individual child's level of academic skill.

Three types of experimental sessions were conducted -

- (i) Parent training sessions.
- (ii) Child training sessions.
- (iii) Observation, recording sessions.

The method used in the study is a quasi-experimental design focusing on a single subject at a time. This is known as a single subject design.

In Baseline, three child target task was identified with the help of the mother, namely Hindi reading. The experimental design was a multi alternating treatments, within subject design. Each mother – child pair was trained on all tasks.

During intervention the mother was asked to teach the task to the child. This phase was called mother's own teaching method or Baseline. A brief write up was given to the mother, on how to issue clear instructions to the child in the context of the first and second child target behavior. Thereafter the phases of Modeling were followed. It involved a reminder to the mother on the general rules and live demonstration by the investigator to show the mother as to how to deliver an instruction regarding the child target behavior, reading Hindi. After 10 days of mother's teaching

\*Associate Professor, D.A.K. (P. G.) College, Moradabad (U.P.) INDIA

her child in the light of modeling procedure, they were followed 3 days evaluation sessions at the rate of one 15 minutes session every day. After observation were over for the Modeling phase the second mother's target behavior namely correct use of prompts was picked for training by means of lecture method.

After evaluation this phase fading was started a brief write up in Hindi was provided to the mother's knowledge about fading after that demonstration plus fading was taken as intervention.

The results show that the mother reached the mastery criterion of teaching skills in cent percent of observation intervals of the evaluation/ sessions and maintained it for some days in a row - only when the only modeling procedure was used as the parent training technique and not when this technique was not used as shown in the baseline weeks approximately in all cases. Therefore using the lecture procedure, there was no change in mother's and child's target behaviors. Thus the fact was demonstrated repeatedly sequentially over the mother target behaviors and the child also reached the mastery criterion of the child target behaviors only when the mother was given modeling plus fading techniques on the reading skills. Thus, in actual practice, model plus fading alone was found useful for teaching each mother target behavior and when the mother had learnt mother target behaviors, the child also had acquired the specific child target behavior. Moreover, the modeling procedure was not at all required and modeling plus fading procedure alone was sufficient at teaching behavioral skills to the mother.

Results of follow up at fifteen days, shows that the mother was able to maintain her behavioral skills over a long time without any professional help and this was further validated by the fact that the mother had successfully taught on her own the other task, recognition of color and Indian coins, to her child as observed during the follow up observation session. Taking into account the overall picture, it is found that much more efforts are needed to be made by all concerned to create an enabling environment which empowers them and bring them into mainstream living.

#### References:-

1. Ault, M.J. "Comparison of progressive and constant time delay procedures in teaching community - sign words reading". American Journal on Mental Retardation, 1988, 93 (1), 44-56.
2. Bansal, M. "Modeling as a technique to develop self-help skills in mentally retarded children". Journal of Disabilities and Impairments, 2008, 22(2), 93-102.
3. Birnbrauer, J.S., Wolf, M.M., Kidder, J.D & Tague, C.E. "Classroom behavior of retarded pupils with token reinforcement". Journal of Experimental Child Psychology, 1965, 2, 219-235.
4. Biswas, M., Mentally retarded and Normal Children. "A Comparative Study of Their Family Conditions". Sterling Publications, New Delhi, 1980.
5. Deitz, S.M., Repp, A.C. & Deitz, D.E.E. "Reducing Inappropriate Classroom Behavior of Retarded - Students through Three Procedures of Differential Reinforcement". Journal of Mental Deficiency Research, 1976, 20, 155 - 161.
6. Gidewell, J.D., Kantor, M., Smith, L.M. & Stringer, L. "Classroom socialization and social structure. In M. Hoffman and L. Hoffman (Eds.)". Review of Child Development Research, New York: Russell Sage Foundation, 1966.
7. Goel, S.K. and Sen, A.K. "Psycho - Educational Research in Mental Retardation". Agra - 2, Ajanta Printers, 1988.
8. Gupta, M. & Jain M. "Effect of music therapy on mentally handicapped children: An observation". Journal of Rehabilitation Council of India, 2005, 1. 33 - 37.
9. Jain, Manju. "Effect of Individualized Training Program on Personal, Social, Academic and Occupational Skills in Mentally Handicapped Children". Ph.D. Thesis, M.D. University, Rohtak, 2006.
10. Shah-Wundenberg, Mihika, Wyse, Dominic, Chaplain, Roland. "Parents helping their children learn to read: The effectiveness of paired reading and hearing reading in a developing country context". Journal of Early Childhood Literacy, 2012, 13(4), 471-500.
11. Stevens, R. & Rosenshine, B. "Advance in Research on Teaching". Exceptional Education Quarterly, 1981, 2(1), 1-9.
12. Terrace, H.S. Discrimination Learning with and without "errors". Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 1963a, 6, 1 - 27.
13. W.H.O. The I.C.D. 10 classification of Mental and Behavioral Disorders, Geneva. Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.

\*\*\*\*\*

## Sarva Shiksha Abhiyan

Dr. Kiran Yadav\*

**Introduction** - Every human being should have the opportunity to make a better life for themselves. Unfortunately, too many children in the world today grow up without this chance, because they are denied their basic right to even attend primary school.

As a result of education programs, by the end of 2000, 94% of India's rural population had primary schools within one km and 84% had upper primary schools within 3 km. Special efforts have made to enroll SC/ST and girls. The enrollment in primary and upper-primary schools has gone up considerably since the first five-year plan. So has the number of primary and upper-primary schools. In 1950-51, only 3.1 million students had enrolled for primary education. In 1997-98, this figure was 39.5 million. The number of primary and upper-primary schools was 0.223 million in 1950-51. This figure was 0.775 million in 1996-97. In 2002/2003, an estimated 82% of children in the age group of 6-14 were enrolled in school. The Government of India aims to increase this to 100% by the end of the decade. To achieve this the Government launched.

A sustainable end to world poverty as we know it, as well as the path to peace and security, require that citizens in every country are empowered to make positive choices and provide for themselves and their families. This can only be achieved if all the children of the world are given the chance to learn in a high-quality schooling environment at least through primary school.<sup>1</sup>

The role of Universal Elementary Education (UEE) for strengthening the social fabric of democracy through provision of equal opportunities to all as been accepted since the inception of our Republic. The original Article 45 in the Directive Principles of State Policy in the Constitution mandated the State to endeavour to provide free and compulsory education to all children up to age fourteen in a period of ten years. The National Policy on Education (NPE), 1986/92, states: "In our national perception, education is essentially for all. Education has an acculturating role. It refines sensitivities and perceptions that contribute to national cohesion, a scientific temper and independence of mind and spirit - thus furthering the goals of socialism, secularism and democracy enshrined in our Constitution"<sup>2</sup>.

Since Independence, India has made impressive

progress in terms of growth of educational institutions at different levels, physical access to schooling for children, and diversification of educational programmes. Today, 18 crore children are taught by almost 57 lakh teachers in more than 12 lakh primary schools.

With schematic interventions from the erstwhile Operation Blackboard, Bihar Education Project, Lok Jumbish, District Primary Education Programme, and the Government's current flagship programme of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), over 98% of our children are estimated to have access to primary schooling within one kilometer of their habitation, and almost 92% to an upper primary school within three kilometers of their habitation. Gross enrolment ratios have increased significantly across all social categories, drop out rates at primary level have declined, and transition from primary to upper primary stage has improved. Decentralised academic support structures have been established in the form of District Institutes for Education and Training (DIETs) in 571 districts, and Resource Centres in 6746 blocks and 70388 clusters in the country. Over 12 crore children participate in the Mid Day Meal programme, the world's largest school feeding programme, which impacts not only enrollment of children, but also their regular attendance in school and participation in the learning process.

This notable spatial spread and physical access has, however, by and large not been supported by satisfactory curricular interventions, including teaching learning materials, training designs, assessment systems and classroom practices, or even suitable infrastructure. "Our Constitution fathers did not intend that we just set up hovels, put students there, give untrained teachers, give them bad textbooks, no playgrounds and say, we have complied with Article 45 and primary education is expanding... They meant that real education should be given to our children between the ages of 6 and 14". Physical expansion has also not adequately addressed the problem of social access. An alarming 46 per cent children, largely girls and SC/ST children drop out before completing the elementary stage of education. The country's expectations in respect of overall coverage, equitable distribution and quality of education have largely not been fulfilled.

The education system does not function in isolation

\*Associate Professor (Zoology) Maharaja Bijli Pasi Govt P.G. College, Lucknow (U.P.) INDIA

from the society of which it is a part. Our social system is stratified into manifold layers based on class, caste, gender, and religion. Unequal social, economic and power equations, which persist, deeply influence children's access to education and their participation in the learning process. This is evident in the disparities in education access and attainment between different social and economic groups. Thus, girls belonging to SC, ST and Muslim minority communities, and children with disabilities, especially those from poor families, are educationally most vulnerable.

Even as the education system seeks to reach out to every child by widening access and providing school infrastructure and teachers, the issue of quality presents daunting challenges. Indian education system is known for its inequitable character – there are high fee charging schools catering to the rich and privileged and ordinary government schools with extremely insufficient facilities to which the masses of people living in rural area and urban slums send their children. There is a range of government and private schools between these extremes. Time has come to make a decisive intervention to change this situation so that all children irrespective of their religion, caste, class, gender and location get an education of comparable quality.

Before going to discuss the universalisation of elementary education firstly we should know what elementary education is and which level it has covered.

1. In India, the elementary education covers the base or starting point of further education or it is a stepping stone of further education. In India, the standard entry age of children in elementary education is 6 and it covers the age level from 6-14 and where the stages of schooling or classes is from I to VIII.
2. The process of socialization that begins at home extends gradually to include the school. It is here that an individual learns to interact with non-kins and with the wider society.

Education is considered as the bedrock of all socio-economic development of the country. In order to promote education to all children irrespective of caste, creed, religion, sex and others and also realizing democratization of education as a birth right to all, the government of India has made several attempts from time to time to achieve the universalisation of education to all. In the importance of Universalisation of elementary education, J.P. Naik, an eminent educator of our country, has observed and commented as "The progress of primary education is an index of the general, social and economic development of the country as a whole." Because, primary education plays an important role in bringing the proper foundation of a child's cultural, emotional, intellectual, moral, physical, social and spiritual development.

Universalisation of primary or elementary education basically involves three things i.e. Universalisation of

Provision, Universalisation of Enrolment and Universalisation of Retention.

1. In school, **Universalisation of Provision** means that school facilities should be provided to all the children between the age group of 6-14 years in the country. The school should be easily accessible within the walking distance of a child.
2. **Universalisation of Enrolment** means all children between the age group of 6 to 14 years must be enrolled. The provision has demand to introduce the compulsory legislation act and under the legislation, parents can be found for not sending their children to schools.
3. **Universalisation of Retention** reveals a child who joins primary school; he or she should remain there till he or she completes all 8 classes.<sup>3</sup>

Right to Education has been recognized as one of the human rights in the Indian statute books as well as in International declarations, Covenants and Conventions. Article 21 of the Constitution of India is interpreted by the supreme Court states that the right to life ensures minimum conditions of living with human dignity. While interpreting this article, the Supreme Court of India stated:

*We think that the right to life includes right to live with human dignity and all that goes along with it viz., the bare necessities of life such as adequate nutrition, clothing and shelter and facilities for reading, writing and expressing oneself in diverse forms.*<sup>4</sup>

The new economic realities have led to increased marketisation across public sector, leading in turn to disaggregation, deregulation, commodification, an emphasis on measurable outputs, managerialism and accountability. Neo-liberal market oriented reforms have affected education at all levels in developed and developing countries. Primary and secondary education have opened up to the market allowing new private providers to offer educational services competing with public education provided by the state As Barlett explains the marketisation of education involved the introduction of market principles in to the education system such as competition, deregulation and stratification.<sup>5</sup>

#### References:-

- 1 <http://www.indg.in/india/sitemap-1/primary-education/primary-education/edu-primedu>
- 2 [http://www.upefa.com/upefaweb/admin/myuploads/SSA\\_Frame\\_work\\_\(revised\)\\_9-6-2011.pdf](http://www.upefa.com/upefaweb/admin/myuploads/SSA_Frame_work_(revised)_9-6-2011.pdf)
- 3 [http://www.kkhsou.in/main/education/sarva\\_siksha.html](http://www.kkhsou.in/main/education/sarva_siksha.html)
- 4 Didla V.Rao & Pulla Lakshmi Ambedkar's Thrust on Education and Reservation (Sunrise Publications 2007 Delhi) pp 181- 182.
- 5 Marie Lall & Geetha B. Nambissaned" Education and Social Justice in the Era of Globalisation Perspectives from India and the UK"(Routledge 2011 New Delhi ) pp 5-8.



# Understanding Certiorari: With Highlighting Features in India

Dr. Saptmuni Dwivedi\*

**Abstract** - In this article, the concept of writ of Certiorari has been made clear in the light of leading cases. Actually the writ of Certiorari is used when there is lack of Jurisdiction. Prior to independence, Privy Council also explained its importance and effectiveness.

**Introduction** - The literal meaning of the word 'certiorari' is "to be more fully informed of".<sup>1</sup>

Certiorari, often abbreviated as cert. in the United States, is a writ seeking judicial review. It is issued by a superior court, directing an inferior court, tribunal, or other public authority to send the record of a proceeding for review.<sup>2</sup>

As Associate Justice James Wilson, the person primarily responsible for the drafting of Article Three of the United States Constitution, explains:

In every judicial department, well arranged and well organized, there should be a regular, progressive, gradation of jurisdiction; and one supreme tribunal should superintend and govern all the others.

An arrangement in this manner is proper for two reasons:

1. The supreme tribunal produces and preserves a uniformity of decision through the whole judicial system.
2. It confines and supports every inferior court within the limits of its just jurisdiction.<sup>3</sup>

The writ of certiorari can be issued by the Supreme Court or any High Court under Articles 32 and 226 of the Constitution of India for quashing the order already passed by an inferior court, tribunal or quasi judicial authority. There are several conditions necessary for the issue of writ of certiorari:

1. There should be court, tribunal or an officer having legal authority to determine the question with a duty to act judicially.
2. Such a court, tribunal or officer must have passed an order acting without jurisdiction or in excess of the judicial authority vested by law in such court, tribunal or officer.
3. The order could also be against the principles of natural justice or the order could contain an error of judgment in appreciating the facts of the case.<sup>4</sup>

"**Lord Chancellor Viscount Simon in Ryots of Garabandho and other villages Vs. Zamindar of Parlakimedi and Anr.**"<sup>5</sup>2."The ancient writ of certiorari in

England is an original writ which may issue out of a superior Court requiring that the record of the proceedings in some cause or matter pending before an inferior Court should be transmitted into the superior Court to be there dealt with. The writ is so named because, in its original Latin form, it required that the King should "be certified" of the proceedings to be investigated, and the object is to secure by the exercise of the authority of a superior Court, that the jurisdiction of the inferior tribunal should be properly exercised. This writ does not issue to correct purely executive acts, but, on the other hand, its application is not narrowly limited to inferior "Courts" in the strictest sense. Broadly speaking, it may be said that if the act done by the inferior body is a judicial act, as distinguished from being a ministerial act, certiorari will lie. The remedy, in point of principle, is derived from the superintending authority which the Sovereign's Superior Courts, and in particular the Court of King's Bench, possess and exercise over inferior jurisdictions. This principle has been transplanted to other parts of the King's dominions, and operates, within certain limits, in British India."

● **Indian Perspective** - Article 226 as stated above vests right to High Court to issue the writ of Certiorari mainly on error of Jurisdiction. In case of "**Hari Vishnu Kamath Vs. Ahmad Ishaque 1955-I S 1104**"<sup>6</sup> ((s)), Hon'ble Apex Court given following four propositions for issuance of the writ of Certiorari:

1. Certiorari will be issued for correcting errors of jurisdiction;
2. Certiorari will also be issued when the Court or Tribunal acts illegally in the exercise of its undoubted jurisdiction, as when it decides without giving an opportunity to the parties to be heard, or violates the principles of natural justice;
3. The court issuing a writ of certiorari acts in exercise of a supervisory and not appellate jurisdiction. One consequence of this is that the court will not review findings of fact reached by the inferior court or tribunal,

even if they be erroneous.

4. An error in the decision or determination itself may also be amenable to a writ of certiorari if it is a manifest error apparent on the face of the proceedings, e.g., when it is based on clear ignorance or disregard of the provisions of law. In other words, it is a patent error which can be corrected by certiorari but not a mere wrong decision."

In case of "**Nagendra Nath Bora & Anr. Vs. Commissioner of Hills Division and Appeals, Assam & Ors.**"<sup>7,3</sup> the parameters for the exercise of jurisdiction, calling upon the issuance of writ of certiorari where so set out by the Constitution Bench :

"The Common law writ, now called the order of certiorari, which has also been adopted by our Constitution, is not meant to take the place of an appeal where the Statute does not confer a right of appeal. Its purpose is only to determine, on an examination of the record, whether the inferior tribunal has exceeded its jurisdiction or has not proceeded in accordance with the essential requirements of the law which it was meant to administer. Mere formal or technical errors, even though of law, will not be sufficient to attract this extra-ordinary jurisdiction. Where the errors cannot be said to be errors of law apparent on the face of the record, but they are merely errors in appreciation of documentary evidence or affidavits, errors in drawing inferences or omission to draw inference or in other words errors which a court sitting as a court of appeal only, could have examined and, if necessary, corrected and the appellate authority under a statute in question has unlimited jurisdiction to examine and appreciate the evidence in the exercise of its appellate or revisional jurisdiction and it has not been shown that in exercising its powers the appellate authority disregarded any mandatory provisions of the law but what can be said at the most was that it had disregarded certain executive instructions not having the force of law, there is not case for the exercise of the jurisdiction under Article 226."

● **Certiorari and Prohibition distinguished**

- i. Though prohibition and certiorari are both issued against Courts or tribunals exercising judicial or quasi-judicial powers, certiorari is issued to quash the order or decision of the tribunal while prohibition is issued to prohibit the tribunal from an ultra vires order or decision.
- ii. While prohibition is available at an earlier stage, certiorari is available at a later stage, on similar grounds. The object of both is to secure that the jurisdiction of

an inferior court or tribunal is properly exercised and to see that it does not usurp the jurisdiction for which it does not possess an authority.

Hence in this way the writ of certiorari is used in India for the lack of Jurisdiction. This writ has proved to be very effective in the fields of Justice.

**References:-**

**Books Referred:-**

1. Administrative Law By- J.J.R. Upadhyaya, Central Law Agency, Seventh Edition, 2009
2. Indian Administrative Law By- Kagzi M.C. Jain, Universal Law Publishing co. Pvt. Ltd, 53<sup>rd</sup> year of Publication, Seventh Edition, 2014
3. The Constitution of India Bare Act, Professional's, Year 2006
4. The Constitutional Law of India By- Dr. J.N. Pandey, 49th Edition, 2011
5. The Constitution of India By- Dr. L.M. Singhvi, 2nd Edition, Volume 2, Modern Law Publication, Year 2008
6. Principles of Administrative Law, Set of 2 Volumes, By- M.P. Jain & S.N. Jain, Revised By Justice D.M. Dharmadhikari, (Former Judge of the Supreme Court), Lexis Nexis, 8<sup>th</sup> Edition, 2016

**Internet:-**

1. [www.google.com](http://www.google.com)
2. [www.indiacurrentaffairs.org](http://www.indiacurrentaffairs.org).
3. <http://www.legalblog.in/2011/05/writ-of-certiorari-scope-and-ambit.html>
4. <http://www.yourarticlelibrary.com/law/4-important-writs-of-india-explained/24873/>
5. "Certiorari ! Define Certiorari at Dictionary.com"
6. "Definition of certiorari in Oxford dictionary (British & World English)"
7. [https://en.wikipedia.org/wiki/Certiorari#cite\\_note-oxf-2](https://en.wikipedia.org/wiki/Certiorari#cite_note-oxf-2)

**Law Journals:-**

1. AIR 1943 PC 164
2. AIR 1955 SC 233
3. (1955) 1 SCR 1104
4. (1958) SCR 1240

**News Papers:-**

1. Dainik Bhaskar
2. Dainik Jagran
3. The Times of India
4. The Hindustan Times
5. The Hitvada
6. Patrika

**Dictionaries:-**

1. Black's Law Dictionary (First South Asian Edition, 2015)

\*\*\*\*\*

## परम्परागत दृश्य कला रूप और संस्थापन कला

**डॉ. अनुराधा आर्य \***

**शोध सारांश** – सृजनात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण परंपरा में ही विकसित होने वाली कला अपने साथ अतीत और वर्तमान को संजोकर चलती है। कला नवीन माध्यम, शैली व तकनीक के सहारे परंपराओं में नवीन आयामों को जोड़कर नयी कला दृष्टि परंपरा को जन्म देती है। पारंपरिक कला सृजन की प्रेरणा के लिए कभी बाँझ नहीं होती। वर्तमान संस्थापन कला रूप भी प्राचीन परंपरागत संस्थापन कला रूपों यथा विभिन्न लोक कलाओं तथा धार्मिक अनुष्ठानों से ही प्रेरित है। दरअसल संस्थापन भारतीय जीवन में रचा-बसा है, परन्तु कला कार्य के रूप में यह विचित्र सा प्रतीत होता है। साठ के दशक में उपजी यह कला चित्रों के सांचों को तोड़ कर कला वीथिकाओं से बाहर आने को मचल उठी। कलाकार संपूर्ण वातावरण बनाने हेतु चित्रों के अतिरिक्त स्थापत्य, रंगमंच, वीडियो, कम्प्यूटर, चलचित्र, ध्वनि, प्रकाश, गति तथा निर्जीव व व्यर्थ वस्तुओं की सहायता से डिजिटल, मल्टीमीडिया और हाइब्रिड मल्टीमीडिया संस्थानों के माध्यम से अभिव्यक्ति करने लगे हैं। समकालीन भारतीय कला जगत में संस्थापन कला के लिए उठ रहे विभिन्न नकारात्मक प्रश्नों के बावजूद संस्थापन कलाकारों का एक बड़ा समूह अपनी पैठ बनाने में सफल है। प्रस्तुत शोध पत्र में विभिन्न समकालीन भारतीय संस्थापन कलाकारों के बारे में अध्ययन किया गया है।

**प्रस्तावना** – कला जगत् में आदि मानव द्वारा छोड़े गये पदचिह्नों पर ही आगामी कलाकार पीढ़ी ने कदम बढ़ाये। सम्पूर्ण कला इतिहास साक्षी है कि कला कला की परम्परा में ही विकसित होती है। यही परम्परा सृजनात्मक ऊर्जा का भण्डार होती है, जिससे कला को बिम्ब और प्रतीक मिलते हैं। परम्परा के साथ कला का सम्बन्ध माता के गर्भ के साथ नवजात शिशु के समान होता है। शिशु का जन्म एक नवीन सृजन है, लेकिन यह सृजन गर्भावस्था की तमाम स्थितियों से नियमित होता है। पश्चिमी कला में प्रभाववाद के प्रमुख कलाकार देगा ने भी पारम्परिक कला से नवीन सृजन के सम्बन्ध को स्वीकार किया है।

जिस प्रकार प्राकृतिक सृजन बीज – अंकुरण – जड़े फैलना – पल्लित होना – पुष्पित होना – फल देना जैसी क्रमिक प्रक्रिया में पारम्परिक वस्तु बीज से लेकर तत्कालीन स्थितियों – पोषक तत्व, प्रकाश, मौसमी हवा का स्पर्श आदि का भी पूर्ण योगदान होता है। 'कला की सृजनात्मकता में भी इसी तरह अतीत और वर्तमान की स्थितियों का संयोग निहित होता है।'<sup>1</sup>

कला भावों की अनुभूति को संप्रेषणीय सौन्दर्य में ढालने का माध्यम है। कलात्मक अभिव्यक्ति देने की यह क्षमता कला माध्यम, शैली व तकनीक की पूर्ववर्ती समझदारी पर आधारित होती है और अपने तात्पर्यानुसार उसे ढाल सकने की कुशलता से आती है। 'कला के रूपाकार और बिम्ब पर सम्पूर्ण अतीत और पूर्ववर्ती कला के रूपाकारों की छाया होती है। समुदाय और परम्परा का अन्योन्य सम्बन्ध होता है। समुदाय अपनी आवश्यकताओं और अपने अनुभवों के अनुसार परम्परा का निर्माण करता है और परम्परा समुदाय की विचारशैली और ग्रहणशीलता को प्रभावित करती है और समुदाय में ही जीवित रहती है। पहली प्रक्रिया से परम्परा का नवीनीकरण होता है, दूसरी प्रक्रिया से समुदाय अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है।'<sup>2</sup>

प्रसिद्ध साहित्यकार, कलाकार और चिंतक गेटे ने भी कलाकार पर समाज के प्रभाव को स्वीकारा है। अलग-अलग कला परम्पराओं में तूलिका की याददाश्त अलग-अलग तथा कलाकार की विशेष कला परम्परा की

निगाह भिन्न-भिन्न होती हैं। इस तरह कलाकार देखने के खास ढंग की परम्परा से बंधा होता है और इसके भीतर ही वस्तुओं और स्थितियों को देखता है। नयी सृजनात्मक कला इस पूरी परम्परा को नहीं तोड़ती बल्कि कुछ बिन्दुओं पर नया आयाम जोड़कर देखने के दायरे का विस्तार करती है, या नजरिया बदल देती है। आगे चलकर नयी कला दृष्टि परम्परा का अंग बन जाती है और भविष्य की सृजनात्मक कला के लिए 'लांचिंग पैड' का काम करती है।'<sup>3</sup>

इस प्रकार स्पष्ट है कि हर सार्थक और सृजनात्मक कला में परम्परा का नाद निहित होता है। नवीन कला सृजन में परम्परा से प्राप्त कला व्याकरण के पुराने नियम टूटकर नये नियम ले लेते हैं इसलिए जब तक कला कला है, इसकी सृजनात्मकता का उत्स भी परम्परागत कला में ही होगा। पर कला-प्रवाह में परम्परा का नवीकरण अनिवार्य रूप से होता रहता है। पारम्परिक कला-सृजन की प्रेरणा के लिए कभी बाँझ नहीं होती।

वेद नायर के अनुसार 'भारत में जब हम एक ट्रक पर एक गाय को सजाकर घर-घर धन एकत्र करने के लिए लोगों को जाते देखते हैं, तो इसमें बड़े संस्थापन की कल्पना करना आसान नहीं है।'<sup>4</sup> वर्तमान संस्थापन कला-रूप भी प्राचीन परम्परागत संस्थापन कला-रूपों यथा लोक कला, धार्मिक अनुष्ठानपरक संस्कारों से प्रेरित है। 'हम अपने सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संस्थापन कला का प्रदर्शन करते आ रहे हैं।'<sup>5</sup> दुर्गा अष्टमी पर दुर्गा की सज्जित प्रतिमा व रावण का बिम्ब, सांझी कला, गोबरधन, गृह प्रवेश, यज्ञ वेदी की व्यवस्था, धार्मिक झाँकियाँ, मुहर्रम के ताजिये, मधुबनी का कोहबर तथा जन्म से लेकर मृत्यु तक किये जाने वाले अनेकों संस्कार हमारे धार्मिक, सामाजिक व परम्परागत भावों को व्यक्त करते हैं। 'दरअसल संस्थापन भारतीय जीवन में रचा बसा है।'<sup>6</sup> व्यावहारिक जीवन में इसे एक अलग दृष्टि से देखा जाता है परन्तु कला-कार्य के रूप में यह विचित्र सा प्रतीत होता है।

'वर्तमान कला चाक्षुष सौन्दर्य की वाहक नहीं है। कला के अर्थ बदल

चुके हैं। अमूर्तन से इन्स्टालेशन तथा कान्सेप्टुअल आर्ट, कम्प्यूटर कला तक के अभिनव प्रयोग कला जगत् समृद्धशाली बना रहे हैं।<sup>7</sup> समकालीन कला में पूर्णतः व्यक्तिगत भावाभिव्यंजना के रूप में संस्थापन कला की विशिष्ट व भिन्न परम्परा है। विश्व का आधुनिक कला इतिहास बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही रचनात्मक क्रान्ति का साक्षी रहा है। यूरोप में मूर्तिशिल्प कला के मूलभूत तत्वों को लेकर संस्थापन कला का जन्म हुआ, जिसमें निर्माण हेतु रंगमंच, प्रतिकृतियां, नाटक व घटना के मौलिक तत्वों को एकत्रित कर संयोजित किया गया। इस क्षणभंगुर अस्थायी कला को छाया चित्रों के रूप में संजोया जा सकता है। 'इसमें पार्थिक कला (Earth Art) वैचारिक कला (Conceptual Art) अति सूक्ष्मवाद (Minimalism) के तत्वों का संयोग रहता है। इसका उद्देश्य धार्मिक सौन्दर्यशास्त्रीय अनुभव या मात्र सज्जा भी हो सकता है। इस कला में क्रियाशीलता महत्वपूर्ण है।'<sup>8</sup>

पश्चिमी आधुनिक कला आन्दोलनों में से घनवाद, दादावाद, नवयथार्थवाद, भविष्यवाद, अतिसूक्ष्मवाद, पॉप कला व ऑप कला में संस्थापन कला के बीज निहित थे, परन्तु साठ के दशक के अन्त तक ही इसे पहचान मिलनी प्रारम्भ हुई। संस्थापन कला भी अन्य कला आन्दोलनों की भाँति पूर्व कला आन्दोलनों के विरुद्ध उपजी एक विधा है। 'शुरु में संस्थापन कला पुराने सामान को नया अर्थ देने का प्रयास था। साठ-सत्तर के दशक की सामाजिक-राजनैतिक सच्चाई के विरुद्ध पश्चिमी कलाकार कला-दीर्घाओं के सफेद घनों की सीमाओं को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने मूलरूप के चित्रों के सांचों को तोड़ दिया तथा उनको रुढ़िगत कला-विधि व दृष्टि के बंधनों से मुक्त कर दिया।'<sup>9</sup>

समकालीन भारतीय कला में संस्थापन कला केन्द्रीय अभिव्यक्ति का माध्यम हो गई। अब संस्थापन कला कला-दीर्घाओं की कला-प्रदर्शनियों में अपना स्थान बना चुकी है। पहले ये द्विआयामी चित्रों तथा त्रिआयामी शिल्पों के खाली स्थानों की नीरसता को दूर करने हेतु प्रयोग होते थे, परन्तु अब तो यह कला-दीर्घाओं में तेजी से बढ़ रही है। युवा कलाकारों का रुझान इस ओर अधिक बढ़ रहा है, चूँकि यह सीमाओं तथा स्थायी वस्तु व माध्यमों से स्वतन्त्र है। इसका एक कारण यह भी है कि यह कला रूप पारिभाषिक शब्दावली तथा बहुआयामी है।<sup>10</sup>

समकालीन कलाकार मात्र चित्र ही नहीं बनाना चाहते अपितु वह एक सम्पूर्ण वातावरण बनाना चाहते हैं। वे अनेक कलाओं को एक साथ अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना चाहते हैं। 'वह स्थापत्य, रंगमंच, वीडियो, कम्प्यूटर, फिल्म, ध्वनि आदि सभी माध्यमों का इस्तेमाल अपनी प्रस्तुति में करना चाहते हैं। जाहिर है कि यह अभिव्यक्ति एक तरह की सामूहिक अभिव्यक्ति भी है। कलाकार एक पूरे दल के साथ अपनी कला दृष्टि को प्रेक्षक के सामने उभारना चाहता है।'<sup>11</sup>

संस्थापन कला एक ऐसा मंच है, जिसमें कलाकार प्रेक्षक का ध्यान खींचने हेतु सम्पूर्ण वातावरण का निर्माण करते हैं और अपनी अभिव्यक्ति को सामने लाते हैं। 'वे अन्तराल के साथ परीक्षण करते हैं। वे अपने चारों ओर के वातावरण को पुनर्परिभाषित कर कला-कार्य की कल्पना करते हैं। यह बिल्कुल चतुर नट जोड़े द्वारा बर्फ पर किये गये फिसलने के प्रदर्शन की भाँति है। शरीर की गतियों को समस्त बोध और विचार के तर्कशास्त्र से परे आकर्षक ढंग से लिया जाता है।'<sup>12</sup>

सन् 1990 में नेकचन्द्र द्वारा चण्डीगढ़ में व्यर्थ वस्तुओं द्वारा बनाया गया रॉक गार्डन भारत में कलात्मक संस्थापन कला का प्रथम प्रयास था, जो स्थायी है। इसी दौरान एम.एफ. हुसैन द्वारा दिल्ली में बनाया गया संस्थापन

कला-रूप 'थियेटर ऑफ दि एब्सर्ड' समकालीन भारतीय कला का महत्वपूर्ण परिवर्तन था। सन् 1991 में विवॉन सुन्दरम् के संस्थापन 'मैमोरियल' द्वारा राजनैतिक वैश्वीकरण परिदृश्य को कला में उजागर किया गया। इसके बाद तो भारत में संस्थापन कला का एक दौर प्रारम्भ हो गया। सुष्मिता विश्वास के शब्दों में 'संस्थापन कलाकार भारतीय कला-प्रेमियों को कैनवास के बाहर का अनुभव प्रदान कर रहे हैं।'<sup>13</sup>

संचार क्रान्ति और भूमण्डलीकरण ने तो संस्थापन कला के सामने अनेकों आधुनिक विधाओं को परोस दिया है। 'नई टेक्नोलॉजी और माध्यमों ने संस्थापन कलाकारों को अपने विचारों को उनके प्रयोग द्वारा व्यक्त करने में सहायता की है और इसमें मानव शरीर तथा वातावरण स्वयं विचारों को संस्थापित करने का सबसे शक्तिशाली पहलू ही सर्वोपरि बन गया है।'<sup>14</sup> निर्जीव व व्यर्थ वस्तुओं से बने संस्थापनों के अतिरिक्त कलाकारों की कला वीडियो, ऑडियो, रोबोट, कम्प्यूटर, परफार्मिंग, डिजिटल, मल्टीमीडिया तथा हाइब्रिड मल्टीमीडिया में भी अभिव्यक्त हो रही है।

रॉयल कॉलेज आफ आर्ट, लन्दन से उच्च कला शिक्षा प्राप्त जगन्नाथ पांडा के अनुसार 'कला का अभ्यास मात्र पत्थर उकेरना, धातु को ढालना या कैनवास व कागज पर काम करना ही नहीं है, यह तो इन सब आश्चर्यों से परे है। मैंने फिल्में देखीं, मेरे लिए फिल्म गतिमान मूर्तिशिल्प है। फिल्में देखने से मैंने मूर्तिशिल्पों में गति प्रवाह ग्रहण किया। मैंने संगीत सुना। जिससे मैंने मूर्तिशिल्पों में ध्वनि ग्रहण की। मैंने ध्वनि को अपने कार्य में एक वस्तु की भाँति प्रयोग किया। खेलों को देखने से मेरी कला में शारीरिक गति व लचीलापन आया। कला अब एक टेक्नोलॉजी प्रकृति की हो गयी है। मुझे अपनी पहुँच में वैज्ञानिक होने की आवश्यकता है। अब कला कार्यशालायें प्रयोगशालायें हो गयी हैं तथा कलाकार तकनीक, अभियांत्रिकी तथा विज्ञान के ज्ञाता हैं।'<sup>15</sup> इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समकालीन भारतीय कलाकार सभी विधाओं व क्षेत्रों में अपने हाथ आजमा रहे हैं।

'वेद नायर लम्बे समय से संस्थापन में रुचि ले रहे हैं। वह मूर्तिशिल्प, पेंटिंग, डिजाइन, स्थापत्य आदि की एक सम्पूर्ण समझ के साथ पर्यावरण की बुनियादी समस्या को एक कलात्मक अभिव्यक्ति देते हैं।'<sup>16</sup> सरोज गोपीपाल का संस्थापन 'सिंहावलोकन:लाल सरयू की आँखें' वर्तमान भारतीय स्त्री की दशा को इंगित करता है। 'एम.एफ. हुसैन ने श्वेताम्बरी नामक इन्स्टालेशन आधुनिक कला दीर्घा में आयोजित किया था जिसमें सफेद कपड़े को पूरे फर्श पर फैलाकर नयी रचना को जन्म दिया था।'<sup>17</sup> सुबोध गुप्ता के संस्थापन 'डेट वाई डेट' तथा 'स्कूल' में उन्होंने ग्रामीण व मध्यवर्गीय भारतीयों के दिन-प्रतिदिन के अनुभवों को शुद्धतम तथा सूक्ष्मतम रूप में विश्व प्रेक्षकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। दीवार एवं धरातल पर हेमा उपाध्याय की कोक्रोचों की रचना या पालीथीन की बड़ी-बड़ी थैलियों में पंखे की हवा भरकर गति व वायु प्रवाह अविस्मरणीय रहा है।

जगन्नाथ पांडा के अनुसार 'विश्व बहुत तीव्र हो गया है। जीवन बहुत तेजी से दौड़ रहा है। इसलिए कला को भी फास्ट फूड होना पड़ेगा। हम प्रमुखतः तेज हैं। हम समय तथा अन्तराल के प्रति बिल्कुल सही हैं।'<sup>18</sup> उनका संस्थापन 'हाउस पैट, पोलीथीन, एअर, फैन, ह्यूमन हेअर' में उक्त कथन के साक्षात् दर्शन होते हैं। पोलीथीन, कागज, गैस, प्रकाश, हवा और ध्वनि का आकर्षक समन्वय उनके संस्थापनों की विशेषता रही है।

'रत्नबाली कांत ने वीडियो फिल्मों का प्रयोग कर उसे प्रदर्शन हेतु रखा था। उनकी 'डेथ आफ डिजायर' में वीडियो फिल्म के रूप में इन्स्टालेशन जिसकी समयावधि दो घंटे की थी उल्लेखनीय है। इसी प्रकार सुदर्शन शेटी ने



लकड़ी पर अक्रेलिक लगाकर फाइबर ग्लास, रस्सी तथा रंगीन कांच से इन्स्टालेशन किया था।<sup>19</sup>

अपने आस-पास उपलब्ध उपयोगी, अनुपयोगी, साधारण, उत्तम, व्यर्थहीन वस्तुओं से मिलाकर संस्थापन बनाने वाले विवॉन सुन्दरम् के लिए ये सभी वस्तुएँ कला के लिए बहुत सार्थक व अर्थपूर्ण हैं। 'रेस्टिंग अगेन्स्ट टेन्ट', 'मैनकाइन्ड', 'डिस्पेयर एण्ड होप ऑफ कल्पवृक्ष', 'द वर्ड', 'व ट्री एण्ड द प्लावर एज ट्राफीज' उनके स्मरणीय संस्थापन हैं।

आधुनिक मशीनों तथा उनके मानव जाति पर प्रभाव से चिंतित बैजू पार्थन ने हाईब्रिड मल्टीमीडिया और डिजिटल संस्थापन में भूत और वर्तमान को नवीन रूप से संमिश्र किया। 'पार्थन का कार्य धार्मिक विश्वासों पर टेक्नोलॉजी के प्रभाव, पैतृक अभियांत्रिकी के फसाद और उत्तार मानववाद की संभावनाओं से प्रेरित है।'<sup>20</sup> 'डायरी आफ द इन्नर साइवार्ज' उनका संस्थापन है।

कृष्णमाचारी बोस का 'एम्पूजम' नामक संस्थापन प्रमुख है। इसमें किताबों की शृंखला, छल्लों में कसी किताबें, उनके चिपके, रंगे हुए व कविता लिखे पृष्ठ जिसे शीशे के खांचों में प्रदर्शन हेतु रखा गया था।<sup>21</sup> प्रिंट मेकर पोला सेनगुप्ता भी संस्थापन में अच्छी पैठ रखती हैं। उनका कहना है कि 'कला दीर्घाएं सदैव उनकी कला के लिए आदर्श जगह नहीं होती हैं।'<sup>22</sup> एलीना बैनिक ने भी चित्रकार और मूर्तिकार से वीडियो तथा मल्टीमीडिया संस्थापनकार तक की कला यात्रा की है। रुट्स-एन-राउट नामक प्रदर्शनी में उनका संस्थापन प्रदर्शित था, जिसको उन्होंने अपनी विश्व यात्राओं के दौरान एकत्रित थैलों व थैलियों से बनाया था। 'उनका कहना था कि यह कार्य प्लास्टिक थैलों के विरुद्ध तथा वातावरण के प्रति मित्रतापूर्ण वस्तुओं के प्रयोग से सम्बन्धित था। मुझे ऐसा लगता है कि शान्ति और सृजनात्मकता का संदेश फैलाना मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कार्य द्वारा दुनियाँ को अपने नम्रतापूर्वक तरीके से बता रही हूँ।'<sup>23</sup>

मुम्बई के कलाकार नवजोत अलताफ द्वारा 2001-03 में 'श्री हाल्वस' नामक संस्थापन में दृश्य के साथ श्रव्य, 2001-02 में 'बिटविन मैमोरी एण्ड हिस्ट्री' नामक संस्थापन में दृश्य व श्रव्य के साथ लिखित सामग्री तथा 1994 में 'लिंग्स डेस्ट्रॉयड एण्ड री-डिस्कबर्ड' नामक संस्थापन में चित्र, पर्दा, छापे, फिल्म तथा संगीत का प्रयोग कर कला को एक नवीन आयाम दिया। पेशे से वेब डिजाइनर शिल्पा गुप्ता के संस्थापन कार्य में भी संचार माध्यमों की विविधता दृष्टिगोचर होती है। उनकी कला वैश्विक भ्रष्टाचार तथा व्यक्तिगत विषमताओं पर प्रहार करती है।<sup>24</sup>

श्रीधर अय्यर एक वीडियो संस्थापन कलाकार हैं। शकुन्तला कुलकर्णी भी मल्टीमीडिया में संस्थापन बनाती हैं। नलिनी मालिनी के रेखाचित्र और चित्र, ऐनीमेशन, वीडियो और फिल्म तक विस्तारित हैं। सुबोध केरकर का 'द मून एण्ड द टाइड', चिन्तन उपाध्याय का 'माया', 'डिजाइनर वेबीज', 'बार-बार, हर-बार, कितनी बार?' तथा 'बोर्द', किर्न सुबैहा का 'स्यूसाइड नोट', सुषमा बहल का 'स्वयंभू 2011', रोमिन मित्रा का 'ड्रीम होम-प्रेटी अग्ली 2010' रंजनी सेतार का 'बर्ड सांगा' आदि संस्थापन के अतिरिक्त अनेकों समकालीन भारतीय कलाकार संस्थापन कला में संलग्न हैं, जिनमें हीरन मित्रा, शैवाक्षी, शीला गौड़, जितेश कल्लट, रीना सैनी कल्लट, अनीस कपूर, एल.एन. तल्लूर, सिद्धार्थ, चित्रभानु मजूमदार, अदीप दत्ता, रूपचन्द्र कुंडू, सुमित दास, विनोद श्रेष्ठ, रनवीर कालेका, अतुल डोडिया, अंजु डोडिया, शिवू नतेसन, सुरेन्द्र नायर, जयश्री चक्रवर्ती, रेखा रोडुत्तिया, जी.रनवीर रेड्डी, अर्पणा कौर, सतीश गुजराल, शमशाद हुसैन, एन. पुष्पमाला, राजेन्द्र

टिक्कू, राजीव सेठी, एन.एस. रिमजॉन, निहाल शाह, ज्योति कोल्टे, दर्शन वीरा, एच.जी. अरुण कुमार आदि प्रमुख हैं।

समकालीन भारतीय कला में संस्थापन कला व कलाकारों की प्रगति देखते हुए एक बड़ा प्रश्न उठता है कि भारत में संस्थापन कला की क्या संभावनाएँ हैं? विवॉन सुन्दरम् के अनुसार 'संस्थापन कला भारत में बहुत सफल नहीं है क्योंकि लोगों का रुख कला की ओर अधिक रुढ़िवादी है।'<sup>25</sup> इसके अतिरिक्त जगह का प्रश्न उठता है। संस्थापन किसी भी ड्राइंग रूम में नहीं टांगा जा सकता और इसके लिए विशाल जगह की आवश्यकता होती है। न ही इसे किसी संग्रहालय या कला संग्रह में रखा जा सकता है। इसको समझने और सराहने वाले दर्शकों की संख्या कम है। इसको न ही बेचा जा सकता है और न ही खरीदा जा सकता है। शेटी के अनुसार 'हमें यह ध्यान रखना है कि संस्थापन कला एक विशाल कला कार्य है और कोई भी एक व्यक्ति सम्पूर्ण कार्य को नहीं खरीद सकता है।'<sup>26</sup> जबकि एलीना बैनिक का मानना है कि कोई भी एक व्यक्ति उसके एक हिस्से को खरीद कर संग्रह कर सकता है। कुछ कला-दीर्घाओं के मालिकों का सोचना है कि संस्थापन कला वर्तमान कला बाजार की खरीद-फरोख्त प्रतियोगिता से बचने का एक तरीका है।

इस प्रकार सार्थकता और सीमाओं के विभिन्न प्रश्नों में उलझी संस्थापन कला समकालीन परिदृश्य पर एक कलाकार व दर्शकों के लिए आकर्षक का केन्द्र बनी हुई है, चूँकि इसमें ज्वलंत विषयों पर व्यापक वस्तुओं व माध्यमों द्वारा स्वतन्त्र प्रदर्शन की अपार संभावनाएँ निहित हैं। इसमें आवश्यक नहीं कि हस्त कुशल कलाकार ही प्रतिभागी हो। व्यापक सोच व मन-मस्तिष्क की अनंत गहराईयों के गोताखोर भी संस्थापन कला के द्वारा कला जगत् में अपनी पैठ बनाने में सफल हैं। यही कारण है कि संस्थापन में मात्र कला तत्वों या सिद्धान्तों का ही नहीं अपितु वर्तमान दर्शन, विज्ञान, मनोविज्ञान, अभियांत्रिकी तथा डिजिटल तकनीकों व सिद्धान्तों का अद्वितीय व आकर्षक संगम दिखायी देता है, जो सहज ही वर्तमान युवा पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित किये बिना नहीं रहता। इसमें परम्परागत प्रस्तुति वही है परन्तु माध्यम और विषय-वस्तु में ही परिवर्तन आया है।

### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. समकालीन कला : नवम्बर 1986/मई 1987, संख्या 7-8, पृ0 13.
2. वही : पृ0 13.
3. वही : पृ0 15.
4. कला-चित्रकला : विनोद भारद्वाज : पृ0 39-40.
5. कला-दीर्घा : अप्रैल 2001, वर्ष-1, अंक-2, पृ0 80.
6. कला-चित्रकला : विनोद भारद्वाज : पृ0 40.
7. कला दीर्घा : वाल्यूम-3, नं0 6, अप्रैल 2003, पृ0 31.
8. समकालीन भारतीय कला : डॉ0 ममता चतुर्वेदी : पृ0 131.
9. [www.artindia.net/johny/art 5.html](http://www.artindia.net/johny/art 5.html)
10. कला दीर्घा : अप्रैल 2001 वर्ष -1, अंक-2, पृ0 80.
11. कला-चित्रकला : विनोद भारद्वाज : पृ0 38-39.
12. [www.artindia.net/johny/art 5.html](http://www.artindia.net/johny/art 5.html)
13. [Telegraphindia.com/1050108/asp/weekend/story.4226003.asp](http://Telegraphindia.com/1050108/asp/weekend/story.4226003.asp)
14. [www.artindia.net/johny/art 5.html](http://www.artindia.net/johny/art 5.html)
15. कला दीर्घा : वाल्यूम-3, नं0 6, अप्रैल 2003, पृ0 77.
16. कला-चित्रकला : विनोद भारद्वाज : पृ0 39.

- |  |             |
|--|-------------|
| 17. कला दीर्घा : वाल्यूम-3, नं0 6, अप्रैल 2003, पृ0 32.          | 4226003.asp |
| 18. वही : पृ0 76.  | 22. वही     |
| 19. वही : पृ0 32.  | 23. वही     |
| 20. Telegraphindia.com/1050108/asp/weekend/story.<br>4226003.asp | 24. वही     |
|  | 25. वही     |
| 21. Telegraphindia.com/1050108/asp/weekend/story.                | 26. वही।    |

\*\*\*\*\*

# On Some Properties of Metric F - Structure Satisfying $F^5 + F = 0$

Lakhan Singh\*

**Abstract** - In this paper we have studied various properties of the F - Structure satisfying  $F^5 + F = 0$ . The metric F-Structure,  $f$  induced on each integral manifold of tangent bundle  $I^*$  have also been discussed.

**Keywords** - Differentiable manifold, projection operators, tangent bundle and Metric.

**1. Introduction** : Let  $V_n$  be a differentiable manifold of class  $C^\infty$  and  $F$  be a  $(1, 1)$  tensor of class  $C^\infty$  defined on  $V_n$  such that

$$(1.1) F^5 + F = 0$$

We define the projection operators  $I$  and  $m$  on  $V_n$  by

$$(1.2) I = -F^4, m = I + F^4$$

from (1.1) and (1.2), we have

$$(1.3) I + m = I, F = I, m^2 = m, Im = mI = 0,$$

$$FI = IF = F, Fm = mF = 0$$

Where  $I$  denotes the identity operator.

**Theorem (1.1)** : If  $\text{rank}((F)) = n$  then

$$(1.4) I = I, m = 0$$

**Proof** : from the fact

$$(1.5) \text{rank}((F)) + \text{nulity}((F)) = \dim V_n = n$$

Thus

$$(1.6) \text{nulity}((F)) = 0 \Rightarrow \ker((F)) = 0$$

Thus

$$FX = 0 \Rightarrow X = 0$$

$$\text{Then } FX_1 = FX_2$$

$$F(X_1 - X_2) = 0$$

$$X_1 = X_2 \text{ or } F \text{ is } 1-1$$

Moreover  $V_n$  being finite dimensional  $F$  is onto also  $F$  is invertible operating  $F^{-1}$  on  $FI = F$  and  $mF = 0$ , we get (1.4)

**Theorem (1.2)** : if  $\text{rank}((F)) = n-1$  then

$$(1.7) I = I - A \otimes T, m = A \otimes T, A \circ F = 0, FT = 0$$

**PROOF** : from (1.1)

$$(1.8) F(F^4 + I) = 0$$

$$(1.9) \text{let } F^4 + I = A \otimes T$$

From (1.8) and (1.9)

$$(1.10) FT = 0$$

Also from (1.2) and (1.9)

$$I = -F^4 = I - A \otimes T$$

$$m = -F^4 + I = A \otimes T$$

from (1.5) and (1.6)

$$F^4X + X = A \otimes T$$

$$F^4X + FX = A(FX)T$$

$$0 = A(FX)T$$

Thus  $A \circ F = 0$

**Theorem (1.3)** : let the operators  $m$  &  $F$  satisfying

$$(1.11) m^2 = m, Fm = mF = 0, (m + F^2)(m - F^2) = I$$

Then we get (1.1)

**Proof** : from  $(m + F^2)(m - F^2) = I$

$$m^2 - mF^2 + F^2m - F^4 = I$$

$$m - 0 + 0 - F^4 = I$$

$$mF - F^5 = F$$

$$F^2 + F = 0$$

**2. Metric F - Structure**

if we define

$$(2.1) 'F(X, Y) = g(FX, Y) \text{ is skew-symmetric, then}$$

$$(2.2) g(FX, Y) = -g(X, FY) \text{ and}$$

**Theorem (3.1)** : on the metric structure -  $F$ , satisfying

(1.1) we have

$$(2.3) g(F^2X, F^2Y) = -g(X, Y) + 'm(X, Y), \text{ where}$$

$$(2.4) 'm(X, Y) = g(mX, Y) = g(X, mY)$$

**Proof** : Using (1.2), (1.3), and (2.2), we have

$$g(F^2X, F^2Y) = g(X, F^4Y)$$

$$= g(X, -IY)$$

$$= -g(X, IY)$$

$$= -g(X, (I - m)Y)$$

$$= -g(X, Y) + g(X, mY)$$

$$= -g(X, Y) + 'm(X, Y)$$

**Theorem (2.2)** :  $\{F, g\}$  is not unique

**Proof** :

$$(2.6) \text{let } \mu F' = F\mu, 'g(X, Y) = g(\mu X, \mu Y)$$

Then from (1.1) and (1.2), (1.3), (2.6)

$$(2.7) \mu F'^5 = F^5\mu = -F\mu = \mu F' \text{ or}$$

$$(2.8) F'^5 + F' = 0. \text{ Also}$$

$$(2.9) g(F'^2X, F'^2Y) = g(\mu F'^2X, \mu F'^2Y)$$

$$= g(F^2\mu X, F^2\mu Y)$$

$$= -g(\mu X, F^4\mu Y)$$

$$= -g(\mu X, -\mu Y)$$

$$= -g(\mu X, -(I - m)\mu Y)$$

$$= -g(\mu X, \mu Y) + g(\mu X, m\mu Y)$$

$$= -'g(X, Y) + 'm(X, Y)$$

**3. Induced structure  $f$  :**

Define (3.1)  $fX' = FX'$  for  $X' \in I^*$

**Theorem (3.1)** : If  $f$  satisfying (3.1) and  $F$  (1.1) then  $\{f^2\}$  is an almost complex structure.

**Proof** : from (1.2), (1.3) and (3.1)

$$\begin{aligned}(3.2) \quad f^2IX' &= F^2IX' \\ &= -f^2X' \\ &= -IX'\end{aligned}$$

Thus  $\{f^2\}$  as an almost complex structure on  $I^*$

Also

$$\begin{aligned}(3.3) \quad \mu I' &= -\mu F'^4 \\ &= -F^4\mu \\ &= \mu\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(3.4) \quad \mu m' &= \mu(I + F'^4) \\ &= \mu + \mu F'^4 \\ &= \mu + F^4\mu \\ &= (I + F^4)\mu \\ &= m\mu\end{aligned}$$

#### References:-

1. Bejancu, A, CR-submanifolds of a Kaehler Manifold I, proc. Amer. Math. Soc., 69,135-143(1978).
2. Demetropoulou-Psomopoulou, D. and Andreou, F. Gouli, On Necessary and sufficient conditions for an

N- Dimensional Manifold to admit a Tensor Field  $f(\neq 0)$

of type (1,1) satisfying  $f^{2n+3} + f = 0$  Tensor (N.S.), 42,252-257(1985)

3. Blair, D.E. and Chen, B.Y., On CR- submanifolds of Hermitian Manifolds. Israel Journal of Mathematics, 34(4),353-363(1979).
4. Goldberg, S.I. and Yano, K., On normal globally framed f- manifolds. Tohoku Math., I. 22,362-370(1970).
5. Goldberg, S.I., On the Existence of Manifold with an F-structure. Tensor (N.S.), 26,323-329(1972).
6. Upadhyay, M.D. and Gupta, V.C. Integrability conditions of a structure  $f_g$  satisfying  $f^3 + \epsilon^2 f = 0$ , publications mathematics, 24(3-4),249-255(1977).
7. Yano, K., On structure defined by a tensor Reid  $f$  of type (1,1) satisfying  $f^3 + f = 0$ , Tensor (N.S.) 14,99-109(1963)
8. Yano, K. and Kon, M., Differential geometry of CR-submanifolds, Geometriae Dedicata. 10, 369-391(1981).
9. Das, L.S., Nivas, R. and Singh, A. On CR-structures and F-structures satisfying  $F^{4n} + F^{4n-1} + \dots + F^2 + F = 0$ , Tensor N.S. 70.255-260(2008).
10. Das, L.S., On CR-structure and  $F(2K+1.1)$ - structure satisfying  $F^{2k+1} + F = 0$ , JTSI, India. 22,1-7(2004).

\*\*\*\*\*



# Environmental Sustainability and Public Policy in India

Dr. Archana Singh\*

**Abstract** - The international organization, developed countries and developing countries are concerned for environment protection and development process in 21<sup>st</sup> century. UN millennium goals clearly target to reduce poverty, hunger disease, illiteracy, environmental degradation, the paper is focused on public policy formulation and implementation related to environmental sustainability.

**Introduction** - The 2030 Agenda for sustainable development, adopted by all united nations member states in 2015, provides a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet, now and into the future. At its heart are the 17 sustainable development goals (SDGs) which are an urgent call for action by all countries developed and developing in a global partnership. They recognize that ending poverty and other deprivations must go hand in hand with strategies that improve health and education, reduce inequality and spur economic growth all while tackling climate change and working to preserve our oceans and forests.

When the discussion on environmental sustainability is argued that the impact of uncontrolled human interactions with natural subsystems may jeopardize these symbiotic relationship, thus leading to genuine ecological crises. Such ecological crises may imply the necessity to emphasize the importance of bringing human development into harmony with the natural environment without jeopardizing the welfare of current and future generations.

"Gandhi is reported to have observed that the world has enough for everyone's but not for everyone's greed". This argument clearly indicates to the concept of sustainable development. The central rationale for SD has been to increase the standard of living and in particular, the well-being of the least advantaged people in societies, avoiding UN compensated future costs sustainable development highlights the importance of the sustainability of ecological and social systems rather than economic sustainability also. It is also defined as a development that improves health care, education and social well being. Given the global and local effects of environmental decay, it is no surprise that sustainable development has become a catch word in development planning and resource management. However interpretation of this concept is still ambiguous. According to the Brundtland Report, the idea of sustainable development reaches for beyond environmental protection, as it means a process of change in which exploitation of resource, direction of investments, orientation of resources,

direction of investments, orientations of technological development and institutional changes are made consistent with future as well as present needs. It is not a fixed state of harmony but rather balanced and adoptive process of change.

It also follows that the goal of SD can only be achieved by making changes in the present political, economic and technological system at the global level and by making major changes in the management of planet earth. There is a need to evolve a new global psychology a fresh way of thinking about both political and economic change and society's relationship with nature.

The threshold of the new millennium has furnished us with a good occasion to reflect upon and evaluate India's experiences in administrative development toward its pursuit of good governance and ponder over the likely emerging trends and the lessons learned for the future. Reflecting on the realities of the Public Administration System in India over the last half century is not a simple exercise for India is a complex society composed of diverse languages, social systems, ethnic, tribal and caste groups, religious, regions and culture patterns of the masses and public functionaries at all levels. All those factors affect the idea of rationalism in administrative behavior it is very difficult to objectively evaluate their impact on governance. Since independence in 1947, the government of India has taken a number of steps to revamp the system of administration at different stages of its evolution with a view to secure objectivity, transparency, efficiency and responsiveness in the administrative process the basic ingredients of good governance in a democratic system based on the concepts of the rule of law and the public welfare. As it appears, the search for the exclusive goal of good governance India has been concurrent with the evolution of a constitutional democratic government, a government that is limited, stable and truly representative of majority of the people, maintains its territorial integrity and national sovereignty, accelerates economic growth and development, upholds the rule of law and renders justice

\*Associate Professor (Political Science) MMH College, Ghaziabad (U.P.) INDIA

without fear or favor and with our delay and ensures the welfare of all sections of the people. These objectives were sought through the adoption of the Republican constitution in 1950. Despite of lofty ideals and values of good governance enshrined in the constitution however we find over selves today in a state in which the system has not been able to provide either a stable government or stable policies what has gone wrong in our constitutinaland administrative system during the last fifty years is a question being raised again and again without any satisfactory answer.

When we analyze this fact we can't ignore the whole process of public policy. Public policy is the chief instrument of a politically organized community, the entire process involving/ concerning public policy needs to be discerned primarily from two dominant angles from the input side the articulation of needs and interests and finally the factors determining the choice activity have to be looked at from the output side a distributed analyses has to be undertaken in that impact of the policy has to be assessed. This bring out two major dimensions to public policy making. It is an instrument of effective control over the environment in that it harbours the potential to create. "Apocalyptic social transformation". The other dimension is the it derives the normative on which it is based from the environment public policy thus both procures and imparts values from to the environment. It is the chief instrumentality by which the impact throughput and output activity is preformatted.

When we talk about India, policy making in India has to take place in context of a complex and variegated society. This has its own fundamentals its own Compulsions and own inner dynamics. The ambitious goals set for society have put it in state of flux and chanae. The goals of national reconstruction, including abolition of poverty have led to rising expectations and generated the need for rapid and orderly change.

The policy making process in India has same major problem areas for governance and administration. It is unfortunate but true that Government and administration have lost a great deal at their credibility. The most vital task is to restore it. The existence of a dual system of values on the part of the Political and administrative elites In India who have the basic responsibility of implementing the system in their public pronouncements and external behavior, the are highly idealistic and show deep concern for integrity equity and justice the prime value of good aovernance:

In practice, however when its comes to actual decision making and its implementation, the same political and administrative elites are vulnerable to all kinds of narrow prejudices bias sand pressure of cast community or religious political compromises in order to continue to remain in power by all possible mans fair or dubious.

Lack at awareness among people to protect our environment.

Unwillingness to pay attention to their duties.

The general decline in standards of behaviors and conduct of mutual relations has been more prominent in the floors of our legislatures.

Lack of participatory management In implementation of policies. On top of everything else the burecracy in India is cold slow and some what in human in dealing with the complaints of it citizens. Lack of team sprit and coordination among policy-making and implementing agencies.

Corruption it another major problem to achieve the goals of development policies.

**Legislative measures and Administrative action taken to protect and improve environment in India:** India is one of the few courtiers of the world that have specific reference In their constituents to the needs for environments protection and improvement article 48 A (inserted after the 42<sup>nd</sup> Amendment Act in 1976) and article 51 A of the Indian Constitution lay down the following duties for the state and the citizen. The state shall endeavor to project and improved the environment and to safeguard the forests and wildlife of the duty of every citizen of Indian to protect and improve the natural environment including. Forest Lakes River and wildlife and to have compassion for living creatures (Article51A). Legislative measures.

The Directive principles (Article 48 and 51 A) of the Indian constitution and Indian Development policy of the Government of India have provided a strong basic of enactment of legislative measures. For the protection of environment resources several lawes have been enacted from time to time that directly or indirectly relate to environment protection and improvement among the more resent ones are: I. Insecticides Act 1968 II. WILDLIFE (Protection Act 1972 III. Water Prevention cesee Act 1977 V. Forest conversion Act 1980, 1988 2003, VI Air (Prevention and control of pollution Act 1981 VII. Environment Protection Act 1986 VIII. Public Liability insurance Act 1991, the national Environment appellate authority 1997 and the National Environment Tribunal Act 1995.

**Intiutional Measures:**Department of Environment: The Government of Indian set up a Department of Environment on 1 November 1980. This department was integrated into the ministry of Environment and forest in 1985 at the center.

**Pollution Control Board:** National waste lands Development Board and NATIONAL land waste lands Development council was set up in 1986. A central Ganga Authority was constituted in 1985 to guide and over the implementation of a programmer for restorinh the quality of the river.

Indian Board for wildlife was set up In 1952 with the objective of managing zoos.

Environment information system was set up in 1982 as a decentralized system.

Environment impact assessment: The ministry of Environment and forest has been assigned the responsibility to appraisal of project with regard to their Environment implications. Based on Environment impact assessment and issue arising there to decision are taken by the

competent authorities in respect of project including selection of sites.

**Pollution Monitoring And Control:** The water and air acts are implemented through the central pollution control board and the State pollution boards. In addition two hundred ninety air quality monitoring stations and one hundred seventy-three coastal monitoring stations have been set up. Under the environment protection act, 1986.

**Control Of Harardous Substances:** The environment (Protection Act) 1986, provides for laying down procedures and safeguar s for the handling of hazardour substances and prevention and control of accidents.

**Biosphere Reserves Programme:** Biosphere reserves are intnded to preserve genetic diversity In representation eco-systems and provide for conservation of plants animals and micro-organisms. Thirteen biogeographically zones in the country have been identified for establishing biosphere reserves. So far seven of them have been set up in the country-Nilgire, Nandadevi, Nokrek, Great Nicobar, Golf of Mannar, Manas and Sunder bans.

To achieve the goal of sustainable development these major steps have to be taken by Government and administration :

Government may adopt more participatory approach. More and more people including political, social and academic thinkers and policy makes are inclined to agree that voluntary association, non governmental initiatives and decentralized, democratic institutions provide important alternatives and supplementing means to state action for empowering the citizen.

Corruption is an important dimension to investigation in the context of public policy formation and implementation. To more effective result, corruption should be controlled by National and International level.

Advanced Technology brought out new era in field of good governance. E-government implies interface between government and citizen.

More accountability and result orientation requires in administration and government level.

In new Global era both private and public sector need more coordination. 6. More Gender sensitized attitude require

**Conclusion:** In conclusion, it should be remembered that for achieving the new challenge of sustainable development participatory public policy and good governance are essential. The India experience has been that while we have recorded economics gains we have generally failed to manage, protect and improve our environment while trading the paths which we thought lead us to greater progress we have caused degradation, despoliation and degeneration. We must refrace our steps and curve out a more sensible path, a path that would lead not to a continuing confrontation with nature which can be truly disastrous but a greater balance and partnership with it. We must aim at sustainable development has equity as an essential ingredient.

#### References:-

1. Bhambhri, C. P. "Globlization India Nation, State and Democracy", Shipra Publications, Delhi, 2005
2. Jain R. B., "Public Administration in India, 21st Century Challenges for Good Governance", Deep & Deep Publication Pvt. Ltd., New Delhi-110002
3. Kothari Ashish, "Is Sustainable Development Desirable and Possible? "The Indian Journal of Public Administration, Vol. xxxix, No.3 July-September 1993
4. Michael Reddeft, "Sustainable Development", London, 1987
5. Sapru, R. K., "Development Administration" Strling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 2002

\*\*\*\*\*

## महिला सशक्तिकरण और भारत में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. नीरजा शर्मा\*

**शोध सारांश** – शिक्षा राष्ट्र निर्माण की आवश्यक कड़ी है यह समाज के लोगों में नैतिक मूल्य एवं राष्ट्रवाद का विकास करती है। ऐसे में राष्ट्र के प्रत्येक प्राणी को शिक्षित करना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। राष्ट्र निर्माण में महिला केन्द्रीय भूमिका निभाती है, माता के रूप में नारी प्रथम गुरु होती है जब एक पुरुष शिक्षित होता है, एक व्यक्ति शिक्षित होता है। ऐसे में हमारे समाज में आधी आबादी कहे जाने वाली स्त्री की शिक्षा की स्थिति उत्साहवर्द्धक नहीं है। वैदिक काल में नारी का स्थान बहुत सम्मानजनक था कलांतर में नारी की स्थिति ह्रास हुआ। आधी आबादी के बाद ऐसा सोचा गया था कि भारतीय नारी एक नई हवा में सांस लेगी तथा शोषण और उत्पीड़न से मुक्त होगी पर ऐसा नहीं हुआ। तदुपरांत आधुनिक भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। प्रारंभ में महिला को शिक्षा देने का उद्देश्य परिवार, समाज एवं राष्ट्र का विकास होता है किन्तु जब महिला स्वयं के प्रति भी संवेदनशील होकर समानता एवं न्याय की गुहार करने लगती है जो इसका विरोध होने लगता है।

**प्रस्तावना** – शिक्षा मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक पहलुओं पर आधारित है। यह समाज विशेष की काल एवं परिस्थितियों के अनुसार महिलाओं को प्रोत्साहित एवं हतोत्साहित करती है। यह सर्वविदित तथ्य है कि शिक्षा महिलाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक रही है। यह उन्हें समाज की नकारात्मक प्रवृत्तियों जैसे जाति, वर्ग, धर्म एवं संस्कृतिक आदि के प्रति एक नवीन सोच देती है।

शिक्षा जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टि कोण का विकास करती है। इससे महिलाओं में आत्मविकास का संचार होता है। यह महिलाओं को अपने प्रति होने वाले व्यवहार एवं लिंगात्मक न्याय व समानता की भावना के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करती है। शिक्षित महिला सशक्त होकर अपने अधिकारों और परिवार में समान साझेदारी के प्रति सजग हो जाती है। इसलिये परिवार एवं समाज के विकास के लिए महिला शिक्षा अत्यधिक आवश्यक है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए महिला शिक्षा का भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के दौरान कई महानुभावों ने समर्थन दिया। राजा राममोहन राय ने 1930 में कहा था कि –

‘महिला अशिक्षा के कारण निम्न सामाजिक स्थिति का निर्माण होता है।’ अस्तु बाल-विवाह, सती-प्रथा जैसी सामाजिक बुराईयों के प्रति जागरूकता लाने के लिए शिक्षा ने महती भूमिका का निर्वह किया। इसके अलावा ईश्वरचंद विद्यासागर, एम.जी. रानाडे और अन्य समाज सुधारकों ने महिला शिक्षा को आवश्यक बताते हुए, सामाजिक सहमति की भूमिका तैयार की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता प्राप्ति हेतु गांधी जी ने महिला वर्ग को प्रोत्साहित किया। स्त्रियों की शिक्षा को जरूरी बताया।

भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है – कादम्बनी गांगुली। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त कर महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रेरित किया। इसके पश्चात् भारत की अनेक महिलाओं ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। भारत के प्रसिद्ध समाज सेवक श्री कर्वे ने 1918 में भारत में महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। महिलाओं में शिक्षा के प्रति जाग्रत करने के लिए 1928 में ‘अखिल भारतीय महिला शिक्षा

परिषद’ की बैठक हुई।

स्वतंत्र भारत के संविधान में अनुच्छेद 15(3) में उपबंधित है कि महिला शिक्षा हेतु विशेष उपबंध किये जायें। 1971 में गठित शिक्षा समिति एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिला शिक्षा हेतु विशेष व्यवस्था की गयी है। महिलाओं की समानता से संबंधित एक कार्यक्रम भी शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। इस तरह विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की शिक्षा हेतु अनेक प्रयास किये जाते रहे हैं। इनसे आंशिक लाभ भी हुआ है।

सवाल उठता है कि महिला शिक्षा क्यों आवश्यक है? दरअसल महिला शिक्षा से समुचित सभ्यता एवं संस्कृति को पनाह मिलती है। विकास को गति मिलती है। मानव व्यक्तित्व का विकास होता है और समस्या का वैज्ञानिक समाधान सम्मद होता है। शिक्षित महिला अपने परिवार में एक कुशल प्रबंधक की तरह कार्य करती है परिवारजनों का स्वास्थ्य, उनका भोजन, कैलोरी की मात्रा, घर की सत्र, बजट, सामाजिक संबंधों की सहजता, बच्चों की देखभाल का वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं उनकी शिक्षा आदि विभिन्न पहलुओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर सकती है। अतः यह कहा जाता है कि ‘एक महिला शिक्षित तो पूरा परिवार शिक्षित। एक महिला सशक्त तो पूरा परिवार।’ यह अवधारणा भारतीय समाज में नवीन आयाम दे रही है। इसलिए परिवार के स्थायित्व, अच्छे प्रबंधन, उचित विकास, प्रारम्भिक शिक्षा एवं संस्कृति की समृद्धि तथा पोषण के लिए महिला शिक्षा ही प्रथम आवश्यकता है।

सर्वविदित है कि केरल में महिला साक्षरता सर्वाधिक है। यहीं की 87 महिलाएं शिक्षा हैं और प्रजनन दर 2.2 है तथा शिशु मृत्यु दर 22 प्रति हजार है। अर्थात् यहां पर देश की सबसे कम शिशु मृत्यु दर है। उल्लेखनीय है कि भारत की राष्ट्रीय शिशु मृत्यु की औसत दर 91 प्रति हजार है। दूसरी तरह जिन राज्यों में महिला साक्षरता की दर कम है जैसे बिहार और राजस्थान आदि। यहां पर शिशु मृत्यु दर 91-118 प्रति हजार है। महिला साक्षरता से नवजात शिशु की पालन-पोषण में परिपक्वता आती है। महिला साक्षरता की स्थिति भी इस परिपक्वता को प्रभावित करती है। जैसे मात्र साक्षर माताओं



में 138 शिशु मृत्यु दर है। माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त महिलाओं में 96 की दर तक लाया जा सकता है और स्नातक या उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं में शिशु मृत्यु दर को कम से कम 28 प्रति हजार लाना संभव है। यह तथ्य शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार - 'शिक्षित महिलाएं स्वच्छ जल की आवश्यकता के विषय में ज्यादा सचेत होती हैं।' दूसरी बात शिक्षित महिला संक्रामक रोगों की आशंका में कमी, टीकाकरण, प्रारम्भिक रोगों के रोकथाम, चिकित्सा सुविधाओं के बेहतर उपयोग एवं जल तथा भोज्य पदार्थों की स्वच्छता के प्रति जागरूक रहकर, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। शिक्षा महिला को सामर्थ्य बनाती है। वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकती है। उसके लिए जीवन के कई क्षेत्र खुल जाते हैं। उसकी निर्णय शक्ति में वृद्धि होती है।

महिला शिक्षा के अनेक लाभ हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रतिफल है - आर्थिक आत्म-निर्भरता। महिला शिक्षित होकर वांछित और उत्कृष्ट सेवाओं में जा सकती है। वर्तमान कालीन महिलाएं अंतरिक्ष, समुद्र एवं मरुस्थल तक जाकर शोध एवं अनुसंधान कर चुकी हैं। विज्ञान, तकनीकी, उच्च शिक्षा, कला, संस्कृत, खेल, सेना, प्रशासनिक सेवा, पत्रकारिता, चिकित्सा और वह सभी क्षेत्र जो मनुष्य की पहुंच में हैं, वहीं तक महिलाएं कार्यरत हैं। वह अपने कौशल एवं योग्यता के आधार पर समाज में अपना स्थान बनाने लगी हैं। उसने राजनीति, साहित्य, शिक्षा एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में नवीन आयाम जोड़ दिये हैं।

दुर्भाग्यवश, आधुनिक समाज में शिक्षा को मात्र नौकरी से सह-स्थापित किया जाता है। वह अवधारणा अत्यधिक संकुचित एवं अधूरी है। शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य मात्र नौकरी की प्राप्ति नहीं होना चाहिए। शिक्षा मानव का बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विकास करती है। मात्र एक उद्देश्य से शिक्षा को जोड़कर देखना अन्यायपूर्ण है। इससे कुन्ठा उत्पन्न होती है। नौकरी नहीं मिलने की दशा में अवसाद एवं निराशा के भाव पैदा होते हैं। फिर भी समाज में इस अवधारणा की काफी गहरी और मजबूत है।

शिक्षा पद्धति मानव को मानव बनाने में सक्षम ही दृष्टिगत नहीं होती है। महिला के प्राकृतिक गुणों के पोषण एवं संबर्द्धन का इसमें कोई स्थान नहीं है और न ही युवाओं की समस्याओं का कोई समाधान है। ऐसी स्थिति में समाज में एकांकी दृष्टि कोण का पनपना स्वाभाविक है किन्तु इससे सर्वाधिक हानि हुई है महिलाओं को। जैसा कि सभी जानते हैं कि उच्चतर शिक्षा पी.एच.डी. की डिग्री प्रदान करने के बाद भी शिक्षा उन महिलाओं में साहस एवं आत्मरक्षा के भाव उत्पन्न करने में असक्षम होती हैं। वे दहेज बहु-विवाह, बेमेल-विवाह और पर्दा-प्रथा जैसी सामाजिक बुराईयों का प्रतिकार नहीं कर पाती हैं। ऐसी महिलाएं अत्याचार करने वाले पति या छेड़खानी करने वाले राहगीर के विरुद्ध भी कार्यवाही नहीं कर पाती हैं।

परम्परागत रूढ़ियों का प्रभाव शिक्षित के मस्तिष्क पर बराबर हावी रहता है। भारत की अनेक स्नातक एवं स्नातकोत्तर महिलाएं अपने अस्तित्व की स्थापना करने में असमर्थ हैं, वह मात्र श्रीमती बनकर रह जाती हैं। उनकी योग्यता एवं कौशल पारिवारिक एवं सामाजिक अन्याय, असमानता एवं अत्याचार को सहन करने में ही विलीन हो जाती है। उन्हें लगता है कि शिक्षा का पैमाना है, इन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों में समायोजन कर लेना। इसलिए वह अपने आत्मसम्मान के पक्ष में कोई निर्णय नहीं ले पाती हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा सामाजिक परिवेश महिलाओं की योग्यता

को नजर अंदाज कर उसका शोषण करने में माहिर है। उसे तो स्त्री को द्वितीय स्थान प्रदान करने में ही संतुष्टि होती है। कई बार तो शिक्षित महिला अपेक्षाकृत अधिक पीड़ित होती है। उसकी इस पीड़ा के दो कारण हैं-

**प्रथम** - जागरूकता अर्थात् अपने अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता और दोहरे सामाजिक मापदण्डों के कारण उत्पन्न आक्रोश।

**द्वितीय** - परिवार एवं समाज का अपेक्षाकृत अधिक दबाव पूर्ण व्यवहार।

भारतीय समाज संक्रमण काल से गुजर रहा है इसलिए वह शिक्षित महिला के प्रति अधिक शंकालू दिखाई पड़ता है शायद उसे अपनी परम्परागत सामाजिक व्यवस्था के चरमराहट का अहसास हो रहा है। चूंकि शिक्षित महिलाएं अपेक्षाकृत अधिक सशक्त होती हैं। इसलिए वह सार्वजनिक भूमिका निर्वाह कर राष्ट्र निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। समाज की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है इसलिए इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। भारत में महिला को एक मानव संसाधन के रूप में पहचाना जाने लगा है अस्तु महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है अनेक कार्यक्रम व परियोजनाएं की जा रही हैं ताकि स्त्री शिक्षा में वृद्धि हो।

भारत के संविधान निर्माताओं व नीति विशेषज्ञों ने महिलाओं के पिछड़ेपन के मर्म को समझा और विभिन्न उपबन्धों के अंतर्गत महिलाओं के समान अधिकार व विकास हेतु अनुच्छेद 15, 16, 19, 21, 23, 39, 42, 51(क), 243(घ), 325, 326 अधिकारों से विधिक स्तर पर संरक्षण प्रदान किया, साथ ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1961 व 2012 में संशोधन, महिलाओं के खिलाफ जघन्य यौन अपराध निषेध विधेयक 2013 के संरक्षण का प्रणयन किया गया।

**महिला शिक्षा की स्थिति :** 1901 में हमारे देश में स्त्री-साक्षरता मात्र 0.6 प्रतिशत थी जो स्वतंत्रता के उपरांत 1951 में बढ़कर 8.9 प्रतिशत हो गई। जनगणना 2011 में 64.84 प्रतिशत थी। इस दौरान स्त्री-साक्षरता की दर में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, 2011 में यह 53.7 प्रतिशत थी जो बढ़कर 2011 में 65.5 प्रतिशत हो गई। 2001-2011 की अवधि के दौरान स्त्री-साक्षरता दर में 11.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रवाद का अच्छा संकेत है। 2011 में निम्न राज्यों में स्त्री साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, जैसे बिहार, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश ये राज्य जनसंख्या व क्षेत्रफल से बड़े हैं लेकिन राष्ट्रीय औसत साक्षरता इन राज्यों में कम है जो राष्ट्रवाद व महिला सशक्तिकरण के लिए चिन्तन का विषय है।

**महिला शिक्षा विकास हेतु शैक्षिक नीतियाँ :** स्त्री शिक्षा के विकास और देश की मुख्य धारा में उनकी सहयोगिता के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-1953 मुख्य रूप से स्त्री शिक्षा के प्रति उदासीन रहा लेकिन आयोग ने लड़कियों के प्रति गृह विज्ञान की शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं देने तथा मांग होने पर लड़कियों के लिए प्रथम विद्यालय खोले जाने का सुझाव दिया तथा भारत सरकार द्वारा गठित दुर्गा बाई देशमुख समिति 1957 ने कम अवधि में पुरुष और स्त्री के मध्य दूरी को भरने का सुझाव दिया तथा भारत सरकार द्वारा गठित दुर्गा बाई देशमुख समिति 1957 ने कम अवधि में पुरुष और स्त्री शिक्षा के मध्य दूरी को ढालने का सुझाव दिया। वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके शिक्षा को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित कर लिया गया।

महिला शिक्षा के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम जनवरी 2015 में सरकार द्वारा बेटी बचाओ अभियान के तहत बेटियों के उच्च शिक्षा और

उनके विवाह के लिए सुकन्या समृद्धि योजना नाम से राष्ट्रीय लघु बचत योजना का सूत्रपात किया गया, वहीं राज्य द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना, गाँव की बेटा योजना एकलव्य विद्यालय, मेधावी बालिकाओं हेतु निःशुल्क स्कूटर योजना इत्यादि प्रमुख हैं।

**निष्कर्ष** – देश की आधी आबादी महिलाओं की है। जब तक इन्हें शिक्षा कार्यक्रमों में सम्बद्ध नहीं किया जाता तब तक उनके चहुँमुखी विकास की संभावनाएं न्यून नहीं रहेंगी। वर्तमान परिवेश में शिक्षा की अनिवार्यता महत्वपूर्ण हो गई। जब महिला पूर्ण साक्षर होगी तभी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकेगी। आज का युग तकनीकी शिक्षा का युग है, इसलिए महिला का केवल साक्षर होना आवश्यक नहीं है बल्कि

उसके बौद्धिक विकास की भी आवश्यकता है। तभी नारी इच्छित गरिमा को प्राप्त कर सकेगी और महिला सशक्तिकरण से ही उनका चहुँमुखी विकास एवं सशक्तिकरण संभव हो सकेगा।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चन्द्रशेखर, ममता, 'महिला सशक्तिकरण की अवधारणा', यथार्थ प्रकाशन, इन्दौर (म.प्र.) 2002
2. कुमारी, अरुणा, 'महिलाओं में अनिवार्य शिक्षा और सशक्तिकरण', रिसर्च लाईन जर्नल, ग्वालियर, 2008
3. यादव, वीरेन्द्र सिंह, 'नई सहस्राब्दी का महिला सशक्तिकरण अवधारणा', चिन्तन एवं सरोकार ओमेगा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010

\*\*\*\*\*

## झाला वंश का मेवाड़ के लिए आत्मोत्सर्ग एवं बड़ी सादड़ी ठिकाना

**डॉ. सुदर्शन सिंह राठौड़ \***

**प्रस्तावना** – राजस्थान के 36 राजकुलों में झाला वंश का नाम शामिल है, इसका प्राचीन नाम मकवाना-वंश मिलता है। यह वंश चंद्रवंशी तथा माध्यमदिनी शाखा के मार्कण्डेय ऋषि से उत्पन्न माना जाता है। इस वंश के संबंध में भी अग्निवंशीय उत्पत्ति के समान एक किंवदंती मिलती है जिसके अनुसार राक्षसों के अत्याचारों से पीड़ित होकर ऋषि मार्कण्डेय ने हिमालय की तलहटी में जाकर महायज्ञ किया जिसके अग्निकुंड से कुण्डमाल नामक योद्धा की उत्पत्ति हुई और उसने राक्षसों का अंत करके सनातन धर्म की रक्षा की।<sup>1</sup> गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार झालावंश का पुराना नाम मकवाना था और यह सिंध के कीर्तिगढ़ से उत्पन्न हुए, बाद में हरपाल मकवाना को गुजरात के सोलंकी वंश के शासक कर्ण द्वारा जागीर प्रदान की गई अतः इस वंश की प्रारंभिक उत्पत्ति के बारे में जो भी तर्क दिए गए हो परन्तु इस वंश के अज्जा और उनके भाई सज्जा का मेवाड़ से विशेष संबंध है।

झाला वंश के रजोधर की 1500 ई. में हलवद में मृत्यु हो गई और उसके पुत्र अज्जा व सज्जा दाह संस्कार में शामिल होने गए हुए थे, परन्तु उसका छोटा पुत्र राणकदेव अल्पवयस्क होने के कारण साथ नहीं गया। इस अवसर का फायदा उठाकर पंवार राजा लगधर ने राणकदेव को झाला वंश का उत्तराधिकारी घोषित कर उसको हलवद की गद्दी पर बैठा दिया। ऐसी परिस्थिति में अज्जा व सज्जा जोधपुर के शासक राव सूजा के पास चले गए।<sup>2</sup>

जोधपुर के शासक राव सूजा ( 1492 ई. से 1515 ई.) के समय राव अज्जा और उनके भाई राव सज्जा हलवद से जोधपुर आये। परन्तु महाराजा द्वारा अज्जा की पुत्री से शादी करने के प्रश्न पर हुए विवाद के कारण अज्जा व सज्जा ने 1506 ई. में जोधपुर छोड़ दिया और मेवाड़ के महाराणा रायमल के आमंत्रण के पश्चात् वे कुम्भलगढ़ आ गए। इन्हें महाराणा ने अजमेर की जागीर प्रदान की। महाराणा सांगा द्वारा 1512 ई. में इन्हें अजमेर परगने के 325 गांवों की जागीर तथा 'राणा पदवी' प्रदान की। 17 मार्च, 1527 ई. को राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा में निर्णायक युद्ध हुआ। इस समय वीरता से लड़ते हुए सांगा घायल हो गये। युद्ध को जारी रखने के लिये तथा घायलावस्था में सांगा को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिये रणकुशल योद्धा अज्जा को महाराणा के स्थान पर युद्ध के संचालन का दायित्व सौंपा गया। अज्जा ने तत्काल इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए महाराणा का राज्य चिन्ह छत्र आदि धारण करके हाथी पर सवार होकर रणक्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में पहुंच गए। इस समय में मुगल सेना के साथ वीरता से लड़ते हुए अज्जा अपने सहयोगियों डूंगरपुर रावल उदयसिंह, हसनखां मेवाती, माणकचन्द चौहान, चन्द्रभान चौहान, रतनसिंह कांघलोत, रामदास सोनगरा (पाली), गोकलदास पंवार (अजमेर), रायमल राठौड़ (जोधपुर), रतनसिंह

मेड़तिया, खेतसी आदि के साथ वीरगति को प्राप्त हुए।<sup>3</sup>

अज्जा के इस आत्मबलिदान के कारण उसके वंशधरों को मेवाड़ दरबार द्वारा सोलह उमरावों में सबसे अक्ल दर्जे का पद-प्रतिष्ठा, ताजिम और कुर प्रदान किया गया, साथ ही उन्हें महाराणा के समान राजचिन्ह धारण करने का अधिकार भी दिया गया। खानवा युद्ध में पराजय के पश्चात् अजमेर परगना मेवाड़ के हाथ से निकल गया। 1528 ई. में चित्तौड़ में महाराणा रतनसिंह की गद्दीनशीनी समारोह में अज्जा का पुत्र राजराणा सिंहा और उनके चाचा सज्जा भी शामिल हुए। इस अवसर पर महाराणा ने उनका सम्मान बढ़ाते हुए उनके उत्तराधिकारियों की तलवार बंधाई पर कैद नजराना माफ कर दिया और दरबार में उन्हें मुंडा बरोबर की बैठक प्रदान की गई। इस अवसर पर ही महाराणा द्वारा अजमेर के स्थान पर झाड़ोल एवं बिछीवाड़ा की जागीर सिंहा को और देलवाड़ा की जागीर सज्जा को प्रदान की गई रतनसिंह ने महाराणा सांगा की बहन रूपकुंवर का विवाह राजराणा सिंहा के साथ करके उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया।

गुजरात के शासक बहादुरशाह द्वारा 1535 ई. में चित्तौड़ पर दूसरा आक्रमण किया गया। इस समय यहां की बागडोर रानी कर्मवती ने संभाल रखी थी। उन्होंने मेवाड़ के सभी सरदारों को चित्तौड़ की रक्षा के लिए आमंत्रित किया। झाड़ोल राजराणा सिंहा और देलवाड़ा राजराणा सज्जा भी अपनी सेना सहित यहां उपस्थित हुए। दोनों अपने-अपने सैनिकों के साथ गणेश पोल की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए।<sup>4</sup> बहादुरशाह के भीषण आक्रमण तथा तोपों व बारूदी गोलों के कारण राजपूत सरदारों ने किले के सभी द्वार खोल दिये और प्रत्यक्ष युद्ध के लिये तैयार हो गये। इस समय लड़ते हुए उनके वीरों के साथ सिंहा और सज्जा भी वीरगति को प्राप्त हुए। राजराणा सिंहा के बाद उसका पुत्र आसा झाड़ोल का उत्तराधिकारी बना जिसकी तलवारबन्धी की रस्म 1535 ई. में महाराणा विक्रमादित्य द्वारा सम्पन्न की गई। महाराणा विक्रमादित्य की दासी पुत्र बणवीर ने हत्या कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। कालांतर में यहां के वास्तविक उत्तराधिकारी उदयसिंह ने 1540 ई. में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस समय राजराणा आसा बणवीर की सेना से मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। उसने मेवाड़ के लिये बलिदान के क्रम में अपने प्राणोत्सर्ग (केवल 23 वर्ष की उम्र में ही) कर अपनी वंश परम्परा के बलिदानी यश को जारी रखा।

1540 ई. में राजराणा आसा की मृत्यु निःसंतान हुई थी। अतः उसका भाई सुरताणसिंह झाड़ोल का शासक बना जिसकी तलवार बन्धी चित्तौड़गढ़ में महाराणा उदयसिंह द्वारा की गई। 1567 ई. में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस समय महाराणा उदयसिंह का रूक्का मिलने पर राजराणा सुरताणसिंह अपनी जमीयत सहित चित्तौड़ की रक्षार्थ पहुंच गया। चित्तौड़ के

किले की रक्षा करते हुए वह सूरजपोल के निकट वीरगति को प्राप्त हुआ। हलवद के झाला राजवंशियों का क्रमबद्ध यह चौथा आत्मबलिदान था।<sup>5</sup>

25 फरवरी, 1568 ई. को राजराणा सुरताण का द्वितीय पुत्र मानसिंह झाड़ोल की गद्दी पर बैठा। यह इतिहास में वीदा के नाम से प्रसिद्ध था। हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप द्वारा सभी मेवाड़ के सरदारों की 'युद्ध-परिषद्' का निर्माण किया गया। इसमें राजराणा मानसिंह शामिल हुआ था। 18 जून, 1576 ई. में मुगल बादशाह अकबर की सेना मानसिंह व आसफ खां के नेतृत्व में यहां पहुंची। महाराणा प्रताप के साथ झाला मानसिंह युद्ध लड़ रहा था। इसी समय प्रताप मुगल सेना को पीछे धकेलते हुए मैदानी भाग में आ गये। यहां मानसिंह पर प्रहार करने के समय चेतक की एक टांग कट गई और प्रताप को मुगल सैनिकों ने घेर लिया। मेवाड़ के सरदार यहां पहुंचे और उन्होंने प्रताप को युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। इस समय राजराणा मानसिंह ने अपने वंश के इतिहास को पांचवी सदी में पुनः दोहराया। वे महाराणा प्रताप का छत्र और राजचिन्ह धारण करके मुगल सेना पर टूट पड़े। उन्होंने अन्य सरदारों के साथ मेवाड़ की रक्षार्थ अपना बलिदान दिया और इतिहास में अपने वंश गौरव को बढ़ाते हुए सदा के लिये अमर हो गये। आज भी मेवाड़ का प्रत्येक नागरिक मातृभूमि की रक्षार्थ बलिदान के लिये उन्हें नमन करता है।

राजराणा दूदा की तलवार बंधायी महाराणा प्रताप द्वारा कोल्यारी में की गई इस समय प्रताप ने अपने पुत्र कुंवर अमरसिंह को इन्हें लेने भेजा। प्रताप ने अज्जा के वंशजों के बलिदान की प्रशंसा की तथा इनकी राह-मरजाद में राजमहल के द्वार तक नक्कारा और ढुंढुभी बजाते हुए घोड़े पर बैठकर आने का सम्मान तथा तलवार बंदी पर इन्हें कैद-नजराना से मुक्त रखने का सम्मान प्रदान किया। महाराणा प्रताप के पश्चात् उनके पुत्र अमरसिंह ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा। मुगल सेनापतियों से मेवाड़ के सरदारों की झड़प होती रहती थी। 1611 ई. में राजराणा दूदा का मुगल सेनापति अब्दुल्ला खां के विरुद्ध रणकपुर की घाटी में भेजा गया। यहां मुगल सेनापति का सामना करते हुए दूदा मारा गया। आज भी इस स्थान पर एक स्मारक बना हुआ है जो 'झाला-छतरी' के नाम से प्रसिद्ध है।<sup>6</sup>

राजराणा दूदा की मृत्यु के पश्चात् झाड़ोल की गद्दी के लिये उसके बड़े पुत्र हरिदास तथा छोटे पुत्र श्यामसिंह के बीच संघर्ष हुआ। इस समय मेवाड़-मुगल संघर्ष चल रहा था, अतः महाराणा अमरसिंह तुरन्त कोई निर्णय न ले सके। हरिदास के कुशल सैन्य प्रबन्ध तथा 1615 ई. की मेवाड़-मुगल संधि में उनकी भूमिका के कारण महाराणा अमरसिंह उनसे प्रसन्न थे। इस समय महाराणा ने हरिदास को झाड़ोल की जागीर छोड़ने के लिये राजी कर दिया और इसके बदले में उन्हें कानोड़ की जागीर दे दी गई। झाड़ोल के राजराणा

श्यामसिंह के पक्ष में हरिदास ने राज्य छोड़ दिया और कानोड़ के राजराणा के रूप में उनकी तलवार बंधी हुई। इस समय झाड़ोल की प्रतिष्ठा कम हो गई और मेवाड़ में सर्वोच्च ठिकाने के रूप में तथा पूर्वजों की सभी राह-मरजाद राजराणा हरिदास व कानोड़ को दी गई। राजराणा हरिदास की योग्यता को देखते हुए महाराणा अमरसिंह ने उसे अपने पुत्र कर्णसिंह का मुख्य सलाहकार बनाकर मुगल दरबार में भेजा। इसके पश्चात् कर्णसिंह के पुत्र जगतसिंह के साथ भी राजराणा हरिदास को भेजा गया। यहां हरिदास को बादशाह द्वारा पांच हजार रुपये, एक घोड़ा और खिलअत देकर सम्मानित किया गया। इससे मेवाड़ में उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई। 1622 ई. में राजराणा की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र रायसिंह की महाराणा कर्णसिंह द्वारा तलवार बंधायी की गई। राजराणा रायसिंह की शादी महाराणा अमरसिंह की पुत्री के साथ हुई थी।<sup>7</sup>

महाराणा कर्णसिंह द्वारा राजराणा रायसिंह की तलवार बंधायी के बाद उन्हें कानोड़ के स्थान पर एक लाख रुपये वार्षिक आय वाली सादड़ी की जागीर प्रदान की गई। इस प्रकार हलवद से आये अज्जा के वंशजों ने अपनी योग्यता, त्याग, स्वामिभक्ति और बलिदान से मेवाड़ के प्रथम श्रेणी का सर्वोच्च ठिकाना सादड़ी प्राप्त किया। इसके साथ ही यह ठिकाना हमेशा के लिए इनके पास ही रहा। यह ठिकाना मेवाड़ के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है एवं उसका अधिकांश भाग अरावली पर्वत के बाहर का मैदानी भाग है। इसकी पूर्वी सीमा नीमच और मंदसोर से, उत्तर-पूर्वी सीमा ग्वालियर और टोंक से, दक्षिणी सीमा प्रतापगढ़ और धरियावद से मिलती है। झाला वंश द्वारा लगातार अपनी सात पीढ़ी के द्वारा मेवाड़ के लिए दिए गए बलिदान के फलस्वरूप बड़ीसादड़ी ठिकाना उन्हें मिला।

### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. पुरोहित राजेन्द्रनाथ, मेवाड़ के दरीखाने एवं रीति-रिवाज, 2005 पृ. - 263
2. सादड़ी बही (राजराणा हिम्मतसिंह व्यक्तिगत रिकॉर्ड) अप्रकाशित, पृ. 117
3. श्यामलदास, वीर-विनोद, पृ. 316
4. टॉड जेम्स, एनल्स एंड एंटिक्वटीज ऑफ राजस्थान, पृ. 250
5. ओझा गौरीशंकर हीराचंद, उदयपुर राज्य का इतिहास भाग-1, पृ. 417
6. ओझा गौरीशंकर हीराचंद, उदयपुर राज्य का इतिहास भाग-1, पृ. 485
7. शर्मा सीताराम, श्री झाला-भूषण मार्तण्ड, पृ. 45

\*\*\*\*\*



## ब्रिक्स विकास बैंक और भारत के लिए इसका महत्व

डॉ. प्रवीण पंड्या\*

**शोध सारांश** – ब्रिक्स (BRICS) दुनिया की पाँच उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक नया संगठन है, जो आपस में आर्थिक सहयोग के साथ-साथ पश्चिम देशों व अमेरिका के प्रभुत्व वाली आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था के स्थान पर एक बहुपक्षीय व्यवस्था की स्थापना के लिए प्रयासरत है। इस संगठन में पाँच देश – ब्राजील, रूस, इण्डिया, चीन तथा साउथ अफ्रीका शामिल हैं। इसका नामकरण इन पाँच देशों के नामों के पहले अक्षरों से हुआ है। भारत इसका एक अहम सदस्य है और क्षेत्रीय संगठनों में भारत द्वारा इसकी सदस्यता ग्रहण करना भारत की बदलती वैश्विक नीति का परिचायक है जो कई अर्थों में प्रासंगिक हो सकता है। ब्रिक्स समूह में भारत का अपना अलग महत्व है। आज भारत विश्व में अपना विशेष स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। दक्षिण पूर्व एशिया की एक प्रमुख शक्ति होने के कारण आज विश्व के शक्तिशाली देशों ने भारत को महत्व देना प्रारंभ कर दिया है। जहाँ भारत को रूस की परंपरागत मित्रता और चीन के साथ आर्थिक सहयोग से लाभ हुआ है तो ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका के साथ (इबसा – इंडिया, ब्राजील एवं साउथ अफ्रीका के सहारे) भारत का मान – सम्मान बढ़ा है।

**प्रस्तावना** – ब्रिक्स का विचार सबसे पहले वित्तीय कम्पनी गैल्डमैन सैच के अर्थशास्त्री **जिम ओ नील** ने 2003 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट '**इमिंग विद ब्रिक्स: द पाथ टू 2050**' में दिया था, उनके अनुसार चार देशों – ब्राजील, रूस, भारत तथा चीन 2050 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ होंगे, वर्तमान में अमरीका तथा यूरोपियन संघ की अर्थव्यवस्थाएँ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार चीन व भारत वस्तुओं तथा सेवाओं उत्पादन में विश्व के सबसे बड़ी निर्माओं के रूप में उभर रहे हैं, दुसरी ओर रूस व ब्राजील विश्व के कच्चे माल के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर रहे हैं अतः इन देशों में आपसी सहयोग की प्रकिया स्वाभाविक रूप से चलेगी। **फालो –अप रिपोर्ट के नाम से उनकी दूसरी रिपोर्ट 2004** में प्रकाशित हुई इसके अनुसार 2007 तक इन देशों में 3000 डॉलर से अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले लोगों की संख्या दोगुनी हो जाएगी तथा इन देशों में मध्यम वर्ग की संख्या 800 मिलियन तक हो जाएगी, यही मध्यम वर्ग इन देशों में आर्थिक विकास आगे बढ़ाएगा। गैल्डमैन सैच की **अगली फालो –अप रिपोर्ट वर्ष 2007** में प्रकाशित हुई जिसमें आने वाले दशकों में भारत की विकास क्षमता पर प्रकाश डाला गया है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी विकास क्षमता को अनुमानित समय के पूर्व ही प्राप्त कर लेगा। विश्व में 30 सबसे तीव्र गति से विकसित होने वाले शहरी क्षेत्रों में से 10 भारत में होंगे, वर्ष 2050 तक भारत के 700 मिलियन लोग शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे होंगे। **गोल्डमैन सैच की अन्तिम रिपोर्ट 2010 में प्रकाशित हुई जिसका शीर्षक है – ई एम इफ्टी इन टु डिसेडस: ए चेन्जिंग लैण्डस्केप** इसमें ब्रिक्स देशों में वित्त व पूँजी की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। 2030 तक चीन पूँजी बाजार में हिस्सेदारी के हिसाब से अमरीका से आगे होगा, 2010 में चीन जापान को पीछे कर विश्व की दुसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, गोल्डमैन सैच के उक्त विचारों को **ब्रिक्स थेसिस** के नाम से भी जाना जाता है।

**ब्रिक्स के प्रमुख उद्देश्य** – ब्रिक्स के सम्मेलनों के अन्त में जारी घोषण-पत्रों

व इनकी गतिविधियों के आधार पर ब्रिक्स के निम्नलिखित उद्देश्य माने जा सकते हैं –

- पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाली राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था के स्थान पर एक न्यायपूर्ण तथा समतापूर्ण विश्व व्यवस्था की स्थापना करना है।
- वर्तमान में विश्व के प्रमुख मुद्दों जैसे – जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, विश्व व्यापार व्यवस्था का संचालन, ऊर्जा सुरक्षा तथा मानवीय विकास आदि का न्यायोचित समाधान करना है।
- सदस्य देशों के मध्य आपसी संबंधों को मजबूत करना है।

### विश्व में ब्रिक्स बैंकों के सदस्यों की वर्तमान स्थिति

	ब्राजील	रूस	भारत	चीन	साउथ अफ्रीका
क्षेत्रफल	5TH	1TH	7TH	3RD	25TH
जनसंख्या	5TH	9TH	2ND	1ST	25TH
श्रमसंख्या	5TH	7TH	2ND	1ST	34TH
प्रतिव्यक्ति – सकल राष्ट्रीय उत्पाद	66TH	51TH	148TH	83TH	80ST

**ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का अन्य क्षेत्रीय राष्ट्रीय एवं बहुपक्षीय बैंकों के साथ सम्बन्ध** – ब्रिक्स देशों की राय में ब्रिक्स बैंक का तालमेल अन्य क्षेत्रीय बहुपक्षीय एवं बैंकों के साथ बैठना जरूरी है ताकि क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत बैंक अपने उत्तरदायित्व को बेहतर ढंग से कार्यान्वित कर सकें। वस्तुतः ब्रिक्स बैंक अन्य बैंकों के लिए एक बेहतर नेटवर्क की तरह कार्य करेगा। इसके पीछे यह तर्क काम करेगा कि अगर राष्ट्रीय विकास बैंक अच्छे ढंग से अपना कार्य तभी निष्पादित सकता है अगर उन्हें किसी बहुपक्षीय बैंक का सहयोग एवं आधार मिले। अतः अन्य क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय बैंकों के साथ मिलकर कार्य करने से बैंकों की कार्यप्रणाली अधिक संतुलित होगी एवं विकास योजनाओं पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा।

## ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था एक-दूसरे की प्रतियोगी न होकर पूरक है,

शिखर सम्मेलन	देश	स्थान	समय
पहला	रूस	येकैटरिनबर्ग	16 जून 2009
दूसरा	ब्राजील	ब्रासीलिया	16 अप्रैल 2010
तीसरा	चीन	सान्या	14 अप्रैल 2011
<b>चौथा</b>	<b>भारत</b>	<b>नई दिल्ली</b>	<b>29 मार्च 2012</b>
पाँचवाँ	दक्षिण-अफ्रीका	डरबन	27 मार्च 2013
छठवाँ	ब्राजील	फोर्टालेजा	15 जुलाई 2014
सातवाँ	रूस	प्रस्तावित	2015

ब्रिक्स में सम्मिलित देशों की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 40 प्रतिशत है तथा इन देशों का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत है। इन देशों का कुल सम्मिलित सकल घरेलू उत्पाद लगभग 15.5 मिलियन डालर है। ब्रिक्स की धारणा के अंतर्गत यह भी बताया गया कि ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था एक-दूसरे की प्रतियोगी न होकर पूरक हैं, रूस एवं ब्राजील कच्चे माल एवं ऊर्जा संसाधन के बड़े आपूर्तिकर्ता हैं वहीं भारत एवं चीन में ऊर्जा खपत एवं विनिर्माण क्षेत्र में अपार संभावनाएं निहित हैं। इन्हीं धारणाओं से प्रेरित होकर 2009 में रूस, ब्राजील, चीन तथा भारत ने ब्रिक्स की स्थापना का निर्णय लिया।

**ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन प्रारम्भ से वर्तमान तक** -ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन ब्रिक्स देशों का प्रथम सम्मेलन रूस के येकैटरिनबर्ग में 16 जून 2009 को सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में इन चार देशों ने अमरीकी उसके यूरोपीय सहयोगियों के प्रभुत्वशाली वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के स्थान पर बहुध्रुवीय विश्व-व्यवस्था की मांग की थी।

ब्रिक्स देशों का दूसरा सम्मेलन ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में 16 अप्रैल 2010 को सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने बहुध्रुवीय प्रजातांत्रिक वैश्विक व्यवस्था की मांग दोहराई। इसी सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि दक्षिण अफ्रीका को भी ब्रिक्स की सदस्यता प्रदान की जाए। इसके बाद से ब्रिक्स का नाम बढ़ाकर ब्रिक्स कर दिया गया।

ब्रिक्स का तीसरा शिखर सम्मेलन चीन के शहर सान्या में 14 अप्रैल 2011 को सम्पन्न हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार इस सम्मलेन में भाग लिया। इस सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों में चल रहे सहयोगात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई तथा नई गतिविधियों के बारे में भी सहमति बनी। इस सम्मेलन में बहस के अन्य विषय थे, सुरक्षा संबंधी चिन्ता, तकनीकी शोध, खाद्य, सुरक्षा, बैकिंग संस्थाओं में सहयोग तथा व्यवसायिक संगठनों के बीच भी सहयोग।

ब्रिक्स देशों का चौथा सम्मेलन नई दिल्ली भारत में 29 मार्च 2012 में सम्पन्न हुआ। इस दौरान भारत ने पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज तथा आतंकवाद को बहस का मुद्दा बनाया तथा ब्रिक्स देशों से अपील की आतंकवाद के खिलाफ एक जुट होकर लड़ने की जरूरत है।

ब्रिक्स देशों का पांचवा सम्मलेन दक्षिण अफ्रीका के शहर में सम्पन्न हुआ इस सम्मेलन के दौरान 27 मार्च 2013 में डरबन में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स बैंक के विचार पर सहमति बनी। डरबन शिखर सम्मलेन के आयोजन के साथ ही पांचों सदस्य देशों में एक-एक बार शिखर सम्मेलन आयोजन का दौर पूरा हो गया। डरबन सम्मलेन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने मेजबान राष्ट्रपति जैकब जमा के अतिरिक्त ब्राजील, रूस व चीन के राष्ट्रपतियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर अनौपचारिक बातचीत की।

चीन के नये राष्ट्रपति शी जिनजिंग के साथ अपनी पहली ही मुलाकात में जिन द्विपक्षीय मुद्दों पर उनकी बातचीत हुई उनमें ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा तीन बांध बनाए जाने का मुद्दा भी शामिल था। इन बांधों से भारत आने वाली पानी के प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की चिन्ता से भारत, चीन को पहले ही अवगत करा चुका है चीन की ओर से ऐसी आशंकाएँ निर्मूल बताई गई।

ब्रिक्स का अगला शिखर सम्मलेन ब्राजील के शहर फोर्टालेजा में 15 जुलाई 2014 को सम्पन्न हुआ जहाँ ब्रिक्स के दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने के साथ ही न्यू डेवलपमेंट बैंक अस्तित्व में आया यह बैंक 2016 से अपना कार्य शुरू कर देगा। भारत के लिए अच्छी बात यह रही कि बैंक की अध्यक्षता भारत के ही जिम्मे हैं, जिसे भारत की कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है।

## वर्तमान परिपेक्ष में ब्रिक्स के लिए भारत का महत्व :

- ब्रिक्स भारत को एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसमें वह अपने विकास अनुभवों को सदस्य देशों के साथ बांट सकता है। साथ ही रूस एवं चीन जैसे देशों के अनुभवों का लाभ भी उठा सकता है, इसका एक कारण यह भी है कि स्वयं ब्रिक्स के अन्य सदस्य देश भी उन्हीं चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिनसे भारत जुझता रहा है।
- ब्रिक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत यह समझने में भी सफल रहा है कि वैश्विक आर्थिक मंदी तथा वित्तीय संकट की स्थिति का किस प्रकार सामना किया जा सकता है और कौन-कौन सी सावधानियां बरती जा सकती हैं।
- भारत के ब्रिक्स देशों के साथ खाद्य सुरक्षा कृषि, बीमारियों, विदेशी सहायता तथा वैश्विक तापन के क्षेत्र में अनुभवों का आदान-प्रदान भी किया इस संदर्भ में भारत में कुछ अभिनव प्रयोग भी किए गए हैं जिनमें अधिकांश का सकारात्मक प्रभाव रहा है।
- चीन के साथ ब्रिक्स के माध्यम से संबंधों को बेहतर बनाकर न सिर्फ चीन के साथ विवादों को सुलझाने में सफल हो सकता है बल्कि पाकिस्तान में चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलित भी कर सकता है।
- भारत ने इंटेलिजेंस तथा सूचना प्रणाली में रूस से मदद भी ली है कि ताकि पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने हेतु एक बेहतर तंत्र का निर्माण कर सके और इस संदर्भ में ब्रिक्स के माध्यम से सामूहिक सुरक्षा की संकल्पना भारत के लिए फायदेमंद साबित हुई है।
- इसके अलावा ब्रिक्स के माध्यम से भारत-रूस के बीच व्यापार-वाणिज्य ऊर्जा तथा अवसंरचना के माध्यम से अपार संभावनाएं बनी हैं।
- ब्राजील-भारत संबंध को ब्रिक्स के माध्यम से ही एक नया आयाम मिला है, जिसका परिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों, डब्ल्यूटीओ विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत की स्थिति अधिक मजबूत मानी जा रही है।
- ब्रिक्स इस संदर्भ में भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि गोल्डमैन सैस के अर्थशास्त्री द्वारा भारतीय अर्थशास्त्री द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को एक प्रभावी एवं निर्णायक अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाना गया है।
- अतः भारत में अवसंरचना से जुड़े परियोजनाओं के लिए ब्रिक्स बैंक वित्तीयन के एक नये स्रोत के रूप में विकल्प भी प्रदान करेगा।

**निष्कर्ष** - ब्रिक्स की कार्य विधि का क्षेत्र काफी विस्तृत है, जिसमें गैर ब्रिक्स देशों के वर्चस्व के स्थान पर ब्रिक्स देशों की भी सहभागिता के द्वारा वित्तीय सुधार, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाओं आदि मुद्दों का

समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में ब्रिक्स देशों में भारत ने अपना अलग ही स्थान बना लिया है, छठवाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि ब्राजील के शहर फोर्टलेजा में 15 जुलाई 2014 को सम्पन्न हुआ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें कर चोरी विकास की एक प्रमुख बाधा है इसे रोकने, गरीबी निवारण के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता, आतंकवाद के प्रत्येक रूप को विश्व शांति व सुरक्षा हेतु खतरा बताते हुए इसकी रोकथाम हेतु प्रभावी कदम उठाना, समेकित एवं टिकाऊ विकास पर बल देना प्रमुख रूप से शामिल था। इस सम्मेलन की प्रमुख बात यह रही कि इसमें ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना की गई है, यह बैंक चीन के शहर शंघाई में स्थापित किया जाएगा, इसकी आरम्भिक पूंजी 100 मिलियन डालर होगी जिसकी अध्यक्षता का कार्यभार भारत को सौंपा गया है।

अतः उपरोक्त बातों की ध्यान में रखकर निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि ब्रिक्स देशों के छठे शिखर सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा कुटनीतिज्ञ के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व कर ब्रिक्स देशों के बीच में भारत का प्रभुत्व एवं वर्चस्व स्थापित करने के कारण ब्रिक्स देशों के द्वारा ब्रिक्स विकास बैंक की प्रथम अध्यक्षता का कार्यभार भारत को सौंपा गया है।

#### संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल मैगजीन - सितम्बर 2014
2. प्रतियोगिता दर्पण हिन्दी मासिक - अक्टूबर 2014
3. महामीडिया मासिक पत्रिका - अगस्त 2014
4. दैनिक पत्र-पत्रिका, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, टाईम ऑफ इंडिया
5. भारतीय अर्थव्यवस्था

\*\*\*\*\*

## वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव-एक आकलन

डॉ. पन्नालाल कटारा \*

**शोध सारांश** - वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री तूफानों की बारंबारता में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप तटीय क्षेत्रों में जान-माल की क्षति होगी। इसके अतिरिक्त अल नीनों की बारंबारता में भी बढ़ोतरी होगी जिससे एशिया, अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया महाद्वीपों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होगी जबकि वहीं दूसरी ओर उत्तरी अमरीका में बाढ़ जैसी आपदा का प्रकोप होगा। दोनों ही स्थितियों में कृषि उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

**प्रस्तावना** - जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण वैश्विक तपन है जो हरितगृह प्रभाव का परिणाम है। हरितगृह प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सतह से टकराकर लौटने वाली सूरज की किरणों को वातावरण में उपस्थित कुछ गैसों अवशोषित कर लेती हैं परिणामस्वरूप पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। कार्बन डाईऑक्साइड, मिथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्षोभमण्डलीय (troposphere) ओजोन वे मुख्य गैसों हैं जो हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं। वातावरण में इन गैसों की निरंतर बढ़ती मात्रा से वैश्विक जलवायु परिवर्तन का खतरा दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है।

हरितगृह प्रभाव के चलते अनेक क्षेत्रों में औसत तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी के अनुसार वर्ष 2020 तक पूरी दुनिया का तापमान पिछले 1000 वर्षों की तुलना में सर्वाधिक होगा। अंतर-शासकीय जलवायु परिवर्तन पैनल Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ने वर्ष 1995 में भविष्यवाणी की थी कि अगर मौजूदा प्रवृत्ति जारी रही तो 21<sup>वीं</sup> सदी में तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। इस शताब्दी का पहला दशक (2000-2009) अब तक का सबसे उष्ण दशक रहा है जो यह साबित करता है कि हरितगृह प्रभाव के परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन का दौर आरंभ हो चुका है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के अनेक प्रभाव होंगे जिनमें से ज्यादातर हानिकारक होंगे।

**वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव** - वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु में तपन के कारण श्वास एवं हृदय सम्बंधी बीमारियों में वृद्धि होगी। दुनिया के विकासशील देशों में दस्त, पेचिश, हैजा, क्षयरोग, पीत ज्वर तथा मियादी बुखार जैसी संक्रामक बीमारियों की बारंबारता में वृद्धि होगी। चूंकि बीमारी फैलाने वाले रोग वाहकों के गुणन एवं विस्तार में तापमान एवं वर्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः दक्षिण अमरीका, अफ्रीका तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों जैसे- मलेरिया, डेंगू, पीला बुखार तथा जापानी बुखार के प्रकोप में बढ़ोतरी के कारण इन बीमारियों से होने वाली मृत्युदर में इजाफा होगा। मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते एक बड़ी आबादी विस्थापित होगी जो 'पर्यावरणीय शरणार्थी' कहलाएगी।

जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप रोगाणुओं में बढ़ोतरी के साथ-साथ

इनकी नयी प्रजातियाँ विकसित होगी जिसके परिणामस्वरूप फसलों की उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। फसलों की नाशीजीवों तथा रोगाणुओं से सुरक्षा हेतु नाशीजीवनाशकों के उपयोग की दर में बढ़ोतरी होगी जिससे वातावरण प्रदूषित होगा साथ ही मानव स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

वैश्विक जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप दुनिया के मानसूनी क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि होगी जिससे बाढ़, भू-स्खलन तथा भूमि अपरदन जैसी समस्याएँ पैदा होंगी। जल की गुणवत्ता में गिरावट आएगी।

वैश्विक जलवायु परिवर्तन जल स्रोतों के वितरण को भी प्रभावित करेगा। उच्च अक्षांश वाले देशों तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के जल स्रोतों में जल की अधिकता होगी जबकि मध्य एशिया में जल की कमी होगी। निम्न अक्षांश वाले देशों में जल की कमी होगी।

जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप ध्रुवीय बर्फ के पिघलने के कारण विश्व का औसत समुद्री जल स्तर इक्कीसवीं शताब्दी के अंत तक 9 से 88 सेमी तक बढ़ने की संभावना है जिससे दुनिया की आधी से अधिक आबादी, जो समुद्र से 60 किमी की दूरी तक रहती है, पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बांग्लादेश का गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा, मिस्र का नील डेल्टा तथा मार्शल द्वीपों और मालदीव सहित अनेक छोटे द्वीपों का अस्तित्व वर्ष 2100 तक समाप्त हो जाएगा। इसी खतरे की ओर सम्पूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए अक्टूबर 2009 में मालदीव सरकार की कैबिनेट ने समुद्र के भीतर बैठकर एक अनूठा प्रयोग किया था। इस बैठक में दिसम्बर 2009 के कोपेनहेगन सम्मेलन के लिए एक घोषणा पत्र भी तैयार किया गया था। प्रशांत महासागर का सोलोमन द्वीप जलस्तर में वृद्धि के कारण डूबने के कगार पर हैं।

वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव समुद्र में पाए जाने वाली जैव-विविधता सम्पन्न प्रवाल भित्तियों पर पड़ेगा जिन्हें महासागरों का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है। समुद्री जल में उष्णता के परिणामस्वरूप शैवाल (Algae) पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा जो कि प्रवाल भित्तियों को भोजन तथा वर्ण प्रदान करते हैं। उष्ण महासागर विरंजन प्रक्रिया के कारण होंगे जो इन उच्च उत्पादकता वाले परितंत्रों को नष्ट कर देंगे। प्रशांत महासागर में वर्ष 1997 में अजनीनो के कारण बढ़ने वाली ताप की तीव्रता प्रवाल की मृत्यु का सबसे गंभीर कारण बनी है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी की लगभग 10 प्रतिशत प्रवाल भित्तियों की मृत्यु हो चुकी है, 30 प्रतिशत गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं तथा 30 प्रतिशत का क्षरण



हुआ है। ग्लोबल कोरल रीफ मॉनीटरिंग नेटवर्क, ऑस्ट्रेलिया का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक सभी प्रवाल भित्तियों की मृत्यु हो जाएगी।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पैदावार पर पड़ेगा। संयुक्त राज्य अमरीका में फसलों की उत्पादकता में कमी आएगी जबकि दूसरी तरफ उत्तरी तथा पूर्वी अफ्रीका, मध्य पूर्व देशों, भारत, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा मैक्सिको में गर्मी तथा नमी के कारण फसलों की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी होगी। वर्षा जल की उपलब्धता के आधार पर धान के क्षेत्रफल में इजाफा होगा।

वातावरण में ज्यादा ऊर्जा के जुड़ाव से वैश्विक वायु पद्धति में भी परिवर्तन होगा। वायु पद्धति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वर्षा का वितरण असमान होगा। भविष्य में मरुस्थलों में ज्यादा वर्षा होगी जबकि इसके विपरीत पारंपरिक कृषि वाले क्षेत्रों में कम वर्षा होगी। इस तरह के परिवर्तनों से वृहद पैमाने पर मानव प्रजनन को बढ़ावा मिलेगा जो कि मानव समाज के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक ताने-बाने को प्रभावित करेगा।

वैश्विक जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप बाढ़, सूखा तथा आंधी-तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता में वृद्धि के कारण अन्न उत्पादन में गिरावट आयेगी। स्थानीय खद्यान्न उत्पादन में कमी, भुखमरी और कुपोषण का कारण बनेगी जिससे स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगे। खाद्यान्न और जल की कमी से प्रभावित क्षेत्रों में टकराव पैदा होगा।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जैव-विविधता पर भी पड़ेगा। किसी भी प्रजाति को अनुकूलन हेतु समय की आवश्यकता होती है। वातावरण में आकस्मिक परिवर्तन से अनुकूलन के अभाव में उसकी मृत्यु हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव समुद्र के तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली दलदली क्षेत्र की वनस्पतियों पर पड़ेगा जो तट को स्थिरता प्रदान करने के साथ-साथ समुद्री जीवों के प्रजनन के लिए आदर्श स्थल भी होती है। दलदली वन जिन्हें ज्वारीय वन भी कहा जाता है, तटीय क्षेत्रों को समुद्री तूफानों से रक्षा करने का भी कार्य करते हैं। जैव-विविधता क्षरण के कारण पारिस्थितिक असंतुलन का खतरा बढ़ेगा।

जलवायु में तपन के कारण ऊष्णकटिबंधीय वनों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि होगी परिणामस्वरूप वनों का विनाश होगा जिसके कारण जैव-विविधता का ह्रास होगा।

नाशीजीवों तथा रोगाणुओं की जनसंख्या में वृद्धि तथा इनकी नयी प्रजातियों की उत्पत्ति का प्रभाव दुधारू पशुओं पर भी पड़ेगा जिससे दुग्ध उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

तापमान में वृद्धि के कारण वाष्पीकरण तथा वाष्पोत्सर्जन की दर में अभूतपूर्व वृद्धि होगी परिणामस्वरूप मृदा जल के साथ ही जलाशयों में जल की कमी होगी जिससे फसलों को पर्याप्त जल उपलब्ध न होने के कारण उनकी पैदावार प्रभावित होगी।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जलीय जंतुओं पर भी पड़ेगा। मीठे जल की मछलियों का प्रजनन ध्रुवीय क्षेत्रों में जान-माल की क्षति होगी। इसके अतिरिक्त अजनीनों की बारंबारता में भी बढ़ोत्तरी होगी जिससे एशिया, अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया महाद्वीपों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होगी जबकि वहीं दूसरी ओर उत्तरी अमरीका में बाढ़ जैसी आपदा का प्रकोप होगा। दोनों ही परिस्थितियों में कृषि उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हिमनदों पर भी पड़ेगा। उष्णता के कारण हिमनद पिघल कर खत्म हो जाएँगे। एक शोध के अनुसार भारत के हिमालय क्षेत्र में वर्ष 1962 से 2000 के बीच हिमनद 16 प्रतिशत तक घटे हैं। पश्चिमी हिमालय में हिमनदों के पिघलने की प्रक्रिया में तेजी आई है। बहुत से छोटे हिमनद पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। कश्मीर में कोल्हाई हिमनद 20 मीटर तक पिघल चुका है। गंगोत्री हिमनद 23 मीटर प्रतिवर्ष की दर से पिघल रहा है। अगर पिघलने की वर्तमान दर कायम रही तो शीघ्र ही हिमालय से सभी हिमनद समाप्त हो जाएँगे जिससे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतजल, रावी, झेलम, चिनाब, व्यास आदि नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इन नदियों पर स्थित जलविद्युत ऊर्जा इकाइयाँ बंद हो जाएँगी परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त सिंचाई हेतु जल की कमी के कारण कृषि उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ेगा। उपर्युक्त नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाने से भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बंगलादेश भी प्रभावित होंगे।

वैश्विक जलवायु तपन के कारण जीवांश पदार्थ तेजी से विघटित होंगे परिणामस्वरूप पोषक चक्र की दर में बढ़ोत्तरी होगी जिसके कारण मृदा की उपजाऊ क्षमता अव्यवस्थित हो जाएगी जो कृषि पैदावार को प्रभावित करेगी।

वातावरण में कार्बन डाईऑक्साइड की वृद्धि के कारण पौधों में कार्बन स्थिरीकरण में बढ़ोत्तरी होगी परिणामस्वरूप मृदा से पोषक तत्वों के अवशोषण की दर कई गुना बढ़ जाएगी जिसके कारण मृदा की उर्वरा शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की दर में वृद्धि होगी।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव वनस्पतियों तथा जंतुओं पर भी पड़ेगा। स्थानीय महासागर उष्णता 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के कारण प्रशांत महासागर में सैलमान मछली की जनसंख्या में अभूतपूर्व गिरावट दर्ज की गई है। बढ़ती उष्णता के कारण बसंत ऋतु में जल्दी बर्फ पिघलने के कारण हडसन की खाड़ी में ध्रुवीय भालुओं की जनसंख्या में गिरावट आई है।

जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों पर पड़ेगा। आर्थिक क्षेत्र का भौतिक मूल ढांचा जलवायु परिवर्तन द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होगा। बाढ़, सूखा, भूस्खलन तथा समुद्री जलस्तर में कृषि के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर मानव प्रजनन होगा जिससे सुरक्षित स्थानों पर भीड़भाड़ की स्थिति पैदा होगी। उष्णता से प्रभावित क्षेत्रों में प्रशीतन हेतु ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी।

**निष्कर्ष** – अंततः इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर खतरा है जिससे संपूर्ण दुनिया प्रभावित होगी। अतः आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हरित गृह गैसों के वातावरण में उत्सर्जन पर प्रभावी रोक लगायी जाये ताकि जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों से बचा जा सके।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. डॉ. डी.एस.लाल, शारदा प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. डॉ. आर.बी.दीक्षित, कल्याणी पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
3. डॉ. सविन्द सिंह, प्रयाग प्रकाशन, इलाहाबाद।
4. दैनिक भास्कर, मई 2010

## रामचरितमानस : नारी पात्रों का चरित्र

डॉ. पुष्पा देवी\*

**शोध सारांश** – युगनायक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस वैदिक परम्परा की कालजयी रचना है। समाज कल्याण हेतु तुलसीदास ने राम राज्य की कल्पना की। यह काव्य सर्वांग सुन्दर, उत्तम काव्य लक्षणों से युक्त, सभी रसों का आस्वादन करवाने वाला, पतिधर्म, भ्रातृधर्म के साथ-साथ सर्वोच्च भक्ति ज्ञान, त्याग तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला यह काव्य स्त्री-पुरुष, बालक-वृद्ध सभी के लिए उपयोगी है। इस ग्रंथ में दार्शनिक-मूल्य, जीवन-मूल्य और समय-मूल्य की त्रिवेणी संचरण करती है। इस ग्रन्थ के विभिन्न पात्र ईर्ष्या, द्वेष, वैर और संघर्ष से जर्जरित समाज के लिए अमृतमयी जीवनदायिनी औषधी माना गया। रामचरितमानस में आए नारी पात्रों के मूल रूप से माता सती, माता कौशल्या, माता सीता, कैकेयी, मन्दोदरी, अनुसूइया इत्यादि चरित्रों का विवेचन किया गया है।

**शब्द कुंजी** – श्रीरामचरितमानस, तुलसीदास, जीवन मूल्य भगवान शंकर, भगवान राम, माता सती, माता सीता, माता कौशल्या, कैकेयी, मन्दोदरी, अनुसूइया ।

**प्रस्तावना**– युगनायक गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्रीरामचरितमानस वैदिक परम्परा की कालजयी कृति है। कोई रचना या घटना कालजयी तब होती है जब वह सीमित कालखण्ड और देश विशेष का अतिक्रमण करके हमेशा के लिए प्रसिद्धि पा लेती है। तुलसीदास ऐसे काल में पैदा हुए जब हिन्दू जाति घोर संकट में थी। बाह्य अत्याचारों के साथ-साथ आन्तरिक विघटन की दोहरी मार से हिन्दू समाज इतना गर्त में पहुँच चुका था कि उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया था। समाज के लोग धर्म के स्वरूप को भूलकर मिथ्याचार में फँसते जा रहे थे। आपसी द्वेष भावना से भाई-भाई का दुश्मन बना हुआ था। वर्णाश्रम धर्म की शिथिलता के कारण लोगों का ईश्वर पर से विश्वास उठ चुका था। समाज कल्याण हेतु तुलसीदास ने राम राज्य की कल्पना की थी। रामचरितमानस मानव जीवन का महाकाव्य है। इसका स्थान हिन्दी काव्य में ही नहीं, बल्कि जगत् के साहित्य में अद्वितीय है। यह काव्य सर्वांग सुन्दर, उत्तम काव्य लक्षणों से युक्त, सभी रसों का आस्वादन करवाने वाला पतिधर्म, भ्रातृधर्म के साथ-साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला यह काव्य स्त्री-पुरुष, बालक-वृद्ध और युवा सबके लिए उपयोग है। इस महाकाव्य में सर्वोपरि सगुण-साकार भगवान के आदर्श मानव लीला तथा उनके गुण, प्रभाव, रहस्य तथा प्रेम के गहन तत्व को अत्यंत सरल रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में व्यक्त किया गया है। संसार में यह काव्य सर्वोच्च स्थान रखता है। इसी कारण गरीब-अमीर, शिक्षित-अशिक्षित, गृहस्थ-सन्यासी, स्त्री-पुरुष, बालक-वृद्ध सभी श्रेणी के लोग इस ग्रन्थ-रत्न को पढ़ते हैं। तुलसीदास ने इस ग्रन्थ के माध्यम से अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा से ओत-प्रोत, समर्पित भाव से गहराई में उतरकर जीवन के लक्ष्य की खोज की है। मानव की आध्यात्मिक और भौतिक समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की है। इस ग्रन्थ में दार्शनिक-मूल्य, जीवन-मूल्य और समय मूल्य की त्रिवेणी संचरण कर रही है। इस ग्रन्थ के विभिन्न पात्र ईर्ष्या, द्वेष, वैर और संघर्ष से जर्जरित समाज के लिए अमृतमयी जीवनदायिनी औषधी माना गया। रामचरित मानस में आए नारी पात्रों में मूल रूप से माता सती, माता कौशल्या, माता सीता,

कैकेयी, मन्दोदरी, अनुसूइया इत्यादि चरित्रों का विवेचन किया गया है। रामचरित मानस के बालकाण्ड में सती-भ्रम के प्रसंग का वर्णन मिलता है। जब भगवान राम लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में दर-दर भटक रहे थे तो भगवान शिव ने श्रीराम को देखा और प्रणाम करते हुए कहा –

**जय सच्चिदानंद जग पावन । अस कहि चलेउ मनोज नसावन ॥  
चले जात सिव सती समेता । पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥<sup>1</sup>**

माता सती ने भगवान शंकर की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा सन्देह उत्पन्न हुआ और मन ही मन कहने लगी कि जिस शंकर भगवान की सारा जगत् वंदना करता है वह एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परधाम कहकर प्रणाम करते हैं। श्रीराम, लक्ष्मण की शोभा को देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गए हैं कि अब तक उन्हें हृदय में उत्पन्न प्रेम रोकने से भी नहीं रुक रहा है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान विष्णु स्वयं देवताओं के कल्याण हेतु मानव रूप धारण करेंगे जैसे कि –

**चौ०-बिंशु जो सुर हित नरतनु धारी । सोउ सर्वग्य जथा त्रिपुरारी ॥  
खोजइ सो कि अग्य इव नारी । ग्यानधाम श्रीपति असुरारी ॥<sup>2</sup>**

सती माता इस बात को भी अच्छी तरह जानती थी कि भगवान शंकर के वचन झूठे नहीं हो सकते। परन्तु फिर उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। जैसे कि –

**संभुगिरा पुनि मृषा न होई । सिव सर्वग्य जान सबु कोई ॥  
अस संसय मन भयउ अपारा । होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥<sup>3</sup>**

दोनों बातों के अन्तर्द्वन्द्व से माता सती विचलित हो उठी। भगवान शंकर की पत्नी होकर भी उसके स्वभाव में नारी की सहज चंचलता है। शंकर भगवान द्वारा समझाए जाने पर भी उन्हें राम की महिमा में विश्वास नहीं होता। उसके आन्तरिक द्वन्द्व को समझकर शिव माता सती को समझाते हैं। जैसे कि –

**जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी। हर अंतरजामी सब जानी ॥  
सुनहि सती तव नारि सुभाऊ। संसय अस न धरिअ उर काऊ ॥<sup>4</sup>**

भगवान शंकर ने माता सती को बहुत समझाया, फिर भी सती माता

को भगवान शंकर का कथन सार्थक नहीं लगी। इसके परिणामस्वरूप माता सती भगवान राम की सर्वज्ञता की परीक्षा लेने के लिए सीता माता का रूप धारण करके उन दोनों भाईयों के समक्ष उपस्थित हुई। जैसे ही लक्ष्मण माता सती को देखते हैं -

**चौ०-लक्ष्मण दीख उमाकृत बेशा । चकित भए भ्रम हृदय बिसेशा ॥**

**कहि न सकत कहु अति गंभीरा । प्रभु प्रभाउ जानत मतिधीरा ॥<sup>5</sup>**

X X X X

**सती कपटु जानेउ सुरस्वामी । सबदरसी सब अंतरजामी ॥**

**सुमिरत जाहि मिटइ अग्याना। सोइ सरबग्य रामु भगवाना ॥<sup>6</sup>**

इस स्थिति पर भगवान शंकर ने प्रभु श्रीराम के चरणों में सिर नवाया और श्रीराम का स्मरण करते हुए उनके मन में आया-

**चौ०-तब संकर प्रभु पर सिरु नावा । सुमिरत रामु हृदय अस आवा ॥**

**एहि तन सतिहि भेंट मोहि नार्ही। सिव संकल्पु कीन्ह मन मर्ही॥<sup>7</sup>**

पति-पत्नी का प्रेम, विश्वास पर कायम होता है। जब सती माता को भगवान शिव अनेक बार समझाते हैं तब भी उन्हें विश्वास नहीं होता और वो सीता का रूप धारण करके भगवान राम के समक्ष जाकर खड़ी हो जाती हैं तो इससे भगवान शंकर और माता सती के प्रेम में दरार पड़ जाती है और भगवान शंकर माता सती का त्याग कर देते हैं-

**दो०-सती हृदय अनुमान किय सबु जानेउ सर्वग्य ।**

**कीन्ह कपटु में संभु सन नारि सहज जइ अग्य ॥**

X X X X

**सो०-जलु पय सहिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति भलि।**

**बिलग होइ रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि ॥<sup>8</sup>**

इस प्रसंग पर यदि विचार किया जाए तो दो बातें सामने आती हैं। एक तो यह कि मनुष्य को ज्यादा भ्रम नहीं करना चाहिए। अधिक भ्रम करने से मानव को हानि उठानी पड़ सकती है जैसे की माता सती को उठानी पड़ी। भगवान शिव से उन्हें भ्रम के कारण ही त्यागा। दूसरा-पति-पत्नी को एक दूसरे के सही विचारों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जैसे माता सती को अपनी गलती की आभास होता है तो वह आत्मग्लानि से भरकर स्वयं की भर्त्सना करती है। आदर्श पति- पत्नी का पारस्परिक सम्बन्ध श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। कल्याण तभी तक है जब तक दोनों में आस्था और विश्वास विचलित न हो। शिव के वचनों में आस्था की कमी एवं झूठ के कारण ही जगत् माता सती को अग्नि में भस्म होना पड़ा। मरते समय माता सती ने भगवान शिव से वर मांगा कि उसका जन्म-जन्मान्तर तक शिव के चरणों में अनुराग रहे। कठोर तपस्या करके माता सती अपने अगले जन्म में पार्वती के रूप में पैदा होकर भगवान शिव को प्राप्त हुई। इस बात की पुष्टि तब होती है जब स्वयं सीता जनक वाटिका में माँ पार्वती की पूजा के लिए पहुँचती हैं और कहती हैं :-

**दो०-पतिदेवता सुतीय महुं मातु प्रथम तव रेख ।**

**महिमा अमित न सकहि कहि सहस सारदा सेश ॥**

X X X X

**चौ०-सेवत तोहि सुलभ फल चारी। बरदायनी पुरारि पिआरी ॥**

**देबि पूजि पद कमल तुम्हारे । सुर नर मुनि सब होहि सुखारे ॥<sup>9</sup>**

इसी के साथ माता सीता की निष्ठा की भी परीक्षा होती है। जब रावण सीता को विभिन्न प्रकार से डराकर, धमका कर अपनी पटरानी बनाने के लिए विवश करता है तो माता सीता अटूट निष्ठा का परिचय देती हैं।

**तव अनुचरी करउँ पन मोरा । एक बार बिलोकु मम ओरा ॥**

**तुन धरि ओट कहति बैदेही। सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥<sup>10</sup>**

X X X X

**स्याम सरोज दाम सम सुंदर। प्रभु भुज करि कर सम दसकंधरा॥**

**सो भुज कंठ कि तव असि घोरा। सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा॥<sup>11</sup>**

राम के प्रति सीता की निष्ठा अटूट रही। वे बिना पति के सब कुछ निरसार समझती हैं। पति के साथ उसे जंगल में भी मंगल दिखाई देता है। वह जीवन में हर तरह के दुःख सहन कर सकती हैं परन्तु पति वियोग नहीं सह सकती। उसकी दृष्टि में पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं है। वो कहती हैं -

**जिय बिनु देह नदी बिनु बारी। तैसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी ॥**

**नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। सरद बिमल बिधु बदन नु निहारे॥<sup>12</sup>**

तुलसीदास के रामचरित मानस में नारी की स्वतन्त्रता की अवहेलना की गई है। उनके काव्य के अनुसार आदर्श नारी पति का अनुगमन करने वाली होनी चाहिए। तुलसीदास की सीता अत्यंत दीन और पराश्रित है। अशोक वाटिका में जब रावण उन्हें भय दिखाता है तो वो राम के बाण का ही सहारा लेती दिखाई देती हैं। जैसे कि -

**सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा। कबहुं कि नलिनी करइ बिकासा ॥**

**अस मन समुझु कहति जानकी । खल सुधि नहि रघुबीर बान की ॥<sup>13</sup>**

तुलसीदास के रामचरित मानस काव्य में एक आदर्श पत्नी के स्वरूप को वर्णित किया है। पत्नी चाहे किसी भी परिस्थिति में हो उसे प्रत्येक पल अपने पति के बल और उसके प्रति विश्वास का ध्यान रहना चाहिए। माता सीता स्वयं एक देवी शक्ति का अवतार थीं। वह एक पल में रावण को खत्म कर सकती थीं परन्तु फिर भी रावण जैसे दानव को अपनी शक्ति न दिखाकर अपने पति के बाण का भय दिखाती हैं और एक आदर्श पत्नी बनकर पति सेवा को ही अपना धर्म मानती हैं।

रामचरित मानस में माता कौशल्या का चरित्र बड़ा ही अनुपम है। वह पुत्र प्रेम, सहिष्णुता, शीलधर्म और सद्भाव की मूर्ति हैं। उसे राम के वनगमन की किसी भी बात का पता नहीं है जैसे ही भगवान राम माता कौशल्या से वनगमन के लिए आज्ञा माँगने आते हैं तो एक बार तो उसकी दशा उस डरी हुई हिरणी के समान हो गयी जिसने सिंह की भयानक गर्जना को सुन लिया हो। परन्तु जल्दी ही धीरज धारण करके सोचने लगती हैं और अन्तर्द्वंद्व में फँस जाती हैं, सोचती हैं -

**चौ०-राखि न सकइ न कहि सक जाहू। दुहुँ भाँति उर उर दारुन दाहू ॥**

**लिखत सुधाकर गा लिखि राहू । बिधि गति बाम सदा सब काहू ॥<sup>14</sup>**

X X X X

**धरम सनेह उभयँ मति घेरी । भइ गति साँप छुछुंदरि केरी ॥**

**राखउँ सुतहि करउँ अनुरोधू । धरमु जाइ अरु बंधु बिरोधू ॥<sup>15</sup>**

इस अन्तर्द्वंद्व से कौशल्या जल्द ही निदान पा लेती हैं और अपनी उदारता प्रदर्शित करते हुए राम को समझाती हैं -

**चौ०-जौं केवल पितु आयसु ताता। तौ जनि जाहु जानि बड़ि माता ॥**

**जौं पितु मातु कहेउ बन जाना। तौ कानन सत अवध समाना ॥<sup>16</sup>**

ऐसी स्थिति में भी माता कौशल्या पिता से अधिक माता के आदेश को महत्व देती हैं और माता के आदेश का पालन करने को कहती हैं।

माँ कौशल्या अपनी ममता में और कैकेयी की ममता में लेश मात्र भी अन्तर नहीं मानती और न ही उसके मन में कैकेयी के प्रति क्रोध या घृणा या सोत का भाव प्रवेश कर पाता है। वह बिल्कुल सहज रहकर आगे की स्थिति को सम्भालने की कोशिश करती है।

जब राजा दशरथ के प्राण एकदम कण्ठ में आ जाते हैं तो स्थिति बहुत ही नाजुक हो जाती है और कौशल्या माता समझ जाती है कि अब सूर्यकूल का सूर्य अस्त होने वाला है तो माता अपने हृदय में धीरज धारण करके राजा दशरथ को समझाते हुए कहते हैं -

नाथ समुझि मन करिअ बिचारू । राम बियोग पयोधि अपारू ॥  
करनधार तुम्ह अवध जहाजू । चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजू ॥

X X X X

धीरजु धरिअ त पाइअ पारू। नहिं त बूझिहि सबु परिवारू ॥  
जौं जियँ धरिअ बिनय पिय मोरी। रामु लखनु सिय मिलहिं बहोरी॥<sup>17</sup>

कौशल्या माता के ये वचन उसकी कर्तव्यपरायणता, नीतिमत्ता, आदर्श सपत्नी (सुमित्रा और कैकेयी) के प्रति निर्मल आचरण विवेकशीलता आदि गुण उसे उस पद पर प्रतिष्ठित कर देते हैं, जहाँ संसार की अन्य नारी नहीं पहुंच सकती। जब भरत और शत्रुघ्न पिता की मृत्यु के बाद अयोध्या लौटते हैं और माता कौशल्या के समक्ष उपस्थित होते हैं तो माता कौशल्या सारे दुःख भूलकर दोनों भाईयों को अपनी छाती से लगा लेती है और कहती है -

चौ०-सरल सुभाय मायँ हियँ लाए। अति हित मनहुँ राम फिरि आए ॥  
भेटेउ बहुरि लखन लघु भाई। सोकु सनेहु न हृदयँ समाई ॥

X X X X

देखि सुभाउ कहत सबु कोई। राम मातु अस काहे न होई ॥  
माताँ भरतु गोद बैठारे। आँसु पोंछि मृदु बचन उचारे ॥<sup>18</sup>

माँ कौशल्या को इस बात का लेश मात्र भी दुःख नहीं है कि उसके पुत्र राम को बनवास भेज दिया गया है उसे तो इस बात की चिन्ता है कि भगवान राम के बिना उसका छोटा भाई भरत महाराज और प्रजा का क्या हाल होगा। गोस्वामी तुलसीदास ने माता कौशल्या का चरित्र अत्यंत उदात्त, विवेकशील और पूर्णतः अनुशासित प्रस्तुत किया है।

रामचरित मानस के अयोध्याकाण्ड में माता कैकेयी को अत्यंत कठोर रूप में चित्रित किया गया है। कैकेयी के दोष निवारण के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने माँ सरस्वती द्वारा बुद्धि-भ्रष्ट होने की घटना का समावेश किया है। इसी के अनेक कथाओं के माध्यम से ज्ञात होता है कि भगवान विष्णु धरती माँ को वचन देते हैं कि वे राम अवतार लेकर धरती माँ के सारे भार को हर लेंगे। जैसे कि -

चौ०- जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा। तुम्हहि लागि धरिहुँ पर बेसा ॥  
अंसन्ह सहित मनुज अवतारा । लेहुँ दिनकर बंस उदारा ॥

X X X X

कस्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन्ह कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा ॥  
ते दसरथ कौसल्या रूपा। कोसलपुरी प्रगट नरभूपा ॥<sup>19</sup>

वहीं दूसरी ओर रावण अपने भाईयों सहित कठोर तप करते हैं और भगवान विष्णु से वर माँगते हैं कि -

करि बिनती पद गहि दससीसा । बोलेउ बचन सुनुहु जगदीसा ॥  
हम काहू के मरहिं न मारें। बानर मनुज जाति दुह बारें॥<sup>20</sup>

इस प्रकार के उद्धरण से ज्ञात होता है कि भगवान राम का जन्म दुष्टों को मारने हेतु हुआ है। सृष्टि ने माता कैकेयी को ही इस योग्य समझा कि कैकेयी ही भगवान राम को उनका लक्ष्य बता सकती है। जिससे भगवान राम का जन्म सार्थक सिद्ध हो सके।

प्रारम्भ में कैकेयी का व्यवहार निष्कपट होता है। मंथरा के वचनों को सुनकर उसका रोष फूट पड़ता है और मंथरा को भला-बुरा कहती है। परन्तु जल्द ही उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है और मंथरा के कहे गए शब्दों को सही

मानकर अपने कुकृत्य को अंजाम देती है। इस कुकृत्य से पति की मृत्यु पर भी कैकेयी का दिल नहीं पिघलता, ऐसे लगता है मानो उसे अपने कृत्य पर संतोष है, उसे अपने किये पर कोई ग्लानि नहीं है -

सेक बिकल सब रोवहिं रानी। रूपु सीलु बलु तेजु बखानी ॥  
करहिं बिलाप अनेक प्रकारा । परहिं भूमितल बारहिं बारा ॥

X X X X

बिलपहिं बिकल दास अरु दासी। घर घर रुदनु करहिं पुरबासी ॥  
अँध्यउ आजु भानुकुल भानू । धरम अवधि गुन रूप निधानू ॥

X X X X

गारी सकल कैकहि देहीं। नयन बिहीन कीन्ह जग जेहीं ॥  
ऐहि बिधि बिलपत रैनि बिहानी। आए सकल महामुनि ग्यानी ॥<sup>21</sup>

इन सब स्थितियों का रानी कैकेयी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब माता कैकेयी भरत और अयोध्यावासियों के साथ भगवान राम से मिलने चित्रकूट जाती हैं तो वहाँ पर भी अधिक कुछ नहीं बोलती। ऐसा लगता है जैसे माता कैकेयी को चित्रकूट लाकर सभी विद्वानजन उसे पश्चाताप करने के लिए विवश कर रहे हों। परन्तु फिर भी वह मौन ही रहती है, ऐसा लग रहा है जैसे अत्यंत गम्भीर भुचाल आया और अपने कार्य को करके थम सा गया हो।

तुलसीदास ने अनुशासनहीन समाज को पुनः मर्यादाबद्ध करने के लिए परम्परा से पूज्य ऋषि पत्नी अनुसूया से ही उपयुक्त उपदेश करवाया। ऋषि पत्नी अनुसूया सीता को पति प्रेम और पति भक्ति का उपदेश देते समय पतिव्रता नारियों की चार कोटियाँ बताती है और जीवन के साथ व्यक्ति के उत्तरदायित्व, दाम्पत्य जीवन की महता तथा धर्म के मर्म को समझाती हुई कहती है-

मातु पिता भ्राता हितकारी। मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥  
अमित दानि भर्ता बयदेही। अध मसो नारि जो सेव न तेही ॥<sup>22</sup>

अनुसूया ने पतिव्रत का जो विस्तृत उपदेश सीता को दिया है वह सीता के निमित्त नहीं बल्कि उस समय के मर्यादाहीन समाज के हित के उद्देश्य से प्रेरित है। तुलसीदास का रामचरित मानस के लेखन का उद्देश्य भी सार्थक सिद्ध होता है। मन्दोदरी रावण की पटरानी है। जब रावण कामवासना की तृप्ति के लिए और अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण करता है तो मन्दोदरी उसे समझाकर सन्मार्ग पर लाने का भरसक प्रयास करती है। एकांत में रावण के चरण पकड़ कर विनती करती है -

रहसि जोरि कर पति पग लागी। बोली बचन नीति रस पागी ॥  
कंत करष हरि सन परिहरहु । मोर कहा अति हित हियँ धरहु ॥

X X X X

तव कुल कमल बिपिन दुखदाई। सीता सीत निसा सम आई ॥  
सुनहु नाथ सीता बिनु कीन्हें। हित न तुम्हार संभु अज किन्हें ॥<sup>23</sup>

X X X X

तासु बिरोध न कीजिअ नाथा। काल करम जिव जौ हाथा ॥<sup>24</sup>

लेकिन कामान्ध एवं दर्प रावण मन्दोदरी की इस चिन्ता को वास्तविक न मानकर उसे उसकी नारी सम्बन्धी दुर्बलता मानता है और उसका मजाक उड़ाता हुआ खूब हँसता है और कहता है -

चौ०-श्रवन सुनी सठ ता करि बानी। बिहसा जगत बिदित अभिमानी ॥  
सभय सुभाउ नारि कर साचा। मंगल महुँ भय मन अति काचा ॥<sup>25</sup>

मन्दोदरी ने रावण को हर दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश की। राम के परब्रह्मत्व का आभास दिलाकर भी समझाया। अनेक घटनाओं को याद



दिलाया परन्तु फिर भी रावण की समझ में कुछ नहीं आता और वो अपनी जिद पर ही अड़ा रहता है।

मन्दोदरी का रावण पर वश नहीं चलता अन्ततः रावण को अपनी करनी का फल मिलता है, पत्नी होने के नाते मन्दोदरी का भी अपने पति के कुकृत्य का फल भोगना पड़ता है।

अतः तुलसीदास ने नारी पात्र को पुरुष पात्र से नीचा स्थान नहीं दिया। उनकी दृष्टि में सामान्य स्त्री तो क्या राक्षस कुल में उत्पन्न हुई एवं वनवासिनी स्त्रियाँ भी भक्ति की अधिकारिणी हैं। शबरी के साथ-साथ त्रिजटा, मन्दोदरी इसका ज्वलन्त उदाहरण हैं। समाज के हर पहलू का प्रभाव प्रत्येक पुरुष एवं नारी पर समान रूप से पड़ता है। तुलसीदास जी की दृष्टि स्त्रियों के प्रति सद्य, उदार, संवेदनशील सम्मानजनक है। रामचरित मानस में ऐसे अनेक प्रसंग आए हैं जहाँ नारी का चरित्र उदार पद पर प्रतिष्ठित हुआ है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्री रामचरित मानस, टीकाकार- श्री हुनमान प्रसाद जी पौढ़ार, प्रकाशक: जय प्रकाश, श्री गीताप्रेस चण्डीगढ़, 1982 पृष्ठ संख्या 64
2. वही पृष्ठ संख्या 64
3. वही पृष्ठ संख्या 65
4. वही पृष्ठ संख्या 65
5. वही पृष्ठ संख्या 66

6. वही पृष्ठ संख्या 67
7. वही पृष्ठ संख्या 70
8. वही पृष्ठ संख्या 71
9. वही पृष्ठ संख्या 243
10. वही पृष्ठ संख्या 803
11. वही पृष्ठ संख्या 804
12. वही पृष्ठ संख्या 433
13. वही पृष्ठ संख्या 804
14. वही पृष्ठ संख्या 423
15. वही पृष्ठ संख्या 424
16. वही पृष्ठ संख्या 424
17. वही पृष्ठ संख्या 517
18. वही पृष्ठ संख्या 527
19. वही पृष्ठ संख्या 196
20. वही पृष्ठ संख्या 185
21. वही पृष्ठ संख्या 519
22. वही पृष्ठ संख्या 692
23. वही पृष्ठ संख्या 832
24. वही पृष्ठ संख्या 866
25. वही पृष्ठ संख्या 833

\*\*\*\*\*

# Merger of Canara Bank and Syndicate Bank: An Overview

Mahendra Krishna\* Dr. Anil Saxena\*\*

**Abstract** - Indian banking industry is taken as one of the largest global industries where there are several types of banks in both the public sector and the private sector. All the banks serve the people all over the country and even in the other countries through their branches spread across the world. The sole purpose of the banks is to promote saving among the people; to provide interest at different rates on the deposits made by the people; to provide various types of loans, such as, vehicle loan, home loan, education loan, personal loan, business loan etc.; to provide safety to the customer's money and valuables kept in the lockers, and to facilitate the deposit and lending transactions through ATMs, Internet banking, Mobile banking etc.

With the service of the banks being provided to the customers, the days are gone when the people would be afraid of the thieves and dacoits; when it would be difficult for them to keep their valuables and liquid money at home; and when they even could not sleep for the fear of the thieves.

Merger and acquisition are the policy matters of the government under which a weaker bank is merged into a stronger public sector bank with certain specific objectives. Public Sector Banks (PSBs) are banks where a majority stake (i.e. more than 50%) is held by a government. The merger of the Syndicate Bank into the Canara bank surprised everyone, but this step was taken with a view to improving the financial health of the nation.

This study deals with most of the major aspects associated to the merger of the Syndicate Bank into the Canara Bank. The findings reveal that there is not a tremendous difference between the pre-merger and post-merger status of the Canara Bank. However, it is hoped that in the years and decades to come, the Canara Bank would be able to meet out all the objectives with which the merger of both the banks was made.

**Key Words-** Merger, Bank, Overview, Financial health, Efficiency, Public Sector.

**Introduction** - For the sake of the strengthening and maintaining the financial health of a nation, the banking system of a nation plays a vital role. The banking system allows the citizens that include common men, businessmen, industrialists as well as the organizations to save their money with the banks through the deposits in various forms. Through the small and large transactions in the banks, the customers not only make savings, but also strengthen the efficiency of the banks.

Report of the World Bank, 2019, comment on the growing importance of the Indian banking system saying that 'India's share in global investments shall be almost double by 2030 designating India as a "Powerhouse in global savings and investment". With 158,373 functioning offices of commercial banks in India as on March, 2020, there are 14.1 banks and 20.95 ATMs per 1,00,000 adults in India. It makes the Indian banking system one of the largest banking systems in the world.

Trends in the various walks in life keep changing with the passage of time. The more the time advances, the more

advanced methods of working are adopted in the world. The Indian banking industry is not an exception to it. Once there was a time when the banks in India were supposed to be suitable only for lending and borrowing; when the people would go to banks either to deposit their money in order to lend it to the banks with a view to getting a handsome interest on it, and thus, to increase the capital money, or to borrow the deposited money for the various purposes. The twenty-first century has brought about revolutionary changes in the Indian banking system and Indian banking industry.

The shift from traditional functioning of the banks to the internet banking (NEFT), mobile banking (Google Pay, Phone Pay etc.), micro banking etc. reveal the changing and changed trends of the Indian banking industry. The Government of India is serious about how to increase the efficiency of the banks in public sector and how to strengthen the financial health. For it, the merger and acquisition of banks is being promoted.

**Merger of Syndicate Bank into Canara Bank: A Historical**

\* Research Scholar, Accounts & Law (Commerce), K.R. (PG) College, Mathura (U.P.) INDIA

\*\* Research Supervisor & Associate Professor, Accounts & Law, Faculty of Commerce, K.R. (PG) College, Mathura (U.P.) INDIA

## Perspective

**Syndicate Bank:** 'Founded in 1925 in the princely state of Mysore, Manipal, Udupibyp UpendraAnanthPai, T. M. A. Pai, and VamanSrinivasKudva, the Syndicate Bank occupied an important place in the Indian banking industry. It is still recognized as one of the oldest and largest commercial banks in India. At the time when it was founded, its nomenclature was made as 'Canara Industrial and Banking Syndicate Limited', and had the status of being the wholly owned subsidiary of Canara Bank.

It was nationalized in addition to the other 13 Indian commercial banks on 19<sup>th</sup> July, 1961. Since the date of its status as a nationalized bank, the Syndicate bank had contributed immensely to the nation as a whole. The role, efficiency and contribution to the financial health of the nation can be noticed through the following achievements of the bank-

1. The collaboration of the Syndicate bank with UNEP in 2003 for the purpose of granting loans for purchasing the solar lamps.
2. The announcement of sabbatical leave scheme with partial pay to make reduction in the employee overhead in 2003.
3. Offering of equity shares in July 2005- 45 million shares with a face value of \$10 @ \$46-\$50.
4. Formation of Karnataka VikasGrameena Bank (September, 2005) through the merger of four Syndicate Bank-sponsored rural banks, namely, MalaprabhaGrameena Bank (MGB), BijapurGrameena Bank (BGB), VaradaGrameena Bank (VGB), and NetravatiGrameena Bank (NGB).
5. Relaunch of Pigmy Deposit Scheme in March 2007.
6. 3552 branches of Syndicate Bank across the country in 2015.

However, despite all this achievement of the Syndicate Bank, it was considered weaker to the Canara Bank, and was finally merged into Canara Bank on April 1, 2020.

**Canara Bank:** 'Founded in the year 1906 in Mangalore by AmmembalSubbaRaoPai and owned by the Ministry of Finance, Govt. of India, the Canara Bank enjoys the popularity and reputation of being the third largest nationalized bank of India. Its offices are not only in India, but in the various countries of the world, such as, London, Hong Kong, Dubai, and New York. At the time of its founding, its nomenclature was made as Canara Hindu Permanent Fund Ltd. which was changed as Canara Bank Ltd in 1910. By June, 2021, the number of the branches of the Canara Bank and its ATMs had been respectively 9,877 and 11,819. There are the following achievements to its name and account-

1. In 1961, the Bank of Kerala was purchased as its first acquisition.
2. Acquisition of Seasia Midland Bank as its second acquisition
3. Acquisition of G. Raghunathmul Bank in Hyderabad in 1958

4. Merger of G. Raghunathmul Bank in 1961.
5. Acquisition and merger of Trivandrum Permanent Bank in 1961.
6. Canara Bank offers credit cards, consumer banking, corporate banking, finance and insurance, investment banking, mortgage loans, private banking, wealth management, personal loans, and payment services.

## Important Dates & the merger of Syndicate Bank with the Canara Bank<sup>4</sup>

S.	Date & Year	Event
1	August 30, 2019	Announcement of the amalgamation of Syndicate bank into Canara bank by the finance minister
2	September 4, 2019	Prior information of board meeting -Amalgamation of Syndicate bank into Canara bank.
3	September 13, 2019	Outcome of the board meeting Amalgamation of Syndicate bank into Canara bank
4	November 20, 2019	Formal Approval of alternate mechanism to proposed amalgamation of Syndicate into Canara bank
5	March 5, 2020	Stock exchange disclosure regarding share exchange ratio for amalgamation of Syndicate bank into Canara bank & intimation of record date
6	March 5, 2020	Gazette notification of scheme of amalgamation of Syndicate bank into Canara bank
7	March 18, 2020	News paper publication, Amalgamation & Expert committee updates
8	April 1, 2020	The amalgamation of Syndicate bank into Canara bank came into existence.

Source: Yogashree C (2019). Effect of Amalgamation on Financial Performance: A Case Study of Canara Bank Ltd.

The above mentioned dates related to the merger of Syndicate Bank into Canara Bank reveal that just in a very short period of time of about seven months, the Syndicate Bank got finally merged and lost its existence. It is worth mentioning that in spite of the merger of the Syndicate Bank into the Canara Bank, the efficiency of the Canara Bank is still more or less the same, and that it has not brought about the change in the Indian banking sector which was expected, predicted and estimated. With the increased staff, transactions, the Canara Bank has new challenges before it.

## Objectives of the Study:

1. To bring forth the increasing trust of the people in the public sector
2. To emphasize the contribution of banks in the public sector
3. To produce a brief note on the merger and acquisition

- of banks
4. To elaborate the impact of the merger of banks on the financial health and efficiency of public sector banks
5. To concentrate on the merger of the Syndicate Bank with the Canara Bank
6. To produce the historical perspective of the Syndicate Bank and the Canara Bank
7. To trace and bring forth the factors responsible for the merger of the Syndicate Bank with the Canara Bank
8. To explore and highlight the causes and effects of the merger of the Syndicate Bank with the Canara Bank
9. To let the reader have a peep into the pre-merger state of the Canara Bank
10. To discuss the post-merger state of the Canara Bank with the Syndicate Bank and its contribution to the financial health

### Related Literature Review

'India's financial sector liberalization since 1991 has been a comprehensive program involving issues related to banking, capital markets, fiscal policy, and international financial integration. Issues of linkage and sequencing between these areas have been central. India makes heavy use of expert commissions to float and develop ideas and agendas. Since the start of reforms in 1991, private sector banks, both domestic and foreign, have been allowed more liberal entry, albeit with different degrees of freedom. By end-March 2004, the domestic private sector banks held 18.6 percent of assets, 17 percent of deposits, and 19.8 percent of advances. The corresponding numbers for foreign banks were 6.9 percent, 5.1 percent, and 7.0 percent. While there is thus a substantial presence of private banking in India, the public sector banks continue even now to dominate the Indian banking sector. Indian banks, led by the public sector banks, have also continued to expand their presence overseas.'

'In a developing country such as India, the banking sector plays a crucial role in financial intermediation, in addition to assisting the government in achieving the social goal. This indispensable connection between economic growth and banking has led the development of the entire economy and is associated with the health of the banking industry. The growing technology and competition highlight the significance of the highly efficient banking sector. It stresses the pertinent monitoring and performance assessment of the banks, as this can affect their entire efficiency and consequently on the profitability.'

'ROA of both the banks under merger<sup>1</sup> and merger 2 ratios have dropped. The provisions for NPA held by banks involved in both merger<sup>1</sup> and merger 2 also have caused negative ROA. Under the mergers of PSBs, the banks have collectively shown Net Interest Margin which is fitting. In terms of Loans-to-Assets, Canara Bank has shown the synergy benefit from the Syndicate Bank under merger<sup>1</sup>. The banks under both mergers 1&2 have revealed suitable Net Interest Margin. Operating Profit Margin ratio indicates that both mergers might be limited since the banks are

handling their operations in an organized way. The negative effect might be limited as the banks share their benefits collectively.

'The banking sector is a rapidly growing industry in India. A comparatively new development in the Indian banking sector is enhanced through mergers and acquisitions. It permits banks to achieve a world class position and throw superior value to the stakeholders. The impact of merger on a company's stock and the effect on the equity share of the shareholder's capital is usually proportional. Performance of the bank pre- and post-merger usually is in the green and improved. To a certain extent M&A's have been successful in Indian banking sector, and that the merger of bank and capital infusion to banking sector leads to stability in the banking sector as well as growth of economy. There is an incredible impact of pre & post-merger financial performance of Canara bank.'

'Banks use mergers and acquisitions as one of the most common corporate restructuring strategies to diversify or develop their operations. Due to the arrival of new competitors and products with advanced technology, globalization of the financial markets, changing customer behavior, expanded services at a lower cost, and other factors, the Indian banking system has changed dramatically in recent years in terms of mergers and acquisitions. The Indian banking system has been strengthened. Canara Bank and Syndicate Bank merged in 2019 to improve efficiency and centralize operations.

'Canara Bank's planned merger with Syndicate Bank Ltd. will create India's fourth-largest public sector bank, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence. The merger is part of the Indian government's push to consolidate the banking sector, with its latest plan involving the merger of 10 state-owned lenders into four bigger banks. The merged entity will have total assets of about 10.248 trillion rupees and total net loan of about 6.332 trillion rupees. The merger will initially be negative for Canara Bank's intrinsic risk profile.

'In the current environment, the central government believes that merging banks will assist to recover and minimise problematic NPAs. The RBI will have an easier time monitoring a smaller number of banks. Another component of bank mergers is cost reduction. When it comes to Syndicate Bank and Canara Bank, the two banks were united with the banking software they both use, iflex. The combined corporation, Canara Bank, was unable to reap the benefits of synergy in the short term. Canara Bank's re-pricing of existing savings account deposits has a negative impact on profitability. However, Canara Bank will benefit in the long run.'

'On 30 August 2019, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced the merger of the Syndicate Bank with Canara Bank, which was approved by the Board of Directors of Canara Bank on 13 September, and by the Union Cabinet on 4 March 2020. The merger was completed on 1 April 2020 with Syndicate Bank shareholders receiving



158 equity shares in the former for every 1,000 shares they hold. After the merger, the Canara Bank has become the fourth-largest public sector bank of the country, with the combined business worth INR 15.20 lakh crore and a lower gross NPA ratio of 8.77%.’

‘Wide-ranging reforms have been carried out in the Indian economy since mid-1991. Two decades of economic and financial sector reforms have strengthened the fundamentals of the Indian economy and transformed the operating environment for banks and financial institutions in the country. The most significant achievement of the financial sector reforms has been the marked improvement in the financial health of commercial banks in terms of capital adequacy, profitability and asset quality and also greater attention to risk management.’<sup>14</sup>

#### Hypothesis:

1. Banking sector is one of the most important sector
2. Merger of banks strengthens and boosts up the efficiency of public sector banks
3. The merger of the Syndicate Bank took place as a result of certain factors
4. The merger of the Syndicate Bank has brought about a new responsibility to the Canara Bank
5. The post-merger status of the Canara Bank is not enthusiastic
6. There is no difference of efficiency and outcome in the pre and post- merger status of the Canara Bank.

**Method:** Made on the basis of the secondary data collected from the various available sources, the study is qualitative, descriptive and interpretative in nature, and it deals with the various aspects associated with the merger of the Syndicate Bank with the Canara Bank. The scientific spirit of the work has been ensured through the use of scientific method and the observance of and adherence to the steps of scientific method. The process of research adopted for the purpose of making this study is approved by the eminent scientists, as the researchers followed the following suggested steps of research-

1. Selection of the Problem (Merger of Canara Bank and Syndicate Bank: An Overview), which is indeed an important issue to be studied.
2. Setting of specific objectives that were met out through the development of the theme and content.
3. Selection of a research design through which the content associated with the problem was shaped up in a presentable form.
4. Adoption of method which enabled the researchers to meet out the objectives of the study, develop the theme accordingly, ensuring scientific spirit of the work, and draw conclusion.
5. Formulation of the hypotheses on the merger and acquisition of banks, impact of the merger of banks on the financial health and efficiency of the public sector banks, causes responsible for the merger of the Syndicate Bank with the Canara Bank, pre and post-merger status of the Canara Bank etc.

6. Study of the previously-made studies on the theme, which encompassed both the Indian studies and the studies made in the foreign countries.
7. Generalization on the basis of the collected data.

**Conclusion:** The merger of Canara Bank and Syndicate Bank was made with a view to cleaning of the Balance Sheet and minimizing NPA. The implication of this merger was-merging one weak bank with its stronger counterparts. The Syndicate Bank was found weaker than the Canara Bank, and therefore, the Syndicate Bank was merged with the Canara Bank despite the fact that the Syndicate Bank enjoyed an immense popularity all over India for decades. However, much later it was found that it was not able to work quite effectively, or to say, it failed to maintain its efficiency in terms of financial health of the nation. It forced the policy makers to merge it with some stronger bank. The Canara Bank was found to be a suitable public sector bank with which it could be merged.

Syndicate Bank and Canara Bank merged in order to form the fourth largest public sector bank in India, as well as to increase the efficiency and competitiveness among the banks in the Indian public banking sector. Beginning in the year 2019, the merger of the Syndicate Bank into the Canara Bank got completed in 2020. The merged entity is supposed to benefit from increased scale and a broader range of products and services, as well as improved access to capital and resources.

The Government of India is serious about the national and international financial issues. For the same of recovery and reduction in bad NPAs, it is promoting merger of banks. Obviously, as it is being predicted, as a result of the merger of banks, there will be only lesser number of banks, and it will be quite easy for the Reserve Bank of India to make a better monitoring. As far as the merger of the Syndicate bank into the Canara bank, they have been merged because both the Syndicate Bank and the Canara Bank used the one and same software, namely, iflex software, and both the banks have their origin in coastal part of Karnataka having a cultural similarity between them. The merger of the Syndicate Bank into Canara bank has won a new identity of being the 4th largest bank in India in terms of business (15.2 lakh crores) and 3rd largest in terms of number of branches.

At the root of the merger, there were the following objectives-

1. Creation of Next Gen Banks.
2. Repositioning PSBs with scale for building of USD 5 Trillion Economy .
3. Enhancement of capacity to increase credit.
4. A strong national presence of banks and their international accessibility.
5. Enhancement of operational efficiency
6. Enhanced risk appetite.
7. Wider offerings and enhanced customization.
8. Betterment in raising the resources from market.

To sum up in a word, there is not a tremendous difference between the pre-merger and post-merger status

of the Canara Bank. However, it is hoped that in the years and decades to come, the Canara Bank would be able to meet out all the objectives with which the merger of both the banks was made.

#### References:-

1. Yogashree C (2019). Effect of Amalgamation on Financial Performance: A Case Study of Canara Bank Ltd. International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 9 Issue 7
2. Mr. Eswar S Prasad, Mr. Steven V Dunaway and Mr. Jahangir Aziz (2006). Domestic Financial Liberalization and International Financial Integration: An Indian Perspective. China and India Learning from Each Other Reforms and Policies for Sustained Growth, International Monetary Fund, 282
3. Krishnaveni Lankapotu (2020). Performance of Selected Public Sector Banks involved in Recent Mega Merger in India. Journal of Shanghai Jiaotong University, Volume 16, Issue7
4. Ranina Sanglap Francis Garrido (2019). Canara Bank, Syndicate Bank merger to create 4th largest PSB in India. S&P Global Market Intelligence
5. Sayooj kumar.K.P (2018). Efficiency Evaluation of Public Sector Banks in India. JETIR, Volume 5, Issue 3

\*\*\*\*\*

# Research: Impact of Public Distribution System Reform on Food Security in Chhattisgarh

Dr. Syed Saleem Aquil\* Rakesh Minj\*\*

**Abstract** - This study examines the impact of food subsidies on poverty reduction among households below the Poverty Line (BPL) in Chhattisgarh. Employing a descriptive research design and utilizing secondary data derived from published reports and surveys, the research scrutinizes food subsidies' trends and growth rates and their efficacy in alleviating poverty. The results indicate a notable increase in food subsidies over time, yet their influence on poverty mitigation remains limited. Consequently, the study underscores the necessity for precise targeting and reduced subsidies to foster sustainable long-term growth and poverty alleviation.

**Keywords:** Food subsidy, Poverty alleviation, BPL households, Chhattisgarh, PDS, Fiscal deficit.

**Introduction** - Poverty is a significant concern in India, and providing food subsidies forms a crucial component of the government's strategy to alleviate this problem. Chhattisgarh, recognised as one of the poorest states in India, has implemented various food subsidy programs to support households below the poverty line (BPL). This study seeks to evaluate the impact of food subsidies on poverty reduction among BPL households in Chhattisgarh, with the potential to provide valuable insights and solutions to this pressing issue.

**Literature Review:** Several research studies have investigated the effects of food subsidies on poverty alleviation. In Sharma's (2012) analysis of food subsidies in India, a regression model was employed to demonstrate that government-led operational factors significantly contribute to the increase in subsidies. Arora (2013) evaluated the food subsidy in India and critically assessed its alignment with the objectives that led to its implementation. The study revealed that the outreach of the Public Distribution System (PDS) in the country needs to be improved, with a concentration in the relatively developed states rather than in the states with higher poverty levels.

**Methodology:** The study adopts a descriptive research design and relies on secondary data from published reports and surveys. The dataset encompasses the trend and growth rates of food subsidies and the fiscal deficit in India. Primary statistical methodologies, such as trend analysis, ratio analysis, and percentage analysis, are employed to facilitate the examination of the compiled data.

**Results:** The data reveals a substantial increase in food subsidies in India over the years. From 1991-92 to 2018-19, the Central Government allocated a sum ranging from Rs. 2850 crore to Rs. 169323 crores for food subsidies.

The escalating magnitude of food subsidies is evident in their growing share of the Gross Domestic Product (GDP). While food subsidies accounted for 0.42 per cent of GDP in 1991-92, this figure rose to 0.89 per cent by 2018-19.

**Food Subsidy in Chhattisgarh up to 2018:** The food subsidy bill for the fiscal year 2018-19 was projected to be approximately Rs 1,69,323 crore, marking a 10 to 15 per cent increase from the preceding year. The Centre's food subsidy bill was anticipated to see a 10 per cent upsurge to around Rs 1.60 lakh crore in the 2018-19 budget. The Government of India was set to disburse Rs 4,800 crore as food subsidy to Chhattisgarh. The state government, playing a crucial role, was slated to administer highly subsidised food grains to more than 80 crore individuals by the National Food Security Act.

**Discussion:** The research underscores the necessity of accurate targeting and reduction of subsidies to achieve sustained long-term growth and poverty alleviation. The analysis indicates that food subsidies have a limited impact on poverty alleviation among BPL (Below Poverty Line) households in Chhattisgarh. Consequently, the study proposes that subsidies may serve as a short-term intervention for addressing social challenges such as poverty. Nevertheless, self-sustained productive measures such as employment creation and educational empowerment will be indispensable in the long term.

**Reasons for Providing Food Subsidy in Chhattisgarh:** The provision of food subsidy in Chhattisgarh is warranted for a multitude of reasons:

- 1. Poverty:** Chhattisgarh contends with a high incidence of poverty, leading to many households being unable to procure essential food items.
- 2. Malnutrition:** The state grapples with considerable levels of malnutrition, particularly prevalent among children,

\* Asst. Professor (Commerce) Kalyan Post Graduate College, Bhilai, Dist. Durg (CG) INDIA

\*\* Asst. Professor, Govt. Daanveer Tularam P.G. College, Utai, Dist. Durg (CG) INDIA

women, and tribal communities.

**3. Food insecurity:** Numerous households in Chhattisgarh experience constraints in accessing dependable and nourishing food supplies.

**4. Agricultural challenges:** The state is susceptible to droughts, floods, and other agricultural adversities, impacting the availability and affordability of food.

**5. Tribal population:** Chhattisgarh is home to a substantial tribal populace, often deprived of mainstream resources and necessitating targeted assistance.

**6. Economic inequality:** Food subsidy narrows economic disparities among individuals, ensuring universal access to fundamental necessities.

**7. Social welfare:** Implementing food subsidies is a pivotal social welfare intervention, guaranteeing indispensable support for vulnerable demographics.

**8. Food price volatility:** Fluid food prices present challenges for economically disadvantaged households, making food procurement only possible with subsidies.

The government endeavours to reinforce food security, enhance health and well-being, and alleviate poverty and disparities in Chhattisgarh by providing a food subsidy.

**Analysis of How Food Subsidies Help Poor Households in Chhattisgarh:** An analysis of the economic condition of poor households receiving food subsidies in Chhattisgarh:

**1. Improved food security:** Food subsidies have ensured access to essential food items like rice, wheat, and pulses, reducing hunger and malnutrition.

**2. Reduced expenditure:** Subsidized food has decreased household expenditure on food, freeing up resources for other essential expenses like healthcare and education.

**3. Increased purchasing power:** Subsidized food gives poor households more disposable income to spend on other necessities, boosting their overall purchasing power.

**4. Better health outcomes:** Access to nutritious food has improved health outcomes, reducing morbidity and mortality rates.

**5. Increased school enrolment:** With food security ensured, poor households are more likely to send their children to school, improving educational outcomes.

**6. Reduced poverty:** Food subsidies have contributed to declining poverty levels in Chhattisgarh, with many households graduating from extreme poverty.

**The Public Distribution System and Food Subsidy in Chhattisgarh:** The Public Distribution System (PDS) in Chhattisgarh is crucial in providing food subsidies to vulnerable populations, but its effectiveness is subject to various limitations and challenges. Here is a critical analysis of the PDS system in Chhattisgarh

#### Strengths:

**1. Wide reach:** PDS covers a significant portion of the population, including rural and tribal areas.

**2. Subsidized prices:** PDS provides essential food items at subsidized rates, making them affordable for poor households.

**3. Food security:** PDS ensures a steady supply of food grains, reducing the risk of hunger and malnutrition.

#### Weaknesses:

**1. Inefficiencies:** PDS is often plagued by inefficiencies, including leakages, corruption, and mismanagement.

**2. Limited coverage:** Despite its broad reach, PDS still excludes many vulnerable populations, such as urban poor and migrant workers.

**3. Quality issues:** PDS food grains are often of poor quality, affecting their nutritional value and acceptability.

**4. Inadequate funding:** PDS funding is often insufficient, leading to shortages and irregularities in food supply.

**5. Lack of transparency:** PDS operations need more transparency, making tracking subsidies easier and ensuring accountability.

#### Challenges:

**1. Infrastructure:** PDS infrastructure, including storage facilities and transportation, needs to be improved.

**2. Supply chain disruptions:** Disruptions in supply chains, such as droughts or conflicts, can impact food availability.

**3. Beneficiary identification:** Identifying genuine beneficiaries and preventing fraud remains a significant challenge.

**4. Political interference:** PDS is often subject to political interference, influencing the selection of beneficiaries and allocation of resources.

#### Reforms:

1. End-to-end computerisation

2. Aadhaar linking for transparent beneficiary identification

3. Doorstep delivery

4. Quality improvement initiatives

5. Increased funding and infrastructure development

**Conclusion:** Food subsidies are vital in supporting households living below the poverty line in Chhattisgarh. Despite their significance, research indicates that these subsidies have limited effectiveness in reducing poverty. The study underscores the necessity of precisely targeting and decreasing subsidies to promote long-term sustainable growth and poverty alleviation. The findings imply that while subsidies can temporarily relieve social issues like poverty, sustainable solutions require a shift towards autonomous measures such as fostering employment opportunities and advancing educational empowerment.

In conclusion, while the PDS system in Chhattisgarh plays a vital role in providing food subsidies, various weaknesses and challenges could improve its effectiveness. Implementing reforms and addressing these issues can improve the efficiency and impact of the PDS system, ensuring that food subsidies reach those who need them most.

#### References:-

1. "Public Distribution System Reforms and Consumption in Chhattisgarh" (2022)

2. "The Impacts of Reforms to the Public Distribution



- System in India” (no date)
3. “Food Price Subsidies and Nutrition: Evidence from State Reforms” (no date)
4. The Impacts of Reforms to the Public Distribution System in India’s (no date)
5. Food subsidy bill may swell by 10 per cent in 2018-19 budget - The Siasat Daily – Archive. <https://archive.siasat.com/news/food-subsidy-bill-may-swell-10-cent-2018-19-budget-1301242/>
6. Where’s My Money, Fool: Conditional Cash Transfers | Develop Economies. <https://developeconomies.com/development-economics/wheres-my-money-fool-conditional-cash-transfers/>
7. Pitch for CSS - The Startup Pitch. <https://thestartuppitch.com/pitches/pitch-for-css/>
8. Cryptocurrency Research Survey. [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR6QImMyuc1EySwOPMpba0et5dSQfnOaGnyYh8aX8ub9I6jA/viewform?usp=sf\\_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR6QImMyuc1EySwOPMpba0et5dSQfnOaGnyYh8aX8ub9I6jA/viewform?usp=sf_link)
9. Sam, V. N. (2016). The Poverty Hypothesis and Intergenerational Transmission of Child Labor: Evidence from Ghana. <https://core.ac.uk/download/478457599.pdf>
10. Dasgupta, N., Baqui, M., Dhingra, S., Raman, P., Ahiduzamman, M., & Kishore, V. (2003). Benefits of improved rice husk combustion, Bangladesh (NRI report no. 2764). <https://core.ac.uk/download/42390208.pdf>

\*\*\*\*\*

## नयी कविता को मुक्तिबोध का प्रदेय

डॉ. डी.पी. चंद्रवंशी\*

**प्रस्तावना** - छायावदी काव्य की वायवीयता एवं सौंदर्य बोध से शुद्ध मानवता बोध के लिए संघर्ष करने वाले तथाकथित प्रगतिशील कहलाने वाले तथ्यों ने हिन्दी कविता को राजनीतिक चेतन्य, जागरूकता, दलित और सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति का आधार लिया, उसमें कुछ कम आग्रह एवं प्रतिबद्धता से हटकर शुद्ध साहित्यिक निष्ठा लेकर चलने वाले कवियों को 'प्रयोगवादी' की संज्ञा से विभूषित किया गया। किन्तु आज यह प्रश्न और अधिक स्पष्ट हो चुका है कि प्रयोगवादी काव्य कोई काव्य-धारा का मोड़ नहीं है। नयी कविता की पृष्ठभूमि का निर्माण करने का ऐतिहासिक महत्व उसका अवयव है। आज भी हिन्दी कविता जिस रूप में लिखी जा रही है, उसे हम 'नयी कविता' के नाम से अभिहित करते हैं। सन् 1958 के बाद से वह भी प्रयोगवादी नाम से पहचाने जाने वाले कवियों के द्वारा बोये गये बीजों के लिए ऋणी है, भले ही तीसरे सप्तक (1959) के प्रकाशन के पूर्व 'नयी कविता' का नाम लेबिल लग चुका था, किन्तु तीनों सप्तकों के कवियों को प्रयोगवाद के तहत् मान लिया जाता था। मुक्तिबोध का काव्य जिस प्रकार के आंदोलन के अंतर्गत आता है, उसका यदि 'नयी कविता' के लिए कुछ प्रदेय है तभी तो मुक्ति बोध का प्रदेय भी सिद्ध हो सकता है। अतः हम उस मूल प्रवृत्तियों की ओर संकेत करना है, जो प्रयोगवाद से आरंभ हुई और आज तक नयी कविता के रूप में अपने प्रभाव को अक्षुण्ण बनाए हुए है।

मुक्तिबोध के काव्य में नये मानव की प्रतिष्ठा, अहंवादी मनोवृत्ति, अभिव्यक्ति शिल्प का नयापन नयी कविता के लक्षणों को इंगित करती हैं। मुक्ति बोध के काव्य में जिस आत्मसंघर्ष की अभिव्यक्ति है, वहीं नयी कविता की आधारशिला मानी जाती है। इसी प्रकार अभिव्यक्ति के क्षेत्र में भी वस्तु तत्व के साथ कथ्य शैली का जो नयापन मुक्तिबोध के काव्य में मिलता है, वही से नयी कविता के शिल्प को नयी पद्धतियों का प्रारंभ माना जा सकता है। आत्मचेतस् और विश्वचेतस का जो सामंजस्य मुक्तिबोध ने अपने काव्य संसार में किया है, वहीं नयी कविता के लिए नया द्वार खोलता है। मुक्तिबोध की कविता में जिस आत्मसंघर्ष की कहानी है वह वस्तुतः नये मानव की नियति हैं। मुक्ति बोध के काव्य से ही नये युग की नयी रचनाओं के मूल्यों का अध्ययन प्रारंभ होता है। डॉ. राजेश्वर दयाल सक्सेना ने गजानन माधव मुक्तिबोध को नयी कविता का आविष्कारक कहा है। शैलीगत नयापन का शुभारंभ भी वे मुक्तिबोध से मानते हैं। उनके शब्दों में 'मुक्तिबोध ने हिन्दी कविता में नये वस्तु तत्व का तथा नयी काव्य शैली का प्रयोग किया। नये काव्य की सामाजिक तथा तार्किक पृष्ठभूमि को निर्मित किया। नयी कविता के काव्य शास्त्र और नये ललित बोध के सौंदर्य शास्त्र का प्रारंभ मुक्तिबोध से होता है।'<sup>1</sup>

यदि हम किसी ऐसी काव्य धारा या उपधारा की खोज करना चाहे जिससे कि मुक्ति बोध को किसी उपधारा का उद्गम स्थल कह सके तो कई बार तो ऐसा लगता है कि आलोच्य कवि तो इतना निराला है कि न तो वह अपने से पहले के किसी कवि का अनुकरण कर सका और न अनुकरणीय ही बन सका। किन्तु फिर भी उनके काव्य में कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ मिल सकती हैं जो आज तक के कवियों में देखी जा सकती हैं। यदि परवर्ती कवि रघुवीर सहाय और श्रीकांत वर्मा के काव्य में देखकर मुक्तिबोध के द्वारा आविष्कृत नयी कथ्य पद्धति का परिचय प्राप्त किया जा सकता है, और नयी कविता में उनके प्रदेय को स्वीकार किया जा सकता है। श्री अशोक वाजपेयी मुक्तिबोध के इसी प्रदेय पर प्रकाश डालते हुए लिख हैं- '..... यह आकस्मिक नहीं है कि आज के महत्वपूर्ण युवा कवि रघुवीर सहाय और श्रीकांत वर्मा दोनों ने अपने ढंग से तुकों, व्यक्तिवाची, नामों, चमकारी संयोगों आदि का जो स्तेमाल किया है, इसका उद्गम कहीं न कहीं मुक्तिबोध में है। आज की महत्वपूर्ण युवा कविता मुक्तिबोध की कविता की तरह खुरदरी, विचलित करने वाली कविता है, चमकीली और प्रीतिकर कविता नहीं और मुक्तिबोध की कविता युवा कविता के लिए लगभग उद्गम काव्य हो गई है।'<sup>2</sup>

नयी कविता की एक सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जा सकती है कि उसमें मानव-जीवन के लिए कुछ कर गुजरने की छटपटाहट है। छटपटाहट मुक्तिबोध के काव्य में अत्यंत सशक्त रूप से अभिव्यक्त हुई है। यही कारण है कि मुक्तिबोध के काव्य में नयी कविता की अनन्त संभावनाएं छिपी हैं, जिसका संकेत उनकी निम्न पंक्तियों से पता चलता है-

'नहीं होती, कहीं खतम कविता नहीं होती  
वह आवेग त्वरित काल यात्री है  
मैं उकसा नहीं कर्ता पिता-घाता।  
कि वह कभी दुहित नहीं होती  
परम स्वाधीन है वह विश्व शास्त्री है।  
गहन गंभीर छाया आगामिष्यत की  
लिए, वह जन-चरित्री है।'

कहना न होगा कि यह 'जन-चरित्री' काव्यधारा मुक्तिबोध से ही प्रारंभ हुई और आज तक नयी कविता मानवता के लिए ही लिखी जा रही है। मुक्तिबोध की कविता में बौद्धिक तंतुओं का ही ताना-बाना देखा जा सकता है। कवि वास्तव में चिन्तक, विचारक के रूप में भी प्रतिष्ठित है तो बौद्धिकता के बल पर ही। मुक्तिबोध काव्य में अपने युग के सामाजिक जीवन की विद्रूपता असंगति, मानव मूल्यों का ह्रास, यन्त्र युग के कारण उद्भूत वर्ग-संघर्ष की स्पष्ट ध्वनि मुखरित हुई है। तब नयी कविता के क्षेत्र में मुक्तिबोध के द्वारा किये गये प्रारंभ के लिए हमें उनका ऋण स्वीकारना पड़ेगा। नयी कविता की

लघु मानव की प्रतिष्ठा को भी मुक्तिबोध के काव्य में ऐसा बहुत कुछ मिल जाएगा, जिसके आधार पर मुक्तिबोध को नयी कविता का आदि आविष्कर्ता कहने में संकोच नहीं होना चाहिए।

‘दिल को ठोकर

वह विकृत आइना मन का सहसा टूट गया  
जिसमें या तो चेहरा दिखता था बहुत बड़ा फूला-फूला  
या अकस्मात् विकलांग व छोटा-छोटा सा।’<sup>3</sup>

मुक्तिबोध ने लघु मानव की प्रतिष्ठा करने के लिए निरूप ब्रह्म की अस्वीकृति एवं उसके प्रति आस्था का चित्रण किया है और मानव के पौरुष एवं पराक्रम को महत्व प्रदान करके मानव के प्रयत्नों के प्रति आस्था एवं विश्वास व्यक्त किया है -

‘मेरे इस सांवले चेहरे पर कीचड़ के धब्बे हैं,

दाग है

और इस फैली हुई हथेली पर जलती हुई आग हैं,  
अग्नि विवेक की।

नहीं, नहीं, वह-वह तो ज्वलंत सरसिज!

जिंदगी के दलदल कीचड़ में धंसकर वक्ष तक पानी में फंसकर  
मैं वह कमल तोड़ लाया हूँ।’<sup>4</sup>

ओ काव्यात्मन फणिधर, कविता में मुक्तिबोध ने फणिधर कोई सर्प नहीं, स्वयं कवि की संवेदना का आत्मचेतस् ही हैं -

‘जीवन के यथार्थ ज्वलनशील मूल्यों को खोज लेने की छटपटाहट

लहराओ, लहराओ नागात्मक कविताओं झाड़ियों में छिपो

उन श्याम झुरमुटों तले कई

मिले जाये कहीं

वे फेके गये रत्न ऐसे

ओ काव्यात्मन फणिधर अपना फन फैलाओं

मणिगण को धारण करो, उन्हें

बल्मीक गुहा में ले जाओ,

एकत्र करो .....।’<sup>5</sup>

**निष्कर्ष** - इस प्रकार देखा जा सकता है कि नयी कविता के स्वर मुक्ति बोध में प्रारंभ से ही मुखरित हुए हैं चाहे वह नये मानव की प्रतिष्ठा हो या अहंवादी मनोवृत्ति या क्षण का महत्व या फिर लघुमानव की प्रतिष्ठा डॉ. राजेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा मुक्तिबोध के लघुमानव संबंधी वक्तव्य उन्हें लघुमानव का प्रतिष्ठाकन सिद्ध करता है- ‘तंत्रयुगीन पिण्डब्रह्म की धारणा की मिलती-जुलती तथा प्राणी-विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान सम्मत दृष्टि से मुक्तिबोध ने अपने रचना मानव की लघु विराट जीवन चेतना का, उसके शक्ति व्यवहार का जो विद्युत चित्र अंकित किया गया है, वही तो नया भाव बोध है। मुक्तिबोध में यंत्र कर्म की बौद्धिक संस्कृति के प्रतीक मानव को देखा जा सकता है, उसे विज्ञान युग की ब्रह्मराक्षसी प्रतिभा की देन कहना चाहिए।’<sup>6</sup>

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. डॉ. लक्ष्मीदत्त गौतम संपादक ‘गजानन माधव व मुक्तिबोध’ पृ. 269
2. वाजपेयी अशोक ‘फिलहाल’ पृष्ठ 125
3. मुक्तिबोध गजानन माधव चांद का मुंह टेढ़ा है। 1964, पृ. 123
4. मुक्तिबोध गजानन माधव एक अरूप शून्य के प्रति चांद का मुंह टेढ़ा है, पृ. 190
5. मुक्तिबोध गजानन माधव ओ काव्यात्मन फणिधर चाँद का मुंह टेढ़ा है, 1964
6. सक्सेना डॉ. राजेश्वर दयाल, ‘गजानन माधव मुक्तिबोध’, संपादक डॉ. लक्ष्मीदत्त गौतम पृ. 263, 264

\*\*\*\*\*

## प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यों एवं नीतियों का विश्लेषण

मोहित कुमार नायक\*

**शोध सारांश** – भारत में संसदीय व्यवस्था के तहत दो सदनों की व्यवस्था है जिसमें लोकसभा एवं राज्यसभा आती है। लोकसभा में प्रत्यक्ष मतदान के तहत सांसदों का चुनाव होता है जिस दल अथवा गठबंधन का लोकसभा में बहुमत होता है उस दल की देश में सरकार होती है एवं उसे दल के संसदीय दल के नेता को देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन किया जाता है। प्रधानमंत्री पद देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं वास्तविक प्रमुख होता है। देश के सभी महत्वपूर्ण फैसले उनके नेतृत्व में ही सरकार द्वारा लिए जाते हैं। भारत के प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की चर्चा देश के वास्तविक प्रमुख पद प्रधानमंत्री के बिना बहुत मुश्किल है। देश की आजादी के बाद से देश के विकास के लिए कई प्रधानमंत्रीयों ने अपनी नीतियों के माध्यम से देश का विकास किया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं डॉ. मनमोहन सिंह देश के विकास के लिए कई प्रकार की नीतियों के माध्यम से चर्चा में रहे। इन दोनों प्रधानमंत्रीयों ने अपने कार्यकाल के दौरान देश के लिए अलग-अलग मुद्दों पर संसद में कानून बनाए।

**शब्द कुंजी** – प्रधानमंत्री, कार्यकाल, नीतियां, भारत, सरकार, परमाणु परीक्षण, उद्योग, ग्रामीण विकास, आर्थिक सुधार, अर्थव्यवस्था।

### प्रस्तावना

**अटल बिहारी वाजपेयी**– विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के तीन बार प्रधानमंत्री रहे कवि अटल बिहारी वाजपेयी अपनी संचार शैली के लिए प्रसिद्ध थे। कवि से एक राजनेता बनने का सफर बहुत ही ऐतिहासिक रहा। जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन का अहम हिस्सा रहा। उनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में देश के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए जिसमें ऊर्जा नीति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना परमाणु परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है।

**डॉ. मनमोहन सिंह**– प्रधानमंत्री बनने से पूर्व डॉ. मनमोहन सिंह नरसिंह सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए देश में आर्थिक सुधारों में अपने योगदान के लिए आज भी याद किए जाते हैं। मनमोहन सिंह वर्तमान तक बने सभी प्रधानमंत्री में सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे प्रधानमंत्री रहे उन्होंने पीएचडी की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की। 2004 में वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। उनके कार्यकाल के दौरान आरटीआई, मनरेगा, आरटीई जैसे कई क्रांतिकारी फैसले लिए गए।

### वाजपेयी के कार्य

**1. वाजपेयी की संचार नीति**– 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में राष्ट्रीय संचार नीति लागू की। संचार क्षेत्र को विकसित करने के लिए वाजपेयी ने कई संरचनात्मक सुधार लागू किया। TRAI एक्ट 1997 में संशोधन किया इस संशोधन से पूर्व ट्राई की भूमिका कड़े नियामक के रूप में थी, जिसके कारण निजी क्षेत्र का संचार क्षेत्र में प्रवेश बहुत ही मुश्किल समझा जाता था। वाजपेयी ने संचार क्षेत्र के विवादों के निपटान के लिए अलग ट्रिब्यूनल बनाना प्रस्तावित किया जिसके तहत टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 2000 में हुई एवं ट्राई को पूर्णतया एक बाहरी नियामक की भूमिका दी गई। वाजपेयी ने संचार क्षेत्र में आयात शुल्क काम किया जिससे भारत में संचार क्षेत्र में नए मोबाइल फोन एवं तकनीकी वया आना हुआ आज हमारा देश विश्व का दूसरा सबसे

बड़ा स्मार्टफोन बाजार है।

**2. खाद्य सुरक्षा से संबंधित नीतियां**– वाजपेयी ने देश की उन्नति में खाद्य सुरक्षा को एक महत्वपूर्ण आयाम माना। उन्होंने 2003 के राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर यह प्रश्न विचार गद्य रखा की जो लोग परिवार में नहीं हैं जिनके पास जीवन जीने का कोई साधन नहीं है उन सभी लोगों का पेट कैसे भरा जाए उसे पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्य का भंडार होते हुए भी लोगों को भूखे रहने की नौबत ना आए क्योंकि यह हमारे प्रबंधन की कमी को दर्शाता है। उन्होंने कृषि क्षेत्र में टेलीकॉम कनेक्टिविटी को बढ़ाने तथा किसानों को फसल का उचित दाम मिलने के लिए अपना ध्यान विजन 2020 के तहत केंद्रित किया। उनके कार्यकाल की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन था उनके अनुसार अगर कृषि का माल खेत से निकलकर मंडी में पहुंचे इसके लिए अच्छी सड़के भी चाहिए साधन भी चाहिए और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गांव को नई सड़कों की सौगात मिली।

**3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना**– वाजपेयी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 25 दिसंबर 2000 को लागू किया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों द्वारा जोड़ना एवं कनेक्टिविटी को विकसित करना था। प्रारंभ में यह योजना पूर्णता केंद्र प्रायोजित के रूप में प्रारंभ की गई क्योंकि इसका लक्ष्य केवल आवागमन नहीं था साथ ही यह सुदूर ग्रामीण इलाकों में गरीबों को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री की दूर दृष्टि की सोच का परिणाम था। इस योजना में जिन गांवों में 500 संख्या तक लोग निवास करते थे उन सभी गांव को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। इस तरह सड़कों के विकास के माध्यम से एक न्यूनतम रोड नेटवर्क जो आमजन के लिए आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं के तक पहुंच के लिए आवश्यक है विकसित किया जाएगा।

**4. ऊर्जा नीति**– ऊर्जा के क्षेत्र का विकास तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे। उद्योगों के विस्तार के लिए



कृषि के विकास के लिए बिजली की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वाजपेयी ने 2003 में विद्युत अधिनियम 2003 पारित किया। इसमें ऊर्जा क्षेत्र को बाजार आधारित तथा मांग के आधारित बनाने का निर्णय किया। उन्होंने बिजली के मामले में सभी दलों को एक साथ बैठकर एक नीति बनाने जैसी बात कही। नरसिम्हा राव की 1991 के आर्थिक सुधार की नीतियों को अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे बढ़ाया।

**5. वाजपेयी के समय राज्य सरकारों से संबंध-** वह हमेशा से ही राज्य व केंद्र के संबंधों को स्वस्थ चाहते थे। उन्होंने दलगत राजनीति से प्रभावित होकर कभी भी किसी राज्य के लिए अहित का निर्णय नहीं लिया। राजस्थान गुजरात आंध्र प्रदेश में सुख के कारण गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी तो वाजपेयी ने उनके लिए विशेष पैकेज की राशि बढ़ाने में तनिक भी संकोच नहीं किया, चाहे राज्यों में विपक्षी दल की भी सरकार रही हो उनके लिए राष्ट्रीय गीत सदैव ही सर्वोपरि रहा। अन्तर्राज्यीय विवाद को सुलझाने में भी वाजपेयी हमेशा आगे रहे जैसे कावेरी समझौते पर कर्नाटक व तमिलनाडु की सरकार के बीच सहमति लाना, पूर्वोत्तर राज्य में हो रही उत्तर-पुथल को संभालना, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उठ रही अलग राज्यों की मांग को भी अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्र की एकता अखंडता के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों की आकांक्षाओं व प्रशासनिक कार्य कुशलता को देख निर्णय लिया। इसी क्रम में 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, 2000 को क्रमशः छत्तीसगढ़ उत्तराखंड व झारखंड नवीन राज्य बनाए गए। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड, एवं बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बनाया।

**6. धन शोधन निवारण अधिनियम-** वाजपेयी सरकार ने काले धन के खिलाफ लगाम लगाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट 2002 पारित किया। गैरकानूनी तरीके से प्राप्त आय को कानूनी बनाने के अनैतिक माध्यमों को अपनाना एक कानूनी अपराध है सरकार द्वारा लाया गया यह कानून मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न साधनों जैसे फिशलल लोन्स, व्यापार लांड्रिंग, हवाला पैसों की बड़ी मात्रा में स्मगलिंग, रियल एस्टेट, जुआ आदि पर सरकार की लगाम लगाता है। वर्तमान मोदी सरकार द्वारा लागू की गई नोटबंदी भी इसी दिशा का एक कदम समझा जाता है। इस अधिनियम ने नियामक के तौर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) को नियुक्त किया। प्रशासक के तौर पर इस अधिनियम को एक सफलता के रूप में देखा जाता है।

**7. पोखरण परमाणु परीक्षण-** वाजपेयी परमाणु परीक्षण 1995 में करना चाहते थे लेकिन अमेरिकी सेंटेलाइट द्वारा पोकरण में हलचल खड़ेस्वर लगने की वजह से परीक्षण नहीं हो पाया। माय 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण करके वाजपेयी ने पूरे विश्व को भारत की मजबूती संदेश दिया। परमाणु परीक्षण पर उठे सवाल का जवाब देते हुए वाजपेयी ने संसद में कहा की पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण के दिन को राष्ट्र की एकता एवं मजबूती का प्रतीक बताया गया। 11 में को हुए इस परीक्षण के दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत की ऊंची उड़ान का प्रतीक है। परीक्षण के पश्चात भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया इसका प्रभाव दक्षिण एशियाई देशों पर भारत की मजबूती दिखा।

**8. वाजपेयी की कश्मीर नीति-** वाजपेयी के कार्यकाल में कश्मीर की नीति सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक नीति का पहलू है। 2003 में उनके द्वारा दिया गया नारा कश्मीरीयत, इंसानियत व जम्हूरियतकश्मीरीयो के दिलो तक प्रभाव करने वाला था। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कश्मीर में विकास की नई धारा बहाने का काम वाजपेयी सरकार ने किया।

## डॉ. मनमोहन सिंह के प्रमुख कार्य

**1. 1991 के आर्थिक सुधार-** डॉ. मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे जिन्होंने देश के वित्तीय संकट के मद्देनजर 1991 के आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी। उनके सुधारों ने 18 उद्योगों को छोड़कर सभी में लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया, अन्य चीजों के अलावा 51% तक विदेशी इक्विटी शेयर को पूर्व-अनुमोदित करके विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया। उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के परिदृश्य को बदल दिया और आने वाले दशकों में उच्च विकास स्तर का मार्ग प्रशस्त किया, जबकि देश को तत्काल वित्तीय संकट से बचाया, जहां सरकारी खजाने लगभग खाली थे। डॉ. मनमोहन सिंह ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को अधिकतम करने के लिए सार्वजनिक निवेश पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि निजी क्षेत्र की भागीदारी को केवल एक पूरक भूमिका के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे आने वाले वर्षों में बुनियादी ढांचे के विस्तार में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में देखा जाना चाहिए। उस समय भारत (केंद्र और राज्य) का संयुक्त राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 8% था (विकासशील देशों में सबसे अधिक)। जब डॉ. सिंह 2004 में भारत के प्रधान मंत्री बने, तो 1991 से उनके आर्थिक सुधारों ने सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दिखानी शुरू कर दीं। 2003 से, भारत की जीडीपी प्रति वर्ष 8% से अधिक बढ़ रही थी, जिससे बेरोजगारी दर, गरीबी आदि में कमी आई।

**2. प्रधानमंत्री कार्यकाल (2004-2014)-** 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में आम चुनाव के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) गठबंधन का गठन हुआ। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस ने किया। विभिन्न मुद्दों पर 59 सांसदों के साथ वाम दलों के बाहरी समर्थन के साथ होने के बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के लिए आश्चर्यजनक पसंद बन गए। 2009 के आम चुनाव में वाम दलों के बिना गठबंधन वापस सरकार में आ गया लेकिन कांग्रेस को ज्यादा ताकत मिली और इस बार प्रधानमंत्री के लिए मनमोहन सिंह स्वाभाविक पसंद थे। उनके ऐतिहासिक कार्यकाल के दौरान भारत ने आरटीआई, आरटीई, मनरेगा, परमाणु समझौता आदि जैसे कुछ क्रांतिकारी नीतिगत बदलाव देखे।

**3. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005)-** डॉ. मनमोहन सिंह सरकार ने अप्रैल 2005 में, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम) की शुरुआत की। 2013 में इस योजना का नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर दिया गया और शहरी क्षेत्रों में भी इसका विस्तार किया गया। यह योजना कमजोर वर्गों की बुनियादी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करती है।

**4. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्य -** ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर बेहतर सुविधा के साथ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की संरचना कराना पब्लिक, प्राइवेट हेल्थमॉडल को फॉलो कर बेहतर स्वास्थ्य सेवा नागरिकों को देना।  
i. स्वास्थ्य मिशन में आवश्यक नियम, शर्तें एवं मापदंड को तय कर अमल करवाना इस तरह के मिशन के अंतर्गत सुगम सेवा के लिए सरकारी खर्च में बढ़ोतरी किया जायेगा। मिशन में लक्ष्य और कार्य प्रगति से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण नागरिकों के साथ साझा किया जायेगा।

**5. मनरेगा (2005)-** एक कल्याणकारी राज्य की सफलता की कल्पना इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वहाँ सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रयास किये गए हैं। समग्र उन्नति की इस पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी राष्ट्रीय

ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात् मनरेगा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि कृषि संकट और आर्थिक मंदी के दौर में मनरेगा ने ग्रामीण किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिये एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य किया है। मनमोहन सरकार की एक प्रमुख योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरुआत हुई यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष 100 दिनों के काम की गारंटी देती है जो कुछ हद तक आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ग्रामीण भारत को 'श्रम की गरिमा' से परिचित कराने वाला मनरेगा रोजगार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है।

**6. सूचना का अधिकार (2005)**—डॉ. मनमोहन सिंह सरकार का एक अन्य ऐतिहासिक कानून जो प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण कदम था सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली तत्पश्चात की जून 2005 को यह अधिनियम राज पत्र में प्रकाशित हुआ। यह संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया। सूचना के अधिकार ने नागरिकों को सभी प्रकार की कानूनी सूचनाओं को जानने का अधिकार दिया जिससे प्रशासन पारदर्शी एवं इमानदार बन सके। इस अधिनियम में कोई भी व्यक्ति कोई भी सूचना ईमेल प्रेस विज्ञापन आदेश रिपोर्ट नमूने इलेक्ट्रॉनिक आंकड़े निजी संस्थाओं से जुड़े कोई सूचना सरकारी संस्थाओं की कोई सूचना सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकता है।

**7. भारत-अमेरिका परमाणु समझौता (2008)**— मनमोहन सरकार ने 2008 में, अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो अन्य बातों के अलावा असैन्य और सैन्य में भारत की परमाणु सुविधाओं को अलग करता था। भारत नागरिक सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) की सुरक्षा के तहत रखने पर सहमत हुआ और अमेरिका भारत में नागरिक सुविधाओं में पूर्ण सहयोग करने पर सहमत हुआ। अमेरिका भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) से छूट दिलाने में भी कामयाब रहा, जिसके बाद भारत अन्य देशों से परमाणु

प्रौद्योगिकी और ईंधन प्राप्त कर सकता था।

**8. शिक्षा का अधिकार (2009)**—शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के अंतर्गत 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित हो।

● **शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के मुख्य उद्देश्य:**

1. इस अधिनियम के तहत शिक्षा निशुल्क एवं अनिवार्य होनी चाहिए।
2. शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र एवं राज्य को अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना।
3. पाठ्यक्रम का निर्माण संविधान के अनुसार करना।
4. विद्यालय एवं शिक्षक की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
5. बाल श्रम पर रोक लगाना बालकों का संरक्षण करना।

**संदर्भ ग्रंथ सूची:-**

1. द प्रॉमिस ऑफ इंडिया हाउ प्राइम मिनिस्टर नेहरू टू मोदी शेपड दी नेशन 1947-2019, जैमिनी भगवती, पेंगुइन, इंडिया, 2019
2. गठबंधन की राजनीति, अटल बिहारी वाजपेयी, (सं.) ना. मा. घटाटे, प्रभात पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2009
3. डॉ. मनमोहन सिंह-टैम्पसच्यूस टैन्डोर, आशे गुणे, शुजाय शास्त्री, के डी प्रिंट, 2018
4. द अनटोल्ड वाजपेयी, एन पी उल्लेख, पेंगुइन, नई दिल्ली, 2018
5. अटल बिहारी वाजपेयी-अमैन फॉर आल सीजन, किंगसुख नाग, रूपा पब्लिकेशन, इण्डिया, 2016
6. राजनीति की रपटीली राहें अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रिका प्रसाद शर्मा, प्रवीण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002
7. <https://www.amarujala.com/columns/opinion/economic-reforms-that-changed-india-starts-in-1991-by-pv-narasimha-rao-and-his-finance-minister-manmohan-singh>
8. 'भारत के प्रधानमंत्री', राशिद किदवाई, राजकमल प्रकाश, नई दिल्ली, 2021

\*\*\*\*\*

## चित्रकला व मूर्तिकला के संगीकार

डॉ. राजीव शर्मा \*

**शोध सारांश** – चित्रकला और मूर्तिकला भारतीय कला परंपरा के दो प्रमुख स्तंभ हैं, जो मानव अनुभव, धार्मिक भावनाओं और सांस्कृतिक पहचान को अभिव्यक्त करने के प्रभावशाली माध्यम रहे हैं। इन दोनों कलाओं का संगम, जिसे हम 'संगीकार' कह सकते हैं, कला की ऐसी समग्र दृष्टि प्रस्तुत करता है जहाँ दृश्य और स्पर्शात्मक अभिव्यक्ति एक साथ साकार होती है। चित्रकला, जहाँ रंगों, रेखाओं और आकृतियों के माध्यम से दृश्य जगत को दो आयामों में दर्शाया जाता है, वहीं मूर्तिकला त्रि-आयामी रूप में आकार, रूप और भाव को प्रस्तुत करती है। जब ये दोनों कलाएँ एक साथ आती हैं, तो वे एक-दूसरे के सौंदर्य को न केवल पूर्ण करती हैं, बल्कि दर्शक के अनुभव को भी अधिक गहराई प्रदान करती हैं। प्राचीन भारतीय मंदिरों में दीवारों पर बने चित्रों और पत्थर की मूर्तियों के मध्य यह समन्वय स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अजन्ता-एलोरा की गुफाओं में चित्रकला व मूर्तिकला का अद्भुत संगीकार भारतीय कला की उँचाइयों को दर्शाता है।

आधुनिक युग में भी कलाकार इन दोनों माध्यमों को एक साथ प्रयोग में लाकर नए रूप और विचारों की खोज कर रहे हैं। समकालीन कला में चित्रित मूर्तियाँ या चित्रों में मूर्तिकला की गहराई का समावेश, एक नई दृश्य-भाषा का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार, चित्रकला और मूर्तिकला का संगीकार न केवल सौंदर्यबोध को समृद्ध करता है, बल्कि यह कला की विभिन्न विधाओं के बीच सामंजस्य और सहयोग का प्रतीक भी है। यह दर्शाता है कि कला कोई एकांगी प्रयास नहीं, बल्कि विविध अभिव्यक्तियों का एक जीवंत संवाद है।

**शब्द कुंजी** – चित्रकला, मूर्तिकला, संगीकार, भारतीय कला, दृश्य अभिव्यक्ति, त्रि-आयामी कला, दो-आयामी कला, धार्मिक भावनाएँ, सांस्कृतिक पहचान, मंदिर कला, अजन्ता-एलोरा, गुफा चित्रकला, पत्थर की मूर्तियाँ, समकालीन कला, आधुनिक अभिव्यक्ति, रंग, रेखा, आकार, रूप, सौंदर्यबोध, कला समन्वय, दृश्य-भाषा, अभिव्यक्ति के माध्यम, भारतीय परंपरा, कलाकार, शैली, रचनात्मकता, जीवंत संवाद, सहयोग, सौंदर्य, प्रेरणा।

**प्रस्तावना** – भारतीय कला परंपरा में चित्रकला और मूर्तिकला का विशेष स्थान रहा है। ये दोनों कलाएँ प्राचीन काल से ही मानव भावनाओं, धार्मिक आस्थाओं और सांस्कृतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति के प्रमुख साधन रही हैं। चित्रकला जहाँ रंग, रेखा और रूप के माध्यम से दो-आयामी दृश्य प्रस्तुत करती है, वहीं मूर्तिकला त्रि-आयामी माध्यम द्वारा रूप, आकार और स्पर्श का जीवंत अनुभव कराती है। जब ये दोनों कलाएँ एक साथ प्रयोग की जाती हैं, तो उसे 'संगीकार' कहा जाता है – अर्थात् कला का समन्वित रूप। चित्रकला व मूर्तिकला का संगीकार केवल सौंदर्यबोध का विस्तार नहीं है, बल्कि यह कलात्मक दृष्टिकोण की एक समग्रता भी है, जो दर्शक के अनुभव को अधिक प्रभावशाली और भावनात्मक बनाता है। भारतीय मंदिरों, गुफाओं, स्तूपों और धार्मिक स्थलों पर इन दोनों कलाओं का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। अजन्ता और एलोरा की गुफाओं में चित्रित भित्तिचित्रों और उकेरी गई मूर्तियों का संयोजन इस संगीकार का श्रेष्ठ उदाहरण है।



अजन्ता गुफा अलंकृत चित्राकृति



एलोरा गुफा अलंकृत मूर्तिशिल्प

यह संगीकार केवल भूतकाल तक सीमित नहीं है, आधुनिक व समकालीन कला में भी इसका उपयोग निरंतर हो रहा है। कलाकार आज डिजिटल माध्यमों, मिश्रित तकनीकों और स्थापना कला के माध्यम से चित्र और मूर्ति का नया समन्वय (कृति) रहे हैं। इस प्रकार, चित्रकला और मूर्तिकला का संगीकार न केवल पारंपरिक कला की गरिमा को बढ़ाता है, बल्कि समकालीन अभिव्यक्ति के नए द्वार भी खोलता है। यह कला के विभिन्न रूपों के बीच संवाद स्थापित करता है, जिससे एक समृद्ध, सजीव और भावनात्मक कलात्मक अनुभव जन्म लेता है।

**भारतीय चित्रकला की परंपरा** – भारतीय चित्रकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन, समृद्ध और विविधतापूर्ण रही है। इसकी जड़ें प्रागैतिहासिक युग की



गुफा चित्रों में देखी जा सकती हैं, जहाँ मानव ने अपने अनुभवों, जीवनशैली और प्रकृति के प्रति भावना को दीवारों पर उकेरा। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएँ इसका प्रमुख उदाहरण हैं, जहाँ शिकार, नृत्य और दैनिक जीवन के दृश्य चित्रित हैं। प्राचीन काल में धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए चित्रकला का व्यापक प्रयोग हुआ। मौर्य और गुप्त काल में चित्रकला ने विशेष उन्नति की। विशेषतः बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ-साथ भित्तिचित्रों का विकास हुआ, जिसमें अजन्ता की गुफाओं के भित्तिचित्र विश्व प्रसिद्ध हैं। ये चित्र केवल सौंदर्य का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि कथा, भाव, रंग और रचना की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हैं। इन चित्रों में बुद्ध, बोधिसत्त्वों और जनजीवन से संबंधित कहानियों को अत्यंत जीवंत रूप में दर्शाया गया है। मध्यकालीन भारत में क्षेत्रीय चित्र शैलियाँ विकसित हुईं, जिनमें राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी, पट्टचित्र, मधुबनी, कांगड़ा, और कलमकारी चित्रकला प्रमुख हैं। इन शैलियों में धार्मिक विषयों के साथ-साथ दरबारी जीवन, प्रेम प्रसंग, प्रकृति और लोक जीवन को भी चित्रित किया गया। मुगल काल में चित्रकला ने एक शाही रूप धारण किया, जहाँ यथार्थवाद, सूक्ष्मता और रंगों की गहराई का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। आधुनिक काल में राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, जमिनी रॉय जैसे चित्रकारों ने परंपरा और आधुनिकता का सुंदर समन्वय किया। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय चित्रकला ने वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई और समकालीन कलाकारों ने नए प्रयोगों से इसकी सीमाएँ और भी विस्तृत कीं। इस प्रकार, भारतीय चित्रकला की परंपरा न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह देश की आत्मा, भावना और सौंदर्यबोध को भी दर्शाती है। यह परंपरा मूर्तिकला के साथ मिलकर एक समग्र कलात्मक अनुभव को जन्म देती है।

**भारतीय मूर्तिकला की परंपरा** – भारतीय मूर्तिकला की परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है और यह देश की सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक चेतना की सजीव अभिव्यक्ति रही है। इस कला के माध्यम से न केवल देवी-देवताओं का रूपांकन हुआ, बल्कि मानव जीवन, प्रकृति, पशु-पक्षी, नारी सौंदर्य और अध्यात्म के विभिन्न पक्षों को भी साकार रूप प्रदान किया गया। भारत में मूर्तिकला की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता (2600-1900 ई.पू.) से मानी जाती है। इस युग की नर्तकी और पुरुष योगी जैसी कांस्य व पत्थर की मूर्तियाँ आज भी अद्वितीय कलाकृतियों के रूप में प्रसिद्ध हैं। मौर्य काल में अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभ और सिंहों की मूर्तियाँ राजकीय शक्ति और शिल्प सौंदर्य का प्रतीक हैं।



**नटराज, कांस्य मूर्तिशिल्प**

गुप्त काल (चौथी से छठी शताब्दी) को भारतीय मूर्तिकला का 'स्वर्ण युग' कहा जाता है। इस काल की मूर्तियाँ संतुलन, सौंदर्य और अध्यात्म का

अद्भुत समन्वय दर्शाती हैं। बुद्ध, विष्णु, लक्ष्मी, शिव आदि देवी-देवताओं की मूर्तियाँ अत्यंत भावप्रवण एवं कलात्मक होती थीं। दक्षिण भारत में चोल वंश (9वीं-13वीं शताब्दी) के दौरान कांस्य मूर्तियों का उत्कर्ष हुआ। विशेषतः नटराज की मूर्ति विश्वविख्यात है, जो शिव के तांडव नृत्य का प्रतीक है। इन मूर्तियों में गति, लय और भाव की अभूतपूर्व छटा दिखाई देती है। मध्यकालीन भारत में मंदिरों की स्थापत्य कला में मूर्तिकला का विशेष स्थान रहा। खजुराहो, कोणार्क, एलोरा, होयसल और बेलूर के मंदिरों में शिल्पकारों ने पत्थरों को जीवंत कर दिया। इन मूर्तियों में धार्मिकता के साथ-साथ मानवीय भावनाओं, श्रृंगार, संगीत और नृत्य की झलक मिलती है। आधुनिक युग में मूर्तिकला ने पारंपरिक शैली से आगे बढ़कर नए प्रयोग किए हैं। रामकिंकर बैज जैसे मूर्तिकारों ने आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर मिट्टी, धातु, लकड़ी और मिश्रित माध्यमों में सामाजिक विषयों पर आधारित रचनाएँ कीं। इस प्रकार, भारतीय मूर्तिकला की परंपरा केवल धार्मिक प्रतीकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह भारतीय जीवनदृष्टि, सांस्कृतिक विविधता और कलात्मकता की गहराई को दर्शाने वाली एक जीवंत परंपरा रही है। चित्रकला के साथ इसका संगीकार एक समग्र सौंदर्य और भावात्मक अनुभव प्रदान करता है।



**मोहन जोदड़ो-नृतकी (कांस्य), योगी (प्रस्तर)**

**चित्रकला और मूर्तिकला का समन्वय** – चित्रकला और मूर्तिकला, दोनों ही दृश्य कलाओं के प्रमुख अंग हैं, जिनका उद्देश्य मानव भावनाओं, धार्मिक विश्वासों और सामाजिक विचारों की अभिव्यक्ति करना है। जब ये दोनों कलाएँ एक साथ आती हैं, तो उनका समन्वय (संगीकार) एक ऐसी कलात्मक समग्रता उत्पन्न करता है, जो देखने वाले को न केवल सौंदर्य का अनुभव कराती है, बल्कि उसमें एक गहन भावात्मक प्रभाव भी उत्पन्न करती है। भारतीय कला में इस समन्वय की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। अजन्ता और एलोरा की गुफाएँ इस कला संगम की श्रेष्ठ मिसालें हैं, जहाँ दीवारों पर चित्रित भित्तिचित्र और पत्थर में उकेरी गई मूर्तियाँ एक-दूसरे के पूरक के रूप में मौजूद हैं। इन गुफाओं में चित्रकला कथा को दृश्य रूप में प्रस्तुत करती है, जबकि मूर्तिकला उस कथा को स्पर्श योग्य, मूर्त और सजीव बनाती है। इस प्रकार, दोनों कलाएँ मिलकर एक समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करती हैं। मंदिर स्थापत्य में भी चित्र और मूर्ति का गहरा तालमेल देखा जाता है। मंदिर की दीवारों, मंडपों और स्तंभों पर उकेरी गई मूर्तियाँ धार्मिक कथाओं, देवी-देवताओं, नृत्य, संगीत और लोक जीवन के दृश्यों को दर्शाती हैं, जबकि चित्रकला उन भावनाओं को रंगों और रेखाओं के माध्यम से गहराई प्रदान करती है।

समकालीन युग में यह समन्वय नए रूपों में उभर रहा है। कलाकार अब मिश्रित माध्यमों का प्रयोग करके चित्र और मूर्ति को एक साथ प्रयोग में ला रहे हैं—जैसे डिजिटल चित्रों के साथ स्थापित मूर्तियाँ, या सार्वजनिक स्थलों



पर बनाए गए 'इंस्टॉलेशन आर्ट' जो दृश्य और भौतिक दोनों अनुभव प्रदान करते हैं। इस प्रकार, चित्रकला और मूर्तिकला का समन्वय न केवल एक कलात्मक तकनीक है, बल्कि यह एक दार्शनिक दृष्टिकोण भी है, जो दर्शक को एक पूर्ण, सजीव और संवेदनशील अनुभव प्रदान करता है। यह समन्वय कला को बहुआयामी बनाता है और भारतीय कला परंपरा की गहराई को उजागर करता है।

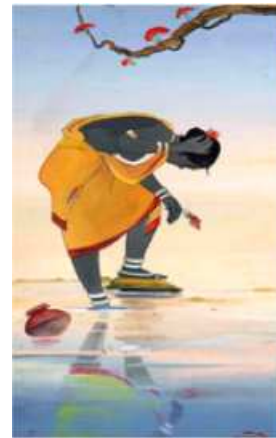
**सांस्कृतिक और धार्मिक अभिव्यक्ति** – भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला की परंपरा सदैव से सांस्कृतिक और धार्मिक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम रही है। इन कलाओं के माध्यम से न केवल धार्मिक प्रतीकों और देवी-देवताओं का चित्रण हुआ है, बल्कि भारतीय समाज की सांस्कृतिक विविधता, जीवन मूल्य, आस्थाएँ और परंपराएँ भी अभिव्यक्त हुई हैं। चित्रकला में धार्मिक कथाओं को जीवंत रूप देने की परंपरा प्राचीन काल से रही है। अजन्ता की गुफाओं में बौद्ध जातक कथाएँ, भगवान बुद्ध के जीवन प्रसंग, करुणा, त्याग और ध्यान की भावना को रंगों व रेखाओं के माध्यम से अत्यंत संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया गया है। इसी प्रकार, मुगल काल में धार्मिक विषयों के साथ-साथ सामाजिक जीवन को भी चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया। मूर्तिकला में यह धार्मिक अभिव्यक्ति और भी अधिक गहराई से देखी जा सकती है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में देवी-देवताओं की मूर्तियाँ केवल पूजनीय नहीं, बल्कि एक गूढ़ दार्शनिक अर्थ की वाहक भी होती हैं। नटराज की मूर्ति शिव के सृजन, संहार और संतुलन की शक्ति का प्रतीक है, तो बुद्ध की ध्यानस्थ मुद्रा आत्मशांति और निर्वाण की ओर संकेत करती है। सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में चित्र और मूर्तियाँ लोकजीवन, रीति-रिवाजों, उत्सवों, नृत्य, संगीत और दैनिक जीवन की झलकियाँ भी प्रस्तुत करती हैं। मधुबनी, वारली, पट्टचित्र जैसी लोकचित्र शैलियाँ स्थानीय सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति हैं। मूर्तिकला में ग्राम्य जीवन, कृषक, नारी, पशु-पक्षी आदि के रूपांकन के माध्यम से संस्कृति को मूर्त रूप मिला है। इस प्रकार, चित्रकला और मूर्तिकला के संगीकार ने भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा है। यह संगीकार न केवल भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि भारतीयता की आत्मा को भी रूप और रंग प्रदान करता है।



**नन्दलाल बॉस कृति शिव विषपान**

**सौंदर्यशास्त्र और कलात्मकता** – चित्रकला और मूर्तिकला दोनों ही कला के ऐसे रूप हैं जो सौंदर्यशास्त्र के मूल सिद्धांतों पर आधारित होते हैं और कलात्मकता के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत करते हैं। जब ये दोनों कलाएँ संगीकार के रूप में एक साथ आती हैं, तो वे न केवल दृश्य सौंदर्य को बढ़ाती

हैं, बल्कि दर्शक के मन और भावनाओं पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। सौंदर्यशास्त्र की दृष्टि से चित्रकला रंग, रेखा, छाया, बनावट और संयोजन के माध्यम से दृष्टिगत आनंद प्रदान करती है। इसमें रचनात्मकता का मुख्य आधार रचनाकार की कल्पना शक्ति और संवेदनशीलता होती है, जो वस्तुओं, भावों और विचारों को दो-आयामी सतह पर जीवंत कर देती है। चित्रकला की रेखाएँ और रंग भित्ति, कागज या कपड़े पर स्थिर रूप में मन को मोह लेते हैं। मूर्तिकला में सौंदर्यशास्त्र का अर्थ आकार, अनुपात, गति और सामंजस्य से होता है। मूर्तिकार त्रि-आयामी माध्यम में काले, संगमरमर, कांस्य या लकड़ी जैसे पदार्थों से जीवंत आकृति निर्मित करता है। मूर्तिकला में सौंदर्य की अनुभूति न केवल देखने से होती है, बल्कि स्पर्श, प्रकाश-छाया और स्थान की समझ से भी होती है। मूर्तियों में भाव, मुद्रा, और अभिव्यक्ति का संयोजन उन्हें जीवंत और प्रभावशाली बनाता है। जब चित्रकला और मूर्तिकला एक साथ संगीकार करते हैं, तो वे दोनों कला के तत्वों का ऐसा समन्वय करते हैं, जो संपूर्ण कलात्मक अनुभव प्रदान करता है। मंदिरों, गुफाओं या स्थापत्य कला में चित्र और मूर्तियाँ एक-दूसरे के पूरक बनकर सौंदर्य और अर्थ दोनों को समृद्ध करती हैं। यहाँ रंग और रूप की सामंजस्यपूर्ण संरचना, रेखाओं की सजीवता और आकृतियों की शारीरिक सुंदरता साथ-साथ महसूस होती है। इस प्रकार, चित्रकला व मूर्तिकला का संगीकार न केवल कलात्मकता की गहराई को दर्शाता है, बल्कि यह दर्शाता है कि कला में सौंदर्य के कई रूप मिलकर एक समग्र, जीवंत और प्रभावशाली अनुभूति उत्पन्न करते हैं। यह संयोजन भारतीय कला की विशेषता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है।



**जमीनी रॉय कृति संधाल महिला**

**महत्वपूर्ण कलाकार और उदाहरण** – भारतीय कला की समृद्ध परंपरा में अनेक कलाकारों ने चित्रकला और मूर्तिकला के संगीकार को नए आयाम दिए हैं। इन कलाकारों ने पारंपरिक कलाओं का सम्मान करते हुए उन्हें आधुनिक दृष्टिकोण और तकनीकों के साथ जोड़कर भारतीय कला को विश्व मंच पर प्रतिष्ठित किया है। चित्रकला और मूर्तिकला के संगीकार में सबसे प्रमुख नामों में से एक हैं रवींद्रनाथ टैगोर। वे न केवल एक महान कवि और दार्शनिक थे, बल्कि कला के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। टैगोर की चित्रकला में चित्र और मूर्तिकला का संयोजन और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति स्पष्ट देखने को मिलती है। उनकी कला में रंगों और आकृतियों का ऐसा समन्वय है जो भावनाओं को गहराई से व्यक्त करता है।

रामकिंकर बैज को आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक माना जाता है। उन्होंने पारंपरिक भारतीय मूर्तिकला की तकनीकों को आधुनिक कलात्मक

दृष्टिकोण के साथ मिलाकर नई शैली प्रस्तुत की। उनकी मूर्तियाँ न केवल स्थापत्य कला का हिस्सा हैं, बल्कि उनमें चित्रकला के रंग और रूप भी झलकते हैं, जो मूर्तिकला को और अधिक जीवंत बनाते हैं। बैज की प्रसिद्ध कृतियाँ जैसे 'कृष्ण लीला' और 'महात्मा गांधी की मूर्तियाँ' उनकी संगीकार की क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

नंदलाल बोस और जमिनी रॉय जैसे चित्रकारों ने भी चित्रकला और मूर्तिकला के संगीकार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके चित्रों में लोक संस्कृति और पारंपरिक कलाओं की झलक मिलती है, जो मूर्तिकला की शिल्पकारी से गहरे जुड़े हुए हैं। इन कलाकारों ने भारतीय लोक जीवन और धार्मिक भावनाओं को चित्रकला के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। प्राचीन काल के उदाहरणों में अजन्ता की गुफा चित्रकला और एलोरा की मूर्तिकला विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यहाँ भित्ति चित्र और शिल्प कला का ऐसा अनूठा संगम है, जो भारतीय कला की संगीकार परंपरा को दर्शाता है। इस प्रकार, भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला के संगीकार में ये कलाकार और उनके कार्य न केवल कलात्मक अभिव्यक्ति के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, बल्कि वे भारतीय सांस्कृतिक विरासत को भी विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करते हैं। इनके माध्यम से कला की सीमाएं विस्तृत हुईं और संगीकार ने एक नया और सशक्त स्वरूप प्राप्त किया।



**जमिनी रॉय कृति माँ और बच्चा, तीन पुजारिन**

**निष्कर्ष** – चित्रकला और मूर्तिकला का संगीकार न केवल भारतीय कला परंपरा की गहराई और विविधता को दर्शाता है, बल्कि यह कलात्मक अभिव्यक्ति के समग्र दृष्टिकोण को भी उजागर करता है। जब रंग, रेखाएँ, आकार और त्रि-आयामी रूप एक साथ आते हैं, तो वे एक ऐसी सौंदर्यात्मक अनुभूति का निर्माण करते हैं जो दर्शक के मन-मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ती है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक, इन दोनों कलाओं का समन्वय न केवल दृश्य सौंदर्य को समृद्ध करता रहा है, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक चेतना का भी संवाहक बना है। अतः चित्रकला व मूर्तिकला का यह संगीकार एक जीवंत परंपरा है, जो निरंतर विकसित होते हुए कला की नई दिशाओं को भी प्रश्रय देता है।

### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. 'भारतीय चित्रकला का इतिहास', डॉ. विद्यानीवास मिश्र, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत सरकार, 2005
2. 'भारतीय मूर्तिकला: एक अध्ययन', डॉ. कृष्णदेव, इंद्रप्रस्थ पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2003
3. 'भारतीय कला और संस्कृति', डॉ. कपिला वात्स्यायन, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, 1992
4. 'एस्थेटिक्स एंड इंडियन आर्ट', अनंद केंटिश कोमरस्वामी, मुनशीराम मनोहरलाल पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1994 (पुनः मुद्रित)
5. 'एलोरा: कला और स्थापत्य', डॉ. आर. नागस्वामी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 1980

\*\*\*\*\*